Punjab Vidhan Sabha Debates

Vol. I—No. 14

8th March, 1966

OFFICIAL REPORT

(37) 14-20

426

8-3-1966

16-3-1966



CONTENTS

Tuesday, the 8th March, 1966

Price : Rs. 9.50 Paise.

Price : Rs. 9.50 Paise. 2.50 Paise

ERRATA

TO

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 14*, dated the 8th March, 1966*

Read	*For*	*Page*	*Line*
पंडित	पडित	(14)1	13 from below
मन्त्री	मन्त्रो मत्री	(14)1 (14)2	10 from below I9
श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री	श्री ओम प्रकाश अन्गिहोत्री श्री ओम प्रकाश अग्नीहोत्री	(14)1 (14)13	8 from below 18 and 22
फी	ह ी	(14)5	5 from below
श्री फतेह चन्द विज	श्री फतह चन्द विज	(14)5	4 from below
प्वाएज़निंग	प्वाएजिंग	(14)10	10
Makhan Singh Tarsikka	Makhan Singh Tarsikkar	(14)25	7 from below
Annexure	Annexxure	(14)25	Last but one
Marriage	Marrigare	(14)28	S. No. 26, Col. 5
hides	bides	(14)36	11
confirmed	ocnformed	(14)36	12 from below
(14)39	(14)3	(14)39	Page No.
Ambala	a	(14)40	Last but one
Assistant	Assistat	(14)41	Last
district	distriact	(14)43	9
said	sid	(14)44	3 from below
statement	stateeent	(14)45	Last
Rajput	Rajpurt	(14)46	10 from below
Kundan Lal	Kundan La	(14)64	3 from below
above	adove	(14)72	3
discharged	disc arged disch;ged	(14)72 (14)78	4 4
Irrigation	Irrigation and Ir igation	(14)96 (14)98	1 1

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Education Minister	Chief Minister	(14)112 (14)114	1 1
ਗੋਗੋਆਣੀ	ਗੋਆਣੀ	(14)128	9 from below
alongwith	alonowith	(14)129	13 from below
इम्पार्टेंट	इम्पर्टिंट	(14)130	9
delete the word 'चिट्ठी' *aftet the word* 'यह'		(14)130	12
Accounts	Acconts	(14)130	10 from below
स्पीकर साहिब	स्पीकर साहिबा	(14)130	4 from below
(14)131	(14)831	(14)131	Page No.
has	hs	(14)131	13 from below
ਤਰ੍ਹਾਂ	ਤਾਂਰ੍ਹ	(14)132	9
ਸਰਦਾਰ	ਸਰਬਾਰ	(14)137	12 from below
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ	ਖਜ਼ਨਾ ਮੰਤਰੀ	(41)137	4 from below
ਵਿਚ	ਵਚ	(14)139	6
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ	ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ	(14)142	1
(14)146	4)146	(14)146	Page No.
scape goat	scope goat	(14)146	4 from below
GENERAL	GENTRAL	(14)147	19
दे सकें	` सकें	(14)161	3
तहसील	तहलील	(14)162	12
चौधरी बालू राम	चौधरी बाल राम	(14)162	6 from below
बारे	बा	(14)163	16
ਸਰਕਾਰ	ਸਕਾਰ	(14)167	9
भावना	भ वना	(14)169	5 from below
फजूल	फलजू	(14)170	7 from below
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ	ਕਾਰਪੋਰੈਸ਼ਨਾਂ	(14)177	15 from below
ਡਰਾਉਟ	ਡਰਾਂਟ	(14)177	9 from below
ਓਪਨ	ਓਪਨ	(14)178	7 from below
ਪੀਹਵੇ	ਪੀਵੈ	(14)179	1
ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ	ਪੋਜ਼ੀਨਸ਼	(14)179	2
ਕ ਗਜ਼	ਕਾਂਗਜ਼	(14)179	6 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 8th March, 1966

The Sabha met in the Assembly Hall, Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supplementaries to *Starred Question No. 8856

Mr. Speaker : Supplementaries to starred question No. 8856 by Comrade Ram Chandra.

(No hon. Member rose to put a question).

Supplementaries to †Starred Question No. 9466

Mr, Speaker : Supplementaries to Starred Question No. 9466 by Sardar Kulbir Singh and Chaudhri Satya Dev.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਇਕ ਇਨਸ-ਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਿਸ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤਾ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

पंडित श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री: उन्हों ने यह पूछा था कि किस तारीख को तहकीकात उनके स्पुर्द की गई और किस तारीख को वह हफता पूरा होगा लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं जिस दिन जवाब दिया गया। यह तो पिछले साल की बात है ।

राज्य मन्त्री : इस में फैक्ट यह है कि वह आदमी जिस के साथ इन्क्वायरी होनी है he is trying to avoid.

श्री श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : इस का मतलब है कि हफ्ता अभी शुरू ही नहीं हुआ है ? वह हफ्ता कब शुरू होगा ?

राज्य मन्त्री : हम ने काम शुरू किया हुआ है लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत है वह avoid कर रहा है ।

Note :—*Starred Question No. 8856 alongwith its reply appears in the PVS Debates Vol I No. 11 dated 2nd March, 1966

2. †Starred Question No. 9466 along with its reply appears in the Debate Vol-I No, 11 dated 2nd March, 1966.

श्री अध्यक्ष : उन का सवाल तो यह है कि किस तारीख को इन्क्वायरी शुरू की गई ?
(His question is, on what date the enquiry was started ?)

Education Minister : The question pertains to last year. Immediately the complaint was received, the Government ordered an enquiry. Unfortunately, the party against whom the complaint was made is avoiding summons. We will immediately send a person from Headquarters and see that if he does not appear before the Enquiry Committee, an *ex-parte* decision may be taken.

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि किस तारीख को इन्क्वायरी आर्डर की गई। उनका स्पैसिफिक क्वेस्चन है। (The question is regarding the date when the enquiry was ordered. It is a specific question.)

शिक्षा मन्त्री : पिछले साल की बात है ऐग्जैक्ट डेट का तो इस वक्त पता नहीं।

श्री बलरामजी दास टंडन : जब किसी सरकारी मुलाजिम या सैमी गवर्नमैंट अदारे के मुलाजिम के खिलाफ इन्कवायरी होती है तो उसका ऐक्सप्लेनेशन काल करते हुए कहा जाता है कि इतने दिन के अन्दर अगर ऐकस्पलेनेशन न आया तो यह समझा जाएगा कि आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है और ऐक्सपार्टी प्रोसीडिंग्ज की जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस केस के अन्दर ऐसा किया गया और अगर नहीं तो क्यों ?

मन्त्री : इन्क्वायरी की गई थी। 20 अप्रैल, 1965 को रिपोर्ट आई है : कुछ ऐम्बैज़लमैंट वगैरा की बात उठाई गई है। हम उसी दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह आदमी मिलता ही नहीं। कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने निकल जाता है। 20 अप्रैल 1965 को प्रोसीडिंग बुक ऐग्ज़ामन की गई थी। कुछ फैबरीकेशन वगैरा का चार्ज है मगर वह आदमी ट्रेस नहीं हो रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जैसा कि उन्हों ने माना है कि इस में ऐम्बैजलमैंट की बात है क्या वह बताएंगे कि इस के बारे में पुलिस में केस रजिस्टर कराया गया अगर नहीं तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री : जैसा कि मैम्बर साहिब को मालूम है कि जब इन्क्वायरी रिपोर्ट आ जाती है और उस में कोई प्राइमाफेसाई केस बनता हो तब केस रजिस्टर कराने की कार्यवाही की जाती है। जैसा कि वज़ीर साहिब ने बताया है वह आदमी ही ट्रेस नहीं हो रहा है जिस से यह सारा पता करना है तो इस केस में जो alleged fabrication of record. और खुर्द बुर्द की बात कही जाती है उसे मज़ीद देख कर अगले दो तीन हफ्तों में सारी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अन्दर अगर कोई ऐसी बात साबित हो जाती है तो फिर आगे कार्यवाही करनी ज़रूरी हुई की जाएगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Keeping in view the fact that it is a case of embezzlement, may I know from the Hon. Chief Minister as to what steps have been taken by the Government to secure the presence of the accused ?

मुख्य मन्त्री : जब तक वह रिपोर्ट आ कर साबित नहीं हो जाता कि ऐम्बैज़लमैंट हुई है या नहीं, कायदे कानून के मुताबिक ही सारी कार्यवाही करनी पड़ती है। दो तीन हफ्ते की म्याद मांगी जा रही है उसके अन्दर रिपोर्ट आ जाएगी और हाउस को सारा पता चल जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ?

मुख्य मन्त्री : रिपोर्ट आ जाने के बाद जिस जिस के खिलाफ कोई कदम उठाया जाना है उठाया जाएगा।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : जब यह चीज़ है कि ऐमबैज़लमैंट का केस है then why not to get a case registered against him in the police ?

मुख्य मन्त्री : कायदे कानून के मुताबिक किसी को चांस तो देना होगा।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : उन्होंने कहा है कि वह आदमी ट्रेस नहीं हो रहा है लेकिन अभी २ मेम्बर साहिब ने बताया है कि अभी भी वह मारकिट कमेटी के ओहदेदार के तौर पर वहां काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर वह ट्रेस कैसे नहीं हो रहा है ?

मुख्य मन्त्री: इन सारी चीजों को देखा जाएगा और इस बात को भी देखा जाएगा कि कोई गलत तौर पर उसे पनाह तो नहीं दे रहा है। इन सारी चीजों को देख कर दो तीन हफतों में सारी रिपोर्ट आ जाएगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. Mr. Speaker, Captain Rattan Singh, Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture was pleased to tell the House in reply to a question that the man concerned was not traceable although efforts were made to trace him. An hon. Member has informed that he is still working as Secretary of the Committee. May I know which of the two positions is correct ?

Mr. Speaker : The hon. Member will agree with me that it is not a point of Order. It is a supplementary question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Kindly listen to me. I want to know whether the stand taken by the State Minister or by the Chief Minister is correct ?

Mr, Speaker : This can be a supplementary and not a point of Order.

श्री बलराम जी दास टंडन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सवाल का जवाब देने के लिये या तो चीफ मिनिस्टर साहिब खड़े न हों लेकिन जब वह जवाब देने के लिये खड़े होते हैं तो जो सवाल पूछा गया है उसका सपैसिफिक जवाब दें। सवाल कुछ हो और जवाब कुछ आए यह मुनासिब नहीं। इस लिये मैं आपका रूलिंग चाहता हूं कि जब वह जवाब देने के लिये खड़े हों तो वह to the point होना चाहिए या नहीं ?

श्री फतेह चन्द विज : यहां बताया गया है कि वह कभी इधर कभी उधर हो जाता है काबू में नहीं आता है। चीफ मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि दो हफतों में सारी पोज़ीशन साफ हो जाएगी आखिर गफलाबाजी कहां पर है ? (हंसी)

Education Minister : From a preliminary enquiry it is clear that some sort of fabrication of the record is there. But to lay responsibility for fabrication of record a number of times some people who were supposed to have done the fabrication were asked to appear before the Enquiry Committee but unfortunately they avoided on one pretext or the other. The Chief Minister has given a categorical statement that even if we have to send some body from here we will see that the House gets full information within two weeks time.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। आपने रूलिंग दिया था कि जिस महकमा का सवाल हो उस का वज़ीर अगर हाउस में मौजूद हो तो उसे ही जवाब देना चाहिए। तो क्या जब महकमा का वज़ीर हाउस में मौजूद हो तो दूसरा वज़ीर जवाब दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष : मैं डिबार तो नहीं कर सकता लेकिन my observation stands. (I cannot debar him but my observation stands).

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Education Minister as to how long will it take the Government to finalise the enquiry ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ प्रिलिमनिरी इन्क्वायरी हुई और उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन उसमें वाइस चेयरमैन का स्टेटमैंट लेना बाकी है और उसके लिए एक सीनीयर इन्स्पैक्टर कोशिश कर रहा है मगर वह वाइस चेयरमैन पता नहीं किस पायंट आफ व्यू से, मैं नहीं कह सकता appear नहीं हो रहा है। स्टेटमैंट हो जाने दें और अगर वह नहीं देता, delaying tactics होते हैं तो भी जो रिपोर्ट आएगी उसे देखेंगे और आप जो इन्फर्मेशन लेना चाहेंगे दे देंगे। कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बताया जाएगा। वाइस चेयरमैन का स्टेटमैंट ले[illegible]बाकी है उसके बाद जो ज़रूरी कदम उठाने दरकार होंगे उठाए जाएंगे।

Promoting Kitchen Gardens and encouraging grow-More Vegetables' at Chandigarh

***9224. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Government has appointed separate staff for the exclusive purpose of promoting kitchen gardens and encouraging 'Grow-More Vegetables' in Chandigarh ;

(b) if the answer to para (a) above be in the affirmative, the number of officers/officials, category-wise appointed for this purpose ;

(c) the quantity of seeds and saplings, etc. distributed through the, agency of the officials in Chandigarh during the year 1965 together with the number of houses visited by the Inspectors personally during the year 1965 for the said purpose ;

(d) the steps taken by the Government to ensure that the Inspectors have actually visited the houses and that the seeds, etc., are not pilfered or misappropriated but actually used for the purposes mentioned above ;

(e) the number of shops or depots selling fertilizers to the citizens of Chandigarh ;

(f) whether the Government is aware of the fact that these shops in Chandigarh are insufficient to meet the needs of the Chandigarh population ?

Captain Rattan Singh (Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture) · (a) Yes.

(b)

Agricultural Inspector	.. One
Agricultural Sub-Inspector	.. One
Beldars	.. Eight
Chowkidar	.. One

(c)

Part (i)	.. 50 Quintals
(ii)	.. One thousand houses

(d) The work of Agricultural Inspectors is being supervised by the Deputy Director of Agriculture (Vegetables). The Seeds are supplied to the residents at their residences to avoid pilferage/misappropriation.

(e) One

(f) Yes. Arrangements are being made to supply fertilizers through various Fair Price Shops.

Shri Ram Saran Chand Mital : Will the Minister of State be pleased to state the number of houses where the kitchen gardens have actually been encouraged or started and the number of houses which have been registered for this purpose but where these kitchen gardens have not been encouraged or started so far ?

Minister of State : According to the funds available, we have started these kitchen gardens in 1,000 houses. If more funds are made available we can start them in more houses.

श्री फतेह चन्द विज : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सीडज़ सप्लाई करने के मुकाबले में घरों में सब्जियों की प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है ?

राज्य मन्त्री : प्रोडक्शन के बारे में लोगों के घर पर जा कर इन्फर्मेशन कुलैक्ट नहीं की जाती। इस लिये कहा नहीं जाता कि सीड्ज़ देने के मुकाबले में कितनी प्रोडक्शन बढ़ी है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Minister whether such steps for promoting kitchen gardens and encouraging 'Grow-More-Vegetables have also been taken in other towns ; if so, the names of those towns ?

Minister of State ; These funds are made available by the Government of India and if more funds are made available we will do it more.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यहां पर घरों में सब्जी उगाने के लिये सरकार की तरफ से लोगों को बीज कीमत पर दिया जाता है या फ्री दिया जाता है ?

राज्य मन्त्री : फ्री दिया जाता है।

श्री फतह चन्द विज : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास कोई शिकायत आई है कि इस महकमे के अधिकारियों ने बीज तकसीम करने में हेरा फेरी की है ? अगर कोई हेरा फेरी हुई है तो उस के बरखिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

राज्य मन्त्री : हमारे नोटिस में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

Shri Ram Saran Chand Mital : Will the hon. Minister be pleased to state as to when the fertilizers would be supplied through the Fair Price Shops or Depots ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਭੀ ਜਲਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Villages under the jurisdiction of Police Station, Bhadaur, tehsil Barnala, district Sangrur

*9732. **Sardar Ranjit Singh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the villages under the jurisdiction of Police Station, Bhadaur, tehsil Barnala, district Sangrur have been placed in the jurisdiction of the court of Magistrate 1stClass at Phul, district Bhatinda in Civil and Criminal cases ;

(b) whether any representations have been received from time to time requesting that the said villages be attached with the Court of tehsil Barnala ;

(c) the steps or decision, if any, taken by the Government to meet the said demands ?

Shri Chand Ram : (a) Yes.

(b) No.

(c) The Punjab High Court have been requested to look into the matter.

Enquiry held against Sarpanch of village Mahalpur Khurd, district Jullundur

*9796. **Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Director, Panchayat held an enquiry into the complaint regarding mis-appropriation of the Panchayat funds against the Sarpanch of Village Mahalpur Khurd, tehsil Nawanshahr, district Jullundur ;

(b) whether it is a fact that during the said enquiry, the case of mis-appropriation was established ;

(c) whether it is a fact that the Panchayat Department has not taken any action against the said Sarpanch so far ;

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, whether the Government intend to take any action in the matter ; if so, what ?

Shri Prabodh Chandra (Education Minister) : (a), (b) Yes. The Assistant Director of Panchayats, Jullundur Division held the enquiry against the Sarpanch Gram Panchayat, Mahal Khurd, and not Mahalpur Khurd.

(c) No. The Deputy Commissioner, Jullundur has been requested to take necessary action against the Sarpanch ;

(d) As against item (c) above.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਭੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

Minister : Government has advised the Deputy Commissioner to take action against the Sarpanch. I will, however, check up whether it has been taken or not.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Education Minister if the case for misappropriation was made out why the Deputy Commissioner was not asked to get the case registered against the Sarpanch ?

Minister : If the findings are that the Sarpanch has been guilty of mis-appropriation then certainly the process of law will come into force. It was the view of the hon. Members of this House that in many cases Sarpanches and Panches are being humiliated by the Police, so the Government has issued instructions that when there is a case of misappropriation against a Sarpanch the Deputy Commissioner should look into the case to avoid any harassment or vindictiveness on the part of the Police.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Education Minister if it is a fact that Government has issued instructions to the Deputy Commissioner that when there is a case of mis-appropriation against a Panch it should be looked into by a Gazetted Officer only ?

Minister : It is upto the Deputy Commissioner to appoint any senior Officer to hold the enquiry. It is not essential that the Deputy Commissioner should himself hold the enquiry.

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस केस को प्राइमा फेसाई केस एस्टैबलिश होने पर इंक्वायरी के लिये भेजा था या सरकार ने इस केस को डिप्टी कमिश्नर को उस की डिसक्रीशन पे छोड़ दिया था कि वह जो भी मुनासिब समझे, वैसा ही ऐक्शन ले ?

मन्त्री : असिस्टैंट डायरैक्टर आफ पंचायतस, जालन्धर डिविजन ने इस केस की इंक्वायरी की। उस ने इस बारे में रिपोर्ट भी दी। डिप्टी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि उस पर मुनासिब ऐक्शन ले। यह भी कहा गया कि वह सारी चीज़ की जांच पड़ताल अच्छी तरह से करे और फौरन ऐक्शन ले।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस केस में डिप्टी कमिश्नर को कब हिदायत की और क्या उस ने कोई ऐक्शन लिया या नहीं : अगर उस ने कोई ऐक्शन नहीं लिया तो इस की क्या वजह है ?

Minister : Ordinarily it is expected of the Deputy Commissioner that if the case of mis-appropriation is established he should not wait for the Government instruction but should set the machinery of law into motion If any hon. Member wants to know what particular action has been taken in this particular case I will check up and let him know.

Comrade Ram Piara : Sir, my point was that when the headquarters sent the directive to the Deputy Commissioner whether a *prima facie* case was established by the headquarters or not.

Minister : Mr. Speaker, how can the Government sitting here in Chandigarh can make up its mind whether there is a *prima-facie* case or not ? But from the application and its contents it seemed that further enquiry was needed and the Deputy Commissioner was asked to look into it.

Comrade Ram Piara : Should we presume that the Deputy Commissioner has started the enquiry or it is yet to start ?

Minister : The enquiry has been completed and there is truth in the allegations. The Deputy Commissioner has been asked to take action according to law.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Education Minister if the Deputy Commissioner was asked to verify the enquiry conducted by the Assistant Director of Panchayats because the Government did not put any reliance on the report of the Assistant Director of Panchayats ?

Minister : The Deputy Commissioner was askea because he was the officer present at the headquarters and the place was nearabout. He was asked to look into the case himself or through his senior officers.

Sardar Gurnam Singh : Sir, may I know the result of the enquiry ? If it was a case of misappropriation, why was it not considered fit for registration ?

Minister : After the enquiry, it was established that he was guilty of mis-appropriation. Then the Deputy Commissioner was asked to take action according to law.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ 1964 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ?

मन्त्री : बिना इन्क्वायरी के कैसे ऐक्शन लिया जा सकता है ? मैं ने अर्ज़ किया है कि जेल डीपार्टमैंट के सीनियर अफसर की ड्यूटी लगा दी है कि मौके पर जा कर मालूम करे कि डैथ बाई प्वाएज़निंग हुई तो वह प्वाएज़न कैसे स्मगल हुआ। वह इन्कावायरी करेगा और जिस का कसूर होगा उस के सज़ा दी जाएगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ poisoning ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ?

मन्त्री : जब तक यह पता न लग जाए कि ज़हर जेल में कैसे स्मगल हुआ और किस अफसर का कसूर है उस वक्त तक कैसे ऐक्शन लिया जा सकता है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : I ask the Minister for Education as to when was the Deputy Commissioner asked to proceed in the matter according to law ?

Minister : Immediately after the findings, he was asked to take action in the matter according to law. But if the hon. Member is anxious to kn ow the date and time, I will let him know all the particulars.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the hon. Minister for Education as to what steps the Government propose to take against the Deputy Commissioner particularly because he has not so far proceeded for registration of the case although there is a *primafacie* case against him ?

Minister : Sir, there is nowhere mentioned either in the Question or in the reply that the Deputy Commissioner has been a defaulter so far as the performance of his duties is concerned. I have said that to avoid any criticism by the hon. members of the House, the Government said that the Deputy Commissioner should look into the case either himself or through his senior officers before the registration of the case.

Death of one Shri Gurdip Singh in Bhatinda Jail in 1964-65

***9492, Comrade Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

a) whether it is a fact that one Shri Gurdip Singh died in Bhatinda Jail during the year 1964-65 ;

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, whether any enquiry was held to find out the causes of the said death, if so, by whom and with what result ;

(c) whether some people of District Bhatinda sent a representation to the Government to hold an enquiry with regard to the said death, if so, when and the action, if any, taken thereon?

Shri Chand Ram : (a) Yes, on 17th August, 1964.

(b) Yes, by the Executive Magistrate, Bhatinda who held that the death in this case had occurred by accident, the cause of death being chloral-hydrate poisoning.

(c) Yes. Government have ordered a departmental enquiry to be made by a Senior Officer of the Jail Department against the officials of the District Jail, Bhatinda, with a view to finding out how the poison was smuggled into the Jail.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the hon. Minister for Welfare and Justice to let the House know as to how long will the Government take for matters of such a serious nature to finalize ?

मन्त्री : जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ $1\frac{1}{2}$ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ?

मन्त्री : जो केस के फैक्टस हैं वह तो आप को बता दिए गए हैं। मैं भी महसूस करता हूं कि काफी देर हो गई है। मैं मालूम करूंगा कि क्यों इतनी देर लगी है, जल्दी से जल्दी ऐक्शन लिया जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਿਕਾਇਤ ਜੇਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

मन्त्री : पहले यह इन्क्वायरी बठिंडे के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट की हिदायत के मुताबिक वहां एग्ज़ैक्टिव मैजिस्ट्रेट ने की था। उस में साबित हुआ कि डैथ जहर देने से हुई है। इस बात का पता लगाने के लिये कि कौन अफसर एट फाल्ट हैं जेल डीपार्टमैंट के सीनियर अफसर के ज़िम्मे यह काम लगाया गया है। अगर उस की रिपोर्ट से तसल्ली न हुई तो किसी और अफसर को यह काम दिया जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कब तक इन्क्वायरी शुरू हो जाएगी और कब तक फाईनल ऐक्शन लिया जाएगा ?

मन्त्री : आर्डज़ तो पहले हो चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : लेकिन इन्क्वायरी शुरू कब तक होगी ?

Minister : Sir, I am sorry, I have not got this information. But I presume that the enquiry must be going on.

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह ट्रेजिडी कब हुई, इन्क्वायरी के आर्डेज़ कब हुए, कब वह कम्पलीट हुई और उस की रौशनी में किस को कौनसी सज़ा दी गई और अगर सज़ा नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई ?

मन्त्री : इस सारी इन्फर्मेशन के लिये नोटिस चाहिए। जब यह वाक्या हुआ तो इन्क्वायरी का आर्डर कर दिया गया था। जब उस की रिपोर्ट आई तो हम ने आर्डर दिया कि जेल डिपार्टमेंट का सीनियर अफसर जाए और जो आदमी एट फाल्ट है उस के खिलाफ ऐक्शन ले।

कंवर राम पाल सिंह : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि डैथ प्वाएज़निंग से हुई। अगर डैथ प्वाएज़निंग से हुई थी तो क्या उस का पोस्टमार्टिम नहीं करवाया गया, अगर करवाया गया तो क्या पोस्टमार्टिम की यह रिपोर्ट नहीं थी कि मौत ज़हर के कारण हुई थी ?

Minister : On the representation of the father of the deceased, the Deputy Commissioner, Bhatinda, ordered the *post-mortem* to be conducted at Chandigarh by the Chief Medical Officer. और मालूम हुआ कि डैथ प्वाएजिंग से हुई।

श्री बलारमजी दास टंडन : इस वाक्या को हुए डेढ़ साल का अर्सा हो गया है लेकिन अभी तक इस का पता नहीं लग सका। क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह इनफर्मेशन हाउस को कब तक दी जाएगी कि यह केस अनट्रेसेबल हो गया है ?

मन्त्री : मैं ने अर्ज़ की है कि जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। यह इन्क्वायरी की जा रही है कि जेल के अन्दर ज़हर कैसे स्मगल हुआ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the hon. Minister for Welfare and Justice to explain or let this House know if any enquiry was also instituted against the Medical Officer who conducted the *post-mortem* Examination and did not give the certificate to the effect that arsenic has been administered to him ?

मन्त्री : अगर आप नोटिस देंगे तो पता कर के बता दिया जाएगा।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਵੀਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ?

मन्त्री : डिटेल्ड इनफर्मेशन मेरे सामने नहीं है। जो सवाल पूछा गया था उस का जवाब दे दिया गया है। अगर कोई ऐसी बात नोटिस में लाई जाए तो हम उस की भी इन्क्वायरी करवाने के लिये तैयार हैं।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब बठिंडे का सी.एम.ओ. भी था तो चंडीगढ़ के सी.एम.ओ.से पोस्टमार्टिम करवाने का क्या कारण था ?

मन्त्री : चूंकि उस के फादर ने रिक्वैस्ट की थी कि वहां से हमारी तसल्ली नहीं होगी इस लिये यहां पर करवाया जाए। गवर्नमैंट ने इस बात को अवायड करने की कोशिश नहीं की। जैसे उन्हों ने कहा वैसे ही करवा दिया। अब इस बात की तफ्तीश करवाई जा रही है कि जेल के अंदर ज़हर कैसे स्मगल किया गया। इन्क्वायरी के बाद जो आदमी ज़िम्मेदार होगा उस को सज़ा दी जाएगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Hon. Minister as to when the enquiry by the Executive Magistrate was finalized and a report submitted to the Government ?

मन्त्री : असल में डेट्स तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। इसके बारे में नोटिस दें तो पूरी डिटेल्ज़ पता करके बता सकूंगा।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I request you, Sir, to postpone the supplementaries on the Question, because it is a case of a very serious nature and also ask the Minister concerned to come prepared with all the necessary information ?

Mr. Speaker : Further supplementaries are postponed, but the Honourable Member may please send all his possible Questions to the Minister.

Pandit Chiranji Lal Sharma : They should be anticipated by the Honourable Minister.

Mr. Speaker : If the Honourable Member wants proper information he should send him the questions and need not put the Minister on trial.

मन्त्री : स्पीकर साहिब, इसी वक्त मैं यह सारी इत्तलाह कैसे दे सकता हूं। इस के लिए तो स्पैसेफिक सवाल करें, मैं पता करके बता दूंगा।

Mr. Speaker : The question is that the replies are not being properly given. I know many things about this case, but I would not like to say any thing about it.

Use of Cotton Waste as Fertilizer

***8857. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether Government has taken any steps to persuade the people to use cotton as a fertilizer, if so, with what result ?

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) : Part (a) No.

Part (b) : The question does not arise.

चौधरी बालू राम : क्या वजीर साहिब यह बताएंगे कि उन्हों ने डिपार्टमैंट से कभी इस बात का एग्ज़ामिनेशन करवाया है कि यह cotton waste बतौर फर्टेलाइजर इस्तेमाल में लाई जा सकती है या नहीं ?

राज्य मन्त्री : साइंटिस्टस से इस बात को एग्जामिन करवाया गया था। उन्हों ने बताया है कि कपास का वेस्ट खाद के लिये फायदेमन्द नहीं, बल्कि नुक्सानदेह साबित होगा।

Effect of drought on the production in the State

***8858. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the effect of drought on the prouction of both Rabi and Kharif crops in the State, district-wise during 1965-66 together with the steps so far taken to mitigate the misery of the cultivators thus affected ?

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) : The figures regarding effect of drought on the production of Kharif and Rabi crops are being collected and are not yet available.

Following steps have been taken to face this situation :—

1. Sufficient additional funds were placed at the disposal of the State Electricity Board so as to energize 11,000 tubewells/pumping sets against about 6,800 during the last year.

[Minister of State for Animal Husbandry]

2. The Samitis were permitted to purchase mobile pumping sets for hiring out the same to the cultivators for lifting water from the ponds, drains/bein and also such tubewells/pumping sets which were awaiting energization.
3. The State tubewells are being run to their maximum capacity.
4. Instructions were issued to the field staff to approach private tubewell owners to sell water to their neighbours if they needed it. The general impression got from the field staff is that the farmers, in general, have supplied water to the needy cultivator at rates mutually decided.
5. An additional sum of Rs 60 lakhs was advanced to the cultivator as loan for sinking open-wells/pumping sets/tubewells.
6. Because of the shortage of electricity material etc. a large number of tubewells are awaiting connections. In order to encourage the cultivators to install diesel engines for lifting water, concession of Rs 750 per engine was continued during the year.
7. Efforts are being made to purchase diesel engines through the State Co-operative Marketing Federation for sale to the cultivators at no profit no loss basis. Officer on Special Duty (Minor Irrigation) and Joint Secretary, State Marketing Federation have already been deputed to Delhi for this purpose.

चौधरी बालू राम : क्या राज्य मन्त्री साहिब यह बताएंगे कि जो फैसिलिटीज़ एनाऊंस की गई हैं उन में से कितनी परसैन्टेज यानी कितनी फैसिलिटीज़ एक्चुअली किसानों तक पहुंच पाई हैं ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7,50 ਰੁਪੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰਲੀ ਕਿਸਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 11,000 ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

डाक्टर बाल कृष्ण : क्या जिन लोगों ने नकद पैसे लगाए हैं, उनको भी यह सबसिडी मिलती है ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, in reply to the question, the hon. Minister was pleased to state that the State Electricity Board follows the

policy of the Government. There was a specific allegation or some sort of a complaint in the shape of supplementary in this connection. In view of it, I would like to know whether it has come to the notice of the Government that officers of the State Electricity Board, do not comply with the directions issued by the Government and tubewells are not being energised as desired by the Government ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : Government does not order the officers of the Electricity Board. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11,000 ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ । ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇੰਜਨ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਉ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉ । ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ।

श्री ओम प्रकाश अग्नीहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो 7,50 रुपए की गरांट है वह लोन वालों को ही मिलेगी या जिसने अपने पास से रुपया लगाया या लगाएगा उसको भी मिलेगी ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਖਾਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਂਅਦ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ।

श्री ओम प्रकाश अग्नीहोत्री : क्या वह बताएंगे कि वह 'खास डेट कौन सी है ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : Off hand I cannot remember the date but it is somewhere in August or September, 1964. ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਦ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੋ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਉ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 1964 ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੇਸਪਾਂਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਥੇ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਮਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no point of order.

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਇੰਜਨ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ 750 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਸਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਸਪਾਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2,200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਮਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਊਬਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ?

ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300 ਇੰਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਐਸ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਅਛੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਹੋਣ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, not more than that.

श्री फतेह चन्द विज: स्टेट मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 1964 के साल में कोई तारीख थी जिस के बाद अगर कोई पंपिंग सैट लगाएगा उसे सरकार ने सबसिडी देने का फैसला किया था। इस के साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि यह सबसिडी उसे दी जाएगी जो एक साल तक अपने सैट को चलाता रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त तक कितने किसानों को यह सबसिडी दी जा चुकी है ?

पशु पालन तथा कृषि राज्य मंत्री: इस के लिये सैपरेट नोटिस दें।

पंडित मोहन लाल दत्त: क्या राज्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी इलाकों में जहां टयूबवैलों के इलावा सिचाई के और कोई साधन नहीं हो सकते, वहां पर हार्ड ग्राउंड में ट्यूबवैल्ज़ बोर कराने के लिये गवर्नमैंट ने कोई रिग हासिल करने का प्रबन्ध किया है ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ: ਰਿਗ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

चौधरी बानू राम : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो सबसिडी देने का गवर्नमैंट ने फैसला किया हुआ है, क्या यह सबसिडी सिर्फ उन्हीं इंजनों के लिये दी जाएगी जो गवर्नमैंट की मारफत खरीद किए जाएंगे या उन के लिये भी दी जाएगी जो प्राईवेट तौर पर खरीद कर के लगाएंगे ?

राज्य मंत्री : सबसिडी सब को देंगे ।

Co-operative Milk Supply Societies registered by Assistant Registrar. Co-operative Societies, Moga, district Ferozepur

*9494. **Comrade Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total number of Cooperative Milk Supply Societies registered by the Assistant Registrar, Cooperative Societies, Moga, district Ferozepore, during the period from 1st January, 1965 to 31st January, 1966 together with their names, addresses, dates of registration and submission of applications for registration and the number of their members ;

(b) whether there are any Societies in whose cases either the registration was refused by the said Assistant Registrar during the period referred to in part (a) above or whose files are still lying pending with him, if so, their names, addresses, the dates of submission of applications for registration and rejection etc., together with the reasons for rejection in each case ?

Chaudhri Rizaq Ram : Requisite information is laid on the Table of the House.

Information regarding Cooperative Milk Supply Societies registered by the Assistant Registarar, Co-operative Societies, Moga, district Ferozpore

(a) Requisite information is as under:—

Serial No.	Name of the Society with full address	Date of submission of application for registration	Number of members	Date of registration
1	Charik Co-operative Milk Supply Society Ltd., tehsil Moga, district Ferozepur	11-1-65	15	6-2-65
2	Singhanwala Co-opertive Harijan Milk Supply Society Ltd., tehsil Moga, district Ferozepur ..	21-4-65	27	29-6-65
3	Rammowala Harchoke Cooperative Milk Supply Society Ltd, tehsil Moga, district Ferozepur ..	17-5-65	14	16-8-65
4	Bir Badhni Cooperative Milk Supply Society Ltd., tehsil Moga, district Ferozepur ..	22-1-65	25	25-8-65

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of the Society with full address	Date of submission of application for registration	Number of members	Date of registration
5	Chuharchak Co-operative Milk Supply Society Ltd, tehsil Moga, district Ferozepur ..	1-9-65	35	28-9-65
6	Khote Co-operative Milk Supply Society Ltd., tehsil Moga, district Ferozepur	7-9-65	11	7-12-65
7	Raoke Kalan Harijan Co-operative Milk Supply Society Ltd, tehsil Moga, district Ferozepur ..	3-5-65	28	31-1-66

(b) Registration of no society was refused by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Moga,. However, the papers of the following three societies were also received before 31st January, 1966:—

Serial No.	Name of the Society with full address		Date of submission of applications
1	The Khote Jadid Co-operative Milk Society Ltd., tehsil Moga, district Ferozepur	..	5-5-65
2	The Janta Didarewala Co-operative Milk Supply Society Ltd., tehsil Moga, district Ferozepur	..	25-10-65
3	Soodan Co-operative Milk Supply Society Ltd., post office Makhu, tehsil Zira, district Ferozepur	..	19-1-66

The Societies at Serial numbers 1 and 2 were registered on 4th February, 1966. Papers of society at Serial No. 3, which were received on 19th January, 1966, are under examination with the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Moga. This case will also be disposed of soon.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Water Stand Post in village Mawa Kaholan, tehsil Una, district Hoshiarpur

3238. Pandit Mohan Lal Datta : Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) whether the Chief Engineer, P.W.D., Public Health Branch received the proceedings of the meeting of the Sanitary Board, Punjab, held on 13th December, 1965 ;

(b) whether the said Chief Engineer obtained the sanction from the Government for starting the works as recommended by the said Board in the said meeting ; if so, when ;

(c) the date when the work for installing the water stand post is likely to be started and completed in village Mawa Kaholan, in tehsil Una, district Hoshiarpur as recommended in the said meeting ?

Shrimati Om Prabha Jain : (a) Yes.

(b) The Chief Engineer, Punjab, P.W.D., Public Health Branch, Patiala, was not required to obtain the sanction from the Government. Secretary Sanitary Board is taking action in this behalf.

(c) The execution of the work will be arranged by the P.W.D., Public Health Branch if and when the funds are made available and the scheme cleared technically by the Central Public Health Engineering Organisation.

Cattle Pound in village Malikpur Kumbowan, tehsil and district Patiala

3241. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state whether he or the Secretary Local Government received in December, 1965, any application forwarded by the Deputy Commissioner, Patiala, or the Revenue Commissioner, for the final sanction of a Cattle Pound in village Malikpur Kumbowan, post office Harrana, tehsil and district Patiala, if so the action so far taken by the Government thereon ; if no action has been taken, the reasons therefor ?

Sardar Ajmer Singh : A proposal was received from the Commissioner Patiala Division, regarding setting up a cattle pound in village Malakpur, police station Julkan, district Patiala and for the appointment of a Pound-Keeper, for Government's sanction. The matter lies within the competency of the district Magistrate. The Commissioner, Patiala Division and the Deputy Commissioner Patiala, have since been informed accordingly.

Construction of Narwana-Tohana Road

3271. Shri Fakiria : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the road from Narwana to Tohana is proposed to be constructed during the Fourth Plan period ?

Chaudhri Ranbir Singh : No please. However, it can be taken up under Village Road Co-operative Scheme, provided the beneficiaries pay their share.

Medical treatment to Communist Detenus

3272. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

(a) the names of the Communist detenus and of the Jails in which they are detained at present, separately ;

(b) the names of the detenus out of those referred to in part (a) above who are ill, the details of their ailments and the details of the medical treatment/medicines being given to each of them ?

Shri Chand Ram : (a) & (b) A statement giving the requisite information is attached at Appendices 'A' & 'B'.

APPENDIX 'A'

Names of the Communist detenus and of the jails in which they are detained at present

(a) 1. Central Jail, Patiala	1 Shri Chattar Singh
	2 Shri Hardit Singh Bhathal

[Minister for Welfare and Justice]

	3 Shri Harnam Singh Chamak
	4 Shri Ram Kishan Bharolian
	5 Shri Gurcharan Singh
	6 Shri Gurbux Singh Atta
	7 Shri Sulakhan Singh
	8 Shri Makhan Singh Tarsikka (On parole)
2 District Jail, Nabha	9 Shri Vidya Dev
	10 Shri Gajjan Singh Tandian
	11 Shri Raghbir Singh Jhakkar
	12 Shri Rachhpal Singh
	13 Shri Dhanpat Rai Nahar
	14 Shri Gandharv Sen
	15 Shri Partap Singh Dhanaula
	16 Shri Balbir Singh
	17 Shri Ram Singh
	18 Shri Satwant Singh
	19 Shri Bhag Singh
	20 Shri Janak Singh Bhathal
	21 Shri Hazara Singh Jassar
	22 Shri Dharam Singh
	23 Shri Udhe Singh Keshav
	24 Shri Ghuman Singh
	25 Shri Mehar Singh
	26 Shri Ganda Singh
	27 Shri Gurnam Singh
3 Central Jail, Hissar	28 Shri Kishori Lal
	29 Shri Prem Chand Bhardwaj
	30 Shri Dharam Singh Kasni
	31 Shri Hazur Singh
	32 Shri K.R. Palta
	33 Shri Amarmeet Singh
	34 Shri Isher Singh Sodhi
	35 Shri Karnail Singh
	36 Shri Kartar Singh
	37 Shri Ganpat Singh

		38	Shri Devki Nandan
		39	Shri Bhim Singh
		40	Shri Dalip Singh
4	District Jail, Sangrur	41	Shri Chanan Singh Dhut
		42	Shri Rachpal Singh
		43	Shri Fauja Singh Bhullar
		44	Shri Satya Mandan
		45	Shri Chanan Singh Brar
		46	Shri Dalip Singh Tapiala
		47	Shri Gian Singh Pleader
		48	Shri Darshan Singh Jhabal
		49	Shri Gurbux Singh, Dakota
		50	Shri Mange Ram Vats
		51	Shri Bhag Singh Sajjon
		52	Shri Daya Singh Prem
		53	Shri Mangal Singh
		54	Shri Bakhshi Ram
		55	Shri Sarwan Singh Cheema
		56	Shri Bishan Singh
		57	Shri Bhajan Singh
5	Central Jail, Delhi	58	Shri Harkishan Singh Surjeet
6	District Jail, Amritsar	59	Shri Kesar Singh

APPENDIX 'B'

Names of the detenus who are ill and the details of their ailments, and the details of the medical treatment/medicines being given to each of them

Name of detenu	Details of ailments	Details of medical treatment/ medicines given to the detenus
(b) 1. Shri H.S. Bhathal	Osteoarthiritis Knees	He has been examined by the Specialist of the Rajindra Hospital, Patiala and necessary treatment is being given to him as advised
2 Makhan Singh Tarsikka	Hiatus hernia	He was examined by the Medical Specialist of Rajindra Hospital, Patiala and is being given necessary treatment as advised He is at present on parole.

[Minister for Welfare and Justice]

	Name of detenu	Details of ailments	Details of Medical treatment/ medicines given to the detenus
3	Shri Sulakhan Singh	Dental trouble	His old denture and spectacles have been replaced by new one
4	Shri Ram Kishan Bharolian	..	His old denture and spectacles have been replaced by new one
5	Shri Gurcharan Singh	Pain in back and knees	He was examined by the Specialist and is being given treatment as advised
6	Shri Gurbux Singh Atta	Hypertension and Ischaemic heart and Nassal polypur, and allergic rhinitis.	He is under the treatment of Medical Specialist of Rajindra Hospital, Patiala
7	Shri Harnam Singh Chamak	Diabetes and Ischoemic heart	Ditto
8	Shri Satwant Singh	Old Injury knee, Arthritis. Dental trouble	He is being given the following treatment Linament Terribinthinae application. Elkosine tab. Tab. Novalgin. Inj. Vit. B.1. Referred to Civil Hospital Nabha for treatment
9	Shri Dharam Singh	Acute Conjunctivities Insomnia. Absence of teeth	Terramycine Eye Ointment Achromycin in oil eye drops Tab. Equinanil. Recommended for denture
10	Dr. Bhag Singh	Enlarged prostrate. Corn	Tab. Stilbisterol Alkosol. Advised operation. No. 20 Oz. 1 T.D.S. Acidacitic For Application Cornik
11	Shri Dhanpat Rai Nahar	Piles. Defective vision	Ung. Galic Mopio Liquid parafin. Inj. Streptopencilin. Tab. Vit. B. Complex. Nepercainol. He is being sent to Rajindra Hospital, Patiala, for examination by the Specialist for defective vision
12	Partap Singh Dhanaula	Dermatitis. Presbopia	Ung. Derm Oquinal. Tab. B. Complex. Tab. Aspirin. Cap. Chloromycetin. Tab. Novalgin. He has been supplied with glasses.
13	Balbir Singh ..	Presbopia ..	Glasses have been provided
14	Janak Singh ..	Bachache. Dental trouble and acute Bronchitis	He has been recommended Diathermy for 15 days and is to be examined by the Dental Surgeon, Nabha. He is being given No. 14

	Name of detenu	Details of ailments	Details of Medical treatment/ medicines given to the detenus
15	Ghuman Singh	Dermatitits. Presbopia. Absence of teeth	Ung. Betnovit. Demoquirol Ung. Tarsalon. Ung. Zinc. Boric Tab. Prednialone. Tab. Dilosyin. Glasses have been supplied. Referred to Skin Specialist of Rajindra Hospital, Patiala, and has been recommended for denture at the same Hospital
16	Vidya Dev Longowal	I.V .P.D. and Peptic Ulcer. Acute Conjuctivitis	Hard Bed. Tab. Gelusil Nutrodone. Tab. Fersolate. Referred to Medical Spl. of Rajindra Hospital for investigation. Terramycine Eye Ointment. Achromycin in oil eye drops
17	Gandharv Sen ..	Dental trouble and defective vision	Scaling and Gum treatment. To be examined by the Eye Specialist of the Rajindra Hospital, Patiala
18	Ram Singh ..	Hypertension. Elergium. Dermetatis and Piles	Tab. Surpina. Inj. P. Penciline. Admitted in Rajindra Hospital, for treatment. Ung. Detonovit. Ung. Nuprecanal
19	Rachhpal Singh	Defective vision	Referred to the Eye Specialist of Rajindra Hospital, Patiala
20	Raghbir Singh	Backach. Ch. Constipation. Neuralgia. G. Debality	Tab. Butacort. Tab. Vitamin B.Z. Tab. Vitamin B. Complex. Enos. Fruit Salt. Tab. Sarodon
21	Hazara Singh Jassar	G. Debality ..	Tab. Vit. B. Complex. Tab. Multa-Vitamin
22	Udey Singh ..	Dyspepsia ..	Tab. Vit. B. Complex
23	Mehar Singh ..	Dyspepsia. Defective vision. Multiplecarries	Becasules. Recommended glasses. Referred to Rajindra Hospital, Patiala for treatment
24	Gurnam Singh ..	Dyspepsia. Croyza. Dental trouble	Becasules. Tab. Medribon. Referred to Rajindra Hospital Patiala, for dental treatment Scaling and Polishing
25	Ganda Singh ..	Gingivitis ..	Referred to Rajindra Hospital, Patiala, for gum treatment
26	Kesar Singh ..	Mental patient ...	He is under the treatment of Dr. Vidya Sagar in the Punjab Mental Hospital

[Minister for Welfare and Justice]

	Name of detenu	Details of ailments	Details of Medical treatment/ medicines given to the detenus
27	Dalip Singh Tapiala	Ch. Ambosis. Teeth	He is being treated by the Jail Medical Officer. The artificial grinders are being arranged from Rajindra Hospital, Patiala
28	Rachhpal Singh	Ch. Conjunctivitis. Vision	He is under the treatment of Jail Medical Officer. Already using spectacles. Applied for change which is being arranged through the specialist
29	Shri Bakhshi Ram	External Piles ..	He is under the treatment of the Jail Medical Officer
30	Fauja Singh Bhullar	Post. Inf. Hapatitis. Vision	Tab. Predinisolone course. Vitazyme Elixir. Being referred to Rajindra Hospital, Patiala, for further investigation. Requests for change of glasses which are being arranged through the local specialist.
31	Satya Mandan	Ch. Dermatitis ..	He is under the treatment of Jail Medical Officer
32	Gian Singh ..	Ch. Para-nasal Sinusitis	He is under the treatment of Jail Medical Officer and is being transferred to E.N.T. Specialist of Rajindra Hospital, Patiala
33	Shri Bhag Singh Sajjon	Ch. Stomititis ..	He is under the treatment of Jail Medical Officer
34	Darshan Singh	Brochial Neuralagia, Pyrroic teeth	He is under the treatment of Jail Medical Officer and Dental Surgeon. He is being provided with artificial denture
35	Shri Gurbux Singh Dakota	Miled Ch. Sarcral. Neuralagia	He is under the treatment of Jail Medical Officer
36	Shri Mange Ram Vats	Ch. Dermatitis Hard of hearing	He is under the treatment of Jail M.O. Case for provision of hearing aid is under consideration
37	Shri Daya Singh Prem	Ch. Glaucoma. (operated) Gum immatura-senile Cataract	He is under the treatment of Eye Specialist
38	Sarwan Singh Cheema	Ch. Ambosis	He is under the treatment of Jail Medical Officer
39	Shri Bhajan Singh	Ch. Conjunctivitis	Ditto
40	Shri Chanan Singh Brar	Ch. Dermatitis	Ditto
41	Shri Bishan Singh	Ch. Ambosis	Ditto

	Name of detenu	Detail of ailments	Details of Medical treatment/ medicines given to the detenus
42	Shri Prem Chand Bhardwaj	Neurits	He is being given treatment locally
43	Shri Hazur Singh	Leucoma Crote Opacity Eye. C. Refrecation	Treated in the Medical College Rohtak by the Specialist and Glasses have been provided
44	Shri K.R. Palta	Old Injury Rt. Ankle joint	Local treatment. Specialist treatment at Hissar-X-Ray.
45	Pt. Kishori Lal	Ch. Bronchitis. Br. Asthama. Loose artifi cial denture	Local treatment. Case for Specialist treatment in the Rajindra Hospital, Patiala is under consideration.
46	Kartar Singh Gujapeer	P.M.	Local treatment
47	Shri Ishar Singh Sodhi	Refrection Check. U Ventral Hernia	Treated in the Medical College Hospital, Rohtak. Glasses have been provided to him.
48	Shri Bhim Singh	Coryza	He is under treatment of the Jail Medical Officer
49	Shri Ganpat Singh	Debility. C. Anemia and Referaction	He is under treatment of the Jail Medical Officer
50	Shri Karnail Singh	Devalaid septum C. Ch. Sinusitis	He is being referred to E.N.T. Specialist
51	Shri Harkishan Singh Surjeet	Gastric Acidity. Osteo Arthritis Spine. Tracho ma as per record shown by him Inter-proximal Carics	For Trachoma and weakness of eyes he has been provided with glasses. His case for Osteo Arthriits and Dental Troubles for which he requires a Radiological treatment in Irwin Hospital is under consideration

Bicycles purchased by the Police at Patiala

*3273. **Comrade Hardit Singh Bhathal** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number of bicycles purchased by the Patiala Police during the years 1965 and 1966 ;

(b) the name of the officer by whom and of the firm from which the said cycles were purchased and the price paid per cycle together with their total value ;

(c) whether the said cycles are still lying in the store or are in use ; if the said cycles are in use, the names of the persons to whom they have been issued ;

(d) whether any of the cycles referred to in part (a) above are in personal use at the residence of the officer or officers to whom these have been allotted ?

Sardar Darbara Singh : (a) During 1965 183 cycles.
During 1966 .—Nil.
(b) By I.G. Police.

	Rs	
20 cycles against Rate Contract entered into by the Controller of Stores, Punjab, with M/s Aden Cycles of India, Ludhiana at Rs 145 each .	2,988·00	including Sales Tax
163 cycles through Controller of Stores Punjab as under :—		
100 cycles from M/s Roadmaster Industries of India (P) Ltd., Rajpura at Rs 139.24P. each ..	14,202·00	Ditto
25 Cycles from M/S Parbhat Cycles, Ludhiana at Rs 139 .75 each ..	3,493·75	Ditto
20 Cycles from M/S Aden Cycles of India, Ludhiana at Rs 144 each ..	2,880·00	Ditto
18 Cycles from M/s Lucky Star Co., Ludhiana at Rs 139.75 each ..	2,505·50	Ditto
Grand total ..	26,069·73	

(c) Cycles in store ..	150
Cycles in use	
Kotwali Patiala ..	13
P.S. Rajpura ..	5
P.S. Sirhind ..	3
P.S. Sadar Patiala ..	3
P.S. Civil Lines ..	5
Orderly to S.P. ..	1
Orderly to D.S.P./Headquarter ..	1
Orderly reserve Inspector ..	1
Orderly to District Inspector (I) ..	1

(d) Nil.

Release of Communist Detenus on Parole

3274. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the number and names of the Communist Detenus who applied for being released on parole during the period from 1st January 1965 to date ;

(b) the names of the detenus out of those referred to in part (a) above whose applications were accepted and of those whose applications were rejected together with the reasons for the rejection ;

(c) the period for which parole was granted to each of the detenus whose applications were accepted ;

(d) the dates on which the said applications were submitted and on which parole was sanctioned and the dates on which sanctions were conveyed to the detenus concerned together with the period for which parole was asked in each case ;

(e) whether it is a fact that the detenus being released on parole are also asked to furnish sureties, if so, to what extent ;

(f) the names of the detenus who were asked to furnish sureties giving the details thereof in each case ;

(g) the number of the detenus out of those referred to in part (f) above who made arrangements for sureties and were released on parole and of those who failed to make such arrangements ;

(h) whether it is a fact that the detenus submitted any protest note, to the Government about the manner in which parole is granted if so, a copy thereof alongwith a copy of the reply sent thereto be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh Home and Development Minister) : (a) 46. Statement enclosed.

(b) 18 accepted out of which 4 could not avail of the concession as they could not furnish sureties. 20 were rejected and 8 are under consideration. Details are given in the enclosed statement.

(c) & (d) Details given in the enclosed statement.

(e) Yes. Two sureties of Rs 10,000 in each case and also a personal bond in the like sum except in the case of Sarvshri Makhan Singh Tarsikkar M.L.A. and Satya Mandan, who were asked to furnish two sureties of Rs 20,000 each and personal bond for the same amount and Balbir Singh and Gajjan Sihgn, who were asked to furnish sureties of Rs 5,000 each.

(f) & (g) Statement giving details is enclosed.

(h) Yes. A copy of the protest note is enclosed (Annexxure A). The protest note is still under consideration.

[Home and Development Minister]

Details asked for in paras

Serial No.	Names of the detenus	Accepted	Rejected	Reasons for rejection	Period for which parole was granted
1	2	3	4	5	6
1	Makhan Singh Tarsikka	1	..	..	2½months
2	Makhan Singh Tarsikka	1	..	..	3 months
3	Vidya Dev Longowal	1	..	..	7 days
4	Gian Singh ..	1	..	..	15 days
5	Gian Singh ..	1	..	..	2 days
6	Bhajan Singh ..	..	1	Wife not ill	..
7	Bhajan Singh ..	..	1	Ditto	..
8	Bhajan Singh	1	..	..	1 week
9	Bhajan Singh ..	..	1	Could perform condolence rites during previous parole	..
10	Dalip Singh ..	1	..	..	7 days
11	Harkishan Singh Surjeet	1	..	..	5 days
12	Chanan Singh ..	1	..	..	..
13	Chanan Singh ..	1	..	..	20 days
14	Rachhpal Singh ..	..	1	Being under detention not able to perform the duties of Chairman M.C.	..
15	Kartar Singh ..	..	1	Wife not ill	..
16	Kartar Singh	1	..	..	3 days
17	Kartar Singh ..		1	Could perform condolence rites during previous parole	..
18	Kartar Singh	..	..	Under consideration	
19	Prem Chand Bhardwaj ..	..	1	Anti-National activities	..
20	Satya Mandan	..	1	Wife not ill	..
21	Satya Mandan ..	..	1	Ditto	..
22	Satya Mandan ..	..	1	Ditto	..
23	Satya Mandan ..	..	1	Ditto	..

(a), (b), (c) and (d)

Date on which					
Application received	Parole granted	Sanction conveyed	Rejection conveyed	Period of parole applied for	REMARKS
7	8	9	10	11	12
14-8-65	1-10-65	1-10-65	..	3 months	
7-1-66	15-2-66	15-2-66	..	Do	
17-12-65	13-1-65	13-1-66	..	7 days	Did not avail
30-12-65	31-12-65	31-12-65	..	1 month	
12-1-66	19-1-66	19-1-66	..	1 month	Did not avail
12-12-65	..	..	29-8-65	1 month	
12-11-65	..	..	16-12-65	1 month	
24-12-65	7-1-66	7-1-66	..	1 week	
28-1-66	..	..	10-2-66	1 month	
20-1-66	22-1-66	22-1-66	..	7 days	Did not avail
2-1-66	22-1-66	22-1-66	..	10 days	
20-9-65 20-1-66	22-1-66	22-1-66	..	1 month	Date of marriage asked for
5-1-66	..	..	22-1-66	1 week	
3-8-65	..	..	16-9-65	1 month	
27-1-66	4-2-66	4-2-66	..	20 days	
5-2-66	..	..	25-2-66	3 days	
1-3-66	..	..		1 month	
1-2-66	..	..	4-3-66	10 days	
8-2-65	..	..	12-3-65	Some time	
16-3-65	..	..	20-3-65	Ditto	
1-11-65	..	..	17-1-66	Ditto	
1-11-66	..	..	17-1-66	Ditto	

Serial No.	Names of the detenus	Accepted	Rejected	Reasons for rejection	Period for which parole was granted
1	2	3	4	5	6
24	Satya Mandan ..	1	..	..	7 days
25	Gurbax Singh Atta	..	1	Best medical aid available in Rajindra Hospital, Patiala	..
26	Gurbax Singh Atta	..	1	Marrigare not of a near relative	..
27	Gurdev Singh ..	..		Under consideration	..
28	Darshan Singh ..	..		Ditto	..
29	Mangal Singh ..	..		Ditto	..
30	Gurnam Singh ..	..		Ditto	..
31	Kishori Lal ..	..	1	Application received after the cremation of Shri B.K. Dutt	
32	Chattar Singh ..	1	..	..	1 day
33	Sulakhan Singh	1	..	..	3 days
34	Sarwan Singh ..	1	..	..	1 week
35	Gajjan Singh ..	1	..	..	8 days
36	Mehar Singh ..	1	..	..	10 days
37	Balbir Singh ..	..	1	Marriage not of a near relative	
38	Balbir Singh ..	1	..	..	1 week
39	Balbir Singh ..	..	1	Sanction not granted	..
40	Chattar Singh ..	..	1	Treated in Hospital	
41	Satwant Singh ..	..	1	Undersirable activities	
42	Kesar Singh ..	..	..	Under consideration	
43	Dhanpat Rai ..	..	1	His release will aggr avate the situation rather than ease it	..
44	Daya Singh ..	..	..	Under consideration	
45	Bhag Singh ..	..	1	Information incorrect	
46	Bishan Singh ..	..	..	Under consideration	
		18	20	8 under consideration	

Date on which				Period of parole applied for	REMARKS
Application received	Parole granted	Sanction conveyed	Rejection conveyed		
7	8	9	10	11	12
28-1-66	21-2-66	21-2-66	..	1 month	
28-7-65	..	..	14-9-65	3 months	
13-1-66 15-2-66	..	..	16-2-66	2 weeks	
19-2-66	..	..	..	1 week	
23-2-66	..	..	..	1 Month	
14-2-66	..	..	..	1 week	
24-2-66	..	..	..	25 days	
19-7-65	..	..	23-8-65	1 week	
17-4-65	19-4-65	19-4-65	..	Not given	
14-1-66	4-2-66	4-2-66	..	21 days	Did not avail
8-11-65	..	..	..	1 week	Sanction received late
20-2-65	6-4-65	6-4-65	..	Not given	
5-11-65	5-11-65	5-11-65	..	1 month	
7-6-65	..	..	25-6-65	6 days	
18-8-65	25-8-65	25-8-65	..	8 days	
30-8-65	..	..	30-8-65	4 days	
4-12-65	..	..	21-12-65	..	
2-6-65	..	..	28-7-65	Not given	
15-11-65	..	..	..	Long period	
11-1-66	..	..	1-2-66	1 month	
15-11-65	..	..	..	1 month	
9-6-65	..	..	17-7-65	2 months	
2-3-66	..	..	..	15 days	

Details asked for in Paras (f) and (g)

Serial No.	Names of persons asked to furnish sureties	REMARKS
1	2	3
1	Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.	Produced sureties and were released on parole
2	Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.	
3	Shri Gian Singh	
4	Shri Bhajan Singh	
5	Shri Harkishan Singh Surjit	
6	Shri Chanan Singh	
7	Shri Kartar Singh	
8	Shri Satya Mandan	
9	Shri Chattar Singh	
10	Shri Gajjan Singh	
11	Shri Mehar Singh	
12	Shri Balbir Singh	
13	Shri Chanan Singh	
14	Shri Sarwan Singh	
15	Shri Vidya Dev Longowal	Could not produce sureties and were therefore not released
16	Shri Gian Singh	
17	Shri Dalip Singh	
18	Shri Sulakhan Singh	

ANNEXURE (A)

To

The Home Secretary, Punjab Government,
Chandigarh

Subject.—Protest against the present procedure in the matter of release on parole.

Shrimanji,

We the undersigned communist detenus hereby draw your attention towards the defective way of granting parole which in fact, cannot be availed of. We give the following instances in support of our contention.

In the beginning it was the policy of the Government not to grant release on parole even in most needy cases such as to look after the ailing and dying relatives of the detenus. In this connection the case of comrade Chattar Singh, M.C., Hiassr, district Hissar may be cited. His mother has died and his parole was rejected. He was only allowed to attend Kirya ceremony under police escort only for few hours.

Latter on though a change has occurred in the policy of the Government in the matter of granting parole to the detenus on occasion of the death of the near relatives and the marriage ceremony of their near relatives, etc. But we regretfully point out that though some of the detenus have been ordered to be released on parole, but not only the duration of the parole is awfully short one that is "three days or so" but practically in most cases such an order has been nullified as the orders of release are generally communicated to the detenus at the nick of the time, thus the detenu is practically unable to manage the required sureties. For intstance our co-detenu Commrade Sulakhan Singh of Batala, district Gurdaspur, was informed about the order of his release on parole on February 5, 1965 at 9.10 a.m. for participation in the marriage of his real brother which was fixed on February 6, 1966. Now please see for yourself can it be possible to furnish sureties to avil of the parole ? In another case similarly Comrade Vidya Deva, detenu in Nabha Jail was communicated about his release only a day before the marriage of his niece.

We strongly present protest aginst such procedure wriggle irregularities on the part of agencies dealing with paroles. Those who are lucky to avail of release can stay at home only for a dy ay and the rest of the two days are practically spent in going to homes and coming back to respective jails. As such out of this practical experience our genuine demand emerges that the duratioh of the paroles should in no case be less than two weeks. And the date of the release should commence from next day that is the date of detenu's release from the prison. Our another difficulty related to availing of parole is this that the orders are being issued at the nick of time. This in no way help us the purpose, as the date of release is mentioned in the order. The reason is simple one as the friends and relatives cannot furnish sureties in time as order for. Therefore we are perfectly justified to demand that the detenus be released on furnishing bonds only, and in case the Government has to stick to continue this procedure, we suggest that in the order of release on parole no specific date should be fixed. But the parole should be started from the date when the sureties required are furnished and reached the jail through proper procedure.

At the end we may expect that you would look into our difficulties and the suggestions sympathetically and redress our grievance.

Thanking you.

Yours truly,

(Sd.) . . .,
HARDIT SINGH BHATHAL, M.L.A.

(Sd.) . . .,
MAKHAN SINGH TARSIKKA- M.L.A

(Sd.) . . .,
HARNAM SINGH CHAMAK

(Sd.) . . .,
CHATTAR SINGH

(Sd.) . . .,
SULAKHAN SINGH,

(Sd.) . . .,
RAM KISHAN BHAROLIAN,

(Sd.) . . .,
GURCHARAN SINGH RANDHAWA

(Sd.) . . .,
GURBAX SINGH ATTA

Dated 9th February, 1966.

Scholarships awarded to the students in Government Middle School, Chananwal, district Sangrur

3275. Comrade Gurbakhsh Singh : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of sons/ daughters of goldsmiths studying in the Government Middle School, Chananwal, distict Sangrur, who were granted scholarships for the year 1964-65 ;

(b) the names and parentage of the said students and the class in which they are studying ;

[Comrade Gurbakhsh Singh]

(c) whether the students referred to in part (b) above have been paid the amount of the scholarships ; if so, the amount so paid in each case ;

(d) whether there is any student in the said school who was granted a scholarship but to whom the amount was not paid ; if so, his name and the class in which he is studying ;

(e) whether there is any student in the said school who was not granted any scholarship but the amount thereof was paid to him ; if so, his name and the class in which he is studying ;

(f) if the answer to part (e) above be in the affirmative, the name of the person responsible for making wrong payments and the action, if any, so far taken against him ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 9 (4 boys and 5 girls.)

(b) Name, Parentage and Class of the students :

(1) Ram Parkash, son of Mah Singh, VIII Class.
(2) Karnail Singh, son of Surjan Singh, VI Class.
(3) Prem Kumar, son of Hari Ram, V Class.
(4) Surinder Lal, son of Dalip Singh, III Class.
(5) Krishna Devi, daughetr of Dalip Singh, I Class.
(6) Raj Rani, daughter of Nand Lal, III Class.
(7) Krishna, daughter of Nand Lal, I Class.
(8) Manjit Kaur, daughter of Lal Singh, III Class.
(9) Manjit Kaur, d/o Hari Ram, IV Class.

(c) Yes, except one student.

		Amount sanctioned	*Amount paid*
		Rs	Rs
(1) Ram Parkash	..	73·50	73·50
(2) Karnail Singh	..	73·50	73·50
(3) Prem Kumar	..	54·25	54·25
(4) Surinder Lal	..	54·25	54·25
(5) Krishna Devi	..	50·00	50·00
(6) Raj Rani	..	52·00	52·00
(7) Krishna, daughter of Nand Lal		50·00	50·00
(8) Manjit Kaur, daughter of Lal Singh		54·25	54·25**
(9) Manjit Kaur, daughter of Hari Ram		54.25	54.25
Total	..	516·00	516·00

(d) Yes. Manjeet Kaur, daughter of Lal Singh, Class III.

(e) Yes, Ram Partap.

(f) Shri Niranjan Singh, Headmaster, Government Middle School, Chananwal is responsible for this wrong disbursement and the action against him is in progress.

**wrongly paid to Ram Partap.

Pay disbursed to the Members of the staff of Government Middle School, Chananwal, district Sangrur

3276. Comrade Gurbakhsh Singh : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the date on which the pay of the staff of the Government Middle School, Chananwal, district Sangrur, for the month of February, 1965, was drawn by the Headmaster of the said school and the date on which it was actually disbursed to the members of the staff ;

(b) the interval permissible under the rules between the drawing and the disbursement of pay ;

(c) whether the Headmaster of the said school violated any rules relating to drawing and disbursing of salaries ; if so, the action taken against him ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The pay of the staff in question for February, 1965, was collected from the office of the District Education Officer, Sangrur on, 11th March, 1965 and disbursed to the staff on 19th March, 1965.

(b) Three months.

(c) No.

Complaint against the Headmaster, Government Middle School, Chananwal, district Sangrur

3277. Comrade Gurbakhsh Singh : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) whether the Education Department received any complaint/complaints from the residents of village Chananwal, district Sangrur, or from the staff of the Government Middle School, Chananwal, during the year 1965 to the effect that the Headmaster of the said school remains absent from the school ; if so, copies thereof be laid on the Table ;

(b) whether any enquiry has so far been held into the said complaints; if so, when and by whom and whether the results of the enquiry have been communicated to the complainants ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. A statement showing the main allegations made in the complaints is enclosed.

(b) Yes. The enquiry was conducted by the Assistant Education Officer (P.T.), on 26th October, 1965. The result of enquiry has not been communicated to the complainants as the final disciplinary action to be taken against the Headmaster, Government Middle School, Chananwal has not been decided pending further probe into the matter.

ANNEXURE TO PART (A)

Particulars of the complaints received against the Headmaster, Government Middle School, Chananwal (Sangrur)

Complaints	*Main allegations*
Gram Panchayat, Chananwal (Sangrur)—two complaints	1. The Headmaster generally remains absent from the school

[Education Minister]

	Main aligations.
	2. He has created party faction in the school as well as in village
	3. He has removed produce from the school farm to his house
	4. He has realised Rs 10 per student as fee from some of the students whom he has promoted to the next class
Staff members of the Government Middle School, Chananwal (Sangrur) five complaints	1. The treatment of the headmaster towards the school staff is rude and non-co-operative
	2. He generally remains absent from the school and marks himself present in the register
	3. He has mis-appropriated school funds
	4. School radio is used at his residence instead of school
	5. Some cases of school staff which are to be sent to the District Education Officer's Office are destroyed by him
	6. Produce from school farm is taken to his house

Enquiry against the Headmaster, Government Middle School, Chananwal, district Sangrur

3278. Comrade Gurbakhsh Singh : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officer of the Education Department in Sangrur District conducted an enquiry against the Headmaster, Government Middle School, Chananwal, in October, 1965 ;

(b) whether it is also a fact that during the course of the said enquiry the lady teachers of the said school submitted a written complaint to the said officer against the Headmaster ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative , the details of the allegation levelled against the Headmaster by the said Lady Teachers in the said complaint and the action taken thereon, if no action has been taken so far, the reasons theefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The Headmaster, Government Middle School, Chananwal is alleged to have threatened the Lady teachers to give statements in his favour at the time of enquiry. The Enquiry Officer went ahead with the enquiry and concluded that the allegation levelled against the Headmaster was the outcome of Party Faction

Complaint by a Class IV Employee of the Government Middle School, Chananwal, district Sangrur

3279. Comrade Gurbakhsh Singh : Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) whether the Education Officers of the Sangrur District received any complaint from a class IV employee of the Government Middle School, Chananwal, district Sangrur, during the month of December, 1965 / January, 1966, alleging that the Headmaster of the said school unduly deducted his pay for some days of November, 1965 ; if so, the action taken thereon.

(b) whether the result of the enquiry, if any, has been conveyed to the complainant ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No.

(b) Question does not arise.

Sanction for Kamla Nehru College in tehsil Narwana, district Sangrur

3280. **Shri Fakiria** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the time by which sanction for starting the Nehru College in tehsil Narwana, district Sangrur, is likely to be accorded ;

(b) whether he is aware of the fact that the residents of the said tahsil which is a backward area have alrady deposited the amount for the purpose and there are 11/12 schools in Narwana area ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The claims of tehsil Narwana for the starting of a Degree College will be considered alongwith similar requests received from other areas of the Punjab.

(b) The facts about the deposit of the amount collected by the residents of the ilaqa for the purpose of starting a college are not known. The number of feeder schools will be taken into consideration when the claims of tehsil Narwana are considered for this purpose.

Providing free education and financial assistance to the children of Balmiki Sweepers in the State

3281. **Shri Fakiria** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state whether Government have decided to provide free education to the children of the Balmiki Sweepers in the State from the Ist to the M.A. classes and also to give financial assistance for the purchase of clothes and books ?

Shri Chand Ram : The Scheduled Caste students (including the students belonging to Balmiki Sweepers) are already entitled to free education from Ist to M.A. Classes. A scheme has been approved for the next financial year 1966-67 for grant of subsidy to all female students belonging to the Scheduled Castes and male children of sweepers / scavangers in High Higher Secondary Classes for purchase of books and writing material.

Evacuated land in village Balamgarh (Garhi), tehsil Narwaan district Sangrur)

3282. **Shri Fakiria** : Will the Minister for Revenue be pleased to state :

(a) whether there is any evacuee land purchased by Government from the Central Government in village Balamgarh (Garhi), tehsil Narwana, district Sangru r;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the said land has been auctioned or sold to any Zamindar ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes.

(b) 19 kanals 8 marla was sold by open auction to Shri AliSher son of Samundu (3 kanals 8 marla) and Shri Ujagar Singh, son of Hari Singh (16 kanal 0 marla) on 9th July, 1963 and 11th November, 1963 respectively according to the instructions then in force. 22 kanal 12 marla evacuee land is still available for disposal.

Amount proposed to be given to Harijans for starting certain Industries

3283. Shri Fakiria : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state :

(a) whether any sum out of the amount of Rs 5 crores raised through the Harijan Welfare Tax is proposed to be advanced to the Harijans in the State for starting certain Industries ; if so, the details of these industries ?

(b) whether he received a request from a Legislator that the said amount be utilised for sheep breeding ; Poultry, improving the buffalo breed, piggery, hides and skins trade and setting up of khaddies, if so, the action taken on the request and the manner in which the said amount is actually proposed to be spent ?

Shri Chand Ram : (a) Yes, the details are being worked out.

(b) Yes. Legislators sent their proposals and they were also consulted. The final shape of schemes to be financed out of this Fund is being worked out.

Field Publicity / Information Assistants

3284. Shri Hunna Mal : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the total number of field Publicity Assistants and Information Assistants appointed till today in each district, date-wise and region-wise together with the name of the district to which each belongs ;

(b) whether Government is considering any proposal to recruit more Field Publicity / Information Assistants in the near future ;

(c) the names of the Supervisors and of the Organisers who have been appointed as Field Publicity Assistants giving the date of their appointment as such ;

(d) a copy of the latest seniority list of Field Publicity Assistants and Information Assistants be laid on the Table ;

(e) whethr Government is aware of the fact that some Field Publicity Assistants who have been serving this departmnt for the last ten years have not been yet confirmed in service ;

(f) whether it is a fact that some Supervisors, who were junior were promoted as D.P.R.Os and have been ocnformed in service while the Supervisors, who were senior, have been ignored and they have not been confirmed as yet ; if so, the reasons therefor ?

Sh. Ram Kishan : (a) and (c) Statement containing the requisite information is enclosed.

(b) No.

(d) The seniority list is being finalised.

(e) Yes.

(f) Only Shri Parma Nand, who was a Supervisor , was promoted on ad-hoc basis within the district . Since no suitable person was available, the post was subsequently advertised through the Public Service Commission, Punjab.

LIST OF FIELD PUBLICITY/INFORMATION ASSISTANTS

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment	Whether old Supervisor / Organiser	District to which belongs
1	2	3	4	5	6
		PUNJABI REGION			
	Hoshiarpur				
1	Shri Siri Ram Arsh ...	Field Publicity Assistant	16th November, 1965	..	Ludhiana
2	Shri Raj Kumar Bali ...	Ditto	17th November, 1965	..	Gurdaspur
3	Shri Babu Singh ..	Ditto	10th February, 1966	Organiser	Bhatinda
	Gurdaspur				
1	Shri Puran Chand ...	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Gurdaspur
2	Shri Parlok Singh ...	Ditto	12th November, 1965	Do	Do
	Jullundur				
1	Shri S.K. Saroor ...	Information Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Jullundur
2	Shri Sukhpalvir Singh Hasrat ...	Field Publicity Assistant ..	Ist September, 1965	Do	Gurdaspur
3	Shri N.N. Sharma ...	Ditto	Ist September, 1965	Organiser	Kapurthala
4	Shmt. Pritam Kharbanda ...	Ditto	16th February, 1966	Do	Jullundur
5	Shri Sant Kumar Juneja ...	Ditto	10th February, 1966	Supervisor	Jullundur

1	2	3	4	5	6
	Ferozepore				
1	Shmt. Swadesh Kumari Chopra ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Organiser	Jullunuur
2	Shri Natha Singh ..	Ditto	17th November, 1965	Organiser	Ferozepore
3	Shri Ravinder Singh ..	Ditto	17th November, 1965	Supervisor	Patiala
4	Shri Taranjit Singh Chawla ..	Ditto	19th February, 1966	..	Ludhiana
	Ludhiana				
1	Shri Babu Singh ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Ludhiana
2	Shmt. Joginder Kaur ..	Ditto	12th November, 1965	Do	Do
3	Shri Kamlinder Singh ..	Ditto	15th November, 1965	..	Amritsar
4	Shri Karnail Singh ..	Ditto	11th February, 1966	Organiser	Ludhiana
	Amritsar				
1	Shri Banwari Lal Mehra ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Amritsar
2	Smt. Gurdarshan Kaur ..	Ditto	12th November, 1965	Do	Do
3	Shri Chatter Singh ..	Ditto	13th November, 1965	Do	Do
4	Shri Swaran Singh Gill ..	Ditto	..	Organiser	Do
	Patiala				
1	Smt. Swatanter Kapur ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Organiser	Patiala
2	Smt. Vimal Kaushal ..	Ditto	18th November, 1965	..	Do

3	Shri Shankar Parkash ..	Ditto	22nd November, 1965	..	Sangrur
4	Shri Vinay Kumar ..	Ditto	15th January, 1966	..	Patiala
5	Shri Krishan Mursari ..	Ditto	15th February, 1966	Organiser	Ludhiana
	Kapurthala				
1	ShriMohinder Singh Gill ..	Field Publicity Assistant	16th November, 1965	Supervisor	Kapurthala
2	Shri Joginder Singh Gill ..	Ditto	17th November, 1965	..	Amritsar
3	Smt. Jaswant Kaur ..	Ditto	16th February, 1966	Organiser	Patiala
	Sangrur				
1	Shri Basant Kumar Sharda ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Jullundur
2	Shri N.S. Shad ..	Ditto	Ist September, 1965	Do	Sangrur
3	Shri Hari Singh ..	Ditto	14th February, 1966	Do	Do
	Bhatinda				
1	Shri Jagmohan Singh ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Bhatinda
2	Shri Rakesh Chander Gupta ..	Ditto	13th November, 1965	..	Do
3	Shri Gurcharan Singh Chalal ..	Ditto	14th February, 1966	..	Do
		HINDI REGION			
	Hissar				
1	Shri Shankar Lal ..	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Hissar
2	Smt. Raj Josh ..	Ditto	15th November, 1965	Do	Do
3	Shri Jagdish Bharti ..	Ditto	15th November, 1965	..	Do
4	Shri Yadavindra Singh ..	Ditto	..	Supervisor	Mohindergarh

[Chief Minister]

1	2		3	4	5	6
	Rohtak					
1	Smt. Shakantla Kumari	...	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Rohtak
2	Shri Chander Bhan	...	Ditto	Ist September, 1965	Do	Do
3	Shri Satvir Singh Rana		Ditto	Ist September, 1965	Do	Do
4	Shri Surrinder Pal Singh Ahlwat	...	Ditto	11th February, 1966	...	Do
	Gurgaon					
1	Smt. Savitri Malik	...	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Rohtak
2	Shri Dayal Chand Miglani	...	Ditto	12th November, 1965	Do	Do
3	Shri Hari Ram Arya	...	Ditto	12th November, 1965	Do	Do
4	Shri Shiv Singh	...	Ditto	15th February, 1966	Organiser	Gurgaon
	Karnal					
1	Shri Chatter Sain Goel	...	Ditto	Ist September, 1965	Supervisor	Karnal
2	Smt. Satya Dutta Sharma	...	Ditto	25th November, 1965	...	Amritsar
3	Shri Madan Mohan Sharma	...	Ditto	26th November, 1965	...	Patiala
4	Shri R.P. Dhawan	...	Ditto	16th February, 1966	Supervisor	Ambala
	Ambala					
1	Shri Gurmukh Singh	...	Field Publicity Assistant	Ist September, 1965	Do	[illegible]
2	Smt. Sharda Gulhati	...	Ditto	Ist September, 1965	Do	Do

3	Smt. Laj Bedi	Ditto	st September, 1965	Do	Do
4	Smt. Bhupinder Paul Kaur	Ditto	Ist September, 1965	Do	Ludhiana
5	Smt. Kusan Lata Jain	Ditto	Ist September, 1965	Organiser	Ambala
6	Shri Subhash Narnla	Information Assistant	Ist September, 1965	Supervisor	Do
7	Shri Rajbir Singh Dhillon	Ditto	Ist September, 1965	Do	Ludhiana
	Delhi				
8	Shri A.K. Saigal	Information Assistant	Ist September, 1965	Do	Delhi
9	Shri Balbir Kapur	Field Publicity Assistant	15th November, 1965	Do	Ambala
10	Shri Siriniwas	Information Assistant	26th November, 1965	..	Ambala
11	Shri Hira Nand Swami	Field Publicity Assistant	16th February, 1966	Supervisor	Karnal
	Simla				
1	Smt. Raman Sharma	Ditto	Ist September, 1965	Do	Ferozepur
2	Shri B.J. Kapoor	Ditto	Ist September, 1965	Organiser	Patiala
3	Shri Baljit Singh Bali	Ditto	26th November, 1965	..	Ambala
	Kangra				
1	Shri Sushil Chand Rattan	Ditto	Ist September, 1965	Organiser	Kangra
2	Shri Om Parkash Sharma	Ditto	17th February, 1966	Do	Jullundur
	Kulu				
1	Shri Vinod Kumar Lakhanpal	Ditto	Ist September, 1965	Supervisor	Hoshiarpur
2	Shri Rup Chand Misra	Ditto	Ist September, 1965	Organiser	Kulu
	Lahaul Spiti				
1	Shri Dharam Pal	Field Publicty Assistat	Ist September, 1965	Organiser	Keylong

]Chief Minister]

1	2	3	4	5	6	
	Mohindergarh					
1.	Sh. Pat Ram Verma ..	Field Publicity Assistant		20th November, 1965	Organiser	Hissar
2.	Sh. Daya Nand ..	Ditto		7th February, 1966	..	Bhatinda
3.	Sh. Bishan Sarup ...	Ditto		10th February, 1966	Organiser	Mohindergarh
4.	Shrimati Shakuntla Kumari ..	Ditto		16th February, 1966	Ditto	Delhi

Complaints/Representations. Received from certain Persons of Kurukshetra, District Karnal

3285. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether he, the Chief Minister, the I.G. of Police/the D.I.G of Police and or the S.P Karnal received any complaints/ representations from Shri Benarsi Dass and or Shri Chain Parkash of Kurukshetra, District Karnal against certain Police officials of P.S. Thanesar (Kurukshetra) distriact Karnal during the period from 1st October, 1965 todate, if so, the number of complaints/representations received by the above said authorities, datewise, together with the details of the action so far taken thereon.;

(b) whether any of the above-mentioned authorities issued orders for the registration of case/cases against certain officials of the Police posted at P.S. Thanesar (Kurukshetra) if, so, the date when order for the registration of case/cases was passed and the date when the case /cases were registered, if the cases were not registered the reasons therefor ;

(c) whether any action on the representations/complaints as mentioned in part (a) above has been taken, if so, the details thereof if no action has been taken the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes, Three complaints dated 14th December, 1965, 17th December, 1965 and 3rd January, 1966 were received. Two complaints dated 14th December, 1965 and 3rd January, 1966 were received from Shri Banarsi Dass while the third dated 17th December, 1965 was sent by Shri Cnain Parkash. The contents of these complaints disclosed the commission of an offence by S.I. Kuldip Singh, Head Constable Mool Chand, Head Constable Goverdhan Dass and Constable Hari Ram in their official relations with the public . After obtaining sanction of tne District Magistrate, Karnal under P.R. 16.38 (1), necessary enquiries were conducted by Shri Rambel Singh, D.S.P/Kaithal. On the basis of his findings submitted on 2nd March, 1966, a case u/s 331 IPC, was ordered to be registered which is under investigation.

(b) Yes. The D.I.G./Ambala Range while camping at Karnal on 6th January, 1966 had ordered for the registration of a case against the Police officials mentioned in part (a) above, but no case was registered as the matter had already been referred to the District Magistrate, Karnal, in terms of the Punjab Police Rule 16.38 (i)

(c) Details of the action taken on the representations have been given in part (a) able.

Enquiries conducted by the Additional inspector General of Police, Punjab

3286. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state :

(a) whether he deputed the Additional I.G. of Police, Punjab during the period from 15th January, 1966 to date to hold enquiries in to the complaints lodged by certain legislators of Karnal

[Comrade Ram Piara]

district or lodged through the legislators of karnal district, if so, the date when the said enquiries were entrusted to him together with the number of complaints/communications handed over to him for holding enquiries;

(b) whether it is a fact that the Additional I.G. of Police visited Karnal in the month of February, 1966, if so, the number and the details of the complaints enquiried into by him together with the names of the legislators who had sent these complaints ;

(c) whether any interim report has been submitted by the said officer if so, the details thereof together with the action, if any, taken by him (Home Minister) or the Additional Inspector-General of Police thereon ;

(d) the total number of communications which were given to the Additional I.G. of Police, for enquiry, and the number of communications which have been disposed of by him with the dates of the oldest communication and the latest communication among them ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. Addl. I.G. was deputed to hold an enquiry into the complaints lodged by Shri Ram Piara, M.L.A. Karnal District. The enquiry was entrusted to him on 7th January, 1966 and as many as 70 complaints received from Shri Ram Piara, M.L.A. were entrusted to him for holding the enquiry.

(b), Yes. He looked into some of these complaints when he visited Karnal in the month of February. He discussed in detail some of these with Shri Ram Piara, M.L.A. who had made these complaints.

(c) No. Addl. I.G. is still looking into them.

(d) 70 complaints were received. The oldest is dated 16th January, 1965 and the latest dated 11th January, 1966 . The enquiry is not yet complete.

Cases of Abductions in District Karnal

3287. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of adbuction cases that occurred in district Karnal Police Station-wise and date-wise during the period from 6th July, 1964 todate together with the names of the abducted persons (male/female and married /unmarried separately) ;

(b) the places from which the said persons were abducted, the dates when they were abducted in each case and the dates when the cases were registered ;

(c) the total number of persons out of those mentioned in part (a) above who have so far been recovered, the date when and the names of places from where they were recovered police station-wise ;

(d) the names of those from whom the sid persons were recovered together with the names of the persons who were arrested in connection with the abductions ;

(e) the names with designations of the Investigating officers/officals who despite their efforts could not recover the abducted persons ;

(f) whether any complainsts against the Investigating officers who failed to recover the abducted persons had been received by him/I.G. of Police if so, the details thereof together with the details of the action, if any, taken in any case ?

Sardar Darbara Singh : (a) to (f) Requisite informtion is given in the stateeent at Annexure A'.

ANNEXURE

Assembly Question

A Part B Part C part

Name of Police Station	Serial No.	Names of abducted persons	Male or female	Married or unmarried	Place from which the said person abducted	Date when they were abducted	Date when the case was registered	Whether recovered or not, date of recovery
1		2	3	4	5	6	7	8
Sadar Karnal	1.	Joginder Singh, son of Rala Singh of Karnal	Male	Unmarried	District Sub. Jail Karnal	5-7-64	6-7-64	Recovered 5-7-64
	2.	Kalawati, wife of Hari Krishan of Kunjpura	Female	Married	Kunjpura	19-7-64	3-8-64	Recovered 13-8-64
	3,	Ram Piari, daughter of Kooju Ram Rajpurt of Basi, P/S. Charaunda	Do	Unmarried	Nagla Magha	8-10-64	19-10-64	Not recovered
	4.	Ukho, daughter of Shanta Model Town, Karnal	Do	Unmarried	Jumna Camp, Karnal	8-11-64	23-11-64	Recovered 2-12-64
	5.	Parveen wife of Kharati Lal resident of Ram Nagar, Karnal	Do	Married	Ram Nagar, Karnal	22-7-65	30-7-65	Returned herself on 10-10-65
	6.	Kuchro Bai, wife of Piaray Lal Ram	Do	Do	Do	Do	Do	Do

'A'

on 3287

Part C	Part D		Part E	Part F
Place from where they were recovered	Names of those persons from whom recovered. These persons along with those given in column No. 11 have been arrested	Name of persons accused.	The names of the officers who despite their best efforts could not recover the abducted persons.	Whether any complaint against the officers who faild recover the abducted persons have been received if so the detail of action if any taken in any case
9	10	11	12	13
rs. Sub Jail Karnai	Ram Parkash, son of Gian Chand Khatri of Rati, P.S. Thaska Miran		..	..
Batwala Ghat	Siri Chand, son of Parma Nand of Chulkana Balkar Singh, son of Sohan Singh of Sirhind Kishan Chand son of Chandgi of Chulkana.	1. Mittar Sain son of Luchho Ram of Kunjpura. 2. Mst. Bhano, wife of Mittar Sain of Kunjpura	..	..
Nil	Nil	1. Biro, son of Dawaya Ram Gamari Kaithal 2. Kesho Ram, son of Parbhu of Sadrpur 3. Dolu Ram, son of Bish Ram of Ahorpur P.S. Gharaunda 4. Kuru Ram son of Dhawya Ram of Gamari Kaithal	1. HC Pritam Singh 2. ASI Gobind Singh	...
Uko daughter Bohay	of Hardara, son of Sunder resident of Atta P. S. Smalkha	Nil	..	...
Partap Watti Returned herself from Mohar Lucknow Dist,	..	Ganesh Dass son of Sawaran Ram of Janmnuna Camp	..	...
do	..	(1) Tikka son of Sawan Ram (2) Vekho, son of Sawan Ram (3) Amir Chand son of Lekh Raj of Jumna Camp	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Raj Bala, daughter of Hari Chand of Samli U.P.	Female	Unmarried	Gheer	22-7-65	6-8-65	Recovered on 6-8-65
	8. Sohna, wife of Laloo of Nagla Megha	Do	Married	Nagla Megha	17-8-65	30-8-65	Recovered on 13-11-65
	9. Krishna Kumari, daughter of Basant Lal, Ram Nagar Karnal	Do	Unmarried	Ram Nagar Karnal	25-10-65	29-10-65	Recovered on 30-10-65
	10 Maya Devi, daughter of Radha Krishan of Bindra Ban U.P.	Do	Do	Dharamshala Karnal	2-10-65	28-11-65	Returned herself on 27-11-65
	11 Bimla Rani, daughter of Phookar Dass of Balari	Do	Do	Balari	4-2-66	4-2-66	Recovered on 12-2-66
			TOTAL	CASES 11			
City Karnal	12 Shrimati Narinder Vati daughter of Iqbal Mohan, resident of Thanesar	Female	Unmarried	City Karnal	19-8-64	20-8-64	Recovered on 20-8-64
	13 Mst. Ongori, daughter of Kalu, resident of Karnal	Do	Married	Do	29-8-64	29-8-64	Recovered on 29-8-64
	14 Shmt. Brahma, d/o Nathu Ram r/o Karnal	Do	Unmarried	Do	26-9-64	30-9-64	Recovered on 2-10-64
	15 Shamsher Singh, son of Mangat Ram Karnal	Male	Do	Do	24-5-65	30-5-65	Returned himself on 29-6-65

9	10	11	12	13
Bus Stand Ladwa	1. Nar Singh 2. Ved Parkash	1. Sarda Ram 2. Rattan Singh 3. Raj Kumar 4. Mst. Sahari 5. Mst. Kasturi 6. Mst. Bimla 7. Mst. Shankari 8. Mst. Rattani 9. Mst. Jukli 10. Mst. Sanari 11. Ram Kishan 12. Jagdish 13. Maru 14. Krishan Chand 15. Babu Ram 16. Ganda Ram 17. Rattan Singh	...	...
Delhi	Dalip Chand, son of Kewal of Jajhiana	1. Bhullar 2. Telu 3. Surja 4. Juman residents of village Nagla Megha	...	...
Delhi	...	The abducted girl was a major college student who had left her parents to live with her paramour. The case was cancelled and no person was arrested	...	...
Returned herself after staying at various Places	..	..	..	...
Railway Station Karnal	Swaran Singh, son of Bhagat Ram of Thalwala	...	..	...
City Karnal	Adwanison of Jasal Charistan Karnal Daram Pal son of Amar Singh resident of Jokhli of District Rohtak	..	..	
Karnal	Rameshwar, son of Mam Raj Ror of Gamari Karnal	Hari Singh, son of Mangat Ram Ror of Mohalla Gamari, Karnal	..	—
Karnal	Manga			
Panipat	...	..	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8
	16 Devi Bai daughter of Sewa Ram Arora of Karnal	Female	Unmarried	City Karnal	30-10-65	31-10-65	Recovered on 5-11-65
				Total Cases 5			
Gharaunda	17. Dharam Pal, son of Mani Ram of Gharaunda	Male	Unmarried	Gharaunda	20-6-64	9-7-64	Not abducted himself returned from Bombay
	18. Parkash Wanti daughter of Ganesh Dass of Gharaunda	Female	Do	Do	1-2-66	13-2-66	Not abducted herself returned on 7-2-66
			Total cases 2				
Indri	19 Mst. Sadiana, wife of Sher Singh Balmiki resident of Garhi Birhal.	Femala	Married	Garhi Birbal	20-5-65	21-7-65	Not recovered
				Total case 1			
Butana	20. Phool Singh, son of Hardey caste Ror, resident of Benikhurd	Male	Do	Bani Khurd	27-11-64	27-11-64	Recovered on 28-11-64
	21 Mst. Chambali Devi wife of Arjan Jogi resident of Madana	Female	Do	Budareo	2-6-65	6-6-65	Recovered on 6-6-65
	*			*Total cases* 2			
Nissing	22 Surinder Kaur, wife of Pritam Singh Labana Sikh resident of Sambali	Do	Unmarried	Sambali	23-6-65	29-6-65	Recovered on 3-7-65
				Total case 1			
Sadr Panipat	23 Sita Ram Brahman of Jalalpur	Male	Married	Jalalpur	7-10-64	7-10-64	Not recovered.
	24 Mst. Bhagwani Devi, wife of Doolu Ram resident of Kuchrauli	Female	Do	Kachrauli	20-1-65	28-1-65	Recovered on 1-2-65
	25 Ramo, wife of Rameshwar resident of Makhi, P.S. Julana	Female	Married	Panipat	10-6-65	11-6-65	Recovered on 11-6-65
	26 Chandro, daughter of Ram Saran Harijan resident of Hatwala P.S. Smalkha	Do	Unmarried	Nazampur	13-8-65	13-8-65	Recovered on 13-8-65
	27 Surjan Singh, son of Hari Ram, resident of Babail	Male	Married	Panipat	4 months prior before the registration of the case	11-9-65	Recovered on 11-9-65

*Statement Printed as received from Government.

9	10	11	12	13
Rohtak	Sohan Lal	..	..	..
Not abducted returned himself from Bombay	..	..	..	..
Not abducted returned herself after staying at various places	..	..	..	..
..	..	Mst. Surji, wife of Jug Lal of Gharaunda	ASI Raja Ram SI Siri Ram	..
Bani Khurd	Giana son of Bora resident of Bani Khurd	1. Lakhi, son of Chala of Bani Khurd 2. Data, son of Mangat of Bani Khurd 3. Mam Singh, son of Lila Singh of Bani Khurd	..	..
Nilokheri	Kartar Singh, son of Sunder Singh, resident of Kamkata	Gurcharan Singh, son of, Bir Singh resident of Boorna	..	..
Jakowala District Ferozepur	Hukam Singh son of Narain Singh resident of Huku	..	..	..
...	..	Tiku, son of Phoola alias Malu son of Sardara, resident of Dabri	..	..
Delhi	Wisanda Ram son of Bila	1. Mst. Lachmi 2. Lal Chand 3. Chaman 4. Piara 5. Godda		
Pani pat	Zila Singh	Lekh Ram	..	..
Nazam pur	Piarye Lal son of Chaman Dass resident of Bukhma	..	..	..
Came back himself after staying at various places		..	..	..

[Home and Development Minister]

1	2	3	4	5	6	7	8
City Panipat	28 Iqbal Fatma daughter of Shakar Hussain resident of Panipat City	Female	Unmarried	City Panipat	5-9-64	15-9-64	Recovered on 21-9-64
				Total cash 1			
Smalkha	29 Danesh Bala, wife of Rati Ram resident of Mir Majra	Do	Married	Binwali Majru	10-7-65	8-8-65	Recovered on 31-8-65
	30 Bhagwani wife of Sarupa Jat resident of Dedkadlu	Do	Do	Dedkadla	5-12-65	30-12-65	Recovered 25-12-65
	31 Kesari wife of Harphool Jat resident of Jarasi Khas		Do	Jarasi khas	2-1-66	2-1-66	Recovered on 14-1-66
				Total case 3			
Urlana	32 Mst. Chando, d/o Ram Saran Harijan resident of Hathwala	Do	Unmarried	Budankalan	20-3-65	21-3-65	Recovered on 14-6-65
	33 Mst. Kaso daughter of Mukhtiara Harijan of Jondan Kalan	Do	Do	Budankalan	26-4-65	14-5-65	Recovered on 13-5-65
	34. Mst. Boli, wife of Shiv Chand, caste Jat, resident of Kheri District Karnal	Female	Married	Dosar	Month of May, 1965	17-9-65	Returned herself on 21-7-65
	34-A. Mst. Krishna wife of Jia Lal, Harijan, of Karabuan District Rohtak	Do	Do	Matoda	4-7-65	15-7-65	Returned herself on 25-7-65
				Total cases 4			
Thanesar	35. Mst. Harbhajani, daughter of Balkar Singh, resident of Baghata	Do	Unmarried	Bagthala	15-7-64	1-8-64	Recovered on 6-8-64
	36. Shmt. Joginder Kaur, wife of Kashmira Singh, resident of Bagthala	Do	Married	Bhalli	25-7-64	2-8-64	Recovered on 20-8-64
	37. Mst. Har Kaur, wife of Paga Singh, resident of Bagthla	Do	Do	Bagthala	27-7-64	1-9-64	Recovered on 5-9-64

9	10	11	12	13
Bewal	Ashak Ali, son of Bararat Ali resident of Kenigror District Muzaffar Nagar	..	..	..
Binawali Majra	Dharam Singh Ratti	..	...	..
Malpur	Bazari Jat	..	..	..
Julor	Dharam Pal, son of Bali Chand of Jatwai	..	1. Pawan Singh son of Mool Chand of Morena	
		..	2. Suba Singh son of Lehna	
		..	3. Mir Singh	
		..	4. Partap	
		..	5. Lakhi	
Fatehabad	Piaria Harijan	..	..	..
Alipur Delhi	Ram Saran son of Amar Singh resident of Hatwala	...		
Returned her self from Garh Rao	..	..	..	..
Returned herself from Rohtak	..	..	..	..
Railway Station, Kaithal	Returned herself from the custody of Balbir Singh accused	Balbir Singh, son of Fauja Singh, resident of Bagathala	..	..
Rocti	Returned herself from the custody of the accused mentioned at column 11	1. Malik Singh 2. Waryam Singh 3. Tarlok Singh 4. Karnail Singh 5. Hakam Singh 6. Asa Singh 7. Karnail Singh 8. Gurcharan Singh 9. Gurbachan Singh 10. Balvinder Singh 11. Sewa Singh 12. Gurbachan Singh 13. Balkar Singh 14. Sardara Singh 15. Jagir Singh	..	..
Baghthala	Ditto	1. Balvinder Singh 2. Gurbachan Singh 3. Sewa Singh 4. Gurcharan Singh 5. Avtar Singh 6. Gurnam Singh 7. Virsa Singh 8. Kulwant Singh 9. Piara	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
	38. Mst. Surita Devi, wife of Atma Parkash Peon University Kurukshetra	Female	married	Thanesar	19-10-64	25-11-64	Came back herself. She was not abducted. She he self went due to the domestic quarrel with her husband
	39. Shmt. Sarain Kaur daughter of Waryam Singh, Jat, residence of Krishan garh	Do	Un-married	Umri	4-9-65	6-9-65	Not recoverred, reported to be murdered
	40. Lila Devi, daughter of Brij Lal Jhinwar of Thanesar	Female	Married	Thanesar	18-8-65	30-9-65	Recovered on 10-3-66
	41. Maya Devi, wife of Mani Ram, resident of Bachgaon	Do	Do	Bachgaon	5-10-65	6-10-65	Recovered on 6-10-65
			Total cases 7				
Shahabad	42 Mst. Jagiro, wife of Chambala Balmik, resident of Islam Nagar	Female	Un-married	Naraingarh	May, 1963	22-3-65	Recovered on 23-3-65
	43. Harbans Singh son of Waryam Singh, Jat of Shahabad	Male	Do	Shahabad	2-6-65	27-7-65	Not recovered
	44. Ram Randhari daughter of Khushal, residence of Pachar Dist Meerut	Female	Do	Kalshana	6-2-66	7-2-66	Not recovered
			Total cases 3				
Rur	45. Nirmla, daughter of Sadhu Ram, resident of Jathlana	Do	Do	Jathlana	8-3-65	12-3-65	Recovered on 14-3-65
	46. Krishna, daughter of Ram Singh, Rajput of Nokan	Do	Do	Nokan	13-3-65	24-3-65	Recovered on 4th Apri 1965

9	10	11	12	13
Came back herself	..	..	..	..
..	..	1. Darshan Singh 2. Avtar Singh, son of Jagat Singh, resident of Krishan Jagti Police station, Thanesar	..	..
Nari Naketan Hardwar	..	1. Dalip Singh 2. Labh Singh 3. Titi	Nil	Nil
Buchgaon	Came back herself from the custody of accused mentioned at column 11	1. Faquira 2. Kamyia 3. Bhagrith 4. Bakat 5. Pintoo 6. Parsa 7. Ratoo 8. Nakitia 9. Niral 10. Ranji	..	..
Chams Nand	Dariya, son of Kaku	..	..	..
Not recovered	..	Mangal Amir	A.S.I. Harbans Singh, S.I. Kesar Singh	..
..	..	..	S.I. Gurbux Singh, A.S.I. Hazari Lal	..
Karnal	Saila	1. Jasmer Singh 2. Kheman 3. Mansha 4. Jhella 5. Gyani 6. Pirthi	..	..
Delhi	Sadhu	1. Baljit 2. Balwant 3. Kishna 4. Amar Singh 5. Ram Sarup	..	..

[Home and Development Minister]

1	2	3	4	5	6	7	8
	47. Lachhmi, daughter of Rikhi Ram, Saini of Village Godhi	Female	Un-married	Godhi	11-1-66	14-1-66	Recovered on 28-1-66
					Total case 3		
	48. Sukhwant Singh, son of Shongra Singh, resident of Thaska	Male	Do	Thaska	3-8-64	3-8-64	Recovered on 3-8-64
	49. Mst. Phatoo, daughter of Ishar Dass, resident of Jharoli, Police station Thaska	Female	Do	Tharwali	26-9-64	9-10-64	Not recovered
	50. Krishan Kumar, son of Mular Ram Saini, resident of Manchal District Patiala	Male	Do	Ismailabad	64	13-11-64	Returned himself on 13-11-64
					Total cases 3		
Kaithal	51. Kartar Singh, son of Labh Singh, Jat Sikh, resident of Chack Ladana	Male	Married	Not known	10-9-64	29-9-64	Not recovered
	52. Mst. Chhotu, wife of Munshi Ram Harijan, daughter of Dehari	Female	Do	Titran	29-11-64	3-12-64	Recovered on 26-12-64
	53. Mst. Bachani, daughter of Milkhi Ram Masha, resident of Jatwala District Gurdaspur	Do	Do	Jatwal	April, 1965	20-7-65	Recoverd on 20-7-65
					Total cases 3		

9	10	11	12	13
Buria	Baru Ram	1. Mst. Gandhi 2. Sada Nand 3. Joti Ram	..	..
Rai	Niranjan Singh	..	..	..
..	..	Chanan Singh alias Sugha, son of Sunder Jat Sikh of Kala	1. S.I. Baru Singh 2. Naurata Ram H.C. 3. A.S.I. Kirpal Singh 4. Joginder Singh H.C.	..
Returned himself from Ismailabad	..	..	..	..
			S.I. Roshan Lal	
Geong	Came back herself from the custody of the accused mentioned in column 11	1. Lilo, son of Rulia of Baini Majra 2. Munshi son of Mangat resident of Babe	..	..
Kaithal	Ditto	1. Jit Singh 2. Nazar Singh 3. Chanan Singh 4. Gurcharan Singh 5. Bhagwan Singh 6. Ishar Singh 7. Hardeep Singh 8. Mistri Lal 9. Mohinder Singh	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
Gubla—	54. Ajit Singh, son of Sadha Singh Jat, resident of Kotla Jangan	Male	Married	Himiu Majra	1½ years before	23-10-64	Not recovered
							23
	55. Raj Rani, daughter of Hazara Singh, Khatri, resident of Ghula	Female	Un-married	Ghula	9-4-65	9-6-65	Recovered on 8-6-65
					Total cases 2		
Ladwa—	56. Mst. Darshni, daugher of Shankar, residence of Surjgarh	Female	Un-married	Sharifgarh	14-8-64	16-8-64	Not recovered
	57. Swaran Singh,, son of Kartar Singh, resident of Singh-Pura	Male	Married	Sangipur	27-9-64	16-10-64	Ditto
	58. Mst. Jagir Kaur, daughter of Banka, resident of Indri	Female	Married	Dara	Not Known	20-10-64	She appeared herself in the court and gave an affidavit that she was not abducted
	59. Nirmla, daughter of Kundan Lal, resident of Ladwa	Female	Do	Ladwa	16-10-65	3-11-65	Not recovered
					Total cases 4		

9	10	11	12	13
..	..	Surjit Singh	S.I. Santokh Singh A.S.I. Surat Singh H.C. Tej Nath H.C. Niranjan Singh	..
Nabha	Bachna	..	..	..
..	..	..	A.S.I. Harbans Singh S.I. Kehar Singh	..
..	..	Ajit Singh Jagiria	A.S.I. Harbans Singh	..
..	..	..	..	-
..	..	..	A.S.I. Sukhdev Ram H.C. Bhagwan Singh	6965/P, dated 6-11-65 621, P.M. dated 25-11-65 7294,P,dated 25-11-65 7785, P,dated 18-12-65 9,PIII, dated 4-1-66 559, P, dated 4-1-66 13, PIII, dated 5-1-66 433, P, dated 28-1-66 87PIII, dated 2-2-66 Inspector C.I.A. was specially deputed to recover the girl

[Home and Development Minister]

1	2	3	4	5	6	7	8
Pehowa	60. Gurdial Singh, son of Budha Singh, Jat Sikh, resident of Gomthala	Male	Married	Gomthala	1½ yrs. prior to the registration of the case	7-1-66	Not recovered
					Total cases 1		
Rajaund	61. Hari Khomar, resident of Bawyia Khera	Male	Married	Bawiya Khera	23-11-64	25-11-64	Dead body recovered
					Total cases 1		
	62. Hazoor Singh, son of Mangal Singh, resident of Tanotha	Male	Married	Not known	28-4-65	7-5-65	Nil
	63. Mahal Singh, son of Shangara Singh, Jat Sikh, resident of Phoral	Male	Do	Phoral	15-6-65	15-6-65	Recovered on 18-6-65
					Total cases 2		

9	10	11	12	13
..	..	..	S.I. Gurchet Singh	..
..	..	..	..	..
..	..	Angres Singh	..	..
	Karnail Singh Hazoor Singh Isha Singh Gurbachan Singh Chan Singh	..	..	..

(Sd) . .
Superintendent of Police,
Karnal.

To

The Superintendent of Police,
Karnal.

Sir,

Respectfully I beg to submit that my son-in-law Shri Ram Sarup, No. 40326, D.E.G.C.E. Coy. 675 (GREF) C/o 56 A.P.O. is serving in the Army.

That he had left his wife Nirmal Devi with me at Ladwa, tehsil Thanesar for being looked after.

That on 16th October, 1965 my daughter Nirmal Devi, wife of Ram Sarup has been abducted from my house at Ladwa, tehsil Thanesar, district Karnal.

That a report has been duly lodged with the P. S. Ladwa tehsil Thanesar district Karnal.

That as there is a hand of some big and influential person of Ladwa in this offence and so the local police is afraid to arrest him or even investigate the case from him and hence there is no hope of any justice from the local police.

That as my in law Shri Ram Sarup is serving in the Army and is on the war front and it is, therefore, respectfully requested that the Local Officers of District Karnal, i.e., the Deputy Commissioner and the Superintendent of Police may very kindly be ordered to depute some honest and impartial officer to get the wife of Shri Ram Sarup a military personnel recovered at the earliest and justice done.

Thanking you.

Yours faithfully,

Dated

Note.—It is also submitted that two real brothers of said Ram Sarup are also serving in the Army.

Kundan Lal, son of Shri Ram Das, Watch Maker, Thanesar, Ladwa tehsil, district Karnal.

Copy of memorandum No. 6938-PII, dated 28th December, 1965 from the Superintendent of Police, Karnal to the Deputy Commissioner/Inspector General of Police, Karnal.

Please refer to your endorsement No. 456-SP/65/CEA, dated 6th November, 1965 the enclosure to which is returned herewith.

The matter has been got looked into by Shri Guriqbal Singh Bhullar, D.S.P., Hdqrs., and a copy of his report is sent herewith.

Endorsement No. 6939/PII, dated 28th December, 1965 by the same officer

Copy forwarded to the Secretary, District S. S. and A Board, Karnal for information with reference to his No. 4262/DSB, dated 23rd November, 1965 the enclosure to which is returned herewith.

To

The Superintendent of Police,
Karnal.

Application for the help of the receovery of the wife of Military personnel who is serving at front.

Sir,

Respectfully I beg to submit that my son-in-law Ram Sarup is serving in the Army and is on the front. His other two brothers are also serving in the Army.

That my son-in-law had left his wife Nirmal Devi, my daughter with me to look after her in his absence for the time at front.

That I am carrying on watch maker business at Ladwa, tehsil Thanesar.

That on 16th October, 1965 said Nirmal Devi, my daughter, wife of Shri Sarup, my son-in-law serving in front was abducted and there is hand of some big and influential persons of Ladwa and a case was duly got registered with the police, P. S. Ladwa. That the police Ladwa is afraid to get hold of the culprits due to their being big influential persons and hence the case is being delayed or is not being investigated properly.

That I am afraid that the local police is not investigating the case properly and hence I approach your kind honour with the request that immediate enquiry should be conducted through special staff police to reach the ends of justice, so that there should be no injustice in the matter and to the military personnel due to the culprits being big influential persons.

That before this I submitted applications to Shri Lal Bahadur Shastri, Prime Minister, Shri Gulzari Lal Nanda, Home Minister, Comd. Ram Kishan, Chief Minister, S. P., and D. S. P., Karnal on 6th December, 1965 and before this I submitted applications on the subject on 18th October, 1965 but to no action at this time. I have doubt on the following persons:—Charanjit Zakhmi Photographer, Sham Lal General Merchant, Beant Singh Fatwari, Karnail Singh Rangrez, Babu Ram Tea Stall.

It is, therefore, prayed that immediate enquiry may kindly be made through special staff police into the matter and the defaulter be brought to book. The S. H. O.,P.S Ladwa is not taking interest in the matter of the reason not known to us.

Thanking you.

Yours faithfully,

Kundan Lal, son of Shri Ram Dass,
Watch Maker, Ladwa, tehsil Thanesar,
district Karnal,

Dated 11th December, 1965.

Copy of memorandum No. 530/PII, dated 3rd February, 1966 from the Superintendent of Police, Karnal to the Inspector General of Police, Punjab, Chandigarh.

Kindly refer to your memorandum No. 92/H, dated 4th January, 1966 and 52/H dated 1st January, 1966, the enclosures to which are returned herewith.

It relates to case F.I.R. No. 93, dated 3rd November, 1965 u/s 363/366 I.P.C., P. S. Ladwa. Efforts are afoot to recover the abducted girl. A. S. I., Tehla Ram has specially been deputed to investigate the case and recover the abducted girl as early as possible. The complainant is satisfied now.

Copy of memo. No. 553/PII, dated 7th February, 1966 from the Superintendent of Police, Karnal to the Inspector General of Police, Punjab, Chandigarh.

Kindly refer to your memorandum No. 766/H, dated 1st Fabruary, 1966, the enclosure to which is returned herewith.

[Home and Development Minister]

It relates to case F.I.R. No. 93, dated 3rd November, 1965 u/s 363/366 I.P.C., P. S. Ladwa. Efforts are afoot to recover the abducted girl. Inspector. C. I. A. instead of A. S. I. Telu Ram has specially been deputed to investigate the case and recover the abducted girl as early as possible.

Shri Ram Sarup, D. E.S., 40326, Coy. 675 has been informed separately and two copies of the reply sent to him are enclosed.

Copy of memo. No. 554/PII, dated 7th February, 1966 from the Superintendent. of Police, Karnal to Shri Ram Sarup DES No. 40326, Coy. 675 C/o 56 A.P.O.,

Reference your application dated 24th January, 1966 reg. abduction of your wife.

It is to inform you that case F.I.R. No. 93, dated 3rd November, 1965 u/s 363/366 I.P.C. has been registered at P. S. Ladwa and Inspector C. I. A. has specially been deputed to investigate and recover Mst. Nirmal Devi.

To

The Superintendent of Police,
Karnal.

Application for the help of the recovery of the wife of Military personnel who is serving on front.

Sir,

Respectfully I beg to submit that my son-in-law Ram Sarup is serving in the Army and is on the front. His other two brothers are also serving in the Army.

That my son-in-law had left his wife Nirmal Devi my daughter with me to look after her in his absence for the time at front.

That I am carrying on Watch Maker business at Ladwa, tehsil Thanesar.

That on 16th October, 1965 said Nirmala Devi, my daughter, wife of Shri Saroop, my son-in-law serving in front was abducted and there is hand of some big and influential persons of ladwa and was duly got registered with the police, P.S. Ladwa. That the police Ladwa is afraid to get hold of the culprits due to their big and influential persons and hence the case is being delayed and is not being investigated properly.

That I am afraid that the local police is not investigating the case properly and hence I approach your kind honour with the request that immediate enquiry should be conducted through special staff police to reach the ends of justice, so that there should be no injustice in the matter and to the military personnel due to the culprits being big influential persons.

That before this I submitted applications to Shri Lal Bahadur Shastri Prime Minister, Shri Gulzari Lal Nanda, Home Minister Comd. Ram Kishan, Chief Minister, S. P. and D. S. P., Karnal on 17th December, 1965 and before this on 18th October, 1965 and 6th December, 1965 on the subject but to no action at this time. I have doubt on the following persons :—Charanjit Zakhmi Photographer, Sham Lal General Merchant, Beant Singh Patwari, Karnail Singh Rangrez, Babu Ram Tea Stall.

It is therefore prayed that immediate enquiry may kindly be made through special staff police into the mater and the defaulters be brought to book. The S. H. O., Ladwa is not taking interest in the matter of the reason not known to me.

Thanking you.

Yours faithfuly,

Kundan La , son of Shri Ram Dass,
Watch Maker, Ladwa, tehsil Thanesar,
district Karnal.

Dated 3rd February, 1966

बहज़ूर जनाबेआली

डी. एस.पी.साहिब बहादुर, ज़िला करनाल ।

राम सरूप नं, 40326,
डी. इ. एस. मारफत 111 कांस्ट
बी. आर. इ. एफ. (675)
मारफत 56 ए. पी. ओ ।

निवेदन है

जनाबेआली, मैं ने आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में एक अदद दरखास्त अरसाल की थी जो कि 30 नवम्बर, 1965 को आपजी को वसूल हुई। आपने मेरे को कोई पता नहीं दिया कि पी. आर. एम. 494/498 उसके बारे में क्या हुआ है। अभी तक मुलजिम गिरफतार नहीं हुए। मेरे को नौकरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करके मुलज़िमों को और मुलज़मान को गिरफतार किया जावे।

बनाम मुसम्मात निर्मला देवी वल्द कुंदन लाल,
वाच मेकर, कामरेड जख्मी कलाल,
स्टूडियो लाडवा चरंजीत वल्द ना-मालूम,
बाबू राम झीवर, साकन लाडवा, ज़िला करनाल,
तहसील थानेसर, पंजाब, मुलज़मान ।

जनाबे आली,

गुज़ारिश है कि मैं लाडवा, ज़िला करनाल, तहसील थानेसर में शादी कर रखी है। और मैं अर्सा चार साल से मिलट्री में मुलाज़िम हूं और मेरी औरत मेरे सुसराल में अपने बाप के घर पर थी। मेरे को पता नहीं कि वहां से कैसे अगवा हुई है। मेरे को बज़रिया डाक पता चला कि 16 नवम्बर, 1965 को निर्मला देवी मेरी औरत ला पता है। जनाब मेरा घर बरबाद हो गया है, आप मेरे ऊपर मेहरबानी करके निर्मला देवी की तलाश जल्दी से जल्दी करो। पता चला है कि थाना लाडवा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम देश सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी औरत का यह हाल है अब हमारे गैरहाज़री में हमारे घर का ख्याल आपने ही रखना है और मेरे को बराय मेहरबानी पता दिया जाए कि अब तक क्या कारवाई हुई है। मेरी बीवी निर्मला देवी और मुलज़मान को गिरफतार किया जाए।

अर्ज़ी दस्तखत उर्दू,
राम सरूप बकलम खुद
24-1-66

[Home and Development Minister]

Cases registered under the Defence of India Rules in district Karnal

3288. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of cases registered under the Defence of India Rules with the names of the persons against whom those were registered in district Karnal, Police Station-wise during the period from 6th July, 1964 to-date together with the dates thereof in each case ;

(b) the date when the challans were put up in each case in the Courts together with the result of the cases which have been decided by the Courts ;

(c) whether some of the cases mentioned, in part (a) above have been withdrawn, discharged, sent untraced, if so, the details thereof with dates and names in each case, police station-wise ?

Sardar Darbara Singh : (a), (b) and (c) A statement giving required information is enclosed.

STATEMENT

Part 'A'				Part 'B'		Part 'C'		
						Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have been withdrawn discharged, sent as untraced with the dates		
Name of Police Station	Sr. No. of case regstered P.s. wise	Particulars of the cases	Names of the accused	Date of Challan	Result of the case	withdrawn	discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Butana ..	1	FIR No. 90, dated 19th June, 1965, under section 125(2) DIR	Jaswant Singh, Baldev Kishan	..	Cancelled	..	..	..
Shahabad ..	1	FIR No. 19, dated 17th January, 1965, under section 125(2) DIR	Babu Ram ..	..	..	..	..	Untraced report sent on 12th, July 1965
	2	FIR No. 56, dated 30th April, 1965, under section 125(2) DIR	Roshan Lal Kanshi Ram Kashi Ram	4-5-65	Pending in Court	..	..	..
Kaithal ..	1	FIR No. 146, dated 25th August, 1964, under section 125(2) DIR	Washu Ram, son of Kotu Ram	27-10-64	Convicted	..	..	..
	2	FIR No. 211, dated 20th September, 1965, under section 125(2) DIR	Chuni Lal	15-11-65	Pending in Court	..	..	..

[Home and Development Minister]

Part 'A'				Part 'B'		Part 'C'		
						Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have deen withdrawn discharged, sent as untraced with the dates		
Name of Police Station	S. No. of cases registered PS. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the case	withdrawn	discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
City Panipat ..	1	FIR No. 48, dated 26th June, 1965, under section 125(2) DIR	Rattan Chand ..	16-8-65	Pending in court ..	..	..	..
	2	FIR No. 49, dated 26th June, 1965, under section 125(2) DIR	Sant Lal ..	16-8-65	Ditto ..	..	..	..
	3	FIR No. 50, dated 26th June, 1965, under section 125(2) DIR	Om Parkash ..	21-9-65	Ditto ..	..	..	..
	4	FIR No. 51, dated 26th June, 1965, under section 125(2) DIR	Om Parkash ..	16-8-65	Ditto ..	..	..	..
	5	FIR No. 55, dated 29th June, 1965, under section 125(2) DIR	Motan Lal Sabash ..	..	Cancelled ..	..	..	..

		6	FIR No. 77, dated 15th September, 1965 under section 125(2) DIR	Gobind Lal ..	29-10-65	Pending in Court ..	..	..	..	..
		7	FIR No. 78, dated 15th September, 1965, under section 125(2) DIR	Sukandar Lal ..	29-10-65	Ditto	..	..	..	..
		8	FIR No. 75, dated 15th September, 1965, under section 125(2) DIR	Harish Kumar ..	29-10-65	Ditto	..	..	..	..
		9	FIR No. 44, dated 15th September, 1965, under section 125(2) DIR	Jagdish Chand, Balbir Singh	29-10-65	Ditto	..	..	..	..
		10	FIR No. 81, dated 15th September, 1965, under section 125(2) DIR	Ram Parkash ..	29-10-65	Ditto	..	..	..	..
Thanesar	..	1	FIR No. 141, dated 21st September, 1965, under section 125(2) DIR	Munshi Ram ..	10-2-66	Ditto	..	..	..	..
Pehowa	..	1	FIR No. 19, dated 18th January, 1966, under section 125(2) DIR	Sadhu Ram, Lanchi Lal & Sadhu Ram	..	Under investigation	..	..	..	
Ladwa	..	1	FIR No. 96, dated 16th November, 1965, under section 125(2) DIR	Sadhu, Shankar ..	..	Under investigation	..	..	..	
Smalkha	..	1	FIR No. 19, dated 26th March, 1965, under section 125(2) DIR	Kabool Chand, Kishori Lal, Barkha Ram, Phuloo, Balbir, Jogi, Dhuja Ram, Ganga Ram, Zila Singh, Baru, Singh, Khushi Ram, Chatru, Agarsain, Chandu, Dunia, Radha Krishan, Tehl Singh	.. Report sent on 25th February, 1966	Cancelled	..	..	Report sent on 25th February, 1966 for discharge of the accused mentioned at Col. 4, Part 'A'	

[Home and Development Minister]

Part 'A'			Part 'B'			Part 'C'		
Name of Police Station	Sr. No. of case registered P.S. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the case	Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have deen withdrawn discharged, sent as untraced with the dates		
						Withdrawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Smalka—concld								
	2	FIR No. 108, dated 24th December, 1965, under section 125(2) DIR	M/s Narinder Kumar Surinder Kumar	..	Under investigation	..	..	..
	3	FIR No. 9, dated 24th January, 1966, under section 125(2) DIR	Sanohara	..	Ditto	..	..	..
	4	FIR No. 10, dated 24th January, 1966, under section 125(2) DIR	Hargian	..	Ditto	..	..	..
Karnal City ..	1	FIR No. 171, dated 1st August, 1964, under section 125(2) DIR	Agya Ram, Som Parkash	..	Cancelled	..	..	..
	2	FIR No. 172, dated 1st August, 1964, under section 125(2) DIR	Anant Ram ..	..	Cancellation report sent on 18th September, 1965	..	..	..

3	FIR No. 173, dated 1st August, 1965, under section 125(2) DIR	Bal Krishan	..	Cancelled	..	..	..
4	FIR No. 174, dated 1st August, 1964, under section 125(2) DIR	Rahtu Ram, Som Parkash, Man Singh, Hari Ram	..	Cancelled	..	..	..
5	FIR No. 190, dated 26th September, 1964, under section 125(2) DIR	Tara Chand, Ishwar Chand	22-3-65	Pending in Court	..	..	..
6	FIR No. 206, dated 11th September, 1964, under section 125(2) DIR	Raghbir Singh ..	25-11-65	Ditto	..	..	..
7	FIR No. 203, dated 14th September, 1965, under section 125(2) DIR	Puran Chand ..	2-11-65	Ditto	..	..	..
8	FIR No. 204, dated 14th September, 1965, under section 125(2) DIR	Banarsi Dass ..	22-11-65	Ditto	..	..	..
9	FIR No. 205, dated 14th September, 1965, under section 125(2) DIR	Jethu Ram ..	9-12-65	Ditto	..	..	..
10	FIR No. 206, dated 14th September, 1965, under section 125(2) DIR	Lachhman Dass ..	2-11-65	Ditto	..	..	..
11	FIR No. 207, dated 14th September, 1965, under section 125(2) DIR	Ramesh Chander ..	9-12-65	Ditto	..	..	..
12	FIR No. 208, dated 14th September, 1965, under section 125/(2) DIR	Gopal ..	22-12-65	Ditto	..	..	..

[Home and Development Minister]

Part 'A'				Part 'B'		Part 'C'		
Name of Police Station	S. No. cases registered P. S. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Results of the case	Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have been withdrawn discharged sent as untraced with the date: withdrawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gharaunda ..	1	FIR No. 211, dated 28th December, 1964, under section 125(2)DIR	Teka Ram	..	Cancellation report sent on 5th March, 1965	..	..	..
	2	FIR No. 217, dated 28th December, 1964, under section 125(2)/DIR	Sri Ram	..	Cancelled	..	..	..
	3	FIR No. 189, dated 31st October, 1965, under section 125(2)/DIR	Milkha, Masha	10-11-65	Pending in Court	..	..	..
	4	FIR No. 209, dated 2nd December, 1965, under section 125(2)/DIR	Khemi, Kabul	28-1-66	Ditto	..	..	..
	5	FIR No. 210, dated 2nd December, 1965, under section 125(2)/DIR	Murari	23-1-66	Ditto	..	..	..
	6	FIR No. 221, dated 26th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Surjit	23-1-66	Ditto	..	..	..

	7	FIR No. 222, dated 26th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Bhim Sain	23-1-66	Ditto	..	..	..
	8	FIR No. 3, dated 5th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Lila, Ram Sarn, Bilu, Nagina, Nrain Singh, Kakroo	..	Under investigation	..	..	..
	9	FIR No. 31, dated 26th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Chur Singh	..	Cancellation report sent on 9th February, 1966	..	..	..
	10	FIR No. 32, dated 27th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Milkhan Singh	..	Ditto	..	..	..
	11	FIR No. 33, dated 27th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Mangal Singh	..	Ditto	..	..	..
	12	FIR No. 37, dated 3rd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Attar Singh	15-2-66	Pending in Court	..	..	..
	13	FIR No. 38, dated 3rd February, 1966	Lakhmi	15-2-66	Ditto	..	..	..
Sadar Panipat ..	1	FIR No. 137 dated 28th September, 1964, under section 125(2)/DIR	Ram Sarup Ramu.	9-2-65	Ditto	..	..	..
	2	FIR No. 3, dated 4th January, 1965, under section 125(2)/DIR	Sadhu, Jogi, Zila Singh, Badhar, Baljit, Ram Chaudhri, Satiya	10-6-65	Aquitted and case cancelled by the Court on 31st August, 1965	..	..	..
	3	FIR No. 40, dated 2nd February, 1965, under section 125(2)/DIR	Humuara	6-4-65	Convicted	..	..	..
	4	FIR No. 41, dated 2nd February, 1965, under section 125(2)/DIR	Zureen	6-4-65	Do	..	..	..

(Home and Development Minister)

Part 'A'				Part 'B'		Par 'C'		
						Whether some of the cases mentioned in Part 'A' adove have been withdrawn, discharged, sent as untraced with the dates		
Name of Police Station	Serial No. of cases registered P.S. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the case	Withdrawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	FIR No. 102, dated 2nd July, 1965, under section 125(2)/DIR	Jang Bahadur	25-10-65	Pending in Court ..		..	..
	6	FIR No. 103, dated 2nd July, 1965, under section 125(2)/DIR	Sri Ram	25-10-65	Ditto		..	..
	7	FIR No. 165, dated 29th October, 1965, under section 125(2)/DIR	Ramzani, Saminea, Ashraf, Multani	20-1-66	Ditto		..	..
	8	FIR No. 169, dated 5th November, 1965. under section 125(2)/DIR	Zurean	20-1-66	Ditto		..	..
	9	FIR No. 178, dated 8th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Khuda Bux, Zurean, Mir Hussain	20-1-66	Ditto		..	..
	10	FIR No. 175, dated 13th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Ghafoor, Shamga	—	Under investigation ..		..	..

		11	FIR No. 178, dated 19th November, 1965; under section 125(2)/DIR	Nathu, Basu, Ram Dhan	—	Ditto	—	—	—
		12	FIR No. 186, dated 13th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Hirea	—	Ditto	—	—	—
		13	FIR No. 3, dated 4th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Nand Lal, Ali Jang, Sardha	—	Ditto	..	..	..
Guhla	..	1	FIR No. 144, dated 23rd September, 1965, under section 125(2)/DIR	Murari Lal	17-2-66	Convicted	..	..	..
Radhaur	..	1	FIR No. 1, dated 5th January, 1965, under section 125(2)/DIR	Chand Kiran	..	..	..	..	Untraced, report sent on 28th October, 1965
		2	FIR No. 1, dated 5th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Bali Ram	4-2-66	Pending in Court	..	..	..
		3	FIR No. 2, dated 5th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Sham Lal, Nathi	..	Under investigation	..	..	..
		4	FIR No. 4, dated 1st February, 1966, under section 125(2)/DIR	Kantu	..	Ditto	..	..	—
Urlana	..	1	FIR No. 4, dated 3rd January, 1965, under section 125(2)/DIR	Sukhbir Singh	26-2-65	Pending in Court	..	..	..
Indri	..	1	FIR No. 48, dated 28th July, 1964, under section 125(2)/D.I.R.	Bhagat Ram	3-9-64	Acquitted	..	..	..
		2	FIR No. 51, dated 2nd August, 1964, under section 125(2)/DIR	Atam Parkash Tarlok Chand	17-9-64	Cancelled by the court	..	..	..

(Home and Development Minister)

Part 'A'			Part 'B'			Part 'C'		
						Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have been withdrawn, discharged, sent as untraced with the dates		
Name of Police Station	Serial No. of cases registered P. S.-wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the cases	With drawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	FIR No. 52, dated 3rd August, 1964, under section 125(2)/DIR	Bathu, Munshi ..	29-8-64	Pending in Court ..	..	..	..
	4	FIR No. 75, dated 9th October, 1964, under section 125-(2)/DIR	Sadhu	..	Cancellation report sent on 1st July, 1965	..	..	..
	5	FIR No. 90, dated 30th December, 1964, under section 125(2)/DIR	Hari Ram	..	Cancellation report sent on 23rd June, 1965	..	..	..
	6	FIR No. 91, dated 21st November, 1965, under section 125(2)/DIR	Nasibo, Hazar Hunani	..	Under investigation	..	..	..
	7	FIR No. 92, dated 21st November, 1965, under section 125(2)/DIR	Rashid	..	Ditto	..	..	..

8	FIR No. 93, dated 21st November, 1965, under section 125(2)/DIR	Amrit	..	Ditto	..	..	..
9	FIR No. 97, dated 23rd December, 1965, under section 125(2)/DIR	Ved Pal	..	Ditto	..	..	..
10	FIR No. 99, dated 26th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Jiva Lal	..	Ditto	..	..	..
11	FIR No. 21, dated 15th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Lukar Hunani	..	Ditto	..	..	..
12	FIR No. 35, dated 20th February, 1966, under section 125(2)/DIR	Tara	..	Ditto	..	..	..
13	FIR No. 42, dated 22nd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Inder	..	Ditto	..	..	..
14	FIR No. 43, dated 22nd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Ahmedu	..	Under investigation	..	..	..
15	FIR No. 44, dated 22nd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Bani	..	Ditto	..	..	..
16	FIR No. 45, dated 22nd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Ratti Ram	..	Ditto	..	..	..
17	FIR No. 51, dated 22nd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Ajmer	..	Ditto	..	..	..
18	FIR No. 52, dated 22nd February, 1966, under section 125(2)/DIR	Muni Lal	..	Ditto	..	..	..

(Home and Development Minister)

Part 'A'				Part 'B'		Part 'C'		
						Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have been withdrawn discha;ged, sent as untraced with the dates		
Name of Police Station	Serial No. of cases registered P. S. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the cases	With drawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sadar Karnal ..	1	FIR No. 341, dated 15th November, 1964, under section 125(2)/DIR.	Tara Chand, Parma Nand	..	..		Discharged, on 9th November, 1965	Untraced report sent on 9th November, 1965
	2	FIR No. 47, dated 11th February, 1965, under section 125(2)/DIR	Ran Singh, Sukhi Ram	30-4-65	Pending in Court	..	..	..
	3	FIR No. 82, dated 23rd March, 1965, under section 125(2)/DIR	Shibir, *Mst.* Antu, Kamla, *Mst.* Sabri and Azizo	1-6-65	Ditto	..	..	..
	4	FIR No. 69, dated 15th March, 1965, under section 125(2)/DIR	Hari Chand ..	1-6-65	Convicted	..	..	..
	5	FIR No. 320, dated 14th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Kartar ..	23-12-65	Pending in Court	..	..	..

6	FIR No. 328, dated 21st November, 1965, under section 125(2)/DIR	Kishan Chand	4-2-66	Pending in Court	..	..	..	..
7	FIR No. 330, dated 21st November, 1965, under section 125(2)/DIR	Daulat Ram	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
8	FIR No. 331, dated 21st November, 1965, under section 125(2)/DIR	Ishar Singh	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
9	FIR No. 334, dated 25th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Puran Singh	..	Under investigation	..	..	..	..
10	FIR No. 343, dated 29th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Saghar	4-2-66	Pending in Court	..	..	..	..
11	FIR No. 344, dated 29th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Sadhu	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
12	FIR No. 345, dated 29th November, 1965, under section 125(2)/DIR	Ram Singh	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
13	FIR No. 350, dated 8th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Surtu	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
14	FIR No. 351, dated 8th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Phul Singh	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
15	FIR, No. 352, dated 8th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Karta Ram	4-1-66	Ditto	..	..	..	..
16	FIR No. 369, dated 29th December, 1965, under section 125(2)/DIR	Neat Ram	..	Under investigation	..	..	..	..

[Home and Development Minister]

Part 'A'				Part 'B'		Part 'C'		
						Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have been withdrawn, discharged, sent as untraced with the dates		
Name of Police Station	Serial No. of cases registered P.S. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the cases	Withdrawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	FIR No. 341, dated 29th November, 1964, under section 125(2)/DIR	Dalail Singh ..	4-2-66	Pending in Court	..	..	..
	18	FIR No. 7, dated 5th January, 1966, under section 125(2)/DIR	..	..	Under investigation	..	..	..
	19	FIR No. 8, dated 6th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Raghbir Singh ..	..	Ditto ..	..	..	..
	20	FIR No. 9, dated 6th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Ram Kishan ..	..	Ditto ..	..	..	..
	21	FIR No. 10, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Sowarn ..	..	Ditto ..	..	..	..
	22	FIR No. 11, dated 7th January, 1966 under section 125(2)/DIR	Punna ..	..	Ditto ..	..	..	..

23	FIR No. 12, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Khema	..	..	Under investigation		..	..	..
24	FIR No. 14, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Hari Ram	..	..	Ditto	..	..	..	..
25	FIR No. 15, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Sant Singh	..	..	Ditto		..	..	..
26	FIR No. 16, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Ajmer Singh	..	..	Ditto	..	..	..	..
27	FIR No. 19, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Jaswant Singh	..	..	Ditto	..	..	..	..
28	FIR No. 21, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Hari Chand	..	..	Ditto	..	..	..	..
29	FIR No. 22, dated 7th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Sujhan	..	..	Ditto	..	..	..	..
30	FIR No. 53, dated 17th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Lila	..	4-2-66	Ditto	..	..	..	..
31	FIR No. 63, dated 27th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Amar Singh	..	..	Ditto	..	..	..	..
32	FIR No. 64, dated 27th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Ram Kishan	..	..	Ditto	..	..	..	..
33	FIR No. 65, dated 27th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Katali	..	..	Ditto	..	..	..	..

[Home and Development Minister]

Part 'A'				Part 'B'		Part 'C'		
Name of Police Station	Serial No. of cases registered P.S. wise	Particulars of the case	Names of the accused	Date of Challan	Result of the case	Whether some of the cases mentioned in Part 'A' above have been withdrawn discharged, sent as untraced with the dates		
						With drawn	Discharged	Untraced
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	FIR No. 68, dated 29th January, 1966, under section 125(2)/DIR	Jindo	..	Under investigation	..	..	..
	35	FIR No. 88, dated 8th February, 1966, under section 125(2)/DIR	Dharam Paul	..	Ditto	..	..	..
	36	FIR No. 111, dated 24th February, 1966, under section 125(2)/DIR	Anutu Lal	..	Ditto	..	..	..
	37	FIR No. 112, dated 24th February, 1966, under section 125(2)/DIR	Singh Ram	..	Ditto	..	..	..
	38	FIR No. 113, dated 24th February, 1966, under section 125(2)/DIR	Charan Singh	..	Ditto	..	..	..
	39	FIR No. 114, dated 24th February, 1966, under section 125(2)/DIR	Kala	..	Ditto	..	..	.

Smugglers arrested in district Karnal

3289. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of persons found to be involved in smuggling and arrested as a result thereof in district Karnal during the period from 6th July, 1964 todate, Police Station-wise together with their names and the dates of arrest in each case ;

(b) the names of those out of the persons mentioned above whose challans have been put up in the courts, with the dates when these were put up together with the result in each case ;

(c) the names of those from among the persons referred to in part (a) above who were discharged by the Court and the names of those whose cases have been withdrawn or have been sent up as untraced with the date in each case, along with the dates when the report for discharge of the said cases was submitted by the police in the Courts ?

Sardar Darbara Singh : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Hon'ble Member. The reply can be furnished regarding any specific point/case, if called.—

Construction of Shamshar-Chawai-Kandaghai Road, tehsil And, district Kulu

3291. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the date when the construction of the Shamshar-Chawai-Kandaghai Road in tehsil Ani, district Kulu was sanctioned together with the amount sanctioned for the purpose ;

(b) the date when the construction of the said road was taken in hand, the name of the Department which is constructing it and the present stage of its construction ;

(c) whether the accounts of the construction work on the road have ever been checked ; if so, by whom ; if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that the Divisional Forest Officer, Kulu sanctioned the Muster Roll expenditure in excess of his authority, if so, the details of the amount so sanctioned by him and the limit up to which he is competent to sanction such expenditure ;

(e) whether any complaints have come to the notice of the Government/Minister that the amount sanctioned for the construction of the said road has not been utilized properly ; if so, whether any enquiry into the matter has been conducted ;

(f) whether it has come to the notice of the Government that the original alignment of the said road has been changed in such a manner that the houses and orchards of private individuals have been adversely affected by it ?

Shri Chand Ram : (a) (i) 26th May, 1965.

(ii) Rs 3.50 lakhs.

(b) (i) June, 1965.

(ii) Forest Department, Punjab.

(iii) About 8 miles of the road have been constructed and the work is in progress.

[Welfare and Justice Minister]

(c) Yes, by Divisional Forest Officer, Seraj Forest Division.

(d) No. The question does not arise.

(e) No.

(f) Yes. In order to improve the gradient for vehicular traffic.

Trade Unions registered under the Indian Trade Union Act, 1926

3293, Comrade Jangir Singh Joga : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of Trade Unions of workers registered in the Punjab State under the Indian Trade Union Act, 1926, stating the total membership of each and the Central Trade Union Organisation to which each of them is affiliated ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Information regarding membership and Central Affiliation of Trade Unions in each case, i.e., in respect of 767 Trade Unions is not being supplied as the time and labour involved therein would not be commensurate with the expected benefit. However, the remaining information is given as under :—

Serial No.	Name of the Central Organisation	No. of registered Unions	Membership of Unions submitting returns
1	INTUC ..	217	47,299
2	AITUC ...	60	19,151
3	B.M.S. ...	23	3,490
4	H.M.S. ..	10	1,461
5	Un-affiliated ..	457	39,772
	Total ...	767	111,173

Disputes between Land-owners and Tenants

3295. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Revenue with reference to reply to Starred Question No. 3904, included in the list of Questions for 17th September, 1963, be pleased to state—

(a) whether the suggestion which according to parts (a) and (b) of the said reply was under examination, has finally been examined ; if so, when, with what result and the name and designation of the authority that examined it ;

(b) the designation of the authorities who went through the applications of Shri Amar Singh referred to in the said reply ?

Sardar Harendar Singh Major : (a) The suggestions made by Shri Amar Singh have been considered and it has not been found necessary to effect any amendment in the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, on that account.

(b) Additional Secretary, Revenue and Revenue Minister had dealt with Shri Amar Singh's applications.

Punjab State Small Industries Corporation

3297. **Comrade Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the date when the Punjab State Small Industries Corporation was set up together with the names of its Directors or the members of its managing Committee ;

(b) the names of the articles/commodities/items in which the said Corporation deals ;

(c) the total amount which Government/private individuals have invested in the said Corporation ;

(d) whether the said Corporation charges any commission on the items it imports and distributes and also on the items it collects/purchases for export ; if so the amount of Commission/profit it has earned since the date of its inception year-wise ;

(e) whether the Government is charging any interest from the Corporation on the amount invested by it therein or gets any share in the profit/commission ; if so the details thereof together with designations of the authorities who supervise the work of the said Corporation and the details of the reports submitted in this respect. if any, year-wise ?

Shri Ram Kishan : (a) The Corporation was incorporated on 17th March, 1962. The names of the Directors are :—

(1) Shri R.S. Talwar, I.A.S., Industries and Supplies Commissioner and Secretary to Government, Punjab, Industries and Food and Supplies Departments — Chairman

(2) Shri K.S. Narang, I.A.S., Secretary to Government, Punjab, Finance Department. .. Director

(3) Shri Paramjit Singh, I.A.S., Director of Industries, Punjab. .. Director

(4) Shri G.R. Bhai, Joint Director of Industries, Punjab. .. Director

(5) Shri B.M. Sharma, Joint Director of Industries, Punjab. .. Director

(6) Shri B.M. Gupta, Additional Controller of Stores, Punjab. .. Director

(7) Shri J.P. Gupta, .. Managing Director

(b) All steel itmes like H.R. sheets, C.R. Sheets, B.P. Sheets, G.P. Sheets, G.C. Sheets, Tinplate, Cut-down, Waste waste and Prime Quality produced by Messrs Hindustan Steel Limited and Tata Iron and Steel Company, Calcutta, imported Steel like stainless steel sheets, high carbon sheets and high speed steel obtained directely through the Minerals and Metal Trading Corporation, Pig Iron, Coal, Copper Ingots, Copper wire,

[Chief Minister]
Bar Rod, Zinc, Tin Ignots, read, Nickle, Antimony, Aluminium Chemicals, Dyes, Molasses, Caustic Soda, Worsted Woollen Yarn, Cotton Yarn, Leather Art Silk Yarn, indigenous and imported Kuth etc. and any other raw-material or industrial produce, the handling of which may be considered in the interest of small scale industry of Punjab.

(c) A sum of Rs. 20 lakhs has been invested by the Punjab Government in the form of 20,000 equity shares of rupees one hundred each. No private individual has made any investment in the capital of the Corporation.

(d) Yes. The Commission on the imported items is fixed in accordance with the provisions contained in the various Import Control Orders in case of controlled items according to the revelevant Control Orders and in case of decontrolled items accrording to the Market position but usually lower than that charged by the other importers and stockists on items of export, service charges are levied at 5 per cent only. The year-wise profits as approved by the Statutory Auditors appointed by the Company law Administration, Government of India and also Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India are given below :—

Year		*Net profit before tax* Rs
1962-63	...	2,25,185
1963-64	..	6,46,307
1964-65	..	6,51,489

(e) No interest is payable on share capital contributed by Government under the Company Law. The Government is only entitled to dividend and the entire profit after payment of taxes and retaining a small amount as reserve is ploughed back to the Revenues of the State in the form of dividend. The details of the dividends declared by the Corporation during the first three years of its working are given hereunder :—

Year		*Dividend percentage*	*Rupees*
1962-63	..	5.5	1,10,000
1963-64	..	9.5	1,90,000
1964-65	..	10.0	2,00,000

The affairs of the Company are managed through a Board of Directors headed by the Industries Commissioner as its Chairman. The day-to-day work of the Company is supervised by Shri J.P. Gupta, Managing Director of the Corporation.

In accordance with Section 619 of the Companies Act the Corporation has already submitted to Government annual reports together with supplementary comments of the Auditor General for the first three accounting years.

Land purchased by the Market Committee, Karnal

3298. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the total area of land purchased by the Market Committee, Karnal at different times and in the different places during the period from 1st March, 1961 to date, the rate at which it was purchased and the total amount paid in each case if

(b) whether the lands referred to in part (a) above were purchased through brokers or direct by the Market Committee ; if through brokers their names and the amount of commission

paid, in that behalf, if it was purchased directly by the Market Committee, the names of the officials or members of the Market Committee who negotiated with the sellers in this respect ;

(c) the names of the sellers in the case of each piece of land purchased by the said committee together with the date of registration of each ;

(d) whether it is a fact that the State Marketing Board or the Agriculture Department/Punjab Government has issued a notice/show-cause notice for the recovery of certain amount from the Chairman of the Market Committee referred to in part (c) above, on the ground that the purchases made by the Market Committee were not bona fide; deals, if so, the date of issue of the notice, the name of the chairman to whom it has been issued and a copy of the notice together with a copy of the reply sent by the Chairman of the Market Committee thereto be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) The Market Committee, Karnal, purchased only five Kanals and four Marlas of land on 2nd November, 1962 at the rate of Rs. 400 per Marla and paid Rs. 50,073.50 Paise, in all.

(b) The land was purchased directly. A sub-committee consisting of Shri Nishan Singh, Chairman, Market Committee and Sarvshri Daya Singh, Amrik Singh and Khushi Ram, Members of Market Committee, Karnal negotiated with the sellers.

(c) M/s Puran Singh and Company, Karnal. The deed was registered on 2nd November, 1962.

(d) A show cause notice based on a number of grounds for the recovery of Rs. 50,073.50 Paise has been issued to Shri Nishan S,ngh, Chairman, Market Committee, Karnal by the Secretary, State Agricultural Marketing Board, Chandigarh, and the matter is under examination in the office of the State Agricultural Marketing Board. It will not be in the public interest to disclose the contents of the reply received from Shri Nishan Singh.

Lajinder Co-operative Farming Society, Ferozepore

3299, **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any Co-operative Society known as Lajinder Co-operative Farming Society registered in district Ferozepore; if so, the date when it was registered together with the names of members and the total area of land under its cultivaion as per records of the Co-operative Department, district Ferozepore ?

Chaudhri Rizaq Ram : There is no Co-operative Society registered in the Ferozepore district known as Lajinder Co-operative Farming Society. As such the question of supplying any information does not arise.

Construction of Abohar-Hindu Mal kot Road in district Ferozepore

3300. **Chaudhri Satya Dev, :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any decision has been taken regarding the construction of a road from Abohar to Hindu Mal Kot in district Ferozepore ; if so, the names of the villages which the said road is expected to serve, the length of the road, the approximate expenditure to be incurred thereon and the time by which the work on it is likely to be started and completed ?

Chaudhri Ranbir Singh, : Yes. Construction of Abohar-Hindu Mal Kot Road has been decided to be taken up in lieu of some saving in length against the scheme of construction of a road from Fazilka to Hindu Mal Kot Road. The alignment for Abohar Hindu-Mal Kot road is yet to be finalized and is being surveyed. The length of the road is expected to be 10 miles and it is likely to cost Rs. 8.00 lacs. The construction work is planned to be started shortly and the entire construction is likely to be completed during the 4th Plan subject to availability of funds.

Shops and Commercial Establishments Registered at certain Places.

3301. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of shops and commercial establishments registered under the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958, as on 31st December, 1965 at Patiala, Sirhind, Rajpura, Gobindgarh, Bassi-Pathana, Nabha, Samana and Banur separately ?

Chaudhri Rizaq Ram :

Name of Station	No. of establishments registered under Shops Act, upto 31st December, 1965
Patiala ..	4,718
Sirhind ..	685
Rajpura ..	1,027
Gobindgarh ..	488
Bassi-Pathana ..	454
Nabha ..	1,603
Samana .	889
Banur .	Shops Act,

Insured persons working in factories etc., at Patiala and other places.

3302. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of persons insured under the Employees State Insurance Scheme at Patiala, Rajpura, Bahadurgarh and Gobindgarh as on 31st December, 1965 ?

Chaudhri Rizaq Ram : The requisite information is as under —

Patiala .	1,500
Rajpura .	3,300
Bahadurgarh .	6,500
Gobindgarh .	2,500

Contribution made by Employers/Employees under the Employees State Insurance scheme at Gobindgarh and other Places.

3303. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the amount contributed by the Employers and Employees separately under the Employees State Insurance Scheme, during the year 1965, at Gobindgarh, Patiala, Rajpura and Bahadurgarh ?

Chaudhri Rizaq Ram : The requisite information is given as under :—

Station	Employers Special contribution	Employees Contribution
Gobindgarh	74,424·22	60,000·13
Patiala	43,445·93	33,508·44
Bahadurgarh	9,605·60	13,954·87
Rajpura	89,268·97	66,773·78

Local Committees formed under the Employees State Insurance Scheme at Patiala etc.

3304. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any Local Committees have been formed at Patiala, Rajpura and Gobindgarh under the Employees State Insurance Scheme ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the number of meetings so far held by these Committees Centre-wise ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) The statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Name of Station	Number of meetings so far held by the Local Committee
Patiala	Nil.
Rajpura	One
Gobindgarh	One

Construction of Hospitals under the Employees State Insurance Scheme at Patiala etc.

3305. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the latest position regarding the cases of construction of the hospitals under the Employees State Insurance Scheme at Patiala, Rajpura, Gobindgarh and Bahadurgarh ?

Chaudhri Rizaq Ram : There is no proposal for constructing hospitals at Patiala, Rajpura, Gobindgarh and Bahadurgarh (District Patiala), under the Employees State Insurance Scheme. However, dispensaries are proposed to be constructed at all these places under the Employees State Insurance Scheme. A statement showing the latest position of each dispensary is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Patiala.—Land is being purchased from the Forests Department which department has since agreed to sell it for the Employees State Insurance Dispensary.

Rajpura.—Land has been purchased from the Pepsu Township Development Board. The plans/estimates of the Dispensary are under preparation.

Gobindgarh.—Land is being purchased from the Forests Department which department has since agreed to sell it for the Employees State Insurance Dispensary.

Bhadurgarh (District Patiala).—Necessary survey for land is being carried out.

Staff in Dispensaries under the Employees State Insurance Scheme

3306. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the full strength of the staff has not yet been posted in the dispensaries opened under the Employees State Insurance Scheme at Patiala, Gogindgarh, Rajpura and Bahadurgarh ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons therefor and the steps, if any, taken in this behalf ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) There is overall shortage of Medical and Para-Medical (technical personnel all) over the country and especially in Punjab. However, best efforts are always made to recrurit and post the staff as sanctioned in the Employees State Insurance Dispensaries as soon as the candidates become available. Non-technical staff such as clerks, peons, Lady Health Visitors, Auxillary Nurses, Midwives are in position almost in full strength.

Cost of living Index for the working class at Patiala and Ludhiana

3307. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to lay on the Table of the House a statement showing the cost of Living Index for the working classes in respect of Patiala and Ludhiana, month-wise during the year 1965 ?

Sardar Ajmer Singh : A statement showing the Consumer Price Index numbers (previous nomenclature "cost of Living Index numbers") for the working class at Patiala and Ludhiana for the year 1965, is laid on the Table of the House.

Statement showing Consumer Price Index Numbers for the working class at Patiala and Ludhiana during the year 1965.

Month and Year		*Patiala (Base-1952-53—100)	†Ludhiana (Base-1949—100)
January, 1965	..	172	139
February, 1965	..	168	136
March, 1965	..	168	135
April, 1965	..	171	136
May, 1965	..	164	134
June, 1965	..	165	137
July, 1965	..	171	139
August, 1965	..	174	139
September, 1965	..	176	139
October, 1965	..	174	137
November, 1965	..	173	141
December, 1965	..	174	‡N.A.

Sheds in the Industrial Estates at Patiala and Rajpura

3308. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of sheds in the Industrial Estates at Patiala and Rajpura, the number of those which are in use at present and position in respect of the rest ?

Shri Ram Kishan :

		Rajpura	*Patiala*
Total sheds	..	10	20
Sheds in use	..	..	8
Vacant	..	10	12

Students in Industrial Training Institute at Patiala, etc.

3309. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of students at present in the Industrial Training Institutes at Patiala, Nabha, Bassi Pathana and Rajpura together with the trades for which they are receiving training ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the information is enclosed.

*Compiled by the Economic and Statistical Organisation, Punjab.
†Compiled by the Labour Bureau, Government of India.
‡Not yet received from the Director, Labour Bureau, Government of India.

[Chief Minister]

Statement regarding students in Industrial Training Institutes at Patiala, etc.

Strength of the Trainees

Serial No.	Name of trade		I.T.I. Bassi Pathana	I.T.I. Nabha	I.T.I. Rajpura	I.T.I. Patiala
1	Blacksmith	..	16	..	..	6
2	Carpenter	..	..	32	7	6
3	Draughtsman (Civil)	...	..	..	..	30
4	Draughtsman (Mechanical)	..	..	..	..	32
5	Electrician	..	32	32	29	50
6	Electroplator	...	13	..	...	6
7	Fitter	..	96	32	49	86
8	Grinder	..	..	..	..	16
9	Wireman	...	..	32	...	33
10	Mechist	..	24	..	..	26
11	Mechanic Refrigerator	..	..	..	..	7
12	Mechanic Instruments	...	32	..	..	..
13	Mechanic Motor	..	..	..	13	27
14	Mechanic Radio	..	..	..	..	26
15	Pattern Maker	..	15	...	10	6
16	Mechanic Tractor	..	..	..	..	33
17	Turner	...	24	24	28	52
18	Moulder	...	..	12	29	12
19	Painter	..	..	..	13	..
20	Hand Composition	...	..	..	8	..
21	Stenography	...	..	..	..	29
22	Cutting and Tailoring	...	17	..	19	...
23	Printing Machine Operator	...	..	..	6	..
	Total	..	269	164	211	495

Profit and Loss Account of the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala

3310. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to lay on the Table of the House a statement

showing the balance sheets along with the profit and loss Account of the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala for the years 1956-57 to 1964-65 ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The time and labour involved in supplying the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. Information, will however, be supplied on any particular point, if sought.

The financial review of the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala is annually laid on the Table of both Houses of the State Legislature and is open to inspection by anybody. Accounts for the year 1964-65 are still under audit with the Accountant-General, Punjab.

Vehicles with Pepsu Road Transport Corporation, Patiala, as on 31st December, 1965

3311. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the total number of vehicles owned by the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala as on 31st December, 1965, stating the make of each ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon :

(a) Total fleet strength as on 31st December, 1965	..	234
(b) Leyland make vehicles ordinary	..	72
(c) Leyland make Deluxe coach	..	3
(d) Dodge/Fargo with P-6 engine	..	123
(e) Dodge/Fargo with Meadow engine	..	36

Recommendations of the Committees fixing Minimum rates of Wages in Public Transport and Iron and Steel Re-rolling Industries in the State

3312. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the latest position regarding the recommendations made by the Committee constituted for fixing minimum rates of wages in respect of the Public Transport and Iron and Steel Re-Rolling Industries in the State ?

Chaudhri Rizaq Ram : Recommendations received from the Committees constituted for fixing minimum rates of wages in respect of the Public Transport and Steel Re-Rolling Industry in the State are under consideration of Government.

Proceedings of the Meeting of the Committees appointed by the Government to advise on the Fixation of Minimum Wages for the Workers

3313. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to lay on the Table of the House copies of the proceedings of the meetings held by the Committees appointed by the Government during the years 1964 and 1965 to advise on the question of fixation of minimum rates of wages for the workers ?

Chaudhri Rizaq Ram : Fifteen Committees were appointed by Government during the years 1964 and 1965 to advise Government on the question of fixation of minimum rates of wages for the workers in different industrial employments. The time and labour involved in supplying copies of the proceedings of the meetings held by the Committees will not be commensurate with the possible benefit to be obtained.

Labour Disputes in Patiala District

3314. Comrade Bhan Singh Bhaura: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of labour disputes raised in the Patiala District during the years 1964 and 1965 along with the names of the Unions/Establishments concerned and the result thereof in each case ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Industrial Disputes raised in Patiala District during the year 1964

Serial No.	Name of the Establishment	Name of the Union	Result
1	2	3	4
1	Ramjidas-Harbans Lal, Sewing Machine, Bassi Pathana	Sewing Machine Workers Unions, Bassi Pathana	Referred for adjudication
2	Green Bus Service, Patiala ..	District Transport Workers Union, Patiala	Filed by Government
3	Asha Ram-Khushi Ram, Iron and Steel Rolling Mills, Amloh	Labour Union, Gobindgarh	Referred for adjudication
4	Gobind Ram-Ghashi Ram, Flour and Oil Mills, Patiala	Flour Mills Workers Union, Patiala	Withdrawn
5	Escorts (P) Ltd., Bahadurgarh	Engineering Workers Union, Patiala	Settled mutually
6	Parshotam Jaura Bhai, Patiala	cigarette-Bidi Sales Union, Patiala	Settled
7	Goetze India (P) Ltd., Bahadurgarh	Engineering Workers Union, Patiala	Withdrawn
8	Municipal Committee, Patiala	Municipal Employees Union, Patiala	Do
9	Bee Gee Group Industry, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Filed
10	Navyug Trading Corporation, Patiala	Ditto	Withdrawn
11	Hindustan Milk Food Manufacturing, Nabha	Milk Food Workers Union, Nabha	Adjudication
12	Samana Roadways, Patiala ..	District Transport Workers Union, Patiala	Withdrawn
13	Imperial Electrical Industries, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Settled
14	Bee Gee Group Industry, Patiala	Ditto	Filed

Serial No.	Name of the Establishment	Name of the Union	Result
1	2	3	4
15	Chief Engineers, Punjab P.W.D., B.&R., Patiala	Simla Himachal Pradesh, Punjab P.W.D., Workers Union, Kandaghat	Pending
16	Bee Gee Group Industry, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Filed
17	Municipal Committee, Nabha	Municipal Employees Union, Nabha	Settled
18	Goetze India (P) Ltd., Bahadurgarh	Engineering Workers Union, Patiala	Do
19	Chief Engineers Punjab, P.W.D. B.&R., Patiala	Simla Himachal Pradesh, Punjab, P.W.D. Workers Union, Kandaghat	Pending
20	Ramjidass-Harbans Lal, Sewing Machine Works, Bassi Pathana	Sewing Machine Workers, Union, Bassi Pathana	Withdrawn
21	Charanji Lal and Sons, Bassi Pathana	Ditto	Do
22	Pollu Ram-Hans Raj, Iron and Steel Rolling Mills, Bassi Pathana	Labour Union, Gobindgarh	Filed
23	Navyug Trading Corporation, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Do
24	Hindustan Milk Food Manufacture, Nabha	Milk Food Workers Union, Nabha	Adjudication
25	Green Hotel, Patiala ..	Hotel Workers Union, Patiala	Do
26	Pollu Ram-Hans Raj, Iron & Steel Rolling Mills, Bassi Pathana	Labour Union, Gobindgarh	Settled
27	Ditto ..	Ditto	Do
28	Bee Gee Group Industry, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Withdrawn
29	Samana Roadways, Patiala	District Transport Workers Union, Patiala	Do
30	Ditto	Ditto	Adjudication
31	Navyug Trading Corporation, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Do
32	Raj Industries, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Settled
33	Green Bus Service, Patiala	District Transport Workers Union, Patiala	Do

37

Serial No.	Name of the Establishment	Name of the Union	Result
1	2	3	4
34	Ramji Dass-Harbans Lal, Sewing Machine Works, Bassi Pathana	Sewing Machine Workers Union, Bassi Pathana	Adjudication
35	Guru Nanak Oil and Flour Mills, Nabha	Trade Employees Union, Patiala	Do
36	Navyug Trading Corporation, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Arbitration
37	Kulwant Rai-Ram Kishan, Distributor, National Tobacco Co., Patiala	Cigarette-Bidi Sales Men Union, Patiala	Settled
38	Bansal Tool Co., Patiala ..	Bansal Tool Co., Workers Union, Patiala	Adjudication
39	Mangal Engineering Works, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Settled
40	Hindustan Milk Food Manufacture, Nabha	Milk Food Workers Union, Nabha	Pending
41	Madho Ram and Sons, Patiala	Cigarette-Bidi Sales Men Union, Patiala	Settled
42	Hindustan Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Labour Union, Gobindgarh	Withdrawn
43	Swastika Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Settled
44	Hira Singh-Hazara Singh, Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Do
45	Gobindgarh Roadways, Gobindgarh	District Transport Workers Union, Patiala	Adjudication
46	Gobind Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Labour Union, Gobindgarh	Do
47	Gobind Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Labour Union, Gobindgarh	Adjudication
48	Hira Singh-Hazara Singh, Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Adjudication. Filed
49	Shri Ganesh Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Arbitration
50	Gupta Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Filed
51	Shree Ganesh Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Arbitration
52	Swastika Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Adjudication

Serial No.	Name of the Establishment	Name of the Union	Result
1	2	3	4
53	Seth Textile Mills, Gobindgarh	Textile Workers Union, Gobindgarh	Settled
54	Shree Ganesh Iron and Steel Rolling Mills, Gobinagarh	Labour Union, Gobindgarh	Arbitration
55	Ditto ..	Ditto	Do
56	Gupta Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Filed
57	Ditto ..	Ditto	Mutually settled
58	Guru Arjan Iron and Steel Rolling Mills, Godinagarh	Ditto	Settled
59	Gupta Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Filed
60	Guru Arjan Iron and Steel Rolting Mills, Gobindgarh	Ditto	Settled
		1965	
1	Indian Home Pipe Co. Ltd., Rajpura	Union Home Pipe Workers Union, Rajpura	Settled
2	Basal Tool Co., Patiala ..	Basal Tool Workers Union Patiala	Do
3	Capital Cinema, Patiala ..	Trade Employees Union, Patiala	Withdrawn
4	Ramjidass Harbans Lal, Sewing Machine Works, Bassi Pathana	Sewing Machine Workers Union, Bassi Pathana	Filed
5	Escorts Ltd., Bahadurgarh ..	Engineering Workers Union, Patiala	Filed
6	Bhagwan Finance Corporation, Rajpura	Bhagwan Finance Mazdoor Union, Rajpura	Adjudication
7	Basal Tool Co., Patiala ..	Basal Tool Workers Union, Patiala	Do
8	Navyug Trading Corporation, Patiala	Engineering Workers Union, Patiala	Do
9	Municipal Committee, Patiala	Municipal Employees Union, Patiala	Pending
10	Municipal Committee, Patiala	Sweepers Union, Patiala	Settled
11	Ramjidass-Harbans Lal, Sewing Machine Works, Bassi Pathana	Sewing Machine Workers Union, Bassi Pathana	Adjudication
12	Municipal Committee, Patiala	Sweepers Union, Patiala	Pending

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the Establishment	Name of the Union	Result
1	2	3	4
13	Industrial Cables (India), Rajpura	Industrial Cables Mazdoor Union, Rajpura	Withdrawn
14	Navyug Trading Corporation, Patiala	Engineering Workers Union Patiala	Adjudication
15	Industrial Cables (India), Rajpura	Industrial Cables Mazdoor Union, Rajpura	Settled
16	Industrial Cables (India), Rajpura	Industrial Cables Mazdoor Union, Rajpura	Pending
17	Pepsu Roadways Transport Corporation, Patiala	P.R.P. Corporation Workers Union, Patiala	Adjudication
18	Municipal Committee, Patiala	Sweepers Union, Patiala	Pending
19	Patiala Biscuit Factory, Manufacturers, Rajpura	Patiala Biscuit Factory Workers Union, Rajpura	Do
20	Industrial Cables (In dia), Rajpura	Industrial Cables Workers Union, Rajpura	Do
21	Patiala Co-operative Consumers Store, Patiala	Trade Employees Union, Patiala	Do
22	Modi Wire Products, Gobindgarh	Engineering Workers Union, Patiala	Settled
23	Guru Arjan Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Labour Union, Gobindgarh	Do
24	Gopal Mills, Gobindgarh ..	Ditto	Do
25	United Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh	Ditto	Do
26	Button Lal Iron and Steel Mills, Gobindgarh	Ditto	Do
27	Modi Wire Products, Gobindgarh	Engineering Workers Union Patiala	Do
28	Punjab Iron and Steel Mills, Gobindgarh	Labour Union, Gobindgarh	Do
29	Iron Factory, Gobindgarh ..	Ditto	Do
30	Button Lal Aggarwal Iron and Steel Mills, Gobindgarh	Ditto	Do
31	Gopal Iron and Steel Industries, Gobindgarh	Ditto	Pending

References made from Patiala District to Industrial Tribunals/Labour Courts for adjudication

3315. Comrade Bhan Singh Bhaura: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to lay on the Table of the House a list of references made during the year 1964-65, from Patiala district for adjudication to the Industrial Tribunal/Labour Courts?

Chaudhri Rizaq Ram: A statement is laid on the Table of the House.

Statement of references made from Patiala District to Industrial Tribunals Labour Courts)for adjudication during 1964-1965

The cases of the following establishments were referred for adjudication to Industrial Tribunal/Labour Courts.

During 1964

1. Gobindgarh Roadways Private Ltd., Gobindgarh.
2. Green Hotel, Patiala.
3. Green Hotel, Bar and Restaurant, Patiala.
4. Gobind Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh.
5. Hindustan Milk Food Manufacturers, Nabha.
6. Hindustan Milk Food Manufacturers, Nabha.
7. Asa Ram Khushi Ram Iron and Steel Rolling Mills, Amloh.
8. Ramji Dass Harbans Lal Sewing Machine Works, Bassi Pathana.
9. Basal Tools, Patiala.

During 1965

1. Swastika Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh.
2. Pepsu Road Transport Corporation, Patiala.
3. Samana Roadways Regd. Patiala.
4. Ramji Dass Harbans Lal Regd. Bassi Pathana.
5. Basal Tool Co., Patiala.
6. Bhagwan Finance Corporation, Regd., Rajpura.
7. Nav Yug Trading Corporation, Registered, Patiala.
8. Nav Yug Trading Corporation, Registered, Patiala.
9. Ramji Dass Harbans Lal Sewing Machine, Bassi Pathana.

Expenditure incurred on the Staff/Medicines in the dispensaries opened under the Employees State Insurance Scheme at Patiala etc.

3316. Comrade Bhan Singh Bhaura: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the expenditure incurred on the staff and the medicines separately in the dispensaries functioning under the Employees State Insurance Scheme at Patiala, Rajpura, Gobindgarh and Bahadurgarh?

Chaudhri Rizaq Ram: The following expenditure has been incurred on staff and medicines from 1st January, 1965 to 31st December, 1965—

		On staff	On medicines
		Rs	Rs
1.	Rajpura ..	20,784·70	25,051·28
2.	Gobindgarh ..	24,279·32	38,001·55
3.	Patiala ..	22,798·80	25,859·62
4.	Bahadurgarh (Patiala) ..	7,887·35	16,000·00

Enforcement of Employees State Insurance Scheme at Sirhind, Nabha and Malerkotla

3317. Comrade Bhan Singh Bhaura: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the time by which the Employees State Insurance Scheme is likely to be enforced at Sirhind, Nabha and Malerkotla;

(b) if the said scheme is not proposed to be enforced at any of the said places, the reasons therefor?

Chaudhri Rizaq Ram: (a) The E.S.I. Scheme has been enforced at Sirhind with effect from 27th February, 1966. As regards Nabha and Malerkotla, no date has been fixed so far.

(b) Due to shortage of doctors and pare-medical staff it is not possible to extend the scheme at Nabha and Malerkotla for the present.

Arrears of rent in certain Industrial Colonies

3318. Comrade Bhan Singh Bhaura: Will the Minister for Public Works be pleased to state the amount of the arrears of rent due in respect of the Industrial Colonies at Patiala, Rajpura and Gobindgarh as on 31st December, 1965?

Sardar Prem Singh Prem (Capital and Housing Minister) The requisite information is as under—

Name of colony	Arrears of rent as on 31st December, 1965
	Rs.
Gobindgarh ..	44,260·67
Rajpura ..	7,076·83
Patiala ..	1,502·60

Cases Registered under Section 409 I.P.C. against Ex-Sarpanches of Rohtak district.

3319. Comrade Makhan Singh Tarsikka: Will the Minister for Home and Development be plased to state the names of the Ex-Sarpanches of district Rohtak against whom cases under section 409 IPC etc. were registered during the years 1964-65 and 1965-66 together with the dates of their registration and the details of the amount alleged to have been mis-appropriated by them separately.

Sardar Darbara Singh : A Statement containing the requisite information is enclosed.

List of cases registered against Ex-Sarpanches of Rohtak District u/s 409 I.P.C. during 1964.65 and 1965-66.

Serial No.	Names of Ex-Sarpanches against whom cases were registered	Dates of Registration	Details of amount alleged to have been mis-appropriated
1	Shri Mange Ram of Stawali ..	1-2-64	Cartons 20 bags of Milk Powder.
2	Shri Mange Ram of Stawali ..	27-1-64	Milk Powder (quantity not known)
3	Shri Partap Singh of Hassanpur ..	5-2-64	Ditto
4	Shri Banwari Lal of Bidhlan ..	14-2-64	Ditto
5	Shri Shiv Charan of Murthal ..	15-2-64	15 Cartons Milk Powder.
6	Shri Hari Singh of Akbarpur Churni ..	11-2-64	40 Cartons Milk Powder
7	Shri Rameshwar Singh of Sikandarpur Majra	13-2-64	15 Cartons Milk Powder.
8	Shri Tara Chand Rubran ..	13-2-64	111 Cartons Milk Powder.
9	Shri Ujala of Puthi ..	19-2-64	50 Cartons Milk Powder
10	Shri Tara Chand of Mimarpur ..	19-2-64	3 Cartons Milk Powder.
11	Shri Bishan Singh of Pur Khas ..	22-2-64	125 Cartons Milk Powder.
12	Shri Raghu Nath of Pur Khas ..	22-2-64	314 Cartons Milk Powder.
13	Shri Siri Lal of Rajlu Garhi ..	22-2-64	24 Cartons Milk Powder.
14	Shri Charan Singh of Sohati ..	29-2-64	41 Cartons Milk Powder.
15	Shri Narinder Singh Kaloi ..	28-2-64	249 Cartons Milk Powder.
16	Shri Balwant Singh of Simli ..	28-2-64	10 Cartons Milk Powder.
17	Shri Jug Lal of Jindrain ..	28-2-64	9 Cartons Milk Powder.
18	Shri Rattan Lal of Chataula ..	1-3-64	20 Cartons Milk Powder.
19	Shri Banwari Lal of Nasarpur ..	21-3-64	31 Cartons Milk Powder.
20	Shri Duli Chand of Mandhoathi ..	30-4-64	Rs 500.00
21	Shri Pritam Singh of Bahuakparpur ..	10-6-64	Rs 300·00
22	Shri Siri Ram of Jharli ..	7-7-64	Rs 690·10
23	Shri Shiv Lal of Mamri ..	8-8-64	Rs 2,000·00
24	Shri Chander Bhan of Mattan ..	31-12-64	Rs 471·13
	1965		
1	Shri Siri Chand of Sardhana ..	1-6-65	Rs 2,395·98
2	Shri Deep Chand of Bisawar Kheri ..	16-7-65	Rs 2,882·00
3	Shri Darya Singh of Silana ..	17-7-65	Rs 1,294·40
4	Shri Bhagwan Dass of Nigana ..	5-9-65	Rs 50,000·00
5	Shri Rameshwar of Bidhala ..	6-9-65	Rs 4,100·00
	1966.		
1	Shri Rampat of Sasana ..	8-2-66	Rs 5,407·82
2	Shri Shiv Charan ..	11-2-66	Rs 11,918·44

Grow-More-Food Compaign launched in Parks/Plots at Chandigarh

3320. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to initiate the grow-more-food campaign and utilize the parks as well as the vacant plots near the roads at Chandigarh for the purpose, if so, the details of the said scneme and the approximate expenditure proposed to be incrurred thereon ?

Sardar Prem Singh Prem : In view of tne food shortage in the country, the Government considered and decided in October, 1965, the question of utilizing the open spaces at Chandigarh for growing food crops/ vegetables.

2. Open spaces at Chandigarh could be classified as under :—

(1) Specified public spaces like public parks, playgrounds etc.	
(a) Already developed	.. 350 acres
(b) To be developed	.. 466 acres
(2) Open spaces which are subsequently to be developed as commercial areas	.. 1,037 acres
(3) Open spaces forming part of road berms in front of residential houses, both private and Government and other open spaces at the back of such houses exclusive of service lanes	
(4) Leisure Valley in Sectors 10 and 16	.. 400 acres approximately
(5) Open spaces in houses both private and Government	

3. The Government considered each class of these open spaces and decided as follows :—

(i) Out of 816 acres of open spaces to be developed for land scaping, 350 acres stand already developed. They are mostly public parks and play-grounds. It would entail a lot of unnecessary expenditure to convert these into food growing areas for a snort while and tnen re-convert them into grassy lawns. Of the remaining 466 acres, about 107 acres could be taken up for cultivation immediately provided the construction of hydrants is accelerated. The remaining 359 acres in this category are relatively smaller plots and it will have to be examined in details as to which of these could usefully be taken up for cultivation.

(ii) Out of an area of 1,037 acres which was subsequently to be developed as commercial areas, 388 acres have already been leased out by the Estate Officer to various private persons on leases varying from 3 to 5 years. Of the remaining areas some would be usefully utilized when the Scheme of Shallow Tube-wells comes through. The Capital authorities, however, cannot deal with the majority of these areas forthwith. But the areas in Sector 25 can be taken up immediately. Other areas in tnis group could be leased out to private persons and water given from Shallow Tubewells to be sunk by the Capital Project Authorities at the rate of 37 paise per thousand gallons.

(iii) Open spaces forming part of road berms and at the back side of houses exclusive of service lanes could be permitted to be utilised for growing vegetables/food crops but this would entail a relaxation of rules regarding access to such areas. As regards the areas in front of houses between road berms and the houses, these could be permitted for cultivation of low-lying vegetables for a period of two years or so provided that the house-holders concerned first utilize their own lawns and vacant spaces.

(iv) As regards open spaces in residential houses both private and Government, the residents might be permitted to grow vegetables/food crops if they so desire in all open spaces inside including lawns but the arrangements should be their own.

(v) As regards the leisure valley some of it has already been developed but there is some area which is still to be developed the portion in Sector 3 will be taken up by the Capital Project Authorities for purposes of growing vegetables/food crops. As regards other areas, the terraine is irregular and would require considerable effort to put it under the plough. The Capital Project Authorities would examine the area in detail and draw up a suitable plan for its utilization immediately for purposes of growing vegetables/food crops and a latter for development into a regular Leisure Valley.

4. For the present a scheme for growing food crops in about 200 acres of land has been prepared by the Capital Project authorities at a cost of Rs 4,51,900. The details of crops to be grown in this area under this scheme are as under :—

(i) Maize and Wheat	.. 75 acres
(ii) Potatos	.. 75 acres
(iii) Papayas	.. 25 acres
(iv) Miscellaneous summer and winter vegetables	.. 25 acres

Scheme for rearing of cocoons in the State

3321. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amount expended by Government on the scheme for the rearing of Cocoons in the State from 1962 onward, yearwise and the details of the income derived from the sale thereof yearwise, during the said period ?

Shri Ram Kishan : Details of expenditure are as follows :—

	Rs
1962-63	.. 2,28,265
1963-64	.. 2,34,715
1964-65	.. 2,67,842
Total	.. 7,30,822

[Chif Minister]

2. The State Goernment do not produce Cocoons for sale. These are produced by the private rearers and are disposed of by them in their own account.

3. The sericulture Schemes are primarily promotional /beneficiary and as such no income accrues to Government. As a result of the implementation of various Sericulture Schemes during the above period, assets in the shape of mulberry farms, plantations/nurseries and grainage centres etc. have however been created.

Persons detained in the Ptate under the Defence of India Rules due to Indio-Pak conflict

22. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state

(a) the names and addresses of persons (Indian Naticnals) who were detained, district-wise, in the State under the D.I.R. during the period from 6th September, 1965, to-date, due to Indo-Pak Conflict ;

(b) the names of persons out of those mentioned in part (a) above who have been released up to this time ?

Sardar Darbara Singh : (a) Statement 'A' is enclosed
(b) Statement 'B' is enclosed.

STATEMENT 'A'

District Gurgaon

1. Maulvi Niaz Mohd. son of Mauz Khan of Ranika, resident of Ranika, police station Ferozepur-Jhirka, now Nuh.
2. Mohd Ilyas Khan, son of Imam Khan, resident of Akera, police station Nuh.
3. M. Hassan Khan, son of Shitab Khan, resident of Gangwani, police station Punhana.
4. Haji Mehrab Khan, son of Baju, resident of F. P. Nakak, police station Nuh.

District Simla

5. Gulam Ahmed Wani alias Pathan, son of Ali Wani, resident of Zamalgam Anantnag (J.&K.), Gali No. 7, Simla.

District Ambala

6. Pir Mod Yasin, son of Faiz Mohd, resident of Ismailpur, police station Sadhaura.
7. Mohd Jan alias Jan Mohd, son of Allah Bux, resident of Sadhaura.

District Amritsar

8. Harnam Singh, son of Banta Singh, resident of Chamiari, police station Ajnala, at present Rudurpur, district Nainital, (U.P.)
9. Bhajan Singh alias Sher Khan, son of Teja Singh, resident of Khalra.
10. Gurnam Singh, son of Bahadur Singh, resident of Khalra.
11. Kishan Singh alias Kisu, son of Sudha, resident of Kaunke, police station Gharinda.

12. Daya Singh Granthi, son of Mehar Singh, resident of Dera Mahant Jawahar Singh, Mitha Taiwana, Chowk Baba Sahib.
13. Qulwant Rai, son of aulat Ram, resident of Sirhali.

14. Dhanna Singh, son of Attu Christian, resident of Valtoha, Amritsar (now at Landra, police station Mamdot, district Ferozepur)

15. Balbir Singh, son of Mayya Singh, resident of Pakharpur, police station Kathu Nangal.
16. Gurnam Singh, son of Hardit Singh, resident of Ladhewali Havelian, police station Gharinda.

17. Chaman Lal, son of Dewan Chand, resident of Gumtala, police station Sadar Amritsar
18. Banta Singh, son of Gujar Singh Mazhbi, resident Dasuwal, police station Valtoha.

19. Mehru, son of Sondhi, resident of Dasuwal, police station Valtoha.

20. Amar Singh, son of Teja Singh, resident of Mulechak, police station Sadar Amritsar.

21. Arjan Singh, son of Sewa Singh, resident of Varpal, police station Jandiala

22. Mangal Singh, son of Dula Singh, resident of Ghariala, police station Valtoha.

23. Jiwan Singh, alias Jiwana Mazhbi, son of Mehnga, resident of Khem Karan.

District Gurdaspur

24. Gurdas, son of Faqiria, resident of Chaura Khurd, police station Kalanaur.

25. Abdul Rehman, son of Ghulam Rasul Wani, resident of Patshahi Bagh, police station Shergarh, district Sirinagar, Proprietor, Kashmir Muslim Hotel, Pathankot.

26. Ghulam Kadar, son of Salam Sheikh, resident of Basant Bagh, Sirinagar, Proprietor, Indian Muslim Hotel, Pathankot.

27. Basir Ahmed, alias Mohinder Singh, son of Mohd Aziz, resident of Moh. Ahmedian Qadian.

28. Rasila, son of Faqiria, resident of Chaura Khurd, police station, Kalanur.

29. Pran Nath, son of Mela Rem, resident of Moh. Krishan Nagar.

30. Piara Lal, son of Niku Ram Dhobi resident of Gurdaspur.

31. Milkha Singh, son of Sangat Singh, Jat resident of Laleem, police station Kalanaur
32. Joginder Singh, son of Gopal Singh Jat, resident of Radiana, police station Kalanaur

33. Dalip Singh, son of Ujjagar Singh, resident of Shaur Kalan, Police station Kalanaur.

34. Darshan Singh, son of Balwant Singh, Goldsmith, resident of Bhagowal, police station Sadar Batala.

35. Niranjan Singh alias Nanjoo, son of Labh Singh, Jat, resident of Rossi, police station Kalanaur.

[Home and Development Minister]

District Jullundur

36. Bhim Sen Pandit, son of Dr. Ram Nath, resident of Jullundur.

37. Parshotam Lal, son of Master Dev Raj, resident of House No. NB/289, Laxmipura, Jullundur City.

District Ferozepur

38. D. Gill, son of Sardar Yusuf, Christian, resident of Lal Kurti, Ferozepur Cantt (at present c/o R. C. Pen Co., Katra Basar Sagar M.P.)

39. Sowaran Singh, son of Ujjagar Singh, resident of Basti Dehrianwali , Ferozepur City

40. Shingara Singh, son of Ujjagar Singh, resident of Bhambra, Azam Shah.

41. Bishan Singh, son of Sundar Singh, resident of Ahmed Dhandi, police station Mamdot.

42. Sarja alias Bassi , son of Lakha, resident of Habibke, police station Sadar, district Ferozepur.

43. Shafi, son of Rehmat, Christian, resident of Harafke , police station Mallanwala.

44. Munsha Singh, son of Lehna Singh, Rai Sikh, resident Ghallu, police station Khuyan Sarwar, district Ferozepur.

District Sangrur

45. Inayat Ullah, son of Baggu Kambo, resident of Jamalpura, police station Malerkotla.

46. Abdul Rashid, son of Hakim Abdul Rehman, resident of Malerkotla.

47. Abdul Rauf, son of Hakim Abdul Rehman, resident of Malerkotla

48. Mohd Bashir Kausri, son of Haji Asmat Ullah, resident of Maler kotla.

49. Maulvi Manzoor Ahmed , son of Mohd Rafiq, resident of Malerkotla.

50. Kafayat Ullah, son of Asmat Ullah, resident of Headmaster, Islamia High School, Malerkotla.

51. Jamadar Khushi Mohd, son of Rehman, resident of Rajpur, Malerkotla.

52. Ishtiaq Ahmad, son of Mohd Ishaq , resident of Malerkotla.

54. Sayed Mohd Yasin, son of Wali Mohd, resident of Malerkotla.

54. Lal Singh, son of Sant Singh, resident of Kasba Barah, police station Mahal Kalan.

District Patiala

Ordered to be detained by the District Magistrate, Patiala

1. Iqbal Singh, son of Sajjan Singh, resident of Yadvindra Colony, Patiala.

2. Kaka Singh alias Kaka, son of Budh Singh, resident of Raipur, district Patiala.

3. Balkar Singh, son of Labh Singh, resident of Bahadargarh Kasba, district Patiala.

4. Sube Singh alias Suba, son of Gurbachan Singh, resident of Jalalpur, district Patiala.

5. Amar Singh, son of Deva Singh, resident of Alipur Raian, district Patiala.

6. Kartar Singh, son of Jai Ram Singh, resident of Mohalla Sukhdaspura, district Patiala.

7. Kartar Singh, son of Sardha Ram, resident of Chabutra Jattan, Patiala.

8. Deputy Lal, son of Bodh Raj, Lahori Gate, Patiala.

9. Chanan Singh, alias Chhanni, son of Badhawa Singh, resident of Sanaur, district Patiala.

10. Inderpal Singh, son of Bishan Singh, resident of Mohalla Chhappar Banda, district Patiala.

11. Chaman Lal, son of Parshotam Dass, Mohalla Kharasian, district Patiala.

12. Assa Singh, son of Deva Singh, resident of Akipur, Main, Pat:ala.

13. Chaman Lal, son of Bodh Raj, Lahori Gate, Patiala.

14. Gulzara alias Resham, son of Wailati, resident of Malerkotla, district Sangrur now at Patiala.

15. Tarlok Singh, son of Makhan Singh, Raghomajra, district Patiala.

16. Balkar Singh, son of Narain Singh, resident of Shamaspur, district Patiala.

17. Ishar Lal, son of Dhanna Ram, resident of Safabadi Gate, Patiala.

18. Piara Singh, son of Kala Singh, resident of Taffazalpur, district Patiala.

19. Sardool Singh, alias Sardha, son of Bahadur Singh, resident of Kherimuslamana, district Patiala.

20. Tarlok Singh. son of Sant Singh, resident of Anardana Chowk, Patiala.

21. Santa Singh, son of Saran Singh, resident of Shankarpur, district Patiala. (police station Sadar Patiala).

22. Gurbachan Singh, son of Ganda Singh, resident of Shamboo Kalan, district Patiala (police station Rajpura).

23. Harlal Singh, son of Bhag Singh, Kalaundi, district Patiala police station Bassi Pathana)

24. Nachhatar Singh, son of Bachan Singh, Gharuan, police station Bassi, district Patiala.

25. Mohinder Singh, son of Labh Singh, resident of Jhalari, police station, Rajpura, district Patiala.

26. Ajit Singh, son of Mehnga Singh, Kalaran, Bassi Pathana, district Patiala.

27. Ram Singh, alias Rama, son of Hans Raj, resident of Mohalla Chowk Devi Duala Nabha, district Patiala.

28. Amar Nath alias Bawa, son of Mohinder Dass, resident of Alipur Arianan, police station Sadar Patiala.

29. Banta Bazigar, son of Shahna Ram, resident of Loharan Gate, Nabha district Patiala

30. Ranjit Singh, son of Banarsi Dass, Harijan Basti, Nabha.

31. Ishar Singh Mazhbui, son of Jiwan Singh, resident of Gulwati, police station Sadar Nabha, district Patiala.

[Home and Development Minister]

32. Zabar Singh, son of Harnam Singh, Sirhind Mandi, police station Sirhind district Patiala.

33. Labh Singh, son of Narata Singh, resident of Thuhi, police station Sadar Nabha.

34. Gurdev Singh, son of Kishan Singh, resident of Gulwati, police station Sadar Nabha.

35. Harnama, son of Nanak, resident of Mohalla Kartarpura, City , Nabha.

36. Gurdial Singh, son of Sant Singh, resident of Lal Bagh, Patiala.

37. Hardev Singh, son of Kishan Singh, resident of Gulwati, police station Sadar Nabha. district Patiala.

38. Kirpal Singh, alias Pali, son of Vir Singh, Chhoti Barandari, Patiala.

39. Devinder Singh, son of Dalip Singh, resident of Jaurian Bhatian, Patiala.

40. Balbir Chand, son of Lahori Ram, 'B' Tank, Kotwali Patiala.

STATEMENT 'B'

(*Names of persons released*)

District Gurgaon

1. Mohd Ilyas Khan
2. M. Hassan Khan
3. Haji Mehrab Khan

District Ambala

1. Pir Mohd Yasin
2. Mohd Jan alias Jan Mohd.

District Amritsar

1. Harnam Singh
2. Bhajan Singh, alias Sher Khan
3. Dhanna Singh
4. Balbir Singh
5. Chaman Lal
6. Banta Singh
7. Mehru
8. Amar Singh
9. Arjan Singh
10. Jiwan Singh

District Gurdaspur

1. Gurdas
2. Abdul Rehman
3. Ghulam Kadar
4. Bashir Ahmed alias Mohinder Singh
5. Piara Lal

District Jullundur

1. Parshotam Lal

District Ferozepur

1. Sowaran Singh
2. Bishan Singh

District Sangur

1. Inayat Ullah
2. Abdul Rashid
3. Abdul Rauf
4. Kafayat Ullah
5. Sayed Mohd Yasin
6. Lal Singh

District Patiala

Serial Nos. 1 to 40 as listed in Statement 'A' shown under Patiala District.

Iron and Steel Quota Holders in Amritsar and Gurdaspur Districts

3323. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of iron and steel quota-holders at present in districts Amritsar and Gurdaspur together with the place of business of each ;

(b) whether any quota certificates of iron and steel were issued to the said quota-holders, during the period from 1st January, 1965, to-date, if so, the quantity of iron and steel including G.P. sheets and B. P. sheets, issued to each quota-holder ;

(c) the purpose for which the said quota has been given as mentioned in each of the said quota certificates issued together with the nature of trade or industry which each quota-holder was carrying on before the issue of the certificates and is carrying on at present, separately ;

(d) the nature of trade/industry shown by each of the said quota-holders in their applications submitted to the Industries Department when thay applied for the grant of the said quota ;

(e) whether it is a fact that certain quota-holders had been supplied with such material as is not normally used in the industry approved by the Department or in the industry at present being carried on by the said quota-holders; if so, the reasons for issuing such materials ;

(f) whether any previous record of the said quota-holders prior to the issue of the said quota certificates had been looked into by the Department, if so, by whom; if not, the reasons therefor ;

(g) whether it is a fact that if a quota-holder is given material against his quota which is different in type or quality from that to which he is entitled or which he requires for the industry approved by the Department, that material goes or is likely to go to the black-market, if so, the reasons for not giving the material of the requisite quality or type to the quota-holders ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the requisite information will not be commensurate with the benefit sought to be derived therefrom.

[Chief Minister]

Teachers/Teachresses of certain Government Girls High Schools in district Amritsar

3324. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the names and home addresses of the teachers and teachresses now in position in the (i) Government Girls High School, Jandiala Guru, (ii) Government Girls High School, Butala, (iii) Government Girls High School, Rayya (all of Amritsar District), together with the educational qualifications and the dates of their joining these schools and their pay scales at present ;

(b) the percentage of the university examination results, subject-wise, shown by the said teachers/teachresses during the years 1964-65 and 1965-66 ;

(c) whether any reports about the mis-behaviour or the general behaviour of any of the members of the staff of the said schools were received by the D. E. O., Amritsar or C.E.O., Jullundur, during the years 1964-65 and 1965-66; if so, the details thereof along with the action taken thereon be laid on the table of the House ?

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) No, hence question of taking action does not arise.

Statement showing the Names, Qualifications, etc. in Government Girls High School, Butala, Rayya and Jandiala Guru

Serial No.	Name of the teachers/teachresses	Home address	Qualifications	Present Pay	Scale	Date of joining in the school	University result subject-wise 1964-65 (A)		1965-66 (B)
1	2	3	4	5	6		7		
	Government Girls High School, Butala (Amritsar)								
	Sarvshrimati—			Rs	Rs			Per cent	
1	Sudesh Kumari ..	C/o Shri Amar Nath, Katra Preju, Amritsar	Matric, Sewing	76	60—120	31-3-64	..	..	Result not declared
2	Pushpa Sharma ..	V. & P. Butala (Amritsar)	B.A., B.T.	134	110—250	6-1-64	X English Hindi	78.6 28	Ditto
3	Balwinder Gill ..	C/o Sub. Teja Singh, V. & P. Bhagwanpur, (Amritsar)	B.A., B.T.	134	110—250	16-10-62	X Arith. HH.	85.71	Ditto
4	Mohinderpaul Kaur	V. & P. Butala (Amritsar)	Matric, J.B.T.	95	60—120	28-8-63	Not outgoing class taught by her		Ditto
5	Charanjit Kaur	Ditto	Ditto	85	60—120	1-5-63	Ditto		Ditto
6	Daya Wanti ..	Ditto	B.A., B. Ed.	85	60—120	4-9-64	X Phy.	100	Ditto
7	Balbir Kaur ..	Ditto	Matric, J.B.T.	85	60—120	21-6-62			Ditto
8	Surinder Kaur	Ditto	Ditto	85	60—120	1-5-62			Ditto

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6	7		
	Government Girs High School, Rayya							
	Sarvshrimati							
1	S.S. Sabharwal	Kapurthala	B.A., B.T.	250—350	3-5-65	No result at Rayya		Ditto
2	Dalbir Kaur	V. & P. Butala (Amritsar)	B.A., B. Ed. ..	110—250	1-5-62			Ditto
3	Krishna Kanta	Sharifpura, Amritsar	B.A., B.T.	110—250	30-1-63			Ditto
4	Satnam Kaur ..	V. & P. Phagwara (KPT)	Ditto ..	110—250	25-9-65			Ditto
5	Amarjit Kaur ..	V. & P. Rayya (Amritsar)	B.A., B.Ed.	110—250	26-3-63	English S.S.	100 96.1	Ditto
6	Manjit Kaur ..	V. & P. Bals Chander, tehsil Ajnala (Amritsar)	Ditto	110—250	12-2-63	J.B.T. Method of teaching Mathematics, Health Edu.	92 96 96	Ditto
7	Darshan Narang	Gopal Nagar, Amritsar	M.A., B.T. M.A. with Punjabi ..	110—250	10-6-64	X Hy. Phy.	88.6	Ditto
8	Kusam ..	V. & P. Jandiala Guru (Amritsar)	B.A., B.T. ..	110—250	26-5-65			Ditto
9	Hardarshan Kaur	V. & P. Baba Bakala	B.A., B.Ed. with B.A. Math. Course ..	110—250	30-4-65			Ditto
10	Nirmal Kumari ...	V. & P. Rayya (Amritsar)	Middle S.V. ..	140—220	4-2-56			Ditto
11	Gurdial Kaur ..	V. & P. Kakakh Ludhiana	Middle Gyani, S.V. ..	60—120	25-2-57	X Punjabi	97.1	Ditto
12	Sudesh Sharma ..	V. & P. Rayya (Amritsar)	Matric J.B.T. ..	60—120	1-5-63	Not teaching University Classes		Ditto

13	Beant Kaur ..	V. & P. Rayya	Ditto	..	60—120	28-8-63	Ditto		
14	Kirpal Kaur ..	Ditto	Ditto	..	60—120	2-5-63	Ditto		Ditto
15	Gulshan Kumari	Ditto	Ditto	..	60—120	20-9-63	Ditto		Ditto
16	Janak Sharma ..	V. & P. Pheruman	Ditto	..	60—120	1-9-62	Ditto		Ditto
17	[illegible]am Kaur ..	V. & P. Rayya	Ditto	..	60—120	24-9-63	Ditto		Ditto
18	Amrik Kaur ..	V. & P. Baba Bakala	Ditto	..	60—120	14-12-64	Ditto		Ditto
19	Amrik M[illegible]ne ..	V. & P. Raya	Ditto	..	60—120	14-12-64	Ditto		Ditto
20	Nirmal Kumari	Ditto	Ditto	..	60—120	14-9-65	Ditto		Ditto
21	Ranjit Kaur ..	Ditto	Ditto	..	60—120	20-10-65	Ditto		Ditto
22	Niranjan Kaur ..	Ditto	Ditto	..	60—120	..	Ditto		Ditto
23	Balbir Kaur ..	V. & P. Bhagwanpura	Matric Art and Craft	..	60—120	1-9-62	Ditto		Ditto
24	Usha ..	V. & P. Badala (Amritsar)	Matric J.B.T.	..	60—120	29-9-63	Ditto		Ditto
25	Surinder Kumari	V. & P. Jullundur	Ditto	..	60—120	10-8-65	Ditto		Ditto
	Government Girls High School, Jandiala Guru (Amritsar)								
1	P. Kumaria ..	C/o Shri P. S. Kumaria, 3363, Partap Bazar, Amritsar	B.A., B.T.	..	250—350	2-8-65	X-A English X-B English	86.07 89.07	Ditto
2	Raj Devinder ..	V. & P.O. Mehranban pur (Amritsar)	B.A., B. Ed.	..	110—250	1-5-63	X-C English X-A Maths.	52.19 93.13	Ditto
3	Rajinder Kaur	173, Rani Ka Bazar, Amritsar	B.A., B.T.	..	110—250	6-9-63	X-B.C. X-A. S.S.	72.02 100	Ditto

[Chief Miniser]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Government Girls High School Jandiala Guru Amritsar—*contd*								
Sarvshrimati								
4	Miss Amrit Sarita	Jandiala Guru (Amritsar)	B.A., B.T. ..	110—250	6-5-64	X-B. S.S. X-C-S.S.	97.04 100	Result not declared yet
5	Avtar Kaur ..	37/2, Gopal Nagar Amritsar	Ditto ..	110—250	9-4-65	X-ABC X Hindi	100 91.4	Ditto
6	Sukhwant Singh	V. & P. Ekal Gada (Amritsar)	B. Sc. Agr. ..	110—250	1-5-65			Ditto
7	Smt. Soma Wati	V. & P. Jandiala Guru (Amritsar)	S.V. & Hindi Social Study ..	120—175	1-10-57	X-Englsih Maths.	50 61.66	Ditto
8	Manohar Bala ..	Ditto	O.T. ..	60—120	17-6-64	S.S. Hyg.	66.66 90	Ditto
9	Bhupinder ..	V. & P. O. Ekal Gadda (Amritsar)	N.D.S. ..	First Grade	28-10-65	Not teaching any University Class		Ditto
10	Sarbir Bedi ..	Mahanu Singh Road, Amritsar	Art and Craft ..	60—120	1-8-62	Ditto		Ditto
11	Raj Balbir ..	Jandiala Guru (Amritsar)	M.T. J.B.T. ..	60—120	30-8-63	Ditto		Ditto
12	Bimla Wadhawa	C/o Atma Ram Wadhawa, V. & P. O. Pandori Kalan	Ditto ..	60—120	12-9-63	Ditto		Ditto
13	Gurbachan Kaur	Jandiala Guru (Amritsar)	Ditto ..	60—120	30-8-63	Ditto		Ditto
14	Ajit Kaur ..	Ditto	Ditto ..	60—120	19-12-64	Ditto		Ditto
15	Prem Kanta ..	Ditto	Ditto ..	60—120	1-5-65	Ditto		Ditto
16	Om Piari ..	Sharifpura, Amritsar	Tailoring Mistress ..	70—150	7-5-65	Ditto		Ditto

Representation from Shri Rachhpal Singh, Detenu in Sangrur Jail

3325. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the Government has received any representation from Shri Rachhpal Singh, M.C., Hissar, now a detenu in Sangrur Jail requesting that he be provided necessary facilities to enable him to contest the election to the office of the Vice-Chairman of the Hissar Municipal Committee to be held on the 22nd February, 1966, if so, a copy of his representation together with the details of the action taken thereon be laid on the Table ;

(b) whether Government proposes to permit him to contest the said election, if not, the reasons therefore ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. A copy of the representation is enclosed.

(b) No. As Shri Rachhpal Singh, being under detention, could not perform any of the duties of Vice-Chairman of the Municipal Committee, he was not provided with facilities to contest the election for this Office. It may be mentioned that Shri Rachhpal Singh applied to the Government for release on parole or for making arrangements for him to take oath as a Municipal Commissioner, Hissar. As he was not able to perform the duties of a Municipal Commissioner while in detention, he was not released on parole for the purpose. A writ petition to the same effect filed by him in the State High Court on 25th March, 1965, was rejected on 19th April, 1965.

COPY OF REPRESENTATION

The Home Secretary,
Government of Punjab, Chandigarh.

Subject:—Participation in election of Vice-President of Municipal Committee, Hissar, going to be held on 19th February, 1965.

Shrimanji,

It is submitted as under :—

1. That I am a member of Municipal Committee, Hissar, and at present detained in District Jail, Sangrur under D.I.R.
2. That the election of the Vice President of Municipal Committee, Hissar, is scheduled to be held on 19th Februarry, 1966, as before this date as the Municipal Committee, Hissar, may decide.
3. That I have decided to constest the Post of Vice-President of Municipal Committee , Hissar. But as I am at present under detention in Sangrur District Jail, I cannot do so without the proper arrangements made by the Government for my personal presence in the meeting held for the purpose of election. It may also be noted that before filing my nomination papers for election, I have to take oath as member necessary according to law.

It is, therefore, requested that I may be granted one week's parole to enable me to take oath and file nomination papers and take part in election. And if the grant of parole for this purpose is not possible by any reason, other necessary arrangements for my oath taking and person at presence and participation in election meeting, may please be made and all concerned be informed accordingly.

An early action on this application is requested.

Yours faithfully,

Dated 5th January, 1966.

(Sd) RACHHPAL SINGH,
(Member, Municipal Committee, (Hissar) at present Communist Detenu, District Jail, Sangrur.

Murder of Harijan Girl of police station Narnaud, district Hissar in August, 1965

3326. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Harijan girl Bibi Sukhma Devi, (daughter of Khazan Singh, police station Narnaud, district Hissar) aged fourteen years was raped and murdered in August, 1965 by the goondas of the area; if so, the names of the persons who were arrested and challaned in the above mentioned case, and a copy of the F.I.R. be laid on the Table of the House ;

(b) whether the Government is aware of the fact that the district police authorities are helping the undesirable persons and are not taking any action against the culprits, if so, whether the Government proposes to appoint a high level enquiry Committee or an Officer from Chandigarh to pacify the public opinion of the area, if so, when ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The dead body of a Harijan girl named Sukhma Devi (aged 14), daughter of Khazan, Singh was recovered from a 'Rajbaha' on 14th August, 1965. The dead body was subjected to post-mortem. After completion of the inquest, case F.I.R. No. 149, dated 14th August, 1965, under section 302, I.P.C., was registered at police station Narnaud. The factum of rape could not be established from the post-mortem examination of the dead body. No eye-witness have been found in this case. No one has yet been arrested and challaned. The case is still under investigation. A copy of the F.I.R. is laid on the Table of the House.

(b) The Government is aware of the fact of this case and general situation in the ilaqa. It is incorrect to say that the district police is helping undesirable persons or not taking any action in the matter. The Harijans suspect the local Jats for the murder, but no evidence, direct or indirect was available or produced by them to connect the Jats with the murder. Since the case is being properly investigated and no lapse on the part of local police has come to notice, the Government does not intend appointing a high level enquiry Committee or an Officer from Chandigarh to look into this case.

थाना नारनौद ज़िला हिसार

नकल F.I.R. No. 149 dated 14 August, 1965

1. रिपोर्ट की तारीख और समय	रिपोर्ट नं. 8, तिथि 14-8-1965 5-15 P.M. । रपट नं. 8 तारीख 13-8-1965 बख्यान सजाना son of अदमी, जात चमार हरिजन सकना खड़क पूनिया under section 302 IPC देह खड़क पूनिया, 16 मील जानिब जनूब, मगरब देह नं० 53 मनजानिब पुलिस को कोई तकलीफ नहीं हुआ ।
2. सूचना देने वाले फरियादी का नाम तथा निवास-स्थान	
3. संक्षिप्त कफियत जुर्म मये दफा	
4. थाने से घटना स्थल की दूरी तथा दिशा	
5. कोई देरी हो तो कारण दो	
6. थाना से रिवानगी की तारीख	

बज़रिया Special Report,

14-8-65

Sd RAM SARUP MHC

वहवाला रपट नं 8, तिथि 14 अगस्त, 1965 रोज नामचा थाना हिजा (नारनोद) श्री शिव चरण, ASI साहिब थाना नारनौद ने एक तहरीर भेजी थी जिस की नकल ज़ैल

है । नकल रपट नं. 8 MHC आमद तहरीर मर्ग इन्सान समय 5-45 बजे शाम एक तहरीर मरतबा मरसला श्री शिव चरण ASI थाना नारनौद, बही मजमून महसूल हुई ब्यान अजाने खजाना, पुत्र उदमी चमार हरिजन, साकन खड़क पूनिया, उमर 45-46 साल मर दो लड़की हैं। चन्दर जाजन बाला शादी शुदा है। छोटी लड़की सुकमा मसमी बदलू, सुपुत्र कबूल हरिजन साकन सूरिया वाला थाना नरवाना के साथ शादी शुदा थी। सूखमा की उमर करीब केवल 14 साल थी। और पिछले साल ही शादी की थी। शादी से एक दफा जाकर उस वक्त से मेरे घर पर ही थी हमारा खेत गांव से करीब तीन मील के फासले पर बरवाला राजवाह से परे है। परसू 11 अगस्त, 1965 को मैं अपने घर पर मौजूद था मेरा लड़का किशन खेत में हल चला रहा था मेरी लड़की सुखमा उसकी सुबह की रोटी लेकर घर से करीब 10-11 बजे दिन गई थी जोकि रोटी लेकर शाम तक वापिस नहीं आई। दिन छुपे मेरा लड़का किशन आया। जिससे मैं ने पूछा कि सुखमा नहीं आई। किशन ने कहा कि वह तो दोपहर ही मुझे रोटी खिला कर घास खोद कर और बरोटी लकड़ियों की लेकर चली आई थी। जिस पर हमें बड़ा फिकर हुआ और इधर-उधर खेतों में तलाश करी। मगर लड़की न मिली कल भी दिन में तलाश करते रहे जब करीब 12-1 बजे दिन, मेरी लड़की की लाश राजवहा के अन्दर लकड़ के साथ जोकि राज बहा के ऊपर डाल रखा है और रास्ता बना रखा है किनारे के साथ लगी, लेकिन घड़ा में उलझी मिली। यह दरबारी वलद छोटू राम कंवर, वलद बरसाला और मेरा लड़का सुरजा जो कि वहां पर नहा रहे थे ने देखी जिस पर पंजाबा और रसाला चौकीदार जो कि देखभाल के लिये फिर रहे थे ने बाहर निकाली तमाम गांव की पंचायत और बहुत से मुरदमान इकट्ठे हुए और पता करते रहे मगर मौत के बारे कोई पता नहीं चला और न ही मेरा किसी पर अब तक किसी किस्म का शुभा है। बराए इत्तलाह थाना जा रहा था कि आप मिल गए। अलवद खजाना पुत्र उदमी, हरिजन, खड़क पूनिया निशान अंगूठा, (Sd,) Shiv Charan ASI. कार्यवाही पुलिस हमरोज मन ASI गए राम जीवन नं 567, सरवन सिंह नं 474 कांस्टेबलान, बिना बरदरयाफत दरखास्त व तालीम इहकमात मौजा छान जा रहा था जोकि मसमी खजाना, पुत्र उदमी, कौम हरिजन, साकन खड़क पूनिया ब्यान वाला तहरीर करवाया जोकि पढ़ कर सुनाया गया। जिसने दुरुस्त तसलीम करके सुन कर अपना बांया अंगूठा ज़ेर ब्यान खुद साबत किया जिसकी मैं तसदीक करता हूं। ब्यान मामला मर्ग इनसान का पाया जाता है। जिसकी दरयाफत मौके पर होनी ज़रूरी है। बमाए रिपोर्ट रोजनामचा भेजी जाती है, नकल ब्यान इत्तलाह दरिन्दा को दी गई है। मन ASI मय हमराही कान्स्टेबलान बिना बरदरयाफत हालात मर्ग खाना मौका का होता हूं। (Sd.) Shiv Charan, ASI., PS. Narnaud 13 अगस्त, 1965, दो बजे दिन अलवद खजाना, पुत्र उदमी हरिजन निशान अंगूठा। आज थाना हसब आदम तहरीर रपट दर्ज रोजनामचा हुई असल तहरीर लफ रोजनामचा की गई है तहरीर हजा बदसल, श्री चन्द चौकीदार खड़क पूनिया, महसूल हुई है, व MHC आज थाना ASI साहिब ने तिथि 13 अगस्त, 1965 को दरयाफत मर्ग जर दफा 174 Cr. P. C. करके लाश अजाने मरामात सुखमा को नए कागजात नक्शा मर्ग बगैरा बवस्ज पोस्ट मारटम खाना सिविल Hospital Hissar की थी जो इस वक्त सरवन सिंह कान्स्टेबल नं 474 व राम जीवन कान्स्टेबल 597 कान्स्टेबल ने नक्शा मर्ग मुतजिकरा बाला गए रिपोर्ट रिपोस्ट मार्टम

[Home and Development Minister]

नं 68/65 थाना पर लाकर दी जो मुलहज़ा रिपोर्टपोस्ट मारटम से Medical Officer साहिब ने नतीजा जैल दिया। Death in my opinion is due to asphyxia due to strangulation चूंकि नतीजा पोस्ट मारटम से सुरत जुर्म 302, IPC पाई जाती है इसलिये रिपोट इबतदाई हज़ा बजुर्म मजकूर मरतब हुई। जोकि बज़रिया स्पैशल रिपोर्ट अफसरान मजाज के पास बदसल राम जीवन, कान्स्टैबल नं० 597 अरसाल हांसी या हिसार हुई नकल रिपोर्ट इबतदाई मये कागजात पोस्ट मारटम बदसत सरवन सिंह Constable 574 निजद ASI साहिब बमकाम खड़क पूनिया जो मौका पर हैं अरसाल हुई। जनाब SHO साहिब बहवाला रपट न 30, तिथि 13 अगस्त, 1965 बराए तफतीश मुकदमा जुर्म 409, IPC Gianpura गए हैं, बदसत भरत सिंह कास्टेबल 502 इत्तलाह अरसाल हुई।

श्रीमान जी नकल मुताबिक असल है।

हर चंद AC

(Sd) RAM SAROOP,
M H C P S Narnaud
14-8-65

Sick leave refused to a Jail Warder of Central Jail, Hissar

3327. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Shri Jage Ram, Jail Warder of Central Jail, Hissar went to the Superintendent of the said Jail thrice in the months of October and November, 1965 and requested for sick leave to join the local hospital for treatment of his serious ailment ;

(b) whether it is also a fact that the said Superintendent refused him leave to join the hospital for treatment, if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is further a fact that the said Warder joined the Hospital for treatment without the permission of the Superintendent and died in the Hospital a few days afterwards ;

(d) whether it is also a fact that during his ailment upto his death, the Superintendent marked him absent in the attendance register; if so, the reasons therefor ;

(e) if the reply to parts (a) to ( ) above be in the affirmative, whether the Government proposes to hold a special enquiry about the said incident, if not, the reasons therefor ?

Shri Chand Ram : (a) No.

(b) Question does not arise in view of reply to part (a) above.

(c) No. He went to join the hospital with a recommendatory letter from the Medical Officer of the Jail for admission into the hospital.

(d) No. He was shown on sick list in the jail records.

(e) In view of replies to parts (a) to (d) above, the question of holding an enquiry does not arise.

Upgrading of Schools in Tehsil Una, District Hoshiarpur

3328. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education be pleased to State—

(a) the names of the Primary and the Middle Schools which were recommended to be upgraded by the A.D.I. and the District Inspectors of Schools during the years 1960-61 and 1961-62 in tehsil Una, district Hoshiarpur ;

(b) the names of the Schools out of those mentioned in part (a) above which have actually been upgraded ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The information is given below :—

1960-61

Primary to Middle	*Middle to High*
1. Government Primary School, Lalri ..	1. Government Middle School, Panjawar
2. Government Primary School, Ghanari (Boys)	
3. Government Primary School, Bhanjal	
4. Government Primary School, Lohara	
5. Government Primary School, Barwa	

1961-62

1. Government Primary School, Basal ..	1. Government Middle School, Jhaj
2. Government Primary School, Nehri	
3. Government Primary School, Gindpur Malun	
4. Government Primary School, Joh	
5. Government Primary School, Sloh Beri	
6. Government Primary School, Amb	
7. Government Primary School, Ghanari (Girls)	
8. Government Primary School, Mubarakpur	
9. Government Primary School, Chalet	
10. Government Primary School, Dasgrain	
11. Government Primary School, Dabheta	
12. Government Primary School, Gindpur Malour	

(b) :—

1960-61

Primary to Middle	*Middle to High*
1. Government Primary School, Lalri	
2. Government Primary School Ghanari (Boys)	
3. Government Primary School, Bhangal	
4. Government Primary School, Lohara	

1961-62

1. Government Primary School, Basal
2. Government Primary School, Nehri
3. Government Primary School, Gindpur Malun
4. Government Primary School, Joh
5. Government Primary School, Sloh Beri
6. Government Primary School, Amb
7. Government Primary School, Ghanari (Girls)
8. Government Primary School, Mubarakpur
9. Government Primary School, Chalet

Search of the House of Shri Krishan Murari

3329. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the house of one Shri Krishan Murari at Chandigarh was searched and attacked by the Chandigarh Police during the University Employees strike last year; if so, the reasons for the same ;

(b) whether it is also a fact that the wife of Shri Krishan Murari was harassed by the raiding Police; if so, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) A raid on the house of Shri Krishan Murari, Convenor of the Punjab State Students Union was carried on 14th April, 1965 by Chandigarh Police in connection with the arrest of Shri Ram Parkash Manchanda, son of Shri Attar Singh against whom a detention order, under the Defence of India Rules was issued by the Government of Punjab on 6th April, 1965 and who had been evading his arrest so far. The said Ram Parkash Manchanda was a very close associate of Shri Krishan Murari and there was reliable information with the Police that the former was taking shelter in the house of the latter. Even Shri Krishan Murari had at that time admitted that Shri Ram Parkash Manchanda had been visiting his place quite frequently. The raid was perfectly authorised and was carried out strictly according to the law and procedure. The Police force deployed for the purpose was also according to the circumstances of the case and situation of the house raided.

(b) There was absolutely no unnecessary harassment to Shri Krishan Murari or his wife and the search was perfectly legal.

State Conference of Nurses

3331. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Health be pleased to state whether Government has received copies of the resolutions passed by the State Conference of Nurses held recently in Chandigarh or any memorandum from their Provincial Union regarding the demands; if so, a copy thereof together with the details of the action likely to be taken thereon be laid on the Table ?

Shrimati Om Prabha Jain : Yes. A copy of the resolutions passed on the 10th Annual Conference of the Trained Nurses Association of India, Punjab State Branch, Chandigarh, dated the 5th February, 1966 is laid on the Table of the House. Various items of the resolutions are yet under consideration/examination and the action taken will be intimated in due course.

Resolutions passed on the 10th Annual Conference of the Trained Nurses Association of India, Punjab State Branch

CHANDIGARH

5th February, 1966

No. 1 Provision of Khadi Linen in Punjab State Hospitals :

RESOLVED : that Khadi Linen be discontinued being used in the State Hospitals as it has proved expensive, coarse and causes discomfort to the patients.

Proposed, seconded and voted by Members.

No. 2 Clerical assistance to Nursing Superintendents in Hospitals :

RESOLVED : that a Steno-typist be provided in the office of the Nursing Superintendent for her asistance in all State Hospitals, who is incharge of the largest Section of the working force.

Proposed, Seconded and voted by members.

No. 3 Non-nursing functions to be discontinued :

(a) RESOLVED : that such duties as keeping of linen and equipment, etc., be entrusted to some non-technical staff (clerical) so that nursing sisters and staff nurses be able to give effective and efficient nursing care and have time for clinical teaching and supervision.

(b) RESOLVED : that the nursing staff be exempted to make good the losses out of their meagre emoluments unless the losses are due to proven neglect.

(c) RESOLVED : that accounting of drugs is time-consuming ; therefore, modern means of distribution and simplified ways of accounting of drugs be adopted.

Proposed, seconded and voted by members.

No. 4 Status of Nurses to be raised.

RESOLVED : that the Nursing Superintendents and Matrons and Sister Tutors be made gazetted. This will allow the Nurses and Nursing Leaders to serve with dignity and honour and attract more young women to this noble profession.

Proposed, seconded and voted by members.

No. 5 Security in service—temporary.

RESOLVED : that a minimum time limit may be fixed for the confirmation of the Nursing Staff in their respective posts. Unlimited temporary service causes frustration and dis satisfaction as many nurses are serving in temporary capacity for 8—10 years.

Proposed , seconded and voted by members.

No. 6 Punjab Nurses Registation Council —Election :

RESOLVED : that the election be held at an early date and that the information regarding nominations be sent to each electorate by the State Government. Under sub section (3), this Council is the body constituted by the Punjab Nurses Registration Act, 1932, Section 3 (1&2) (c), (d), (e) and (3).

Proposed, seconded and voted by members.

No. 7 Revision of Pay Scales :

• RESOLVED : that the pay scales of nursing staff, which are inadequate , may be raised suitably in view of the arduous work performed. These scales have not been revised for about 15 years.

Proposed, seconded and voted by members.

No. 8 Implementation of new syllabus of the Indian Nursing Council :

RESOLVED : that the arrangements should immediately be made to implement the syllabus accepted by the State Government and facilities provided for class rooms/laboratories and reading rooms in all nursing schools . Also a separate Budget be earmarked for these schools.

Proposed, seconded and voted by members.

[Home and Development Minister]

No. 9 Designation of Nursing Officer at State Level

RESOLVED : that nursing Officer at State Level be designated as Deputy Director of Health Services (Nursing), as recommended by the Mudaliar Committee. This will enable her to discharge her duties efficiently and provide leadership to the profession.

Proposed, seconded and voted by members.

No. 10 Earned leave with all allowances.

RESOLVED : that nursing staff should be allowed one months' earned leave on full pay (including all allowances as is the practice in other States, since no gazetted holidays are allowed to nursing staff in Punjab.

Proposed, seconded and voted by members

No. 11 Operation of finances of the Association :

(a) RESOLVED, that the State Bank of India be and are hereby appointed Bankers.

(b) RESOLVED : that all cheques on the banking account be signed and all bills, notes and other negotiable instruments be drawn accepted and made on behalf of the Punjab State Branch by the President and the Secretary-cum-Treasurer, as per memorandum.

(c) RESOLVED . that all cheques, bills, notes and other negotiable instruments payable to the Punjab State Branch may be endorsed for the Punjab State Branch by them Secretary, Treasurer of the State Branch for the time being.

Proposed, seconded and voted by members.

Cycles in District Police Lines, Patiala

3332. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that about 300 new cycles are rotting in District Police Lines, Patiala for the last 9 months; if so, the reasons for the same ;

(b) the reasons, if any for not issuing the said cycles to the police station concerned so far ;

(c) the names of the gazetted officers who were issued new cycles from this lot or for the police guards posted at their bungalows ?

Sardar Darbara Singh : (a) No. Only 150 cycles purchased in September, 1965, have been kept by the Supdt. of Police, Patiala in the Godown to be utilised as and when necessity arises.

(b) As in (a) above . These cycles are being kept as emergency reserve.

(c) Nil.

Development of Punjabi Language in the State

3334. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the details of the steps taken by the Government for the development of the Punjabi Language in the State during the years 1963-64, 1964-65, 1965-66 and the details of the amount spent during the said years for the purpose ;

(b) the details of the steps Government propose to take during the year 1966-67 for the full development of the Punjabi Language in the State ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Under the Plan scheme (Development of Punjabi) the Department brought out twelve issues each of Punjabi Duniya' and 'Jan Sahit' in Punjabi ; awarded prizes to six authors and two publishers in Punjabi for their best literary productions ; honoured a litterateurs as well as two Rajya Kavis ; orgainsed sixty six literary contests and 18 Kavi Darbars ; organised three writers seminars ; awarded research and merit scholarships to the students ; translated one standard work into Punjabi :; compiled and edited rare manuscripts ; prepared entries for the Punjabi encyclopaedia and awarded financial asistance to indigent writers.

All these items continued to be repeated every year. The details of the amount spent under the Plan Scheme (Development of Punjabi) is as under:—

1963-64	1964-65	1965-66
Rs 0.77 Lacs	Rs 0.84 lacs	Rs 0.94 lacs antici-pated)

(b) The schemes noted above are of continuous and repititive nature and shall be continued during the year 1966-67 also. Besides, the Offices of the District Language Officers at all the District Headquarters in the State are being strengthened and a large number of literary activities, will be organised in each District .

Arrears of salaries of teachers of Schools taken over by Government

3335. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the teachers of the schools taken over by the Government in the Punjab have not been paid their salaries for the years 1962 and 1963 so far, the reasons for the same and the time likely to be taken for paying the same ;

(b) whether it is a fact that no formula has yet been evolved for the fixation of pays of the said teachers, if so, the reasons for the same and the time likely to be taken to come to a decision ;

(c) the conditions , if any, imposed by the Government on the earning of the annual increments by the teachers/members of the said schools ;

(d) whether Government have received any representation from the said teachers requesting therein that they be brought at par with other erstwhile local bodies schools teachers, if so, the action so far taken or proposed to be taken thereon ;

(e) the names of masters/mistresses/teachers with the names of the schools where they are posted whose cases are still pending regarding the regularisation of their services with the reasons in each case and the time by which the matter is likely to be finalised ;

(f) the details of the formula under which trained graduates (BT and BEd, are being absorbed after the taking over of the schools ;

(g) the names and addresses of the trained graduates of each of the schools referred to in part (a) above who have been absorbed together with the names of those whose cases are still pending ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No.

(b) No.

(c) The condition of earning increments has been imposed on those teachers who did not possess the requisite qualifications for entry into Government service. They will earn grade increments only when they acquire the prescribed qualifications.

(d) Yes. It has been considered and rejected.

(e) Statements giving the requisite information is laid on the table of the House. Their cases are with the S.S.S. Board, Punjab, for approval of their candidature or otherwise . No time limit can be fixed.

(f) Trained graduates should fulfil the conditions of combination of subjects or other conditions prescribed for fresh entrants subject to the approval of the S.S.S. Board.

(g) In view of reply at part (a) aobove question does not arise.

Statement relevant to part (e)

Serial No.	Name of Headmaster/Masters/Mistresses	Name of the School
1	2	3
1	Man Singh Headmaster	Government High School, Dhira Kangra
2	Uttam Chand	Government High School, Khaira (Kangra)
3	Hem Raj	Government High School, Lohara, (Hoshiarpur)
4	Amar Nath Kaul	S.D.A.S. High School, Pundri, Karnal
5	Shiv Lal	Ditto
6	Sher Singh	Ditto
7	Narotam Chand	D.A.V. High School, Bawarna (Kangra)
8	Tilak Raj Dogra	Ditto
9	Sukhderjit Singh	Naween Janta High School, Harse Chhina (Amritsar)
10	Sarbjit Singh	Janta High School, Bhakna (Amritsar)
11	Sukhdev Singh	Ditto
12	Kanwar Sewa Singh	H.C.S.M. High School, Pollian—Prohiton
13	Puran Chandra Joshi	R.H.S.D. Higher Secondary School, Haripur (Kangra)
14	Sat Dev Sharma	Ditto
15	Randhir Singh	S.G.H.G. Khalsa Higher Secondary School, Mandi Gobindgarh Patiala

Serial No.	Name of Headmaster/Masters/ Mistresses	Name of the School
1	2	3
16	Sarwan Singh ..	S.G.H.G. Khalsa Higher Secondary School, Mandi Gobindgarh, (Patiala)
17	Ajaib Singh ...	Ditto
18	Ajit Singh ..	Ditto
19	Joginder Singh ...	Ditto
20	Attar Chand Yadav ..	Higher Secondary School, Kund (Gurgaon)
21	Kanwar Pancham Singh ..	H.C.S.M.High School, Polian—Prohitan
	Mistresses	
22	Jagjit Kaur Gill ..	Naweeen Janta High School, Harse Chhina (Amritsar)
23	Amar Jit Kaur ..	Public High School Girls, Dakha
24	Gurwant Kaur ...	Ditto
25	Joginder Kaur ...	Ditto
26	Shrimati Shashi Kaushal	Mata Gujri Higher Secondary School, Fatehgarh Sahib (Patiala)
	Teachers	
1	Shri Harbans Singh ..	G. N. Khalsa High School, Harpura Dhandri (Gurdaspur)
2	Ram Labhaya ..	Ditto
3	Bhagat Singh ..	Ditto
4	Sukh Dass ..	Ditto
5	Janam Singh ..	Ditto
6	Shri Ram Swarup Singh ..	Ditto
7	Shri Ram Nath Prashar ..	Ditto
8	Shri Raghu Nath Dutt Shastri ..	S.D. High School, Jawalamukhi.
9	Nasib Chand Sharma ...	G.N. Khalsa High School, Harpura Dhandri (Gurdaspur)
10	Mohinder Singh ...	Ditto
11	Gurcharan Singh ...	Ditto

[Education Minister]

Serial No.	Name of Headmaster/Masters Mistresses		Name of the School
1	2		3
12	Sant Singh	..	G.N. Khalsa High School, Harpura Dhandri (Gurdaspur)
13	Gurdial Singh	...	Janta National High School, Bhakna (Amritsar)
14	Swinder Singh	...	Ditto
15	Jarnail Singh	..	Ditto
16	Sudesh Kumar	...	M.T.A./Sharse Chhina (Amritsar)
17	Kulwant Kaur	...	Public High School Girls, Dakha
18	Harbans Kaur		Ditto
19	Kailash Wati	..	Polian Prohitan School
20	Urmil Loomba	..	M.G. Girls Higher Secondary School, Fatehgarh Sahib
21	Avtar Kaur	...	Ditto
22	Parkash Kaur Dhillon	..	Ditto

Different Class in Jail given to Shri R. P. Manchanda detenu from 8th September, 1965 to 28th September, 1965

3337. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state the reasons for treating as 'B' Class detenu Shri R. P. Manchanda from 8th September, 1965 to 28th September, 1965 in Central Jail, Patiala and the district Jail, Karnal as a 'C' class detenu when he was a 'B' class detenu in Ferozepure Jail ?

Shri Chand Ram : Due to India-Pakistan conflict Shri R. P. Manchanda was transferred from Central Jail, Ferozepur to Central Jail, Patiala and thereafter to District Jail, Karnal. An intimation about this classification could not be sent alongwith him at the time of tranfer by the Superintendent, Central Jail, Ferozepur, due to disturbed conditions. He was, however, classified as 'B' class detenu at District Jail, Karnal, immediately on receipt of intimation from the Central Jail, Ferozepur.

Confirmation of the Teachers/Masters in Hissar District

3338. Shri Amar Singh : Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that a large number of teachers/masters in Hissar District who have put in 15 to 20 years service have not yet been confirmed ; if so, the reasons therefor and a list of such teachers/masters be laid on the Table of the House ?

Shri Prabodh Chandra : No. Only three such teachers are still unconfirmed. The reasons for not confirming them will be communicated later on. Their names are as under :—

(1) Shri Mai Lal, Teacher.
(2) Shri Ram Sarup, Teacher.
(3) Shri Prem Parkash, Teacher.

Statement by the Minister of State

Minister of State for Excise, Printing and Labour (Chaudhri Sunder Singh) : Mr. Speaker, You will recall that a few days ago, I promised to make a statement before this House regarding the demands of the Government Press Workers, Sir, ...

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਯਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़, आर्डर। मैं बार बार यहां पर कह चुका हूं कि इस हाउस में तीन ज़बानें इस्तेमाल हो सकती हैं और मैं किसी आनरेबल मैम्बर को इस बात के लिये बाईण्ड नहीं कर सकता कि वह इन तीन ज़बानों में से किसी एक में न बोले। (Order please, order, I have repeatedly made it clear to the House that here the members can express themselves in three languages and therefore, I cannot bind any hon. Member not to speak in any particular language out of these three languages.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। सरदार तारा सिंह जी आप बैठ जाइए। (Order, please, Sardar Tara Singh should resume his seat.)

Minister of State for Excise, Labour and Printing : Mr. Speaker, you will recall that a few days ago, I promised to make a statement before this House regarding the demands of the Government Press Workers. Sir, with your permission, I am accordingly making the promised statement to the House.

2. The Government Press Workers had submitted a charter of 17 demands to the Government in the Printing and Stationery Department. The most important of these demands relate to the revision of their pay-scales, reduction in the working hours, confirmation of temporary employees, recognition of their Union, special Holidays, change in Service Rules, abolition of the Apprenticeship system, abolition of system of promotion by test, etc.

3. In July, 1965, the Press Workers had given a notice of observing 21st July as the Protest Day. With a view of personally ascertaining the position regarding these demands, I convened a meeting of the departmental

[Minister of State, Excise Labour and Printing]

officers and representatives of the Workers in my office. All the demands were thoroughly discussed and the exact position as then obtaining in respect of each demand was fully explained. I assured the Workers that the Government would consider their reasonable demands sympathetically and speedly. I also advised them not to resort to any agitation or demonstration for the fulfilment of their demands. The Workers appreciated that an opportunity was given to them to explain their demands personally and they assured me of their full co-operation.

4. I have ever since been making earnest efforts to expedite decisions on the various demands of the Workers. I may mention that their most important demands, particularly those regarding the revision of pay-scales and reduction in working hours, have been constantly receiving my personal attention. I am glad to say that decision has now been taken to reduce the working hours foom 44½ to 43 hours per week. As regards the revision of pay-scales, I shall be referring the matter to the Finance Department shortly. Steps are also being taken to meet their demand for scrapping the Apprentiseship scheme. As regards demand for confirmation, I may say that confirmation against permanent posts have already been made. A proposal for the conversion of temporary posts to permanent ones is also under active consideration. I also hope to settle the question of recognition of the Workers' Unions soon. The demand regarding observance of special holidays, such as the one declared on the occasion of the Reception of the Holy Relices of Guru Gobind Singh Ji, seems to me to be reasonable. I feel that there should be no discrimination between the ministerial and industrial employees in such matters, The Workers are no less devote than their brothern working in the offices This aspect of the matter was specially represented to me on the 25th February, 1966 and the workers were feeling sore about the step-motherly treatment meted out to them in this behalf. I propose to take up this matter with the Chief Minister.

5. I do not want to take up more time of this august House and it would suffice to say that the other demands of the Workers will also be considered sympathetically. Before I close, I would like to express my unhappiness about the methods of agitation and coercion lately adopted by the Workers for pressing their demands, culminating in the one day strike on 25th February, 1966. I expect them to abide by the Government Servants Conduct Rules and would like to make it clear that if they take the law into their own hands, they will lose my sympathies and shall bear the responsibility for the consequences.

6. Mr. Speaker : I thank you before I resume my seat.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਆਣੀ : On a point of order, Sir. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਇਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ difficulty ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (It is the discretion of the Government in respect of the statements which are made here by them. But as for the papers

circulated in the House these are done in all the three languages:)

Personal Explanation by Welfare and Justice Minister

Welfare and Justice Minister (Shri Chand Ram) : As you know, I was not present in the House on the 3rd March, 1966, due to my confinement in bed. Since then, I have not been well and could not attend the House on 4th March also. I learn that during this period certain things have been said by some Hon'ble members in the House and some motives have been attributed to me in my absence. I, therefore, feel constrained to say a few words by way of personal explanation. In the outset I may make it clear that I had no connection whatsoever with the walk-out staged by the Harijan legislators on 3rd March, 1966 and as far as I know, it was not pre-planned. No doubt, at the instance of some Harijan Legislators, a meeting was called in the Committee Room No. 1 of Vidhan Sabha on 2nd March, in which I gave a copy of the schemes proposed to be implemented out of the Harijan Kalyan Fund to each of the members present. I also requested them to let me know if they had any more ambitious or useful schemes. The meeting lasted about half an hour and dispersed to meet againat the residence of Chaudhri Sunder Singh in the evening. In the meeting some of the members present expressed dis-satisfaction with the handling of the Harijan Kalyan Fund. I apprised the members of the position of the Harijan Kalyan Fund and the schemes I had formulated for being implemented out of this Fund as I thought it my duty to keep these legislators in touch with this matter. After a good deal of discussion, it was decided to form a Negotiating Committee to have talks with the Finance Minister and the Chief Minister. I had advised restraint in handling this matter particularly when the Cabinet was fully seized of the matter and had, in fact, constituted a Sub-Committee to go into this question on the basis of my note circulated to the members on the subject on the 18th February, 1966, before the Cabinet meeting.

As already stated, I was confined to bed on the day of the walk-out, i.e., 3rd March, and as you will please recall I arrived in the Vidhan Sabha lounge at about 11.30 a.m. when I learnt that the House had been adjourned. I then came to your room and after some talks with you met the Harijan members alongwith Chaudhri Sunder Singh in the small lounge. Although the Harijan members were higly agitated I strongly advised them not to precipitate matters further. I also asked them to take up the matter with the Finance Minister and the Chief Minister instead of staging any walk-out and creating any untoward scene. While I was still discussing the matter with them, the bells resummoning the House started ringing and the Harijan members also rushed to the Chamber.

From the above it will be appreciated that the whole incident took place in spite of my best efforts and persuation to restrain the members and the walk-out appeared to be the result of some misunderstanding.

श्री बलरामजी दास टंन्डन : यहां पर जो गंगा जली की महिमा गाई गई थी वह बात कलीयर हो जाए कि मीटिंग हुई कहां थी (विघ्न) ।

Mr. Speaker: It is a personal explanation.

Papers laid on the Table

Chief Minister (Shri Ram Kishan) : Sir, I beg to lay on the Table the additions/amendments (3 notifications) made by the Governor in the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, as required under Article 320(5) of the Constitution. (*Interruption*)

Chief Minister (Shri Ram Kishan) : Sir, I beg to lay on the Table the Draft Outline of Fourth Five Year Plan, Punjab State.

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन जी मैं ने एक रिक्वैस्ट करनी है । एक बार पहले भी ऐसा हुआ कि एक इम्पर्टेंट डाकुमेंट कौन्सल के मेज़ पर पहले रखा गया और असैम्बली के मेज़ पर बाद में रखा गया । यह थी हरियाणा डिवैल्पमेंट कमेटी की रिपोर्ट । मेरी इत्तलाह के मुताबिक यह जो चौथी प्लैन की आउटलाइन है यह भी इसी तरह से पहले कौन्सल की मेज पर रखी गई और बाद में आज यहां पर । मुनासिब हो अगर दोनों हाउसिज़ में यह चिट्ठी इक्ट्ठी ही लाई जाए । (I would like to make a request to the hon. Chief Minister. It happened once earlier also. An important document was placed on the Table of the Legislative Council before it was laid on the Table of the Assembly. It was the Report of the Hariana Development Committee According to my information the Draft Outline of the fourth Five-Year Plan of the Punjab State was similarly placed on the Table of the Council earlier to that done in this House. It would be proper if such documents are placed in both the Houses simultaneously.)

मुख्य मन्त्री : यह वाजिब बात है इस पर अमल किया जाए गा ।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, आप ने मेरे सवालों के बारे में कहा था कि सात सात दिन की एक्स्टैनशन दी गई है । "मेरे सवालों 3095, 3066 वगैरह का जवाब 16 फरवरी को आना चाहिए था.....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मेरे चैम्बर में बात कर लें । आफिस से पता करके आप से बात करूंगा । (The hon. Member may talk to me in my Chamber about this matter. I will first find out from my office and then discuss with him.)

Presentation of the 23rd report of the Public Accounts Committee

Dr. Bal Krishan (Chairman Public. Accounts Committee) : Sir, I beg to present the Twenty Third Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1963-64 and the Audit Report 1965 and Finance Accounts of the Punjab Government for the year 1963-64.

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिबा, मैं ने उस दिन एक काल अटैनशन मोशन दी थी और मैं ने अर्ज़ किया था कि मेरी अरैस्ट में होम मिनिस्टर सरदार दरबारा सिंह का हाथ है । आप ने फरमाया था कि मैटर अन्डर इन्क्वायरी है । मैं ने रिक्वैस्ट की थी कि यह पता कर के बताएं कि यह इन्क्वायरी कौन कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष : डी. आई. जी. ।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, भला एक डी. आई. जी., आई. जी. और होम मिनिस्टर के कन्डकट की क्या इन्क्वायरी करेगा। यह इनजस्टिस है। या तो आप इस को सम्भाल लें। मैं विद दी हैल्प आफ दी आफिशयल रिकार्ड साबित करूंगा कि मेरी अरैस्ट सरदार दरबारा सिंह की डायरैक्ट बलैसिन्ज़ से हुई और यह बात आई. जी. और डी. आई. जी. की नौलिज़ में है। यह तो आप इस इन्क्वायरी को समभालें। (विघ्न) या हाउस के ग्रुप लीडर्ज़ के हवाले की जाए, या केबिनेट की एक सबकमेटी इस की पड़ताल करे. . . .

Mr. Speaker: It is an enquiry made by the Government.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, यहां पर चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब ने जो गलत स्टेटमेंट दी थी उस को चैलेंज किया था। जो उन्हों ने कहा. . . .

श्री अध्यक्ष: मैं ने आप का वरशन मिनिस्टर कनसर्ड को भेज दिया है। (I have sent the version of the hon. Member to the Minister concerned.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : एक हफते से ज्यादा हो गया है उसे।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहिब का रिप्लाई आप को भेज दिया जाएगा। (The reply given by the hon. Minister will be supplied to the hon. Member.)

General Discussion of the Budget for the year 1966-67 (Resumption of)

Mr. Speaker : The House will now resume general discussion of the Budget for the year 1966-67.

The hon. Member, Comrade Jangir Singh Joga, was in possession of the House the other day. He may now resume his speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵਿਚ 53 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੇਰਕੇ ਜਿਹਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਧ, ਮੱਖਣ, ਘੀ ਆਦਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 53 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਗਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1962–63 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।

3.00 p.m.

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭੈੜੀਆਂ ਸਿਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਹੀ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਂਰ੍ਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਐਮੇਰਿਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤੀ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਲ ਧਕੇਲਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਢ ਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ; ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ। ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਡੇ ਵਿਚ ਸੁਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕ ਟੇਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕਲਰਕ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਟੇਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਭੇੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕੀ ਮਹਿਕਮਾ

ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਰਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘਟ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਕ ਕਲਰਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਲਵੇ। ਇਥੇ ਕਲਰਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਹਨ ਜਾਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 64 ਦੀ ਬਜਾਏ 70 ਕਰੋੜ ਇਸ ਚੌਥੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 64 ਕਰੋੜ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 55 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਰਖਣ ਦੇ ਇਹ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅਗਾਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਡਸਟਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਜਾਏ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੁਝੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਅਨਤੀ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਦੋਸ਼ਮਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਘਟ ਖਰਚ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਅਨਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਜਿਥੇ ਤਕ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਪਾਲਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ 57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸ 76 ਕਰੋੜ 34 ਲਖ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 78 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਧੇ ਟੈਕਸ ਕੇਵਲ 22 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ 2700 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 4200 ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾ 1.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ 7 ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 9 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇਸ ਸਾਲ ਨ ਵੀ ਲਗਾਣ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਪਾਲੇਸੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਦੂਬਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੀਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਲੀਫ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹਥ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਨੌਮੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਉ। ਉਥੇ ਅਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਘਟ ਹਨ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿਚ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਣ ਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਡੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ

ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਂਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਕਲਰਕ, ਟੀਚਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਨੂੰਮਨਥੱਯਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਨਥਯਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਘਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਯੂਨਨਿਸਟ ਵਜਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ 7 ਮਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ 16 ਜਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੇ ਤੇ ਅਲਾਊਂਸਾਂ ਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ 4500 ਦੇ ਅਲਾਊਂਸ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 10,000, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਭਤੇ ਅਲਾਉਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਨਯਥਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਟੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਦਾਹਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੱਮ ਗਜ਼ੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੇਜਲੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਲਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜੇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਦਸ ਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ 80,000 ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗਵਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਥ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰ ਜੋ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਾਵਜੂਦ ਏਤਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਕ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ? (How much more time will the hon. Member, Comrade Joga, take ?)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਬਸ ਜੀ ਕੋਈ 5—7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਗਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਸੂਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਸੂਦ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰਜ਼ੁਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮ ਵਿਚ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼. ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਚੌਥਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਨ ਕਰਣ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ 2—3 ਨੁਕਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਗ ਦਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ 1000 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਤਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਪਾਲੀਸੀ ਨਾਲ ਫੁਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਹਤਤਾ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਖ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿਚਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਸਾਨ ਬਤੌਰ ਸਬ-ਸੀਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਐਸ. ਸੀ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਦ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਤਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (**ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ** : ਗਰੀਬ ਤਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ]

ਚੰਗਾ ਸੀਡ, ਫਰਟੈਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਸੀਡ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਮੁਹਰਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੀਡ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ । ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਮਿਲੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ । ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ । 30 ਰੁਪਏ ਟਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ? ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਏਥੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ । ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਕੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ? ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਾਂ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਦਿਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾ 60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾ ਇਕ ਲਖਤ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਗੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਲਾ ਗੁੜ ਦਾ ਭਾ ਐਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਿਆ ? ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ੨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦੇਵੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾ ਦੇਵੇ । ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਟੇਲਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਡ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁ-ਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ । ਏਥੇ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਆਦਮ ਪੁਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਪਰੋਂ ਉਤਰੇ ਸਨ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ । ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਸੁਹਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਸੁਹਾਗਾ

ਫੇਰ ਦਿਤਾ । ਅਜੇ ਤਕ ਆਦਮ ਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਠੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਏਥੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ । ਅਸਲ ਵਚ ਸਾਡੀ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਇਹ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਨਾਲ ਪਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਾ ਦਿਤੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ । 1964-65 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ :

> "As stated earlier , Rs 5 crores have been set apart for schemes for the welfare of Harijans".

ਇਹ ਸਫਾ 21 ਤੇ 1964-65 ਦੀ ਬੱਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੁਆਰਾ ਦਸਿਆ "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1962 ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 386 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ 114 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 500 ਲਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ । ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਦਿਨ ਦੇ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਗਿਣਵੀਂ ਮਿਣਵੀਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਰਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਰਖੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਕਮ ਰਖ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਗਏ, 114 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ । ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ]
8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ 246 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਕੇਜ ਸੀਡ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਧਿਆ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ੨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਕ ਜਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ । ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਧਾੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲਈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿਉ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ । ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ । ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋ । ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਭੀਖ ਚੁਰਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ । ਉਦੋਂ ਇਕ ਪਿਗਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਹਰਿਆਣੇ ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਰ ਰਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੀਪ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ 10—10 ਭੇਡਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਆ-ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਤ ਦਿਉ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਏਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪਰਾਈ-ਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਇਹ ਤਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਉ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ । ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਤਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਭੇਜੋ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 35 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦਾ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਉਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਂਗੇ । ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਕਲ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਛਡ ਦਿਉ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਡ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚਲਣ, ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਿਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ

[ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੰਨਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਗਾ ਕੀਤਾ ।

ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਾਸ II ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਖਾਇਆ ਹਰੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਜ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਢ ਦਿਓ । ਉਹ ਐਮ ਏ. ਪਾਸ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਉਸਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਹੋਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ, ਹਰੀਜਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਿੰਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਛਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

प्रिंसिपल रला राम (मुकेरियां): अध्यक्ष महोदय, सरदार कपूर सिंह जी ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है उसके लिये उन्हें मैं बधाई देता हूं । उन्होंने अपने बजट में दो बातों की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया और ज़ोर दिया है जो मैं समझता हूं सरकार के लिये क्रेडिटेबल हैं । पीछे जो संकट आया वह बड़ा भारी था और उसका ज़्यादा बोझ पंजाब की जनता और पंजाब सरकार पर पड़ा लेकिन जिस खुशअसलूबी, सूझ बूझ के साथ इस सारी इकनोमिक सिचुएशन को फेस किया गया उसके लिये मैं पंजाब सरकार और खास तौर पर वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । यह बात भी बड़ी प्रशंसनीय है कि बावजूद इस भारी संकट के बारिश न होने की वजह से, भारी खुश्क साली पड़ने के बावजूद हमारी सरकार कुछ हद तक प्राइस लेवल को कंट्रोल कर पाई है । उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । मैं मानता हूं कि कुछ परसैंट कीमतें अप गई हैं । लेकिन इस भारी संकट को देखते हुए और कुदरत की तरफ से जो कोप हम पर आया उसे देखते हुए सरकार बधाई की पात्र है कि उसने प्राइस लाइन को गैर मुनासिब हद से बढ़ने नहीं दिया और इसके लिये मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं ।

बजट स्पीच में हमारे वित्त मंत्री ने कृषि के सम्बन्ध में बजा तौर पर ज़िक्र किया है । हमें फख्र है कि पंजाब हिन्दुस्तान ग्रेनरी माना जा रहा है । जब भी किसी प्रदेश में अन्न संकट पैदा होता है तो हमारी सरकार पंजाब के किसान जो अन्न पैदा करते हैं, जिसके लिये वह बधाई का पात्र है, उन संकटग्रस्त प्रदेशों को भेज कर वहां की जनता की सेवा कर पाते है । इस के लिये

पंजाब सरकार और पंजाब के लोग प्रशंसा के पात्र हैं। पीछे हमारे राज्य में 21 फीसदी प्रोडक्शन में बढ़ौती हुई और यह कोई कम बढ़ौती नहीं है। अगर इस दफा कुदरत हमारे खिलाफ न चलती तो शायद हम हिन्दुस्तान की अन्न की खासी ज़रूरत को पूरा कर पाते और हमें जो एक अरब से ज्यादा रुपया विदेशों से अन्न मंगाने के लिये खर्च करना पड़ता है उसमें काफी कमी होती। लेकिन कुदरती हालात हमारे मुआफिक नहीं रहे। फिर भी आशा है कि जो प्रयत्न सरकार और जनता की तरफ से कृषि के सम्बन्ध में हुआ उसे ध्यान में रखते हुए जो अन्न संकट आता अप्रैल में आने का डर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त संकट खास भयानक शक्ल में आएगा, मैं समझता हूं पंजाब के लोग उस संकट को टालने में खासी मदद कर सकेंगे उस प्रोडक्शन की वजह से जो सरकार और जनता की कोआप्रेशन से बढ़ रही है। यह प्रोडक्शन और भी बेहतर हो सकती है अगर सरकार हमारी खाद की मांग को पूरा करने के लिये विशेष प्रयत्न करे यह कहना कि खाद की कीमत गवर्नमैंट आफ इन्डिया मुकर्रर करती है इस लिये पंजाब सरकार बेबस है किसी हद तक तो ठीक है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उसकी कीमत गवर्नमैंट आफ इंडिया कम नहीं करती तो हमारी सरकार को चाहिए कि वह रूरल एरिया में और खास तौर पर बैकवर्ड एरियाज़ में फर्टेलाइज़र को सबसिडाइज़ करके लोगों को सप्लाई करे। अगर कीमत का कम करना पंजाब सरकार के बस में नहीं तो उसे सबसिडाइज़ करके लोगों को देना तो इनके बस में है। इस तरीका से फर्टेलाइज़र की कीमतों को नहीं बढ़ने देना चाहिये और कम करना चाहिए। हम गांव जाते हैं और लोग हमें बताते हैं कि जहां उन्होंने फर्टेलाइज़र इस्तेमाल किया बारिश बेशक देर से आई लेकिन उसकी वजह से जहां 2 फर्टेलाइज़र पड़ा है वहां अगर पहले गंदम का एक स्टाक था वहां अब नीचे से कई कई स्टाक फूट रहे हैं। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि फर्टेलाइज़र की दिक्कत को और इसकी महंगाई को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए और दिहात में खास तौर पर छोटे ज़मींदारों को यह सबसिडाइज़ करके कम कीमत पर सप्लाई करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि इस अन्न संकट में पंजाब और हिन्दुस्तान की सेवा कर सकें।

ट्यूबवैल्ज़ ऐनरजाइज़ करने के लिये सरकार ने प्रयत्न किया जिसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। लेकिन यह प्रयत्न न्यायपूर्वक ढंग से नहीं हुआ। अनेकों ऐसे अलाके हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मेरे एक सवाल में जवाब में मुझे आज ही बताया गया है कि इतने लोगों ने मुकेरियां के हलके से कुनैक्शन्ज के लिये अरज़ियां दी मगर मिला निल। यह ठीक है कि बिजली बोर्ड जो है वह अटानोमस बाडी है लेकिन जो पालिसी है वह तो इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्टरी ले डाउन करती है। यह इन्साफ की बात नहीं है कि कुछ बलाक तो 100 फीसदी इलैक्ट्रीफाई हो जाएं लेकिन कुछ ब्लाक ऐसे हों जहां एक भी गांव इलैक्ट्रीफाई न हो। आज ही मेरे एक सवाल का जवाब आया है कि हाजीपुर ब्लाक में पिछले 10/15 साल में एक भी गांव इलैक्ट्रीफाई नहीं हुआ। यह कितनी ना इनसाफी की बात है। अगर बिजली बोर्ड गलती करता है तो इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्टरी जो पालिसी ले डाउन करती है उसका तो फ़र्ज़ है कि वह किसी इलाके को निगलैक्ट न होने दो। यह बड़ी irrational and unjust distribution बिजली की हो रही है और यह काबिले अफसोस है और काबिले एतराज़ भी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह इन्साफ की

[प्रिंसीपल रला राम]

आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि वह इस का इलाज करे। इस तरह करने से प्रोग्रैस लौप साइडिड हो जाती है। हमें विकास के मामले में पूरे न्यायपूर्वक ढंग से चलना चाहिए वरना सही मायनों में विकास नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ने वित्त मंत्री महोदय की स्पीच ऐजूकेशन के बारे में पढ़ी और मुझे पढ़ कर बहुत खुशी हुई। उस में लिखा हुआ है कि सरकार ने इस वर्ष प्राइमरी तथा मिडल स्कूलों को अपग्रेड करने की स्कीम बनाई है। उन्होंने इन के लिए 100–100 स्कूलों की संख्या निश्चित की है। पहले भी स्कूल अपग्रेड किए गए। मैं मानता हूं कि स्कूलों को अपग्रेड करने पर फिनांस के बारे में काफी दबाव पड़ता है। मैं यह भी कहने में हिचक नहीं समझता कि यह मसला किसी तरह से निग्लैक्ट नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने अपग्रेड करने के लिये स्कूलों की जो संख्या निश्चित की है, वह बहुत कम है। इस लिए सरकार को इस संख्या को बढ़ा कर 200, 200 कर देनी चाहिए ताकि पंजाब के लोगों की कुछ डिमांड मीट हो सके। स्कूलों की क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है लेकिन इस के मुकाबले में क्वालिटी में बढ़ौतरी उतनी नहीं हुई जितनी हमें आशा थी। इस के बारे में आप दूसरे देशों के साथ मुकाबला करें तो आप को पता लगेगा कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है। हमारी क्वालिटी ना तसल्ली बख्श के बराबर ही है। इस लिए मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ शीघ्र ध्यान दे। टीचर्ज़ के लौट को बेहतर बनाया जाए। प्राइमरी स्कूलों के टीचर्ज़ की तन्खाह 100 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ने टीचर्ज की तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि वह अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकेंगे क्योंकि उन्हें अपने पेट को भरने की समस्या सामने रहती है। इस लिए सरकार को टीचर्ज़ के स्टेटस को बेहतर बनाना चाहिए। सरकार ने टीचर्ज के लिये 25 लाख रुपए दिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने उन के लिए थोड़ी राशि रखी है। प्राइमरी स्कूलों के टीचर्ज़ और दूसरी उच्च क्लासों के टीचर्ज बुरी तरह से रॉट हो रहे हैं। यह शिक्षा देने की सब से नीचे की पौड़ी है। उन की हालत को सुधारने के लिये सरकार को प्रबन्ध करने चाहिएं। इस लिए सरकार को टीचर्ज़ फंड के लिए और रुपया प्रोवाइड करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हमारे देश में को-एजूकेशन की तालीम चालू करने से अपने ऊपर बहुत ही ज़िम्मेवारी ली है। यह इतनी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि अगर सरकार इस ज़िम्मेदारी को सही ढंग से निभा न सकी तो हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत भारी खतरा होगा। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस ज़िम्मेदारी को बड़ी संजीदगी से निभाए और इस तरफ खास ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, सुनने में आता है कि स्कूलों के अन्दर इम्मौरल के कई केसिज़ हो रहे हैं। इस लिये सरकार को इन केसिज में किसी तरह से किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। मुझे यह बात भी देख कर अफसोस होता है कि स्कूलों के अन्दर टीचर्ज़ और टीचरैसिज़ शराब पीते हैं। आप भी समझते हैं कि इन बुरी चीजों का जनता पर और बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि को-एजूकेशन इक्नामिक रीज़न्ज की वजह से दूर नहीं हो सकती

है। रूस के अन्दर जब कम्युनिस्ट हकूमत बनी थी तो उन्होंने वहां पर को-एजूकेशन की प्रणाली चालू की थी। लेकिन वहां पर जल्दी ही यह स्कीम बन्द कर दी गई थी। हर गांव के अन्दर एक लड़कों और लड़कियों के अलैहदा स्कूल खोले नहीं जा सकते हैं। इस का सब से बड़ा रीज़न माली हालत का है। मैं समझता हूं कि सरकार पर को-एजूकेशन प्रणाली को चालू कर देने से बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। जब यहां पर इम्मारेल के और अध्यापकों तथा टीचर्ज़ के स्कूल के अन्दर ही शराब पीने के केसिज बढ़ते जा रहे हैं तो इन हालात में सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इस लिये एजूकेशन विभाग को विशेष कर ध्यान देना चाहिए और ऐसी नाजायज़ हरक्तों को रोका जाए ताकि हमारा स्टैंडर्ड नीचे न गिरे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। जितनी देर तक सर्विसिज़ कोआप्रेटिव सोसायटीज़ खोलने में देर होती रहेगी उतनी देर तक ग्रो मोर फूड में बाधा रहेगी। हर ब्लाक के अन्दर एक सर्विस कोआप्रेटिव सोसायटी खोली जाए। वहां पर सरकार ट्रैक्टर्ज़ रखे। वहां पर सरकार किसानों को सस्ते रेट्स पर ट्रैक्टर मुहैय्या करे ताकि गरीब किसान उन ट्रैक्टरों से अपनी खेती करके लाभ उठा सकें। हमारे इलाके के अन्दर हज़ारों एकड़ भूमि नौ-तोड़ के काबिल है। वहां के लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह खुद उस बन्जर जमीन को नौ-तोड़ कर सकें। वहां पर जमीन ऊपर नीचे है। उस की लैवल बराबर लाने के लिये सरकार को खुद किसानों की मदद करनी चाहिए। सरकार वहां पर बुल-डोज़र मुहैय्या करे ताकि वहां के किसान अपनी ज़मीन को लैवल करके ज़ेरे-काश्त ला सकें। वहां के किसान उन जमीनों को ज़ेरे काश्त लाने के लिये तैयार हैं लेकिन यह तभी हो सकता है कि अगर सरकार उन के लिये वहां पर बुल-डोज़र मुहैया करे। यह बहुत भारी प्राब्लम है। इस लिये सरकार इस समस्या को हल करने के लिये शीघ्र प्रबन्ध करे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार उन किसानों की मदद करेगी तो वह किसान राज्य में खेती की उपज बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, बजट पर स्पीच देते हुए हाउस के अन्दर अकाली ग्रुप के लीडर ने पंजाबी सूबे के मुताल्लिक बातें कहीं। वह खास तौर पर पंजाबी रिजन के हिन्दुओं पर खासे बर्से। मैं समझता हूं कि वह बात बिल्कुल तथा सरासर गलत थी जिस का उन्होंने वर्णन किया। जिस उदारता का सबूत और जिस फ्राख दिली का सबूत पंजाबी रिजन के हिन्दुओं ने दिया, उस की मिसाल देश के अन्दर किसी जगह पर नहीं मिल सकेगी यह ठीक है कि भाषा के मुताल्लिक मतभेद था। जब हमारी सरकार ने और लीडरों ने फैसला किया कि यहां पर रिजनल फारमूला लागू होना चाहिए पंजाबी रिजन के अन्दर स्कूलों पर पहली कक्षा से पंजाबी लागू की जाए तो उस वक्त पंजाबी रिजन के हिन्दुओं ने इस झगड़े को सुलझाने के लिये हर तरह से सरकार का सहयोग दिया। हर चार साल के बाद यह झगड़ा खड़ा हो जाता है। पंजाबी रिजन के हिन्दुओं ने रिजनल फारमूले को बड़ी उदारता के साथ स्वीकार किया था। आप देखते हैं कि पंजाबी रिजन की पब्लिक लाइफ में पंजाबी भाषा का कोई झगड़ा नहीं है। वहां पर रिजनल फार्मूला का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यह लोग वही

[प्रिंसिपल रला राम]

फार्मूला इख्तियार कर रहे हैं जो हिटलर ने फासिस्ट टैकनीक अपनाई थी। यह कुछ चीज को और कुछ लोगों को नफरत शो कर के पोलीटीकल राइट्स हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इन की यह टैकनीक अच्छी नहीं है। यह हेट करने वाली बात खतरनाक है। यह पंजाबी रिजन के हिन्दुओं को हेट करने लग पड़े हैं। यह इन के लिये मुनासिब बात नहीं है। पंजाबी रिजन के हिन्दुओं ने हमेशा फराख दिली का सबूत दिया है। पंजाबी रिजन के हिन्दुओं ने कभी भी नहीं सोचा कि प्रान्त के अन्दर कितने कम हिन्दू उच्च अधिकारी हैं और कितने ज्यादा सिख अधिकारी हैं। वहां के हिन्दुओं ने कभी भी नहीं सोचा कि मंत्रिमंडल में कितने सिख हैं और कितने हिन्दु हैं। आप को पता है कि हिन्दुओं ने सिख मिनिस्टरों को तथा चीफ मिनिस्टर को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट दी है। यह बात किसी से छुपी नहीं हुई है। वहां के हिन्दू समझते हैं कि अगर स्टेट के अन्दर सिख अधिकारी 10 ज्यादा होंगे या 10 हिन्दू कम होंगे तो उस से स्टेट के अन्दर कोई तबाही नहीं होगी। कौन सा तूफान आ जाएगा क्योंकि यह भी हमारे भाई हैं। लेकिन जिस तरह से यह हाउस के अन्दर अपना केस प्लीड कर रहे हैं वह पंजाबी रिजन के हिन्दुओं के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। पंजाबी रिजन के हिन्दू हमेशा फराख दिली का सबूत देते आए हैं। वहां के हिन्दुओं ने नेशनलिज्म का सबूत दिया। जहां पर कहा जाता है कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए और हरियाणा प्रान्त दिया जाए। हरयाणा इलाके के लोग समझ रहे हैं कि उन के साथ डिवैल्पमैंट के बारे में इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि उन की यह मांग दूर करनी चाहिए। यहां पर जो लोग पंजाब को तकसीम करने की बातें चाहे वह इस वक्त हरयाणा प्रान्त के बनाने में हमदर्दी शो कर रहे हो, मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रान्त के बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पंजाबी रिजन के हिन्दुओं को नफरत की निगाह से देख रहे हैं और उन में नफरत डालने की कोशिश कर रहे हैं, वह किसी तरह से स्टेट को अलैहदा करने में स्टेट की सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई गलती है तो उसे दूर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पंजाबी रिजन के हिन्दू फरिश्ते नहीं कि वह कोई गलती नहीं करते हैं। अगर कहीं कोई नुक्स है उस को दूर किया जा सकता है। जिस तरह से अकाली पंजाबी रिजन के अन्दर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमारा रवैय्या हमेशा से फराख दिली का रहा है। यहां पर अब अलैहदा सूबा बनाने की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि यह निहायत ही अफसोसनाक बात है। यहां पर फिरकाप्रस्त एडमिनिस्ट्रेशन लाने की बात पीछे छुपी हुई है। इस के पीछे चौधरमें की बात छुपी हुई है। 4-3-66 को अकाली ग्रुप के लीडर ने जिस तरह से इस केस को प्लीड करने की कोशिश की वह काबेल अफसोस है। मैं उन की बात का जबरदस्त प्रोटैस्ट करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है कि अपने आन्दोलन को कामयाब करने के लिये इस किस्म के तरीके अपनाए जाएं कि Let us find out some scope goat to hate यह अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप का धन्यवाद।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : अध्यक्ष महोदय, यह जो इस साल का बजट, सैशन है यह एक महत्वपूर्ण सैशन है क्योंकि हमें इस में पन्द्रह साल के विकास क्रम के बाद

4.00 p.m.

डीवैलपमैंट के प्रोग्राम के बाद आत्म निरीक्षण का मौका मिलता है, सैल्फ इन्ट्रासपेक्शन का मौका मिलता है। हमारे उद्देश्य क्या थे, क्या लेकर हम चले थे और क्या हम प्राप्त कर सके हैं। हमें देखना चाहिए कि अगर कुछ गलतियां हैं, उन को मान कर कोई अच्छी राह निकालें, अच्छे मैथिड अडाप्ट करें अच्छे प्रोग्राम चलायें। हमें यह सोचना चाहिये। लेकिन हमारा बहुत सा बजट और समय हरयाणा प्रान्त, पंजाबी सूबा और हिल्ली एरियाज में ही लग जाता है।

MEMBER DETERMINED BY THE ASSEMBLY TO OCCUPY THE CHAIR

श्री अध्यक्ष : मुझे किसी जरूरी मीटिंग के लिये अभी बाहर जाना है। इस वक्त हाउस में डिप्टी स्पीकर भी नहीं हैं, पैनल आफ चेयरमैन में से भी कोई मैम्बर नहीं है। अगर हाउस इजाजत दे तो मैं प्रिंसीपल रला राम जी से रिक्वैस्ट करूं कि वह चेयर पर बैठ जाएं। (I have to go out of the Chamber in connection with an important meeting. At this moment neither Deputy Speaker nor any of the Member of the Panel of Chairmen is present here. If the House agrees Principal Rala Ram may be determined by the Assembly to take the chair.)

आवाजें : ठीक है।

(इस समय श्री रला राम जी ने कुर्सी ग्रहण की)

RESUMPTION OF THE GENTRAL DISCUSSION OF THE BUDGET

पंडित मोहन लाल दत्त : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमें संजीदगी से विचार करना चाहिए। हमारे देश के सामने इतने बड़े बड़े मसले हैं, देश तूफानी दौर से गुजर रहा है, तरह तरह के संकट हमारे सिर पर हैं। मगर इस पर विचार करने के लिये इस समय कितनी हाजरी हाउस में है। वजीरों में से कोई भी आप नहीं बैठता। सिर्फ सरदार कपूर सिंह जी बैठे हैं जिनका काम केवल पैसे बांटने का है और कोई वह काम नहीं कर सकते। मैम्बरान उठ कर बधाइयां देंगे कहेंगे कि बड़ा अच्छा बजट है। हम यह मानते हैं कि सड़कें बनी हैं स्कूल बने हैं डैम भी बने हैं मगर आप अंदाजा लगाएं कि कितने साल लग गए हैं? देश को आजाद हुए 18 साल हो गए हैं, विकास के लिए अरबों रुपये खर्च किये गए, देश पर कितना कर्जा चढ़ गया, अरबों खरबों रुपये देश पर कर्ज हो गया। लेकिन नतीजा क्या निकला है? चेयरमैन साहिब, नतीजा यह है कि अगर बिरला, टाटा, डालमिया या वजीरों के नुक्ता निगाह से देखा जाये तो बड़ा विकास हुआ है लेकिन, अगर गरीब के नुक्ता निगाह से अंदाजा लगाएं तो विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ है। जैसे एक शायर ने कहा है।

हम ने माना बहुत की है तरक्की हम ने,
एक भूखे से पूछो कि हकीकत क्या है।

आप की एप्रोच गलत है। आप जन-साधारण की खाल उधेड़ कर पैसा इकट्ठा करते रहे और फजूलखर्चियों पर खर्च करते रहे। आपने पैदावार बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं

[पंडित मोहन लाल दत्त]

दिया। अगर पैदावार बढ़ी भी है तो जो कीमतें बढ़ीं और उन से जो दौलत बनी वह किस के पास आई? वह आई चंद बड़े बड़े व्यापारियों के पास, चंद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के जेब में और वह दौलत आई बड़े बड़े जागीरदारों के पास या फिर वज़ीरों ने गुलछर्रे उड़ाए। लेकिन बाकी जन-साधारण का कचूमर निकल गया। उन की हालत पहले से भी बदतर हो गई। चेयरमैन साहिब, मैं यह बातें ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा। यह बातें सरकारी आंकड़े बताते हैं, सरकारी स्टेटिक्स बताते हैं जो कि गवर्नमैंण्ट की कमेटियों के द्वारा बताए जाते हैं। हालत यह है कि आज हमारी कौमी पर कैपिटा आमदनी गवर्नमैंण्ट आफ इंडिया की तरफ से जो बताई जाती है वह 25 रुपये है। हो सकता है कि पंजाब में ज़्यादा हो। मगर आप देखें कि 25 रुपये में क्या बनता है? आप अंदाज़ा लगाएं कि कौमी स्टैंडर्ड जो हमारा है उस के मुताबिक जिसमानी हालत को ठीक रखने के लिये 35 रुपये सिर्फ खुराक पर खर्च आता है। और अखराजात तो दरकिनार रहे, सिर्फ रोटी पर 35 रुपये खर्च आता है। यह अंदाज़ा है कि 25 रुपये भी सब की इन्कम नहीं है। 60 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन की आमदनी 25 रुपये से कम है उन की पर कैपिटा इन्कम 25 रुपये भी नहीं। यह बातें रिपोर्टें बताती हैं। यह बातें जमा खर्च नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा। आप खादी ग्राम उद्योग का जुलाई के महीने का जर्नल पढ़ें। महता बैकुन्ठ लाल बड़े मशहूर इकोनोमिस्ट हैं, उन का लेख पढ़ें और देखें कि देश की क्या हालत है। इन सारी बातों को सामने रखते हुए हमें सोचना चाहिये कि हमारा पहला काम क्या था। हमारा पहला काम ही पूरा नहीं हो सका। पहला काम तो यह है कि यहां के लोगों को कम से कम मिनीमम कन्ज्यूमर्ज़ गुड्ज़ और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बेसिक नैसेसीटीज़ हैं इस आबादी की अक्सरियत को वह तो मुयस्सर हों।

"At the conclusion of its deliberations, the seminar urged that in national planning the first priority should be accorded to the securing of a national minimum of basic consumer goods and social amenities for all the households in the country."

सही प्लानिंग का तरीका तो यह है कि आप मिनीमम कन्ज्यूमर्ज़ गुड्ज़ तो लोगों को दें। जितनी भी आप की प्लानिंग है वह सारी हैपहैज़र्ड है, अन्धाधुंध है। इस का नतीजा क्या निकला है? हमारी पन्द्रह साल की प्लानिंग का नतीजा क्या निकला है? इस सम्बन्ध में हमारी 22 तारीख की ट्रिब्यून के एडीटोरियल में छपा है। वे कहते हैं :

"The gravamen of the charge against the economic policies of the Government is that the tax burden is very heavy. That it is not equitably distributed. That the resources mobilized by the Government for development are not properly utilised and are not yielding results commensurate with the sacrifices of the people. No statistics of mounting production can obscure from us the asperities of the present economic situation—an oppressive tax system, continuously increasing prices which has made exceedingly difficult for the common man to make both ends meet, growing unemployment and increasing concentration of economic power."

यह बात उन्होंने लिखी है। यह उन की निर्पेक्ष राए है। उधर वाले चाहे गवर्नमैंट को बधाइयां देते रहें। मैंने यह हकीकत आप के सामने रख दी है। मैं आप के सामने कुछ

बेसिक बातें रखना चाहता हूं । आप ने बजट में विकास के लिये आंकड़े रखे हैं कि इतने रुपये फलां काम के लिये, इतने रुपये फलां काम के लिये एलोकेट कर दिये गये हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि बिना बुन्याद के इमारत कभी खड़ी हो सकती है । बिना बुन्याद के इमारत को खड़ो करना मूर्खता की बात है । चेयरमैन साहिब, सरदार कपूर सिंह जी ने पिछले एक सैशन में जो भाषण दिया उस में उन्होंने फरमाया कि जो डीवैल्पमेंट की बातें हम कर रहे हैं, यह डीवैल्पमेंट नहीं चलेगी । क्यों नहीं चलेगी ? आप फरमाते हैं :

"Elimination of corruption is a vital factor for ensuring the success of our development plans and for raising the moral standards of the community."

यह आपने फरमाया था । आगे चल कर कहा कि हम कुरप्शन को दूर कर रहे हैं । विजिलेंस डिपार्टमेंट बना दिया कि ऐसे लोगों पर केसिज़ चलाएं । आप ने बताया कि ऐसा इन्तजाम कुरप्शन को रोकने का किया है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुरप्शन इस तरीके से नहीं रुकेगी । महज़ कुअरसिव मैथड्ज़ से ही आप कुरप्शन को नहीं दूर कर सकते । कुरप्शन रोकने का सही तरीका है मारेल वैल्यूज़ की स्थापना । पहला काम है इसमें रुहानियत को लाना । मगर यह जो बुनियादी काम है वह तो आप ने किया नहीं । इस की तरफ तो आप ने ध्यान नहीं दिया । आपने किया क्या ? देश की आज़ादी के बाद आप ने लोगों को शराब पिला कर, उन को अफीम खिला कर, नशे पिला कर और तरह तरह का भ्रष्टाचार पैदा कर के उन को इखलाकी तौर पर तो बिल्कुल गिरा ही दिया है । यह एक हकीकत है जिस से कोई भी आदमी इस वक्त इनकार नहीं कर सकता क्योंकि क्या शराब पीने से इनसान की बुद्धि ठीक रहती है ? आप स्वयं ही देख लें कि जब से देश आज़ाद हुआ है आप की शराब की नीति कैसी रही है ।

(पंडित चिरंजी लाल शर्मा जो कि पैनल आफ चेयरमन के सदस्य हैं, ने कुर्सी ग्रहण की)

आपने तो हर साल इस शराब की इल्लत को ज्यादा और ज्यादा बिढ़ाने का यत्न किया और कर रहे हैं पैसे के मोह से । आखिर यह जो आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं यह किस लिए ? पैसा तो इनसान को उत्तम इन्सान बनाने के लिये होता है लेकिन आपने इसी पैसे से इन्सान को हैवान बना दिया है । उस का इखलाक आप ने बिगाड़ कर रख दिया है । तो फिर आप ने क्या बनाया है ? मुख्य बात है ह्यूमन फैक्टर । क्या व्यक्ति को सही मानों में आप ने इन्सान बनाया है ? जैसा कि प्रिंसिपल रला राम जी ने बताया कि आप ने ठीक प्रकार से शिक्षा का इन्तज़ाम नहीं किया । आप की जो शिक्षा नीति है वह भी सर्वथा गलत । अन्धाधुन्ध आप स्कूल खोले जा रहे हैं । आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई पालिसी आपने नहीं बनाई, कोई सही दिशा आपने नहीं दी । जहां पर किसी एम. एल. ए. ने कह दिया वहां पर स्कूल खोल दिया । और अब अठारह साल के बाद आप को होश आया है जो कि शिक्षा के बारे में एक कमिशन बैठाया है यह देखने के लिये कि कौन सी शिक्षा चाहिए, कौन सी शिक्षा नीति अपनानी चाहिए । अब होश आई है यानि पूरे अठारह साल के बाद । इसी तरह से जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी का सम्बन्ध है, वह भी वही पुरानी तर्ज़ की. . . .नौकरशाही, पुरानी ब्यूरोक्रेसी वाली । अब कई सालों

[पंडित मोहन लाल दत्त]

के बाद सोचा, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज़ कमिशन बनाया, उस की रिपोर्ट गो आ चुकी है लेकिन उस पर गौर ओ खोज़ होगा और आप देख लेना कि उस पर भी अमल कुछ नहीं होगा। किसी प्रकार से उस की सिफारिशात पर अमल नहीं किया जाएगा। तो मेरे कहने का भाव यह है कि तरक्की महज़ अन्धाधुन्ध पैसा खर्च करने से नहीं होती। इस मौके पर मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब तक आप का यह आर्थिक और सामाजिक ढांचा पूंजीवादी आधार पर कायम रहेगा, तरक्की कभी नहीं हो सकती। कम अज़ कम कामन मैन के हित की दृष्टि से, जन साधारण के हित की दृष्टि से ऐसे ढांचे में तरक्की का कोई स्थान नहीं है। कोई विकास सम्भव हो नहीं सकता। आप इस सम्बन्ध में ज़बानी जमा खर्च जो चाहें करते रहें लेकिन वास्तविक तौर पर आप कह नहीं सकते कि जनसाधारण को कोई लाभ पहुंचा है। ठीक है, यह कहा जा रहा है कि सोशलिज़्म लाएंगे पर अब तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम आप उठा नहीं सके। ला नहीं सके। सरकारी पार्टी के लोगों में आईडिआलोजीकल कन्फयूज़न है। मैं पूछता हूं कि क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस कदम उठाया है, कोई भी ठोस पालिसी आप बना सके हैं ? इस वक्त कांग्रेस, जो कि देश में रूलिंग पार्टी है, उसी के अन्दर चार किस्म के ग्रुप हैं : एक राईटिस्ट, दूसरा लैफ्टिस्ट, तीसरा सैण्ट्रलिस्ट और चौथा अपरच्यूनिस्ट यानी मौका ताड़ने वाले। चार किस्म के ख्यालात इस पार्टी में हैं जो कि देश के अन्दर सोशलिज़्म लाने का दावा करती है और कर रही है। इस प्रकार हमारे देश के अन्दर इन्होंने एक तरह से आईडिआलोजीकल कन्फ्यूज़न सा पैदा किया हुआ है। कोई डैफिनिट पालिसी नहीं, कोई डैफिनिट प्रोग्राम नहीं। अभी जो आल इंडिया कांग्रेस का सैशन पिछले दिनों हुआ वहां पर भी इकनामिक पालिसी के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। वहां पर भी एक कमेटी बैठा दी गई जो कि अभी अठारह साल की हकूमत के बाद भी इस बात पर सोच विचार करेगी कि देश को किस आर्थिक ढांचे की ज़रूरत है और वह कैसे प्रोवाईड किया जा सकता है। कोई निर्णय वहां पर भी नहीं कर सके कि देश के लिये क्या करना है और क्या नहीं करना है। चेयरमैन साहिब, मैं तो यही कहूंगा कि इस समय हमारे देश की तरक्की के रास्ते में तीन रुकावटें हैं ;

(1) भौतिकवाद

(2) पूंजीवाद; और

(3) राजवाद;

सबसे पहिली बात तो यह है कि इस समय लोगों का दूसरी बातों को, अपने देश की पुरानी अच्छी २ बातों को छोड़ कर, मैटीरियलिस्टिक दृष्टिकोण हो गया है। इस लिये इस दृष्टिकोण से जो भी काम होगा निश्चय है कि इस में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भौतिकवाद को दूर करने का, भौतिकवाद के असर को दूर करने का एक ही हल है कि आप लोगों में रुहानियत का प्रवेश कराएं, उन में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बढ़ाएं और उसे लाने का केवल मात्र तरीका यही है कि शिक्षा जो है वह ठीक ढंग की हो और जहां जहां जो जो बुराई है उसे दूर करने के यत्न किए जाएं। सोशल एजूकेशन आप

बेहतर तरीके पर लाएं। मैं मानता हूं कि सोशल और कल्चरल एजूकेशन पर पैसा खर्च होता है, बजट में आप पैसा रखते हैं लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार की एजूकेशन आप बच्चों को, लोगों को दे रहे हैं वह उन्नति की तरफ नहीं बल्कि गिरावट की तरफ ले जा रही है और इस से देश विनाश की तरफ ही जा रहा है। जहां तक पूंजीवाद को दूर करने का ताल्लुक है, उसके लिये आप कहते हैं कि सोशलिज़्म लाएंगे। लेकिन, जैसा कि मैं ने अभी अभी निवेदन किया है, वह तो ठीक ढंग से लाने की बात ही क्या उसकी ठीक परिभाषा भी अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। आप को चाहिये कि जिस समाजवाद का स्वप्न गान्धी जी ने देखा था, समाजवाद की जो रूपरेखा उन्होंने खैंची थी आप को चाहिए कि आप उस किस्म का सोशलिज़्म देश में लाने का यत्न करें। भगवान की कृपा से हमारा देश एक महान देश है जिसमें महात्मा गान्धी जैसे महान नेता पैदा हुए.. हमारी रहनुमाई करने के लिये इतने महान नेता पैदा हुए। लेकिन कितने दुख की बात है कि आप उन की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और हैपहैज़र्डली चल रहे हैं। न तो आप गान्धी जी की शिक्षा को मानते हैं और न रूस को। न आप इंगलैंड को ही पूरी तरह से मानते हैं और न ही किसी दूसरे को। आप की पालिसी का नाम क्या है आप की पालिसी का नाम है "मिकस्ड पालिसी"। यानि जैसा जो कोई मर्ज़ी हो समझ ले। जिस की मर्ज़ी हो पूंजीवाद की तरफ चले, जिस की मर्ज़ी हो सोशलिज़्म की बात कर दे और जिसकी मर्ज़ी हो वह कोई और बात बना दे। यह क्या खिचड़ी है? चेयरमैन साहिब, चीन की बाबत आप कहते थे कि वहां डिक्टेटरशिप है। वहां पर फलां चीज़ है, फलां बात है। मैं आप को बताऊं कि वह एक अफीम खाने वाले लोगों का देश था। एक समय था जब कि लोग वहां अफीम के नशे में डूबे रहते थे। लेकिन चन्द ही वर्षों में उन्होंने वहां से अफीम का नाम भी खत्म कर दिया है। अफीम खाना बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने मुल्क में देखें। अपनी निश्चित नीति.... प्रोहिब्शन की नीति के बावजूद भी यहां पर नशा करने की इल्लत को बढ़ा रहे हैं। आखिर यह किस किस्म की पालिसी है? फिर यह जो राजवाद है, यह जो वैलफेयर स्टेट की तस्वीर आप ने लोगों के सामने रखी हुई है यह राजनीतिक ढांचा भी बिल्कुल बोदा है, गलत है। यह एक ऐसा राजनीतिक ढांचा है जिस में पार्लियामेंट, असैम्बली और दूसरी इस तरह की चीजें, यह बिल्कुल फिज़ूलखर्ची है। यह तो एक सैंट्रेलाईज़्ड स्टेट आफ एफेयर है। सैंट्रेलाईज़्ड राजप्रबन्ध में कोई काम भी नहीं हो सकता। होता क्या है? लोगों के ऊपर बोझ पर बोझ पड़ता है, आप सही ढंग से लोगों की समस्याओं को समझ नहीं पाते। चंडीगढ़ या देहली में बैठकर आप जनसाधारण की कठिनाइयों का क्या अनुभव कर सकते हैं? इस के लिये जरूरत है डीसेंट्रेलाईज़ेशन की ......

Mr. Chairman : Sardar Kapoor Singh Ji, will you please ask the Members to come to the House, as there is no quorum ? If they do not turn up, I am afraid, I will have to adjourn the House.

(*Bells were rung and the House was in quorum*)

पंडित मोहन लाल दत्त : चेयरमैन साहिब, मैं कुछ बुनियादी बातों का ज़िक्र कर रहा हूं। इसलिये मुझे कुछ ज़्यादा समय दिया जाए। तो मैं यह निवेदन कर रहा था

[पंडित मोहन लाल दत्त]

कि तरक्की के रास्ते में तीन बड़ी रुकावटें हैं: भौतिकवाद, पूंजीवाद और राजवाद। जब तक यह रहेंगी देश में कोई भी, किसी प्रकार की तरक्की या उन्नति नहीं हो सकेगी। आप को चाहिए कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को डीसेंट्रेलाईज़ करें जैसा कि पंचायतराज सिस्टम है। मगर उसको भी तो आप ने खराब कर दिया। उसे भी आप ने ठीक ढंग से नहीं बनाया और न ही बनने दिया है। पूंजीवाद को दूर करने के लिये आप ने सोशलिज़्म का नारा लगाया। और वह भी आप लोगों को ठीक तरीके पर नहीं दे पाए। मैं निवेदन करूं कि इकनामिक प्रास्पैरिटी का आधार होता है लैंड सिस्टम। आप कहते हैं देश में अन्न की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। लेकिन पैदावार बढ़ नहीं सकती, ऐग्रीकल्चरल प्रोडच्स बढ़ नहीं सकती जब तक कि लैंड सिस्टम ठीक नहीं होता। बेशक हिन्दुस्तान की बाकी स्टेट्स में तो इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ हुआ लेकिन पंजाब में इस दिशा में भी बिल्कुल कोताही की गई। आप के साथ ही जो अर्स्टवाईल पैप्सू स्टेट थी इसी इलाके में आप के पंजाब की निस्बत अच्छा सिस्टम है। वह सिस्टम उस इलाके में अब भी चल रहा है। यानि पंजाब में इस वक्त दो लैंड लाज़ चल रहे हैं। एक भूतपूर्व पैप्सू वाला और एक पंजाब वाला। आप अभी तक इन दो अलग अलग लैंड लाज़ को भी एक नहीं कर पाए कारण यह है कि पैप्सू वाला कानून ज़रा प्रोग्रेसिव है और यहां पर जो चौधरी हैं, जिन के हाथ में हकूमत है, वह उसको अपनाना नहीं चाहते। लैण्ड रिफार्मज़ के सम्बन्ध में यहां हर सैशन में वावेला किया जाता रहा है लेकिन इस के बावजूद भी हालत यह है कि मुज़ारों को धड़ाधड़ बेदखल किया जा रहा है। जब तक इस तरह से रोज़ बेदखलियां होती रहेंगी उस वक्त तक अन्न की पैदावार बढ़ नहीं सकती। जब तक मुज़ारों के मन में इस तरह की अनसर्टनटी रहेगी और वह उन ज़मीनों के मालक नहीं बन जाते जिन को वह जोतते हैं तब तक न तो यह अनसर्टिनिटी दूर हो सकती है और न ही पैदावार बढ़ सकती है। The greatest incentive is that the land should go to the tiller. तो मैं समझता हूं कि यही सब से बड़ा इनसेनटिव है जो आप काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिये दे सकते हैं। इस के इलावा आप जितने जी चाहे उन्हें इनसेंटिव दे लें चाहे फर्टेलाईज़र दे लें चाहे बिजली सस्ती दे लें वह इतनी पैदावार नहीं बढ़ा सकते जितनी कि वह ज़मीनों के मालिक बन कर बढ़ा सकते हैं। अगर वह ज़मीन के मालिक बन जायेंगे तो वह पूरी लगन के साथ काम करेंगे और पैदावार बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त पंजाब में हालत क्या है? आप सुन कर हैरान होंगे कि इस वक्त पंजाब में 33 लाख एकड़ ज़मीन मुज़ारों के तहत है। यह जो 'पंजाब ग्रौन दी मार्च' की पुस्तक सरकार की तरफ से 1963 में दी गई थी, इस में एक हैडिंग के नीचे स्टैटिस्टिक्स आन साईज़ आफ होल्डिंगज़ दिये हुए हैं। आप ज़रा मुलाहज़ा फरमायें कि 1963 में कितने मुज़ारे पंजाब में थे। फिर चेयरमैन साहिब, मैं आप की विसातत से फाईनांस मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पहले हर साल बजट स्पीच में और गवर्नरज़ एड्रैस में लैंड रिफार्मज़ का ज़िक्र किया जाता रहा है लेकिन इस साल न गवर्नरज़ एड्रैस में इस का ज़िक्र किया गया

है और न ही इस बजट स्पीच में जिस पर आज बहस हो रही है, कोई जिक्र है। आप देखें 1963 में बजट स्पीच में एग्रेरियन रिफार्म्ज़ का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि पंजाब में 15 लाख मुज़ारे हैं जिन्हें बसाया जाएगा। मैं कहता हूं कि जहां इतनी ज़्यादा तादाद में काश्तकार हों जिन की अपनी ज़मीन न होने के कारण उन के दिलों में न कोई उत्साह हो और न कोई उन में हिम्मत हो तो वह किस तरह से पैदावार बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में सब से बड़ी रुकावट यही है कि जो काश्तकार हैं वह ज़मीन के मालिक नहीं हैं और इस के कारण एक तो हर वक्त यह डर लगा रहता है कि वह ज़मीन उन के पास रहेगी कि नहीं रहेगी और दूसरा उस में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती जितनी उन की अपनी ज़मीन में हो सकती थी। इस तरफ आज तक इन की तवज्जोह नहीं गई। सिर्फ प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में एक बार दिल्ली में सेमीनार किया था और उस में उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो 28 फरवरी के पेट्रिआट में छपा था। इस में दिया हुआ है—

> "The seminar on land reforms, convened by Planning Commission, has recommended vigorous implementation of the entire land reform programme during the Fourth Plan including an end to 'landlord-tenant Nexus' and to give land to the tiller........."

At that Seminar, Dr. V.K.R.V. Rao stressed—

> "The fundamental principle of giving land to the tiller and ensuring owner cultivation.....was the most important and basic incentive for maximising agricultural production........"

मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इस चीज़ को बिलकुल नज़र अन्दाज़ किया है। पहले तो गवर्नर एड्रैस में और बजट स्पीच में इस का जिक्र किया जाता था चाहे वह नाम मात्र ही होता था कि हम यह करेंगे और वह करेंगे और करते कराते कुछ नहीं थे लेकिन इस साल तो इस बारे में जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिये मैं इस इम्पार्टेंट मसले की तरफ इन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर इस तरफ ठीक तरह से ध्यान दिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि पंजाब में इतनी ज़्यादा पैदावार हो सकती है जो न सिर्फ पंजाब की ज़रूरत को पूरा कर सकती है बल्कि वह सारे हिन्दुस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सकेगी। यहां पर इतनी कल्टीवेबल ज़मीन वेस्ट पड़ी हुई है जो अगर काश्तकारों को दे दी जाए तो यहां पर बहुत ज़्यादा पैदावार हो सकती है और अनाज का मसला हल किया जा सकता है लेकिन मुश्किल यह है कि ऐसी कल्टीवेबल वेस्ट ज़मीन यह उन काश्तकारों को तो देते नहीं जो उस में मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें बल्कि यह ऐसी ज़मीन बिरले जैसे पूंजी पतियों को देते हैं।

चेयरमैन साहिब, इसी तरह से यहां पर माइनर इरीगेशन का मसला है। आज ही एक सवाल पूछा गया था कि हिल्ली एरियाज़ में और सब-माऊंटेनस एरियाज़ में बोरिंग करने के लिये क्या सरकार के पास कोई रिंग है तो उस के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने बताया था कि इस के लिये आर्डर प्लेस किया गया है। यह हालत है कि इन के पास वहां पर बोरिंग करने के लिये कोई रिंग ही नहीं है। इस तरह से यह 18 साल तक सोए रहे हैं

और वहां पर हज़ारों एकड़ प्लेन ज़मीन अन कल्टीवेटिड पड़ी रही जिस से माइनर इरीगेशन स्कीमों से पैदावार की जा सकती थी। फिर वहां पर रवां नदी में हर वक्त पानी बह रहा है जिस पानी को उठा कर लिफ्ट इरीगेशन के ज़रिए उस खुश्क ज़मीन को पानी दिया जा सकता था और वहां पर पैदावार की जा सकती थी। लेकिन इस तरफ इस सरकार ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया।

इस के इलावा मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं और इन्हें कहता हूं कि आप दिल्ली की तरफ न जाएं और चलें देहात की तरफ और वहां जा कर देखें कि वहां लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। इस बारे में मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास कैपिटल तो है नहीं जिस से हम सारी योजनाएं पूरी कर सकें लेकिन हमारे पास मैन पावर काफी है जिस को यह आज तक पूरी तरह से यूटेलाईज़ नहीं कर सके। उन को इस ने आज तक काम नहीं दिया। इन के पास हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। यह उन को यह ज़मीन देकर उन को काम तो देते नहीं जिस में वह मेहनत कर सकें। अगर यह उन को ज़मीन देकर काम दे सकते तो आज हमें दूसरे देशों से भीख मांगने की ज़रूरत न रहती। आज हालत यह है कि इन्होंने विदेशों से भीख मांग मांग कर सारे लोगों को हरिजन बना दिया है। आप ज़रा देखें कि किस तरह से भीख मांग मांग कर हमारी जो खुददारी थी उस का इन्होंने मलियामेट कर दिया है और इस तरह से हमारी खुददारी को चैलेंज हो रहा है।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇਨ ਗੁਡ ਸੈਨਸ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ ਬੈਡ ਸੈਨਸ ਕਹੀ ਹੈ।

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं ने यह इन गुड सेनस कहा है। मेरे कहने का मतलब था कि जिस तरह से इस सरकार ने हरिजनों को ग्रांटें दे कर उन की हिम्मत और काम करने की शक्ति को खत्म कर दिया है इस तरह से इन्हों ने देश के लोगों की शक्ति को बाहर से भीख ले ले कर और उन्हें दे कर उन की शक्ति को हरिजनों की शक्ति की तरह खत्म कर दिया है और उन जैसा बना दिया है।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਰਿਜਨ ਨਿਵਾਜ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Mr. Chairman : Order please.

पंडित मोहन लाल दत्त : बात यह है कि यहां पर मैन पावर इतनी बेकार रखी हुई है और इस का कारण यह है कि यहां मीनज़ आफ प्रोडक्शन मेहनत करने वालों के हाथ में नहीं। यहां मज़दूरों की कमी नहीं है।

> "(i) India loses daily at the lowest estimate, a crore of man-days in labour due to unemployment and a crore and a half of mandays in labour due to underemployment ..."

यह है इन की करतूत। यानी मैन पावर कितनी वेस्ट हो रही है और इस का कारण यह है कि यह यहां पर सही बेसिज़ पर सोशलिजम ला नहीं रहे।

Mr. Chairman (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Pandit Jee, are you paying these tributes to the hon. Finance Minister or to the Government ?

पंडित मोहन लाल दत्त : चेयरमैन साहिब, यहां पर गवर्नमैंट के नुमायंदे बैठे हुए हैं। मैं उन को बता रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि गवर्नमैंट ने मैन पावर को यूटेलाईज़ नहीं किया।

फिर हमारे जिला होशियारपुर में चोओं ने हज़ारों एकड़ ज़मीन को बरबाद कर के रख दिया है। मेरे पास यह इन की रिपोर्ट है इस में दिया हुआ है कि 68 हज़ार एकड़ ज़मीन जिला होशियारपुर में चोओं की वजह से नाकारा हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी प्राब्लम की तरफ इन का ध्यान न जाए तो यह लोगों का क्या भला कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ हरकत में लाएं, उन की शक्ति का उपयोग करें, तब इस का हल निकलेगा। इस के लिये आप पंचायतों को कम से कम आधी ग्रांट दें। आप जानते हैं कि यहां पर सौ साल तक अंग्रेज़ का राज रहा, आप को भी यहां पर 17-18 साल हो गए हैं, मगर आप के महकमे इस काम में सफल नहीं हो सके। पिछली दफा सरकार ने रहमत की और चार लाख रुपया दिया मगर इस से क्या होगा। इस से तो दो चार चो ही बनेंगे। यह काम तो लाखों लोगों की शक्ति का उपयोग कर के ही सिरे चढ़ाया जा सकता है। इस के लिये पंचायतों को कम से कम आधी ग्रांट दे कर इस काम को सिरे चढ़ाएं। (घंटी) मैं आप का धन्यवाद करता हूं और आखिर में बस इतना ही निवेदन करूंगा कि अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक नई हकूमत आएगी। तो मैं चाहता हूं कि अब इस सारे मसले पर रीथिंकिंग की जाए। यह न हो कि हम पुरानी रट में ही पड़े रहें। इस सारे मसले को अच्छी तरह से गहराई में जा कर एक नए तरीके से सोचा जाए कि हम ने क्या गल्तियां कीं और उन को कैसे दूर किया जा सकता है। मुझे आशा है कि मैं ने जो यह चन्द सुझाव दिए हैं इन पर पूरा गौर होगा और कोई ठोस प्रोग्राम बनेगा जिस से लोगों का भला हो।

श्री रूप लाल महता (पलवल) : चेयरमैन साहिब, वित्त मंत्री महोदय ने जो इस साल का बजट सदन के सामने पेश किया है उस के बारे में कुछ विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि जो बजट इन्होंने पेश किया है इस में ओवर आल 525 लाख रुपये का डिफिसिट दिखाया है। और इस कमी को पूरा करने के लिये कुछ थोड़े से टैक्स भी लगाए हैं जिन से इस खसारे को पूरा करने की कोशिश की है। यह बात सही है कि जब भी लैजिसलेचर में कोई भी टैक्स लगाने की तजवीज़ आती है तो हम सब उस का विरोध करते हैं। मगर यह बात सब के सामने है कि अभी जो इन्डो-पाकिस्तान कन्फलिक्ट हुआ उस की वजह से पंजाब के आर्थिक ढांचे को एक ज़बरदस्त धक्का लगा। इस का खास तौर पर ज्यादा असर बार्डर के इलाका पर हुआ। इंडस्ट्री बन्द हो गई, डिवैलपमेंट का सारा काम ठप्प हो गया, हज़ारों आदमी बेकार हो गए, हज़ारों अपने घरों से उजड़ गए, बैंकों ने इंडस्ट्री को क्रैडिट देना बन्द कर दिया। इस तरह से कोई 15-20 करोड़ रुपया का नुक्सान पैदावार का हुआ होगा।

[श्री रूप लाल महता]

पंजाब सरकार ने यहां पर अमन बहाल रखने के लिये, उखड़ हुए लोगों की देख भाल करने के लिये लाखों रुपया खर्च किया। इस बजट में जो 525 लाख रुपये का घाटा है इस को थोड़े सा टक्स लगा कर पूरा करने की कोशिश की है। बेशक आपोजीशन ईंटों पर या पैटरोल पर थोड़ी सी टैक्स में बढौती पर नुक्ताचीनी करने के लिये हकबजानब है मगर उन को इस बात को नजर अन्दाज़ नहीं कर देना चाहिए कि पिछले साल में पंजाब में किस तरह के हालात रहे मगर बावजूद इतनी ज्यादा कठिनाइयों के, मुसीबतों के पंजाब ने तरक्की की है, इस का डिवैलपमेंट का काम रुका नहीं, कारखानों ने माल तैयार किया, साइकल बने, मशीनें बनीं, औज़ार बने बल्कि उन में इज़ाफा हुआ और दूसरे कामों में भी तरक्की हुई है। आप जानते हैं कि जिस राज की जनता तरक्की मांगती हो, सहूलतें मांगती हो, तरह २ की चीजें मांगती हो वहां पर सरकार को टैक्सों का कुछ न कुछ बोझ तो लोगों पर लादना ही पड़ता है। ठीक है, लोग टैक्सों का लगाया जाना पसन्द नहीं करते उन में बढ़ौती नहीं चाहते मगर सूबे की आर्थिकता को बढ़ाने के लिये डिवैल्पमेंट के कामों को जारी करने के लिये इस तलखी को बरदाश्त करना ही पड़ता है। आपोजीशन के भाई कुछ ही कहें मगर वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि पिछले 17–18 सालों में जितने भी बजट यहां पर पेश हुए हैं उन में पार्टीशन से लेकर यहां पर काफी तरक्की का काम हुआ है। हमें एक निशाने पर पहुंचना है मगर उस तक पहुंचने के लिये वक्त तो लगेगा ही। मगर कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस सरकार ने इन 17–18 सालों में डिवैलपमेंट का बहुत काम किया है। इस का क्रैडिट सारे हिन्दोस्तान में बरसरे इक्तदार पार्टी को मिल रहा है। इस बजट में जो खसारा है उस को पूरा करने के लिये जहां कुछ टैक्स बढ़ाए हैं वहां पर हर जगह से कुछ न कुछ खर्च को कम करके इस कमी को पूरा करने की भी कोशिश की है। मगर ऐग्रीकलचर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये काफी रुपया रखा गया है अगर ऐग्रीकल्चर के महकमें ने इस का ठीक इस्तेमाल किया, पंचायत समितियों वगैरह की मदद से जो ढांचा लोगों की मदद के लिये या उन को बीज या फर्टेलाइज़र देने के लिये बनाया जाएगा अगर उस ने ठीक काम किया, लोगों को वक्त पर सहूलतें पहुंचाई, फर्टेलाइज़र वगैरह दिया तो यह सूबा सारे खसारे को जो मुल्क ने बरदाशत किया है इस को पूरा कर सकता है। तब उम्मीद हो सकती है कि अगले सालों में बजट में खसारा नहीं होगा और लोगों पर टैक्स भी नहीं लगेगा। मैं वित्त मंत्री महोदय को यह बजट पेश करने पर बधाई देता हूं। आप जानते हैं कि इन्होंने सेल्ज़ टैक्स के मसले को किस तरह से टैकल किया है। सब जानते हैं कि इस में इवेयन होता है, लीकेज भी होती है, हर जगह पर बलैकशीप्स होती हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने सारी चीज को लिया है उस से इवेयन कम होगा, लीकेज भी कम होगी और साथ ही साथ व्यापारियों की दिक्कतें भी बहुत हद तक दूर होंगी। साथ वाली स्टेट्स को जो यहां से व्यापार जाता है, लीकेज होती है वह भी कम होगी। 232 करोड़ का जो खसारा है वह भी पूरा होगा। जो स्टैप यह यहां पर एग्रीकल्चर की तरक्की के लिये ले रहे हैं उन से हमारी पैदावार बढ़ेगी। यह सूबा सारे हिन्दुस्तान की ग्रैनरी कहा जाता है। मगर हम जो ज्यादा अनाज पैदा करते हैं, रिज़र्व स्टाक वह हम दूसरे राज्यों को दे देते हैं इस तरह जब यहां पर कमी पड़ती है तो हम को सैंटर

से इम्पोर्टिड व्हीट मंगाना पड़ता है, वह हम अपने लोगों को देते हैं। मगर इस तरह से लोगों को तकलीफ होती है, मार्किट का ट्रैंड ऊपर को जाता है, कीमतें चढ़ जाती हैं। हमें अपने लोगों की ज़रूरतें अपने ही व्हीट से पूरी करनी चाहिएं ताकि हमें बाहर से अनाज मंगाना न पड़े। इस तरह से कीमतें काबू में रह सकती हैं। मुझे याद है कि दूसरी बड़ी जंग के दिनों में सन् 1941–42 के दिनों में बंगाल में कितना बड़ा कहत पड़ा था। लाखों आदमी पेट पर पत्थर मार २ कर मर गए। उस वक्त अंग्रेज़ की सरकार थी। लाखों लोगों का जानी नुक्सान हुआ। मैं समझता हूं कि यह जो अभी हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई इन दिनों हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को यह मौका नहीं दिया कि वह इस नाज़ुक मौके का नाजायज़ फायदा उठा सके महंगाई तो थी मगर उसे बढ़ने नहीं दिया। और इस मौका पर लोगों में जज़बा हुब्बलवत्नी इतना था कि उन्होंने खुद भी कीमतें नहीं बढ़ाईं।

इस लिये मैं अपनी प्रान्तीय सरकार को मुबारिकबाद दूंगा कि इन्होंने इफैक्टिव तौर पर प्राइस कन्ट्रोल किया है। नहीं तो अगर यह सरकार इस सम्बन्ध में फौरी कार्रवाई न करती तो प्रांत में बदअमनी फैल जाती।

इस के आगे मैं अपने माननीय वित्त मंत्री और सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज ट्यूबवैलों के लिये बिजली सप्लाई की क्या हालत है और लोगों की निगाह में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की क्या हालत है ? इलैक्ट्रिसटी बोर्ड कहता है कि फन्डज़ की कमी की वजह से और मैटीरियल की कमी की वजह से बिजली ट्यूबवैलों को नहीं दी जाती। जितने भी एस. डी.ओज़. इलैक्ट्रिसिटी के महकमा के तहसीलों में लगाए हुए हैं वह हर बार, जब भी उन से मिलो, यही कहते हैं कि मैटिरियल नहीं है फन्डज़ न होने की वजह से ट्यूबवैलों को ऐनरजाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इस की ज़िम्मेदारी किस पर है ? या तो वह अफसरान बिजली देते नहीं और या उन को देते हैं जिनकी उन तक रसाई हो या फिर उन के पास सामान नहीं जाता और जो फन्डज़ की एलोकेशन उन के पास है वह कम की जाती है। उन लोगों के हिस्से में फन्डज़ नहीं इसलिये बिजली नहीं दी जाती। मैंने बजट सैशन में सवाल पूछा था और मुझे जो इत्तलाह मिली थी उस को आप देखें तो पता चलता है कि बिजली की क्या हालत मेरे हलका पलवल में है। बिजली के कितने कुनैक्शन पलवल गांव में नहीं दिए गए। पलवल के एस.डी.ओ. इलैक्ट्रिसिटी ने बताया है कि 133 गांवों को बिजली नहीं दी गई क्योंकि दे आर पैंडिंग फार वांट आफ इलैक्ट्रिसिटी मैटिरियल। और इस के आगे 354 केस पैंडिंग पड़े हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं आज तक हुई। हर साल इस बात की चर्चा की जाती है कि बिजली के मैटीरियल की कमी है फन्डज़ की कमी है इस लिये villages को बिजली नहीं दी गई। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बिजली के लिये रुपया किसी और फन्डज़ में से निकाल कर दिया जाए ताकि electrification को पूरा किया जा सके और जितने केसिज़ एस.डी.ओ., पलवल के पास पैंडिंग हैं उनका फैसला किया जाए। अगर सरकार यह समझती है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड काम ठीक ढंग से नहीं चला सकता, जैसा कि ज़ाहिर है, और हर साल इस बात का चर्चा किया जाता है, तो मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि इस बोर्ड को तोड़ दिया जाए और सरकार बिजली का इन्तज़ाम अपने हाथ में ले ले। या फिर इतने फन्डज़

[श्री रूप लाल महता]

बिजली बोर्ड को दिए जाएं जिस से लोगों की दिक्कत को दूर किया जा सके क्योंकि जिन इलाकों में सिंचाई के आम साधन नहीं हैं, न ही कोई नहरें हैं, वहां पर बिजली दी जाए तो लोग ज़मीन से पानी ट्यूबवैलों के जरिए खेंच सकेंगे और ज़मीन की सिंचाई कर सकेंगे। इस बात का फौरी तौर पर हल होना चाहिए

ड्रौट की हालत यह है कि गुड़गांव ज़िला में 518 गांव इस की ज़द में आ गए हैं। 425 गांवों में 24 से 49 परसैंट तक नुक्सान हुआ है। 75 गांव ऐसे हैं जिन में 49 से 75 परसैंट तक नुक्सान हुआ है और 18 ऐसे हैं जिन में 100 परसैंट तक नुक्सान हुआ है। कुल 518 गांव ड्रौट की ज़द में आ गए हैं। लेकिन इस बात के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया। न ही बजट स्पीच में और न ही गवर्नर ऐड्रैस में इस बात का कोई ज़िक्र किया गया है। सरकार ने इस बजट में एक पैसा भी नहीं रखा हालांकि महेन्द्रगढ़ की खुशकसाली को दूर करने के लिये रकम रखी गई है। इस लिये मैं यह सरकार से कहूंगा कि इस तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए और डी. सी. साहिब को हिदायत कर दी जाएं कि रिलीफ फौरी तौर पर इस ड्राट के इलाके में तक्सीम किया जाए। फिर लोगों के पास और कोई साधन पेट पालने के लिये नहीं है। अगर कच्ची सड़कों पर मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया जाए तो इस से गरीब लोग अपना पेट पाल सकेंगे, इन्हें कुछ मज़दूरी मिल सकेगी इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था।

इस के इलावा वित्त मंत्री ने मारकिट कमेटियों को डिवैलप करने के लिये रकम रखी है लेकिन मैं सरकार का ध्यान पलवल मंडी के हालात की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह कई सालों से तैयार पड़ी हैं और अर्सा 15 या 20 साल हो गया है कि मारकिट कमेटी ने ज़मीन खरीद कर ली थी और मंडी के दफतर भी बन कर तैयार हैं, किसानों के लिये अनाज मंडी में लाते हैं, रैस्ट हाउस तैयार कर लिया गया है लेकिन कितने अफसोस की बात है कि पलवल मारकिट कमेटी का चेयरमैन मन्डी को बाहर नहीं जाने देता क्योंकि उस का अपना इन्ट्रैस्ट इस बात में है कि मन्डी तंग बाज़ारों और पुरानी जगह ही रहे और खुले इलाके में न जाए। पलवल मारकिट कमेटी का चेअरमैन इस बात पर बज़िद है, हालांकि चीमा साहिब ने कहा रैज़ोल्यूशन पास किए पड़े हैं, इस लिये इस तरफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मन्डी तैयार पड़ी है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जहां पर ज़मीन एक्वायर कर ली जाए, मोल ली जाए और रुपया खज़ाना में सरकार के पास पड़ा हो तो उस जगह मन्डी को किसी निजी इन्ट्रैस्ट को सामने रख कर वहीं पर रहने नहीं देना चाहिए। इस लिये मैंने आप का ध्यान इस तरफ दिलाना था कि सरकार जल्द से जल्द इस मण्डी को नई जगह पर खुलवाए और वहां पर एल.आई.सी. या किसी और स्कीम के मुताबिक प्लाट होलडर्ज़ को कर्ज़ा दे ताकि दुकानदार बाहर नई मन्डी में जा सकें। आज कल मन्डी कनजैसटिड और तंग गलियों में है और जब किसान अपना अनाज मण्डी में ले जाते हैं तो उन्हें सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस तरह मन्डी को बाहर ले जाने में किसानों को आराम मिलेगा और वे अपनी जिनस को आसानी से बगैर किसी नुक्सान के मण्डी में ले जा सकेगा।

फिर जो रुपया animal husbandry के लिये रखा जाता है उस में पसमांदा इलाके का ध्यान नहीं रखा जाता और न ही रक्म रखी जाती है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि Dadhola गांव में जो जी. टी. रोड से केवल 4 मील की दूरी पर है कोई सड़क नहीं जाती और न ही पशु चिकित्सा के लिये कोई हस्पताल है। किसान को अपने मवेशी 8 और 10 मील की दूरी पर ले जाने पड़ते हैं। इस लिये अगर यहां पर मवेशियों का हस्पताल बना दिया जाए तो इस इलाके की दिक्कत को दूर किया जा सकता है। इस के लिये land और building गांव वाले देने को तैयार हैं।

जहां तक रूरल इंडस्टरी की डिवैल्पमेंट का सम्बन्ध है, हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि हमारे इलाका पलवल की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले चार साल में यह पांचवां बजट पेश किया गया है लेकिन पलवल की रूरल इन्डस्ट्रीयल estate की स्कीम अधूरी पड़ी है सिर्फ 9 shed रूरल इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट के तैयार हुए हैं और आज तक कोई चालू नहीं की गई। हम यह कहने पर मजबूर कर दिए गए हैं कि हमारा पसमांदा इलाका है इसी के साथ इस सम्बन्ध में सोतेली मां का सलूक किया जा रहा है। या तो सरकारी अफसरान की सुस्ती की वजह से या इन्डस्टरी विभाग के पक्षपाती सलूक की वजह से इस इलाके में इन्डस्ट्रीयल ऐस्टेट कायम नहीं की गई। सरकार को चाहिए कि यहां पर जल्द से जल्द और शार्टेस्ट पीरियड में इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट कायम कर दी जाए, नहीं तो आप जानते हैं कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं और लोगों को अपने इलाके में जवाब देह हूं कि मैं ने अपने इलाके के लिये क्या कुछ किया है। इस लिये सरकार से आप के जरिए, चेयरमैन साहिब, अर्ज करूंगा कि इस तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए।

चेयरमैन साहिब, सड़कों के लिये रकम रखी जाती है लेकिन हमारे इलाके में सिफर के बराबर है। फोर्थ प्लान में जो रकम प्रोवाईड की गई है उस में मेरे इलाके की क्या हालत है? आप यह देख कर हैरान होंगे कि सिवाए चन्द जगहों पर मिट्टी डालने के और काम नहीं हुआ। पलवल-अलावलपुर की सड़क आधी बनी है और बाकी का हिस्सा रहता है जो आज तक मुकम्मल नहीं किया गया। किसान के मवेशी रास्ते में मर जाते हैं और बैल गाड़ियां रास्ते में नहर में गिर जाती हैं क्योंकि पुल नहीं। यू०पी० सरकार को कहने के बावजूद अलावलपुर की नहर पर पुल नहीं बनाया गया इस लिये मैं सरकार से कहूंगा कि इस काम को टाप प्रायर्टी देनी चाहिए ताकि पुल बन जाए और उस काम के लिए किसी और फण्ड में से रकम निकाल ली जाए पलवल-अलावलपुर की सड़क मुकम्मल हो जाए। इस से चार पांच हजार की आबादी, जो इस गांव की है, को अपनी जिन्स मन्डी में लेजाने में जो आजकल दिक्कत आ रही है वह दूर हो जाएगी। और यह काम बरसात से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए।

एक बात मैं, चेयरमैन साहिब, आपकी मारफत स्वास्थ्य मन्त्री, जो यहां पर इस वक्त बैठी हैं, कहना चाहता हूं कि पलवल में जो डिस्पैन्सरी है इस को प्रोविनशेलाइज़ कर दिया जाए। इस की आज यह हालत है कि डाक्टर नहीं है और न ही वहां कोई दवाई है। बिल्डिंग की खस्ता हालत है। इस का आधा खर्चा म्यूनिसिपल कमेटी बरदाश्त करने को तैयार है। इस लिये इस को ऐक्सपीडाइट किया जाए ताकि वहां माडरन ढंग के मुताबिक सब तरह की सहूलियतें मिल सकें, डाक्टर हो और लेडी डाक्टर हो। पलवल में जो मिशन हस्पताल है उस का खर्चा इतना बढ़ गया है कि गरीब उस को बरदाश्त नहीं कर सकता। पहले वहां पर मिशनरी

[श्री रूप लाल महता]

काम करते थे लेकिन आज कल फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब अपना इलाज वहां पर नहीं करवा सकता और अगर हस्पताल को सरकार ले ले तो बेहतर होगा क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी अपना कण्ट्रीब्यूशन देने को तैयार है। इस लिये मैं स्वास्थ्य मन्त्री से कहूंगा कि इस हस्पताल में मार्डन एक्विपमेंट मंगवा दी जाए ताकि गरीब लोग वहां पर अपना इलाज करवा सकें।

यह ठीक है कि डिस्पैंसरीज़ तो हमारे इलाके में खोल दी गई हैं मगर इनमें डाक्टरों की कमी है। एक डाक्टर तो तीन महीनों के लिये गया था मगर इस के बाद वहां पर कोई नहीं पहुंचा। मैं कहता हूं कि इनको इस ढंग से चलाया जाए जिस से लोगों को कोई लाभ हो। अगर और कुछ नहीं तो आयुर्वेदिक डिसपैंसरीज़ का ही इंतज़ाम किया जाए जिन से लोगों को इमदाद मिल सके। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम अज़ कम इस इलाका के लिये मोबाईल डिस्पैंसरी का ही प्रबन्ध किया जाये जो गांव गांव फिर कर उन गरीब लोगों की इमदाद कर सकें। मैं समझता हूं कि लोगों की बेहतरी के लिये, हमें आज़ाद कौमों की तरह ऐसे तरीके अपनाने चाहिएं जिस से पसमांदा लोगों का भला हो। इन शब्दों के साथ, चेयरमैन साहिब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे कुछ ज्यादा वक्त बोलने की इजाज़त दी। हम पसमांदा लोग हैं जो बड़ी देर से भुलाए हुए हैं। आज जब कि एक तरफ पंजाब की तकसीम की बात चल रही है, हमारा इलाका वहां का वहां है। इस में किसी तरह की कोई भी डिवैल्प-मैंट नहीं हुई। पंजाबी इलाका के लोग पंजाबी सूबा मांग रहे हैं और दूसरे लोग हरियाणा प्रांत की मांग कर रहे हैं, मगर हमारा इलाका ऐसे हालात में हमेशा से रहा है जोकि बिल्कुल भी डिवैल्प नहीं हो सका है। अगर डिवैल्पमेंट के लिये भाषाई आधार पर सूबे की तक्सीम की जा रही है तो हम समझते है कि हमारा इलाका सब से पीछे है। इस की तरक्की तभी हो सकती है अगर बजट में से इस इलाका के लिये ज्यादा से ज्यादा फंडज ऐलोकेट किए जाएं। हमारे इलाके को सरविसिज़ में भी अभी तक पीछे रखा गया है। अब सूबे की तक्सीम करना देश के हित में नहीं है।

चौधरी बालू राम (आनन्दपुर) : चेयरमैन साहिब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भी मौजूदा साल के बजट के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। इस साल भी वैसे ही बजट पेश किया गया है जैसे हर साल पेश किया जाता है। मगर इस साल हम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में से गुज़र रहे हैं जिसे खत्म नहीं समझना चाहिए, जो कि अब भी जारी है। मुझे यह कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि इस वक्त जो गवर्नमैंट के कर्णधार हैं वह एक खास किस्म की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सरकारी मशीनरी का ध्यान तामीरी कामों पर लग नहीं रहा। इस की ज़िम्मेवारी, मैं समझता हूं ऐसे लोगों पर है जिस में हम सभी लोग आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमें ऐसी बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिएं जिन से अमन में खलल पड़ने का खदशा हो। मगर देखने में कुछ ऐसी बातें अकसर आती हैं जिन से सरकारी मशीनरी तामीरी कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उनकी तवज्जोह ज़रूरी तौर पर किसी और तरफ पर लगाई जा रही है। हमें इस तरफ खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हम उन का ध्यान उन बातों की तरफ न जाने दें जिन से लोगों को कोई फायदा न हो। अव्वल तो उन का ध्यान बदलने के हम ज़िम्मेवार हैं, दूसरे हम

उनको इसलिये बुरा भला कहते हैं कि वह तामीरी कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिएं जिस से वह ज्यादा से ज्यादा वक्त तामीरी कामों की तरफ दे सकें। हम ऐसा खुद होने नहीं देते फिर उन को कोसते हैं कि गवर्नमैंट ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। हमें उनकी इस मौका पर हैल्प करनी चाहिए।

गवर्नमैंट को पालिसी ठीक तरीके से implement करने के मुताल्लिक मुझे यह कहना पड़ता है कि जो पालिसी सरकार बनाती है उस को implement करने के लिये यद्यपि बड़े बड़े तजरूबाकार आफिसर्ज मौजूद हैं जो बखूबी सही ढंग से उस पर अमल करा सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि कुछ आफिसर्ज ऐसे हैं जिन्हों ने अपनी पुरानी हुकमरानों वाली पालिसी अभी तक छोड़ी नहीं है। वह बजाए इस के कि कोई तयशुदा पालिसी पर अमल करें, उस में मुश्किलात पैदा करने को कोशिश करते हैं। जब गवर्नमैंट की एक काम को करने की इंटैनशन है और उसके लिये बाकायदा रकम की प्रोवीज़न भी कर दी जाती है ताकि लोगों को वक्त पर सहूलियात दी जा सकें, तो इस मेन purpose की तरफ ध्यान देने की बजाए छोटी छोटी टैकनीकल बातों को सामने रख लेते हैं जिस से काम वक्त पर होने की बजाए उस में रुकावटें पड़ती हैं। मैं इसको मिसाल हाऊस में देना चाहता हूं। $1\frac{1}{2}$ साल हुआ सरकार ने 25 प्रतिशत सबसिडी ट्यूबवैल लगाने वालों को देने का एलान किया था। यह तकरीबन 750 की रकम बनती है, इस के मुताल्लिक मिनिस्टर साहिब ने इस हाउस के अन्दर और बाहर भी अपनी स्पीचों में बार बार सबसिडी देने का ऐलान किया। हम ने भी इनके ऐलानों का समर्थन किया कि देखिए सरकार लोगों की इमदाद कर रही है। मगर डिपार्टमैंट के अफसरान ने इस ऐलान पर अमल होने नहीं दिया इस होने वाले नेक काम की सरकार को ऐप्रीसिएशन हासिल होने नहीं दी। ऐसी अड़चनें लगाते रहे जिस से वह लोग अभी तक कोई फायदा नहीं ले सके। उन्हों ने यह पाबन्दी आगे रखी कि जो आदमी सरकार से कर्ज़ा लेगा उसे 25 प्रतिशत ट्यूब वैल के लिये कर्ज़ा दिया जाएगा हालांकि जो लोग अपने रुपये से ट्यूबवैल्ज़ लगाते हैं, कर्ज़ा नहीं लेते उसे यह facility सब से पहले मिलनी चाहिए। यह गलत-फहमी आज सवालों के जवाब में स्टेट मिनिस्टर कैप्टन रतन सिंह ने क्लीयर की है, आगे देखें क्या होता है।

श्री चेयरमैन : जवाब अब भी गोल मोल दिया है। (Even now they have given the reply in a round-about way.)

चौधरी बालू राम : खैर जो अब तो यह बात क्लीयर हो ही गई है कि सहूलयतें मिलेंगी, मगर असल बात कलीयर तब होगी जब असल में 50--100 आदमियों को यह सबसिडी मिल जाएगी। मैं ने यह एक मिसाल दी है कि ज्यादातर आफिसर्ज़ इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि इस में जो टैकनीकल खामी है उस से रुकावट कैसे डाली जाए। चाहिए तो यह कि अगर इस रुकावट को दूर करने में रूलज़ में और प्रोवीज़न करने की ज़रूरत हो तो वह करके इस दिक्कत को दूर करें।

इस के इलावा मेरी बहन हैल्थ मिनिस्टर साहिबा, जो कि यहां बैठी हैं, उनके नोटिस में भी एक बात ला देनी चाहता हूं। मैं ने उनसे कहा भी था तो उन्हों ने कहा कि मेरे से पहले

[चौधरी बालू राम]

की यह बात है। वह यह कि बजट में 3 रूरल डिस्पैंसरीज़ खोलने की प्रोवीज़न की गई थी। मगर यह खोली कहां गई? यह ज़रा आप सुन लें। एक चंडीगढ़ के सैक्टर 8 में, एक शायद सैक्टर 12 या 21 में मुझे सैक्टर नम्बर पूरी तरह याद नहीं और तीसरी सैक्रीटेरिएट में। अब आप अंदाजा लगाएं कि कैसे बजट को तोड़ मरोड़ कर उस पर अमल किया जाता है। कहने को तो सब कुछ मौजूद है मगर प्रैक्टीकल क्या होता है, इसकी मैंने मिसाल दी है। मैं समझता हूं कि सिवाए इस के लोगों में निराशा फैले, और कोई बात नहीं है। इन बातों की तरफ ध्यान नहीं। मेरा मतलब यही था, जैसा कि मैंने शुरु में कहा कि इनको दूसरी बातों से, जो कि झगड़े आजकल चल रहे हैं, जो कुछ सीरीयस नेचर के हैं, उनकी तरफ से टाईम नहीं मिलता।
5-00 इसलिये इधर उधर ध्यान नहीं जाता। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से अर्ज़ करूंगा कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। चंडीगढ़ में बड़े २ हस्पताल हैं। इसी तरह बड़े २ शहरों में बड़े २ हस्पताल और डिस्पैंसरियां हैं। ज़िला कांगड़ा तो पहाड़ी इलाका है ही। तहसील ऊना और तहसील गढ़शंकर का कुछ हिस्सा भी पहाड़ी इलाका में शामिल है। उन की तरफ ध्यान दिया जाए। वह इलाके पीछे रहे हुए हैं। उन को सिर्फ इस किस्म के एलान कर देने से फायदा नहीं पहुंचता जब तक सही तौर पर उनके लिये कोई काम न किया जाए। मैं ने चीफ मिनिस्टर साहिब से, जब वह एक दो दिन पहले अनन्दपुर साहिब थे, ज़िक्र किया कि आप इस इलाका में आए हैं, सड़कों को छोड़ इधर उधर नज़र मार कर देखें, न तो पिछली सावन की फसल हुई है और हाढ़ी की फसल होने का तो सवाल ही नहीं। उन्हों ने पूछा कि क्या पिछली बारिश का कुछ फायदा पहुंचा है। मैंने बताया कि फसल बोई ही नहीं गई तो बारिश का क्या फायदा पहुंचता। उस इलाका में 2 फसलें फेल हो गई हैं। कोई साधन नहीं जिस से वह इलाका गुज़ारा कर सके। उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों के चन्द एक मसले हैं। गवर्नमैंट ने कुछ सहूलतें देने का ऐलान किया जिसमें यह लिखा कि ऊना तहसील, गढ़शंकर तहसील (विघ्न) कंडी एरिया, असैसमेंट के लिहाज़ से बाकी एरिया छूट जाता है, आज तक उस की इतनी बदतर हालत है कि कागज़ात में रकड़ एरिया चला आता है, बीट एरिया लिखा रहा है, वह बीट एरिया बड़े सालों से छूट जाता है, उसे कोई सहूलियत नहीं मिलती। उसको इन्क्लूड करना चाहिए। मैं समझता हूं कि गवर्नमैंट की इंटैंशन नहीं कि उसे महरूम रखा जाए। क्योंकि टैक्नीकल वह लफ्ज़ उसमें नहीं है वह सारी सहूलतों से वंचित रह जाएगा। उसको महरूम नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ईंटों पर टैक्स लगाया गया है।

वित मंत्री : अभी नहीं लगाया।

चौधरी बाल राम : मुझे निहायत खुशी हुई है कि फिनांस मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि अभी नहीं लगाया, आगे भी नहीं लगाएंगे, निहायत मेहरबानी होगी उनकी। मैं तो खुश हूंगा ही, इस बात से सारे पंजाब के लोग खुश होंगे।

श्री सभापति : लगाया नहीं, लगाएंगे,। आपको यह एशोरेंस नहीं दी कि लगाएंगे नहीं। (He has not imposed this tax but will impose it. He has not given any assurance that it will not be levied.)

चौधरी बालू राम : उन्होंने यही कहा है कि लगा नहीं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि अभी नहीं लगा तो आगे भी न लगाए। जो टैक्स यह लगाने वाले हैं हम उस से कहीं ज्यादा टैक्स अब भी दे रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में इतनी तादाद में ईंटों के भट्ठे नहीं हैं। जिस से लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। यहां पहले एक सज्जन अपनी स्पीच कर रहे थे तो कहा गया कि देहात में तो कच्चे मकान बनाए जाते हैं। यह ठीक है। कच्चे मकान बारिश में कई दफा गिर जाते हैं। वह लोग चाहते हैं कि अपना सर छुपाने के लिये पक्की जगह बना लें। उस के लिए ईंटें खरीदने की जरूरत है। शहरों की बजाए देहात में हर लिहाज से मकान बनाना महंगा पड़ता है। वहां ईंटें मिलती नहीं। 10 या 20 रुपये दे कर ब्लैक देकर दुगना भाव कर लेते हैं। जितनी ईंट की कीमत है तकरीबन उतना ही लाने का किराया लग जाता है, वहां ट्रांस्पोर्ट के साधन मौजूद नहीं। भट्ठे दूर २ हैं। वहां से लाना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों भी मैंने कहा था, इस बात को माना भी गया था। वहां पर लोगों को भट्ठे लगाने के लाइसेंस गवर्नमैंट को लिबरली देने चाहिएं जहां पर भट्ठे मौजूद नहीं हैं। उस के लिये कोयला भी देना चाहिए। खास तौर पर कुछ ऐसी सहूलतें हों, कोई सबसिडी दी जा सके। मैं समझता हूं कि उस इलाका को सहूलतें पहुंचाई जाएं, उस से वह इलाका अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा।

ट्यूबवैल्ज़ के बारे में, कर्जे के बारे में भी मैं अर्ज़ करूंगा। कुछ इलाके ऐसे हैं जिला होशियारपुर, का अनन्दपुर का इलाका है। इस के इलावा तहसील गढ़शंकर का इलाका ऐसा है जहां आबपाशी के कोई साधन नहीं। (विघ्न) अनन्दपुर कंस्टीच्युऐंसी है। ऊना तहसील सारी की सारी में, वहां पर खास तौर पर जब तक गवर्नमैंट ऐसा इन्तज़ाम नहीं करेगी मसला हल नहीं होगा। लोग अपने पल्ले से, जिस के पास गुंजाइश है, ट्यूबवल लगाने की कोशिश करते हैं। वह कई २ जगह बोर कर के देखते हैं मगर पानी नहीं मिलता, नीचे पत्थर अड़ जाता है, बोर हो नहीं सकता। मुझे डिपार्टमैंट के अफसरों से पता लगा कि पहिले इस किस्म के साधन हों कि अगर कोई आदमी अपने तौर पर बोर करके देखे, जब तक उसको सफलता न मिल जाए उस वक्त तक का खर्च गवर्नमैंट का बोरिंग डिपार्टमैंट करता था। ट्रायल के तौर पर जो खर्च होता था वह उस से नहीं लेते थे। जहां उस का ट्यूबवैल कामयाब हो जाए वहां से खर्च लिया जाए। उन लोगों को सहूलत देनी चाहिए जहां नहर का पानी लाने का कोई चान्स नहीं, इस किस्म के कोई साधन नहीं वहां पर उन लोगों को फैसिलिटीज़ दी जानी निहायत जरूरी हैं। सरकार का यह एलान है कि फर्टलाइज़र देंगे, बिजली के कुनैक्शन देंगे, पानी देंगे और दूसरी सहूलतें देंगे, अच्छे बीज देंगे, इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचता। यह चीजें कहानी सी बन कर रह जाती हैं। सरकार ने पंजाब में ऐसी फैसिलिटीज़ देनी हैं ऐसे इलाकों को मगर वह उन तक पहुंचती नहीं। इसलिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अपने छोटे भाई से, वैसे मिनिस्टर होने के नाते कैप्टन रतन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, वह खास तौर पर उस इलाका की नुमायंदगी करते हैं। (एक माननीय सदस्य–वह लुध्याना में रहते है।) वह सब जगह रहते है, लुध्याना भी आ जाते हैं। वह सारे पंजाब में जाते हैं। उन से अर्ज़ करूंगा कि वह ऐसे इलाका की तरफ-ऊना तहसील, गढ़शंकर तहसील का इलाका कंडी, रक्कड़ और बोट एरियाज और इस किस्म के जो पंजाब में दूसरे इलाके हैं उनकी तरफ

[चौधरी बालू राम]

खास तौर पर ध्यान दें और पैदावार बढ़ाने के लिये जमींदारों को सहूलतें दें और उन्हें आसानियां दें। इन बातों की तरफ मैं खास ध्यान दिलाना चाहता हूं। (घंटी)

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ, ਐਸ. ਸੀ.) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਥੇ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹਿਰ ਵੇਹਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਏਡੀ ਵਡੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਚ ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਡਾ ਇਕਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖੜੀ ਬਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਗੱਡੀ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦਿਖ਼ਣੋ ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਕਿਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਟਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਗ਼ਲਤ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਏਥੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਏਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੋਗਰੈਸ ਪੁਛਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ

ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੀ. ਏ. ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੋਗਰੈਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਔਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ । ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ । ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਉ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਟ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਉਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਮਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੀ ਲਗਣਾ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਓਵਰ ਸੀਅਰ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲਾਂ ਵਿਛਵਾ ਲਈਆਂ । ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ-ਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲਾਂ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ. ਸੀ. ਐਨ. ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਘੇ ਕਣਕ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਂ ਵਿਛਵਾ ਦਿਉ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1,950 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹੈ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]

ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ 22 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 167 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1964-65 ਵਿਚ 45.81 ਲਖ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41.55 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 544 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 502 ਬਣਾਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਫੈਮੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। 1962 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਗੋੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ ਸੂਦ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸੂਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਸੂਦ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਤੋੜ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਪ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1964 ਵਿਚ 45 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਲੇਕਨ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 30 ਰੁਪਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਛੇ ਕਿ ਅਜ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ 30 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਜਕਲ ਮੁਣਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਇਹ ਹੈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 45 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ । ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਪਾਸ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ 4,500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਕਿ 4,500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਜ ਹਲ ਵਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ? ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲਰ ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਹੋ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੁਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲ ਵਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਥਮਲਾ ਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਚ ਬਣਾਕੇ ਦਸ ਦੇਣ । ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਕਲ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੈਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । 1962 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]

ਵਿਚ ਵਰਤ ਲੈਣ (ਸ਼ੋਰ)। ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਲਾਈ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਲਾ ਹਰੀਜਨ ਲਭਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਟਾਟਾ ਹਰੀਜਨ ਲਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੂਟ ਬਨਾਉਣੇ ਸਿਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਲਾਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟ ਬਨਾਉਣੇ ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਕਾਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇਨਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਰਨਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਰੇਡ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਗਰਾ ਕਾਨਪਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜ ਸ਼ੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਡਸਟਰੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੈਦਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਜੋ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਦਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਰਗਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਤ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਜਨ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਨਗੇ । ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਕਮਿਹਊਨਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਨਟ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ (ਘੰਟੀ) । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ।

(Deputy Speaker in the Chair.)

ठाकुर मेहर सिंह (डेरा गोपीपुर) : वित्त मन्त्री महोदय ने हाउस के अन्दर अगले माली साल के लिए बजट पेश किया है। मैं उसको रवायती तौर पर बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस में ज़िक्र किया गया है कि ज़िला महेंद्रगढ़, हिसार तथा रोहतक के अन्दर लैंड रैवेन्यू रिमिशन किया गया। इस के अलावा वहां पर तकावी लोन को सस्पैंड करने का भी ज़िक्र किया गया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने वहां पर इन चीज़ों की रिमिशन की है। वहां पर इस प्रकार की सहायता होनी चाहिए क्योंकि वहां पर कहतसाली के हालात पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हम ने बार बार सरकार को रिप्रिजैंटेशन दी कि ज़िला कांगड़ा के अन्दर मक्की की फसल नहीं हुई। इसके अलावा वर्षा न होने के कारण वहां पर गेहूं की फसल होने की बिल्कुल आशा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो वह अपनी एजैंसी के द्वारा इस बात का जायज़ा ले सकती है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने वहां की हालत को देखने की तनिक भी चिन्ता नहीं की। सरकार ने वहां के लोगों की दयनीय हालत की ओर ध्यान नहीं दिया। वहां के लोग गरीब हैं। सरकार ने वहां पर लैंड रैवेन्यू भी रिमिट नहीं किया। कांगड़ा के लोग तो किसी प्रकार की तकावी लेना जानते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हमारे इलाके के साथ सरकार की तरफ से सौतीली मां का सलूक किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे इलाके के लिए खेती बाड़ी के बारे में स्कीमें बनती हैं। उसके लिए सरकार कुछ सबसिडी देती है। सरकार ने वहां पर बीज 78 पैसे फी किलो के हिसाब से दिया लेकिन बाद में उसकी कीमत 60 पैसे फी किलो कर दी। वहां के ब्लाक समिति वालों ने 18 पैसे फी किलो जमींदारों को वापस करने के लिए भी कहा लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने तथा ब्लाक समिति ने उन को अभी तक 18 पैसे फी किलो के हिसाब से पैसे वापस नहीं किए। सरकार को चाहिए कि वह अपने वायदों को पूरा करे ताकि लोगों के अन्दर सरकार के प्रति उल्टी भावना न पैदा हो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर डैफिसिट बजट होने के कारण टैक्स लगाए जाते हैं। मैं ने पहले भी बार बार सरकार के ध्यान में बातें लाई और आज भी मैं वित्त मन्त्री महोदय को प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां पर स्कीमें चालू हैं और काम हो रहे हैं वहां पर सख्ती

[ठाकुर मेहर सिंह]

से निगरानी की जाए। अगर वहां पर रुपया अच्छी तरह से यूटेलाइज़ किया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार को गरीब लोगों पर मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हाउस के अन्दर एक मिसाल रखना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युएंसी के अन्दर एक कोटला कम्युनिटी हाल बनाया गया, जिस पर 7 हजार रुपए खर्च किए गए और यह रुपया सैंटर की तरफ से इम्दाद के रूप में मिला। वहां पर सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए खर्च किए गए। वह हाल भी मुकम्मल नहीं हुआ। वहां पर सरपंच ने 4-5 हज़ार रुपया खर्च किया और इस के इवज़ 7 हज़ार रुपए की लागत शो कर दी। इस के इलावा ब्लाक समिति ने भी कुछ रुपया मंज़ूर किया। लेकिन उस व्यक्ति ने वह रुपया भी हड़प कर लिया। इस के बारे में मैं ने सरकार से सवाल किया। सरकार ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस काम के लिए ब्लाक समिति ने कोई रुपए नहीं दिए। ब्लाक समिति ने कहा कि उस साबिका के पास सिर्फ 33 रुपए कुछ आने निकलते हैं। उन्हों ने इतनी थोड़ी राशि बताई है जो कि उस से वसूल होनी है। मैं समझता हूं कि यह नुक्स हमारे कर्मचारियों में है जो कि सरकार के रुपए से खेल रहे हैं और वह कर्मचारी रुपए को मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारियों को हिदायत करे कि वह चालू काम के लिए सख्त निगरानी रखें ताकि रुपए का मिसयूज़ न हो सके। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट की इन्क्वायरी श्री सकोट जो कि विजीलैंस डिपार्टमैंट का अधिकारी था, उस के ज़रिए कारवाई की गई थी। उस ने सरकार को रिपोर्ट भी दी। सरकार को वह रिपोर्ट मंगवानी चाहिए ताकि उस पर बाकायदा ऐक्शन लिया जा सके। इस के अलावा एस. डी. ओ. सिविल (देहरा गोपीपुर) की रिपोर्ट भी इस हाल के बारे में सरकार के पास आई है। अगर सरकार उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से देखभाल करे तो पता लग सकता है कि उस जगह पर कितने रुपए की हेरा फेरी हुई है। वहां पर रसीदें बोगस बनाई गई हैं। कई खर्च शो किए गए हैं लेकिन उस की रसीदें मिल नहीं रही हैं। मैं ने कई बार सरकार के नोटिस में यह बात लाई है लेकिन बड़े खेद से कहना पड़ता है कि सरकार ने इस हेरा फेरी के बारे में कोई ऐक्शन नहीं लिया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे इलाके के अन्दर कुएं और बाउलिओं के लिए बार बार ग्रांटें दी जाती हैं लेकिन वहां पर कोई काम नहीं होता है। इस का कारण यह है कि सरकार की तरफ से इन कामों के लिए कोई चैकिंग नहीं होती है। सरकार के लाखों रुपए हेरा फेरी के द्वारा ज़ाया हो रहे हैं। अगर सही तरह से इस रुपए को यूज़ किया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार को मज़ीद टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को फ़िज़ूलखर्ची को बन्द करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी सरकार अगले माली साल के अन्दर 600 के करीब फेयर प्राईस शाप्स खोलने जा रही है। मैं वैसे तो इस स्कीम के हक में हूं ताकि गरीब लोग वहां से सस्ते भाव पर चीज़ें खरीद सकें। लेकिन मैं सरकार के सामने दूसरी तसवीर भी रखना चाहता हूं। आप को मालूम है कि जो समाल होल्डिंग जमींदार हैं, उस की हालत बहुत ही दयनीय है। उन की पिछली दो फसलें तबाह हो चुकी हैं। वह इतने ग़रीब हो चुके हैं

कि वह अब अपने बच्चों को पेट भर कर खाना भी खिला नहीं सकते हैं। उन्होंने अपनी आमदन में से जो कि खेती की उपज कर सकते हैं, उसी से कपड़ा और खाने के साधन जुटाने होते हैं लेकिन उन की हालत फसलें ठीक न होने से खराब हो चुकी है। वह लोग अब फेयर प्राइस शाप्स से खरीद नहीं सकते। इसलिए उन की हालत सुधारने के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए। मैंने कई बार सरकार के सामने स्कीमें रखी हैं कि हमारे इलाके के अन्दर छोटी छोटी सड़कें और लिंक रोडज़ बनाई जाएं ताकि वह लोग वहां पर मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सरकार को इन स्कीमों को लागू करने के लिए ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को मालूम है कि बड़े आदमी गरीब आदमियों को किस तरह से 107/151 के अधीन ऋश करते हैं। वह अधिकारियों से मिल कर गरीब आदमियों को नाजायज़ तौर पर तंग करते हैं यह चीजें डैमोक्रेसी की हकूमत में किसी तरह भी शोभा नहीं देती। वह लोग जमानतों के लिए डिस्ट्रिक्ट हैड क्वारटर्ज़ पर मारे मारे फिरते हैं लेकिन उन की कोई सुनवाई नहीं होती है। उन के बरखिलाफ झूठे मुकदमें बनाए जाते हैं और उन को बुरी तरह से हारास किया जाता है। उन के बरखिलाफ 182 सी. आर.प.सी. के अडंर मुकद्मे बनाए जाते हैं। उस के बरखिलाफ साजिशें बनाई जाती हैं ताकि वह अपना पेट भर कर गुज़ारा न कर सकें। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वह लोग इन साजिशों से बच सकें और अपना काम करके अपने बाल बच्चों को रोटी खिला सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बजट के अन्दर क्लास फोर ऐम्पलाइज़ के लिए कोई रियायत नहीं दी गई। आप को मालूम है कि चंडीगढ़ शहर बहुत ही महंगा शहर है। यहां पर क्लास फोर के ऐम्लाइज़ को 100 रुपए तनखाह मिलती है। आप ही बताएं कि उन्होंने अपने बाल बच्चों को शिक्षा देनी है, तथा अपने बच्चों को पेट भर का खाना खिलाना होता है, उन्होंने स्टैंडर्ड भी मेनटेन करना होता है, वह इतनी थोड़ी तनखाह में गुज़ारा नहीं कर सकते हैं। सरकार ने उन को रियायत न दे कर कोई अच्छी बात नहीं की। यहां पर बड़े बड़े प्रोजैक्ट चल रहे हैं। अगर उन में कमी की जाए और वह रुपए उन को दिए जाएं ताकि वह अपने बाल बच्चों को तालीम दिला सकें और अपने स्टैंडर्ड को भी मेनटेन कर सकें। मैं चहाता हूं कि उन की तनखाह 200 रुपए होनी चाहिए ताकि वह अपना गुज़ारा कर सकें। सरकार ने उन को किसी प्रकार की रिलीफ न देने से कोई सराहनीय काम नहीं किया है। सरकार को उन की हालत को सुधारने के लिए यथासम्भव कदम उठाने चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट के अन्दर सरकार ने 11 हज़ार ट्यूबवैल्ज़ के कुनैक्शन देने के लिए कहा गया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ज़िला कांगड़ा का रकबा 12 लाख एकड़ है लेकिन वहां पर अभी तक एक भी ट्यूबवैल्ज़ नहीं लगया गया है। वहां जितनी भी लिफ्ट इरीगेशन स्कीमज़ बनती है, उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पर चार साल से स्कीमें बनाई गई हैं। उन को अमल में नहीं लाया जा रहा है। वहां पर चोमुखा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है जोकि कई सालों से चालू हुई है वहां पर पक्की नहीं बनाई गई

[ठाकुर मेहर सिंह]

है। अगर वहां पर पानी डाला जाए तो वह पानी वहां पर जज़ब हो जाएगा। इस से वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहां पर नहर को पक्का किया जाए। इस के अलावा पडोली स्कीम बनाई गई है लेकिन अभी तक वह नामुकम्मल है, दरियाए ब्यास के आसपास हज़ारों एकड़ ज़मीन है जहां पर लिफ्ट इरीगेशन स्कीमें अमल में लाई जा सकती हैं लेकिन अभी तक सरकार ने उन स्कीमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस के अलावा वाटर नैशनल सप्लाइज़ स्कीमें सदों, डलियारा और बीहन में चालू की गई। उन के लिए ऐस्टीमेंट्स भी तैयार हो चुके हैं लेकिन कई सालों से उन पर अमल नहीं हो रहा है। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उन स्कीमों को जल्दी ही टेक-अप करे जो अंडर कंसिड्रेशन हैं ताकि लोगों को उन स्कीमों के मुकम्मल होने से लाभ हो सके।

यही बात है कि जब एक भाई को दूसरे भाई से मुनासिब हिस्सा नहीं मिलता तो वह उस के साथ रहने के लिये तैयार नहीं होता। जब हम महसूस करते हैं कि हमें कमाई में से मुनासिब हिस्सा मिलने वाला नहीं है तो हम पहाड़ी सूबे की मांग करते हैं। हमारे साथ पिछले 19 साल से सौतीली मां जैसा सलूक होता रहा है। यह ठीक है कि हमारी कुछ न कुछ डिवैल्पमेंट हुई हैं लेकिन जो कुछ हमें मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। इस लिये मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि वह हमारी समस्याओं की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे तभी हमारी डिवैल्पमेंट हो सकेगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यही हाल शिक्षा क्षेत्र में है। हम तालीमी तौर पर भी बहुत पिछड़े हुए हैं। कारण यह है कि न तो हमारे इलाके में स्कूलों की तादाद काफी है और न ही हमें स्टाफ पूरा मिलता है। दूर दूर से जा कर स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लड़कियों को खास कर इस सम्बन्ध में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कस्बों में तो शायद एक एक या दो दो लड़कियों के स्कूल होंगे लेकिन देहात में 12/12 और 15, 15 मील के फासले पर भी लड़कियों के लिये स्कूल नहीं मिलते। जब सूबे में सर्विसिज़ में हर एक को बराबर का शेयर मिलना है तो वह किस तरह मिल सकता है जब कि लड़कियों को मुनासिब तालीम ही नहीं मिलती। शहरों में रहने वाली लड़कियां ही सर्विस में आ सकती हैं या चंडीगढ़ में रहने वाली सर्विस में आ सकती हैं। इस लिये मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज़्यादा स्कूल रूरल एरिया में खोले जाने चाहिये (तालियां) हमारे इलाके की पसमांदगी को मद्देनज़र रखते हुए वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं।

एक बात और इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। हमारे इलाके के 90 फीसदी डोगरे आर्मी में सर्विस करते हैं लेकिन वहां पर कोई सैनिक स्कूल नहीं है। फौजी नुक्ता निगाह से भी यह बहुत ज़रूरी है कि वहां पर एक सैनिक स्कूल ज़रूर खोला जाए। मैं नहीं कहता कि ज़रूर मेरी कांस्टीच्यूएंसी में ही सैनिक स्कूल खोला जाए। जहां भी सरकार मुनासिब समझती है, कोई सैंट्रल प्लेस हो वहां पर एक सैनिक स्कूल खोल दे। हम बहुत देर से कहते आ रहे हैं कि गरली में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल ज़रूर खोला जाना चाहिये।

कई बार यह मुतालबा किया गया लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गरली के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं, बिल्डिंग देने के लिये तैयार हैं इस लिये वहां पर जरूर इन्स्टीट्यूट खोला जाना चाहिये। पिछले नौ साल से वहां पर अस्पताल की बिल्डिंग का प्रबन्ध किया हुआ है लेकिन वहां पर आज तक डाक्टर नहीं भेजा गया। पीर सलूही में भी कोई डाक्टर नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली के मामले में भी एक अर्ज मैं करना चाहता हूं। देहरा में बिजली का प्रोजैक्ट बना हुआ है। मेन लाइन भी गांव से आधा आधा मील या दो दो फर्लांग के फासले से गुजरती है लेकिन उन गांव में बिजली नहीं दी गई। उन लोगों ने सिक्योरेटी भी जमा करवा रखी है लेकिन इस के बावजूद उन को बिजली नहीं दी गई। इन बातों से हमारे लोगों में रीजेंटमेंट ज्यादा बढ़ती है। मैं आप के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां से मेन लाइन गुजरती है और जिन लोगों के मकान मेन लाईन से एक एक मील के फासले पर हैं उन को जरूर बिजली दी जानी चाहिये। एग्रीकल्चर के औजारों के लिये जो सबसिडी दी जाती है उस का मुनासिब प्रबन्ध नहीं है। मैं तो यह महसूस करता हूं कि जो बलाक्स बने हुए हैं वह भी सियासी अखाड़े बने हुए हैं। जहां वे देखते हैं कि हम ने वोट लेने हैं या किसी कैंडीडेट को कामयाब करवाना है वह वहीं पर रुपया भी तकसीम करवाया जाता है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह रुपये की तकसीम को चैक करे कि कहां कहां पर कितना कितना रुपया दिया जाता है। मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर सरकार इस बात को चैक करे तो करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है और हमें नए नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप का धन्यावाद आप ने मुझे अपने विचार हाउस में रखने का समय दिया।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1960-61 ਦੇ ਜਿਹੜੇ Accounts ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਉਹ ਸੀ 33, 23 ਲੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 1966-67 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 76,34 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $2\frac{1}{3}$ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ $2\frac{1}{3}$ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ"। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਥੇ 1960-61 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 1966-67 ਦੇ ਬਜਟ ਤਕ 11,51 ਲਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੇਖੋ—ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 1960-61 ਵਿਚ ਇਨ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 24 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1966-67 ਵਿਚ 64,83 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ $2\frac{3}{4}$ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਗਲ ਫਖਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਦ ਖਾਧੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦ ਜਦ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦ ਜਦ ਨੌਰੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ) ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਡੰਡਵਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋ ਪੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ—ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਪੇਡ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60 ਰੁਪੈ ਮਾਹਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ 40 ਰੁਪੈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ 10 ਰੁਪੈ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਾਨੀ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਅਜਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1960-61 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਨ 1960-61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ $2\frac{1}{3}$ ਗੁਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ 100 ਤੋਂ 150 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਵਜ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਪੇਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋ ਪੇਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਮਖਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਦੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਔਰ ਫੇਅਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਸਿਵਾਏ ਚੰਦ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ—ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਡੀ. ਸੀ. ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਡੈਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਨਾਲ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਜ਼। ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਅਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1960-61 ਦੇ Accounts ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1960-61 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ 23 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ 1964-65 ਵਿਚ 33 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 34 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 16 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇ—ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਡਿਗ ਕੇ 16 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆਈਟਮਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਸੈਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ—ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਤਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਲੜੀ ਲਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਸਰਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਤ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਥ ਦਿਉ ਤੇ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਉਸ ਹੱਥ ਖੋਹ ਲਉ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 86 ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 75 ਰੁਪੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ 11 ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੁਕਮ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਥੇ ਮੁਕੱਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਲੰਟੈਰੀਲੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋ ਪੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਰ ਜਦ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਨੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਝਾਟਮ ਝਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ—ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਖਿਚਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਡੀਆਂ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਚਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਫਾਰਸ (**Farce**) ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ (effective) ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਭਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਉਭਰ ਪੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਸਟਰੈਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

6.00 p.m.

ਜਿਥੇ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ 44 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ 19 ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਉ ਮਿਤਰੋ ਪਿਉ, ਅਜ ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਜ ਨਾ ਪੀਉਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੀਉਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਥੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹਨ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਡਰਾਟ ਕਰ ਕੇ ਭੁਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 1960-61 ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਣੀ 1960-61 ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਣੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮਦਣੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਣੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਮਦਣੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਦ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜ ਕਪਾਹ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜ ਰੀਵਾੜੀ, ਊਨਾ, ਨਾਰਨੌਲ, ਭੀਵਾਨੀ ਔਰ ਹਾਂਸੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਜ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਧਰ ਖੇਮਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੈਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਦ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਂਟ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਟੀਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ ਜਦ ਕੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਲਾਇਤੀ ਖਾਦ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਖਾਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇਗੀ? ਫਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 12 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਤਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਤਰਾਹੀਂ ਤਰਾਹੀਂ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। *Mr. Speaker in the Chair.* ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਉਵਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੀ ਫੂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬੀਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34—35 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਕੀ ਬਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਦਮੀ 38 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਡ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਤਨੀ ਬਿਡ ਵਪਾਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਉਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਇਕ ਨੇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਖੋ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਖ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹ ਪਿਆ ਪਰ ਅਜ ਉਸ ਦਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕਟ ਵਿਚ 54 ਜਾਂ 55 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਗਿਣ ਲੈਣ। ਇਹ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਉ ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ

ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨ੍ਹੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚਟੇ। (ਇਕ ਆਵਾਜ਼: ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ?) (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਨਸ਼ ਪੁਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਗਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼-ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਬੇਇਤਮੀਨਾਨੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਮਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਕੋਈ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਬੀਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਲਤਿਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਹੈ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਆਤਸ਼ਫਸ਼ਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਭਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਚਾਰ-ਜਿਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਫਜ਼ੂਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛਡਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘਾਟੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਗਾੜਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੇ, ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿਉ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਡੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਉ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਬ ਲਈ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਅਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭੁਖੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੜ ਵਲ ਵੇਖੋ। ਇਥੇ ਗੁੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਗੁੜ ਇਮਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 34—35 ਰੁਪਏ ਮਨ ਮਕੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੱਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 92 ਲਖ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ 92 ਲਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ $1\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਬਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ New Expenditure ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ 'New Expenditure' ਵਿਚ ਲਲਤੋਂ ਤੋਂ ਸਰਾਬੇ ਤਕ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸੜਕ, ਨਾ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 7 ਮੀਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਮਗਰ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਤਨੇ ਨਾਅਹਿਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ fish fingerlings ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਕ pond ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਇਹ 3 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਛਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਥੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਟਿਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਵਿਚ ਮਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਲੇ ਪਈ ਹੈ।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER, PUNJAB REGARDING THE PUNJAB SITUATION

Chief Minister (Shri Ram Kishan) : Mr. Speaker, Sir, with your permission I want to make a statement on the present Punjab situation. With the re-opening of the Punjabi Suba issue, opposite views have been expressed and in some quarters slogans and counter-slogans have created a situation of anxiety.

It will be recalled that under similar circumstances in 1956, a decision was taken to resolve the language controversy. However, due to one reason or the other, some people, have remained dissatisfied. It was against this background that the Government of India agreed to re-open the issue of Punjabi Suba and to give a calm consideration to various aspects of the question with a view to finding a solution, which should not only resolve the controversy, but bring about maximum satisfaction and stability in Punjab.

It is a tribute to our democratic processes that all shades of public opinion have had an opportunity to express themselves on the issue of Punjabi Suba. The Congress Working Committee and the Union Cabinet are also giving their best consideration to this problem. We can rest assured that the solution thus arrived at after cool and thorough deliberations will be in the best interests of the State and the country.

It is the constitutional right of indivisuals and parties to express their views and even influence other people. But the law of the land does not give permission to any one to exceed the limits and pose a threat to peace and tranquility of the State. No Government can tolerate violence of thoughts and action calculated to disturb the peace. I wish to make it clear that the Government have absolutely no desire to suppress the free and frank expression of views and opinions but law and order shall be preserved at all costs.

The Government have taken careful note of the present trend that in the eagerness to gain a point over the adversary, some people are oblivious of the harmful consequences of provocative slogans and counter-

slogans. Government's patient toleration in the interest of fairplay should, however, not be misunderstood by anyobody ; as necessary, the administration will be quite prepared to initiate suitable action to preserve peace. If required, necessary restrictions will also be imposed to preserve order and stability.

At the time of the Chinese aggression in 1962 and again in the recent Indo-Pakistan conflict Punjabis of all communities shed their blood together for the territorial integrity of the country. We have not yet fully recovered from the shock which our economy received as a result of the recent war. Problems like the resettlement of the war displaced and the rehabilitation of the agricultural and industrial economy of the border districts still remain to be dealt with. These problems cannot be solved unless we have conditions of ability in our State. It is, therefore, of utmost importance that nothing should be permitted to happen which may weeken the State and, in turn, its capability of competently dealing with the problems arising out of the after-math of the war.

May I, therefore, appeal to all Punjabis who are proud of the common heritage of the Gurus and the Saints and to all the religious and political leaders of the State not to forget the basic unity of Punjabis derived through the common heritage of Hindus and Sikhs and other communities of Punjab. It is on the basis of this unity that we have decided to celebrate the 500th birth anniversary of Shri Guru Nanak Devji and also the 300th birth-anniversary of Shri Guru Gobind Singhji on a proper scale with a view to highlighting the fact of common spiritual heritage of all people of Punjab. Let not any intolerance or violence leave a slur on the fair name of the Punjab, the land that has given birth to great ideas of humanity, universal brotherhood and amity.

Sardar Lachhman Singh Gill : What is the occasion to make this statement? (*Interruptions and noise in the House.*)

Mr. Speaker : Order, order please.

Chief Minister : I would particulary appeal to Sant Fateh Singh Ji, for whom we all have sincere respect, to keep the basic interests of the Punjab in view in the present situation. May I also urge that with him the need for calm and comprehensive discussions and mutual consideration on such a vital matter. (Interruptions and Noise in the House.)

Mr. Speaker : Order, order please.

Chief Minister : I have no doubt that he would find full and fair response. To Swami Satyanand and other leaders too would go my appeal for similar tolerance and understanding. We must avoid saying or doing things which might aggravate the existing difficult situation or precipitate any crisis.

I take this opportunity of assuring all fellow Punjabis—the farmers, the industrialists and other law-abiding citizens—that this Government will maintain peace and tranquility under all circumstances. (Thumping.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਨਟਾਈਮਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ।

Mr. Speaker : Order, order please.

Chief Minister : No one need have any fear on account of a few irresponsible statements. Life and property will be protected with all the power at the disposal of the State Government.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਬਲੇ ਓ ਪਹਿਲਵਾਨਾ........ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਹਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਨੋ ਇਨਟਰਪਸ਼ਨਜ਼ । (Order please. No interruptions.) (ਵਿਘਨ) Order, order please.

Chief Minister : Let us remain calm and have faith that the Government of India will evolve a solution which will end all acrimonious controversies for ever. Let us not forget the closest bonds that have cemented the Hindus and the Sikhs in a common heritage over centuries.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ? (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order, order please.

Chief Minister : The essence of this heritage is love, unity and tolerance. Let us resolve to preserve and promote mutual trust and understanding and settle our problems in that spirit.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲਖ ਨਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੋ। (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order, order please. No interruption.

Chief Minister : I have no doubt that at this critical juncture leaders of all political parties will give true guidance to their followers not to forget the sacred blood shed by our brave soldiers for saving the honour of Punjab and the country and to remain peaceful. (*thumping*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ....(ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। (On what subject is the hon. Member speaking ? If he wants any clarification, he can put a question.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲੀ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਮਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ? (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼। ਟੇਕ ਯੋਅਰ ਸੀਟ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਕਲੈਰੀ-

ਫਿਕੈਸ਼ਨ ਗਰੁਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Order please. A convention is in vogue in the Lok Sabha that if any important statement is made by the Government on their own then by way of clarification each of the group leaders are entitled to ask a question.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛੱਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ..... (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please. Take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਲਛੱਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ......

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਆਪ ਬਰੀਚ ਆਫ ਪੀਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪ ਅਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਜਾ ਅਪੀਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਅਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰੀਚ ਆਫ ਪੀਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰੈਸ਼ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ।

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਲਛੱਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:::..... (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਆਪ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਗੌਰਮੈਂਟ........... (ਵਿਘਨ)

6.30 p.m. **Mr. Speaker** : The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow on Wednesday, the 9th March, 1966.

(*The Sabha then adjourned till* 9.30 *a.m. on Wednesday, the 9th March,* 1966).

8506PVS—462—9-8-66 —C., P. & S. Pb., Chd.

APPENDIX

TO

P.V.S. DEBATES VOL I—NO. 14.

Dated the 8th March, 1966.

Cases withdrawn from the Courts.

3296. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Welfare and justice be pleased to state :

(a) whether any cases from the Courts have been withdrawn by the Punjab Government/District Magistrates or by any authority in the State during the period from 6th July, 1964, to date ; if so, the details thereof, year-wise, district-wise, together with the names of the persons cases have been withdrawn stating the dates when these were withdrawn and the reasons for withdrawing these cases.

(b) the designation of the authority who ordered the withdrawal of each of the said cases ?

Shri Chand Ram : (a) and (b) A statement indicating the district-wise number of cases withdrawn and the authority under which these cases were ordered to be withdrawn is enclosed. The time and labour involving in giving the details of each of these 214 cases will not be commensurate with any possible benefit to be derived therefrom.

STATEMENT

Sr. No.	District	No. of cases withdrawn by District Magistrate	No. of cases withdrawn by State Government.	Total number of cases withdrawn
1.	Sangrur	6	..	6
2.	Hoshiarpur	4	1	5
	Kapurthala	4	1	5
4.	Ferozepore	5	..	5
5.	Ludhiana	6	3	9
6.	Hissar	7	..	7
7	Gurdaspur	..	1	1
8.	Simla	11	..	11
9.	Kangra	5	..	5
10.	Jullundur	63	..	63
11.	Rohtak	9	1	10
12.	Mohindergarh	..	1	1
13.	Gurgaon	1	4	5
14.	Bhatinda	3	..	3
15.	Patiala	3	..	3
16.	Kulu	2	..	2
17.	Ambala	12	7	16
18.	Karnal	13	7	20
19.	Amritsar	37	..	37
	Total	191	23	214

APPENDIX

to

P.V.S. DEBATES VOL I—NO. 14.

Dated the 8th March, 1966.

Cases withdrawn from the Courts.

3296. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state :

(a) whether any cases from the Courts have been withdrawn by the Punjab Government/District Magistrates or by any authority in the State during the period from 6th July, 1964, to date ; if so, the details thereof, year-wise, district-wise, together with the names of the persons cases have been withdrawn stating the dates when these were withdrawn and the reasons for withdrawing these cases.

(b) the designation of the authority who ordered the withdrawal of each of the said cases ?

Shri Chand Ram : (a) and (b) A statement indicating the district-wise number of cases withdrawn and the authority under which these cases were ordered to be withdrawn is enclosed. The time and labour involving in giving the details of each of these 214 cases will not be commensurate with any possible benefit to be derived therefrom.

STATEMENT

Sr. No.	District	No. of cases withdrawn by District Magistrate	No. of cases withdrawn by State Government	Total number of cases withdrawn
[illegible]	Sangrur	6	..	[illegible]
2.	Hissar	4	1	5
[illegible]	[illegible]	4	1	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]
[illegible]	[illegible]		..	[illegible]
[illegible]	[illegible]		1	[illegible]
[illegible]	Simla	[illegible]	..	11
9.	Karnal	[illegible]	..	[illegible]
10.	Jullundur	[illegible]	..	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	1	10
[illegible]	[illegible]garh		1	[illegible]
[illegible]	[illegible]		4	[illegible]
[illegible]	[illegible]		..	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	2
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	37	..	[illegible]
	Total	191	23	214

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

9th March, 1966

Vol. I—No. 15

OFFICIAL REPORT



CONTENTS

Wednesday, the 9th March, 1966 — PAGE

Price: Rs. 7.00 P. se.

ERRATA

To

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES Vol. I, No. 15, DATED THE 9TH MARCH, 1966

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਅਖਤਿਆਰ	ਅਖਿਤਆਰ	(15)1	Last
इनसेक्टीसाईड्ज़	इनमेक्टीसाइज	(15)2	4
therefor	therfor	(15)2	23
Government	Governmsnt	(15)4	1
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ	ਸਰਦ'ਰ ਗੁਰਚਨ ਸਿੰਘ	(15)4	14
क्राईटीरिया	काईटीरिया	(15)4	Last
मुख्य	मख्य	(15)6 (15)87	13, 27, 31 6 from below
फास्ट	फ'रट	(15)6	20
1962-63	1963-62	(15)9	2
1963-64	1936-64	(15)9	2
1964-65	1995-65	(15)9	2
April, 1965	April, 196	(15)10	9
complete	completed	(15)10	16
9271	927,	(15)10	Last but one
[Education Minister]	[Education of Minister]	(15)12	1
ਹਾਊਸ	ਹਾਓਸ	(15)19	1
where	were	(15)22	24
ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ	ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ	(15)25	19
कामरेड राम प्यारा	कामरेड र म प्यारा	(15)25	22
ਫੇਰ	ਡਰ	(15)26	9
may	my	(15)27	8 from below
Sarvshri	Sarvshr	(15)31	3
School	Sdhool	(15)37	4

P. T. O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
stands	stand	(15)50	3
loanees	loanes	(15)52	1
	lonees	(15)60	2
Simultaneously	Simulataneously	(15)71	5
EXPLANATION	EXLANATION	(15)73	14
regarding	regardineg	(15)74	21
reflections	reflection	(15)78	10
censure	censur	(15)79	11
form	from	(15)86	19 from below
आफ	आप	(15)91	17
ਨਫਰਤ	ਨਫਤਰ	(15)92	8 from below
ਹੋ	ਹੈ	(15)93	4 do
(Interruptions)	(Intettuptions)	(15)95	7
ਮੰਤ	ੰਤ	(15)95	22
ਖਿਲਾਫ	ਖਿਲਾਢ	(15)96	5 from below
चौधरी नेत राम	चौधरी नत राम	(15)99	4
	चौध,ी नत राम	(15)125	16
does	dose	(15)99	24
comply	be comply	(15)100	13
sufficiently	sufficently	(15)100	Last but one
Noes	Nos	(15)101	25
ਮੈਂਡਮ	ਮੈਂਡਮਾ	(15)116	4
ਬੈਠਦੇ	ਬੈਨਦੇ	(15)123	23
arrested	arested	(15)124	6
bail	bale	(15)124	6
ਕੇ	ਦੇ	(15)125	8 from below
ਅਸੂਲ	ਅਸਲ	(15)126	24
ਹਿੰਦੂ	ਹਿਦੂ	(15)127	10

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 9th March, 1966

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan Sector 1, Chandigarh at 9.30 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Damage by cold to sarson crop in district Gurgaon

***9383. Shri Babu Dyal Sharma** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether he is aware of the fact that the sarson crop of Gurgaon District has been totally destroyed by excessive cold and other crops dependent on Chak Sahbi stream for irrigation are withering owing to scarcity of water ; if so, the details of the steps being taken by the Government to protect them ?

Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister) : (1) The sarson crop of Gurgaon District has not been totally destroyed by excessive cold. This crop has caught some disease because of lack of rain. The sarson crop in the bed of the Sahibi has been least damaged.

(2) The water of the Sahibi is not used for irrigation. This water is used to charge the brackish sub-soil water, to sweeten it. As such, the question of taking any steps to save the crops from withering because of drought does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order, Sir., ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ।

Minister : Sir, it has been stated in the reply that this crop has got some disease because of lack of rains.

श्री बाबू दयाल शर्मा : जैसे बताया गया है कि तेला लगा था इस लिए नुक्सान हुआ मैं पूछना चाहता हूं कि इस से बचने के लिए गवर्नमैंट ने क्या तजवीज इख्तयार की ।

ਮੰਤਰੀ : ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਛਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਮੇਈਅਰਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮੇਈਅਰਜ਼ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਖਿਤਆਰ

[ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ]

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈਲਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਏਸ ਵੇਲੇ।

श्री बाबू दयाल शर्मा : यह बताया जा सकता है कि कितने इनमेक्टोसाईड्ज़ यूज़ हुये और कितने बचे ।

Minister : I require notice

Agricultural land of Livestock Farm, Hissar

***9471. Shri Hunna Mal** : Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the the past years agricultural land of the Government Livestock Farm in district Hissar used to be cultivated by the tenants on batai system but the same has now been got vacated from them and under a new scheme it is being cultivated by the Government by means of tractors etc.; if so, the total income that accrued to the Government from the said tenants on account of Batai during the period from Kharif 1960 to Rabi 1965 together with the present total net income accruing to the Government after deducting the wear and tear of the tractors and other expenses incurred under the present system ;

(b) whether Government have earned more profit by taking over the cultivation than it did from the said tenants under batai system ; if so, what, if not, the reasons therfor ?

Captain Rattan Singh :(a) *First Part.*—Yes, only 4,599 acres out of 6,893 acres of land was got vacated during the year 1965-66.

Second Part.—Rs. 28,73,525 as 'batai' from tenants during the five years from 1960-61 to 1964-65. The net income through mechanised cultivation will be known after crops have been harvested and accounts finalised.

(b) Not yet known.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जिन मुज़ारों को बेदखल किया गया था क्या उन को पहले कहीं ज़मीन अलाट की गई थी ? अगर नहीं तो इस की क्या वजह है ?

राज्य मन्त्री : ऐसी कोई बाईंडिंग स्टेट गवर्नमैंट पर आयद नहीं होती, इस लिये यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, will the hon. Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state the criteria kept in view to eject some tenants while to keep others on the land ?

राज्य मन्त्री : गवर्नमैंट जो मुनासिब समझती है उस के मुताबिक काम करवाया जाता है और तकरीबन सारे का सारा ऐरिया हम अडंर कल्टीवेशन ले रहे हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या यह दरुस्त है कि गरीब हरिजनों को बेदखल किया गया है मगर जो रिसोर्सिज वाले हैं वह अभी भी बैठे हुए हैं ।

राज्य मन्त्री : किसी को बेदखल नहीं किया गया यह तो year to year के लिये breeding programme के तहत cultivation के लिये जमीन दी जाती है । under the breeding programme we have to keep the land.

श्री अमर सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुजारे कितने बेदखल हुए और जब मुजारे बेदखल नहीं हुए थे उस वक्त पैदावार ज्यादा होती थी मगर जब ट्रैक्टरों से वहां पर काम किया गया तो पैदावार कम हो गई इस की क्या वजह है ?

राज्य मन्त्री : मुजारों के नम्बर का तो मुझे पता नहीं है, बाकी जो इनका सवाल था उसका मैं ने जवाब दे दिया है ।

श्री अमर सिंह : मैं ने सवाल किया था कि कितने मुजारे बेदखल हुए थे, और ट्रैक्टरों से पैदावार क्यों कम हुई, इस का जवाब आना चाहिये ।

राज्य मन्त्री : मैं ने अर्ज किया कि जितनी ज़मीन हिसार फार्म के लिये चाहिये वह ट्रैक्टर आरगेनाईज़ेशन के जरिये काश्त कराई जा रही है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਉਥੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਯੀਅਰ ਟੂ ਯੀਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट उन मुजारों को फिर स इस जमीन पर आबाद करने को तैयार है जो मौजूदा ट्रैक्टरों की कल्टीवेशन की निस्बत ज्यादा पैदावार करते थे ?

राज्य मन्त्री : यह ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत बिजाई जाती है अगर कोई पैदावार ज्यादा करके दिखा सकता हो तो हम उसे ज़रूर देंगे ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state whether the provisions of the Punjab Security of Land Tenures Act are kept in view while ejecting the tenants ?

Minister of State : Certainly

Transfer of Patwaris in Ferozepur District

***8961. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of patwaris transferred from one place to another in district Ferozepur in the months of March and April, 1965 ;

(b) whether any of the said patwaris were re-transferred, immediately after their first transfer ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister): (a) 142 patwaris.

(b) 19 patwaris.

[Planning and Local Governmsnt Minister]

According to Government Policy all the Patwaris in the State are to be posted beyond a distance of 20 miles from their homes. Nineteen patwaris were ordered to be re-transfrerred as in their case the actual distance was found to be of more than 20 miles from their homes.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 142 ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 20 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? what are the reasons ?

ਮੰਤਰੀ : 19 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਈ 90 ਮੀਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 100-100 ਮੀਲ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿ-ਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

श्री अमर सिंह : बहुत से पटवारी ऐसे हैं जो अपने रैंजीडैंस से 3-4 मील के फासले पर लगे चले आ रहे हैं, वह रात को अपने घर जाकर सोते हैं । अगर गवर्नमैंट की पालिसी यह है कि सरकार इस लिये दूर ट्रांस्फर करती है ताकि घरों के नज़दीक रहने से सरकार के काम में बाधा पड़ता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों की अभी तक ट्रांस्फर क्यों नहीं की ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਂਡ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਘਰ ਨਾ ਕਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ । 1961 ਵਿਚ 20 ਮੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ ।

श्री सुरेंद्र नाथ गौतम : यह जो २० मील का फासला रखा गया हैं यह प्लेंज और बैकवर्ड हिल्ली एरिया के लिए बराबर ही रखा गया हैं अगर ऐसा है तो क्या काईटीरिया हैं क्योंकि हिल्ली एरिया में आने जाने के साधन बहुत कम हैं ।

(No reply)

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੌਤਮ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਲੈਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏਹੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਆਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦਿਸ।

ਮੰਤਰੀ : ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀ 20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। **(This is no point of order.)**

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ 20 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਇਹ 20 ਮੀਲ ਕਰੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 20 ਮੀਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਕਰੋ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ।

Chaudhri Darshan Singh : Are there any instructions or rules, according to which the patwaris could be posted within twenty miles ?

ਮੰਤਰੀ : ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਮੀਲ ਏਧਰ ਓਧਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਓਥੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਓਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰਾਂਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ।

Memorandum from Punjab Subordinate Services Federation

***9624. Shri Om Parkash Agnihotri** . Will the Minister for Finance be pleased to state whether the Punjab Subordinate Services Federation submitted a Memorandum regarding the revision of pay scales, appointment of a pay Commission and fixation of D.A. keeping in view the price index etc. during the period from October, 1965 to 10th February, 1966 ; if so, the details of the action so far taken or proposed to be taken in this connection ?

Shri Ram Kishan (Chief Minister) : Yes. The matter is under examination.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मुख्य मन्त्री साहिब ने सबार्डिनेट सर्विसिज़ फैड्रेशन को कई बार एशोरेंस दी हैं कि यू. के. की तरह यहां भी व्हिटले काऊंसिल्ज़ बनाई जाएंगी और पंजाब में सारे इम्प्लाईज़ के ग्रीवेंसिज़ दूर करने के लिए ज्वायंट कंसलटेटिव मशीनरी कायम की जाएगी, क्या वह बताएंगे कि इस बारे में क्या किया है ?

मुख्य मन्त्री : आनरेबल मैंबर को मालूम है कि इसी हाउस में मैंने जवाब दे के कहा है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया और मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमैंट्स से, जो ज़रूरी काम किया है, जो स्टेप्स ले रहे हैं, खतो किताबत की गई थी, लिटरेचर पहुंचा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज कमीशन कायम किया गया उन के सामने सवाल आया था। उन्होंने गौर करके कुछ रिकमेंडेशन्ज़ की हैं। सारे सवाल पर गौर हो रहा है। अंडर एग्ज़ामीनेशन है। जिस वक्त कन्सरंड डिपार्टमैंट्स की तरफ से यह मामला एग्जामिन हो कर आ जाएगा कार्रवाई हो जाएगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask as to how long will it take the Government to finalise the matter after due consideration ?

मुख्य मन्त्री : कुछ कहा नहीं जा सकता। सारा मामला अंडर कंसिडरेशन है, अंडर एग्जामीनेशन है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਨੇ ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ?

मुख्य मन्त्री : डेट मुकर्रर नहीं की जा सकती।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : उन की डिमांडों में यह भी है कि जो रिट्रैंचमैंट हो रही है। वह बन्द की जाए। मुख्य मन्त्री ने एशोरेंस दिलाई थी और इस पर उन्होंने फास्ट ब्रेक किया था। अगर कोई ऐसी एशोरेंस है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया ?

मुख्य मन्त्री: कोई एशोरेंस नहीं दी गई। एक डैपूटेशन मिला था उन की बात को गौर से सुना था और कहा था कि उन की बात पर गौर किया जाएगा। मामला ज़ेरे गौर है। अभी कोई रिटरेंचमैंट नहीं हुई है।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ. ਏ. ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ?

मुख्य मन्त्री : जो स्टेट के रिसोर्सिज़ होंगे उसके मुताबक सारी बात को मद्देनज़र रखा जाएगा।

सरदार रणजीत सिंह नैनेवालिया : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि कोई नोटिस आ गया है कि वह पैन डाउन स्ट्राईक करेंगे इसी हफ्ता में ?

मुख्य मन्त्री : कोई नोटिस नहीं।

कामरेड राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वह अंडर एग्ज़ामीनेशन है। उस रिक्वेस्ट या उन डिमांड्ज़ में वज़न है तो क्या यह मान रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री : 17 फरवरी को वह डैपूटेशन मुझे मिला था। 21 फरवरी को उस डैपूटेशन को एक अफसर के पास भेजा गया। डिमांड्ज़ कन्सरंड डिपार्टमैंटस को भेज दी गई है। वह अंडर एग्जामीनेशन हैं।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : सैंटर में, और कई सूबों में पे कमीशन कायम किए गए हैं। क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि क्या वजह है कि पंजाब में इंप्लाईज की डिमांड के बावजूद पे कमीशन कायम नहीं किया गया ?

मुख्य मन्त्री : उन की डिमांड में यह भी एक डिमांड थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमीशन के पास भेजी थी। उन की रिकमैंडेशन्ज़ जो हैं वह सब अंडर एग्जामीनेशन हैं।

Loss of Crops due to failure of Rains in Naraingarh Sub-Division of District Ambala

***9683. Tikka Jagjit Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that Naraingarh Sub-Division of district Ambala is facing a great crisis of foodgrain shortage due to the failure of rains during Kharif 1965, and Rabi, 1966 ;

(b) the number of villages in the said Sub-Division where loss to the Rabi crop, 1966, has been found to be more than 50 per cent during the special girdawari ordered by the Government ;

(c) the measures taken or proposed to be taken by the Government for giving relief to the people of the said Sub-Division ;

(d) the number and names of villages of the said Sub-Division where the loss to the Kharif, Crop 1965, was found to be more than 50 per cent and the details of the relief given or proposed to be given by the Government to such drought affected villages ?

Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister) : (a) No. There is no crisis of foodgrains shortage in Naraingarh Sub-Division of Ambala District. Scarcity conditions because of severe drought, however, exist.

(b) 334 villages.

(c) (i) Remission of land revenue has been allowed in the drought affected areas on the following scale :—

(a) Where the damage was more than 50 per cent :	Total remission
(b) Where the damage was below 50 per cent but more than 25 per cent	75 per cent remission

(ii) Recovery of taccavi loans has been suspended till Rabi, 1966 in such areas.

(iii) Fair price food-grain depots are functioning in the Sub-Division.

(d) (1) Number and names of villages, where the loss to kharif crop 1965, is more than 50 per cent are as follows :—

(i) Rajpura.
(ii) Serli.
(iii) Rajauli.

(2) Remission of land revenue and suspension of recovery of taccavi loans mentioned against part (c) of the question have been allowed.

टिक्का रणजीत सिंह : वज़ीर साहिब ने बताया है कि तकावी की रिकवरी की सस्पैन्शन कर दी गई है । 334 गांव में बिल्कुल फसल नहीं हुई। 36। के करीब गांव हैं सारी तहसील में, सारी तहसील में एक साल के लिए रिकवरी पोस्टपोन होनी चाहिए थी क्योंकि सारी तहसील में ही फसल नहीं हुई।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know as to how many Fair Price Shops have been started or opened in the Sub-Division ?

Minister : I have no information with me to tell the number.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਅਰ ਪਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Minister : It is a general question, Sir.

चौधरी बालू राम : वज़ीर साहिब ने बताया है कि जहां 50 परसैंट से ज्यादा क्राप फैल्योर हुई है वहां 100 परसैंट लैंड रेविन्यू रिमिशन की है, जहां टोटल क्राप फेल्योर हुई है वहां के लिए क्या किया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਟੋਟਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

Books written by Principal/Professors of Randhir Government College, Kapurthala

***9054. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there are any rules for the recovery of a share of the profits earned by the employees of the Education Department from the sale of books written by them ; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) the profits earned by the Principal and other Professors of the Randhir Government College, Kapurthala, during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 from the sale of Books written by them and the share realised by the Government from each with the dates of realisation in each case ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No.

(b) Profits in the nature of royalty are as under :—

Name of the Principal/ Lecturer	Year 1962-63	Year, 1963-64	Year, 1964-65
1. Dr. A.C. Kapur, Principal	27,503·65	28,659·15	Account not yet rendered to him by the publishers

Name of the Principal/ Lecturer	Year 1963-62	Year 1936-64	Year 1995-65
2. Shri Ujagar Singh, Lecturer in Punjabi	..	300·00	..
3. Shri O.P. Avasthi, Lecturer in Hindi	..	160·00	Rs 160 (Approximately)
4. Shri S.K. Malhotra, Lecturer in Economics	..	..	Rs 300

In view of (a) above the question of Government realising any share out of the royalities does not arise

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : Is the hon. Minister aware of the fact that there is a Rule in the Punjab Civil Service, Rules, according to which 1/3rd share of the royalty has to be recovered by the Government ?

Minister : Whatever the Government is doing, it is doing according to the Rules and no departure has been made in these cases.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੂਲ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

Minister : Sir, I have before me the Rules. I have gone through the whole question and there is no departure from the Rules.

Chaudhri Darshan Singh : Is it a fact that according to the existing Rules, Government is entitled to get a share out of these royalities received by the said employees of the Education Department ?

Minister : Sir, I have already said that whatever the Government is doing is strictly in accordance with the Rules and Government is not competent to realise anything out of the royalities received by the said officials/ Lecturers etc.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਅਗੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि चौधरी लखी सिंह की लिखी हुई किताब का शेयर तो उन से लिया जा रहा है लेकिन इन प्रिंसीपलज़ और प्रोफैसर्ज़ से नहीं लिया जा रहा इस डिसक्रिमीनेशन की क्या वजह है ?

Minister : Sir, I have no knowledge whether Sardar Lakhi Singh has written any book or any share/royalty is being taken by the Government out of the proceeds of his book.

Mr. Speaker : Next question please.

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : On a point of personal explanation.

Mr. Speaker : Not now please. The hon. Member may rise on a point of personal explanation after the question hour.

Government High/Higher Secondary Schools without Headmasters/Staff

***9271. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of the Government High/Higher Secondary Schools in the State, district-wise, which are without Headmasters/staff and which are complete with the sanctioned staff since April, 1965 to date, separately ;

(b) the details of the steps taken by the Government to provide full strength of staff in the newly upgraded Government High/Higher Secondary Schools in the State ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement showing the names of Government High/Higher Secondary Schools, except those located in Jullundur District, which are without Headmasters/staff is laid on the Table of the House. The remaining High/Higher Secondary Schools have completed sanctioned staff. Information in respect of Jullundur District will be supplied later. As regards names of schools which are complete with sanctioned staff the time and labour involved in compiling the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) (i) In most of the districts full staff has been provided in newly upgraded Government High/Higher Secondary Schools.

(ii) The Subordinate Services Selection Board and the Punjab Public Service Commission have been asked to recommend the names of the suitably qualified candidates for making appointments in this school.

(iii) Pending receipts of the recommendations from the recruiting agencies, the Heads of these institutions can make temporary appointments through Employment Exchanges.

(iv) Where Employment Exchanges fail to provide suitable candidates, efforts are made to recruit candidates from the open market.

STATEMENT GIVING NAMES OF GOVERNMENT HIGH/HIGHER SECONDARY SCHOOLS WHICH DO NOT HAVE COMPLETE STAFF AND HEADMASTERS

Amritsar District

Nil

Ferozepore District

Government High School ,Bhime Shah.
Government High School, Maujgarh.

Gurdaspur District

Government High School, Baimial.
Government Co-Education High School, Kalanaur.
Government High School, Badhani.
Government Girls High School, Dera Baba Nanak.
Government High School, Harpu Dhandoi.

Hoshiarpur District

Government Girls High School, Una.
Government High School, Ambota.
Government High School, Saloh.

Note : For further information regarding Starred Question No. 927, please see Appendix to this Debate.

Government High School, Suraya.
Government High School, Nangal Township.
Government High School, Santokhgarh.

Kangra District

Government Higher Secondary School, Hamirpur.
Government Higher Secondary School, Behr.
Government Higher Secondary School, Galore.
Government Higher Secondary School, Lathiani.
Government Higher Secondary School, Sunhi.
Government Higher Secondary School, Nadaun.
Government Higher Secondary School, Bagwara.
Government Higher Secondary School, Garh Jumla.
Government Higher Secondary School, Rehn.
Government Higher Secondary School, Jalag.
Government Higher Secondary School, Balkrupi.
Government Higher Secondary School, Bhalana.
Government Higher Secondary School, Baroh.
Government Higher Secondary School, Nagrota Bagwan.
Government Girls Higher Secondary School, Chadhiar.
Government Girls Higher Secondary School, Garli.
Government Girls Higher Secondary School, Dhugiari.
Government High School, Gander.
Government High School, Sari Molag.
Government High School, Lamba Gaon.
Government High School, Rakkar.
Government High School, Dhameta.
Government High School, Bani.
Government High School, Mair.
Government High School, Baijhari.
Government High School, Karoa.
Government High School, Khamroor.
Government High School, Baddle Thore.
Government High School, Rajhoon.
Government High School, Ranital.
Government High School, Matli.
Government High School, Mundkher.
Government High School, Ladraur.
Government High School, Rail.
Government High School, Shahpur.
Government High School, Gangath.
Government High School, Choki Maniar.
Government High School, Krishan Nagar.
Government High School, Khera.
Government High School, Patlander.
Government High School, Takauli.
Government High School, Bhadwar.
Government High School, Re.
Government High School, Mandli.
Government High School, Bathu Tippri.
Government High School, Khudian.
Government High School Kakkar.
Government Girls High School, Nadaun.

Kapurthala District

Government Higher Secondary School, Dhilwan.
Government Higher Secondary School, Hadiabad.
Government Higher Secondary School, Kapurthala.
Government Girls Higher Secondary School, Kapurthala.
Government Girls Higher Secondary School, Dialpur.
Government Girls Higher Secondary School, Phagwara.
Government High School, Ramidi.
Government Girls High School, Sultanpur.
Government High School, Dalla.
Government High School, Surakhpur.
Government High School, Nadla.
Government High School Sidhwan.

Education of Minister]

Kulu District

Nil

Ludhiana District

Nil

Bhatinda District

Government Higher Secondary School, Chauke.
Government Higher Secondary School, Kalayan Sukha.
Government Higher Secondary School, Bhaini Bagha.
Government Higher Secondary School, Hari Nau.
Government Higher Secondary School, Kuti.
Government Higher Secondary School, Jhunir.
Government Higher Secondary School, Budlada.
Government Higher Secondary School, Kot Fatta.
Government Higher Secondary School, Matta.
Government Higher Secondary School, Mehma Sarja.
Government Higher Secondary School, Phaphare Bhai Ke.
Government Higher Secondary School, Chughe Kalan.
Government Higher Secondary School, Sardulgarh.
Government Higher Secondary School, Bajakhana.
Government Higher Secondary School, Mathana.

Mohindergarh District

Government High School, Kanina.
Government High School, Kanti.
Government High School, Chirya.

Government High School, Berla,
Government High School, Nizampur.
Government High School, Bhojewa.
Government High School, Bhungarkha.
Government Higher Secondary School, Ranila
Government Higher Secondary School, Mohindergarh.
Government Higher Secondary School, Madohgarh.
Government Higher Secondary School, Jatnali.
Government Higher Secondary School, Charkhi Dadri.
Government Higher Secondary School, Dalanwas.
Government Girls High School, Kanina.

Patiala District

Government Higher Secondary School, Bassi Pathana.
Government Higher Secondary School, Gobindgarh.
Government Girls Higher Secondary School, Gobindgarh.
Government High School, Tarkheri.
Government High School, Tephla.
Government High School, Dialpur
Government Girls High School, Samana.

Sangrur District

Government Girls Higher Secondary School, Lehra Gagga.
Government High School, Bibipur.
Government High School, Tigana.

Ambala District

Government High School, Barwala.
Government High School, Korwa Khurd.
Government High School, Ram Shahr.
Government Co-Education High School, Kharwan.

Gurgaon District

Government Higher Secondary School, Punhana.
Government Higher Secondary School, Anangpur.
Government Higher Secondary School, Bahin.
Government Higher Secondary School, Kund.
Government Higher Secondary School, Aurangabad.
Government Higher Secondary School, Sherpur.
Government Higher Secondary School, Kauru.
Government Higher Secondary School, Nagina.
Government Higher Secondary School, Faridabad N.T.
Government Higher Secondary School, Hali Mandi.
Government High School, Kurthala.
Government High School, Ujina.
Government High School, Wazirabad.
Government High School, Bajidpur.
Government High School, Ferozepore Jhirka.
Government High School, Dundahera.
Government High School, Khandevla.
Government High School, Sondhadh.
Government High School, Kaurali.
Government High School, Banchari.
Government High School, Daultabad.

Hissar District

Government High School, Jamal,
Government High School, Nuhianwali.
Government High School, Kharian.
Government High School, Kharak Punian.
Government High School, Kungar.
Government High School, Chumar Khera.
Government High School, Sisar Kharbala.
Government High School, Puthi Saman.
Government High School, Deorala.
Government High School, Dhani Mahu.

Karnal District

Government Higher Secondary School, Atta.
Government Higher Secondary School, Balla.
Government Higher Secondary School, Naguran.
Government Higher Secondary School, Sewan.
Government Girls Higher Secondary School, Kaithal.
Government High School, Kathana.
Government High School, Chatter.
Government High School, Nabri.
Government High School, Jakhauli.
Government High School, Kurana.
Government High School, Chamrori.
Government High School, Mowna.
Government High School, Salwan.
Government High School, Arainpur.
Government High School, Babain.
Government High School, Bapauli.
Government High School, Jundla.
Government High School, Kheri Naru.
Government High School, Rasina.
Government High School, Yara.
Government High School, Urlala Kalan.
Government High School, Gangat Heri Popran
Government High School, Karmla.
Government High School, Kunjpura.
Government High School, Sanch.
Government High School, Katlaheri.

Rohtak District

Government High School, Birohar.

[Education Minister]

Government Higher Secondary School, Bhali Anandpur.
Government Higher Secondary School, Bega.
Government High School, Bhawar.
Government High School, Berhana.
Government High School, Bhalaut.
Government High School, Chhana.
Government High School, Chulkana.
Government High School, Dunjana.
Government High School, Deepalpur.
Government High School, Farmana (M).
Government High School, Gorar.
Government High School, Ismaila.
Government High School, Jogsi.
Government High School, Jaswar Kheri.
Government High School, Khanpur Kalan.
Government High School, Kharkhauda.
Government High School, Kharakra.
Government High School, Kosli.
Government High School, Ladain.
Government High School, Meham.
Government High School, Machhrauli.
Government High School, Purkhas.
Government High School, Pinana.
Government High School, Ritauli.
Government High School, Rajlu Garahi.
Government High School, Subana.
Government High School, Silani.
Government High School, Talao.
Government Higher Secondary School, Badli.
Government Higher Secondary School, Bahu Jholri.
Government Higher Secondary School, Jhajjar.
Government High Secondary School, Jehazgarh.
Government Higher Secondary School, Murthal.
Government Higher Secondary School, Rohtak.

Simla District

Government Higher Secondary School, Simla.
Government Higher Secondary School, Portmore Simla (Girls.)
Government Higher Secondary School, Kandaghat.
Government Higher Secondary School, Sabathu (Girls).
Government High School, Cha il.
Government High School Chamian.
Government High School, Dagshai.
Government High School, Dharampur.
Government High School, Khalag.
Government High School' Kasauli.
Government High School, Mamligh.
Government High School. Shoghi.

श्री अमर सिंह : यह जो लिस्ट हाउस की टेबल पर रखी गई है जिस में उन हाई और हायर सैकंड्री स्कूलों के नाम दिए गए हैं जिन मे हैड मास्टर्ज़ नहीं हैं उससे से साफ ज़ाहर होता है कि पंजाबी रिजन के तकरीबन तमाम हाई और हायर सैकंड्री स्कूलों में हैडमास्टर्ज़ भेजे हुए हैं लेकिन हिन्दी रिजन में कांगड़ा, महेन्द्रगढ़ वगैरा सारे ज़िलों में भारी तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहां पर हैडमास्टर्ज़ नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाबी के मुकाबले मे हिन्दी रिजन के साथ इम्तयाज़ी सलूक क्यों किया जा रहा है ?

मन्त्री : पंजाबी रिजन के बहुत सारे ज़िले ऐजुकेशनली ऐडवांसड हैं और वहां ट्रेंड स्टाफ की कमी नहीं है लेकिन कांगड़ा, महिन्द्रगढ़ के ज़िले ऐजुकेशनली उतने आगे नहीं हैं

इस लिये वहां ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल पा रहा है । अब नए जे.बी.टी. स्कूल खोलने की वजह से उमीद है दो तीन साल में यह कमी पूरी हो जाएगी।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : वज़ीर साहिब ने फरमाया कि पंजाबी रिजन में ट्रेंड टीचर्ज़ की कमी नहीं है। जब तमाम स्टेट की सर्विसिज़ एक हैं तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या लाज़मी नहीं था कि यहां से टीचर्ज़ ट्रांस्फर करके वहां की कमी को पूरा करते ? आयंदा के लिए क्या वह फरमाएंगे कि इस तरह से जहां शारटेज है उसे पूरा किया जाएगा ?

मन्त्री : हमारी कोशिशों के बावजूद टीचर्ज़ कांगड़ा, महिन्द्रगढ़ वगैरा के ज़िलों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस लिए हम ने जो टीचर्ज़ वहां जाएंगे उन के लिए कुछ खास कनसैशन भी दिए हैं और कम्बीनेशन आफ सबजैक्टस की बात भी हटा दी है। पिछले चार साल में आप देखें कि 50 फीसदी से ज्यादा कमी पूरी हो गई है । Within the next two three years the whole of the deficiency will be removed.

श्री अमर सिंह : जिन गांवों के लोगों ने 28/29 हज़ार रुपया जमा कराया हुआ है और एक साल हो गया वहां कोई स्टाफ नहीं पहुंचा क्या उन लोगों की तसल्ली के लिए जल्दी स्टाफ भेजने की कोशिश करेंगे ?

मन्त्री : जनाबेआली, it is too wide an insinuation कि वहां कोई स्टाफ नहीं पहुंचा है। ऐसी बात नहीं है, हर स्कूल में कुछ न कुछ स्टाफ पहुंचा है। कुछ कमी है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । इस के लिए यह हिदायत भी कर दी है कि अगर कमीशन और सुबार्डीनेट सरविसज़ बोर्ड से आदमी नहीं मिलते हैं तो 6 महीने के लिए अगर लोकल आदमी मिलते हों चाहे वह जे.बी.टी. न भी हों उन को ले लिया जाए ताकि कुछ न कुछ काम चले।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या यह बात वज़ीर साहिब के नोटिस में आई है कि जहां हैडमास्टर्ज़ नहीं हैं वहां टीचर्ज़ को तन्खाह लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है और छ: छ: महीने तक उन्हें तन्खाह नहीं मिलती है ?

मन्त्री : मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि किसी को छ: महीने तक तन्खाह न मिलती हो। अगर मैंबर साहिब ऐसा कोई वाक्या नोटिस में लाएंगे तो देख लेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਰਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਗਰੇਡ ਕੁਝ ਘਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ only left over come in the Education Department, ਗਰੇਡਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Mr. Speaker: Next question by Chaudhri Inder Singh Malik.

Pandit Chiranji Lal Sharma: This is a very important question. I would request that some more supplementaries may kindly be permitted.

Mr. Speaker: I have called the next question.

Seniority of Naib-Tehsildars

***9454. Chaudhri Inder Singh Malik:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether a joint Seniority list of the Naib-Tehsildars of Punjab was compiled and provisionally approved by the Union Government in the month of November, 1965; if so, the reasons for not implementing the same?

Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister) : A tentative joint seniority list of Naib-Tahsildars of all the three Divisions was prepared, with the approval of the Government of India, as required under sub-section (7) of section 115 of the States Reorganisation Act. There is no provision in the Punjab Tehsildari Rules for bringing of the seniority of Naib-Tahsildars/Naib-Tahsildar candidates at State level. The said list will, therefore, be finalised after necessary provision has been made in the said Rules.

10.00 a.m.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि पैप्सू के जो नायब तहसीलदार पंजाब के दूसरी डवीजन में तहसीलदार बन कर गए क्या उन्हें रिवर्ट करके वापिस पटियाला डिवीजन में भेजा जा रहा है ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੇਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।

Chaudhri Inder Singh Malik: But they are senior.

Minister: They may be senior *vis-a-vis* Naib-Tehsildars of other divisions. But their seniority will be determined according to the rules applicable to them till these are amended. When the rules are ultimately amended which we propose to that there should be one cadre throughout the State they will be fixed at proper place. But at present their cadre is division-wise.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब गवर्नमैंट आफ इंडिया से नायब तहसीलदारों की जायंट सीनियारिटी लिस्ट बनाने की मंजूरी ली जा चुकी है तो उस चीज़ को क्यों इम्पलीमैंट नहीं किया जा रहा ?

ਮੰਤਰੀ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ । ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਰੂਲਜ਼ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਐਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

They are with the Legal Remembrancer who is vetting them and after that the needful will be done.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Minister for Planning if it is a fact that Naib-Tehsildars and Tehsildars of one Division are still posted in other divisions against the directive of the Government?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । Government has power to shift the Tehsildars ਮਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਡਿਵੀਯਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੂਲਜ਼ ਕਦੋਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਡੀਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਲਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਲ॰ ਆਰ॰ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत पहुंची है कि दूसरी डिवीज़न के जूनियर तहसीलदार या नायब तहसीलदार को अम्बाला डिवीज़न में प्रोमोट करके लगाया गया था और इस अम्बाला डिवीज़न के कर्मचारी को नुक्सान हुआ । सरकार ने उस शिकायत पर क्या ऐक्शन लिया ?

ਮੰਤਰੀ ; ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਫਨਿਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਵੇਨਿਉ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि पटियाला डिवीज़न रैवेन्यू ऐक्ट के तहत पंजाब के अन्दर नहीं है । क्या पैप्सू डिवीज़न के नायब तहसीलदारों के साथ डिस्क्रीमीनेटरी सलूक किया जा रहा है । और पैप्सू के नायब तहसीलदारों को रिवर्ट किया जा रहा है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Minister for Planning if it is a fact that the present Revenue Minister had issued a directive to the effect that Naib-Tehsildars and Tehsildars of one division should not be posted in other divisions and if at all they have been posted they should come back and the orders were not implemented?

Minister: I require notice about it.

Mr. Speaker: Next question.

Evacuee land along the Sutlej Bet Area

*9804. **Comrade Bhan Singh Bhaura:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government has issued any order for the suspension of auctioning of the evacuee land along the Sutlej Bet Area;

(b) if the answer to part (a) be in the affirmative, the total acreage of land covered by the said Scheme, and the reasons for suspending the auctioning?

Sardar Ajmer Singh (Minister for Planning and Local Government): (a) Yes.

(b) Roughly 110,000 acres. As the lands were to be acquired by the Irrigation Department (now the Agriculture Department) for reclamation, the auctions were suspended.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मेरे एक सवाल के जवाब में आया कि there is no Patiala Division in the Punjab under the Revenue Act. मैं पूछना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष : जब नैक्सट सवाल काल अपोन कर दिया जाए और मिनिस्टर साहिब ने उसका जवाब दे दिया हो पिछले सावल के बारे में प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। Please take your seat. (No point of order is allowed on a previous question when the next question has been called and answered by the hon. Minister. The hon. Member may please take his seat.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਪੁਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਫਲੀ 1,10,000 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਟੇਜ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ this will create difficulties ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਉਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਵੈਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आडर, सर। अभी अभी प्लानिंग मिनिस्टर साहिब ने आनरेबल मेम्बर के सवाल के जवाब में फरमाया है कि इस का ज़िक्र तो पहले कई बार आ चुका है। मैं आप का रूलिंग इस सम्बन्ध में चाहता हूं कि अगर कोई आनरेबल मेम्बर कोई इनफर्मेशन चाहता है तो क्या कोई मिनिस्टर यह बात कह कर टाल सकता है कि यह तो पहले भी कई बार हाउस में बात डिस्कस हो चुकी है?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उसी का हिस्सा है। (The hon. Minister has stated that it forms part of that scheme.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟ-ਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅੰਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨਸੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

श्री अमर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वही ज़मीन है जिस के बारे में 1963 में फाइनैंस मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि हरिजन टैनैंटस को और लैंडलैस टैंनेटस को दी जाएगी ?

मन्त्री : मेरे पास वह इनफर्मेशन नहीं है। आई रीक्वायर नोटिस अबाउट इट ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਲਲੀਗਲੀ ਅਤੇ ਇਰ-ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

चौधरी नेत राम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सतलुज बेट एरिया की ज़मीन रीक्लेम की है, इस लिये की है कि जो मुज़ारे पंजाब के उजड़े हैं उन को तीस रुपया फी एकड़ के हिसाब से दी जाएगी जैसे बिरला ब्रादर्स को दी गई थीं या कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जाएगी ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਲੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਤੇ ਇਲਲੀਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

Mr. Speaker : It is no point of order.

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰੀਟੀ ਕਿਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕਿਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਿਲੀਟੀ ਕਿਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ then I will find out and the needful will be done.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या यह सही बात है कि सतलुज बेट एरिया में से किसी मिनिस्टर ने भी एक हज़ार एकड़ ज़मीन ली है ?

श्री अध्यक्ष : दिस इज़ नो प्वायंट आफ आर्डर (This is no point of order.)

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या योजना मंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि आया यह अमर वाक्या नहीं है कि तहसील ऊना में बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहां पर कल्टीवेटिड एरियाज़ डेढ सौ एकड़ से बहुत ज़्यादा है ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ on the whole ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਲ ਲੈਂਡ ਓਨਰਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 150 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ 150 ਏਕੜ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਘਟ

ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜਿਥੇ 150 ਤੋਂ 300 ਏਕੜ ਤਕ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ 5 ਏਕੜ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ 300 ਤੋਂ 500 ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ 10 ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਹਿਟ ਹਾਰਡ।

पंडित मोहन लाल दत्त : जो पिछड़े हुए इलाके हैं और बेहद्द ज़मीन वहां पर कम है लेकिन जंगलात का एरिया बहुत ज्यादा है क्या गवर्नमैंट ने ऐसा कोई असूल नहीं बनाया कि पंचायतों को आमदनी देने के लिये कंसालीडेशन के वक्त बंजर ज़मीन का हिस्सा उन को दे दिया जाए ?

Minister: It is too late in the day to talk about it because the consolidation operations are practically on the verge of completion and the re-opening of this issue will upset the whole thing. Even in some 'A' class Tehsils of plains where the consolidation operations were started in earlier stages no land has been reserved for panchayats and we are not going to re-open the whole issue to reserve land for the panchayats there.

———

Reservation of land for Panchayats during Consolidation Operations

***9049. Pandit Mohan Lal Datta:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that no land was reserved for the panchayats as a source of income in the course of consolidation operations in the villages of tahsil Una; if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that lands are so reserved for the panchayats during the course of consolidation operations in the plains;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons for the difference?

Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister) : (a) Yes. Government took a decision that no reservation of land for village Panchayats should be made in Una Tahsil of Hoshiarpur District.

(b) Yes.

(c) According to Government policy, reservation of land for Panchayats in the plains is to be made on the cultivated area in a village if the cultivated area exceeds 150 acres. The cultivated area in most of the villages of Una Tahsil is very small and as such it was decided that no such reservation of land for panchayats need be made in Una Tahsil.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि तहसील ऊना के बहुत से गांव में अभी तक कन्सालीडेशन होनी है और उन गांव में बेशुमार जंगलात हैं और क्या जब वहां पर कन्सालीडेशन की जाएगी तो उन जंगलात का कुछ रकबा पंचायतों को दिया जाएगा ताकि वह डिवैलपमेंट के साधन पैदा कर सकें ? क्या गवर्नमैंट ऐसा करने के लिए तैयार है ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਵਿਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Assessment of surplus area in village Ramgarh Dhani and others

***8968. Comrade Ram Piara:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the lands belonging to Sardarni Pavitar Kaur and Sardarni Pritam Kaur, widows of late Sardar Mukand Singh, situated in village Ramgarh Dhani and in other villages, which collectively were under the superintendence of the Court of Wards, have been assessed or are being assessed for surplus area by the staff engaged for the purpose; if so, the date when the work of assessment was started together with the date when it was finalised;

(b) if the said lands have been assessed for surplus area, the extent of the surplus in each village;

(c) whether the Government intend to rehabilitate those tenants who were in possession of these lands for more than ten years, but who had been ejected for one reason or another; if so, the approximate time by which they are likely to be rehabilitated;

(d) whether the area or any part thereof which has been declared as surplus has since been utlized; if so, when; if not, the reasons for the same;

(e) the total area which has been left with the widows mentioned in part (a) above as their reserved area together with the names of villages were such areas have been reserved;

(f) if the said lands have not been assessed for surplus area, the reasons therefor;

(g) the names of those villages in district Sangrur in which the work of assessment of surplus area could not be started till the 6th July, 1964, and of those where the work of assessment of surplus areas has not been finished till today together with the reasons, if any, therefor?

Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister): the information is laid on the Table of the House.

(a) Assessment of surplus area started on 27th June, 1958 and ended on 9th April, 1965

(b) Area declared surplus in each village is given below—

District	Name of the village		Area declared surplus	
			S.As.	Units
Sangrur	Jind		21	00
	Kar Heri	..	10	6
	Gunkali	..	554	65
	Ramgarh Dhani		391	39
Bhatinda	Ramtirath Jagga		102	15
	Total	..	1,079	25

(c) Some of the ejected tenants have filed cases in Courts for the restoration of their possession and as such, it is regretted that a time-limit by which old tenants will be resettled cannot be fixed.

(d) Area declared surplus has not been utilised due to the stay orders issued by the appellate authorities.

(e) Village		Area	
		S.As.	Units
(1) Sangrur	..	39	12
(2) Ramtirath Jagga (district Bhatinda)	..	20	88
Total	..	60	00

(f) In view of reply to part (b) above, question does not arise.

(g) (i) Statement I giving the list of villages in which assessment of surplus area was not started till 6th July, 1964, is laid on the Table of the House.

(ii) Statement II giving the list of villages where assessment has not been finished so far is also laid on the Table of the House.

(iii) Reasons for pending work:—

(1) Late detection.

(2) Remanded by appellate authorities and Punjab High Court, etc.

Statement No. 1 giving the list of villages in Sangrur District in which assessment of surplus area was not started till 6th July, 1964

S. No.	Name of village	S. No.	Name of Village
1	Abdullapur	37	Chandu Rain
2	Ahmedpur	38	Changli
3	AlbelaPura	39	Dehlize Kalan
4	Amir Nagar	40	Delawargarh
5	Adampaul	41	Dallanwala
6	Attaulpur	42	Dugri
7	Abbaspura	43	Dhiro Majra
8	Ahmedabad	44	Daulowal
9	Brarwal	45	Dhadewari
10	Budra Heri	46	Didargarh
11	Burj Seda	47	Dhura
12	Banganwali	48	Dhuri
13	Belewal	49	Dohla
14	Belewal	50	Faridpur
15	Bhikam Pur	51	Pharwahi
16	Baur Hai	52	Pharwahi
17	Battian	53	Faizgarh
18	Bir Amamgarh	54	Gajjan Majra
19	Badechhe	55	Giga Majra
20	Battan	56	Ghauns Pura
21	Bhulran	57	Ghanauri Khurd
22	Bhation Kalan	58	Hussainpura
23	Bhari Mansa	59	Hakimpura
24	Bazeed Garh	60	Hasanpur
25	Bukkanwala	61	Ibrahimpura
26	Bir Sherwani Kot	62	Ilatfatpura
27	Bahadurgarh	63	Ikthiarpura
28	Bhagwan Pura	64	Issi
29	Barri	65	Issapur
30	Balabgarh	66	Jati Majra
31	Bhasaur	67	Jitwal Khurd
32	Banbhauri	68	Jandali Kalan
33	Bir Ahmedabad	69	Jatiwal
34	Bhaini Kamboon	70	Jattuan
35	Chupka	71	Jagowal
36	Chokran	72	Jafrabad

[Planning and Local Government Minister]

S. No.	Name of the villages	S. No.	Name of the village
		102	Rampur-Chhana
73	Jamalpura	103	Ratolan
74	Kasampur	104	Rurke
75	Kelon	105	Rehmat Garh
76	Kuram	106	Rami Ke
77	Kishangarh	107	Ruldu Singh Wala
78	Kheri Khurd	108	Ramgarh
79	Khurd	109	Rurgarh
80	Kaler	110	Shergarh
81	Kheri Jattan	111	Sampurangarh
82	Laddewal	112	Sheikhu Purkhurd
83	Momanabad	113	Sheikhu Purkalan
84	Moola Badha	114	Shadatpur
85	Mohala	115	Sarwarpur
86	Mohali	116	Sadra Bad
87	Mahboobpura	117	Shikakpur Sanghan
88	Mohmad Nagar	118	Salempur
89	Mehmudabad	119	Sherpur
90	Maloo Majra	120	Tibha
91	Mangewal	121	Thuliwal
92	Mahdevi	122	Thulewal
93	Mir Heri	123	Patti Khalil
94	Nangal	124	Walaitpura
95	Nathu Majra	125	Bhurthala Mander
96	Natho Heri	126	Josoi
97	Nangal	127	Hazoorgarh
98	Phalaund Kalan	128	Mandi Ahmedgarh
99	Rurki Kalan	129	Moranwali
100	Rurki Khurd	130	Kar Heri
101	Raipur	131	Sangrur

Statement II giving the list of villages in Sangrur District where assessment has not been furnished so far

S. No.	Name of Villages	S. No.	Name of the villages
1	Amar Garh	22	Monik Heri
2	Alal	23	Mubarikpur
3	Batuka	24	Gowara
4	Burj Gohra	25	Kakarwal
5	Ferozepur	26	Mohmadpura
6	Ghanauri Kalan	27	Badla
7	Lahat Buddi	28	Bhoodan
8	Bagrian	29	Kanganpur
9	Gobindpura	30	Naudharani
10	Killa Hakima	31	Moharana
11	Badshahpur	32	Kanghli
12	Bhagowali	33	Kurar
13	Bhaini Kalan	34	Attar Garh
14	Sakendepura	35	Alike
15	Saraud	36	Bazidke Khurd
16	Wazirpur	37	Sanghera
17	Ghanaur Khurd	38	Dailwan Patiala
18	Himtana	39	Pakhoke
19	Kalian	40	Daggahr
20	Kheri Sodhian	41	Mauran Nabha
21	Ranwan	42	Kaleke

S. No.	Name of the villages	S. No.	Name of the villoges
43	Gobindgarh	53	Longowal
44	Daraj	54	Dharamgarh
45	Kaleke	55	Dhanouri
46	Karamgarh	56	Mahlan
47	Dasaunda Singh Wala	57	Gobindpura
48	Bhadaur	58	Shahr
49	Gadriani	59	Lehragaga
50	Mander Kalan	60	Chural Kalan
51	Khokhar	61	Lehal Kalan
52	Basi Arkh	62	Ram Nagar Sibian

कामरेड राम प्यारा: क्या प्लैनिंग मिनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि रामगड़ धानी और गुनकली की जमीन की यह असैस्मैंट जो 27 जून 1958 को शुरू हो कर 9 अप्रैल, 1965 को खत्म हुई इस पर सात साल लग जाने के क्या कारण हैं और क्या कोई ऐसा और भी केस सारे पंजाब के अन्दर है ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । 60-60 ਏਕੜ ਦੋਹਾਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰਪਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । After this litigation is over, the land will be allotted to the tenants.

कामरेड राम प्यारा: क्या प्लनिंग मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि अब 1,079 एकड़ सरप्लस निकल चुका है, क्या इस सम्बन्ध में मैं यह पूछ सकता हूं कि इस में से कुछ जमीन मुज़ारों से खाली करवा कर गवर्नमेंट की मार्फत हरिजनों को बेच भी दी गई है जिसका ज़िक्र दास कमिशन के सामने भी आया था ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੀ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਘ : ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 131 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਜੁਲਾਈ, 1964 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

Minister : I need notice.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक: प्लैनिंग मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि कुछ जमीन हरिजनों को दी गई थी। अब जो दूसरे टैनेंट्स इजैक्ट किए गए थे उन्होंने प्रीराईट्स के दावे अदालतों में कर दिए हैं कि उन को दुबारा जमीनों पर बसाया जाए । इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि गवनमेंट की क्या पोज़ीशन है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 131 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ, 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

The hon. Minister for Planning and Local Government has said that he requires notice. Part (g) of the question clearly asks the names of those villages in District Sangrur in which the work of assessment of surplus area could not be started till the 6th of July, 1964. So, the question has already been asked. What for a separate notice is required by the hon. Minister ?

ਮੰਤਰੀ : ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ।

कामरेड राम प्यारा : पार्ट जी के जवाब में अनैक्शर II में उन 62 गांव के नाम दिए गए हैं जहां पर को सरपलस एरिया की असैंसमैंट का काम अभी शुरु नहीं हुआ। क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर सरपलस एरिया की असैस्मैंट का काम न शुरु करने के क्या कारण हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। I can not say about the reasons.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਔਰ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਈਲਡ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

कामरेड राम प्यारा: वज़ीर साहिब ने पार्ट "डी" के जवाब में बताया है कि स्टे आर्डज़ किए गए थे। क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि यह स्टे आर्डज़ कब गवर्नमैंट के पास आए और जब उसे डिक्लेअर हुए इतना अर्सा हो चुका है तो वह ज़मीन अभी तक यूटीलाईज़ क्यों नहीं की गई ?

ਮੰਤਰੀ : ਡੇਟਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ !

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : वज़ीर साहिब ने बताया है कि इस ज़मीन पर टैनेंट्स को दुबारा बसाने के लिए सारी चीज़ अंडर कन्सिडरेशन है। मैं उन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि उन टैनेंट्स ने अदालतों के अन्दर प्री-राईट्स के दावे दायर किए हुए हैं और लैंड लार्डज़ ने प्री-राईट्स न मानने के जवाबी दावे दायर किए हुए हैं। क्या वह बताएंगे कि उन के केसिज़ का फैसला होने का क्या असर पड़ेगा ?

Minister : This is hypothetical.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि पार्ट 'जी' के जवाब में इन्होंने जो अनैक्शर II में 62 गांव की लिस्ट दी है जिन की बाबत यह बताया है कि वहां पर सरपलस की असैस्मैंट शुरू नहीं की। क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह हकीकत नहीं है कि इस के पीछे एक दो ऐसे तकड़े ज़मींदार हैं जिन की बात मिनिस्टर मानते हैं और आम तौर पर जिन के पास जा कर वह ठहरते हैं, इसी वजह से उन गांवों में सरपलस एरिया की असैस्मैंट का काम शुरू नहीं किया गया ?

Recall of an Officer of Education Department at present on deputation to the Kurukshetra University

*9797. **Pandit Chiranji Lal Sharma** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether he has received any communication from the Vice-Chancellor, Kurukshetra University, suggesting that Dr. J.D. Verma, lent to the said University by the Punjab Government on deputation for five years should be recalled ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the steps, if any taken by him to recall the said officer ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) The matter is under consideration of Government.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the hon. Minister for Education as to when were the services of this Professor lent to the Kuru-Kshetra University ?

Minister : About three years back or a little more than three years back, his services were lent to the University for five years. The period was to expire by the end of 1967.

Pandit Chiranji Lal Sharma : The hon. Minister for Education has said that the matter is under consideration. Sir, may I know as to who is the final authority to take a decision in this respect?

Minister : The Punjab Government is the final authority to take a decision.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, how long will the Government take to decide the matter finally ?

Minister : This is a University affair. The officer whose services were lent to the University is on the cadre of the education Department of the State Government. His services were lent to the University for five years. The present Vice-Chancellor has come forth with the request that his services my be taken back.

Mr. Speaker : Question hour is over now.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, will supplementary questions continue?

Mr. Speaker : The hon, Member has already put so many supplementary questions.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I request that more supplementary questions may be allowed.

Mr. Speaker : All right, supplemetary questions will continue.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Free X-Ray and other facilities for Patients in Government Hospitals

***8941. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) the minimum income prescribed by Government which entitles a patient for free- X-Ray facilities or for free Blood, Urine or Sputum test in a Government Hospital together with the date when this minimum income limit was fixed ;

(b) whether the said minimum income limit varies from place to place ; if so, the details thereof ?

Shrimati Om Prabha Jain : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) The income limit varies only in respect of X-Ray and not in other cases.

Statement containing information to part(a)

I No X-Ray charges are levied from persons whose income is below Rs 150 per mensem attending Punjab Government Hospitals in the State except V. J. Hospital, Amritsar, Rajindra Hospital Patiala, Medical College, Rohtak and Post-Graduate Institute, Chandigarh while free X-Ray facilities are provided to patients at these specialised institutions having income not exceeding Rs 30 per mensem.

II. As regards blood, urine or sputum tests, no charges are levied for these tests from the patients attending the out-patients department of the Hospital irrespective of income groups while charges are recovered from patients admitted in paying wards with income above Rs 149.

III. So far as the date for charging the X-Ray fees etc., in the hospitals, other than the medical institutions and Post-Graduate Institute, Chandigarh is concerned, no exact date is available as these rates were fixed before partition. As regards the date for fixing the rates of X-Ray facilities in the medical Institutions, these were fixed in 1949 and the same rates have been applied in Post-Graduate Institute from the date of its functioning. The rates for blood, urine and sputum were fixed before partition and the exact date is not available.

High and Higher Secondary Schools in district Karnal

***9252. Shrimati Parsanni Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of High and Higher Secondary Schools in District Karnal at present and names of Headmasters/Principals posted in the said schools with their grade of pay and the present pay of each ?

Shri Prabodh Chandra : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

List of Headmasters/Headmistresses/Principals of High/Higher Secondary Schools in Karnal District indicating their Grade and Present Pay

Serial No.	Name of the School	Name of the Principal/ Headmaster/Headmistress	Scale of pay	Present Pay
		Sarvshri—	Rs.	Rs.
1	Government Higher Secondary School, Atta	Shridutta Lakhanpal, P.E.S.	250—750	250
2	Government Higher Secondary School, Balla	Ram Sarcop Gupta, P.E.S.	250—750	375

Serial No.	Name of the School	Name of the Principal/ Headmaster/Headmistress	Scale of pay	Present pay
		Sarvshri—	Rs.	Rs.
3	Government Higher Secondary School, Gharaunda	Dalip Chand Sachdeva, P.E.S.	250—750	250
4	Government Higher Secondary School, Israna	Chanan Singh Allakh, P.E.S.	250—750	250
5	Government Higher Secondary School, Kaithal	Tarlochan Singh, P.E.S.	250—750	250
6	Government Higher Secondary School, Kunjpura	Vidya Sagar Passi, P.E.S.	250—750	375
7	Government Higher Secondary School, Karnal	Manohar Lal Gambhir, P.E.S.	250—750	250
8	Government Higher Secondary School, Kurukshetra	Inderjit Singh Jindha, P.E.S.	250—750	325
9	Government Higher Secondary School, Nilokheri	Gian Sarup Sharma, P.E.S.	250—750	250
10	Government Higher Secondary School, Naguran	Inder Sain Ghai, P.E.S.	250—750	250
11	Government Higher Secondary School, Sewala	Sunder Shyam, P.E.S.	250—750	250
12	Government Higher Secondary School, Samalkha	Dharam Singh, P.E.S.	250—750	250
13	Government Higher Secondary School, Shahabad	Presm Parkash, P.E.S.	250—750	250
14	Government Higher Secondary School, Sewan	Mrs. Passy, P.E.S.	250—750	425
15	Government Girls Higher Secondary School, Karnal	Mrs. M.Jogi, P.E.S.	250—750	425
16	Government Girls Higher Secondary School, Kaithal	Miss Satya Thakar, P.E.S.	250—750	425
17	Government Girls Higher Secondary School, Pehowa	Mrs. Usha Taneja, P.E.S.	250—750	425
18	Government Girls Higher Secondary School, Panipat	Mrs. Leela Wati Malhotra	250—750	425
19	Normal School, Karnal ..	Dewan Singh, P.E.S.	250—750	400
20	Government Girls Higher Secondary School, Fatehpur	Miss Raj Mehta	250—350	300
21	Government High School, Adyana	Teerath Ram Dhoop	250—350	300
22	Government High School, Alwa	Ashwani Kumar	250—350	300
23	Government High School, Assandh	H. K. Khanna	250—350	300

[Education Minister]

Serial No.	Name of the School	Name of the Principal/ Headmaster/Headmistress	Scale of pay	Present pay
		Sarvshri—	Rs	Rs
24	Government High School, Biana	Isher Dass	250—350	310
25	Government High School, Buwana Lakhu	Punna Ram Sharma	250—350	310
26	Government High School, Chatter	Ved Parkash	250—350	290
27	Government High School, Chika	Ram Kishan	250—350	310
28	Government High School Gagsiana ..	Punjab Rattan	250—350	310
29	Government High School, Gulyana	Lok Nath	250—350	310
30	Government High School, Habri	Charan Singh Sindhu	250—350	310
31	Government High School, Jaurasi	Preet Singh	250—350	310
32	Government High School, Katlaheri	Vacant	250—350	—
33	Government High School, Kirmach	Mangat Ram Sharma	250—350	290
34	Government High School, Kaimla	Teja Singh	250—350	310
35	Government High School, Kalkha	Ram Lal Gomer	250—350	310
36	Government High School, Prem Nagar, Karnal	Mrs. M. S. Gambhir	250—350	300
37	Government High School, Karora	Om Parkash Aggarwal	250—350	280
38	Government High School, Keorak	Sadhu Ram Jain	250—350	300
39	Government High School, Kurana	J. N. Narula	250—350	290
40	Government High School, Ladwa	J. N. Anand	250—350	310
41	Government High School, Madhuban	Nau Nihal Krishan	250—350	320
42	Government High Sdhool, Mowana	Lachhman Dass	250—350	290
43	Government High School, Nissang	Sita Ram Sharma	250—350	330
44	Government High School, Padla	Pran Krishan Dutt	250—350	310

Serial No.	Name of the School	Name of the Principal/ Headmaster/Headmistress	Scale of Pay	Present Pay
		Sarvshr—	Rs	Rs
45	Government High School, Padha	Mohinder Singh	250—350	280
46	Government High School, Pundri	Kuldeep Chand	250—350	250
47	Government High School, Patti Kalyana	Kanshi Ram	250—350	310
48	Government High School, Pehowa	Kundan Lal	250—350	310
49	Government High School, Rajaund	Kukam Chand	250—350	300
50	Government High School, Taraori	Siriram Sharma	250—350	310
51	Government Girls High School, Gharaunda	Miss S. Kharbanda	250—350	300
52	Government Girls High School, N.T., Karnal	Mrs. Sharamjit Kaur	250—350	290
53	Government High School, Panipat	Mrs. Gurbachan Kaur	250—350	300
54	Government High School, Thanesar	Mrs. M. Jammu	250—350	280
55	Government High School, Salwan	Vacant	250—350	Nil
56	Government High School, Gangatheri Popran	Lachhman Singh	250—350	290
57	Government High School, Bapauli	Kartar Singh	250—350	280
58	Government Girls High School, Chamrori	Kuldip Singh	250—350	280
59	Government Girls High School, Jhansa	M. L. Khuller	250—350	280
60	Government Girls High School, Babain	Jermej Singh	250—350	280
61	Government Girls High School, Kheri Naru	D. N. Paul	110—250	250
62	Government Girls High School, Jundla	Bhagirathi Lal Soni	250—350	310
63	Government Girls High School, Arain Pura	Jot Singh	250—350	300
64	Government Girls High School, Kathana	Vacant	250—350	..

[Education Minister]

Serial No.	Name of the School	Name of the Principal/ Head master/Headmistress	Scale of pay	Present pay
		Sarvshri—	Rs.	Rs.
65	Government Girls High School, Yara	Sulekh Chand	250—350	320
66	Government Girls High School, Sanch	Vacant	250—350	..
67	Government Girls High School, Urlana Kalan	Baldev Parshad	250—350	320
68	Government Girls High Sdhool, Rasina	H. L. Malhotra	250—350	330
69	Government Girls High School, Jakhauli	H. R. Moga	250—350	290

Primary Health Unit, Patto-Hira Singh, district Ferozepore

***9025. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether he is aware of the fact that no doctor is serving at present in the Primary Health Unit at Patto-Hira Singh, district Ferozepore ; if so, the time by which one is likely to be posted there ?

Shrimati Om Prabha Jain : Yes, Sir, A new recruit was offered the post at Patto-Hira Singh but he did not join service. Another doctor is being posted there shortly.

Schools in Block Education Circles, Sidhwan Bet, Sudhar and Pakhowal in district Ludhiana

***8879. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to —

(a) lay on the Table of the House a list of schools in Block Education Circles, Sidhwan Bet, Sudhar and Pakhowal in district Ludhiana ;

(b) state the number of boy students, girl students and teachers, respectively, in each of the schools mentioned above :

(c) state whether there is a shortage of teachers or their number is surplus in the said schools ;

(d) state the number of students after which a teacher is appointed in the said schools ?

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) A statement showing the names of the schools where there is shortage or the number of teachers is surplus is laid on the Table of the House.

(d) One teacher for the first block of 60 children and an additional teacher for every next block of 50 children or part thereof.

Statement giving information in respect of parts (a) and (b)

Enrolment

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block Education Circle, Sidhwan Bet					
1	Government Primary School, Salimpura ..	5	66	125	3	
2	Government Primary School, Sidhwan Bet ..	156	165	321	7	
3	Government Primary School, Kiri ..	35	28	63	2	
	Government Primary School, Bhaini Gujran ..	19	10	29	1	
5	Government Primary School, Anupura ..	36	27	63	2	
6	Government Primary School, Gidder Wandi ..	69	50	119	3	
7	Government Primary School, Lodhiwala ..	9	14	23	1	
8	Government Primary School, Tihara ..	..	57	57	2	
9	Government Primary School, Patti Multani ..	31	23	54	2	
10	Government Primary School, Talwara ..	44	24	68	2	
11	Government Primary School, Gorsian Khan Mohd. ..	42	21	63	2	
12	Government Primary School, Madarpura ..	33	27	60	2	
13	Government Primary School, Kotkana ..	38	22	61	1	
14	Government Primary School, Pindi Chak ..	37	24	61	1	
15	Government Primary School, Birk ..	100	82	182	5	
16	Government Primary School, Barsai ..	108	84	192	5	
17	Government Primary School, Sidhwan Kalan ..	164	48	212	5	
18	Government Primary School, Bazurg ..	83	48	131	4	

[Education Minister]

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block Education Circle, Sidhwan Bet—*Contd.*					
19	Government Primary School, Dhothar ..	35	30	65	2	
20	Government Primary School, Raowai ..	93	74	167	4	
21	Government Primary School, Gorsian Makhan ..	35	27	62	2	
22	Government Primary School, Poona ..	39	41	80	2	
23	Government Primary School, Leelan ..	134	79	213	5	
24	Government Primary School, Bangsipura ..	33	36	69	2	
25	Government Primary School, Sardarpura ..	57	21	78	2	
26	Government Primary School, Malsian Bhaike ..	159	26	185	4	
27	Government Primary School, Jandi ..	103	69	172	4	
28	Government Primary School, Malsian Bajan ..	60	53	113	3	
29	Government Primary School, Janetpura ..	45	35	80	2	
30	Government Primary School, Sodhwal ..	37	22	59	2	
31	Government Primary School, Bhanowal Kh. ..	133	107	240	5	
32	Government Primary School, Majri ..	51	29	80	2	
33	Government Primary School, Khanjarwal ..	60	33	93	2	
34	Government Primary School, Porian ..	..	72	72	2	
35	Government Primary School, Walipur Khurd ..	47	31	78	2	
36	Government Primary School, Walipur Khurd ..	30	8	48	1	
37	Government Primary School, Ghamnewal ..	18	8	26	1	
38	Government Primary School, Talwandi Rai ..	26	1	38	1	

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block Education Circle, Sidhwan Bet—*Concld*					
39	Government Primary School, Ranki ..	22	10	32	1	
40	Government Primary School, Bhundi ..	74	46	120	3	
41	Government Pr'mary School, Sherpur Kalan ..	60	60	120	3	
42	Government Primary School, Sherpur Kalan ..	207	101	308	7	
43	Government Primary School, Galib Khurd ..	56	42	98	2	
44	Government Primary School, Galib Ram Singh ..	70	61	131	3	
45	Government Primary School, Fatehgarh Sivian ..	58	48	107	2	
46	Government Primary School, Sheikh Daulat ..	78	64	142	4	
47	Government Primary School, Amargarh Kaler ..	131	89	220	5	
48	Government Primary School, Boadlwala ..	41	28	69	2	
49	Government Primary School, Sowaddi Kh. ..	60	51	111	3	
	Block Education Circle, Sudhar					
1	Government Primary School, Sudhar ..	..	245	245	7	
2	Government Primary School, Sudhar (Boys) ..	252	..	252	6	
3	Government Primary School, Akalgarh ..	156	116	272	6	
4	Government Primary School, Jassowal ..	137	111	248	5	
5	Government Primary School, Bopa Rai Ki ..	244	228	472	11	
6	Government Primary School, Togal ..	863	53	116	3	
7	Government Primary School, Aittian ..	167	130	297	7	
8	Government Primary School, Heran ..	147	125	272	7	

[Education Minister]

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block E'ucation Circle, Sudhar—*Contd*					
9	Government Primary School, Rajoana Ki ..	74	54	128	3	
10	Government Primary School, Rajoana Kh. ..	102	64	166	4	
11	Government Primary School, Halwara ..	233	182	415	10	
12	Government Primary School, Rattowal ..	118	72	180	5	
13	Government Primary School, Ahuwal ..	116	102	218	5	
14	Government Primary School, Toowa ..	111	240	351	8	
15	Government Primary School, Sahauli ..	108	95	203	5	
16	Government Primary School, Mohie ..	141	148	290	8	
17	Government Primary School, Jangpur ..	166	140	306	6	
18	Government Primary School, Hissowal ..	135	99	234	5	
19	Government Primary School, Ghuman ..	91	73	164	4	
20	Government Primary School, Budhel ..	35	29	64	2	
21	Government Primary School, Ghandoor ..	185	122	307	7	
22	Government Primary School, Morkrima ..	41	39	80	2	
23	Government Primary School, Talwandi Ki ..	183	199	302	8	
24	Government Primary School, Talwandi Kh. ..	108	73	181	5	
25	Government Primary School, Dhatt ..	108	94	202	5	
26	Government Primary School, Pandori ..	90	73	163	4	
27	Government Primary School, Sheikhpura ..	76	57	133	3	
28	Government Primary School, Mandiani ..	146	115	261	5	

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block Education Circle Sudhar—*Concld*					
29	Government Primary Sdhool, Shahjhanpur ..	42	31	73	2	
30	Government Primary School, Achwal ..	61	41	102	2	
31	Government Primary School, Jatpura ..	56	93	148	3	
32	Government Primary School, Hjorran ..	178	123	301	6	
33	Government Primary School, Bopa Rai Khurd ..	80	50	130	4	
34	Government Primary School, Burj Hari Singh ..	118	105	223	5	
35	Government Primary School, Burj Naghiana ..	103	58	161	4	
36	Government Primary School, Binjal ..	115	79	194	4	
37	Government Primary School, Silovi ..	44	46	80	2	
38	Government Primary School, Raikot ..	838	..	838	19	
39	Government Primary School, Rupa Patti ..	31	32	63	2	
40	Government Primary School, Ramgarh Sibli ..	74	53	127	3	
41	Government Primary School, Rurka Kalan ..	83	59	142	3	
	Block Education Circle, Pakhowal					
1	Government Primary School, Dolan Kh. ..	44	30	74	2	
2	Government Primary School, Dolan Ki ..	95	70	165	4	
3	Government Primary School, Bilah ..	83	37	120	2	
4	Government Primary School, Shahzad ..	49	30	79	2	
5	Government Primary School, Mansuran ..	150	116	266	6	
6	Government Primary School, Jodhan ..	147	106	253	5	
7	Government Primary School, Rattan ..	57	27	84	2	

[Education Minister]

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block Education Circle Pakhowal—*Contd*					
8	Government Primary School, Chakkar ..	25	16	41	1	
9	Government Primary School, Andlu ..	139	84	223	5	
10	Government Primary School, Bhaini Darera ..	109	77	186	3	
11	Government Primary School, Bhaini Rora ..	122	66	188	4	
12	Government Primary School, Rajgarh ..	101	71	172	4	
13	Government Primary School, Thga Heri, ..	47	39	86	2	
14	Government Primary School, Akalgarh Khurd ..	44	31	75	2	
15	Government Primary School, Gujjarwal ..	239	—	239	5	
16	Government Primary School, Narangwal (B) ..	154	..	154	4	
17	Government Primary School, Narangwal (G) ..	..	63	63	2	
18	Government Primary School, Ballowal ..	98	58	156	3	
19	Government Primary School, Chimanda ..	114	65	179	4	
20	Government Primary School, Dhaipati ..	149	67	216	4	
21	Government Primary School, Tajpur ..	152	87	239	5	
22	Government Primary School, Bhaini Bringa ..	169	112	281	6	
23	Government Primary School, Kishangarh ..	47	28	75	2	
24	Government Primary School, Bassroan ..	45	48	93	2	
25	Government Primary School, Sukhana ..	45	19	64	1	
26	Government Primary School, Barhmi ..	169	110	279	6	
27	Government Primary School, Bruj Littar ..	144	110	254	6	

Serial No.	Name of School	Boy students	Girl students	Total	Staff sanctioned	REMARKS
	Block Education Circle, Pakhowal—*Concld.*					
28	Government Primary School, Nurpura ..	111	66	177	3	
29	Government Primary School, Gondwal ..	129	75	204	4	
30	Government Primary School, Littar ..	58	63	111	2	
31	Government Primary School, Kaila ..	78	51	129	3	
32	Government Primary School, Leel ..	103	92	195	4	
33	Government Primary School, Dhalian ..	53	32	85	3	
34	Government Primary School, Burj Hakiman ..	56	30	86	2	
35	Government Primary School, Dorgan ..	94	64	158	4	
36	Government Primary School, Nangal Kalan ..	83	55	138	3	
37	Government Primary School, Nangal Khurd ..	90	77	167	4	
38	Government Primary School, Jand ..	111	58	169	3	
39	Government Primary School, Shahpur ..	26	20	46	1	

Statement giving information in respect of part (c)

Name of the Block Education Circle	Name of the Primary Schools where staff is needed	No. of teachers needed	Name of the Primary Schools where posts are surplus	No. of surplus posts
1	2	3	4	5
Sidhwan Bet ..	**Kot Mana**	**One**	**Tihara**	**One**
	Fidai Chak	**One**	**Birk**	**One**
			Barsal	**One**
			Bazurg	**One**
			Sodhiwala	**One**
			Sheikh Daulat	**One**

[Education Minister]

Name of the Block Education Circle	Name of the Primary Schools where staff is needed	No. of teachers needed	Name of the Primary Schools where posts are surplus	No. of surplus posts
Sudhar	Mandiani	One	Sudhar (Girls)	Two
			Sudhar (Boys)	One
			Boparai Kalan	One
			Aittian	One
			Heran	One
			Halwara	One
			Rattowal	One
			Toosa	One
			Sahauli	One
			Mohle	Two
			Gandoor	One
			Talwandi Kl.	Two
			Talwandi Kh.	One
			Dhatt	One
			Boparai Khurd	One
			Raikot	One
				One
Pakhowal ..	Billah	One	Burj Litter	One
	Dhaipati	One	Dhallain	One
	Sukhana	One		
	Nurpura	One		
	Littar	One		
	Jand	One		
	Bhaine Darera	One		

O. T. Special Certificates Awarded to Vishard Pass Students

***9632. Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number and names of Vishard (High Proficiency in Sanskrit) teachers who have represented to the Government and who have been awarded O.T. Special Certificates during the years, 1965 and 1966 ?

Shri Prabodh Chandra : There are fourteen Vishard Pass teachers who have represented for the award of O.T. Special Certificates in 1965 and 1966. Their names are given in the Annexure 'A'. It has been decided to award a special O.T. Certificate to only one Vishard Pass Teacher Shri Uma Datt Joshi, during the year, 1966, as he had more than 20 years service to his credit.

ANNEXURE 'A'

Names and addresses of the Vishard pass teachers who have applied for the award of Special Certificate during 1965-66.

1. Shri Puran Chand Sharma, Teacher,
Government Co-education Higher Secondary School Dhugiari. (Kangra)

2. Shri Ishwar Dutt, Teacher,
D.A.V. Higher Secondary School, Karnal.

3. Shri Ram Parshad Teacher,
Government Middle School, Kheri Kalan (Gurgaon).

4. Shri Onkar Nath, Teacher,
Shri L. O. High School, Rampur Haler (Hoshiarpur).

5. Shri Hans Raj, Teacher,
D.A.V. Middle School, Bhanopli (Hoshiarpur).

6. Shri Ramji Lal Bohra,
Government Higher Secondary School, Mohindergarh.

7. Shri Pyara Lal Sharma,
Government Higher Secondary School, Dhilwan (K. Thala).

8. Shri Ram Rekha Mal,
D.A.V High School, Bral.,npur.

9. Shri Rulia Ram,
Public High School, Binewal (Hoshiarpur).

10. Shri Ram Swarup,
Jat High School, Thol (Karnal),

11. Shri Ganga Dhar Bohra
Government Higher Secondary School, Mahindergarh.

12. Shri Hukam Chand teacher,
D.A.V. High School, Santokhgarh (Hoshiarpur).

13. Shri Vasudev Sharma, Teacher,
of Karnal District.

14. Shri Uma Dutt, Teacher,
of Kapurthala District.

Work allotted to a Lecturer in Government Randhir College, Kapurthala

***9461. Sardar Lakhi Singh Chaudhri:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any of the Lecturers in the Government Randhir College, Kapurthala, was required to teach only one to two periods a day from Wednesdays to Saturdays during the months of October and November, 1965 and also earlier;

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, the nature of other duties allotted to the said lecturer for the remaining 7 to 8 periods a day;

(c) the pay and allowances of the Lecturer referred to in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra: (a) and (b) A Lecturer in French has been taking 7 periods a week for teaching French. He could not be assigned work in any other subject as he is M.A. in French only.

		Rs.	
(c) Basic pay	..	230	per month
Dearness pay	..	50	per month
Dearness allowance	..	15	per month

Introduction of crafts in Basic Primary Schools in tehsil Una, District Hoshiarpur

***9050. Pandit Mohan Lal Datta:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government has introduced the teaching of crafts in the Basic Primary Schools in tehsil Una, District Hoshiarpur; if so, details of the crafts introduced in such schools;

(b) the expenditure so far incurred on the crafts introduced in each of the said schools and the income, if any, accruing therefrom;

[Pandit Mohan Lal Datta]

(c) the details of the steps, if any, taken or proposed to be taken to make the crafts taught a paying proposition or a gainful work for the students;

(d) whether the Government has considered the question of reorientating the basic education in the schools to make it real and constructive?

Shri Prabodh Chandra: (a) Yes. Agriculture, Toy making and Mat making.

(b) The flower seeds worth of Rs. 47/- were purchased by the D.E.O. and distributed to the Basic Primary Schools in Tehsil Una. No expenditure was incurred on the Craft of Toy making and Mat making. The raw material for these Crafts is provided by the students and the finished products are taken by them.

(c) So far more emphasis has been laid on educational value of the craft rather than on the economic returns.

(d) It is now proposed to make Basic Education production oriented by opening more agriculture farms and garden plots and by introducing Practical Arts in Middle, High and Higher Secondary Schools.

Loanees arrested in district Karnal

***8983. Comrade Ram Piara:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of the loanees in district Karnal, tehsil-wise, against whom warrants for recovery of loan amounts as arrears of land revenue stood on 1st May, 1965 together with the date of issue of the warrants in the case of each loanee;

(b) the names of the said loanees against whom the said warrants stand even today in the said district, tehsil-wise;

(c) whether it is a fact that some defaulting loanees owing comparatively less amounts were arrested in the district of Karnal during the period from 1st January, 1965 todate, whereas other defaulting loanees from whom large sums are due were not touched till 31st December, 1965; if so, the reasons therefor;

(d) the total amount outstanding against each of the defaulting loanees as on 1st May, 1965 and on 31st December, 1965, separately, in the said district tehsilwise;

(e) the names of the persons arrested by the Revenue Authorities in the said district, tehsilwise, during the period from 1st January, 1965, to date together with the amount which was outstanding against each such defaulting loanee at the time of arrest?

Sardar Harinder Singh Major : (a) (b), (d) and (e) The Statement giving the required information is laid down on the Table of the House.

(c) No. The loanees whether big or small who refuse to pay the loan outstanding against them are treated equally under the rules.

Tehsil Karnal

	A			B	D		E	
Village	Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Amount	Date of issue of warrant	Name of loanee against whom warrant stands even today	Total amount outstanding on 1st May, 1965	31st December, 1965	Persons arrested from 1st January, 1965, todate	Amount outstanding at the time of arrest
		Rs.			Rs			Rs
Bularpur ..	Hem Raj, son of Kainya	939.07	1-10-64	..	939.17	..	1. Thana, son of Partap	495.29
Baragaon	Kartar Singh son of Khushal Singh	1387.09	25-11-64	..	1387.09	..	2. Banta Singh s/o Nehal Singh	926.98
Budha Khera ..	Ranjeet Singh, son of Balwant Singh	405.00	25-11-64	..	405.00	..	3. Makhan Singh, son of Khaki	277.80
Ditto	Feta Singh son of Wadhawa Singh	839.31	25-11-64	..	839.31	839.31	4. Banta Singh, son of Bagail Singh	140.00
Ditto	Raghbir Singh, son of Sant Singh	3,855.44	25-11-64	..	3,855.44	..	5. Hardeep Singh, son of Warrayam Singh	167.85
Ditto	Teja Singh, son of Boota Singh	1,522.76	25-11-64	..	1,522.76	..	6. Amrik Singh, son of Amar Singh	1,382.93
Ditto	Surinder Singh, son of Mehal Singh	1,198.79	25-11-64	Surinder Singh son of Mehal Singh	1,198.79	1,189.79	7. Shitag Singh, son of Hari Singh	1,853.06
Poundrak ..	Data Kalu, son of Chaju	523.62	25-11-64	..	523.62	..	8. Kashmira Singh, son of Dhan Singh	647.76
Do	Jagira, son of Sahoo	510.22	25-11-64	..	510.22	..	9. Nonihal Singh,	3,218.30
Dara ..	Narian Singh, son of Asa Singh	840.00	25-11-64	..	840	..	10. Wirsa Singh	2,483.76
Do	Nishabar Singh, son of Hansa Singh	607.50	25-11-64	..	607.50	..	11. Sadhu	55.75

[Revenue Minister]

	A		B				D	E
Village	Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Amount	Date of issue of warrant	Name of loanee against whom warrant stands even today	Total amount Outstanding on 1st May, 1965	Total amount Outstanding on 31st December, 1965	Persons arrested from 1st January, 1965 todate	Amount out standing at the time of arrest
		Rs.			Rs.			Rs.
Dadupur Rangran	Inder Singh, son of Labha Mal	560.86	25-11-64	..	560.86	560.86	12. Dabara Singh, son of Tehal Singh	366.19
Dabri ..	Iqbal Singh, son of Khazan Singh	775.20	25-11-64	..	775.20	..	13. Harbans Singh, son of Narain Singh	512.00
Ranwar ..	Ganga Dass, son of Barham Dass	1,177.01	25-11-64	..	1,177.01	1,177.01	14. Dalip Singh, son of Sadhu Singh	4,299.77
Do	Sardara Singh, son of Sunder Singh	967.49	25-11-64	..	967.49	..	15. Ram Kishan, son of Moola Ram	7,000.00
Do	Captain Harbans Singh	673.50	25-11-64	Captain Harbans Singh	673.50	673.50	16. Kapoor Singh, son of Labh Singh	1,287.00
Do	Vir Singh, son of Bhagwan Singh	898.29	25-11-65	..	898.89	..	17. Sadhu Singh, son of Dewan Singh	901.10
Do	Shadi, son of Ganpat	600.98	25-11-64	..	600.98	..	18. Dalip Singh, son of Banta Singh	508.97
Do	Surat Singh, son of Narain Singh	1,377.61	25-11-64	..	1,377.61	..	19. Gopala, son of Chandan	253.00
Raba ..	Hari Kishan, son of Daulat Ram	1,170.57	21-11-64	..	1,170.57	..	20. Birbal, son of Manshi	376.27
Salaru ..	Harbans Lal, son of Dewan Chand	678.36	21-11-64	..	678.36	..	21. Puran Chand, son of Gokal	4,262.00
Do	Surat Singh, son of Sucha Singh	996.80	21-11-64	..	996.80	..	22. Nanoo Ram, son of Soran Singh	3,423.92
Do	Kuldip Singh, son of Inder Singh	696.68	21-11-64	..	696.68	..	23. Puran Singh, son of Mota Singh	647.40

Do	Balwant Singh, son of Nand Singh	653.81	21-11-64	..	653.81	653.81	24. Darshan Singh, son of Dalial Singh	554.36
Do	Jarnail Singh, son of Nand Singh	662.70	21-11-64	..	662.70	662.70	25. Kehar Singh, son of Hazara Singh	567.74
Do	Tirlok Singh, son of Nehal Singh	629.35	21-11-64	..	629.35	..	26. Shingara Singh, son of Fauja Singh	409.12
Shergarh Tapa	Ram Kishan, son of Jhandho	609.40	21-11-64	..	609.90	..	27. Jarnail Singh, son of Harpal Singh	735.87
Shiekhupura	Dedar Singh, son of Hari Singh	517.70	21-11-64	..	517.70	..	28. Hazara Singh, son of Dial Singh	714.60
Sohana Zarifa Viran ..	Sucha Singh, son of Roor Singh	1,048.11	21-11-64	..	1,048.11	..	29. Natha Singh, son of Mohar Singh	44.75
Kalron ..	Milkhan Singh, Sultan Singh, sons of Balak Singh	1,061.60	21-11-64	..	1,061.60	..	30. Narjan Singh, son of Kapoor Singh	477.18
Do	Daya Singh, son of Saroop Singh	675.00	21-11-64	..	675.00	..	31. Bhartu, son of Kania	791.83
Katail ..	Rajpal Singh, Jai Singh, sons of Mullan	530.72	21-11-64	..	530.72	..	32. Kanaiya Ram, son of Tailu Ram	305.19
Kunjpura ..	Siri Ram, son of Abha Ram	675.00	21-11-64	..	675.00	..	33. Dedar Singh, son of Kartar Singh	172.40
Do	Prem Parkash, son of Girdari Lal	1,010.00	21-11-64	..	1,010.00	..	34. Jaimal Singh, son of Boota Singh	1,313.46
Do	Gita, son of Niader	549.60	21-11-64	..	549.60	549.60	35. Balkar Singh, son of Bhagat Singh	3,627.45
Ramba ..	Balaka Singh	508.00	26-11-64	..	508.00	..	36. Kirpa [illegible], son of Laoh Singh	1,119.88
Ghroundha ..	Amar Singh, son of Gurdat Singh	527.76	2-12-64	..	527.76	..	37. Man Singh, son of Mangal Singh	3,397.12

[Revenue Minister]

	A			B	D			E
Village	Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Amount	Date of issue of warrant	Name of loanee against whom warrant stands even today	Total amount Outstanding on 1st May, 1965	31st December, 1965	Persons arrested from 1st January, 1965 todate	Amount outstanding at the time of arrest
		Rs.			Rs.	Rs.		Rs
Ghrounda	Dalip Singh, son of Sucha Singh	494.75	2-12-64	..	494.75	..	38. Avtar Singh, son of Khushal Singh	407.22
Do	Lal Singh, son of Bhag Singh	742.13	2-12-64	..	742.13	..	39. Moola Singh, son of Chiragh Singh	408.06
Do	Balkar Singh, son of Gurdat Singh	527.76	2-12-64	..	527.76	..	40. Virsa Singh, son of Wadhawa Singh	402.47
Amin ..	Dhan Singh, son of Jai Ram	163.47	2-12-64	..	163.47	..	41. Chiman Singh, son of Kapoor Singh	—
Sheikhupura Mach	Ladha Singh, son of Baghail Singh	137.50	20-1-65	..	137.50	..	42. Anoop Singh, son of Khem Singh	531.04
Salaru ..	Banta Singh, son of Nehal Singh	923.98	19-1-65	..	923.98	923.98	43. Hazara Singh, son of Dharam Singh	942.69
Sheikhupura ..	Pala Singh, son of Rachpal Singh	3,085.01	20-1-65	..	3,085.01	..	44. Rajinder Singh, son of Gurdit Singh	1,219.53
Machoori ..	Shihag Singh, son of Labha Singh	1,765.90	20-1-65	..	1,765.90	..	45. Narjan Singh, son of Barkat Singh	1,525.45
Ditto	Kala Singh, son of Teja Singh	546.93	20-1-65	..	546.93	..	46. Pala Singh, son of Gurdit Singh	756.16
Do	Amrik Singh, son of Sohan Singh	1,379.03	20-1-65	..	1,379.3	..	47. Shihag Singh, son of Raja Singh	2,213.82
Do	Hardip Singh, son of Nehal Singh	164.88	20-1-65	..	164.88	..	48. Bhagat Ram, son of Mehar Chand	3,071.47

Do	Sadhu Singh, son of Hari Singh	1,850.63	22-1-65	..	1,850.63	..	49. Gurdeep Singh, son of Bishan Singh	2,560.50
Do	Dalip Singh, son of Sadhu Singh	4,144.40	22-1-65	..	4,144.40	4,144.40	50. Chanan Singh, son of Ram Singh	438.00
Do	Kashmir Singh, son of Labh Singh	644.76	22-1-65	..	644.76	..	51. Sawan Singh, son of Doola Singh	2,061.31
Bansa ..	Mehar Singh, son of Virsa Singh	1,084.38	26-1-65	..	1,084.38	..	52. Gopal Singh, son of Shivdev Singh	2,685.24
Do	Harbans Singh, son of Bahadar Singh	687.36	26-1-65	..	687.36	..	53. Pala Singh, son of Bela Singh	477.39
Do	Virsa Singh, son of Khushal Singh	2,480.76	26-1-65	..	2,480.76	..	54. Sadhu Ram, son of Chittar	277.82
Do	Ujagar Singh, son of Khushal Singh	325.30	26-1-65	..	325.30	..	55. Arjan Singh, son of Kundan	476.76
Bansa ..	Shisha Singh, son of Dargahi	758·04	26-1-65	..	758·04	..	56. Dra, son of Mangtu	25·69
Sheikhu pura Machoori ..	Kapur Singh, son of Labh Singh	1,284·19	18-2-65	..	1,284·19	1,284·19	57. Moti Ram, son of Gokal	166·68
Do ..	Gurcharan Singh, son of Partap Singh	363·45	18-2-65	..	363·45	..	58. Parkash Chand, son of Puran	2,109·05
Do	Harbans Singh, son of Warrayam Singh	688·14	18-2-65	..	688·14	..	59. Kapoor Singh, son of Man Singh	1,736·78
Do	Gurbax Singh, son of Thakar Singh	3,643·94	18-2-65	..	3,643·94	..	60. Babu Ram, son of Joti Ram	429·96
Do	Thakar Singh, son of Gulab Singh	1,825·11	18-2-65	..	1,825·11	..	61. Parsa, son of Atma Ram	324·75
Do ..	Rati Ram, son of Datu Ram	276·00	20-2-65	..	276·00	..	62. Jangir Singh, son of Ralla Singh	591·75

[Revenue Minister]

	A			B	D			E
Village	Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Amount	Date of issue of warrant	Name of loanee against whom warrant stands even today	Total amount Outstanding on 1st May, 1965	Total amount Outstanding on 31st December, 1965	Persons arrested from 1st January, 1965 todate	Amount outstanding at the time of arest
		Rs.			Rs	Rs		Rs.
Do ..	Fauja Singh, son of Khushal Singh	368·53	20-2-65	..	368·53	..	63. Ronaq Ram, son of Puran	1,702·29
Do ..	Ranjeet, son of Partap	67·50	20-2-65	..	67·50	..	64. Nishan Singh, son of Phola Singh	1,329·25
Nissing ..	Dina Nath, son of Hakam Chand	673·23	23-3-65	..	673·23	..	65. Pala Singh, son of Raja Ram	733·12
Do	Sada Singh, son of Dewan Singh	898·10	19-3-65	..	898·10	..	66. Lachman Singh, son of Phola Singh	122·60
Sadha ..	Prithi Singh, son of Sudhar	258·75	3-3-65	..	258·75	..	67. Fauja Singh, son of Maghar Singh	1,340·63
Nilokheri ..	Kirpal Singh, son of Udham Singh	1,068·37	16-3-65	..	1,068·37	..	68. Nanu, son of Soran	1,070·53
Do ..	Kartar Singh, son of Udham Singh	726·27	16-3-65	..	726·27	..	69. Singoo, son of Bichia	348·87
Do	Sewa Singh, son of Udham Singh	413·02	16-3-65	..	413·02	..	70. Kundan Singh, son of Sant Singh	1,022·62
Chakda ..	Surinder Singh, son of Ishar Singh	204·75	3-3-65	..	204·75	..	71. Amar Nath	490·69
Sadha ..	Rulia Ram, son of Bhola Ram	405·00	3-3-65	..	405·00	..	72. Matu Ram	112·92
							73. Bakhshish Singh	365·11

74. Kapoor Singh, son of Labh Singh	378·43
75. Ram Narain	552·60
76. Raghbir Singh, son of Sant Singh	3,017·50
77. Sucha Singh, son of Roor Singh	790·70
78. Hirda Ram, son of Lakhi Ram	1,321·62
79. Bhartoo	597·50
80. Gija Singh, Jila Singh, sons of Har Narain	958·46
81. Balwant Singh	1,996·00
82. Ram Lal, son of Puna Ram	552·54
83. Bhagwan Singh	1,128.74
84. Sama Singh, son of Dalip Singh	801·58
85. Piara Lal, son of Rulia Ram	2,228·81
86. Amar Singh, son of Ram ji Lal	806·45
87. Gian Singh, son of Ujagar Singh	1,353·00
88. Sada Singh, son of Bakhtawar Singh	253·00

[Revenue Minister]

Village	Names of loanes against whom warrants stood on 1st May, 1965	Amount	Date of issue of warrant	Name of loanes against whom warrant stand even today	Total amount Out-standing on 1st May, 1965	Total amount Out-standing on 31st December, 1965	Persons arrested from 1st January, 1965 todate	Amount outstanding at the time of arrest
								Rs.
							89. Balwan Singh, son of Nand Singh	352·43
							90. Jarnail Singh, son of Nand Singh	672·58
							91. Banta Singh, son of Nehal Singh	875·50
							92. Hazara Singh, son of Sur Singh	624·53
							93. Amar Singh, son of Banta Singh	3,768·78
							94. Manga Ram, son of Sewa Ram	743·58
							95. Rattan Singh, son of Wadhawa Singh	387·60
							96. Labh Singh, son of Sarda Singh	593·00
							97. Moola Ram, son of Bakhtawar	825·00
							98. Bisawa Singh, son of Mangal Singh	114·33

99. Man Singh, son of Matu	510·75
100. Gurmaj Singh. son of Ujagar Singh	274·80
101. Punu Ram, son of Mathra Dass	939·80
102. Kewal, son of Chitra	270·72
103. Puran Singh, son of Boota Singh	490·40
104. Jagir Singh, son of Sohan Singh	246·00
105. Balkar Singh, son of Atar Singh	8,218·64
106. Rulia Ram, son of Harnam	331·80
107. Puran, son of Megh Raj	173·00
108. Sher Singh, son of Devtia	87·39
109. Soran, son of Mansa	379·05
110. Talib, son of Chaju	570·28
111. Sadhu Singh, son of Lakha Singh	475·25
112. Hakam Chand, son of Ram Singh	1,651·89
113. Kishan Singh, son of Chaju Singh	264·25

[Revenue Minister]

Village	Names of loanes against whom warrants stood on 1st May, 1965	Amount	Date of issue of warrant	Name of loanee against whom warrants stands even today	Total amount Out-standing on		Persons arrested from 1st January, 1965 todate	Amount outstanding at the time of arrest
					1st May, 1965	31st December, 1965		
								Rs. P.
							114. Roop Chand, son of Tala Ram	485·08
							115. Baru, son of Munshi	155·92
							116. Arjan, son of Akha Ram	521·46
							117. Jai Bhagwan, son of Shadi Ram	1,785·25
							118. Hazari Ram, son of Sita Ram	397·62
							119. Gobind Ram, son of Bakhtawar	215·03
							120. Molu Ram, son of Sata Ram	162·75
							121. Sharif, son of Nasiboo	117·37
							122. Imam Din, son of Zahora	155·50
							123. Hakimoo, son of Zohara	269·87
							124. Natha, son of Zohara	403·43
							125. Fata, son of Zohara	706·78

126. Anta Ram, son of Chandu	185·71
127. Todar, son of Ram Dia	567·28
128. Sita, son of Surjan	185·32
129. Partap Chand, son of Devdita	370·20
130. Bahadur Singh, son of Kirpal Singh	992·76
131. Chanan Singh, son of Sarwan Singh	369·84
132. Jaimal Singh, son of Ganda Singh	940·06
133. Chatar Singh, son of Bichea Ram	234·80
134. Kartar Singh, son of Kehar Singh	336·11
135. Punjab Singh	437·43
136. Chanan Singh, son of Mohan Singh	399·03
137. Dhana, son of Jamana Ram	118·93
138. Dina Nath, son of Hakam Chand	1,245·70
139. Hirda Ram, son of Bhagwana	70·46
140. Phool Singh, son of Hinder Ram	154·13
141. Dalip Singh, son of Ujagar Singh	493·15
142. Dila Ram, son of Natha	727·26

[Revenue Minister]

TEHSIL THANESAR

A

Sl. No.	Name of Village		Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Date of issue
1	Sodhi	..	Hardeep Singh, son of Wisakha Singh	22-10-64
2	Lal Chhapar	..	Mukandi, son of Molu	26-10-64
3	Thanesar	..	Gian Singh, son of Wadhawa Singh	2-11-64
4	Bhagwangarh	..	Heshiar Singh, son of Mehar Singh	6-11-64
5	Azmat Pur	..	Surja Singh, son of Santokh Singh	11-11-64
6	Ajrana Khurd	..	Ram Lal son of Kishan Chand	13-11-64
7	Jharauli Khurd	..	Bhupinder Singh, son of Rajinder Singh	16-11-64
8	Rawa	..	Om Parkash, son of Devi Chand	17-11-64
9	Kharkali	..	Bhera Singh, son of Surat Singh	26-11-64
10	Dabkheri	..	Gurbax Singh, son of Kundan Singh	18-12-64
11	Do	..	Milkha Singh, son of Isher Singh	18-12-64
12	Do	..	Didar Singh, son of Kesar Singh	18-12-64
13	Do	..	Arjan Singh, son of Gulab Singh	18-12-64
14	Do	..	Ghasitta Singh, son of Uttam Singh	19-12-64
15	Do	..	Udham Singh, son of Thakar Singh	19-12-64
16	Dhurala	..	Bhagwan Singh, son of Bhagat Singh	19-12-64
17	Thaska Miranji	..	Menga Singh, son of Wadhawa Singh	21-12-64
18	Barkan	..	Sadhu, Sora, sons of Joti	25-12-64
19	Sabbad	..	Lal Singh, son of Arjan Singh	27-12-64
20	Masana	..	Mela Singh, son of Sunder Singh	28-12-64
21	Thaska Ali	..	Harbhajan Singh, son of Harnam Singh	30-12-64
22	Sahbad	..	Phoola Singh, son of Alla Singh	14-1-65
23	Rattangarh	..	Des Raj, son of Deviditta Mal	19-1-65
24	Dabkheri	..	Uali Ram, son of Shadi	19-1-65
25	Do	..	Bir Singh, son of Hakam Singh	19-1-65
26	Do	..	Darshan Singh, son of Kala Singh	19-1-65
27	Do	..	Santokh Singh, son of Bawa Singh	19-1-65
28	Do	..	Dilbagh Singh, son of Ujaggar Singh	19-1-65

B	D		E	
Name of the loanee against whom such warrant stands even today	*Total amount outstanding* On 1st May, 1965	On 31st December, 1965	Names of the persons arrested from 1st January, 1965 to-date.	Amount outstanding at the time of arrest.
	Rs.	Rs.		Rs.
Shri Hardeep Singh	492.53	492.53	(1) Des Raj, son of Devi Ditta	114.50
Shri Mukandi	387.51	387.51	(2) Nihala, son of Jamant	466.11
Shri Gian Singh	177.28	177.28	(3) Gulab Singh, son of Alla Singh	233.40
Shri Hehiar Singh	3.00	3.00	(4) Udey Ram, son of Ganga Ram	233.40
Shri Surja Singh	945.36	945.36	(5) Puran Singh, son of Sucha Singh	260.74
Shri Ram Lal	637.04	637.04	(6) Darshan Singh Dabkheri	295.28
Shri Bhupinder Singh	1,858.70	1,858.70	(7) Kirpa Singh	
Shri Om Parkash	98.47	98.47	(8) Banwari, son of Manga Singh	231.50
Shri Bhara Singh	679.69	679.69	(9) Atwari, son of Manga Singh	231.50
Shri Gurbux Singh	963.38	963.38	(10) Karta, son of Pana	231.50
Shri Milkha Singh	3.984.63	13,984.63	(11) Megh Raj Kheri, Brahamn	1,620.29
Shri Didar Singh	1,631.69	11,631.69	(12) Kapoor Singh Ajrang Khurd	488.08
Shri Arjan Singh	1.353.37	1,353.37	(13) Banta Singh Ajrana Khurd	488.08
Shri Ghasita Singh	3,139.09	13,139.09	(14) Harbhajan Singh Thaska A.G.	2,124.2
Shri Udham kingh	1,411.50	1,411.50	(15) Herdev Singh, son of Gurdial Singh	235.21
Shri Bhagwan Singh	394.39	394.39	(16) Rulia, son of Telu	235.21
Shri Menga Singh	855.96	855.96	(17) Pirthi, son of Keshori	1,825.07
Sadhu, Sora, sons of Joti	578.48	578.48	(18) Banta Singh, son of Jagat Singh	486.30
Shri Lal Singh	168.95	168.95	(19) Gurbachan Singh, son of Phaga Singh	558.82
Shri Mela Singh	299.63	299.63	(20) Kulwant Singh, son of Bakhshish Singh	1,988.28
Shri Harbhajan Singh	2,265.00	2,265.00	(21) Dal Singh, son of Isher Singh	82.42
Phoola Singh	3,713.14	3,713.14	(22) Sunder, son of Rulia	147.71
	111.50	111.50	(23) Bhag Singh, son of Melapi	890.75
Udey Ram	157.45	157.45	(24) Amar Singh, son of Isher Singh	307.74
Bir Singh	231.94	231.94	(25) Bachan Singh, son of Rulia Ram	606.96
Darshan Singh	111.65	111.65	(26) Banshi Ram, son of Kirpa Ram	367.21
Santokh Singh	231.94	231.94	(27) Harbans Singh, son of Sher Singh	76.96
Dilbagh Singh	231.94	231.94	(28) Makhan Lal, son of Isher Singh	165.88

[Revenue Minister]

TEHSIL THANESAR—contd.

A

Sl. No.	Name of village		Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Date of issue
29	Dabkheri	..	Beant Singh, son of Khajan Singh	19-1-65
30	Do	..	Balbir Singh, son of Uttam Singh	19-1-65
31	Do	..	Sulakhan Singh, on of Partap Singh	19-1-65
32	Do	..	Harbhajan Singh, son of Sawan Singh	19-1-65
33	Do	..	Harbans Singh, son of Gurbax Singh	19-1-65
34	Do	..	Anup Singh, son of Tehal Singh	19-1-65
35	Do	..	Uttam Singh, son of Thakar Singh	19-1-65
36	Do	..	Tehal Singh, son of Uttar Singh	19-1-65
37	Do	..	Waryam Singh, son of Hari Singh	19-1-65
38	Do	..	Sheo Singh, son of Uttam Singh	19-1-65
39	Do	..	Kulwant Singh, son of Bakhshish Singh	19-1-65
40	Do	..	Mangal Singh, son of Jawahar Singh	19-1-65
41	Do	..	Nishan Singh, son of Bhan Singh	19-1-65
42	Do	..	Nishan Singh, son of Kahan Singh	19-1-65
43	Do	..	Jangir Singh, son of Giwan Singh	19-1-65
44	Do	..	Tirlok Singh, son of Harnam Singh	19-1-65
45	Do	..	Inder Singh, son of Isher Singh	19-1-65
46	Do	..	Sheo Singh, son of Bawa Singh	19-1-65
47	Do	..	Jiwan Singh, son of Sunder Singh	19-1-65
48	Do	..	Balkar Singh, son o f Hamela Singh	19-1-65
49	Do	..	Khajan Singh, son of Mangal Singh	19-1-65
50	Do	..	Makhan Singh, son of Hajara Singh	19-1-65
51	Do	..	Pritam Singh, son of Mohan Singh	19-1-65
52	Do	..	Bawa Singh, son of Labh Singh	19-1-65
53	Do	..	Singara Singh, son of Jiwan Singh	19-1-65
54	Do	..	Thakar Singh, son of Jiwan Singh	22-1-65
55	Shahbad	..	Ram Chander, son of Mool Chand	22-1-65
56	Masana	..	Mela Singh, son of Sunder Singh	27-1-65
57	Bhokar Mazra	..	Gurbachan Singh, son of Bakhshish Singh	16-2-65

B	D		E	
Name of the loanee against whom such warrant stands even today	Total amount outstanding 1st May, 1965	31st December, 1965	Names of the persons arrested from 1st January, 1965 to date	Amount outstanding at the time of arrest.
	Rs.	Rs.		Rs.
Beant Singh	231.94	231.94	(29) Shib Ram, son of Jai Ram	163.32
Balbir Singh	231.94	231.94	(30) Bhagat Singh, son of	
Sulakhan Singh	238.84	238.84	(31) Gurdial Singh, son of Jamana	244.96
Harbhajan Singh	521.02	521.02	(32) Khushal Singh, son of Arjan Singh	328.12
Harbans Singh	331.73	331.73	(33) Tulsi, son of Antu	543.34
Anup Singh	275.99	275.99	(34) Inder Singh, son o Narain Singh	1,081.36
Uttam Singh	378.58	378.58	(35) Jagat Singh, son of Sant Singh	236.33
Tehal Singh	198.25	198.25	(36) Hallam Singh, son of Gujar Singh	233.53
Waryam Singh	305.79	305.79	(37) Sucha Singh, son of Bishan Singh	67.69
Sheo Singh	1,232.99	1,232.99	(38) Mamula Dir, son of Ahnad	165.88
Kulwant Singh	1,947.30	1,947.30	(39) Mukandi, son of Gurdial	2,640.01
Mangal Singh	1,982.17	1,982.17	(40) Ajit Singh, son of Bahadur	986.44
Nishan Singh	500.70	500.70	(41) Mohan Singh , son of Isher Singh	592.00
Nishan Singh	867.58	867.58	(42) Waryam Singh, son of Dult kingh	412.31
Jangir Singh	662.15	662.15	(43) Mahant Singh, son of Kishan Singh	308.27
Tirlok Singh	1,610·76	1,610·76	(44) Kapur Singh, son of Ujaggar Singh	433.00
Inder Singh	392·39	392·39	(45) Chandan , son of Mam Maru	206.91
Sheo Singh	664·54	664·54	(46) Uiagar Singh, son of Khushal Singh	495.36
Jiwan Singh	845·90	845·90	(47) Fateh Singh, son of Wadhawa Singh	2,284·38
Balkar Singh	853·04	853.04	(48) Bishana, son ofHaria	2,681.13
Khajan Singh	828·14	828·14	(49) Kapoor Singh, son of Ujaggar Singh	43,3·03
Makhan Singh	391·19	391·19	(50) Naranjan Singh, son of Inder Singh	515.78
Pritam Singh	1,013·10	1,013.10	(51) Ramesh son of Harsarup	459.55
Bawa Singh	675·41	675.41 5	(52) Kartar Singh, son of Munshi	125.08
Singara Singh	1,609·02	1,609.02	(53) Raja, son of Partapa	4,009.39
Thakar Singh	145·82	145·82	(54) Kapoor Singh, son of Ujaggar	436·19
Ram Chander	419·74	419·74	(55) Kishan Singh, son of Inder Singh	603·95
Mela Singh	299·63	299·63	(56) Sadha Singh, son of Surjon Singh	451.45
..	392·64	...	(57) Birkha Ram, son of Ganga Ram	1,014·54

[Revenue Minister]

Tehsil Thanesar—*contd*

A

S. No.	Name of village	Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Date of issue
58	Shahabad	.. Pritam Singh, son of Kishan Singh	10-3-65
59	Padlu	.. Iqbal Singh, son of Kesar Singh	10-3-65
60	Dhakala	.. Khushal Singh, son of Sham Singh	10-3-65
61	Kheri Brahman	.. Mehga Ram, Lambardar	25-3-65
62	Thaska Ali	.. Hardev Singh, son of Gurdial Singh	29-3-65
63	Ajrana Khurd	.. Banta Singh, son of Jagat Singh	1-4-65
64	Barri	.. Gurbachan Singh, son of Phaza Singh	2-4-65
65	S	.. Gurdial Singh, son of Phaga Singh	2-4-65
66	Soli Kalan	.. Mohinder Singh, son of Nathu Singh	8-4-65
67	Dabkheri	.. Kulwant Singh, son of Bakhis Singh	21-4-65
68	Kesani	.. Milkha Singh, son of Sunder Singh	23-4-65
69	Sumalka	.. Hari Singh, son of Sobha Singh	23-4-65
70	Lakhmari	.. Shingara Singh, son of Surdual Singh	24-4-65
71	Shahabad	.. Bhola Singh , son of Alla Singh	25-3-65
72	..	..	..
73	..	..	..
74	..	..	..
75	..	..	..
76	..	..	..
77	..	..	..
78	..	..	..
79	..	..	..
80	..	..	..
81	..	..	..
82	..	..	..
83	..	..	..
84	..	..	..
85	..	..	..
86	..	..	..
87	..	..	..

Name of the loanee against whom warrant stands even to-day	Total amount outstanding 1st May, 1965	31st December, 1965	Names of the persons arrested from 1st January, 1965 to-date	Amount outstanding at the time of arrest
	Rs	Rs		Rs
..	750 ·69	750 ·69	(58) Inder Singh, son of Harnam Singh	1,030 ·93
Iqbal Singh ..	998 ·32	998 ·32	(59) Buta Singh, son of Bhagat Singh	885 ·72
..	190 ·37	..	(60) Langru Ram, son of Bali Ram	723 ·56
Mehnga Ram	1,617 ·29	1,617 ·29	(61) Siri Krishan, son of Brij Lal	667 ·06
Hardev Singh	274 ·82	274 ·82	(62) Nathu Ram, son of Mansa Ram	1,185 ·56
..	486 ·30	..	(63) Mehan Chand, son of Sant Ram	1,893 ·87
Gurbachan Singh	555 ·82	555 ·82	(64) Balwant Singh, son of Bhagwan	370 ·87
Gurdial Singh	279 ·41	279 ·41	(65) Kirpal Singh, son of Pritam Singh	989 ·37
Mohinder Singh	2,174 ·02	2,174 ·02	(66) Dayal Singh, son of Telu Ram	719·7
Kulwant Singh	1,982 ·28	1,982 ·28	(67) Daulat Ram, son of Datu	453 ·63
..	593 ·30	..	(68) Nirmal, son of Devi Dayal	94 ·38
..	340 ·96	..	(69) Maya Singh, son of Prem Singh	903 ·17
..	150	..	(70) Mangal Singh, son of Sunder Singh	751 ·40
Bhola Singh	2,945 ·07	2,945 ·07	(71) Hira Nand, son of Kewal Ram	58 ·53
..	..	..	(72) Banarsi Dass, son of Datu	108 ·06
..	..	..	(73) Sadhu, son of Bira	279 ·44 244
..	..	..	(74) Dewa Singh, son of Hari Singh	2,033 ·48
..	..	..	(75) Pohen, son of Nagar	981 ·34
..	..	..	(76) Jangir Singh, son of Inder Singh	368 ·75
..	..	..	(77) Mangat, son of Chhittar	368 ·90
..	..	..	(78) Puran, son of Kundan	1,184 ·18
..	..	..	(79) Harphul Singh, son of Bakhatwar	871 ·38
..	..	..	(80) Jangri Singh, son of Sohan Singh	733 ·00
..	..	..	(81) Sher Singh, son of Buta Singh	263 ·62
..	..	..	(82) Mansa Singh, son of Krishana	963 ·90
..	..	..	(83) Kalu Ram, son of Kishouri	663 ·20
..	..	..	(84) Nathu, son of Partapa	244 ·37
..	..	..	(85) Ram Partap, son of Gainda	744 ·30
..	..	..	(86) Mehar Singh, son of Bhola Singh	136 ·40
..	..	..	(87) Tara Singh, son of Sunder Singh	299 ·95

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of village	Name of lonees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Date of issue
88	..	..	..
89	..	..	..
90	..	..	..
91	..	..	..
92	..	..	..
93	..	..	..
94	..	..	..
95	..	..	..
96	..	..	..
97	..	..	..
98	..	..	..
99	..	..	..
100	..	..	..

B	D		E	E
Name of the loanee against whom such warrants stand even today	Total amount outstanding on 1st May, 1965 to 31st December, 1965		Names of the persons arrested from 1st January, 1965 to date	Amount outstanding at the time of arrest
	..	..	88. Sohan Singh, son of Nathu	299·90
..	..	..	89. Labh Singh, son of Assa Singh	172·05
..	..	..	90. Mehar Singh, son of Uttam Singh	151·45
..	..	..	91. Sujan Singh, son of Hira Singh	387·71
..	..	..	92. Megh Singh, son of Manger Singh	233·00
..	..	..	93. Fauja Singh, son of Gurdeep Singh	294·00
..	..	..	94. Bhan Singh, son of Bhagat Singh	93·00
..	..	..	95. Ram Kishan, son of Hirda Ram	208·20
..	..	..	96. Ghasita Ram, son of Rohela	380·75
..	..	..	97. Ramji Lal, son of Santu	257·00
..	..	..	98. Munshi, son of Santu	611·21
..	..	..	99. Ram Nath, son of Nanaku	1,594·66

[Revenue Minister]

TEHSIL KAITHAL

Serial No.	Name of the loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Date of issue of warrants	Names of the said loanees against whom the said warrants stand even today	*The total amount outstanding against each loanee as on* 1st May, 1963	*The total amount outstanding against each loanee as on* 31st December, 1965	The names of the persons arrested by the Revenue authorities during the period from 1st January, 1965, to date together with the amount which was outstanding against each such defaulting loanee at the time of arrest: Name	Amount
	A		B	D		F	[illegible]
				Rs	Rs		Rs
1	Mehar Singh, son of Kartar Singh, of Assandh/Dussain	14-10-64	..	6,715.20	..	Haria, son of Kalu, of village Beg Pur	524.04
2	Iqbal Singh, son of Mehla Singh, surety of Kartar Singh, Sangrauli	19-10-64	Iqbal Singh, son of Mehla Singh	2,342.37	1,822.50	Tota Singh, son of Sohan Singh, Mandhwal	625.00
3	Ganga Bishan, son of Hoshiara, of village Behri	30-10-64	Ganga Bishan	6,655.00	700.00	Siri Ram, son of Netu, village, Jajan Pur	339.76
4	Kishan Singh, Bakhtawar Singh, sons of Man Singh of village Rajond	25-11-64	Kishan Singh etc.	7,087.50	7,087.50	Gurnam Singh, son of Pritam Singh, Bodha	877.50
5	Ram Chand, Girdhari Lal, sons of Sham Dass of Bhagana	4-12-64	..	6,682.50	..	Sunder Singh, son of Teja Singh, Masat Garh	381.62
6	Jita, son of Haria of village Rajond	1-12-64	..	229.53	..	Jagir Singh, son of Veryam Singh, Ramthali	73.80

7	Khazan Singh, Dhian Singh, son of Hukam Singh, sureties of Shrimati Piar Kaur of Rattan Khera Lukman	11-12-64	..	3,542.00	..	Ram Sarup, son of Kundan of Mandhwal	70.44
8	Sarmukh Singh, son of Jai Ram, of village Shah Pur	20-12-64	..	354.75	..	Ishar Singh, son of Prem Singh, of Bakhali	434.61
9	Kartar Singh, son of Sohan Singh, of village Sanjauli	2-2-65	Kartar Singh	2,402.00	1,822.50	Kartar Singh, son of Kishan Singh, of Sultania	37.72
10	Sadha Singh, son of Waryam Singh, of Sanjauli	2-2-65	Sadha Singh	2,500.00	1,485.48	Kartar Singh, son of Basawa Singh, Shadi Pur	154.13
11	Haria, son of Kalu, of village Beg Pur	11-2-65	..	524.04	..	Bhan Singh, son of Gainda Singh, Shadipur	128.30
12	Jaswant Singh, son of Sharam Singh, of Gumthala Garhu	26-2-65	..	331.40	..	Joginder Singh, son of Achhat Singh, of Mahmood Pur	123.41
13	Om Parkash, son of Netu, of village Jajan Pur	2-3-65	..	216.40	..	Khan Chand, son of Ganga Ram Kangthali	338.78
14	Siri Ram, son of Netu of village Jajan Pur	2-3-65	..	339.76	..	Gurmukh Singh, son of Maggar Singh, Kaithal	109.56
15	Munshi, son of Tota of Chandlana	2-3-65	Nil	193.81	..	..	..
16	Gurbachan Singh, son of Buta Singh. of village Habri	15-3-65	..	1,171.90	..	Amar Singh, son of Singh Ram, Bhainshi Majra	227.57
17	Yadvinder Singh, village Kh Majra	17-12-64 / 24-3-65	..	888.47	..	Phool Singh, son of Jati, of Teukar	943.35
18	Lila Ram, son of Gita Ram of Village Khan Pur Roran	20-3-65	Lila Ram	1,433.00	1,433.00	Tara Singh, son of Hari Singh of Kaurtan	662.25
19	Baghail Singh, son of Kara Bhag Singh, village Bhonslan	24-3-65	Bhagail Singh	293.57	51.30	Puran Singh, son of Achhar Singh, of Kaurtan	1,164.42

[Revenue Minister]

	A	B		C	D	E	
				Rs	Rs		Rs
20	Kashmir Singh, son of Karam Singh, Bhonslan	24-3-65	..	267.73	..	Surain Singh, son of Achhar Singh, of Kaurtan	116.76
21	Bhag Singh, son of Daya Singh, of Bhonslan	24-3-65	..	394.64	..	Manga Singh, Jhanda Singh of Mangna	249.01
22	Jhanda Singh, son of Dula Singh, of Bonslan	24-3-65	Jhanda Singh	531.44	317.55	Avtar Singh, son of Sardara Singh, Kaithal	1,402.84
23	Phulla Singh, son of Sohan Singh, of Bhonslan	24-3-65	Phulla Singh	270.18	42.48	Bhag Singh, son of Sant Ram, Kaithal	104.31
24	Ujjagar Singh, son of Gokal, of village Bhonslan	24-3-65	..	55.82	..	Bag Ram, son of Sant Ram, of Kaithal	104.31
25	Dalip Singh, son of Jit Singh of village Bhonslan	24-3-65	..	313.06	..	Gajjan Singh, son of Veer Singh, Kheri Daban	129.35
26	Ram Singh, son of Surjit Singh, of Bhonslan	24-3-65	..	246.94	..	Rai Pathor, son of Sarpanoh, Kakot	1,356.03
27	Kartar Singh, son of Sher Singh, of Bhonslan	24-3-65	..	293.46	..	Lachhman Singh, son of Ganga Singh, Bodhani	122.28
28	Gurnam Singh, resident of village Bodha	29-3-65	..	877.50	..	Tara Singh, son of Telu of Rajound	238.29
29	Amar Nath, son of Sunder Dass, of Sayana Saidan	29-3-65	..	144.34	..	Dalip Singh, son of Boor Singh, of Sailu Majra	129.21
30	Guljar Singh, son of Kishan, of village Beg Pur	2-4-65	..	625.00	625.00	Shiv Ram, son of Har Dayal of Rohera	104.31
				1,236.00	..		
31	Prem Singh, son of Bur Singh of Mandhwal	24-4-65	Prem Singh	625.00	625.00	Darshan Singh, son of Narain Singh, Pehowa	382.98
32	Pritpal Singh, son of Ishar Singh of Mandhwal	24-4-65	Pritpal Singh	625.00	625.00	Boota Singh, son of Narain Singh, Gaggar Pehowa	314.46
33	Ram Sarup, son of Kundan of, Sandil	29-4-65	..	70.44	..	Joginder Singh, son of Lakha Singh, Gaggar	314.46

Tehsil Panipat

Serial No.	Names of loanees against whom warrants stood on 1st May, 1965	Date of issue of warrants	The names of the loanees against whom said warrants stand even today	The total amount outstanding on 1st May, 1965	31st December, 1965	Persons arrested by the Revenue Officers from 1st January, 1965 to-date	Amount outstanding at the time of arre
	A	B	C	D		E	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rs	Rs		
1	Ram Kishan, son of Badlu Babail	16-1-65	Ram Kishan, son of Badlu	254.82	254.82	Bhola, son of Bhatt Singh	736.09
2	Nand Lal, son of Hazara Ram, Patti Kalina	13-2-65	Nand Lal, son of Hazara Ram	643.65	643.65	..	..
3	Piara Lal, son of Gehna Ram, Kalina	18-2-65	Piara Lal, son of Gehna Ram	616.47	616.47	..	..
4	Gian Chand, son of Wasawa Ram Kalina	18-2-65	Gian Chand, son of Wasawa Ram	1,065.08	1,065.08	..	..
5	Raghbir Singh, son of Rattan Chand, Razapur	22-2-65	Raghbir Singh, son of Rattan Chand	302.61	302.61	..	..
6	Chaman Lal, son of Sunder Dass Panipat	11-3-65	Chaman Lal, son of Sunder Dass	1,895.00	500.00	..	..
7	Charan Dass, son of Sadhu Urlana Kalan	11-3-65	..	600.00	..	..	..
8	Ram Chander, son of Lehna Ram Patti Kaliyana	15-3-65	Ram Chander, son of Lehna Ram	1,019.28	1,019.28	..	..

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of the loanees against whom warrants stood on 1st May 1965	Date of issue of warrants	Names of the loanees against whom said warrants stand even today	The total amount outstanding on 1st May, 1965	The total amount outstanding on 31st December, 1965	Persons arrested by the Revenue officers from 1st January, 1965	Amount outstanding at the time of arrest
9	Bhola Ram, son of Bharat Singh, Babail	16-7-65	Bhola Ram, son of Bhart Singh	736.09	200.00	..	..
10	Ranbir Singh, son of Herphul Babail	19-5-65	..	504.25	..	..	..
11	Sher Singh, son of Buta Ram, Panipat	23-3-65	..	5,000.00	..	..	..
12	Tehal Singh, son of Banta Ram Baholi	24-3-65	Tehal Singh, son of Banta Ram	487.55	487.55	Tehal Singh, son of Banta Singh	487.55
13	Jarnail Singh, son of Banta Singh, Baholi	24-3-65	Jarnail Singh, son of Banta Singh	995.13 240.44	995.13 240.44	..	..
14	Bhagwan Singh, son of Ladha Singh	24-3-65	Bhagwan Singh, son of Ladha Singh	487.55	487.55	..	..
15	Santa Singh, son of Kushal Singh. Baholi	24-3-65	Santa Singh, son of Kushal Singh	240.44	240.44	..	..
16	Nand Singh, son of Deva Singh, of Baholi	24-3-65	Nand Singh, son of Dewa Singh	240.44	240.44	..	..
17	Thakar Singh, son of Jodha Singh of Baholi	24-3-65	..	240.44	240.44	Thakar Singh, son of Jodha Singh	240.44
18	Sada Nand, etc., Jaipar ..	5-4-65	..	1,704.82	..	..	..
19	Bhulan, son of Harkesh Ujha	24-4-65	..	633.65	..	..	..
20	Ram Singh, son of Dai Ram Nimbri	24-4-65	..	465.11	465.11	..	..
21	,son of Lal Chand	24-4-65	..	516.16	..	..	..
22	Dhan Singh, son of Bali ..	24-4-65	..	471.76	..	..	..
23	Narjan Singh, son of Fateha Singh Ujaha	28-4-65	Narjan Singh, son of Fateh Singh	272.53	272.53	..	..

Boys Hostel in the Campus of Kurukshetra University

*9798. **Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister had inaugurated a Boys' Hostel in the Campus of the Kurukshetra University early in 1965 ;

(b) whether he is aware of the fact that the Hostel was put to use six months after the said inauguration ;

(c) whether he is aware of the fact that a sum of Rs 5,000 or more was spent by the University on the inaugural ceremony against the explicit instructions of the University Grants Commission to the effect that no such function should involve any expense exceeding Rs 500 in all ; if so, the action taken by Government in the matter ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) The Hostel was intended for use in the Academic Session 1965-66, i.e., from July, 1965.

(c) Expenditure incurred on this function was Rs 3,994.90. The University is not aware of any such instructions issued by the University Grant Commission.

Amalgamation of House and Property Tax

*8946. **Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

(a) whether Government has finalised any scheme for the amalgamation of the House and the Property Taxes in the State ; if so, the details of the scheme ;

(b) whether Government have called for the comments of the different Municipal Committees in this regard ; if so, the details of the comments, if received ?

Sardar Kapoor Singh ; (a) Part (I) The matter is under consideration.

Part (II) The details of the scheme will be supplied as and when it is finalised.

(b) Part (I) No.

Part (II)—Question does not arise.

Middle Schools in Tehsil Kaithal, District Karnal

*9253. **Shrimati Prasanni Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Middle Schools in tehsil Kaithal, district Karnal, at present ;

(b) the names of the Headmasters posted in each of the schools referred to in part (a) above together with their present salaries and grades of pay ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 40.

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

[Minister for Education]

Statement containing information required by Part (b) of the question

Names of Headmasters of Government Middle Schools working in tehsil Kaithal (Karnal) together with their present salaries and grades of pay.

Serial No.	Name of Government Middle School	Name of the Head-master (Boys Schools)	Present Pay	Grade
				Rs
1	Agondh ..	Shri Darshan Singh	110	110—8—190/10—250
2	Arnauli ..	Shri Ranjit Singh I/C	85	60—4—80/5—100/5—175
3	Bhagal ..	Shri Vishnu Datt I/C	100	60—4—80/5—100/5—175
4	Bahri ..	Shri Om Parkash	110	110—8—190/—10—250
5	Baraut ..	Shri Amar Singh I/C	135	60—4—80/5—100/5—175
6	Bhana ..	Shri Bhalla Singh	158	110—8—190/10—250
7	Bakhli ..	Shri Om Parkash	150	110—8—190/10—250
8	Bhir Saidan	Shri Karam Singh	190	110—8—190/10—250
9	Chandana ..	Shri Avtar Singh	110	110—8—190/10—250
10	Dahola ..	Shri Manga Ram	174	110—8—190/10—250
11	Deeg ..	Shri Ranjit Singh I/C	95	60—4—80/5—100/5—175
12	Dhilowal ..	Shri Tirath Dass I/C	90	60—4—80/5—100/5—175
13	Deoban ..	Shri Pyare Lal	110	110—8—190/10—250
14	Dhatrat ..	Shri Om Parkash I/C	76	60—4—80/5—100/5—120
15	Guhna ..	Shri Sunder Singh	134	110—8—190/10—250
16	Harsola ..	Shri Dhanpat SinghI/C	68	60—4—80—5—100/5—175
17	Jadaula ..	Shri Ranjit Singh	110	110—8—190/10—250
18	Kheri Sharaf Ali	Shri Hazara Singh,I/C	110	60—4—80—5—100/5—175
19	Kher Majra	Shri Tara Chand	174	101—8—190/10—250
20	Khakaut ..	Shri Ram Kishan	126	110—8—190/10—250
21	Ladana Baba ..	Shri Manohar Lal Wadhawa	142	110—8—190/10—250
22	Naina Dhos ..	Shri Laxmi Narain	190	110—8—190/10—250
23	Nawach ..	Shri Narain Dass I/C	110	110—8—190/10—250
24	Pharral ..	Shri Laxmi Narain	145	110—8—190/10—250
25	Pegan ..	Shri Mahi Pal	174	110—8—190/10—250
26	Pai ..	Shri Jagdish Rai	134	110—8—190/10—250
27	Pahnawa ..	Shri Yash Pal	142	110—8—190/10—250

Serial No.	Name of Government Middle School	Name of the Head-Master (Boys Schools)	Present Pay	Grade
28	Rahara ..	Shri Gopal Dass, I/C	95	60—4—80/5—100/5—175
29	Rohera ..	Shri Hari Singh	110	110—8—190/10—250
30	Sarsa ..	Shri Shekhar Chand, I/C	200	140—10—220
31	Sisla Sismore	Shri Mangat Ram	126	110—8—190/10—250
32	Thana ..	Shri Om Parkash	174	110—8—190/10—250
33	Teontha ..	Shri Nahar Singh	110	110—8—190/10—250
		Government Girls Middle Schools		
1	Assandh ..	Smt. Sneh Lata Garg	174	110—8—190/10—250
2	Habri ..	Smt. Antu Ram I/c	76	60—4—80/5—100—5/175
3	Kaul ..	Smt. Sharabati Devi	150	60—4—80/5—100/5—175
4	Kichhana ..	Shri Lal Chand	174	110—8—190/10—250
5	Pundri ..	Smt. Sud ershan Vedehra		110—8—190/10—250
6	Rorar ..	Shri Banarsi Dass, Gupta I/C	95	60—4—80/5—107/5—172
7	Rajaund ..	Smt. Kusam Lata, I/C	94	60—4—80/5—100/5—175

Medicines received by Deputy Commissioner, Ferozepore, from Red Cross Society

***9069. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether it is fact that the Deputy Commissioner, Ferozepore, has taken medicines worth a large sum from the Red Cross Society ; if so, whether he was competent to take this free aid ?

Shri Ram Kishan : *First Part* : No

Second part : Does not arise.

Government Primary School, Jangpur, district Ludhiana

***8880. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to —

(a) lay on the Table of the House a list of the names of the teachers working in the Government Primary School, Jangpur, district Ludhiana as on the 31st August, 1964 and as on the 31st March,, 1965, separately ;

[Sardar Kultar Singh]

(b) state whether it is a fact that some transfers were effected from the said school during the period from the 31st August, 1964 to the 31st March, 1965 and that the persons so transferred were all girls ;

(c) state whether it is also a fact that the girls referred to in part (b) above were not asked to give their choice before their transfers ;

(d) state the reasons for which the said transfers were considered necessary and the justification for posting the teachresses away from their villages ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A list showing the names of Teachers working in Government Primary School, Jangpur (Ludhiana) is laid on the Table of the House.

(b Yes.

(c) Yes.

(d) These women teachers had to be shifted on administrative grounds.

However, to avoid any inconvenience to them, they have been accomdated near about Jangpur.

List showing the names of the Teachers working in the Government Primary School, Jangpur, district Ludhiana, on 31st August, 1964 and 31st March, 1965.

31st August, 1964.

1. Shrimati Bishan Devi.
2. Shrimati Harcharan Kaur
3. Shrimati Gurdial Kaur.
4. Shrimati Jagdish Kaur.
5. Shrimati Kartar Kaur.
6. Shri Jaginder Singh.
7. Shri Gurmail Singh.

31st March, 1965.

1. Shrimati Bishan Devi.
2. Shrimati Harcharan Kaur.
3. Shrimati Ram Kaur.
4. Shri Bhan Singh.
5. Shri Haquiquat Singh.
6. Shri Jaginder Singh.
7. Shri Gurmail Singh.

Retrenchment in Consolidation Department

***9636. Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of the Patwaris, the Kanungos, the Assistant Consolidation Officers, and Consolidation Officers so far retrenched from the Consolidation Department ?

Sardar Harinder Singh Major : No Kanungo/Inspector, Assistant Consolidation Officer and Consolidation Officer has been retrenched from the Consolidation Department in the recent reduction. 419 Patwaris/Sub-Inspectors have been retrenched.

Duties performed by Certain Lecturers in Physics Simulataneously in two Colleges.

***9463. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether some of the Lecturers in Physics worked in two colleges simultaneously, namely (i) the Randhir Government College, Kapurthala and (ii) the National College, Sathiala, during the years 1964-65 and 1965-66 ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the emoluments (pay and allowances) of the said lecturers from both the institutions, separately ;

(c) the distance between Sathiala and Kapurthala ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes, one from 21st October, 1964 to 31st March, 1965.

(b) Emoluments:—

Randhir College, Kapurthala		*National College, Sathiala*
Pay at Rs 215 per month D.A. at Rs 40 per month T.A. at Rs 25 per month	..	Remuneration at Rs 150 per month Pocket expenses as Rs 535.48 for the whole period.

(c) Twenty miles approximately.

Teaching Agriculture in Government Basic Training Institute, Mubarakpur, Tehsil Una, District Hoshiarpur

***9051. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government has made any arrangements to teach and impart practical knowledge regarding agriculture in the Government Basic Training Institute at Mubarakpur in tehsil Una, district Hoshiarpur ;

(b) whether any trained graduate in Agriculture has also been appointed to teach the subject of Agriculture ;

(c) whether any agricultural implements for this purpose have been supplied to the said Institution ;

(d) whether any irrigational facilities and land are available there for imparting adequate training in the subject ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) No. It is being taught by trained B.Ed. Masters, who are eligible and competent to teach Agriculture.

(c) Yes, arranged by students.

(d) Yes, a well and also a plot of land within the premises is available

---

Tenants faced with Ejectments at the hands of Big/Small Landowners

***9148. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Revenue with reference to the reply to Unstarred Question No. 2869, included in the List of Questions for 11th October, 1965 be pleased to state—

(a) whether the points which were under the consideration of the Revenue Department as stated in part (a) of the said reply have since been finally considered ; if so, when and with what result, and if not yet considered, the reasons for the same and the time by which these are likely to be considered finally ;

(b) whether the Government has finally considered the question of integrating the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, and the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955 which according to part (b) of the said reply was still under consideration ; if so, when and with what result ; if not yet considered, the reasons for the same and time likely to be taken to finally decide this issue ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) The points in question are still under consideration of the Revenue Department. Action in respect thereof for the amendment of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, and the PepsuTenancy and Agricultural Lands Act, 1955 will be taken along with other proposed amendments which are under consideration.

(b) The question ofintegrating the two Acts is linked up with the case of effecting amendments in the law. As the proposed measure is likely to have far reaching effects it will require scme more time to finalise.

Registrar, Kurukshetra University

***9878. Pandit Charanji Lal Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Chief Minister wrote to the Vice-Chancellor, Kurukshetra University, some time in early 1964 suggesting that the services of the Registrar of the University should be dispensed with ;

(b) whether the present Chief Minister wrote to the Vice-Chancellor of the Kurukskhetra University tnat the services of the Registrar mentioned in part (a) above should not be extended ?

Shri Prabodh Chandra : It is not in the public interest to give a reply to this question ?

Verka Milk Plant

***8971. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state—

(a) the total cost of the land and building of the Verka Milk Plant ;

(b) the rate at which the milk processed at the said plant is being sold, quality-wise ;

(c) the rate at which the cow and buffalo milk is being purchased for the said Plant ;

(d) the average daily production of butter and ghee together with the quantity of milk processed daily at the said plant;

(e) the rate at which butter and ghee referred to in part (d) is being sold ?

Captain Rattan Singh .. (a) Rs 22,57,840.

(b) Whole milk .. 90 paise per litre.

Toned milk .. 62 paise per litre

(c) No. cow milk is being purchased. The minimum basic price for buffalo milk containing 6.2 per cent of butter fat is Rs 24.00 per 40 Kg. The basic price is also increased by 2 paise per Kg. if individual suppliers supply 40 Kgs. or more and Cooperative Societies of milk producers supply 100 Kg. or more and indvidual contractors 400 Kg. or more per day. Contractors, who were operating creameries previously and held licenses for this purpose are being allowed 4 paise per Kg., as a special case.

(d (i) Milk processed 34,592 Kgs.
(ii) Butter .. 822 Kgs.
(iii) Ghee .. 382 Kgs.

(e) *Butter*—Rs 9.50 Kg.
Ghee—2 Kg. tin Rs 20,00
4 Kg. tin Rs 39.50

PERSONAL EXLANATION BY SARDAR LAKHI SINGH CHAUDHRI

ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ **ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ** : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ० ਐਸ० ਆਰ० ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਨ ਦੇ ਰੂਲ ਨੰ: 5.58 ਹੇਠ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰੀਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੀਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

CALL ATTENTION NOTICES

Serial No. 43

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ **ਸਿੰਘ** ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਮੁਤੱਲਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਥ ਦੀ ਤਰਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪਿਛੇ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਹ ਹਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਰਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Yes, it is admitted.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੋਈ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ I will make enquiries whether it is a fact or not.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਟੀਗਾਰੀਕਲੀ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸੈੱਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.........

Mr. Speaker : The honourable Minister has promised to make enquiries into the matter. What more does the honourable Member want ?

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਸੀ . . . .

श्री अध्यक्ष : श्री तरसिक्का, आप को शायद मालूम नहीं कि यहां अब यह फैसला किया गया हुआ है कि एक दिन में दो काल एटैनशन नोटिसज़ से ज्यादा नहीं लिए जाएंगे और वह भी वही लिए जाएंगे जो एडमिट किए गए हों। इस लिए जो दो पहले एडमिट किए गए हैं उन को लाने की इजाज़त दी गई है। (The hon. Member Com. Tarsikka is, perhaps, not aware that it has now been decided not to take up more than two call attention notices a day and also that only such of these motions would be taken up as have been admitted. That is why the first two call attention notices, which had been admitted, have been taken up today.)

(*Serial No.* 44)

Comrade Shamsher Singh Josh : I beg to draw the attention of the Government to a communication by President, Municipal Committee Chheharta, Amritsar, dated 19th February, 1966, D.O. No. 316, regardineg payment of compensation to the families of those who lost their lives during Pak-Bombing at Chheharta on 29th September, 1965. The families of earning hands were paid compensation at the rate of Rs. 1,500 each family but the families of 12 unearning dead hands have not been paid any compensation so far. General expectation of the public has been that some financial help would be given by the Government to the families of uneaning dead persons as well although the same may not be Rs. 1,500 per case. State Government is hereby asked to do the needful in the matter at the earliest.

Mr. Speaker : This is admitted.

मुख्य मंत्री : इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਰ ਇਹ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.........

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਇਹ ਬੜਾ ਐਹਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ..........

Mr. Speaker : Mr. Tarsikka, please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ.........

Mr. Speaker : Please take your seat.

Let us now take up the next item. This is in regard to the Punjab Panchayat Samities and Zila Parishads (Amendment) Bill.

ADJOURNMENT MOTION

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ।

Mr. Speaker : I have disallowed it.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸ ਐਲਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.....

Mr. Speaker : Order Please.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਕ ਏਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਲ੍ਹ ਇਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸੀ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ...........

Mr. Speaker : Please take your seat. Sardar Lachhman Singh, please take your seat

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਔਰ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਅਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ............

Mr. Speaker : Sardar Lachhman Singh, please take your seat. Order please.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ...........

Mr. Speaker : Order please. Sardar Lachhman Singh, will you please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ.........

Mr. Speaker : Order please. Take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਕਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਗਰੁਪ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਦ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ...........

Mr Speaker : Comrade Josh, order please. Please take you se at.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਨ ਸੰਘ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪਏ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਔਰ ਹਰੀਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ..........(ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Will you please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ........

Mr. Speaker : Please take your seat

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ । ਬੜੀ ਸਿਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ...... ..... (ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (*Interruptions by some Members from the Akali Party*) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਧੀਰਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ..........(ਵਿਘਨ) ਇਹ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ citadel ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਂਮਰਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ worth the name Government ਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਆ ਗਈ। (The hon. Member may now resume his seat. His point has come.)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, कल जो स्टेटमैंट हाउस के अन्दर चीफ मिनिस्टर साहिब ने दिया उस पर किसी को एतराज़ हो या न हो मगर जो एडजनमैंट मोशन आप ने डिसएलाऊ की है तो उस पर जब कुछ दोस्तों ने कोई प्वायंट आप से क्लैरीफाई करवाने की कोशिश की तो इधर से और उधर से भी इन्टरप्शन्ज़ होने लगीं। इस से जाहिर है कि यह जो स्टेटमैंट था यह परीपलैन्ड था और इस का फैसला पहले किया हुआ था (विघ्न) इस तरह से यह पंजाब के अन्दर आग लगाना चाहते हैं। जब केबिनट सब कमेटी बनी हुई है तो उस सूरत में ऐसे हालात पैदा करना और जानबूझ कर किसी को भूख हड़ताल पे बैठाना कहा तक जायज़ है? मैं जानता हूं कि जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वह कैसे आदमी हैं और वह कहां तक पहुंचेगे। (विघ्न) जब सैंट्रल गवर्नमैंट ने अभी तक फैसला नहीं दिया तो मैं आप का रूलिंग चाहता हूं कि क्या यह ऐसा इनीशियेटिव ले सकते हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का स्टेटमैंट दे सकते हैं जिस से कि सूबे में बाहर आग लगे। इस आग लगने का सबूत यह हैं कि यह हाउस भी परटर्बड है और सभी लोग इस बात को बुरी तरह से महसूस करते हैं। (विघ्न) यही सभी लोग कहते थे कि हमें किसी को न एग्जैक्टिव को पता था कि ऐसा स्टेटमैंट आयगा। इन्होंने किसी को कनसल्ट भी नहीं किया। क्या यह ऐजीटेशन को दबा लेंगे जब कि सरदार प्रताप सिंह कैरों भी इस को न दबा सके? (विघ्न) मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि क्या किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह की स्टटमैंट जो कि सूबे में एक प्लैनड तरीके से इंटरफियरेंस करती हो यहां पर आ सकती है? यह मामूली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (Now he may resume his seat)

चौधरी देवी लाल : इस वक्त हरियाणा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और पंजाबी सूबा के लोग अपना-अपना सूबा मांगते हैं और यह उन के लिये जिन्दगी और मौत का सवाल है। क्या यह अपनी डौमीनेशन के बल-बोते पर इसके रास्ते में खड़े हो सकते हैं। इस को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यह ऐसी कोशिश करेंगे तो मैं आप के ज़रिये इन को वार्निंग देना चाहता हूं कि इस मामले में अकाली अकेले नहीं हैं, तमाम हरियाणा प्रांत इन की पुश्त पर है, तमाम रिपब्लीकन पार्टी इन की पुश्त पर है, कम्यूनिस्ट पार्टी इन की पुश्त पर है और यह बात इन इलाकों की तमाम पार्टियां चाहती हैं। तो जब मियां बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी? यह इस में रुकावट डाल कर पंजाब में फसादात करवाना चाहते हैं। (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਦ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। (The hon. Member may please take his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿਘ : ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ। (ਵਿਘਨ) ਸਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। (ਵਿਘਨ)

****

****

****

---

*Note : Expunged as ordered by the Chair.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। (ਸ਼ੋਰ) (The hon. Member may please take his seat.) (*Noise*.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ? ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਮਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਵਾਂਗੇ।

श्री अध्यक्ष : देखिए अगर तो कुछ मैम्बरान डिटरमिन्ड हैं कि कार्यवाही नहीं चलने देनी तो हाउस को एडजर्न किया जा सकता है। (शोर) जो रिफ्लेकशन श्री नन्दा पर की गई है (विघन) वह beyond the scope of this House है इस लिए एक्सपंज की जाती है। (The hon. Member may please listen. If some of them are determined to obstruct the proceedings then the House can be adjourned. (*Noise*) Any reflection that were cast on Shri G. L. Nanda, are beyond the scope of this House and (*Interruptions*) therefore stand expunged.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of order, Sir. ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫਜ਼ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੀਸ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। (ਸ਼ੋਰ)..........

Mr. Speaker : The House stands adjourned for half an hour.

10.45 A.M.

The Sabha adjourned at 10.45 a.m. and re-assembled at 11-15 a.m.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ।

श्री अध्यक्ष : वह जो स्टेटमैंट चीफ मिनिस्टर साहिब ने कल दिया था उस के बारे में किसी एडजर्नमैंट मोशन या किसी प्वाइन्ट आफ आर्डर की इस वक्त इजाजत नहीं दी जा सकती। (No adjournment motion or a point of order can now be allowed on the statement made by the Chief Minister yesterday.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਉ। ....(ਵਿਘਨ) ਸ਼ੋਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਸਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਤੇ

ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁਪ ਦਾ ਪਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਤੇ ਚਲੋ । (Now I would like to make a submission to the hon. Members that in connection with the statement made by the Chief Minister yesterday neither any Adjournment Motion can be moved nor that statement can be the basis of such a motion. If the hon. Members think that making of this statement was not propor then their opinion can differ from others. So in this connection the remedy open to them is to bring a "no confidence" motion against the Government or move a censur motion against it. General discussion on the Budget is on and will continue for another three days. They can express the point of view of their groups in one way or the other during the general discussion. Now I would appeal to all to take up the next item on the agenda.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ . ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ-ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਤਾ.......

Mr. Speaker : No point of order. Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ । * * * * * * * * * * * * । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please. Take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : * । (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please. Sardar Ajaib Singh Sandhu, please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰਖ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ........... (ਵਿਘਨ)

Mr Speaker : Order please. Sardar Ajaib Singh may please take his seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੋਅਰ ਸੀਟ । ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ? (Sardar Ajaib Singh Sandhu may please take his seat. Why is he speaking without permission?).

*Expunged as ordered by the Chair.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ (*)

Mr. Speaker : Please take your seat. (ਸ਼ੋਰ) ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ । (Order please. Any words used by Sardar Ajaib Singh Sandhu against Shri Nanda Ji, Home Minister or Government of India, will not form part of the proceedings.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ..........

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ...........(ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ।

The hon. Member, Sardar Ajaib Singh Sandhu, is obstructing the proceedings of the House. I, therefore, order him to withdraw from the House. (The hon. Member Sardar Ajaib Singh Sandhu is not taking his seat in spite of my repeated warnings. He is obstructing the proceedings of the House. I, therefore, order him to withdraw from the House.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਉਹ ਤਾਂ obey ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं आप की रूलिंग इस बात पर चाहता हूं कि आप के कहने से पहले जब कि सरदार अजायब सिंह संधू बैठ गए हैं तो किस बात पर आप ने इन को बाहर जाने का हुक्म दिया है ? किस तरह से वह प्रोसीडिंग्ज़ को आब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ?

---

*Note—Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Speaker : When I order an hon. Member to stop, he is to stop. If he does not obey thte Chair, he obstructs the proceedings.

ਮੇਰੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਫਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ । (Sardar Ajaib Singh Sandhu despite my warning him ten or twelve times, failed to resume his seat, that is why I have ordered him to withdraw from the House.) (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਉ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਇਟਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (That is right. I have already submitted to the Members that no point of order can be raised in connection with this statement; now this matter should be closed and the House should proceed with the next item on the agenda.) (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

चौधरी नेत राम : आन ए पवायंट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : आप चौधरी नेत राम जी बैठ जाइए । (The hon. Member Chaudhri Net Ram may please take his seat.)

चौधरी नेत राम : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि कल आप ने हुकम दिया था कि हर ग्रुप में से एक मैंबर को सवाल पूछने का हक है तो क्या मुझे सवाल पूछने का हक नहीं है ? मैं सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । नो प्वायंट आफ आर्डर पलीज़ । (The hon. Member may take his seat. No point of order please.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Order please.

श्री इन्द सिंह मलिक : आन ए पवायंट आफ आर्डर, सर। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आप ने किस बात पर सरदार अजायब सिंह संधू को नेम किया है जब कि उस ने आप का हुकम मान लिया और बैठ गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री मलिक, क्या वह बात भी आप को बतानी पड़ेगी कि किस बात पर सरदार अजायब सिंह संधू को नेम किया गया (विघ्न) आर्डर प्लीज़ । (Will it have to be explained to the hon. Member, Shri Inder Singh Malik as to why Sardar Ajaib Singh Sandhu has been named ?) (*Interruption*) (Order please.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ।..........

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਆਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਟ ਦੇਣ। ....(ਵਿਘਨ)

Mr Speaker : Order please, take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਉ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।...........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੋਅਰ ਸੀਟ। **(Please take your seat.)**

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ..........

Mr. Speaker : Will the hon. Member please take his seat ? I am not allowing him to speak further.

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : I sit. But I again rise to say that the proceedings of the House are not being carried on properly.....

Mr. Speaker : I am not allowing the hon. Member to speak. He may please take his seat.

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : I sit to rise again.......

Mr. Speaker : I am not allowing the hon. Member to proceed with his speech.

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : I do sit. But I further rise.... *(noise)*.

Mr. Speaker : No further please. Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੋਅਰ ਸੀਟ। **(Please take your seat.)**

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ....(ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਚਲਣ ਦਿਉਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ? Next item please. (Order please, will the hon. Member let the proceedings to go on or not ? Next item please.)

Deputy Minister for Development and Irrigation and Power: (Sardar Gurmit Singh) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਟੀ ਹੈ . . . . (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ (Order please.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ । (Will the hon. Member sit down or not ?)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ । (The hon. Member Sardar Ajaib Singh Sandhu has said that he (Sardar Jagjit Singh Gogoani) will not resume his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ . . . . . . (ਵਿਘਨ ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੋਅਰ ਸੀਟ । (No point of Order. The hon. Member may please take his seat.)

श्री मोहन लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। ग्राप ने इस हाउस के एक ग्रानरेबल मेम्बर को इस हाऊस से विदडरा करने का हुक्म दिया था ग्रौर ग्रभी तक उस को इम्पलीमैंट नहीं किया गया ग्रौर कारवाई जारी है। यहां तक कि डिप्टी मिनिस्टर ने ग्रपनी एक मोशन भी मूव कर दी है। तो मैं ग्राप से, स्पीकर साहिब, जानकारी चाहता हूं कि जो ग्राप ने उस मेम्बर को विदड्रा करने का हुक्म दिया था उसको क्या हुग्रा ? ग्राप के दिये हुए हुक्म के मानने से पहले ग्रौर कोई कारवाई नहीं चल सकती . . . .

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ.........(ਵਿਘਨ) (I had ordered Sardar Ajaib Singh Sandhu to withdraw from the House but . . . (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਗਲਰ, ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੱਕੂ ਠਪਾਂਗੇ । ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਛੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ।

(Loud noise and furore in the house.)

Mr. Speaker : Order please.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: On a point of order, Sir. मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी इस हाउस के एक आनरेबल मैंबर ने दूसरे आनरेबल मेम्बर को चोर, डाकू, बदमाश, और समगलर तक के जो अल्फाज़ कहे हैं क्या कोई एक मैंबर किसी दूसरे मैंबर को कह सकता है। अगर नहीं तो यह विदड्रा करवाये जायें (विघ्न) ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़, मैं ने शोर शराबे में कुछ नहीं सुना । अगर आप ने सुने हैं तो बतायें कि किसने किसको कहे हैं ? (Order please. I did not hear any such thing in this uproar. If the hon. Member has heard these words then he may tell me as to who used them.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : यह शब्द सरदार अजायब सिंह ने सरदार जै इन्द्र सिंह को कहे हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ । ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ . . . .

Mr. Speaker: Order, order please.

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਗੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹਨ . . .

Mr Speaker: Order please. ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੋ । (Order please. The hon. Member Sardar Ajaib Singh may please withdraw the words he had used.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ' ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਜੀ । (He should also withdraw his words.)

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Please no aspersions. ਸਿਰਫ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ । (There should be no aspersions please. These words should be simply withdrawn.)

ਸਰਦਾਰ ਜੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਉਹ ਤਾਂ ਅਗ ਲਾਉ ਹਨ ।) Order Order, please. ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੋਸੀਡਿਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । (My submission is that the hon. Member Pandit Mohan Lal had raised a point. (Interruption) Order please. I had deliberately refrained from clarifying my order because according to Rules no discussion in any form or a point of order can be raised on a statement made by a Minister. As a matter of fact anything said in violation of the Rules would be expunged from the proceedings. But according to the convention obtaining in the Lok Sabha, instead of raising a discussion thereon, a Member of each party in the House can, of course, ask a question in this connection for purposes of clarification.)

चौधरी नेत राम : On a point of order, Sir. कल जो आप ने आर्डर किया था उस के मुताबिक क्या मैं सवाल कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखें । मैं ने यह भी कहा था कि बावजूद इस के कि रूल नं० 64 में कोई प्रोवीजन नहीं है कि स्टेटमैंट हो चुकने के बाद इस पर कोई क्वैसचन किया जा सके या कोई किसी तरह की आबजरवेशन की जा सके । फिर भी लोक सभा में एक कनवैनशन जरूर है कि हर पार्टी का एक मैंबर इस पर एक सावल कर सकता है । अगर आनरेबल मैंबर्ज चाहते हैं कि उस कानवैनशन को फालो किया जाये तो ऐसा हो सकता है । लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा कि जिसे मैं काल करूं वह स्पीच करनी शुरू कर दे । वह केवल एक सवाल बतौर क्लैरीफीकेशन के जरूर किया जा सकता है । (The hon. Member may please take his seat. I had also submitted that despite the fact that no provision under Rule 64 existed for asking any question or raising a discussion on a statement after it had been made by the Minister, a convention in the Lok Sabha did obtain that a Member from each party could ask one question about it. If the hon. Members want to follow that convention here also, then that can be done. But this would not be permitted that a Member, whom I call up to put a question, should start making a

[Mr. Speaker]

speech. He can of course, ask only one question for purposes of clarification.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ?

Mr. Speaker : Yes, the Minister can make a statement at any time.

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : But not irrelevant.....

Mr. Speaker : It is not for me to judge the merits of this statement.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब-----

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी नेत राम : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं स्टेटमेंट के बारे में।

Mr. Speaker Yes please.

चौधरी नेत राम : * ** **

** ** **

** ** **

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैंबर ने एक सवाल की शकल में स्पीच की है। इस लिए जो कुछ उन्होंने कहा है वह प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होगा। (The hon. Member has made a speech under the pretext of asking a question. Therefore, whatever he has said, will not from part of the proceedings.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ? (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please. It is for him to reply or not to reply.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : On a point of order, Sir, आप ने फरमाया कि हर ग्रुप का एक एक मैंबर सवाल पूछ ले। इस लिये जो भी सवाल किया जाता है उसका जवाब चीफ मिनिस्टर को देना चाहिये।

Mr. Speaker : If the Government does not want to reply, I cannot compel them.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Then what is the fun of putting these questions.

Mr. Speaker : It is for the Government to reply or not to reply.

*Expunged as ordered by the Chair

मुख्य मन्त्री : मेरे स्टटमैंट देने पर जो सवाल कामरेड शमशेर सिंह जोश ने किया है मैं समझता हूं कि अगर वह इसको गौर से पढ़ते तो इन को यह सवाल करने की जरूरत ही न पड़ती । इस में मैं ने साफ लिखा है कि–

"The Congress Working Committee and the Union Cabinet are also giving their best consideration to this problem. We can rest assured that the solution thus arrived at after cool and thorough deliberation will be in the best interests of the State and the Country,,

स्पीकर साहिब, मैं ने अपने उस बयान में कोई उसके हक में या खिलाफ बात नहीं कही है ।

सरदार लच्छमणसिंह गिल : मैं जालन्धर का पूछता हूं, वहां क्या कहा था ?

Mr. Speaker : I would request the hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill not to interrupt the hon. Chief Minister and allow him to complete his reply. There should be no interruptions in the House.

मुख्य मन्त्री : सारे पंजाब के लोगों के सामने एक रास्ता खुला है, हर एक की अपनी राए है । मेरी स्टेटमैंट का जो मन्जर है मैं उसके एक एक लफज़ पर कायम हूं । पंजाब में प्रेम, प्यार, मुहब्बत और एकता हो । पंजाब में ला एंड आर्डर कायम रहना चाहिये । जहां तक मेरी उस स्टेटमट का ताल्लुक है मेरी अब भी जबरदस्त खाहिश है कि पंजाब यूनाईटिड रहनी चाहिये । मेरी यह खाहिश है कि पंजाब यूनायटड रहना चाहिये और मैं ने वह स्टेटमैंट दिया है । मैं ने जब भी इस के मुताल्लिक स्टेटमैंट दिया है हमेशा यही कहा है, मेरी खाहिश है कि पंजाब यूनाईटिड रहना चाहिये । पंजाब के मुख्तलिफ रीजन्ज हैं, यहां मुख्तलिफ सैक्शन्ज़ हैं, मुखतलिफ काम्यूनिटीज हैं, उन के सैंटीमैंट्स को, एस्पिरेशन्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए एसा हल निकलना चाहिये जो सब के लिए अच्छा हो । यह मेरी राय है । आज भी मेरी यही राय है । जहां तक मेरी स्टेटमैंट का ताल्लुक है इस के पीछे एक ही बात है कि किसी कम्यूनिटी के खिलाफ, किसी सैक्शन के खिलाफ, किसी ग्रुप या इंडीवीजुअल के खिलाफ किसी चीज़ को मैंने टच नहीं किया । एक ही बात को टच किया है । ला एंड आर्डर को कायम रखा जाए । उस में मेरा कसूर नहीं है । लेकिन अमन की इच्छा रखते हुए यह एक ऐसी भावना है जिस को कोई मना नहीं कर सकता । हम ने इस प्राविंस में प्यार और प्रेम के जज़बात को पैदा करना है । जहां तक इस सवाल का, प्राब्लम का ताल्लुक है मैं ने आगे भी कहा है कि यह तकरीरों से, नारों से, जज़बाती नारों से एक दूसरे पर नारे कसने से हल नहीं हो सकता । इसे हल करने के लिए हमारे हिंदोस्तान के लीडर्ज़ इस पर गौर कर रहे हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ : ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ।

मुख्य मन्त्री : मेरे दोस्तों की तरफ से बार बार कहा गया है कि यह स्टेटमैंट दिया है । जो मैंने एक अपनी तरफ से दिया है । (विघ्न) पंजाब गवर्नमैंट की तरफ से दिया है । अगर कोई भाई इस सूबे के पीस को, ला एंड आर्डर को डिस्टर्ब करेगा, कोई इंडीविजुअल है या कोई है, वह गवर्नमैंट की ज़िम्मेवारी है कि कार्रवाई करे । हमारी खाहिश है, हमारी कोशिश है, हम किसी के जज़बात को नहीं दबाना चाहते, किसी के जज़बात को नहीं कुचलना चाहते जो कंस्टीट्यूशनल हक है, लेकिन जो गवर्नमैंट की जिम्मेवारियां हैं हम उन जिम्मेवारियों से

[मुख्य मन्त्री]

भी एब्डीकेट नहीं कर सकते। उन ज़िम्मेवारियों को निभाना हमारा फर्ज़ है। पूरे काम से निभाएंगे पूरे जोर से निभाएंगे। लेकिन सूबे में हर मुम्किन कोशिश करनी है कि काम्यूनिटीज़ का आपस में झगड़ा न हो। आपस में प्यार हो। किसी तरह की कोई ऐसी बात न हो जिस से से एक दूसरे के जज़बात को ठस पहुंचे। एक दूसरे के जज़बात को भड़काया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ।

मुख्य मन्त्री : कोई ऐसी बात न की जाए जिस से सूबे का ला एंड आर्डर, अमन डिस्टर्ब हो।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ।

मुख्य मन्त्री : यह मेरी आप से दरखास्त है।

Sardar Gurnam Singh : You permitted . . . .

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੌਤਮ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਨੇ। ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

Sardar Gurnam Singh : Sir, I was pointing out something else. You permitted one hon. Member from each group in the House to put one question and if the Chief Minister wanted to make it clear he could do so. But, Sir, you have permitted the Chief Minister to make an irrelevant speech in answer to the question put by the hon. Member, Comrade Shamsher Singh Josh.

Mr. Speaker : It is for me to judge.

Sardar Gurnam Singh : Therefore, Sir, I am submitting to you that the hon. Chief Minister did not confine himself to the question which was put by Comrade Shamsher Singh Josh and he went extraneous to that question. I am, therefore, submitting to you that you consciously or unconsciously permitted the Chief Minister to make an irrelevant speech in answer to that question which entitles us to put further questions.

Mr. Speaker : I never expected this observation from Sardar Gurnam Singh. I have stated a number of times that a Minister is entitled to make a statement at any time.

Voices from the opposition Benches : Even irrelevant statements ?

Mr. Speaker : It is for me to judge. When a question is put, a Minister may give his reply in any manner he likes and along with that he can also make a statement.

(*Interruptions and Noise in the House*)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ क्लैरीफीकेशन, सर। मेरा सवाल यह है कि सरदार शमशेर सिंह जोश के सवाल के जवाब में इन्होंने यह कहा है कि गवर्नमैंट की यह डयूटी है कि वह ला एंड आर्डर को मेनटेन करे। इस से किसी को इन्कार नहीं कि गवर्नमैंट का काम है कि ला एंड आर्डर को मेनटेन करे।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करें। (Let the hon. Member put his question.)

चौधरी देवी लाल : उसके लिए इंतजाम करें, तैयारी करें। लेकिन यह यहां प्रोवोकेटिव स्टेटमैंट दे करके अमन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करें। (Let him ask a question.)

चौधरी देवी लाल : यह क्लैवर मूव है। यह हिंदू और सिख का सवाल खड़ा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करें। (The hon. Member may ask a question.)

चौधरी देवी लाल : इस बात का यह सबूत मिल रहा है। यह क्लैवर मूव है। यह सवाल खड़ा करके लोगों की जो डिमांड है पंजाबी सूबा, हरियाणा प्रांत और हिमाचल की उसको दबाना चाहते हैं। यह जो कांग्रेसी बैंचों पे बैठे हैं यह अपने आप को बेबस समझते हैं। मैं आप की मार्फत उन से पूछना चाहता हूं कि वह इस के बारे में जवाब दें कि यह इतनी क्लैवर मूव यहां से चली है या दिल्ली से आई है?

(At this stage, Sarvshri Gurbakhsh Singh and Makhan Singh Haruwal rose to say something).

Mr. Speaker : Only one of the hon. Members is entitled to put a question.

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹਰੂਵਾਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲ ਦਿਤੀ ਹੈ——

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। (He may please put the question.)

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹਰੂਵਾਲ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी २ आनरेबल सरदार मक्खन सिंह ने कहा है कि डंडा चाढ़ कर स्टेटमैंट दिलाई गई है। Is it, Sir, parliamentary ? In order to keep the dignity of the House, I would like to know whether it is parliamentay ; if not.......

(Interruptions and Noise in the House.)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਟ੍ਰਪਸ਼ੰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ। (Many a time due to interruptions it does not become clear as to what words have been used. Sardar Makhan Singh may kindly withdraw these words.)

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹਰੂਵਾਲ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ। (The hon. Member may please withdraw his words.)

ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਹਰੂਵਾਲ : ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਿਨੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ....(ਸ਼ੋਰ)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मैं ने भी एक सवाल करना है ....(शोर.)

श्री अध्यक्ष : आप के ग्रुप में से चौधरी देवी लाल ने कर लिया है। (Out of his group Chaudhri Devi Lal has put one question.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : उन्होंने सवाल नहीं किया है प्वायंट आफ आर्डर किया है। उन से पूछ लें (.........(शोर)

Mr. Speaker : It is for me to judge this. He said that he was putting the question. Please take your seat.

Chaudhri Inder Singh Malik : I may be permitted to put the question. I never disobey the Chair. He has not put the question.

Mr. Speaker : Please take your seat. Chaudhri Devi Lal did put the question. You are obstructing the proceedings. I give you a final warning.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आप वारनिंग हजार बार दें मैं ने क्वैशचन करना है। वह कहते हैं उन्होंने क्वैशचन नहीं किया है। मैं ने अपने ग्रुप.........

श्री अध्यक्ष : पंडित चिरंजी लाल जी, इन को सम्भालो वरना मुझे ऐक्शन लेना पड़ेगा। (Pandit Chiranji Lal may please bring him round or I shall have to take some action.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मैं ने क्वैशचन करना है। उन्होंने नहीं किया है।

Mr. Speaker : You are obstructing the proceedings of the House. I order you to withdraw from the House.

Chaudhri Inder Singh Malik : I won't go.

Mr. Speaker : Please withdraw from the House.

Chaudhri Inder Singh Malik : I must be allowed to put the question.

(Interruptions and noise in the House.)

(At this stage, the Marshal was sent to the honourable Member.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मैं आपका हुक्म मानता हूं और जा रहा हूं लेकिन आपने यह धक्केशाही चलाई है और यह हुक्म नाजायज़ तौर पर किया है .... (शोर)

Chief Parliamentary Secretary : While leaving the House, the honourable Member has made certain remarks, which should not form part of the proceedings.

Mr. Speaker : Let the fact, that he has been flouting the Chair, come on record. He has made certain remarks while leaving, which he should not have done.

Chief Parliamentary Secretary : These remarks should be expunged, Sir.

Mr. Speaker : Let these come in the Press, so that people may know how he has been behaving.

चौधरी देवी लाल जी, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप ने सवाल किया था या नहीं। आप ने कहा था कि मैं सवाल कर रहा हूं। मैं ने दस बार उन्हें कहा लेकिन वह नहीं माने। (I want to enquire from Chaudhri Devi Lal whether he did put a question or not. He had stated that he was putting a question. I pointed out this fact to Chaudhari Inder Singh Malik but he refused to believe this.)

चौधरी देवी लाल : मैं ने तो प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किया था लेकिन आप ने कहा था कि सवाल करो। इस से उन्हें गलतफहमी हो गई कि मैं ने सवाल नहीं किया, प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किया था।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦਾ ਤਅੱਲਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਪੀਚ ਨਾ ਕਰੋ। (The hon. Member may put a question and avoid making a speech.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ.... (ਸ਼ੋਰ).... (ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)......(ਸ਼ੋਰ)......

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਝੋਟੇ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੇ ਤਕ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ (I could not hear this word. Sardar Harchand Singh may please withdraw it.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੋਟਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ......(ਹਾਸਾ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ। (Sardar Harchand Singh may please withdraw this word.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਹੀ ਸਹੀ....(ਹਾਸਾ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ((I never expected this from the hon. Member)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਵਜੁਹ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 1960 ਵਿਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਫਿਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਏਤਮਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ....(ਵਿਘਨ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਪੈਰੈਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪੀਸ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖੀਰ ਤਕ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਨਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ

ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਟ ਉਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh): Mr. Speaker, after the observations of the Chief Minister, I would request all the Members of this House through you, to close this Chapter. There are occasions and occasions when we can ventilate our sentiments during the Budget Session. Today is fixed for General Discussion on Budget and Members of both the sides want to urge certain things regarding their constituencies. Therefore let us now finish this matter and allow the next item on the agenda to be taken up.

12-00 Noon

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ? (ਸ਼ੋਰ)....(ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order, please, order.

Sardar Lachhman Singh Gill : If the Chief Minister's objections are in relation to what Master Tara Singh has said, we condemn him, and we are against any direct action etc.

Chief Minister : I appreciate the sentiments expressed by the hon. Member. (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ......(ਸ਼ੋਰ)(ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾਉ। (This is no point of order. The hon. Member may please take his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : * * * * *

Mr. Speaker : Order please, order please.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ) ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ? (Is the hon. Member putting a question or raising a point of order.)

*Expunged as ordered by the Chair.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, is Giani Zail Singh a Minister ? How have you permitted him to make a statement on behalf of the Government ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਉ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਸ਼ੋਰ) (When the hon. Member got up, I enquired of him whether he was putting a question in connection with the statement or raising a point of order. I asked him several times to resume his seat but he did not. Here it has become a convention with the Members to continue to speak despite my request to the contrary. I try to stop this convention by persuation.) (*Noise*)

Sardar Gurnam Singh : Therefore, I request you to expunge everything that he has said.

(*Interruptions and noise.*)

Mr. Speaker : Order please, order.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ...... (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

Mr Speaker : Please take your seat. Order please.

Deputy Minister for Development, Irrigation and Power (Sardar Gurmit Singh) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Panchayat.......................

(*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ......

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਉ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ......(ਵਿਘਨ)

श्री अध्यक्ष : यह झगड़ा किस तरह से मिटाना है, हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ किस तरह से चलानी है यह मेरी जिम्मेवारी है (विघ्न) (It is for me to see how to resolve this dispute and conduct the proceedings of the house.) (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ : ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ......

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। आप बैठेंगे कि नहीं आप किस बिना पर बोल रहे हैं ? (*Intettuptions*) (The hon. Member may please take his seat. Will he sit down or not. On what basis is he speaking?)

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ : ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਹਲ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਨਾ। ਇਹ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬਦਅਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਗੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਅਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲ ਚੁਭੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ......

श्री अध्यक्ष : आप बैठोगे या नहीं ?.... Order please. (Will he take his seat or not ?)

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ : ਨੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਅਰੇ : [* * * * * * *]

Mr. Speaker : Order please.

ਨਾਅਰੇ : [* * * * * *]

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : इस हाउस में नारे नहीं लगाए जा सकते। जो नारे लगे हैं वह प्रोसीडिंग्ज़ का हिस्सा नहीं होंगे। किसी किस्म का नारा नहीं लगाया जा सकता ....

(Shouting of slogans of any kind is not permissible in this House. The slogans that were raised here will not form part of the proceedings.)

(नारे) : * * * *

श्री अध्यक्ष : कोई नारा हाउस में नहीं लगाया जा सकता। आर्डर प्लीज़।

(Order please. No slogan can be raised in this House.)

नारों की आवाज़।.........

कोई भी नारा हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ का हिस्सा नहीं बन सकता। (No slogan raised in this House, will form part of the proceedings.)

(विघ्न)......................(शोर).........(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। (Order please)

आवाज़ें : स्टेटमैंट वापस लो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। देखिये, रूल के मुताबिक अगर कोई चीज कोई स्टेटमैंट अनपार्लियामेंटरी है तो मैं उस को वापिस लेने के लिए कह सकता हूं। (Order please. The hon. Members may please listen. If under the Rules, anything or any statement made, is unparliamentary, then I can ask for its withdrawal.)

Sardar Surjit Singh Theri : If it is provocative then.......

श्री अध्यक्ष : जो कुछ कोई मैंबर कहता है या मिनिस्टर कहता है जब तक वह अनपार्लियामेंटरी न हो उस में से कोई चीज़ एक्सपंज करवाना मेरे अख्तियार में नहीं है। (Unless anything said by a Member or a Minister, is unparliamentary, it is not within my competence to get anything expunged out of it.)

(आवाज़ें)............(शोर) (विघ्न)

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਨੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਾਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ....

(ਨਾਅਰੇ)....(ਸ਼ੋਰ)....

श्री अध्यक्ष : मैं ने कहा है कि हाउस में कोई नारा नहीं लग सकता। (I have already told the House that no slogan can be raised in this House.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਦਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ।

The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966

(Leave to Introduce)

Deputy Minister for Development and Irrigation and Power (Sardar Gurmit) Singh : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966.

POINT OF ORDER

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्राडर, सर। चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो दोबारा स्टेटमैंट दी थी उस में उन्होंने कहा कि कोई कोग्राप्रेटिव सौल्यूशन निकालना चाहिये, हम बड़ा मान करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं संत फतेह सिंह का। लेकिन ग्राप देखिये कि संत फतेह सिंह जी ने ग्रपने बयानों में डायरेक्ट एक्शन को ग्रौर इस किस्म के झगड़ों को सदा कंडेम किया है फिर भी इन्होंने ग्रपील की है उन से। बड़ी होशियारी के साथ इस किस्म के हालात पैदा किये जा रहे हैं ....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठ जाइये। (The hon. Member may please take his seat.)

चौधरी देवी लाल : हम ग्रपने जज़बात ग्राप के सामने रखना चाहते हैं। ग्रगर ग्राप एडजर्नमैंट मोशन ग्रलाऊ कर देते तो कोई हर्ज नहीं था। हम देखते हैं कि कोग्राप्रेटिव सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि पंजाबी सूबा ग्रौर हरियाणा प्रांत बना दिया जाए.......

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राडर प्लीज़, ग्राडर। (Order please, order.)

चौधरी देवी लाल : ग्रगर यह कोग्राप्रेटिव सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं तो इस किस्म की प्रावोकेटिव स्टटमैंट देने का क्या मतलब था, मैं यही बात ग्राप की मार्फत इन से पूछना चाहता हूं। मान ग्रौर ग्रादर तो सब कुछ करते हैं ....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। (Order Order.)

चौधरी देवी लाल : संत जी से ग्रपील करने का क्या मतलब था। गवर्नमैंट खुद इस किस्म के हालात पैदा कर रही है। कभी इंडस्ट्रियलिस्टों के काफले वहां भेजे जाते हैं .....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, प्लीज़, ग्रार्डर। ग्राप बैठ जाइये। (Order please, order. The hon. Member may please take his seat.)

चौधरी देवी लाल: सैंट्रल गवर्नमैंट इस बात पर गौर कर रही है। स्पीकर साहिब, मैं बैठ जाऊंगा, ग्राप मेरी बात तो सुन लें ....

श्री ग्रध्यक्ष: चौधरी देवी लाल ग्राप बैठ जाइये। (The hon. Member Chaudhri Devi Lal may please take his seat)

चौधरी देवी लाल : मैं पूछता हूं कि इस स्टटमैंट देने की स्टेज कैसे आ गई थी, यह तो खुद गड़बड़ करवा रहे हैं।

Mr. Speaker: Order order.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਅਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਉ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ।

Mr. Speaker : Order please.

BILL(s)

The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966

(Introduced)

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966.

The motion was carried.

Deputy Minister for Development and Irrigation and Power : Sir, I introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, आप ने अभी फरमाया था कि जो शब्द पार्लियामेंटरी हो वह आप हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में से नहीं निकलवा सकते। मैंने सवाल किया था और आप ने इजाज़त दी थी, मैंने कायदे के खिलाफ या अनपार्लियामेंटरी शब्द कोई नहीं इस्तेमाल किया था। मैंने सही सवाल किया था..............मैंने कहा था कि सरकार हिन्दुओं और सिखों को लड़ाना चाहती है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। देखिए आप ने सवाल की शक्ल में स्पीच की थी सवाल नहीं किया था और मेरे बावजूद बार बार मना करने के आप बोलते ही गए। आप ने डिसओबे किया था इसलिये मैंने उसको एक्सपंज करवा दिया था.....आप बैठ जाइये... (विघ्न) (Order please. The hon. Member may please listen. He had made a speech under the pretext of putting a question. He did not ask a question and despite my admonishing him to discontinue his speech, he contiued speaking, he disobeyed the Chair and therefore that speech was got expunged from the proceedings. Now he may take his seat.)

चौधरी नेत राम : मैं ने यह कहा था कि यह खुद लोगों से भूख हड़ताल करवा रहे हैं..... (विघ्न) सन्त फतह सिंह से अपील करते हैं और खुद अमल नहीं करते। यह इन का आडम्बर है। सिखों और हिन्दुओं को लड़ाना चाहते हैं......

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम, आप बैठ जाइये। (Chaudhri Net Ram may now please take his seat.)

Reference of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1966 to the Regional Committees

Deputy Minister for Development, Irrigation and Power (Sardar Gurmit Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st March, 1966.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st March, 1966.

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, समझ में नहीं आता कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब अपील तो करते हैं सन्त फतेह सिंह को, जन संघ वालों को और दूसरों को ....

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ, आप बैठ जाइए। (The hon. member Shri Jagan Nath may please resume his seat.)

श्री जगन्नाथ : आप हमारी बात तो सुन लें। बैठ भी जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठ जाइए। अब यह मुनासिब नहीं है। (No please he may resume his seat. Now it dose not appear to be proper.)

श्री जगन्नाथ : आप को यहां पर बंगाल वाली हालत पैदा नहीं करनी चाहिए। आप को हमारी बात सुननी पड़ेगी ....

श्री अध्यक्ष : श्री जगन नाथ, प्लीज़ बैठ जाइए। (Shri Jagan Nath should please take his seat.)

श्री जगन्नाथ : बैठ कैसे जाऊं ? आप बात तो सुनते नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर वाली बात नहीं है। आप बैठ जाइए। (This is not a matter for raising a point of order. He may sit down.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, आप ने मेरे प्वायंट आफ आर्डर का जवाब नहीं दिया। मैं ने कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं कहा था (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : चौधरी देवी लाल जी, मैं आप से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप श्री जगन् नाथ को इस तरह से करने से बन्द कीजिए। यह मुनासिब बात मालूम नहीं देती। ठीक है कि मैम्बर साहिबान का राईट है कि वह प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करें लेकिन जहां पर मैं देखूं कि यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है और मैं उन को बन्द करूं तो उन को बन्द हो जाना चाहिए। यही प्रोसीजर है। यह बात नहीं होनी चाहिए कि प्वायंट आफ आर्डर की आड़ लेकर जो मन में आए कहते चले जाएं। यह मैम्बर का राईट नहीं है। मैं आप से अपील करूंगा कि आप उन को समझाएं। (I would request Chaudhri Devi Lal to persuade Shri Jagan Nath to desist from behaving like that. This does not appear to be proper. Undoubtedly, it is the right of the hon. Members to raise points of order but when I feel that point of order being raised is irrelvant and I ask the hon. Member raising it to discontinue speaking, he should be comply with promptly. That is the procedure. To continue speaking out their mind under the pretext of a point of order should be strictly avoided. No Member is entitled to do so. I would appeal to him to bring Shri Jagan Nath round.)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन, सर। मेरा प्वायंट यह है कि आप ने मुझ से अपील की है। इस का मतलब यह है.....

श्री अध्यक्ष : वह इसलिये कि आप उन के ग्रुप लीडर हैं। (I have appealed to the hon. Member because he is the group leader.)

चौधरी देवी लाल : वह आप के सामने एक सवाल रख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर ने सन्त फतेह सिंह से अपील की लेकिन सूर्य देव से, सत्या नन्द से और वीर यज्ञदत्त से कोई अपील नहीं की। सवाल यह है कि वह खुद ही इस समस्या को हिन्दु सिख सवाल बनाना चाहते हैं। हम इस सवाल को हिन्दु सिख सवाल नहीं बनाना चाहते। यही प्वायंट वह रेज़ कर रहे थे।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਢੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

(At this stage there were continued interruptions and voices of point of order including that raised by Shri Jagan Nath.)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। मैं हाउस से फिर अपील करना चाहता हूं और खास तौर से ग्रुप लीडर्ज़ से कि इस बात पर काफी बहस हो चुकी है। आउट आफ दी वे भी बहस आप ने की है, मेरे न कहने पर भी बहस की है और सवालात भी किए हैं। अब मैं अपील करूंगा कि प्रोसीडिंग्ज़ को नार्मल तरीके से चलने दें। हर बात पर काफी बहस हो चुकी है इसलिये मुनासिब होगा कि आप नार्मल प्रोसीडिंग्ज़ को चलने दें। (Order please. I would again like to appeal to the house and particularly to the group leaders, that this matter has sufficently been discussed. Not only this. They have discussed it

even going beyond the rules or even when I advised them not to discuss the matter. They have also asked questions about it. Now I would request them to permit the proceedings to continue in a normal way. Every aspect of the matter has been discussed. It will, therefore, be proper that the proceedings be allowed to be carried on under the normal procedure.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ obey ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਉ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਚਲ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। (Let the proceedings start in a normal way first and then I will send for him.)

Shri Jagan Nath : On a point of order..................

Mr. Speaker : Please take your seat.

Mr. Speaker : Question is —

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendmant) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st March, 1966.

After ascertaining the votes of the Members present by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged. The bells were sounded. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Ayes" and those who were for "Nos", respectively, to rise in their places, declared that the motion was carried.

The motion was declared carried.

General Discussion of the Budget for the year, 1966-67

(Resumption)

Mr. Speaker : Now we resume discussion on the Budget.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਯਾ ਦੇਵ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਖਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਿਨਸਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

(ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ):

* * * *

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज तीसरे दिन इस हाउस में बजट पर बहस हो रही है। जो बजट फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने हाउस के अन्दर पेश किया है और उन्होंने इस की जो तस्वीर इस हाउस के सामने रखी है उस को देख कर हैरानगी होती है। उम्मीद यह की जा रही थी कि यह सरकार इस बजट के ज़रिए पंजाब के लोगों के लिये कुछ बेहतरी के काम, कुछ राहत के काम और लोगों को कुछ रिलीफ देने के काम करेगी। लेकिन जो बजट पेश किया गया है और उस की जो तस्वीर इन्होंने हमारे सामने रखी है, मैं समझता हूं कि वह तस्वीर पंजाब के सही हालात को हमारे सामने नहीं रखती। हैरानगी की बात यह है कि यहां पर बजट के अन्दर जो आमदन की फिगर्ज़ दिखाई गई है, जो मद्दें दिखाई गई हैं, वह तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। अगर उस को एट ए ग्लांस देखने की कोशिश की जाए तो हैरानगी होती है कि पिछले लगभग चार पांच साल के अन्दर जो रैविन्यू रिसीट्स हैं वह काफी हद तक बढ़ी है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ।

Mr. Speaker : He is allowed to come.

श्री बलरामजी दास टंडन : जो रैविन्यू रिसीट्स की आमदन यहां पर दिखाई गई है उस का जायज़ा आप लें तो पता चलता है कि सन् 1960-61 के अन्दर जो रिसीट्स थीं वह 64 करोड़ थीं। सन् 1961-62 में यह 77 करोड़ हो गई। उस के बाद की फिगर्ज़ 91 करोड़ हुई और फिर 113 करोड़, 113 करोड़ से 123 करोड़ और पिछले साल 132 करोड़ थी जब कि अब यह फिगर्ज़ 148 करोड़ तक पहुंच गई है। अगर पिछले पांच साल की इन फिगर्ज़ को देखा जाए तो यह दुगनी से भी ज़्यादा हुई हैं। 64 करोड़ से 128 करोड़ को तो दुगना कहा जा सकता है लेकिन यह 64 करोड़ से बढ़ कर 148 करोड़ तक पहुंच गई है। उम्मीद तो यह की जाती थी कि अगर यह फिगर्ज़ ठीक है, अगर पंजाब की स्टेट इकनामिक तौर पर इस कदर प्राग्रैस कर रही है, रैविन्यू रिसीट्स इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो हर आदमी यह उम्मीद कर सकता था कि वह बातें जिन की वजह से पंजाब के लोग पिस रहे हैं, जिन की वजह से पंजाब के लोग हाहाकार कर रहे हैं, उन से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया जाता। वह यह काम तो कम अज़ कम इस बजट में कर सकते थे। पंजाब की ऐग्रीकल्चर को तो किसी तरह से बढ़ावा यानि इन्सैन्टिव दे सकते थे। एग्रीकल्चर के अन्दर हम कुछ किसी तरह से लोगों को इनसैंटिव दे सकते थे। और उस के ज़रिए से, यानी लैण्ड रैवेन्यू के ज़रिए से इस सकार की तरफ से आंकड़े पेश किय गए हैं उन के मुताबिक यह आमदनी तीन करोड़ और 68 लाख रुपए होगी। अगर इस आमदनी में से पंजाब की कुल धरती में जो लोग हल चलाते हैं यानी जो यहां के हलवाहक हैं और जो सारा साल मेहनत कर के और पसीना बहा कर सिर्फ पंजाब के बाकी लोगों

*Note :—Expunged as ordered by the Chair.

को ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को अनाज खाने के लिये पैदा कर के देते हैं, उन को अगर कुछ रिलीफ दिया जाता तो वे लोग यह समझते कि अपनी सरकार ने हलवाहक जनता के हित का काम किया है। सरकार भी लैण्ड रेवैन्यू में कुछ मुआफी दे सकती है। अगर यह अपनी बढ़ती हुई आमदनी को देख कर सारा मामला न सही, क्योंकि सारा लैण्ड रेवैन्यू तो शायद कोई भी गवर्नमेंट मुआफ न करना चाहे, लेकिन उस का कुछ हिस्सा ही मुआफ कर देती तो उन लोगों को काफी रिलीफ मिल जाता। कम अज़ कम यह कर लेती कि उन से इन्कम टैक्स के आधार पर ही मामला लेना स्वीकार कर लेती तब भी बड़ी बात थी। क्योंकि इस तरह से यह कर सकती थी कि जिन लोगों की ज़मीन 5 एकड़ या इस से कम है उन से मामला नहीं लिया जाएगा तो इस से भी काफी लोगों को रिलीफ मिल जाता और इस से कोई ज्यादा फर्क गवर्नमेंट की आमदनी में पड़ने वाला नहीं था क्योंकि इस तरह के लोगों का मामला मुश्किल से एक करोड़ या पचास लाख से ज्यादा न होता अगर यही कर दिया जाता तो इस से पंजाब की गवर्नमेंट को कोई बड़ा घाटा पड़ने वाला नहीं था और न ही कोई बड़ी कमी पड़ने वाली थी और इस से पंजाब के लोगों को कुछ तो रिलीफ मिलता और यह रिलीफ पंजाब के छोटे एग्रीकल्चरिस्टस को मिलता जिस से वह अपने पावों पर मज़बूती के साथ खड़े हो सकते। लेकिन इस सरकार ने यह भी नहीं किया। मैं तो समझता हूं कि इस के रैवेन्यू में इतने बढ़ौती असल में हुई नहीं है जितनी इस ने बजट में दिखाई है। यह तो फिगरज़ की जगल्लरी ही है और कुछ नहीं जो हमारे सामने पेश की गई हैं। यह सिर्फ फिगरज़ के आगे और पीछे करने की बात है क्योंकि इन की यह बात समझ में नहीं आ सकती कि बगैर किसी टैक्स लगाए के रैवेन्यू की इन्कम में 18 करोड़ रुपए की बढ़ौती हो जाए। अगर वाक्या ही यह बढ़ौती होती तो क्या यह छोटा सा रिलीफ भी उन लोगों को न दे सकती ?

इसी तरह से आप प्रापर्टी पर टैक्सों की हालत को देखें। अर्बन प्रापर्टी पर अनेकों टैक्स इस ने लगा रखे हुए हैं। उन को इन्कम टैक्स देना पड़ता है, फिर प्रापर्टी टैक्स देना पड़ता है, उस पर हाउस टैक्स भी देना पड़ता है और इस के अलावा उस पर मरला टैक्स भी लगा हुआ है। इस सब के बावजूद इस तरह से जो गवर्नमेंट को इन प्रापर्टीज़ टैक्सों से आमदनी होती है वह कुल एक करोड़ और चार लाख रुपए हैं जो इस ने साल के लिए आंकी है। मैं पूछता हूं कि जब कि इस के रेवैन्यू में इतनी आमदनी बढ़ी है तो इस के लिये यह एक करोड़ रुपए की रकम मुआफ कर देना अथवा प्रापर्टी टैक्स समाप्त करना कौन सा मुश्किल काम था। यह कोई बड़ी राशि नहीं थी। अगर यह और किसी सैक्शन आफ पब्लिक को रिलीफ टैक्सों में नहीं दे सकते थे तो कम अज़ कम इन को ही दे देते। जब पंजाब सरकार की टैक्सों से आय को बढ़ते हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि इस तरह से एक करोड़ रुपए का रिलीफ दे देने से कोई ऊंच नीच होने वाली नहीं। इस सरकार की इन बातों से तो हमें यही समझ आता है कि इस की दी हुई फिगरज ठीक नहीं है क्योंकि अगर यह ठीक होती तो इस ने जो अर्बन प्रापर्टी पर मल्टीपल टैक्स लगा रखे हुए हैं इन में यह जरूर रिलीफ दे देती। (इस वक्त उपाध्यक्षा चेयर में आ बैठीं) फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज कल जो देश में हालात बने हुए हैं उन के अन्दर एक

[श्री बलरामजी दास टण्डन]
यह कांग्रेस सरकार सेंटर में और यहां पर स्टेट के अन्दर इस प्रचार की तरफ बड़ा ज़ोर लगाने की कोशिश कर रही है कि हम सोशलिज़म की तरफ जा रहे हैं और यहां पर एक सोशलिस्ट नज़ाम कायम करने जा रहे हैं लेकिन इन की बातों को देख कर बड़ी हैरानी होती है। यह जो सोश्लिज़म के नारे लगाते हैं और इस बारे में यह जो पार्लीयामैन्ट में और यहां पर असैम्बली में एक्सप्लेनेशन देते हैं तो बड़ा ताजुब होता है कि यह बातें क्या करते हैं और उन पर एक्शन क्या लेते हैं। इन की बातों में और एक्शन्ज़ में यह जो इतना महान फर्क पाया जाता है यह शायद दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट में न पाया जाता हो। एक तरफ तो वह ज़मीन जो इन्होंने सतलुज बेंड से रिकलेम की है वह बिरले और टाटों को दे रहे हैं और उन छोटे काश्तकारों को नहीं दे रहे जो बेचारे खेमकरन और दूसरे बार्डर के ज़िलों में तबाह और बरबाद हुए हैं। उन लोगों के लिए तो इन के पास ज़मीन नहीं है लेकिन जो टाटे और बिरले हैं उन को तो यह रिक्लेम कर के भी देने को तैयार हैं हालांकि इन टाटों और बिरले के पास पहले से ही अरबों रुपए हैं और वह कई कई कारखानों के मालिक हैं और उन की इतनी आमदनी होती है कि जिस का हिसाब किताब भी नहीं हो सकता। उन लोगों के पी. एज़. भी हज़ारों रुपए माहवार तनखाह ले लेते हैं। और बिरला का पी. ए. 40,000 मासिक तन्खाह लेता है। यह कैसी बातें हैं जो एक एसी गवर्नमैन्ट की तरफ से की जा रही हैं जो सोश्लिज़म का नारा लगाती रहती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां हाउस में अक्सर जिक्र होता रहता है कि आज कल कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। और हमें इस पर अफसोस होता है और हम चाहते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें कम हों ताकि आम लोग इन से घबरा न जाएं लेकिन उन लोगों को यह सरकार किसी किस्म की राहत देने के लिये शायद सोचती ही नहीं है। जो लोग सेलरीड कलास में आते हैं वही इन बढ़ती हुई कीमतों से ज्यादा दुखी हैं क्योंकि जो दुकानदार होते ह उन के लिये यह कहा जा सकता है कि कीमतों के बढ़ने के साथ साथ वह अपना मारजिन आफ प्राफिट भी बढ़ा लेते हों लेकिन जो फिक्सड इन्कम ग्रुप है वह बेचारे इस महंगाई से पिस रहे हैं और यह सरकार उन की बात सुनने को भी तैयार नहीं है और न ही यह सरकार चीजों की बढ़ती हुई कीमतों पर कन्ट्रोल कर सकती है। दूसरी चीज़ों की कीमतें इस ने क्या कन्ट्रोल करनी हैं जब यह उन चीजों की कीमतें काबू में नहीं रख रही और उन की कीमतें यह खुद बढ़ाती जा रही हैं जो इस के अपने बस में होती हैं जिस तरह से खान्ड है, रोडवेज़ की बसों के किराए हैं, इस की अपनी डेरी फार्मों का बना हुआ मक्खन है, सीमेंट है या रेलवे के किराए हैं। जो ऐसी चीजें हैं जिन की कीमतें सरकार की तरफ से फिक्स की जाती हैं और यह आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीजें हैं, इन की कीमतें भी आप देखें तो आप को पता चलेगा कि यह भी रोज़मर्रा बढ़ती जा रही हैं। अगर सरकार की यह हालत हो तो अगर किसी व्योपारी ने किसी चीज़ का दाम एक पसा बढ़ा भी दिया हो तो उस में उस का क्या कसूर हो सकता है। हर साल हम देखते हैं कि गवनमैन्ट रेलवे की टिक्टों की कीमतें बढ़ा देती है। इसी तरह से फर्टीलाईज़र की

कीमतें बढ़ाती जाती हैं जिस में सिवाए बिजली और पानी के और कोई मैटीरयल दरकार ही नहीं होता और यह सरकार बिजली भी फर्टीलाईज़र फैक्टरीज़ को एक पैसा फ़ी यूनिट से कम रेट पर दे रही है। मगर यह सरकार इन चीज़ों की कीमतों को कम रखना मुनासिब नहीं समझती ताकि यह चीज़ें कामन मैन की रीच में आ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिर्फ इतना ही नहीं है, जहां तक पंजाब के हालात का ताल्लुक है हमें इस के उस पहलू को ही देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि स्टेट का इकनामिक ढांचा कैसा है, इस के साथ कुछ और बातें भी आ जाती हैं जिन की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। इस पंजाब के अन्दर कोई डिवैल्पमैंट होनी है, कोई प्लैनिंग होनी है और उस प्लैनिंग पर अमल होना है यह सब बातें आखिर कैसी हैं ? यह सब इस बात पर मुनहसर हैं कि पंजाब के अन्दर बाकी के हालात कैसे हैं और इन हालात को बनाना और उन को बिगाड़ना सब गवर्नमैण्ट पर मुनहसर होता है और इस सब की जिम्मेवारी पंजाब गवर्नमैण्ट की होती है क्योंकि इस के हाथ में ताकत है, इस के पास इस मतलब के लिये पुलिस होती है और इस के हाथ में ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिए कानून बनाने और उन में तबदीली लाने के लिये ताकत होती है, और इस के अलावा इस के पास सरमाया भी होता है। मगर हैरानगी की बात यह है कि जिस पार्टी की आज पंजाब के अन्दर हुकूमत है और जो पंजाब के अन्दर आज सब से बड़ा स्टैबिलाइज़िंग फैक्टर हो सकता है उस में आज एक हो कर चलने और सोचने का ढंग दिखाई नहीं देता। आज यह हालत बनी हुई है कि जिस की डफली उस का राज। इस पार्टी का एक लीडर एक बात कहता है, दूसरा जैसे ज्ञानी जी ज्ञानी करतार सिंह हैं, या कोई और है वह कुछ और ही कहता है। वह दूसरी तरफ को ही कदम उठाता है। नतीजा यह है कि उन के दिमाग के अन्दर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है और जो डिसरप्शनिस्टस हैं उन को पंजाब के अमन, यहां पर भाई 2 के प्यार और मिल कर चलने के लिये उठाए गए कदम को रोकने का मौका मिलता है। मेजारिटी पार्टी के अन्दर जो कन्फयूजन है स्टेट में और सेंटर में भी उस से नाजायज़ फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तब यहां पर चलने वाले सारे प्लैन और डिवैल्पमैंट के काम नजर से ओझल हो जाते हैं। यह हकूमत करने वाली पार्टी यहां पर स्टेट में और सैंटर में भी 18 साल से राज कर रही है। यहां पर 154 में से 110 मैम्बर यह क्लेम करती है और सैंटर में भी बहुत मेजारिटी क्लेम करती है। इस के लिये आज जरूरत इस बात की है कि यह सारे मिल कर चलें, कदम मिला कर एक तरफ को चलें वरना यह डिसरप्शनिस्ट्स को पंजाब के अमन को तबाह करने का मौका देगी। जहां पर सोचने के अन्दर कनफयूजन होता है वहां पर अपरचूनिस्ट लोग उस से फायदा उठा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अकाली भाई जो यहां पर भी बैठे हैं और बाहर भी हैं, वह एक नारा लगाते हैं। यह बात मेरी समझ से बाहर है कि एक बात जो मुझे समझ नहीं आती उस को मुझे प्यार से बैठ कर, आराम से हर पहलू से सोच कर समझने क्यों नहीं दिया जाता। क्यों हुल्लड़बाज़ी से समझाने की कोशिश की जाती है। आज यह नारा लगाया जाता है कि पंजाबी का सूबा होना चाहिए। अब

[श्री बलरामजी दास टण्डन]

इस का मतलब क्या है? वैसे तो हर कोई यह समझ सकता है कि स्टेट लैंग्वेज पंजाबी हो और सारे काम काज में पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो। उस को कहा जायेगा कि यह पंजाबी का सूबा है। जिस पार्टी को मैं रैप्रेज़ैंट करता हूं उस का नज़रिया बड़ा साफ है। (विघ्न) वह यह है कि हम सिर्फ लैंग्वेज के ही बेसिज़ पर सूबों की नए सिरे से तशकील नहीं चाहते। इस को मुनासिब नहीं समझते। जनसंघ कहता है कि लैंग्वेज एक फैक्टर है but it is not the only factor जिस के बेसिज़ पर सूबों की नए सिरे से हदबन्दी की जाए। इस के और कई फैक्टर्ज़ हैं, जैसे डिवैलपमैंट प्लैन्ज़, सुरक्षा, इकनौमिक वाया-बिलिटी वगैरह। इन को भी सामने रख कर सोचना होगा कि किस तरह से सूबों की तशकील मुनासिब रहेगी। पिछले दिनों यह बात सैन्टर के अन्दर भी आई। हम समझते हैं कि पंजाब एक बाईलिंग्वल सूबा है यानी यहां पर हिन्दी भी पंजाबी के साथ 2 बोली जाती है और काम काज में लाई जाती है। मगर उन पंजाबी के हक में बड़े तमतराव से बोलने वालों की वह मुखालिफत समझ में नहीं आती जो वह इस बात की करते हैं कि पंजाब यूनीलिंग्वल सूबा हो जाए, पंजाबी पंजाब की स्टेट लैंगवेज हो जाए। यह बात समझ नहीं आती कि आखिर उन के दिल में है क्या। वह पंजाबी के अगर हामी हैं तो अगर पंजाबी यहां पर स्टेट लैंग्वेज होने की बात कही जाती है तो वह उस की मुखालिफत क्यों करते हैं। जनसंघ की मुखालफत तो समझ में आती है क्योंकि हम इस प्रान्त को bi lingual कहते हैं और वैसा ही देखना चाहते हैं। परन्तु इन की opposition समझ नहीं आती। तो इस का मतलब यह निकलता है कि उन को पंजाबी लैंग्वेज से प्यार नहीं है। यह तो महज़ कहने की ही बात है। आज सारा पंजाब पंजाबी पढ़ता है। तो फिर इस की मुखालिफत क्यों होती है? मैं किसी प्रिंसीपल की बिना पर किसी बात की मुखालिफत कर सकता हूं और मैं उस प्रिंसीपल को साफ कहता हूं। मगर यह बात साफ नहीं करते। जब यह मुखालिफत करते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि इन के दिल में पंजाबी के लिये प्रेम नहीं है। अगर उन के दिल में पंजाबी के लिये प्रेम होता तो यह खुल कर कहते कि ठीक ऐसा यूनीलिंग्वल सूबा बनाओ, बल्कि इस से भी आगे दिल्ली में बनाओ वहां पर भी पंजाबी बैठे हुए हैं। मगर कोशिश यह की जाती है कि इस के दायरे को छोटे से छोटा बनाया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : On a point of order, Madam. ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿਉਗੇ?

Deputy Speaker : It is not a point of order. Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਜਿੰਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗਰੁਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਗਰੁਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚੋਂ ਕਟ ਲਵਾਂਗੀ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਉ। (The time taken by the Group Leaders on such points of order, will be deducted from the time to be given to

those groups (*Interruption*). I vacate the Chair and let the hon. Member occupy it.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ)

श्री बलारम जी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले दिनों अकाली पार्टी के लीडर ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने एक बात यह कही कि जब तक लोगों की अपनी हकूमत न हो तब तक वहां पर डिवैलपमैंट नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती। अब यह बात समझने की है कि उन की 'अपनी हकूमत' से क्या मुराद है। इस का मतलब मैं तो नहीं समझता, वह खुद ही बता सकते होंगे। मगर कोई भी समझदार आदमी यह पूछ सकता है कि क्या आज हम अंग्रेज की हकूमत के अन्दर बैठे हुए हैं, क्या हमारा गवर्नर या चीफ मिनिस्टर कोई फारेनर बना बैठा है या सैंटर में प्रैज़ीडैंट या प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है? आज असलियत यह है कि हम ही अपनी किस्मत के बनाने वाले हैं। बाकी अगर इन का नजरिया यह हो कि अकाली पार्टी की हकूमत हो तो लम्बड़दार बनने की तरह उन की भी बारी आने वाली नहीं है। बाकी किस्मत की बात है। आज के युग में इस तरह की बातें करना और सोचना इस से ज्यादा तंग नजरिया और क्या हो सकता है। यह किसी दूसरे केशधारी (सिक्ख) को भी अच्छा नहीं समझते जैसे कि यह अकाली पार्टी के आदमी को समझते हैं। अगर दूसरे केशधारियों को यह अच्छा समझते होते तब भी यह ऐसी बातें न करते। आज इस पंजाब का गवर्नर सिख है, चीफ मिनिस्टर कैरों साहिब रहे हैं। पंजाब में बड़े से बड़े हाकिम केशधारी हैं। केशधारी हमारे भाई हैं, जीवन के अंग हैं, सहजधारी और केशधारी में कोई फर्क नहीं है। वह दोनो एक शाख की दो टहनियां हैं, एक ही टहनी के दो पत्ते हैं, और एक ही पत्ते पर खिंची हुई दो लकीरें हैं। इन में तकसीम की बात सोचना इन को अलग 2 रख के चलना यह पंजाब की बदकिस्मती होगी। जहां पर यह सोचा, जाता है कि अपनी हुकूमत हो, अपने लिये ही सोचें चाहे चार जिलों को मिला कर ही सूबा क्यों न बनाना पड़े, सोशलिज्म के नाम पर, इकनौमिक ढांचे के नाम पर भी और दूसरी बातों के नाम पर भी सूबे का नाम लिया जा सकता है, अगर हर बात में पोलीटीकल तौर पर ही सोचा जाए तो यह पंजाब की बदकिसमती होगी। इस बात को किसी और ढंग से भी चलाया जा सकता है और वह तरीका यह है। यहां पर बड़े से बड़े अफसर और कैबिनिट के मिनिस्टर और सैंटर में भी मिनिस्टर पंजाब में से केशधारी हैं इस पर किसी को आपत्ति नहीं। और कभी भी किसी वक्त भी जिस पार्टी को मैं इस हाऊस में रिप्रिज़न्ट करता हूं उस ने इस बात पर न एतराज़ किया है और न करने को तैयार है कि सारी की सारी केबिनिट केशाधारी हो जाती है। अगर मैरिट और इन्टैलीजैंस की बिना पर सारे के सारे केसाधारी आ जाते हैं तो इस में जनसंघ को किसी तरह का मलाल नहीं। बात सोचने की यह है कि इस तरह का नज़रिया रखना कि केशाधारी या सहजधारी है या हिन्दु और सिक्ख है, कितना छोटा है और इस का ज़िक्र इस तरह से नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्षा : काइन्डली वाइन्ड अप। (Kindly wind up.)

श्री बलराम जी दास टंडन : आपने दूसरी पार्टी का व्यू प्वायंट डेढ़ घंटे तक सुना और अब मेरे व्यू प्वायंट को भी कहने का समय दीजिए।

उपाध्यक्षा: हरेक मैम्बर इस तरह से मुझे डिक्टेट नहीं करवा सकता। ो गलतियां मिल कर एक दरुस्ती नहीं हो सकती। आप को 22 मिन्ट बोलते हो चुके हैं: अब आप वाइन्ड अप कीजिए। (Every Member cannot dictate me like this. Two wrongs cannot make one right. The hon. Member has spoken for 22 minutes. Now he may wind it up.)

श्री बलराम जी दास टंडन : मैं बस एक दो बातें ही और कहना चाहता हूं और फिर खत्म कर दूंगा। मे ‍अकाली भाई अपना केस पुट करते हैं तो एक आरगूमेंट यह देते हैं कि सिक्खों को सैकंड रेट सिटिज़न माना जाता है। (विघ्न) आप न सही आप की पार्टी के लीडर कहते हैं और यह आरगूमेंट देते हैं कि सिक्खों को सैकंड रेट सिटिज़न माना जाता है। कितनी हैरानगी की बात है कि किस तरह से यह अपना केस पुट करते हैं और इस के बेसिज़ किस तरह से इस बात को मानते ह। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सैकन्ड रेट का आम तौर पर जो मतलब लिया जाता है और समझा जाता है वह यह हो सकता है कि हमारी कानस्टीचूशन में कोई बार हो कि एक आदमी को जो सिक्ख हो और केशाधारी हो उस को मुल्क का प्रधान मन्त्री नहीं बनाया जा सकता। वह किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता या मुल्क का प्रधान मन्त्री नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस तरह की बार हमारी कान्स्टीचूशन में नहीं है। अंग्रेज़ के वक्त इस तरह की बार थी और पहले तो ऊपर के हिस्सा में थी फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे के तब्का तक आ गई। और जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो यह बार आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती गई। पहले अंग्रेज़ के वक्त यह था कि किसी ज़िला में एस. पी. अंग्रेज़ के इलावा कोई नहीं बन सकता। इसी तरह मिलेटरी में यह बार था कि कैप्टन से ऊपर के रैंक पर अंग्रेज़ के सिवाए कोई नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह पाकिस्तान की कानस्टीचूशन में यह दर्ज है कि वहां का प्रैजीडैण्ट मुस्लम के सिवाए दूसरा कोई नहीं हो सकता। वहां पर और वहां के हालात के मुताबिक तो कहा जा सकता था कि पाकिस्तान में सभी नान-मुस्लिम सैकन्ड रेट सिटीज़न हैं मगर क्या इस तरह की कोई बार सिक्खों पर है और कहा जा सकता है कि किसी जाती को सैकन्ड रेट सिटिज़न माना जा रहा है? अंग्रेज़ के वक्त में कहा जा सकता था लेकिन जहां तक हमारे कान्सटीचूशन का तालुक है इस में कोई इस तरह का बार नहीं है। चाहे कोई केसाधारी हो या सहजधारी, क्रिस्चीयन हो या पार्सी, हर कोई ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। कोई भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधान मन्त्री बन सकता है किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बन सकता है। लेकिन इस तरह के आरगूमेंट दिए जा रहे हैं कि पंजाब की जनता को, सीधे सादे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें करना लोगों के सैंटीमैंटस को उभारने की कोशिश की जा रही है। यह देश के हित के मुनाफी है। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पांच मिन्ट और लूंगा।

उपाध्यक्षा : आप दो मिन्ट में खत्म कीजिए। (Let the hon. Member finish in two minutes.)

श्री बलराम जी दास टंडन : सवाल तो यह है कि जो भाई पंजाब की तकसीम की मांग करते हैं उन के बेसिज़ क्या हैं। हम न उन के बेसिज़ को समझने की कोशिश की है। हमारी तरफ से ही नहीं, और लोगों की तरफ से पचासों बार कहा गया है कि यह मांग कमयूनल है लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि यह मांग कमयूनल नहीं है। यह तो लिंगविस्टिक बेसिज़ की डिमांड लेकर आए हैं और लिंगविस्टिक बेसिज़ पर स्टेट चाहते हैं। अब कोई भाई इन से यह पूछे कि अपनी ग्रेबान में जरा मूंह डाल कर तो देखें कि इस डिमांड के पीछे क्या भावना निहित है। आप इन के लीडरों की स्पीचों को देख लें कि किस तरह की बातें करते हैं। इन के लीडर बड़े सुल्झे हुए इन्सान हैं, आप उन की पिछले चार पांच सालों की स्पीचों को सुन लें और देखलें कि किस तरह की बातें करते हैं। असैम्बली में इनके बड़े से बड़े नेता यदि किसी केस के बारे में बात करेंगे तो वह केसाधारी के मुतालिक होगा चाहे पियन ही हो। कहेंगे कि उस केशाधारी पियन को तरक्की नहीं मिली, उस के बारे में यह किया गया, वह किया गया। इस के आगे वह और कोई बात सोच ही नहीं सकते। हालांकि वह जानते हैं कि किसी भी सूबा के अन्दर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पचासों आदमी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इस लिए इस तरह के नैरो माइंड से किसी बात को नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इस बात को मानते हैं कि इनकी लिंगविस्टिक डिमांड है तो फिर खुले आम सामने आ कर इस बात को मानते क्यों नहीं और क्यों नहीं साफ शब्दों में कहते कि हमारी मांग कमयूनल मांग नहीं और फिर इस तरह का केशाधारी का सवाल क्यों उठाते ह, सब का सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों यह मांग करते हैं कि पंजाबी सूबा का न बनाना सिक्खों के साथ वितकरा है फिर यह क्यों नहीं कहते कि पंजाबी सूबा न बनाना सारे पंजाबियों के साथ वितकरा है। अगर इन के सामने सिर्फ भाषा का सवाल है तो यह मांग क्यों नहीं करते कि पंजाबी भाषा को सारे हिन्दुस्तान में लागू किया जाए! जब भी यह जिक्र करते हैं तो सिक्खों का। यह कहते हैं कि अगर सिक्ख फौजें लाहौर पर मार्च कर सकती हैं तो दिल्ली की तरफ भी मार्च कर सकती हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पंजाबी फौजें! इन की बातों से साफ पता चलता है कि इन की डिमांड कमयूनल है। लेकिन यह नारा देते हैं कि हमारा व्यू प्वायंट कमयूनल नहीं है। इन की यह स्टेटमैंटस में सैल्फ डिसैप्शन है। (घंटी) मैं एक आध मिन्ट में ही खत्म करता हूं मैं इस के लिये आप से, डिप्टी स्पीकर साहिबा, माफी चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह पंजाबी सूबे की बात करते हैं लेकिन दरअसल इन क दिल में पंजाबी से प्रेम नहीं। अगर इन को पंजाबी भाषा से प्रेम होता तो इन की मांग यह होती कि इस भाषा को सारे हिन्दुस्तान में लागू कर दिया जाए। और न ही इन के दिल में इस बात से प्रेम है कि लिंगविस्टिक स्टेट बन जाए। इन को तो पोलीटीकल पावर से प्रेम है। आप इन का पहला इतिहास देखें कि अगर सन 1957 में इलैक्शन्ज़ होते हैं तो इन की एजीटेशन होती है सन 1956 में और अगर सन 1962 में इलैक्शन्ज़ होते हैं तो इन की एजीटेशन सन 1961 के अन्दर होती है। इसी तरह अब अगर इलैक्शन्ज़ सन 1967 में होने हैं तो इनकी एजीटेशन सन 1966 में होती है। कोई इन से यह पूछे कि सन 1958 में क्यों एजीटेशन नहीं की

[श्री बलराम जी दास टंडन]

गई। क्योंकि इन्हें ख्याल होता था कि सन 1962 की इलैक्शन्ज़ तक लोग इस बात को भूल जाएंगे और यह असैम्बली में मैम्बर बन कर कैसे आयेंगे और अपनी सीट को किस तरह से कायम रखेंगे। जब कहीं पर फूट पड़ी तो यह फायदा उठाना चाहते हैं और अपनी पोलीटीकल पावर को कायम करने के लिये आन दी ईव आफ इलैक्शन्ज एजीटेशन को शुरू करते हैं। इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ना तो इन्हें पंजाबी भाषा से प्यार है और न ही पंजाब की जनता से प्यार है। और अगर यह सोचते हैं तो इस ढंग से नहीं कि सिक्खों को किस नीति से फायदा हो सकता है बल्कि इस तरह कि इन के सैल्फ के लिये और पोलीटीकल पावर को कायम करने के लिये प्यार है। हर पांच साल के बाद पोलीटीकल पावर लेने का सवाल आता है तो डिसग्रन्टल्ड एलीमेन्ट इस तरह का नाहरा ले कर सामने आ जाता है और पंजाब की जनता को गुमराह किया जाता है। यह नहीं सोचते कि इस सूबा में जिस की यह मांग कर रहे हैं इकनामिक स्टैबिलिटी किस तरह से कायम रहेगी। और फिर इसी तरह से हरियाणा के भोले लोगों को गुमराह किया जाता है और वह भी कहने लगते हैं कि हम चार जिलों का ही हरियाणा प्रान्त चाहते हैं।

(इस समय डा० प्रकाश कौर पेनेल आफ चेयरमैन की एक सदस्या ने कुरसी संभाली।)

यह मांग की जाती है कि चीफ मिनिस्टर हमारे प्रान्त का हो या हमें मिनिस्टर के पद पर लगाया जाए। इस का मतलब साफ है कि बगैर पोलीटीकल पावर के और कोई बात नहीं और यह हमारी बदकिस्मती है। यह फिसीपेरस टैन्डैन्सी का नमूना है जो इन की तरफ से पेश किया जा रहा है। हरियाणा वालों की मांग है कि हमें चार जिलों का ही सूबा दे दिया जाए। और कहा यह जाता है कि हम सूबा इस लिये मांग रहे हैं क्योंकि यहां का पसमांदा इलाका है, पछड़ा हुआ इलाका है, इस में ज़राए आमदोरफत नहीं है और सरकार इस इलाके की तरफ ध्यान नहीं देती। इसलिये हमें अलग सूबा दे दिया जाए। चेयरमैन साहिबा, अब आप ही अंदाजा लगाएं कि किस तरह से यह अपने चार जिलों का अलग सूबा बना कर उस का पछड़ापन दूर कर सकेंगे। फिर कहते हैं कि एकनामिक तौर पर हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। कितनी कन्ट्रेडिक्शन है इन की बातों में।

सभापति : (डा० प्रकाश कौर) आप अब वाइन्ड अप करें। (The hon. Member may please now wind up).

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं बस एक बात कह कर खत्म करता हूं। कितनी कन्ट्रेडिक्शन है इन की बातों में। यह कहते हैं कि हम अपने इलाका को डिवैल्प करना चाहते हैं लेकिन मांग करते हैं कि चार जिलों का अलग सूबा बना दिया जाए। अगर डिवैल्प ही करना है तो उस के लिये बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन चार जिलों में किस तरह से एकनामिक हालत को बेहतर किया जाएगा? पता नहीं यह किस अनालोजी पर काम कर रहे हैं। अगर इसी अनालोजी पर चला जाए कि अलग सूबा बनाने से किसी इलाके का पिछड़ापन दूर हो जाएगा तो फिर कल संगरूर का जिला भी यही मांग करेगा कि मुझे अलग सूबा बना दिया जाये, हमारी अपनी हकूमत इस जिला में होनी चाहिए। इसी तरह ऊना के इलाके की यही मांग होगी कि हमारा अलग सूबा बना दिया जाए, इसी तरह

महेन्दरगढ़ के इलाके वाले कहेंगे कि हमारा सूबा अलग बना दिया जाए क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और इलाके को बेहतर बनाने में, पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में इसी इलाके के लोगों पर ज्यादा टैक्स लगायेंगे और इस तरह से पिछड़ापन दूर करेंगे।

चेयरमैन साहिबा, मुझे यह बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि जब एक बात तय हो जाती है कि इस को चलाने के लिये यह यह आधार हैं, अगर इस पर मज़बूती से चला जाये तो यह मसला हल हो जायेगा, जब एक लाईन को मान ही लिया तो फिर उस से इधर उधर होने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। पहले रिजनल फारमूले पर चलने की बात आई और फैसला हुआ। अब यह कहते हैं कि वह कुछ नहीं था वह तो अब खत्म हो गया है, वह तो हाऊस की एक कमेटी ही बन कर रह गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बताये तो सही कि जब एक कमेटी की राये में और असैंबली की राये में किसी तरह का इखतलाफ होता है, तो वह बिल हाऊस का पास समझा जाने की बजाये सीधा गवर्नर के पास जाता है। जिस कमेटी के चेयरमैन का बाकायदा स्टेटस हो, अलग तन्खाहें हों तो उन्हें Committee of the House कैसे कहा जा सकता है? कहने के लिये तो आप चाहें कुछ भी कहें, मगर यह मानी हुई बात है कि इन दोनों कमेटियों को एक फारमूला के अधीन अमल में लाया गया था। आप अगर रिगल आऊट करना चाहते हैं इस के लिये तो 100 तरीके हो सकते हैं। मगर जब एक दफ़ा एक बात मान ही ली गई तो उस पर पूरे ढंग से अमल होना चाहिये। मगर आज तै शुदा मुआमलों को छोड़ कर इस लिये नई लाईन इखत्यार कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी कह रहा है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं मर जाऊंगा। यह एक नया क्वैश्चन है जो अब ओपन कर दिया है। यह एक ऐसा सवाल है जिस की डैमोक्रेसी में कोई वुक्त नहीं है। अगर इनको डैमोक्रेसी के अंदर विश्वास था तो जो असूल एक दफा मान लिया गया था उस के आधार पर चलने की कोशिश करते, मगर मैं तो हैरान होता हूं जब यह आत्म-हत्या की बार बार धमकियां देते हैं। अगर ऐसा ही है आप ने पंजाबी सूबा के नाम पर तीन इलैक्शनें लड़ी हैं मैं आज फिर चैलेंज करता हूं कि अगर इन को किसी बात का शक है तो यह 1967 की इलैक्शन भी लड़ कर देख लें। इसी इशू पर इन्होंने 1962 की इलैक्शन लड़ी है और देख लिया है कि 154 आदमियों में से महज़ 19 ऐसे हैं जो इस इशू पर कामयाब हुए, यानी 15 प्रतिशत से भी कम ऐसे हैं जो इस इशू पर कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूं पंजाबी सूबा के नाम पर लोगों के सैंटीमैंट्स को उभारा जा रहा है और मासिज़ की इन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर कुछ चाहते हैं तो डैमोक्रेसी का रास्ता इखत्यार करें, मगर यह क्या कि हम ने एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे ने मरने की लिस्टें तैयार कर ली हैं।

सभापति : टंडन साहिब, आप को इतनी दफा घंटियां बजा कर वांईड अप करने को कहा है। अब आप बैठ जायें। (Shri Tandon has been requested several times to wind up his speech by ringing bells many a time. Now he may resume his seat.)

श्री बलरामजी दास टंडन : बस जी मैं वाइंड अप ही करने लगा हूं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मरने की धमकियां देकर कोई भी शख्स A.B.C., चाहे कोई हो, अगर इस ढंग से पंजाब के अमन में बाधा डालने की कोशिश करे तो, उसे किसी भी तरह से ऐसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लोगों के जज़बात को उभारने की बजाये इस मुआमला को अमन से, डैमोक्रैटिक ढंग से सुलझाना चाहिये। मेरी आप से यही प्रार्थना है, इसी में पंजाब का भला है और . . . .

1.00 A.M.

सभापति : टंडन जी, आप बैठ जायें, अब और वक्त आपको दिया नहीं जा सकता। (The hon Member Shri Tandon may take his seat. He cannot be given any more time.)

शिक्षा मन्त्री (श्री प्रबोध चंद्र) : चेयरमैन साहिबा, मैं सिरफ चंद मिनटों के लिये आप की इजाज़त से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। जो माहौल पिछले चंद दिनों से देखने में आ रहा है, मुझे भी कोई 20 साल हो गये हैं, मैं पार्टीशन के पहले से असैंबली का मैंबर बना आ रहा हूं मगर ऐसा माहौल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इस किस्म की बातें करके यह पिछली यादों के मुकाबला में हमें छोटा कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, हज़ारों आफीसर जो यहां पर बाहर से आये हुए हैं, वह इस ख्याल से आये हैं कि चल कर देखें कि हमारे चुने हुए नुमायंदे किस तरह से इस हाऊस की कार्यवाही कंडक्ट करते हैं। यहां पर पंजाब का सवाल नहीं है, इस हाऊस की कार्यवाही का असर मौजूदा हिंदुस्तान पर और आने वाली हिन्दुस्तानी नसलों पर भी पड़ता है। मगर जो बातें इन दिनों हम ने की हैं इन से दिल को इन्तहा दरजे का दुख होता है। हम शर्म महसूस करते हैं कि इस हाऊस के मैंम्बर होने का सवाल कोई वकार का सवाल नहीं रहा। बार बार चेयर की डिगनिटी को डिफाई किया जाता है, इस बात को लेकर कि हमारे साथ नाइन्साफी होती है। चंद दिनों से आपने इस माहौल को देखा है कि कुछ मुट्ठी भर आदमियों ने हर बात में इस हाऊस की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की है। (आवाज़ें : मुट्ठी भर की है, मुट्ठी भर की हुंदा है, सानूं दसो।) मैंने मुट्ठी भर उन को कहा है जो अपने फायदे की बात तो सुन लेते हैं मगर जब किसी और बात को कहा जाये तो सुनने को तैयार नहीं होते। मैंने उनको कहा है और यह गिनती के आदमी हैं। (विघ्न) अगर मैं इस बात को लूं. . . . (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ 100 ਵਿਚੋਂ 85 ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਠੀ ਭਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਿਰਕਾਦਾਰ ਹੈ।

शिक्षा मन्त्री : यह इन्होंने अपने दिल की बात कही है कि गवर्नमैन्ट फिरकेदारी को बढ़ावा देती है। मगर हम जितना इन से शराफत से पेश आते हैं यह उतना ही बढ़ कर इस सूबे की फिजा को खराब करने के लिये तुले हुए हैं। आज हम यही कहते हैं कि इस सूबे के अमन को खराब ना करो, फिरकेदाराना रंगत ना दो, हम अमन की पालिसी चाहते हैं। पिछले दिनों जब जालन्धर में डायरैक्ट एक्शन की धमकी दी गई थी अगर इन में हिम्मत थी तो यह उस बात को कंडैम करते। (विघ्न)

Sardar Lachhman Singh Gill : We condem it. (*Interruptions.*)

शिक्षा मन्त्री : मगर इनकी कंडैम करने की हिम्मत ना हुई......

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of Order, Madam.

Education Minister : I do not give way.

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of Order, Madam.

Chairman (Shrimati Dr. Parkash Kaur) : He does not give way.

Sardar Lachhman Singh Gill : Who is he not to give way ? I rise on a point of Order.

Education Minister : You must have manners to talk......

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ? ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਗੈਰਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ–ਲੱਖਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਸਭਾਪਤੀ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ? ਇਹ ਗਲ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। (Why does Sardar Lachhaman Singh interrupt the hon. Minister ? He can explain all this after he has finished.)

शिक्षा मन्त्री : चेयरमैन साहिबा, अभी दो दिन हुए हैं, इसके बाद यह कहा गया कि इस पर पैसे लगा दिए गए। वह तो दुनिया जानती है कि हम ने पैसे दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमानदारी से, ठंडे दिल से इस पर विचार किया जाए तो जो आप के साथ इख्तलाफ रखते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। (विघ्न) (शोर) शोर मचा कर कम अज़ कम मुझे नहीं दबा सकते। (सरदार लछमन सिंह गिल द्वारा विघ्न) मैं आपकी तरह का आदमी नहीं हूं। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं।

सरदार लछमन सिंह गिल : टाईगर में क्या लिखा है ?

शिक्षा मन्त्री : टाईगर को कोई छोटे पैमाने का आदमी पढ़ता होगा। यह अपनी आदत से मजबूर हैं। पुरानी आदत है। मगर मैं यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि ... (विघ्न) (शोर) अगर हाउस में दस आदमी ऊंचा बोल कर शोर मचा कर किसी को बोलने से बन्द कर सकते हैं तो उन की भूल है। सिख पंथ, सिख कौम के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इन के अपने मुहतरम हुडियारा साहिब से बातें हुईं। उन से पूछा गया कि आप की कौम के साथ क्या ज्यादती हुई है तो वह कहने लगे कि हम तीन बातें चाहते हैं। पंजाबी ज़बान के साथ ज्यादती हुई है, सिख सर्विसिज़ से ज्यादती हुई और तीसरे हम पर विश्वास नहीं किया जाता है। हमें देश-भक्त नहीं समझा जाता है। जहां तक सिख सर्विसिज़ का सवाल है, जिस के कंधों पर दिमाग है, वह समझ सकता है कि सारे पंजाब में 16 सैक्रेटरीज़ हैं, उन में से 9 सिख हैं। आबादी के लिहाज़ से इतने ज्यादा नहीं होने चाहियें जितने इस समय लगे हुए हैं। जितना रुपया पंजाबी भाषा की उन्नति के लिये खर्च किया गया है पिछले दस सालों में देख लें आप को पता लगेगा कि इतना पहले कभी खर्च नहीं किया गया। पंजाबी भाषा के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। हरियाणा में हर पंजाबी को हिंदी पढ़नी पड़ती है।

[शिक्षा मंत्री]

जो सर्विस में हैं हर एक को पंजाबी पढ़नी पड़ती है। पंजाबी सूबा बनना चाहिए तो किस बिना पर कहेंगे कि पंजाबी पढ़ो? तीसरी बात उन्होंने कही कि पेट्रीआटिक नहीं समझा जाता। उस का अंदाजा इस बात से लगता है कि जिस कौम की आबादी एक फीसदी हो हिंदोस्तान में उस के 20 या 22 फीसदी फौज में सिख हैं। कोई मुलक जिसको किसी कौम पर विश्वास न हो वह बरदाश्त नहीं करेगा कि उस को अपनी फौज में नुमायां हिस्सा दे। मैं दोनों तरफ के भाइयों से कहूंगा कि यह एक इतना बड़ा मसला है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी हुई है। हम उस के बिल्कुल पाबन्द हैं, जो फैसला करेंगे, चाहे वह गलत हो, चाहे ठीक हो, हमें पसंद हो या न हो, मैं वाज़ेह अलफाज में कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की शराफत को गवर्नमैंट की कमज़ोरी न समझा जाए। गवर्नमैंट चाहती है कि अपने मुखालिफ को प्यार से जीते। कोई आदमी गलत अंदाजा लगा कर कहे कि गड़बड़ डालना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : * * * *

शिक्षा मंत्री : * * * *

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : * * * *

शिक्षा मंत्री : * * *

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : * * * *

(ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

शिक्षा मंत्री : * * * * *

सरदार लच्छमन सिंह गिल : * * * * *

शिक्षा मंत्री : * * *

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : * * * *

Education Minister : He is off his head. Let him interrupt. I do not take him seriously.

Sardar Lachhman Singh Gill : I, too, do not take you seriously.

Education Minister : Do not take me seriously.

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of order, Madam. My point of order is that how long these proceedings will continue. This sort of things must be discouraged and ended, otherwise the House be adjourned.

Chairman : Now things have come to normal.

शिक्षा मन्त्री : चेयरमैन साहिबा, किसी कौम के साथ ज्यादती नहीं हुई, किसी किसम की कोई नाइन्साफी नहीं हो रही। हरियाणे वालों को पूरा हक है। मैं खुद समझता हूं कि हरियाणा वालों के साथ पूरा इन्साफ नहीं हुआ। वह इस के लिये लड़ें। हर चीज़ के लिए लड़ने का तरीका होता है। (विघ्न) (शोर) ऊंचा बोल कर या आवाजें कस कर किसी को दबाया नहीं जा सकता। जिसने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है, वह ऐसे नहीं दबेगा। इन्होंने चैलेंज किया है, इन्होंने समझा है कि इस तरह का ही चक्कर चलता है।

*Expunged as ordered by the Chair.

गलत तरीके से प्रापेगंडा कर के कोई सही शक्ल नहीं बनेगी..... (सरदार लच्छमन सिंह गिल द्वारा विघ्न) मेरे हाथ में नहीं है।

सरदार लछमन सिंह गिल : * * * *

शिक्षा मन्त्री : * * * * *

सरदार लछमन सिंह गिल : * * * (विघ्न) (शोर)

शिक्षा मन्त्री : * * * * *

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : * * * *

(*Deputy Speaker in the Chair.*)

शिक्षा मन्त्री : कई भाई ऐसे हैं, जिनकी आदत हरेक की पगड़ी उछालना है।

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहिबा, प्रबोध जी दूसरों को कहते हैं कि वे इन्ट्रप्ट करते हैं और खुद आज इन को यह कह कर इनवाईट किया है कि उन्हें हरेक की पगड़ी उछालने की आदत पड़ी हुई है। खुद यह दूसरों को ऐसा कहते हैं और फिर उन्हें ब्लेम करते हैं।

उपाध्यक्षा : मैंने कुछ सुना नहीं। अगर प्वायंट आफ आडर पर बहस करेंगे तो लम्बी चौड़ी बात की इजाज़त नहीं दूंगी। अपनी अपनी बारी में कहें जो कहना है। (I have not heard anything. If the hon. Member wishes to discuss a matter by raising a point of order, then long discussion will not be permitted. Every member should say at his own turn whatever he wants to say.)

(*Interruption*)

शिक्षा मन्त्री : अगर लुध्याना में होता तो आज इस हाउस में न बैठा होता।

सरदार लछमन सिंह गिल : * * * *

शिक्षा मन्त्री : * * * *

सरदार लछमन सिंह गिल : * * * *

शिक्षा मन्त्री : * * * *

सरदार लछमन सिंह गिल : * * *

Education Minister : * * * *

Sardar Lachhman Singh Gill : * * *

शिक्षा मन्त्री : देख लूंगा। *

उपाध्यक्षा : सरदार लच्छमन सिंह।

सरदार लछमन सिंह गिल : * * * *

शिक्षा मन्त्री : * * * *

सरदार लछमन सिंह गिल : * * * *

*Expunged as ordered by the Chair.

उपाध्यक्षा : मैं किसी को धमकी देने की इजाजत नहीं दूंगा। आप शांति से बैठे रहें। (I would not allow anybody to hold out threats. They should hold themselves in peace.)

ठाकुर मेहर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडमा। मैं इस हाउस का 15 साल से मैम्बर चला आ रहा हूं, लेकिन मेरे देखने में कभी ऐसी बात नहीं आई कि हाउस में इस किसम की बातें हों और जब चेयर खड़ी हो तो उस के बावजूद उसके आर्डर को डिसउबे करें और इस किसम की निकम्मी जबान इस्तेमाल की जाए जिसे कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग दूर दूर से इस हाउस की कार्यवाही देखने आए हैं वह क्या सोचेंगे कि क्या यही पारलीमैंट्री तरीका है हमारा काम करने का।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। (Whatever has transpired, will be expunged from the record of proceedings.)

शिक्षा मन्त्री : मैं अर्ज कर रहा था कि हम जो अवाम के नुमायंदे हैं हमें जिन्दगी में फखर हासिल हुआ है अपनी कौम की, अपने हलकों के लोगों की नुमाइंदगी करने का, हमें आज खास तौर पर जब कि सूबा के सामने, देश के सामने इतने बड़े फैसले करने वाली बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस से आवाम के जजबात भड़कें। गवर्नमैन्ट की तरफ से मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर कोई अपना नजरिया लोगों के सामने रख सकता है और अपने विचारों का प्रापेगंडा कर सकता है लेकिन एक हद के अन्दर ही ऐसा होना चाहिए उस से आगे इजाजत नहीं दी जा सकती और न ही दी जाएगी। गवर्नमैन्ट कोई ऐसी बात बरदाशत नहीं करेगी जिस से फिरकादाराना मनाफरत फैले और सूबा का अमन भंग हो। (विघ्न) मैं अब ज्यादा वक्त न लेता हुआ आप का मशकूर हूं जो आपने वक्त दिया है और आपसे चाहूंगा कि हाउस का डैकोरम जो इतना नीचा चला गया है उसे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करें। जहां तक इन बैंचों का सवाल है आपका पूरा साथ ऐसा करने में देंगे ताकि आपकी इज्जत बढ़े, हाउस की इज्जत बढ़े और जिस जिस पार्टी की हम नुमायंदगी करते हैं उस का डैकोरम बढ़े।

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture : Madam, I rise on a point of Order. My point of Order is simply this. It is the practice of this House that when a Minister stands up, the Chair always calls upon him. But to-day, I stood up twice and my name has also been sent up by the party Whip. I was not called upon by the Chair and I feel that the Chair is not fair to me.

Voices from the Opposition Benches : It is a reflection on the Chair.

Deputy Speaker : When three or four Ministers stand up at a time, the Chair is not bound to call upon each one of them.

लाल रुलिया राम (घरौंडा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बजट पंजाब गवर्नमैण्ट ने पेश किया है वह मैं समझता हूं काफी अच्छा है लेकिन इस में कुछ त्रुटियां हैं जो मैं आपके द्वारा गवर्नमैण्ट के ध्यान में लाना चाहता हूं । मैं इस पंजाबी सूबे और दूसरे झगड़े में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ज़रा इस हाउस को संभाल कर रखा जाए और इस को समझाया जाए कि .....

उपाध्यक्षा : रुलिया राम जी, यह न मेरे बस का रोग है और न आपके बस का, आप अपनी बात जो कहनी है कहें (In this connection both of us are helpless. Let the hon. Member express his views on the Budget.)

लाला रुलिया राम : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब के 17 ज़िले हैं .....

कुछ आवाज़ें : 18 हैं ।

कुछ आवाज़ें : नहीं बीस हैं . . . . (शोर)

उपाध्यक्षा : मुझे आप का तो पता नहीं लेकिन कम से कम मुझे तो यह सब देख कर बड़ी शर्म आती है । There must be some decorum in the House. (I do not know, whether the hon. Members feel it or not. But I for one feel ashamed to see all this. There must be some decorum in the House).

लाल रुलिया राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे पंजाब के 20 ज़िले हैं लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य यू.पी. के 52 ज़िले हैं । हमारे इस 20 ज़िलों वाले सूबे पर यू.पी. के 50 ज़िलों के मुकाबले में भारी ऐडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इतना बोझ पड़ा हुआ है कि जनता हाहाकार कर रही है । आप सुन कर हैरान होंगे 52 ज़िलों वाले यू. पी. में तो सिर्फ 40 सैक्रेट्री, डिप्टी सैक्रेटरी, जायंट सैक्रेटरी, अंडर सैक्रेट्री, डायरैक्टर वगैरा हैं लेकिन हमारे सिर्फ 20 ज़िलों वाले पंजाब में इन अफसरों की संख्या 90/92 है । यही वजह है कि जनता पर इतना भारी बोझ टैक्सों का पड़ रहा है । उस के अलावा एक बात और देखने में आती है कि अगर कोई सैक्रेट्री छुट्टी पर चला जाता है तो डिप्टी सैक्रेटरी उस की जगह सैक्रेट्री लग जाता है । जब छुट्टी पर गया सैक्रेट्री वापस आता है तो जो उसकी जगह लगा होता है उसे नीचे नहीं किया जाता बल्कि उस के लिये जायंट सैक्रेट्री या डायरैक्टर की पोस्ट बना ली जाती है और इस तरह यह अफसरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और पंजाब की जनता पर बोझ बढ़ा हुआ है । फिर आप चंडीगढ़ में देखें कि इन अफसरों ने यहां बड़ी २ कोठियां डाली हुई हैं । खुद तो सरकारी कोठियों में रहते हैं लेकिन अपनी कोठियां आगे किराये पर दी हुई हैं । बहुत सारी कोठियों में तो सरकारी दफतर भी चल रहे हैं । अगर उन कोठियों को जो अफसरों को दी हैं खाली कराया जाए और उन्हें अपनी कोठियों में जाने को कहा जाए तो सरकार को एक एक सरकारी कोठी का पांच सात सौ रुपया किराए का मिल सकता है । अगर उन अफसरों को हाउस रैंट के पैसे भी दे दिये जाएं तब भी सरकार को फायदा है । मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो मुलाज़म 500 रुपया तक तन्खाह लेता है उसे ही सरकारी मकान दिया जाए और इस से ज्यादा तन्खाह लेने वालों को मकान अलाट न किया जाए । जितने बड़े

बड़े मुलाज़म हैं उन की तन्खाह कम की जाए और तीसरे और चौथे दरजे के मुलाज़मों क
तन्खाह बढ़ाई जाए। अब मैं ट्रांस्पोर्ट के महकमे के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। जितन
रद्दी से रद्दी गाड़ियां हैं वह इस पंजाब रोडवेज़ में चलती हैं। अम्बाला से करनाल को
ऐसी गाड़ियां चलती हैं जो अडडे से चल कर रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। उन के इन्जन
रेल के इन्जन की तरह धुआं छोड़ते हैं। छकड़े की तरह चलती हैं और चंगे भले आदमी
की हड्डियां उन में सफर करने से दर्द करने लग जाती हैं। पब्लिक को बड़ी भारी तकलीफ
है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिला करनाल के अन्दर बहुत सारा इलाका खादर का इलाका
है। मैं ने वहां की हालत को सुधारने के लिए सिंचाई तथा विद्युत मंत्री साहिब से तथा
चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में कई बातें लाई लेकिन उन की हालत सुधारने के लिये
ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह ठीक है कि पिछले साल फलड्ज़ कम आए जिस की वजह
से वहां का इलाका फलड्ज न आने के कारण बचा रहा लेकिन फलडज को रोकने के लिये
कोई खास कदम नहीं उठाए गए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां के इलाके
की डिवैलपमैंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपए प्रोवाईड करें। वहां पर बिजली पहुंचाने के
प्रबन्ध किए जाएं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टयूबवैल्ज़ लगाए जाने चाहिएं। वहां पर गन्ने
की ज्यादा प्रोडक्शन होती है। सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए फोर्थ फाइव इयर प्लैन
में एक शूगर मिल करनाल में खोलने का प्रबन्ध किया है। मैं इस के लिये सरकार को बधाई
देता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक शूगर मिल खोलने से
फायदा नहीं होगा क्योंकि गन्ने की फसल कैथल तहसील में, शाहबाद के इलाके में तथा
जिला करनाल के आस पास के इलाके में बहुत होती है। एक शूगर मिल वहां के गन्ने की
कंज़म्पशन नहीं कर सकेगी: इस लिये सरकार को चाहिए कि वह दो शूगर मिल्ज़ करनाल
ज़िला के अन्दर लगाने का प्रयत्न करे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिला करनाल के अन्दर तालीम के अदारे में भी इंसाफ नहीं
हो रहा है। वहां न कोई टैक्नीकल कालिज है और गवर्नमैण्ट कालिज भी नहीं है। वहां के
लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिये बाहिर जाना पड़ता है। मैं सरकार से प्रार्थना करना
चाहता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी टैक्नीकल कालिज और गवर्नमेंट कालिज खोला
जाए ताकि वहां के लड़के वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी कांस्टीचुऐंसी के गांव जी.टी. रोड के साथ लगते हैं।
वहां के लोगों को जी.टी. रोड तक आने जाने में काफी मुश्किलें महसूस होती हैं। इस लिये
मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो गांव जी.टी. रोड
से एक मील या डेढ़ मील के करीब हैं, वहां पर लिंक रोड्ज़ बनाई जाएं ताकि वहां के
लोगों को आने जाने में सहूलत हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को मालूम ही है कि पंजाब के बड़े बड़े आफिसर्ज, मिनिस्टर्ज
और एम. एल. एज़. साहिबान दौरा करते समय रैस्ट हाउस में रहते हैं। मैं भी माननीय
सदस्यों में से एक हूं। किसी को यह आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि मैं ने एम. एल. एज़.
साहिबान का नाम लिया है लेकिन मैं महसूस करता हूं कि वह लोग देहात के अन्दर नहीं

जाते। उन्हें देहात के अन्दर जाने के बगैर वहां के लोगों की दिक्कतों का पता नहीं लग सकता इस लिये मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि सरकार पंजाब के अन्दर सारे के सारे रैस्ट हाउस बेच दे ताकि वहां पर सरकारी आफिसर्ज़ और दीगर साहिबान न रह सकें अगर सरकार मेरी बात को मान ले तो सरकार को काफी लाभ हो सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्दर जितने भी बड़े बड़े आफिसर हैं, वह मैडिकल फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। इस तरह से सरकार के लाखों रुपए नाजायज़ तौर पर ज़ाया हो रहे हैं। मुझे पता चला है कि पंजाब के एक बड़े आफिसर ने अपनी बीमारी पर 50 हज़ार रुपए सरकार के खर्च कराए जब कि वह खुद अपने पैसों से इलाज करा सकता था। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को आफिसरों की फैसिलिटीज़ कम कर देनी चाहिए जिस से सरकार का रुपया उन्हीं पर खर्च न हो सके और जो रुपया खर्च होता है, वह जनता की भलाई के लिये खर्च करना चाहिए। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खादर ऐरिया की हालत सुधारने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਤੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਹੋ.......

उपाध्यक्षा : वह सब कुछ एक्सपंज कर दिया है आप अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर हो। आप को ऐसी बातें रेज करनी शोभा नहीं देती। (All that has been expunged. The hon. Member is the Deputy Leader of his party. It ill-becomes him to raise such matters.)

ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਤੀ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਥ ਬਾਗ ਡੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

उपाध्यक्षा : मेरे सामने उन्होंने आप को कई धम्की नहीं दी। जो कुछ उन्होंने अनपार्लियामैंटरी लफ्ज इस्तेमाल किये है, वह एक्सपंज कर दिए गए हैं। Please take your seat. In my presence he did not hold out any such threats. What ever unparliamentary words he used, have been expunged from the record. He may have take his seat.)

(*Interruption by Sardar Lachhman Singh Gill*)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੁਝ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਆਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਰੱਪਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਿਨਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਦੀ ਰਾਮ ਜਾਣੇ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਟਰਾਂਗੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਕਹਿਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਛਡਣ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਮਗਲਰ ਛੱਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਵਰਨੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਬੂਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 25(50)/60-65- **P.M.** ਮਿਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰਜ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਸਮਗਲਰ ਚਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਘ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ **Mr. Hitkari of M/s Sky Lark Cinema, Jullundur,** ਨੂੰ ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

"Now a mean type of mischief just to discourage me by insulting and humiliating me has just come to my notice and I smell your approval. That mean step is being conspired by Shri Brijinder Singh most probably in consultation with the I.G. Police. I am not afraid of any such thing and even arrest or harrassment but want to warn you that you and Police Department through corrupt officers should desist from setting up bad precedents".

ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਆਖਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

"....................Hence with an implicit faith in nature and truth I am writing this letter to you so that either you may clear your position or do your worst by patronising this element like the soldiers of the battle field. You are at liberty to patronise the old henchmen of Shri Kairon with whom you had the privilege to dine at Sham Garh on your previous visit to Karnal. I refuse to believe that I. G. plus S.P. Karnal can have any courage to play any mischief without your blessings."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਯਹ ਦੇਖਾ ਹੈ:—

'ਵੋਹ ਕੌਨਸਾ ਗੁਲ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਚਾਕ ਜਿਸ ਕਾ ਦਾਮਨ,
ਵੋਹ ਬਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਾ ਖਿਜ਼ਾਂ ਸੇ।'

ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ :

'ਵੋ ਪਥ ਕਿਆ ਪੱਥ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਆ,
ਜਿਸ ਰਾਹ ਮੇਂ ਬਿਖਰੇ ਸ਼ੂਲ ਨਾ ਹੋ,
ਨਾਵਿਕ ਕੀ ਧੈਰਯ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਾ ਕਿਆ,
ਜਬ ਧਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਾ ਹੋ।'

ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੌਂਸਲੇ :

'ਧਾਰਾ ਕੇ ਮਵਾਫਕ ਬਹਿਨਾ ਤੋ ਤੌਹੀਨੇ ਦਸਤੋਬਾਜ਼ੂ ਹੈ,
ਪਰਵਰਦਾ ਤੂਫਾਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੋ ਧਾਰੋਂ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਹਿਨੇ ਦੋ।'
'ਐ ਨਾਖੁਦਾ ਸਫੀਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਕਰ,
ਹਮ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈਂ ਕਿ ਸਾਹਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ।'

ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ:

'ਮੇਰੇ ਹਾਥੋਂ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੂਏ ਪਥਰ ਕੇ ਸਨਮ,
ਆਜ ਬੁਤਖਾਨੋਂ ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਬਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈਂ।'

ਆਖਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ :—

'ਅਖਤਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੌਫੇ ਤਲਾਤਮ,
ਮੌਜੇਂ ਜੋ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਲ ਹੀ ਬਦਲ ਡਾਲੂੰ।'

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਤੀ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਐਸੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਦੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਖਿਲਾਫ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਪੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

"I have received your letter dated the 6th January, 1966, regarding unprecedented murders in the District of Karnal and particularly in this week. Government is fully seized of the facts and is looking into the matter with utmost care to find out the exact causes of this heneous crime and how to control it."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਜਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਉ ਵਰਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ :

"..........................since serious allegations had been made against quite a number of members of the police force posted at Karnal, the State despite notice has not considered it fit to enter appearance before me and to make its position clear. The non-representation of the State is likely to create an impression that the State is not interested either in the fair trial of the case or in seeing that the offenders are brought to book. Such an impression should be avoided to the interests of administration itself and to inspire confidence in its impartiality."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ **ਵਿਚਾਰੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਰੀਪੋਰਟ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਉਦੀ ਹੈ ਇਸ** ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਡੀ, ਐਸ. ਪੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਚਿਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਚਿਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੀ ਆਈ. ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਗੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨੇ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਗੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ. . . .

ਆਵਾਜ਼ : ਸ਼ੇਮ. ਸ਼ੇਮ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3247 ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਤਾ—

"The time and labour involved in collecting information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained."

ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਫਸਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਸਨ ? ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 1965.....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹਨ ? (Is the hon. Minister, Sardar Darbara Singh in his seat?)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬੈਠਣ। ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਸਟਰਾਂਗ ਹੈ' 'ਸਟਰਾਂਗਰ ਹੈ' ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟਰਾਂਗ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਿੱਗੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਉ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੌਡੀ ਹਾਉਸ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 45491 ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ, 1965 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਫਾਈਲ ਰਖ ਛਡੋ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ।

ਇਕ **ਆਵਾਜ਼ :** ਮਨਿਸਟਰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Deputy Speaker : Kindly wind up.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ A. I. G. Police ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ 76 ਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, "ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ!" ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟਿਊਟਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਸਟਾਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਕੇ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਕ ਹੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰਖੋ। (The hon. Member Comrade Ram Piara is levelling allegations against a Minister. He can do so by bringing a Substantive Motion against him. He should confine himself to the discussion on the Budget only.)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਟਾਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ A. I. G. ਕਰਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀਆਂ 76 communications ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ।

Deputy Speaker: Kindly wind up.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਇਕ ਕੇਸ ਹੋਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਟਰੇਸਡ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਕਿਉਂ ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਹਰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਔਰ ਅਨਟਰੇਸਡ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—

"The case has been sent with the report that the case be treated as untraced. Since the accused in this case was arested and released on bale from the court, the case cannot be treated as untraced."

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਸਤੰਬਰ, 1964, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਰਾਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਦਿਤਾ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੇਸ ਫੇਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ 5 ਮਈ, 1965 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, 5 ਜੂਨ, 1965 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

Deputy Speaker: Please resume your seat now.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ: ਬਸ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

Deputy Speaker: No please.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ: ਬਸ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਸਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। Please wind up within one minute. (I shall have to devise some means for future to deal with Members who insist on this to continue speaking. This is not proper. The hon. Member may please wind up in one minute.)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ: ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ S. Is. ਵਿਚੋਂ 26 ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :—

"On the other hand there is enough material on the file to suggest that S. I. Gurbax Singh has been indulging in corrupt practices while posted as S. H. O. Police Station Thaska Miranji. He had even gone to the extent of making fabrication in his T. A. bill and records maintained at the Police Station."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਲੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

(ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਦਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Sardar Darbara Singh is equal to Sardar Partap Singh Kairon less his qualities plus his inefficiency and the services being rendered by his Private Secretary, Mr. Mahant, to be disclosed at a later stage.....

ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੰਹਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। (ਵਿਘਨ)

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहिबा....

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, आप बैठिए और छोड़िए इन बातों को। (The hon. member may please leave this matter and resume his seat.)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कामरेड राम प्यारा ने हाउस के अन्दर होम मिनिस्टर के खिलाफ बड़े सीरियस अलज़ाम लगाए हैं कि उन्होंने मर्डर करवाए हैं और लाश को रिमूव कराया है, वगैरा वगैरा। यह बड़े अहम अलज़ामात हैं। मेरी आप से रिक्वैस्ट है कि आप सरकार को कहें कि वह इन बातों का जवाब दे और हाउस को यकीन दिलाए कि क्या कामरेड राम प्यारा ने गलत बातें कहीं हैं या कि होम मिनिस्टर ने ऐसी कार्यवाही नहीं की है। अगर होम मिनिस्टर ने खुद इस तरह की कार्यवाइयां की हैं तो पंजाब के अन्दर किसी की भी इज्ज़त महफूज़ नहीं रह सकती। इस के अलावा इन्होंने जो रात के खर्चे वाली बात कही है इसका भी पता लगवाएं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉਤੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੇ ਔਰ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਜੀ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟੰਡਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ..... .....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਗਲ ਸੁਣ ਲਉ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟਾ 26 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹਿ ਲਉ। (The hon. Member may please listen to one thing. His group leader has spoken for one hour and 26

[ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ]

minutes. It would be proper that if at all he has to say anything about this matter, he may do so after he has referred to matters relating to his constituency.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਾਂ ਕਰਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। (I have not prevented the hon. Member from speaking.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਚਿਕੜ ਸੁਟਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਖ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਰੇਕ ਲਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਮੰਨ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਉਠਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਉਹੀ ਮੁਠੀ ਭਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ।

ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 99 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ (ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਈਸ਼ੂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ 7 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਸਿਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : 15 ਨਹੀਂ, 25 ਨੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।)

ਲਉ ਜੀ 25 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਡ ਹਰੀਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਲੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬੜੀ ਹੈ ?

ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਕ ਬੁਕਾਂ ਚੁਕ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੱਟ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਹਿਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਵਾਏ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।

ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਰੋਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸ਼ਲਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਤਕ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ **ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ।**

उपाध्यक्षा : सदन कल 9-30 बजे सुबह तक के लिए स्थगत किया जाता है ।

(The House stands adjourned till 9-30 A. M. to-morrow.)

*(The Sabha then adjourned till 9-30 A. M. on Thursday, the 10th March, 1966.)

8860/PVS—384—30-8-66—C., P. & S., Pb., Chd.

APPENDIX

To

Punjab Vidhan Sabha Debates dated the 9th March, 1966
Vol. 1-No. 15

---

*FURTHER INFORMATION RE. STARRED QUESTION No. 9271.

Statement showing the names of Government High/Higher Secondary Schools of Jullundur District without Headmasters/staff.—

1. Government High School, Samrai Jandiala
2. —do— Nakodar
3. —do— Shanker
4. —do— Rahon
5. —do— Aur
6. —do— Nurmahal
7. —do— Pharala
8. —do— Khurdpur
9. —do— Goraya
10. —do— Naura
11. Government Girls High School, Jandiala
12. —do— Dosanjh Kalan
13. —do— Model Town, Jullundur
14. Government Girls Higher Secondary School, Shanker
15. Government Higher Secondary School, Rurka Kalan
16. Government Model Higher Secondary School, Jullundur.

---

*NOTE.—Starred Question No. 9271 alongwith its answer is printed at page (15) 10 of this Debate.

8860 P.V.S.—384—29-8-66—C., P. & S., Pb., Chd.

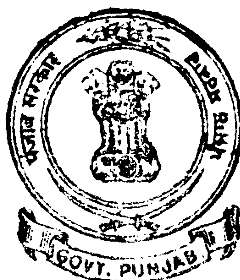
PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

10th March, 1966

Vol. I, No. 16

OFFICIAL REPORT



CONTENTS

Thursday, the 10th March, 1966

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh

Price : [illegible]

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 16, dated the 10th March, 1966.

Read	*For*	*Page*	*Line*
रिपोटें	रिपोट्रें	(16)4	9
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ	ਉਨ੍ਹਾਂ	(16)10	2
लोग	लोगे	(16)10	4 from below
आप	अ प	(16)12	29
ਸਰਕਾਰ	ਸਰਕਾਟ	(16)13	5
the	he	(16)17	10
Posts of	posts	(16)33	Last but one
foodgrains	foodgrins	(16)41	27
accuont	accoun	(16)41	27
Complainant	Complaintant	(16)43	Last but one
spot	sport	(16)43	last
VEGETABLES	VEGEABLES	(16)44	1
TAMPERING	TEMPERING	(16)46	1 and 5
Girdawari	Girdwari	(16)46	6
Kapurthala	Kapurthal	(16)46	9
Settlement	Settlenent	(16)46	10
departmental	deportmental	(16)49	14—15
Minister	Minster	(16)50	Heading
against	againlst	(16)50	14
allegations	alegation	(16)50	15
involved	involed	(16)50	18
and	nd	(16)50	19
not be	not	(16)52	23
District	Districts	(16)52	34
Chopra	chopre	(16)65	7 from below
affect	effect	(16)75	27
ਗੰਭੀਰ	ਗੰ ੀਰ	(16)83	10 from below
सैक्रेटरीज़	सकेटरीज़	(16)105	10
प्रोपोर्शन	प्रोपोर्णन	(16)105	11
पोस्टस	योस्टस	(16)105	12

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
एजूकेशन	एज्यूक्शन	(16)105	12
की	को की	(16)106	7
अपने	आपने	(16)106	20
इन्डस्ट्रियलिस्टस	इंडस्ट्रियस्टिस	(16)106	26
इन का वोकल	इन वोका कल	(16)106	7 from below
एक्सैप्ट	एक्सप्ट	(16)106	5 from below
चाहिए	कहिए	(16)106	3 from below
होना चाहिए	होन चाहिए	(16)106	first
है	ह	(16)107	17
[10th	1oT	(16)108	Heading
चौधरी	चाधरी	(16)108	First
तौर	तोर	(16)108	5
और	आर	(16)108	6
वर्किंग	वकिग	(16)108	7
टेंडैंसी	टैन्डैन्हसी	(16)108	8
सवाल	साबाल	(16)108	14
इसी	इसो	(16)108	7 from below
में	म	(16)109	10
मित्तल	मिहतल	(16)109	11
प्रिंसिपल	प्रिन्सिपल	(16)109	20
आप को	आप	(16)109	6 from below
सिंह	सिं	(16)110	5
जबान	यबान	(16)110	12
अर्सा	अरवसा	(16)110	17
रह रहे	रहे	(16)110	19
रवायत	रावरत	(16)110	5 from below
और	गौर	(16)110	2 from below
देना है	देना	(16)111	4
कमांड	कमां	(16)111	15
जो	जोय	(16)111	23
कुछ	कुच्छ	(16)111	25
पिसते	प्सिते	(16)112	2
रख	करख	(16)112	5
प्रताप सिंह कैरों	प्रताप सिंह करों	(16)112	6
ਮੰਤਰੀ	ਮਤਰੀ	(16)112	9 from below

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਮੁਤੱਲਿਕ	ਮੁਤਾਲਕ	(16)112	7 from below
ਨੂੰ	ਨੂੰ ਨੂੰ	(16)112	Last
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ	ਰਜ਼ੋਲਿਓਸ਼ਨ	(16)113	1
ਕ਼ਢ	ਕਢ	(16)113	7 from below
mover	move	(16)115	18
motion was	was motion	(16)115	9 from below
Seat	eat	(16)115	6 from below
ਨਹੀਂ	ਨਰੀਂ	(16)116	21
ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ	ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ	(16)116	last but one
House	H use	(16)117	14
(Amendment) Bill,	(Amendment Bill,	(16)117	4 from below
hon. Minister	hon. Member	(16)118	7
business	bu iness	(16)118	8
Deputy Speaker	Mr. Speaker	(16)118	6 from below
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ	ਉਨ੍ਹਾਂ	(16)122	13
That	T	(16)124	10

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 10th March, 1966

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh at 9-30 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

BLOCK LEVEL EXTENSION OFFICERS (INDUSTRIES)

*9728. **Comrade Shamsher Singh Josh** (put by Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the actual Number of Block Level Extension Officers (Industries), withdrawn from the various blocks and posted at the Headquarters /District Offices;

(b) whether it is a fact that the said officers have been assigned duties other than those for which they were specially trained at Government expense;

(c) the reasons for the withdrawal of the said officers and the duration of the period for which they have been withdrawn from the blocks ?

Shri Ram Partap Garg: (Chief Parliamentary Secretary): (a) Eighteen Block Level Extension Officers (Industries) have been withdrawn from various Blocks and posted at Headquarters or district offices.

(b) No.

(c) The Block Level Extension Officers (Industries) have been withdrawn from certain Blocks to assist the District Industries Officers and the Headquarters Officers in the disbursement of additional emergency loans, defence production work and similar measures being taken for the rehabilitation of Industry in the State which suffered a serious set back during the Pakistani aggression in September, 1965. The duration is 3 months for the present but it may be extended, if found necessary.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਰਾਗਰੈਸ ਵਿਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਨਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰੇਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਰੇਨ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਪੰਡਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਦੱਤ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼) ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਆਇਆ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬੀ. ਐਲ. ਈ. ਓਜ਼. ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਓਥੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਓਥੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਟੂ ਹੈਲਪ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ । ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : ग्रान ए प्वांयट ग्राफ ग्रार्डर, सर । सरदार ग्रजायब सिंह ने पंजाबी में सवाल किया ग्रौर चीफ पार्लियामैंटरी साहिब नें पंजाबी में जवाब दिया है, क्या यह हाई कमांड के फैसले की बात हैं ?

EXCESS BUS FARE CHARGED BY THE FAZILKA-DABWALI TRANSPORT CO., (PRIVATE) LTD..

*9788. **Chaudhri Satya Dev** (put by Shri Fateh Chand Vij): Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether he has received any complaint in regard to the excess bus fare charged by the Fazilka-Dabwali Transport Company Private Limited from the passengers who travelled by its buses from Fazilka to Abohar during the Indo-Pak conflict; if so, the action, if any, taken by the Government in this matter ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Yes. But the allegations were not substantiated during the course of enquiries.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ?

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਵੈਸੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ੁਗਨ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ there was no person of this name. ਇਕ ਸ਼ੁਗਨ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

श्री फतेह चंद विज : क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह इंक्वायरी किस अफसर के जरिए करवाई गई ?

मंत्री : पहले मोटर वैहिकल्ज़ एक्ट के तहत हुई । इसके बाद एस. डी. श्रो ने भी की है ।

श्री फतेह चंद विज : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो एलीगेशन्ज़ हैं क्या इन की इंक्वायरी किसी और अफसर के ज़रिए कराने के लिए तैयार हैं ?

मंत्री : जैसे भी आपकी तसल्ली हो सकती है कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन allegations have been also enquired into by the S. D. O. (Civil) Fazilka.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जब इंक्वायरी अफसर ने इंक्वायरी की उस वक्त कंप्लेनैंट को बुलाया था या नहीं ?

मंत्री : मैं अर्ज़ करूंगा कि शुगन लाल जो कंप्लेनैंट था वह आया नहीं । उसका एड्रैस जो दिया था वह सरपंच का था । पंचायत ने कहा कि इस नाम का कोई आदमी नहीं है । श्री कुलबीर सिंह के बारे में डेट्स हैं कि वह उनके पास कितनी दफा गए । वह कंप्लेनैंट था । They visited his residence on 14, 27 and 28th. वह 3 दफा गए ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise out of this question. ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । (This supplementary does not arise out of this question which is about a particular complaint.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤ੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਹਿਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

Minister : That was on the complaint of these persons which was not substantiated.

श्री फतेह चद विज : एक तो इंस्पैक्टर के ज़रिए इंक्वायरी की गई और दूसरी एस. डी. ओ. के ज़रिए क्या ट्रांसपोर्ट मंत्री बताएंगे कि यह दोनों रिपोर्ट्स एक जैसी हैं या आपस में डिफर करती हैं ?

मंत्री : वह आदमी ही नहीं मिला है । जिस गांव का एड्रेस दिया था वहां की पंचायत ने कहा कि यहां इस नाम का कोई आदमी नहीं है ।

REPORT OF ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION

*9893. **Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government have received the report of the Administrative Reforms Commission;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether it is proposed to place a copy of the said report on the Table of the House, if not, the reasons therefor ;

(c) whether the Government have accepted all the recommendations made in the said reports, if not the reasons therefor;

(d) the total number of Government employees likely to be affected if the relevant recommendations of the said Commission are accepted and the estimated annual saving as a result thereof ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : (a) Yes.

(b) No. It will not be in the public interest to place a copy of the report on the Table of the House till the Government have had the opportunity to study the recommendations made therein.

(c) The report has just been received and the recommendations contained therein are being looked into.

(d) It is not possible to give information of this nature at this stage.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Chief Parliamentary Secretary as to how long will it take the Government to give consideration to the report of the Administrative Reforms Commission ?

Chief Parliamentary Secretary : No time can be fixed. It is a lengthy report and the Government has got to study it.

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Chief Parliamentary Secretary if it is a fact that there are specific observations by the Administrative Reforms Commission that administration in Punjab is paper-logged as Punjab is water-logged ?

Chief Parliamentary Secretary : I cannot say. So far the report has not been discussed by Government.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?

Is it a fact that the Commission has recommended that the number of Ministers in the State should not exceed ten ?

Education Minister : The Chief Parliamentary Secretary has already stated that the Government is giving consideration to the report of the Commission and if by indirect implications any hon. Member wants him or the Government to give contents of the report, I don't think he will succeed. But whatever has appeared in the Press has not leaked through the Government. The Chairman of the Commission held a Press Conference and he might have said something. The Government is not aware of it.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Supplementary, Sir.

Mr. Speaker : When the details are not being disclosed, what useful purpose would be served by putting more questions.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, the Commission of a very high level with the Chairman from outside the State was appointed by the Government and Government is not ready to give specific information about the recommendations of the Commission. But, I think, we should be given an opportunity to get out something which may not be relating to facts but other points.

Mr. Speaker : All right.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Education Minister if the Government can at all turn down the recommendations of the Commission ?

Education Minister : At no stage either the Chief Parliamentary Secretary or any representative of the Government has said this. We will certainly take the House into confidence, discuss it with them and have the privilege and pleasure of their wise guidance and do whatever we can in the interest and betterment of the State.

श्री फतेह् चन्द विज : पंजाब सरकार ने छांटी का प्रोग्राम बनाया है क्या उस में यह चीज़ करने को तैयार है कि छांटी पहले ऊपर से करके फिर नीचे से की जाए ?

Education Minister: This reduction has not taken place as a result of the recommendation of the Commission.

That has taken place independent of that Report and whatever possibly the Government can do for the betterment of the State keeping in view the recommendations of the Commission, we will certainly do and take the House into confidence.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਗੇਗਾ ? ਕੀ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ?

Education Minister: The Chief Parliamentry Secretary has already stated that it may not be possible to give the exact date but I can assure the House that we will try to decide about it as early as possible and I think it will be possible for the Government to take the House into confidence before we meet for the next session.

COMPLAINTS REGARDING NON-IMPLEMENTATION OF ASSURANCES GIVEN BY THE CHIEF MINISTER

*9251. **Dr. Baldev Parkash** (Put by Shri Fateh Chand Vij) : Will the Chief Minister be pleased to state whether he has received any complaints to the effect that the District officers do not comply with the assurances given by him outside the House and that people are put to a great hardship; if so, the action if any, taken thereon ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : It is regretted that in the absence of probable month or date of the complaints, it is not possible to furnish the requisite information.

ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਇਨਸਟਾਂਸ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

श्री फतेह् चंद विज : पिछले दिनो ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि मिनिस्टर जो बाहिर ऐलान कर आते है गवर्नमैंट उन को मानने के लिए तैयार नहीं । लेकिन चीफ पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी साहिब ने कहा है कि अगर उन के नोटिस में स्पैसेफिक चीज़ लाई जाए तो वह कनसिडर करेंगे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्या ऐक्शन लेंगे ?

Education Minister : Sir, the other day while speaking in the Upper House I had said that the speeches or pronouncements made by the Ministers/Chief Minister outside the House are not binding on the Government. They are the pious wishes, sentiments and the intentions of the Government to do something. I gave the constitutional position that the statements made outside the House are not binding on the Government. The Government is bound by the assurances given on the floor of the House and the Cabinet decisions.

Pandit Chiranji Lal Sharma : In view of the reply to the supplementaries given by the Chief Parliamentary Secretary and the hon. Education Minister, will the Government kindly give the definition of 'assurance' ? Do the assurances given outside the House fall within the definition of 'assurance' as given in the Rules ?

Education Minister : I would like the hon. Member to read May's Parliamentary Practice and also see a number of pronouncements of the Speaker, Lok Sabha and the Speakers of other State Assemblies that the assurances for the purposes of the Assurances Committee mean the assurances given on the floor of the House. Anything said outside the House is not within the purview of the Assurances Committee and cannot be treated as an assurance.

Mr. Speaker : I may also make it clear that so far as the technical term 'assurance' is concerned that is defined under the Rules of Business of the Assembly. Only those assurances can be considered by the Assurances Committee which are given on the floor of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma : In view of the reply given by the Education Minister and the observations made by your goodself, shall we take it that the answer given by the Chief Parliamentary Secretary is wrong and against facts ?

Mr. Speaker : I said that the Assurances Committee can go into those assurances which are given on the floor of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma : He has just replied that the assurances given by the Ministers outside the House will also be implemented.

Mr. Speaker : It is for the Government to decide.

Transport and Elections Minister : Mr. Speaker, on the point, that has been raised, I want to submit that if there is any doubt about the nature of any assurance or its effectiveness that can be examined by you and a ruling given. Since you have already made certain observations, I don't think there is any scope left for any doubt. It is unfortunate that any statement given outside the House cannot be treated as an assurance and is, therefore, meaningless. But it, sometimes, as you know, depends upon person to person and the reporting done. Sometimes misreporting is done which puts the Minister in an awkward position. You are very well aware, Sir, that sometimes many things are put into our mouths. It is known to both the sides of the House. Therefore, the only authentic assurance which should be effective should be that which is given on the floor of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, my point of order is very simple. I want your ruling whether the reply given to a supplementary question by the Chief Parliamentary Secretary that the assurances given outside the House will be fulfilled is wrong in view of the definition given by you and the Education and Transport Ministers ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਨਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ । (Any assurance given on the

[Mr. Speaker

floor of the House, if not honoured, will be looked into by the Assurances Committee but it has nothing to do with any assurance given outside the House. It is the duty of the Government to look to its implementation).

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿਚ ਅਗੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ?

Mr. Speaker ; You do not treat them as assurances.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਗਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ?

Education Minister : Sir, I think the hon. Members are mixing two things. I just explained the constitutional position that only those statements can be taken as assurances which are made on the Floor of the House. The promises and intentions of the Government that are declared in public meetings, they are the pious intentions and desires of the Government to do something but constitutionally Government is not bound to fulfil all those promises.

INDO-PAKISTAN CONFLICT AFFECTED PERSONS STATIONED AT ABOHAR CAMP

***98/5. Sardar Kulbir Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) the number of war hit persons in the Abohar Camp;

(b) the number of quilts (Razais) and blankets and the details of medical facilities provided to the persons mentioned in part (a) above together with the total expenditure incurred on these items todate ; and

(c) the details of the educational facilities provided for the Children of the residents of the said camp, alongwith the number of students and the number of teachers provided for them, with the total amounts spent on the educational facilities ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) 2,303.

(b) 2,118 quilts and 436 blankets have been supplied to the inmates of the Camp at a total cost of about Rs. 55,378.

A dispensary has been started in the Camp for catering to the medical needs of the campers. Information regarding expenditure incurred on running the dispensary is not available.

(c) The children of the residents of the Camp are being provided with free education in Government and other private schools at Abohar. No claim for reimbursement of charges for educating the children in private educational institutions has so far been received.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 50 ਸਨ ਪਰ ਆਨ ਦੀ ਸਪਾਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ 12 ਨਿਕਲੀਆਂ—

—from the very day they came to the camp and up to the date on which you issued the statement. The statement was rather unfair.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਅਥਾਰੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਉਸ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖਿਆ..

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰੋ ਸਪੀਚ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member may put the supplementary. He should make a speech)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਛੌਲਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਐਨੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੈਂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਹੀ ਚਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਓ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਇਹ ਜੋ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਲੂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ I do not think it is unnatural.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਜੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ । ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਵਾਰ ਹਿਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਥੇ ਦੇ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਧਰ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀ ਡਿਫੀਟ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ROUTE PERMIT FROM TALWARA TO NADAUN VIA DADA DHALIARA

*9293. **Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a route permit from Talwara to Nadaun *via* Dada Dhaliara was sanctioned in favour of Prabhat Co-operative Transport Society, if so, when ;

(b) the date up to which the said society operated on the route referred to in part (a) above ;

(c) whether the said society is now operating on the said route, if not, the reasons therefor;

(d) whether the Government has considered the question of permitting another Co-operative Transport Society to operate on the said route to meet the transport needs of the public?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) A route permit was sanctioned in favour of Harsamansar Prabhat Transport Co-operative Society Ltd ; in 1961.

(b) Up to 1964 regularly.

(c) No. The road between the two stations is 'kacha' and has become unmotorable due to constant plying of buses and lack of proper maintenance.

(d) No other society has offered to operate the service as the road is unmotorable.

ठाकुर मेहर सिंह : वज़ीर साहिब ने बताया है कि यह रूट कच्चा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त रूट सैंकशन हुआ था। उस वक्त भी यह कच्चा था तो फिर क्या वजह है कि बस नहीं चलती ?

ट्रांस्पोर्ट मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि 1964 तक तो चलती थी लेकिन उसके बाद यह सड़क ज्यादा ट्रैफिक चलने की वजह से खराब हो गई; मेनटेनैंस हुई नहीं इस लिए बस चलाना मुश्किल हो गया और जो लोग चिलाते थे उन्हें बन्द करना पड़ा।

ठाकुर मेहर सिंह : वह सड़क बिल्कुल ठीक है बल्कि आगे से भी अच्छी है। वह तो दीदा दानिसता बसें नहीं चला रहे क्यों कि उनके पास बसें नहीं।

मंत्री : जब आपने दरखास्त दे दी है और लिखवा कर ले गए हैं कि इस की पड़ताल करो तो फिर दोबारा पूछने की क्या ज़रूरत है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, shall I take it from the reply given by the hon. Minister for Transport and Elections that the recommendations for the issue of the route permit made by the Regional Transport Authority can be turned down by the Provincial Transport Controller ?

Minister for Transport and Elections: Sir, I am told that this is not a relevant question.

Mr. Speaker : I have allowed this question.

Minister for Transport and Elections : Sir, this is the procedure but if this is rejected there is an appellate authority and they can go to that authority. Sir, everything is provided.

Unfortunately, in this State the impression goes that the Government grants it. They come to me and I just write to the R. T. A. or the P. T. C. Very responsible persons come to me. It is an unfortunate convention and I have discontinued it.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Transport Minister as to who is the final authority to give route permit-R. T. A. or the P. T. C. ?

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री: स्पीकर साहिब, इस बारे में लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है । वह मेरे पास आ जाते हैं । रिजनल अथार्टी वालों ने रूट परमिट्स के लिए फार्मज़ छपवाए हुए हैं । उन को रूट परमिट्स लेने के लिए फिल करना पड़ता है। जब फार्म फिल कर लिए जाते हैं तो वह फार्मज़ रिजनल ट्रांस्पोर्ट अथार्टी को दे दिए जाते हैं । उस के बाद ए. आई. जी. उन फार्मज़ की वैरीफिकेशन करता है कि उस व्यक्ति के पास ट्रक या रिक्वायर्ड चीज़ है या नहीं । उस के बाद प्रोविंशियल कंट्रोलर, पंजाब के पास केस आ जाता है । इस के फाइनल आर्डर्ज़ होते हैं । प्लेन्ज़ के अन्दर रूट्स के देने में मुश्किल पैदा नहीं होती है जितनी कि बाकी जगह पर होती है ।

I am sorry, this is not relevant. अगर आप चाहें तो और भी इन्फार्मेशन दे सकता हूं लेकिन स्पीकर साहिब यह न समझें कि मैं बिलकुल आउट आफ स्कोप जा रहा हूं ।

GRANT DISTRIBUTED IN GURGAON DISTRICT TO THE FAMILIES OF ARMY PERSONNEL KILLED IN THE RECENT INDO-PAK CONFLICT.

*9331. **Shri Roop Lal Mehta** : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the grants distributed by the State Government in Gurgaon district to the families of Military Personnel who were killed in the recent Indo-Pak conflict ?

Shri Ram Partap Garg [Chief Parliamentary, Secretary]: The details of the *ex-gratia* grants distributed by State Government are as under :—

(1) Officers............	Rs. 5000/-	Rs. 500/- to be paid in cash and the balance amount in the form of National Savings Certificates. State Government however, reserve the right to pay the entire amount in lump sum in hard cases.
(2) J. C. O.s..........	Rs. 3000/-	
(3) Other ranks........	Rs. 2000/-	

श्री रूप लाल महता : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला गुड़गांव के लिए जितनी ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट मंज़ूर हुई थी, क्या वह सारी की सारी सम्बधिंत लोगों को तकसीम कर दी गई हैं या नहीं ?

मुख्य संसद सचिव : कंनसर्नंड सब लोगों को तकसीम कर दी गई है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the Chief Parliamentary Secretary if the *Ex-gratia* grants were also given to the widows of those officers who were serving in the P. A. P. and were killed in action ?

Chief Parliamentary Secretary: Sir, I need notice.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I rise on a point of Order. This point has been explicitly stated in the Governor's Address.

Mr. Speaker : Then why does the hon. Member seek this information ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I pity the ignorance of the Government. When something has been explicitly stated in the Address of the Governor.... -

श्री अध्यक्ष: आप ने जो सवाल किया, वह डैफिनेटली आउट आफ स्कोप है। मैं ने आप को सवाल करने की इजाज़त इस लिए दे दी थी कि आप का सवाल कुछ एक्स ग्रेशिया ग्रांट्स से सम्बन्ध रखता है। अगर माननीय चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब के पास पाज़ेटिव इन्फर्मेशन न हो तो वह सेपेरेट नोटिस के लिए कहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह वाजिब बात है। अगर वह वेग इन्फर्मेशन के आधार पर हाउस में इन्फर्मेशन दें तो ठीक नहीं है।

(The supplementary question put by the hon. Member is definitely out of scope. I had allowed the hon. Member to put the question as it related to *ex-gratia* grants. When the Chief Parliamentary Secretary does not have positive information and he asks for a separate notice I consider the request to be justified, but if he gives this House vague information, it would not be proper.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I rise on a point of Order. My submission is that the Governor's Address is nothing but a policy of the Government. Anything that has been stated in the Governor's Address, our Minister sitting here should know. . .

Mr. Speaker : There should be no reflection please.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : उन्हें 500 रुपए नकद दिया जाता है और बाकी की राशि नैशनल सेविंग्ज़ सर्टीफिकेट्स के रूप में दी जाती है । अगर कोई हार्ड केस हो तो सारी ग्रांट नकद दे दी जाती है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : हमें गवर्नमैंट आफ इंडिया से इन्स्ट्रक्शनज़ आई है कि उन के नाम डिस्क्लोज़ न किए जाएं, इस लिए यह इन्फार्मेशन नहीं दी जा सकती है ।

WIDENING OF BHIWANI-ROHTAK ROAD

***9589. Shri Sagar Ram Gupta** : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether the Government received any representation from a Legislator during the year 1965, for widening of the Bhiwani-Rohtak Road; if so, the action, if any taken thereon ;

(b) whether it is proposed to widen the said road in the near future ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) & (b) Yes, Sir. In the 1st phase the portions of the road which pass through Abadis are being widened. As regards the rest of the portions of the road, the matter is being examined.

श्री सागर राम गुप्ता : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब शुरू की जाएगी और कब तक तैयार हो जाएगी ?

लोक कर्म मंत्री : मैं इस समय नहीं बता सकता कि यह सड़क कब तक चौड़ी कर दी जाएगी क्योंकि यह मामला अभी तक ज़ेरे गौर है ।

श्री सागर राम गुप्ता : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मालूम है कि यह सड़क उन की कांस्टीच्युएंसी में से हो कर गुज़रती है, इस लिए उन्हें यह सड़क जल्दी तैयार कराने का यत्न करना चाहिए ?

मंत्री : वैसे सड़क किसी न किसी हलके में से हो कर जानी ही है । यह सड़क माननीय सदस्य की कांस्टीच्युएंसी से हो कर भी गुज़रती है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਰਣ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This is not allowed.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, May I ask the hon. Minister for Public Works if the Government have considered the recommendations of the Haryana Development Committee regarding the construction of roads ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पार्टीकुलर सड़क के बारे में है । (This main question is about a particular road.)

Public Works Minister : This is under active consideration of the Government.

METALLING OF MUBARAKPUR-TALWARA ROAD

***9118. Principal Rala Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether the metalling of the Mubarakpur-Talwara road *via* Daulatpur has been started ; if not, the reasons therefor ;

(b) whether the Government have since decided to start the metalling work on the said road immediately as a relief measure to meet the scarcity conditions created by the prolonged drought in these hilly areas ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) No, the finalization of alignment and preparation of detailed estimates have recently been completed and the work is being started.

(b) No.

APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR OF KURUKSHETRA UNIVERSITY

***9550. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether he received any request from the Central Government to look into the appointment as Vice-Chancellor of a University in Punjab of an I. A. S. Officer of the Madhya Pradesh Cadre who was compulsorily retired in February, 1963, by the President of India on the recommendation of the Union Public Service Commission ;

(b) if the reply to part (a) above in the affirmative, the date when the said request was received and whether the Chlef Minister entrusted this enquiry to some Senior Officer of the State Government ;

(c) the name and designation of the said enquiry officer together with a copy of the enquiry report, if submitted by him be placed on the Table of the House ;

(d) whether the said enquiry report was sent to the Central Governmet, if so, when ?

Shri Prabodh Chandra (Minister for Education) : (a) Yes.

(b) & (c), 10th November, 1965. The inquiry was not entrusted to any officer. However, the Chancellor (Governor, Punjab) who is the appointing authority in the case of this Vice-Chancellor, has been requested to look into the matter; and the matter is still under his consideration.

(d) In view of the reply to (b) and (c) above, the question does not arise for the present.

श्री फतेह चंद विज : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वाइस चांसलर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत मध्य प्रदेश में थी और उसे सर्विस से जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था और क्या उस के बर्खिलाफ कोई इन्क्वायरी अब चल रही है ? अगर इन्क्वायरी चल रही है तो क्या इस का फैसला जल्दी हो रहा है या नहीं ?

Minister for Education : Sir, I am one with the hon. Member that a great blunder has been committed. But the Government was not aware of the fact that Dr. Bool Chand was compulsorily retired. Before he was appointed as Vice-Chanceller, he was acting as a Professor of Political Science in the University. Therefore, the Government did not think it advisable or essential to go into his past antecedents. Now the matter has been brought to the notice of Government and the Chancellor has been requested to look into the case. I hope decision will be taken early.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the honourable Education Minister if it is not a fact that before his appointment as a Professor of Political Science in the Punjab University, the Syndicate of the said University had looked into the case in detail and haa come to the conclusion that there was nothing objectionable to his appointment as Professor of Political Science ?

Education Minister : I am afraid, I cannot say whether the Sayndicate had looked into the case or not. But, when it was brought to the notice of the Government that the man so appointed, had been compulsorily retired, they decided to look into the case thoroughly.

Chaudhri Hardwari Lal : Will the Minister kindly lay on the Table of the House the factual charges which the Vice-Chancellor had to face, while he was a Member of the I. A. S., and the actual findings of the U. P. S. C.

Education Minister : I can read out the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 10, dated the 28th February, 1963, Published in the Gazette of India dated the 9th March, 1963. It is stated therein :

> "No. F. 7/12/62—VIG—The President, in consultation with the Union Public Service Commission, hereby compulsorily retires Dr. Bool Chand, an officer of the Madhya Pradesh Cadre of the Indian Administrative Service, from the service with immediate effect."

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the honourable Education Minister if it is not a fact that there were absolutely no charges involving integrity, moral turpitude or dishonesty on the part of the said Vice-Chancellor, in Madhya Pradesh?

Education Minister : The findings of the Union Public Service Commission are that he was 'guilty of gross negligence of duty' and that as a responsible officer he should have behaved better than he did.

Chaudhri Hardwari Lal : The honourable Minister has not replied to my question. I want to know whether he is prepared, either today or even later, to lay on the Table of the House the actual charges he had to face and the findings of the U. P. S. C. ? It is unfair to the man concerned, if we discuss him on the floor of the House, when we have no charges and the actual findings of the U. P. S. C. before us.

Education Minister : I can read out the actual findings..........

श्री अध्यक्ष : अगर लम्बी नहीं है तो.. (If it is not lengthy)

शिक्षा मंत्री : आधा सफा है, जनाब ।

श्री अध्यक्ष : पढ़ दीजिये (The hon. Minister may read it out.)

Eduction Minister : I can read out the facts leading to the compulsory retirement of Dr. Bool Chand, as supplied to us by the Government of India, Ministry of Home Affairs. But, this would not be in the interest of Dr. Bool Chand nor in the interest of the University itself. I can, however, explain to the honourable Members these facts personally.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : हाउस की प्रापर्टी है, आप पढ़ कर सुना दीजिये ।

शिक्षा मंत्री : अगर स्पीकर साहिब इजाज़त दें तो मुझे पढ़ कर सुनाने में इनकार नहीं है,

becuase the enquiry is still pending.

Mr. Speaker : Does the honourable Member still insist that the charges, etc., should be read out ?

Chaudhri Hardwari Lal : Yes. Sir. There is no enquiry pending now.

Education Minister : As the honourable Member still insists, I, very reluctantly, would like to give the details, because it does not look nice that the man so highly placed should be discussed in the House.

The facts leading to the compulsory retirement of Dr. Bool Chand, as supplied by the Ministry of Home Affairs, are as follows :

"Dr. Bool Chand, an officer of the Indian Administrative Service, borne on Madhya Pradesh Cadre, was called upon on 23rd June, 1961, to answer the following four charges: —

Charge No. I. That while he was Collector, Rajgarh, he accepted a large number of gifts totalling Rs. 2,559 in value without the permission of State Government at the time of marriage of his daughter in June, 1958, in contravention of Rule 10 of the All India Services (Conduct) Rules.

Charge No. II. That he, on or about the 31st December, 1957, purchased a plot of land measuring about 2.28 acres, including an old bungalow, two wells, a mango grove and other trees, from the Ruler of Khulchipur for Rs. 1000 only in the name of his wife, the transaction apparently not having been conducted through any regular or reputed dealer. Dr. Bool Chand, however, failed to obtain the previous sanction Government as required by proviso to Rule 15 of the All India Service (Conduct) Rules, nor did he even give previous intimation to the Government as required by the main text of the said rule ,

Charge No. III. That while relinquishing charge of Rajgarh District, he recorded an irresponsible and malicious statement in his charge note dated 5th December, 1958, regarding the association of intimate character of the Commissioner, Bhopal, with one Shri R. L. Gupta, a pleader of Zirapur .

Charge No. IV. That in June, 1958, he got removed, without Government, permission, a Government safe from the Rajgarh Treasury, first to his bungalow at Rajgarh and then to the residence of a friend of his at. Gwalior, with an ulterior motive".

I may further state that Shri K. Radhakrishanan, I. C. S., who was then President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, was appointed as Inquiry Officer. The Inquiry Officer found that charges 1, 2 were not proved, charge 3 proved and charge 4 proved to the extent

that Dr. Bool Chand removed the safe without Government permission first to his bungalow at Rajgarh and subsequently to the house of a friend at Gwalior, but he had no ulterior motive.

श्री फतह चंद विज : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि उन की पुरोटोकल साइंस के प्रोफैसर की अप्वायंटमैंट करते वक्त बोर्ड के नोटिस में यह एलीगेशन नहीं आए ?

शिक्षा मंत्री: मैं ने जवाब दिया कि —It isnot for me to say— कि उस वक्त सैनिट ने कोई इन्क्वायरी की या नहीं की, या उन के नोटिस में यह बात थी या नहीं थी.... All that I can say is that it was not within the knowledge of the Punjab Government or he Chancellor when the gentleman was appointed as Vice-Chancellor of the Kurukshetra University.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Transport Minister, who was then a member of the Syndicate, state whether these charges had been gone into by the Syndicate ?

Mr. Speaker: It cannot be put to him. The question can be put only to the Minister Incharge. I cannot allow the question to be put in this manner.

Pandit Chiranji Lal Sharma : You know, Sir, there is a joint responsibility of the Cabinet. If any Member of the Cabinet is in possession of facts and circumstances of the question, there is no bar to his replying to the question. Is there any procedure debarring him from doing so?

Mr. Speaker: If the Transport Minister, Sardar Gurdial Singh Dhillon, is in possession of certain facts as a Member of the Syndicate he cannot be forced to reply to the question. A Minister has to reply to the question only as a representative of the Government and not in any other capacity. As I have observed earlier, only the Minister Incharge can reply to the question.

Education Minister: Sir, I most respectfully submit that there is no intention on the part of the Government to hide anything from the honourable Member. I can ask the Vice-Chancellor of the Punjab University to find out from the proceedings if there is any reference about it in them. I am also prepared to take the hononrable Member into confidence in this matter.

Pandit Chiranji Lal Sharma: The honourable Minister has stated that there is no intention on the part of the Government to conceal any facts. If that is so, let the Transport Minister, who is in possession of full facts, reply to the question.

Mr. Speaker : I am sorry, I cannot allow questions like this. Only the Minister concerned can reply to the question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : The questions put to the Minister concerned are replied to by other Ministers as well. Where is the bar, Sir? Will you kindly let me know?

Mr. Speaker: I never expected that you will insist like this. The question asked by the hon. Member does not fall within the official cognizance of the Minister for Transport. I do not know why does the hon. Member not appreciate this point.

Pandit Chiranji Lal Sharma: I again rise on a Point of Order.

Mr. Speaker : I am sorry, I do not allow it. The hon. Member has already raised his point of Order.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, after all we are here to ventilate the grievances of public here.

Mr. Speaker: But you did have your say. You have already raised the point of Order.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, the fact remains, Sir, that the principle of joint responsibility cannot be brushed aside. When the hon. Minister for Transport and Elections is thoroughly prepared to answer the question, I do not understand why the hon. Speaker should stand in the way.

Education Minister : Sir, I take exception to the observations made by the hon. Member. The Government is fully prepared to place all the facts in their possession before the House.

Mr. Speaker: This is my final decision that if anything is in the knowledge of a Minister not in his official capacity but in another capacity, he cannot be forced to place that before the House.

Minister for Transport and Elections: Mr. Speaker, I was an elected Member of the Senate, and also an elected member of the syndicate not in my capacity as a Minister but as an ordinary citizen at that time. So, Sir, so far as this question asked by the hon. Member is concerned, your Ruling is very sound. If the hon. Member wishes I can tell him anything that I know outside the Chamber and of course I will satisfy him.

Chaudhri Hardwari Lal : Will the hon. Minister for Education kindly state the nature of the enquiry that is being conducted against Shri Bool Chand especially in the context of the charges and the findings which he was pleased to read out only a moment ago?

Education Minister: Sir, now there is not much to be enquired about. The Chancellor was not in the know of this fact. A complaint was received from one M.P. and then from the Union Education Mini ster The Chancellor ashed for all those charges from the Union Public Service Commission and the Home Ministry. I have read out the charges and the findings on those charges and now the Governor/Chancellor is fully seized of the fact. He will take a decision as demanded by justice and law.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Minister for Education if it is not a fact that certain element in the State of Punjab is out to see that Dr. Bool Chand is removed from the post of Vice-Chancellor of the Kurukshetra University and that is why the allegations and enquiry have been manoeuvred ?

Education Minister : I strongly differ from my hon. colleague. Somebody may be against Dr. Bool Chand and somebody may be for him. Some one may be against Shri Suraj Bhan and some one in his favour. But when the Government takes a decision it is absolutely without any prejudice and without taking into consideration whether he belongs to one region or the other. Therefore, the hon. Member should rest assured that justice would be done to Dr. Bool Chand and nobody would be allowed to stand in his way.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या ऐजकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन चार्जिज़ की इन्क्वायरी वाईस-चान्सलर के खिलाफ हो रही है, वह गवर्नमैंट कर रही है या कि गवर्नर साहिब एज़ चान्सलर कर रहे हैं और कब तक उस पर ऐक्शन लिया जाएगा ?

मन्त्री : यह चीज फाइनल स्टेज पर है वैसे इन्क्वायरी वगैरा कुछ नहीं। जब गवर्नमैंट के पास ऐसी शिकायत आई तो, जैसा कि मैंने पहले बताया है, गवर्नमैंट ने यूनियन होम मनिस्टर को और यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को पूछा था कि कैसे चार्जिज़ हैं, क्या इन्क्वायरी हुई और उसकी क्या फाइन्डिंग्ज़ थीं। अब कोई खास इन्क्वायरी नहीं है। फाईनल डिसीज़न इस पर होने वाला है और यह फैसला खुद चान्सलर साहिब लेंगे, गवर्नमैंट नहीं लेगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Education Minister if it is within the knowledge of the Government that the Chancellor of the University asked Dr. Bool Chand to resign failing which his services would be terminated ?

Education Minister : It is entirely for the Chancellor to take any action whatever he considers proper. Government will not interfere one way or the other.

कामरेड राम प्यारा : क्या ऐजुकेशन मनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब श्री बूल चन्द की बतौर वाईस-चान्सलर के एप्वायंटमैंट हुई तो क्या उस वक्त गवर्नमैंट के सामने कोई इस तरह की कम्पलेंट, इस तरह की कोई इन्क्वायरी या फाइंडिन्ग आई और क्या उस का असर उस वक्त इस एप्वायंटमैंट पर हुआ या नहीं हुआ था ?

मन्त्री : मैंने पहले ही बता दिया है कि डाक्टर बूल चन्द वाईस-चान्स्लर लगने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बड़े इम्पारटेंट ओहदे पर लगे हुए थे इस लिए इस तरह की इन्क्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई कि उन के एंटिसीडैंट्स की बाबत पूछा जाए।

*NEW SMALL SCALE INDUSTRIES ESTABLISHED DURING 1964-65 AND 1965-66

***9847. Sardar Niranjan Singh Talib** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of places in the State where new small scale industries were established during the years 1964-65 and 1965-66, together with the number of those established in rural and urban areas separately ;

[Sardar Niranjan Singh Talib]

(b) the amount of financial aid, if any, given by the Government to the managements of such industries ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : The requisite information shall have to be collected from the field offices in the districts. The time and labour involved in the collection and compilation thereof will not be commensurate with the benefit likely to be derived therefrom.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਾਲ-ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ । (The Government does not want to oblige the hon. Member).

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ **ਸਪੀਕਰ** : ਅਗਰ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਉ । (The Chief Parliamentary may give the information about District, if he can.)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਮਾਲ-ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ । I only asked about Ambala District.

Mr. Speaker : I will find it out from the record and if the original question sent by the hon. Member is with regard to Ambala District alone, then the question will again be brought on the notice paper.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 1964-65 ਵਿਚ ਔਰ 1965-66 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਡੌਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : This is not within the scope of the question.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN DISTRICT HOSHIARPUR

*9780. **Shri Surinder Nath Gautam** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

(a) the names of the villages, if any, in Hoshiarpur District. Tehsil-wise, which were electrified during the Five-Year Plan period and during the year 1965-66, separately ;

(b) the names of the villages, which are proposed to be electrified, tehsil-wise, in the said district during the Fourth Five-Year-Plan period ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) Statement is laid on the Table of the House.

(b) There is no programme for electrification of villages because rural electrification is to be mainly confined to energisation of tube-wells.

STATEMENT

Serial No.	Name of the Village	Tehsil
	Villages electrified in Hoshiarpur District during 1961-62	
1.	Batoli	Una
2.	Badla	Do
3.	Barolin (Gujran)	Do
4.	Chartgarh	Do
5.	Jakhora	Do
6.	Kotla Khurd	Do
7.	Aulakh	Do
8.	Bathal	Garshanker
9.	Bahoona	Do
10.	Bilaspur	Do
11.	Bullanwal Ratian	Do
12.	Dhakon	Do
13.	Bandowal	Hoshiarpur
14.	Manan	Do
15.	Bada Saran	Garshanker
16.	Binjon	Do
17.	Balachaur	Do

[Transport and Elections Minister]

Sr. No.	Name of Village	Tehsil
	Villages electrified in Hoshiarpur District during 1961-62—contd.	
18.	Dansawal	Garhshanker
19.	Dehana	Do
20.	Jaitpur	Do
21.	Pindlana	Do
22.	Salana	Do
23.	Kuther	Do
24.	Totoo Majra	Una
25.	Suthiana	Garshanker
26.	Singhpur	Hoshiarpur
27.	Tejpur	Do
28.	Kakon	Do
29.	Attalgarh	Do
30.	Bhugarni	Do
31.	Bohla	Do
32.	Chak Gujran	Do
33.	Kaimpur	Do
34.	Mehtiana	Do
35.	Meghowal	Do
36.	Phuglana	Do
37.	Powal	Do
38.	Sarhala	Do
39.	Niazion	Do
40.	Randhwa	Dasuya
41.	Budo Barkat	Do
42.	Langarpur	Do
43.	Ramian Mangat	Do
44.	Dala	Do
45.	Johal	Hoshiarpur
46.	Khanpur	Dasuya
47.	Joja	Do
48.	Khudd Adda	Do
49.	Nangal	Do
50.	Hardothala	Do
51.	Balla	Do
52.	Kalianpur	Do
53.	Alampur	Do

Sr. No.	Name of Villages	Tehsil
	Villages electrified in Hoshiarpur District during 1961-62—concd.	
54.	Khanpur	Dasuya
55.	Mehna	Hoshiarpur
56.	Mehatpur	Do
57.	Bassi Balo	Do
58.	Bassi Panj Bhaian	Do
59.	Bhaliana	Do
60.	Jai Sahota	Do
61.	Mona	Do
62.	Nila Nalwa	Do
63.	Nangal Shahidan	Do
64.	Churian	Dasuya
65.	Dalopur	Do
66.	Gallowal	Do
67.	Hamza	Do
68.	Kotli	Do
69.	Mangat	Do
	Villages electrified during 1962-63	
1.	Jand	Dasuya
2.	Uchi Bassi	Do
3.	Jhawan	Do
4.	Chhaugla	Do
5.	Nihalpur	Do
6.	Fatehllapur	Do
7.	Sherpur (Chehal)	Do
8.	Mansurpur	Do
9.	Khariabad	Do
10.	Lamin	Do
11.	Bishanpur	Do
12.	Bajwa	Do
13.	Chak Allabaksh	Do
14.	Karala Kalan	Do
15.	Chahal	Do
16.	Lodhi Chak	Do
17.	Manaklehra	Do
18.	Prempur	Do
19.	Dahdiala	Do

[Transport and Elections Minister]

Sr. No.	Name of village	Tehsil
	Villages electrified during 1962-63—contd.	
20.	Randian	Dasuya
21.	Pandori	Do
22.	Odhpur	Do
23.	Kandhala Jattan	Do
24.	Bainswan	Do
25.	Bhakhal	Hoshiarpur
26.	Lambra	Do
27.	Didhiana Kalan	Do
28.	Hassainpur	Do
29.	Bassi Now	Do
30.	Bhikhowal	Do
31.	Sajjan Barhmijit	Do
32.	Kotla Nad Singh	Do
33.	Nirazpur Dhariwal	Do
34.	Hargarh	Do
35.	Rorian	Do
36.	Bhattian	Do
37.	Mehmowal	Do
38.	Punga	Do
39.	Sherpur	Do
40.	Golind	Do
41.	Khebropur	Do
42.	Mehnalan Wali	Do
43.	Dandoh	Do
44.	Machina	Do
45.	Talwandi Jattan	Do
46.	Ahran Khurd	Do
47.	Gagret	Una
48.	Hajipur	Do
49.	Sehjowal	Do
50.	Rai Siri	Do
51.	Dangori	Do
52.	Mangewal	Do
53.	Bassowal	Do
54.	Kalewal	Garhshanker
55.	Khaurandi	Do

Sr. No.	Name of Village	Tehsil
	Villages electrified during 1962-63—concld.	
56.	Khera	Garhshanker
57.	Thinda	Do
58.	Sarhala Khurd	Do
59.	Parowal	Do
60.	Badon	Do
61.	Nangal Kalan	Do
	Villages electrified during 1963-64	
1.	Kotla	Hoshiarpur
2.	Bassi Purani	Do
3.	Chagran	Do
4.	Bassi Gulam Hussain	Do
5.	Kuriala	Una
6.	Brahmpur	Do
7.	Loharan	Hoshiarpur
8.	Arbanakalan	Do
9.	Paldi	Garhshanker
10.	Pandori	Dasuya
11.	Kalitran	Una
12.	Bhanapli	Do
13.	Bhunga	Hoshiarpur
14.	Bhulowal	Do
15.	Madda	Dasuya
16.	Darya	Do
17.	Ajowal	Hoshiarpur
18.	Gilzian	Dasuya
19.	Kamalpur	Do
20.	Nangli	Do
21.	Kandhala Sheikhan	Do
22.	Una Bharalina	Una
23.	Barnoh	Do
24.	Bandhhri	Do
	Villages electrified during 1964-65	
1.	Bohan	Hoshiarpur
2.	Kabirpur	Do
3.	Hukran	Do
4.	Adamwal	Do

[Transport and Elections Minister]

Sr. No.	Name of village	Tehsil
	Village electrified during 1964-65—concld.	
5,	Ambote	Una
6.	Usmanshahid	Dasuya
7.	Talwandi Salan	Do
8.	Mirpur	Do
9.	Ool	Una
10.	Amb	Do
11.	Khuda	Dasuya
12.	Kharar Achharwali Khapor	Garshanker
	Villages electrified during 1965-66 (Up to December, 1965)	
1.	Haveli	Garshanker
2.	Dharmpur	Dasuya
3.	Manak	Do
4.	Pajjo Ditta	Hoshiarpur
5.	Mallokpur	Una
6.	Saidpura Datta	Dasuya
7.	Harspind	Do
8.	Allahabad	Hoshiarpur
9.	Langeri	Garshanker
10.	Ramgarh	Dasuya
11.	Salalpur	Do

श्री सुरेंद्र नाथ गौतम : वज़ीर साहिब ने जो पांच साल की इनफरमेशन दी है उसके मुताबिक ज़िला हुशियारपुर की तहसील ऊना में सन् 1961-62 में 69 में से आठ गाँव को कुनेक्शन दिए गए हैं ।......

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमटरी पूछें । (Please put a supplementary.)

श्री सुरेंद्र नाथ गौतत : सन् 1962-63 में 61 में से सिर्फ दो गाँव को कुनेक्शन दिए गए, 1963-64 में 24 गाँव में से 6 को, 1964-65 में 12 में से 3 को और 1965-66 में 11 में से सिर्फ 1 गाँव को बिजली का कुनेक्शन दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री गौतम, आप तशरीफ रखिए । यह सप्लीमैंटरी नहीं है । (The hon. Member should resume his seat. This is no supplementary.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मैं सप्लीमेंटरी पर ही आ रहा हूं । मैं वजीर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि यह क्या मयार रखा गया है जब कि तहसील ऊना बैकवर्ड हिली एरिया है, जहाँ से बिजली पैदा करके आप सारे हिन्दुस्तान को पहुंचाते हैं ....

Mr. Speaker ; Please take your seat. I have not allowed it.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मैं सरकार से यह दरियाफत करना चाहता हूँ कि क्या यह तहसील ऊना के साथ इस तरह से इम्त्याज़ी सलूक नहीं हो रहा कि बावजूद इस बात के कि वह बैकवर्ड हिली एरिया है और वहां से बिजली पैदा करके आप सारे हिन्दुस्तान को देते हैं फिर भी वहाँ इतने कम गाँवों को बिजली दी गई है ? क्या सरकार आयन्दा के लिए इन गाँव को इलैक्ट्रीफाई करने का कोई प्रोग्राम बनाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है । (This is no supplementary.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि तहसील ऊना को बाकी तहसीलों की निस्बत कम कुनैक्शन दिए है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । (This is not a point of order.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ Pockets ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਾਕੇਟਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

Voices : Sir, supplementaries may be allowed to be asked on the next day.

Mr. Speaker : All right, more supplementaries will be allowed next day.

ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

TRUCK PERMITS ISSUED ON PATHANKOT-JAMMU ROUTE

***9549. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the number of truck permits issued by the Government during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1965, on Punjab-Pathankot-Jammu route and a list of the names and complete addresses of the holders of truck permits mentioned above be laid on the Table of the House ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

LIST OF PUBLIC CARRIERS RECOMMENDED FOR J. & K. STATE

Serial No.	Names and addresses of permit-holders	Number of permits issued
1.	Shri Mohinder Singh, s/o Santa Singh, village Chhapa Ram Singh, P.O. Fatehpur Rajputan, district Amritsar	1
2.	Shri Khushi Ram, B.A., LL.B., Sadar Bazar, Gurdaspur	1
3.	Shrimati Kamla Devi Lochar, w/o Chaman Lal, H. No. 202, Chahar Bagh, Jullundur City	1
4.	Shri D.L. Raizada, s/o Sant Ram, Mohalla Qazian, Pathankot	1
5.	Shri Narinder Nath Kaushal, s/o Mahant Kirpa Nath, Rang Mahal, Gurdaspur	1
6.	Jullunder Ex-Servicemen Motor Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur	6
7.	Chadha Motor Transport Co. (P) Ltd., Amritsar ..	1
8.	The Union Co-operative Transport Co-operative Society Ltd., Ferozepore	1
9.	Th. Ajit Singh, Kehar Singh, General Lorry Stand, Jullundur	1
10.	Th. Nasib Singh, Bachan Singh, General Lorry Stand, Jullundur	1
11.	Th. Nasib Singh, Managing Director, Kartar Goods Carrier Ltd.	1
12.	Northern Carriers (P) Ltd., Jullundur ..	2
13.	Suraj Goods Carriers (P) Ltd., Amritsar ..	1
14.	New Suraj Transport Co. (P) Ltd., Amritsar ..	1
15.	Shri Brahm Parkash Syal, s/o Amin Chand, 165 Adarsh Nagar, Jullundur	1
16.	Shri Pishori Lal Sahni, s/o Sohne Sahah, Pathankot –	1
17.	Jullundur Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur	2
18.	Kumar Transport Co., Amritsar ..	1
19.	Amritsar Transport Co. (P) Ltd., Amritsar ..	2

Serial No.	Names and addresses of permit-holders	Number of permits issued
20.	Northern India Co-operative Transport Society Ltd., Jullundur	1
21.	Shri Pritam Singh, s/o Wazir Singh, Ludhiana ..	1
22.	Shri Parshotam Dass Marwah, Pathankot ..	1
23.	Shri Partap Singh, c/o Northern India Goods Transport Co., Jullundur	1
24.	Kartar Bus Service Ltd., Jullundur ..	1
25.	M/s Daulat Ram-Chaman Lal, Amritsar ..	1
26.	Shri Surmukh Singh Chamak, s/o Mangal Singh, 68 Ajit Nagar, Amritsar	1
27.	M/s Radha Kishan-Kulbhushan Rai Syal, Hamirpur ..	1
28.	Shri Vijendar Singh Mehta, S/o Ranbir Singh, Railway Road, Khanna	1
29.	Com. Amin Chand-Avtar Singh, 313-Adarsh Nagar, Jullundur	1
30.	M. Kamal Khan, s/o M. Ajmal Khan, 71-Sher Mers, New Delhi, c/o Sabir Hussain-Metro Hotel, Pathankot	1
31.	M/s Prithvi Raj Kapur, s/o Arjan Dass, Kapurthala ..	1
32.	M/s Gurdas Singh-Chan Devi, 4-Patel Chowk, Jullundur	1
33.	M/s Asian Goods Transport Co., G. T. Road, Jullundur	1
34.	Shri Bhagat Ram, s/o Sadhu Ram, Phagwara, district Kapurthala	1
35.	Shri Bishan Dass, s/o Gujjar Mal, Dalhousie Road, Pathankot	1
36.	Bibi Nihal Kaur, w/o Prof. Jaswant Rai, c/o Gulzar Singh & Co., Ludhiana	1
37.	M/s Express Goods Service, Amritsar ..	1
38.	Beant Singh and Co., Shaheed Bhagat Singh Road, Amritsar	1
39.	S. Jasbir Singh, s/o Waryam Singh, G. T. Road, Batala	1
40.	S. Sikandar Singh, s/o Bachan Singh, V. and P. O. Ochiniwala, district Ferozepore	1
41.	Shri Ajit Singh, s/o Shri Sadhu Singh, Civil Station, Bhatinda	1
42.	Shri Prem Partap Singh, s/o Shri Isher Singh Majhal, Civil Lines, Patiala	1

FLAG HOISTING CEREMONY AT RAJPURA ON THE REPUBLIC DAY

*9285. **Dr. Baldev Parkash** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that a non-official took salute from the Police and performed the flag hoisting ceremony at the Republic Day function held on the 26th January, 1966 at Rajpura Township ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the said person was authorised by the Government to take the salute ;

(c) whether the Government or the Deputy Cnmmissioner, Ambala, have received any complaint from the people of Rajpura about the said matter; if so, the action taken in the matter ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) No.

(c) A complaint has been received from the President, Bhartiya Jan Sangh, Rajpura Township, which is being looked into.

ROADS METALLED IN KANGRA DISTRICT

*9307. **Pandit Amar Nath Sharma** : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the names of the roads in Kangra District which were to be metalled during the 1st, 2nd and 3rd Five-Year Plan periods together with the names of those among them which have not yet been metalled stating the reasons therefor in each case ;

(b) the total mileage of the roads which have so far been constructed in the said district ;

(c) the details of the roads in the said district which are proposed to be metalled in the 4th Plan period ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) A statement is laid on the Table of the House. Roads at S. Nos. 3, 5, 6, 10, 14, to 17 and 19 to 38 have not yet been completed due to paucity of funds.

(b) 97.32 miles of road have so far been constructed in Kangra District.

(c) Details of roads proposed to be metalled in Kangra District in the 4th Plan period have not yet been finalised.

STATEMENT

Detail of Roads Proposed for Metalling in I, II and III Five-Year Plans in Kangra District and their Present Position

Sr. No.	Name of Road	Length (miles)	Plan in which proposed to be constructed	Mileage constructed up to date	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Ranital-Jawalamukhi Road	12.00	I Plan	12.00	Completed
2.	Jullundur-Hoshiarpur Dharamshala Road (Missing Links)	5.00	Ditto	5.00	Do
3.	Hamirpur-Nadaun-Mubarikpur Road	32.00	II and III Plan	17.00	Work in Progress
4.	Nadaun-Jawalamukhi	7.00	Ditto	7.00	Completed
5.	Una-Aghar-Mandi (Except Sec. Bhota to Jahu)	38.00	Ditto	7.50	Work in Progress
6.	Bilaspur-Aghar-Hamirpur	12.00	Ditto	8.00	Ditto
7.	Dadh-Malah Road	3.00	II Plan	3.00	Completed
8.	Jawalamukhi-Dera Gopipur	8.00	II and III Plan	8.00	Do
9.	Palampur-Thurl-Sujanpur	11.00	Ditto	11.00	Do
10.	Hamirpur-Sujanpur	15.00	Ditto	—	Work in progress
11.	Sujanpur-Baghera (Jeepable Road)	5.00	Ditto	5.00	Completed
12.	App. to Jawalamukhi Temple	1.00	Ditto	1.00	Do
13.	App. to Wah, and Holta Estate	2.50	Ditto	2.50	Do
14.	Mohal Khad Bridge to join A.P.K. Road with Rajpura near Palampur	0.90	III Plan	—	Only preliminaries to be completed in III Plan, actual work to be started in IV Plan
15.	Indura to Ghaila Railway Station	5.00	Ditto	—	—
16.	Constructing link road from Gajjanwala to Thakar Dwara-Thurd Road near Daroh Khas	3.38	Ditto		Only preliminaries to be completed in III Plan, actual work to be started in IV Plan
17.	Dharamsala Cantt to Dal Lake	2.50	Ditto	—	Only preliminaries are to be completed, actual work to be started in IV Plan
18.	Kangra to Tanda Sanatorium	2.00	Ditto	2.00	Completed

[Public Works Minister]

Sr. No.	Name of road	Length (miles)	Plan in which proposed to be constructed	Mileage constructed up to date	Remarks
1	2	3	4	5	6
19.	Road from Kotwali Khanyara to Charind Khad Bridge at Dharamsala	0.15	III Plan	—	Work in progress
20.	Kotwali Chari-Road including surfacing at Dharamsala	0.10	Ditto	—	Ditto
21.	Maclaud Ganj-Bhagsu Nath Road at Dharamsala	0.75	Ditto	—	Ditto
22.	Metalling Palampur Bundla-Tea Factory to Tourist Park	0.50	Ditto	—	Ditto
23.	Palampur Rest House to Bundla	0.75	Ditto	—	Preliminaries to be completed. Actual work to be started in IV Plan.
24.	Bhota-Johu Road	14.00	Ditto	—	Ditto
25.	Thurl-Sujanpur Road	9.50	Ditto	—	Ditto
26.	Bhota-Bilaspur Road up to Ukhli	7.00	Ditto	—	Earthwork in progress
27.	Rajaka Talab to Jawali	10.00	Ditto	—	Actual work to be started in IV Plan
28.	Dharamsala-Yol-Dadh-Palampur Road	20.00	Ditto	1.00	Work in progress
29.	Dharamshala-Chambi Road	9.00	Ditto	3.00	Ditto
30.	Nurpur Fatehpur-Dhameta-Reh Road	30.00	Ditto	3.00	Ditto
31.	Palampur-Holta-Chadiar Road	20.00	Ditto	—	Actual work to be started in IV Plan
32.	Nurpur-Suliali Road	7.00	Ditto	—	Earthwork and construction of B & C in progress
33.	Thana-Mandli-Bhakra Dam Road (Metalling only)	18.00	Ditto	—	Only preliminaries to be done in III Plan. Actual work to be started in IV Plan
34.	Ranital-Kotla Road (Bridges only)	—	Ditto	—	Ditto
35.	Andaura-Mothly Road	5.70	Ditto	—	Ditto
36.	Palampur to Bir Khas *via* Bundla-Chandpur-Kandbari Lanod and Deval Khas	25.00	Ditto	—	Ditto
37.	Ahju to Bir Khas Tea State up to district boundary)	1.32	Ditto	1.32	Completed
38.	Jawalamukhi to Palampur-Thure road *via* Kundian Bari	15.00	Ditto	—	Earth work in progress in first ten miles
				97.32	

ROUTE PERMIT FOR PLYING BUS SERVICE FROM HOSHIARPUR TO NADAUN

*9597. **Thakur Mehar Singh** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Bus route permit was sanctioned for operating a bus service from Hoshiarpur to Nadaun *via* village Hatli-Pir Salohi in favour of the Victory Transport Co. Ltd., Hoshiarpur; if so, the date when it was sanctioned ;

(b) whether the said Company is operating on the said approved route; if not, the reasons therefor?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) No.

(b) Does not arise.

INDUSTRIAL PROJECTS ALLOTTED BY THE GOVERNMENT OF INDIA

*9194. **Sardar Balwant Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Rural Industrial Projects allotted by the Government of India, to the Punjab and the place of location of each ;

(b) the impact of the said Projects upon the development of rural industries in the Project areas ;

(c) the annual financial budget allotted for each such Project and whether the funds are being utilised fully ;

(d) whether the Government have appointed Project Officers in all the said Projects ; if not, the names of the Projects for which project officers have not been appointed and the time since when these posts are lying vacant ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Two. Palampur and Malerkotla.

(b) These have created an industrial climate and atmosphere and have given a boost to private enterprise.

(c) *Year*		*Rs. in lacs*	
1962-63	...	.50	There was consolidated budgeting during these years
1963-64	...	6.00	
19646-65	..	7.75	
1965-66	...	20.92	

Yes, almost fully.

(d) One of the Posts Project officers at Malerkotla, is lying vacant, since 25th February, 1965.

LAND ACQUIRED IN VILLAGE MEWAL MAHARAJPUR, DISTRICT GURGAON

*9846. **Shri Rup Lal Mehta** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government acquired 115 Bighas of land of Chaudhry Ghasita Singh of village Mewla Maharajpur in Gurgaon District for the New India Spinning Mills started by the sons of the late S. Partap Singh Kairon ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the Government has paid compensation to the owner of the said land at the rate of Rs 4.50 paise per sq. yard; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan: (a) Out of the land acquired for the purpose, only 39 Kanals and 4 marlas belonged to Chaudhry Ghasita Singh.

(b) No. The Collector has not yet announced the award.

ACQUISITION OF 'KOHI-NOOR' FROM THE BRITISH GOVERNMENT

*9740. **Shri Fateh Chand Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the State Government has urged the Union Government to take up the matter regarding the return of the 'Kohi-Noor' with the British Government ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the Government has received any intimation from the Union Government about the latter's efforts in this behalf ; if so, when and the nature thereof ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, Sir.

(b) Nothing has been heard so far from the Government of India.

LOANS ADVANCED UNDER L.I.G.H. AND M. I. G. H. SCHEMES

*9781. **Shri Surinder Nath Gautam** : Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state the total amount of loans advanced under the Low-Income-Group and the Middle-Income-Group Housing Schemes, separately, in the Backward Hilly area of tehsil Una, district Hoshiarpur, Block-wise, during the period from 1962 to date together with the names of the loanees ?

Sardar Prem Singh 'Prem' : The information is laid on the Table of the House.

Statement showing the loans advanced in the Backward Hilly area of tehsil Una, district Hoshiarpur, Block-wise, from the year 1962 to-date

Scheme	Block	Number of loanees	Amount
			Rs.
Low-Income-Group Housing Shome	Anandpur Sahib	.. 13	41,400
	Una	.. 17	49,800
	Nurpur Bedi	.. 1	2,000
	Amb	.. 4	10,800
	Gagret	5	23,250
	Total	.. 40	1,27,250
Middle-Income-Group Housing Scheme		—	—

List of the loanees is enclosed.

Statement of the Loanees under LIGH Scheme from the year 1962 to-date, Block-wise tehsil Una, district Hoshiarpur

S. No.	Name of the Block	Particulars of the loanees	Amount sanctioned	Remarks
			Rs.	
1.	Anandpur Sahib	Shri Ram Rakha, s/o Shri Tulsi, Oustee Colony, Nangal	2,000.00	
2.	—do—	Shri Atma Ram, s/o Shri Roda Ram, Oustee Colony, Nangal	1 200.00	
3.	—do—	Shri Chhote Lal, s/o Shri Nirader Singh, Oustee Colony, Nangal	3,500.00	
4.	—do—	Shri Basanta Ram, s/o Shri Ralla Ram, Oustee Colony, Nangal	1,200.00	
5.	—do—	Shri Hans Raj, s/o Shri Nathu Ram, Partap Nagar, Jawahar Market, Nangal	3,000.00	
6.	—do—	Shri Niranjan Singh, s/o Shri Khazan Singh, Oustee Colony, Nangal	4,000.00	
7.	—do—	Shrimati Satya Devi daughter Shri Pola Ram of Nangal Township	2,000.00	
8.	—do—	Shri Piara Singh, s/o Shri Rulia Ram of village Dhir	1,500.00	
9.	—do—	Shri Gurdial Singh s/o Shri Jhanda Ram Cloth Merchant of Anandpur Sahib	6,000.00	

[Capital and Housing Minister]

1	2	3	4	5
			Rs.	
10.	Anandpur Sahib	Shrimati Bhagwati Devi, daughter of Shri Polo Ram of Nangal Township	2,000.00	
11.	—do—	Shri Avtar Singh, s/o Shri Karam Singh of Anandpur Sahib	3,000.00	
12.	—do—	Shri Ram Asra, s/o Shri Rikhi Ram of Khamara	8,000.00	
13.	—do—	Shri Ved Ram Nath, s/o Shri Amba Datt of Anandpur Sahib	4,000.00	
14.	—do—	Shri Khushi Ram, s/o Shri Daya Ram of Una	2,600.00	
15.	—do—	Shri Harbans Lal, s/o Shri Shiv Ram of village Sasan	2,500.00	
16.	—do—	Shri Om Parkash, s/o Shri Basant Mal of Una	1,700.00	
17.	—do—	Shri Chinta Singh, s/o Shri Ram Ditta of Una	1,600.00	
18.	—do—	Shri Charan Dass, s/o Shri Ram Rakha Mal of Una	2,500.00	
19.	Una	Shri Ajit Singh, s/o Shri Gurbax Singh of Una	1,700.00	
20.	—do—	Shri Kashmiri Lal, s/o Shri Amin Chand of Basdera	2,500.00	
21.	—do—	Shri Puran Chand, s/o Shri Nathu Ram of Jakhera	2,000.00	
22.	—do—	Shri Ram Asra, s/o Shri Babu Ram of Una	2,000.00	
23.	—do—	Shri Choranji Lal, s/o Shri Sita Ram of Rampur	1,200.00	
24.	—do—	Shri Hazari Lal, Advocate of Una	4,000.00	
25.	—do—	Shri Anant Ram, s/o Shri Biru Ram of Badhera	1,500.00	
26.	—do—	Shri Sant Ram, s/o Shri Harnam, Dass of Una	4000.00	
27.	—do—	Shri Ganda Singh, s/o Shri Harnam Dass of Una	4,000.00	
28.	—do—	Shri Partap Singh, s/o Shri Gian Singh, Cloth Merchant of Una	5,000.00	
29.	—do—	Shri Dayal Singh, s/o Shri Mana Singh of Una	5,000.00	

1	2	3	4	5
30.	Una	Shrimati Joginder Kaur, wife of Shri Ajit Singh of Una	6,000.00	
31.	Nurpur Bedi	Shri Gurbux Singh, s/o Shri Hako Ram of Village Nurpur Bedi	2,000.00	
32.	Amb	Shri Karam Chand, s/o Shri Mangat Ram of village Bhanjal	1,300.00	
33.	—do—	Shri Suram Singh, s/o Chhangu Ram of Nari	2,000.00	
34.	—do—	Shri Hans Raj, s/o Shri Ganesha Ram of village Akrot	5,000.00	
35.	—do—	Shri Bhagat Ram, s/o Shri Nathu Ram of Amb	2,500.00	
36.	Gagret	Shri Kashmir Singh, s/o Shri Lehna Singh of Oel	3,000.00	
37.	—do—	Shri Beli Ram, s/o Shri Belu Ram of village Sanghnai	3,000.00	
38.	—do—	Shri Balak Ram s/o Shri Sohan Lall of village Gagret	6,000.00	
39.	—do—	Shri Achhar Ram, s/o Shri Prabh Dayal of village Guglehar	8,000.00	
40.	—do—	Shri Ram Tirath, s/o Shri Chhajju Ram of Gagret	3,250.00	
		Total ..	1,27,250.00	

RECOVERY OF LOANS FROM THE INDUSTRIALISTS IN THE STATE

***9308. Pandit Amar Nath Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount of arrears of the Industrial Loans recoverable from the Industrialists, tehsil-wise, in the State on the 31st March, 1965 ;

(b) the steps so far taken to recover the said loan amount ;

(c) the total amount of the loan money in respect of which the loanees are not traceable, tehsil-wise ?

Shri Ram Kishan : (a) Statement I giving the requisite information is attached.

(b) Notices are issued to the loanees for the repayment of loans. In case of any default, the cases are referred to the Collectors to recover the outstanding amount as arrears of land revenue after completing all the formalities prescribed under he Punjab State Aid to Industries Act and the Rules made thereunder.

(c) Statement II giving the requisite information is attached.

[Chief Minister]

STATEMENT I

S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Amount of loan outstanding on the 31st March, 1965
1	2	3	4
			Rs
1.	Ambala	Ambala	1,23,000
		Jagadhri	1,31,000
		Rupar	39,000
		Kharar	90,000
		Nalagarh	5,373
		Naraingarh	7,367
			3,05,740
2.	Patiala	Patiala	2,44,789
		Rajpura	86,901
		Sirhind	36,725
		Nabha	30,464
			3,98 829
3.	Jullundur	Jullundur	3,89,738
		Nawanshehar	1,40 082
		Nakodar	26,550
		Phillaur	58,500
			6,20,870
4.	Rohtak	Rohtak	1,08,111
		Sonepat	2,01,578
		Gohana	67,560
		Jhajjar	82,378
			4,59,627
5.	Bhatinda	Bhatinda	1,34,041
		Faridkot	2,23,782
		Mansa	89,741
			4,47,564
6.	Gurdaspur	Batala	3,27,931
		Gurdaspur	1,05,378
		Pathankot	1,17,782
			5,51,091
7.	Kapurthala	Kapurthala	1,24,198
		Phagwara	1,05,751
			2,29,949
8.	Kangra	Kangra	61,191
		Hamirpur	12,181
		Nurpur	31,030
		Dehra	23,801
		Palampur	20,970
			1,49,173

1	2	3	4
			Rs
9.	Hoshiarpur	Hoshiarpur	84,000
		Garhshankar	90,000
		Dasuya	80,000
		Una	89,417
			3.43,417
10.	Kulu	Kulu	23,791
		Seraj	4,104
		Nirmad	1.247
			29,142
11.	Amritsar	Patti	20,709
		Ajnala	12,204
		Tarn Taran	56,055
		Amritsar	1,62,686
			2,51,654
12.	Ludhiana	Ludhiana	7,36,601
		Samrala	16,795
		Jagraon	21,542
			7,74,938
13.	Hissar	Hansi	2,33,200
		Hissar	80,000
		Fatehabad	18,065
		Bhiwani	56,000
			3,87,265
14	Gurgaon	Gurgaon	78,567
		Ballabgarh	25,030
		Rewari	11,121
		F. P. Jhirka	9,946
		Nuh	4,239
		Palwal	20,379
			1,49,282
15.	Simla	Kandaghat	58,677
16.	Sangrur (Malerkotla)	Sangrur	63,865
		Malerkotla	1,12,550
		Barnala	22,704
		Jind	17,909
		Narwana	12,575
			2,29,603
17.	Panipat	Karnal	2,66,359
		Panipat	3,31,460
		Kaithal	1,28,700
		Thanesar	59,294
			7,85,813

[Chief Minister]

1	2	3	4
			Rs
18.	Narnaul	Narnaul	70,437
		Mohindergarh	39,259
		Charkhi Dadri	53,541
			1,63,237
19.	Ferozepur	Zira	16,121
		Moga	71,366
		Muktsar	6,909
		Fazilka	20,727
		Ferozepur	80,605
			1,95,728
	Grand Total.—		66,45,599

STATEMENT II

S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Total amount of loan money in respect of which loanees are not traceable
1	2	3	4
			Rs
1.	Ambala	Jagadhri	23,000
2.	Patiala	...	...
3.	Jullundur	Jullundur	6,350
		Nawanshehar	1,500
4.	Rohtak	Sonepat	2,500
5.	Bhatinda	Faridkot	3,250
6.	Gurdaspur	...	...
7.	Kapurthala	Kapurthala	300
8.	Kangra	Kangra	1,150
9.	Hoshiarpur	...	...
10.	Kulu	..	..
11.	Amritsar	..	...
12.	Ludhiana	...	...
13.	Hissar	..	..
14.	Gurgaon	Gurgaon	200
		Ballabgarh	5,000
		Rewari	130
15.	Simla	Kandaghat	12,480
16.	Malerkotla (Sangrur)	Malerkotla	1,400
17.	Panipat	..	...
18.	Narnaul	...	..
19.	Ferozepur	...	...
	Grand Total—		57,260

FOODGRAINS DESPATCHED TO OTHER STATES

*9727. **Sardar Balwant Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the quantity of foodgrains of various types despatched by the Government to the different States of India, during the current financial year along with the price of each type of foodgrains received in the State from the different States;

(b) the average procurement price of the above-mentioned foodgrains category-wise;

(c) the prevailing price of the above-mentioned foodgrains in the respective States, to which the foodgrains from Punjab were despatched and whether the said State Governments sold the foodgrains supplied to them at the price at which they received the foodgrains from the State of Punjab or at the rates prevailing in those State ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Commodity :		*Quantity despatched (tonnes)*	
		On State account	On Govt. of India account
(i) Wheat	..	9,704	159,481
(ii) Gram/Gramdal	..	147,630.6	..
(iii) Kabli Gram	..	396·1	..
(iv) Maize	..	2,264	43,249
(v) Bajra	..	..	26,754·3 and
(vi) Rice	..	8,299.6	221,070

(a) (i) The stocks of foodgrins exported on State accoun were charged for at the following rates :—

(i) Wheat superior	..	Rs 64·35 per quintal
(ii) Wheat dara	..	Rs 60·77 „
(iii) Gram	..	Rs 53·10 to Rs 61·80 per quintal
(iv) Gramdal	..	Rs 57·40 to Rs 64·05 per quintal
(v) Kabli Gram		Rs 80·35 to Rs 83·00 per quintal
(vi) Maize		Rs 43·70 per quintal ; and
(vii) Rice Basmati		Rs 85·33 per quintal (bagged)·

(a) (ii) As for exports on Government of India account, the realisations from the deficit States are made direct by the Government of India at rates determined by them.

(b) (i) Wheat	..	Rs 52·00 to Rs 56·00 per quintal
(ii) Gram	..	Rs 52·11 to Rs 60·81 per quintal
(iii) Gramdal	..	Rs 56·41 to Rs 63·06 per quintal
(iv) Kabli-gram	..	Rs 79·36 to Rs 82·00 per quintal
(v) Maize	..	Rs 42·71 per quintal
(vi) Bajra	..	Rs 52.75 to Rs 58·00 per quintal and
(vii) Ricc	..	Rs 56·00 to Rs 88·75 per quintal according to the variety

(c) This information is not available.

ASSISTANCE FOR THE REHABILITATION OF REFUGEES UPROOTED DUE TO PAKISTANI AGGRESSION FROM THE UNION GOVERNMENT

*9741. **Shri Fateh Chand Vij** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

(a) whether Government have submitted any memorandum/note etc. to the Union Government seeking their help in the rehabilitation of the Punjabi uprooted as a result of the Pakistani aggression; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) the details of the reply ; if any, received from or commitment, if any, made by the Union Government in connection with the subject referred to in part (a) above ;

(c) whether in the recent meeting of the Chief Ministers held in New Delhi, the Government of India intimated that certain other State Governments had undertaken to help the Punjab State in connection with the said task of rehabilitation ; if so, how and when ; and

(d) the details of the help received in this behalf from the Union Government as also other State Governments be placed on the Table of the House ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) There have been various formal and informal moves by the Punjab Government for aid by the Union Government. The matter being still under correspondence with the Union Government, the stage for laying paper on the Table of the House has not yet reached.

(b) The Union Government has provided the following assistance so far :—

(i)	*Ad-hoc* grant to the State Government for providing relief to the uprooted persons	Rs 38.00 lakhs
(ii)	Subsidy to Local Bodies ..	Rs 4.45 lakhs
(iii)	Subsidy for repair/construction/widening of roads and strengthening of bridges, etc.	Rs 40.00 lakhs
(iv)	(a) Loans for industrialists ..	Rs 50.00 lakhs
	(b) Loans for business and agricultural purposes.	Rs 10.00 lakhs

(v) The Central Government had supplied tents for accommodating the uprooted persons in Camps.

(c) and (d) No other State Government has provided any help for the rehabilitation of uprooted persons.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ALLEGATIONS OF MIS-APPROPRIATION OF PANCHAYAT FUNDS ETC., AGAINST THE SARPANCH OF VILLAGE PANCHAYAT KURIALA, DISTRICT HOSHIARPUR

3336. **Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Home and Development be pleased be state —

(a) whether it is a fact that allegations of mis-appropriation of Panchayat funds and of misuse of powers were levelled by the people of village Kuriala in Amb Block, district Hoshiarpur, during the year 1964-65, against the Sarpanch of Kuriala ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether any enquiry has been held into the said allegations; if so, with what result ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes, Sarvshri Sant Ram, Sarpanch, Dina Nath and Karam Singh, Panches were placed under suspension by the Deputy Commissioner, Hoshiarpur, as a result of the said enquiry.

SUGAR QUOTA DRAWN FRADULENTLY BY CERTAIN PERSONS IN BLOCK SAMITI MOGA—I

3339. **Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Moga (Ferozepore), received during the year 1965, any representation from Shri Dalip Singh, a member of the Village Panchayat, Takhanwadh, Block Samiti Moga, I, district Ferozepore, in which certain allegations were levelled against S. Amar Singh, Sarpanch, Santokh Singh Panch and Santokh Singh s/o Harnam Singh of village Takhanwadh that they have fraudulently drawn more sugar by showing an incorrect number of members of their families in their ration cards ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the date when the application was received and the details of the action, if any, taken thereon ;

(c) whether any enquiry has been held into the said representation; if so, whether the results of the enquiry have been conveyed to the complainants ; if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) On 25th June, 1965 and 29th June, 1965 through the Deputy Commissioner, Ferozepore, and Sub-Divisional Officer, Moga, respectively. These were enquired into, and were found baseless based upon party faction.

(c) Yes. The enquiry was held in the presence of the complaintant and he was informed of the result on the sport.

VEGEABLES GROWN IN JAIL GARDENS IN THE STATE

3340. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

(a) the particulars of the vegetables grown in the jail gardens in the State together with the quantity thereof produced in each jail, separately, during the period from 1962 to-date ;

(b) the details of the vegetables sold in the market and provided to the prisoners' kitchen, separately, during the said period ;

(c) whether the same kind of vegetables which are sent for sale in the market are also given for use in the prisoners' kitchens; if not, the reasons for providing different kinds of vegetables for prisoners' kitchens ;

(d) the categories of employees who are supplied vegetables on payment of the fixed price under the Jail Warders' Rules ;

(e) whether the employees including warders of the Patiala Jail are provided with the facility of purchasing vegetables at the price fixed by the jail authorities ; if not, the reasons therefor ?

Shri Chand Ram : The time and labour involved in the collection and compilation of the requisite information, which will be very elaborate and voluminous, will not be commensurate with any possible benefit sought to be derived therefrom.

RESIDENTIAL QUARTERS FOR MARRIED JAIL WARDERS IN CENTRAL JAIL, PATIALA

3341. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

(a) the total number of married jail warders in the State at present together with the number of residential quarters for them, jail-wise;

(b) whether the proportion of quarters for married warders is uniform in all the jails or different and the proportion in the Patiala Central Jail;

(c) the criterion fixed for the allotment of quarters to married warders in the Patiala Jail;

(d) whether every married warder gets a residential quarter according to his turn;

(e) the total number of married warders in the Central Jail, Patiala, who have not been allotted any quarter so far?

Shri Chand Ram :

(a) Total number of married jail warders in the State: 1,177.

Total number of residential quarters: 597.

(A jail-wise list is enclosed).

(b) Different proportion of quarters for married jail warders in Central jail, Patiala is 2.8 : 1.

(c) A quarter is allotted to married warder turn by turn from the date of submission of applications by them. The period for occupation of quarter is two years.

(d) Yes.

(e) Sixty-eight (out of these only 11 have so far applied for allotment of quarters.)

JAIL-WISE STATEMENT OF TOTAL NUMBER OF MARRIED JAIL WARDERS AND RESIDENTIAL QUARTERS FOR THEM

S. No.	Name of the Jail		Married Jail Warders	Residential quarters
1.	Central Jail, Ambala	..	101	64
2.	Central Jail, Ferozepur	..	100	34
3.	Central Jail, Patiala	..	103	37
4.	Central Jail, Delhi	..	97	139
5.	District Jail, Jullundur	..	41	13
6.	District Jail, Ludhiana	..	42	20
7.	District Jail, Amritsar	..	79	36
8.	District Jail. Rohtak	..	45	15
9.	Central Jail, Hissar	..	70	57
10.	District Jail, Nabha	..	35	24
11.	District Jail, Bhatinda	..	37	27
12.	District Jail, Gurdaspur	..	34	16
13.	District Jail, Sangrur	..	39	14
14.	B. I. & Jail, Faridkot	..	36	24
15.	Reformatory School, Hissar	..	12	10
16.	Special Jail, Hissar	..	—	—
17.	District Jail, Karnal	..	24	5
18.	District Jail, Gurgaon	..	25	6
19.	District Jail, Hoshiarpur	..	20	6
20.	Sub Jail, Kapurthala	..	22	6
21.	Sub Jail, Mohindergarh	..	10	4
22.	Sub Jail, Dharamsala	..	25	9
23.	Sub Jail, Palwal	..	8	—
24.	Sub Jail, Rupar	..	10	—
25.	Sub Jail, Muktsar	..	12	—
26.	Sub Jail, Sirsa	..	11	5
27.	Sub Jail, Moga	..	21	—
28.	Sub Jail, Fazilka	..	8	—
29.	Sub Jail, Patti	..	16	—
30.	Sub Jail, Kulu	..	7	—
31.	Sub Jail, Simla	..	7	3
32	Sub Jail, Charkhi Dadri	..	7	7
33.	Sub Jail, Malerkotla	..	9	3
34.	Sub Jail, Dasuya	..	8	1
35.	Sub Jail, Bassi Pathana	..	5	5
36.	Sub Jail, Mansa	..	8	—
37.	Sub Jail, Hamirpur	..	7	—
38.	Sub Jail, Panipat	..	8	—
39.	Sub Jail, Bhiwani	..	8	1
40.	Sub Jail, Phagwara	..	6	—
41.	Sub Jail, Pathankot	..	6	—
42.	Sub Jail, Barnala	..	8	6
	Grand Total	..	1,177	597

CASE OF TEMPERING WITH THE REVENUE RECORD REGISTERED WITH KAPURTHALA KOTWALI POLICE

3342. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any case of tempering with the record of the Register of Jamabandi and Khasra Girdwari regarding a piece of land bearing Khasra No. 2148 situated in village Kapurthala proper was got registered at the Kapurthala Kotwali by the Deputy Commissioner, Kapurthala, on the complaint of the Settlement Officer, Rehabilitation, Jullundur;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the year of registration of the said case and the action taken in the matter; if no action has been taken, the reasons therefor;

(c) whether the record of the then Patwari Kapurthala taken into possession by the Kapurthala Kotwali police is still in the possession of the latter; if so, the reasons therefor;

(d) whether the Government is aware of the fact that the farmers of the said Halqa are experiencing difficulties for the reasons that they are unable to get the requisite information from the Patwari in the absence of that record; if so, the steps, if any, taken to remove their grievances?

Sardar Harinder Singh Major: (a) Yes.

(b) (i) F. I. R. No. 102 of 27th May, 1963;

(ii) The case has been filed by Chief Judicial Magistrate, Kapurthala, as untraced.

(c) No. The record is with the Patwari.

(d) Does not arise in view of (c) above. No difficulty is being experienced by the people of the Halqa (areas).

TRANSFER OF SUB INSPECTORS/STATION HOUSE OFFICERS IN DISTRICT KARNAL

3343. Comrade Ram Piara: Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the names of Sub-Inspectors/Station-House Officers posted as Incharge in each of the Police Stations in district Karnal as on 1st May, 1964, Police Station-wise;

(b) the date of transfer after 1st May, 1964, of each of the said S. H. O.s from the Police Station of his posting and the name of the Police Station/or any other place to which he was transferred;

(c) whether any of the S. H. Os. mentioned in part (b) above was re-transferred to some other Police Station; if so, their names and the names of the Police Stations to which they were re-transferred and the reasons therefor in each case;

(d) the names of the S. H. Os. referred to in part (c) above who were re-transferred within three months together with reasons therefor;

(e) whether any communication (s) was/were received by the I. G. of Police, D. I. G. of Police, Ambala, and/or the S. P. Karnal; in connection with the procedure of postings and transfers of Sub-Inspectors/S. H. Os. during the period from 31st January, 1966, to date; if so, the action if any, taken thereon; if no action has been taken, the reasons therefor;

(f) the name of the sender of the communications mentioned in part (e) above and whether the receipt thereof was acknowledged; if not, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh :

(a) (b) (c) (d) The required information is given in Columns 'A','B', 'C' and 'D', respectively, of the enclosed statement.

(e) & (f) A letter dated 1st February, 1966, in connection with the procedure of postings and transfers of S. Is./S.H.Os., from Comrade Ram Piara, M. L. A., was received by the Supdt. of Police, Karnal and a copy was endorsed to the Deputy Inspector General of Police, Ambala Range. As the subject-matters related to administrative matter no correspondence on the subject was called for. The letter was accordingly not acknowledged by the Supdt. of Police, Karnal. The Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, is, however, looking into the matter.

[Home and Development Minister]

STATEMENT

The names of S.I.s/SHOs posted as incharge in each of the P.S.s in district Karnal, as on 1st May, 1964 Police Station-wise	The date of transfer after 1st May, 1964 of each of the said S.H.O.'s from the P.S.s of his posting and the name of the Police Station or any other place to which he was transferred	(c) Whether any of the S.H.O.s mentioned in part (b) above was re-transferred to some other P.S., if so, their names and the names of the P.S.s to which they were re-transferred and the reasons therefor in each case	(d) The names of the S.H.O.s referred in part (c) above who were re-transferred within 3 months together with the reasons therefor
1	2	3	4
1. S.I. Chatter Singh, S.H.O. Sadar Karnal	S.I. Chatter Singh to P.S. Nissing on 23rd November, 1964	1. S.I. Chandan Singh promoted as Inspector and transferred to C.I.D. on 1st December, 64	1. S.I. Ajaib Singh was transferred from P.S. Kaithal to P.S. Sadar Panipat due to compassionate reasons as the education of his son was likely to be adversely affected if he had gone to Kaithal. He had represented before me and his representation in this regard was accepted.
2. S.I. Chandan Singh, S.H.O. City Karnal	S.I. Chandan Singh to P.S. Sadar Panipat on 11th September, 1964	2. S.I. Mohan Singh transferred to Accident Staff on 21st September, 1964 and further from Accident Staff to P.S. Radaur on 8th September, 1965. The reasons of his transfer are that he could not pull on with the heavy charge of P.S. Butana and from Accident Staff to P.S. Radaur in place of S.I. Sunder Singh who was transferred to Lines for his departmental enquiry.	2. S.I. Walaya Ram was transferred from P.S. Pehowa to P.S. Sadar Karnal within 3 months of his posting at Pehowa as no other suitable and mature S.I. was available for posting at P.S. Sadar Karnal which is a heavy and important charge.
3. S.I. Mohan Singh, S.H.O. Butana	S.I. Mohan Singh to Police Lines on 31st August, 1964		
4. S.I. Ajaib Singh, S.H.O., Nissing	S.I. Ajaib Singh to P.S. Kaithal on 23rd November, 1964		
5. S.I. Gurdev Singh, S.H.O. Sadar Panipat	S.I. Gurdev Singh to P.S. Rajaund on 11th September, 1964		
6. S.I. Inder Raj, S.H.O., City Panipat			
7. A.S.I. Banarsi Lal, S.H.O., Gharunda	A.S.I. Banarsi Lal to P.S. Samalkha on 13th February, 1966	3. S.I. Ajaib Singh was transferred from P.S. Kaithal to P. S. Sadar Panipat on 16th December, 1964 in place of S.I. Chandan Singh since promoted as Inspector. Further S.I. Ajaib Singh while posted as S.H.O. P.S. Sadar Panipat was involved in a murder case on 20th April, 1965. He was reinstated on 20th December, 1965 and then posted as S.H.O.	
8. S.I. Sohan Lal, S.H.O., Assandh	S.I. Sohan Lal proceeded on L.P.R. on 1st June, 1964		
9. S.I. Ram Labhaya, S.H.O., urlana	S.I. Ram Labhaya to Police Lines on 22nd July, 1964		
10. S.I. Daulat Ram, S.H.O., Samalkha	S.I. Daulat Ram to Interrogation Centre Amritsar on 22nd July, 1964		

11. S.I. Roshan Lal, S.H.O., Kaithal	S.I. Roshan Lal to P.S. Pehowa on 23rd November, 1964
12. A.S.I. Walaya Ram, S.H.O., Thanesar	A.S.I. Walaya Ram to P.S. Assandh on 5th June, 1964
13. S.I. Santokh Singh, S.H.O., Guhla	S.I. Santokh Singh transfered to Hissar District on 5th November, 1964
14. A.S.I. Harbans Singh, S.H.O., Ladwa	A.S.I. Harbans Singh to Shahabad on 11th May, 1965
15. A.S.I. Raj Singh, S.H.O., Pehowa	A.S.I. Raj Singh to P.S. Pundri on 18th July, 1964
16. S.I. Gaje Singh, S.H.O., Radaur	S.I. Gaje Singh promoted as Inspector on 1st December, 1964
17. S.I. Karnail Singh, S.H.O., Pundri	S.I. Karnail Singh to Samalkha P.S. on 18th July, 1964
18. S.I. Attal Behari Lal, S.H.O., Rajaund	S.I. Attal Behari Lal to City Karnal on 11th September, 1964
19. S.I. Sukhdev S.H.O., P.S., Shahabad	S.I. Sukhdev transferred to Rohtak for departmental enquiry on 5th March, 1965
20. S.I. Gurbux Singh, S.H.O. P.S. Thaska	S.I. Gurbux Singh to Police Lines on 29th June, 1964
21. A.S.I. Mansa Singh, S.H.O. P.S. Indri	A.S.I. Mansa Singh proceeded on L.P.R. on 5th November, 1964

P.S. Sadar Karnal on 26th January, 1966 from where he has now been transferred to Ambala District under the orders of D.I.G./Ambala Range.

4. S.I. Gurdev Singh was transferred from P.S. Rajaund on 8th April, 1965 as he had committed some serious misconduct while posted as S.H.O. There were also complaints about his corruption and bungling in this P.S. for which a deportmental enquiry was initiated.

5. S.I. Ram Labhaya (reduced as A.S.I. in a departmental enquiry) was posted as S,H.O. Ladwa on 24th February, 1966.

6. S.I. Roshan Lal, S.H.O. P.S. Pehowa proceeded on leave with effect from 14th April, 1965 and after availing the leave was posted as S.H.O. P.S. Samalkha on 1st May, 1965. From P.S. Samalkha he was transferred to P.S. Butana on 13th February, 1966 on administrative grounds.

7. S.I. Walaya Ram was transferred from P.S. Assandh to P.S. Pehowa on 9th November, 1964 on heavy charge being no other suitable S.I. but on 23rd November, 1964

[Home a nd Development Minster]

1	2	3	4
		when the S.H.O. P.S. Sdr. Karnal was transferred to P.S. Nissing S.I. Walaya Ram was posted to P.S. Sadar Karnal being heavy and important charge.	
		8. A.S.I. Harbans Singh was transferred from P.S. Shahabad to Police Lines on 14th October, 1965 as there were complaints of corruption and partisan approach in a serious murder case. A departmental enquiry is pending againlst him as a result of these alegations.	
		9. A. S. I. Raj Singh while posted as S.H.O. P.S. Pundri was involed in a corruption case of P.S. Pehowa nd was transferred to Lines on 4th September, 1964.	
		10. S.I. Karnail Singh was transferred from P.S. Samalkha to district Hissar on 8th May, 1965 under the orders of D.I..G.A.R.	

11. S.I. Attal Behari Lal was trans ferred from P.S. City Karnal to P.S. Kaithal on 13th February, 1966 on administrative grounds.

12. S.I. Gurbux Singh was transferred from Police Lines Karnal to P.S. Shahabad on 14th October, 1965 in place of A.S.I. Harbans Singh transferred to Police Lines to face the departmental enquiry pending against him.

CASES CHALLANED UNDER THE OPIUM ACT, 1878

3344. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of cases challaned under the Opium Act, 1878, in district Karnal during the period from 6th July, 1964 to-date, the names of persons who were challaned, the dates when they were challaned and the dates when the challans were put up in the court;

(b) the number and names of persons referred to above who were acquitted and convicted, separately, in the said cases;

(c) the names with residential addresses of the witnesses who appeared in the cases in which the accused referred to in part (a) above were acquitted, Police Station-wise;

(d) the names with residential addresses of witnesses, Police Station-wise, in district Karnal, who did not support the prosecution story and as a result thereof the said accused were acquitted ;

(e) whether any of the witnesses referred to in part (d) above were again cited by Police as witnesses in some other cases on a subsequent date ; if so, their names together with the reasons for citing them as witnesses again ?

Sardar Darbara Singh : The time and labour involved in collecting the information will not commensurate with the benefits sought to be derived by the Hon'ble Member. The reply can be furnished regarding any specific point/case, if called.

LIFE PRISONERS

3345. **Comarde Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the names and home addresses of the life prisoners, Jailwise, whose release cases were recommended to the Inspector General of Prisons by the Jail Superintendents during the years 1964-65 and 1965-66;

(b) the names of the Prisoners out of those mentioned above whose cases were recommended by their respective districts Police Officers and the Inspector General of Prisons, to the Home Departments ;

(c) the names of Prisoners referred to above whose release cases are pending decision in the Inspector General of Prisons, office and in the Home Department at present, separately, and the date since when they have been pending ?

Shri Chand Ram : The time and labour involved in the collection and compilation of the requisite information, which will be very voluminous, will not be commensurate with any possible benefit sought to be derived therefrom. In case the Hon'ble Member desires to have information in respect of any particular prisoner, or any particular Jail the same can be supplied to him.

COMPLAINT MADE BY A LEGISLATOR REGARDING INORDINATE DELAY IN PUTTING UP A CHALLAN

3346. **Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that on a complaint lodged by a legislator of Karnal on the subject of "Inordinate delay in putting up challan under the Nuisance Act, against Shri Kirpal Singh, M. C., Gurdeep Singh, Ram Kishan Azad ete." case FIR 159/64 (P. S. City Karnal) of the "Punjab Instruments (Control of Noise) Act", was enquired into by the D. I. G. of Police, Ambala Range and the S. P., Karnal, during the period from 23rd September, 1965 to date; if so, the date when both the officers conducted the enquiries;

(b) whether the officers mentioned in part (a) above informed the complainant of the result of the enquiry; if so, when, together with the copy of the findings of each be laid on the Table of the House; if the complainant was not informed the reasons therefor ;

(c) whether any action against any Police official/officer has been taken as a result of the said enquiry; if so, what; if not, the reason therefor ;

(d) whether any explanation has been called by the higher authorities from the S. P., Karnal; if so, what; if not, the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that the S. P., Karnal, held in his enquiry that there was no fault on the part of the Police whereas the D. I. G., Ambala, held some of the Police officials of the City Police guilty ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. An enquiry was held by the D.I.G., Ambala Range, into the complaint preferred by Com. Ram Piara, M. L. A., regarding the alleged delay in putting up the challan in case State Vs. Kirpal Singh u/s 5 of the Punjab Instruments (Control of Noise) Act. This enquiry was held on various dates in December and January and completed in January last.

(b) The D. I. G., Ambala Range informed Shri Ram Piara, M.L.A. the result of his enquiry,—vide his memo. No. 1177, dated 25th January, 1966, a copy of this communication is placed on the Table of the House.

(c) On the conclusion of the enquiry, S. P., Karnal was directed by the D. I. G., Ambala Range, to take action against the officers responsible for the delay.

(d) On recepit of Com. Ram Piara's original complaint dated 10th November, 1965, a report on the facts of the case was called from S. P., Karnal.

(e) S. P., Karnal had reported that the delay mostly occurred in court, whereas the D. I. G.,Ambala Range, noticed that there was lack of vigilance on the part of Local Police too.

[Home and Development Minister]

Copy of Memo No. 1177, dated 25th January, 1966 from the Deputy Inspector General of Police, Ambala Range, to Com. Ram Piara, M.L.A. Model Town, Karnal.

Kindly refer to your letter dated 11th January, 1966 regarding the delay in putting up the challan of case FIR No. 159/64 U/S 5 of the Punjab Instruments (Control of Noise) Act.

2. The delay in the final disposal of the case has been due to the variety of reasons, some of which were really beyond the control of Police. It is, however, a fact that there was certain amount of lack of vigilance on the part of the local Police of which I have taken notice for necessary disciplinary action.

PLYING OF PEPSU ROADWAYS BUSES ON NARWANA-UKLANA ROUTE

3349. **Shri Fakiria** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the authorities to ply Pepsu Roadways buses on the Narwana-Uklana route ; if so, when; if not, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that old buses are being plied on the said route which is a long one; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) Yes. An application for the grant of permits on this route by the Corporation is already pending before the Regional Transport Authority. As and when permits are sanctioned operation will be undertaken.

(b) The route is being operated by private operators at present.

POST OF INSPECTORS ETC IN THE FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

3350. **Sardar Trilochan Singh Riasti** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number and names of the Inspectors, Assistant Food and Supplies Officers and District Food and Supplies Officers in the Food and Supplies Department as on 11th September, 1963 and 1st January, 1966, separately, and the number and names of those belonging to the Scheduled Castes amongst them ;

(b) the total number of posts of Inspectors, Assistant F. & S. officers and the District F. & S. officers filled in the said department after 12th September, 1963 todate together with the date(s) on which these were filled category-wise ;

(e) the total number of posts amongst those mentioned in part (a) above reserved for the members of the Scheduled Castes;

(d) whether all the said posts mentioned in part (c) above have since been filled by promotion from among the members of the Scheduled Castes; if so, their names category-wise, and whether the percentage of reservation in promotion cases fixed for persons belonging to the Scheduled Castes was kept in view while filling the said posts;

(e) if the reply to part (d) above in respect of any of the said categories of services be in the negative, the reasons therefor;

(f) whether any cases of promotion of the Scheduled Castes officials mentioned above have been considered by the Head of the Department concerned, if so, their names and their position at present ;

(g) whether any cases of promotion of the Scheduled Castes officials were referred to the Welfare Branch of the Government (in the Secretariat) if so, when and with what result and the details thereof ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any benefit to be derived therefrom.

ASSISTANTS ETC. IN THE OFFICE OF DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, PUNJAB

3351. Sardar Trilochan Singh Riasti : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number and names of the Assistants, Superintendents and Assistant Registrars in the office of the Director of Public Instruction, Punjab, as on 11th September, 1963 and 1st January, 1966, separately, and the number and names of those belonging to the Scheduled Castes amongst them ;

(b) the total number of the posts of Assistants, Superintendents and Assistant Registrars filled in the said department after 12th September 1963 to-date together with the date(s) on which these were filled category-wise;

(c) the total number of posts amongst those mentioned in part (a) above reserved for the members of the Scheduled Castes;

(d) whether all the said posts mentioned in part (c) above have since been filled by promotion from among the members of the Scheduled Castes, if so, their names, category-wise, and whether the percentage of reservation in promotion cases fixed for persons belonging to the Scheduled Castes was kept in view while filling the said posts;

(e) if the reply to part (d) above in respect of any of the said categories of services be in the negative, the reasons therefor;

(f) whether any cases of promotion of the Scheduled Castes officials mentioned above have been considered by the Head of department concerned; if so, their names and their position at present;

(g) whether any cases of promotion of the scheduled castes officials were referred to the Welfare Branch of the Government (in the Secretariat); if so, when and with what result and the details thereof ?

Shri Prabodh Chandra : (a) & (b) The requisite information is given in statements Nos. I and II enclosed, respectively.

(c) Two posts of Assistants.

No post of Superintendent.

No post of Assistant Registrar.

[Minister for Education]

Out of 30 posts, first 11 posts were given to those officials who were reverted on the application of 15% cut with effect from 1st April, 1963. According to Government instructions the reservation for promotion of Scheduled Caste members was to be applied after absorbing all such reverted officials.

Against the remaining 19 posts of Assistants, 2 posts were reserved for Scheduled Castes officials.

(d) (i) Yes.

(ii) Sarvshri Shingara Ram and Benarsi Lal promoted as Assistants.

(iii) Yes.

(e) The question does not arise.

(f)& (g) (1) Yes, one on 5th December, 1964 in respect of Shri Pritam Singh, Superintendent. The second post of Assistant Registrar (Examinations) was originally sanctioned in April, 1963 for two months from the date of entertainment. Shri Raghbir Singh, Superintendent, who was senior to Shri Pritam Singh, was appointed by Government to officiate with effect from 17th June, 1963 to 16th August, 1963. On the 14th August, 1963, just before the expiry of the sanctioned tenure, the Director Public Instruction, Punjab sent a proposal for the continuance of this post up to the end of the financial year 1963-64. The processing of this proposal by the Administrative Department and the issue of Government sanction in consultation with the Finance Department took some time and the requisite sanction for the continuance (and not creation) of the post of Assistant Registrar was issued on 28th September, 1963.

(2) The cadre of Superintendent, Assistant Registrars (Examinations), etc. is common, the only difference being that the post of Assistant Registrar (Examinations) carries a special pay of Rs. 50 per month, while the post of Superintendent does not. Earlier the Scheduled Castes and Backward Classes Department had advised in another case *vide* their U.O. No. 3687-4WGI-65, dated 17th April, 1965 that the posts carrying special pay within the same service/cadre and bearing the same grade are not to be treated as promotional posts for the purpose of reservation for the members of Scheduled Castes.

(3) On receipt of a representation from Shri Pritam Singh, Superintendent, belonging to Scheduled Castes, matter was taken up with the Scheduled Castes and Backward Classes Department and they advised that in the peculiar circumstances of the case explained in paras 1 and 2 above there was no objection to the action taken by the Education Department with regard to the treating of the vacancy of Assistant Registrar as not a fresh vacancy arising after 12th September, 1963. Shri Raghbir Singh was accordingly allowed to continue as Assistant Registrar and the representation of Shri Pritam Singh was rejected. Shri Raghbir Singh was, however, not paid as Assistant Registrar (Examinations) for the period from 17th August, 1963 to 20th October, 1963 due to the late issue of Government sanction.

(4) On another representation submitted by Shri Pritam Singh, Superintendent, to the Scheduled Castes and Backward Classes Department against the Government decision referred to in para 3 above, the matter is now under correspondence between that Department and the Education Department.

STATEMENT No. 1

PART A

Name of the post	Position as on 11th September, 1963		Position as on 1st January, 1966		Remarks
	Total Number	Number of Scheduled Castes employees	Total Number	Number of Scheduled Castes employees	
(i) Assistants ..	153	2	172	4	
(ii) Superintendents ..	23	1	27	1	
(iii) Assistant Registrars ..	2	—	2	—	

PART B

Serial No. (1)	Names as on 11th September, 1963 (2)	Serial No. (3)	Names as on 1st January, 1966 (4)	Remarks (5)
	Assistants			
1.	Shri Kulwant Singh			
2.	,, Manohar Lal			
3.	,, Harbux Singh			
4.	,, Basakha Singh			
5.	,, Gurnam Singh			
6.	,, Harbhajan Singh			
7.	,, Balwant Singh			
8.	,, Chaman Lal Pathak			
9.	,, Karam Singh (Pepsu)			
10.	,, Gurwant Singh		As in column 2	
11.	,, Hardutt Dev			
12.	,, Pritam Singh			
13.	,, Amrik Singh			
14.	,, Prithi Singh			
15.	,, Gurdas Ram			
16.	,, Santokh Singh			
17.	,, Mohinder Singh			
18.	,, Aya Singh			
19.	,, Tara Chand			

[Minister for Education]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Shri Krishan Kumar	As in column 2		
21.	„ Beant Singh			
22.	„ Tarlochan Singh			
23.	„ K. K. Puri			
24.	„ Mohinder Nath Chopra			
25.	„ Kuldip Singh			
26.	„ B. N. Dogra			
27.	„ Karam Singh			
28.	„ Sushil Chandar			
29.	„ Omesh Chand			
30.	„ Parhlad Singh			
31.	„ Rup Chand			
32.	„ Jaswant Singh Arora			
33.	„ Hardial Singh			
34.	„ Sarwan Singh			
35.	„ Jaishi Ram			
36.	„ Kultaran Singh			
37.	„ Tilak Raj Suri			
38.	„ Narain Singh			
39.	„ Satya Parkash			
40.	„ Gursharan Singh			
41.	„ Rattan Lal Sharma			
42.	„ Walaiti Ram Dua			
43.	„ Dharam Singh			
44.	„ Ram Chand			
45.	„ S. S. Kayshap			
46.	„ G. S. Sukhija			
47.	„ Raj Kumar			
48.	„ Mahvir			
49.	„ B. N. Sehgal			
50.	„ Jatindar Singh			
51.	„ Satwant Singh			
52.	„ Rattan Singh Kalyan			
53.	„ Ishar Dass Sud			
54.	„ Madan Gopal			
55.	„ Sham Lal Sharma			
56.	„ Jit Parkash			
57.	„ Saranjit Singh			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58.	Shri Komal Sarup	As in column 2		
59.	,, Madan Lal Mahajan			
60.	,, Tarseem Singh			
61.	,, M. C. Kapur			
62.	,, L. C. Suri			
63.	,, T. C. Chopra			
64.	,, Jaswant Singh Chabra			
65.	,, Sardul Singh			
66.	,, B. B. Gandhi			
67.	,, Datar Singh			
68.	,, Amarjit Singh Duggal			
69.	,, Dev Parkash			
70.	,, Krishan Kumar Kapila			
71.	,, Amar Singh			
72.	,, D. D. Vasudeva			
73.	,, Som Nath Chadda			
74.	,, Harbhajan Singh			
75.	,, Jagdish Chander			
76.	,, Gian Singh Jaiswal			
77.	,, Sohan Dutt Talwar			
78.	,, Rattan Singh			
79.	,, Ram Parkash Tandon			
79.	,, Ram Parkash Tandon			
80.	,, Darshan Kumar Khanna			
81.	,, Munshi Ram			
82.	,, Chaman Lal			
83.	,, Mohan Lal			
84.	,, Tarseem Lal			
85.	,, Krishan Gopal			
86.	,, Shamsher Singh (Scheduled Caste)			
87.	,, Parmatma Sarup			
88.	,, Jai Dyal			
89.	,, Raghbir Singh			
90.	,, Udhey Bhan			
91.	,, Anand Sarup			
92.	,, Nagina Singh (Scheduled Caste)			
93.	,, Sat Pal Sharma			

1	2	3	4	5
94.	Shri Amar Dass Bedi	As indicated in column 2		
95.	,, Gurcharan Singh Duggal			
96.	,, S. S. Sharma			
97.	,, D. R. Khullar			
98.	,, Barrinder Singh			
99.	,, Raj Kumar Vaid			
100.	,, Sandhia Dass			
101.	,, Surjit Singh Bhatia			
102.	,, Yash Pal Thapar			
103.	,, B. R. Midha			
104.	,, M. L. Khurana			
105.	,, Bakshish Singh			
106.	,, W. C. Khana			
107.	,, K. L. Sethi			
108.	,, Jaswant Singh Virk			
109.	,, Sewa Nath			
110.	,, A. N. Mittal			
111.	,, Bhagwant Singh			
112.	,, Hans Raj Soni			
113.	,, Karamjit Singh			
114.	,, Abnashi Ram			
115.	,, Kartar Singh Suri			
116.	,, Joginder Singh Chadda			
117.	,, S. S. Bindal			
118.	,, Om Parkash Tola			
119.	,, Gurbachan Singh			
120.	,, Chiranjit Lal			
121.	,, K. L. Sethi			
122.	,, Gurbaksh Singh			
123.	,, Ved Parkash Adalakha			
124.	,, A. P. Verma			
125.	,, Kanwar Bhan Batra			
126.	,, Harjit Singh			
127.	,, Nand Lal Nanda			
128.	,, Kidar Nath			

1	2	3	4	5
129.	Shri Khushi Ram	As indicated in column 2		
130.	„ Bakshish Singh	As indicated in column 2		
131.	„ N. C. Khurana	As indicated in column 2		
132.	„ Sant Lal	As indicated in column 2		
133.	„ Udhe Vir Singh	As indicated in column 2		
134.	„ Lekh Ram	As indicated in column 2		
135.	„ Rajinder Nath Chadda	As indicated in column 2		
136.	„ Rajinder Pal Gupta	As indicated in column 2		
137.	„ Manohar Lal Babar	As indicated in column 2		
138.	„ B, S. Sidhu	As indicated in column 2		
139.	„ Om Parkash	As indicated in column 2		
140.	„ Daljit Singh	As indicated in column 2		
141.	„ Rang Behari Lal	141. Shri Prabh Dayal		
142.	„ Harbans Lal Sharma	142. „ D.K. Khana		
143.	„ Hukam Chand	143. „ O. P. Dhingra		
144.	„ Kulwant Singh Hans	144. „ P. L. Nayer		
145.	„ Tarlok Singh	145. „ Piara Lal Kapur		
146.	„ Suraj Balram	146. „ O. P. Bhatia		
147.	„ Rajinder Mohan	147. „ Hoshiar Singh Varma		
148.	„ Ishwar Singh	148. „ Jagdish Rai Singla		
149.	„ Tilak Raj Gujral	149. „ Darshan Lal Dua		
150.	„ Dasondhi Ram	150. „ Tej Ram		
151.	„ Hardev Singh	151. „ Mukandi Lal		
152.	„ G. S. Minhas	152. „ Gurdev Singh		
153.	„ S. K. Agnihotri	153. „ Shingara Ram (S. Caste)		
		154. „ Manohar Lal		
		155. „ Joginder Sihgh		
		156. „ Amarjit Singh Sidhu		
		157. „ Gajjan Singh		
		158. „ Jai Gopal		
		159. „ Amolak Raj Khanna		
		160. „ Ishar Dass Bhardwaj		

[Minister for Education]

1	2	3	4
		161.	„ Kartar Singh Kapur
		162.	„ Sikandar Lal
		163.	„ Benarsi Lal (S. Caste)
		164,	„ Randhir Singh
		165.	„ S. S. Gupta
		166.	„ Bhagwan Singh
		167.	„ Radhe Sham Singla
		168.	„ O. P. Bhandari (post reserved)
		169.	„ N. N. Puri „ „
		170.	„ Kahanya Lal „ „
		171.	Vacant
		172.	Vacant
	Superintendents		
1.	Shri Laxman Singh		As indicated in column 2.
2.	„ Dharam Paul		
3.	„ Gurbux Singh		
4.	„ Pritam Singh (S. Caste)		
5.	„ Pritam Singh (Pepsu)		
6.	„ Madan Gopal Nijhawan		
7.	„ Gurdial Singh		
8.	„ Rattan Singh Sodhi		
9.	„ Hans Raj Kataria		
10.	„ Harchand Singh		
11.	„ Ram Kishan Gupta		
12.	„ Ram Parshad Lakhanpal		
13.	„ Krishan Gopal		
14.	„ Des Raj Kharbanda		
15.	„ G. S. Bedi		
16.	„ B. N. Kohli		
17.	„ Arjan Dev		
18.	„ J. K. Tandon		
19.	„ Narinder Singh		
20.	„ M. N. Madan		
21.	„ Harbans Singh Sindhu		
22.	„ Madan Lal Sharma		
23.	„ Kishori Lal Sharma	23.	Shri Hari Parshad Dewan

1	2	3	4	5
		24. Shri Zorawar Singh		
		25. Vacant		
		26. Vacant		
		27. Vacant		
	Assistant Registrar (Examinations)			
1. Shri O. P. Chopra				
2. Shri Raghbir Singh			As indicated in column 2.	

STATEMENT II

Name of post	No. of posts	Date on which filled up
1	2	3
(i) Assistants	30	One on 1-2-64
		One on 23-1-64
		One on 23-3-64
		One on 11-5-64
		One on 2-10-63
		One on 28-9-63
		One on 27-9-63
		One on 11-10-63
		One on 3-3-64
		One on 16-3-64
		One on 25-4-64
		One on 19-9-64
		Three on 27-11-64
		Two on 1-4-65
		Five on 15-12-64
		Two on 1-4-64
		Three on 1-11-65
		Three on 19-2-66 to 28-2-66
(ii) Superintendent		Nil
(iii) Assistant Registrar		Nil

PROMOTION OF TECHNICAL ASSISTANTS ETC. IN THE ECONOMIC AND STATISTICAL ORGANISATION, PUNJAB

3352. Sardar Trilochan Singh Riasti : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

(a) the total number and names of the Technical Assistants, the District Statistical Officers and the Research Officers in the office of the Economic and Statistical Advisor to Government, Punjab, as on 11th September, 1963 and 1st January, 1966,separately and the number and names of those belonging to the scheduled castes amongst them ;

(b) the total nnmber of posts of Technical Assistants, District Statistical Officers and Research Officers, filled in the said department after 12th September, 1963 todate together with the date(s) on which those were filled categorywise ;

(c) the total number of posts amongst those mentioned in part (a) above reserved for the members of the Scheduled castes;

(d) whether all the said posts mentioned in part (c) above have since been filled by promotion from among members of Scheduled Castes; if so, their names, category-wise, and whether the percentage of reservation in promotion cases fixed for persons belonging to the Scheduled castes was kept in view while filling the said posts ;

(e) if the reply to part (d) above in respect of any of the said categories of services be in the negative, the reasons therefor;

(f) whether any cases of promotion of the Scheduled castes officials mentioned above have been considered by the Head of the Department concerned; if so, their names and their position at present ;

(g) whether any cases of promotion of the Scheduled castes officials were referred to the Welfare Branch of the Government(in the Secretariat); if so, when and with what result and the details thereof ?

Sardar Ajmer Singh : (a)

I. Total number and names of Technical Assistants—

(i) on 11-9-1963 .. 36 (Names are given in Annexure I.)

(ii) on 1-1-1966 .. 91 (Names are given in Annexure II.)

II. Total number and names of District Statistical Officers/Research Officers—

(i) on 11-9-1963 .. 28 (Names are given in Annexure III.)

(ii) on 1-1-1966 .. 40 (Names are given in Annexure IV.)

III. Total number and names of District Statistical Officers/Research Officers and Technical Assistants belonging to Scheduled Castes :—

District Statistical Officers/ Research Officers—

(i) on 11-9-1963 Nil

(ii) on 1-1-1966 .. 2 (Names are given in Annexure V.)

Technical Assistants—

(i) on 11-9-1963 .. 2 (Names are given in Annexure V.)

(ii) on 1-1-1966 .. 8 (Names are given in Annexure V.)

These figures/names include officers who are away on deputation etc. or are officiating on higher posts in the Organisation.

(b) I. Technical Assistants—

(i) by direct recruitment 58

(ii) by promotion .. 8

II. District Statistical Officers/ Research Officers—

(i) by direct recruitment 4 (Offer has been made to the fifth candidate. He has yet to join.)

(ii) by promotion .. 6 (Four officers have been given proforma promotion. Total number of officers promoted is, therefore, 10.)

The dates on which these posts were filled, category-wise, are given at Annexure VI.

(c) I. Technical Assistants—

(i) by direct recruitment 12

(ii) by promotion .. 1.

II. District Statistical Officers/ Research Officers—

(i) by direct recruitment 2

(ii) by promotion 1

(d) (i) Yes. One post of Technical Assistant and one post of District Statistical Officer/Research Officer was filled by promotion from among members of Scheduled Castes etc. Shri R. S. Chopre was appointed Technical Assistant and Shri Manohar Singh was given proforma promotion as District Statistical Officer/Research Officer.

(ii) The percentage of reservation in promotion cases fixed for persons belonging to the Scheduled Castes etc. was kept in view while filling the said posts.

(e) In view of reply to part (d) above, question does not arise.

(Minister for Planning & Local Government)

(f) & (g) Yes. The case of Shri Gurcharan Singh, Technical Assistant, for promotion to the post of District Statistical Officer/Research Officer was considered by the Economic and Statistical Adviser and referred to the Planning Department for clarification regarding proforma promotions. A reference was made, on 15th November, 1965, by the Planning Department to the Scheduled Castes and Backward Classes Department (in Welfare General Branch) to clarify whether or not the Technical Assistants/Scrutiny Inspectors who were given proforma promotion against the posts of District Statistical Officers/Research Officers are also to be counted as to have been promoted for purposes of reservations in services for Scheduled castes etc. A reply in the affirmative was received in the Planning Department, on 21st Febuary, 1966 and conveyed to Economic and Statistical Adviser, on 2nd March, 1966. Economic and Statistical Adviser has also been addressed to send, to the Planning Department, proposals regarding promotions to the vacant posts of District Statistical Officers/Research Officers, urgently.

ANNEXURE I

List of Technical Assistants/Scrutiny Inspectors on 11th September, 1963

1. Shri S. P. Malik	Officiating as District Statistical Officer
2. ,, S. L. Kaushal	Ditto
3. ,, S. L. Kapoor	Ditto
4. ,, S. P. Gupta	Ditto
5. ,, A. S. Sanghi	Ditto
6. ,, T. L. Sharma	Officiating as Research Officer
7. ,, R. L. Suri	
8. ,, Lajpal Singh	
9. ,, J. K. Singlis	
10. ,, S. S. Aulakh	
11. ,, T. R. Bhalla	(On deputation to Government of India)
12. ,, S. C. Mathur	(On deputation to Industries Department)
13. ,, Manohar Singh	(On deputation to P. C. S.)
14. ,, Jag Pal Singh	(On deputation to Sports Department)
15. ,, V. P. Tandon.	
16. ,, Pawan Kumar	(On deputation to Government of India)

17. Shri G. S. Multani
18. „ Amolak Singh Bhagat
19. „ Mohinder Singh
20. „ Joginder Singh (Granted Emergency Commission)
21. „ Sher Singh
22. „ J. S. Nagi (Officiating as District Statistical Officer where appointed by direct recruitment)
23. „ R. K. Khanna
24. „ Maheshinder Paul Moudgil
25. „ Darshan Singh Walia
26. „ Raj Kumar Jain
27. „ Inder Mohan Soni
28. „ Joginder Pal
29. „ Hardev Raj
30. „ Gurcharan Singh
31. „ Narinder Kumar
32. „ R. C. Walia
33. „ Khem Raj Aggarwal
34. „ Patwant Singh
35. „ Bal Krishan Jain
36. „ Sukhdev Singh

ANNEXURE II

List of Technical Assistants/Scrutiny Inspectors as on 1st January, 1966

1. Shri S. P. Malik (Officiating as District Statistical Officer)
2. „ S. L. Kaushal Ditto
3. „ S. L. Kapoor Ditto
4. „ S. P. Gupta Ditto
5. „ A. S. Sanghi Ditto
6. „ T. L. Sharma (Officiating as Research Officer)
7. „ R. L. Suri (Officiating as District Statistical Officer)

(Minister for Planning & Local Government)

8. Shri Lajpal Singh	(Officiating as District Statistical Officer)
9. ,, J. K. Singli	(Officiating as Research Officer)
10. ,, Sewa Singh Aulakh	(Officiating as District Statistical Officer)
11. ,, T. R. Bhalla	(Deputation to Government of India) Officiating as District Statistical Officer
12. ,, S. C. Mathur	(On Deputation to Industries Department) Officiating as District Statistical Officer
13. ,, Manohar Singh	(On Deputation to P.C.S.) Officiating as District Statistical Officer
14. ,, Jagpal Singh	(On deputation to Sports Department)
15. ,, V. P. Tandon	(Officiating as District Statistical Officer)
16. ,, Pawan Kumar	(On deputation to Government of India) Officiating as District Statistical Officer
17. ,, G. S. Multani	(Officiating as District Statistical Officer)
18. ,, A. S. Bhagat	(Officiating as Research Officer)
19. ,, Mohinder Singh	(Officiating as District Statistical Officer)
20. ,, Joginder Singh	(Granted Emergency Commission).
21. ,, Sher Singh	
22. ,, J. S. Nagi	(Officiating as District Statistical Officer)
23. ,, R. K. Khanna	
24. ,, Maheshinder Pal Moudgil	
25. ,, Darshan Singh Walia	
26. ,, R. K. Jain	
27. ,, Inder Mohan Soni	
28. ,, Joginder paul	
29. ,, Hardev Raj	
30. ,, Gurcharan Singh	
31. ,, Narinder Kumar	
32. ,, R. C. Walia	
33. ,, Swaran Singh	

34. Shri Satish Kumar Kakar
35. „ Malkiat Singh
36. Miss R. K. Sahib
37. Shri Harbans Singh
38. „ Rajinder Singh Chopra
39. „ Suresh Chander
40. „ Niranjan Dev
41. „ Sudershan Lal
42. „ Ajit Singh
43. „ Ramesh Kumar Jain
44. „ Arya Mitter (Granted Emergency Commission)
45. „ Balbir Dutt
46. „ Krishan Kumar Mahajan
47. „ Sukhwant Singh Grewal
48. „ Joti Parkash
49. „ Mohinder Nath Rishi
50. „ M. L. Nagpal
51. „ Perma Nand Kanwar
52. „ Om Parkash
53. „ Kewal Krishan
54. „ Jagdish Parshad Yadav
55. „ Bhupinder Singh Nanda
56. Miss Veena Gautma
57. Shri Kidar Nath
58. „ Harbhajan Singh
59. „ Bikrem Jit Singh
60. „ Sharanjit Singh
61. „ S. K. Gupta
62. „ Surinder Mohan Mahajan
63. „ Chander Parkash Budhiraja
64. „ Chander Mohan Mehra

(Minister for Planning & Local Government)

65. ,, P. K. Bhandari

66. ,, M. K. Sood

67. ,, Dharam Vir Rehlan

68. ,, Kuldip Singh Bedi

69. ,, Inder Parkash Goel

70. ,, Baldev Raj Sharma

71. ,, Mohinder Singh

72. ,, Brij Bhushan Lal

73. ,, Durga Parkash Vaid

74. ,, Sudershan Lal Gopal

75. ,, Ranbir Singh Chohan

76. ,, Parshotam Lal Vij

77. ,, Satinder Pal Singh

78. ,, Hazara Singh

79. ,, Harbhajan Singh Ramdasia

80. ,, Uttam Singh

81. ,, Partap Singh Chawla

82. ,, Bhim Sen Maul

83. ,, Sukhdev Singh

84. Miss Kanwal Jit Kapoor

85. Shri Punnu Lal Sharma

86. ,, R. R. Bansal

87. ,, Sukhbir Singh

88. ,, Parshotam Dass

89. ,, Surinder Singh Marya

90. ,, Ram Sarup Bangur

91. ,, Harbhajan Singh Kang

ANNEXURE III

List of District Statistical Officers/Research Officers, on 11th September, 1963

Sarvshri—

1, J, N. Sharma, (on deputation to Government of India)

2. J S. Sandhu, officiating Dy. ESA.

3. R. P. Chopra, Offg. C, O.

Sarvshri—

4. O. P. Gupta.
5. Ved Parkash Sharma.
6. M. M. Bhardwaj.
7. J. S. Bhalla.
8. Satish Pandit.
9. Vidhya Parkash Sharma.
10. Y. P. Bhasin.
11. Ajit Singh.
12. M. L. Garg.
13. K. K. Sharma,
14. P. N. Kaul.
15. J. S. Kapoor.
16. Amrit Lal Katyal.
17. Rabindar Nath.
18. Jagjit Singh.
19. A. S. Sanghi
20. I. S. Gauba.
21. K. S. Aulakh.
22. J. S. Nagi.
23. S. P. Malik.
24. S. L. Kaushal.
25. S. L. Kapoor.
26. Kashmir Singh.
27. S. P. Gupta
28. T. L. Sharma.

ANNEXURE IV

List of District Statistical Officers/Research Officers as on 1st January, 1966.

Sarvshri—

1. R. P. Chopra, Offg. Dy. ESA.
2. O. P. Gupta, Offg. Dy. ESA.
3. Ved Parkash Sharma, Offg. C. O.
4. M. M. Bhardwaj.
5. J. S. Bhalla.
6. Satish Pandit (on deputation to Government of India.)
7. Vidya Parkash Sharma.
8. Y. P. Bhasin.
9. Ajit Singh.
10. M. L. Garg
11. K. K. Sharma.
12. P. N. Kaul.
13. J. S. Kapoor.
14. Amrit Lal Katyal.
15. Rabinder Nath.
16. Jagjit Singh.
17. A. S. Sanghi.
18. I. C. Gauba.
19. K. S. Aulakh.

(Minister for Planning and Local Government)

Sarvshri—

20. J. S. Nagi.
21. S. P. Malik.
22. S. L. Kaushal.
23. S. L. Kapoor.
24. Kashmir Singh.
25. S. P. Gupta.
26. T. L. Sharma.
27. Manohor Singh (Given Proforma Promotion) On deputation to P. C. S.
28. R. L. Suri.
29. Lajpal Singh.
30. J. K. Singlis.
31. Sewa Singh]
32. T. R. Bhalla (Given Proforma Promotion, on Deputation to Government of India.
33. S. C. Mathur. (Given Proforma Promotion, now on deputation to Industries Department)
33. V. P. Tandon.
34. Amolak Singh Bhagat,
36. Y. P. Seth.
37. Mohinder Singh.
38. Mehtab Singh.
39. Pawan Kumar (Given Proforma Promotion, on deputation to Government of India.)
40. G. S. Multani.

ANNEXURE V

List of Technical Assistants/District Statistical Officers/Research Officers belonging to Scheduled Castes

On 11-9-1963	*On 1-1-66*
Technical Assistants	
1. Shri Manohar Singh (On deputation to P.C.S.)	1 Shri Manohar Singh (On deputation to P.C.S.)
2. Shri Gurcharn Singh.	2. Shri Gurcharn Singh.
	2. Shri Malkiat Singh.
	4. Shri Rajinder Singh Chopra.
	5. Shri Harbhajan Singh Ramdasia.
	6. Shri Uttam Singh.
	7. Shri Bhim Sain Maul.
	8. Shri Ram Sarup Bangur.
District Statistical Officers/Research Officers	
Nil	1. Shri Manohar Singh (on deputation to P. C. S.)
	2. Shri Mehtab Singh.

ANNEXURE VI

The list showing the dates on which the posts of Technical Assistants and D.S.Os/R.Os were filled after 11-9-1963.

No. of posts filled by direct recruitment	Date on which filled	No. of posts filled by promotion.	Date on which filled
1	2	3	4
	Technical Assistants		
1	21-2-64	1	8-10-63
1	6-3-64	2	21- 2-64
2	3-3-64	1	2-3-64
1	5-6-64	1	7-4-64
1	23-6-64	2	27-6-64
2	3-6-64	2	4-6-64
1	6-6-64	9	
2	1-8-64		
2	6-8-64		
2	25-7-64		
1	23-8-64		
1	10-8-64		
1	22-8-64		
1	20-10-64		
1	6-9-64		
8	5-9-64		
8	7-9-64		
1	11-9-64		
2	1-9-64		
4	10-9-64		
1	3-9-64		
2	4-9-64		
1	2-9-64		
1	14-12-64		
2	4-3-65		
1	15-3-65		
1	15-2-65		
1	15-1-65		
2	23-2-65		
1	3-3-65		
1	31-8-65		
1	4-9-65		
58			

[Minister for Planning and Local Government]

No. of posts filled by direct recruitment	Date on which filled	No. of posts filled by promotion	Date on which filled
	District Statistical Officers/Research Officers		
1	15-3-65	2	20-12-63
1	19-3-65	1	6-5-64
1	9-4-65	1	29-6-64
1	6-4-65	4	10-8-64
		2	29-1-65
4		10	

ENQUIRY AGAINST THE REGISTRAR OF THE BOARD OF AYURVEDIC AND UNANI SYSTEM OF MEDCIINE, PUNJAB

3353. **Pandit Amar Nath Sharma** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an enquiry is being conducted against the Registrar of the Board of Ayurvedic and Unani systems of Medicine, Punjab; if so, the name of the authority who is conducting the enquiry and the present stage thereof;

(b) whether the said Board has been informed about the said enquiry ?

Shrimati Om Prabha Jain : (a) Yes; Director Health Services, Punjab. The enquiry has not so far, been completed.

(b) The inquiry is being conducted by the Chairman of the Board himself.

10-30 a.m.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Order. please.

ADJOURNMENT MOTION

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ।......

Mr Speaker : Please take your seat.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहब, पहले इन का प्वायंट आफ आर्डर सुन तो लें......

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ हर वक्त यह अच्छा नहीं लगता। Do not try to be too wise.

कामरेड तरसिका, मैं ने आप की adjournment motion disallow कर दी है। अगर आप इस बारे में काल-एटैनशन का नोटिस दे दें तो वह मैं एडमिट कर लूंगा। (It does not look nice for the hon. Member, Shri Jagan Nath to interrupt like this every time, He should not try to be too wise.

I have disallowed the adjournment motion given notice of by Comrade Makhan Singh Tarsikka. I can admit a call attention on this subject if he gives notice for it.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਲਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ......

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਦਿਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ......

Mr. Speaker : Order, please.

CALL ATTENTION NOTICES

(*Serial No. 46*)

Sardar Gurcharan Singh ; I draw the attention of the Minister concerned towards the fact that the Punjab Government has promulgated section 144 in some big cities—Amritsar and Jullundur in the State on the flimsy ground for maintaining law and order in the State. This has brought sense of unstability, insecurity and fear among the different sections of the society and it will effect the trade and bring economic disorder and create vicious circle of rumour mongering. It is necessary to make the position clear and bring confidence in all sections of the society.

Mr. Speaker : This is admitted.

सिचाई मंत्री : मेरा ख्याल है कि आप इसे अब बिदड़ा करना चाहते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

श्री अध्यक्ष : आप इस मोशन को वापस तो नहीं लेते ? (Does the hon. Member want to withdraw his notice ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Mr. Speaker ; Also please maintain law and order in the House.

(Serial No. 47)

Sardar Hari Singh : I draw the attention of the Government towards the fact that in the villages Apra, Chak Sahbod and Turan (Phillaur Block), wheat, gram and fodder crops have been completely destroyed by a severe hailstorm, while in villages Samrain, Lohgarh Katana, Garhi Mahal Singh, Rajpura and Chima Ualar all the above-mentioned crops have been greatly damaged. The Government should immediately rush to give relief to the kisans and the tenants who are the worst sufferers in the villages where the crops have been completely destroyed and help others whose crops have been partially damaged.

Mr. Speaker : This is admitted.

Chief Parliamentary Secretary : Sir, the District Officers have already visited the villages and they are taking necessary action.

PRESENTATION OF REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE

Sardar Balwant Singh (Chairman, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Budget Estimates for the year 1965-66.

CONSIDERATION AND ADOPTION OF REPORTS OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

Sardar Niranjan Singh Talib (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to move—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the publication of the speech of Sardar Lachhman Singh Gill, M.L.A. in the Daily 'Evening News', Ludhiana, dated the 1st April, 1965, under the caption "Lachhman Singh Gill Ko Griftar Karo", which was presented to the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the publication of the speech of Sardar Lachhman Singh Gill, M.L.A., in the Daily 'Evening News', Ludhiana, dated the 1st April, 1965, under the caption "Lachhman Singh Gill Ko Griftar Karo" which was presented to the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the publication of the speech of Sardar Lachhman Singh Gill, M.L.A., in the Daily 'Evening News', Ludhiana, dated the 1st April, 1965, under the caption "Lachhman Singh Gill Ko Griftar Karo", which was presented to the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

THE MOTION WAS CARRIED

Chairman, Committee of Privileges : Sir, I also move—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Question is—

That this House having eonsidered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

The motion was carried

Sardar Niranjan Singh Talib (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to move—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege arising out of the Government instructions prohibiting its employees to approach Legislators, which was presented to the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of Privilege arising out of the Government instructions prohibiting its employees to approach Legislators, which was presented to the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege arising out of the Government instructions prohibiting its employees to approach Legislators, which was presented to the House on the 4th March, 1966 be taken into consideration.

The motion was carried

Chairman, Committee of Privileges : Sir I also move—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House having considered the report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Question is—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

The motion was carried

Sardar Niranjan Singh Talib (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to move—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the position assigned to the Members of the Punjab Vidhan Sabha derogatory to their status on the occasion of the swearing-in ceremony of the Governor designate, Sardar Ujjal Singh, on the 1st September, 1965, which was laid on the Table of the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the position assigned to the Members of the Punjab Vidhan Sabha derogatory to their status on the occasion of the swearing-in-ceremony of the Governor designate, Sardar Ujjal Singh on the 1st September, 1965, which was laid on the Table of the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਰਿਵਿਲਿਜਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਲ ਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ੇਨਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੈਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਡੇ ਵਡੇ ਚਾਰਜ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸੇਟੀ ਵਿਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੈਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਥਈਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 23. ਸੈਕਟਰ 10-ਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 13 ਤੇ ਐਚ. ਪੀ. ਨੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਵਿਰਮਾਨੀ, ਫਿਰ ਬੀ. ਡੀ. ਕਪੂਰ, ਬੀ. ਕੇ. ਬੇਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਹਿਲ, ਆਈ. ਪੀ. ਆਨੰਦ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਤਾਈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ (ਵਿਘਨ) 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਹਨ (ਹਾਸਾ) ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੈਜਸਲੇਟਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੜਬੜਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਤਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਰੂਪ ਚੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਲਿਖ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (* * * * * * * * *)

(ਹਾਸਾ)

A voice : Too strong a language.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Pandit Bhagirath Lal Shastri : On a point of order, Sir.

(*Interruptions*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (* *) ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ

*Expunged as ordered by the Chair.

ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । (He has withdrawn the word. - xx) It will not form part of the proceedings.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ—ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ—ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਸੀ Deputy Secretary, Administration. ਇਥੇ ਦਰਜ ਹੈ :—

"The Deputy Secretary, Administration and Political of the Chief Secretary's Organisation, who appeared before the Committee on behalf of the Additional Chief Secretary to Government, Punjab, in the meeting of the Committee held on the 10th December,1963, stated that the Maharaja of Patiala was assigned a place at Serial No. 1 of the list of invitees on account of his being an Ex-Ruler, Lt. General Kulwant Singh was accorded position at serial No. 2 because he was a retired Officer of the Defence Forces, Shri K. Hanumanthaiya, M. P., Chairman Punjab Administrative Reforms Commission, was placed at serial No. 3 and Shri Sant Parkash Singh, retired Inspector General of Police, was at serial No. 4 in the same way as was done in the case of Lt. General Kulwant Singh. Some Members of the Punjab Vidhan Sabha and all Members of the Punjabi Regional Committee were assigned places at serial Nos. 3, A, B, C, D, E, F, and G, as the information about the holding of the meeting of the Punjabi Regional Committee was received after the list of invitees had been drawn up.........................."

ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹਨ । ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨਡਸਟ੍ਰਅਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਦੇ ਐਡ੍ਰੈਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ਸਿਵਾਏ ਪਰਸਨਲ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ । ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀਜ਼. ਲਈ ਅਲਗ ਐਨਕਲੋਯਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ

*Expunged as ordered by the Chair.

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਆਊਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸ਼ਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਲਫ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਗੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਕੱਰਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂਦੀਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ........................

(ਵਿਘਨ)

ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਫੈਕਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਇਨਡਸਟ੍ਰੀਅਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਲ.ਏਜ਼. ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਕਬਜਾਨਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (*Noise in the House*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Order please. ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਊਂਜ ਜਾਂ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਥੇ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੀ ਗਲ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ (Order please. I would like to request the hon. Members, including the Ministers, to go to the lobbies if they want to converse among themselves. It does not look proper to keep

standing and talking in the House especially when it is seized of the matter of the Members' order of precedence. (*Interruption*) I again request the Members, including the Ministers, to go to the lobbies if they have to talk among themselves.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰੀ ਨੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਪਤਰ ਦੀ ਜੋ ਚਿਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ । ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨੇ ਵਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਲ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਥਲੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ; ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਤੇ ਬਤੌਰ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਨ । ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਹ ਮੀਲ ਅਗੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿਠੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਠੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ.............(ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : I would request the hon. Member not to raise such a discussion.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਲ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਲਿਖ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ! ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਪਰਾਪਰ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਟਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਡਾਇਸ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀ. ਏ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਡਾਇਸ ਤੋਂ ਥਲੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਦਿਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜ ਐਸ਼ਿਓਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨਾਲ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕਨਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਮ. ਐਲ ਏਜ਼. ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਕ

ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਤਕ ਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਰ ਸਵਾਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਸਟ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥਲੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਰ ਅਜ ਇਹ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਨਾਅਹਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ :

> "This Committee unanimously recommends appropriate action against Additional Chief Secretary for issuing a circular letter in connection with the Swearing-in of the Governor in which M. Ps. and M. L. As. have been assigned places derogatory to their status."

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਮਾਨ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਐਚ. ਐਮ. ਟੀ. ਦੇ ਇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦਾ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਚ. ਐਮ. ਟੀ. ਦੇ ਜੈਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਿਟਨ ਅਪਾਲੋਜੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਪਰ ਅਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਡਿਗਨਟੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅੰਦਰ ਚਿਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15—15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤੋਂ ਵਡਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਘਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਵੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰੇਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਮੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਥ ਦੀ ਜੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼., ਐਮ. ਐਲ. ਸੀਜ਼. ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਾਹਿਤ ਇਨਵਾਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1962 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ 12—13 ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ । ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਚ. ਐਮ. ਟੀ. ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਮਨਿਸ਼ਟਰਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਹੈਡਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੈ । ਬਾਜੂਦ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल): स्पीकर साहिब, जो पुराना वा क्या यहां पर सरदार कुलबीर सिंह ने श्री प्रबोध चन्द्र स्पीकर के वक्त का बयान किया है, उस वक्त मैंने इस सारे मुआमले पर एक प्रिविलेज मोशन पेश की थी जिस पर कि डाक्टर गोपी चंद को एक ब्यान देना पड़ा था और सरदार प्रताप सिंह को हाउस म मुआफी मांगनी पड़ी थी । यह मुआमला चीफ सैक्रेटरी के साथ भी टेक अप किया गया, वार्निंगज तक हुई पर इस से कोई मसला हल नहीं हो सका । जब चीफ मिनिस्टर साहिब यहां पर एशोरैंस पर एशोरैंस देते हैं तो लैजिस्लेटरज़ उनकी एपरी-

[कामरेड राम प्यारा]

सिएशन करते हैं, मगर बाहर के हालात देखो कि किस तरह लेजिसलेचर के लोगों को स्नब किया जाता है। बावजूद इस मसला पर बार बार ग़ौर करने के यह मसला आज तक हल नहीं हो सका है। अगर लेजिसलेटर के फरायज़ को आप देखें तो मैं समझता हूं कि उसे एक पायस ड्यूटी को सरअंजाम देना होता है। उस का पैसे के लिहाज़ से किसी बिजनैस मैन से मुकाबला करना मैं समझता हूं यह उसकी तौहीन है। अगर वह समझते हैं कि उन के सरमाया से यह गवर्नमैंट चलती है तो जितने सफैद पोश हैं अगर इनके हकूक की हिफाज़त यह लैजिसलेटर्ज़ न करते तो यहां पर कोई सफैद पोश बैठा दिखाई न देता। इनकी बुरी हालत होती। यह इस लिए आज बैठे हैं क्योंकि जनता के नुमायंदों ने उन बड़ी बड़ी आसामियों से बचाये हुये हैं। उन लैजिसलेटर्ज़ ने, जिनको कि जनता प्यार करती है। यह ठीक है कि बिग बिज़नैसमैन चंदा दे सकते हैं, कारें प्रोवाईड कर सकते हैं मगर जो स्टेटस एक लैजिसलेटर का है उस के बराबर या इस से आला वह शुमार नहीं किये जा सकते। यह नहीं हो सकता कि एक कंटरैक्टर जिस को सैंटरल गवर्नमैंट ने बलैक लिस्ट किया हुआ हो उसको तो ऐसे फंक्शन्ज़ पर अच्छा स्टेटस दिया जाये मगर एक लैजिसलेटर को उस से पीछे धकेल दिया जाया। मैं कहता हूं कि आखिर इस तरह की मैंटैलिटी है क्यों? यह एक बड़ा अहम मसला है जो बार बार सामने आता है। कई दफा जब हम छोटे छोटे अफसरों के पास जाते हैं तो आफीसर हमें स्नब करते हैं, बात बात पर ऐगज़ागिन करते हैं। ऐसे माहौल को बदलने की ज़रूरत है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे अफसरों को इगनोर करें और पैटी कामों के लिये उनके पास न जायें। जब तनखाह के मुताबिक और स्टेटस के मुताबिक एक शाया शुदा आर्डर आफ प्रेसीडैंस है तो हमें भी चाहिए कि हम उस का एहतराम करें। अगर कोई बात इसके मुताबिक नहीं होगी तो चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को चाहिए कि जो भी आफीसर ऐसी गलती का मुरतकिब होता है उस की भी पूछ ताछ की जायें। जब तक उस अफसर की पूछ ताछ नहीं होती तब तक यह एशोरैंस सिर्फ इंप्लीमैंट ही नहीं होगी बल्कि ऐसे वाक्यात आयंदा के लिए और बढ़ते जाएंगे। मैंबरों ने यह रिपोर्ट दी है, जिस के मुताल्लिक हाउस ने मुतफिक्का तौर पर मांग की है कि यह रिपोर्ट गवर्नमैंट को भेजी जाए। मैंबरों को अपने स्टेटस का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बनिस्बत आफीसर्ज के जिन को रूलज़ के मुताबिक़ काम करना पड़ता है। कई दफा फंक्शन्ज़ होती हैं। जब सीटिंग अरैंजमैंट होते हैं तो क्लर्क कुर्सी उठा के दूसरों को लेजिस्लेटर्ज़ के आगे बिठा देते हैं। लैजिस्लेटर लड़ नहीं सकता। फंक्शन का मौका आ जाता है वरना वह खुद भी इंतज़ाम कर ले, जब चीफ सैक्रेटरी को लिखा जाता है वह उसको डिफैंड करने के लिए आ जाता है। सरकार इस मैंटैलिटी को चेंज करने के नाकाबिल है। मैं ने उस मैंटैलिटी चेंज करने के लिए इस हाउस की तवज्जो दिलाई है। लैजिस्लेटर्ज के स्टेटस को ऊंचा

करना चाहिए । इन अलफाज़ के साथ इस रिपोर्ट को कमेटी को वापस भेजा जाए और गवर्नमैंट इस बात का ख्याल कर कि जब कोई अफसर इस गलती का मुरतकिब होता है तो पूछ ताछ की जाए वरना यह प्रैस्टीज़ मैनटेन रहने वाला नहीं । मुझे उम्मीद है कि आप और गवर्नमैंट ध्यान देंगे कि आयंदा के लिए यह नहीं होगा कि ऐसी प्रिविलेज मोशन आने की नौबत आए ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਸਨ । ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਹੋ ਗਏ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੰਞ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਿਵੀਲਿਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (ਵਿਘਨ) ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦੀ ਉਤਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਜਿਥੇ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਓਥੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਨਾਲ (ਏ) ਕਰ ਦਿਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਡਿਊ ਪਲੇਸ" । (ਵਿਘਨ) ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਨਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਐਮ, ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਲੋ ਰਖਿਆ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ

[ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ]

ਨੇ ਰਿਗਰੇਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ । ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 'ਭੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਅਗਰ ਅਗੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਲੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਰ । ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ । ਓਥੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਆਏ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁਅਲੁਕ ਰਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਟ ਜਾਂ ਜਾਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਦਿਆ । ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਦਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ): ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਚਾਹੁਣ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਏਧਰ ਆਇਆਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰਖਾਂਗਾ । ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਕਢਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਮੁਅਜ਼ਿਜ ਦੋਸਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ । ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਫਰੈਂਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਦਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਸਗੋਂ 3 ਏ, 3 ਬੀ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰ ਪਲੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਖੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਠੇ ਬੈਠੇ । ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਵਖਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਵਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ (ਵਿਘਨ) **(ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ : ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੀ ਤਕ ਗਏ ।)** ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇਂ ਤਕ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਜਾਂ 22 ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਬਲਕਿ 3 ਏ ਅਤੇ 3 ਬੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਜਿਥੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਬੈਠੇ ਉਥੇ ਹੀ ਮਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ । (ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਨੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ । (ਵਿਘਨ) ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਗਰੈਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ । ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ?

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਥਲੇ ਲਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੇਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਲ ਆਇੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ । ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ (ਵਿਘਨ) ਮੁਖ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਓਧਰ ਹੀ ਨੇ । ਤਾਬੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡ-ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ । (Comrade Shamsher Singh Josh and Bhan Singh Bhaura have given notice of this amendment) :

> That the Report regarding the position assigned to the Members of the Punjab Vidhan Sabha etc., be sent back for reconsideration.

ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਡੀਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਹਾਉਸ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ । (Although this amendment was not received within the prescribed time limit, yet being the matter of the member's privileges, I declare it in order. The House may now give its verdict.)

Now I will first put this amendment to the vote of the House, Question: —

> That the Report regarding the position assigned to the Members of the Punjab Vidhan Sabha etc., be sent back for reconsideration.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Ayes' and those who were for "Noes" respectively, to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was lost.

The Motion was lost.

चौधरी देवी लाल : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब यहां पर लेजिस्लेटर्ज़ पब्लिक को रिप्रेज़ेन्ट करने के लिए आते हैं । लेकिन जो अपने आप को रिप्रेजैंट नहीं कर सकता क्या वह मैम्बर रह सकता है इस हाउस का ?

Transport and Elections Minister : Mr. Speaker, there is no question when the hon. Member is misrepresenting his own self.

Mr. Speaker : Question is—

That the Report of the Committe of Privileges on the question of privilege regarding the pcsition assigned to the Members of the Punjab Vidhan Sabha derogatory to their status on the occasion of the swearing in-ceremony of the Governor designate, Sardar Ujjal Singh, on the Ist Septembar, 1965, which was laid on the Table of the House on the 4th March, 1966, be taken into consideration.

The motion was carried

Chairman, Committee of Privileges : I also move—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendation contained therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Question is—

That this house having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

The motion was carried

RESOLUTION *re.* ALLOCATIONS OF 60 PER CENT OF THE PLAN FUNDS FOR HARYANA AREA AND HILLY AREAS (*RESUMPTION*)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the resolution moved by Shri Balramji Dass Tandon, M. L. A, on the 17th February, 1966,

Chaudhri Darshan Singh who was in possession of the House when it adjourned the other day may please resume his speech.

Education Minister : I have a submission to make. In view of the resolution of the Congress Working Committee passed yesterday, the resolution under discussion becomes infructuous.

Chaudhri Darshan Singh : I would submit that this resolution does not become infructuous on that ground....

Mr. Speaker : If the hon. Member wants to speak, he may resume his speech.

Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : I beg to move that. question be now put,

11-30 a.m.

Voices : No, No

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀ ਸਦੀ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਜ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕ ਵਜੇ ਤਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ ਟੇਕਅਪ ਹੋਵੇਗਾ । (According to today's agenda discussion on this Resolution is to continue till 1.00 p.m. and thereafter next item on the agenda is to be taken up).

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਐਸਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ something is wrong at the bottom, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਿਜਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ । (*Deputy Speaker in the chair*). ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨਫਰੈਕਚੁਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੁਰੈਕਟ ਤੇ ਹਿਸਟਾਰੀਕਲ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਓ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਓਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਡਰਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਾਲੂ ਰਾਮ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਕਤ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਇਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਕੇ ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਮਤਾ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤਕ ਟਰੇਯਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਚੇਅਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾਹੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । (I am sorry to say that despite my remark last time that this resolution should not remain under discussion for more than three day's there was no response from the Treasuary Benches till the last movement. The Chair cannot make abrupt change in the programme.)

चौधरी देवी लाल : यहां यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि नए हालात के मुताबिक इस रैज़ोल्यूशन की ज़रूरत नहीं । मैं पूछना चाहता हुं कि क्या आप हरियाणा प्रांत बनाने के हक मे हैं ! अभी तो पंजाबी सूबा ही बना है हरियाणा प्रांत नहीं बना है ।

उपाध्यक्षा : चेयर का इन बातों से कोई संबंध नहीं। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि आज लास्ट डे है लेकिन कहा गया कि चलने दो । इस लिए आज जो एजंडा है उसके मुताबिक ही कार्यवाही चलेगी । (The Chair is not concerned with these matters. I remarked last time that that was the last day of its discussion but continuation of the discussion was demanded. We must, therefore, adhere to the day's agenda.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਗਰੱਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਘਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਧਿਆਨ ਉਥ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਰੈਜ਼ਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੋ । (These matters can be raised during the General Discussion. The hon. Member should now confine himself to the resolution under discussion.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਾਇਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ....

Deputy Speaker : Chaudhri Darshan Singh, you cannot dictate to the Chair, Speak on this Resolution only.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀ ਹੋਈ । ਇਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਥੋਂ ਦੋ ਸੌ ਮੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸੌ ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਆਏ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਲਾਨੀ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਗਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ......

Deputy Speaker: Please be relevant.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਵੇ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਰੁਪਏ ਫੀ ਬੋਰੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਉ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 1947 ਤੋਂ 12 ਦਫ਼ਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਤੇ ਗਿਣੀ ਭੀ

(ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ)

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਉਤੇ ਫਰਟੇਲਾਇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ । ਇਥੋਂ ਝੋਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਗ ਭੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 85% ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ 25 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ । ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ 80 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਮਣ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ।(ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹਿਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਏਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰੀਬਯੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਲੈਨਜ਼ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਏਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

Deputy Speaker : Kindly wind up now.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਏਂਸੀ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਏਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਨਾ ਭੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : (* * * * *)

(ਵਿਘਨ)

*Expunged as ordered by the Chair.

Deputy Speaker : Order please. Please take your seat. There must be some limit.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਛੀ ਲਗੇ।

Deputy Speaker : Please take your seat.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस रैज़ोल्यूशन पर 3, 4 रोज़ से बहस चल रही है। मैं आप की इजाज़त से इस रैज़ोल्यूशन की वर्डिंग हाउस में फिर पढ़ना चाहता हूं। वह यह है कि–

> "With a view to bring the hilly areas of the Punjab, which are backward, at par with the adjoining areas of the State and the Hariana area at par with the rest of the State in the matter of development, this House recommends to the Government to make plan allocations in such a way that sixty per cent of the plan funds are earmarked for the said Hariana area and the hilly areas."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस रैज़ोल्यूशन को पढ़ कर ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी हुई कि यह रैज़ोल्यूशन हमारे उस भाई की तरफ से आया जो पंजाबी रिजन का रहने वाला है। ताज्जुब इस बात का है कि जिस चीज़ का वह दिल से विरोध करते थे, आज हालात को सामने रखते हुए अपने आप को उसी को स्पोर्ट करने के लिए बेबस और मजबूर समझते हैं। उन्होंने अपने लिये हरियाणा प्रान्त की हमदर्दी मोड़ने और हासल करने के लिए यह रैज़ोल्यूशन हाउस के अन्दर पेश किया। वह कहते हैं कि जनसंघ वाले भी हरियाणा प्रान्त की डिवल्पमंट के बारे में हमदर्दी रखते हैं और सारे बजट का 60 प्रतिशत भाग हरियाणा की डिवैल्पमैंट के लिए खर्च किया जाए। इस रैज़ोलुशन के मूवर ने कल बजट पर स्पीच करते हुए कुछ फरमाया था। मैं ने उन की वर्डिंग नोट की थी। वह हाउस में कहना चाहता हूं। उन्हों ने कहा कि हरियाणा के लोग भी भोले भाले हैं और भोली भाली बातें करते हैं। उन को शायद पता नहीं कि वहां के लोग भोले भाले होते हैं और शैतान भी। रैज़ोल्यूशन के मूवर साहिब ने हरियाणा प्रान्त पर दबाव डालने की बातें कीं। उन्होंने कहा कि 4 जिलों का कैसे अलग सूबा बन सकता है। कल उन्होंने जो तकरीर की उस से उन की दिली भड़ास निकल गई। एक तरफ तो ऐसी बातें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हरियाणा प्रान्त की डिवैल्पमैंट के लिए बजट का 60 प्रतिशत भाग खर्च किया जाए। उन्होंने अपने दिल की बात कल बता दी कि वह हरियाणा प्रान्त के साथ बजट इस तरह क्यों शेयर करना चाहते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या हम उन से भीख मांगें। वह कौन हैं हमें देने वाले ? हम भी टैक्स पे करते हैं। हम भी आबियाना देते हैं। हम भी सरकार की हर वक्त मदद करते हैं। लेकिन जब बजट की ऐलोकेशन मांगते हैं तो क्या वह ऐलोकेशन उन की सिफारिशों से पंजाब सरकार देगी ? जो रैज़ोल्यूशन के मूवर थे। He was not sincere in his

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

efforts and in his mind in moving the resolution.

यह आपत्ति क्यों आई। उस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि भारतीय सरकार ने महसूस किया कि यहां पर अन्दर ही अन्दर जो फोड़ा पक रहा है, उस का आप्रेशन किए बगैर काम नहीं चल सकता है।

जब गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से एलान कर दिया गया कि पंजाबी सूबे की डीमारकेशन के बारे में नए सिरे से गौर होगा तो दिल्ली के चक्र काटे जाने लगे, इंडस्ट्रिलिस्टस के अलग डैपूटेशन्ज़ जा रहे हैं, लेडीज़ के अलग डैपूटेशन जा रहे हैं। पंजाबी रिजिन, जालंधर और अमृतसर का कोई अढ़ाई तीन सौ आदमी रोज़ दिल्ली में रहता था। क्यों रहता था ? आज सुबह इस बात का पता लग गया कि हाई कमांड की वर्किंग कमेटी ने पंजाबी सूबे का प्रिंसीपल कंसीड कर लिया है तो झट से कह दिया कि विदड्रा दिस रैज़ोल्यूशन। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उन से पूछता हूं कि क्या वे इस बात को तसलीम करते हैं कि हरियाणा वालों की डीमांड जायज़ थी अगर वे इस रैज़ोल्युशन को इनफ्रकचुअस कहते हैं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाई कमांड वालों की सूझ बहुत गहरी है। हम इस से बेखबर नहीं हैं, हम कोई बहरे नहीं हैं, अंधे नहीं हैं। हम सुन सकते हैं और हम देख सकते हैं। हम अपने दिमाग से काम ले सकते हैं। हाई कमांड की वर्किंग कमेटी ने यह प्रिंसीपल कंसीड कर लिया है कि भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बनेगा। The formation of Punjabi Suba on the basis of language does not lead us to an irrebuttable conclusion at this stage that Hariana will come into existence. We will have to strive for it. यह तो वक्त ही बताएगा कि वह बनेगा या नहीं। लेकिन रैज़ोल्यूशन के मूवर ने जो हमदर्दी हमारे साथ ज़ाहिर की उस के लिये शुक्रिया अदा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हम मांगते नहीं हैं, हम कोई भिखारी नहीं हैं। हम तो आप की विसातत से अपनी सरकार के सामने फैक्टस और फिगर्ज़ रखते हैं जिन से मालूम होगा कि हमारी क्या दुर्दशा इस राज में हो रही है। मैं ने पहले भी अर्ज़ की थी कि हरियाणा डिवैलपमैंट कमेटी की रिपोर्ट इस हाउस में रखी जा चुकी है और वह इस हाउस की प्रोसीडिंगज़ का एक हिस्सा बन चुकी है। वह एक मुँह बोलती तस्वीर है इस बात की कि वाकई हरियाणा के साथ बेइन्साफी होती रही है। पेश्तर इस के कि मैं हरियाणा के बारे में फैक्टस और फिगर्ज़ पेश करूं मैं पंजाब के मशहूर इंग्लिश अखबार ट्रिब्युन का लीडिंग आर्टीकल आप के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आज तक हरियाणा के बारे में कोई लीडिंग आर्टीकल किसी अखबार ने नहीं लिखा और पंजाब के उर्दू अखबार तो हरियाणा का मज़ाक उड़ाते हैं, वे हमें बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि प्रैस में हमारी आवाज़ नहीं है। मैं रैलेवेंट पोर्शन इस अखबार का पढ़ता हूं।

In the Tribune, dated January 31, 1966, it is stated:

"**Focus on Hariana**: For three decades and more Punjab's southern districts have been complaining, with good reason, of step-motherly treatment by the State Government. While the central areas of United Punjab—and since partition, of East Punjab—have made rap. ' all-round progress, the forlorn and forgotten Hindi-speaking region has been way behind trudging along at bullock-cart speed."

यह ट्रिब्यून का लीडिंग आर्टीकल कह रहा है । आगे चल कर डिप्टी स्पीकर साहिबा, लिखा है :

"This prolonged neglect led to agitations and discontent, at first sporadic and hence ineffective, but later assuming a magnitude which compelled attention. Then came repeated ministerial assurances, particularly in pre-election months, but these remained largely unimplemented. Some tell-tale figures may be quoted......."

फिर कुछ फिगर्ज़ भी हैं जो अभी आप के सामने रखूंगा :

"The people, by and large, are still steeped in ignorance and poverty, with antique-style farming and a frail industrial structure...."

इस किस्म की ऑबज़र्वेशन की है । फिर कहते हैं :

"To ensure uniterrupted attention, the setting up of special administrative machinery and a Development Board are obviously needed. Presence of an effective non-official element on the Board to watch the progress and advise the State Government on development efforts would be fruitful. A separate Cabinet portfolio for Hariana is overdue....."

फिर आगे चल कर उन्हों ने कहा है :

"Fourth Plan provisions for 1966-67 will reflect the Government's thinking. No amount of official patronage will, however, redress the imbalance unless the people of Hariana themselves display greater initiative and extend active co-operation in executing all projects which may henceforth be designed for their good...."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने कुछ लाईन्ज़ लीडिंग आर्टीकल की पढ़ कर सुनाई हैं । जिस चीज़ के लिये हम सिस पार्टीशन आहोपुकार कर रहे थे, गला फाड़ फाड़ कर इस हाउस के अन्दर भी और बाहर भी कह रहे थे, हमारे उन जज़बात की इस लीडिंग आर्टीकल ने सही तर्जमानी की है। हमारे ख्यालात का ठीक मज़ाहरा किया है कि वाकई हरियाणा के साथ इस हकूमत के वक्त में बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं आप के ज़रिए अर्ज़ करूं कि 60 परसेंट से काम नहीं चलेगा । हमें तो, टू कोट सरदार दर्शन सिंह, 100 परसेंट चाहिये । हम पंजाबी रिजिन का नही मांगते, हम हिल्ली एरियाज़ का बजट नहीं मांगते, हम किसी दूसरे का नहीं मांगते, हम तो यह चाहते हैं कि जो बजट हमारा है वह हमारे ऊपर खर्च हो। आप देखिए कि पंजाब की कुल आबादी 203 लाख है । हरियाणा की 75.27 लाख, पहाड़ी इलाका की 24.29 यानी यह कुल 99.56 लाख बनी । कुल आबादी का 49.02 परसेंट हुई । गोया हिल्ली एरिया और हरयाणा की पापुलेशन 49.02 परसेंट हुई । नान हरियाणा की आबादी हुई 50.98 परसेंट । अब आप एरियाज़ का मुलाहज़ा फरमाएं । हरियाणा का 16,835 सेक्वेयर माईल, हिल्ली

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

एरियाज़ का 12,434 सेक्योर माईल्ज़। यह 61.88 परसेंट एरिया कंस्टीच्यूट करता है। गोया एरिया हमारा ज्यादा है। अब एक्सटैंट आफ इरीगेशन देखिये। पहले 1.9 क्यूसेक्स पर थाउज़ैंड एकड़ज़ आफ लैंड थी फिर बढ़ कर 2.4 हो गई। यह हरियाणा रिजन के लिये है। नान हरयाणा के अंदर है 3.5 क्यूसेक्स पर थाउज़ैंड एकड़ज़ आफ लैंड है। आप अंदाज़ा लगाएं। एक दरिया है, उस में पानी नहीं है। कहते हैं कि उस में कुशाऊ डैम बनाएंगे। डैम तो बनना बनाना नहीं है। कहते हैं कि पानी की कमी है इस लिये ट्यूबवैल्ज़ लगा कर पानी की कमी को सप्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो एशोरेंस गवर्नमेंट यहां पर देती है किसी को पूरा नहीं करती। अब मैं आप के सामने इलैक्ट्रीसिटी की बाबत यानी परसेंटेज आफ इलैक्ट्रीफाईड विलेजिज इन हरियाणा बताता हूं। हरियाणा में 18 परसेंट विलेजिज इलैक्ट्रीफाईड हैं, नान हरियाणा एरिया में 29 परसेंट इस का ब्योरा इस तरह से है : अमृतसर : 69 परसेंट, ज़िला लुधियाना : 41 परसेंट, गुरदासपुर : 42 परसेंट और ज़िला जालंधर : 33 परसेंट। इस के मुकाबला में महेन्द्रगढ़ : 13 परसेंट, गुड़गांवां : 16 परसेंट, हिसार 18 परसेंट करनाल 19 परसेंट। यह बिजली का हाल है कि चौथा हिस्सा परसेंटेज बनती है। इन फिगर्ज़ से साफ ज़ाहिर है कि जितनी इलैक्ट्रिसिटी अकेले ज़िला अमृतसर को मिलती है उतनी सारे हरयाणा को नहीं मिलती।

इस के बाद आप नम्बर आफ रजिस्टर्ड फैक्टरीज़ पर लेख आफ पापुलेशन देखें। इस में देहली के कुरबो जवार का इलाका भी शामल है, देहली के आसपास का इलाका शामिल है जिसमें फरीदाबाद को भी कोट किया जाता है और हम जानते हैं कि इस फरीदाबाद की डिवैलपमैंट का जहां तक ताल्लुक है वह सैंट्रल गवर्नमेंट की पैट्रोनेज से ही है। तो रजिस्टर्ड फैक्टरी हरियाणा के अन्दर 14.9 परसेंट है जब कि नान हरयाणा के इलाके में यह परसेंटेज 36.5 है यानी 75 परसैंट से भी ज़्यादा फैक्टरीज़ नान हरयाणा एरिया में है।

फिर मैं तालीम की तरफ आता हूं। लिटरेसी परसेंटेज आफ पापुलेशन इन दी रिजन पर आता हूं। इस सिलसिले में ऐजूकेशन मनिस्टर साहिब ने सवालों का जवाब देते हुए भी बताया कि यहां पर कितने ही स्कूल विदाऊट टीचर्ज़ हैं और उन्होंने खुद इस बात को ऐडमिट किया है कि वाकई यह हकीकत है कि बैक्वर्ड एरियाज़ में, हिल्ली एरियाज़ में और हरयाणा के एरिया में टीचर्ज़ जाते नहीं, जाना पसन्द नहीं करते। इस लिए उन्होंने बताया कि हमारे यहां स्कूलों में स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए स्टाफ नहीं है। कई दफा हम ने कहा है कि वहां पर आप ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट ही कोई न कोई खोल दें ताकि वहां पर इस कमी को दूर किया जा सके लेकिन वह भी नहीं किया जाता। बात, मैडम डिप्टी स्पीकर, यह है कि इन की नीयत साफ नहीं है, उन का दिल साफ नहीं है। यह चाहते नहीं हैं, दिल से चाहते नहीं हैं कि इस इलाके की तरक्की की जाए या वहां पर

लोगों को सहूलियात बहम पहुंचाई जाएं । लेकिन फिर भी यहां पर प्रेम और मुहब्बत की मुरली बजाने का सन्देश हमें देते हैं कि प्यार से रहो, डिवीज़न न मांगो । हम तो कहते हैं कि हम ने रो कर देख लिया, चिल्ला कर देख लिया । अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और अब हम चाहते हैं कि हमारा इस मुहब्बत से पिंड छूटे वरना इन अठारह साल इस पंजाब के साथ रह कर हमने तो अपनी हैसियत को ही खत्म कर दिया हुआ था, पंजाब के नकशे में से अपना नाम तक मिटा लिया था । लेकिन हर एक चीज़ की कोई हद होती है, कोई अन्त होता है। फिर यह प्रावलम क्राप अप हुई, आवाज़ उठी कि हमारे जज़बात को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए । अब पता नहीं कि यह सिलसिला बन पाए वरना अभी तक भी हम इस फैसले को मशकूक निगाहों से ही देखते हैं । हां, तो मैं तालीम की बाबत अर्ज़ कर रहा था। बावजूद इस बात के कि स्टेट के अन्दर एक हद तक फ्री ऐजूकेशन है, इस सम्बन्ध में भी इस हरियाणा के इलाके की तरफ हमारी हकूमत और सरदार अजमेर सिंह डेढ़ आँख से ही देखते हैं (हंसी) लिट्रेसी की परसैंटेज जहाँ पर नान हरियाणा के अन्दर 26.7 है वहां हरियाणा के अन्दर वह भी सिर्फ 19.8 है । इतना ही नहीं, आप फीमेल ऐजूकेशन को भी ले लें तो आप को मालूम होगा कि इस सम्बन्ध में भी हमारे इलाके के साथ किस कदर इम्तयाज़ी सलूक किया जाता रहा है और किया जा रहा है । फीमेल ऐजूकेशन की परसैंटेज हरियाणा के अन्दर 9.1 है जब कि उधर नान हरियाणा में दुगनी के करीब यानी 17.6 है ।

इसी तरह से कोआपरेटिव क्रैडिट पर वर्कर हरियाणा के अन्दर 23 रु० और नान हरियाणा के अन्दर 62 रु. है, ओवर आल लिट्रेसी की पोज़ीशन में हरियाणा डिवैलपमैंट कमेटी की रिपोर्ट की बिना पर आप को बता रहा हूं कि हरियाणा के मुकाबले में नान-हरियाणा में 35 फी सदी ज़्यादा है । जहां तक फरटेलाईज़र्ज़ की कनज़म्पशन का ताल्लुक है वह बावजूद इस बात के कि हरियाणा का रकबा ज़्यादा है, यह नान हरियाणा में 66.2 परसैंट है और हरियाणा में सिर्फ 26.7 यानी यहभी यहां इसकी आप डिटेलज़ में अगर जाएं पंजाबी रिजन में हरियाणा के मुकाबले में अढ़ाई गुना ज्यादा है । तो आप को और भी ज्यादा हैरान होगी । कन्ज़म्शन पर थाउज़ैंड एकड़ नान-हरियाणा में 16.5 परसैंट है जब कि हरियाणा के अन्दर सिर्फ 6.8 परसैंट । आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि अकेले लुध्याना के अन्दर एक हज़ार एकड़ पर 30 टन की और जालन्धर में एक हज़ार एकड़ पर 32 टन की कनज़म्पशन है जब कि हरियाणा के इलाके में यह भी सिर्फ 10.9 टन पर थाऊज़ैंड एकड़ है ।

क्या क्या आप को बताऊं । मेरे पास इस कदर आदादोशुमार हैं कि मैं ब्यान नहीं कर सकता । इम्प्रूव्ड सीड्ज़ को ही आप ले लें । मेरे दोस्त शायद मज़ाक कर रहे हैं । मैं उन को आप की मार्फत बता देना चाहता हूं कि हरियाणा वजूद में आ चुका है और दुनिया की कोई भी ताकत अब इस के रास्ते में हायल नहीं हो सकती । तो मैडम डिप्टी स्पीकर, जहां तक इम्प्रूव्ड सीड्ज़ का

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

ताल्लुक है, इस वक्त जो पंजाब में सीड फार्मज़ हैं उन में से सिर्फ 46 ही हरियाणा के अन्दर है जब कि नान-हरियाणा में इन की तादाद 82 है यानी बेशतर हिस्सा नान-हरियाणा में है जब कि हालत यह है कि जो रकबा ज़ेरे काश्त है वह दोनों रिजन्ज में बराबर है ।

इस के अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज पर आता हूं । इस वक्त पंजाब के अन्दर 74 वेयर हाउसिज हैं लेकिन उन में से सिर्फ 20 ही हरियाणा रिजन में हैं । मैडम, यह देख कर दुख होता है कि किस तरह से यह सरकार हरियाणा को नजर अन्दाज़ करने पर तुली हुई है । क्या हरियाणा की आबोहवा वहां का पानी, वहां की ज़मीन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी मुआफिक नहीं ? क्या वहां की ज़मीन इस बात को नहीं मानती कि उसकी बुनियादों में ईंटें रख कर वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं ? अगर ऐसी हालत होते हुए हम कहते हैं कि हमें बजट का साठ फीसदी हिस्सा दो, हमारा बजट हमारे ऊपर खर्च करो तो हम किसी तरह से भी देशद्रोही नहीं हैं, ट्रेटर्ज़ नहीं हैं ।

ऐजूकेशन के सम्बन्ध में, मैं फिर इस बात का ज़िक्र करूं कि वहां पर कोई टैक्नीकल कालेज नहीं है । जो हैं पटियाला में हैं या अमृतसर और दूसरी जगहों पर हैं । हमारे बच्चों को टैक्नीकल ऐजूकेशन हासिल करने के लिए कभी पटियाला भागना पड़ता है, कभी जालन्धर और कभी अमृतसर भागना पड़ता है । उन दिनों चौधरी सूरज मल्ल वज़ीर थे । वहां पर एक मैडीकल कालेज बनाया था । बिल्डिंग भी बन गई लेकिन दवाइयों के लिए पैसा नहीं । जो आदमी वहां पर दाखिल होता है वह मरे बगैर वहां से नहीं निकलता । कहते हैं कि डाक्टर्ज़ की शारटेज है । डाक्टर मिलते नहीं हैं । अगर मैडीकल सुप्रिंटैंडैंट को लिखा जाता है तो वह जवाब देता है कि डाक्टर्ज़ है ही नहीं, मिलते ही नहीं । मैं कहता हूं कि रोहतक के लिए डाक्टर नहीं मिलते, हिसार के लिए डाक्टर नहीं मिलतें, महेन्द्रगढ़ के लिए डाक्टर नहीं मिलते, लेकिन यहां पर पी.जी.आई. के अन्दर जो सैकड़ों डाक्टर हर रोज़ टाईयां लगाए बैठे रहते हैं यह सफैद हाथी क्यों यहां पर बिठाया हुआ है । क्यों नहीं इन को देहातों में भेज देते । इतना ही नहीं यहां चंडीगढ़ की बाबत बताया गया है कि सैक्टर सात और सैक्टर बारह में रूरल डिस्पैंसरीज़ खोली हुई हैं । रूरल डिस्पैंसरीज़ के नाम पर चंडीगढ़ में तो बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन वहां पर देहाती इलाकों में जहां पर कि गरीब लोग बगैर इलाज के मर रहे हैं, भेजने के लिए आप के पास डाक्टर मौजूद नहीं हैं । कितनी अफ़सोसनाक बात है ? मैडम डिप्टी स्पीकर, क्या आप यहाँ अपनी आंखों से नहीं देखतीं कि बुल डोज़र्ज़ लगे हुए हैं, ट्रैक्टरज़ से काम हो रहा है, दरख्तों को काट काट कर यहां पर घास लगाई जा रही है ताकि वज़ीर साहिब सैर कर सकें । इतना पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन हरियाणा की जनता बेयर नैसैसिटीज़ के लिए चीखो पुकार कर रही है । इधर हमारे एम. एल. ए. होस्टल के बाहर जो जगह थी वहां पर तो आप ने आलू बो दिए हैं । वही जगह थी हमारे सैर करने की ।

उपाध्यक्षा : पंडित चिरंजी लाल, अब आप वाइंड अप कीजिए । (Please wind up now.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : बस जी, एक दो मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं । जहां तक सरविसिज़ का ताल्लुक है, इस की बाबत तो मैं बाद में बोलूंगा जब मुझे बजट पर बोलने का मौका मिलेगा और बताऊंगा कि कहीं पर पांच परसेंट है, कहीं पर दस परसेंट और कहीं पर पंद्रह परसैंट । लेकिन जो फिगर्ज़ मेरे पास हैं, उन की बिना पर मैं आप को बताउंगा कि हरियाणा ऐज़ ए होल तो सरविसिज़ में डेढ़ परसैंट भी नहीं है । इसलिए मैं कहता हूं कि चोर को क्यों मारो, चोर की मां को मारो ताकि वह चोर जनना ही छोड़ दे । मैं यह कहूंगा हरियाणा कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि सरविसिज़ के अन्दर हमारे इस इलाके की फेअर रिप्रिज़ैंटेशन न हो ।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : On a point of order, Madam. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਬੀਨਟ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ? ਇਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹੋ ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ! (*Laughter*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ ਜੀ । ਪੰਡਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ । (He should resume his seat, Pandit Chiranji Lal is requested to please wind up early.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैडम, आप का हुक्म है । इस लिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता गो मेरे दिमाग के अन्दर ख्यालात का समुन्द्र मौजज़न है । लेकिन बैठने से पहले आप का शुक्रिया अदा करते हुए इस रैज़ोल्यूशन का समर्थन करता हूं और हकूमत से इस बात की मांग करता हूं कि जब तक हरियाणा की नई डीमारकेशन नहीं होती, जब तक हमारी अलग हकूमत नहीं बन जाती, जब तक हमारी अलग लैजिस्लेचर नहीं बन जाती, जब तक हमारी अलग हाई कोर्ट नहीं बन जाती, जब तक राज्य प्रबंध हमारे हाथों में नहीं आ जाता......जिसे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती......तब तक हमारे इलाके की डिवैलपमैंट के लिए इस बजट से कम अज़ कम 60 फी सदी हमें ज़रूर दिया जाए । मैडम, डिप्टी स्पीकर, आप का शुक्रिया ।

उपाध्यक्षा : मित्तल साहिब, अगर आप आराम से बोलना चाहते हैं तो चौधरी दर्शन सिंह को वहां से हटा दीजिए। (If the hon. Member wants to speak uninterrupted then he should ask Chaudhri Darshan Singh to move away.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आप का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे अपना विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। और अभी अभी आप ने फरमाया कि अगर आराम से बोलना है तो इन को ज़रा सा एक तरफ हटा दूं। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि प्रस्ताव तो यह है कि हरियाणा और हिल्ली एरिया की डिवैलपमैंट के लिए प्रोवीज़न किया जाए लेकिन मेरे यह साथी इसमें भी अपनी कान्स्टीचुएंसी की डिवैलपमैंट का सवाल ले आए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सम्बन्ध में मुझे एक इन्सीडैंट याद आ गया है। एक दफा एक आदमी किसी दुकान से कुछ सौदा ले रहा था तो उस की दुकानदार से पैसे के लेन देन में कनट्रोवर्सी हो गई। जब वह आपस में झगड़ रहे थे तो उन के पास बैठे हुए एक तीसरे आदमी ने अच्छा मौका देख कर दुकानदार से कहा भाई इस लड़ाई में मेरे पांच रुपए के नोट को मत भूल जाना। इसी तरह से यह भाई भी पांच रुपए का नोट बीच में वसूल करने चले हैं। रैज़ोल्यूशन तो यहां पर हरियाणा और हिल्ली एरियाज़ की बैकवर्डनैस को देख कर उन की डिवेलपमेंट के लिए लाया गया है लेकिन यह इस में अपने एरिया को बीच में ला कर अपने लिए पांच रुपए की वसूली करना चाहते हैं। (हंसी) He wants to fish in troubled waters.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री प्रबोध चन्दर जी ने कहा है कि अब तो यह रेज़ोल्यूशन इनफ़क्चूअस हो गया है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंजाबी सूबा कार्व आउट करने के बारे में एक रेज़ोल्यूशन पास कर दिया है। इस बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं भी कांग्रेस मैन हूं और मुझे उस बाडी की हाइस्ट रिसपैक्ट है लेकिन इस बारे में इतना कहना जरूरी समझता हूं कि जो रेज़ोल्यूशन उन्होंने पास किया है उस की लीगल इण्ट्रप्रेटेशन मैं यह समझता हूं कि मौजूदा पंजाब स्टेट में से एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बना दी जाए और जो बाकी का बचे वह भी एक स्टेट बनी रहती है। यानी इस का मतलब यह हुआ कि मौजूदा पंजाब के दो टुकड़ बना दिए जाएं और उन में से एक पंजाबी स्पीकिंग सूबा हो। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से कलैरीफ़िकेशन आ जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से कम अज़ कम यह दो स्टेटस बन जाती हैं यानी एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट और दूसरी हिन्दी स्पीकिंग स्टेट।

अब इस रेज़ोल्यूशन के बारे में जो सदन के सामने पेश है मैं ज़्यादा फेक्टस और फिगरज़ में मैं नहीं जाऊंगा जैसा कि पंडित चिरंजी लाल जी ने यहाँ अभी पेश की हैं लेकिन उन के साथ यह कहने में मुतफ़िक हूं कि जिस महाशय ने, जिस महोदय ने यह रैज़ोल्यूशन यहां पेश किया है उस ने हरियाणा की बैक्वर्डनेस पर मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश की है और उन्होंने यह इस लिए किया है क्योंकि वह पंजाबी सूबा की मांग के खिलाफ़ हैं इस लिए उन्होंने यह फ़राख़दिली हरियाणा के लोगों के साथ दिखाई है। उन्होंने यह रैज़ोल्यूशन हरियाणा की ग़रीब जनता के साथ हमदर्दी करने के लिए बड़ी फ़राख़दिली के साथ

पेश किया है और यह उन्होंने इस लिए किया है ताकि हम अलग हरियाणा की मांग न करें इस पर भी अगर हम हरियाणे की मांग करते हैं, हम उन के सामने अपने आप को अनग्रेटफुल होते हैं क्योंकि उन्होंने तो हमारे साथ फराखदिली दिखाई है और इस के बावजूद हम उन से जुदा होने की बात कर रहे हैं। इस तरह से वह आप न कह सकेंगे। इस नुकता-निगाह से यह रैज़ोल्यूशन वह शायद ले आए हों। इस रैज़ोल्यूशन में उन्होंने हमारे इलाका की डिवैलपमेंट के लिए बजट में 60 फी सदी बजट का प्रोवीज़न करने के लिए इस में सिफारिश करने के लिए कहा है। इस बारे में मुझे अपने बचपन में जो हम एक किताब मैकमीलन रीडर के नाम की जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे उस में लिखे एक फिकरे की याद आ गई है जिस में दिया हुआ है कि एक बार एक आदमी अपना चाकू एक ग्राइण्डंग स्टोन पर ग्राईण्ड करने के लिए आया था तो उस कहानी में लड़के ने यह कहा था :

When I hear a flatterer; flatter
I know he has an axe to grind.

तो यह चीज़ देख कर हमें यही मालूम पड़ता है कि इन का रैंज़ोल्यूशन पेश करने के पीछे ज़रूर कोई न कोई मोटिव है। जहां तक पंजाबी सूबे का ताल्लुक है....

उपाध्यक्षा : मित्तल साहब, आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब जो रेज़ोल्यूशन हाउस के सामने है आप इस पर बोलें न कि उस रैज़ोल्यूशन के बारे में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया है कि उस से क्या सिद्ध होता है और क्या सिद्ध नहीं होता। (The hon. Member is a seasoned parliamentarian. He should confine his remarks to the resolution before the House instead of referring to the Resolution passed by the Congress Working Committee and stressing on what that resolution proves or does not prove.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं ने तो इस लिए, इस बारे में कहा है क्योंकि श्री प्रबोध चन्दर जी ने कहा है कि अब क्योंकि वर्किंग कमेटी ने पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने के बारे में रैज़ोल्यूशन पास कर दिया है इस लिए इस रैज़ोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। उस से मुझे यह खदशा था कि इस तरह से शायद हरियाणा वालों के साथ इनसाफ न हो। इस लिए मैं ने कहा है कि इस बारे में क्लैरीफिकेशन हो जानी चाहिए। मैं इस रैज़ोल्यूशन के बारे में फैक्टस और फिगरज़ में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो रिपोर्ट हरियाणा डिवैलपमेंट कमेटी ने दी हुई है उस में यह सारी फिगर्ज़ दी हुई हैं और मेरे से पहले जो भाई बोले हैं, उन्हों ने भी काफी फिगर्ज़ दी हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले हमें यह खदशा था कि पंजाबी सूबा रिलीजस बेसिज़ पर बनाया जाने वाला है इसी वजह से हरियाणा के लोगों ने इस को अपोज़ किया था और जो कुछ उस

[श्री राम सरन चन्द मित्तल]

वक्त हमारे इन भाइयों ने कहा था कि यह पंजाब को युनाइटिड रखना चाहते हैं तो हम ने उन को स्पोर्ट किया था। लेकिन अब यह डिमांड क्लीयर हो गई है और यह संत फतेह सिंह जी जैसे महान व्यक्ति की तरफ से आई है कि पंजाब की लिंगउस्टिक बेसिज़ पर डीवीज़न हो तो यह नेचुरल था कि हम भी इन की इस डिमांड को मान लेते और कुछ की इस डिमांड के साथ हमारी पार्टी की जो हायस्ट बाडी है यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस ने भी यह मान लिया है। हम भी इन के साथ एग्री करते हैं लेकिन एकता वालों के लिए मैं कहता हूं कि वह इसी तरह से एकता के नारे दे दे कर कहते रहे हैं जैसा कि जब हम अंग्रेजों के साथ अपने देश की लड़ाई लड़ रहे थे और जब हमारे नौजवान लोग उन के खिलाफ लड़ते थे तो कुछ अंग्रेज लोक कहा करते थे----

> Indians should be proud of being members of the British Empire, the biggest Empire in the world, the Empire on which the Sun never sets.

चाहे अंग्रेज हमारे देश को लूटते जा रहे थे और खाते जा रहे थे लेकिन इस के बावजूद कहते रहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में रह कर हिन्दुस्तान वालों को प्राऊड होना चाहिए। इसी तरह से हमारे यह एकता का सबक देने वाले भाई एक तो हमें एकसप्लायट करते रहे हैं। और साथ यह एकता का यानी युनाईटिड पंजाब बने रहने का सबक देते रहते हैं। खैर बात यह है कि अब यह सवाल तो खत्म हुआ। जब प्राउड होने का सवाल नहीं है। अब तो सीधा सा सवाल है और यह बात नहीं रही कि यह जो 60 फीसदी बजट का हिस्सा हरियाणा की डिवेलपमैंट पर खर्च करने वाली बात है यह कोई ट्रेप के तौर पर इस्तेमाल हो। अब तो वर्किंग कमेटी ने रेज़ोल्यूशन पास कर दिया है और पंजाब की डवीज़न मान ली गई है। इस लिए अब तो सवाल है कि आया 60 फीसदी हिस्सा हमारे हरियाणे पर खर्च किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हमें तो चाहिए सिर्फ अपना हिस्सा और हमें दूसरे का हिस्सा नहीं चाहिए लेकिन हम इस के साथ ही यह चाहते हैं कि जो अब तक हमें यह मिसलीड करते रहे है अब यह चीज़ खत्म हो जानी चाहिए और यह चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक की कास्ट पर दूसरा फायदा उठा ले जाए। इस बारे में मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि इस वक्त से पहले हमारा इनट्रेस्ट निगलेक्ट होता रहा है उसके लिए मैं किसी मिनिस्टर को चाहे वह पहले का हो या मौजूदा हो ज़िम्मेवार नहीं समझता क्योंकि सिस्टम ही ऐसा चला आ रहा था। दरअसल बात यह है कि जब कोई बजट बनता है तो सारा बजट मिनिस्टर तो खुद नहीं बनाता वह तो सर्विसिज़ बनाती है और सरविसिज़ के लिए जैसा कि इस रिपोर्ट के अन्दर दिखाया गया है कि उन के अंदर हरियाणे का आदमी तो कोई भूला भटका ही मिलेगा और यह तो यह खुद भी यहाँ पर एडमिट कर चुके हैं। इस लिए अगर इस रेज़ोल्यूशन को पास कर के अगर हरियाणा को 10 फीसदी बजट का ज्यादा

हिस्सा मिल भी जाए तो भी इस से कुछ बनेगा नहीं। किसी इलाका की डिवैल्पमैंट तब तक नहीं हो सकती जब तक उस के करने वालों के दिल में ऐसा करने के लिए भावना ना हो और जिन को उस के न करने से नुकसान पहुंचता हो वह उस में एसोशिएटिड हों। इस लिये मैं यह कहता हूं कि अगर तो इस रैज़ोल्यशन को देख कर के पेश करने वालों का यह मतलब हो कि इस रैज़ोल्यूशन को देख कर हरियाणे वाले खुश हो जाएंगे और वह सैप्रेट हरियाणा की डिमांड छोड़ बैठेंगे तो यह उन के मन में भूल होगी । आप ज़रा देखें कि हरियाणा डिवेल्पमैंट कमेटी की यह जो रिपोर्ट है इस के पैजिज़ न० 262 व 263 पर अगर आप देखें तो आप को पता चलेगा कि जहां डिप्टी सक्रेटरीज़ और अण्डर –सैक्रेटरीज़ व एसिस्टेंट सक्रेटरीज़ में पंजाबी रिजन वालों की गिनती 116 है तो वहां हिन्दी रिजन वालों की गिनती सिर्फ 9 है : यह है प्रोपोर्शन जो हिन्दी रिजन वालों को आज तक मिलता रहा है। इसी तरह से आप एजूकेशन डिपार्टमैंट में गज़िटिड पोस्टस की तादाद को देखें तो पता चलता है कि 305 पोस्टें पंजाबी रिजन वालों को मिली हुई हैं और सिर्फ 18 पोस्टें हिन्दी रिजन वालों के पास हैं। तो आप बताए कि इस में कोई तुलना हो सकती है। अगर यह एक्सप्लायटेशन नहीं तो और क्या है?

और भी ऐसी बातें हैं मगर मैं ज्यादा फैक्टस में इस वक्त नहीं जाना चाहता मगर इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो हमें साठ फीसदी का लोभ दिया जा रहा है क्या यह उस कमी को पूरा कर देगा : थोड़े दिन हुए अकाली पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला जिसके मुताल्लिक इन प्रस्ताव पेश करने वाले साहिबान ने कहा कि पोलीटीकल पावर के लिए ऐजीटेट कर रहे हैं। उन लोगों का यह भी कहना है कि हरियाणा की मांग के पीछे पोलीटीकल पावर को लेने की कोशिश है। मैं इन के इस सेंटीमेंट का कुछ अनेलेसिज़ करना चाहता हूं । ठीक है आप कह सकते हैं कि अगर हम अपना हिस्सा मांगते हैं तो जो कुछ भी यह है जिनके हाथ में यह है वह इसको छोड़ना नहीं चाहते, वह हमें देना नहीं चाहते । अब अगर यह पोलीटीकल पावर का सवाल है।

एक आवाज : उस में आप भी गुनाहगार हैं :

श्री राम सरन चंद मित्तल : यह ठीक कहते हैं कि उस में हम लोग गुनाहगार हैं। मैं इस बात को मान सकता हूँ। जैसे हमारे साथी ने कहा कि हिन्दी रिजन के लोग भोले भाले हैं । वाकई कुछ ऐसा है या इसे हमारी आपस की डिसयूनिटी कहिए या आपस की फूट कि हम लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुँचा है। वरना हम इन्टलैक्ट में किसी से कम नहीं हैं। आप को पता होगा कि यूनाईटिड पंजाब में जो हाई कोर्ट के पहले परमानैंट चीफ जस्टिस थे वह सर शादी लाल थे वह रिवाड़ी के थे। और भी थे । तो कहने का मतलब यह है कि इन्टलैक्ट की तो हमारे हां कमी नहीं है, मगर जिस तरह से पावर मेनटेन की जाती है वह बातें हमारे यहां नहीं थी । और नतीजा यह हुआ कि जिन के पास यह पावर थी उन लोगों ने इस को ऐक्सप्लायट किया, उन की हम पर

(श्री राम सरन चन्द मित्तल)

डौमीनेशन हो गई : मगर जैसा कि मैं ने अर्ज किया मैं अपने साथियों को दोष नहीं देता, वह तो पुराना ढर्रा ही था । बाकी बातों में उनकी हमदर्दी हमेशा हमारे साथ रही है मगर यह हमदर्दी भी वैसी ही थी जैसे कि जो भी अँग्रेज इंगलिस्तान में मिलता था तो कहता कि तुम हिन्दोस्तानियों से मुझे बहुत हमदर्दी है तुम लोगों की मांगें जायज हैं मगर जैसे ही वह स्वेज नहर को क्रास करके इधर आता था वह भी sun dried bureaucrat की तरह से ही बीहेव करने लगता था : ठीक इसी तरह की हमदर्दी यह हम से करते थे । हमारे ईलाके में गए तो कहने लगते थे कि यहां पर तो बहुत कमी है, आपको और ज्यादा मदद मिलनी चाहिए लेकिन ज्यूं ही उधर से इधर पहुँचे तो फिर वही पुरानी रट : (विघ्न) उसी तरह की बातें करते थे और उसी सिस्टम को लागू करते थे जो चला आ रहा था । महात्मा गांधी त पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत टाल स्टेचर के आदमी थे वह सारे हिन्दोस्तान को अपना ही समझते थे उनके सामने हरिजन और नान हरिजन का सवाल नहीं था । वह जहां पर कमी देखते थे, डिवेलपमेंट की या दूसरी तो उस को पूरा कर देते थे, सब की इज्जत भी करते थे । मगर सभी ऐसे नहीं हैं। अगर सभी अपना अपना फर्ज पूरा करें, सबको अपना हक मिले तो झगड़ा न हो। मगर यहां तो दिमाग में कुछ होता है, कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और ही जाता है । तब कन्फलिक्ट पैदा होते हैं।

उपाध्यक्षा : अब वाईंड अप करें । (Please wind up now.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल . मैं आप का हुकम मानते हुए आपने बहुत से प्वायँटस छोड़ता हू और एक दो बातें ही कहूंगा । आप देखें कि यहां पर झगड़ा हुआ और आप ने देखा कि किस तरह से जोड़ तोड़ कर वहां पर बातें पहुँचाई गई । इन लोगों के पास प्रेस है, पैसा है, इन्डस्ट्रिलिस्टस हैं जो वहां पर जा कर इनकी बातें कहते हैं । मगर हरियाणा वालों को पोजीशन तो आर्फन जसी है । हर लेवल पर, हर स्टेज पर आप देखें इनकी मनमानी और इन की हेराफेरी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा । अखबार, इडस्ट्रियस्टिस गर्ज कि so many persons speak against the division of Punjab .जहां भी देखो इन वोका कल ऐलीमेंट एक एटमास्टफीयर क्रियेट करता है । हमारी आवाज तो कहीं है ही नहीं । अब यह जो कुछ किया है पता नहीं इस की इन्टरप्रेटेशन क्या होगी । अगर तो हमारी मांग ऐक्सप्ट हो जाती है तो सारा झगड़ा खतम है वरना पता नहीं आगे क्या होगा । (घँटी) इस रेज़ोल्यूशन में जो वजुहात पेश की गई हैं उन्हें मैं ठीक नहीं समझता । हमें यह साठ फीसदी नहीं चाहिए, हमें तो हमारा हिस्सा पूरा मिलना चाहिए, डिवैलपमेंट में और दूसरी सारी बातों में । यह प्रस्ताव कोई प्रापर सोल्यूशन नहीं है इस लिये हम इस का विरोध करते हैं और

यह पास नहीं होना चाहिए। मुझे बातें तो बहुत सी कहनी थीं परन्तु चूंकि और समय नहीं है मैं समाप्त करता हूं। आप का धन्यवाद।

चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद) : मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा यह जो रैजोल्यूशन आया है इस में बजट का साठ फीसदी हरियाणा के लिये रिकमैंड किया गया है। (विघ्न) हां हिन्दी रिजन के लिये रिकमैंड किया गया है। हम बहुत लम्बे अर्से से मांग करते आ रहे थे कि सरकार की तरफ से हमें डेढ़ क्युसेक पानी मिलता है दूसरी तरफ 5 क्यूसेक पानी दिया जाता है, हमें भी दो क्यूसेक पानी दे दो, उन के आधे से भी कम दे दो। हमारी तरफ गुड़गांव जहां के वज़ीर रहे हैं को 16 फीसदी बिजली दी गई है, रोहतक जहां के वजीर हैं को 18 फीसदी बिजली दी गई है और मेरे जैसे जो खड़पैंच हैं उस के ज़िले हिसार के लिये सौ में से सिर्फ 14 गांव को बिजली दी गई गई है जब कि अमृतसर को सौ में से 79 को बिजली दी गई है। हमने कहा कि हमें भी 30-40 फीसदी बिजली दे दो। अब इसमें कहते हैं कि 60 फीसदी बजट देंगे। और यह जो रजोल्यूशन दिया गया है यह जनसँघी साथियों की तरफ से पेश किया गया है। जिन दिनों सूबे पर यूनिलिंग्वल वाली बात लादी जा रही थी तो यहां से मैमोरेंडम भेजे गए। इन दोस्तों की तरफ से मैमोरेंडम जाता है कि साहिब कुल्लू से लेकर गुड़गांव तक हर गांव, हर पँचायत, हर तहसील में हिन्दी और पंजाबी बोली और समझी जाती है इस लिये पँचायतों का काम पँजाबी और हिन्दी में होना चाहिए, और सैक्रेटेरियेट में भी होना चाहिए। हरियाणा में इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज उठी। जब जब इन तक हजारों और लाखों लोगों की यह आवाज़ पहुँची तो यह घबरा उठे। पिछले दिनों हम ने यूनिलिंग्वल वाली स्कीम के खिलाफ दस्तखत करवा कर भेजे जो कि 97 थे जब अब 112 हो गए हैं तो इन्होंने हमारे साथ दस्तखत किये हम इन का शुक्रिया अदा करते है। मगर अब यह हमें साठ फीसदी बजट दिलाने की बात करते हैं, सरकार इससे भी ज्यादा देने को तैयार है और कहती है कि हम हरियाणे वाले किसी भाई को तकलीफ नहीं होने देंगे, हम ने देखो हरियाणा डिवैल्पमैंट कमेटी बिठा दी है, उस को रिपोर्ट पर पूरा अमल किया जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजीट यहां पर पेश हुआ, वह भी हम ने देखा। उस में हमारा कोई ख्याल नहीं रखा गया है मगर उस को बात हम जैनरल डिसकशन में करेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह बातें आ तक उन साथियों की तरफ से आ रही हैं जिनके बारे में कहा जाए कि 'मां से हेजली, फफेकुट्टन' तो सवाल यह है कि अब इन को क्यों हम से इतना प्रेम उमड़ पड़ा है।

उपाध्यक्षा : यह हिन्दी बोल रहे हैं, चौधरी साहिब, या पँजाबी? (Is the hon Member speaking in Hindi or Punjabi ?)

चौधरी देवी लाल : चलो कुछ समझ लो (विघ्न) बाईलिंग्वल ही समझ लो। तो अर्ज़ यह है कि आज हालत बदल गई है पँजाबी सूबे की मांग इन

(चौधरी देवी लाल)

प्रिंसीपल मन्जूर हो गई है तो इस रैजोल्यूशन को वापस लेने की बात चली थी तो हमने जोर दिया कि हमें अपने ख्यालात रखने का मौका तो मिले । यह सरकार कल तक हमें धमकियां देती रही है, यह कामरेड सरकार कहती रही है कि हम ला ऐंड आर्डर मेनटेन करेंगे जोकि इनडयारैक्ट तौर पर धमकियां ही थी और इस सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की यह पंजाबी सूबा और हरियाणा प्रान्त नहीं बनने देगी । आज वकिंग कमेटी जो इस सरकार और सैंटर की सरकार को चलाती है, ने पंजाबी सूबे की मांग को इन प्रिन्सिपल मान लिया है। यह सरकार इस को कभी इम्पलीमेंट नहीं होने देगी । मैं यह मांग करता हू कि जो सरकार पंजाबी सूबा और हरियाणा प्रांत के खिलाफ है उसको मुस्तफी हो जाना चाहिए ताकि इस बात पर सही मानों में अमल हो सके । (प्रशंसा) मैं इन की जहनीयत की बात करता हू कि इनकी टैन्डेन्हसी को बदला नहीं जा सकता । और हम से जो सलूक होना चाहिए नहीं किया जा रहा । यह इस सूबे के बारे में स्कीम पर सही ढंग से अमल नहीं कर सकती। जब यह सावाल पीक पर पहुँचा तो जलसे हुए, लाखों आदमियों तक आवाज पहुची और उन की तरफ से आवाज उठाई गई और सरपंचों ने कनवेन्शनें कीं : दो दो हजार और तीन तीन हजार लोगों ने इस सवाल को कनवैन्शनों में उठाया और यहां तक कि 36 लैजिस्लेटर्ज़ ने अपना इसतीफा तक देना मन्जूर किया । इस के बावजूद भी हरियाणा के लोगों के साथ इस सरकार की तरफ से किस तरह का सलूक किया जा रहा है । पिछले दिनों कौंसल में 5 मैम्बरों की नामीनेशन करनी थी । उन में सिर्फ एक हरियाणा का लिया गया श्री बंसी लाल । हमारा सिर्फ एक ही लिया गया और बाकी और 2 थे । श्री प्रताप नारायण गुजराल, श्री दुर्गा दास खन्ना श्री जसवंत राए यह सारे के सारे पंजाबी रिजन के हैं। वोट हिन्दु का और 17 हिन्दु मैम्बर उन के हों और हमारी तरफ से ६४ हों यानी इलैक्ट होना हो हमारी वोटों से मगर आदमी पंजाबी रिजन के लिए जाएँ : यह कहां तक जायज़ है । और फिर जब कि सवाल यहां तक पहुंच जाए कि हम किसी भी सूरत में पंजाबी रिजन में शामिल नहीं होना चाहते । इतना कुछ होने के बावजूद और इतना करने के बावजूद इन की जहनियत नहीं बदली : टिकट मिलता है पंजाबी रिजन वालों को और वोट हम देते हैं :

12.30 p.m.

इसी तरह, डिप्टी स्पीकर साहिबा, राज्य सभा में हमारी तरफ से ११ सदस्यों में से १ है श्री नेकी राम । वह भी उन पर मेहरबानी नहीं की ऊपर से जोर था श्री मुरारजी देसाई का और ख्याल था कि शायद राजनीति किसी वक्त पलटा खा जाए । इस लिये श्री नेकी राम को लिया गया । और आज इस रैजोलयूशन के ज़रिया से हमें यह लालच दे रहे हैं। 'प्रताप' और 'प्रदीप' की तरफ से लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हरियाणा वालों को कोई एक टुकड़ा फैंको और एक २ टुकड़े पर बीस-बीस आ कर इकट्ठे हो जायेंगे : दौड़े

आएंगे । लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि हम किसी के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं। हम भिखारी नहीं हैं, हम अपना हक्क मांगते हैं, खरात नहीं मांगते और अपना हक्क हर कीमत पर ले कर रहेंगे । (प्रशंसा) यह कहां का असूल है कि हम राज की रक्षा करें और राज की गद्दियों को तुम संभालो । डोंगराई, खेमकर्न और बर्की पर हमारे जवान जा कर रक्षा करें और राज की गद्दी पर तुम बैठो । सिक्खों की बात तो और है क्योंकि उन के मुंह पर दाहड़ी है और वह अपनी अलग स्टेट चाहते हैं लेकिन हम तो पोलीटीकल पावर चाहते हैं। हम सीधे पोलीटीकल पावर की मांग करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पोलीटीलक पावर के बिना डिवलपमेंट नहीं हो सकती । आज डिवलपमेंट की क्या हालत है और हरियाणा के लोगों का सरकार की सर्विसों म क्या हाल है। इस के बारे में श्री मित्तहल ने और श्री चिरंजीलाल ने बताया है कि सर्विसों में १४ में से कोई भी सक्रटरी हरियाणा का नहीं और पंजाबी रिजन के लोग और लुगाई दोनों मौजूद हैं । फिर बजट हर साल पास होता है तो इस में आप देख ल कि जितनी स्कीम हरियाणा के लिये तयार की जाती हैं वह आज तक अधूरी कीअधूरी पड़ी हैं और जो रकम इन स्कीमों के लिये रखी जाती है वह इन पर खर्च न कर के और कहीं पर खर्च करदी जाती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस रैजोल्यूशन को पेश करने वालों का मशकूर हूँ कि उन्ह इस बात का ख्याल आया कि हरियाणा को कुछ देना चाहिए । लेकिन इन टुकड़ों पर हम पलने वाले नहीं । यह ठीक है कि पंजाबी सूबा की प्रपोज़ल को एक प्रिन्सिपल के तौर पर मान लिया गया है लेकिन खतरा अब भी है और मैं समझता हूँ कि हमारे सिर पर अब भी तलवार लटक रही है । हरियाणा को बाइफरकेट किया जा सकता है या हिमाचल को साथ मिला कर यूनीलिंगवल पंजाब बनाया जा सकता है लेकिन इन को यह पता होना चाहिए कि हम ने अहद किया हुआ है कि हम मिनिस्टरी की गद्दियों के लालच में आने वाले नहीं । हम ३६ लेजिसलेटज अस्तीफा देने को तयार हैं। हमारे इलाके के वज़ीर भी अस्तीफा दे कर सामने आने को तैयार हैं। अगर हमारा इलाका काट कर या किसी और तरह से यूनीलिंगवल पंजाब बनाया गया तो हम भेड़ बकरियां नहीं हैं जो चुप बठे रहें रहेंगे । अगर हम देश की रक्षा कर सकते हैं तो हम अपने हक्क की रक्षा भी कर सकते हैं। आप यहां पर किसी मिनिस्टर को, किसी एम० एल० ए० को अपना हक्क मांगने से नहीं रोक सकते । हम आप कैसे रोक सकते हैं और हम अपने हक्क के लिय लड़ाई लड़ेंगे । वक्त आएगा तो इन लोगों का इम्तिहान होगा जो इस रज़ोल्यूशन के मूवर हैं और जो यह सरकार हरियाणा डिवलपमेंट कमेटी बना वाली है कि वह किस तरह से सलूक करते हैं । क्या वह हरियाणा की कास्ट पर पंजाबी सूबा के हक्क में होंगे या हरियाणा की सही तौर पर डिवलपमेंट चाहते होंगे । मैं हरियाणवी होने के नाते इस रज़ोल्यूशन की मुखालफत करता हूँ ।

(चौधरी देवी लाल)

यह एक ढंग था कि चलते हालात में हमारे इलाके की हमदर्दी लेने के लिये इस तरह का रैज़ोल्यूशन मूव किया जाए। हम चाहते हैं कि हमें हरियाणा अलैहदा दिया जाए और पूरा स्टेटस दिया जाए:

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक (सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस रैज़ोल्यूशन के बारे में बोलने के हक्क में नहीं था लेकिन कुछ इस तरह की बातें कही गई कि जिन की वजह से कुछ कहना पड़ा। यह कहा गया है कि कांग्रेस हाई कमान्ड की वर्किंग कमेटी ने पंजाबी सूबा के बारे में जो रैज़ोल्यूशन पास किया है, इन व्यू आफ दैट, मैं समझता हूं कि यह रैज़ोल्यूशन रिडन्डैन्ट और बेमायने हो जाता है। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस को कन्डेम भी किया जा रहा है। इस की आड़ में नाम ले ले कर एक पार्टी को कोसा भी जा रहा है जिस को देख कर अफसोस होता है। यह यबात मानी हुई है और देयर इज़ नो डिनायल आफ दी फैक्ट कि हरियाणा का इलाका आज तक इगनोर होता चला आ रहा है। इसकी डिवैल्पमेंट न कर के इस के हकूक पर छापा मारा गया है। और हरियाणा को पंजाबी रिजन की एक कालोनी के तौर पर ट्रीट किया जाता रहा है। लेकिन यह बात देखने वाली है कि इस तरह किन लोगों की वजह से होता रहा है। इस १८ साल के अरसा में जब से इन्डीपैन्डैंस मिली है शासन कांग्रेस के हाथों में रहा है और कांग्रेस की हकूमत के अंदर जो लोग बैठे ह और रहे हैं वह, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक साईलैन्ट स्पैक्टेटर के तौर पर सेदेखते रहे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा है कि हम किसी के टुकड़ों पर बिकने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जो लोग कांग्रेस के अन्दर रहे और रहते हैं खाह उस वक्त चीफ मिनिस्टर सरदार प्रतापसिंह कैरों हो या श्री राम किशन हों, उन्होंने हरियाणा को पंजाबी रिजन के हाथों रहन रखा और फरोखत करने की कोशिश की। एक चौधरी छोटू राम थे जिन्होंने हरियाणा के अन्दर जागृति लाई और किसी ने नहीं। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने हरियाणा की लीडरशिप को खत्म कर दिया और आज वह आदमी जो उस पार्टी में रहे और आज सर उठा कर फिरते हैं लेकिन पार्टी में नहीं रहे, उस वक्त सरदार प्रताप सिंह के टुकड़ों पर पलते रहे। उन्हीं लोगों ने हरियाणा को खत्म किया और आज हरियाणा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हू कि हरियाणा के लोगों में आज एक चीज़ आई है कि वह एक जगह इकट्ठे हैं और इकट्ठे हो गए हैं। कभी वक्त अच्छा आता कभी बुरा आता है। हरियाणा की लीडरशिप जाती रही और उस लीडरशिप का भट्ठा बैठ गया और एक बुरी रवायत चल पड़ी कि नखट्टू से नखट्टू को अच्छा समझा जाने लगा। हरियाणा के लोगों ने यह समझना शुरु कर दिया कि जो वज़ारत में आए वही हरियाणा का लीडर समझा जाए। और जो असली लीडर था उसके पीछे लोग न लगें और ऐसे लोगों को अपना लीडर मान बैठे जो किसी गद्दी के ऊपर बैठ गया, जो सरदार प्रताप

सिंह के टो को चाट कर वजारत में आ गया उस नाम निहाद को अपना लीडर समझ बैठे ।

उन्होंने सारे हरियाणे को बिल्कुल एक तरह से खत्म ही करके रख दिया ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, अभी मिनिस्टर कनसरन्ड ने भी जवाब देना आप इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें । (Addressing Ch. Mukhtiar Singh. The Minister has also to give a reply to the debate, The hon Member should, therefore, wind up.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਤੌਰ ਮੂਵਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : आपने मुझे पहले कहना था । (He should have said so earlier,)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿਘ: ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਦਾ !

चौधरी मुख्त्यार सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अकाली पार्टी की तरफ से पंजाबी सूबा की मांग की गई । जब यह सवाल हाई कमां के सामने आया तो उन्होंने जबान के आधार पर मांगी गई एक चीज़ को जिस आधार पर वह पहले मानते आये हैं इस बात को मान लिया मगर जन संघ वाले स्टेटस को चाहते थे । उन्होंने पंजाब की यूनीलिंगुअल नहीं माना । मगर इस बात के कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि हरियाणा के मुताल्लिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पता नहीं क्या करना या नहीं करना मगर २०० के करीब ऐसे लोग हैं जो लीडरों के पास दिल्ली में भागे फिर रहे हैं कि हमारे साथ कम्परोमाइज़ करो । पता नहीं इसके पीछे क्या है। There is a mischievous move at the Centre, इस के मुताल्लिक जनसंघ की जोयसटैंड है वह साफ है । उन्होंने कभी भी यूनीलिंगुअल सूबा बनाने के लिये सिफारिश नहीं की । वह आज तक स्टेटस-को चाहते रहे हैं। यहां पर कुछ साहिबान बोले हैं। किसी ने कहा कि इसको यूनीलिंगुअल बना दिया जाये कोई कहता है कि इसके टुकड़े कर दिये जायें, कुछ बातें यहां पर चौधरी देवी लाल ने कहीं और कुछ पंडित चिरंजीलाल ने कहीं । यह बातें तो मैं साफ कह दूं कि हरियाणा के लोग अज किसी के हाथों बिकने वाले नहीं हैं । उन में गुड सैंस प्रीवेल हुई है और आज हरियणा के लोग चाहे आप उनके किसी पार्टी के नुक्ता निगाह से लें, वह हरियाणा के हकूक के लिये इकट्ठे हुये हैं। मैं आप से अर्ज करूंगा की इस असैम्बली के अन्दर भी अगर हरियाणा के टुकड़े किये जाने के मुताबिक या इसको यूनीलिंगुअल बनाने की किसी तरह की भी कोई मूव चलाई गई या और किसी तरह की कम्प्रोमाइज़ की मूव को बढ़ावा देने की कोशिश की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । अब और तकलीफ गवारा नहीं की जा सकती । अगर हिन्दुस्तान की पारटीशन होती है तो उसमें हम

(चौधरी मुखत्यार सिंह मलिक)

पिसते हैं। पाकिस्तान बनाया गया तो हमारी नाक के ऊपर बनाया गया ताकि जब भी इसे मौका मिले यह दनदनाता हुआ हमारे ऊपर आ चढ़े। अब हरियाणा को यूनिलिंगुअल बनाने या इसे किसी अजीब ढंग से बाईफरकेट करने की चाल खेली जा रही है ताकि इस घुन को बिलकुल ही पीस कर करख दिया जाए। मगर अब हम ने खूब अच्छी तरह से देख लिया है कि चाहे प्रताप सिंह करों की वज़ारत हो या राम किशन की वजारत हो इनसे हमारा भला नहीं होगा। यह हम टुकड़े दिखा कर अपनी हकूमत कायम रखना चाहते हैं। उधर से कहा गया कि डिवलपमट कमिशन की रिपोर्ट आ गई है, हम बकवर्ड एरियाज़ की हैल्प करना चाहते हैं, मगर इसके हाथ ही बजट बनता है जिसन हमारे इलाके को बिलकुल ही इगनोर किया जाता है। हमारे लिये तो जैसे प्रतापसिंह थे वसे ही यह राम किशन हैं। यह को अच्छी ही बात नहीं है कि अगर किसी पर ज़यादती होती रही है तो इसके साथ ज्यादतियां ही होती रहें। हमारे साथ अगर ना-इनसाफी हुई तो हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर कोई मिसचीवियस मूव कम्परोमाईज़ के नाम पर चलाने की कोशिश की गई तो हम मानने वाले नहीं हैं। (घंटी)

यह पाबन्दी आप हम पर ही लगाती हैं। आखिर हमें अपनी बात करने का भी हक नहीं है क्या ? लीजिये मैं बैठ जाता हूँ।

चौधरी देवी लाल : **On a point of personal explanation, Madam,** मैं सिर्फ यह कह कर अपनी पोजीशन क्लीयर करनी चाहता हूँ कि चौधरी मुखतियार सिंह ने सरदार प्रताप सिंह का नाम लेते हुए हमें इंडीकेट करके कहा और मेरा नाम लिया कि हम उनके पिट्ठू रहे हैं। मगर मैं यह अर्ज़ कर दूं कि मैं कभी कैरों का पिट्ठू नहीं रहा और इसका सबूत यह है कि १९६२ में ४ टिकटें राज्य सभा की थीं और इतनी ही विधान सभा की थीं मगर मैं यह बात कह सकता हूँ कि मैंने, बन्सीलाल और नेकी राम ने जो टिकट लिये अपनी ताकत से लिये इसलिये वह मेरा नाम हर्गिज़ ऐसे न लें।

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾੱਲਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਤੇ ੪ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਨਡੀਵੈਲਪਡ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਵਰ ਨੇ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਇਹ

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਰਜ਼ੋਲਿਓਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 24.29 ਲਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11.96% ਯਾਨੀ 12% ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 75.27 ਲਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 37.06% ਯਾਨੀ 37% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 103.51 ਲਖ ਹੈ ਜੋ 50.98% ਜਾਂ 51% ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 12% ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 37% ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਸਕੀਮਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਫਾਈਵ-ਯੀਅਰ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ 22.85 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਿੱਲੀ ਰਿਜਨ ਦੀ 12% ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ 37% ਜਾਂ 38% ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਿਜਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1% ਜਾਂ 2% ਵਧ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ-ਯੀਅਰ ਪਲੈਨ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪਲੈਨਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 24% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 60% ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। I think every body would mark it. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਲੀ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ 60% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 24% ਤਾਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ 36% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਰਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 37% ਜਾਂ 38% ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 61% ਜਾਂ 62% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਂਡਜ਼ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ 60% ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ 24% ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ. ਤਾਂ 16% ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ 60% ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਦਰ-ਅਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਘਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। (ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ 60% ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਅਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਜਟ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ

[ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ]

ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ । ਕੀ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ? ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ । ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਇਕਠੇ ਹੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਰੀਵੈਂਸ ਹੈ । ਹਰਿਆਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ-ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠੀ ਉਹ ਉਠਾਈ ਗਈ । ਮੈਂ ਯੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ । ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ । ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤਕ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਥੈਂਕ ਯੂ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰੀਪਲਾਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਵਰ ਨੇ । ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਰੂਲਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਸੀਟ । (The Rules do not permit, please take your seat.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ..........

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਉ । (Please take your seat.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ।

Deputy Speaker : Mr. Kulbir Singh, I am on my legs. मैं आप को यह कह देना चाहती हूं कि देअर इज़ नो टाईम । तीन दिन यह बहस हुई । उस के बाद मिनिस्टर को आउट आफ कर्टसी टाईम मिलना चाहिए । एक बात ऐसी आ गई, मैंने चौधरी मुख्तियार सिंह को कह

दिया कि वह बोल लें । Now I am to put it to vote. (Mr. Kulbir Singh, I am on my legs. I would like to tell the hon. Member that there is no time. This discussion has lasted for three days. Out of courtesy the Minister should get some time to give reply to the debate. During the discussion such a point was raised for which I allowed some time to Chaudhri Mukhtiar Singh Malik. Now, I am to put it to vote.)

(Sardar Kulbir Singh rose to speak)

Deputy Speaker : I have given my ruling that you have no right of reply.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam, right of reply ਦੇ ਬਾਰੇ Rules of Procedure ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੋ ਹੈ:—

(2) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion was moved by a private member, the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak after the move has replied"

Deputy Speaker : No, please. The hon. Member should please resume his seat.

Chaudhri Mukhtiar Singh : Madam, it is very unfortunate. If an hon. Member wants to make a submission, you should hear it patiently.

Deputy Speaker : Question is—

With a view to bring the hilly areas of the Punjab, which are backward, at par with the adjoining areas of the State and the Hariana area at par with the rest of the State in the matter of development, this House recommends to the Government to make plan allocations in such a way that sixty per cent of the plan funds are earmarked for the said Hariana area and the hilly areas."

The was motion lost.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਉਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ ।

Deputy Speaker : Will you please take your eat.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਲਉ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ।

Deputy Speaker : Sardar Kulbir Singh, will you please withdraw from the House

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ।

Deputy Speaker : Then I will see to it.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਭੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

Deputy Speaker : I have ordered you to withdraw from the House.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

(ਮਲਿਕ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ)

उपाध्यक्षा : मलिक इन्दर सिंह, आप बैठ जाएं । (The hon. Member, Mr Malik may please take his seat.)

मलिक इन्दर सिंह : (* * * *) उन को पहले बोलने दें ।

Deputy Speaker: Please mind your business.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Deputy Speaker: Sardar Kulbir Singh, I have asked you to withdraw from the House.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

Deputy Speaker : I have asked the hon. Member to withdraw from the House but he is not obeying me.

(*At this stage Sardar Kulbir Singh resumed his seat*).

Deputy Speaker : Sardar Ajmer Singh.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : On a point of Order, Madam ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ resolution ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ (The hon. Member's resolution is not there on the agenda for today.)

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ: ਹੈਗਾ ਏ ਜੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਹੈ ।

*Expunged as ordered by the Chair.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਟਰੋਡਿਉਸ ਕਰ ਲਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ । (The hon. Member may please take his seat).

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਿਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਉ ।

Deputy Speaker : I have got the time with me. Please do not try to guide me.

ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਨਾਵਾਲੀਆ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । (I asked Sardar Kulbir Singh to withdraw from the House).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5/7 ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਊਸ ਦੇ । (The hon. Minister was not here when the hon. Member wasted 5/7 minutes of the House).

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक : इस का यह मतलब तो नहीं कि आप हमारे राईटस पर छापा मारें ।

Transport and Elections Minister : It is unfortunate that the hon. Member defied your order. But after you had named him he resumed his seat. I would request that rather than precipitating the matter, you kindly withdraw your order.

Deputy Speaker : Since the hon. Member has resumed his seat, I do not press the enforcement of my order. But I would request him to be careful in future.

THE PUNJAB LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 1966

Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh) : Madam, I beg to move—

> That the Punjab Land Revenue (Amendment Bill, be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ । ਇਕ ਡੀਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ

[ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ]

ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ । (The hon. Member is right, but the House has to proceed with the business.)

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ । (I say that what the hon. Minister says is proper but his own party Members do not agree to this. The hon Minister should control them.)

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰੀਲੀਫ ਵਜੋਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਐਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Deputy Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Land Revenue (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Land Revenue (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker ; Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh) : Madam, I beg to move—

That the Punjab Land Revenue (Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Land Revenue (Amendment) Bill be passed.

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो मज़दूर वार हिट हुए और जिन्हें जो रुपया उधार दिया है उसे बतौर एरियर्ज़ आफ लैंड रैवनियू वसूल करने के लिए यह बिल लाया गया है। पहली बात तो मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बिल गैर जरूरी है क्योंकि सरकार को याद होगा कि चार पांच साल पहले जब अमृतसर में बिजली की कमी वाकया हुई थी उस वक्त भी मजदूरों को लोन्ज दिए गए थे लेकिन उस वक्त सरकार ने वसूली के लिए कोई एसा बिल पेश नहीं किया था। वह लोन्ज़ दिए गए और उन की रिकवरी भी हुई और उस में कोई मुश्किल नहीं आई। अब पता नहीं यह चीज क्यों लाई जा रही है। मैं ने यह बात पहले भी अर्ज़ की थी कि यह जो लोन दिए जा रहे हैं यह एक बड़ा भारी मज़ाक है जो

[श्री सागर राम गुप्ता]

उन से किया गया है और किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस में लोन का सवाल नहीं था यह तो उन्हें सबसिडी दी जानी चाहिए थी। अगर दिया भी गया है तो फिर उन से यह दूसरा मजाक किया जा रहा है। अब तहसीलदार वसूली के लिए आए दिन रुक्के भेजा करेंगे और इन्हें हवालात में बन्द करेंगे। यह लोन क्या हुआ जहमत हो गई उनके लिए। यह बिल मजदूरों के हित के खिलाफ लाया गया है। मैं अर्ज करता हूं कि मजदूरों के हित को सामने रखते हुए और इस बात का एहसास करते हुए कि उनकी नुमायां मदद भी नहीं की गई है वह इस बिल को वापस ले लें।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਵੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੇਹਰਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜ-ਛੇ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਐਜ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਉ ਦੇ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝਟਾ ਫਟ ਰਕਮ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 8/9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

पंडित बाबू दयाल शर्मा (पटौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मजदूरों के साथ बड़ी भारी हमदरदी है और मैं चाहता हूं कि मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा हिफाजत की जाए और रियायतें दी जाएं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि यह सामने बैठे भाई चाहते हैं कि लाकानूनी फैले और कोई किसी से चीज ले कर वापस न करे। अगर इस तरह लाकानूनी फैलेगी कि जो आदमी करजा ले उसे कहा जाए कि डिफालटर बन जा और वापस मत कर तो फिर यह कैसे सारा काम चलेगा (शोर) आप देखेंगे रिकशा वाले कायदे कानून से नहीं चलते, तांगे वाले नहीं चलते और सरकारी अफसर कायदे कानून से नहीं चलते। अब मजदूरों को यह सबक देना कि उन से लोन लेकर वापस न लिया जाए मैं समझता

हूं लाकानूनी फलाने वाली बात है । मैं उमीद करता हूं कि आयंदा ऐसी बात नहीं कही जाएगी । आज दिन बदिन देश में कानून और अखलाक का दीवाला निकलता जा रहा है । मुझे अफसोस हो रहा था कि आप ने एक मैम्बर साहिब को हुकम दिया लेकिन उन्होंने उसे नहीं माना और आपके बार बार कहने पर भी उन्होंने........

बाबू बचन सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं आप का रूलिंग चाहता हूं कि जो मैम्बर इरैलेवैंट बोलता जाए उसे किस तरह रोका जाए । (हंसी)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਛੇ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਸ.... (ਹਾਸਾ) (The hon. Member did not check his neighbour whom I tried in vain to stop from interrupting the proceedings).

पंडित बाबू दयाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं । अगर वह मेरी बातों को ध्यान से सुनते तो इन्हें इररैलेवैंट कहने का मौका न मिलता । मैं समझता हूं कि इन्हें खुद पता नहीं कि रेलेवेंट और इररैलेवैंट क्या होता है । ...... (विघन) (शोर)

(इस समय चौधरी नेत राम अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने के लिए खड़े हुए । हाउस में कुछ भी सुनाई नहीं देता था)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह बिल जल्दी ही पास हो जाना चाहिए ।

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । क्या ट्रेज़री बैंचों पर बैठा हुआ मम्बर अपनी सरकार की निन्दा कर सकता है । वह उस सरकार की निन्दा कर रहा है जो कि अपने आप को त्याग करने वाली, तपस्वी कहलवाती है । मैं समझता हूं कि यह सरकार अपने 19 साल के शासन के अन्दर भुखमरी, बेरोज़गारी को रोकने में असमर्थ रही है और यह महज आबादी को रोकने का नारा लगाने वाली ही है । इस सरकार ने जनता का हर तरह से दिवालिया निकाल दिया है । क्या उसी पार्टी का मैम्बर खुद सरकार की निन्दा कर सकता है ।

(विघन) (शोर)

उपाध्यक्षा : इस का मतलब यह है कि आप को आगे के लिए प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने की इजाज़त न दी जाए । यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । (That means that the hon. Member should not be allowed to rise on a point of order. This is no point of order).

Deputy Speaker: Planning and Local Government Minister.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : I have already called upon the hon. Minister for Planning and Local Government. He should resume his seat.

(*Interruptions*)

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅਗਰ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜਨ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਾਅਵੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ । ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਭੀ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਨਾਨ-ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Land Revenue (Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB URBAN RENT RESTRICTION (AMENDMENT) BILL, 1966

Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh) : Madam, I beg to move—

That the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be taken into consideration.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be taken into consideration.

Deputy Speaker : Question is—

That the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be taken into consideration.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Deputy Speaker : Question is—

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh) : Madam, I beg to move—

That the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be passed.

The motion was carried.

THE PROVINCIAL SMALL CAUSE COURTS (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1966

Minister for Welfare and Justice (Shri Chand Ram) : Madam, I beg to move—

That the Provincial Small Cause Courts (Punjab Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be taken into consideration.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Provincial Small Cause Courts (Punjab Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be taken into consideration.

Deputy Speaker : Question is—

That the Provincial Small Cause Courts (Punjab Amendment) Bill as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be taken into consideration.

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House will now consider the Bill Clause by Clause. If it is the sense of the House, I will put the clauses and the Title together to the vote of the House.

Voices : Yes. Yes.

CLAUSES 2, 1 AND TITLE

Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2, 1 and Title, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Welfare and Justice (Shri Chand Ram) : Madam, I beg to move—

That the Provincial Small Cause Courts (Punjab Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be passed.

Deputy Speaker : Motion moved—

T the Provincial Small Cause Courts (Punjab Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be passed.

Deputy Speaker : Question is—

That the Provincial Small Cause Courts (Punjab Amendment) Bill, as passed by the Punjab Vidhan Parishad, be passed.

The motion was carried.

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी तक हाउस को एडजर्न करने में आधा घंटा बाकी है। अगर सरदार सम्पूर्ण सिंह धौला अपना रैजोल्यूशन मूव करना चाहें तो वह मूव कर लें ।

बाबू बचन सिंह : अगर ऐसा कहा जाए तो माननीय सदस्य के साथ बहुत ज्यादती होगी ।

उपाध्यक्षा : सदन कल साढ़े नौ बजे मिलेगा । (The House will meet tomorrow at 9-30 a.m.)

1.30 p.m.

The House then adjourned till 9-30 a.m. on Friday, the 11th March, 1966.

1700 P.V.S.—386—13-10-66—C., P., & S., Pb., Patiala.

APPENDIX

TO

Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I, No. 16

Dated the 10th March, 1966

MISUSE OF LOANS ADVANCED UNDER THE L. I. G. H. SCHEME

3347. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of cases in the State district-wise and Police Station-wise registered at different Police Stations regarding the misuse/misutilization of the loans advanced under the L.I.G.H. Scheme, stating the names of those against whom these were registered, the dates when, at whose instance, the amount for which and the places where these were registered and the provisions of law under which these were registered;

(b) the names of persons who signed/verified/attested the said loan application forms and also the names of persons who attested/verified the facts of completing the plinth level stage, the roof level stage and complete construction of the house concerned, together with the provisions of law under which the persons verifying the said facts have been charged, if cases have been registered against them along with the loanees/applicants referred to in part (a) above ;

(c) the names of the persons arrested out of those referred to in parts (a) and or (b) above together with the dates when and the provisions of law under which they were arrested and the name of the Police Station when they were arrested ;

(d) the names of the Legislators, Municipal Commissioners, Panches, Sarpanches out of those referred to in part (c) above together with the names of those who have been cited as prosecution witnesses and not prosecuted ;

(e) the details of the cases, the challans in respect for which have been put up in the Courts and also the details of the cases which have been withdrawn stating the result in each case?

The answer to Assembly Question No. 3347 appearing in the list of Unstarred Questions on the 10th March, 1966 in the name of Comrade Ram Piara, M. L. A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/—
Minister for Capital and
Housing, Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 1727—2Hg—66, dated Chandigarh, the 9th March, 1966.

CASE REGISTERED IN POLICE STATION SADDAR KARNAL UNDER F. I. R. No. 302, DATED 14TH OCTOBER, 1964

3348. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that a case was registered at P. S. Saddar Karnal against one Amar Singh, son of Shri Buta Singh, Goldsmith of Police Station Pehowa, district Karnal, u/s 420/467/468, I.P.C., on 14th October, 1964, under F.I.R. 302, dated 14th October, 1964 on the basis of a memo sent by the Deputy Commissioner, Karnal; if so, a copy of the F.I.R. be laid on the Table of the House together with the names and designations of the Police officials who investigated the case, the dates of starting and completion of investigation ;

(b) whether any arrests in connection with the said case had been made; if so, the names of those who were arrested, the dates when they were arrested and the date when they were bailed out ;

(c) the provisions of law under which the said persons were arrested and by whom they were arrested ;

(d) the names of those which signed the application form and verified the plinth level stage, roof level stage and completion stage of the house together with the name of the officer, if any, who looked at any stage into the proper/improper utilization of the loan ;

(e) whether it is a fact that the challans of the case registered on 14t October, 1964, were not put up in the Court; if so, the reasons therefor ;

(f) whether any correspondence between any arrested persons connected with the case referred to in part (a) above and the Superintendent of Police, Karnal, with copies to the Home Minister, Punjab, has taken place; if so, a copy of the same be laid on the Table of the House stating whether at the time of arrest any section was changed and if that was done the reasons therefor ;

(g) whether he had also replied to any of the said communications of the accused arrested in the said case; if so, a copy of the same be laid on the Table of the House ?

The answer to Assembly Question No. 3348 appearing in the list of Unstarred Questions on the 10th March, 1966, in the name of Comrade Ram Piara, M.L.A. is not ready.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/—
Home and Development Minister,
Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 293/CR (6), dated Chandigarh, the 9th March, 1966.

Punjab Vidhan Sabha Debates

11th March, 1966

Vol. I, No. 17

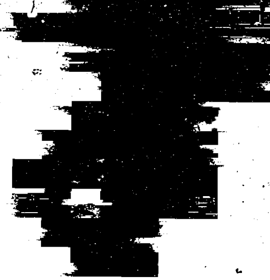
OFFICIAL REPORT



CONTENTS

Friday, the 11th March, 1966

Price: Rs. 5.15 Paise.



ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 17,
DATED THE 11TH MARCH, 1966

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਏਟ	ਟ	(17)1	21
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ	ਮੈਜਿਸਟੇਟ	(17)2	2
matter	matte	(17)2	last
ਉਥੋਂ	ਉਤੋਂ	(17)3	9
resulted	resuted	(17)7	31
loans	loand	(17)7	32
ਵਿਚ	ਵਿਰ	(17)13	18
क़ाइम	क़ाई	(17)13	20
श्री ओम प्रकाश अग्नि होत्री	श्री ओप प्रकाश अग्निहोत्री	(17)14	16
हैमे	हमे	(17)16	20
लिया गया रुपया	लिया गया	(17)23	26
applications	applicaions	(17)24	5
informs	infoms	(17)24	31
programme	programee	(17)24	32
Lehragaga	Lehregage	(17)28	11
Khurd	Kuhrd	(17)29	5
•Panchayat	Panchay	(17)36	10
personnel	personel	(17)41	1
Sarpanch	Sarpnach	(17)42	8 from below
bags	bagss	(17)42	Last but one
Samiti	Samititi	(17)45	8-9 from below

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Government	Governkment	(17)49	22
none	non	(17)49	34
entire satisfaction	entires atisfaction	(17)49	36-37
opposite	opposit	(17)49	41
redressing	re-addressing	(17)49	14 from below
Inspector	Inspecto	(17)49	12 from below
report	eport	(17)49	12 from below
entrusting	enteresting	(17)49	11 from below
society	soeciety	(17)49	5 from blow
have	has	(17)50	16
sympathetic	sympathatic	(17)50	21
Adjournment	Ajournment	(17)50	29
Delete the word 'of'	after the word 'today'	(17)51	3
ਮੌਸਟ	ਪੌਸਟ	(17)55	3, 4
जा	था	(17)64	21
प्लान्ज	ज्वानज	(17)65	12
ਇੰਟੈਂਸਿਵ	ਇੰਟੈਂਵਿਸ	(17)66	14 from below
ਜਿਹੜਾ	ਜਿਫੜਾ	(17)69	15 from below
ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ	ਕਰਿਟੀਸਿਮ	(17)71	4
ਅੰਡਰ	ਅੰਦਰ	(17)71	Last
Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal	Comrade Gurbaksh Singh. Dhaliwal	(17)73	24
ਆਈਆਂ	ਆਂਦੀਆਂ	(17)78	18
House	Houle	(17)78	Last but one
उपाध्यक्षा	उपाध्क्षा	(17)79	3
	उाध्क्षा	(17)82	18
spoken	spokan	(17)79	5
off	off of	(17)79	14
recipients	receipients	(17)79	17

Read	For	Page	Line
ਤਕਾਈ	ਤਕਾਈ	(17)79	5 from below
ਏਜੰਟ	ਏਡਜਸਮੈਂ	(19)82	19
ਇਨਡਸਟ੍ਰੀ	ਇੰਡਸਟੀ	(17)82	27
ਮੁੜੇ	ਮੁਤ	(17)83	21
The hon.	The hon?	(17)84	8 from below
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ	ਲਿਡਰਸ਼ਿਹ	(17)85	2-3 from below
ਕੀਤਾ	ਕਤਿਾ	(17)87	13
ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ	ਸੀਲੈਕਸ੍ ੨	(17)87	Last but one
ਆਧਾਰ	ਆਧਰ	(17)89	Last
ਕਿਤੋਂ	ਕਿਥੋਂ	(17)91	17
ਭੇਜੇ	ਭੇਜੇ	(19)91	Last
ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਬਲ	ਪਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਬਲ	(17)91	Last
ਮੋਢੇ	ਮੋਡੇ	(17)92	8
ਹੋਣ	ਹੋਨ	(17)93	Last
ਜ਼ਮੀਨ	ਮਜ਼ੀਨ	(17)94	13
speeeh	speach	(17)94	3 from below
ਮਨਿਸਟਰ	ਾਨਸਟਰ	(17)94	Last
ਭਲਾਈ	ਭਾਲਈ	(17)95	17
ਚੌਧਰੀ	ਚੌਧਚੀ	(17)96	1
ਏਨਾ	ਇਨ੍ਹਾਂ	(17)96	13
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ	ਤਹਾਡਾ ਸ਼ਕਰੀਆ	(17)96	6
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ	ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ	(17)98	7

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 11th March, 1966

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber Sector 1, Chandigarh, at 9.30 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS
SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO 9492*

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ?

कल्याण तथा न्याय मन्त्री (श्री चांद राम) : मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि ए० आई० जी० और कोई सीनियर आफिसर जाएगा और इन्क्वारी करेगा । पहले यह बात हमारे नोटिस में आई नही थी । फरवरी 66 में आई०जी० प्रिज़न० ने कहा था कि इसमें जेल का कोई आफिसर इन्वालव्ड नहीं है लेकिन इस बात सें गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया इसलिए हुक्म दिया गया कि सीनियर आफिसर इन्क्वायरी के लिए जाए ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : सवाल तो यह पूछा गया था कि किस डेट को मिनिस्टर इन्चार्ज ने जेल अधिकारियों के खिलाफ इन्क्वायरी करने का आर्डर दिया और क्या इन्क्वायरी शुरू हो गई है और अगर शुरू है तो कब तक इन्क्वायरी को खत्म कर लिया जाएगा ?

मन्त्री : पहले एगज़ेकटिव मैजिस्ट्रेट ने 22 जनवरी, 1965 को रिपोर्ट की कि इस में जेल अधिकारी एट फाल्ट हो सकते हैं। इस पर आई. जी. प्रिज़न ने कहा कि जेल अधिकारी इस आधार पर एट फाल्ट नहीं थे । इस के बाद फाइल गवर्नमेंट के पास आई और गवर्नमेंट ने इस से एग्री नहीं किया और हुक्म दिया गया कि जेल आफीसर्ज़ के खिलाफ इन्क्वायरी हो सकती है कि किस तरह से पायज़न को जेल के अन्दर समगल किया गया और किस की शह पर इस तरह से किया गया ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Minister for Justice that taking into consideration the circumstances of the case and the gravity of the offence committed in the Jail, would the Government consider the desirability of getting a judicial enquiry instituted in the matter ?

मन्त्री : एगज़ैक्टिव मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी भी तो समी जुडीशल ही होती है । यह सन 65 का वाका है और आज इस पर जुडीशल इन्क्वायरी कराने का कोई फायदा नहीं होगा । जब रिपोर्ट हमारे सामने आई तो हम ने आई. जी. प्रिज़न के साथ एग्री नहीं किया और सरकार का ख्याल है कि इस में जेल आफीसर्ज़ कसूरवार हो सकते हैं इस लिये सीनियर आफीसर को इन्क्वायरी करने के लिए कहा गया है । ए. आई. जी. 14 मार्च, 1966 को इन्क्वायरी के लिए जाएगा ।

Note :—Starred Question No. 9492 and reply thereto appear in P. V. S. Debates Vol. I, No. 14, dated the 8th March, 1966.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ, 1965 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਵਰੀ, 66 ਵਿਚ ਆਈ, ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਥੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡੀਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ?

मन्त्री : इस में डीले की बात नहीं, जनवरी में एग्ज़ैकटिव मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजी और उस ने आई. जी. प्रिज़न को भेजी और फिर आई. जी. प्रिज़न ने गवर्नमेंट के पास भेजी तो सरकार ने आबजर्व किया कि इस में जेल आफीसर्ज़ इनवालव्ड हो सकते हैं इस लिए फिर से इन्क्वायरी का हुक्म दिया गया।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਜੀ. ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : उस वक्त तो तबदील नहीं किया गया था उसके बाद सुपरिन्टेंडेंट जेल को 14-9-65 को डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट को 19-2-65 को और डिसपेंसर को 23-2-65 को तबदील किया गया था।

श्री बाबू दयाल शर्मा : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने ने फरमाया है कि जेल आफीसर्ज़ कसूरवार न थे तो प्वायज़न का जेल के अन्दर चला जाना इटसैल्फ यह शो नहीं करता कि जेल अधिकारियों की केयरलैसनैस और नैगलीजेंस है, अगर है तो इस के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

मन्त्री : इसी बात की तो इन्क्वायरी हम करवा रहे हैं कि how that poison was smuggled in the Jail.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ?

मंत्री : नाम तो इस वक्त मेरे पास नहीं है आप अगर नोटिस दें तो पता करके बता दूंगा।

कंवर राम पाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जैसा कि इन्होंने फरमाया है कि हैडक्वार्टर्ज़ से सीनियर आफीसर इस बात की इन्क्वायरी करेंगे तो यह फैसला किस डेट को किया गया और इस में डीले के क्या कारण हैं ?

मन्त्री : मैंने अर्ज किया है कि 26 फरवरी को होम सैक्रेटरी ने आई. जी. प्रिज़न. को लिखा है कि सीनियर आफीसर जाएगा और वह 14 मार्च, 1966 को जाएगा। इस में डीले का सवाल नहीं है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : In reply to a question the hon. Minister for Justice was pleased to tell us that it would be futile to institute a judicial enquiry in the matter as the matte has been delayed. Will he kindly tell

us if an enquiry by a departmental officer will be fruitful as against a judicial enquiry because of this delay ?

मन्त्री : मैंने अर्ज किया है कि अगर आप यह समझते हैं कि आई. जी. प्रिज़न या ए. आई. जी. प्रिज़न पर आप का ऐतमाद नहीं है तो हम सैक्रेटेरिएट से किसी और सीनियर आफीसर को भेजने के लिये तैयार हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

मन्त्री : इस में कई सवाल कम्पलीकेटिड हैं एग्ज़ैक्टिव मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह देखने वाली बात है कि आया प्वायजन उस के मिलने वाले के ज़रिया से उस के पास पहुंचा या डिसपैन्सर की मारफत दिया गया इस बात की रिसपान्सेबिलिटी किसी आफीसर पर फिक्स नहीं की जा सकती थी । इस लिये उन्हें ट्रांसफर न किया गया और बाद में तबदील कर दिया गया था ।

Sarpanch of Village Panchayat Karela, Tehsil Jind

***9719. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether he is aware of the facts that the Sarpanch of Village Karela, Tehsil Jind does not allow the Panchayat Secretary to write the minutes of the meetings of the Panchayat in the Minute Book of the Panchayat ;

(b) whether he is aware of the facts that the minutes of the said Panchayat have been written by some other persons than the Panchayat Secretary in the absence of the Panches ; if so, their names and the names of the persons who generally wrote the minutes of the meetings of the said Panchayat in the minutes book since the election of the present Sarpanch ;

(c) whether the Government have enquired or intend to enquire into the matter referred to in parts (a) and (b) above and take action against the said Sarpanch for the irregularity committed by him ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) The minutes are written by the Sarpanch or a person knowing Urdu. The minutes are signed by the Sarpanch/Panches and the name of the writer of minutes is not indicated.

(c) The pros and cons of this matter are being looked into.

चौधरी दल सिंह : क्या विकास मन्त्री बतायेंगे कि इन्होंने कहा है कि मीटिंग के मिनटस को उर्दू में सरपंच ने खुद लिखा तो क्या यह हकीकत नहीं है कि जींद के एक पैटीशन राइटर रन्जीत लाल ने इन को लिखा था ?

मन्त्री : मेरे पास तो इस तरह की इन्फरमेशन नहीं है । यह इत्तलाह है कि वह सरपंच सिरफ उर्दू ही जानता है इस लिये वह खुद या किसी से उर्दू में ही मिनटस लिखवाता है ।

चौधरी दल सिंह : क्या यह हकीकत नहीं कि पंजाब गवर्नमैण्ट ने हिदायत जारी की है कि पंजाबी ज़ोन में पंजाबी और हिन्दी ज़ोन में हिन्दी में मिनटस को रिकार्ड किया जाए ।

और उर्दू जब कि कोई और मम्बर नहीं जानता तो क्यों इस भाषा में मिनटस को रिकार्ड किया जाता है ?

ਮੰਤਰੀ: ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਮਿਨਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਪਰ ਇਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਉਰਦੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਨਟਸ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या डिवैलपमेंट मिनिस्टर यह बताएंगे कि क्या उर्दू में मिनटस को रिकार्ड करना जुर्म है और क्या यह ज़रूरी है कि अगर सरपंच पढ़ा लिखा हो तो भी अपने पंचायत सैक्रेटरी से ही मिनटस को रिकार्ड करवाए ?

मंत्री : यह ज़रूरी नहीं कि वह पंचायत सैक्रेटरी से ही मिनटस को लिखवाए सरपंच उर्दू जानता था इस लिए उस ने उर्दू में मिनटस को रिकार्ड कर लिया अगर सरपंच पढ़ा लिखा न हो तो वह पंचायत सैक्रेटरी से मिनटस को रिकार्ड करवा सकता है।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪ ਮਿਨਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੌਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, will the hon. Minister for Home and Development be pleased to state the provisions of the Act under which a third person is debarred from writing the proceedings of the meetings of a Panchayat ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਦ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੇ । ਪਰ ਅਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖੇ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of Order. My point of Order is this. Sir, I put a simple supplementary question to the hon. Minister for Home and Development whether a third person, i.e., a person other than the Sarpanch or the Secretary, is debarred from writing the proceedings and the answer to this question has not come.

Minister: I have given the reply that he is not debarred. But normally or preferably these should be written by the Sarpanch or the Secretary.

चौधरी दल सिंह : क्या यह दरुस्त है कि पंचायत रजिस्टर में जो कार्रवाई लिखी गई उस की बावत पंचों को कुछ भी मालूम नहीं।

मन्त्री : इस की बाबत सरपंच से ही पूछा जा सकता है इस की मुझे कोई वाकफियत नहीं है।

Enquiry into the working of the Lyallpur Co-operative Joint Farming Society Ltd., Murtzapore in District Karnal

***9906. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether it is a fact that an enquiry into the constitution, working and the financial position of the Lyallpur Co-operative Joint Farming Society Ltd., Murtzapore in district Karnal was ordered under Section 50 of the Co-operative Societies Act, on 12th March, 1965 ;

(b) whether it is a fact that a show cause notice was issued to the Manager of the above Society, on 12th October, 1965 and a reply thereto was received by the Department ;

(c) a copy of the enquiry report mentioned in part (a) above alongwith a copy of the show cause notice issued to the Manager of the said Society and of the reply received from him be laid on the Table of the House ;

(d) whether any final orders have been passed by the Department in the above case ; if so, the details and if no orders have been passed, the reason for the same ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d) An appeal against the order of the Deputy Registrar Co-operative Societies, Rohtak, winding up the Society is pending before Government under the Punjab Co-operative Societies Act, 1961. As the case is *sub-judice* desired copies of the documents cannot be laid on the Table of the House at this stage.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਖ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ?

मन्त्री : इस के मुतािल्लक कोई इतलाह अगर हो तो डिपार्टमैंट में ही होगी मुझे मालूम नहीं ।

कामरेड शमशेर सिंह जोश : अगर कोई इस तरह की दरखास्त दे तो क्या उसे वकील पेश करने की इजाज़त दी जाएगी ?

मन्त्री : यह कोई ऐसी बात नहीं कि वकील पेश ना हो सके फिर भी इस ऐगज़ामिन कर लिया जाएगा ।

Election of Office bearers of Central Co-operative Bank Ltd., Faridkot

***9810. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether any date for the election of the office bearers of the Central Co-operative Bank Ltd., Faridkot was fixed ; if so, what ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmaive, the names and number of candidates with their addresses who filed the nomination papers for the said election together with the last date fixed for filing the nomination papers ;

(c) whether the said election has been postponed ; if so, when, the reasons therefor and under whose orders ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) to (c) Information is laid on the Table of the House.

[Minister for Irrigation and Power]

Statement

(a) Yes, the election of the Central Co-operative Bank Ltd., Faridkot was Scheduled to be held on 31st December, 1965.

(b) The following 30 candidates filed the nomination papers. The last date for filling nomination papers was fixed as 23rd December, 1965 :—

Serial No.	Name of the candidate	Address
1	2	3
		Individual share holders
1	Master Sunder Singh	.. Harinder Nagar, Faridkot.
2	Chetan Dev	.. Faridkot, Mohalla Banianwala, Faridkot.
3	Amar Nath	.. Line Bazar Faridkot, C/o M/s Ganga Mal
4	Nathu Ram	.. Nathu Ram Aggarwal, Old Jail road, Faridkot
5	Dayal Singh	.. Manjit Inderpura, Faridkot
6	Amar Singh	.. Behind Fort Faridkot
7	Bihari Lal	.. Railway Road, Kotkapura
8	Amar Nath Dhawan	.. Kotkapura
9	Mengh Raj Jain	.. C/o M/s Mengh Raj Phool Chand Jain, Kotkapura
10	Ram Rakha Mal	.. C/o M/s Moti Ram Sant Ram General Merchants, Faridkot
		Representatives of Societies
11	Karnail Singh	.. Faridkot Agwar Vani Ke No. 2 Co-operative Credit and Thrift Society, Faridkot
12	Mehnga Singh	.. The Scheduled Caste Co-operative Land Owing Society Ltd, Faridkot
13	Ram Karan Singh	.. The General Co-operative Store Ltd., Kotkapura
14	Narinjan Dass	.. The Janta Co-operative Transport Scciety Ltd., Kotkapura
15	Jasmat Singh Dhillon	.. The Dana Ramana Co-operative Agricultural Service Society Dana Ramana
16	Gurnam Singh	.. Virewala Khurd Co-operative Agricultural Service Society Post office Kotkapura
17	Kapur Singh	.. The Sekhun Co-opeative Joint Farming Society Ltd., Machakimal Singh
18	Ram Gopal	.. The Gopal Shoe makers co-operative Industrial Society Ltd., Jaitu Post office Jaitu Tehsil Faridkot
19	Balwant Singh	.. The Behbal Kalan Co-operative Agriculture Service Society

Serial No.	Name of the candidate		Address
20	Jawant Rai Kochar	..	The Janta Co-operative Dairy Society Ltd., Jaitu Post office Jaitu, Tehsil Faridkot
21	Jit Singh	..	The Nathewala Co-operative Agricultural Service Society, Village Nathewala, Post office Kotkapura
22	Nazar Singh	..	The Misriwala Co-operative Joint Farming Society Ltd., Misriwala
23	Gurmail Singh	..	The Dhillwan Khurd Co-operative Joint Farming Society Ltd., Dhillwan Khurd
24	Joginder Singh	..	The Dhilwan Khurd Co-operative Agricultural Service Society Dhilwan Khurd, Post office Jand Sahib
25	Jugraj Singh	..	The Ramuwala Co-operative L&C Society Ltd., Ramulwala, Post office Jaitu, Tehsil Faridkot
26	Mukhtiar Singh	..	The Dod Co-operative Agriculture Service Society Ltd., Post office Dod, via Goniana , Tehsil Faridkot
27	Avtar Singh	..	Gurand Khand Co-operative Industrial Society Ltd., Dal Singh Wala Village and Post office Dal Singh Wala
28	Ranjit Singh	..	Cashier, The Dhillon Co-operative Joint Farming Society Ltd., Bajekhana
29	Gurbachan Singh	..	The Kot-Sukhia Co-operative Agriculture Service Society Kot Sukhia
30	Karnail Singh	..	The Agriculture Service Co-operative Society, Mehmuana

(c) Yes, the Scheduled election was postponed by the Registrar, Co-operative Societies, Punjab, vide his order dated, 25th December, 1965 on the basis of an affidavit given by Shri Dayal Singh, Senior Vice-President of the Faridkot Central Co-operative Bank Ltd., Faridkot starting there in that the Faridkot Tehsil had been adversely affected due to the recent hostilities with Pakistan resulting in economic dislocation of the people of that which in turn resuted in the a inability of more than one hundred Co-opertvie Societies of this Tehsil to pay the instalments of loand borrowed by them from that Bank and thereby becoming defaulter. Further it has also been stated in the affidavit that the notice of the election was served upon the Societies at a very short notice with the result that the Societies could not elect their nominees well in time.

चौधरी दर्शन सिंह : वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो रैप्रिज़ैंटेशन आई वह मिनिस्टर के पास आई या रजिस्टरार के पास ?

मंत्री : रेप्रिजटशन मेरे पास आई और मैंने रजिस्टरार के पास भेज दी।

चौधरी दर्शन सिंह : क्या स्टे आर्डर करने के लिये कोई हिदायत जारी की गई थीं ?

मन्त्री : नहीं ।

चौधरी दर्शन सिंह : क्या उस वक्त फरीदकोट का एरिया वार इफैकिटिड डिकलेयर किया गया था ?

मन्त्री : यह तो मुझे मालूम नहीं मगर इस की सरहदें वार इफैक्टिड एरिया से ज़रूर लगती हैं।

चौधरी दर्शन सिंह : जब गवर्नमेंट ने वार इफैक्टिड एरिया डिकलेयर नहीं किया ग्रौर नामीनेशन पेपरज रिसीव किये गये थे, इस के बाद सटे ग्रारडर देने की क्या वजह है ?

मंत्री : मैंने इस का जवाब पहले ही रिपलाई में दे दिया है।

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ?

मंत्री : इस का मुझे इस वक्त पता नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਰ ਇਫੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : इस वक्त मुझे पता नहीं है मगर यह रिकार्ड की चीज़ है जो गालबन बैंक ने फिक्स की होगी।

---

33 K.V. Line from Bhiwani to Charkhi Dadri in District Mohindergarh

***9619. Shri Banwari Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether the 33 K.V. Line from Bhiwani to Charkhi Dadri in District Mahendragarh has been completely changed into a High Power Line ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether Government have received any representation for changing the 33K.V. Line into 11 K.V. Line and to supply electricity to the villages situated near the said line; if so, the decision, if any, taken thereon ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to send the material of the said 33 K.V. Line to another district ; if so, the reasons why the said material is not being used in district Mohindergarh where it is already in short supply ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

श्री बनवारी लाल : On a point of order, Sir. मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि ग्राप चल कर देख लें 23 के. वी. लाइन चेंज हो चुकी है मगर वज़ीर साहिब जवाब दे रहे हैं कि does not arise । ग्राप इस की इनक्वायरी करवा सकते हैं।

Mr Speaker : Please resume your seat. This is no point of order.

श्री बनवारी लाल : मैं पूछना चाहता हूं कि 33 के. वी. लाइन चेंज हो चुकी है या नहीं ?

मंत्री : हम ने 33 के वी. लाइन को हाई पावर बनाया है। ग्रब यह 132 के. वी. लाइन में चेंज हो गई है।

श्री बनवारी लाल : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप पहले प्वायंट आफ आर्डर रेज करते हैं और बाद में सप्लीमेन्टरी। आप प्वायंट आफ आर्डर पर ही बोलें सप्लीमेंटरी की अजाजत नहीं दी जायेगी। (The hon. Member first raises a point of order and then asks a supplementary question. He should speak first on the point of Order as he will not be allowed to ask a supplementry question.)

श्री बनवारी लाल : अच्छा जी, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि सवाल में लिखा है कि whether 33 k.v. line from Bhiwani to Charkhi Dadri in district Mohindergarh has been completely changed into a high power line मगर जवाब आता है 33 k.v. line 132 k.v. line में चेंज हो गई है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, this is no point of order. (The hon. Member may please resume his seat; this is no point of order.)

B.D. and P.O., Lahra Gaga Block District Sangrur

***9799. 1. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal**
2. Comrade Bhan Singh Bhaura, : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any case was institued in the court of Shri Jug Bhushan Garg, P.C.S., Judicial Magistrate 1st Class, Sunam, by Shri Lachhman Singh Joshi against Shri Manjit Singh Inspector, Agricultural Seed Farm, Chural Kalan, Block Lehra Gaga, District Sangrur ;

(b) whether the Block Development and Panchayat Officer Lehra Gaga was the only witness who appeared for evidence in the said case ;

(c) whether it is a fact that the case was dismised by the Court, with some remarks against the witness referred to in part (b) above ;

(d) whether attested copies of the judgement in the said case was received by the authorities concerned from the Chairman, Panchayat Samiti, Lehra Gaga, soon after the judgement was delivered ;

(e) if the reply to part (c) above be in the affirmative, the action taken on the basis of the remarks in the said judgement ; if no action taken, the reasons for the same ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) It was produced on 12th November, 1965 by the Chairman, Panchayat Samiti Lehragaga in an enquiry against Block Development and Panchayat officer for reference only.

(e) No action was taken because the court did not send any report in in this behalf to the District Magistrate in accordance with the procedure prescribed for cases in which it is intended to take action against Government servants.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਬਹੁਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਉਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਉਹ ਕੁਛ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਭਾਗ (ਸ) ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਚ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਮ ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੀ ਗਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

Chaudhri Inder Singh Malik : By what time will the enquiry be completed and the proposed action taken ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਲੇਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਪਤਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦਿਉ।

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਥਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ੨ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੁਛ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੜਾ ਦਿਆਂਗੇ।

Tour by Superintendents of Police

*9027. **Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the number of days for which each Superintendent of Pclice remained on tour during the period from 1st April, 1965 upto date, district-wise ;

(b) the amount of T.A. drawn and yet tobe drawn by each of the above mentioned officers on account of the tours referred to in para (a) above ?

Sardar Darbara Singh : The requisite information is given in the enclosed statement.

Statement showing the number of days spent on tour by District Superintendents of Police and the amounts of T.A. drawn/yet to be drawn by them

			(a) Number of days spent on tour period 1st April, 1965 to date	(b) Amount of T.A. drawn and yet to be drawn
				Rs. Paise
1	Senior Superintendent of Police, Amritsar	..	96	570.07
2	Senior Superintendent of Police, Ferozepur	..	90	639.20
3	Superintendent of Police, Gurdaspur	..	68	616.50
4	Superintendent of Police, Hissar	..	158	1,487.80
5	Superintendent of Police, Rohtak	..	145	1,278.00
6	Superintendent of Police, Gurgaon	..	79	762.25
7	Superintendent of Police, Karnal	..	176	2,086.90
8	Superintendent of Police, Ambala	..	62	2,132.90
9	Superintendent of Police, Simla	..	43	551.55
10	Superintendnet of Police, Hoshiarpur	..	111	1,351.61
11	Superintendent of Police, Jullundur	..	106	891.22
12	Superintendent of Police, Ludhiana	..	108	473.62

			(a) Number of days spent on tour period 1st April 1965 to date	(b) Amount of T. A. drawn and yet to be drawn
13	Superintendent of Police, Kapurthala	..	89	707.52
14	Superintendent of Police, Kangra	..	114	1,280.33
15	Superintendent of Police, Kulu	..	86	927.85
16	Superintendent of Police, Lahaul and Spiti	..	152	3,931.15
17	Superintendent of Police, Patiala	..	103	913.50
18	Superintendent of Police, Sangrur	..	157	2,082.95
19	Superintendent of Police, Bhatinda		127	1,143.00
20	Superintendent of Police, Mohindergarh	..	74	818.00

Mr. Speaker : Next Question (9027) by Comrade Ram Chandra please.

In this connection, I would like to bring to the notice of the Home Minister that there was a similar question by Sardar Niranjan Singh Talib, which appeared in the List on the 17th February and which was postponed, because it was represented that the Government were not ready with the information. Accordingly, extension was given till the 8th March, but up till now the requisite reply has not come to the office. I cannot understand why the same Department gives information to a similar question., but withholds it in regard to a question of a similar nature by another Member. Somebody has been responsible for misleading.

Home Minister (Sardar Darbara Singh) : I will check up, Sir, and let you know.

कामरेड राम चन्द्र : मुझे जो लिस्ट सप्लाई की गई है उसमें बताया गया है कि मुखतलिफ सुपरिन्टेंडेंटस ने साल में जो दौरे किए वह 43 से 176 दिन तक चले जाते है । मैं दरयाफत करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि उनके दौरों में इतना फर्क है और वैसे ही प्रोपोरशनेटली खर्च ज्यादा किया गया है टूर पर यह किस हद तक जायज है ।

ਮੰਤਰੀ : ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਕਰਾਈਮ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਓਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

कामरेड राम चन्द्र : स्पीकर साहिब मैं मानता हूं कि दौरे करने पड़ते हैं, लेकिन साल में 176 या 158 दिन जो दौरे किए गए है क्या इतने ज्यादा क्राईमज़ है जो उन जगहों पर ही दौरे किए गए हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਸੀ । ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ । ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਪਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ।

कामरेड राम चन्द्र : वज़ीरसाहिब ने फरमाया कि पिछले दिनों में जब जंग हुई तो ज्यादा दौरे करने पड़े । मैं यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि जंग की वजह से करनाल और रोहतक में ज्यादा दौरे होने चाहिए थे या अमृतसर और फिरोज़पुर में होने चाहिए थे ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜਾਹ ਨਹੀ । ਐਸ. ਪੀਜ਼. ਨੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो 11 महीनों के दौरों के दिन बताए गए हैं उस में करनाल ज़िला के एस. पी. ने 176 दिन टूर किया और वजह बताई है कि देहात में, गांव में क्राईम बढ़ता जा रहा था उस को रोकने के लिये यह किया । क्या गांव में जा कर यह क्राइम को बढ़ाते हैं या घटाते हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਈਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ।

श्री लाल चन्द प्रार्थी : लाहौल और स्पिती के ज़िला में 6 महीने आमदो रफ्त कम होती है बरफ में वहां उन्होंने 152 दिन दौरा किया । वहां क्राइम नहीं होता । किन हालात में यह दौरे हुए ? क्या यह दौरे जस्टीफाईड हैं या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵਲੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ।

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि दौरों और क्राई में कोई प्रोपोरशन है कि जहां दौरे हुए है वहां क्राईम कम है और जहां कम दौरे हुए है वहां क्राईम ज़्यादा है ।

ਮੰਤਰੀ : ਨਾਰਮਲੀ ਦੌਰਾ ਕਰਾਈਮ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ । ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜ਼ਰਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੀਚੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਲੇ ੨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਬ-ਰਪਟਲੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ. ਪੀ. ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ । ਅਨਫੋਰ੍ਹਸੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

Trade Unionists/Communist Detenus in the State

***9626. Shri Om Parkash Agnihotri** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of detenus at present in the Punjab stating the number of Communists and Trade Unionists separately among them together with the number of those enjoying A, B and C Classes respectively ;

(b) whether any of the said detenus have been given family allowance by the Government ; if so, the number and the amount of allowance granted in each case ?

Sardar Darbara Singh : (a) 108 — 59 Communists ; 1 Trade Unionist and others non-Political.

Classification

Communists—		
Special Class	..	2
Ordinary Class	..	57
Trade Unionist	..	..
Ordinary Class	..	1

(b) Part (i) No.

Part (ii) Question does not arise.

श्री ओमप्रकाश अग्निहोत्री : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सैंट्रल गवर्नमैण्ट की तरफ से पंजाब सरकार को जो तजावीज़ आई हैं सारे देश में डैटिनस को फैमीली पैनशनज़ के सिलसिले में यूनीफारमिटी लाने के लिये उस पर गवर्नमैण्ट ने क्या एक्शन लिया है ?

10-00 a.m.

मंत्री : अभी तक वह अंडर कनसिडरेशन है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या यह अमर वाक्या है कि उन को पुलीटिकल वजूहात से नजरबन्द किया गया है। अगर यह ठीक है तो क्या उन के साथ पुलीटिकल नजरबन्दों वाला सलूक किया जा रहा है ?

मंत्री : कलासीफिकेशन मैंने आप के सामने रख दी है ?

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਜਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਮ. ਪੀਜ਼, ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਔਰ ਐਮ. ਐਲ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਟਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲ ਹੈ, ਪੀ. ਸੀ. ਭਾਰਦੁਆਜ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ, ਸਤਿਆ ਨੰਦਨ ਨਾਰਨੌਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੌਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

ਮਨਿਸਟਰ : ਹਰ ਕੇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Hon. Home Minister as to when the instructions of the Government of India were received by the State Government and how long will it take for the State Government to give a final consideration and come to a conclusion ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि Trade Union Leader Shri R. B. Manchanda जिन को पहले 'B' class दी गई थी अब 'C' class देने की क्या वजह है ?

Minister : इस के लिए नोटिस चाहिए । I do not know. I will have to get information from office.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾਓ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Home Minister if the detenus about whom information is being given are political detenus ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 59 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਨ-ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹਨ । ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਹੈ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जो प्रोपोज़लज़ सैंटर से मिली हैं उन को कनसिडर करते तो कुछ देर लगेगी इस लिये क्या उन लोगों को इनटैरिम रिलीफ के तौर पर फैमिली पेंनशनज़ देने के लिये तैयार है जैसा कि दूस ी कई स्टेट्स ने किया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਮਦਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਈਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Next question please.

(Some hon. Members insisted that more supplementaries be allowed because the question was very important.)

Mr. Speaker : That is why I have allowed more than 15 supplementaries to be put.

Sardar Lakhi Singh Chaudhri : No. 9678 please.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, पंडित अग्निहोत्री जी का क्वेश्चन था कि पंजाब में इस वक्त कुल कितने नजरबन्द हैं और उन में से कम्युनिस्ट और ट्रेडयूनियन के नज़र बन्द कितने हैं इस पर मैं ने स्पलीमेंटरी किया था कि इन के अलावा ब्लैक मार्किटीअर्ज़ और स्मगलर्ज़ रिश्वतखोर, मुनाफाखोर कितने हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है ? यह मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मेरा सप्लीमेंटरी इस क्वेश्चन के मुताबिक है मगर आप ने डिस अलाउ करके मेरे साथ ज्यादती की है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । (The hon. Member may please resume his seat.)

चौधरी नेत राम : कितने मुनाफाखोर, रिश्वतखोर और ब्लैक मार्किटीयर्ज़ पकड़े हुए हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष : मैं ने आप को इजाजत नहीं दी आप बैठ जाइये। (I have not allowed the hon. Member to put a supplementary question. He may take his seat.)

चौधरी नेत राम : मैं ने यह स्पलीमेंटरी किया था कि ......कितने और.....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। (The hon. Member may take his seat.)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चौधरी नेत राम शायद एक्सप्लेन नहीं कर सके। सवाल में यह पूछा गया था कि पंजाब में कुल कितने नज़र बन्द हैं। इन का सवाल था कि उन में से रिश्वतखोर और ब्लैक मारकीटियर कितने थे। यह शायद अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये विघ्न। (The hon. Member may take his seat.) (*Interruptions*)

चौधरी नेत राम की तरफ से विघ्न)

चौधरी नेत राम : आप स्पीकर साहिब सरकार का पक्ष करते हैं और अब में रिश्वत-खोरों और ब्लैक मार्किटअर्ज़ के मुताल्लिक कुछ पूछता हूं और भ्रष्टाचार को नंगा करता हूं तो आप मुझे पूछने नहीं देते। इस लिये मेरी सप्लीमेंट्री को एलाऊ करनी चाहिए।

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी नेत राम : मैं वाक आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी नेत राम सदन से वाक आउट कर गए।)

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੌਪ੍ਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਇੱਕਠਾ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चौधरी नेत राम का यह सवाल था कि कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन के नज़र बन्दों के इलावा भी कोई और नज़रबन्द पंजाब में है......

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (The hon. member may take his seat.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, आप ने जवाब नहीं देखा जवाब में बताया गया है उन के अलावा भी नज़र बन्द ....

श्री अध्यक्ष : आप तो बड़े समझदार मेम्बर हैं। जब एक क्वेश्चन डिसअलाउ कर दिया गया हो तो उस पर आप प्वायंट आफ आर्डर किस तरह से रेज़ कर सकते हैं ? आप बैठ जाइये। (The hon. Member is a seasoned parliamentarian. When a question has been disallowed how can he raise a point of order thereon ? He may please take his seat.)

It was beyond the scope. The hon. Member may discuss the matter with me in my Chamber.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੇਟੀਨਿਊ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । No, I have called upon the next question.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

Mr. Speaker : Will the hon. Member please withdraw these words ?

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ।

Mr. Speaker : Every question is an important question and in this particular case I have already allowed a number of supplementaries to be put.

Will you, Mr. Tarsikka, withdraw your words ?

Comrade Makhan Singh Tarsikka : No please.

Mr. Speaker : Comrade Makhan Singh Tarsikka is not obeying the Chair and has made a reflection on the Chair. Therefore, I am constrained to order him to withdraw from the House.

Comrade Tariskka, please withdraw from the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

Bund constructed by the villagers of Ghaloti, district Ludhiana

***9678. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the villagers of Gholoti, district Ludhiana had constructed a bund so that the flood water of village Ghodani, district Patiala (now in district Ludhiana) may not pass through their fields ;

(b) whether Government cut the said bund in the year 1964 or 1965, so that the water could flow through its natural courses ;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether the Government is aware of the fact that but for the courage and devotion to duty by any one or more of the officers of Government, some of the officers/villagers would have been killed ;

(d) if the reply to part (c) above is in the affirmative, the reward, if any, paid or proposed to be paid to the officers who acted courageously ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) No.

I.P.S. Officers in the State

***9820. Shri Amar Singh (Put by Shri Banwari Lal) :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number and names of I.P.S. Officers in 1957 and the number of said officers belonging to the Scheduled Castes ;

(b) the total number and names of the I.P.S. Officers serving at present in the State and the number of Scheduled Castes amongst them ?

Sardar Darbara Singh : (a) 68 officers were borne on the I.P.S. cadre of the Punjab in 1957. Of these 3 belonged to the Scheduled Castes.

[Home and Development Minister]

A list containing the names of officers concerned is placed on the Table of the House as Annexure I.

(b) 98 Officers are borne on the I.P.S. cadre of this State at presnt Of thses 11 belong to the Scheduled Clastes. A list containing the names of the officers concerned is placed on the table of the House as Annexure II.

ANNEXURE (I)

Names of Officers borne on the I.P.S. cadre in 1957

1. Shri D.C. Lal, I.P.
2. Shri B.S. Bindra, I.P.
3. Shri W.C. Mehra, I.P.
4. Shri Waryam Singh, I.P.
5. Shri Gurdial Singh, I.P.
6. Kanwar Shamsher Singh, I.P.
7. Shri Balbir Singh, I.P.
8. Shri Ram Singh, I.P.S.
9. Shri F.B. Manley, I.P.
10. Shri L.R. Malhotra, I.P.S.
11. Shri Piara Lal, I.P.S.
12. Shri A. Kumar, I.P.
13. Shri J.R. Chhabra, I.P.S.
14. Shri A.K. Kaul, I.P.S.
15. Shri H.C. Saxena, I.P.S.
16. Shri C.L. Malhotra, I.P.S.
17. Shri Bhagwan Singh Rosha, I.P.S.
18. Shri A.S. Midha, I.P.S.
19. Shri Ajaib Singh, I.P.S.
20. Shri Manohar Lal Nanda, I.P.S.
21. Shri D.S. Grewal, I.P.S.
22. Shri B.N. Muttoo, I.P.S.
23. Shri Naurang Singh, I.P.S.
24. Shri R.N. Shukla, I.P.S.
25. Shri M.L. Puri, I.P.S.
26. Shri J.C. Vachchar, I.P.S.
27. Shri B.R. Chadha, I.P..S.
28. Shri Randip Singh, I.P.S.
29. Shri V.N. Bakshi, I.P.S.
30. Shri B.A. Rosha, I.P.S.
31. Shri Hem Raj Talwar, I.P.S.
32. Shri S.M. Mathur, I.P.S.
33. Shri T.S. Sachdeva, I.P.S.
34. Shri Chhabil Lal, I.P.S.
35. Shri V.C. Occam, I.P.S.
36. Shri Gurpuran Singh, I.P.S.
37. Shri Kesri Chand, I.P.S.
38. Shri Puran Singh, I.P.S.
39. Shri Anup Singh, I.P.S.
40. Shri Madan Gopal Singh, I.P.S.
41. Shri Gurdial Singh, I.P.S.
42. Shri Ranjit Singh, I.P.S.
43. Shri S.S. Bajwa, I.P.S.
44. Shri Harjit Singh, I.P.S.
45. Shri Surinder Nath, I.P.S.
46. Shri Bhagwan Singh Danewalia, I.P.S.
47. Shri Birbal Nath, I.P.S.
48. Shri Karam Singh, I.P.S.
49. Shri J.S. Bawa, I.P.S.
50. Shri M.S. Bhatnagar, I.P.S.
51. Shri P.C. Wadhwa, I.P.S.
52. Shri Bishamber Nath, I.P.S.
53. Shri Ujagar Singh, I.P.S.
54. Shri Parkash Chand, I.P.S. (Scheduled Caste).
55. Shri V.K. Kalia, I.P.S.
56. Shri Inderjit Verma, I.P.S.
57. Shri Baljit Rai Sud, I.P.S.

58. Shri V.S. Seigell, I.P.S.
59. Shri C.K. Sawhney, I.P.S.
60. Shri M.S. Bawa, I.P.S.
61. Shri Inderjit Singh Sodhi, I.P.S.
62. Shri Krishan Kumar, I.P.S.
63. Shri D.D. Kashyap, I.P.S. (Scheduled Caste).
64. Shri M.L. Bhanot, I.P.S.
65. Shri G.S. Mander, I.P.S.
66. Shri P.S. Shukla, I.P.S.
67. Shri K.L. Dewan, I.P.S.
68. Shri Hans Raj Swan, I.P.S. (Scheduled Caste).

ANNEXURE II

Names of I.P./I.P.S. Officers borne on the Punjab State cadre as on 28th February, 1966

1. Shri Gurdial Singh, I.P.
2. Kanwar Shamsher Singh, I.P.
3. Shri Balbir Singh, I.P.
4. Shri Ram Singh, I.P.S.
5. Shri Piara Lal, I.P.S.
6. Shri A. Kumar, I.P.
7. Shri J.R. Chhabra, I.P.S.
8. Shri H.C. Saxena, I.P.S.
9. Shri Bhagwan Singh Rosha, I.P.S.
10. Shri A.S. Midha, I.P.S.
11. Shri Ajaib Singh, I.P.S.
12. Shri D.S. Grewal, I.P.S.
13. Shri B.N. Muttoo, I.P.S.
14. Shri M.L. Puri, I.P.S.
15. Shri J.C. Vachchar, I.P.S.
16. Shri B.R. Chadha, I.P.S.
17. Shri Randip Singh, I.P.S.
18. Shri V.N. Bakshi, I.P.S.
19. Shri P.A. Rosha, I.P.S.
20. Shri Hem Raj Talwar, I.P.S.
21. Shri S.N. Mathur, I.P.S.
22. Shri Gurpuran Singh, I.P.S
23. Shri Puran Singh, I.P.S.
24. Shri Madan Gopal Singh, I.P.S.
25. Shri Ranjit Singh, I.P.S.
26. Shri S.S. Bajwa, I.P.S.
27. Shri Harjit Singh, I.P.S.
28. Shri Surinder Nath, I.P.S.
29. Shri Bhagwan Singh Danewalia, I.P.S.
30. Shri Birbal Nath, I.P.S.
31. Shri J.S. Bawa, I.P.S.
32. Shri M.S. Bhatnagar, I.P.S.
33. Shri P.C. Wadhwa, I.P.S.
34. Shri Dalip Singh, I.P.S.
35. Shri A.C. Pushong, I.P.S.
36. Shri Jaswant Singh Bakshi, I.P.S.
37. Shri Parkash Chand, I.P.S. (Scheduled Caste).
38. Shri Brijinder Singh, I.P.S.
39. Shri Manmohan Singh, I.P.S.
40. Shri Dharam Singh, I.P.S.
41. Shri I.M. Mahajan, I.P.S.
42. Shri Avinash Chander, I.P.S.
43. Shri V.K. Kalia, I.P.S.
44. Shri Inderjit Verma, I.P.S.
45. Shri Baljit Rai Sud, I.P.S.
46. Shri Bakhtawar Singh, I.P.S.
47. Shri M.K. Luthra, I.P.S.
48. Shri Harpal Singh, I.P.S.
49. Shri V.S. Seigell, I.P.S.
50. Shri C. K. Sawhney, I.P.S.
51. Shri Daljit Singh, I.P.S.
52. Shri Gurbhagat Singh, I.P.S.

53. Shri M.S. Bawa, I.P.S.
54. Shri Inderjit Singh Sodhi, I.P.S.
55. Shri Baljit Singh Dhaliwal, I.P.S.
56. Shri Krishan Kumar, I.P.S.
57. Shri D.D. Kashyap, I.P.S. (Scheduled Caste).
58. Shri M.L. Bhanot, I.P.S.
59. Shri G.S. Mandar, I.P.S.
60. Shri P.S. Shukla, I.P.S.
61. Shri K.L. Dewan, I.P.S.
62. Shri H.R. Swan, I.P.S. (Scheduled Caste).
63. Shri P.S. Bhinder, I.P.S.
64. Shri J.S. Anand, I.P.S.
65. Shri S.S. Brar, I.P.S.
66. Shri Balbir Singh, I.P.S.
67. Shri K.K. Zutshi, I.P.S.
68. Shri H.C. Jatav, I.P.S. (Scheduled Caste).
69. Shri Kalyan Rudra, I.P.S.
70. Shri Rattan Lal, I.P.S. (Scheduled Caste).
71. Shri H.S. Sekhon, I.P.S.
72. Shri R.R. Singh, I.P.S. (Seheduled Caste).
73. Shri Surjit Singh, I.P.S.
74. Shri P.S. Hura, I.P.S.
75. Shr Lachhman Dass, I.P.S. (Scheduled Caste).
76. Shri J.P. Atray, I.P.S.
77. Shri Inderjit Singh Bindra, I.P.S.
78. Shri Ramesh Sehgal, I.P.S.
79. Shri Ramesh Chander Sharma, I.P.S.
80. Shri Sube Singh, I.P.S. (Scheduled Caste).
81. Shri Lekh Ra m Bhagat, I.P.S. (Scheduled Caste).
82. Shri Ram Sarup, I.P.S.
83. Shri Surinder Nath, I.P.S.
84. Shri Shiv Dass, I.P.S.
85. Shri Amar Singh, I.P.S.
86. Shri Sukhdev Singh, Palta, I.P.S.
87. Shri Tarlok Singh, I.P.S.
88. Shri B.S. Verma, I.P.S.
89. Shri S.R. Sharma, I.P.S.
90. Shri R.L. Wadhwa, I.P.S.
91. Shri V.K. Wadhwa, I.P.S.
92. Shri J.C. Jogoi, I.P.S..
93. Shri Budh Ram, I.P.S. (Scheduled Caste).
94. Shri Sarabjit Singh, I.P.S.
95. Shri Rajendra Prashad Rai, I.P.S.
96. Shri Swadesh Kumar, I.P.S.
97. Shri Shambhu Partap Singh Rathore, I.P.S.
98. Shri Chaman Lal Bains (Scheduled Caste).

Resolution passed by the Panchayat Samiti, Dhuri, district Sangrur

***8836. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the reasons, if any, for which the resolution adopted by the Panchayat Samiti, Dhuri, district Sangrur regarding the Professional Tax in the year 1963 has not been accepted so far ;

(b) whether the Development Department has any objections to the acceptance of the said resolution ; if so, the nature thereof ; if not, whether it has been communicated to the said Samiti, but it has not been communicated, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh : (a) The exemption limit of income for the levy of Professional Tax had been proposed by the Panchayat Samiti Dhuri to be Rs 1,000 per annum instead of Rs 400 prescribed in the schedule

of rates for this tax to be followed by all the Local Bodies in the State. It was for this reason that its resolution has not been accepted.

(b) Yes. The proposed schedule of rates of professional tax was not in conformity with the uniform schedule of rates approved by Government. The Samiti has been advised to reconsider the issues.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਘਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਰਖੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿਘ ਭੌਰਾ : ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ?

(No reply)

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਲਗਾਏ, ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ? ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਇਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੰਨਫਾਰਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ?

ਮਤਰੀ : ਡੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਸੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या सरकार इस लिमिट को बढ़ाने के लिये तैयार है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Restrictons imposed on Sarpanches for withdrawing amount from the Banks

***9840. Shri Babu Dayal Sharma** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether Government is aware of the fact

[Shri Babu Dayal Sharma]

that the Block Development and Panchayat Officers have imposed arestriction on the rights of the Sarpanches to withdraw money from the Bank accounts of the Panchayats without attestation by the Block Development and Panchayat Officers concerned on the resolution of the Panchayats to this effect ; if so, the reasons therefor

Sardar Darbara Singh : Yes. Some Block Development and Panchayat Officers in the State had imposed restrictions in order to ensure proper control and supervision. All Block Development and Panchayat Officers in the State had been directed to withdraw such instructions.

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इस तरह बी. डी. ग्रो. के ग्रटैस्ट करने के ग्रार्डर से दिक्कत पेश नहीं ग्राती है ?

मंत्री : वह ग्रार्डर तो ग्रब विदड्रा हो गया है ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਲੀਸੀ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ।

Grants received by the Sarpanch of Village Panchayat Karela, Tehsil Jind

***9720. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Sarpanch of village Kerala, tehsil Jind, who is also the chairman of the Panchayat Samiti Jind, received the following grants from the B.D.P.O., Jind ;

Rs 250 for community centre on 31st March, 1965.
Rs 200 for Children's park on 31st March, 1965.
Rs 100 for young farmer's club.
Rs 150 for buffalo-bull on 27th February, 1965.
Rs 2,000 for School buildnng on 31st March, 1965.
Rs 2,000 for extension of School building.
Rs 1,000 for Panchayat Ghar on 17th July, 1965.
Rs 100 for library books on 13th July, 1965.

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the grants received by the said Sarpanch have been utilised for the purposes for which these were sanctioned ; if not, the reasons therefor and the action proposed to be taken against him ;

(c) whether the amount of grants or any part thereof received by the said Sarpanch is lying in his personal custody or has been deposited in the bank in the account of the said village Panchayat ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) & (c) (i) Materials for Community Centre have been purchased.

(ii) Grant of Childrens' park is still to be utilised.

(iii) Sports materials have been purchased.

(iv) Buffalo bull has been purchased.

(v) & (vi) Bricks and cement against the grant of Rs 4,000 have been purchased for the construction of school building.

(vii) Bricks have been purchased for the construction of Panchayat Ghar.

(viii) Books for Library have been purchased.

According to the Cash Book of the Panchayat the Panchayat is still under debt of Rs 3,933.41 and Rs 11.70 is deposited in the Bank. The matter is being looked into and action will be taken on the basis of the facts revealed.

चौधरी दल सिंह : वज़ीर साहिब ने बताया है कि 1965 में जो 200 रुपए की पार्क के लिए ग्रांट मिली थी वह यूटीलाइज़ नहीं हुई है और साथ ही यह भी बताया है कि बैंक में सिर्फ 11.70 रुपए जमा हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 1965 से लेकर अब तक सरपंच ने इतना रुपया खर्च न करके अपने पास रखा हुआ है क्या उस के खिलाफ ऐक्शन लेंगे या नहीं ?

मंत्री : अर्ज़ यह है कि जो सवाल किया उसका जो जवाब दिया गया है वह इग्ज़्लिसिट है।

चौधरी दल सिंह : सवाल के जवाब में बताया गया है कि सरपंच ने पंचायत के लिये 3993.41 रुपए का कर्ज़ ले रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सरपंच सरकार की मंज़ूरी लिए बगैर कर्ज़ लेकर पंचायत पर खर्च कर सकता है ?

मन्त्री : नार्मली ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस सरपंच ने पंचायत से कर्ज़ा लेने की मंज़ूरी ली होगी तो उसे उस के खर्च का हिसाब बाकायदा रखना होगा।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस सरपंच ने वह कर्ज़ा किसी बैंक में रखा था या अपने पास ही रखा ?

मन्त्री : मेरे पास यह इन्फार्मेशन नहीं है। वैसे तो इसी बात की इनक्वायरी हो रही है कि उस ने उस पैसे को कैसे यूटेलाइज़ किया और क्या उस ने पंचायत से कर्ज़े के लिए मनज़ूरी है या नहीं।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि उस सरपंच ने कर्ज़ पर लिया गया स्कूल के अपग्रेड करने के लिये खर्च किया और इस में ग़बन की कोई बात नहीं है ?

मन्त्री : मैं ने पहले कहा कि अगर उस सरपंच ने पंचायत से कर्ज़ा लेने की मंज़ूरी है तो ठीक नहीं तो जो कुछ भी उस ने खर्च किया तो वह उस की अपनी जिम्मेदारी होगी। इस के लिये पता किया जा रहा है।

चौधरी दल सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि एस. डी. ओ., जींद ने इस केस की इंक्वायरी की और उसने अपनी रिपोर्ट डी. सी. को भेजी। क्या यह सच है कि उस अफसर ने उस सरपंच को सस्पैंड करने की सिफारिश की क्योंकि उस रिपोर्ट में रुपया मिसयूज़ करने की बात साबित हो चुकी।

मंत्री : इस के लिए असिस्टैंट डायरैक्टर पंचायत ने इन्क्वायरी की और वह इन्क्वायरी सरकार के विचाराधीन है।

Applications for Tube-well connections received by the Line Superintendent, Jhoju, tehsil Charkhi Dadri, district Mohindragarh

***9620. Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of applicaions received in the office of the Line Superintendent, Jhoju, tehsil Charkhi Dadri, district Mohindragarh, from the residents of village Mandola, tehsil Charkhi Dadri, district Mahendragarh for providing electric connections for tubewells together with the date of each such application ;

(b) the distance at which the said village is situated from the 11K. Line together with the reasons for not giving the said connections so far ?

Chaudhri Rizak Ram : (a) 3, two dated 22nd December, 1965 and one dated 5th January, 1966.

(b) 4,000 (feet).

The work of giving connections is in progress.

श्री बनवारी लाल : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सवाल "बी" के जवाब देते हुए बताया है कि 4 हज़ार फुट। क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कुनेक्शन मैटीरियल की कमी के कारण नहीं दिए गए या और कोई कारण है ?

मंत्री : इस के लिये 22 दिसम्बर 1965 और 5 जनवरी, 1966 को दरखास्तें आई थीं। वहां पर कुनैक्शन जल्दी ही दिए जाने की कोशिश की जाएगी।

Tours conducted by B.D./P.O., Lehragara, district Sangrur

***9800. (1) Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal**
(2) Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the details of the tour programme of the Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, district Sangrur, during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1965 ;

(b) whether the said officer prepares his tour programmes in consultion with the Chairman, Block Samiti or infoms him about his programee ;

(c) the number of tours referred to in part (a) above in respect of which the Chairman referred to in part (b) above was consulted or informed together with the number of cases in which this was not done ?

Sardar Darbara Singh : (a) The details of the tour programme are laid on the Table of the House.

(b) The Block Development and Panchayat Officer informed the Chairman of his tour programme.

(c) The Chairman was informed in every case.

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer. Lehragaga, Sangrur for the month of January, 1965

Serial No.	Date	From	To	Purpose
1	5th January, 1965 ..	Lehragaga	Sangrur	To attend the meeting and stay at Sangrur
2	6th January, 1965 ..	Sangrur	Do	To attend the D.A.O. meeting in connection with Agricultural Production
3	11th January, 1965 ..	Lehagaga	Do	To get the reharsal regarding Gurdwara Election
4	16th January, 1965 ..	Do	Sangatpura	To attend the Gurdwara Election
5	17th January, 1965 ..	Sangatpura	Lehragaga	Ditto
6	21st January, 1965 ..	Lehragaga	Ludhiana	Government orders
7	22nd January, 1965 ..	Ludhiana	Do	Ditto
8	29th January, 1965 ..	Lehragaga	Sangrur	Meeting with D.A.O., Sangrur

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga for the month of February, 1965

Serial No.	Date	From	To	Purpose
1	1st February, 1965 ..	Lehragaga	Alampur and back	Development Works
2	3rd February, 1965 ..	Do	Kahi, Roreala	Ditto
3	5th February, 1965 ..	Do	Ramagarh	Ditto
4	7th February, 1965 ..	Do	Khai, Jhloor	Inspection of Panchayat and Development work
5	10th February, 1965 ..	Do	Gaga Sangatpura	Ditto
6	15th February, 1965 ..	Do	Changaliwala	Development work
7	18th February, 1965 ..	Do	Arkabas, Khokar	Agricultural Production
8	22nd February, 1965 ..	Do	Rampura, Jawaharwala	Ditto
9	28th February, 1965 ..	Do	Ghural Kalan	Seed Farm

[Home and Development Officer]

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga for the month of March, 1965

Serial No.	Date	From	To	Purpose
1	5th March, 1965 ..	Lehragaga	Gurney, Rampura and back	Agriculture work
2	7th March, 1965 ..	Do	Khai, Ghorenab	Ditto
3	10th March, 1965 ..	Do	Arkabas, Changaliwal	Ditto
4	15th March, 1965 ..	Do	Alsishr, Chotian	Ditto
5	18th March, 1965 ..	Do	Gurney and back	Ditto
6	20th March, 1965 ..	Do	Gobindpura, Jawarwala	Inspection of Drain work
7	22nd March, 1965 ..	Do	Sangatpura	Drain work
8	26th March, 1965 ..	Do	Ladla	School building
9	28th March, 1965 ..	Do	Khokar	Development work
10	31st March, 1965 ..	Do	Almpur	Ditto

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, of April, 1965

Serial No.	Date		Time	Comp-leted	From	To	Mileage	Purpose
1	21st April, 1965	..	12·30	21·00	Lehragaga	Chotian, Moonak, Bangan, Bhunder, Bhani, Surjan, Bhani and back	70	Inspection of construction work of Banga and Agri. culture work
2	22nd April, 1965	..	12·00	21·30	Do	Ghural Khurd, Moonak, Surjan Bhain, Chural Khurd, stay at Chural Farm	38	Panchayat Inspection Work and Cinema Shows
3	23rd April, 1965	..	6.00	7·00	Chural Seed Farm	Lehragaga	14	Ditto
4	23rd April, 1965	..	1.00	9·15	Lehragaga	Ramgarh Sekhubas Ghore Nab	20	Drain work
5	26th April, 1965	..	11. 20	21·00	Do	Nowan Goan, Badalgarh	72	C., I disposal at Chural Kalan and T.C. Retirer at Moonak
6	27th April, 1965	..	11.30	20·00	Do	Moonak, Salaimgarh Moonak	43	Inspection of Panchayat
7	28th April, 1965	..	10·45	19. 30	Do	Bhaikipishore Nagla	23	Ditto
8	30th April, 1965	..	12. 00	21.00	Do	Khokrar, Alampur, Alisher	27	Local Development Works

[Home and Development Minister]

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga for the month of May, 1965

Serial No.	Date		Time	Completed	From	To	Mileage	Purpose
1	3rd May, 1965	..	6.00	9.00	Lehragaga	Gaga Ramagarh	14	Drain work
2	4th May, 1965	..	12.15	10.00	Do	Moonak, Chural Kalan	42	Seed Farm checked
3	7th May, 1965	..	3·00	1.30	Do	Sunam, Sangrur Karian, Ladbanjara, Khurd, Sangrur	138	Survey of drain work with G.A.
4	9th May, 1965	..	4.00	6.30	Do	Ramgarh, Selhubas, Bhaikipishore stay	13	Ramgarh Co-operative Society Work
5	10th May, 1965	..	6.00	6.30	Bhaikipishore	Lehragaga	10	Ditto
6	19th May, 1965	..	11.30	9.00	Lehregage	Nagla Alampur	24	Excavation of Village Link Drain
7	20th May, 1965	..	7·00	8·30	Do	Nagla, Ladbanjara Khurd	46	Ditto
8	21st May, 1965	..	7.00	8.00	Do	Nagla, Ladbanjara Khurd, Bangamn Moonak	74	Ditto
9	22nd May, 1965	..	11.30	9·00	Do	Ramgarh Sekhubas	25	Ditto
10	23rd May, 1965	..	11·00	9·30	Do	Ghore Nan, Nagla	14	Ditto
11	24th May, 1965	..	12·00	9.00	Do	Moonak, Ladbanjara Khurd	67	Ditto
12	25th May, 1965	..	2.00	6.00	Do	Rampura and Jawaharwala	16	Digging of drain
13	26th May, 1965	..	1·00	2.00	Do	Nadampur, Ladbanjara Khai, Kheri Nagla, Kaurian, Sangrur	135	With G.A., Sangrur
14	27th May, 1965	..	4.30	6.00	Do	Bhaikipishore stay	10	Regarding utilization grants of pray ground
15	28th May, 1965	..	7·00	8.00	Bhaikipishore	Lehragaga	10	Ditto

16	23th May, 1965	..	8. 30	10·00	Lehragaga	Jawaharwala, Lehragaga	16	Digging of Drain
17	28th May, 1965	..	11.40	9·00	Do	Alampur, Chural Kalan, Moonak	28	Development Work
18	29th May, 1965	..	11·00	9.30	Do	Chural Moonak, Alisher	39	Tax and Seed Farm Work
19	30th May, 1965	..	10. 00	7.00	Do	Ramgarh, Chora Nab, Nagla	25	Excavation of Drain
20	31st May, 1965	..	4. 00	6. 30	Do	Ladbanjara Kuhrd, Kakuwala, stay at Ladbanjara	25	Ditto

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, for the month of June, 1965

Serial No.	Date	Time	Completed	From		To	Mileage	Purpose
1	1st June, 1965	..	7.00	9.30	Ladbanjara Khurd	Kakuwala, Ladbanjara, Khetla	34	Development Work
2	1st June, 1965	..	12.00	5.30	Lehragaga	Chural Kalan	31	Inspection of Seed Farm
3	2nd June, 1965	..	11.00	8.00	Do	Ladbanjara	36	Excavation of Drain
4	3rd June, 1965	..	10.00	11.00	Do	Rampura, Nagla, Ladbanjara, Kakuwala, Sangrur	20	Excavation of Drain with D.D.P.O., Sangrur
5	4th June, 1965	..	9.30	6.00	Do	Shaiheri, Ladbanjara, Khetla and stay Bhaikipishore	48	Ditto
6	5th June, 1965	..	8.00	9·00	Bhaikipishore	Sekhubasm Ramgarh	11	Development Work
7	5th June, 1965	..	4.00	7.00	Lehragaga	Ladal, Hary, stay at Haryoo	11	Ditto
8	6th June, 1965	..	9.00	10.00	Haryoo	Lehragaga	11	Execution of Plan
9	8th June, 1965	..	11.00	10.00	Lehragaga	Ramgarh, Ladbanjara, Kanuwala, Khetla	60	Ditto
10	10th June, 1965	..	6·00	3·00	Do	Shaiher, Ladbanjara Khetla	70	Ditto
11	10th June, 1965	..	8·00	10.00	Do	Khetla, Nagla, Ramgarh	73	Ditto

[Home and Development Minister]

Serial No.	Date		Time	Completed	From	To	Mileage	Purpose
12	16th June, 1965	..	6.00	9.00	Lehragaga	Sekhubas, Ghore Nab	20	Execution of Plan
13	17th June, 1965	..	8·00	2.00	Do	Ghore Nab, Sekhubas, Rore Wala, Shadihirr, Ladbanjara, Kakuwala, Khetla, Sunam	16	Excavation of Drain with S.D.O. (C)
14	18th June, 1965	..	5.00	21.00	Do	Sunam, Bhirba, Khetla, Kanwala, Ladbanjara	63	Alignment of Link Drain with N.T., Sunam
15	24th June, 1965	..	9.00	2.00	Do	Sekhubas, Chorenab, Chotian, Sangrur	126	Inspection of drain work
16	26th June, 1965	..	4·00	5·00	Do	Sekhubas, Ghorenab, stay at Ghorenab	12	Procurement of wheat seed
17	27th June, 1965	..	4.00	6·00		Sekhubasm, Nagla, stay at Pishore	16	Construction of school building
18	28th June, 1965	..	6.00	7.00	Pishore	Lehragaga	10	Ditto
19	28th June, 1965	..	9·00	1.00	Lehragaga	Rorewala	20	Excavation of drain
20	29th June, 1965	..	7·00	10·00	Do	Chural Kalan, Moonak, stay Chural Kalan	30	Development Work
21	30th June, 1965	..	6·00	7·00	Chural Khurd	Lehragaga back at H/Q	10	Ditto

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, for July, 1965

Serial No.	Date		Time	Completed	From	To	Mileage	Purpose
1	3rd July, 1965	..	9.00	12.00	Lehragaga	Harigarh	30	Inspection of Drain XEN, Patisl
2	Ditto	..	9.00	10.00	Do	Sekhubas, stay Pishore	15	Inspection of school building and flood

3	4th July, 1965	..	10.00	11.00	Pishore	Lehragaga	10	Ditto
4	4th July, 1965	..	4.00	6.00	Lehragaga	Ghorenab, stay at Ladbanjara	20	Drain Work
5	5th July, 1965	..	6·00	8.00	Ladbanjara	Lehragaga	18	Ditto
6	7th July, 1965	..	8·00	8·00	Lehragaga	Shadiheri, Rorewala, Ghorenab	28	Ditto
7	8th July, 1965	..	10·0	7·0	horenab	Bokhar Kalan, Lehragaga	27	Ditto
8	8th July, 1965	..	1.	6·00	Lehragaga	Pishore sta y at Khetla	36	Ditto
9	9th July, 1965	..	9·00	11·00	Khetla	Lehragaga	28	Ditto
10	9th July, 1965	..	1·00	9·00	Lehragaga	Alampur Chotian Lehal Khurd, Ghorenab, Ramgarh Sahdiheri	56	Construction of Ring Band
11	10th July, 1965	..	8·00	11·00	Ladbanjara	Kakuwala stay at Ladbanjara Raidhiran	23	Ditto
12	10th July, 1965	..	3.00	10·00	Lehgagaga	Chotian Moonak, Chotian and back Moonak	78	Ditto
13	11th July, 1965	..	4.00	10.00	Moonak	Chural Khurd	78	Ditto
14	12th July, 1965	..	10·00	8·00	Chural Khurd	Chotian, Jakhal, Moonak, Bokhra Kalan stay at Chotian	39	Ditto
15	13th July, 1965	..	10.00	2.00	Chotian	Ghorenab, Chotian, Chural Kalan	15	Ditto

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, for August, 1965

Serial No.	Date		Time	Comp-leted	From	To	Mileage	Purpose
1	2nd August, 1965	..	10·00	6·00	Sangrur	Lehragaga Rorewala, Ladbanjara, Ramgarh, Jhlor	68	Drain work
2	3rd August, 1965	..	11.00	9·00	Lehragaga	Ramgarh, Ghorenab, Sekhubas, Nagla, Khokar, Statu, Pishore	200	Compost work
3	5th August, 1965	..	1·00	9·00	Do	Nagla, Khokar, Statu, Pishore	20	Drain work

[Home and Development Minister]

Serial No.	Date		Time	Completed	From	To	Mileage	Purpose
4	6th August, 1965	..	8.00	10.00	Pishore	Ghorenab, Rorewala	18	Drain work
5	8th August, 1965	..	9.00	6.00	Lehragaga	Ghorenab, Pishore, Rorewala	35	Development work
6	9th August, 1965	..	10.00	9.00	Do	Sekhubam Pishore, Nagala	25	Ditto
7	10th August, 1965	..	1.30	10.00	Do	Arkbas, Nagla, Ghoreban	19	School building
8	11th August, 1965	..	12.00	9.00	Do	Ghural Kalan, Moonak	39	Ditto
9	12th August, 1965	..	4.00	5.00	Do	Bokhra Kalan	7	Ditto
10	13th August, 1965	..	8.00	9.00	Bokhra Kalan	Lehragaga via Lehal Khurd	9	
11	17th August, 1965	..		6.00	Lehragaga	Nagla	11	
12	19th August, 1965	..	2.00	7.00	Do	Banga, stay at Chural Khurd	56	Construction of School
13	20th August, 1965	..	8.00	10.00	Chural Khurd	Bokhar, Ghoranab	18	Ditto
14	21st August, 1965	..	1.00	4.00	Lehragaga	Sekhubas, Pishore	23	
15	22nd August, 1965	..	1.30	7.00	Do	Ramgarh, Sekhubas, Sekhuba	12	
16	25th August, 1965	..	12.30	8.00	Do	Sangatpura, stay at Haryoo	25	
17	26th August, 1965	..	7.00	4.39	Haryoo	Lehragaga	4	
18	26th August, 1965	..	1.30	9.00	Lehragaga	Ghorenab, Lehragaga, Sumam	48	
19	30th August, 1965	..	2.00	8.00	Do	Chural Kalan	45	Construction of ringband
20	31st August, 1965	..	9.00	11.00	Do	Chotian, Sekhubas, Ghorenab, stay at Rorewala	40	

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, for the month of September, 1965

Serial No.	Date	Time	Completed	From	To	Mileage	Purpose
1	1st September, 1965 ..	9.00	12.00	Rorewala	Sekhubas, Nangal, Ghorenab, stay at Rorewala	40	Drain work
2	2nd September, 1965 ..	6.00	7.00	Do	Lehragaga	10	Ditto
3	3rd September, 1965 ..	11.30	2.00	Lehragaga	Moonak, stay at Moonak	38	Ditto
4	4th Septmber, 1965 ..	4.00	5.00	Moonak	Ghoranab	12	Ditto
5	6th September, 1965 ..	12.00	10.00	Lehragaga	Chural Kalan, Bangan, Dhurabahni, Surjan Bhai ni	50	Ditto
6	8th Sep'ember, 1965 ..	3.00	11.00	Do	Rampura, Jawaharwala, Kakuwala	30	Thikiri Para
7	9th September, 1965 ..	2.00	9.00	Do	Gurney, Bokhra Kalan, Ghorenab, Rorewala, Bhipishore, Nagla	35	Ditto
8	10th September, 1965 ..	8.00	9.00	Do	Khai, Ramgarh, Ghorenab, Rorawala, Harigarh, Pishore, Nagla, Gaga, Ladal	55	Ditto
9	11th September, 1965 ..	8.00	9.00	Do	Rampura, Gobindpura, Kotra, Lehal, Ghural Khurd, Dasks, Ratt Khera Phulra, Fatehgarh, Haryoo, Gimani, Sangatpura, Changaliwala	70	Ditto Ditto
10	12th September, 1965 ..	11.30	4.00	Do	Nagla, Ramgarh	15	Ditto
11	13th Sept:mber, 1965 ..	8.30	11.30	Do	Rokhra Kalan, Bakohra Khurd,	19	Ditto
12	14th September, 1965 ..	10.00	8.00	Do	Ramgarh, Ghorenab, Rorewala	24	Defence Fund Collections
13	15th September, 1965 ..	10.00	7.00	Do	Alisher, Monnak, Surjabnai, Badalgarh, Bangan, Bushera, stay at Chural Kalan	50	Ditto
14	16th September, 1965 ..	7.00	8.00	Chural Kalan	Moonak, Slaimgarh, Hamirgarh, Bushera, Rajalheri, Kalbanjra, Ror wala	48	Ditto
15	17th September, 1965 ..	8.00	7.00	Lehragaga	Rorewala, Khetla. Ladla, Ladbanjar Chural Kalan, Rampura	60	Ditto

[Home and Development Minister]

Serial No.	Date	Time	Time completed	From	To	Mileage	Purpose
16	18th September, 1965 ..	7.30	9.00	Lehragaga	Sangrur	30	Jeep Service
17	20th September, 1965 ..	8·00	9.00	Do	Ghorenab, Hamirgarh, Bhundr Bhani, Moonak, Surjan Bhai, Ghorenab	80	Defence Fund
18	21st September, 1965 ..	9·00	8.00	Do	Bokhra Khurd, Kalan, Balran stay at Bushera	35	Ditto
19	22nd September, 1965 ..	7.00	8·00	Bushera	Badalgarh, Bangan, Mian Singhwala stay at Moonak	65	Ditto
20	23rd September, 1965 ..	8·00	7.00	Moonak ..	Delha, Bokhar Kala stay Ghorenab	48	Ditto
21	24th September, 1965 ..	7.00	9·00	Ghorenab	Moonak, Slaimgarh, Badalgarh	78	Ditto
22	25th September, 1965 ..	11.00	10·00	Legragaga	Sangatpura, Ratta Khera	34	Ditto
23	26th September, 1965 ..	2.00	7.00	Do	Rampura, Jawaharala	10	Ditto
24	27th September, 1965 ...	8.00	9.00	Do	Sangrur	58	Ditto
25	28th September, 1965 ..	11.00	7.00	Do	Rorewala, Dhindsa, stay at Rokhra Kalan	32	Ditto
26	29th September, 1965 ...	8.00	9·00	Bokhra Kalan,	Lehragaga	10	Ditto
27	30th September, 1965 ..	3.30	7·00	Lehragaga	Chural Khurd stay at Moonak	30	Ditto

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, for October, 1965

Serial No.	Date	comp-leted		From	To	Mileage	Purpose
1	1st October, 1965 ..	8·00	9 00	Moonak	Lehragaga	27	Defence Fund
2	3rd October, 1965 ..	1·30	2·00	Lehragaga	Ladbanjara stay at Khetla	25	Ditto

3	4th October, 1965	..	9·00	10.00	Khetla	Lehragaga	23	Ditto
4	6th October, 1965	..	2·00	6.00	Lehragaga	Shaiheri stay at Ladbanjara	30	Ditto
5	7th October, 1965	..	8.00	9·30	Ladbanjra	Lehragaga	22	Ditto
6	8th October, 1965	..	5·00	8·00	Lehragaga	Sunam stay at Rattakhera	35	Ditto
7	9th October, 1965	..	9.00	4.00	Rattakhera	Butal Kalan	25	Ditto
8	11th October, 1965	..	2·00	7.00	Lehragaga	Nagla Ghorenab, Rorewala stay at Pishore	35	Ditto
9	12th October, 1965	..	9.00	11.00	Pishore	Lehragaga	10	Ditto
10	13th October, 1965	..	11.30	8.30	Lehragaga	Moonak Papra, Bhutal, Dhindsa	55	Ditto
11	14th October, 1965	..	12·30	9·00	Do	Sangatpura, Rattakhera, Haryoo	35	Ditto
12	15th October, 1965	..	3·00	6·00	Do	Ghorenab, Rorewala, stay at Khetla	28	Ditto
13	16th October, 1965	..	4·00	6.00	Khetla	Chural Kalan, Khurd, Vushera stay at Moonak	75	Ditto
14	17th October, 1965	..	7.00	8.30	Moonak	Lehragaga	22	Ditto
15	18th October, 1965	..	2·00	5.30	Lehragaga	Ghorenab, Ladbajra	36	Ditto
16	20th October, 1965	..	3.00	9·00	Do	Bhikipishore, Khetal, Ladbanjara	51	Inspection of Panchayat
17	21st October, 1965	..	4·00	8·00	Do	Ramgarh, Sekhubas, Ghorenab, stay at Ladbanjra	53	To give the demarcation
18	22nd October, 1965	..	8.00	6·00	Ladbanjra	Lehragaga, Ladal, stay at Haryoo	41	Ditto
19	23rd October, 1965	..	7·00	8·00	Haryoo	Lehragaga	10	Ditto
20	26th October, 1965	..	5.00	6·00	Lehragaga	Moonak	20	Defence duty
21	27th October, 1965	..	9.00	10.00	Moonak	Balran, Chotian	23	Ditto

[Home and Development Minister]

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga (Sangrur) for November, 1965

Serial No.	Date	Time	Time completed	From	To	Mileage	Purpose
1	12th November, 1965 ..	9·30	5·00	Lehragaga	Moonak, Bushera, Doolian, Hamirgarh	58	Small Saving
2	13th November, 1965 ..	3·00	6·00	Do	Nagla, Sekhubas	12	..
3	14th Novemher, 1965 ..	9·00	7·00	Do	Sunam, Ghorenab	43	Small Saving
4	16th November, 1965 ..	1·30	5·00	Do	Kalia, Balran stay at Bokhra Kalan	45	Small Saving. Inspection of Panchayat
5	17th November, 1965 ..	9·00	6·00	Bokhra Kalan	Lehragaga, Ladal, Sangatpura, stay at Khetla	61	Small Saving
6	18th November, 1965 ..	6·00	8.00	Khetla	Lehragaga	23	Ditto
7	20th November, 1965 ..	3.00	7·00	Lehragaga	Ghorenab, Gurney, Lehal, Sangat, Jawharwala	25	Demonstration of plots
8	21st November, 1965 ..	1·30	8·00	Do	Chural Kalan, Balran, Lehal Kalan, Ladbanjara, Khetla	75	Inspection of seed arm and development work
9	22nd November, 1965 ..	3. 00	7·00	Do	Sekhubas, Ghorenab, Pishore	25	Agriculture Production
10	25th November, 1965 ..	31·00	8·00	Do	Chural Kalan, Moonak, Hamirgarh	46	Ditto
11	26th November, 1965 ...	2·00	5.30	Do	Chural Kalan, Bokhra Kalan	80	Ditto
12	27th November, 1965 ...	1.30	7·00	Do	Nawaon Goan	64	Development work

Tour Programme of Shri Kuldip Singh, Block Development and Panchayat Officer, Lehragaga, for December, 1965

Serial No.	Date	Time	Time completed	From	To	Mileage	Purpose
1	7th December, 1965 ..	9.00	6.00	Lehragaga	Sangrur, Pishore	70	Small Saving
2	13th December, 1965 ..	1.30	9.00	Do	Chural Kalan, Bokhara Kalan	57	Inspection of Seed Farm
3	14th December, 1965 ..	12.00	8.00	Do	Badalgarh, Bushera	52	Small Saving
4	15th December, 1965 ..	2.00	5.30	Do	Bhaikipishore, Gurney, Ghorenab	23	Ditto
5	16th December, 1965 ..	1.30	7.00	Do	Bhaikipishore, Chural Kalan	48	Ditto
6	22nd December, 1965 ..	1.30	6.00	Do	Pishore	20	Ditto
7	23rd December, 1965 ..	3.00	7.00	Do	Chural Kalan, Bokhra Kalan	35	Ditto
8	24th December, 1965 ..	11.30	5.00	Do	Bokhra Kalan, Chotian, Chural Kalan	38	Ditto
9	28th December, 1965 ..	11.00	5.30	Do	Ladbanjara stay at Khetla	28	Ditto
10	29th December, 1965 ..	9.00	10.30	Khetla	Lehragaga	23	Ditto
11	30th December, 1965 ..	4.00	7·00	Lehragaga	Chural Kalan Petrol Pump, Bushera	64	Agricultural Production
12	31st December, 1965 ..	3.30	8·00	Do	Bhaikipishore, Sunam	50	Ditto

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓ., ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਥੇ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਟੂਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 6, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓ., ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ।

Chaudhri Darshan Singh : Will the Home Minister be pleased to state that in case the B.D. & P.O. is called by the Deputy Commissioner to attend some official meeting is it mandatory for the B.D. & P.O. to ask for the permission of the Chairman of the Samiti ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਆਪਣੇ ਇੰਮੀਜੀਏਟ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ 6, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3/4 ਬਾਰ ਮੀਟਿਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ 5, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੋਂ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।

कामरेड राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने सवाल का जवाब देते हुए फरमाया है कि नार्मली बी. डी. श्रो. अपने ब्लाक समिति के चेयरमैन से टूर प्रोग्राम की मनजूरी हासल करे। क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट के अन्दर दूसरे ब्लाक समितियों के चेयरमैनों ने बी. डी. ओ. के बरखिलाफ सरकार को रिप्रैजैंट किया कि वह उन से टूर प्रोग्राम फिक्सड करते समय मनजूरी नहीं लेता जैसा कि बी. डी. पी ओ., लहरा गागा, ज़िला संगरूर ने किया ?

मंत्री : मैं इस सवाल का जवाब श्राफ हैंड नहीं दे सकता हूं। सवाल के लिए सैपरेट नोटिस दरकार है।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ B.D.P.O., Lehra gaga, district Sangrur ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Not allowed.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Home and Development Minister if it is a fact that because of some tussle that is going on between the Chairmen of the Block Samitis and the B.D. &P.Os. the State Government has issued instructions to the Deputy Commissioners that they should write the confidential reports of the B.D. & P.O.s and not the Chairmen of the Block Samitis.

मंत्री : मैं इस वक्त जनरल सवाल का जवाब नहीं दे सकता।

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मेरी सबमिशन है कि कामरेड राम चन्द्र का सवाल ला एंड आर्डर के साथ सम्बन्ध रखता था। वह सवाल भी बहुत ही इम्पार्टेंट था। उस में एस.पी., करनाल के बारे में इन्फमशन कुलैक्ट करनी थी। यह ठीक है कि उस पर 3, 4 सप्लीमेंटरीज़ सवाल करने की आप ने इजाज़त दी। यह भी ठीक है कि उन में स सारी इन्फार्मेशन कुलैक्ट नहीं की जा सकी। इस लिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप ऐसे इम्पार्टेंट सवाल पर ज़्यादा सप्लीमेंटरी सवाल करने की इजाज़त दिया करें।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS PLACED ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Police Personnel posted for the protection of Ministers etc.

*9032. **Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number of Police personnel posted for the protection of each Minister, Minister of State and Deputy Minister during the period from 1st April, 1965, to date ;

(b) the total expenditure incurred by the Government on the salaries, allowances etc., of the said personnel during the said period ?

Sardar Darbara Singh : (a) 25 with C.M.; 19 with H.D.M.; 10 with E.M.; 6 each with F.M., T.E.M., P.W.M., P.L.G.M., R.M., I.M.P. C.H.M. W.J.M., H.M., M.E.P.L., D.M.F.S. and D.M.D.I.; One with M.A.H.A.; five with D.M.I.H., one as supervising officer.

(b) Rs. 1,41,243.81.

Sugar Quota given to Sugarcane Suppliers against each cart

*9628. **Shri Om Parkash Agnihotri** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is fact that the farmers who supplied sugarcane to the J.J. Sugar Mills, Phagwara, were granted some quota of sugar-against each cart of sugarcane supplied to the Mill during the 1964-65 crushing season ;

[Shri Om Parkash Agnihotri]

(b) whether the said quota is being granted during the 1965-66 crushing season as well ; if so, whether it is for the same quantity ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Under consideration.

Cement applied for by the Villagers of Sham Churasi, district Hoshiarpur

*9680. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any applications for Cement for use on the tube-wells were submitted by the villagers of Sham Churasi, district Hoshiarpur, to the Block Development and Panchayat Officer (S. Dhanwant Singh), Hoshiarpur, during the quarters ending 31st October, 1965 and 31st December, 1965 ; if so, the names of the said applicants together with the dates when they applied in each case ;

(b) whether any of the applications referred to in part (a) above endorsed by the Chief Minister and/or the Deputy Commissioner, Hoshiarpur ;

(c) whether any cement was actually issued to the said applicants if not, the reasons therefor ;

(d) whether any cement was issued to the persons who had applied after the submission of the applications by the villagers of Sham Churasi ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. A statement showing the names of the applicants together with the dates when they applied in each case is enclosed as Annexure 'A'.

(b) Yes. An application of Shri Gurnam Singh was endorsed by Deputy Commissioner, Hoshiarpur.

(d) No cement could be issued to Shri Gurnam Singh as the permits for all the stock at disposal had already been prepared when his application was received and no stock was left for further issue.

(d) Yes. Some of the persons, who applied after the submission of applications by the villagers of Sham Churasi, were issued cement because the latter had already been issued cement over and above their fixed quota.

ANNEXURE 'A'

Showing the names of the applicants together with the dates when they applied in each case.

Serial No.	Names of personnel	Date of application for cement	Cement issued
	Quarter ending 30*th September*, 1965		
1	Shi Surain Singh, son of Shri Ishar Dass	14-7-65	5 bags
2	Shri Surjit Singh, son of Pritam Singh ..	July, 1965	2 bags
3	Shri Jaswant Singh	29-7-65	Nil (Application not recommended by the President, Municipal Committee)

Serial No.	Names of personel	Date of application for cement	Cement issued
	Quarter ending 31st December, 1965		
1	Shri Dharam Pal, son of Ram Lal ..	16-10-65	2 bags
2	Shri Mani Singh, son of Basant Singh ..	16-10-65	10 bags
3	Shri Avtar Singh ..	15-10-65	10 bags
4	Shri Kulwant Singh ..	15-10-65	10 bags
5	Shri Sohan Singh ..	16-10-65	Rejected, as according to report of President, Municipal Committee he had already received sufficient cement
6	Shri Tilak Singh, son of Khushal Singh	16-10-65	5 bags
7	Shri Nirmal Singh, son of Har Singh ..	16-10-65	Rejected as no tubewell was found on verification
8	Shri Shiv Singh, son of Udham Singh ..	16-10-65	5 bags
9	Shri Charan Singh, Lambardar ..	16-10-65	5 bags
10	Shri Sohan Singh, son of Hakam Singh	16-10-65	Rejected by President, Municipal Committee
11	Shri Surjit Singh son of Pritam Singh ..	16-10-65	6 bags
12	Shr Niranjan Singh, son of Hira Singh ..	16-10-65	5 bags
13	Shri Surain Singh ..	27-11-65	5 bags
14	Shri Darshan Singh, son of Ujagar Singh	27-11-65	15 bags
15	Shri Mani Singh, son of Basant Singh ..	27-11-65	10 bags
16	Shri Ram Partap ..	27-11-65	5 bags
17	Shri Gurmit Singh ..	27-11-65	5 bags
18	Major Bhagat Singh ..	27-11-65	8 bags
19	Shri Bakhshish Singh ..	27-11-65	5 bags
20	Shri Kashmira Singh ..	27-11-65	5 bags
21	Shri Gian Chand ..	27-11-65	3 bags
22	Shri Amar Singh Retired Jamader ..	14-12-65	..
23	Shri Mewa Singh, son of Basant Singh ..	14-12-65	..
24	Shri Gurnam Singh ..	22-12-65	..

Use of Loud-speakers in district Sangrur

***8929. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the procedure laid down for obtaining sanction for use of loud-speakers by the political parties in distict Sangrur ;

(b) whether it is a fact that every political party has to get permission from the police for the purpose before getting final approval from the S.D.O. (Civil), if so. the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) The political party seeking permission to use loud-speaker is required to submit an application bearing a court fee stamp of the value prescribed under section 4(A) of the Punjab Instruments (Control of Noises) (Amendment) Act, 1960.

(b) No.

Jeep of Block Samiti, Palwal, district Gurgaon

***9870. Chaudhri Har Kishan :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the Jeep of the Block Samiti, Palwal, district Gurgaon, was given on hire to some official on any day(s) during the period from 1st January, 1965 todate, if so, the rate fixed per mile and the total amount realised on this account ;

(b) whether the permission of the Deputy Commissioner or the Sub-Divisional Officer, Palwal or any other authority was taken before giving the said Jeep on hire, if not, the reasons therefor and the name of the officer who gave the Jeep on hire ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. (i) The jeep was hired by Chairman, Panchayat Samiti, Palwal on 11th April, 1965. (ii) At the rate of 50 paise per mile, a sum of Rs 23 was realised.

(b) No. No prior permission was taken as there was no time on account of sudden death of the Chairman Zila Parishad, Gurgaon. However, the use of Jeep was allowed by Shri Karanti Kumar, the then Block Development and Panchayat Officer, Palwal.

Cement received by the Sarpanch of Village Panchayat Kerala, tehsil Jind

***9721. Chaudhri Dal Singh :** Will the Home and Development Minister be pleased to state—

(a) whether the Sarpanch of village Panchayat Kerala, tehsil Jind, received any quantity of cement for the construction and extension of school building and also for other purposes from the B.D.P.O. Jind ; if so, the number of cement bags received by the Sarpanch since his election ;

(b) whether the Sarpnach utilised the said cement for the purpose for which it was received ; if not, the action taken or proposed to be taken by the Government against him ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The Sarpanch received 150 bags of cement.

(b) Out of above quantity 120 bags including 10 received in charge from the previous panchayat are lying with the Sarpanch. 40 bagss have been utilised for the construction of drinking water well.

Loan given to Block Samitis in District Mohindergarh for agricultural purposes

***9621. Shri Banwari Lal:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that all the Block Samitis of district Mohindergarh requested for loans from the Government for agricultural purposes during the year 1965;

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, the list of such Block Samitis and the amount asked for by each;

(c) whether the loan was advanced to all the Samitis mentioned in the list referred to in part (b) above; if not, the reasons therefore?

Sardar Darbara Singh: (a) No. Only 5 out of the 8 Block Samitis of Mohindergarh District asked for loans for agricultural purposes during the year 1965.

		Rs
(b) (1) Ateli Nangal	..	10,00,000
(2) Narnaul	..	2,70,000
(3) Kanina	..	4,37,000
(4) Mohindergarh	..	8,00,000
(5) Dadri	..	3,95,000

(c) Yes. The loan was advanced to all the Samitis mentioned in part 'b' above.

Arrears of Reclaimed Land

***9812. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the State Government has appointed some special staff to realise the arrears from the peasants of Patiala district on account of the charges of reclamation of waste lands carried out over 12 years ago;

(b) whether it is a fact that in the past, the realisation of land reclamation charges from the peasants had been postponed because a high-powered Committee appointed by the Punjab Government had pointed out many defects in the Land reclamation work carried out during the regime of the former Pepsu Government;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the details of the defects pointed out by the said Committee;

(d) whether the said reclamation work has been done by the Government or by any private company/companies;

(e) if the work was done by private companies, whether the charges were paid to those companies, if so, the amount so paid to each of them;

(f) whether it is a fact that in the erstwhile Pepsu Vidhan Sabha some members criticised high officers of the erstwhile Pepsu Government and levelled allegations against them for the above said reclamation operations by the private companies;

(g) if the reply to part (f) be in the affirmative, whether any inquiry was made into those allegations, if so, the result thereof;

(h) the kind of land reclaimed by the said operations;

(i) whether Government has recently received any representations from the said peasants or from any organisation or Political

[Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal]

party for cancellation of orders passed for the realisation of the charges referred to in part (a) above, if so, the number of representations received and the name of the organisation/party from whom these have been received and the action taken thereon?

Sardar Darbara Singh: (a) Yes.

(b) No.

(c) Question does not arise.

(d) By private companies.

(e) (i) Rs 42,69,970 to M/S E.M. Allcock.

(ii) Rs 18,08,674 to M/S United Provinces Corporation.

(iii) Rs 76,907 to M/S Shivrattan G. Mohatta.

(f) Record is not available.

(g) Does not arise.

(h) Culturable Waste land.

(i) No.

Suspension of Sarpanch Shri Narsingh Dayal of Rehan Panchayat, tehsil Nurpur, district Kangra

***9033. Comrade Ram Chandra:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that on the report of enquiries held by a Divisional Officer, he recommended to the D.C. to suspend Surpanch, Shri Narsingh Dayal of Rehan Panchayat, tehsil Nurpur, district Kangra; if so, the dates when the said recommendation was issued and complied with;

(b) whether it is a fact that during that period the Home Minister again ordered an enquiry into the case by Ch. Dasondha Singh, Deputy Secretary, Development Department;

(c) the number of days for which the officer referred to in part (b) above stayed at (i) Indora and /or (ii) any other place in Nurpur tehsil in connection with the said enquiry;

(d) whether any intimation about the fresh enquiry referred to in part (b) was given to the complainants;

(e) whether it is a fact that the old foundation of former Girls School over which the Sarpanch had established his possession was dug in the presence of the said Deputy Secretary at Rehan;

(f) a copy of the report, if any, submitted by the Officer referred to in part (b) above be laid on the Table of the House?

Sardar Darbara Singh: A Statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) (i) The Deputy Commissioner, Kangra at Dharamsala was asked to take necessary action in the light of the report and the suggestions of the Assistant Director of Panchayats, Jullundur Division.

(ii) The reference was issued on 15th July, 1965.

(iii) Shri Narsingh Dayal Sarpanch, was, placed under suspension by the Deputy Commissioner, Kangra vide his orders dated 8th October, 1965, after observing the necessary formalities.

(b) The Deputy Secretary, Development I, was asked to hold enquiry on 20th October, 1965.

The Deputy Secretary, Development I, reached Indora in the late afternoon on 24th November, 1965 and left in the early morning on 27th November, 1965. He examined papers of the case at Indora on 25th November, 1965 and visited Village Reha on 26th November, 1965, for enquiry on the spot.

(d) Yes, through the Block Development and Panchayat Officer, Indora on 11th November, 1965.

(e) The back yard of the shop was dug up in the presence of the Deputy Secretary Development I.

(f) The report is under consideration of Government. It will not be in public interest to lay a copy of the report on the Table of the House.

Promotion of Head Clerks as Assistant Employment Officers

***9631. Shri Om Parkash Agnihotri:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number and names of the Head Clerks promoted as Assistant Employment Officers in the State during the years 1964 and 1965;

(b) the number and names of the Head Clerks whose cases for promotion as Assistant Employment Officers recommended by Director of Employment Exchanges are under the consideration of the Government and the time by which a final decision is likely to be taken in the matter?

Chaudhri Rizak Ram: (a) 1964—Three, namely, Sarvshri Daryao Singh, Mangal Singh and B.R. Khadotra.

1965 .. Nil

(b) Three Head Clerks, namely, Sarvshri V.D. Kanwar, Raman Singh and Kirpal Singh were recommended for promotion as Assistant Employment Officer against one vacancy only. The case is under consideration and will be decided shortly.

Expenditure incurred on Jeep No. PNC 5001, by the S.D.M. Malerkotla

***9143. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the expenditure incurred on jeep No. PNC 5001, by the S.D.M., Malerkotla, which he used for his tours, during the period from December, 1963 to October, 1964, has been debited to the Panchayat Samiti, Dhuri ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons for which the Panchayat Samiti, Dhuri had to pay the expenditure incurred on the said jeep ?

Sardar Darbara Singh : (a) Only to the extant of money expended in propulsion of the vehicle in the territorial jurisdiction of Panchayat Samtiti, Dhuri.

(b) As S.D.O. (Civil) used the jeep No. PNC 5001 in connection with development and agricultural production work during the period December, 1963 to October, 1964, the expenditure incurred on propulsion charges of the jeep for these tours had been apportioned amongst the three Panchayat Samitis of Malerkotla Sub-Division Viz., Dhuri, Malerkotla and Ahmedgarh according to the extent of journeys performed in the jurisdiction of each Panchayat Samiti.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mari Megha Drain in Tehsil Patti, District Amritsar

3354. **Baboo Bachan Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of the villages in tehsil Patti, district Amritsar through which Mari Megha Drain passes ;
(b) the date when the construction of the said drain was taken in hand by the Government ;
(c) the total length of the above mentioned drain ;
(d) the length of the said drain so far completed and the names of villages in which it has been completely dug ;
(e) whether any part of the said drain remains un-dug (incomplete) ; if so, its particulars and the reasons for the same ;
(f) whether any resolution passed by the Gram Panchayat of Narli, tehsil Patti, district Amritsar, was received by the Executive Engineer, Drainage Department, Amritsar on 20th July, 1965, by post under registered cover ;
(g) whether any resolution passed by the said Gram Panchayat was received by the same officer under a registered post between 21st December, 1965 and 25th December, 1965 ;
(h) if the answers to parts (f) and (g) above be in the affirmative, the details of the points raised in the said resolutions and the action, if any, taken in the matter ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) (1) Narli.
(2) Sidhwan.
(3) Amin Shah.
(4) Moghal Chak.
(5) Mari Megha.
(6) Mari Udoke.
(7) Mari Kamboke.
(8) Baserke.
(9) Handal.
(10) Mader Mathra Bhagi.
(b) 1st April, 1960.
(c) 13 miles.

(d) Pilot section of the whole length of the drain is complete. Bed clearance on the wider scale has been completed near the following villages:—
(1) Mader Mathra Bhagi.
(2) Handal.
(3) Baserke.
(4) Mari Kamboke.
(5) Mari Udoke.
(6) Mari Megha.
(7) Moghal Chak.
(8) Amin Shah.
(9) Some portion in village Sidhwan.

(e) No. The drain is complete in pilot section. Bed clearance to a large section in a length of about 3 miles not yet complete.

(f) No.

(g) Yes.

(h) It was desired in the resolution to complete the bed clearance of Mari Megha Drain. This work will be completed before the flood season of 1966.

Old age Pension applications received from tehsil Hansi, district Hissar

3356. Shri Amar Singh : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the names and addresses of persons in tehsil Hansi, district Hissar from whom applications for old age pension have so far been received by the Government and the dates on which they were received ;

(b) the names and addresses of the persons out of those mentioned in part (a) above who have been sanctioned the said pensions, the amount sanctioned in each case and the date when it was sanctioned ;

(c) the period within which the remaining applications are likely to be disposed of ?

Shri Chand Ram : (a) No separate Tehsil-wise record of the persons who have applied for old age pension has been maintained. The compilation of the requisite data will entail huge time and labour which will not be commensurate with the benefit likely to be achieved. However 295 persons from Hissar District have so far been applied for old age pension.

(b) 28 persons of Hansi Tehsil are being paid old age pension as per details given in the attached statement. The rate of pension in all cases is Rs 15 per month.

(c) Efforts will be made to dispose of the remaining applications, if any, as early as possible subject to availability of funds.

List of Persons of Tehsil Hansi, District Hissar who are in receipt of Old Age Pension

Serial No.	Application No.	Name	Date from which payment started
1	75	Shri Kesar Dass	1-2-64
2	2069	Shri Mukha	1-5-64
3	2243	Shri Jai Lal	Do
4	2244	Shrimati Man Bhari	Do
5	2245	Shri Gilla Ram	Do
6	3544-A	Smt. Kishani Devi	1-8-64
7	3545-A	Shri Jessa Ram	Do
8	3546-A	Smt. Dharmo	Do
9	3547-A	Smt. Sohana	Do
10	3548-A	Smt. Wasandi Bai	Do
11	3551-A	Smt. Veeran Bai	Do
12	3552-A	Smt. Tirathi Bai	Do
13	4281-A	Smt. Lachhmi Devi	1-3-65
14	4282-A	Shri Chela Ram	Do

[Minister for Welfare and Justice]

Serial No.	Application No.	Name	Date from which payment started
15	4283-A	Shri Jhangi Ram	1-3-65
16	4515-A	Smt. Ram Piari	1-4-65
17	4519-A	Smt. Bhirawan Bai	1-4-65
18	4520-A	Smt. Jethi Bai	1-4-65
19	4548-A	Smt. Man Bhari	1-5-65
20	5130-A	Smt. Phulian	1-8-65
21	5126-A	Smt. Shuhari Bai	1-8-65
22	5131-A	Smt. Santi	1-8-65
23	5132-A	Shri Asha Ram	1-8-65
24	5133-A	Shri Bhulan	1-8-65
25	5134-A	Smt. Santi	1-8-65
26	3549-A	Shri Sewa Ram	1-10-65
27	4514-A	Shri Attar Chand	1-4-65
28	3882-A	Shri Banda Ram	1-10-65

Murders committed in district Hissar

3357. Shri Amar Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of murders committed in Hissar district during the years 1965 and 1966 todate, separately, and the number of cases out of those which so far remain untraced alongwith the detailed reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : 61 cases of murder were reported during the year 1965. Seven cases of murders were reported up-to-date during the current year. Only two cases of murder of 1965 remained untraced. Cases of the current year are still under investigation. Facts of the untraced cases of murder of the year 1965 are as under :—

(i) F.I.R. No. 12 dated 14th January, 1965 u/s 302 I.P.C. P.S. City Sirsa. In this case a dead body was recovered from behind a local Gurdwara. The deceased was identified as Jagdish, who was a peon in tne office of the B.D.O. He had been missing since 8th January, 1965. It was a blind murder and despite best efforts no clue as to the identity of the culpirts could be found.

(ii) F.I.R. No. 91 dated 19th July, 1965 u/s 302 I.P.C., P.S. Ratia. In this case Duni Chand, a cloth hawker, was murdered while ne was asleep in front of a shop in village Khunan. He was shot dead by the culprits at about 3 A.M. Despite best efforts, the culprits could not be traced.

Representation from President, Kokari Kalan Zamidara Agriculture co-operative Society, Ltd., Kokari Kalan (Ferozepore)

3358. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal: Will the Minister of Irrigation and Power to be pleased to state—

(a) whether he received a representation in the month of December 1965 from the President "The Kokari Kalan Zamidara Agricultural Co-operative Service Society Ltd., Kokari Kalan.(Ferozepore)" regarding the allotment of the Fertiliser Depot to the said society;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, a copy of the said representation alongwith the action taken thereon be laid on the Table of the House;

(c) whether any enquiry has been held into the allegations made by the said Society; if so, when and with what result;

(d) whether the said Society has been informed about the result of the enquiry; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Rizaq Ram: (a) Yes.

(b) to (d) A copy of the representation is enclosed. It is under enquiry.

Copy of the application dated 10th December, 1965 from Shri Pakhar Singh Gill, President, The Kokri Kalan Agriculture Service Society Ltd., Kokri Kalan (Ferozepur) to the address of the Minister for Co-operation, Punjab Governkment, Chandigarh with copies to Registrar, Co-operative Societies, Punjab Government, Chandigarh, The Home Minister, Government of India, New Delhi and The Minister for Co-operation and Panchayat Government of India, New Delhi.

I have the honour to place the following few lines for your kind and sympathetic consideration.—

(1) This Society was established under the name of The Kokari Kalan Zimindara Co-op. Multipurpose Society Ltd., Kokri Kalan (Ferozepur) in1955.

(2) In consideration of people's demand a fertilizer Depot was started in 1957, 1958 this was the time when margin of profit was negligible even then the society worked to the entire satisfaction of all concerned.

(3) Thesociety built a Building of its own at the cost of Rs 4,000 in the year 1959-60 Department assured Government help for thisbut non has been given till date. In 1960 when the Sugar was controlled this society was interested with the distribution of sugar which was carried out to the entires atisfaction without any complaint from any quarter.

(4) In 1962-63 although there was no complaint or any deficiency on the partofthe society the supply of fertilizer was stopped and given to an other society the Kokri Kalan Janta Coop. Multipurpose society Kokri Kalan (Ferozepur) without any licence. This society has its office opposit to our society.

(5) On 1st February, 1963 the society submitted an application to The Registrar Co-operative Societies Jullundur for re-addressing the unjustice done to this society, on this Assistant Registrar, Co-op. Societies, Moga sent an Inspector for enquiries into the matter. Inspector submitted a report cancelling Depots of both the societies enteresting it to another society the Patti-Nangal Co-operative Agriculture Service Society Ltd., Kokri Kalan. This society has as its member persons having share in Janta Society ie., to say Depot remains with the same peoples.

(6) In December, 1963 this society adopted by-laws of an Agricultural Service Society. Since then it is working to the entire satisfaction of thedepartment and peoples of the village. This soeciety has majority of Military pensioners and a considerable number of Harijans which other societies lack.

(7) On 15th February, 1964 the society requested the Chief Minister Punjab for an appointment for a deputation to meet him.

[Irrigation and Power Minister]

(8) On 16th August, 1964 Society's deputation met Minister Co-operation Punjab at the village of Dhudike and submitted an application regarding the matter.

(9) On 13th November, 1964 an application to D.C., Ferozepur was submitted for this.

(10) On 27th January, 1965 Assistant Registrar, Co-operative Societies, Moga informed the society under letter No. 810 dated 27th January, 1965 that the society is being sanctioned fertilizer depot very soon. But nothing happened.

(11) On 26th March, 1965 another application to the Registrar Co-operative Societies, Punjab, Chandigarh was given by hand.

(12) On 18th May, 1965 an application was submitted to Minister, Co-operation at Moga in the presence of the Deputy Commissioner, Ferozepur.

(13) Now recently the fertilizer depot has been given to the Janta Agriculture Society Kokri Kalan as the Patti Nangal Agriculture Service Society's papers has been taken over by Police due to a case of 420 against this Society.

(14) This society has got the largest number of members against all the societies of the village individually 60 per cent of these members are Military pensioners. Societies Capital is largest. Only this society has a building of its own for the storage of fertilizers. I have sanguine hopes that a sympathatic consideration will be given to the above facts and justice done to the society.

CALL ATTENTION NOTICE

श्री अध्यक्ष : कल दो एडजर्नमेंट मोशन्ज़, एक कामरेड तरसिक्का की तरफ से और एक कामरेड जोश की तरफ से एक ही मैटर के मुतअल्लिक दी गई थीं। मैं ने कहा था कि काल अटेनशन दे दो तो कनसिडर कर लेंगे। उन्होंने काल अटेनशन नोटिस दिया है। नाउ आई काल अपान कामरेड तरसिक्का। (Yesterday, two notices of Ajournment motions, one by Comrade Makhan Singh Tarsikka and the other by Comrade Shamsher Singh Josh were given in connection with the same matter. I told them that if a notice of a Call Attention Motion is given, the matter can be considered. They have accordingly given a notice of a Call Attention Motion. I call upon Comrade Makhan Singh Tarsikka to move it.)

Comrade Makhan Singh Tarsikka: Sir, I beg to draw the attention of the Government towards serious condition and discontentment due to today's (10th March, 1966) foot march of more than 20 thousand Government employees of the Secretariat and other Government Offices of Chandigarh, on the main roads etc. and the attitude of the State Government towards their 5 lakhs employees in the State by not fulfilling their most genuine demads regarding pay scales etc. due to high prices etc. Due to the attitude of the Government there is much discontentment in the State by not increasing their pay scales from 1945 onwards, in spite of the fact that the Central Government has raised on more than six occasions the pay scales of Central Government employees (including Central Government employees stationed at Chandigarh). The situation is very serious therefore Government must make a statement.

Mr. Speaker : This is admitted.

सरदार दरबारा सिंह जी, आप आज स्टेटमैण्ट देंगे या बाद में ? सरदार कपूर सिंह जी, आप

कुछ कहना चाहते हैं ? (This is admitted. Addressing Sardar Darbara Singh : Does the hon. Minister propose to give a statement today of or some other day ? (Addressing Sardar Kapur Singh). Does the hon. Minister wish to say something.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ your motion has been disallowed. ਡਿਸਅਲਾਉ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

Mr. Speaker: The motion of the hon. Member was on the same subject. His name will be bracketed with Comrade Makhan Singh Tarsikka in respect of this Call Attention Motion.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਠੀਕ ਹੈ।

Minister for Finance: Mr. Speaker, Sir, to some extent the attitude of the Government is reflected in my Budget speech. Further, I may submit that the matter is under the active consideration of the Government.

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER REGARDING THE LEASE OF LAND TO M/S BIRLA BROTHERS

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 17, 18 ਫਰਵਰੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਡੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਿਛੋਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (**ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ**) : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker: I have a suggestion to make to the Government. The Government have, on occasions more than one, given assurances about the time by which they will make a report. It does not look nice, if the Government does not stick to the time schedule. I hope this will be the final assurance and it will be honoured by Government.

Minister for Home and Development : Sir, the Sub-Committee will be meeting today.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : On a point of order, Sir. ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਸਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬੀਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। (The assurance given was that the Cabinet Sub-Committee will give their report within a week.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕਿਸ ਨੂੰ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੂੰ । (The report will be submitted to the Cabinet.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਊ ਕਰ ਦਿਉਗੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ।

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement in reply to Call Attention Motion No. 44 of Comrade Shamsher Singh Josh.

On account of Indo-Pakistan hostilities of August-September, 1965, about 55,000 persons, including infants, had to leave their hearths and homes to take shelter in safe places. The Punjab Government were placed with host of problems to be tackled on top priority basis. Apart from the uprooted persons belonging to the border districts of Amritsar, Ferozepore and Gurdaspur who were provided relief in cash and kind, there have been many more persons of these districts as well as other districts who suffered loss of lives, house properties etc., on account of bombing or shelling by Pakistan Armies or action of enemy paratroopers.

2. Government sanctioned relief to the families of those killed, displaced, injured at the following rates :—

(a) For families whose breadwinners have been killed by air bombing, paratroopers, shell fire or other enemy action.	(i) Rs 1,500 *ex-gratia* grant. (ii) Free education of children in Swaraj Bhawan Allahabad. All widows to be sent to GandhiVanita Ashram and others similar places, fee to be paid by Government.
(b) For those injured by action as above and who have lost a limb or have been disabled.	(i) Rs 500 *ex-gratia*. (ii) Rs 50 for three months. (iii) Free medical aid.
(c) Fully and permanently disabled civilians by action as above.	Rs 1,500 *ex-gratia* grant.

3. According to the present policy of the Government, *ex-gratia* grants at the rate of Rs 1,500 are to be paid to the families whose *bread-winners* have been killedby air bombing paratroopers shell fire or any other enemy action. The Government of India is not in favour of paying any compensation for the persons, who were not bread-winners because dependent of bread-winners are to be compensated and not the persons whose dependents have been killed. However, the matter in regard to the payment of *ex-gratia* grants in respect of other civilians killed though not 'bread-winners' was considered and dropped as it was not covered under the provisions of Personal Injuries(Emergency Provisions) Act, 1962.

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1966-67 (RESUMPTION)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਗੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ

ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਇੰਜਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਇੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੇਸਫੁਲੀ ਮੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਭੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਟ ਹੈ , ਇਥੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਏਕਤਾ ਰਖਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਸਪਰਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬਜਟ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਤੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬੜੀ ਨੀਟ ਔਰ ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਨੀਟ ਔਰ ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡ-ਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਗਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਸ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲ ਸੁਣੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਉ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਥੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਥੇ ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਔਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 109 ਕਤਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸੈਟ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਨੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਚ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਉਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਇਜ਼ ਜਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਇਕ ਬੜੀ ਵਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਡੀ. ਸੀ. ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਗਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਡੀ ਸੀ. ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੀ. ਸੀ. ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ, ਵੀ ਸਿਵਾਏ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਅਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਨੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਅਰਦਲੀ, ਸਵੀਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਮਾਰ ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਡੀ. ਸੀ. ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਸ ਬੀਮਾਰ ਲੜਕੇ ਕੈਪਟਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਨਾ 500 ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੈਕ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਨਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ . ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖ ਅਫਸਰ ਅਗਰ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟਰਾਂਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਅਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 150 ਰੁਪੈ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 102433 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਿਆ ਸਵੀਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ

ਪੂਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ, ਨੰਬਰ 335480 ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਕਢਾ ਕੇ ਉਥੇ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ 2,400 ਰੁਪਿਆ ਇਸ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ" ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਐਸ. ਡੀ. ਉ. ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ—ਉਸ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਾਅਨਤ ਹੈ।

(*Interruption by Chaudhri Darshan Singh*)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੋ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ। (Addressing Chaudhri Darshan Singh. If the hon. Member has to make an interruption he should do so from his own seat. He should not resort to both the things at one and the same time.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚ ਐਮਬੇਜ਼ਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। 25 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਦਮ ਸ਼ਿਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ—ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠਪ ਕਰ ਦਿਉ, ਪਦਮ ਸ਼ਿਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਠਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼ਿਰੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਸੁਮਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਜਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਕੇ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼ਿਰੀ ਲੈ ਗਿਆ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ within the radius of five miles ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਇਹ ਰਿਕੁਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ—ਦੀਨਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਹੈ—ਉਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਭੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਰੀਕਵੈਸਟ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਭੱਠਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿ 5 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ $1\frac{1}{2}$ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਦੋਂ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਇਹ ਗਲ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ I would resign from the House ਵਰਨਾ ਉਸ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ . . .

Finance Minister : Can this be expected of the honourable Member to make allegations like this? Sir, when the officer is not in a position to reply to these allegations, such allegations should not be made against him?

Sardar Gurcharan Singh: Mr. Speaker, I am giving factual position and everything about his official functioning.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ but if an offiicer cannot be criticized for the action done in the course of the discharge of his official duties then I do not think anything can be done here. If any hon. Member has got any personal grievances against an officer and he wants to refer the same in the House then it is right that this should not be allowed to be done, but if an Officer cannot be cricitized for the action done in the course of the discharge of his official duties then I do not think anything can be done here.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲ ਸੇਲ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਬ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੁਟ ਦਿਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਨੋ ਨੋ ਇਹ 20 ਮੀਲ ਕਰੋ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਵਿਨਿਉ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 20 ਮੀਲ ਕਰੋ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ

he was Kind enough ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੇਵੇਨਿਉ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ but he did not care ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 19 ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਟੋਟਲ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ, ਰੇਲਵੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਸਾਂ ਜੋ ਅਰਸਟਵਾਈਲ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ 1956 ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਔਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ 50, 50 ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੰਨ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਅਛਾ 50, 50 ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀ-ਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

'The Chief Minister assured the Patiala Division operators that their right will be considered equally with other two divisions of Ambala and Jullundur without any discrimination.

1956 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ, 1959 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ—

On 20th June, 1959 a meeting was held by the Director of Transport, Punjab State at Chandigarh jointly of Private Bus Operators and the Pepsu Road Transport Corporation in the presence of the General Manager of the Corporation where both the parties agreed and signed the documents for 50:50 scheme to be applied in Patiala Division.

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿਚ—

Duiing 1960, the then Chief Minister assured the operators by giving an answer on the floor of this House i.e., the Punjab Assembly that 50:50 scheme will be applied to Patiala Division.

ਇਹ 1960 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ, 1962 ਨੂੰ—

On 3rd March, 1962, a deputation of the Pepsu Motor Federation approached the Chief Minister, Punjab to decide the case of Patiala Division. Then a preliminary step was taken.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ— that viable units be created in Patiala Division. ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉ ਯਾਨੀ ਸਤ ਸਤ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ—

A letter was addressed by the Provincial Transport Controller, Punjab to the Regional Transport Authority, Patiala.

ਇਹ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 5296/ਈ, ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ, 1962 ਹੈ। ਇਤਨੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਅਰਸਟਵਾਈਲ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 650 ਹੈ ਔਰ ਉਹ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਕੁਲ ਮਾਈਲੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6000 ਮੀਲ ਕਚੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 235 ਬਸਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 210 ਸੀ ਔਰ ਇਹ 28000 ਮੀਲ ਪਕੇ ਰੂਟ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਕ ਇਕ ਬਸ 125 ਤੋਂ 250 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਈਲੇਜ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ 25 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੰਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 650 ਬਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਵਾਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਰੂਟ (ਘੰਟੀ)———

[Quorum Bells]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

11.00 A.M.

ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ 8,400 ਮੀਲ ਡੋਲੀ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 7,400 ਮੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 7,400 ਮੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਮਾਈਲੇਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 650 ਵਹੀਕਲਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਗਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੇਟ ਬਣੇਗੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਅਲਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਉਗੇ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਟ ਪਾਰ ਟਰੀਟ ਕਰੋ । (ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਛਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1953 ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਕਿ 50 : 50 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਤਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਓਵਰ ਲੈਪਿੰਗ ਰੂਟਸ ਵਿਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਿਟਿਡ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਲੈਪਿੰਗ ਰੂਟਸ ਤੇ 50 : 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਆਫੀਸ਼ਲ ਬਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਾਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ । ਵਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ । ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । (ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ 32 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵੇਗੀ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟ ਕਰੋ। ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਟ ਪਾਰ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ । (Addressing Captain Rattan Singh : Pandit Chiranji Lal has to attend a meeting of a Committee. The hon. State Minister may deliver his speech after him.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : स्पीकर साहिब, बजट पर डिसकशन दो तीन रोज से चल रही है, इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं जब फिनांस मिनिस्टर साहिब की स्पीच पढ़ रहा था तो मुझे एक बात खास तौर पर खटकी कि वह हकूमत जो हरिजनों के सहारे जिन्दा है, जो बैकवर्ड क्लासिज़ के सहारे जिन्दा है उस गरीब तबके के लिये इस बजट में जगह नहीं है। स्पीकर साहिब, आप को मालूम है कि आज से चार साल पहले इसी हकूमत ने इसी सदन में हरिजन कल्याण टैक्स का एक्ट बनाया और उस के तहत पंजाब की जनता से 3 करोड़ 86 लाख रुपया इकट्ठा किया और उस वक्त के मुख्य मन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने एलान किया कि इस रकम में सरकार एक करोड़ 14 लाख रुपया और मिलायेगी . . . .

श्री अध्यक्ष : ज़रा ठहरिये, कोरम नहीं है। सरदार कपूर सिंह जी, अगर बजट डिसकशन पर भी यही हालत हो. . . . . (The hon. Member may stop for a while, there is no quorum. Addressing Sardar Kapoor Singh: If such is the state of affairs when discussion on the Budget is going on then. . . .)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : तो उन को यह ऐशुरेंस दी गई, सब्ज़ बाग दिखाए गए कि इस राज में इतना हरिजन कल्याण किया जायगा कि यहां पर कोई भी दुखी नहीं रह जायगा, उन के पक्के मकानात बनवाए जाएंगे, उन के लिए रोज़गार के साधन मुहैया किये जाएंगे मगर चार साल बीत चुके, गवर्नमैण्ट इन्टरैस्ट कमा रही है और वह गरीब बहुत ज्यादा बेचैन हैं जिस का जिन्दा सबूत यह है कि इस हाउस के तमाम हरिजन लैजिस्लेटरज़ और लीडिंग कांग्रेसी लैजिसलेटर्ज़ और ऐक्स मिनिस्टर्ज़ ने इस बात पर वाकआउट किया कि जो ऐश्योरेंस हाउस में उन को दी गई थी उस को इम्पलीमैंट न करके सरकार उन पर ज़ुल्म कर रही है। स्पीकर साहिब, आप अन्दाज़ा लगाएं कि किस तरीके से उन के साथ मज़ाक किया जाता है। अब इलैक्शन आ रहे हैं और यह उन के आगे पीछे हाथ जोड़ते फिरेंगे कि अगर किसी और को वोट दोगे तो कांग्रेस का और मुल्क का भट्ठा बिठाओगे उन के घर आएंगे, उन की रज़ाइयां ओढ़ते फिरेंगे। (विघ्न) रोटी खाएंगे लस्सी पियेंगे मगर जब उन को कुछ देने का मौका आया तो सरदार कपूर सिंह साहिब फरमाते हैं :—

At page 44 of the Budget speech it is written—

"In view of the tight Plan ceiling, it has not been possible to provide this amount within the Plan."

Finance Minister: Also read the next sentence.

Pandit Chiranji Lal Sharma: All right. It reads—

"Keeping in view, however, the commitment already made, the Government have decided to add Rs. 22.8 lakhs out of the non-plan budget."

(Interruptions)

यह प्रिंटिड डाकुमैंट है, अगर कहें तो सारा ही पढ़ दूं, आप का काम कर दूं। स्पीकर साहिब हमारी गवर्नमैण्ट ने एक इवेल्यूशन कमेटी बनाई जिस के चेयरमेन एक बड़े ऐक्स्पीरियेंस्ड लैजिस्लेटर साबका मिनिस्टर श्री वृषभान जी को बनाया। मुझे तो मालूम नहीं कि उस कमेटी की कभी कोई मीटिंग भी बुलाई गई। आखिर यह मज़ाक उन से क्यों किया गया यह सब कुछ तो उन लोगों की आंखों में धूल डालने के लिये किया गया है। दिस इज़

नथिंग बट ऐन आई वाश। मैं पूछता हूं कि अगर यह इवैल्यूएशन कमेटी बनाई गई थी यह देखने के लिये सरकार ने हरिजनों के लिये 18–19 साल में क्या किया है तो उस की रिपोर्ट कहां है ? (Quorum Bells)

तो कहां है उस कमेटी की रिपोर्ट ? कितनी मीटिंग्ज़ हुई हैं उस कमेटी की ? इस बात पर तो श्री वृष भान जी को भी अर्ज है कि उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई।

फिर यह कहा जाता है कि हम 100 रुपया की रकम दे रहे हैं हरिजनों को कि वह मिल के शेयर खरीद कर लें तो क्या मिल का शेयर खरीद करने से उन के पेट में अनाज चला जाएगा ? और क्या इस तरह से उन का कल्याण हो जाएगा ? आप आज देहात के अन्दर जा कर देखें कि क्या हालत है। गरीब को सुबह को रोटी का टुकड़ा मिला तो शाम का फिक्र उस को सताना शुरु कर देता है। आज गेहूं 26 से 28 रुपए मन तक मिलता है और अगर एक कुन्बे में 6 या 8 आदमी हैं तो वह अपना पेट किस तरह से पाल सकते हैं। वह 100 रुपया के शेयर को ले कर क्या करेगा और किस तरह से अपना और सारे कुंबे का पेट पालेगा ? फिर कहते हैं कि हम उन्हें ज़मीन दे रहे हैं तो क्या ज़मीन है या रबड़ है जो खींच कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप बढ़ा लेंगे। हम ने कहा कि इवेक्यूलैंड में से दे दो तो उसे आप ने नीलाम करना शुरू कर दिया। इस लिये मैं पूरे ज़ोर से यह कहना चाहता हूं कि यह हकूमत गरीब तबका के साथ, हरिजनों के साथ पसमान्दा लोगों के साथ और पछड़े हुए लोगों के साथ सरासर ज्यादती कर रही है और जुल्म कर रही है। उन के पास रहने को मकान नहीं छोटी छोटी कोठड़ियां हैं और फिर उसी कोठड़ी में बीबी भी लड़की भी, दामाद भी, ससुर भी, बच्चे भी और अगर कटरू हो तो वह भी वहां पर ही रहता है, यह हालत आज उन बेचारों की इस हकूमत ने कर रखी है ? इस लिये मैं कहूंगा कि इस हकूमत के पास अभी 9 या 10 महीने हैं और इन को हरिजनों की हालत को बेहतर बनाने की तरफ फौरी तौर पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं देंगे तो चांद को नारेंगे। यह हमारे डायलेक्ट की बात है। आप ने चांद राम को वज़ीर बना लिया या, मास्टर गुरबन्ता सिंह को बना लिया या फिर चौधरी सुन्दर सिंह को बना लिया स्टेट मिनिस्टर तो क्या इस से पंजाब की 25 या 30 फीसदी आबादी के पेट में टुकड़ा चला जाएगा ? अगर वाकई हकूमत गरीबों को उभारना चाहती है और हरिजनों का कल्याण करना चाहती है और मदद करना चाहती है तो सही मायनों में इमदाद करनी चाहिए जिस से उन के पेट में रोटी जा सके। हकूमत तो लाज़म है कि इन के गुज़ारा के लिये कोई साधन बनाएं और कोई काटेज इन्डस्टरी खोले सिरफ 100 रुपये के शेयर देने से कोई काम नहीं होगा।

इस के बाद मैं चंद लफ्ज़ विमुक्त जातियों के बारे में कहना चाहता हूं। इन की पंजाब में काफी तादाद है। धोबी, तेली, खाती, लोहार, मन्यार, सुनार, आदि बहुत सी जातियां हैं और इन की हालत इस हकूमत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। इन की किसी भी जगह कोई रैप्रिज़ैंटेशन नहीं है। आज आप झीवरों की हालत देखें, घुमारों की हालत देखें आप दिहात में जा कर देखें कि क्या हालत है। (एक आवाज़ : आप शायद नए गांव में गए हैं।) मैं ने तो देहात की पवित्र भूमि में जन्म लिया और देहात के कूओं ने मेरी प्यास

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

बुझाई है और देहात की पवन ने मुझे जिन्दगी दी है, मैं ने देहात की हालत देखी है। फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि इन के पास भी एक कमरा है तो हो सकता है कि अब यह एक कमरा में रह रहे हों। सोते तो एक कमरा में ही होंगे क्योंकि कोठी के बाकी कमरों में तो यह जा नहीं सकते। अनलैस ही इज डिवाइडिड इन्टू पीसीज। (हंसी) तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि पछड़ी जातियों और विमुक्त वर्ग की एकनामिक हालत क्या है। कहते हैं कि उन्हें वज़ीफे दे दिए और ट्रेनिंग एन्स्टीच्यूटों में दाखल करवा दिया, क्या इस से उन सब का कल्याण हो जाएगा। मैं इस हकूमत से यह पूछता हूं कि इस 18 और 19 साल के अर्सा में कौन सी कलियर पिक्चर हमारे सामने डिपिक्ट की है। रुपया हरिजन कल्याण के लिये इकट्ठा कर लिया है और दूसरे धन्धों में लगा दिया है और उन के उपर खर्च नहीं किया। इस तरह की कार्रवाइयों से हकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती

इस के बाद स्पीकर साहिब, यहां पर जैनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है इस की आज क्या हालत है। यह हकूमत कमिशन बनाती है कमेटियां बनाती है और As I said earlier this Government is Government of Committees and Commissions.

विजिलैंस कमिशन, दास कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफामर्ज़ कमीशन और इसी तरह हरियाना डिवैल्पमैंट कमेटी और पता नहीं कौन कौन सी कमेटियां और कमीशन बनाए गए हैं और जब उनकी रिपोर्ट आती है तो पता नहीं कहां चली जाती है। जिस वक्त किसी कमटी या कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सवाल किया जाता है तो कहा जाता है under consideration. When is this consideration going to be over? When are these reports to be implemented? When will this Government die out?

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह कमिशन और कमेटियां गवर्नमैंट के एक्सचैकर र पब्लिक के खजाना पर सरासर डाका है और भारी बोझ है। इन की कोई यूटिलिटी नहीं। दास कमिशन की रिपोर्ट आई और उस के बाद फालो अप के लिये कमेटियां बनाई गई और फिर कई आफीसर्ज़ को चार्ज शीट किया गया लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आखिर में यह कहा गया कि इन का कोई कसूर ही नहीं। कितना वेस्ट है सरकार के खज़ाने का और कितनी परेशानी है उन अफसरों को। फिर विजेलैंस कमीशन बनाया गया विद ए रिटायर्ड जज आफ दी हाई कोर्ट जसटस टेक चंद लेकिन मैं शक करता हूं कि एक भी केस इस कमीशन को आज तक रैफर नहीं किया गया। इस कमिशन की एस्टेबलिशमेंट क्या है यह तो परमात्मा ही जानता है। मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था तो पता चला था कि कमीशन मुकरर किया गया है। मैं यह समझता हूं कि जितने भी यह कमीशन और कमेटियां हैं कोई रैशन्ल कमेटी है? यह फजूल हैं। They create problems, they create confusion, they fail to find out the solution out of it.

स्पीकर साहिब, इस हकूमत के अन्दर मैं यह समझता हूं कि कोई इनिशिएटिव नहीं है कोई ओरिजनेलेटी नहीं है, कोई इन्डीपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। They depend upon

Committees and Commissions. But how long ? इस हकूमत ने हमें दिया क्या है ? Corruption. Corruption is rampant. It is on the increase. छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक आप चले जाएं unless he greases the palm of the clerk the needful will not be done। जहां तक कि अगर किसी ने महकमा में भी काम लेना हो तो unless he tips the man concerned उस का काम नहीं होगा। तो, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करूंगा कि कुरपशन इस हद तक बढ़ी हुई है। इस की वजह क्या है कि Bureaucracy is in full swing. वुज़रा साहिबान को कोई पूछता नहीं। इन की हिम्मत नहीं कि कोई आर्डर पास कर दें और उस को इम्पलीमेंट करवा दें। इस वक्त भी मेरे सामने दो वुज़रा साहिबान जलवा अफरोज़ हैं और वह जानते हैं इस बात को। कहा यह जाता है कि दास कमीशन की रिपोर्ट हमारे लिए बाइबल का दर्जा रखती है। लेकिन हालत यह है कि कोई बात जायज हो या नाजायज़ हो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफीरेंस चलती है इन की। और इन में लिख कर देने की तो हिम्मत नहीं इस लिये टैलीफोन पर बात करते हैं और मैसेज जाते हैं और फिर जिस अफसर से काम लेना हो उस को अफसर के नाते से नहीं भाई चारे के नाते से कहा जाता है कि देखना भाई यह काम करना है चाहे जिस तरह भी हो। मैं अर्ज़ करूं कि दखल दर माबूलात एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस हकूमत ने हमें नीट और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दी है कुरप्शन बढ़ी है और इनएफीशंसी बढ़ी है। Highly inefficient administration we are having in the State at present. एक छोटे से काम के लिए भी unless you pursue the matter on personal level काम होता नहीं और छ: महीने तक सड़कें मापनी पड़ती हैं। और unless you wander from pillar to post, unless you just knock at the doors of the individuals आप का काम नहीं चलेगा। आप ने गवर्नमैण्ट मुलाज़मों की क्या हालत कर रखी है। जब तक किसी का खूंटा भारी न हो तब तक वह नौकरी के अन्दर रह नहीं सकता। आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं लैजिस्लेटरों को तो आप अलाऊंस 300 से 400 करना चाहते हैं ताकि इन का मूंह बन्द कर दिया जाए और हमें खुश रखने की खातर इस तरह किया जा रहा है लेकिन गवर्नमैण्ट मुलाज़मों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। खाह कोई अमीर या गरीब है, देहाती या शहरी हो, मुलाज़म या मालिक हो सब के लिये महंगाई यकसां है फिर क्यों एम. एल. एज़. को तो अलाऊंस बढ़ा रहे हैं और मुलाज़मों को कुछ नहीं दिया गया। क्या वजह है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अपने मुलाज़मों का डी. ए. 6 दफा बढ़ाया है ? तो फिर क्या वजह है कि पंजाब की हुकूमत ने इन मुलाज़मों का डी. ए. नहीं बढ़ाया। और हर चीज महंगी हो रही है आप ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं ईन्टों पर लगा दिया ज़मीन महंगी कर दी लकिन मुलाज़मों की तनखाह नहीं बढ़ाई। इफ दे वांट टू पुट एन एंड टू कुरप्शन तो उस का एक ही हल है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को नीट एंड क्लीन किया जाए। और मुलाज़मों की तन्खाहों में अज़ाफा किया जाए ताकि वह अपना गुज़ारा इन बढ़ती हुई कीमतों में कर सकें। आज इन में फरस्ट्रेशन है।

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

अभी अभी मैं चैंबर में आ रहा था तो मुझे पी.सी.एस. एसोशिसिएशन की तरफ से यह एक मैमोरैंडम मिला। मुझे वह तो मालूम नहीं कि किस ने दिया लेकिन इस को देख कर तअाजुब होता है। मैं ने इसे पढ़ कर देखा है जिस में उन्होंने ज़िक्र किया है कि पी.सी.एस. काडर पिछले 40 साल से इसी तरह से चला आ रहा कोई इस को तरक्की नहीं दी गई जब कि महंगाई इन दिनों कहीं से कहीं चली गई है। मेरा कहने का मतलब यहां पर पी.सी.एस. आफीसर्ज़ के काज़ को प्लीड करने का नहीं है और ना ही मुझे किसी पी.सी.एस. से प्यार है। But the facts are facts and they must be faced squarely. एक तरफ आप कहते हैं कि तमाम महकमों के लोगों की इन्स्पैक्टर्ज़ और सब-इनस्पैक्टर्ज़ की, दीगर अमले की तनखाहें बढ़ी हैं, मगर किया कुछ नहीं गया। इस हाऊस के अंदर भी और बाहर भी बड़ी बड़ी एशोरैंसिज़ दी जाती हैं मगर किया कुछ नहीं जाता। रैप्रिजैंटेशन्ज़ लेकर रख ली, उन को ऐंश्योरैंस दे दी और इस के बाद कुछ ना किया यह आज की सरकार का काम है। इस लिये मैं इस केस के मुताल्लिक इतना ही कहूंगा कि इन लोगों की, जिन के पहले 40 साल से गरेड मुकरर हैं इनको रिवाईज़ कर के इनकी हौसला अफज़ाई ज़रूर की जाये।

जहां तक इंडस्टरी का सवाल है इस के मुतल्लिक मैं पहले भी काफी फैक्टस ऐण्ड फिगर्ज़ दे चुका हूं। जहां तक पंजाब की इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट का सवाल है, पंजाब ने इंडस्टरी में काफी डिवैल्पमैंट की है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इंडस्टरी में साबिका हकूमत के बाद जो मौजूदा हकूमत आई है इस ने 10 प्रति शत तरक्की भी नहीं की। इस की मैं एक मसाल देता हूं कि कसबा घनौर में 157 एकड़ जमीन अक्वायर की गई, मगर जब फैक्टरी लगने का वक्त आया तो यह फैक्टरी या लगी ज़िला कांगड़ा में। यह 14 लाख की स्कीम थी जब इस के मुताल्लिक इस सरकार से पूछा गया तो इस का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। बताऊं इस फैक्टरी को क्यों रिमूव किया गया इस लिये कि यह मेरे हलका के अपने कसबा घनौर में लग रही थी। इस लिये रिमूव किया क्योंकि यह मेरे अपने हलका सोनीपत में लग रही थी। इस लिये भी यहां नहीं लगाई गई क्योंकि यह डिस्टरिक्ट रोहतक के अंदर लगने वाली थी और इस लिये भी नहीं लग सकी क्योंकि यह डिस्टरिक्ट हरियाना प्रान्त में आता है। इसी तरह से पानीपत में एक पेपर मिल लगनी थी मगर वह पालमपुर उठा कर ले जाई गई। यह आखिर हमारे इलाके से ऐसा स्लूक होता क्यों है। क्या उन की निगाह में हमारे इलाके की ज़मीन इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट के लिये अच्छी नहीं है? ठीक है, इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट, आप अगर अम्बाला से आगे अमृतसर तक चाहे चले जायें, वहां ही हो सकती है मगर इस इलाका के लिये ना कोई इंडस्टरी है, ना कोई परमिट कोटे का सवाल वहां अट्रैक्शन की कोई चीज़ नहीं है, nothing of the kind and no encouragement और जब से बिजली की शार्टेज हुई है उस वक्त से कुनैकशन भी कटने शुरू हो गये हैं। ना कोई सैंट्र से हैल्प मिलती है और ना ही इस सरकार से। ना हम इंडस्टरी में डिवैल्प हो सके हैं, और ना हम एग्रीकलचर में ही आगे आ सके यह एक कमज़ोरी है जो दिन बदिन हमारे इलाके में बढ़ती जाती है जिस से मैं समझता हूं कि यह कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी।

इक चीज़ स्पीकर साहिब, मैं रोड ट्रांस्पोर्ट के बारे में भी अर्ज़ करदूं कि आर.टी. ए. का जो महकमा है यह एक बनिये की दुकान है। इस महकमे का काम है लोगों को रूट परमिट देना। अगर किसी गुड़गावां के आदमी को रूट परमिट लेना पड़े तो इस को अम्बाला आना होगा, इसी तरह से कोई रोहतक का झज्जर का रूट परमिट लेना चाहता है तो उसे भी रिजनल ट्रांस्पोर्ट अम्बाला के आफिस में आना पड़ेगा। इस के साथ ही महेंद्रगढ़ वालों को रिजनल ट्रांस्पोर्ट आथेरिटी पटियाला के पास जाना पड़ेगा। अगर सौदा की ज़रूरत तो यहां हो और बनिये की दुकान यहां से दूसरे गांव में हो तो वहां पर कोई सौदा खरीदने नहीं जाता मगर यह कहते हैं कि इतनी दूर से अंबाले आओ अगर रूट परमिट लेना हो तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि आर. टी. ए. का हैड क्वारटर ही अंबाला से रोहतक शिफट कर दिया जाये ताकि दूसरे ट्रांस्पोर्टर्ज़ को किसी तरह की भी कोई इनकनवीनियेंस ना हो।

स्पीकर साहिब, वैसे तो बड़ी बड़ी ज्वानज़ चल रही हैं मगर कल जो पेपर में न्यूज़ आई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, इसका जो रैजोल्यूशन है इस ने एक चीज तो कलियर कर दी है कि on the basis of language पंजाबी सूबा बना दिया जाये, हिल्ली एरिया के बारे में भी यह कलैरीफिकेशन आ गई है कि इसे हिमाचल में मरज कर दिया जाये but our fate is still hanging in the balance. जहां तक हरियाने का सवाल है इस के बारे में हाई कमांड भी अभी तक कलियर नहीं है। मगर on the floor of the House हरियाना के लोगों की तरफ से मैं यह बात कलियर कर देनी चाहता हूं कि हरियाना के लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जिधर मरजी हो उन को धकेल दिया जाये वह अपनी किसमत का फैसला खुद करेंगे। वह यह हरगिज़ बरदाश्त नहीं करेंगे कि उन के ऊपर किसी तरह से पंजाबी ठोसी जाये या इस को बाईफरकेट किया जायेगा या इस के टुकड़े ही किये जायें। यह इस तरह की बातें हरगिज़ हरगिज़ बरदाश्त नहीं करेंगे। यह अपनी किसमत के खुद ज़िम्मेवार हैं। मैं यह बात भी याद करा देना चाहता हूं कि 1857 की तहरीके आज़ादी हरियाना से चली थी, इस के बाद मेरठ, झज्जर और जींद से गदर शुरू हुआ था। क्या यह हमें आज़ादी हासिल करने का बदला दिया जा रहा है। हरियाना ने आज तक हकीकत की लड़ाइयां लड़ी हैं। हरियाना ने गंगा यमुना पार तक दुशमन को भगाया, कुरुक्षेत्र में हकीकत की लड़ाई लड़ कर दिखाई। हम हमेशा से झूठ के मुखालिफ हैं, हकीकत के खिलाफ हमारे ऊपर अगर कोई बात हम पर ठोसी जायेगी तो हम उसे बरदाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बात हकीकत के खिलाफ हम पर लादी गई, पंजाबी सूबा बने या ना बने, इस से हमें कोई सरोकार नहीं मगर हम अपने हित को किसी के लिये कुरबान नहीं करेंगे। अगर हाई कमांड ने हमारे जज़बात के साथ खलवाड़ किया तो याद रखें इन की दनदनाती हुई गोलियां हमारे लिये फूल बन जायेंगी।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

[ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਹੌਕੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਲੈਨਜ਼ ਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਟ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਹੀ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮਣ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ..........

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। (ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ)

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਊਟਲੁਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਰੈਟੇਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦਿਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 1966-67 ਵਿਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਤਦ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲੇਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਮੰਗ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਮਾਨੀਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਯਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ

ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਛਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਏ । ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨਾਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 75 ਲਖ ਟਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1961-62 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਪਤ 63,000 ਟਨ ਸੀ। 1962-63 ਵਿਚ 1,04,000 ਟਨ ਹੋਈ। 1965-66 ਵਿਚ ਇਹ 3,30,000 ਟਨ ਹੋਈ। 1966-67 ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5,77,000 ਟਨ ਹੋਏਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਓਥੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । 1961-62 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 29,600 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਤਾ । 1,285 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, 17,482 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦਾ, 819 ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਦਿਤਾ । 1965-66 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਤਾ 1,22,060 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ । ਰਾਈਸ ਦਾ 8,400 ਕੁਇੰਟਲ, ਨਰਮੇ ਦਾ 44,500, ਬਾਜਰੇ ਦਾ 1,900 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਮੇਜ਼ ਦਾ 3,962 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਬਲਮ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਛਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਕਲ ਜਦ ਤਕ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਊਟਲੁਕ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈਏ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ । ਜਿਥੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੇ-ਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਡ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅਕਾਨੋਮੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰੈਡਿਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲੋਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਤਕਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ

[ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ]

ਹਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸ-ਟਰੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਪਲੇਂਟ ਕਮਿਊਨਿਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਰਸਰੇਇਕਤਦਾਰ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਏਗੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡਿਆਲੋਜੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲੈਂਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਨਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਿਰ 1964-65 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ 8 ਸੌ ਟਿਊਬਵੈਲ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 1965-66 ਦੇ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਔਰ 1966-67 ਦੇ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਵਰਆਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 66 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੂਡ ਵਿਚ ਸੈਲਫਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਘਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਜੇ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 36 ਲਖ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ । ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 30 ਲਖ ਟਨ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜਾਂ ਤੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1966-67 ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀਟ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਦਾ ਕੇ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਜੋ ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਹ 70 ਤੋਂ 90 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿਚ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਝਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਉਥੇ ਦੋ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੀਟ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਡਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਡਬਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਧਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬਾਜਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਾਉ ਨਾ ਪਕਾਉ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਫੇਸਿਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ

[ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ]

ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੂਪਸਾਈਡਿਡ ਆਊਟਲੁਕ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤਦ ਤਕ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਰਜ਼ੂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਘਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ Punjab is the granary of India. If Punjab can become the granary of India, it must also be turned into milk-shed of India.

ਔਰ ਮਿਲਕ-ਸ਼ੈਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ-ਸ਼ੈਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਲਕ-ਸ਼ੈਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾੜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਪ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ

ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹਨ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਰਿਟੀਸਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗ਼ਲਤੀ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਹਲਾ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੇਹਵਨ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ..........

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੈਕਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ, ਬਾਬੂ ਜੀ , ਇਹ ਹਕ ਕਨਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕੰਨਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

There are rules and regulations under which he has to work. ਜੇਕਰ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਰਨਾ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਜ ਕਿਉਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਉਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਘਟੀ) ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮ-ਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕੰਨਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲੀਆ (ਮਹਿਲਕਲਾਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਾਰਸਾਈਟਿਡਲੀ ਡੀਸੀਯਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਭੁਲ ਕੇ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਉ ਤਾਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਸਿਟ ਬਜਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਬਿਉਰੋਕਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਾਊਂਟ 5 ਕਰੋੜ 28 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਿਸਿਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਿੰਪਲੀ ਟੂ ਇਮਪੋਜ਼ ਮੋਰ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਫਿਸਿਟ ਦਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੀਸੀਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਟੀ-

[ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲੀਆ]

ਮੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 1961-62 ਵਿਚ 425 ਲਖ 1962-63 ਵਿਚ 466 ਲਖ, 1963-64 ਵਿਚ 503 ਲਖ ਅਤੇ 1965-66 ਵਿਚ 416 ਲਖ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, 20 ਲਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਟਰਲਾਗਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਡਰੇਨਾਂ ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ 207 ਲਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 24 ਕਰੋੜ 62 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਵਧ ਦਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਰਚ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 8 ਲਖ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਚ 12 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੈਮਨ ਰੀਲੀਫ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 9 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਲਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਪਰ ਪੂਰਾ ਰੀਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 1966 ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਅਰਬ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਬਤੌਰ ਬਿਆਜ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਸ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 28 ਕਰੋੜ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ । ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਜਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 4.49 ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 4.86 ਕਰ ਦਿਤੀ

12.00 Noon

ਗਈ । ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਨ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਗਰਜ਼ ਇਹ ਹਨ । 1960-61 ਵਿਚ 12.03 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 27.41 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 438 ਕਰੋੜ, ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ 6.7 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 50.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧ ਸਕੇ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 : 50 ਬੇਸਿਜ਼ ਉਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਦਰ ਸਮਾਲ ਬਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ 900 ਮੀਲ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲੀਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਤੀਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਣੇ ਪਏ । ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਤੀਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੀ-ਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

(Interruption by Comrade Gurbaksh Singh. Dhaliwal) ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ, ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੋਦੀ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਮਿਲਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ

[ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲੀਆ]

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਤਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੀਟਰੈਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਪ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ 2 ਜਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 200 ਜਾਂ 300 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਜ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ........ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ । ਉਥੇ ਦੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐਫੀਸੈਂਸੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਕ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੋ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਲਾਗਡ ਹੈ, ਕੱਲਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਟਿਲੇਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 20,000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ । ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲਾਗਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਖੰਭਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਗੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਕੰਮਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਦਿਆਲਪੁਰ ਡ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੋਕਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ

ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਇਕ ਵਿਘੇ ਤੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਨਾਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਿਘੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? (ਘੰਟੀ)

ਇਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਤੌੜ ਤੱਪੇ ਦੀ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾਂ 62 ਸਫੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 80—82 ਸਫੇ ਬਣ ਗਏ—ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ...........

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ . ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਹੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1965 ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜੰਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਰਾ—"ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ"—ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਗੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ, ਸੱਤ ਲਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਜ ਕੋਈ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭੁਖ ਮਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲ ਬੰਗਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ । ਬਹੁਤ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ. ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਹੋਵੇਗੀ ਅਜ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਖ ਮਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕ ਅਜ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਂਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਈ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਪਿਛੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਰਾਇਤ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 231 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਪਜਾਬ ਵਿਚ $78\frac{1}{2}$ ਲਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ 54.70 ਲਖ ਟਨ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਗਲ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਵਧ ਖਰਚਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਟੀਚਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ $24\frac{1}{2}$ ਲਖ ਟਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੱਈ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ—ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਰੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ । ਬੇਸ਼ਕ ਦੋ ਐਕਟ—ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਲਗ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਅਲਗ ਬਣੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ—ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਗਾਂ ਹੇਠ, ਫਾਰੈਸਟ ਹੇਠ ਰਖ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਸਾਨ, ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡਣਯੋਗ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਤੁੜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਮੈਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । ਮੁਕਤਸਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਾਗੀਰ-ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ, ਰੀਕਾਰਡ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਲਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਖ ਲਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬੇਹਤਰ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਹੱਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਖੇ ਗਏ । ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੀ ਹਦ ਮਿੱਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਕਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪੁਜ ਸੱਕਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਗੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ—ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ, ਈਵੈਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਵਿਚੋਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚੀ; ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਈਵੈਕੂਈ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਖ ਵਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ । ਹੁਣ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਲਖ ਔਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਾਂ ਕਿਤਨੀ ਹੈ-- ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਨੇਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਥੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਦ ਤਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਔਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ।

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । ਜੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਜਾਂ ਪੰਪਿਗ ਸੈਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਨ 1965 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਲਈ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 750 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, "ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਿਆ ਔਰ ਰੈਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਂਦੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪਾਲਿਉਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 750 ਰੁਪਿਆ—ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇ—ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਸਰੇ ਉਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ—ਨੰਬਰ 9489 ਜਿਹੜਾ 2 ਮਾਰਚ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸੀ; ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਕਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਨੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ :—

Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government have made an announcement that 25 per cent subsidy will be given to those land-owners who instal tube-wells and pumping sets either by spending the amount from their own pockets or by raising taccavi loans ; if so, the total number of the land-owners who have since been paid such subisdy according to the said announcement ;

(b) the number of landowners out of those referred to in part (a) above given such subsidy who have spent the amount from their own pockets or by raising taccavi loans, separately ;

(c) whether any procedure has been laid down for distributing the said subsidy; if so, the details thereof and a copy thereof be laid on the Table of the Houle ?"

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਦਾ ਹਾਂ————

Deputy Speaker: Please wind up.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ———

उपाध्यक्षा: आप को बोलते हुए 15 मिंट हो गए हैं। Within five minutes अब खत्म करो आप को घड़ी की तरफ भी देखना चाहिए बाकियों ने भी बोलना है (The hon. Member has already spokan for 15 minutes, he should finish within five minutes. The hon. Member should look to the watch as well. Other members have also to speak.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਈਂਡਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ: —

The reply given by Sardar Darbara Singh, Home and Development Minister is :—

"(a) 25 per cent subsidy has been sanctioned with effect from 1964-65 only for the loanees who installed tube-wells and pumping sets run by diesel engines. Since subsidy is to be given in the form of waiving off of the recovery of last instalments of the loan, no subsidy has been paid so far.

(b) Does not arise.

(c) Subsidy to the receipients of loans is given in case they instal new diesel engines within one year of the receipt of loans and use them at least for one year. Subsidy is allowed in the form of waiving off recovery of an appropriate amount out of the last instalment of the loan repaid by the loanee."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਥੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ.......

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਰੂਫ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਹ (ਖਾਦ) ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਹ ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੇਹ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਿਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਾਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਠੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਠੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਲੈ ਆਉ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਉ ਔਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੋਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਦਸ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਹਨ? ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਲ 17 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਈ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੋਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ -ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਜਿਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

श्री बाबू दयाल शर्मा (पटौदी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज बजट पर बहस हो रही है इस को मैं ने सुना है और इस से पहले भी जो बहस हो चुकी है वह भी मैं ने सुनी है और इस से मैं यही अन्दाजा लगा सका हूं कि यह जो बजट का इतना लम्बा चौड़ा पोथा है इस पर जो भी आदमी तकरीर करनी चाहे और अपनी राए कायम करना चाहे कर सकता है और मेरे अपने ख्याल में जो कुछ बातें आपोजीशन की तरफ से कही गई हैं उन में से कुछ तो ठीक भी हैं लेकिन वह ज्यादा तर गलत हैं। अभी एक सज्जन ने फरमाया है कि यह बजट बिरोक्रेटिक है। मुझे यह बात अफसोस के साथ करनी पड़ती है जिस सज्जन ने यह बात कही है उन्हें शायद बिरोक्रेटिक शब्द की डैफीनीशन का पता ही नहीं है। बियोरोक्रैटिक बजट वह होता है जिस में ज्यादा खर्च पुलिस और फौज और इस तरह की दूसरी चीज़ों पर किया गया हो लेकिन अगर इस बजट पर आनरेबल मैंम्बर साहिबान नज़र डालें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस बजट का 17 फीसदी एजूकेशन और साइंटेफिक पर्पिजिज़ से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रखा गया हुआ है जिन से वसूली कम होती है और खर्च ही खर्च होता है। जिस बजट की यह हालत हो उस को बियोरोक्रेटिक कैसे कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम रैवेन्यू टैकसिज़ के खाते को देखें तो पता चलता है कि इस खाते में हम ने एक अरब और 48 करोड़ रुपए वसूल करने हैं और खर्च करना है एक अरब और 43 करोड़ रुपये और पांच लाख रुपए। जिस का मतलब यह हुआ कि तकरीबन पांच करोड़ रुपए रवेन्यू टेकसिज़ में बचत होगी इसी तरह से आप रिसीट साईड को देखें तो पता चलता है कि 3 अरब पांच करोड़ और 58 लाख कुल आमदनी है और इस पर खर्च होगा 3 अरब 10 करोड़ और 83 लाख जिसका मतलब यह है कि माइनस 5 करोड़ और 25 लाख रुपए खर्च होगा। अगर आप पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस

देखें और इस साल का ओपनिंग बेलेंस देखें तो 56 लाख की बचत है। इन चीज़ों को देख कर कौन नहीं कह सकता है कि यह एक वेलफेयर स्टेट का बजट है और इस के अन्दर ज़्यादा से ज्यादा हालात को ठीक करने की कोशिश की गई है हालांकि यह बजट जिस वक्त में बनाया गया उस वक्त हमारे सूबा पर बहुत मुसीबतें छाई हुई थीं और यहां पर कुदरत की तरफ से सूखा पड़ा हुआ है और भी कई मुसीबतें नाज़ल हुई थीं और इन मुसीबातों का मुकाबला करते हुए इस सरकार ने यह बजट निर्माण किया है मैं इस के लिये अपने फाईनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं। लेकिन जब मैं इस बजट को अपने ज़िला के नुक्ता निगाह से देखता हूं तो मैं इस में कई खामियां पाता हूं जिन की तरफ मैं गवनर्मेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे ज़िला गुड़गांवां में एक सड़क है होडल-नूह-ताड़-पटौदी-पटौदा जो नूह से ताऊड़ तक है। यह बड़ी इम्पार्टेंट जगह है और यह पांच मील का टुकड़ा है। मगर सन 1952 से ले कर हर बजट स्पीच में इस बारे में सरकार से, प्रार्थना करने के बावजूद यह नहीं बनाई जाती। यह टुकड़ा सड़क का बनाना निहायत ज़रूरी है। इस के न होने की वजह से नूह के लिये 84 गांवों को 22 मील का चक्कर काटना पड़ता है क्योंकि बाज़ दफा उन लोगों का टिकट नहीं मिलता, ताऊड़ू से डायरेक्ट टिकट मिलते हैं। इस तरह से उन को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस पांच मील के सड़क के टोटे का जिक्र मैं बराबर 15 साल से कर रहा हूं मगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह सरकार की पब्लिक की तरफ बड़ी भारी केअरलैसनैस है।

दूसरी बात मैं अलैक्ट्रिक पावर के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं ने पहले भी अर्ज़ किया है कि भाखड़ा डैम का निर्माण इस लिये किया गया था कि हरियाणा के ज़िलों खास तौर पर गुड़गांव, रोहतक, हिसार और करनाल को सैराब किया जा सके। मगर हुआ यह कि इस की नहरों से ज़िला गुड़गांव का एक कतरा पानी का नसीब नहीं हुआ। सन् 1953 में इस बात की बड़ी चर्चा की गई और हम से वादा किया गया, फिनांस मिनिस्टर साहिब इस प्वायंट को नोट कर लें, क्योंकि वहां पर मीठा पानी ज़मीन के नीचे है इस लिये मेरे ज़िले को इलैक्ट्रिक पावर देने के सिलसिले में टाप मोस्ट प्रायर्टी दी जायगी ताकि वहां पर परकोलेशन वैल्ज़ लगकर लोगों को पानी मुहैया कर सकें। मगर उन को टाप प्रायर्टी देना तो दरकिनार वहां पर जो बिजली ले जाने के लिये खम्बे डाले थे वह वैसे ही पड़े हैं गुड़गांव ज़िले में एक इलाका थली है जहां पर ज़मीन के नीचे पानी बहुत बढ़िया है मगर गहरा है। अगर वहां पर हम पावर दे सकें तो वहां पर बहुत ज्यादा अन्न की पैदावार हो सकती है। (विघ्न)

अब मैं कुछ सप्लाई आफ फ्रैश पीने का वाटर टू विल्लेजिज़ के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, जिला गुड़गांव में कोई साढ़े चार सौ देहात ऐसे हैं जहां का पानी कतई खारा है। आप जानती हैं कि देहात के अन्दर जब बयाह शादियां होती हैं तो बेसाख जेठ का महीना होता है जब कि किसान फसल काट कर फारिग़ हो जाता है उन दिनों में वह ब्याह शादियां करते हैं और उन की ज्याफतों में पक्का अन्न का भोजन करते

[श्री बाबूदयाल]

हैं तथा खारा पानी पीते हैं जिस से वहां के हजारों आदमी हैज़े के शिकार हो जाते हैं। वह पक्का पकवान खाते हैं और पानी पीते हैं खारा तो हैज़े का शिकार होते हैं।

इसके आगे मैं गुड़गांव ज़िले की साल्ट इन्डस्ट्री का ज़िक्र करना चाहता हूं। गुड़गांव की साल्ट इन्डस्ट्री 1913 से पहले बहुत मशहूर थी वहां के लाखों मन साल्ट आगरे में जमा किया जाता था वहां से सारे देश को जाया करता था। मगर बाद में जब एक अंग्रेज़ी फर्म ने साम्भर झील का ठेका लिया तो इस इन्डस्ट्री को सरकार ने खत्म कर दिया। हमारी अपनी सरकार ने भी उस को रिवाईज करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है यह बड़े अफसोस की बात है।

इस के बाद मैं स्माल इंडस्ट्रीज़ की एस्टैबलिशमैंट के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं ने अर्ज़ किया है यहां पर कई दफा कि मेरा ज़िला इन इन्डस्ट्रीज़ के लिये रा मैटीरियल की सहूलियात के लिहाज़ से पंजाब में सब से बढ़िया है मगर इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पर मैं आप को बताता हूं कि ज़िला गुड़गांव में जो सरसों पैदा होती है वह दूसरे स्थानों में पैदा होने वाली सरसों से दो तीन सेर तेल प्रतिमन ज्यादा देती है......

उपाध्यक्षा : कोरम नहीं है (There is no quorum in the House)

[Quorum Bells sounded]

उपाध्यक्षा : अगर मुझे इस तरह से बार 2 कोरम के लिये बैल बजानी पड़ी तो मैं हाउस को ऐडजर्न कर दूंगी। (If quorum bells have to be rung-up again and again then I will adjourn the House.),

पंडित बाबू दयाल शर्मा : मैं सरसों की स्माल इन्डस्ट्री के बारे में अर्ज़ कर रहा था जो सरसों ज़िले गुड़गांव के स्थान बावल और नूह में होती है वह कलकत्ता की मार्किट में दूसरे बीजों के मुकाबले में तीन चार रुपये ज्यादा दाम पर बिकती है। हमारे यहां इस के लिये अभी एक आध मिल ही लग रही है वह भी अभी चालू नहीं हुई। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस इन्डस्ट्री की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दे। जिस सरसों से कलकत्ते के व्यापारी लाखों रुपया कमाते हैं उस से गुड़गांव क्यों न लाभ उठाये और किसान को अधिक दाम क्यों न मिले। एक और इंन्डस्टी जो हमारे हां लग सकती है बारले की। यदि सरकार इस इंडस्ट्री की ओर ध्यान दे तो बड़ा लाभ हो सकता है (विघ्न) मैं बताता हूं यह क्या इन्डस्ट्री है। हमारे ज़िले गुड़गांव में जो सब से ज्यादा पैदा होते हैं और यह होता भी बहुत आला किसम का है जिससे दो ढाई पौंड के भाव पर बिकने वाला बारले तैयार किया जाता है। इस बारे में अब थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। मैं आप की मारफत फिनांस मिनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इस समय जौ का भाव 100 रु० क्विन्टल तक पहुंच गया है। और जौ गेहूं और चने से महंगा है क्योंकि बंगाल में इस की बहुत जरूरत है। इस पर कोई पाबन्दी नहीं थी। लोग इस का छिलका उतार कर बंगाल भेजते थे और वह लोग इस को खाने में इस्तेमाल करते थे। तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बारले की इन्डस्ट्री ज़िला गुड़गांव में ही कायम की जाए। प्राइवेट तौर पर एक दो लोगों ने जारी की है परन्तु सरकार ने (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी...

उपाध्यक्षा : मैं यह रिवाज बन्द करना चाहती हूं कि हर एक मैम्बर ज्यादा टाइम के लिये इनसिस्ट करे। (I want to put an end to this practice that every hon. Member should insist on taking more time

पंडित बाबू दयाल शर्मा : मैं दो मिनट में ही अपनी बात कह लेता हूं। इस के अलावा गुड़गांव में जो बड़ी इन्डस्ट्री है वह स्टोन (stone) क्रशिंग की है। हमारे हां ऐसे पहाड़ हैं जिन से सड़क के लिये जीरा रोड़ी तैयार होती है वहां पर इस काम के लिये दो तीन प्राइवेट क्रशर लगे हुए हैं मगर इस के लिये गवर्नमैण्ट की तरफ से न कोई सबसिडी है और न ही कोई ग्रांट दी गई है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि स्टोन क्रशिंग की इन्डस्ट्री जितनी वहां पर डिवैल्प हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती।

हमारे जिले की एक और इम्पोर्टेंट इन्डस्ट्री है स्लेट इन्डस्ट्री, क्योंकि हमारे हां स्लेट का पथर निकलता है कुन्ड के इलाके में। लोग ठेकों के लिये मारे 2 फिरते हैं। मैं दरखास्त करता हूं कि इस इंडस्ट्री की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए।

फिर एक इन्डस्ट्री है मुंज की। मूंज से बान बनता है और मूड़े तैयार किये जाते हैं। इस तरह का काम फरूखनगर में होता है और हजारों मजदूर इस इन्डस्टरी से अपना पेट पालते हैं। एक बार सरदार प्रताप सिंह वहां पर गए थे तो उन्होंने इस इन्डस्टरी को बढ़ावा देने के लिये वहां के मजदूरों को प्राईवेट तौर पर कर्जे दिए थे और यह भी कहा था कि इन कुरसियों की बजाए आप यह मूड़े इस्तेमाल करें यह ज्यादा कमफर्टेबल हैं इस लिये मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि मूंज की इन्डस्ट्री को फरोग देने के लिए हर तरह इमदाद करे। सरदार प्रताप सिंह ने बचन दिया था कि मैं पंजाब के सरकारी दफतरों में फरूख नगर मूड़े इस्तेमाल कराउंगा परन्तु सरकार ने इस वायदे को पूरा नहीं किया।

इस के बाद और भी बहुत सी इन्ड़स्टरीज़ हैं। इस में एक एग्रीकलचर की इन्डस्टरी है। इस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इन्डस्टरी कैटल ब्रीडिंग की है। जैसा कि आप जानती हैं, उपाध्यक्षा महोदया, कि हरियाना की कैटल की ब्रीड सारे हिन्दुस्तान में अच्छी मानी गई है। इस में दो वैरायटीज़ हैं, एक मुराह और दूसरी नीली। यह इन्डस्टरी हरियाना में बहुत डिवैल्प हो सकती है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्लान के अन्दर जो स्कीमें रखी गई हैं इन में इस हरियाना की इन्डस्टरी की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आप अगर इन स्कीमों को गौर से देखें तो पता चलेगा कि इन्होंने इस स्कीम के लिये 1 लाख 60 हज़ार रुपए की रकम रखी है और इस में से हरियाना रिजन के लिये सिरफ 55 हजार 670 और इस के मुकाबिला में पंजाबी रिजन के लिए 1,04,330 रखा है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हरियाना के लिए 60 फीसदी रकम रखी जाए और दूसरी तरफ इस स्कीम का सब से बड़ा हिस्सा पंजाबी रिजन को दे दिया गया है। गवर्नमेंट ने हरियाना डिवैल्पमेंट कमेटी बनाई है और उस की रिपोर्ट के सफा 37 से 44 तक इस बात का जिक्र किया गया है कि हरियाना में डैरिइंग की इन्डस्टरी इतनी डिवैलप की जा सकती है कि यह डेनमार्क आफ इंडिया बन सकता है। लेकिन

[पंडित बाबू दयाल शर्मा]

उस की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी गई। कहां तो बात की जाती है कि हरियाना को 60 परसैंट आफ दी बजट एलोकेशन की जाए, और कहां पर सिरफ 30 परसैंट दिया जा रहा है। इस की तरफ फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

इस के साथ ही सफा 79 पर प्लान स्कीम है आर्टिफिशल इनसैमीनेटेशन की, जिस के लिए सैंटर खोलने हैं इस से ब्रीड में डिवैल्पमैंट की जा सकती है इस के लिये भी हरियाना में पैसा नहीं रखा गया और यह कहा है कि इस स्कीम को महज़ पंजाबी रिजन में ही अमल में लाया जाएगा। इस तरह से डैरिएंग की जो स्कीम है वह सारी की सारी पंजाबी रिजन में खेंच कर ले गए हैं। इतनी बड़ी इन्डस्टरी हरियाना की यह थी जो आज बिलकुल खत्म की जा रही है। और यही एग्रीकल्चर की सब से बड़ी इन्डस्टरी है। इस लिये मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब की तवज्जोह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर अभी नहीं तो इस साल के बजट में इस बात का परोवीजन किया जाए ताकि हरियाना में कैटल ब्रीडिंग और डैरिंग की इन्डस्टरी को तरक्की मिले। घंटी) आप अगर उपाध्यक्षा महोदया चाहती हैं कि मैं अपनी स्पीच खत्म कर दूं तो मैं बैठ जाता हूं नहीं तो अभी बहुत ही बातें रहती थीं जो सरकार के नोटिस में लाना चाहता था।

ਗਿਆਨੀ ਚੇਲ ਸਿੰਘ (ਫਰੀਦਕੋਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬਜਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਟ੍ਰੋਵਰਸੀ ਚਲੀ, ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਅਲੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉ। (What has this decision to do with the General Administration¿ The hon? Member should not bring in the Congress Working. Committee.)

ਗਿਆਨੀ ਚੇਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗਲ ਇਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ

ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਗੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਘੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਵਖਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਮੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਯਗ ਦਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਜਨ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਯਗ ਦਤ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ-ਸ਼ਿਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਮੰਨ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਯਗ ਦਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯੱਗ ਦੱਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂਗਾ। (ਤਾਲੀਆਂ) ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਉ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਈਨਾਰੇਟੀ ਅਤੇ ਮੇਜਾਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਫਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਏ ਹਨ ਮੈਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਂਡ, ਰਵਿਸ਼ ਅਜ ਏਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਰਮੀਮਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਲੀਆ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਲਕੇ ਬਨਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ

ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਰੁਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਰਿਜਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮਰਜਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਸਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟੇਗਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਿਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਧਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 50—50 ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਧਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ? ਪਰ ਜੈਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਖਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 50—50 ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚੋਂ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਕਢੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ 10—12 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਥੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 2—2½ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਸ਼ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਲੁਕ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਸੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(Quorum Bells sounded)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲੋਗੇ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ 18 ਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। (How much more time will the hon. Member Giani Zail Singh take, ? He has already spoken for 18 minutes. He should finish within two or three minutes.)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਛਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਥੇ ਜਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਲਬ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਓਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

"ਮੁਫਲਿਸ ਖੁਦਾ ਕੇ ਰਹਿਮ ਪੇ ਜੀਤੇ ਹੈਂ !" ਉਹ ਗਰੀਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਥੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਥਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕੇ ਐਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਢ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਏਥੇ ਉਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਤਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਏਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 10 ਦਿਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ, 10 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 2 ਹਫਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗੇ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਘੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਸੀ ਦੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਬਿਆਨਾ ਉਨਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਰਖੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਫਾ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਧਿਆ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਕੋਲ ਜੀਪ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਐਨੀ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿਘ ਗੋਗੋਆਣੀ (ਜ਼ੀਰਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਰ

[ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਆਣੀ]

ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹਲ ਕਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਿਚੋ ਤਾਣ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹਨ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਮਾਈ ਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਐਨੀ ਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਪਾਇਲ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੈਪਟਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਬਿਓਰੋਕਰੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਐਂਟੀ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ।

ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕ ਅਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

(Quorum Bells Sounded)

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਨਥੀਆ ਨੇ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਲੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਬਾਬੂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ

ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਉਪਰਲੇ ਤਾਂ ਕਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫੇਜ਼ਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਫੇਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਡੀਆ ਵਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਲਣ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਜਿਤਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਵਿਲਿੰਗ, ਐਨਥੀਉਜ਼ੀਐਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਰਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫੌਜੀ ਅਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜੈਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਨਰਲ ਕਟੋਚ, ਜੈਨਰਲ ਬਰਾੜ ਔਰ ਏਅਰਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਨਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਗਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਚਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ—

But the General sitting in the Rajya Sabha will ask "Mr. Chavan, provide so many things, provide this thing to Punjab, do this, do that" Mr. Chavan will rise and say "Sir, this is like this."

ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਬਲ

[ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਅਤੇ ਮੈਚਿਉਰਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਲਉ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬੈਲਟ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਉਥੇ ਮੋਡੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ—

ਭੁਖਿਆਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਐਹ ਲੈ ਫੜ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ।

ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਉਗਦੀ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਣੀ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 62 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਠਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਠੀਕ ਭਾਓ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਭਾਓ 49 ਤੋਂ 53 ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਦੀ 67 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਅਜ ਕਮਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਬਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵੈਗਣ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਥੇ ਭੇਜ ਦਿਉ ਉਹ ਚੂਪ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ (ਹਾਸਾ) ; ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਛਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ (ਵਿਘਨ) ਕਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੁਣ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੂਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਉਸਤੇ ਇਹ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੂਦ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਮਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਭੋ ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਇਕ ਧੜਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਧੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁੜ ਵੀ 13 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸੇਡਾਈਜ਼ਡ ਸੂਦ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਓ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਢੇਰ ਬਰਾਂਡ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੋਮ ਸਾਇਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਚੇ ਉਚੇ ਮਨਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਜੈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸੇ ਐਗਰੀਗਲਚਰਲ ਰੀਸਰਚ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿਤਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਇਲੇਕੋ' ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਟ ਸਨੇਲਜ਼ ਪੇਸ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਤਲਵਾੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਸੇ ਪਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਾਜੈਕਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਕ ਇਸ ਗਲ ਦਾ

[ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿਘ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਜ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਠਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਵੈਕੂਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਇਕ ਦਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਡ ਨਹੀਂ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਓ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਮੋੜ ਲਈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਨਸਿਡਰ ਕਰੇ ਅਤੇ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਸੀਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਹਸੀਲ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਨੇ ਹੀ ਤਹਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਤਹਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਹਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਐਨੀ ਬੜੀ ਤਹਸੀਲ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਹਸੀਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਪਾਇਲ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਜੋ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੁਲਫਲੈਜਡ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ...........

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ "ਬਾਬਾ ਜੀ" ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : माननीय सदस्य को बोलने के लिये कभी कभी मौका मिलता है, इसलिए उन्हें ऐसे लफ्ज स्पीच करते हुए इस्तेमाल नहीं करने चाहियें। (The hon. Member speaks very rarely. Therefore, he should not use such an expression in his speach.)

ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ : ਮੈਂ "ਬਾਬਾ ਜੀ" ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੁਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਜਟ ਉਤੇ ਹਰੀਜਨ

ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ । ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਨਾਕਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭੀ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਚਾਲਾਕ ਆਦਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੀ ਸਚ ਮੁਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲਈ ਲਈ ਕੁਝ ਭੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਮੇਜਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹਰੀਜਨ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਉਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸੀਲੀਟੀ ਭੀ ਤਕੜਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੀਲੈਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕੜਿਆਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ

[ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ]

ਹੈ । ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 2, 3 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਨ । ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਭੀ ਲੈਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਭੀ ਕੀਤਾ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵੇਖੇ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੂਟ ਦਾ ਸੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਖਦਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਤੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਪੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਖੁਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਫਲਾਂ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਜ਼ਾਬ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ 2,500 ਰੁਪਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2,500 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 5,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਵਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਝ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੰਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੰਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ

ਸਕਣਾ । ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ........(ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ । ਆਪ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਘੰਟੀ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ।

कंवर राम पाल सिंह (पुंडरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज बजट पर डिस्कशन हो रही है। इस सभा का यह आखरी बजट सैशन है। जो बजट स्पीच फाईनैंस मिनिस्टर साहिब ने इस हाऊस में पढ़ी, उस को अगर पढ़ते हैं तो उस से उम्मीद की कुछ झलक नज़र आती है कि शायद जिस ढंग से बजट स्पीच में हर कदम को डिसकस किया गया है कोई डिवैल्पमैंट हो। मैं यह कहने के लिये तो तैयार नहीं हूं कि जब से यह सरकार आई है इस सूबे की कोई तरक्की नहीं हुई है। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि कितनी तरक्की की हम को उम्मीद थी या जितनी हमारी प्लानिंग थी इस ढंग से हम तरक्की करेंगे, उस हिसाब से हम तरक्की नहीं कर पाए हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के बारे में जो डिवैल्पमैंट कमेटी की रिपोर्ट आई है वह इस बात का सही सबूत है कि जो डिवैल्पमैंट हर शोभे में हर एरिया में होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। जिस वक्त यह कमेटी बिठाई गई थी तो उस वक्त हरियाणा के एम. एल. एज़. बिना किसी पार्टी के इम्तयाज़ के चीफ मिनिस्टर साहिब से मिले थे और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि बजट से पहले इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और इस सिलसिले में बजट में खास तौर पर प्रावीज़न रखा जाएगा। लेकिन जब बजट स्पीच को देखा जाता है तो उस में केवल इस बात पर ज़िक्र कर दिया गया है कि हरियाणा की डिवैल्पमैंट के बारे में कमेटी बिठाई गई है, इस की रिपोर्ट आई है उस को कनसिडर किया जाएगा। मैं नहीं समझ पाया कि यह कंसिड्रेशन कितनी देर तक चलेगी या कंसिड्रेशन बता कर ही इस मामले को खटाई में डाल दिया जाएगा। अगर सरकार का मनशा उस रिपोर्ट को इम्पलीमैंट करने का होता तो बजट में इस के लिये स्पेशल कोई प्रोवीज़न की जाती लेकिन वह चीज तो इस में नज़र नहीं आ रही। हां, बजट से दो तीन चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक तो यह कि गवर्नमैण्ट ने एक मामले में बड़ी मज़बूती के साथ स्टैंड लिया और उस में कामयाबी भी हासिल की। हमारे मैम्बर साहिबान हर सैशन में मांग करते रहे कि बाडर पुलिस का खर्च पंजाब अकेला क्यों बरदाश्त करे । हमारी सरकार ने मज़बूती के साथ स्टैंड लिया और हमारे व्यूज़ सैंट्रल गवर्नमैण्ट के सामने रखे और इस मांग को पूरा करवा लिया। मैं इस के लिये अपनी सरकार को बधाई देता हूं। वह बधाई की पात्र है। दूसरे हमारी सरकार ने जो मेहरबानी हमारे ज़िले पर की है, उस के लिये भी मैं उन को बधाई देता हूं। वहां से को-आप्रेटिव शूगर मिल के लिये बहुत दिनों से मांग की जा रही थी। इस साल बजट स्पीच से यह नज़र आता है कि वह कोआप्रेटिव शूगर मिल करनाल को अलाट हुई है। जहां तक मुझे मालूम है पांच साला प्लान में पंजाब को एक मिल दी गई थी और वह मिल करनाल को अलाट की गई है इस लिये मैं पंजाब गवर्नमैण्ट को वहां के

[कंवर रामपाल सिंह]

लोगों की तरफ से बधाई देता हूं। इस सदन में मैम्बरों की तरफ से एग्रीकल्चर की डिवैल्पमेंट के लिये बार बार कहा जाता रहा है। इस सूबे की 80 फीसदी पापूलेशन एग्रीकल्चर पर डीपेंड करती हैं। पिछली बजट स्पीच में भी एग्रीकल्चर डिवैल्पमेंट के लिये बहुत से इनसैंटिवज़ का जिक्र किया गया। अब की बार भी बहुत जिक्र किया गया। लेकिन अगर बजट स्पीच में नज़र मारें तो उन्होंने हर टौपिक को लेकर अलग अलग डिसकस किया है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर डिवैलमैंट एक बेसिक डिवैल्पमैंट है जो कि हमारे देश की 80 फीसदी प्राब्लमज़ को हल कर सकती है। आज कल हमारे देश के सामने फूड प्राबल्म सब से बड़ा और भयंकर प्राब्लम है। एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है कि अगर इस की तरफ ध्यान दिया जाए और इस को डिवैल्प किया जाए तो फूड की समस्या साल्व हो सकती है। सिर्फ यह कह देना कि हम एग्रीकल्चर की डिवैल्पमेंट बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत से प्लानज़ बना रहे हैं तो मैं प्लानज़ के बारे में यह कह देना चाहता हूं कि अभी एक डेढ़ महीना हुआ ....

2.00 p.m. (Kanwar Rampal Singh was still on his legs when the House adjourned.)

उपाध्यक्षा : सदन चौदह तारीख को दो बजे मिलेगा। (The House stands adjourned till 2.00 p.m. on the 14th March, 1966.)

(The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 14th March, 1966).

8682 PVS-384—2—9-66—C., P. & S., Pb., Chd.

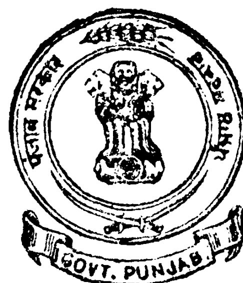
PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

14th March, 1966

Vol. I—No. 18

OFFICIAL REPORT



CONTENTS

Monday, the 14th March, 1966

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs : 6.85

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 18, dated the 14th March, 1966

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ	ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ	(18)3	34
POSSESSION OF	POSSEIO N O	(18)4	13
श्रा हुन्ना मल	श्री हुन्ना मल्ल	(18)5	1
ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ	ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ	(18)7	27
issued	issused	(18)9	5
competition	compitition	(18)9	25
irregularly	irregularity	(18)9	27
purchase	purschase	(18)10	13
Infructuous expenditure	Infructions expenidture	(18)11	38
filed	filled	(18)12	27
fast	fact	(18)12	32
Scrutiny	Scruting	(18)12	33
purchased	pruchased	(18)13	7 from below
New	Now	(18)16	26
Delhi	Dlehi	(18)17	14
penalty	panalty	(18)17	6 from below
for 23,475 kgs	for 2.3475 kgs	(18)18	18 —do—
Rs. 523	Rs. 5.23	(18)18	17 —do—
put	pu	(18)20	3
become	becom	(18)20	12
August	Augus	(18)21	3
enumerated	enumeated	(18)21	5 from below
injudicious	in jiditious	(18)22	18 —do—
श्री	श्रीं	(18)29	3
श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री	श्री. औम प्रकाश अग्निहोत्री	(18)29	3 from below

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
[Minister for Health]	ister for Health]	(18)32	1
distinct	distinet	(18)43	3 from below
HOLDERS	HOLD	(18)45	3
Girls	Gilrs	(18)46	S. No. 26, col. 3
Government	Governmnt	(18)47	S. No. 40, col. 3
Headmistress	Headmstress	(18)50	S. No. 99, col. 3
full	ful	(18)57	S. No. 216, col. 5
Phagwara	Bhagwara	(18)57	S. No. 217, col. 4
	Phgwara	(18)58	S. No. 222, col. 4
कामरेड राम प्यारा	श्री राम प्यारा	(18)70	1
	कामरेड राम यारा	(18)73	1
Mrs. Om Prabha Jain	Mrs. Om Prabha Ja n	(18)71	last but one
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	(18)74	8 from below
ਠੀਕ	ਠੀਲ	(18)85	11 —do—
ਸਟੇਟ	ਸਟਟ	(18)96	14 —do—
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ	ਐਜਕੇਸ਼ਨ	(18)96	5 —do—

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 14th March, 1966

The Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh, at 2 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CULTIVABLE WASTE LAND

*8963. **Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the area of cultivable waste land given to the landless cultivators and agricultural labourers, respectively, during the Third Plan Period in the State, district-wise;

(b) whether Government intend to lease out for long periods such lands as have been kept vacant for two or three years by the landowners owning thirty acres or more of cultivated or cultivable land; if so, details thereof;

(c) the number of landless cultivators and agricultural labourers, respectively, in the State, district-wise, who have not so far been resettled on surplus area or on Government lands and the measures contemplated to resettle them ;

(d) whether the Government intend to make a thorough survey of the cultivable waste land in the State through an independent agency to find out how much such waste land could be made available to the landless cultivators and agricultural labourers in the State ?

Sarder Harinder Singh Major : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Lands lying uncultivated for six or more consecutive harvests are taken over under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, and are leased out to lessees for a period ranging from 7 to 20 years.

(c) Surplus land declared under the tenancy laws is allotted to tenants on the land of small landowners or those on the reserved area of big landowners. It is not allotted to landless cultivators and agricultural labourers. The number of eligible tenants, who have not been resettled on surplus area is given in the statement referred to above.

(d) In view of reply to part (b) above, question does not arise.

[Minister for Revenue]

STATEMENT

Sr. No.	Name of the District	Cultivable waste land leased out to landless cultivators during Third Five Year Plan	Cultivable waste land leased out to Agri. labourers during Third Five Year Plan	Number of tenants eligible for the allotment of surplus area and who have not so far been resettled
1	2		(a)	(c)
1.	Hissar	—	—	5,635
2.	Rohtak	300	—	706
3.	Gurgaon	3,773	750	19,385
4.	Karnal	42	—	23
5,	Ambala	725	75	14,434
6.	Simla	—	—	—
7.	Kangra	—	—	64,322
8.	Hoshiarpur	—	—	20,962
9.	Jullundur	3,274	—	1,351
10.	Ludhiana	590	—	25
11.	Ferozepur	11,806	1,791	173
12.	Amritsar	—	4,332	11,392
13.	Gurdaspur	3,861	—	22,650
14.	Kulu	—	—	—
15.	Patiala	318	—	53
16.	Sangrur	190	—	282
17.	Bhatinda	—	—	15
18.	Mahendargarh	—	—	335
19.	Kapurthala	390	—	37
	Total	25,269	6,948	*1,61,780

*Out of 1,61,780 tenants, 58,046 are pre-Act and 95,022 post-Act tenants. The pre-Act tenants are mostly in Hoshiarpur and Kangra Districts. Surplus area for their resettlement is not available in their own districts and they are not willing to move to other districts for resettlement.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला कांगड़ा और होशियारपुर में जो 1,61,780 मुज़ारे अभी तक रीसैटल नहीं हो पाए, इसका क्या कारण है ? क्या सरकार ने उन को रीसैटल करने के लिए उन को दूसरे ज़िलों में सरप्लस ज़मीन देने का यत्न किया और अगर नहीं किया तो इसकी क्या वजह है ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ।

As far as I can recollect, efforts were made to re-settle the tenants who were ejected from the land. But since the land available in Hoshiarpur was not enough, as compared to the number of tenants, the efforts did not bear any fruit.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जैसा कि वज़ीर साहिब ने बताया है कि मुजारे दूसरी जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्या मैं उन से जान सकता हूं कि आया दूसरे जिलों में इतनी सरपलस जमीन है जहां पर कि 1, 61, 780 मुज़ारों को बसाया जा सके ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਲਗ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟਸ 100 ਹੋਣ ਔਰ ਸਰਪਲਸ 5 ਏਕੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वांयट आफ आडर, सर। सवाल के जवाब में बताया गया है कि मज़ारे दूसरी जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं । इस लिए मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने कोई ऐसी कोशिश की, उनको नोटिस दिए कि उनको फलां फलां डिस्ट्रिक्ट में जहां पर कि जगह खुली पड़ी है, बसाया जा सकता है ? मैं इस बात की डैफिनिट रिप्लाई चाहता हूं ।

Revenue Minister : As far as I remember, an effort was made to settle them. I can now say that an opportunity will be given to the tenants to re-settle them in other districts, if they are prepared to go out of the district.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ efforts will be made to remove those hurdles.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ 'Tribunal ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ tenants ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

Revenue Minister : No, Sir. There is no such thing.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਨਣ ਵਾਸਤੇ 1956 ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਗਰ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 1956 ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਆਏ; ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਕੀ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੂਲ ਰੀਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ I can simply say that I can take action against the defaulter irrespective of his position.

ILLEGAL POSSE() N O GOVERNMENT LAND IN HISSAR CITY

*9472. **Shri Hunna Mal** : Will the Minster for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a political person illegally took possession of Government land situated in between the Gujri Mahal and Civil Hospital in Hissar City adjacent to his garden and started construction of a building thereon during the months of May/June , 1965;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whethere this fact was brought to the notice of the Government officers who after holding an inquiry held the said possession as illegal and got the building dismantled;

(c) if reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the name of the person who took illegal possession, his political position, the area of the said Government land in feet and the market value there of;

(d) whether any action has been taken against the person referred to in part (c) above; if so, what, if no action has been taken; the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh Major :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) (i) Shri Balwant Rai Tayal, Ex-M.L.A.

(ii) 1 Kanal and 8 marlas (7, 623 Sq. feet.)

(iii) Rs. 8,400.00

(d) Yes ; notice was served on Shri Balwant Rai Tayal and in compliance thereto, he removed the encroachment.

श्री हुन्ना मल्ल : क्या वज़ीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बलवन्त राय तायल रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी अम्बाला का मेम्बर भी है और अगर है तो जैसा कि इस सवाल के जवाब में बताया गया है क्या उसके पेशेनज़र उस के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता और अगर नहीं लिया जा सकता तो क्यों ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने जवाब में बताया है कि उस ज़मीन पर जो कि 7,623 सक्वेयर फुट है और जिसकी कीमत 8,400 रुपए है, श्री बलवन्त राय तायल, ऐक्स ऐम. ऐल. ए. ने नाजायज कबज़ा रखा । क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह जो उसने इतनी देर तक यह नाजायज कबज़ा रखा, क्या उस का रैंट वसूल करने के लिए सरकार ने कोशिश की और अगर नहीं की तो इस की क्या वजह है ?

Minister : That encroachment has been removed by him.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਉਸ ਐਕਸ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਪੁਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ । ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री ; क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस एनकरोचमेंट को रिमूव करने में ही सरकार की तसल्ली हो गई है और अगर तसल्ली नहीं हुई तो क्या उस पर कोई पैनलटी लगाई गई है ?

ਮੰਤਰੀ : ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਗਲ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । For the time being it was considered enough. ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

श्री हुन्ना मल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उसनें इस एनक्रोचमैंट के अलावा कोई और भी दूसरी एनक्रोचमैंट की हुई है जो कि सरकार के नोटिस में आई हुई है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ਼ਾਲਬਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਗ਼ਾਲਬਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਤਾਇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ to show cause why action should not be taken against him.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਅਗੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਤੇ ਐਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ political ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ? Why does Government think it desirable to appoint him on so many different Committees ?

(*No reply was given.*)

श्री हुक्म चन्द: क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी हालत में, जब कि वह आर. टी. ए., अम्बाला का मेम्बर है तो उसके लिए उसके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया जाता ?

Minister: It would be proper if this question could be put to the Transport Minister.

COMPLAINT AGAINST TEHSILDAR, KAITHAL

***9662 Chaudhri Ran Singh**: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Chief Minister received a complaint/complaints from any legislator of Karnal District against Shri Kapoor Singh, Tahsildar Kaithal, during the month of December, 1965, or January, 1966; if so, the contents thereof and the details of the action taken in the matter and if no action has yet been taken, the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh, Major: Yes, sir. A complaint dated 17th December, 1965, was received. It was alleged therein that the Tahsildar, was anti-Harijan and invariably harassed them whenever any one of them went to him for obtaining a certificate required from a Tahsildar. It was further alleged that the legislator himself went to the Tahsildar with some applications, which he had verified, but the Tahsildar refused to issue the requisite certificates and behaved in an objectionable manner. Further that quite derogatory and objectionable language was used by this Tahsildar while addressing the M. L. A.

On enquiry it was found that the Tahsildar was not rude to the legislator and that he genuinely felt that he could not sign the certificates in question. In view of this no action against the Tahsildar was considered necessary. The Tahsildar was, however, advised not to give cause for such complaints, in future.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

चौधरी रण सिंह : सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहब ने फ़र्माया है कि इस बारे में इनक्वायरी की गई थी लेकिन एलीगेशन जो थीं वह साबत नहीं हुईं । तो मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि यह इनक्वायरी किस अफ़सर ने की थी और इस कम्पलेंट में जिन आदमियों का नाम था जिन को तहसीलदार ने सर्टीफिकेट देने से इनकार किया था, क्या उस इनक्वायरी के वक्त उन को बुलाया गया था ?

Minister: I have not got the complete information with me here at present. But the Chief Minister sent this application to the Commissioner for a Report and the Report of the Deputy Commissioner, Karnal, was obtained.

चौधरी रण सिंह : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब ने जो यह फरमाया है कि इस वक्त उन के पास इस बारे पूरी इनफर्मेशन नहीं है तो क्या वह इस बारे में दोबारा इनक्वारी कराने के लिए तैयार हैं और इस के साथ ही मैं उन से यह भी पूछना चाहता हूं कि इस में यह जो लिखा है इस के क्या मायने हैं—that he genuinely felt that he could not sign the certificates in question.

ਮੰਤਰੀ : ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ he is sadly mistaken. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਿਉਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ then certainly, Sir, the M. L. A. will be given an opportunity to say whatever he likes.

श्री अमर सिंह : क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कम्पलेंट चीफ मिनिस्टर साहब को एड्रेस की गई थी वह किस एम. एल. ए. के नाम पर थी और क्या उस ऐम. एल. ए. के इस की इनक्वायरी करते वक्त कोई ब्यान लिए गए थे?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਲਬਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਤਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ another opportunity will be given to the M. L. A to substantiate the charges levelled in his complaint.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪਰੈਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦਿਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

(*No reply*.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या माल मंत्री जी बताएंगे कि सवाल के जवाब में तो उन्होंने बताया है कि उस तहसीलदार ने कोई रूड बीहेवियर नहीं किया तो इस का क्या कारण है जो उस को एडवाईज़ किया गया है कि वह आगे के लिए महृतात रहे?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਨਵਾਲਵਡ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਇੰਦਾ ਲਈ ਮਹੁਤਾਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इस इनक्वायरी की जो रिपोर्ट उन के पास आई है, क्या वह चौधरी रण सिंह को दिखाने के लिए तैयार हैं ताकि वह देख सकें कि इनक्वायरी ठीक ढंग से हुई है कि नहीं हुई ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੈ ਆਉਣ ਔਰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ।

RESOLUTION PASSED BY THE GOVERNMENT TEACHERS' UNION, LUDHIANA, AND FORWARDED TO D. E. O.

*8881 **Sardar Kultar Singh**: Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the total number of resolutions passed and forwarded to the District Education Officer's office by the Government Teachers' Union, District Ludhiana, during the period from 1st January, 1964 to 31st December, 1965 and a copy of each of the said resolutions be laid on the Table of the House;

(b) the number of resolutions out of those referred to in part (a) above on which action has been taken;

(d) the number of resolutions on which no action has so far been taken together with reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra: (a) Nil

(b) and (c) } Question does not arise.

FINANCIAL IRREGULARITIES IN GOVERNMENT AYURVADIC CENTRAL PHARMACY, PATIALA

*9793 **Comrade Babu Singh Master** (Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal on his behalf): Will the Minister for Health be pleased to state :

(a) whether there were any financial irregularities in the Government Ayurvedic Central Pharmacy, Patiala, during the last two years resulting in huge loss to the Government;

(b) whether a departmental audit of the Pharmacy accounts was coducted by the Directorate of Research and Medical Education, Punjab, in 1964;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the details of the Report of the auditors and the action taken by the Government, if any, in the matter ?

Shrimati Om Prabha Jain: (a) Yes

(b) Yes

(c) A copy of the Audit Report is placed on the Table of the House;

Supervisory charge of the Pharmacy has since been taken away from the Principal Government Ayurvedic College, Patiala, and placed under the charge of Director, Health Services, Punjab. The case has been entrusted to the Vigilance Department for further investigation.

Subject:—Report of the findings in complaint-cases against the Principal, Government Ayurvedic College, Patiala.

Reference :—Secretary to Government, Punjab Medical and Health Department Endst. No. 5956-ASOII-HBII-64/29609, dated 18th August, 1964 and orders dated 27th August, 1964 issused thereon by the Deputy Director, Research and Medical Education at page (2)-ante.

In compliance with the above orders, all of the initial-records relating to the cases complained against were scrutinised for ascertaining factual position. After thorough study of each case, irregularities committed by the Principal were enumerated in a "Questionnaire" handed over to him for explaining his position with respect thereto, so that final decision thereupon, could be easily taken by higher authorities without further delay. Copies of the 'History' of each individual case as per office-files, "Questionnaire" framed thereon and "Explanations" of the Principal against them are placed below, in original, for perusal.

The serious financial irregularities committed, seriatim, are however, summarised hereunder :—

Case No. 1 PURCHASE OF TABLET MAKING MACHINE

1. (a) Tender notice, was issued to the local businessman at Patiala only. Manufacturers of these machines at Nikodar and Ludhiana etc., were ignored despite advice of the Mechanic/Technician of Pharmacy workshops.

(b) Time and date of opening the tenders were not notified to tenderers without which they could not come for being present at the time of opening the tenders as required under the rules.

(c) *While comparing various quotations*—Only the cost price was kept in view. Status of tenderers and quality of machinery offered in compitition by different firms were totally ignored in disregard of Rule 6 of Appendix 5 in P.F.R. Vol. II, as a result of which order was irregularity placed with a contractor whose supply has not only been 'wrong' but also "unserviceable".

2. Verbal order was, irregularly, placed by the Principal without even prior-sanction of the Director, Research and Medical Education. This violated the provisions of Rule 7 of Appendix 5 and Rule 4 and 7 of Appendix 14 in P.F.R. Vol. II and Rule 17.2 P.F.R. Vol. I

3. *The Security deposit of Rs. 100 required*—under condition No. 2 of Tender Notice was also not obtained from the firm while entering into an agreement of supply with them.

4. Bill of Rs. 2372.99 was, objectionably, passed by the Principal for making 100 per cent "Advance payment" in anticipation of all the supplies still to be made by the firm. This order of the Principal is in total defiance of all the Financial rules framed by the Government.

5. Order was placed for the purchase of 'Tablet Making Machine" whereas the firm mischievously supplied an unserviceable "Biscuit Making Machine" as repeatedly stated in Principal's letter dated 26th August, 1964 (addressed to the Director, Research and Medical Education) and written statement dated 9th October, 1964, (placed below) of Shri Madho Singh Mechanic/Technician of Pharmacy Workshops. Written orders dated 31st March, 1964 given by the Principal for taking this machine (though wrong and unserviceable) on the Stock Registers and making full-payment of its bill were most objectionable given to favour the firm at public costs.

[Minister for Health]

6. Since the correct and complete machine on order was virtually, still not supplied by the firm, undue favour was again done to firm by the Principal through his following *wrong-decision* dated 31st March, 1964:— "Take an affidavit from the Contractor. Post-facto sanction will be taken from the Director, Research and Medical Education. The bill may be passed and submitted to the Treasury for payment".

Examination of the records has revealed that even this "Affidavit" was not obtained from the firm before or after their bill was passed for payment by the Principal. It will not be out of place to mention here that this bill could not be passed for full payment even on the basis of said affidavit.

7. The firm has failed to supply the required machine urgently needed in the Pharmacy workshops but no risk-purschase action has so far been taken by the Principal, in terms of condition No. (1) of the tender Notice as also Director, Research and Medical Education letter No.............................. dated........................ .

Note.—Concluding sentence of this complaint is that "the firm from whom he has accepted a sum of Rs 500 is now being asked to get back the machine".

Appropriate investigation on this aspect of the complaint could only be done by the Police-Authorities. It is, however, quite apparent that findings at para (2) to (7) above considerably prove mis-use of his powers in favour of the firm.

Case No. II. PURCHASE OF GLASS CARBOUYS

1. In this case the first and second lowest quotations were respectively those of M/s Verindra Jain Patiala and M/s Obrai and Co., Patiala as deailed below:—

I. Quotation of M/s Verindra Jain	II. Quotation of M/s Obrai and Co.
(i) Rate per carbouy including cost of one wooden frame and one rubber cork fitted with the carbouy.	(i) Rate per carbouy including the cost of one wooden frame only.
(cost of one cork is about 50 nP. each) Rs. 27	(without cork.) Rs 26.80 nP.
(ii) Cash discount of 1% was offered.	(ii) No such cash discount was offered.
(iii) Insurance charges were not demanded.	(iii) Insurance charges were claimed extra.
(iv) Supply within one month	(iv) Supply within two months.
(v) Sample of glass-carbouy supplied by this firm was approved being better in following respects:— (a) Larger size. (b) Better glass and shape. and (c) Transparent Glass	(v) Sample brought by this firm was outrightly rejected.

In view of the above it is quite clear that the Principal misused his powers while giving the following written (incorrect) orders in favour of M/s Obrai and Co., Patiala whose quotation was the second lowest:—

(a) "Rate of M/s Obrai and Co., is the lowest and is approved.
(b) "M/s Obrai and Co., Patiala may be asked to make the supplies strictly in accordance with the sample supplied by M/s Verindra Jain Patiala".
(c) If M/s Obrai and Co., Patiala do not agree to this position the order will be cancelled."

2. Perusal of the file relating to this case has disclosed that " a change in the sample originally brought by M/s Obrai and Company was also, somehow or other allowed and made" as remarked by the Superintendent Pharmacy and Stores in his noting dated 6th January, 1964 (see page 23) without any subsequent contradictory recorded-contention by the Principal to whom the said noting on the file was sent for his consideration. Despite this objectionable change, sample of M/s Obrai and Company remained un-approved/ rejected as seen from the office-notings on that file. In this case, the Principal, is responsible for the following financial irregularities:—

(1) *Approval*:—of the second lowest tender of M/s Obrai and Co., Patiala without getting prior sanction of the Director. Research and Medical Education which could be had only on the basis of recorded reasons, if any, in their favour.

(2) *Placement of order* with M/s Obrai and Co., Patiala with *an objectionable condition* "to make supplies as per approved -sample of M/s Verindra Jain Patiala."

3. *Written instructions* to the effect that if M/s obrai and Co., do not make supplies as per approved sample of M/s Verindra Jain, the *purchase order will be cancelled.* In these instructions the firm was objectionably favoured with. In its place orders should, in this pretext, have been that "risk purchase will be made at their cost if they failed to execute the order as per its items and conditions."

4. Reply of the Principal given vide his letter dated 16th September, 1964 (see page 27) in response to Director, Research and Medical Education office No. S P (1)-64/4130, dated 7th August, 1964 (see page 24-25) viz., complaint of M/s Verindra Jain Patiala—was not only evasive and incomplete but also void of actual facts and as such mis-leading.

5. *Sample* of M/s Obrai and Company, Patiala brought originally was changed though without the desired success as mentioned in para (2) above.

6. M/s Obrai and Co., were given undue favour in his written orders that they may be asked to make supplies according to the approved sample of M/s Verindra Jain Patiala the complainant.

7. *Old Carbons* were purchased *at the rate quoted for new*. From the above conclusion it is clear that complaint of M/s Verindra Jain Patiala is correct and based on facts. Orders for taking further action may please be given in this case accordingly.

Infructious expenidture : of Rs. 21.30 incurred by the Principal through placing the order, in an unauthorised way, may also either be got regularised with the sanction of the competent authority or orders be issued for its recovery from the defaulter.

Case No. III Overpayment of Rs. 246.33 made to *M/s Shiv Shakti Traders, Patiala*

Risk purchase of 'Sonth' was effected twice at the cost of M/s Pushkarna Ayurvedic Pharmacy Amritsar, once during December, 1963 and thereafter in February, 1964. The financial irregularities committed by the Principal, in this case, are as under:—

1. In both the risk purchase cases, the *first lowest* quotations were those of M/s Jatinder Paul Jain Patiala. The Second-lowest bidder were M/s Shiv Shakti Traders Patiala. As such orders should have been placed with M/s Jatinder Paul jain and not with *M/s Shiv Shakti Traders* unless prior sanction of the Director Research and Medical Education could be obtained in favour of the second-lowest on the basis of recorded reasons. Undue favour was, however, done to M/s Shiv Shakti Traders Patiala as both of the orders at the rate of Rs 3.98 per kg. and Rs 4.75 per kg. were placed on them by the Principal.

2. Sonth weighting 33.376 kgs. was supplied by M/s Shiv Shakti Traders Patiala during March, 64. Its bill should have been passed at the rate of Rs 3.98 per kg. for 317 kgs. and at the rate of Rs 4.75 per kg. for the balance of 14.376 kg

[Minister for Health]

plus 1 per cent sale tax on the total cost thus worked out. The bill was, however, incorrectly passed and paid for whole of the supply at the rate of of Rs 4.75 per kg. thereby making an over payment of Rs. 246.33 to the firm. This over-payment was caused by the principal on 17th April, 1964 despite of the fact that:—

(a) On 31st March, 1964 whole of this payment was withheld by written instructions of the Superintendent pharmacy and Stores.

(b) Orders were also issued vide letter No. 1987 dated 4th April, 1964 to correct this bill before its payment by the office-accountant.

The Accountant when asked to explain his position replied that he was compelled to make this payment on the basis of following order dated 17th April, 1964 given by the Principal :—

"Since the firm M/s Shiv Shakti Traders have supplied Sonth against the second order also, their payment detained by you in connection with the supply of sonth may be released".

The supply referred to in this "Release-order" was rejected by the Purchase Committee. Payment at the rate of Rs 4.75 kg. could not be allowed and made untill and unless full supplies at the lower rate of Rs 3.98 kg. had been executed.

3. During the examination of this case of over-payment, another irregularity came to notice in which 100 kgs. of "*Shilajeet Pather*" found surplus in its stock with the Manufacturing section was irregularly not allowed, by orders of the Principal, to be brought on the receipts side of the stock Register. Whole of this quantity of Shilajeet Pather, thus, remained un-accounted for in the stores Accounts of the Pharmacy. It was also told by the office-staff that firms bill for this quantity was also received but has been filled without taking any dueaction thereon. This bill was however, not produced on demand.

Case No. IV. Loss of Rs 500 to Government through Excessive *purchase of "Kamal Dodagiri"*

"Kamal-Doda-giri" is a fact deteriorating raw drug which cannot be successfully preserved for more than a year at the most. Scruting of the last-four five years records shows that its reqirement never exceeded to maximum annual limit of six to seven kgs. During this year, however, 110 kgs. of this raw-drug has been purchased against an incorrect order for 118.66 kgs. got placed by the Principal, with M/s Bhaiyon ka Dwakhana, Amritsar, which is sixteen times more than the fixed maximum annual requirements.

This purchase has been made in total disregard of the Financial Regulations laid down by the Government vide Rule 2.10 (1) and (2), 15.2 (b), 15.18 and 15.21 of P. F. R. Vol. I as also the "Pharmacopia" approved by the Government. As regards consumption it is stated that only 7.143 kgs. of Kamal Doda Giri has so far been actually consumed. An equal quantity is, at the most, liable to be consumed by the end of current financial year if at all the whole of other component raw drugs are also made available for preparing double quantity of the relative madicines whole of the existing stock has since been infested by the insects and is liable to be to tally spoiled as stated and confirmed by the joint report of Incharge Stores, I, Incharge Manufacturing unit and Superintendent Pharmacy and stores received vide their letter No. P/71 dated 28th October, 1964 (see page No. 49).

The Government has, thus been put to a loss of about Rs. 500 in this injusticeably excessive purchase as mentioned in the complaint.

In this complaint it has also been remarked "*This was done to earn money*"

Since the Principal has failed to appropriately justify so much excessive purchase of this fast deteriorating raw drug, the authorities may take decision on this aspect of the complaint as is considered most appropriate.

Case No. V. RISK PURCHASE OF MISRI AND KESHAR ETC.

During investigations in this complaint it has been verified that orders placed for the costly raw drugs like Kehrwa Samai, Keshar, Sat Ajwain and Misri etc. were not executed by the firms. Decision was taken to effect the risk purchases of all those costly and urgently needed drugs at the cost of defaulters. Thereupon quotations were also invited and compiled in a comparative statement dated 13th March, 1964 (copy placed below at page 60). Lowest rates offered in respect of each raw drug were marked for placing the order with their tenderers. Risk purchase orders, were, however, not placed because of the following orders dated 26th March, 1964 recorded by the Principal on the back of aforesaid comparative statement:—

> "Orders for effecting purchases except kehrawa Samai, Keshar, Desi-Khand, Sat Ajwain and Misri may be released." All of the costly raw drugs referred to in this order were immediately needed in the Pharmacy as reported by Shri O. P. Gupta Incharge Stores I in his letter No. 4, dated 24th February, 1964 (office diary No. 1061 dated 25th February, 1964 (see page 57). Reasons for which risk purchase orders were not allowed to be placed by the Principal were not kept on on record. This order in favour of the defaulting firms has not only resulted into a heavy loss of more than rupees seven thousand to the State Exchequre (see statement at page 64) but also great delay in manufacture of urgently needed medicines while their other component raw-durgs already kept continuously de-deteriorating in the pharmacy stores.

Instead of effecting risk purchases of all those costly items, as decided upon previously, it is highly surprsing to note that original orders placed with those ultimately defaulting firms have been cancelled by the Principal thereby ignoring the public interests despite recorded resistance and correct opposition of the Superintendent Pharmacy and stores on the genuine grounds that the same are urgently needed and moreover cost of all those drugs has since considerably risen in the market. In the concluding sentence of this complaint it has been remarked that:—

> "The contractors after paying something got the orders cancelled and no risk purchase was made". In view of the above position found on records, this allegation of the complainant cannot be without basis. The exact position could, however, be investigated by the Police Authorities only, because Audit is not to make enquiries from other than the official sources.

Case No. VI. PURCHASE OF BANSLOCHAN

Irregularities committed in this case are:—

1. Order for the purchase of 300 kgs. Banslochan at the rate of Rs 53 per kg. amounting to Rs 18,900 was irregularly placed without prior sanction of the Government required under Rule 17.2 P.F.R.
2. Sufficient balance of about 300 kgs. Bansolochan was available in Stores (during first quarter of the financial year) when lists of annual requirements of raw drugs were drawn up for obtaining Government sanction. This item was, therefore, not included in those lists of annual requirements.

During personal discussions with the Pharmacy staff officials it has been disclosed by them that the old rate contract was on the verge of the expiry after which rate of this raw drug was, probably, going to have a fall in the market for the reasons best known to the dealers. One of the firms' representative visited Patiala, called on the Principal and returned with this heavy order which could not have been placed by the principal without prior sanction of the Government. Had this order been not, thus placed hastily and in an ill considered manner, there would have been a net saving of Rs 600 to the Government becuase the rate subsequently offered by the same firm and accepted by the Department is lower by Rs. 200 per quintal (See the report at page 79) since the newly purchased quantity is still lying unconsumed (see its statement of balances at page 78), the Principal is also, *interalia*, responsible for infructuous expenditure of Rs 600 in this deal.

3. Cost of 300 Kgs. Bansolochan pruchased at the rate of Rs 63 per Kg. amounts to Rs 18,900 whereas the *ex-post facto* sanction of the Government obtained by the Principal is for Rs. 18,522 only which covers only a part of the total cost and as such is not in order. Revised sanction for the full amount is needed to regularise this transaction.

Case No. VII. LOSS OF RS 1300 THROUGH EXCESSIVE PURCHASE OF ZAND BADASTER

[Minister for Health]

In this case following serious financial irregularities have been committed by the Principal:—

1. The annual requirements of this costly raw drug have, never in the past beei more than the maximum limit of 1.496 kgs. prescribed in the "Pharmacopia" approved by the Government. This time, however, Zand Badaster which is a meat of some foreign animal and cannot be preserved without its complete deterioration beyond a period of one year at the most, has injusticeably been purchased by the Principal (without even consultation of the Superintendent Pharmacy and Vaidya Incharge Manufacturing Section) six times more than the normal requirements.

Consumption of this drug has so far been NIL, though a period of seven months has elapsed since its receipt in the pharmacy stores. During the next half year its consumption cannot be more than 1.496 kgs. as confirmed vide joint report of the I/C Stores, I, I/C Manufacturing Unit and Superintendent Pharmacy in their letter No. P/71, dated 28th October, 1964 (See page 49). In view of the above, a loss of Rs 1,290 (Rs 178.87 X 7 plus 1 % sales tax plus 2 % storage charges (thereon) is involved through deterioration of this excessively purchased costly drug; for which the Principal is responsible as he has failed to justify his action taken in this case.

2. The full supply of 10 kgs. Zand Badaster on order was made by the firm during third week of March, 1964 after purchasing it from M/S Oari Ram, Ram Chand Merchants and Commission Agents, Loha Mandi, Amritsar vide their Bill dated 20th March, 1964 as confirmed in suppliers letter dated 28th October, 1964 (See page 87). Whole of this supply made by the firm was twice rejected in full by the purchase committee, once on 24th March, 1964 (see page 82) and thereafter on 29th March, 1964 (See 83) with the remarks that the same is of inferior/sub standard in quality. It has, however, been noted with great surprise that 8.400 kgs. out of the same (as confirmed by the supplier himself) twice rejected inferior supply of 10 kgs. Zand Badaster was, in an objectional unauthorised way, accepted on 30th March, 1964 by the incompetent purchase committee of local members only and that too without any reduction into the rate payable to the firm. This acceptance of the twice rejected inferior supplies at full rate by the incompetent officials requires special consideration for taking administrative action against the defaulters and issuing a directive to recover the overpayment amounting at least ten/fifteen per cent of the total cost of Rs. 15,02.50 irregularly paid to the contractor.

Case No. VIII. PURCHASE OF KEHRAWA SAMAI.

An order for the purchase of 22.700 kgs. Kehrwa Samai at the rate of Rs 69/80 per kgs. was placed on 25th January, 1963 with M/s Surrindera and Co., Patiala. The firm failed to supply the material. Risk purchase action against this firm was taken and fresh orders placed with M/s Shiv Shakti Traders, Patiala at the rate of Rs 221.50 per kgs. on 4th March, 1964. Before the second contractor could supply the material M/s Surrindera and Co. brought whole of the supply on order with them, during first fortnight of March 1964. Instructions were issued vide DRME letter D/18th April, 1964 (See page 91) to accept the material supplied by this firm and in case full order is not executed by them, risk purchase action may be proceeded with. Despite these orders dated 18th April 1964 the following irregularities have been noticed in this case:—

I. Supply made by M/s Surrindra and Co., was not inspected till 16th July, 1964 which the P. C. of local members should have inspected much earlier as they previously did in case of Zand Badaster and Keshar etc. (See pages 93 and 94)

II. Although only 14.530 kgs. of Kehrwa Samai was approved and accepted by the P. C. on 16th July, 1964 the same has not so far been taken on stock register by Shri O. P. Gupta thereby causing a further delay of five months in making payment to the firm in terms of Rule 2.10 (b) of P. F. R. Vol. I and D. R. M. E.'s order dated 18th April, 1964. He has failed to give due justification for whole of this delay on his part.

III. In compliance with the order dated 18th April, 1964, issued by the D. R. M. E., the Principal has not so far taken any risk purchase action for want of which the remaining supply still remained held up against

the order placed with M/s Shiv Shakti Traders, Patiala in spite of their letter dated Nil (complaint endorsed over the Principal for report,—*vide* D.R.M.E. No. 4-MEIII-64/3476 dated 19th March, 1964 (*see* page 95) and extra expenditure involved amounting to Rs 1,251.77 still not recovered from M/s Surrindra and Company. According to the complaint under report, whole of this delay in accepting the supplies and making payment to the firm has been caused by the Principal because:—

"He accepted a sum of Rs 1,000 from Surrindra and Co., Patiala. They have in possession a receipt for this amount and is accounted for in their books. He wanted the receipt back which they have refused to part with."

Investigation into this allegation of the complaint is not within the scope of Audit and as such cannot be commented upon. It is, however, quite clear that firms bill for the said accepted supplies amounting to Rs 1,600 has already been delayed by Shri O. P. Gupta and the Principal for seven months without due justification which indicates that complaint in question might not be at all without bases.

The other cases, in which payment was delayed from five to seven months remained unscrutinised because Shri O. P Gupta did neither supply his records nor give due help despite repeated requests by the Junior Auditor as also by the undersigned during last week of our stay at Patiala Pharmacy for this purpose. This he (Shri O. P. Gupta) did partly because he remained over busy with the principal's job of framing replies to the said "questionnaire" handed over to the latter for explaining his position *vis-a-vis* the various irregularities enumerated in them; and partly for the reasons best known to him.

Case No. IX. EXCESS PURCHASE OF GUGGAL

In this case the following irregularities have been committed by the Principal:—

1. The order was placed in such a defective way in defiance of Rules (1) to (5) in app. 5 of P. F. R. Vol. II that the same could be objectionably fraudulently altered / tempered with easily in favour of the contractor. Had the total amount of this order been written at its end, both in words and in figures as required under the rules, no complication would have arisen.

2. Office copy of the order is, still for 440 kgs. Whereas quantity on the copy of the P. O. with the firm is stated to be irregularly-stood altered/ tempered with and increased to 840 kgs. without any attestation. The cause of so much alteration in favour of the firm (as per complaint under report) and that too, only in their own copy of the P. O. was not fully investigated by the Principal when it was produced in original before him (On his demand) by firms representatives; which should have been done by him for proper attestation of that change if actually found to be perfectly genuine, thereby, also simultaneously amending his own office-copy of the orders to make both of them agreeable in all respects.

3. Whole of the excess supply of 400 kgs. of Guggal was accepted by the Pharmacy as per objectionable orders of the Principal (See page 102) given without prior sanction from the D. R. M. E required under Rule 17.2 P. F. R., at the time when huge stock of 980 kgs. was already there in the Stores, there **by** raising it to 1,380 kgs. (*See* page 104) against the normal requirements of 440 kgs. only per annum.

4. A sum of Rs 1,425 which should have been recovered from firms bill for these supplies was actually not so deducted while recording a "Pass-order" thereon (See page 106 Q. No. 5) as a result of which whole of this amount was incorrectly overdrawn from the Treasury. This amount thus irregularly kept in the office for full one month (out of Government A/Cs) after which it has deposited back into Treasury, thereby causing false increase in the total expenditure as also the receipts of the Department.

[Minister for Health]

Case No. X. LOSS OF RS. 1,800 IN THE OBJECTIONABLE CANCELLATION OF ORDER FOR "ARQ. GULAB"

Consumption of Arq Gulab has been up to 26-27 mds. during the year 1960-61 and almost an equal quantity was used up during 1961-62 (*See* page 116). Accordingly an order was placed with M/s Bhaionka Dwakhana Amritsar for the supply of 790.200 kgs. Arq Gulab at the rate of 50 nP. per kg. during the year 1962-63. Supplies made by the firm were twice or thrice rejected (*See* page 110) being the inferior quality. In view of the pressing and continuous demands, the said order was also renewed during the year 1963-64. On firms' request, a sample of standard quality Arq Gulab was also sent to them,—*vide* Principal's letter No. 1110, dated 21st February, 1964 for expediting despatch of whole supplies on order. Subsequently firm sent to the Pharmacy two samples which were also rejected being inferior. The firm, thus, failed to execute the order. Since the supply of Arq Gulab was urgently needed in preparation of medicines held up in its absence since 1962-63 fresh quotations were invited in which lowest rate offered by M/s Obrai and Co., Patiala was Rs 2.75 per kg. (*See* page 115). The risk purchase order, as per decision already taken should have in the public interest, been placed with M/s Obrai and Co.. Patiala at the extra cost of M/s Bhaiyon-Ka Dwakhana, Amritsar to avoid further delay in preparation of urgently needed medicines for the otherwise starving and dried up, Dispensaries and Aushdhalayas through out the State, whereas the Principal, gave wrong orders dated 23th April, 1964 (*See* page 111) on the relative file that previous purchase-order may be cancelled and the Arq Gulab prepared in the Pharmacy itself.

As a result of this highly objectionable order given by the Principal—

(i) the Government has been put to loss of Rs 1,796 (Now rate of Rs 2.75 less old rate of 50 nP. per kg. *plus* 1% sale tax thereon);

(ii) no medicine, in which Arq Gulab was to be used, has so far been prepared because the required Arq Gulab has not at all been so far extracted in the Pharmacy for want of appropriate equipment and its requisite raw drug though a further period of more than six months has since elapsed;

and

(iii) all other component raw drugs which were to be consumed along with the non-available Arq. Gulab might also have considerably deteriorated in the Stores-bins lying un-utilised since the years 1962-63 and 1963-64.

Case No. XI. ORDER OF "PANNA"

Irregularly placed with the second lowest tender at extra avoidable expenditure of Rs 30. An order for the purchase of 4.100 kgs. of "Panna" at the rate of Rs 120 per kg. was placed on 23rd January, 1963 with M/s Pushkarna Ayurvedic Pharmacy, Amritsar. The firm, however, failed to execute that order. Risk purchase action at their cost was, therefore, decided upon and fresh quotations called during the month of December, 1963 (See page 122). In this case following irregularities have been noticed:—

1. The first lowest quotation of Rs 400 per kg. was from M/s Krishana Ayurvedic Pharmacy, Amritsar and the second lowest offer of Rs 407.23 per kg. was given by M/s Shiv Shakti Traders, Patiala. With a view to favour the second-lowest local tender, the Principal did not place the order with the first lowest firm of M/s Krishna Ayurvedic Pharmacy, Amritsar on the flimsy and false pretext that they did not give the earnest money along with their quotations which he was not competent to so do without prior sanction of the D.R.M.E. He has, thus also incurred an extra/infructuous expenditure of Rs 30.02 which should be recovered either from the firm or the defaulter.

2. The sum of Rs 1,190 due from M/s Pushkarna Ayurvedic Pharmacy, Amritsar on account of this risk purchase has actually not been recovered from their bills amounting to Rs 9,524.71 subsequently paid during the months of February, 1964 to April, 1964 (*See* page 125) as a result of which they were overpaid to that extent. Recovery of Rs 1,190 needs to be effected at once.

3. The supply of Panna has also not been executed by M/s Shiv Shakti Traders, Patiala but no risk purchase action has so far been taken by the Principal against them. Consequently the corresponding component raw drugs are also deteriorating in the Stores and medicines needed by the Dispensaries/Aushdhalayas remain unprepared.

Case No XII. PURCHASE OF HOT WATER BOTTLES

In this case the following irregularities have been committed by the Principal :—

1. Decision dated 6th March, 1963 given on the comparative Statement (*see* page 127) that rate of M/s General Agency Delhi was higher than that of M/s Dee/Dee Corporation, Patiala is wrong in view of the follownig facts :—

Rate quoted by M/s Dee Dee Corporation, Patiala	Rate quoted by M/s General Traders Agency, Dlehi
Rate per Dozen Rs 42.00	(1) Rate per Doz. 35.76 (Ex-godown Delhi)
	2) Sales tax 0.70
	(3) R/Freight 2.50 (confirmed by the Railway Authorities at page 130 A)
	4) Packing and Forwarding 2.00
	Total (Max. payable Rs 40.96.)

It is quite clear from the above facts that the first lowest quotation was that of M/s General Traders Agency, Delhi. M/s Dee Dee Corporation, Patiala, were, however, given undue favour and order was placed on them at the rate of Rs 42 per Dozen without getting prior sanction of the D.R.M.E.

2. The purchase order was placed in such a defective and incomplete form that its timely execution could not be enforced as replied to by the Prinicipal (*See* page 132-Q No. 4) when asked as to why 4 per cent liquidated damages were not levied on the supplies made two months late.

3. According to the joint reports of the Store-keepers and Superintendent, P. & S. whole of the supply was defective and too poor in quality to be accepted in comparison with its price. Besides the supply was not as per specifications offered in the quotation of the firm and also incorporated in the purchase order. As such orders issued by the Principal to the Store-keepers direct for accepting that same supply by levying a token penalty of 5 per cent only—*vide* his letter No. 2808, dated 19th May, 1964 were not justified because the material should have either been rejected or levied a panalty of 20--25 per cent as seen from the files.

4. The bill of the firm was neither "Passed' nor enforced with a "Pay order" of the Principal as required under the rules but was got paid by him through the office-accountant with some verbal orders. This payment has also not been accounted for in the office cash accounts as verified from the Cash Booke tc.

[Minister for Health]

Case No. XIII. PURCHASE OF DESI GHEE

The irregularities committed by the Principal in this case are listed below :—

1. An order for the purchase of 425 kgs. of Desi Ghee was abruptly placed by the Principal without —

   (a) any detailed office proceedings regarding its emergent requirement;
   (b) prior sanction of the D.R.M.E., and
   (c) taking into account the existing stock of Desi Ghee in stores [complete details whereof have also not been supplied in reply to question No. (3) of this case].

2. No justification is forthcoming from the office records on the basis of which whole of this demand of Rs 3,049 worth of Desi Ghee could be treated as "Emergent" or even "Immediate."

3. Actual consumption of Desi Ghee during the years 1961-62 and 1962-63 had been only five to six kgs. and 135 kgs during the year 1963-64 as shown by the Stock Register kept by the I/C Stores I. Keeping in view the sufficient balance already existing in the Stores, it is not understood as to how could a further demand of 425 kgs be justified. The Principal in his replies at page 152 has failed to give due justification for this deal.

4. (i) After the suppliers' bill for Rs 3,048.72 had been verified by the I/C Stores, I;

   (ii) passed not only by the Principal on 29th September, 1964 but also by the Treasury Officer on 30th September, 1964 for its payment at the State Bank of Patiala; and

   (iii) enfaced subsequently by the Principal with his (un-dated) pay order to the State Bank of Patiala in favour of Shri Janak Raj Office-Accountant-during the first week of October, 1964, the same has surprisingly been irregularly cancelled by him on 13th October, 1964 without cogent reasons, though it could be finalised in its existing position.

Case No. XIV. SHORTAGE OF 82.88 QUINTALS OF FUEL-WOOD.

Following irregularities exist in this case:—

1. The whole supplies made by the Contractor during the last week of March, 1964 should have been received and directly taken on charge by Shri O. P. Gupta Incharge Store I, thereby making a correct record-entry in his stock registers for arranging payment to the firm. This was not done by him but instead Vaid Bant Ram I/C Pharmacy was made to weigh and receive initially as also finally whole stock of the fuel-wood from the contractor direct.

2. Initial records reveal that Shri Bant Ram actually received 23,400 kgs. of fuel-wood whereas he incorrectly gave an acknowledgement for 2.3475 kgs. thereby causing an overpayment of Rs 5.23 worth of wood (75 Kgs.) to the firm. This overpayment may either be recovered from the contractor or from the official at fault.

3. Whole of the stock must have been kept under the immediate charge of Shri O.P. Gupta, I/C Stores I from which only reasonable quantity as per daily or weekly requirements of consumer could be issued on his regular indent *vide* rule 16.5 of P.F.R. Vol. K. Disregard of this procedure and absence of the proper supervisory check rendered the misappropriation of Public-stores possible for which immediate custodian as also the I/c Pharmacy stores are both proportionately responsible.

4. Examination of the relative records show that—

   (i) according to the detailed (item-wise) acknowledgement (*see* page 166) given to Shri Bant Ram, whole of the charge was correctly taken over by Shri Tripur Sudan without any remarks of the shortages, if any;

   (ii) as per note kept in the consumers stock-registers of consumption, the charge was ultimately taken over by Shri Krishan Lal I/C Bhathi Section. In view of the subsequent contradictory statements of Shri Tripur Sudan

Shri Bant Ram, there has arisen a confusion, whether Shri Krishan Lal took over charge of fuel wood from Shri Tripur Sudan or Shri Bant Ram. Any how clear acknowledgement for the receipt of whole stocks, then existing in the stores as per its book-balances as also a "No Demand Certifiate given in the third week of July, 1963 to Shri Bant Ram (*See* page 167 absolve him of responsibility for any shortages, whatsoever subsequently caused and/or found in those stores. The shortage of 82.88 quintals of the fuel wood was noted and brought to light on 31st December, 1963 only for which full responsibility rests either with Shri Krishan Lal or Shri Tripur Sudan or both of them proportionately for the following three main reasons :—

(a) Receipt of 16,936 kgs of F. wood was clearly acknowledged to Shri Bant Ram, the previous stock-holder by both of them, without any remarks of shortage, if any there in during the month of June/July, 1963.

(b) Shri Tripur Sudan and Shri Krishan Lal, had, both of them right from the very beginning the actual consumers of fuel wood. As such if entries for day-to-day consumption were not correctly made by them as required under the rules, they have got to shoulder its consequences.

(c) Since whole of the stock of Pharmacy stores remained with Shri Tripur Sudan and /or Shri Krishan Lal after June, 1963 they were personally responsible *vide* Rule 15.7 read with the Rule 2.33 of the P.F.R. Vol. I to keep it in their perfect custody and accounting in order to guard against losses/ shortages therein. In view of the fact that this shortage has been caused either by some malpractices followed by the custodians/consumers in maintaining true accounts or an embezzlement in their stores; the loss cannot be written off. Orders may therefore be issued for immediate recovery of the whole loss of 8,288 Kgs. fuel wood from the defaulters either in lump sum or in monthly instalments as may be considered more appropriate by the authorities.

(5) The entries for 'consumption' of fuelwood were allowed to be made in the Stock Registers several months after actual dates of those transactions on the basis of some un-authorised "LACHI COPIES" containing innumerable cuttings and over writings which led to inestimable wrong booking of consumptions. Consequently, those registers have become totally unreliable. Had the prescribed "Supervisory checks" been exercised by the I/c Pharach and or its head of office, the irregularity could have been detected well in time to save this eventuality.

The custodians, consumers, I/C Pharmacy Stores and Head of their office may, therefore, be appropriately warned to be more vigilant for ensuring perfect custody and accurate accounting of all stores entrusted to them as laid down in the Financial Rules framed by the Government.

Case No. XV. IRREGULARITIES CONCERNING THE QUOTATIONS CALLED FOR AGAINST THE SANCTION FOR THE YEAR 1963-64

In examining the quotations for the year 1963-64 the following irregularities committed by the Principal despite rightful recorded resistance of the Superintendent Pharmacy and Stores, have been noticed :—

(1) The sanction for the annual requirements of raw drugs etc. solicite,—*vide* Principal letter dated 8th November, 1963 was granted *vide* D.R.M.E. letter dated 17th December, 1963. No procurement action was, however, taken by the Principal in calling quotations before 4th February, 1964. Consequently, due time was not allowed to the prominent State-owned and private concerns in the country dealing in the wholesale of those drugs etc. for submission of their most competitive quotations, on the receipt of which a very large number of drugs could have been purchased at much more cheaper rates than those otherwise paid to the other local middle men succeeding (among the tenderers of their own low status) to secure bulk of the public purchase orders. As a result of so much delay in issuing Tender Notice by the Principal , thereby keeping the cheapest

[Health Minister]

(Government approved) sources of supplies plucked off (*See* page 169) the Government has been pu to a considerable loss through comparatively higher amounts paid tot the middlemen during thc year 1963-64.

2. Several quotations received before 13th February, 1964 in response to the Tender Notice dated 4th February, 1964 were kept unopened till 4th March, 1964 without any justification as a result of which—

(a) one important quotation of M/s Pushkarna Ayurvedic Pharmacy, Amritsar was lost by the Principal as admitted by him in his explanations as page 173 (Question No. 3). This loss is a very serious matter and calls for strict disciplinary action against him;

(b) a No. of cheapest/lowest rates quoted in those tenders had becom inoperative, thereby causing financial loss to the Government.

3. "Register of quotations" for recording therein all the tenders with full particulars, on the date of their receipt in this office has not been kept and maintained. In its absence no effective control over the correct receipt and accounting of all the tenders received from various firms is practicable.

4. Before the quotations received uptil 13th February, 1964 were suitably dealt with and decision taken thereon as required under the rules, revised/ fresh quotations (without any recorded reasons) were forced to be called for the same raw drugs from almost the same firms on 22nd February, 1964 for which last date was fixed as 29th February, 1964. This was done in spite of correct and recorded resistance of the Superintendent Pharmacy and Stores (See page 169), action of the Principal in so doing, is not justifiable.

5. Still greater irregularity was committed by the Principal in issuing another Tender Notice on 24th February, 1964 to the same six local firms of Patiala, thereby inviting separate special quotations for some of the same items as already twice included in the quotations received before 13th February, 1964 as well as those due by 29th February, 1964. Quatations against this third Tender Notice were made due by 26th February, 1964 and were called despite recorded (correct) resistance of the Superintendent Pharmacy and Stores (See page 170). All of these quotations due on 26th February, 1964 were, however, neither found placed on records nor otherwise produced for scrutiny despite repeated demands from the officials concerned.

6. The lists of annual requirements were prepared and submitted to the D.R.M.E. as late as 8th November, 1963. All these lists must have been finally prepared at least three/four months earlier and submitted to Government for necessary sanction. So much delay in finalising the lists of annual requirements greatly contributed towards procuring the drugs at much higher rates from the middlemen than those at which supplies could otherwise be had at cheaper rates as stated in para (P) above.

Case No. XVI. IRREGULARITY IN KEEPING THE "EARNEST MONEY DEPOSITS" OUT OF THE PUBLIC ACCOUNTS OF THE STATE

During perusal of the purchase files of the Pharmacy Stores, Patiala it has been noticed that none of the following Bank Drafts received from the intending tenderers 'Earnest money Deposits" (*See* page 174) have so far been encashed and their amounts deposits in the Government Accounts kept at the Bank to Treasury.

1. Bank Draft dated 12th February, 1962 for Rs. 200 given by M/S Verinder Jain Patiala.

2. Bank Draft dated 8th Augus, 1963 for Rs. 100 given by M/S S. B, S. Trading Co., Patiala.

3. Demand Draft dated 28th October, 1963 for Rs. 50 given by M/S Obrai and Co., Patiala.

4. Demand Draft dated 30th December, 1963 for Rs. 500 given by M/S Shiv Shanti Traders, Patiala.

Total .. 850

Effective measures may now be taken to get whole of this amount deposited immediately into the appropriate public Accounts of the State and Strict instructions/issued to guard against all such serious financial irregularities in future.

Case No. XVII. **Loss of about three-four thousand of Rupees involved in deterioration of Raw drugs in appropriately kept in Stores**

The general survey of the raw drugs kept under the immediate charge of Shri O. P. Gupta I/C Stores (1) got done through himself, vide our letter Nos. Audit Part 10 and 11 dated 23th October, 1964 (See reports duly countersigned by the Superintendent P and S at Pages 49 and 73-D has revealed that raw drugs costing about three to four thousands of rupees has deteriorated either in full or upto considerable extent thereby causing heavy losses to the State Government. Year-wise break up of these losses is as under :—

Serial No.	Year of Purchase	Amount of loss involved in rupees
1.	1953-54	42
2.	1954-55	18
3.	1955-56	18
4.	1956-57	250
5.	1957-58	8
6.	1958-59	28
7.	1959-60	32
8.	1960-61	561
9.	1961-62	675
10.	1962-63	221
11.	1963-64	2274
	Total	4,127

Some of the important items of these losses are enumeated hereunder :—

Serial No.	Name of Raw Drugs	Quantity (Kgs)	When purchased	Amount involved
1.	Zand Badsater.	7	March, 1964	1,300
2.	Kamal doda Giri.	100	March 1964	500

[Health Minister]

1	2		3	4	5
3.	Kewrey-ke-phool	..	9	March, 1961	702
4.	Anar-dana	..	97	March, 1961	231
5.	Bakery-ke-Mooter	..	30	March, 1957	195
6.	Talmakhana	..	93	March, 1961	144
7.	Khajoor	..	79	March, 1964	106
8.	Pipramool	..	27	March, 1963	97
9.	Badam-Giri	..	9	March, 1962	94
10.	Mall Kanjiri	..	40	March, 1963	93
11.	Magaj Bahi-dana	..	7	March, 1962	67
12.	Piste	..	2	March, 1964	58
13.	Kakra Singhi	..	36	March, 1962	57
14.	Kankole	..	55	March, 1962	57
15.	Supari	..	8	March, 1962	52
16.	Dhania	..	44	March, 1962	52
			Total		3,805

The major causes of the above-mentioned losses have been found as under :—

(1) Serious defects in the system of estimating the correct annual requirements as also the consumption of drugs in the manufacturing process adopted by the Pharmacy as a result of which purchases of raw drugs were highly injiditious and/or excessive (see the causes of Kamal Dada Giri, Kewery-ke-phool and Anardana, etc.

(2) Wrong acceptance of deteriorated and inferior quality of raw drugs, as is apparent from the case of Zand Badaster.

(3) Lack of proper watch and ward as also the due maintenance of drugs by the custodian of Stores.

(4) No-preparation of the preplanned medicines for which all these drugs were purchased. Consequently all of them were left to fell prey to considerable decay and deterioration for so many years in the neglected stores-bins of the pharmacy.

Responsibility of all these losses through carelessness at one stage or the other may, therefore, be administratively fixed for issuing orders of recovery from the defaulters concerned.

Case No. XVIII. Heavy losses of several thousand of rupees caused by serious defects in procurement policy and payment-procedure.

The general review of procurement policy and payment-procedure adopted by the Principal has revealed the following Serious defects which have resulted into

heavy losses amounting to several thousands of rupees to the State Government :—

(1) Cases in which risk purchase orders had been placed, recoveries on account of the extra expenditure incurred and due from the defaulting firms were not calculated and effected from their bills subsequently paid those firms have, thus been overpaid to the extent of recoveries due from them (*see* pages 71 and 73-C.).

(2) In a large number of cases, supplies already included in the purchase orders previously placed were not executed either in part or in full by the firms, probably, becuase their market price had considerably risen. After expiry of the last financial year all such orders should have been renewed and firms concerned asked to complete those supplies.

Neither those orders were, however, actually so renewed nor risk purchase action against them taken but instead fresh quotations were, in any easy way, invited and new orders placed at the rates, then offered, which were more than the old rates at which supplies already on order could be rightfully procured from those very firms, failing which extra expenditure incurred at their cost and risk adjusted from their bills subsequently paid by the department. (*See* pages 71 and 73-C).

(3) Most of the financial rules and regulations framed by the Government for the guidance of officers, while calling quotations, approving the lowest rates and placing Public orders, stand either ignored or defied and trespassed in as-much as that:—

(a) A list of reputed and prominent State owned and private concerns dealing with the production/first-hand collection and sale of raw-drugs etc. at the most competitive rates within Punjab and also the other neighbouring States has not all been prepared and maintained. The result is that middle men's trade is taking being given under financial benefits as the quotations are almost repreatedly called only from the same old and intimated local small business-men.

(b) Howsoever high may be the total cost of all the intending annual purchase, *press enquiry* has never been issued in order to obtain the most competitive rates through wide publicity which is very essential under the rules.

(c) Sufficient time of at least three to four weeks has never been allowed to the outsiders, despite their requests without which they have shown their inability to submit their most competitive rates quotations (*See* Page 169).

(d) Time and date of opening the tenders have never been notified in the tender notice. Consequently tenders are seldom opened in the presence of intending tenderers.

(e) In selecting the tender for acceptance the financial status of the individuals and firms is not at all taken into consideration in addition to all other relevant factors as required vide rule (5) of appendix 5 in the P.F.R. Vol. II.

(f) Purchase orders are often irregularly placed with the second lowest tenders without obtaining prior sanction of the competent authority and for recorded reasons in its support as laid down in the rules (*see* pages 29 and 124).

(5) Form of the purchase orders being used is very defective and incomplete as it does not exhibit therein all the terms and conditions essential to make it not only enforceable but also precise and definite as required,—*vide* instructions contained in Appendix 5 and 14 of the P.F.R. Vol. II. Consequently the Department has often incurred avoidable liabilities through the said deficiencies in the purchase orders. For instance see the cases of Guggal and Hot-water Bottles purchased by the Principal (*See* 104 and 132-Q. No. 1 and 4 respectively).

[Health Minister]

CONCLUSIONS

The large number of serious financial irregularities enumerated in the foregoing report have brought to light that not only the recoveries a mounting to about Rs.5,000 due from the defaulting officials and firms have been continuously ignored for long, but also the State Government has in addition, been put to heavy losses,—*vide* cases at Serial Nos. 4 to 7, 17 and 18, to the tune of say Rs. 15,000 through the wrong procurement policy and payment procedure adopted by the Principal. This seems to have, purposely, been done by him as witnessed by the several irregularities complained against and also his own office-proceedings/orders existing on the relative-files (extracts placed below) in spite of the sufficient correct guidance provided by the Superintendent P and S through his recorded notes on the files which have been found (extracts placed below) to be perfectly in public interest and also in consonance with the Financial Rules. It will not be out of place to mention here that there would be still greater nu mber of equally serious financial irregularities detected if all the accounts of the pharmacy stores are-managed to be thoroughly scruitinised. Feasibility whereof may kindlybe appropriately considered for taking the desired decision.

2. The draw-backs and bottle-necks existing in the financial management of this pharmacy Stores have also no less contributed in undesirably causing and creating serious deficiencies observed inactual conduct of the monetary-transactions, proper up-keep of stores, greater out-turn from the medicines manufacturing section, and regulating all the supplies as per scheduled quota of me.icines, well in time to all the dispensaries and Aushdhalayas throughout the State.

Under the above circumstances, the Principals of Financial propriety laid down by the Government in General and the Public interest in particular demand no less a realistic improvement in the present financial set-up; than to riase and bring the status of Superintendent Pharmacy stores at par with that of the existing Superintendent Ayurvedic Hospital, Patiala. The ad ministrative action in this regard may please be considered and decided upon in the light of all the above said irregulatrities and due recommendations in that respect made to the Government for final orders early.

3. Orders, after the due consideration may also please be issued —

(a) to effect all the recoveries due from vaiious parties mentioned in the report;

(b) overhaul all the unexecuted previous/purchase orders for considering risk-purchase action due against the defaulters; and

(c) for providing effective checks against —

(i) objectionably placement of orders with the second lowest tenderers without their prior approval from the D.R.M.E. on the basis of recorded reasons;

(ii) orders, irregularly being placed by the I/c Pharmacy and Stores, Patiala in total disregard of the orders according to which there must exist a prior sanction of the competent authority,—*vide* Rule 17.2 P.F.R.Vol. I;

(iii) injuditious and excessive purchases being injustifiably resorted to thereby causing considerable losses to the Government;

(iv) irregular acceptance of the stores brought in by the firms but rejected once or twice in full (as is the case with Zand Badaster) by the Purchase Committee of local member only without obtaining approval of the next higher authority for recorded reasons and that too after appropriate cut levied in their rates;

(v) originally agreed to;

(vi) heavy delays in preparing and sub mitting complete lists of all the annual demands/requirements for obtaining Government sanction;

(vii) defective and imcomplete tender notices being issued for inviting quotations by the I/c Pharmacy Stores, Patiala;

(viii) any possible losses of quotation's submitted by the intending tenderers;

(ix) cancellation of purchase orders already placed which cannot be justified in view of the considerable loss involved therein;

(x) Serious omissions in adjusting all the recoveries due upto-date, from a contractors bill, before it is actually passed and sent to the Treasury for its payment, which otherwise causes overdrawals from the Treasury;

(xi) payments made without a written pass order' and pay order by the responsible drawing and disbursing officer both in words and in figures as required under the rules.

(xii) placement of purchase orders without incorporating there in all the conditions essential to make it not only enforceable for timely execution but also precise and definite in all respects,—*vide* Government orders contained in the appendices 5 and 14 of the P.F.R., Vol. II;

(xiii) heavy losses being sustained through speedy decay and deterioration of costly and/or in large quantity of raw-drugs inappropriately and carelessly kept in the stores as mentioned in case No. XVIII above and

(xiv) non-observance of relative instructions required to be fully complied with by all the officials concerned in the office of the D.R.M.E. while dealing with the financial sanction solicited by the subordinate offices from time to time and being granted or other wise decided upon by the higher authorities.

Submitted for orders please.

A/O. Sd/- Encls.	A file of 174 pages containing history of each case with its relative "questionnaires" and explanations of the Principal in original	Sd/-.
Deputy D.R.M.E.		S.P. SHARMA, 12-11-1964 Senior Auditor.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਸਹਿਬਾ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

स्वास्थ्य मंत्री : मुझे इस वक्त एग्जेक्ट डेट तो मालूम नहीं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि गालबन 1965 में यानी पिछले साल यह केस विजीलेंस डिपार्टमेंट को रैफर किया गया था और उस के बाद रीमांईड भी कराया गया है कि जल्द इस की इनक्वारी करके रिपोर्ट भेजी जाए।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

मंत्री : नहीं उसे सस्पेंड नहीं किया गया । उस से फारमेसी का चार्ज ले कर एक असिस्टैंट डाइरैक्टर को दे दिया गया है और इनक्वारी के लिए केस विजीलेंस डिपार्टमैंट को भेज दिया गया है ।

श्री ओम प्रकाश अग्नि होत्री : क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि जब कि उस रिपोर्ट में इतनी सीरियस एलीगेशनज़ उस प्रिंसीपल के खिलाफ थीं तो फिर उस को इनक्वारी से पहले सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

मंत्री : यह केस विजीलेंस के सुपर्द इस लिए किया गया है ताकि वह जो अपनी इन इररेगुलैरेटीज़ के बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन देनी हो वह दे ले और उस के बाद तमाम इन्क्वायरी हो जाए और उस के मुताबिक उस पर ऐकशन लिया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ?

मंत्री : यह जो आडिट रिपोर्ट पेश की गई है उस से मालूम होता है कि बहुत सारी इररेगुलेरेटीज़ की गई थीं और सारी चीज़ें उस में लिखी हुई हैं । इस लिए हम नें वह सारा केस विजीलेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है ताकि वह सारी चीज़ों के बारे में पड़ताल करें ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ?

(*No reply*)

J. B. T. CLASSES IN TEHSIL KAITHAL, DISTRICT KARNAL

*9944. **Kanwar Ram Pal Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the names of places where JBT classes are functioning at present in tehsil Kaithal, district Karnal, Blockwise ;

(b) whether it is a fact that a JBT unit was first allotted to Government High School, Pundri in 1965 and a few days later it was transferred to the Arya High School, Pundri by telegraphic order; if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the JBT class had remained attached to the Government High School, Pundri, during the last three or four years, before it was shifted to the Arya High School, Pundri; if so, the reasons for this change ?

Shri Prabodh Chander : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Yes, because of the availability of better facilities to impart JBT training at A. S. High School, Pundri.

(c) No.

STATEMENT

S. No.	Name of the School/Place	Tehsil	Block
1.	Government Higher Secondary School, Kaithal	Kaithal	Kaithal
2.	Government Girls High School, Kaithal	Do	Do
3.	Jat Higher Secondary School, Kaithal	Do	Do
4.	Government High School, Padlah	Do	Do
5.	Government J.B.T. Centre, Pundri	Do	Pundri
6.	Janta High School, Kaul	Do	Do
7.	A. S. High School, Pundri	Do	Do
8.	Government High School, Asandh	Do	Asandh
9.	Government High School, Karora	Do	Do
10.	Government High School, Naguran	Do	Rajaund

कंवर राम पाल सिंह : इस सवाल के जवाब में जो स्टेटमेंट दी गई है, इस के पार्ट (बी) में दिया हुआ है 'availability of betters fecilities' तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह आर्य हाई स्कूल को पहली दफा यह युनिट दिया गया है ?

Minister : I think so, Sir.

कंवर राम पाल सिंह : इन्होंने पार्ट 'सी' के जवाब में नो कहा है तो क्या यह बताएंगे कि गवर्नमैंट स्कूल से टेक ओवर करने से पहले यह यूनिट 1965 में सनातन धर्म स्कूल में काम कर रहा था या नहीं ?

Minister : I cannot say off hand whether a J. B. T. unit was working there before the Government took over.

कंवर राम पाल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्कूल में यह यूनिट पहले काम कर रहा था उस में फैसिलिटीज़ में क्या कमी थी और आर्य स्कूल में कौन सी बैटर फैसिलटीज़ मौजूद थीं ?

Minister : Sir, previous to 1964 for some years private schools were not allowed to run J. B. T. classes. Then the Government reverted back to the old policy to associate private schools with the allotment of J. B. T. units and as a result of that this school was given a J. B. T. unit.

कंवर राम पाल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो यूनिट दाखले से दो दिन पहले ट्रांस्फर किया गया आर्डर्ज़ (आरडर्ज़) टैलीग्राफीकली किये गए क्या यह एक्स एम. एल. ए. श्री गोपी चंद गुप्ता जो सच्चर वज़ारत में एम. एल. ए. थे के प्रैशर से ट्रांस्फर नहीं किया गया ?

Minister : My department does not submit before pressures.

P. S. S. (CLASS II SERVICE RULES)

***9807. Chaudhri Ran Singh** : Will the Minister for Revenue with reference to the reply to Unstarred Question No. 2570 included in the list of questions for the 29th March, 1965, be pleased to state—

(a) whether the P. S. S. (Class II) Service Rules for the office of the Financial Commissioner, Revenue has since been framed; if so, a copy of the same be laid on the Table of the House; if the rules have not been framed so far the probable time by which these rules are likely to be framed ;

(b) the mode of promotion to the P. S. S. (Class II) Services in the said office ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Part first. No.

Part second. Question does not arise.

Part third. The Rules are being framed and are expected to be finalised shortly.

(b) Promotion to the posts of Superintendents Private Secretaries to the Financial Commissioners, Establishment Officer and Assistant Secretary, which comprise P. S. S. (Class II) in the Financial Commissioner's Office is made from amongst the personnel of the Office, on the basis of the recognised principle of seniority-cum-merit, as indicated below :—

Sr. No.	Designation of Post	Category of officials eligible for promotion along with the requisite experience, etc.	REMARKS
1.	Superintendent	Five years experience as Assistant or Deputy Superintendent in the Financial Commissioners' Office.	
2.	Private Secretary	Five years experience as Senior Scale Stenographer or Personal Assistant.	
3.	Establishment Officer.	Five years experience as Superintendent or Private Secretary.	
4.	Assistant Secretary	Five years experience as Superintendent/Private Secretary or Establishment Officer.	

चौधरी रण सिंह : इन्होंने जवाब में कहा है कि दी रूल्ज़ आर टू बी फ्रेमड, फाइनलाइज़्ड शार्टली। तो इस शार्टली से कितना अर्सा मुराद है ?

श्री अध्यक्ष : इस का तो वही जवाब होगा जो हर ऐसे सवाल का होता है।

COMPLAINTS AGAINST DISTRICT EDUCATION OFFICER, LUDHIANA

*8882. **Sardar Kultar Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the number of complaints received by the Education Department against the District Education Officer, Ludhiana, during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1965 and a copy of each of the said complaints be laid on the Table of the House ;

(b) the number of complaints, out of those referred to in part (a) above, into which enquiries were held with the result of the enquiry in each case ;

(c) the number of complaints which were not enquired into and the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra : (a) Three, but it is not advisable to place copies thereof on the Table of the House.

(b) Two, still under inquiry.

(c) One, being an anonymous complaint.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

Minister : Sir, I have already stated that it will not be in the public interest to place a copy of the report on the Table of the House. But a senior officer is making the enquiry and after that is completed I will convey the facts to the Member.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Minister : I had instructed that a senior officer from the headquarters should hold the enquiries. If the hon. Member is particular to know the name I will let him know after making enquiries.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : इन्होंने कहा है कि तीसरी कम्पलेंट एनानीमस है। तो क्या यह बताएंगे कि ऐसी कम्प्लेन्ट्स के बारे में इन्क्वायरी करवाने के बारे में क्या पालिसी है ?

Minister : Sir, it is ordinarily the policy of the Government not to make enquiries into the anonymous complaints. But if these complaints can be substantiated by the documentary evidence available at the headquarters, we try to look into them.

SUPPLY OF AYURVEDIC UNANI MEDICINES BY THE GOVERNMENT CENTRAL AYURVEDIC PHARMACY, PATIALA

***9794. Comrade Babu Singh Master** : (put by com. Gurbakhsh Singh Dhaliwal) Will the Minister for Health be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that no drugs for the preparation of Ayurvedic and Unani medicines were purchased by the Government Central Ayurvedic Pharmacy, Patiala, during 1964-65;

(b) whether it is also a fact that no medicines were manufactured and no supplies made to the dispensaries resulting in a lot of suffering for the ailing humanity;

(c) whether any action has been taken for the said negligence on the part of the authorities concerned; if so, what;

(d) whether it is a fact that the Government purchased some prepared medicines for use in its dispensary during the said period ?

(e) if the reply to part (d) above be in the affirmative, the reasons why it was done when Government has a big Pharmacy of its own?

Shrimati Om Prabha Jain : (a) No.

(b) No.

(c) Question does not arise.

(d) Yes.

(e) The entire demand of medicines of the Ayurvedic/Unani dispensaries in the State could not be met with from the medicines prepared by the Pharmacy. Therefore, prepared medicines from the market had to be purchased.

FAMILY PLANNING

***9351. Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the names of the districts where the number of males was larger than that of females who offered themselves for operation under the Family Planning Programme together with the number of those males who have actually been operated upon so far in each such district;

(b) the names of the districts where a larger number of females offered themselves for the loop system as compared to males who offered themselves for vasectomy operation together with the number of females who availed of this facility under the Family Planning Programme;

(c) the total number of males and females in the State, district-wise, who offered themselves up to date for either one or the other;

(d) whether the Health Department has ever assessed as to who is more responsive, males or; females, if no assessment has been made, the reasons therefore ?

Shrimati Om Parbha Jain : (a) to (d) : The information is laid on the Table of the House.

(a) In all the districts of sterilization in the Punjab State the number of males is larger than that of females who offered themselves for sterilization operation under the Family Planning Programme during the year 1965. The number of operations. performed on males and females in each district has been shown in the enclosed Annexure No. 1.

(b) The 'LOOP', a new contracentive device, has been started in the Punjab state from April, 1965. The district-wise comparative statement for Vasectomy operations and Loop insertions is at Annexure II.

(c) Total number of males and females in the State district-wise who offered themselves for operation is given in Annexure I.

(d) Yes; the assessment is done through monthly returns of various institutions for Family Planning work. Females are more responsive than males.

ANNEURE I

Vasectomy Tubeligation Operation Programme in the State during the period 1-1-1965 to 31-1-1966 (District-wise)

	Male	Female	Total
Hissar	2794	65	2859
Rohtak	1399	15	1414
Gurgaon	1448	2	1450
Karnal	1226	23	1249
Ambala	2066	8	2074
Simla	448	33	481
Kangra	1516	18	1534
Hoshiarpur	1114	1	1115
Jullundur	3377	0	3377
Ludhiana	2973	12	2985
Ferozepore	2281	38	2319

ister for Health]

	Male	Female	Total
Amritsar	2151	5	2156
Gurdaspur	1653	0	1653
Patiala	1317	245	1562
Sangrur	2576	11	2587
Bhatinda	3328	4	3332
Kapurthala	509	0	509
Narnaul	1559	0	1559
Chandigarh	126	8	134
Talwara	48	1	49
Nangal	105	32	137
Kulu	417	0	417
Keylong	62	0	62
Private Institute	95	86	181
Total	34,588	607	33,195

** N. B. According to weekly reports the figures of Loop insertion up to 12-2-1966 are 78,295.

ANNEXURE II

Statement Showing the Performance of Vasectomy and Loop during the Period 1-1-65 to 31-1-66 (District-wise)

Name of the Distt.	No. of person operated upon Vasectomy	No. of loops inserted
1	2	3
Hissar	2794	3063
Rohtak	1399	2954
Gurgaon	1448	2796
Karnal	1226	8784
Ambala	2066	10,309
Simla	448	1003
Kangra	1516	2169
Hoshiarpur	1114	2709
Jullundur	3377	5724
Ludhiana	2973	3723
Ferozepore	2281	2410
Amritsar	2151	3023
Gurdaspur	1653	3791
Patiala	1317	7274

1	2	3
Sangrur	2576	2738
Bhatinda	3328	2565
Kapurthala	509	3328
Mohindergarh	1550	697
Chandigarh	126	2922
Talwara	48	83
Nangal	105	540
Kulu	417	121
Keylong	62	—
Private Institute	95	—
	34,588	72,731

कामरेड राम प्यारा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगी कि जो यह लेडीज़ की तरफ से रिसपोंस कम है इस को बढ़ाने के लिये सरकार क्या स्टैप्स ले रही है ।

स्वास्थ्य मन्त्री : जवाब में बताया गया है कि लेडीज़ की तरफ से रिसपोंस ज्यादा है डयूरिंग दी लास्ट ईयर ।

कामरेड राम प्यारा : अगर मेल्ज़ की तरफ से रिसपोंस कम है तो उस को बढ़ाने के लिये क्या स्टैप्स लिये जा रहे हैं ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : इस के लिये आप की ड्यूटी लगाई जायेगी । (हंसी) (The hon. Member will be put on duty to do this job.) (laughter)

Health Minister : Obviously it is the ladies who bear all the pang of labour.

GOVERNMENT SCHOOLS UPGRADED IN DISTRICT KARNAL

***9945. Kanwar Rampal Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of Government Schools upgraded from the Primary to the Middle and from the Middle to the High/ Higher Secondary Standards in 1965 in district Karnal together with the names and dates of upgradation of each School, Block-wise;

(b) whether the Headmasters and the other necessary staff have been appointed in all the said Schools from the date of upgradation; if not, the names of the schools where neither the Headmaster nor the staff has been appointed and if appointed have not joined their duties so far stating the reasons therefor in each case ?

Shri Prabodh Chandra : (a) & (b) The requisite information is laid on the Table of the House.

PRIMARY TO MIDDLE

[Minister for Education]

Name of the School		Block	Date of upgrading	Whether the Headmaster and the Staff has been appointed or not
1.	Atowala ..	Madloda	6/22-5-1965	Yes
2.	Alupur ..	Do	6/13-5-1965	Do
3.	Agondh ..	Kaithal	30-6-1965	Do
4.	Baraut ...	Do	6/13-5-1965	Headmaster not joined. Teachers working in the school
5.	Bhusthala ..	Shahbad	6-6-1965	Yes
6.	Chandana ..	Kaithal	6/17-5-1965	Do
7.	Charhoni Jattan ..	Shahbad	16-11-1965	Do
8.	Deeg ..	Assaudh	12-8-1965	Do
9.	Gundiana ..	Radaur	16-9-1965	Staff is being appointed
10.	Gheer ..	Karnal	6/14-5-1965	Yes
11.	Harsola ..	Kaithal	10-6-1965	Do
12.	Karhans ..	Samalkha	6/17-5-1965	Do
13.	Mandi ..	Do	6-5-1965	Do
14.	Nara ..	Madlouda ..	6/27-5-1965	Do
15.	Poothar ..	Samalkha	6/22-6-1965	Staff is being appointed.
16.	Rohera ..	Pundri	8-11-1965	Yes
17.	Raison ..	Nilokhri	5-8-1965	Do
18.	Rahara ...	Assaudh	12-7-1965	o
19.	Raja Kheri ..	Panipat	31-5-1965	Do
20.	Sanoli Khurd ...	Do	7-5-1965	Do
21.	Seinsar ..	Thanesar	29-5-1965	Do
22.	Teontha ..	Pundri	6/15-5-1965	Do
23.	Bansa			The classes in these schools have not so far been started either due to inadequacy of accommodation or due to not depositing the share of contribution in respect of schools upgraded on contributory basis.
24.	Barut			
25.	Sultanpur			
26.	Khanpur			
27.	Chari Jattan			
28.	Mohiudinpur			
29.	Madhlouda			
30.	Sikri			
31.	Topra Kalan			

MIDDLE TO HIGH

1.	Arampura ..	Gharaunda	25-6-1965	Yes. One vacancy is to be filled in April, 1966.
2.	Babain ..	Radaur	20-5-1965	Yes
3.	Bhapauli ..	Panipat	15-5-1965	Do
4.	Chamrori ..	Radaur	20-5-1965	Do
5.	Jhansa ..	Shahbad	28-8-1965	Do
6.	Ganga there popran	Assand	19-5-1965	Do
7.	Jundla ..	Nissang	15-5-1965	Do
8.	Jakhauli ..	Kaithal	8-11-1965	Do
9.	Kathana ..	Assandh	17-5-1965	Headmaster appointed but has not joined as yet. Arrangement exists against two posts of masters.
10.	Kheri Naru ..	Nissing	17-5-1965	Yes. Arrangement exists against three posts of masters.
11.	Resina ..	Pundri	24-5-1965	Yes.
12.	Sanch ..	Do	6/14-5-1965	Head master appointed but has not joined as yet. Arrangement exists against three posts of masters.
13.	Salwan ..	Assaudh	21-5-1965	Do
14.	Uriana Kalan ..	Madlauda	6-5-1965	Yes. Arrangement exists against three posts of Masters
15.	Yara ..	Shahbad	17-5-1965	Do

The reasons for which some of the Headmasters/Masters who have been appoint ed but have not joined so far are being ascertained and will be intimated later on.

कंवर राम पाल सिंह : यह जो इनफरमेशन दी गई है इस में बताया गया है कि 31 स्कूल प्राईमरी से मिडल स्टैंडर्ड के किये गए हैं और 15 मिडल से हाई स्कूल बनाए गए हैं। इस बाद वाले में जो नम्बर 18 पर है राढ़ा विलेज ब्लाक असंध में कहा है कि स्टाफ पूरा हो गया है 12 जुलाई 1965 से। स्पीकर साहिब, मैं चैलेंज करता हूं कि यह सूचना गलत है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमैंट्री कीजिये, चैलेंज नहीं। (Please put the supplementary and not throw the challenge.)

कंवर राम पाल सिंह : अगर जवाब गलत हो तो उस का क्या किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (Please take your seat)

Minister : What I feel is that instructions were issued for certain teachers to join that school. I will check up why they have not joined. I do not see ony reason to disbelieve the hon. Member. Equally the information supplied to me is that the staff was supplied However, I will check up and let the hon. Member know.

कंवर राम पाल सिंह : जहां पर मिडल से हाई अपग्रेड किये गए स्कूलों के स्टाफ का जिक्र है उस में जिक्र है तीन स्कूलों के हैडमास्टर्ज़ को एप्वायंट किया गया मगर उन्होंने जायन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन हैडमास्टरों ने जायन नहीं किया उन्होंने क्या रीज़न्ज़ दिये हैं ? क्या इन की पड़ताल करके मन्त्री महोदय उन के खिलाफ ऐक्शन लेंगे या लेने को तैयार हैं ?

Minister : Sir, I cannot make any commitment whether any action has been taken or not. But if they have no justifiable reason for not joining, the department does take action against such officers. Whether in this particular case any action has been taken or not I will not be in a position to say just now.

चौधरी रण सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब साल खत्म हो रहा है, बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, साल में मास्टरों की शार्टेज रही है तो क्या इस से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ा ? वह इस कमी को पूरा क्यों नहीं कर पाए ?

Minister : Sir, the shortage is not as such to the effect that studies of the students suffer. Supposing there is a strength of 10 teachers in a particular school and there are 8 or 9 teachers in position, the work is distributed amongst those 8 or 9 teachers. The student's education does not suffer.

कंवर राम पाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो हाई स्कूल अपग्रेड किया गया है उन में तीन हैडमास्टरों ने जायन नहीं किया और भी स्टाफ वहां पर नहीं गया। यह तीनों स्कूल असंध और पुंडरी ब्लाकस यानी मेरे हल्के में पड़ते हैं। मैं इन से जानना चाहता हूं कि करनाल ज़िले में जब बाकी जगह पर टीचरज़ भेजे जाते हैं तो इन तीनों स्कूलों में ही क्यों नहीं भेजे गए ?

Minister : I think the hon. Member has got a wrong feeling of differentiation. The orders were issued to the Headmasters and the teachers to join there. What I feel is that the place which Mr. Kanwar Ram Pal Singh represents is not very attractive and that is why the teachers are reluctant to go there. However, I will check up and see why the Teachers do not go there.

श्री जगन्नाथ : क्या एजूकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब से यह मिनिस्टर बने हैं स्कूलों और कालोनी के अन्दर तालीम का भट्ठा बैठ गया है तो क्या इस में कभी इम्प्रूव करने की आशा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउड। (Not allowed)

श्री अमर सिंह : क्या एजूकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि बहुत सारे स्कूलों में हैडमास्टर नहीं हैं और जैसा कि कंवर राम पाल सिंह ने बताया है निरियाना रिजन में हैड मास्टर नहीं है तो ऐसे स्कूलों में कब तक हैडमास्टर भेज दिए जाएंगे ?

मन्त्री : मेरी अर्ज यह है कि अगर आनरेबल मेम्बर साहिब यह जानने की कोशिश करें तो उनको मालूम होगा कि सरकार ने इस साल इतने स्कूल अपग्रेड कर दिए हैं जितने कि पिछले सात आठ साल में इकट्ठे मिला कर नहीं किए गए तो इस लिए स्टाफ की शार्टेज हो गई है । हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीचर लगा दिए जाएं ।

कंवर राम पाल सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब के नोटिस में है कि बहुत से स्कूलों में स्टाफ की कमी है और फिर उन इलाकों में अनट्रेन्ड टीचर नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे टीचरों की पोसटिंग की जा सकती है ?

मन्त्री : जनाबे आली, मुझे इस तरह की बात परसों करनाल के एस. पी. साहिब ने भी बताई थी और हदायात जारी कर दी गई हैं कि चाहे ट्रेन्ड हों या अनट्रेंड हों अगर कोई टीचर ना मिले तो उनको 6 महीने के लिए लगा लिया जाए ।

This policy will be given shape within few days.

DIFFERENT GRADES OF PAY FOR STATISTICAL ASSISTANTS IN THE OFFICE OF THE DIRECTOR OF HEALTH SERVICES, PUNJAB

*9808. **Chaudhri Ran Singh** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there are four different grades of pay for the posts of Statistical Assistants in the office of the Director of Health Services, Punjab ; if so, the time scale of pay for each of these grades ;

(b) whether there is any difference in the duties and responsibilities assigned to each of the four categories of Statistical Assistants; if so, what ;

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons for retaining four different grades for one and the same category of posts ;

(d) whether there is any proposal under the consideration of the Goverment for reorganisation of all the categories of Statistical Assistants; if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

Shrimati Om Prabha Jain :

(a) Yes. (i) Rs. 150—10—250/10—350.

(ii) Rs. 100—10—250.

(iii) Rs. 105—5—120/8—200/10—220

(iv) Rs. 106—6—160/8—200

(b) Yes. Comparative statement showing duties allotted to the posts of Statistical Assistants in different pay scales is laid on the Table of the House.

(c) Does not arise in view of (b) above

(d) No.

[Minister for Health]

COMPARATIVE STATEMENT SHOWING THE DUTIES OF STATISTICAL ASSISTANTS IN THE SCALES OF Rs. 150—10—250/10—350, (ii) Rs. 100—10—250, (iii) Rs. 105—5—120/8—200/10—220, (iv) Rs. 106—6—160/8—200

Statistical Assistant in the scale of Rs. 150—10—250/10—350	Statistical Assistant in the scale of Rs 100—10—250	Statistical Assistant in the scale of Rs 105—5—120/8—200/10—250	Statistical Assistant in the scale of Rs 106—6—160/8—200
1	2	3	4
1. Guiding and developing the organisation in the districts and instituting remedial measures in case of break-downs.	1. Tabulation, Analysis of statistical data, collected and computed by the computors.	1. To receive reports on vital statistics from the various Blocks and Municipalities in the area, check them, and transmit them to State level.	1. To receive monthly reports from various levels scrutinize and consolidate them.
2. Improving quality as well as timely receipt of returns.	2. To ensure the in flow of information from Sub-offices.	2. To compile simple abstracts of the statistical data, for presentation and interpretation to the Zila Parishad and to the concerned health staff.	2. To scrutinize the collected data on WHO/Unicef individual cards or any other cards prescribed for the purpose and do the preliminary analysis, tabulation and evaluation of the results
3. Pursuing and improving the chronic defaulters by taking up with State authorities when efforts of District Registrars fail.	3. To explore new fields of development.	3. To participate in various special studies related to assessment of the effects of the family planning programme throughout the District.	3. To keep an up-to-date record of all the unit, and assii in improving the efficiency of the units
4. Setting up an efficient system of compilation of vital statistics—ensuring submission of weekly, monthly and annual returns in prescribed forms by stipulated dates.			4. To assist the ADHS in preparing monthly quarterly and annual reports of the programme as may be prescribed
5. Looking into working of registration in districts, examining periodical reports received and suggesting further improvement			

1	2	3	4
6. Coordinating the publicity and training programmes in the Districts of the State.			
7. Printing and timely supply of registration forms to District Registrars.			
8. Follow up arrangements for permanent preservation of registration records and issuing instructions for proper maintenance of these records to facilitate issue of birth and death certificates to public.			
9. Preparing Annual Vital Statistical Reports and Publishing them regularly and timely.			

चौधरी रन सिंह : क्या मिनिस्टर साहिबा ने जो स्टेटमेंन्ट दी है इन की ड्यूटीज़ की इन्हें कब से लागू किया गया है ?

मंत्री : यह इन्फरमेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है अगर आप नोटिस दें तो पता कर के बता दूंगी ।

TEACHERS SUSPENDED/TERMINATED IN LUDHIANA DISTRICT

***8883. Sardar Kultar Singh** : Will the Minister for Education be pleased to —

(a) lay on the Table of the Ho use a list of the names, of such teachers working in the Government Primary, Middle and High Schools in Ludhiana District who were suspended or whose services were terminated during the pericd from 1st January, 1965 to 31st December, 1965;

(b) the nature of allegations on the basis of which action mentiond in part (a) above was taken in each case ;

(c) whether the said teachers were given an opportunity to give their explanations before suspending them or before terminating their services; if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) & (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) Yes, as and when required under the rules.

STATEMENT

Sr. No.	Name of the Teacher	Allegations	Action taken against the teacher
1.	Shri Narbhai Singh, Government Primary School, Sirthala (Khanna).	Arrest by the Police under Section 323/324/325/326/452/147/148. I.P.C.	Placed under suspension on arrest by the Police. Later, dismissed on being convicted by the Court.
2.	Shri Malkiat Singh, Government High School, Dhamot (Ludhiana).	Arrest by the Police under Section 326 I. P. C.	Placed under suspension on arrest by the Police Later, dismissed on being convicted by the Court.
3.	Shri Kartar Singh, Government Primary School, Majri (Doraha Block)	Arrest by the Police under Section 364/123-B. I. P. C.	Placed under suspension on arrest by the Police. The case is pending in the Court.
4.	Shri Joginder Singh, Government High School, Katani Kalar (Ludhiana).	Arrest by the Police under Section 377/511/580 I. P. C.	Placed under suspension on arrest by the Police. The case is pending in the Court.
5.	Shri Harbhagat Singh, Government Primary School, Jodhan (Pakhowal).	Arrest by the Police under Section 353/342/336/279 I. P. C.	Placed under suspension on arrest by the Police. Later on, reinstated without prejudice to the action to be taken against him in the light of the judgement of the Court which is still awaited.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ?

Minister : It goes without saying that if they are not held guilty, Government reinstates them. But if they get the benefit of doubt the department tries not to take them back.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਸਪੈਂਡ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Minister : I do not know the section but it seems that the nature of the charges against him is not very serious and the departmental officers have reasons to believe that he is innocent. But if the verdict of the court goes against him he will not be kept in service.

Sardar Gurnam Singh : Does the hon. Education Minister understand that the phrase 'benefit of doubt' is meaningless in the judicial dcisions. A man is either held guilty or not guilty. In cases where the aquittal on benefit of doubt does the Government consider it appropriate to reinstate them ?

Minister : Sir, I have already explained that if he is acquitted or discharged by giving him the benefit of doubt and otherwise the department is convinced that the teacher was actually guilty and his reinstatement is not in the interest of education of the students we try not to take him back.

कामरेड राम प्यारा : क्या ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह पालिसी सिर्फ टीचरों के सम्बन्ध में ही है या सारे गवर्नमैंट सरवैन्टस के बारे में लागू है कि जहां पर बैनिफिट ग्राफ डाऊट हो वहां पर उसे रिइन्स्टेट नहीं किया जाता ?

Minister : Sir, I am referring to my own department. I am sorry, I do not know what the procedure in other departments is.

ENQUIRY HELD INTO THE SURPLUS LAND OF SHRI KULDIP SINGH OF VILLAGE MUKANDPUR

*9795. **Comrade Babu Singh Master** : (Put by Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal on his behalf) Will the Minister forRevenue be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Vigilance Department conducted an enquiry into the case regarding the surplus land of Shri Kuldip Singh of village Mukandpur, tehsil Nawanshahar, district Jullundur and sent the report to the Under Secretary, Revenue Department, Punjab ; if so, a copy of the report of the enquiry be placed on the Table ;

(b) the action the Gavernment has taken or proposes to take in the matter ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) (i) Yes.

(ii) The report of enquiry conducted by the Vigilance Department is a secret document and cannot, therefore, be placed on the Table of the House.

(b) The Deputy Commissioner, Jullundur, got a case registered with the Police Station, Banga, on the basis of the report of the Vigilance Department.

COLLECTIONS OF FUNDS BY THE EDUCATION DEPARTMENT FOR JAWANS AND DEFENCE PURPOSES

*9353. **Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) the total amount collected by the Education Department, district-wise for the Jawans and Defence purposes together with the date when the collections were started and the date when these were stopped ;

(b) the names of the districts which stood 1st, 2nd and third in the said collections ;

(c) whether any complaints from any district in connection with the collections for the said funds were received by the Government ; if so, the number thereof and the action taken thereon ;

(d) the target fixed for the collection of the said funds together with the amount actually collected by the Education Department ;

(e) whether any officer of the Education Department was made incharge for the said collections ; if so, his name and designation ;

(f) whether any prizes have been given or commendation certificates issued to these teachers who attained distinct positions in collecting the said funds ; if so, the names of such teachers, district-wise ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The total amount collected by the Education Department for the Punjab Defence and Security Relief Fund so far, district-wise is Rs. 65,56,706 as per list placed on the Table of the House.

(b) Effective campaign for collection was started from the 11th October, 1965 and concluded on the 10th November, 1965, although some amounts continue to pour in even now.

(b) Ambala District stood first, Karnal second and Rohtak third.

(c) Yes ; nine complaints were received. Two of them have been found baseless ; others are under investigation.

(d) The target fixed for collection of the Fund was Rs. 26.10 lakhs, while actually collections have gone up to Rs. 65,56,706 in cash as well as in kind.

(e) Shri Roshan Lal Verma, Deputy Director, School Administration was deputed to see the campaign was conducted strictly according to Government instructions and there was no coercion.

(f) Yes ; prizes in the form of shields and commendation Certificates were issued to those teaching personnel who secured distinct positions in collection of the said Fund. Their district-wise list is placed on the Table of the House.

[Minister for Education]

Statement showing the up-to-date collection of Punjab Defence and Security Relief Fund made by the Education Department, Punjab, in respect of part (a) of Starred Assembly Question No. 9353.

Serial No.	District		COLLECTION DEPOSITED WITH			Total
			Education Departmnt	Other authorities, viz, Ministers. D. C.'s and Army etc.		
			Cash	Cash	In kind	
	Ambala Circle					
1.	Ambala	..	7,49,033	84,887	..	8,33,920
2.	Gurgaon	..	2,43,069	16,844	..	2,59,913
3.	Hissar	..	2,39,222	37,868	350	2,77,440
4.	Karnal	..	5,45,232	32,209	18,925	5,96,366
5	Rohtak	..	5,16,810	15,424	3,546	5,35,780
6.	Simla	..	38,554	8,573	..	47,127
	Total	..	23,31,920	1,95,805	22,821	25,50,546
	Jullundur Circle					
7.	Amritsar	..	3,46,546	17,272	70,000	4,33,818
8.	Ferozepore	..	3,55,902	10,870	..	3,46,772
9.	Gurdaspur	..	1,75,501	4,628	40,360	2,20,489
10.	Hoshiarpur	..	3,66,980	3,040	..	3,70,020
11.	Jullundur	..	2,33,299	86,436	1,27,466	4,47,201
12.	Kangra	..	1,57,984	11,723	..	1,69,707
13.	Kapurthala	..	1,34,102	9,035	1,209	1,44,346
14.	Kulu	..	49,434	807	12,564	62,805
15.	Ludhiana	..	3,21,055	51,585	7,766	3,80,406
	Total	..	21,20,803	1,95,396	2,59,365	25,75,564
	Patiala Circle					
16.	Bhatinda	..	3,27,300	4,282	..	3,31,582
17.	Mohindergarh	..	2,09,151	111	..	2,09,262
18.	Patiala	..	4,59,322	26,774	..	4,86,096
19.	Sangrur	..	3,44,394	11,785	5,777	3,61,956
	Total	..	13,40,167	42,952	5,777	13,88,896
	Headquarters					
20.	Directorate	..	41,700	..	..	41,700
	Total		41,700	..	..	41,700
	GRAND TOTAL	..	58,34,590	4,34,153	2,87,963	65,56,706

Statement in respect of part (f) of starred Assembly Question No. 9353

PUNJAB EDUCATION DEPARTMENT

PUNJAB DEFENCE AND SECURITY RELIEF FUND HOLD OF HONOURS IN COLLECTIONS

Serial No.	Name	Designation	Place	Amount collected
1	2	3	4	5
		AMBALA DISTRICT		
		Award of Shields		
1.	Shri Chander Gupta Jain	Principal, M.L.N. Higher Secondary School	Yamunanagar	15,500
2.	Smt. K. Azad	Head mistress, Arya Girls High School	Kharar	8,015
3.	Mrs. R.K. Jaswant Singh	Headmistress, Government girls High School, Model Town	Ambala City	7,670
4.	Sh. P.C. Bhatia	Headmaster, C.B. High School	Ambala Cantt.	13,373
5.	Sh. Sarvjit Sharma ..	Headmaster, Government Co-educational Middle School, Baldev Nagar Camp	Ambala City	3,158
		Gold Medal		
6.	Shri Goverdhan Lal	Principal, Government College	Chandigarh	10,816
7.	Shri Chander Gupta	Principal, M.L.N. Higher Secondary School	Yamuna Nagar	15,500
8.	Shri Harchand Singh	Principal Khalsa Higher Secondary School	Chamkaur Sahib	13,129
9.	Miss P.S. Bhola	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Yamuna Nagar	10,746
10.	Miss. P.C. Bhatia	Headmistress, C.B. High School.	Ambala Cantt.	13,373
11.	Mrs. K. Azad	Headmistress, Arya Girls High School	Kharar	8,015
12.	Mrs. R.K. Jaswant Singh	Head mistress, Government Girls M.T. High School	Ambala	7,676
13.	Shri Suraj Bhan	Teacher, S.D. Higher Secondary School	Ambala	1,114
14.	Smt. Phullan Devi	Teacher, Government Primary School	Ambala City	1,021
		Silver Medal		
15.	Shri Kharati Lal	Headmaster, G.R.S.D. High School	Ambala City	6,107
16.	Shri Iqbal Singh	Headmaster, Government High School	Chhachhrali	5,763

[Minister for Eductaion]

1	2	3	4	5
		AMBALA DISTRICT—contd.		
		Silver Medal—*cotd.*		
17.	Shri Faquir Chand	Headmaster, S.A. Jain High School	Ambala City	5,750
18.	Shri Mohinder Singh	Lecturer, Government Higher Secondary School	Purkhali	1,038
19.	Shri Probodh Chander	Lecturer, Government Higher Secondary School	Ambala City	1,101
20.	Shri Ram Kamar Shar ma	Lecturer, S. D. Higher Seccondary School	A mbala	1,124
21.	Shri Shya m Lal Gupta	Master, Government Middle School	Badhanli	1,000
22.	Shri R.D. Gupta	Teacher, C.B. High School	A mbala Cantt.	851
23.	Shri Parkash Nand	Teacher, C.B. High School	A mbala Cantt.	800
24.	Shri Jai Parkash	Teacher, Government Primary School No. 6	Dera Salempur	825
		Bronze Medal		
26.	Shmt. S. Gaind	Principal, Government Gilrs Higher Secondary School Sector—18	Chandigarh	5,926
27.	Shri Darshan Singh	Principal, Khalsa Higher Seccondary School	Kharar	7,100
28.	Shri R.R. Sharma	Principal, Governmnt Higher Secondary School, Sector-23	Chandigarh	6,582
29.	Shri Satya Sarup	Principal, A.S. Higher Secondary School	A mbala City	6,094
30.	Shri Dhara m Singh	Principal, Khalsa Higher Secondary School	Kurali	6,000
31.	Shri Ram Lal Kakkar	Principal, Government Multipurpose School	Jagadhari	5,803
32.	Mrs. D. Kalra	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Ambala City	5,579
33.	Shri Harbachan Singh	Principal, Government Higher Secondary School	Naraingarh	5,023
34.	Shri Sharma ..	Headmaster, S. D. Higher Secondary School	Jagadhari	5,000
35.	Shmt. P. Datt.	Headmistress, Government Girls High School, Sector—21	Chandigarh	4,504
36.	Shri D.R. Sharma	Headmaster, B.D. High Schoool	Ambala Cantt.	4,429
37.	Shri Balwant Singh	Headmaster, Khalsa High School	Rupar	4,001

Serial No. 1	Name 2	Designation 3	Place 4	Amount collected 5
		AMBALA DISTRICT—contd.		
38.	Sht. S. Anand	Head mistress, Hindu Girls High School	Jagadhari	4,000
39.	Shri R.S. Datt.	Headmaster, Governmet High School	Chandigarh	3,728
40.	Miss Raj Uppal	Headmistress, Govern mnt Co-education High School, Sector 27	Do	3,696
41.	Mrs. Kalia	Headmistress, P. K. R. Jain Girls High School	Ambala City	3,712
42.		Headmistress, Govern ment Girls High School	Nalagarh	3,712
43.	Miss A. Karam Singh	Superintendent, Government Senior Model School	Chandigarh	5,000
44.	Shri Sarvjit Singh	Head master, Government Co-Educational Middle Schools Baldev Nagar	Ambala City	3,158
45.	Shri Ghanshyam Dass	Head master, Government Middle School	Mustafabad	2,169
46.	Shri Vidya Sagar	Lecturer, Government Higher Secondary School	Adoya	780
47.	Shri Bhupinder Singh	Ditto	Chhachhrauli	870
48.	Shri Ram Murti Gulshan	Ditto	Jagadhri	1,000
49.	Shri K.K. Gupta	Lecturer, G.B. Higher Secondary School	Ambala	994
50.	Shri Jagdish Parshad	Ditto	Ambala	815
51.	Shri Sarv Dayal	Lecturer, S. D. Higher Secondary School	Ambala	764
52.	Shri Ramesh Chander	Teacher, Government Middle School	Rattawali	510
53.	Shri Nathu Ram	Ditto	Rattawali	514
54.	Shri B.S. Moudgil	Teacher, C.B. High School	Ambala	705
55.	Shri Kali Ram	Ditto	Ambala	563
56.	Shri Vishwa Nath	Teacher, Government Primary School No. 6	Ambala City	501
57.	Sh. Lachman Dass	Teacher, Government Primary School	Majri	520
58.	Shri Amar Chand	Ditto	Dang	561
59.	Shri Rattan Lal	Ditto	Bathlana	621
60.	Shri Mehar Singh	Ditto	Giga Majra	502
61.	Shri Dali Ram	Ditto	Mattloi	711
62.	Smt. Parkash Kaur	Teacher, Government Primary School	Desu Majra	750
63.	Shri Gurbhajan Singh	Teacher, Government Primary School	Niamian	750

[Minister for Education]

1	2	3	4	5
		Commendation Certificate		
..	..	..	..	..
		GURGAON DISTRICT		
		Award of Shields		
..	..	..	..	..
		Gold Medal		
..	..	..	..	..
		Silver Medal		
..	..	..	..	..
		Bronze Medal		
64.	Shri P. Grover	Principal, Government Girls Higher Secondary School.	Rewari	5,560
		Commendation Certificate		
..	..	..	..	..
		HISSAR DISTRICT		
		Award of Shields		
..	..	..	..	..
		Gold Medal		
65.	Shri Ra m Saran Dass	Principal , Government Higher Secodary School	Fatehabad	10,034
66.	Shri B.K. Datt	Teacher, Government Primary School	Madhawala	1,050
		Silver Medal		
67.	Miss Janki Chopra	Principal, F.C. College for Women	Hissar	8,101
68.	Shri Krishan Chand	Headmaster, Governmnt High School	Rattia	5,216
		Bronze Medal		
69.	Shri S.S. Gupta	Principal, Government College	Hissar	5,001
70.	Shri Jai Bhagwan	Principal, Governmnt Higher Secondary School	Sirsa	6,051
71.	Shri M.L. Sehgal	Ditto	Hissar	5,064
72.	Shmt. Bimla Minhra	Head mistress, Government Girls High School	Sirsa	4,273
73.	Shmt. S. D. Malik	Ditto	Fatehabad	3,501
74.	Shri Balwant Singh	Head master, Movernment Middle School	Ja malpur Shiekhan	2,601
		Commendation Certificate		
	..	..	..	..

1	2	3	4	5
		KARNAL DISTRICT		
		Award of Shields		
..	..	..	..	..
		Gold Medal		
75.	Shri Trilochan Singh	Principal, Government Higher Secondary School	Kaithal	..
76.	Shri Jagan Nath	Headmaster, Government High School	Ladwa	..
77.	Sahib Ram Gulshan	Teacher, Government Higher Secondary School	Kaithal	1,001
78.	Shri Deva Singh	Teacher, Government Primary School	Kheri Sher Khan	1,017
79.	Shri Om Parkash	Ditto	Chochru	1,046
80.	Shri Kishan Datt	Ditto	Rajond	1,363
81.	Shri Prithi Singh	Ditto	Kawartan	1,155
82.	Shri Madho Ram	Ditto	Kalron	1,085
83.	Shri Ram Kishan	Teacher, Government High School	Ladwa	1,372
		Silver Medal		
84.	Mrs. G. Nagpal	Headmistress, Government Girls High School, Model Town	Panipat	..
85.	Mrs. M. Jamu	Headmistress, Government Girls High School	Thanesar	..
86.	Shri JagdishSingh	Teacher, Government High School	Ladwa	766
87.	Shri Mage Ram	Teacher Government Primary School	Sagal	820
88.	Shri Lal Chand	Teacher,Government Primary School	Rohera	761
89.	Shri Jai Bhagwan			
		Brozne Medal		
90.	Smt. Satya Thakur	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Kaithal	
91.	Smt. Lila Malhotra	Ditto	Panipat	..
92.	Shri Inderjit Singh	Principal, Government Higher Secondary School	Kurukshetra	..
93.	Shri Dalip Chand	Ditto	Gharaunda	..
94.	Shri Gian Sarup	Ditto	Nilokheri	..
95.	Shmt. M. Jogi	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Karnal	..
96.	Shri Prem Parkash	Principal, Government Higher Secondary School	Shahabad	..
97.	Shri Kala Ram	Headmaster Government High School	Babain	..

1	2	3	4	5
		DISTRICT KARNAL—contd.		
		Brozne Medal—*contd*		
98.	Shmt. Sharanjit Kaur ..	Headmistress, Government Girls High School, Model Town	Karnal	..
99.	Smt. S. Gambhir	Headmstress, Government High School, Prem Nagar	Do	..
100.	Shri Kundan Lal	Headmaster, Government High School	Pehowa	..
101.	Sh. Peare Lal	Teacher, Government Primary School No. 18	Karnal	542
102.	Shmt. Krishna Kathuria	Teacher, Government Primary Schoo No. 1	Do	537
103.	Shmt. Pushpa Tateja	Teacher, Government Primary School No. 6.	Do	544
104.	Sh. Hotu Ram	Teacher, Government Primary School No. 9	Do	502
104.	Shrl Rameshwar Dayal	Teacher, Government Primary School	Barrer	631
105.	Shri Amar Nath	Teacher, Government Primary School	Kaithal	625
106.	Shri Dina Nath	Teacher, Government Primary School	Kaithal	550
107.	Shri Gyan Inder Slngh	Teacher, Government Primary School	Chhajpur	560
108.	Shri Om Parkash	Teacher, Government Primary School	Jainpur	510
109.	Shri Arja Dass	Teacher, Government Primary School	Kheri Simbal wali	649
110,	Smt. Nirma Kumari	Teacher, Government Primary School	Jai Gullah	603
111.	Shri Satya Paul	Teacher, Government Primary School	Gullah	706
112.	Shri Ram Bhan	Teacher, Government Primary School	Kohand	505
113.	Shri Bhagat Singh	Teacher, Government Primary School	Gucha	505
114.	Shri Jag Dhia	Teacher, Government Primary School	Gharaunda	505
115.	Shri Lakhi Ram	Teacher, Government Primary School	Barrana	501
116.	Shri Madan Lal	Teacher, Government Primary School	Barant	501

1	2	3	4	5
		DISTRICT KARNAL—concld.		
117.	Shri Jiwan Dass	Teacher Government High School	Namba	740
118.	Shri Bhagwat Sarup	Teacher Government Middle School	Ramba	505
119.	Shri Mohan Singh	Master Government High School	Lacwa	764
120.	Smt. Vimla Sachdev	Mistress Government Girls High School Model Town	Panipat	900
		Commendation Certificate		
—	—	—	—	—
		ROHTAK DISTRICT		
		Award of Shields		
121.	Shri Randhir Singh	Headmaster Government Middle School	Kehrawas	3,025
		Gold Medal		
122.	Miss S. Sharma	Principal Government Girls Higher Secondary School	Bahadurgarh	14,000
123.	Miss Oma Sharma	Principal Government Girls Higher Secondary School	Rehtal	14,096
124.	Shri Chandar Bhan	Teacher Government Primary School	Balra	1,163
125.	Shri Jai Narain	Teacher Government Primary School	Dighal	1,608
126.	Shri Ram Singh	Teacher Government Primary School	Sanghi	1,140
		Silver Medal		
127.	Shri Dhani Ram	Headmaster, S. M. Mindu High School	Sonepat	5,200
128.	Shri Rishi Cash	Headmaster, Government High School	Sampla	5,021
129.	Shri Narain Singh	Headmaster, Government High School	Bulhera	5,012
130.	Shmt. Chambeli Devi	Teacher Government Primary School	Beri	753
131.	Shri Abhe Ram	Teacher Government Primary School	—	973
132.	Shri Jai Ram Dass	Teacher Government Primary School	Kahanaur	814

[Minister for Education]

2		3	4	5
		ROHTAK DISSRICT—concld.		
		Bronze Medal		
133.	Shri Partap Singh Jain	Principal, Government Higher Secondary School	Rohtak	7,C01
134.	Shri Randhir Singh	Headmaster, Government Middle School	Kehrawas	3,025
135.	Shri Shamsher Singh	Teacher Government Primary School	Kheri Shad	735
136.	Shri Charan Singh	Teacher Government Primary School	Kataur	550
137.	Smt. Vidya Wati	Teacher Government Primary School	Sanghi	542
138.	Shri Visakhi Bai	Teacher Government Primary School	Sunar Guplapm	594
139.	Shri Lubhaya Ram	Teacher Government Primary School	Kharak	730
140.	Shri Suraj Bhan	Teacher Government Primary School	Madina	634
141.	Shri Ram Dass	Teacher Government Primary School	Ghansaini	610
142.	Shri Radha Krishan	Teacher Government Primary School	Katwara	508
143.	Shri Gopi Ram	Teacher Government Primary School	Gannan	675
144.	Shri Ravi Datt	Teacher Government Primary School	Rajlughari	722
		Commendation Certificate		
—	—	—	—	—
		SIMLA DISTRICT		
		Award of Shields		
—	—	—	—	—
		Gold Medal		
—	—	—	—	—
		Silver Medal		
145.	Miss. P. Bahl	Headmistress, Government School	Lakkar Bazar Simla	5,020

1	2	3	4	5
		DISTRICT SIMLA—concld.		
		Bronze Medal		
—	—	—	—	—
		Commendation Certificate		
—	—	—	—	—
		AMRITSAR DISTRICT		
		Award of Shields		
		Gold Medal		
146.	Smt. Miss A. Natha	Principal Government College for women	Amritsar	11,450
147.	Shri Harjinder Singh	Master, Government High School	Ajnala	6,851
		Silver Medal		
148.	Shri Jagdish Chander	Principal Government Higher Secondary School	Amritsar	7,569
149.	Shri Jawahar Singh	Teacher Government School	Patti	800
		Bronze Medal		
150.	Shri Amolak Singh	Headmaster, Government High School	Ajnala	3,505
151.	Shri Raghbir Lal	Lecturer Government Higher Secondary School	Patti	800
152.	Shri Amar Singh	Master Government Higher Secondary School	Patti	800
153.	Shri Kuldip Singh	Master Government Higher Secondary School	Patti	800
154.	Smt. Surja Kaur	Teacher Government Girls High School	Ajnala	540
		Commendation Certificate		
—	—	—	—	—
		FEROZEPORE DISTRICT		
		Award of Shileds		
—	—	—	—	—
		Gold Medal		
155.	Shri Maghar Singh	Principal Government Higher Secondary School (Main)	Abohar	10,385
156.	Shri Gurbachan Singh	Teacher Government Middle School	Baurwali	

[Minister for Education]

1	2	3	4	5
		DISTRICT FEROZEPORE—contd.		
		Silver Medal		
157.	Shri B. B. Chhabra	Head master, Government School	Guru Har Sahai	5,009
		Bronze Medal		
158.	Smt. Kaushalya Devi	Teacher Government Primary School	Ferozepur	600
159.	Shri Ram Nath	Teacher Government Primary School	Kaleke	573
160.	Shri Apar Singh	Teacher Government Primary School	Ballangarh	588
161.	Shri Inderjit Pal	Teacher Government Primary School	Charewan	600
162.	Shri Pal Singh	Teacher Government Primary School	Dharampur	507
		Commendation Certificate		
163.	Shri Brij Lal	Teacher Government Middle School	Azamwal	Donated full months salary
164.	Smt. Surjit Kaur	Teacher Government Primary School	Gajjanwal	-do-
165.	Shri Gurdial Singh	Teacher Government Primary School	Jandiala West	-do-
166.	Shri Purna Singh	Teacher Government Primary School	Chida	-do-
167.	Shri Gurcharan Singh	Teacher Government Primary School	Naleke	-do-
168.	Shri Atma Singh	Teacher Government Primary School	KetleNhear Singh	-do-
169.	Shri Gurnam Singh	Teacher Government Primary School	Jit Singhwala	-do
170	Shrimati Sikadar Kaur	Teacher, Government Primary School	Jit Singh wala,	-do-
171	Shri Balbir Singh	Teacher, Government Primary School	Vairake	-do
172	Shri Karnail Singh	Teacher, Government Primary School	Phulewal	-do-
173	Shrimati Sampuran Kaur	Teacher, Government Primary School	Vairke	-do-
174	Shri Majar Singh	Teacher Government Primary School	Nathawala	-do-

1	2	3	4	5
		FEROZEPORE DISTRICT—CANCLD		
175.	Shrimati Ajit Kaur	Teacher, Government Primary School	Channawan	Donated full month,s salary
176.	Shri Jagjit Singh	Teacher, Government Primary School	Smach Bhai	Do
177.	Shri Gurdyal Singh	Teacher, Government Primary School	Do	Do
178.	Shri Pritam Singh	Ditto	Mari	Do
179.	Shri Bahadur Singh	Ditto	Mari	Do
180.	Shri Shara Chand	Ditto	Sukha Nand	Do
181.	Shri Marnet Singh	Ditto	Dala Wala	Do
182.	Shri Malkiat Singh	Ditto	Sahake	Do
183.	Shri Gurmail Singh	Ditto	Sibian	Do
184	Shri Sareer Singh	Ditto	Do	Do
185.	Shri Jarnail Singh	Ditto	Do	Do
186.	Shrimati Bachint Kaur	Ditto	Thathi Bhai	Do
187.	Shri Marchara Singh	Ditto	Chellia Kalan	Do
188.	Shrimati Harjinder Kaur	Ditto	Chollia Kalan	Do
189.	Shrimati Surinder Kaur	Ditto	Do	Do
190.	Shrimati Gurbachan Kaur	Ditto	Do	Do
191.	Shrimati Dalip Kaur	Ditto	Do	Do
192.	Shri Satya Parkash	Ditto	Kalar Khera	Do
193.	Shri Baldev Gill	Ditto	Mahana	Do
194.	Shrimati Mukhtiar Gill	Ditto	Do	Do
195.	Shri Ajit Singh	Ditto	Thandiana East	Do
196.	Shrimati Dhan Kaur	Ditto	Laneyke	Do
197.	Shri Gurbachan Singh	Teacher Government Middle School	Barawali	Till the duration of Emergency
		GURDASPUR DISTRICT		
		Award of Shields		
—	—	—	—	—
		GOLD MEDAL		
—	—	—	—	—
		SILVER MEDAL		
198.	Shri Saudagar Singh	Headmaster Government High School	Batala	5,142

1	2	3	4	5
		GURDASPUR DISTRICT—CONCLD.		
		BRONZE MEADAL		
199.	Mrs. Shanti Gupta	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Gurdaspur	6,053
200.	Mrs. So	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Batala	5,693
201.	Shrimati Inder Jit Kaur	Headmistress Government Girls High School	Dina Nagar	4,151
		COMMENDATION CERTIFICATE		
202.	Shrimati Bavinder Kaur	Headmistress Government Girls High School	Sohal	Donated, full month's Salary.
		HOSHIARPUR DISTRICT		
		AWARD OF SHIELD		
203.	Shri Girdhari Lal Thappaswi	Principal, Government Higher Secondary School	Tanda Urmar	23,501
		GOLD MEDAL		
204.	Shri Girdhari Lal Thappaswi	Principal, Government Higher Secondary School	Tanda Urmar	23,501
205.	Shrimati Surinder Kaur	Teacher Government Primary School	Mahilpur	1,247
		SILVER MEDAL		
206.	Shri Mahinder Singh	Master, Government Higher Secondary School	Tanda	1,048
		BRONZE MEDAL		
207.	Shri Mohan Singh	Master Government Higher Secondary School	Tanda	914
		COMMENDATION CERTIFICATE		
—	—	—	—	—
		JULLUNDUR DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
—	—	—	—	—
		GOLD MEDAL		
—	—	—	—	—
		SILVER MEDAL		
—	—	—	—	—
		BRONZE MEDAL		
208.	Shri Peare Lal Beri	Principal, S. D. A. S., Higher Secondary School	Jullundnr	5,872

1	2	3	4	5
		JULLUNDUR DISTRIC—CONCLD.		
209.	Shrimati Thandi	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Phillaur	5,872
210.	Shri B. K. Manda	Headmaster, Government Middle School	Baipur Basulpur	2,606
211.	Shrimati Lalita Kakkar	Headmistress, Government Girls High School Ladowali Road	Jullundur	4,000
		COMMENDATION CERTIFICATE		
212.	Shrimti Hardyal Kaur	Teacher Government Middle School	Khankhana	Donanted, full months salary
213.	Shrimati Ajit Kaur	Ditto	Nagal Karar Khara	Ditto
214.	Shrimati Ajmer Kaur	Teacher Government Middle School	Paulat Pur	Ditto
		KANGRA DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
—	—	—	—	—
		GOLD MEDAL		
215.	Shri K. R. Chaudhri	Principal Government College for Boys	Dharam sala	10,425
		SILVER MEDAL		
—	—	—	—	—
		BRONZE MEDAL		
—	—	—	—	—
		COMMENDATION CERTIFICATE		
216.	Miss. K. Hukam	Headmistress, Government Girls High School	Dehra	Donated ful month's salary
		KAPURTHALA DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
—	—	—	—	—
		GOLD MEDAL		
217.	Shri Amar Singh	Principal, Ramgarhia College	Bhagwarn	14,189
		SILVER MEDAL		
218.	Shri Amarjit Singh	Headmaster, Government High School	Tibba	5,055
219.	Shri Prem Parkash	Teacher, Government Primary School	Dudwandi	921

[Minister for Eduction]

1		2	3	4	5
		KAPURTHALA DISTRICT—CONCLD			
		BRONZE MEDAL			
220.	Shrimati S. K. Mann	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Phagwara	5,663	
221.	Miss Amrit Ahluwali	Headmistress, Government Girl High School	Sultanpur	4,378	
222.	Shrimati Ata Kaur	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Phgwara	518	
223.	Shrimati Shakuntal Kunera	Ditto	Do	516	
224.	Shri Mohan Singh	Teacher, Government Middle School	Ke Baddo	501	
		COMMENDATION CERTIFICATE			
—	—	—	—	—	
		KULU DISTRICT			
		AWARD OF SHIELDS			
—	—	—	—	—	
		GOLD MEDAL			
225.	Shri Gia Chand Goel	Teacher Government Primary School	Bajara	1,008	
		SILVER MEDAL			
—	—	—	—	—	
		BRONZE MEDAL			
—	—	—	—	—	
		COMMENDATION CERTIFICATE			
—	—	—	—	—	
		LUDHIANA DISTRICT			
		AWARD OF SHELDS			
226.	Shri K. S. Thaper	Principal, Government College for Boys	Ludhiana	14,648	
		GOLD MEDAL			
227.	Shri K. S. Thaper	Prinicpal Government College for Boys	Ludhiana	14,648	
228.	Shri Bhaja Singh	Teacher Government	Mallah	Full month's salary till emergency	

1	2	3	4	5
		LUDHIANA DISTRICT—CONCLD		
		SILVER MEDAL		
229.	Shri Shiv Shankar Sood	Principal, Government Higher Secondary School	Ludhiana	8,151
230.	Shrimati R. N. Shawhney	Principal, Government College for Women	Ludhiana	9,415
		BRONZE MEDAL		
231.	Shrimati Malti Singh	Principal, Government Girls Higher Secondary School Civil Lines	Ludhiana	5,936
232.	Shrimati D. J. Ball	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Khanna	5,700
233.		Principal, Government Girls Higher Secondary School	Ludhiana	5,995
234.		Principal S. D. P. Higher Secondary School	Ludhiana	7,096
235.		Headmistress, Government School, Lakkar Bazar	Ludhiana	4,204
236.		Headmistress, Government Girls Middle School, Karan Boad	Ludhiana	2,580
		COMMENDATION CERTIFICATE		
237.	Shri Bhaja Singh	Teacher, Government Primary School	Mallah	Donated full months, pay till emergency
238.	Shri H. L. Anand	Prof. Khalsa College for women	Ludhiana	Donated full month's salary
		BHATINDA DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
239.	Miss S. Sachdeva	Principal, Government Girls Higher Sncondary School	Kot Kapura	18,002
		GOLD MEDAL		
240.	Miss S. Suchdev	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Kot Kpura	18,002
241.	Shri Karanekam Singh	Headmaster, Government High School	Junir	8,350
242.	Shri G. R. Sahir	Lecturer Rajindera Government College	Bhatinda	1,584
243.	Shrimati Karamjit Kaur	Mistress Government Girls Higher Secondary School	Kot Kapura	1,819

[Minister for Education]

1	2	3	4	5
244.	Mr. Surjit Kaur	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Kotkapura	1 074
245.	Mrs. Surjit Brar	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	1,025
246.	Mrs. Sukhnandan Kaur	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	1,025
		SILVER MEDAL		
247.	Dr. O. J. Bhardwan	Principal, Rajindra Government College	Bhatinda	8,304
248.	Miss. Surjeet Sandhu	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Kot Kapura	7(0
249.	Shri Balbir Singh	Master, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	1,010
250.	Sht. Jaswinder Kaur	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	1,073
251.	Sh. Bhupinder Singh	Master, Gôvernment Middle School	Gobindpur	1,279
		BRONZE MBDAL		
252.	Sh. Baldev Kumar	Principal, Government Higher Secondary School	Kot Kapura	5,001
253.	Sh. Gora Lal	Headmaster, Government Middle School	Budhalada	3,501
254.	Sht. Ravinder Kaur	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Kot Kapura	765
255.	Sh. Kartar Singh	Master, Government Middle School	Tungwali	900
256.	Sh. Tarsem Lal	Master, Government High School	Jhunir	903
257.	Mrs. Satya Wati	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Kotkapura	504
258.	Mrs. Tajendar Kaur	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Do	536
259.	Miss Narinder Bhalla	Teacher, Government Girls Secondary School	Do	603
260.	Mrs. Som Lata	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Do	517
261.	Mrs. Prem Kaur	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Bhatinda	600
262.	Sh. Om Parkash	Teacher, Government Middle School	Akhanwali	504

1	2	3	4	5
263.	Sh. Bachan Singh	Teacher, Government High School	Joga	519
264.	Sh. Balbir Singh	Teacher, Government High School	Jhunir	56,7
265.	Sh. Bhan Singh	Teacher, Government High School	Do	516
266.	Sh. Jaspal	Teacher, Governmrnt High School	Do	526
267.	Shri Krishan Kumar	Teacher, Government High School	Do	505
268.	Shri Jagan Nath	Teacher, Government Primary School	Kheri Kalan	517
		COMMENDATION CERTIFICATE		
269.	Miss Satya Sachdev	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Kotkapura	Donated ful month's pay
270.	Miss Ravinder Kaur	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	Ditto
271.	Miss Amarjit Kaur	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	Ditto
272.	Shrimati Jaswinder Kaur	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	Di.to
273.	Shri Prem Singh	Teacher, Government Primary School	Bucho Kalan	Ditto
274.	Shri Ujagar Singh	Teacher, Government High School	Mandi Phul	Ditto
		MOHINDERGARH DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
—	—	—	—	—
		GOLD MEDAL		
275.	Shri Rao Sultan Singh	Principal Government Higher Secondary School	Kanina	10,716
276.	Shri Sajjan Singh	Master, Government Higher Secondary School	Ditto	1,826
277.	Shri Ganga Singh	Master, Government Higher Secondary School	Mohindergarh	1,521
278.	Shri Shiv Kumar Mehta	Teacher, Government Primary School	Sarai Narnaul	1,033
279.	Shri Sajjan Singh	Master, Government Higher Secondary School	Kanina	1,826

1	2	3	4	5
		Mohindergarh District—CONCLD.		
		SILVER MEDAL		
		BRONZE MEDAL		Rs.
280.	Shri D.V. Kapoor	Principal, Government Higher Secondary School	Mohindergarh	7,138
281.	Shri Hari Parkash Joshi	Principal, Government Higher Secondary School	Narnaul	6,965
282.	Shrimati Sudarshan Khanna	Mistress, Government Girls High School	Mohindergarh	838
283.	Shri Hari Sharma	Teacher, Government High School	Nangal Sarohi	668
		PATIALA DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
284.	Miss A. Dass Gupta	Principal, Government College for Women	Patiala	16,127
285.	Shri B. S. Paul	Headmaster, Government High School	Rajpura	9,301
286.	Shri Ayudhia Parshad	Headmaster, Government High School	Nandpur Kesho	9,153
287.	Miss S. Joshi	Headmistress, Government Girls High School, Chowk Anardana	Patiala	5,200
288.	Shri Inder Singh	Headmaster, Government Middle School	Sirhind City	6,710
289.	Miss Parkash Kapur	Headmistress, Government Girls Middle School, N.P.H.C.	Patiala	6,000
290.	Shri Ved Parkash	Headmaster, Government High School, Tripri Town	Patiala	5,040
		GOLD MEDAL		
291.	Miss Dass Gupta	Principal, Government College for Women	Do	16,127
292.	Shri Mohan Singh	Principal, Ripudaman College	Nabha	10,311
293.	Shrimati Navlila Kaushal	Principal, Government Girls Victoria Higher Secondary School	Patiala	13,000
294.	Shrimati Inderjit Kaur	Principal, Government Girls Higher Secondary School, Old Police Lines	Do	10,010

1	2	3	4	5
		Patiala District—CONTD.		Rs.
295.	Shri B.S. Pal	Headmaster, Government High School	Rajpura	9,301
296.	Shri Ayudhia Parshad	Headmaster, Government High School	Nandpur Kesho	9,153
297.	Shri Inder Singh	Headmaster, Government Middle School	Sirhind	6,710
298.	Shri Ved Parkash	Headmaster, Government Middle School	Tripri Town, Patiala	5,040
299.	Shri Parkash Kapoor	Headmistress, Government Girls Middle School, N.P.H.C.	Patiala	6,000
300.	Shri Inder Singh	Master, Government Middle School	Sirhind	1,501
301.	Shri Tirlochan Singh	Teacher, Government Primary School	Fatehpur	1,832
302.	Shri Prem Singh	Teacher, Government Middle School	Bakala	1,328
303.	Bibi Baljit Kaur	Teacher, Government Primary School	Kahan Garh	1,068
304.	Shrimati Satpal Kaur Sethi	Teacher, Government Middle School, Tripri Town	Patiala	1,013
305.	Shrimati Tarawati	Teacher, Government Middle School, Tripri Town-N.P.H.C.	Ditto	1.005
306.	Shri Hari Chand Bhatia	Teacher, Government Primary School	Badwali	1,001
307.	Shri Dhanwant Singh	Teacher, Government Primary School	Kutha Kheri	1,001
308.	Shri Jaswant Singh	Teacher, Government Middle School	Sirhlnd City	1,001
309.	Shri Ditta Mal Sharma	Teacher Government Middle Sehool	Ditto	1,001
310.	Shri Mohinder Singh	Teacher, Government Primary School	Chagger Sarai	1,001
311.	Shri Mohinder Singh	Teacher, Government Primary School	Gobindpura	1,001
312.	Shri Sadhu Ram	Teacher, Government Primary School	Godda Pur	1.001
313.	Manmohan Singh	Teacher, Government Primary School	Kheri Gurna	1,001
314.	Shri Manjit Singh	Teacher, Government Primary School	Suraj Garh	1,001
315.	Shri Ranjit Singh	Teacher Government Primary School	Kotla Fazal	Donated full month's pay till emergency

[Minister for Education]

1	2	3	4	5
		Patiala District—CONTD.		
		SILVER MEDAL		
316.	Shri Rajinder Singh	Principal Government Higher Secondary School	Nabha	7,650
317.	Bibi Sarla Puri	Principal, Government Girls Higher Secondary School	Do	7,503
318.	Shri P.D. Loomba	Headmaster, Government High School	Sangrur	5,227
319.	Shrimati Joshi	Headmistress, Government Girls High School, Chowk Anardana	Patiala	5,200
320.	Shrimati S. Madhok	Headmistress, Government Girls High School	Rajpura	5,005
321.	Shri Gurbachan Singh	Teacher, Government Primary School	Kalbahera	896
322.	Shrimati Harbhajan Kaur	Teacher, Government Primary School	Patiala	850
323.	Shri Ram Parkash	Teacher, Government Primary School	Joga	815
		BRONZE MEDAL		
324.	Shri Nand Kishore Mohan	Principal, S.D.S.E. Higher Secondary School	Patiala	6.113
325.	Shrimati Sharma	Principal, Government Basic Girls N.T.C., Higher Secondary School	Rajpura	5,546
326.	Shri Som Nath	Principal, A.P. Kumar Sabha Higher Secondary School	Patiala	5,100
327.	Shri—Name missing in Government Statement.	Principal, Yadvindra Public School	Do	7,295
328.	Shri Basheshar Singh	Headmaster, Government High School	Samana	3,692
329.	Shrimati Jagdish Singh	Headmistress, Government High School	Dera Bassi	3,536
330.	Shri Bachitter Singh	Headmaster, Government Middle School	Salana	2,657
331.	Shri Sham Lal	Headmaster, Government Middle School	Dakala	2,700
332.	Shrimati Raj Kumari Ahluwalia	Headmistress, Government Middle School, Tripri Town	Patiala	753

1	2	3	4	5
		Patiala District—CONTD.		
333.	Shri Bachiter Singh	Master, Government Middle School, Tripri Town	Patiala	757
334.	Shri Kasturi Lal	Teacher, Government Primary School	Bhatari	700
335.	Shri Jagan Nath	Teacher, Govenment Middle School	Shamsher Pur	611
336.	Shri Kasturi Lal	Teacher, Government Primary School	Rupalheri	600
337.	Shri Harnam Singh	Teacher, Government Primary School	Mahodian	590
338.	Shri Giya Singh	Teacher, Government Primary School	Narali	589
339.	Shrimati Vidya Wati	Teacher, Government Primary School	Patiala	550
340.	Shrimati Jagdish Kaur	Teacher, Government Primary School	Do	550
341.	Shrimati Sheela Singla	Teacher, Government Primary School	Do	550
342.	Shrimati Santosh Walia	Teacher, Government Primary School	Do	550
343.	Shri Balwant Singh	Teacher, Government Primary School	Nahanu	533
344.	Shri Baldev Singh	Teacher, Government Primary School	Chail	511
345.	Shri Pashaura Singh	Teacher, Government High School	Rajpura	503
346.	Shri Darshan Singh	Teacher, Government Primary School	Majhal	504
347.	Shri Hari Ram	Teacher, Government Primary School	Kawalipur	501
348.	Shri Dev Raj	Teacher, Government High School	Rajpura	504
349.	Shrimati Sudarshan Puri	Teacher, Government Middle School	Sirhind City	501
350.	Shri Gurdev Singh	Teacher, Government Middle School	Ditto	501
351.	Shrimati Tripta Sud	Teacher, Government Middle School	Ditto	501
352.	Shri Gobind Ram	Teacher, Government Primary School	Thuiha	722
353.	Shri Jaimal Singh	Teacher, Government Primary School	Bathan Nirva	550

[Minister for Education]

1	2	3	4	5
		Patiala District—CONTD.		
		COMMENDATION CERTIFICATE		
354.	Shri Ranjit Singh	Teacher, Government Primary School	Katla Fazal	Denated full month's salary till emergency
355.	Bibi Ravinder Kaur	Teacher, Government Middle School	Patiala Cantt.	Donated full month's salary
356.	Miss Indra Devi Sharma	Teacher, Government Girls High School	Rajpura	Ditto
357.	Miss Bhara Vati	Teacher, Government Girls High School	Do	Ditto
358.	Shri Nand Kishore Rattan	Principal, S.F.S.E. Higher Secondary School	Patiala	Ditto
359.	Shri Ayudhia Parshad Sharma	Headmaster, Government High School	Nandpur Kesho	Ditto
360.	Miss Surinderjit Brar	Lecturer	Patiala	Ditto
361.	Shri Mohinder Singh	Master, Government High School	Nandpur Kesho	Ditto
362.	Shri A. C. Sahar	Master, Government High School	Ditto	Ditto
363.	Shri Gurcharan Singh	Master, Government High School	Ditto	Ditto
364.	Shri Baldev Sahai	Master, S.D.S E. Higher Secondary School	Patiala	Ditto
365.	Shrimati Rabinder Kaur	Mistress, Government Middle School	Patiala Cantt.	Ditto
366.	Bibi Prem Singh	Mistress, Government M.P. Higher Secondary School	Patiala	Ditto
367.	Shri Hari Mohan	Master, S.D.S.E. Higher Secondary School	Do	Ditto
368.	Shrimati Surjit Kaur	Mistress, Government Institute of Oriental Language	Do	Ditto
369.	Shrimati Krishanwanti	Teacher, Government Primary School	Baura Kalan	Ditto
370.	Shrimati Swarn Shali	Teacher, Government Girls High School	Rajpura	Ditto

1	2	3	4	5
		Patiala District—CONTD.		
371.	Shri Banarsi Dass	Teacher, Government High School	Nandpur Kesho	Donated full month's salary
372.	Shri Kishori Lal	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
373.	Shri Harbans Singh	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
374.	Shri Pritam Singh	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
375.	Shri Budh Raj	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
376.	Shri Nirmal Singh	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
377.	Shri Jugal Kishore	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
378.	Shrimati Ravinder Kaur	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
379.	Shri Vidya Parkash	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
380.	Shri Jaswinder Singh	Teacher, Government High School	Ditto	Ditto
381.	Shri Gurdial Singh	Teacher, Government Higher Secondary School	Ditto	Ditto
382.	Shri Gurcharan Singh	Teacher, S.D.S.E. Higher Secondary School	Patiala	Ditto
383.	Shrimati Mohinder Kaur	Teacher, Government Middle School	Taruah	Ditto
384.	Shrimati Savitri Devi	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Sirhind Mandi	Ditto
385.	Shrimati Parbati Devi	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	Ditto
386.	Miss Sur Parbha	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	Ditto
387.	Smt. Bachni Devi	Teacher, Government Girls Higher Secondary School	Ditto	Ditto
388.	Shri Shakti Parshad	Teacher, Government Primary School	Badali Ala Simli	Ditto
389.	Shri Baldev Singh	Teacher, Government Primary School	Jhampur	Ditto

[Minister for Education]

1	2	3	4	5
390.	Shri Tarawati	Teacher, Government Middle School, N. P. H. C.	Patiala	Donated full month's salary
391.	Shrimati Gurcharan Kaur	Teacher, Government Middle School	Tripri Town, Patiala	Ditto
392.	Shri Sadhu Ram Shastri	Government V. G. Higher Secondary School	Do	Ditto
393.	Shrimati Harbans Kaur	Teacher, Government V. G. Higher Secondary School	Do	Ditto
394.	Shrimati Bhagwanti Devi	Teacher, Government Higher Secondary School	Do	Ditto
395.	Shrimati Prita Shani	Teacher, Government V. G. Higher Secondary School	Do	Ditto
		SANGRUR DISTRICT		
		AWARD OF SHIELDS		
		GOLD MEDAL		
396.	Shri Sukha Singh	Principal, Government Higher Secondary School	Sangrur	11,492
397.	Shrimati E. Singh	Principal, Government Higher Secondary School	Do	11,361
398.	Shri O. P. Puri	Lecturer, Government Higher Secondary School	Do	1,502
399.	Shri O. P. Jindal	Master, Government Higher Secondary School	Do	1,596
400.	Shri Prem Chand	Teacher, Government Higher Secondary School	Do	1,004
401.	Shri Kedar Nath	Headmaster, Government High School	Sherpur	7,505
		SILVER MEDAL		
402.	Shri S. N. Rao	Principal, Government College	Jind	8,103
403.	Shri Harbans Singh	Teacher, Government Primary School	Haiyao	811
404.	Shri Moda Singh	Teacher, Government Primary School	Nawan Gaon	771
405.	Shri Mali Rai	Master, Government Higher Secondary School	Sangrur	1,003

1	2	3	4	5
406.	Shri Nirmal Singh	Master, Government Higher Secondary School	Sangrur	1,002
407.	Shrimati Shakuntala Moudgil	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Do	1,001
408.	Shri Avinash Chander	Lecturer, Government Higher Secondary School	Do	1,004
		BRONZE MEDAL		
409.	Sh. Om Parkash Batra	Principal, Government Higher Secondary School	Jind	6,277
410.	Shri Janardhan Sharma	Principal Government Higher Secondary School	Safidon	5,171
411.	Miss K. Anand	Headmistress, Government High School	Dhuri	3,509
412.	Shri Ved Parkash	Headmaster, Government High School	Malerkotla	4,113
413.	Shri Narain Singh	Headmaster, Government High School	Jind	4,500
414.	Shri Sada Nand	Headmaster, Government High School	Barnala	3,502
415.	Shri P. K. Ulfat	Master, Government Higher Secondary School	Sangrur	755
416.	Shri Kulwant Rai	Teacher, Government Primary School	Chanan	510
417.	Shri Krishan Kumar	Teacher, Government Primary School	Mangwal	501
		COMMENDATION CERTIFICATE		
418.	Miss E. Singh	Headmistress, Government Girls Higher Secondary School	Sangrur	Donated full month's salary
419.	Shri Mali Ram	Master, Government Girls Higher Secondary School	Do	Ditto
420.	Shri O. P. Jindal	Master, Government Girls Higher Secondary School	Do	Ditto
421.	Miss Nirmal Singal	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Do	Ditto
422.	Miss Shakuntla Moudgil	Mistress, Government Girls Higher Secondary School	Do	Ditto
423.	Shri Sukhdev Singh	Teacher, Government Primary School	Ranike	Ditto

श्री राम प्यारा : क्या ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो लिस्ट टेबल पर रखी गई है उस में अंबाला डविज़न के जहां 6 स्कूल हैं रुपया ज्यादा इक्ट्ठा हुआ है और जालंधर सरकल में जहां पर 9 स्कूल हैं रुपया कम इक्टठा हुआ है तो क्या वजह है जालंधर सरकल में जहां ज्यादा सकूलें हैं कम रुपया इक्ट्ठाहुआ है?

मंत्री : जनाबे आली जहां तक अंबाला सर्कल की बात है वहां पर लोगों की पेइन्ग कपैसिटी ज्यादा है। ज़मीनें वगैरा आबाद हुई हैं they are in a position to pay और मेरी पर्सनल फीलिंग यह है कि they are more generous than the people of this side.

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि 1st, 2nd और 3rd नंबर जो दिया जाता है वह फंडज़ के देने की मिकदार के मुताबिक दिया जाता है या टीचर्ज़ की गिनती को सामने रख कर दिया जाता है।

मंत्री : इसमें टीचर्ज की गिनती का सवाल नहीं है, जिस ने ज्यादा रुपया दिया ही उसे 1st नंबर पर उस से कम देने वाले को 2nd नंबर पर इसी तरह से last में 3rd नंबर पर आता है।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो 9 कम्पलेंट्स मिलीं जिस में 2 बेसलैस हैं यह कौन कौन सी है और इस की इन्क्वायरी कौन कर रहा है।

Minister for Education : Sir, I have stated more than once in this august House that it will not be in public interest to disclose the nature of the complaints unless they have been fully gone into and substantiated.

कामरेड राम प्यारा : मैंने सप्लीमैंटरी बड़ा कलीयर किया है कि जो कंपलेंट्स आई हैं वह कौनसी हैं और इस की इनवैस्टीगेशन कौन कर रहा है। जो बेसलैस बताई गईं वह क्या हैं।

Minister for Education : Sir, I am sorry, I am not in a position to tell the names at the moment. I will, however, let the hon. Member know if he is very anxious about it.

चौधरी अमर सिंह : मैं वज़ीर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट वाइज़ स्कूलों को ग्रुप किया है या जिन्हों ने ज्यादा इमदाद की है। ज्यादा इमदाद करने वालों का क्या अवार्ड दिया जायेगा ?

मंत्री : मैंने लिस्टस दी हैं जिन में बताया गया है कि इन को मैड्ल्ज़ दिये गये हैं जिन्हों ने ज्यादा इमदाद की है उन के सकूल अप ग्रेड किये जायेंगे।

श्री जगन्नाथ : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि टीचर्ज़ डिफैंस फंड की कुलैकशन भी करते हैं और अपनी डियूटीज़ भी देते हैं, इस के साथ उनकी डियूटी पंजाब के चूहे मारने और टिडियां मारने की भी है। आखिर इस एकस्ट्रा सरविस का कुछ पे किया जाता है या मुफ्त में काम ही कराया जाता है ?

Minister : Sir, I don't think that the question put by the hon. Member is worthy of any attention.

कामरेड राम प्यारा : कमपलेंट्स की इन्कवायरी के लिये कौन सा आफीसर मुकर्रर किया गया है ?

मंत्री : इसके लिये मैं ने लिखा है कि वह आफीसर लगाया जाये जिस की वोनाफाईडीज बीयांड डाऊब्ट हों ।

कामरेड राम प्यारा : यह जो मैडल दिये गये बताएं गए हैं यह किस फंड से दिये गये हैं ?

मंत्री : और तो कुछ नहीं कहना मगर मैं इतना कह सकता हूं कि यह डिफैंस फंड में से नहीं खर्च किया गया ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वजीर साहिब उस आफीसर का नाम बतायेंगे जो इन्कवायरी कर रहा है और इस की सिलैक्शन का आधार क्या है ?

शिक्षा मंत्री : जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया वह आफीसर लगाया जायेगा। जिसकी इनटैग्रटी वियांड डाऊट है । बहुत सी जुदा जुदा इनकवायरीज हैं इनके नाम के मुतालिक मैं आफ हैंड कुछ नहीं कह सकता ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਬੇਸਲੈਸ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

HOSPITALS/DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS IN THE STATE

***8978. Shri Balramji Dass Tandon** : (Put by Shri Fateh Chand viz on his behalf) : Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) the total number of Hospitals/Dispensaries in the State which are at present without doctors, district-wise ;

(b) the total number of Doctors required by the Government at present ;

(c) the number of students admitted every year to the M. B. B. S. and L. S. M. F. classes separately in the State, College-wise ?

Mrs. Om Prabha Jain : (a), (b) & (c) The information is laid on the Table of the House.

[Minister for Health]

STATEMENT

(a)

Serial No.	Name of the District	Number of Hospitals/ Dispensaries etc. which are without doctors
1.	Ambala	4
2.	Amritsar	6
3.	Bhatinda	6
4.	Farozepore	11
5.	Gurdaspur	4
6.	Gurgaon	12
7.	Hissar	14
8.	Hoshiarpur	3
9.	Jullundur	1
10.	Karnal	7
11.	Kulu	3
12.	Kangra	14
13.	Kapurthala	4
14.	Lahaul & Spiti	3
15.	Ludhiana	3
16.	Mohindergarh	6
17.	Patiala	10
18.	Rohtak	6
19.	Sangrur	7
20.	Simla	2
	Total	126

(b) 674 doctors (PCMS=II=500+174 Non-Gazetted) are required for filling up the various vacancies in the Punjab Health Department.

Number of Students admitted in MBBS Classes

(c) (i)

1.	Medical College, Amritsar	150
2.	Medical College, Patiala	150
3.	Medical College, Rohtak	100
4.	Christian Medical College, Ludhiana	50
5.	Daya Nand Medical College, Ludhiana	50

(ii) Admission to L.S.M.F. class has since been stopped as the Arya Medical School, Ludhiana, the only institution in the State where L.S.M.F. students were trained has been upgraded to the status of a Medical College and named as Daya Nand Medical College, Ludhiana.

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब मैं बस से लेट था ? पहला सवाल पुट नहीं कर सका । अगर अजाज़त हो तो अब पुट कर दूं ।

Mr. Speaker: That cannot be allowed.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਟੇਪ ਹੁਣ ਤਕ ਉਠਾਏ ਹਨ।

मंत्री : रूरल डिसपैंसरीज़ में सीनियर डिसपैंसरज़ को काम चलाने के लिये लगाया जा रहा है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

मंत्री: इस कमी को पूरा करने के लिये बहुत स्टैपस उठाये गये हैं जोकि इस रिपलाई में दर्ज हैं । रूरल ऐरिया में काम करने वाले डाक्टरों को रूरल अलाउंस दिया गया है । गवर्नमेंट सरविस में आने वाले डाक्टरों को एडवांस इनकरीमैंट दी जाती है । मैडीकल सटूडैंटस को जब देहातों में काम पर लगाया जाता है तो इसके लिये भी पे किया जाता है । डिटेल टेबल पर ले कर दी है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਇਕਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ......

Mr. Speaker : Order please, Not during the question hour.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਇਕ ਵਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

मंत्री : यह भी पिछले दो साल से तरीका बंद है मगर अभी इसका असर हमारे पर नहीं पड़ सकता ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ M.B.B.S. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

मंत्री: हमारे सटूडैंटस को फेसिलिटीज़ देने के लिये मैं ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है अभी इस के बारे जो फैसला हुआ उस का इंतज़ार किया जा रहा है ।

पंडित भागीरथ लाल : पठानकोट में हस्पतालों की बहुत कमी है । जो है उस में बहुत कम जगह है मरीज़ ठहर नहीं सकते। यह लोग दूर दराज़ से आते हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री इसकी तरफ ध्यान देंगे ।

मंत्री : जहां तक मुझे मालूम है पठानकोट में एक दो डाक्टर ज़रूर हैं । एक म्युनिसीपल हस्पताल है ।

चौधरी अमर सिंह: क्या हैलथ मनिस्टर साहिबा बतायेंगी कि जो डाक्टर पंजाब के फारन चले जाते हैं जिन का पंजाब के दिहातों को फायदा होना चाहिये था उसके बारे में आप की क्या राये है ।

स्वास्थ्य मंत्री : इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने काफी रेस्ट्रिशन्ज लगाई थीं और डाक्टरों का बाहर जाना बंद हो गया था । अब यहां भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन की गई है कि जिनकी काफी सरविस हो गई है और जिन्हों ने बहुत ज्यादा कमैंडेबल काम किया हो उनको बाहर भेजते हैं, नहीं तो डिस्करेज ही करते हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗਰੇਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਏਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ।

मंत्री: सैंट्रल गवर्नमेंट के ग्रेड हम से ज्यादा हैं लेकिन दूसरी स्टेटस की निसबत पंजाब गवर्नमेंट के ग्रेड ज्यादा हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਥੇ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ ।

Minister : This matter is under our consideration.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।

मंत्री : मेरे पास ऐसी कोई इनफर्मेशन नहीं है । आज अखबार में आया है । मेरे पास इन राईटिंग ऐसा नहीं आया है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ?

मंत्री : उन्होंने अपनी कुछ डीमांडज़ रखी हैं। उन डीमांडज़ के सिलसिले में उन्होंने यह ब्लैक बैजिज़ वेयर करने शुरू किए हैं।

श्री प्रकाश अग्निहोत्री : जो डिमांडज़ डाक्टरों ने रखी हैं क्या सरकार ने उन पर विचार किया है? और उन की कौन कौन सी डिमांडज़ को मान लिया है ?

मंत्री : उनकी 5 डिमांड्ज़ हैं। पहली यह कि उनका नान-प्रेक्टिसिंग अलाउंस बढ़ाया जाए। दूसरी यह कि उन के पे स्केल रिवाईज किए जाएं। तीसरी यह कि डाइरेकटोरेट की पोस्टें ज्यादा की जाएं। चौथी यह कि उनकी कन्फर्मेशन्ज की जाएं। पांचवीं उन की कैजुअल लीव के बारे में है। कन्फर्मेशन और कैजुअल लीव का मामला अंडर एक्टिव कंसिड्रेशन है और बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। दूसरी डिमांडज के बारे में यह है कि ओवर आल स्टेट के ग्रेडज पर रीपकर्शन्ज होगी। दूसरे भी कहेंगे कि हमारी पे स्केल बढ़ाई जाएं।

श्री फतेह चन्द विज : पहले मंत्री साहिबा ने कहा कि आज अखबारों में पड़ा है और फिर 5 डिमांडज गिन कर सुनाई हैं। यह कैसे पता लग गया।

मंत्री : पहला जवाब मैंने उस सवाल का दिया था जो यह था कि उन्होंने नोटिस दिया है अपना काम बन्द करने का या स्ट्राईक करने का। दूसरी बात यह थी कि मैंने उनकी डिमांडज बताई हैं। बोथ दीज़ थिंग्ज़ आर सैपेरेट।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TRANSFER OF PATWARIS IN PATWAR CIRCLE, SHABAZPUR, TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

3367. Babu Bachan Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of the revenue patwaris who remained posted in the Patwar Circle of Shabazpur, tehsil Patti, district Amritsar between 1st January, 1953 and 31st December, 1964 together with the date of their posting in the said circle in each case;

(b) the dates of transfers of the said Patwaris from the above mentioned circles in each case;

( ) whether at the time of the transfers mentioned in part (b) above any roznamcha wakiati were handed over by the out going Patwaris to their successors in addition to other revenue records, if so, the list of such roznamchas ;

[Babu Bachan Singh]

(d) whether any roznamchas wakiati were handed over by the consolidation patwaris, who remained posted in the various villages of the said patwar circle during the consolidation of holdings operations between 1st January, 1952 and 31st December 1959, if so, the list of such rosnamchas which were handed over by them to the revenue patwaris of their circles on the completion of the consolidation operations.

(e) whether any complaints were made to the Tehsildar Tarn Taran by Shri Sajjan Singh Margindpuri about certain missing roznamchas wakiati of the above—mentiond circle between 1st June, 1965 and 31st January, 1966, if so, when ;

(f) whether any enquiry was ordered into the said complaints, if so, the result of the enquiry and the action taken in the matter ?

Sardar Harinder Singh Major ;

(a) A list is attached. (Statement 'A')

(b) As per list attached. (Statement 'A')

(c) Yes. The list is enclosed. (Statement 'B')

(d) Yes. The list is attached. (Statement 'C')

(e) Yes. During the months of August and November, 1965.

(f) An enquiry is in progress.

STATEMENT 'A'

Sr. No.	Name of the Patwari	Date of posting	Date of transfer
	S.Shri		
1.	Sodagar Singh, Patwari	25th December, 1948	20th April, 1955
2.	Kishori Lal ,,	21st April, 1955	6th September, 1955
3	Nahar Singh ,,	7th September, 1955	2nd April, 1956
4.	Dalip Singh ,,	3rd April. 1956	25th July, 1956
5.	Ajaib Singh ,,	26th July, 1956	30th September, 1956
6.	Nahar Singh ,,	1st October, 1956	31st October, 1956
7.	Jagir Singh ,,	12th June, 1957	12th December, 1957
8.	Om Parkash ,,	18th July. 1958	4th November, 1958
9.	Kundan Lal ,,	5th November, 1958	19th August, 1959
10.	Krishan Muni ,,	20th August, 1959	1st June. 1960
11.	Ram Krishan ,,	2nd June, 1960	15th July. 1960
12.	Virsa Singh ,,	16th J1th July, 1960	13st January, 1963
13.	Janak Raj ,,	14th January, 1963	Working at present.
			Circle Shahbaspur remained vacant from 1st November 1956 to 11th June, 1957 and 13th December, 1957 to 17th July, 1958. During the latter period the Patwari joined the *Strike*.

STATEMENT B

List of Roznamchas Wakiati handed over by Consolidation Patwari who remained posted in the circle during 1st January, 1953 and 31st December, 1964.

Sr. No.	Name of the Patwari	Roznamchas Wakiati handed over
	S/Shri	
1.	Saudagar Singh	21 Roznamcha, Waquati. Prior to 1948. Current 7 (1948-54-55)
2.	Kishori Lal	Roznamcha Wakiati 1926-27 to 1944-45 and 1946-49-50, 50-51 to 53-54. 1948-49, 1946-47 and current.
3.	Nahar Singh	1955-56.
4.	Dalip Singh	1948-49, 1946-47 and current 1955-56.
5.	Ajaib Singh	Nil.
6.	Nahar Singh	Nil.
7.	Jagir Singh	Nil.
8.	Om Parkash	Current 1958-59. Previous one
9.	Kundan Singh	Current 1958-59
10.	Krishan Muni	1951-52, 1958-59, 47-48, current 1959-60
11.	Ram Krishan	1947-48, 1951-52, 58-59 and current 1959-60 *Previous—17*
12.	Shri Virsa Singh	1947-48, 1948-49, 1949-50, 50 51, 51-52, 52-53, 54-55, 55-56 56-57, 58-59 59-60 60-61. 61-62, 62-63 of Circle Shahbazpur. 1956-57, 1957-58 of Circle Kamalpur Consolidation. 1954-55 of Circle Miania Consolidation.

STATEMENTS C

(d) **List of Roznamchas Wakiati handed over during the Consolidation Operations between 1st January, 1952 to 31st December, 1959.**

1954-55 of Circle Maini

1956-57 and 1957-58 Kamalpur.

ARREARS OF INSPECTORS POSTED UNDER THE EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D., B. and R., JULLUNDUR.

3378. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the arrears of salary of some of the Inspectors posted under the Executive Engineer, P.W.D., B. and R., Jullundur, for the months of September, October and November, 1963, have not been paid so far; if so, the reasons for that together with the number and names of such Inspectors whose arrears have not been paid;

(b) whether these Inspectors are still working under the Executive Engineer, P.W.D. B. and R., Jullundur, or have been transferred somewhere, if transferred, when and where;

(c) whether any representation from these Inspectors as in (a) has been received by the Department/Minister for the early payment of arrears of salaries from 1st October, 1963 to date if so, when, by whom, together with the action, if any, taken on the representation, if not taken, the reasons for that together with the approximate date by which these arrears are expected to be finalised/cleared/paid ?

Chaudhri Ranbir Singh :

(a) Yes—In case of Shri Salig Ram, Work Inspector—he has not been allowed pay from 6th September, 1963 to 22nd November, 1963 because he did not perform any duty during this period;

(b) Shri Salig Ram is still working under the Executive Engineer. Jullundur Provincial Division ;

(c) Yes—by Shri Alakh Ram, father of Shri Salig Ram. The matter is being considered with a view to finalise this case, and, if necessary, pay the dues.

ADJOURNMENT MOTION

3.00 p.m.

श्री अध्यक्ष : आज तीन एजर्नमैंट मोशन्ज हैं । एक कामरेड शमशेर सिंह जोश की । दूसरी कामरेड भौरा और कामरेड गुरबख्श सिंह की और तीसरी श्री जगन्नाथ की । वह एक ही मामला से रिलेट करती हैं कि ला ऐंड आर्डर की जो सिचुएशन आज कल चल रही है । हमारी कन्वैन्शन यह है कि हम बजट सैशन में एडजर्नमैंट मोशन्ज टेक अप नहीं करते । एक टैकनीकल फला भी है कि एक्सप्लेनेटरी मैमोरेंडम नहीं दिया और मिनिस्टर कनसर्नड को कापी नहीं भेजी । लेकिन मैं यह समझता हुं कि यह मामला इंपार्टेंट है । यह मोशन्ज आउट आफ आर्डर हैं । मैं आज या कल इस मामला को डिस्कस करने के लिए 2 घंटे अलाऊ करूंगा । (Today three notices of ajournment motions have been received. One is from Comrade Shamsher Singh Josh, second one is

from Comrade Bhaura and Gurbaksh Singh and the third motion is from Shri Jagan Nath, All these motions are identical and relate to the present law and order situation in the State. The convention of this House has been that we do not take up adjournment motions during the Budget Session. Besides, there is a technical law that the explanatory memoranda have not been attached to these motions and copies thereof have also not been sent to Minister concerned. However, I feel that this matter is very important. These motions are out of order. I will allow two hours discussion on this subject either today or tomorrow.

श्री जगन्नाथ : हालात खराब हो रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : मेरे कहने के बाद भी आप कहे जाएंगे। (Will the hon. Member go on speaking even after my ruling ?)

श्री जगन्नाथ : हालात ऐसे खराब हो रहे हैं कि लोग विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, मैं इस पे डिस्कशन की इजाज़त आज ही दे देता 2 घंटे के लिए, लेकिन आज गवर्नर साहिब रिटायर हो रहे हैं, उनका सैंड आफ हो रहा है साढ़े पांच बजे। (I would have allowed two hours discussion even today but since the Governor is retiring and he is being sent off today I am unable to allot time).

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मैंने भी एक एडजर्नमेंट मोशन दी है कि अमृतसर में ज़ुल्मो तशदद हो रहा है——(विघन)

CALL ATTENTION NOTICES

श्री अध्यक्ष : अब काल अटैंशन होंगी। सरदार कुलबीर सिंह। (Now we will take up call attention notices. There is one from Sardar Kulbir Singh).

(SERIAL NO. 52)

Sardar Kulbir Singh. Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact, namely, that Gidderbaha Municipality was superseded by the Government on the ground that Gidderbaha Municipal Committee had totally failed rather refused to remove the leather tenneries from their present location in spite of best pursuation.

One Shri Harnam Singh, Naib Tahsildar, is appointed Administrator since 11th January, 1966. As is evident that Committee is superseded on the ground of not removing leather tenneries. Now present Administrator intentionally is not doing his duty but is out and out to help the leather tenneries people.

[Sardar Kulbir Singh]

Attention of the Government is drawn towards this serious negligence on the part of the Government tenneries at once be removed from the present place.

Mr. Speaker : This is admitted.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਢਦੇ ਨੇ । ਕੀ ਉਹ ਟੈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ?

(SERIAL NO. 53)

Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the indiscriminate policy followed by the State Government with regard to the posting/transfers of Gram Sewkas/Mukh Sewkas by issuing Memo No. 16023-5 ECDII-65/4082, dated the 17th February, 1966. According to this order, the Gram Sewkas/Mukh Sewkas have been debarred from being posted in their Home Tehsils/Districts, while all other lady Government employees have this privilege of being posted in their Home Towns even. This exception has created heart-burning and resentment amongst these ladies. The Government have not taken into consideration for their security protection and some occasions of serious illness if they are at a distant place, while issuing this order. Therefore, the policy with regard to the posting/transfers of Gram Sewkas/Mukh Sewkas should be the same as in the case of other lady employees.

Mr. Speaker. This is admitted.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ?

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : As required under Rule 289 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. I have to inform the House that Shri Balramji Das Tandon, M.L.A. was arrested and detained at Amritsar on the 12th of March, 1966 under Rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules, 1962, and is, at present, lodged in District Jail, Amritsar.

HOURS OF SITTING

Mr. Speaker : Before we pass on to the next item i.e. "Resumption of general discussion on the Budget" if the House agree, we may today adjourn at 5.00 P.M. instead of 6.30 P.M., because we have to give a send off to the retiring Governor.

(*Interruption by Sardar Kulbir Singh*)

Mr. Speaker : We will look into it. Let us now resume discussion on the Budget.

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1966-67

(*Resumption of Discussion*)

(*Not concluded*)

Mr. Speaker: Now the House will resume General Discussion of the Budget. When the House adjourned on the 11th March, Kanwar Ram Pal Singh was on his legs. He may resums his speech.

कंवर राम पाल सिंह (पुंडरी): स्पीकर साहिब, मैं बजट पर बोलता हुआ एगरीकल्चर टापिक पर आया था कि हाउस एडजर्न हो गया था । मैं यह कह रहा था कि किसी स्टेट या मुलक की तरक्की एग्रीकल्चर पर मेनली बेस करती है । खास कर हमारा मुलक एग्रीकल्चरल कंटरी के नाम से मशहूर है । हमारी बेसिक प्राब्लम्ज़ मेनली ऐसी हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर की डीवैल्पमेंट नहीं करेंगे तो वह कभी भी सालव नहीं हो सकेंगी ।

मिसाल के तौर पर आज देश के सामने फूड प्राब्लम का मसला मुंह फाड़े खड़ा है और उसका हल अभी नजर नहीं आ रहा है । हमें दूसरे देशों की तरफ देखना है कि कब वह हमारी इमदाद करें और कब हम उन से अनाज ले कर लोगों को भूखमरी से बचा सकें । हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री शास्त्री जी ने इस मसला की तरफ बहुत ध्यान दिया था और उन्हों ने एक नाअरा भी दिया था कि जय जवान जय किसान लेकिन यह नाअरा ही रह गया है किसान की प्राब्लम की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा । पलैनिंग तो बहुत होती है सकीमें अच्छी अच्छी बनती हैं लेकिन उनकी इम्पलीमैंटेशन बहुत सलो चलती है । अभी पिछले दिनों पलैनिंग मिनिस्टर साहिब ने ज़िलों में मीटिंगज़ करके सारा जायज़ा लिया था कि पलैनिंग को किस तरह इम्पलीमैंट किया जा रहा है । उनके नोटिस में यह चीज़ लाई गई थी कि इन्सैक्टीसाइड और पैस्टी साइड के लिए जो रुपया ज़िलों को जाता है वह ठीक ढंग से खर्च नहीं किया जाता है । इस में एक और दिक्कत है ... ...

श्री अध्यक्ष : आप माइक से ज़रा मुंह दूर करके बोलें आवाज़ गूंज रही है । (The hon. Member should more a bit away from the mike. The sound is resounding.)

कंवर राम पाल सिंह : इन्सैक्टीसाइडज़ और पैस्टीसाइडज़ के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस में एक दिक्कत यह है कि यह कई महकमों की मारफत किसानों को दिया जाता है जिस से भोले भाले किसानों को यह पता नहीं चलता कि वह किस महकमे के पास इस मतलब के लिए जाएं । कुछ कोआप्रेटव डिपार्टमैंट की मारफत, कुछ बलाक समिति की और कुछ ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की मारफत दिया जाता है । इस बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो इमदाद इस ढंग से दी जाती है वह एक अफसर के कंट्रोल में रखी जाए ताकि किसान को पता हो कि कहां इस काम के लिए जाना है ।

[कंवर रामपाल सिंह]

और सीधा वहां से इमदाद ले सके। एग्रीकल्चरल डिवैल्पमैंट के लिए कई एक मसलों की तरफ पानी खाद, अच्छे बीज, एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंट्स की सपलाई की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइस भी उसे उसकी उपज की पूरी मिलनी चाहिए। यह बेसिक चीजें हैं जिनसे ज़रायत की तरक्की हो सकती है। पानी के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हर सैशन में इस के बारे में आवाज़ उठाई जाती है और कहा जाता है कि पानी की इतनी कमी है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नहरी पानी पूरा नहीं दिया जा सकता तो फिर ट्यूबवैल्ज़ के लिए लोगों को लोन्ज़ दिए जाएं, बिजली के लिए कुनैक्शन दिए जाएं और इस तरह नहरी पानी की कमी को पूरा किया जाए। इस से सेम का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन आज यह हालात है कि लोन्ज़ की बात एक तरफ रखें जो लोग खुद आगे आते हैं और ट्यूबवैल्ज़ लगाते हैं उन्हें ट्यूबवैलज़ चलाने के लिए कुनैक्शन नहीं मिलते। पहले यह हालत थी कि बीस तीस मील अपने अपने इन्ट्रैस्ट के मुताबक बिजली लाइन खेंच ली जाती है थी और बीच के गांव रह जाते रहे। अब जब शोर मचा कि हरियाणा-प्रांत में कुनैक्शन की इतनी कमी है तो उनके बारे में यह डीसीज़न लिया गया कि लाइन के दो मील के फासले तक ही कुनैक्शन्ज़ दिए जाएंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डीसीज़न से हरियाणा प्रांत को फायदा नहीं हो सकता क्योंकि वहां कोई लाइन ही नहीं तो कुनैक्शन कहां से मिल सकता है। इस लिए, मैं यह कहता हूं कि इस की बजाए किया जाना चाहिए कि जिन अलाकों में लैंड फरटाइल है लेकिन पानी की कमी है वहां हर हालत में कुनैक्शन्ज़ दिए जाएं ताकि देश का अन्न संकट दूर हो सके। इस से अन्न संकट ही दूर नहीं होगा बल्कि हमारी फारन ऐक्सचेंज जिस की आज हमें भारी ज़रूरत है और जो अब बाहर से फूड लाने के लिए खर्च हो रही है बच सकती है और दूसरों के सामने जो हमें अनाज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं उन से भी निजात मिलती है। किसान के लिए एक और बड़ी दिक्कत है। लैंड मारगेज बैंक बना तो किसानों की सहूलित के लिए है लेकिन इनका प्रोसीजर इतना लम्बा चौड़ा है कि तीन चार साल तक केसिज़ पैंडिंग पड़े रहते हैं। वहां जाते हैं तो कहते हैं फलां कागज़ लाओ और दूसरी दफा कागज़ ले कर जाते हैं तो कहते हैं अब यह कागज़ लाओ। किसान को जितना लोन मिलता है उसका दसवां हिस्सा तो इन चक्करों में ही खर्च हो जाता है। इस प्रोसीजर को जल्दी सिम्पलीफाई किया जाएं ताकि किसान को दिक्कत न हो (घंटी) सरविस स्टेशन और इन्डस्टरियल कारपोरेशन का ज़िकर किया गया है कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। यह बात बहुत दिनों से सुन रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन् हो गई है तो गवर्नमैंट उसके बारे में डैफिनिट स्टेटमैंट दे कि कब तक यह अपना काम शुरू कर देगी।

मै एक बात ऐजुकेशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। अभी एक सवाल के जवाब में वज़ीर साहिब ने एशुरैंस दिलाई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक

तरफ तो टीचर्ज़ की पोसटिंग का मसला है दूसरी तरफ सकूलों में स्टाफ पूरा नहीं है और बच्चों की तालीम का नुक़सान हो रहा है। जो सकूल अपग्रेड किए गए हैं वह कागजों पर ही हुए हैं लेकिन जो बच्चे वहां दाखिल हैं स्टाफ न होने की वजह से उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। इस की तरफ ध्यान दिया जाए। ऐग्रीकल्चरल नालज के बारे में पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि करनाल की जनता से अपनी हिम्मत से पैसा इकट्ठा करके वहां एक ऐग्रीकल्चरल कालिज ग्राम कोल में बुनियाद रखी जिसमें इस साल ऐडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्स्टी के अंडर हुआ लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो ex gratia grant या ग्रांट इन एड कालिजों को दी जाती है उसका इस कालिज को देने के लिए इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। मुझे हैरानी इस बात की है कि कई एक कालिज जो पंजाबी रिजन में हैं उन्हें तो बहुत ग्रांट दी गई है लेकिन हिन्दी रिजन को इगनोर किया गया है। मुझे उन से हसद नहीं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उनको ग्रांट दी जाती है तो हरियाणा के लोगों ने अपनी हिम्मत से जो कालिज बनाया है उसके लिए भी लोगों की होसला अफजाई करने के लिए इस बजट में कोई न कोई प्राविज़न किया जाए जिस से वहां की जनता ऐग्रीकल्चरल नालज हासिल करके देश के मुफीद साबित हो सके। अब मैं एक बात सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं मेरे अलाके में पिछले पांच साल में एक इंच सड़क भी नहीं बनाई गई है। वहां चंद एक सड़कें तो बहुत ही जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि एक सड़क पुंडरी से पानीपत बरास्ता हाबड़ी जाती है। अगर यह बन जाए तो यह 10 मील के एरिया को कवर कर सकती है और लोग आराम से सफर कर सकते हैं और अपनी पैदावार मंडी में ला सकते हैं।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां की सड़कों की हालत सुधारने के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा रुपया रखा जाए। वैसे सरकार ने रोड्ज़ की हालत सुधारने के लिए 25%वाली स्कीमें तैयार की हैं। मैं समझता हूं कि उन स्कीमों के लागू होने से मेरे इलाके की डिवैल्पमैंट हो सकेगी।

स्पीकर साहिब, मैं ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में भी कुछ हाऊस में जिक्र करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं लगा कि पंजाब रोडवेज़ डिपो अम्बाला और करनाल के लिए डैंज बसें ही रखी गई हैं ताकि वह रास्ते में बिगड़ी रहें। वहां पर जितनी बसें हैं, उन में से शायद की क्रमश: 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत बसें ऐसी होंगी कि जो अच्छी सर्विसएबल हों। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन डिपुओं में अच्छी बसें अलाट की जाएं ताकि मुसाफिरों को सफर करते वक्त दिक्कतें महसूस न हों।

स्पीकर साहिब, सरदार रणजीत सिंह नैनावालिया ने अपनी स्पीच करते हुए सरकार को पैप्सू की डिवैल्पमैंट न होने के कारण हाउस में अपने विचार प्रकट

[कंवर राम पाल सिंह]

किए । मैं उन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जहां पर सरकार ने बैकवर्ड एरिया या हरिजनों को अपलिफ्ट करने के लिए लाइनें भी निश्चित कीं लेकिन इस के बावजूद भी उन की हालतें सुधारने में सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की हालत भी सुधरी नहीं और न ही बैकवर्ड एरिया के रहने वालों की हालत सुधरी है । वह तो वैसे के वैसे ही नज़र आते हैं । इस लिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह ऐसी बातें करें तो उन की भूल होगी ।

(घंटी)

स्पीकर साहिब, पंजाब गवर्नमैंट के एम्पलाइज़ ने अपने पे स्केल्ज रीवाइज़ कराने के लिए काफी मांग की लेकिन सरकार ने उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । बजट के अन्दर कुछ के पे स्केल रीवाइज़ करने का ज़िक्र किया है। मैं उस की एक मिसाल हाउस में रखना चाहता हूं । वह मिसाल भी फिनांस डिपार्टमैंट के साथ सम्बन्ध रखती है । इन्होंने टैक्सेशन डिपार्टमैंट के बड़े अफसरों के पे स्केल्ज रीवाइज़ कर दिये हैं । यह पे स्केल्ज़ भी दूसरों की कास्ट पर रिवाइज़ किए गए हैं । सरकार ने इन के पे स्केल्ज़ रीवाइज़ करने के लिए इंस्पैक्टर्ज़ और और अन्य स्टाफ रीट्रेंच कर दिया और उन से सरकार को जो बचत हुई, वह रुपया इन के पे स्केल्ज़ रीवाईज़ करने में लगा दी । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार ने जो स्टाफ रीट्रेंच किया है उस की डिपार्टमेंट को कैंडीडेचर लिस्ट पर रखा जाए ताकि जब जब सरकार के पास डिमांड हो तो उस लिस्ट के हिसाब से वह नियुक्त किए जाएं ।

स्पीकर साहिब, चंडीगढ़ के अन्दर क्लास फोर के लिए मकान बनाए गए लेकिन आज कल वह क्वार्टेंज़ क्लास थ्री के एम्पलाइज़ को भी दिए हुए हैं । इन में कुछ मकानों के अन्दर वाटर मीटर लगे हुए हैं और कुछ के अन्दर वाटर मीटर नहीं हैं । जहां पर वाटर मीटर लगे हुए हैं, वहां से सरकार 5, 6 रुपए पानी के बिल वसूल करती है लेकिन दूसरी तरफ जहां पर वाटर मीटर नहीं लगे वहां पर उन्हें सिर्फ दो रुपए प्रति मास देना पड़ता है । इस तरह से कर्मचारियों के अन्दर एक जैसा सलूक न होने के कारण घृणा पैदा हो रही है। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को इस बारे में एक जैसी पालिसी इख्तियार करनी चाहिए । अगर सरकार सब के लिए वाटर मीटर लगाना चाहती तो वाटर मीटर लगा दे नहीं तो सब से दो रुपए के हिसाब से वाटर का बिल चार्ज करे ।

(घंटी)

मैं इन शब्दों के साथ अपनी स्पीच खत्म करता हूं । आप का धन्यावाद ।

श्री मोहन लाल (बटाला): स्पीकर साहिब, इस से पहले कि बजट पर अपने ख्यालात रखूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि सूबे के अन्दर आजकल के जो हालात

है, उन का कुछ जिक्र करूं। इस में कोई दो राए नही हैं और न हो सकती हैं कि सूबे के अन्दर बहुत दुखदायी हालात पैदा हुए हैं और ऐसे वाक्यात हो रहे हैं। जो कुछ अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना और कुछ दूसरे शहरों में हुआ, वह अफसोसनाक है। जैसा कि आप जानते हैं यह मूवमैंट नौजवान स्टूडैंट्स के हाथ में आज है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंजाब के मुताल्लिक जो फैसला किया, उसके बर्खलाफ जज़बात उभरे और कुछ ऐसे वाकियात हुए। कुछ भी हो, वर्किंग कमेटी के फैसले के बारे में अपने अपने विचार हो सकते हैं चाहे वह इंडीविज्युल हो या किसी पार्टी के हों। इस के बारे में पोलीटीकल पार्टीज और व्यक्तिगत भी अपने अपने विचार हो सकते हैं। मैं अपने विचार हाउस के अन्दर रखूंगा। लेकिन यह मौका नहीं है कि उस फैसले के बारे में मैं इस वक्त अपने विचार रखूं। मैं अपने विचार मुनासिब वक्त पर रखूंगा। हाउस के अन्दर जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं बिचार प्रकट करूं। आज मै यह कहना चाहता हूं कि इस आन्दोलन से जो कुछ हो रहा है, उस मैं बुराई ही दिखाई देती है। जो कुछ भी हुआ, इस में किसी की शह हो, अथवा किसी का हाथ हो, किसी एक पार्टी का या किसी दूसरी पार्टी का हाथ हो, अथवा एक व्यक्ति का या खुद नौजवानों की आन्दोलन के बारे में अपनी सोची हुई बात हो, यह निन्दनीय है, हमें सब को मिल कर इस की निन्दा करनी चाहिए। जिस रास्ते पर इस वक्त नौजवान स्टूडैंट्स चल रहे हैं, हमें उन को अपील करनी चाहिए कि वह उस रस्ते को छोड़ें क्योंकि इस से किसी का भला होने वाला नहीं है। इस में बुराई ही दिखाई देती है। यह ठीक है कि प्रजातन्त्र में हरेक को हक है कि वह किसी फैसले की तारीफ करें या न करें उसे अच्छा कहे या बुरा। लेकिन यहां तक प्रापर्टी का सम्बन्ध है, चाहे वह किसी की निजि प्रापर्टी है या सरकार की प्रापर्टी है, उस को किसी को भी नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इस के अलावा किसी को हक नहीं है कि वह कानून को अपने हाथ में ले या कानून विरुद्ध वाक्यात करे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ वह बहुत अफसोसनाक है। नौजवान स्टूडैंटस किसी जज़बात के तहत में आ कर इस तरह के वाकियात करने के लिए तैयार हुए, यह ठील नहीं। हमें उन से अपील करनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हाउस का हर मेम्बर इस अपील के साथ शामल है कि स्टूडैंट्स तशद्दद के रास्ते को तुरन्त छोड़ें। इस के समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि पंजाब का कुछ बने लेकिन जहां तक पंजाब के हिन्दु तथा सिक्ख का सम्बन्ध है, उन्हें मिल कर रहना होगा और उन को एक दूसरे के साथ प्यार से रहना होगा। (दोनों तरफ से तालियां) इन में नफरत का बीज किसी को भी नहीं बोना चाहिए। इस से किसी को फायदा नहीं हो सकता है। इस लिए कोई फिरका-प्रस्त नारे किसी तरफ से चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, या छोटी पार्टी हो, नहीं लगाए जाने चाहिएं जिस से सिक्ख और हिन्दू का नुक्सान हो। इस से पंजाब का भला नहीं होगा। इस लिए हमें एक बात का पक्का इरादा करना होगा कि हमें किसी हालात में भी कोई ऐसी नफरत नहीं फैलानी होगी जिस से हिन्दुओं

[श्री मोहन लाल]

और सिक्खों में कोई भेद भाव पैदा होने की सम्भावना हो । हमें आपस में ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारे के जज़बात बनाने चाहियें । मैं कहना चाहता हूं कि जन संघ के प्रधान ने जो स्टेटमेंट अख्बारों के अन्दर दिया, वह मेम्बर साहिबान ने पढ़ा होगा-----

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर कल दो घंटे निश्चित किए गए हैं। इस लिए यह मुनासब होगा कि यह मामला कल डिस्कस किया जाए। (Two hours, discussion has been fixed for tomorrow on this subject. It would, therefore, be proper if this matter is discussed tomorrow)

पंडित मोहन लाल : चूंकि मैं ने इस सबजैक्ट को इस वक्त शुरू कर दिया है मैं लम्बी बात नहीं करूंगा दो तीन मिनट में ही बोल कर इसे खत्म करूंगा ।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि जन संघ के प्रधान ने जो स्टेटमेंट अखबारों में दी है वह उन्हों ने बहुत मुनासिब किया है । जो वाक्यात हुए हैं, उन की उन्हों ने निन्दा की है और स्टूडैंट्स से अपील की है कि वे ऐसी बातों को छोड़ दें । श्री यज्ञ दत्त जिन्हों ने मरण व्रत रखा हुआ है इस इशु पर उन्हों ने भी इस बात की निन्दा की है और स्टूडैंट्स से अपील की है । इस लिये हम आशा रखते हैं कि जो भी नौजवान दोस्त गुमराह हुए हैं, किसी कारण से, उस रास्ते को छोड़ कर वे अमन और शान्ति के रास्ते पर चलेंगे ।

स्पीकर साहिब, इस से पहले कि मैं बजट पर अपनी बात कहूं मैं अफसोस ज़ाहिर करता हूं कि कुछ ऐसी बातें आज ज़िम्मेदार हलकों की तरफ से कही जा रही है जिन की हमें अवश्य निन्दा करनी होगी । आज ही आप ने अखबारों में पढ़ा होगा —हरयाणा लीडर्ज़ की पंजाबी हिन्दू को धमकियां, और मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जिन की तरफ से यह स्टेटमेंट आई प्रेस इन्टरव्यू के ज़रिये से उन में से कुछ हमारे कांग्रेसी दोस्त भी हैं । इस से ज़्यादा बुराई की बात कोई और नहीं हो सकती । मैं समझता हूं कि कांग्रेस में होते हुए कोई भी हो, छोटा बड़ा, जो इस किस्म की धमकी अपने या दूसरे भाइयों को एक इलाके या दूसरे इलाके में रहने वालों को देता है, उस को अपने आप को कांग्रेस में रहने का कोई हक हासिल नहीं है । मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ और अफसोस भी हुआ कि हमारे कुछ कांग्रेसी दोस्त इतने गिर जाएं अपनी ज़िम्मेदारी को इतना भी न समझ सकें कि वह इस इशू पर किसी से इख्तलाफ रखते हों, यह किसी से इतफाक करते हों, परन्तु वह मज़मून तौर पर पंजाब के किसी हिस्से में रहने वाले लोगों को, अपने भाइयों को यह धमकी दें कि इस का असर पंजाबी हिन्दू पर जो हरयाणा में रहते हैं बुरा होगा, और इस तरह से हरयाणा में रहने वाले भाइयों को पंजाबी हिन्दू के विरुद्ध इश्तआल दिलाएं, इस से ज्यादा बुराई और कोई नहीं हो सकती है । मैं आशा रखता हूं कि कांग्रेस के जिम्मदार व्यक्ति इस का मुनासिब

नोटिस लेंगे और इस बात की रोक थाम करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बातों को न दोहराए । स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ दूसरे तबके के भाई के भी, मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी भूपिन्द्र सिंह, सरदार आत्मा सिंह जैनरल सैक्रेटरी अकाली दल, ने भी आज से दो तीन दिन पहले इश्तालअंगेज़ ब्यानात दिये लोगों को भड़काने के लिये, उन्हों ने भी बहुत बुराई की है। उन की भी जितनी निन्दा और कंडेमनेशन की जाए वह भी थोड़ीहै । मैं उन से भी कहूंगा कि पंजाब के इंट्रेस्ट के लिये, पंजाब की बेहतरी के लिये हिन्दू और सिख के भाईचारे नाते अपने आप को काबू में रखें । ऐसे मौके पर कोई और ऐसी बात न कहे जिस से आग और ज्यादा सुलगे । इस वक्त मैं इतनी ही अपील करते हुए बजट के मुताल्लिक दो तीन बातों के बारे में कुछ कहूंगा ।

स्पीकर साहिब, मैं जानता हूं कि पिछला साल एक गैर मामूली, एबनार्मल साल था । उस में जंग की वजह से पंजाब की इकोनोमी को धक्का लगा । पंजाब की इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को भी धक्का लगा और खुश्कसाली की वजह से भी पंजाब की इकोनोमी बिखरी और कमज़ोर हुई । इन हालात में हमारी सरकार ने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबक, जो कुछ कर सकती थी, युद्ध पीड़त, उखड़े हुए लोगों के वास्ते उन्होंने ने यत्न किया । इस साल के बजट के मुताल्लिक मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, इतना शायद समय न हो । हमारी सरकार ने एग्रीकलचर के लिये, इंडस्टरी के, बिजली के लिये और पानी देने के लिये अपने रीसोर्सिज के मुताबिक काफी प्रोविज़न रखने का यत्न किया है और कठिन हालात के होते हुए भी अपने ऊपर उन्हों ने ज़िम्मेदारी ली है कि वह 11 हज़ार ट्यूबवैल्ज़ के लिये काश्तकारी की उपज बढ़ाने के लिये कुनैक्शन देगी और दस हज़ार डीज़ल सेट्स भी काश्तकारों को देगी, अच्छे बीजों की सप्लाई के बारे में भी सोचेगी और खाद और दूसरी चीज़ों के मुताल्लिक भी प्रबन्ध करेगी । मैं उन के इन कामों की सराहना करता हूं कि हालात के मुताबिक जो कुछ वे बजट में रख सकते थे, उन्हों ने रखा है, अच्छा किया है । लेकिन दो एक बात के बारे में मुझे अफसोस है कि सरकार की नीति की नुक्ताचीनी करनी पड़ेगी । पहली बात जो इस बजट में सब से ज़यादा काबले एतराज़ मैं देखता हूं वे हैं टैक्सिज । इस साल 308 लाख के नए टेक्सिज़ इन्हों ने लगाए हैं । मैं इस बात की तफसील में जाना ज़रूरी नहीं समझूंगा । मैं ने सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन्ज दी जा रही हैं कि यह टैक्सिज़ हैं या नहीं हैं । चूंकि फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी स्पीच में ही उनको टैकिसज़ कहा है इस लिए मैं इस बात में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत ना इन्साफी की है । इन को पंजाब में इतने भारी तादाद में नए टैक्सज़ नहीं लगाने चाहिये थे । आप जानते हैं कि पिछली दफा अक्तूबर सैशन में जंग के बाद जब फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने यहां पर तीन टैक्सिज़ कुमर्शियल क्रास सेस, पब्लिक कैरियर्ज़ पर और सेल्ज़ टैक्स के बारे में लगाए थे तो उस वक्त इस हाउस के हर कोने से उन टैकिसज के खिलाफ आवाज़ उठी

[श्री मोहन लाल]

थी । उस वकत सरकार ने अपनी मजबूरी बतलाई थी लेकिन साथ ही यह कहा था कि आइंदा यानी इस साल के बजट सेशन में वह कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी । कांग्रेस की लेजिसलेचर पार्टी की तरफ से भी जब टैक्सों के बारे में नुकताचीनी हुई थी तो भी सरकार की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि अगले साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा । यही नहीं, इस के बाद भी मिनिस्टर साहिब ने पब्लिक में ऐसे ब्यानात दिये हैं, स्पीचों के ज़रिये जो प्रेस में आई । यह कहा गया था कि इस साल नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे । पब्लिक अब पूछना चाहेगी कि उन्हों ने जो एशोरेंस दी थी, जो ऐसी अंडरटेकिंग दी थी, उस का आज क्या हुआ ? कोई मिनिस्टर इस बात का फख्र महसूस करे तो करे कि जो एशोरेंस बाहर दी जाती है, पब्लिक में कोई मिनिस्टर देता है गवर्नमेंट उस की पाबंद नहीं है । मैं नहीं समझ सकता कि उन को इस बात में किस तरह से फख्र महसूस हो सकता है । एक मिनिसटर खुले तौर पर लैजिस्लेटिर कौंस्लि में और इस हाउस में भी कहे कि गवर्नमेंट ऐसी एशोरेंस की या कही हुई बात की पाबंद नहीं है । और उन का यह कहना कि ऐसी स्पीचिज, एसी एश्योरेंसिज, ऐसे बयानात सिर्फ लोगों की वाह वाह हासिल बरने के दिए जाते हैं, मुझे तो उन की इस बात में कोई जान दिखाई नहीं दी । अगर ऐसी बात हो फिर तो यह लोकराज का मज़ाक बन जाएगा लोक राज की तो बुनियाद ही यही है कि लोगों का मनिस्टर्ज़ की तरफ से दी गई एश्योरेंसिज़ पर, उन की तरफ से दिए गए वचनों पर विश्वास रहे । अगर गवर्नमेंट की बातों पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है फिर तो लोकराज की बुनियादें ही हिल जाती हैं । इस लिए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिब से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो वादा किया था कि हम और कोई नई टैक्सिज़ नहीं लगाएंगे, उन को आखिरी फैसला करतें वकत इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए । मैं उन से प्रार्थना करने वाला हूं कि जितनी टैक्सिज़ उन्होंने लगाई है उन सब को वे वापिस ले लें और इस तरह से अपनी पहली दी गई ऐश्योरेंससिज़ को पूरा करें ।

स्पीकर साहिब, मुझें फाईनेंस मिनिस्टर साहिब को उन की अपनी ही स्पीच का हवाला भी देना पड़ेगा इस बात पर बहस करने के लिए कि नए टैक्सिज़ लगाने के लिए इस वक्त कोई वजह नज़र नहीं आती, उन्होंने इस बात को माना है, कि पंजाब की इकानोमी टूटी हुई है और जनता नई टैक्सिज़ का बोझ उठाने के काबल नहीं । सफा 1 पर अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है :

"The State, as the hon. Members are well aware, had to face a grim and unprecedented situation of economic distress as a result of aggressive military action by Pakistan on our borders."

इकनामिक डिस्ट्रेस के शब्द को शायद वह नोट करना मुनासिब समझेंगे। इसी सफा पर आगे उन्होंने कहा है :

"Although all attempts were made to maintain the economic activities at their normal pace, the condition, as a consequence of war, threw out of gear the economy of the State and more particularly of the border districts which had to bear the main brunt of the enemy attack For a time, normal activities of trade, commerce, industry and banking in these districts came virtually to a stand still.

The remaining parts of the State also did not remain unaffected. In this hour of trial, we might have hoped to have Nature on our side. Unfortunately, this was not to be so, for large areas of the State have been in the grip of drought conditions and power scarcity. The agricultural and industrial economy of the State, therefore, has been put to severe stress and strain."

उन्होंने फिर आगे चलकर कहा :

"With all our efforts the wheels of industry would turn but with slow speed with the result that the producton suffered an estimated loss of the order of Rs. 15 crores."

तो फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी स्पीच में इस बात को माना है कि इंडस्ट्रियल सैक्टर को प्रोडक्शन में 15 करोड़ रुपए का खसारा हुआ और कहा कि:

"The Punjab, in a way, faced and is still facing ....

Mr. Speaker, Sir, I will repeat the words "and is still facing the consequences and after effects of war in much wider and bigger way than the rest of the country."

यही नहीं, और भी कई जगहों पर उन्होंनें खुले तौर पर इस बात को माना है। इसी सफे पर लास्ट पैरा में उन्होंने कहा है :

"The aggression from Pakistan took place at the time of preparatory tillage for Rabi sowing. The situation got aggravated by the failure of rains and consequent drought and fall in the supply of waters in the rivers as also in the Gobind Sagar."

इसी तरह से आगे भी उन्होंने इस बात को माना है। सफा 24 के पैराग्राफ 11 की तरफ भी मैं आप का ध्यान दिलाता हूं। वहां पर लिखा है :

"The recent Indo-Pak conflict on Punjab orders caused the capital Market to shrink and credit facilities so Vitally needed for industrial production practically dried up in the border districts of the State."

तो, स्पीकर साहिब, इन की अपनी स्पीच की तरफ ध्यान दिलाता हुआ मैं इन के रीज़न्ज़ में भी जाना चाहूंगा....वह रीज़न्ज़ जो कि फाईनैंस मनिस्टर साहिब ने नए टैक्सिज़ लगाने की बाबत सफा 11 पर दिए हैं। उन्होंने कहा है :

"After discussion with the Planning Commission, therefore, an outlay of Rs. 59.92 crores has been settled for 1966-67 with the promise that if the State Government raise an additional amount of Rs. 2.2 crores, the Government of India, would provide matching contribution as additional central assistance over and above Rs. 33 crores."

[श्री मोहन लाल]

इस से पहले उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था:

"The Planning Commission had earlier indicated that it would not be possible for them to provide central assistance beyond Rs. 33 crores against Rs. 38 crores provided in 1965-66.........In the conext of this commitment, the undertaking of the State Government to mobilise additional resources of the order of Rs. 2.20 crores assumes a special significance ...."

तो अब एक ही बहुत बड़ी वजह फाईनैंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी स्पीच में दी है कि चूंकि प्लैनिंग कमिशन मानता नहीं था इसके लिए रुपया देना और वह इस सूरत में माना कि अगर हम 2.2 करोड़ रुपया पंजाब में नए टैक्सिज से इकट्ठा करें तो उसी सूरत में वह भी 2.2 करोड़ रुपया पंजाब को देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्लैनिंग कमिशन के पास से रुपया उसी सूरत में निकल सकता है अगर पंजाब में नए टैक्सिज़ लगा कर लोगों का खून चूसा जाए, किसी दूसरी शकल में नहीं निकल सकता। मैं पूछता हूं कि अगर प्लैनिंग कमिशन के पास पहले रुपया नहीं है तो अब भी नहीं है...अगर अब उसके पास २.२ करोड़ रुपया देने को है तो पहले भी था। कहां से आ गया वह रुपया उन के पास ? कौन सी जस्टीफीकेशन बन जाती है इस बात के लिए ? स्पीकर साहिब, मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार की यह अपनी कमज़ोरी है। अगर प्लैनिंग कमिशन वाले या गवर्नमैंट आफ इंडिया आप को यह कह देती कि दस करोड़ रुपया और पंजाब से टैक्सिज़ के जरिए इकट्ठा करो और दस करोड़ हम देंगे तो हमारी सरकार इस बात को मान जाती कि वह दस करोड़ रुपये के नए टैक्सिज़ पंजाब के लोगों पर लगाएगी ? यह उन का रीज़न है, यह उन की आरगुमैंट है कि सैंट्रल गवर्नमेंट पंजाब सरकार को उतना रुपया ही देगी जितना कि वह अपने सूबे में लोगों पर टैक्स लगा कर वसूल कर सकेगी। मैं पूछता हूं कि आप गवर्नमैंट आफ इंडिया को क्यों नहीं समझा पाए कि वार की वजह से जो पंजाब को नुकसान पहुंचा है, पंजाब की इकानोमी को जो धक्का लगा है, वह पंजाब ने सारे देश के लिए बरदाश्त किया है ? यह सारे देश की लड़ाई थी। पंजाब ने उस के लिए सफ्फर किया, पंजाब का जो नुकसान इसमें हुआ, यहां की इन्डस्टरी, ऐग्रीकल्चर जो तबाह हुई, बरबाद हुई तो वह सारे देश के लिए हुई। इस के लिए क्यों वहां पर नहीं कहा जा सकता था ? क्यों गवर्नमैंट आफ इंडिया पर प्रैशर नहीं डाला जा सकता था ? क्यों नहीं उन को ऐसे समझाया जा सकता था ? क्यों न ऐसा स्टैंड हमारी गवर्नमैंट वहां पर ले सकी ? क्यों नहीं सरकार उन को कह सकती थी कि इन हालात में पंजाब के लोग किसी किस्म का भी टैक्सों का और बोझ बरदाशत करने के काबल नहीं हैं। अगर वह इन बातों के बावजूद 2.2 करोड़ देते हैं तो दें नहीं देते तो न दें लेकिन पंजाब की जनता हरगिज़ ऐसी पोज़ीशन में नहीं कि और टैक्सों का बोझ बरदाश्त कर सके। इस लिए मुझे तो यह आरगुमैंट जो कि फाईनैंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी स्पीच में दिया है, बिल्कुल बेजान दिखाई देता है। और फिर हमारी सरकार की पोज़ीशन क्या है ? यह गिला करती है सैंटर की सरकार पर। एक

जगह पर फाइनैंस मनिस्टर साहिब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हम ने उस वक्त जब कि यह पंजाब उजड़ा था, बिखरा था, गवर्नमैंट आफ इंडिया से मदद मांगी थी, रीहैबिलीटेशन के लिए मदद मांगी थी और उन की तरफ से इन्कार हो गया था, गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हमारी यह डिमांड मंजूर नहीं की थी। उन्होंने कहा there was no response from the Government of India. कैसी रेस्पांस होती गवर्नमैंट आफ इंडिया से ? अगर आप किसी भी बात पर मज़बूती से स्टैंड ही नहीं ले सकते तो गवर्नमैंट आफ इंडिया में आप की मानेगा कौन ? गवर्नमेंट आफ इंडिया भी उन की बात को मानती है जो अपने पांव पर खड़े हो सकें। जो जानते हैं स्टैंड लेना गवर्नमैंट आफ इंडिया उन्हीं की बात को मानती है। जो हर बात के लिए यहां से मंज़ूरी लेने के लिए वहां भागें और जो हर बात पर गवर्नमैंट आफ इंडिया और प्लैनिंग कमिशन के दबाव में आ जाएं उन की बात गवर्नमैंट आफ इंडिया कैसे मानेगी ? वह क्यों न आप पर इस बात की कन्डीशन लगा दे जब कि आप ऐसे हालात में भी, जब कि पंजाब इस वार की वजह से उजड़ चुका है, सोना भारी तादाद मे इकट्ठा करवा कर उन को दे सकते हैं ? मुझे यह ज्ञात हुआ है कि टीचर्ज पर इस बात के लिए प्रैशर डाला जा रहा है। उन की तरफ से प्रोटैस्ट पर प्रोटैस्ट आ रहे हैं लेकिन हमारी सरकार टीचर्ज को एजंसी बना कर जब सोने की इस कदर तादाद इकट्ठा करा सकती है तो गवर्नमैंट आफ इंडिया को कैसे एतबार आ जाए कि पंजाब की इकानोमी शैटर हो गई है ?

अगर पंजाब के स्कूलों के बच्चों से ज़बरदस्ती चन्दा इकट्ठा कराया जा सकता है लाखों की तादाद में तो आप किस तरह से गवर्नमैंट आफ इंडिया से कह सकेंगे कि आज आप की जनता गरीब हो चुकी है और यह अपना और खून चुसवाना बरदाशत नहीं कर सकती ? जब हमारी सरकार बलंद आवाज़ में दावे कर सकती है कि हम ने इस एमरजंसी के बाद चार करोड़ रुपया इकट्ठा किया है तो कैसे गवर्नमैंट आफ इंडिया मान लेगी कि अब पंजाब की जनता में जान नहीं है। अगर सितम्बर के महीने में लड़ाई खत्म हो और अक्तूबर के महीने में हमारी सरकार और तीन नए टैक्स लगा सकती है तो किस तरह से गवर्नमैंट आफ इण्डिया को विश्वास आएगा कि हमारी जनता में और टैक्स देने के लिए जान नहीं है ? इस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपना केस गवर्नमैंट आफ इण्डिया के पास प्लीड ठीक तरह से नहीं कर पाए तो आप इस बात की शैल्टर लेने की कोशिश न करें कि क्योंकि गवर्ननेंट आफ इण्डिया अपने पास से यह दो करोड़ रुपए की रकम देने को तैयार नहीं हुई इस लिए आप को यह नए टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ी है। इस तरह से जो नए टैक्सों का बोझ लोगों पर डालने के लिए आप ने दलील दी है मैं यह समझता हूं कि यह एक बड़ी बोदी दलील है।

फिर, स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि इण्डस्टरी के लिए इन के दिल में बड़ा एहसास है और इण्डस्टरी और एग्रीकल्चर को जो नुकसान हुआ है इस से

[श्री मोहन लाल]

पंजाब की इकानोमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है लेकिन नए टैक्स लगाते वक्त यह इस बात को भूल जाते हैं । आप इस बजट में देख रहे हैं कि किस तरह से यह बार बार कहते हैं कि इस वार से पंजाब की इण्डस्टरी को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इस से पंजाब की इन्डस्टरी को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और खसारा हुआ है और इन्डस्टरी जो इस वार के बाद अभी अपने पावों पर ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पाई उस पर हमारी यह सरकार एक करोड़ रुपए के नए टैक्सिज़ लगा कर बड़ी कृपालता कर रही है और ऐसा करते हुए इन्होंने इसी बात का सहारा लिया है । आप इस बजट स्पीच के पेज 61 पर जहां इस का जिक्र किया हुआ है देखें वहां इस बात को इन्होंने फिर दोहराया है–

"As stated by me earlier, the Planning Commission while considering the Annual Plan for Punjab State for 1966-67 have promised an additional central assistance of Rs. 2.20 crores on the condition that the State Government should mobilise additional resources to the same extent mainly through additional levies on land revenue, irrigation rates, electricity tariffs and urban immovable property...."

This is the commitment which our Government made to the Planning Commission. It is further stated :

"In pursuance of the above commitment made by the State Government, it has been decided to increase the existing tarrif on power used for industrial consumption as follows...."

आप इस पर ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं । इस में बड़े कारखाने भी आ गए हैं और मीडियम स्केल के कारखाने भी आ गए हैं और छोटे भी आ गए हैं और जो बड़े कारखाने हैं उन पर इस सरकार की खास अनायत हुई है। आप इस में ज़रा देखें तो आप को पता लगेगा कि जहां एक किलो वाट का ऐग्ज़िसटिंग रेट 5 प्वायँट 76 पैसे पर यूनिट है तो वहां पर अब यह 10 प्वायंट 19 पैसे पर युनिट करने जा रहे हैं यानी साढ़े तीन पैसे फी युनिट और यह बढ़ाने जा रहे हैं । इसी तरह से छोटी छोटी यूनिटस के बारे में भी यह बढ़ा रहे हैं । तो इस तरह से यह सरकार अपनी इण्डस्ट्री को हिम्मत दे रही है अपने पावों पर फिर से खड़ा होने के लिए । एक तरफ हमारी सरकार उन को इंजेक्शन के ज़रिए खून दे रही है उन को कर्जे दे कर उन की मदद कर के और दूसरी तरफ यह उन का खून चूस रही है, एक करोड़ रुपए के और टैक्स लगा कर । तो क्या हमारी केन्द्रीय सरकार यह मानेगी कि आज जब कि पंजाब की इण्डस्टरी एक करोड़ रुपए के नए टैक्स दे सकती है तो क्या यह सही है कि इस को इस वार से बड़ा धक्का लगा है और इस को 15 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है और इस की उपज में कमी हुई है । इस चीज़ को देख कर वह कैसे नहीं मानेगी कि यहां की इण्डस्ट्री अपने पावों पर खड़ी हो गई हुई है जब कि हमारी सरकार इस से एक करोड़ रुपए के और टैक्स इकट्ठे करने जा रही है । इस के बावजूद भी हमारी सरकार बड़े ऊंचे ऊंचे दावे करती है इण्डस्टरी को इस स्टेट में बढ़ाने के लिए और कहती है कि वह बाहर से और इण्डस्टरीज़ को इनवाईट कर

रही है। यह बड़े दावे करती है कि प्राईवेट सैक्टर में और पब्लिक सैक्टर में भी इस को बढ़ाने जा रही है और कहती है कि इस ने प्राईवेट इण्डस्टरी को लाने के लिए बड़ी कशिश पैदा कर दी है जिस से वह अपने आप ही यहां खिंची आएगी और दूसरी तरफ यह उन पर और टैक्सों का बोझ डालने जा रही है और हमारी सरकार को शायद समझ लग सके कि इस की इस कृपालता से यहां की इण्डस्टरीज़ की कितनी कम्पीटीशन की केपेसेटी बढ़ जाएगी जो इस टूटी हुई कमर वाली इन्डस्टरी पर, चाहे वह बड़ी है और चाहे छोटी है, एक करोड़ रुपए के टैक्सों का और बोझ रखने लगी है। इस से उस की कमर कितनी मजबूत हो जाएगी और बाहर से इन्डस्टरी यहां पर खिंची चली आएगी। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इस तरह से और टैक्स लगा कर अन्याय किया है जिस से यह अपने पावों पर खड़ी नहीं हो सकती। यह तो इस ने उस को धक्का लगाया है जिस से वह मूंह के बल गिर जाए। मैं समझता हूं कि इन की मनशा यह है कि इस को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्डस्टरी में कानफीडेंस क्रिएट करने के लिए इन प्रोपोज़ड टैक्सों को यह वापिस ले लें।

स्पीकर साहब, इसी तरह से इन्होंने इंटों पर एक रुपए 33 पैसे फी हज़ार इंट पर और टैक्स लगा लिया है—

श्री अध्यक्ष : आप कितनी देर में वाइंड अप करेंगे ? (How much time the hon. Member would take to wind up his speech.)

श्री मोहन लाल : जब आप चाहेंगे मैं उसी वक्त वाइंड अप कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट में वाइंड अप कर दें। (He should wind up with in five minutes.)

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहब, मैं 10 मिनटों में वाइंड अप कर दूंगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईंटें जो मिट्टी से बनेंगी उन पर एक हज़ार ईंट पर एक रुपए और 33 पैसे इन्होंने टैक्स लगाया है और इसी तरह से जो अर्बन प्लाटस शहरों में खाली पड़े हुए हैं उन पर पता नहीं किस शक्ल में यह लेंगे ? उन पर 20 लाख रुपए साल में और इकटठा करेंगे। इस तरह से यह और टैक्स लगा कर बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ कहती है कि यह इस का सोशलिज्म की तरफ एक कदम है। इसी तरह से यह 20 लाख रुपए जो अर्बन एरियाज़ में प्लाटस हैं जिन में छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे और आम तौर पर यह छोटे होते हैं उन पर वसूल करने जा रही है। इस तरह से यह एक बहुत बड़ा कदम सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ उठाने जा रही है और इसी लिए इन्होंने इंटों पर टैक्स लागू कर दिया है क्योंकि शायद पंजाब में बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े २ कारखाने तो न बनें लेकिन गरीबों के छोटे २ मकान जो इस बार की वजह से तबाह हो गए हैं या कई जगहों पर जो वाटरलागड एरियाज़ हैं वहां पर ग़रीबों के जो कच्चे मकान बने हुए हैं और इस ख्याल से कि वाटर लागिंग की वजह से या फलडज़ की वजह से हर बार गिर जाते हैं वह उन के स्थान पर पक्के बना लें ताकि वह गिरें न, उन लोगों को अब एक रुपए और 33

[श्री मोहन लाल]

पैसे फी हज़ार ईंट पर गवर्नमैंट को देना पड़ेगा । इस तरह से यह इन का सोशलिस्ट सोसाईटी बनाने की तरफ एक कदम होगा......

वित मंत्री : उन पर यह नहीं लगेगा ।

श्री मोहन लाल : इसी तरह से जो टैक्सिज़ हमारी सरकार लगा रही है अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं एक २ करके सारी बातें आप के सामने रखता और अर्ज़ करता कि टैक्सिज में भी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिसे यह कहा जाए कि यह सोशलिज्म की तरफ एक कदम है । इस बजट में भी कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जिसे कहा जा सके कि यह भी सोशलिस्ट सोसायटी की तरफ कोई कदम है, सोशलिज्म की तरफ हम इससे बढ़ते हैं । हां लफ्ज़ ज़रूर वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इस बात का एहसास कर लें कि टार्गेट हमारा सोशलिज्म और सोशलिस्ट सोसायटी है ।

अब देखें कि चावल पर परचेज़ टैक्स लगाया गया है और हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब अपनी बजट स्पीच में कहते हैं कि इस से कोई असर कन्ज्यूमर या काश्तकार पर नहीं होने वाला है । मैं यह बात नहीं समझ पाया कि परचेज़ टैक्स का पैडी की कीमत पर कैसे असर नहीं होगा । अगर यह अदा करना पड़ेगा तो इस का असर मार्किट की दूसरी प्राइसिज़ पर कैसे नहीं होगा ? खैर, मैं आशा रखूंगा कि जब जवाब देने का वक्त आयेगा तो फिनांस मिनिस्टर साहिब इस को तफसील के साथ समझाएंगे कि इस का असर कन्ज्यूमर और ग्रोअर पर कैसे नहीं पड़ेगा । (विघ्न) इसी तरह स पैट्रोल पर भी टैक्स लगाया गया है । इस से गरीब आदमी का किराया बढ़ेगा । बसिज़ वाले कुदरती तौर पर किराया बढ़ाएंगे । यह भी शायद इन के ख्याल में सोशलिज़म की तरफ एक कदम है ; (विघ्न) मैं डीटेल में नहीं जाता । मैं एक ही बात अर्ज़ करके अपनी जगह लूंगा । मैं चाहता था कि अपनी सरकार को बहुत सारी सजैशन्ज़ दूं । मैं इन को बताना चाहता था कि इन को अपने खर्च की तरफ ध्यान देना चाहिए, बचत की जा सकती है । सरकार ने बहुत सा फाल्तु खर्च बांध रखा है । पिछली दफा भी यहाँ पर ऐसी ही नुक्ताचीनी हुई है । आसामियों के मुताल्लिक जैनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहस में ज़िक्र करूगा तफसील के साथ । मैं इतना ही कहूंगा कि इस सरकार का यह आखिरी बजट है क्योंकि अगले बजट से पहले तो नई इलैक्शनज़ होने वाली हैं । (विघ्न) यह इन का आखिरी बजट है । तो यह सोचें और अब भी विचार करें कि यह किसी तरह से तल्ख और दुखदाई न रहे । जितने नए टैक्सिज़ लगाए गए हैं यह पंजाबियों की बरदाशत से बाहर हैं । इस बात को कई दफा फिनांस मिनिस्टर साहिबान इस हाउस में अपनी स्पीचिज़ में कबूल करते आए हैं कि पंजाब का टैक्सेशन स्ट्रक्चर बेकिंग प्वायंट तक पहुंचा हुआ है । इन नए टैक्सिज़ को लगाने की कोई जस्टीफिकेशन नहीं बनती है, सरकार इन को वापिस ले । मैं ज़रूरी समझता था कि इस का सिर्फ इतना ही चर्चा न करता, बल्कि इस के साथ कुछ और कन्स्ट्रक्टिव

बातें भी सरकार के सामने रखता लेकिन आप ने और वक्त देना मुनासिब नहीं समझा, इस लिये मैं अपनी स्पीच को यहीं बन्द करता हूं । शुक्रिया ।

श्री अध्यक्ष : कल पौने दस बजे नए गवर्नर साहिब की ओथ टेकिंग सैरेमनी है । इस लिए हाउस साढ़े नौ बजे नहीं मीट कर सकेगा । तो कल की सिटिंग 11 बजे शुरू होगी । (The new Governor will take an oath of office at 9.45 a.m. tomorrow. The House will therefore, not be in a position to meet at 9.30 a. m. and it will meet at 11 a.m. tomorrow.)

मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्ज़ : 11 बजे की बजाए साढ़े 11 बजे कर दें ।

श्री अध्यक्ष : देख लें कल दो घंटे ला ऐंड आर्डर सिचुएशन की डिसकशन के लिए भी एलाट करने हैं । इस तरह से कल साढ़े 6 घंटे की सिटिंग हो जायगी (विघ्न) पांच बजे पार्टी भी है । कल बजट डिसकशन का लास्ट डे है । अगर हाउस पसंद करे तो कल क्वैस्चन आवर टेक अप न किया जाए । (He may also keep this fact in view that two hours are to be allotted for raising discussion on the Law and Order situation in the State. In this way, tomorrow's sitting will be of 6.30 hours. (interruptions) A party has also been arranged at 5 P.M. Tomorrow is also the last day of discussion of the budget. If the House agrees Question Hour may be dispensed with tomorrow.)

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : तो यह करें कि हाउस 11 बजे शुरू हो कर 5 बजे शाम तक चलता रहे । (Then the House will meet at 11 a.m. and continue sitting till 5 p.m.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਅਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਸ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉ। (ਵਿਘਨ) ਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । (It would be better if the hon. Member spend the whole of his time in discussing other things. (Interruptions). Discussion of law and order situation will be held tomorrow. (Interruption). He will get the time as said before).

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਅਜ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਖਾਸੀ ਵਡੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ । ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3-4 ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧ ਨੇ ਅਧ ਪਚੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'There is no question why, we are to submit and die.' ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ

4.00 p.m.

ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗਏ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਣ ਦੀ। ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ? ਕਲ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨ 1947 ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਲਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ:

'ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਵੈਸਚਨ ਵਾਈ
ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਐਂਡ ਡਾਈ।'

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕੇ ਇਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

[*Deputy Speaker in the Chair*]

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ, ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜ 80% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਨ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤੇਆਲ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕ ਤਬਕਾ ਭੜਕ ਉਠੇ ਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਖ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਭੜਕ ਉਠੇਗਾ ਸਿਖ ਭੜਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਫਸਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਗ ਭੜਕ ਉਠੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖ ਅਵਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਆਲ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਨਚ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ

ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜੜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰਖ ਕੇ ਹੋਰ ਉਕਸਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਐਟੀਚੂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਤੱਲਕਾਤ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਭੜਥੂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 18 ਅਕਾਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਨਡੈਮਨੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਅਤੇ 'ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਅਜ ਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ, ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਾਵਤੀ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਪ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ । ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ । ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ । ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਬਣਾਉ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਸਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7% ਸੂਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 2% ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਉ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਤੋਂ ਟਯੂਬਵੈਲ ਲੈ ਲਉ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੋਕਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਉਂ ਹੈ। ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗਿਦੜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਿਦੜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਲਾਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਛਕ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਦੜ ਫੇਰ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਭੁਖ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ,

ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਛਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕੰਬਲ, ਰਜ਼ਾਈ ਗੁਦੇਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਦੇਉ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਿਦੜ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਡੇ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਗੁਦੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला) : मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम कई दिन से इस बजट पर बहस कर रहे हैं । हमारे वज़ीर खज़ाना भी इस को सुन रहे हैं । मगर वह एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं और कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जो कुछ हमारे सूबा पंजाब में हो रहा है जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा था कि अफसोसनाक है मैं तो कहूंगा कि यह निहायत ही शर्मनाक है । ज़बान के आधार पर सूबा मिलने से जितने लोग खुश हुए हैं उतने नाराज़ भी हैं । मगर जिन लोगों ने तशद्दुद पर कमर बाँधी हुई है मेरी उन लोगों के साथ हरगिज़ हमदर्दी नहीं है। जहां तक इस झगड़े को खत्म करने का सवाल है मैं समझता हूं कि अगर लीडर साहिबान--मैम्बरान सच्चे दिल से इस को हल करने का तहैया कर लें तो यह कोई ऐसी बात नहीं कि यह रुक न सके । बजट के मुताल्लिक मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हर साल जब भी यह बजट पेश किया जाता है तो यही कहते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है । हम भी बड़े खुश होते हैं और जनता भी बड़ी खुश होती है कि हमारे वज़ीर खज़ाना सरदार कपूर सिंह इस खज़ाना में और नए टैक्स के ज़रिया से रुपया दाखल होने नहीं देंगे। मगर होता क्या है ? चाहे यह आटम सैशन है या बजट सैशन है यह किसी न किसी तरीका से हमारे पर टैक्सों का बोझ डालते ही रहते हैं हमारी कमर दोहरी हो गई है यह बोझ और बरदाश्त करने के नाकाबिल है मगर वज़ीर साहिब वादा जरूर करते हैं कि कोई टैक्स नहीं है मगर इस की खिलाफवरज़ी ज़रूर करते हैं। यहाँ तक, डिप्टी स्पीकर मोहतरिमा, आप देख सकते हैं कि बजट पर बहस हो रही है और मासवाए सरदार कपूर सिंह के फरंट की लाईन में कोई मिनिस्टर नहीं है। जब हमारी बहस का जवाब देने का वक्त आएगा तो जो महकमा का छोटा वज़ीर है वह यह समझ कर जवाब नहीं देगा कि ऊपर वाला वज़ीर जवाब देगा मगर ऊपर वाला जवाब ही क्या देगा जब उस ने हमारा कोई लफ्ज़ सुना ही नहीं ।

डिप्टी स्पीकर मोहतरिमा, हमारा बजट अजीब तरीका का होता है । वायदे कुछ हैं और किया कुछ जाता है। इन्होंने एक बात समझ ली है कि "वह वायदा ही क्या जो वफा हो गया", हर बात पर वादा कर के मुकर जाना इन का काम है । बकौल गालिब--

"जब तवक्को ही उठ गई गालिब--क्यों किसी का गिला करे कोई"

[खान अबदुल गुफ्फार खां]

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन से तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। दो तीन महीनें में न जाने क्या होगा । हम में से कौन कौन होगा, हम मे से कौन किधर होगा । सरदार कपूर सिंह तो शायद उधर चले गए हैं इस लिए इन्हें कहने का फायदा नहीं। अब सवाल यह है कि इन्होंने बजट में भी बताया है और अपनी तकरीरों में भी बताया है, सरदार कपूर सिंह ने कहा है के यहां के हालात खराब हैं । जंग की वजह से और कहत की वजह से, बारिश न होने कि वजह से सूबे की इकानोमी तबाह और बरबाद हो चुकी है। लोगों पर और तबाही और बरबादी लाने के लिए तीन करोड़ और कुछ के टैक्स और लगा दिए । यह किस चीज़ पर लगाए ? जरा मुलाहज़ा कीजिए इन्होंने कहाँ पर टैक्स लगाया है। बड़ा भारी सोच कर एक टैक्स तो निकाला कि तुम्हारी ईन्टों पर टैक्स लगाते है। यह ईन्टों पर टैक्स उन बेचारे गरीबों पर है जिन के पास न खाने को है और न पहनने को है, जिन के तमाम मकान तबाहो बरबाद हो गए हैं । इन के लिए तो कहना यह चाहिए था कि हम फ्री ईन्टें देते हैं, मकान बनाओ । फाईनैंस मिनिस्टर सरदार कपूर सिंह साहिब कहते हैं कि कोई मकान न बना सके तो यह ईन्टें बरसाने वाली बात नहीं तो और क्या है । आप कहेंगे कि क्या करें हमारा खर्च पूरा नहीं होता था । सफा नौ पर इन की तकरीर में कहा है की रैविन्यू असैट्स 6,48,36,00,000 रुपये हैं और एक्सपैंडीचर 1,43,08,00,000 रुपये है, नैट इन्कम 5,28,00,000 रुपये है, जब 5,28,00,000 रुपये की बचत होती है, वह भी इस में रैविन्यू साईड में बचत होने के बाद फिर भी यह कहते नहीं कि लोगों पर टैक्स लगा दें । यह इनकी कारगुज़ारी है। सरदार कपूर सिंह साहिब हमारे वज़ीर खज़ाना ने यह बजट रखा है । जब हम यह मांग करते हैं कि कहत के मारे लोगों का गला न दबाओ तो हम बजा मांग रहे हैं इस वक्त सरदार कपूर सिंह साहिब मिनिस्टर खज़ाना हमारी कमर तोड़ने के लिए और टैक्स लगाते हैं खैर इनकी मर्ज़ी, बाखितयार हैं यह । अख्तियार बा–दस्तखत "खुद मुख्तयार" इन के हाथ में है वह जो चाहें कर दें । मैं यह कहना चाहता हूं, कि इन तमाम बातों के लिए पब्लिक के सामने इन को जवाब देह होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों । इन्हें जो पंजाब के गरीब हैं उन के सामने जवाब देह होना पड़ेगा । टैक्स तो बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन जो इतनी टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है इस की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी । लोग कहते हैं कि खुदा के वास्ते ये बी० डी० ओज० हटा दो, इतनें कमिश्नर हैं हटा दो, फानैंशल कमिश्नर हटादो, जहां दो डिवीज़नल कमिश्नर लगाए हैं उन को हटा दो, ऐसे लोगों को हटाओ लेकिन वो उन को नहीं छेड़ना चाहते, इन कीतरफ तवज्जो नहीं करना चाहते । यह तो जवानी लुटाते हैं, सरदार कपूर सिंह तो अभी जवान हैं। यह कहते हैं कि चार चपड़ासी हटा दो, दो कर्लक हटा दो कहीं कफायत की है, अब आप मुलाहज़ा फर्माएं की इतनी टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए फिर भी किसी को नहीं कहा जाता इस के माने क्या हैं । यह अफसरों को नाराज़ नहीं करना चाहते, जो बड़े बड़े गवर्नमैंट अफसर है उन से डरते हैं और डरते हुए इन्हें हाथ नहीं लगाना चाहते । दूसरी तरफ जनाब यह कहते हैं कि साहिब हम नया टैक्स नहीं लगाएंगे। मैंने पिछले

ग्राटम सैशन में यह कहा था कि यह ग्रांखों में मिर्चे झोंकते हैं पिछले दिनों इन्होंने शूगरकेन ग्रौर मिर्चों पर कुछ टैक्स लगाए, सरचार्ज लगाया, मैंने उस वक्त भी कहा था कि "It is a last straw on the camel's back." लेकिन ग्राज वो last straw तो क्या इन्होंने last Ton हमारी पीठ पर लाद दिया है। ग्रब खुराक की कमी है। मैं तो यह बात कहना चाहता हूं वो माफ करेंगे कि हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं सारे के सारे यह सब की सब उन की मेहरबानी है कि हमारे यहां खुराक की कमी हुई, क्यों कि जो चीजें खुराक ज्यादा पैदा करने के लिए मतलूब हैं, ज़रूरी है उन से इन्कार किया जाता है। मसलन ट्यूबवैल्ज़ नहीं, बिजली के कुनैक्शन नहीं ग्रच्छे बीज नहीं ग्रौर खाद नहीं जब मौका पर जो चाहिये वो चीज़ किसान, को नहीं मिलती तो वो क्या करे। ग्रब तो बड़ी मेहरबानी की है हमारे मिनिस्टर बरकियात नें! जैसे वो कहते हैं कि जहां से लाईन जाएगी उस से ग्राध ग्राध मील के फासला पर बिजली देंगे। श्री रामपाल सिंह ने कहा है कि जहां बिजली की लाईन ग्राई ही नहीं वहां क्या होगा? मसलन मैं ग्राप से ग्रर्ज़ करूंगा मेरी कंस्टीचुएंसी में इन से पूछो कि 15 साल में कोई एक भी बिजली की लाईन उधर निकाली हो! लोग चाहते हैं, मांग करते हैं लेकिन यह सुनने से लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम ट्यूबवैल लगाएंगे हमें कुनैक्शन देने के लिए बिजली का बन्दोबस्त कर दो। ग्रब ग्राई सड़क। जनाब, सड़कों की जो हालत है वो तो ग्राप को मालूम ही है, वो टुटी हुई हैं, नीचे दबी हुई हैं। जब यह जाते हैं तो इन के तो शौक रोकने वाले कारों में लगे हुए हैं जो दूसरी ट्रांस्पोर्ट में नहीं। इन को क्या पता कि हिचकोले लगते हैं। खुदा करे कि यह उस ट्रांसपोर्ट में बैठ कर जाएं जिन से पता चलेगा कि मोटर में क्या तकलीफ होती है (घण्टी) मैं ग्रभी खत्म किये देता हूं। मैं पहले नहीं बोला मैंने बोलना था ऊठ बैठ करता रहा। I could neither catch the eye nor the ear of the Chair.

उपाध्यक्षा : मैंने ग्राप को सिर्फ वाईंड ग्रप करने के लिए कहा है, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा। (I have asked the hon. Member to wind up and not to resume his seat.)

खान ग्रब्दुल गफ्फार खां : ग्रब ग्रगर रोए जाएं तो सुबह से शाम तक जितने कारनामें हैं इन्हें रोने के सिवा ग्रौर कुछ नहीं। हम रोते हैं यह हंसते हैं। यह कहते हैं कि हम हंसें। हरिजन भाइयों को हम ने इतनी मुद्दत तक दबाए रखा उनके ऊपर हम जुलम करते रहे। महात्मा गांधी ग्राए उन्होंनें महसूस किया कि जब तक इनका कल्याण नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। यह कल्याण क्या करने लगे। यह तो हरिजन कल्याण फंड खा गए दूसरों से मांग कर। लुतफ यह कि जिमींदार कहते थे कि हम पर यह टैक्स किस बात का लगाया जाता है लेकिन हमने कहा कि हम तो हरिजन भाइयों की बेहतरी के लिए, उन की हालत बेहतर बनाने के लिए यह टैक्स लेना है। बड़ी मुश्किल से लोगों को तैयार किया कि वो इस के लिए टैक्स दें। मगर यह जनाब उसे खा गए। ऐसे खा गए कि डकार भी नहीं लिया। ग्रब जनाब जितने इन्होंने टैक्स इस बजट में लगाए हैं उन के बारे में लोगों की ग्रांखों में धूल

[खान अब्दुल गफ्फार खां]

झोंकने के लिए कहते यह फिरते हैं कि साहिब यह तो बराएनाम लगाए हैं ट्रांस्पोर्ट पर लगा दिए इस पर लगा दिए, उस पर लगा दिए, ईंटों भट्ठों पर लगा दिए, लोगों पर तो नहीं लगाए लेकिन मैं इन साहबान से कहना चाहता हूं कि जनाबेआली इनडायरैक्ट टैक्स तो ज्यादा तकलीफ देह हैं क्योंकि यह आप ने रोजमररा की ज़िन्दगी की चीजों पर लगाए हैं इस लिए यह नावाजब हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि खुदारा अगर हमारे इन नेताओं की समझ में यह बात आ जाए और इन को वापिस ले लें इस से इन की मेहरबानी होगी और दुनियां में भी इन की वाह वाह होगी। इस वक्त अगर आप कहें कि हमें वाह वाह दो तो वह हम नहीं देते हम सब यहां लोगों के चुने हुए नुमायंदे आए हैं अगर चंद खुशामदी वहां खड़े हो कर वाह वाह कर दें तो इस में कोई खुशी की बात नहीं बनती। वाह वाह लेनी है तो हम से लो क्यों कि हमारी वाह वाह ही पब्लिक की वाह वाह होगी। खुशामदियों की वाह वाह कोई मायने नहीं रखती। (शोर) अब जनाब मैं कुछ अपने इलाके के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि शायद वज़ीरे खज़ाना साहिब नाराज़ हो जाएं। अब जनाब क्या कहूं। न यहां इस वक्त बिजली के वज़ीर और न सड़कों के वज़ीर तशरीफ फरमा हैं लेकिन हजूर मैं आप से इल्तजा करता हूं कि आप ही उन तक मेरी बात पहुंचा दें। मेरे हलका में एक भी सड़क गवर्नमैंट ने नहीं बनाई।

वित्त मंत्री : अब अगले साल बनेंगी।

खान अब्दुल गफ्फार खां : अगले साल तो आप ही नहीं रहेंगे (हंसी) बल्कि यह तो अब ही ढोल पिटने वाला है। (हंसी) साहिब क्या कहूं न वहां बिजली न वहां पानी न वहां कोई ब्लाक दिया गया है। वहां के लिए कुछ नहीं किया गया। कहते हैं अगले साल डालेंगे। हर साल यही कहा जाता है पता नहीं इन का अगला साल कब आएगा।

वित्त मंत्री : दुनियां बा उम्मीद कायम अस्त।

खान अब्दुल गफ्फार खां : यह जब उम्मीद ही टूट जाए तो फिर क्या होगा। अम्बाला में पानी की दिक्कत है और लोग प्यासे मरते हैं। पानी के लिए वहां सरफटोल होती है लेकिन हमारे वज़ीरों के कान पर जूं तक नहीं रींगती। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने अम्बाला को पंजाब की फहरिस्त में से निकाल दिया है। अगर यही बात है तो हमें बता दो अभी तो हमें पता नहीं कि हमारी किस्मत किधर है ! कोई कहते हैं अम्बाला को भी लेंगे, करनाल को भी लेंगे और कोई कहते हैं न अम्बाला देंगे, न करनाल देंगे। यह भी लेंगे वो भी लेंगे हमें तो पता नहीं कि हम कहां होंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस बात की परवाह नहीं की किधर होंगे। हम लोग हर तरह से तैयार हैं हरियाणा में रहें या पंजाबी सूबा में रहें। हम सब खुशी के साथ तैयार हैं। हमें किसी बात का डर खौफ नहीं हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सदर मोहतरिमा खुदारा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो

इन को अकल की बात बता दें ताकि लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऐसी बात करें जिस से इनका नाम रह जाए क्योंकि चंद दिन की बात है फिर न यह होंगे न इन का नाम बाकी होगा। (हंसी) इस तरफ होंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा (घण्टी) अब जनाब एडमिनिस्ट्रेशन का यह हाल है कि from top to bottom corruption, corruption और corruption.........।

बाबू बचन सिंह : जादू वो जो सर चढ़ बोले.....

खान अब्दुल गफ्फार खां : इस में आप के भी कुछ होंगे और हमारे भी कुछ होंगे सब कुरप्शन में मिले हुए हैं। आप भी बचे हुए नहीं हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई बात बगैर पैसे के नहीं होती है। बावजूद इस बात के कि नन्दा साहिब ने भी एलान फरमाया कि यह होगा, वह होगा इस के लिए विजीलैंस डिपार्टमैंट बना और अब विजीलैंस के ऊपर भी विजीलैंस डिपार्टमैंट दरकार है। (हंसी) मैं कहता हूं कि कुरप्शन को हटाओ। अगर आप लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं कुरप्शन रोकने वाली बात करो। वरना याद रखो यह कुरप्शन सब को ले डूबेगी चाहे इधर के हों या उधर के, पंजाबी सूबे वाले हों या हरियाणे वाले। हरियाणा बनना भी है या नहीं यह भी पता नहीं लेकिन अगर बनना है तो उन को भी ले बैठेगी। मैं अम्बाला के हलके की बात कर रहा था कि वहां सड़कें बनाओ बिजली तो वहां है ही नहीं और लोगों को पता नहीं कि बिजली किस जानवर का नाम है। (हंसी) मैं कहता हूं कि उधर भी ध्यान दो वरना तंग आमद बजंग आमद वाली बात होगी। और वे लोग भी कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे इस लिए मेहरबानी करके इस हलका की तरफ भी नजरें अनायत करें। आप का शुक्रिया।

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट) : डिप्टी सपीकर साहिबा मैं आप का धन्यावाद करता हूं जो आपने मुझे समय दिया है। यह जो बजट हर साल सरकार सदन में रखती है उसमें वह अपने आय व्यय का ब्योरा हाउस के सामने रखती है कि क्या आमदनी है और क्या खर्च करना है क्योंकि सरकार हाउस के सामने उत्तरदायी है।

मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने उसी ढंग में सालाना बजट की रूप रेखा अपनी स्पीच में बताई। इस में कोई संदेह नहीं है कि पिछले वर्ष समय पर वर्षा न होने से फसलें तबाह हो गईं और साथ में पिछला वर्ष ऐसा बीता जो कि पंजाब के लिए एक इम्तहान का वर्ष था। हमारे सूबे ने उस इम्तहान में सफलता पाई और बड़े गर्व के साथ पंजाब का नाम ऊंचा किया। मैं सरकार को इस काम के लिए बधायी देता हूं क्योंकि यह सरकार का काम सराहनीय है जिस ढंग से सरकार ने उस वक्त के हालात को सम्भालने की कोशिश की। जो व्यक्ति उस युद्ध में शहीद हुए, उन के परिवारों की जिस प्रकार से सहायता की, उस के लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने अपने बजट के अन्दर बहुत अच्छी स्कीमें बनाई हैं, उन के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे इलाका पठानकोट और

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]

डलहौजी में पिछली दो फसलें खराब हो गईं। सावनी की फसल तबाह हुई, हाढ़ी की फसल बीजी नहीं जा सकी। मैं ने खुद डिप्टी कमिश्नर, गुरदासपुर को ले कर अपने इलाके की हालत का जायजा करवाया। वह खुद मान गए कि वहां पिछली दो फसलें नहीं हुईं। मैं ने इस के लिए चीफ़ मिनिस्टर साहिब को लिख कर और जबानी भी प्रार्थना की कि वहां के लोगों की हालत को सुधारने के लिए प्रबन्ध किए जाएं। वहां पर सस्ते भाव पर अन्न दिया जाए लेकिन सरकार ने अब तक वहां के लोगों की हालात सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली लड़ाई में पठानकोट के इर्द गिर्द बम्बार्डमेंट हुई और वहां का काफी नुक्सान हुआ। बम्बार्डमेंट के अन्दर काफी फसलें तबाह हुईं। वहाँ पर जितनी फसलें खड़ी थीं, उन को कटवा दिया ताकि उन फसलों में पैरा टरूपर्ज़ छिप कर हमारी सम्पत्ति तथा व्यक्तियों को नुक्सान न करें। सरकार ने कहा कि जहां पर फसलें कटवाई जा रही हैं, वहां पर मुआवज़ा दिया जाए लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने उस वायदे को अभी तक पूरा नहीं किया। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार को अपने इस वायदे को पूरा करना चाहिए क्योंकि वहां के लोगों ने उस वक्त सरकार की बड़ी हिम्मत से मदद की। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कई बार पठानकोट ई है। आप ने शाहपुर कंडी का इलाका देखा है। मैं उस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर सरकार ने लोगों को पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं किया। इस के लिए स्कीम बनाई गई। स्कीम चालू भी हुई लेकिन पता नहीं कि उस में क्यों ढील हुई। मुझे पता नहीं चलता कि यह ढील सरकार की तरफ से है, या सरकार का अपने कर्मचारियों पर रोब नहीं रहा और पता नहीं लगता कि अब सरकारी कर्मचारी अपने काम को करना नहीं चाहते हैं। मैं ने पहले अर्ज़ की कि वहां पर पानी के बारे में स्कीम बनी। वहां पर वाटर वर्क्स बना लेकिन वहां पर मशीनरी नहीं है। जहां पर मशीनरी है, वहां पर चलाने वाला नहीं है। अगर मशीनरी को चलाने वाला हो तो वहां पर पानी सप्लाई करने का प्रबन्ध नहीं होता है। मुझे तो सरकार की पालीसी को देख कर दुख होता है क्योंकि वहां पर सरकार ने पहले लाखों रुपए खर्च किए लेकिन अभी तक वहां पर पानी सप्लाई करने का इन्तज़ाम सरकार नहीं कर सकी। आप को मालूम है कि दुनियां 5 तत्वों पर अधारित है। उस में जल तत्व सब से प्रमुख है जल तत्व के बाद ही दूसरे तत्व आते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पानी लोगों के लिए सब से जरूरी है लेकिन हमारी सरकार लोगों को पीने का पानी सप्लाई करने के प्रबन्ध नहीं कर सकी तो सरकार वहां की जनता को और क्या सुविधा दे सकेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर शीघ्र प्रबन्ध करे ताकि वहां के रहने वालों को पानी पीने के लिए मिल सके। (विघ्न) (शोर)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पठानकोट जिला गुरदासपुर की एक बड़ी तहसील है। यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक दर्रा है लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार ने वहां पर इंडस्ट्री लगाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर शीघ्र इंडस्ट्री स्थापित करने के लिये कदम उठाए ताकि वहां के लोगों को रोज़गार मिल सके। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने अभी तो सरकार के नोटिस में काफी बातें लानी हैं। इस लिए मुझे कुछ और टाइम दिया जाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार ने पठानकोट के अन्दर कोई हस्पताल नहीं खोला। सरकार को इस बारे में प्रार्थना की गई। सरकार ने कहा कि वहां पर वहां की म्युनिसिपल कमेटी का हस्पताल है। वहां पर बिल्डिंग बनाई है लेकिन उस के लिए लिखा गया कि इस को गवर्नमेंट ले ले। इसके लिए सरकार से तीन चार साल से बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए (घंटी)।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एजुकेशन के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। इस समय हाउस में शिक्षा मंत्री बैठें हुए नहीं हैं। लेकिन मैं आप के द्वारा वित्त मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में संस्कृत से अन्याय हो रहा है। संस्कृत से सारी ज़बानें निकली हैं। सारे देश के अन्दर संस्कृत का मान है और सारे देश की जनता इस का मान करती है। पंजाब की पार्टीशन से पहले लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी थी। वहां पर ओरियंटल की कलासें, प्राग्य, विशारद, शास्त्री तथा प्रोफीशेंसी की क्लासें थीं। लेकिन पंजाब की पार्टीशन के बाद यह क्लासें होशियारपुर के अन्दर खोली गईं जोकि स्टेट के एक कोने पर हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से संस्कृत का विकास नहीं हो सकता है। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह क्लासें पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रैमिसिज़ में खोली जाएं।

उपाध्यक्षा : आप किसी और डिमांड पर अपने विचार हाउस के अन्दर प्रकट कर लेना। आप बैठ जाइए। (He may express his views during the discussion on some other Demand. He should now resume his seat.)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हरिजन कल्याण फंड के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन के साथ बुरा सलूक न किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस सम्बन्ध में एक संस्कृत का श्लोक सुनाना चाहता हूं :

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्चविश्वास घातक:,
ते नर: नरकं यान्ति पावच्चन्द्रो विकारी।

इस का अर्थ यह है कि मित्र से द्रोह करने वाले, एहसान फरामोश और विश्वास घात करने वाले जब तक चांद और सूर्य रहते है तब तक नर्क में रहते हैं। हम

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]

हरिजनों के साथ विश्वास घात कर रहे हैं । हम ने जो वायदे उन के साथ किये थे उन को पूरा नहीं कर रहे । हमें इस बात का दंड भुगतना पड़ेगा । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि हमें उन का कल्याण करना चाहिये । मेरी एक दो बातें बड़ी ज़रूरी कहने वाली रह गई हैं। आप का शुक्रिया ।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1966-67 का बजट सरदार कपूर सिंह जी ने पेश किया है जिस पर बहस का आज पाँचवाँ दिन है । जो हालात आज हमारे राज्य में अमृतसर से ले कर पानीपत तक हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं । शहरों में हड़तालें हो रही हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और पुरअमन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, ...

अवाजें : नो, नो, (विघ्न) बजट पर बोलो । (विघन)

श्री मंगल सेन : पंजाब की पुलिस लाठियां चला रही है। (अकालियों की तरफ से आवाजें : नो नो, कुछ नहीं हो रहा) आप जोश ठंडा रखिये, मैं उसी बात पर आ रहा हूं । एक निर्णय लिया गया । इस से पहले कांग्रेस के ट्रेयरी बैंचों पर बैठने वाले मित्रों ने जनता में, हाउस में यह बात कही कि पंजाब का एक ही रहने में भला है । जिस प्रताप सिंह कैरों के सोल्हड़े, गीत और घोड़ियां गाते हुए मेरे दोस्त थकते नहीं थे, कहते थे कि वह आहनी मैन है आखिर उस आहनी मैन में क्या था, उस ने पंजाब के बेटवारे के आंदोलन दबा दिये थे । उस के सिर में सुर्खाब के पर इस लिये लगाए गए और कहा जाता था कि यह बड़ा मज़बूत आदमी है किसी गलत आदमी के सामने नहीं झुक सकता । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस में विवाद की बात नहीं अगर भाषा का ही प्रश्न होता तो भाषा के साथ किसी का झगड़ा नहीं है । भाषा तो देश की जनता की भाषा है । भाषा के पीछे, भाषा की आड़ में कुछ और ही बात है । आज भी उन के अपने जिम्मेदार आदमी ने कहा है कि हमें भाषाई राज्य नहीं चाहिये हमें तो खुद मुख्तयार रियास्त चाहिए ....

आवाजें : नो, नो। कौन कहता है ?

श्री मंगल सेन : मास्टर तारा सिंह कहता है, और कौन कहता है ।

विघ्न)

Sardar Gurcharan Singh : We have nothing to do with Tara Singh.

श्री मंगल सेन : वह कहता है कि हमें खुद मुख्तियार रियास्त चाहिए। खुले बंदों यह मांग वे कर रहे हैं । जो आदमी पंजाब की एकता चाहते है, श्री बलरामजी

दास टंडन, उस को डी० आई० आर० के मातहत गिरफतार कर लिया गया है । हम चाहते हैं कि देश का बंटवारा न करो, देश की डीवैल्पमैंट रुक जाएगी ......

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ....

Deputy Speaker : Please resume your seat. This is no point of order.

श्री मंगल सेन : मैं भी इस हाउस का मैम्बर चला आ रहा हूं और मेरा भी दसवां बजट सेशन है । मेरे दोस्तों को आप से बाहर नहीं होना चाहिए । जो शख्स यह बात कहते हैं मैं उन की बात कर रहा हूं । मास्टर तारा सिंह यह बात कहते हैं । उन को खुलें बंदों छुट्टी दे रक्खी है । उन को डिफेंस आफ इंडिया के मातहत नहीं पकड़ा जा रहा, उन पर यह लागू नहीं होता । (विघ्न) लेकिन बलरामजी दास टंडन से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गुलज़ारी लाल नंदा हिन्दुस्तान में बदअमनी चाहते हैं ......

उपाध्यक्षा : आप नंदा जी का नाम न लें । (Please do not mention the name of Shri Nanda.)

श्री मंगल सेन : नाम क्यों न लूं उस सत्यानाशी का, बंगाल में गए तो बंगला वालों ने अक्ल ठिकाने लगा दी । वे चाहते हैं कि अब पंजाब के लोग भी इन की अकल ठिकानें लगा दें । अगर उन्हों ने पंजाबी सूबा देना था तो दस साल पहले क्यों नहीं दिया ? क्यों लोगों को भड़काया । प्रताप सिंह कहता था कि मैं झुकने को तैयार नहीं हूं । अगर पंजाबी सूबा देना ही था तो क्यों पंजाब का करोड़ों रुपया आंदोलन को दबाने के लिए खर्च किया ? (विघ्न) मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त जो बड़े काबिल हैं, हर एक की बात को सुनें । अगर आप मुझे इन्ट्रप्ट करेंगे तो मुझे भी इन्ट्रप्ट करना आता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि तीन कानों वाली मंडली जो यहां पर बैठती थी, आज पता नहीं कि कहां गई है, सरदार दरबार सिंह खुद कहते थे कि वह पंजाब की एकता चाहते हैं । इसी वजह से उन्हों ने अपने लैफ्टीनैंट्स को भी छोड़ दिया । आज पंजाब के लोग उन से पूछते हैं कि कहां गई उन की जुरअत । बड़े गांधी के चेले बने फिरते हैं । कहते हैं कि हम बड़े सत्यवादी हैं, सत्यवादी बनने का बड़ा अच्छा तरीका इन्हों ने निकाला है......

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ oppose ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟਸ ਹਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ...... ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ .. .. (विघ्न)

Deputy Speaker : This is no point of order,

श्री मंगल सेन : ऐसा मालूम होता है कि लैफ्टीनैंट को तकलीफ हो गई है ...... कामरेड राम किशन बार बार कहा करते थे कि मेरी सरकार पंजाब की तकसीम के हक में नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम तो यह जानना चाहते हैं कि आखिर जनता को धोके में क्यों रखा ? फिर जब निर्णय के बाद पंजाब की जनता ने पुर अमन तरीके से अपनी नाराज़गी का इज़हार किया तो सरकार ने जान बूझ कर इन्तशार पैदा करने के लिये दफा 144 लगा दिया । आप को मालूम ही है कि जालन्धर और अमृतसर में क्या हाल हो रहा है । आप ही बताएं कि अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करने का डैमोक्रेसी में और क्या पुर अमन तरीका हो सकता है ? इन को चाहिए कि जा कर उन को कनविंस करवाएं, कनविंस तो करवा नहीं सकते उल्टा गोलियों से मासूम जानों का स्वागत करते हैं । सोलह साल की मासूम जान रवीन्द्र कुमार को मार दिया, पब्लिक पर निहत्थे लोगों पर लाठियां और गोलियां चलाईं । आप समझते हैं कि गोलियों और लाठियों से लोगों के जज़बात को दबा देंगे यह नामुमकिन है। जितना ज्यादा आप दबाएंगे उतने ज्यादा जज़बात और भड़केंगे । आप आग न लगाएं, ठंडे दिमाग से इस का हल सोचें । एक तरफ नैशनल इन्टेग्रेशन की बात करते हैं दूसरी तरफ जनता को भड़काने वाली बातें करते हैं । यह जनता को गुमराह करने वाली बात है। मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल ने वादा किया था, जब स्टेट्स रीआर्गेनाइज़ेशन कमिश्न बैठी थी तो बड़ी माथा पच्ची के बाद .....

(Shri Mangal Sein was still on his legs when the House adjourned,)

उपाध्यक्षा : सदन कल मंगलवार 15 तारीख को 11 बजे सुबह मिलेगा ।

5.00 p.m.

(The House will meet on Tuesday, the 5th March, 1966 at 11 a.m.)

The Sabha then adjourned till 11.00 a.m. on Tuesday, the 15th March, 1966.

1636 PVS—386—15-6-65—C., P., & S., Pb., Patiala.

APPENDIX

TO

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I No. 18, dated the 14th March, 1966

Subject:—Unstarred Assembly Question No. 3370 asked by Comrade Ram Chandra, M.L.A., regarding amount paid by the Government to the Panchayat Samitis in the State,

The answer to Assembly Question No. 3370 appearing in the list of Unstarred Questions on 14th March, 1966 in the name of Comrade Ram Chandra, M L A, is not ready, The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

PRABODH CHANDRA,

for Home and Development Minister.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha,
Chandigarh.

U.O. No. 1297-BSIX-66/6316, Chandigarh, dated the 14th March, 1966.

Subject:—Unstarred Assembly Question No. 3376 asked by Shri Fakiria, M.L.A., regarding the amounts collected by the B.D.P.Os. Narwana, Kalayat and Uchana towards Small Savings Scneme.

The answer to Assembly Question No. 3376 appearing in the list of Unstarred Questions on the 14th March, 1966, in the name of Home and Development Minister, Punjab, is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

DARBARA SINGH,

Home & Development Minister, Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha,
Chandigarh.

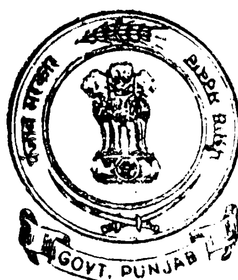
U.O. No. 2279-3CDI-66/6640 Chandigarh, dated the 14th March, 1966.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

15th March, 1966

Vol. I—No. 19

OFFICIAL REPORT



CONTENTS

Tuesday, the 15th March, 1966

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price : Rs. 5.75

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 19, dated the 15th March, 1966

Read	*For*	*Page*	*Line*
19(10)	(10)19	(19)10	Heading
ਡਿਸਟਰੈਸਡ	ਡਿਸ਼ਟ੍ਰੈਰਸਡ	(19)10	4
ਭੁੱਖਾ	ਭਖ	(19)25	32
ਹੋ	ਹ	(19)26	2
ਚਾਹੇ	ਵਾਹੇ	(19)30	20
ਰੋਡਜ਼	ਰੋਜ਼	(19)31	5
ਦਿਤੀਆਂ	ਦਿੱਤਿਆਂ	(19)35	19
ਬੈਠੇ	ਬਠੇ	(19)40	2
ਸੂਬੇ	ਸੂਬ	(19)40	5
ਬਾਬੇ	ਬਾਵੇ	(19)41	35
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ	ਜ਼ਿਜ਼ਮੇਂਵਾਰ	(19)42	19
ਖਿਲਾਫ	ਖਿਲਾ	(19)42	33
ਫੈਸਲਾ	ਫੈਸਲ	(19)42	33
ਫੋਰਸਾਂ	ਫੋਰਸਾ	(19)42	Last line
ਇਜ਼ਹਾਰ	ਇਜ਼ਹਾਰਜ	(19)43	9 from below
ਹਿਫਾਜ਼ਤ	ਹਿ ਾਜ਼ਤ	(19)44	13
ਸੂਬਾ	ਸਬਾ	(19)44	28
ਆਈ	ਆ ੀ	(19)44	28
ਕਾਰਵਾਈਆਂ	ਕਰਵਾਈਆਂ	(19)49	33

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
स्पीकर	स्पाकर	(19)55	14
ਲੈਣਾ	ਲਣਾ	(19)56	4 from below
हरियाणा	हरिवाणा	(19)58	Last
करे	करगे	(19)58	Last
ਇੰਜਣਾਂ	ਇਜਣਾਂ	(19)61	Last
ਦੀ	ਵੀ	(19)63	2
ਹਨ	ਹਨ ਹਨ	(19)63	10
ਕਿ	ਕਿ ਕਿ	(19)64	4
ਤਸੀਂ	ਅਸੀਂ	(19)71	10 from below
पैदा	पदा	(19)73	7
अंगेज़	अंग्रेज़	(19)74	4
प्राईम	प्राई	(19)81	23
मिनिस्टर	मिनिटर	(19)81	5 from below
ਕਾਰਣ	ਕਰਣ	(19)82	4 from below
सिर्फ	सिफ	(19)92	2
आर्डर	आर्डं	(19)93	9 from below
ਇਹ	ਇਰ	(19)94	14 from below
ਪਆਇੰਟ	ਪੁਆਇਟ	(19)97	6 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 15th March, 1966

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh, at 11.00 a.m. of the clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

ADJOURNMENT MOTIONS/CALL ATTENTION NOTICES

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਦੋ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ–ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ । ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤੇਹ ਚੰਦ ਵਿਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ । ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ; ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਹੈ ਨੰਬਰ 55..... (There are two Adjournment Motions given notices of one by Shri Om Parkash Agnihotri and the other by Sardar Ajaib Singh Sandhu. Both of these relate to the Law and Order situation. Similarly, there is a Call-Attention Notice by Chaudhri Mukhtiar Singh Malik, Shri Fateh Chand Vij, Shri Satya Dev and Sardar Kulbir Singh. This is also regarding the law and order. As two hours have been allotted exclusively for discussion on this subject today, all these things can be said at that time. Call-Attention Notice No. 55 has been given by Sardar Ajaib Singh Sandhu.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ....

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ—ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਯਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ....

Mr. Speaker : Please take your seat. This is not proper. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। (The hon. Member may please take his seat. This is not proper. He can have his say during the course of two hours discussion on the subject.)

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहिब, यह जो हमारी काल-अटेनशन मोशन एडमिट हो गई ह, गर्वनमेंट इस पर स्टेटमेंट देगी या नहीं ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰੀਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। (I have stated that the two Adjournment Motions and the Call-Attention Notice of the hon. Member relate to the law and order situation about which two hours discussion has been specially allotted to-day. These have not been allowed but since these relate to the law and order the Government will also reply thereto.)

Does the hon. Member, Sardar Ajaib Singh Sandhu, want to read his Call-Attention Notice ?

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Yes, Sir. It reads—

CALL-ATTENTION NOTICE

(Serial No. 55)

I draw the attention of the Minister concerned to a matter, namely, the revision of pay-scales of the Pharmacists, grant of Rural Allowance to the Pharmacists as is given in the case of Doctors and Health Visitors who are working in the rural areas, House rent and counting of Local Body Service on entering the Government service as recommended by the Director of Health Services, Punjab, about 6, 7, 8 years back but the Government has failed to arrive at any decision in spite of several representations made by the Pharmacists. This inordinate delay has caused frustration and discontentment among the services and particularly Pharmacists in the State. The State Government may make its position clear.

Mr. Speaker : This is admitted.

Chief Parliamentary Secretary : We will make a statement about it.

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहिब, मेरी एक काल-अटेनशन मोशन इस हाउस के आनरेबल मेम्बर श्री टंडन जी की अरेस्ट के बारे थी। वह सवाल तो इस दो घंटे वाली डिस्कशन में नहीं आ सकता। वह तो ऐडमिट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को उस की बाबत जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेह चन्द विज, आप तो एक तजरुबाकार लैजिस्लेटर हैं और आप को पता है कि यह जो अरैस्ट्स वगैरा होती हैं यह भी ला एंड आर्डर की सिचुएशन के सिलसिले में हैं। और मेरा ख्याल है जब कि आज डिस्कशन होगी तो उस पर भी गवर्नमेंट का जवाब आएगा। (The hon. Member, Shri Fateh Chand Vij is an experienced legislator and he knows that the arrests etc. also relate to the law and order situation. And I think that after the matter is discussed to-day the Government would reply thereto also.)

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE PUNJABI REGIONAL COMMITTEE ON THE PUNJAB CATTLE PRESERVATION BILL, 1964

Principal Rala Ram (Chairman, Punjabi Regional Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, as amended by the Punjab Vidhan Parishad.

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE HINDI REGIONAL COMMITTEE ON THE PUNJAB CATTLE PRESERVATION BILL, 1964.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move—

> That the time fixed for the presentation of the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be further extended up to the 15th April, 1966.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the time fixed for the presentation of the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be further extended up to the 15th April, 1966.

Mr. Speaker : Question is—

> That the time fixed for the Presentation of the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be further extended up to the 15th April, 1966.

The motion was carried.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 8 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.... ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ? (When did the hon. Member give notice of his motion ?)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ: 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (That has been admitted. The Government may give statement thereon any day.)

STATEMENTS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to lay statements in reply to the following Call-Attention Notices on the Table of the House :—

(i) Call-Attention Notice No. 52 by Shri Kulbir Singh, M. L. A. regarding removal of leather tanneries from ward No. 5 at Giddarbaha; and

(ii) Call-Attention Notice No. 31 by Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A. regarding demands of teachers working in privately-managed schools etc.

(i) Statement in respect of Call-Attention Notice No. 52 moved by Shri Kulbir Singh, M. L. A. in Budget Session of the Punjab Vidhan Sabha regarding removal of leather tanneries from Ward No. 5 at Giddarbaha.

1. In August, 1964, a complaint was received from Secretary, Mohalla Committee, Ward No. 5, Giddarbaha, district Ferozepore, and other regarding nuisance caused by leather tanneries situated in residential locality (Ward No. 5) of Gidderbaha and a request was made for their removal. In the complaint it was alleged *inter alia* that the President, Municipal Committee, Gidderbaha, was at helm of affairs because he himself was maintaining tanneries in this place irregularly and illegallyand was violating the basic principles of public health. The complainants had requested the Government to safeguard their interests and take necessary action in the matter.

2. The Sub-Divisional Officer (C) Muktsar, suggested that as the Municipal Committee, was not willing to shift the tanneries from that place and had failed to challan the offenders Government may supersede the Municipal Committee, Giddarbaha, under section 238 of the Punjab Municipal Act, 1911, because the committee has failed to perform its functions about the sanitary conditions of the town.

3. The Deputy Commissioner, Ferozepore, reported that the Municipal Committee Gidderbaha had resolved in October,1963, to remove the leather tanneries from the present place to some suitable site outside the town of Gidderbaha but, despite repeated reminders, the Committee did not honour its commitments because its president was one of the tanneries-holders and was putting great hinderence in their removal/shifting. Agreeing with the S. D. O. (C), Muktsar, he suggested that the Municipal Committee Gidderbaha may be superseded under section 238 of the Punjab Municipal Act, 1911. Though Government agreed with the suggestion of the S. D. O. (C), Muktsar and the Deputy Commissioner, Ferozepore, for the supersession of the Municipal Committee, Gidderbaha, they however did not take decision to this effect because elections to this committee were scheduled to be held on the 19th September, 1965, and it was considered desirable to give the new committee a chance to improve the state of affairs. As the elections of the committee along with elections of all other municipal committees scheduled for September, 1965 were postponed, steps were taken to supersede this Committee mainly on account of its apathy in not removing leather tanneries outside the Municipal limits. Consequently, the committee was superseded in January, **1966, and an Administrator was appointed.**

4. It will be seen from the foregoing statement that the leather tanneries being run in Ward No. 5 at Gidderbaha, are a source of nuisance and injurious to the health of the inhabitants of the town. The old municipal committee had issued licences to these tanneries, and these licenses are to expire on 31st March. 1966. The Administrator has been asked not to renew the license and to tackle the problem effectively by giving immediate personal attention to this matter. He has, however, reported that he has not been able to initiate any action because the file relating to the removal of leather tanneries in question has been sent to the court of Executive Magistrate 1st Class, Muktsar, in which case concerning the removal of tanneries is pending. Thus the case is subjudice and no action can be taken in the matter at present.

5. The Administrator will take immediate necessary action in the matter as soon as the matter is decided by the Court and the municipal file is available.

AJMER SINGH,
Planning and Local Government.

(ii) Statement in respect of Call-Attention Notice No. 31 by Comrade Shamsher Singh Josh regarding demands of teachers working in Privately-managed Schools.

Shri Shamsher Singh Josh has given notice of a motion calling the attention of the Education Minister to the demands of teachers working in Privately-managed Schools mentioned in a Memorandum which has been submitted by the Punjab State Recognised School Teachers' Union which has also been circulated amongst the members of the Legislative Assembly and Council. The main demands are the following:—

1. The removal of disparity in the pay scales of teachers working in Government and Non-Government Schools.

2. Appointment of Judicial Officer to decide the disputes between the teachers and the managements.

The Honourable member feels that this matter deserve serious and immediate attention of the Government.

The teachers of the Privately-managed Schools have been representing to the State Government often and on with regard to the following:—

(i) They should be paid Government scales of pay.

(ii) They should have security of service and should not be left at the mercy of the managements who may dispense with their services at their sweet will.

The State Government have been looking into the demands of the teachers working in the Privately-managed Schools and have, from time to time, been trying to ameliorate their lot. Under the existing grant-in-aid rules the Privately-managed Schools which on the grant-in-aid list can pay their staff with requisite qualifications the same scales of pay as are obtainable in Government Schools and these salaries are admitted for the purpose of grant-in-aid. However, the present rules simply provide that the members of the staff should be adequately paid. Wherever the State Government allows a Privately-managed School to charge tuition fees at rates which are 20 percent higher than those prescribed by the Government, undertaking has to be given by the management that the staff will be paid at Government rates.

According to the provisions of Article 232 (iv) of the Punjab Education Code, the managements of the privately-managed recognised schools are required to execute a written agreement with the teachers indicating the terms on which they are appointed. This agreement provides *inter-alia* that any dispute which may arise between the teachers and the management can be referred to an Arbitration Board consisting of the following:—

(a) District Education Officer or his/her nominee;

(b) A representative of the management; and

(c) A representative of the teacher.

Either party may move the District Education Officer within two months of the arising of the dispute. According to an amendment made in the Punjab Education Code in 1963 for the

[Chief Parliamentary Secretary]

purpose of ensuring quick and prompt disposal of such a dispute referred to an Arbitration Board, the District Education Officer is required to announce the final decision within one month of the coming into existence of the Board or within such extended period not exceeding one month as the District Education Officer may allow for reasons to be recorded in writing. In case the Arbitration Board fails to reach a unanimous decision, the decision of the majority of arbitrators shall be final and binding on both the parties. Besides, the District Education Officer is competent to decide the dispute *ex parte*:—

(i) if the party fails to nominate its representative on an Arbitration Board within 15 days of the receipt of notice, or

(ii) if the District Education Officer is satisfied for reasons to be recorded in writing that the Board could not decide the non-cooperative conduct of the nominee of either party or both the parties.

The question of liberalising the grant-in-aid rules is however, receiving, the active consideration of Government. It is proposed to make adequate provision to pay liberal grants-in-aid to the privately-managed recognised schools subject to the adoption of the Government scales of pay and the acceptance of an effective procedure for ensuring security of service to the staff of those schools. Every efforts will be made to achieve the object aimed at by the Honourable Member by making suitable and effective provisions in the proposed liberalised grant-in-aid rules.

शिक्षा मन्त्री : जनाबेआली, मैं आप की इजाज़त से इस स्टेटमैंट के साथ एक दो अल्फाज़ और कहना चाहता हूँ । कल ही मुझे प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के नुमाइन्दे मिले हैं और मैं नें उन्हें कहा है कि जो उनकी तरफ से टीचरों के नुमाइन्दे इस हाऊस में या अपर हाऊस में हैं उन से मिल कर चीज़ें तह कर लें और फिर उन की और डी० पी० आई० के दफतर में अफसरों की एक राऊन्ड टेबल कानफरंस कर ली जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें गवर्नमेन्ट की तरफ से दिलाने की कोशिश की जाए। (प्रशंसा) मगर इस में एक चीज़ यह है कि अगर बिल लाएंगे तो उस में और देर हो जाएगी और जो मतलब है वह फौत हो जाएगा। इस लिये जो ग्रांट-इन-एड के रूल्ज़ हैं उनमें फिलहाल तबदीली कर दी जाए तो इस से भी मसला हल हो सकता है। एन्ड दैट इज़ व्हट वुई आर गोइंग टू डू । (प्रशंसा)

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1966-67 (RESUMPTION)

Mr. Speaker : The House will now resume General discussion of the Budget for the year 1966-67. Shri Mangal Sein was in possession of the House when it adjourned yesterday. But since he is not present in the House so I call upon Sardar Gian Singh Rarewala.

चौधरी दल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । अर्ज़ यह है कि सन् 1964 में मेरे इस विधान सभा का मेम्बर चुने जाने के बाद आज दो बजट सैशन हो चुके हैं । मैंने आप से बार बार रिक्वेस्ट की कि मुझे बोलने के लिये टाईम दिया जाए । चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब को भी कहा कि मुझे टाईम दिया जाए । मैंने इस सिलसिले में पार्टी मीटिंग में भी एतराज़ किया है मुझे टाईम नहीं मिलता । मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ बड़ी ज्यादती है । मैं भी लोगों की तरफ से चुनकर यहां पर आया हुआ हूं । पब्लिक की वोटों से आया हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । (The hon. Member may please resume his seat.)

WALK-OUT

Chaudhri Dal Singh ; I must say whatever I wish to say. मैं बार बार आप के चेम्बर में भी मिलता रहा हूं कि आप मुझे टाईम दीजिए । वहां पर तो गुंडागर्दी हो रही है। रिश्वतखोरी का गढ़ है । ऐसी हालत में मैं एज़ ए प्रोटैस्ट हाउस से वाक आऊट करता हूं कि मुझे बोलने से लिए टाईम नहीं दिया गया ।

(इस समय चौधरी दल सिंह हाउस से वाक आउट कर गए ।)

श्री अध्यक्ष : देखिए, बहुत से आनरेबल मेम्बर साहिबान जब भी मुझे टाइम लेने के लिए मिलते रहे हैं तो मैं उन से यही अर्ज़ करता रहा हूं कि इस आखरी दिन के लिए ही आप अपने आप को रिज़र्व न रखिए । पहिले दिनों में तो वह बोलने के लिए उठते नहीं रहे और सारे ही अगर इस आखिरी दिन बोलना चाहें तो सभी को कैसे एकामोडेट किया जा सकता है । जितनों को एकामोडेट किया जा सकता है किया जाएगा । लेकिन यह कहना कि ज्यादती हो गई है, यह हो गया है, ऐसा कहना मुनासिब मालूम नहीं देता । अभी भी बहुत से ऐसे मेम्बर साहिबान हैं जो कि पिछले पांच सालों में भी नहीं बोल पाए । सो जितना टाइम हमारे पास है उस के मुताबिक कोशिश की जाएगी कि जितने मेम्बर साहिबान को एकामोडेट किया जा सकता है किया जाए । (I may inform that whenever the hon. Members came to see me in connection with allotment of time to them I always told them that they should not keep themselves reserved to speak on the last day of the General Discussion on the Budget. They did not rise to speak on the previous days and if all of them want to speak on the last day, they can not be accommodated. Those who can be accommodated will be allowed to speak. But to say that fairness has not been done and the like does not look proper. Still there are many hon. Members who could not get time to speak during the last five years. So according to the time at our disposal, efforts will be made to accommodate as many hon. Members as possible.)

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1966-67 (RESUMPTION)

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (ਸਰਹੰਦ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘੰਟੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਦਾ ਵਕਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਖਿਆਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹਨ । ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਿਗਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਦਾ ਦਾਨਿਸਤਾ, ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਅਪੋਜ਼ੀਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ) ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਤੱਦਦ ਦਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੀਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਕੁਛ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗਏ । ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੂੰਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦੰਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਦੰਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਯਗਦਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਇਕ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੋ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਅਨਟੂ ਡੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਮਿਨਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਦੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੋਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਦਰਾਨਾ ਰਗੰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹੇਗਾ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਯਗਦੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਦੂਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਲਿਆਉਣ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ. ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟੀ ਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆ ਔਰ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੀਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਰ-ਸਾਈਟਿਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਗੂਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਹਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਅਖਤਿਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਰੋ ਗੁਜ਼ਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਦੰਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਸੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ grim and unprecedented economic distress ਇਹ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੇਨ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਦੰਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਰਸਡ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਸਿਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅਦੰਰ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਖਫੀਫ ਕਰਦੇ । ਅਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੋ ਇਸ ਤਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਕੋਈ ਤੱਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ । 25.24 ਕਰੋੜ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਦ ਇਸ ਕਰਜੇ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਦੰਰ ਆਏ ਸਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਬਕਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1948 ਤੇ ਲੈਕੇ 1965 ਤਕ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਰੀਟੇਰੀਏਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 7 ਸੀ। ਜੋ ਗਜ਼ਟਿਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸਨ ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਕੇ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਟ ਇਹ

ਫਾਈਲਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਂਰਹਾ ਫਾਈਲਜ਼ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹਨ ਮਗਰ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਉ । ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ, ਏਰੀਏ ਆਦਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਡੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਗਜ਼ਟਿਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਕਲਾਸ III ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 32 ਅਫਸਰ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵੀ ਇਥੇ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਹੈ ਇਥੇ ਦੀ ਟਾਪਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਗਵਰਨਰਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਤਵੱਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 1948 ਦੀਆਂ ਜ ਫਿਗਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼, 3 ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼, 4 ਅੰਡਰ-ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਸਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਥੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 17 ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਜ਼, 4 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਜ਼, 5 ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਜ, 45 ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼, 22 ਅੰਡਰ-ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਜ਼ ਇਤਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਤਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਕੇ ਫਿਗਰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । 1948 ਵਿਚ ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 320 ਸੀ ਉਹ ਅਜ 2,226 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਭਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਨੂਮੰਥਈਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਣ ਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਮੰਗਈਆ ਹੋਣ ਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਰਫ 13 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 13 ਡੀ. ਸੀਜ਼. ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਤਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਮਗਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਘੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਤਨਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਸੰਥਾਨਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਅਤੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਤਵੱਕੁਹ ਰਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ 700 ਰੁਪਏ 800 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਜਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 2,700 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2,800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕੰਨਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੌਕਰ ਰਖ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫਰ ਰਖ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਉ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਜ ਕਲ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੈ ।ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਵਕੋ ਰਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਪੇ ਹਿਮ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੋਈ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰੇਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਜਗਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕਤ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ । ਇਥੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਵਕੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੈਟ ਅਫ ਰੂਲਜ਼ ਦਸੇ ਜਾਣ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

TIME LIMIT FOR SPEECHES

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ । ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਚਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਇਮ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਉ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 15 ਮਿੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । (The time of the sitting has already been extended when the law and order situation is to be discussed. If the House agrees a time-limit of fifteen minutes may be fixed for a speech.)

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਜੀ ਹਾਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸ਼ੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ । (The hon. Member Sardar Gian Singh Rarewala may now please wind up.)

GENERAL DISCUSSION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1966-67 (RESUMPTION)

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪਾਸ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱਵਜੋ ਦੇਵੇ । ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰੇ । ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਖਰ ਅਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੱਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ

ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ । ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਕਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲ ਪੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਂਗੋਂ ਤੇਹ ਹੋਈ ਸੀ । ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਪੀਰੀਐਂਸ ਨਹੀਂ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਡੀਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਲਾਹ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਫਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਟੀ. ਏ. ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸਕਰੁਟਿਨੀ ਕਰਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਨਾਨਕੁਆ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਗਾਲਬ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਾਪਰ ਸਕਰੂਟਿਨੀ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 39 ਲਖ ਤੇ ਜਦ ਸਕੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ? ਓਸ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਾਪਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਿਨਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ? ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਉਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੀਫੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗੇਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ।

कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, सब से पहले पंजाब की मौजूदा स्थिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, अपनी ही नहीं बल्कि कांगड़ा के लोगों की तरफ से कि यह जो पंजाब की तकसीम हो रही है और पहाड़ी

[कामरेड राम चन्द्र]

इलाका को हिमाचल प्रदेश में मिलाने का फैसला हमारी खाहिश के मुताबिक है इस लिए हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मशकूर हैं (प्रशंसा) और हम यह चाहते हैं कि इस इदग़ाम के मसला को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस काम को मुकम्मल करने के लिए मैं यह समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमैंट को रीशफल किया जाए और कांगड़ा का एक नुमाइन्दा केबिनेट में लिया जाए ताकि सब लोग बैठ कर आपस में इलाका और एसेट्स की तकसीम का फैसला करें। (प्रशंसा)

दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि मौजूदा स्टेट की हालत जन संघ और अकाली पार्टी ने बिल्कुल खराब की हुई है, इन्हों ने मुल्क में एक गलत फिज़ा पैदा कर रखी है। मैं यह चाहता हूं कि मुल्क में अमन हर हालत में कायम रखना चाहिये, किसी मिस्क्रियंट से कोई लिहाज़ नहीं रखना चाहिये।

दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि मेरे दिल में श्री यज्ञ दत और स्वामी सत्य नंद जी के लिये दिली सत्कार है मगर मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि अगर तो वह सूबे में अमन कायम करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं तो वह जुदा बात है, लेकिन अगर उनका मतलब यह है कि हिमाचल या हरियाणे में जाने से कुछ इलाकों को रोका जाये या कांगड़ा पंजाब में ही रखा जाये तो यह उनकी सख्त गलती है। कांगड़ा वाले अब हिमाचल में जाने पर बज़िद हैं। वह पंजाब में अब रहना नहीं चाहते। यह एक बड़ा अहम सवाल है जिस को अभी तक मामूली चीज़ समझा जाता रहा है और जिस के नतीजे आज हमारे सामने हैं।

अब मैं बजट की तरफ भी आना चाहता हूं। सब से बड़ा अफसोस आज मुझे इस बात पर है कि सरकार ने बजट बनाते वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। मुझे यह कहने में कोई हिचकचाहट नहीं कि पिछले 18 साल से कांगड़ा के इलाके को डिवैल्प करने में सरकार ने ध्यान नहीं दिया और दो फसलों के लगातार फेल होने पर उस इलाका के नुमायंदे ने चीफ मिनिस्टर साहिब का बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि अगर इस इलाके में छोटे-मोटे रिलीफ वर्क्स जारी कर दिये जायें तो इन में काम करके वे लोग कुछ पैसा कमा सकते हैं और इस तरह वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकते हैं।

(इक माननीय मैंबर : पैसे दा तां ही सारा सिआपा पिआ होइआ है।)

लेकिन यह बात सुनी अनसुनी कर दी गई है।

मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि सितम्बर, 1965 में पठानकोट के हवाई अड्डा से 5 मील के फासले तक लोगों की फसलें जो बीजी हुई खड़ी थीं वह डिप्टी

कमिश्नर के आर्डर से कटा दी गई मगर 8 महीनें हो गये हैं उन को आज तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला। मैं इस के मुतअल्लिक चीफ मिनिस्टर साहिब से भी मिला था। उन्हों नें कहा था कि यह मिलटरी का मुआमला है, जल्दी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि उन लोगों ने डी० सी० के आर्डर्ज़ से कटाई का काम एक्सीक्यूट किया है इस लिये सरकार को ही पेमैंट का इंतज़ाम करना चाहिये दूसरी तरफ उन किसानों से मुआमला की वसूली के लिये जबर किया जा रहा है हालांकि सरकार मुआवजा देने में मजबूरी दिखा रही है। सरकार के लिये यह कितनी शर्मनाक बात है।

अभी मेरे बर्ज़ुग दोस्त सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला ने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि जो टैक्नीकल डिपार्टमैंट्स हैं उन में सैक्रेटरीज़ भी टैकनीशियन होने चाहियें। मगर सरकार उनमें आई. ए. एस. आफीसर्ज़ लगा देती है। वह बजाये किसी तरह का अज़ाफा करने के काम में रुकावटें डालते हैं। टैक्नीकल तौर पर उन्हें किसी बात का इल्म नहीं होता। नौजवान हो कर भरती होते हैं जो पैसे लेकर दफतरों में बैठे रहते हैं। पिछली जंग के दिनों में नूरपुर के सब-डवीज़न में हम ने देखा कि वहां पर एक ना-अहल सब-डवीज़नल मैजिस्ट्रेट लगा हुआ था जिस ने डिफैंस के काम में हमारी कोई इमदाद नहीं की। अत: मैं इस बात की ताईद करता हूं कि टैक्नीकल महकमों के सैक्रेटरीज़ टैक्नोक्रैट ही होने चाहियें।

इसके अलावा एक और बात मैं अर्ज़ करूंगा कि मज़दूरों और गरीबों में महंगाई के कारण बेचैनी दिन–बदिन बढ़ती जा रही है। हकूमत यह कहती है कि हम सोशलिज़म की तरफ जा रहे हैं मगर दर असल ऐसा नहीं हो रहा। बड़े–बड़े लोगों की तो और तनखाह बढ़ाई जा रही हैं और छोटी तनखाह वाले मंहगाई में पिस्तें ही चले जा रहे है। हमें एक मयार मुकर्रर करना चाहिये कि ज़यादा से ज़यादा तनखाह 1,000 की हद होनी चाहिये और कम से कम 100 रुपये। इस से किसी को भी कम नहीं देना चाहिये, मगर यहां पर जो 1,000 रुपयें से उपर तनखाहें ले रहे हैं उनको और महंगई अलाऊंस दिये जा रहे हैं। मेरी राय में 500 रुपये से ज्यादा तनखाह हासिल करने वाले को कोई महंगाई अलाऊंस नहीं दिया जाना चाहिये। बड़े-बड़े आफीसर्ज़, कमिशनर्ज़, सैकरेटरीज़, आई. ए. ऐस. और पी. सी. ऐस आफीसर्ज और गज़िटिड स्टाफ जो है अगर इनकी तनखाहें काट कर छोटे अफ़सरान को अधिक तनखाह दी जाये तब सोशलिज्म आ सकता है। मैं ने इंडस्ट्री डिपार्टमैंट के मुताल्लिक एक सवाल भी किया है कि इस महकमा में कितने अफसर और कितने क्लर्क हैं।

आवाजें : आपको पता है तो बता दें।

कामरेड राम चन्द्र : मेरे इलम में इस डिपार्टमैंट में 84 या 86 गज़ेटिड आफीसर्ज़ हैं और 129 क्लर्क हैं। आप बतायें इस प्रोपोर्शन की वजह क्या है। क्या

[कामरेड राम चन्द्र]

कोई गवर्नमेंट इस तरीका से भी चलाई जा सकती है। आफीसर तो बढ़ाए जा रहे हैं मगर दूसरी तरफ छोटे मुलाजमों को न पूरी तनखाह ही मिलती है और न ही उन को महंगाई ही दी जा रही है। इस कद्र महंगाई है कि गरीब मुलाजम और मज़दूर लोग अपने बाल बच्चों का पूरी तरह से पेट भी पाल नहीं सकते हैं।

स्पीकर साहिब, एक चीज जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि अगर सरकार सोशलिज़म की हामी है तो इन बड़े-बड़े अफसरान की तनखाहों में कमी करे और ऐसे अफसरान को हकूमत में रखे जो थोड़ी तन्खाह लें और लायक हों। गवर्नमेंट के कैरेक्टर को देखें तो वही सरकार कामयाब हो सकती है जो फर्म गवर्नमेंट हो। जस्ट गवर्नमेंट ही और आनैस्ट गवर्नमेंट हो। जो लोग कुरपशन करते हैं उनका हरगिज़ लिहाज नहीं होना चाहिये। आज देखने में हर जगह आ रहा है कि कुरपशन ही कुरपशन है। इस के बारे में अपनी अलग राये रखता हूं। मैं कहता हूं कि जब कुरप्ट लीडर होते हैं तो कुरप्शन फैलती है। यहां पर 8 साल तक इस सूबा का कुरप्ट चीफ मिनिस्टर रहा। उस की तहकीकात हुई तो यह साबत हो गया कि यह लोगों के साथ बेइनसाफी करता रहा है। इस के मुताल्लिक मैं दास कमिशन रिपोर्ट से 1-2 लाईनें पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इस में लिखा है

> "There is a case where the Chief Minister himself abused his influence and power for his own beneflt."

Then, it is stated that :—

> "There are cases where the Chief Minister abused his influence and powers, personally and or by or through his colleagues or subordinates, to help his sons or relatives to acquire or dispose of properties or business in violation of law or rules or established procedure.

Further it is stated in the Das Commission Report—

> "......All that this Commission can say, for the consideration of the authorities, is that those several charges thus brought home to the Chief Minister cannot but be regarded as unbecoming of a person holding the high and responsible office of Chief Minister of a State."

और अब कितनी शर्म की बात है कि कुरप्ट चीफ मिनिस्टर के जाने के बाद जो मिनिस्टर बनता है वह उस की समाधि पर जाकर मत्था टेकता है, उसके मैमोरियल कायम करता है उसके लिये सरकारी फंड्ज देता है। अपनी जेब से कुछ नहीं देता। यह एक गलत चीज़ है जिस की मुज़म्मत होनी चाहिये। फंडज़ को इस प्रकार खर्च करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिये।

दूसरी चीज़ मैं कहता हूं कि कुरपशन यहां ही खत्म नहीं होती मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इस बात की मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंने छान बीन करके

अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार ने 1,20,000 रुपया कैरों केस में डिफैंस पर खर्च किया है । यह कानून के विरुद्ध खर्च है । कमेटी ने यह मुआमला सेंटरल गवर्नमैंट को रैफर करने को कहा । इसके इलावा इस रिपोर्ट में लिखा है:—

> "Audit has pointed out that dues amounting to Rs. 13,091 were outstanding against 18 ex-Ministers and Deputy Ministers......"

It is shameful for them not to make payment of amounts due from them. How can they carry on Government if the Minister do not pay dues to the State, if they themselves are dishonest, if they are disloyal to the Constitution and disloyal to the State. स्पीकर साहिब, मैं दूसरी चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूं । यह भी पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की रिपोर्ट है ।

> Under the East Punjab Ministers' Salaries Act, 1947, each Minister is provided with a free furnished house, the maintenance charges of which are borne by the State Government. In March, 1953, the following ceiling limits were prescribed by Government for free supply of electricity and water at the residences of Minister—

X X X X X

उन्होंने लिमिट बताई है । उसके बाद उन्होंने कहा है कि कई मिनिस्टर हैं जिन्होंने दो मकान लिए । हमारे साबका चीफ मिनिस्टर ने दो हाउस लिए । वह कहते हैं कि एक गैस्ट हाउस था । अगर गैस्ट हाउस था तो उसका किराया देना चाहिए था । जो न पिछली मिनिस्टरी ने दिया और न नयी मिनिस्टरी ने मांगा । अब दलील दी जा रही है कि वह गवर्नमैंट गैस्ट हाउस था । पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि अगर यह गवर्नमैंट गैस्ट हाउस था तो बताया जाये कि कौन से लोग थे, उनका क्या दर्जा था और गवर्नमैंट ने कब करार दिया और हुक्म जारी किया कि फलां साहिब सरकारी महमान है । ऐसे महमानों का नाम, पता और खर्च का रिकार्ड और हिसाब दिया जाये । It was misuse of his power and authority and that is why that man was removed from office. It is an act of shame that Ministers are now going to raise memorial to that person at the cost of public funds, public exchequer and not by paying anything from their own pockets. स्पीकर साहिब, लोगों को गलतफहमी हुई है । मेरे दोस्त कह रहे हैं कि प्रताप वाला उनकी तारीफ करता है मेरी राय में जो कुछ पंजाब में हो रहा है जो टेनशन आज पैदा हुई है इसकी ज़िम्मेदारी राम किशन पर नहीं, प्रताप सिंह पर ही है । वह इन झगड़ों को दाग बेल डाल गया था । राम किशन जी के सम्बन्ध में तो यही कहा सकता है कि he has proved to be an inefficient person.

[कामरेड राम चन्द्र]

कांगड़े वालों को जो शिकायत थी, हरियाने वालों को जो शिकायत थी उस को दबाने के लिए प्रताप सिंह जी ने डन्डा इस्तेमाल किया इस तरह डैमोक्रेसी फेल हुई । उनको चाहिए था कि लोगों को प्यार से समझाते। डन्डे से लोगों को दबा सकते हैं। आखिरकार लोग उठे हैं। आज लोग वायलेन्ट हुए हैं । लोगों में इन्तहा बेसबरी आ गई है । पहले वह डन्डे खाते रहे लेकिन आज वह गोली खाने के लिए तैयार हैं । आज के हालात की जिम्मेवारी सरदार प्रताप सिंह के कुरप्ट और टायरिनीकल और अनपापूलर राज पर है ।

Sins of the parents visit upon their children.

कल यहां एक साबक मिनिस्टर सहिब कह रहे थे कि आज ला एन्ड आर्डर की हालत खराब है । वह भूल जाते हैं कि यह उन के ज़माने की लिगेसी है । इस की यह गवर्नमैंट उतनी जिम्मेवार नहीं जितनी कि इस से पहले की गवर्नमैंट । (घंटी)

स्पीकर साहिब, मैं एक दो मिन्ट ही में एक दो बातें और कहना चाहता हूं । मैं ने अभी कहा था कि मिनिस्टरी रिशफल होनी चाहिए जिसमें कांगड़ा के नुमाइन्दे आने चाहिएं । इस बजट में कांगड़ा के लिए जो फन्ड्ज़ अलाट किए गए हैं उन का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए । जब तक कांगड़ा अलग हो कर हिमाचल में शामिल नहीं हो जाता बजट में जो फन्डज़ आएं हैं वह वहां के लिए खर्च किए जाएं । इन सब बातों पर अमल होना चाहिए और पूरे तौर पर अमल होना चाहिए ।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : आदरणीय स्पीकर साहिब 19 साल से यह कांग्रेस सरकार लगातार हर साल अपने फन्डज़ का बजट पेश करती आई है और बढ़ चढ़ कर पेश करती है । आज पंजाब अजीब ढंग से तबाह हो चुका है । जंग से तबाह हो चुका है, कहत से तबाह हो चुका है । लेकिन आज भी सरकार ने एक साल का वही खाता बढ़ चढ़ कर पेश किया है और खसारे का बजट पेश किया है । आज पंजाब की हालत यह है कि लोग नए टैक्स बरदाश्त नहीं कर सकते । इस सरकार ने सब से बड़ी बात 19 साल में यह की है कि अमीर ज़यादा अमीर किए और गरीब ज़यादा गरीब हुए । यह गलत बात है । इस तरह से यह सरकार जो बजट पेश करती है उस से यह दिखाई देता है । इन के वायदे और नाहरे एक ढोंग बन कर रह जाते हैं । मेरी यह इच्छा और भावना है कि इस सरकार का यह आखरी बजट है । स्पीकर साहिब, मैं बजट के दो हिस्से समझता हूं । एक आमदन और एक खर्च का आमदन में न डिफैंस फन्ड का रुपया जमा है, न स्माल सेविंग्ज़ का रुपया जमा है, न रैड क्रास का रुपया जमा है ना गोल्ड बांड का रुपया जमा है, न बिल्डिंग फन्ड का रुपया जमा है । जितने ऐसे फन्ड हैं जो रुपया सरकार जनता से इकट्ठा करती है इस में जमा नहीं है । ऐसे तो रोज़ाना कांग्रेस सरकार में जनता से हर काम में रुपया लिया जाता है उसको इस बजट में कहीं नहीं दिखाया गया । जो रुपया रिश्वत का लेते हैं वह कहीं नहीं । इरिगेशन का महकमा है,

वहां रिश्वत चलती है । वह रुपया कहीं नहीं दिखाया। बिजली के महकमा में भी रिश्वत चलती है । चाहे कोई महकमा है, पुलिस है, चाहे वह माल का महकमा है, चाहे कोई भी महकमा है, पंजाब में दिन दिहाड़े खुल्मखुला रिश्वत ले रहे हैं। जो अरबों रुपया जनता से रिश्वत का लिया जा रहा है उस का एक पैसा भी इस बजट में जमा नहीं है । स्पीकर साहिब, मै आप के द्वारा अर्ज़ करूँगा कि सरकार के बजट में खर्च करने के ढंग अजीब हैं । रुपया जाया किया जाता है । जनता के खून पसीने का पैसा टैक्सों के ज़रिए इक्ट्ठा किया जाता है मगर वह ठीक ढंग से खर्च नहीं किया जाता । पिछले दिनों भिवानी में 27 लाख 60 हज़ार रुपए की सरकार ने एक तजवीज़ बनाई कि वहां पर आबपाशी के ज़राए मुहैय्या किए जाएंगे लेकिन सिर्फ दो लाख रुपया खर्च किया और 25 लाख 60 हज़ार रुपया बजट में जो दिखाया गया था भिवानी तहसील के नाम से वह पता नहीं किस ढंग से हेरा फेरी कर के अपने मतलब के लिए खर्च किया । इसी तरीके से आज जो घघर की स्कीम है उस बारे में किया गया । एक रैक्लेमेशन का महकमा बना है जो अप्रेल, 1964 में कायम किया गया और लाखों रुपया वहां जनता के टैक्सों का बरबाद किया । वहां 92 मील लंबी नहर खोदने की स्कीम थी । मारकंड नदी की तुग्यानी से जो ज़मीन तबाह होती है उस को बचाने की स्कीम थी । यह स्कीम अच्छी थी लेकिन सरकार ने लाखों रुपया खराब कर दिया । वह 92 मील लंबी नहर कामयाब नहीं हुई । हजारों एकड़ ज़मीन खराब हो रही है । हजारों मन सीमैंट और लोहा खराब हो रहा है । मुलाज़मों को बिना मतलब वहां तनखाहें दी जा रही हैं । जनता का रुपया इस तरह सरकार खराब किए जा रही है । स्पीकर साहिब, आप हैरान होंगे कि यहां सूरजपुर फैक्टरी में 2 करोड़ रुपया की मशीनरी मालकान को दे रहे हैं । इस के इव्ज में अपने लिए लाखों रुपया इलैक्शन्ज के लिए फंडज़ का लिया जा रहा है । हरिजन कल्याण फंड का रुपया आपके सामने जनता से उगराहा गया । इस सरकार ने सारे पंजाब में हरिजन और गैर हरिजन का सवाल पैदा कर दिया, जिसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ । फिर भी वह रुपया इक्ट्ठा किया गया । वह रुपया सरकार ने हरिजनों के लिए इक्ट्ठा किया था । इस तरह से सरकार की नीति निहायत ही गलत है । वह पैसा जो सरकार पंजाब में इक्ट्ठा करती है वह उन मदों में खर्च नहीं होता बल्कि सरकार उस ढंग से ख़र्च करती है जिस से कांग्रेस की गद्दी महफूज रहे, जनता मजदूर और किसान जहन्नम में जाएं, पैदावार बढ़े या ना बढ़े । अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो यह होटल बंद कर देंगे और लोगों को भूके मारेंगे । यह है इनकी तरक्की का ढंग और बजट बनाने का ढंग ।

12.00 Noon

बार्डर पर जंग की वजह से जो लोग तबाह और बरबाद हो गए हैं उन को यह 38 रुपए फी फैमिली के हिसाब से सहायता के लिए दे रहे हैं जिन में से 17 रुपए तो मशीनरी पर खर्च होंगे और उस के बाद, 21 रुपए गांव तक पहुंचते २ उन के खर्च हो जाएंगे । अब आप अंदाज़ा

[चौधरी नेत राम]

लगाएं कि वह रोटी कहां से खाएंगे, कपड़ा कहां से लेंगे और फसल कैसे उगाएंगे। उन के बच्चे भूख से मर रहे हैं और उन को मुआवज़ा दे रही है सरकार 38 रुपए, जो कि गांव तक पंहुंचने से पहले ही खर्च हो जाना है। इसी तरीके से, स्पीकर साहिब, चपड़ासी को 30.50 रुपए बेसिक तनखाह और 29.50 रुपए उसे अलाऊंस मिलता है। अब इन के तीन-तीन, चार-चार, बच्चे भी हैं और किसी किसी के बूढ़े मां बाप भी होंगे। तो वित्त मन्त्री साहिब मुझे बताएं कि उन का किस तरह से गुज़ारा होता होगा। इस के अलावा सिवल सैक्रेटेरिएट के जो मुलाज़िम हैं वह 1945 में 150--300 रुपए माहवार पाते थे और आज भी उन का वही ग्रेड है जब कि महंगाई पहले से 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मेरे अनुमान के मुताबिक महंगाई 20 गुना बढ़ गई है। लेकिन 750 % सरकार के मुताबिक बढ़ी है। सरकार ने सिविल सैक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन के जो 1945 में ग्रेडज़ थे उन को अभी तक नहीं बढ़ाया। सरकार ने अपने मन्त्रियों आदि बड़े बड़े अफसरों की तन्खाहें बढ़ाई हैं लेकिन गरीब क्लर्क आदि, गरीब मुलाज़मीन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

चपड़ासियों तथा चौकीदारों की जोकि सरकारी अदारों में काम करते हैं $30\frac{1}{2}$ रुपये माहवार बुनियादी तनखाह है और $29\frac{1}{2}$ रुपए महंगाई अलाऊंस है। असैम्बली के सामने पंजाब के इतने बड़े-बड़े बही खाते का पोथा जिस को बजट कहते हैं, सरकार के वित्त मन्त्री ने पेश किया है। तो क्या मैं वित्त मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह इस छोटे से गरीब चपड़ासी तथा चौकीदार के परिवार, जिसकी संख्या एक आदमी, बीबी, और 3 बच्चे हो का बजट पेश करने के लिए तैयार है जिस से उनका एक महीने के खर्च का निर्वाह हो सके। इन को देने के लिए तो यह कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन दूसरी ओर मिनिस्टरों पर और बड़े बड़े अफसरों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। स्पीकर साहिब, यह गरीबों के लिए एक पाई देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। दुकानदार जैसे इन्कम टैक्स बचाने के लिए एक बही दुकान पर रखता है और एक घर पर रखता है, इसी तरीके से इस सरकार के बजट को जो इन्हों ने हाउस में पेश किया है मैं जाअली समझता हूं क्योंकि दूसरा बजट वित्त मन्त्री के घर में पड़ा हुआ है जिस के अन्दर लाखों रुपया वज़ीरों ने और बड़े-बड़े अफसरों ने खाना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेसी चोर सरकार के चोर वित्त मन्त्री ने जो चोर बजट पेश किया है जिस के अन्दर अपनी जाअलसाज़ी को छिपाने की कोशिश की गई है इस की हम सख्त विरोधता करते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम जी, अब आप वाईंड अप करें। (The hon. Member Chaudhri Net Ram may please wind up now.)

चौधरी नेत राम: स्पीकर साहिब, लूट खसूट की क्या क्या बातें बताऊं। इन्होंने श्री डी० डी० पुरी जैसे सरमाएदार को 12 लाख. रुपया दे दिया है इस लिए कि वह इन के खयाल में गरीब हैं लेकिन दूसरी तरफ 10 हज़ार मुलाज़मों को छांटी करके उजाड़ रहे हैं। यह कमीनी सरकार गरीब मुलाज़मों, मजदूरों और किसानों की आवाज को दबाने के लिए पंजाब में फिरकाप्रस्ती का ज़हर फैला कर फसाद करवा रही है वरना कोई ऐसी बात नहीं जिस में झगड़े की गुंजायश हो। विधान के मुताबिक मांग थी और पुरअमन तरीके से पंजाबी सूबा बन जाना चाहिए था जैसे कि हिन्दुस्तान में दूसरी स्टेटस जबान के अधार पर बनी हैं। लेकिन सरकार लोगों की अवाज़ को दबाने के लिए पंजाब को फिरकाप्रस्ती का अखाड़ा बना कर तबाह करना चाहती है। इब के बाद मैं चीनी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हलवाइयों को जितना चीनी का कोटा मिलता है वह कहते हैं कि हमारे दो दिन से ज़यादा नहीं निकलते, बाकी 28 दिन हम ब्लैक में चीनी खरीदते हैं। तो मैं दो दिन नहीं समझता, मैं मानता हूं कि एक हफता उनका निकल जाता होगा और बाकी जो 23 दिन रहते हैं वह ब्लैक में लेकर इस्तेमाल करते हैं। देहात वाले जो गन्ना पैदा करते हैं उन को सेर चीनी भी नहीं मिलती और वह चीनी ब्लैक में हलवाइयों को दी जाती है। वह ब्लैक में जो तीन रुपए किलो के हिसाब से चीनी खरीदते हैं वह मुनाफा कौन खाता है? वह बड़े बड़े सरमाएदार और मिल मालिक खाते हैं जिन को यह सरकार 12 लाख रुपया दे रही है। इस से साफ ज़ाहिर है कि यह सरमाएदारों की सरकार है और मज़दूर व किसानों की विरोधी है। आज 11 लाख एकड़ ज़मीन सरकार की बेकार पड़ी हुई है जो कि काबले काशत हो सकती है। यह साल में दो हज़ार एकड़ से ज्यादा ज़मीन को ठीक नहीं करते। इस का मतलब है कि उसे ठीक करने के लिए पांच सौ साल से भी ज़यादा वक्त लगेगा। यह क्यों नहीं उस ज़मीन को किसानों को दें देते ताकि वह खुद उस पर मेहनत करके पैदावार करें।

Mr. Speaker : Please wind up now.

चौधदी नेत राम: स्पीकर साहिब, हमारे उधर किसानों ने धरती को काबले काशत बनाया है लेकिन यह सरकार उन को बेरहमी से नोटिस दे कर बेदखल कर रही है। इन्होंने खुद लुध्याने और हिसार में धरती रिक्लेम करवाई है इस लिए इन को पता होना चाहिए कि ज़मीन को काबले काशत करने के लिए कितना खर्च होता है। इसी तरीके से आज बेदखलियों का तांता लगा हुआ है। और लगातार बेदखलियों का तांता लगा हुआ है। इस तरह पैदावार नहीं बढ़ सकती। आज इस सरकार द्वारा तंग की हुई जनता की इच्छा है और होगा भी ऐसा ही कि यह इस सरकार का आखरी बजट सैशन है और आयंदा यह सरकार जो सरमायेदारों की है नहीं आएगी।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰੈਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ?

श्रीमती शन्नो देवी (जगाधरी) : स्पीकर साहिब, आज बजट की डिसकशन का पाँचवां दिन है और आज मैं आप की वसातत से इस आगस्ट हाउस के मैम्बर साहिबान के सामने जो कुछ मैं आज पंजाब में देख रही हूं और जो मेरी फीलिंगज़ है वह रखने के लिए मजबूर होकर खड़ी हुई हूं। यह इस असेम्बली का अन्तिम बजट सैशन है और इस तरह के तीन बजट सैशनों में मैं यहां मौजूद थी लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं हाउस में एक ऐसी जगह पर बैठी हूं जहां काफी निज़ाम और ज़बत की ज़रूरत है। आज मैं उसी निज़ाम और ज़बत से प्रेरणा लेकर, स्पीकर साहिब, मैं इस हाउस में खड़ी हुई हूं। इस सूबा में एक बड़ी जाबर हकूमत थी और 1962 तक कभी कोई इधर उधर की बात चलती थी तो हर कोई दोस्त दुशमन सोच कर बात करता था लेकिन जुलाई, 1964 में एक दिन ऐसा वक्त आया कि यहां त्रिमूर्ती का राज कायम हो गया और उन्होंने इस सूबा की हकूमत की बाग डोर अपने हाथों में लेली। जनता को आशा थी, उत्साह था और इच्छा थी कि जो कुछ गल्ती पीछे हुई है वह हटेगी और कुछ नुमायां अच्छे काम होंगे लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और अगर मैं न कहूं तो अपने फर्ज़ से कोताही करूंगी कि 25 साल से लगातार मैं इस असेम्बली की मैम्बर चली आ रही हूं जो आज एडमनिस्ट्रेशन की हालत है वह मैंने पहले कभी नहीं देखी। जो आज मेरे सूबे में हकूमत चल रही है वह इस से पहले कभी नहीं देखी। जो कुछ आज हो रहा है उसे देख कर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर एक ज़बरदस्त लीडर न हो तो कोआप्रेटिव लीडरशिप तो चल सकती है लेकिन वह भी तब चले जब आपस में कोआप्रेशन हो। अगर यह कोआप्रेटिव ढंग से हकूमत चलती तो आज हमें यह दिन देखना न पड़ता जो आज हम देख रहे हैं। इधर उधर से जो आज आवाज़ें उठ रही हैं यह कुछ नहीं हैं। यह सब वही बात है कि कभी कोई वक्त था कि देने की बात कहते थे आज लेने की कहते हैं। आज इस देश की जो हकूमत है उसका हर कोई हिस्सेदार हो जाना चाहता है। अगर एक घर में एक मां के पास सेर भर चूरमा हो और वह आध सेर एक बच्चे को दे दे, पाव भर दूसरे को दे दे, दो छटांक तीसरे को दे दे और किसी एक को खाली अगूंठा ही दिखा दे तो वह भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं। मैंने तो यही बात समझी है कि यह जो माल एडमनिस्ट्रेशन आफ पावर है और सूबा की हकूमत कमज़ोर हाथों में आई है, आज जो कुछ पंजाब में देखने को मिल रहा है यह उसी का नतीजा है मेरा सिर शर्म से झुक जाता है और मुझे दुख होता है जब मैंने अखबारों में पढ़ा

कि मेरे सूबा के तुलबा को, बच्चों को लड़ाया जा रहा है। मैं पंजाब के सारे भाई बहनों और इस आगस्ट हाउस के मैम्बरान से कहना चाहती हूं कि यह सिंह भूमि यह सिंह द्वार पंजाब जिसने आज भी हिन्दुस्तान की रक्षा की है और जिसने आजादी के लिए ज्यादा से ज्यादा कुरबानियां दीं और बड़े से बड़े रैवोल्यूशनरीज़ और देश-भक्त पैदा किए उस में रहने वाले हम सब को चाहिए तो यह था कि पाकिस्तान को नाकों चनें चबा कर जो नुकसान हम ने उठाया है उस के लिए हम सब मिल जुल कर 10—20 करोड़ रुपया लेकर उन उजड़े लोगों को बसाते लेकिन हमने तो एक काम पकड़ा हुआ है कि रोटी यहां खाएंगे तो पानी देहली पीएंगे, सोएंगे यहां, जागेंगे देहली। 1947 के पार्टीशन के बाद जब हमारी हकूमत शिमला में थीं तो उस वक्त हमारे बजुर्ग चीफ मिनिस्टर कभी एक आध बार हफता में देहली में जाया करते थे। क्योंकि वह व्योबृद्ध थे इस लिए मालूम हुआ कि दो हैलीकापटर लिए जा रहे हैं। मैं उसी वक्त सरदार पटेल के पास चली गई और कहा कि, सरदार जी, कि 29 ज़िलों का पंजाब छोड़ कर 12 ज़िलों के पंजाब में आई हूं....उस वक्त 12 ज़िले ही थे पैप्सू नहीं मिला था और पैप्सू के साथ भी जो सलूक किया गया वह भी मुझे मालूम है। तो मैंने सरदार जी से कहा कि इस उजड़े पंजाब के सिर पर इतना बोझ नहीं पड़ सकता। बादली से देहली 12 मील का टुकड़ा है और ओल्ड सैक्रेटेरियट में पंजाब की राजधानी बना दो, सुबह इन को पढ़ा दो और शाम को सुन लो क्योंकि अब शिमला तक जाते रास्ते में भूल जाते हैं (हंसी) लेकिन अब तो यहां हद ही हो गई। जोगा साहिब के सवाल का जवाब मैंने अखबारों में पढ़ा, क्यों कि उस वक्त मैं यहां थी, कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने तीन महीनों की तन्खाह तो ली 4,500 रुपया लेकिन भत्ता लिया, अगर अखबारों में ठीक छपा है, 10 हज़ार रुपया। मैं कहना चाहती हूं कि सरदार प्रताप सिंह जैसा जाबर आदमी, उसे अच्छा कहो या बुरा अपनी अपनी राए है, कत्ल न होता अगर जी० टी० रोड बनी होती। अगर बन जाए तो मिनिस्टरों की गाड़ियां उसे तोड़ देती हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो हम ने स्वप्न लिया था कि भूखे को अन्न देंगे, नंगे को कपड़ा, बीमार की तीमारदारी करेंगे और किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे वह कहां गया और क्या पूरा हो सकता है ? मैंने एक बात उपनिषदों में पढ़ी थी और मैं सोचती थी कि जब हम आज़ाद होंगे तो मैं मिनिस्टरों से पूछ सकूंगी कि क्या यह बात हमारे राज में हमने कर दी है उपनिषदों में एक राजा का ज़िक्र आता है जिसने एक महात्मा से कहा कि मेरे घर भोजन कर लो लेकिन वह महात्मा बोले नहीं, चुप रहे। राजा ने कहा कि महात्मा जी मेरे राज्य में कोई भखा नहीं, नंगा नहीं और अनपढ़ नहीं फिर अन्न क्यों नहीं खाते। हमारे इस राज्य में देखनी चाहिए तो यह चीज़ थी जो राजा ने कही थी लेकिन मैं देख कुछ और रही हूं। हिन्दुस्तान का पार्टीशन हुआ, बड़ी-बड़ी नावाजब बात थी। हमें किसी ने नहीं पूछा कि पार्टीशन करने वाले हैं। लाखों लोग अपनी जायदाद, घर बार छोड़ कर और अपनी बहू बेटियों

[श्रीमती शन्नो देवी]

को छोड़ कर पता नहीं क्या क्या ज़िल्लतें उठा कर इधर आए, लेकिन एक चीज़ हुई कि हम आज़ाद हो गए । यह बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन हम आगे ही चलते गए और पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि हमारा मकसद क्या है । अब यहां तक पहुंच गए जिसे देख कर सिर शर्म से झुकता है, अब तो परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई कि यह त्रिमूर्ती की हर मूर्ती अलग अलग बात करने लग गई । अगर एक एक ब्यान दे, दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा तो बताओ बात कैसे बने । मुझे रंज होता है जब मैं कहती हूं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं । कुछ लोग कहते हैं क्या करें सैक्रेटरी साहिब नहीं मानते हमारा कहना ।

मैं समझती हूं कि वह मास्टर मास्टर कहलाने के काबिल नहीं जिन के अपने स्टूडैंट्स उस का कहना नहीं मानते । मैं भी किसी वक्त यह काम करती थी । मुझे पता है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है । मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि इस समय भी वही सर्विसिज़ है, वही सूबा है और वही जनता है । इस वक्त सरकार को बीमारी की तह तक जाना होगा और ढूंडना होगा कि यह बीमारी कैसे दूर हो सकती है । मैं ने तो कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा और किसी को कुछ नहीं कहा लेकिन आज हरियाणा की तरफ से, इधर उधर से और कांगड़े की तरफ़ से स्टेट को तकसीम करने की बातें हो रही हैं, वह ठीक नहीं है । हमें इस बीमारी की खोज करनी चाहिए कि इस में तकलीफ कहां पर है ।

मुझे हर इलेक्शन के समय में नयी जगह पर पटक दिया जाता है । इस दफा मैं जगाधरी से नुमायंदा हो कर हाउस में आई हूं । मैं अरज़ करना चाहती हूं कि मुझे पत्थर की तरह फैंक दिया जाता है लेकिन मुझे खुशी है कि वहां के लोग मुझे दिल में उपर उठा लेते हैं । मैंने उन के लिएकुछ नहीं किया ।

स्पीकर साहिब, चौधरी रिजक राम दिन में दो बार कोट बदलते हैं । मैं ने उन से एक बात कही थी कि दो लेबर टाउन्ज़ हैं, वहां पर लेबर रहती है । मिल्टरी के लिए हमारे दिलों और देश में इतना प्यार और सम्मान है, हजारों की संख्या में नौजवान वहां पर बैठे हैं । उन्होंने लिख कर दिया । मैंने भी कई बार कहा और वहां के लोगों ने भी लिख कर दिया कि वहाँ के दो लेबर टाउन्ज़ की हालत सुधारी जाए लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । हमारे लेबर मंत्री श्री रिजक राम दिन में अपनी हालत को ठीक करने के लिए दो बार कोट तो बदल लेते हैं लेकिन उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

मैं ने पी. डबल्यू. डी. मिनिस्टर को सड़कों की हालत सुधारने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हम सड़क बना देंगे लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि अगर हमारे में हिम्मत होगी तो हम खुद सड़क बनवा लेंगे । मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि हमें सैंटर से नुक्सान की पूर्ति के

लिए मांग करनी चाहिए क्योंकि पिछली लड़ाई से हमारे पंजाब को बहुत हानि हुई। इस की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या आप ने सोचा कि लड़ाई के समय फिरोज़पुर, अमृतसर, गुरदासपुर ज़िलों और खेमकरण के अन्दर क्या कुछ हुआ। वहां पर कैसे खंडरात हो चुके हैं। मैं समझती हूं कि उस की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को वहां की हालत सुधारने के लिए काम करना चाहिए। आज कल उस मसले की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान से बच निकले हैं और जो कुछ मल्लाहों के सहारे में रहे, वह डूब गए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप तो इस तूफान में डूब गए हैं हमें तो इस तुफान में ना डुबाओ। मैं अपने इस आगस्ट हाउस से दरखास्त करना चाहती हूं कि हमें अपने फर्ज को सोचना चाहिए। हमारे सूबे की जिम्मेवारी कामरेड राम किशन, सरदार दरबारा सिंह, श्री प्रबोद चन्द्र और सरदार कपूर सिंह के ऊपर ही नहीं है बल्कि इस सूबे की ज़िम्मेदारी हमारे सब के ऊपर है। अगर यहां पर गड़बड़ी होती है और इस बारे में इतिहास लिखा गया तो माननीय सदस्यों को पता होगा कि उन के नाम किस सियाही से लिखे जाएंगे (विघ्न) स्पीकर साहिब, मैं आप से प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप सरदार लछमण सिंह गिल को इंट्रप्शनज़ करने से रोकें।

Mr. Speaker : Order please.

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब, माननीय सदस्यों ने हनुमन्थया एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्ज़ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी। माननीय सदस्यों को पता होगा कि उस रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कितने ही कमीशन और कितनी ही कमेटियां बनाई जाती हैं। मुझे तो उस कमेटी में मैम्बर बनाया नहीं जाता। मैं समझती हूं कि उन कमेटियों में कोई काम नहीं होता। अगर हनुमन्थेया की रिपोर्ट को पढ़ कर उस पर अमल किया जाता तो मैं समझती हूं कि हमारे सूबे का कल्याण हो जाता। हज़ारों गरीब आदमियों और छोटे तबके के कर्मचारियों की छांटी की जाती है। मैं पुलिस की ही मिसाल हाऊस के अन्दर रखना चाहती हूं। पुलिस के सिपाही को 100 रुपये से अधिक तनखाह नहीं मिलती। मैं ने इस के बारे में 1940 से कहना शुरु किया। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कहीं मेरी यह बात मान ली और उस ने उन की तन्खाह 100 रुपये कर दी। उस से पहले किसी ने उन की तरफ ध्यान नहीं दिया। आजकल के मंहगाई के ज़माने में 100 रुपये से क्या गुज़ारा हो सकता है? इस से उन का क्या बनता है? लेकिन इस के इलावा हर महकमे के अन्दर जहां पर किसी अफसर की जरूरत नहीं होती वहाँ पर धड़ाधड़ अफसर बनाए जा रहे हैं। जहां पर एक सैक्रेटरी से काम चल सकता है, वहां पर और सैक्रेटरी और अफसर लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त पेपर्ज़ और नोटिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती कि किन किन स्टेजिज़ से हो कर फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं। अगर मैं यह बात टेक अप करूं तो मैं समझती हूं कि यह बातें वर्णन करने से हाऊस का काफ़ी समय ज़ाया हो जाएगा।

[श्रीमती शन्नो देवी]

मैं तो सरदार कपूर सिंह से कहना चाहती हूं कि हम ने अपनी जिन्दगी में देश को आगे ले जाने का निश्चय किया हुआ है। अगर यह अपने गरेबान में मूंह डाल कर देखें तो इन्हें पता लगेगा कि क्या यह देश को आगे ले जा रहे हैं या देश को पीछे ले जा रहे हैं। पहले तो सैल्फलैस वर्कर्ज़ थे और वह देश को सर्वप्रिय समझते थे। वह देश की सेवा करते थे और देश को आगे ले जाते थे लेकिन आज हालत यह है कि हर एक सैल्फ सैल्फ के लिए सोच रहा है। आज कल तो यह हो रहा है कि

लूट पड़े तो लूट, जो न लूटे तो नामाकूल।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि इस समय माकूल लोगों को आगे आना चाहिए ताकि वह देश की सेवा करें। आखिर में माकूल लोगों को मिल कर, और आपस में बैठ कर सोचना चाहिए और इस बीमारी को दूर करने का ढंग निकाला जाना चाहिए कि हम ने देश को आगे किस तरह से ले जाना है। मैं ने जयपुर का सैशन एटेंड किया। वहाँ पर मैंने देखा कि हर सूबे के लोगों ने पंजाब के लोगों की किस तरह से सराहना की। उन्होंने किस तरह पंजाब के निवासियों की तारीफ की लेकिन आज क्या कुछ हो रहा है। आज कल जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज तो जनता हालात को देख कर, सरकार की और लीडरों की हरकतों को देख कर आंसू ही आँसू बहा रही है। मैं कहना चाहती हूं कि इस खिलवाड़ को बन्द करना होगा। हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखना होगा। हर रोज़ किसी न किसी तरफ से चिट्ठियों पर दसतखत कराए जा रहे हैं। वह चीजें हमें छोड़ देनी चाहिएं। इस से देश का भला होने वाला नहीं है।

स्पीकर साहिब, मैं किसी मिनिस्टर साहिब के पास जनता के काम के लिए गई। मैं ने जनता की दरखास्त उन को दी और उन्होंने मान ली। वहाँ पर कुछ दूसरे मैम्बर साहिबान भी बैठे हुए थे। वह मुझे कहने लगे कि मिनिस्टर साहिब हमारी बात तो मानते नहीं और आप की बात मान ली। मैं ने उन से कहा कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। मैं इन से कोई ट्रकों के प्रमिट्स नहीं मांगती हूं। मैं किसी की नाजायज़ सिफारिश नहीं करती। मैं तो माननीय सदस्यों को कहती हूं और वज़ीरों को कहती हूं कि वह नाजायज़ बातें न करवाया करें।

स्पीकर साहिब, मैं आप का शुक्रिया अदा करती हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं खास तौर पर हाउस के माननीय सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरी बातों को शान्तिपूर्ण सुनने का प्रयत्न किया। मैं माननीय सदस्यों से आशा रखती हूं कि हम देश को आगे ले जाने की तरफ बढ़ेंगे।

चौधरी मनफूल सिंह (टोहाना) : स्पीकर साहिब, मैं ने बजट को सरसरी तौर पर ही पढ़ा है। मैं इस बजट को दोबारा इस लिए भी नहीं पढ़ सका क्योंकि यह बजट दोबारा पढ़ने के लिए इंट्रेस्ट भी क्रीएट न कर सका। इस बजट के अन्दर

जिन चीजों को इनकार्पोरेट करना चाहिए था उन को बजट बनाते समय नज़र अंदा[ज़] किया गया । वह चीजें खास कर यह हैं—

Calculation and utilization of funds must be made for the welfare of the State without any discrimination towards any area or any class.

हमें आशा थी कि हरियाणा के इलाके की ओर डिवैल्पमैंट के लिए सरकार ध्यान देगी क्योंकि सरकार ने वहां की हालत का जायजा लेने के लिए हरियाणा डिवैल्पमेंट कमेटी नियुक्त की । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी । जब हम ने बजट को देखने की कोशिश की तो हमें अपने इलाके की उन्नति के लिए कुछ भी नज़र नहीं आया । हम सोचते थे कि जिस तरह से हमारे साथ 17–18 सालों से इम्तयाज़ी सलूक हो रहा है, वह इस बार नहीं होगा क्योंकि सरकार के पास इस सिलसिले में रिपोर्ट आ चुकी है । हम सोचते थे कि हमारे साथ कुछ अच्छा स्लूक होगा । लेकिन क्या हुआ, वह रीवार्ड रीवार्ड बन कर ही रह गया है । आप देखिये कि जहाँ इस हाउस के अन्दर, इस सरकार की तरफ से हरयाणा के साथ इम्तयाज़ी स्लूक बरता जा रहा है वहां कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने भी हरयाणा के साथ इम्तयाज़ी स्लूक किया है । उन्होंने पंजाबी सूबे के सवाल को तो क्लियर कर दिया है लेकिन हरयाणा के बारे में अभी तक कुछ रौशनी नहीं डाली, सारा मामला अंधेरे में ही पड़ा हुआ है । इस इम्तयाज़ी सलूक के जर्मज़ हरयाणा के लीडरों में और हरयाणा के वर्कर्ज़ में भी दाखिल हो चुके हैं । इस का नतीजा बहुत ही बुरा होगा। आप ने यह देखा होगा कि प्रोग्रेसिव इंडीपैंडैंट पार्टी के लीडर चौधरी देवी लाल ने परसनल एक्सप्लेनेशन पर बोलते हुए यह कहा था कि जब मैं अहम हैसियत रखता था तो मैं ने हरयाणा के दो आदमियों को राज्य सभा का मेम्बर बनवा लिया था लेकिन इन राज दुलारों ने क्या करवाया है । खैर मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता और मैं अपने अन्दर इन जर्मज़ को दाखिल नहीं होने देना चाहता । लेकिन इतना ज़रुर कहना चाहता हूं . .

(इस समय पैनल आफ चेयरमैन के सदस्य श्री राम सरन चन्द मितल चेयर पर बैठे ।)

कि अगर दो आदमी राज्य सभा के मेम्बर बन गए तो क्या इस से समझ लेना चाहिये कि हरयाणा को उस के हकूक मिल गए ? हमें तो हैरानी होती है कि इतने बड़े लीडर केवल अपने दो साथियों को राज्य सभा का मैम्बर बनवा कर इक्तफा कर के बैठ जाएं । हर एक क्षेत्र में हमारे साथ इम्तयाज़ी सलूक बरता जा रहा है । जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है उसी वक्त से हमारे साथ इम्तयाज़ी सलूक किया जा रहा है । यह रवाज ही नहीं बल्कि रिवायत कायम हो गई है । इस इम्तयाज़ी सलूक की रिवायत को तोड़ने के लिये हमें कुछ सोचना पड़ेगा । जदोजिहद करनी होगी । पंजाबी सूबा तो बन रहा है लेकिन हरयाणा की किस्मत अभी अन्धेरे में ही है । उधर से स्टेटमैंट दे दी गई है कि अगर हरयाणा का कुछ हिस्सा पंजाबी सूबे में शामिल कर लिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है ।

आवाजें : यह गलत बात है ।

चौधरी मनफूल सिंह : अगर गलत है तो इस की तरदीद करवाइये । खैर, मैं अपने आप को इस बहस मुबाहसे में नहीं डालना चाहता । मैं तो केवल यही दरखास्त करना चाहता हूं कि दोनों ओर के मुफाद को मदेनजर रख कर काम करना चाहिये । देहात में जो किसान मजदूर रहता है उस से भी इम्तयाज़ी सलूक किया जा रहा है । हमारे देश की डीवैल्पमैंट का दारोमदार खेती पर है और खेती बढ़ाने के लिए जरुरी है कि गांव में बिजली पहुंचाई जाए ताकि किसान लोग खेती के लिये पानी हासिल कर सकें । लेकिन हमारी सरकार किसान मजदूर जो कि गांव में बैठा है उस को बिजली पहुंचाने का यत्न नहीं कर रही । मिसाल के तौर मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में भुन्ना, रतिया और टोहाना गांव में ट्यूबवैल तो लगे हुए हैं लेकिन उन को बिजली नहीं दी जा रही । अगर उन गांव को बिजली दे दी जाए तो वे लोग लाखों मन ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं । लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही । हिसार से फतहआबाद तक बिजली की लाईन जाती है लेकिन रास्ते में अगरवा और बड़ौल गाँव लाईन पर ही पड़ते हैं वहाँ पर बिजली नहीं है । बड़े बड़े गाँव को बिजली से महरूम रखा जाता है । हिसार और फतहआबाद में तो हीटर जलते हैं और पंखे चलते हैं लेकिन रास्ते में इतने बड़े बड़े गांव वैसे ही पड़े हुए हैं । इस से ज्यादा इम्तयाज़ी सलूक और क्या हो सकता है । हम ने देखा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अगर किसी पहलू से कुछ नुकसान पहुंचता है तो सरकार उन को किसी तरह से ज़रुर कंपैनसेट करती है और चाहे उस को दूसरे पहलूओं से कितना मुनाफा ही होता हो । लेकिन इस के खिलाफ किसान को चाहे कितना नुकसान होता हो सरकार उन को मुआविज़ा देने की कोशिश नहीं करती । इंडस्ट्रियलिस्टस को चाहे दस लाख या बीस लाख या इस से भी ज्यादा लोन की जरुरत पड़े तो सरकार फौरन दे देती है लेकिन इस के मुकाबले में किसान मज़दूर चाहे कुलैक्टिवली मजमूई तौर पर भी दस बीस या तीस गांव मिल कर भी लोन मांगें तो सरकार देने में गुरेज़ करती है । अगर उन को लोन दे दिया जाए तो वह लाखों मन ज्यादा अनाज पैदा करके देश की उपज में बढ़ावा कर सकते हैं । मेरे इलाके में से यह डीमांड की गई कि फरीदपुर माईनर एक्सटैनशन बना दी जाए और खारा खेड़ी माईनर एक्सटैनशन बना दी जाए और जो खर्च आए वह लैंड रैवेन्यू के साथ ले लिया जाए । बीस गांव ने मिल कर यह डीमांड की है कि इस से देश की पैदावार में इज़ाफा हो जाएगा । लेकिन हमारी सरकार का रवैया देखिये, फाईनैंस मिनिस्टर साहिब का और एल० आर० का रवैया देखिये । वे कहते हैं कि लोन तो दे दिया जा सकता है लेकिन रीकवरी कहां से होगी । जब किसान को लोन देने का सवाल आता है तो रीकवरी की बात सोची जाती है लेकिन इंडस्ट्रियलिस्टस को लाखों रुपये एक एक को दे दिये जाते हैं । उस वक्त रीकवरी की बात इन के सामने नहीं आती । अगर हज़ारों किसान भी मिल कर केवल साठ हज़ार रुपया लोन का मांगते हैं तो इन को देने

में दिक्कत महसूस होती है। कहते हैं कि रीकदरी कैसे करेंगे, इन को खतरा महसूस होता हैं। इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार का रवैया हम से कैसा है। इसी का नतीजा है कि आज चारों तरफ से इस किस्म की आवाजें सुन रहे है।

रोड्ज़ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बदकिसमती समझिये या खुशकिसमती समझिये कि मैं रोड्ज़ बिल्डिंग एडवाईज़री कमेटी में मेम्बर बन गया। मुझे पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से हिदायात हैं कि रोड्ज के बारे में जो खर्च होता है उस का बीस परसेंट विलेज रोड्ज़ पर खर्च होना चाहिये। लेकिन हो क्या रहा है ? केवल पांच परसेंट विलेज रोड्ज़ को बनाने पर खर्च किया गया है। मैं पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर साहिब को इस बात की वधाई देता हूं कि वे चाहते हैं कि विलेजिज में रोड्ज़ ज्यादा बनाई जाएं लेकिन इस बात की गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा कि उन्हों ने साथ ही एक अड़चन पैदा कर रखी है। वह यह है कि उन्हों ने शर्त लगा रखी है कि विलेज रोड्ज़ बनाने के लिए चौथा हिस्सा खर्च गांव वाले देंगे। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जिस किसान को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती वह पैदावार कैसे पैदा कर सकता है। फिर जब उस के पास पैदावार ही नहीं है तो वह सड़कों के खर्च के लिये चौथा हिस्सा कहां से देगा ? इस लिये मैं उन से दरखास्त करना चाहता हूं कि जहां पर उन्हों ने देहात के लिए बीस. परसेंट कोटा मुकर्रर किया है वहां उन को चौथा हिस्सा देने से भी मुस्तसना कर देना चाहिये।

उक्लाने में टैक्सटाईल मिल मंजूर की गई है। लेकिन जब तक मिल के लिये रा मैटीरियल नहीं पहुंच सकेगा उस वक्त तक मिल कैसेक ामयाब हो सकती है ? इतनी बड़ी इंडस्टरी वहां पर कायम की जा रही है तो वहां पर चारों तरफ से रा मैटीरियल को पहुंचाने के लिये भी प्रबन्ध करना चाहिये। इस मतलब के लिए उक्लाने को लिंक रोड्ज़ से और एप्रोच रोड्ज़ से मिला देना चाहिये ताकि मिल को रा मैटीरियल भी पहुंच सके और दूसरी तरक्की भी हो। गवर्नमैंट आफ इंडिया की हिदायत है कि जहां जहां पर भी भाखड़े का पानी पहुंचता है वहां से खेती की प्रोडूयस को मार्किट में लाने के लिये सड़कें भी बनाई जानी चाहियें। हमारी सरकार कहती है कि हम तो हिसार में पहले से ही बहुत सी सड़कें बना चुके हैं। लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा है कि जहां पर भाखड़ा का पानी पहुंचा है और लोगों ने पैदावार में इज़ाफा किया है अगर सड़कें ही नहीं होंगी तो वह उस प्रोड्यूस को कैसे मार्किट में लाएगें ? तो किसान को उस से पूरा फायदा नहीं हो सकेगा। खैर, चेयरमैन साहिब, इस वक्त मैं इस बात पर और ज्यादा न कहता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं।

मैं ऐजूकेशन को लेता हूं। कहा जा रहा है कि इस दफा हम ने बहुत स्कूल खोले हैं और तालीम के तौर पर देहाती इलाकों को बहुत आगे ले जाया जा रहा

[चौधरी मनफूल सिंह]

है । चेयरमैन साहिब, मुझे इस बात का पता नहीं कि हरियाणा में कभी आप ने दौरा किया है या नहीं । मैं वाज़या तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जितनी भी प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगें बनी हैं, जितनी भी मिडल स्कूलों की बिल्डिंगें बनी हैं, जितनी भी हाई स्कूलों की बिल्डिंगें बनी हैं सारी पब्लिक की कन्ट्रीब्यूशन से बनी हैं लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है ? वहां पर उन बिल्डिंगों के अन्दर गधे, कुत्ते और सुअर भरे पड़े हैं । कितने दुःख की बात है, कितने अफ़सोस की बात है कि देहात में रहने वाले लोगों ने अपने पेट को भूखा रखकर, अपने बच्चों के पेट को भूखा रखकर, सर्दियों में अपने आप को नंगा रखकर, बच्चों की तालीम के लिए वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कीं लेकिन वहां पर मन्जूरी अभी तक नहीं मिली । मैं इस सम्बन्ध में श्री प्रबोध चन्द्र जी को मुबारिकबाद ज़रुर दूंगा कि पीछे कुछ स्कूलों की अपग्रेडिंग की और इस बार भी वह कह रहे हैं कि अपग्रेडिंग करूंगा लेकिन आप की मार्फत उन से — जो इस वक्त हाउस में नही हैं — अर्ज करना चाहता हूं कि उस इलाके की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਥੇ ਅਗ ਲਗਾਉਣ ।

(ਵਿਘਨ)

चौधरी मनफूल सिंह : इस लिए आप की मार्फत उन से अर्ज़ करूंगा कि इस तरफ इस बारे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जिस जिस इलाके में लोगो ने अपनी मेहनत से, मुशक्कत से अपने बच्चों को तालीम दिलाने की खातिर बिल्डिंगें बना रखी हैं उन को मन्जूरी जरूर दी जाए। ऐसी बात न हो, जैसा कि हमारे देहात में एक मिसल मशहूर है :

खावे पीवे भौंगरे
जा भौंसे भुडान

यानि आप ने हरियाणा के इलाका से जो आमदनी की है उसे आप मेहरबानी करके उसी इलाके के फायदे के लिए लगाइए । यह नहीं होना चाहिए कि आमदनी तो आप ने देहात से की और कालेज खोले जा रहे हैं शहरों के अन्दर । (घंटी) चेयरमैन साहिब, मैं आप को एक मिसाल देता हूं । भाबड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक गांव है जिस की वोटर्ज़ लिस्ट का नम्बर 7,000 है। वहां पर हाई स्कूल बना हुआ है, बेसिक इन्स्टीच्यूशन बनी हुई है लेकिन बावजूद इस बात के कि वहां से बार बार डिमांड आ रही है, आज तक वहां पर कालिज नहीं दिया गया । इन्होंने कभी नहीं इस बात को सोचा कि वहां पर भी कालेज की जरुरत है और वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए कालेज दिया जाए । चूंकि टाईम बहुत कम है, इसलिए इस बात पर मैं आगे किसी वक्त अर्ज़ करूंगा और अब एक ही बात और कह कर मैं अपनी जगह ले लूंगा ।

कहा गया है कि यहां पर बड़ी फेयर और क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन कायम की जाएगी । मैं आप को बताता हूं कि क्या तमाशा है इस फेयर और क्लीन

एडमिनिस्ट्रेशन का । मैं आप के ज़रिए हाउस में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने उसके लिए ग्रीवैंसिज़ कमेटीज़ बना रखी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ग्रीवैंसिज़ कमेटीज़ हैं । वहां पर एम० एल० एज़० को भी लिया हुआ है । मैं आप को बताता हूं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवैंसिज़ कमेटी में एम० एल० एज़० ने शिकायत पेश की और उस का नक़शा आप की विसातत से पेश करता हूं । ज़िला हिसार की इस कमेटी में शिकायत आई कि पावड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी में आर० डी० 56 और आर० डी० 59 पर कट हुआ है । आर० डी० 56 की बाबत पुज़ीशन यह है कि महकमा का ऐक्स. ई. ऐन. इस बात को मानता है कि यह कट है लेकिन पुलिस ने उस की बाबत कोई ऐक्शन नहीं लिया । इसी तरह से आर० डी० 59 की बाबत अर्ज़ यह है कि महकमा पुलिस का गज़ेटिड अफसर, डी० ऐस० पी० इस बात को मानता है कि यह कट है लेकिन महकमा माल ने अभी तक इस की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप अन्दाज़ा लगाएं कि इस फेयर और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का ही यह नतीजा है कि टेल पर लोग सफ़र करते हैं । वहां पर पानी नहीं पहुँचता जैसे इस बार हुआ कि थोड़ा बहुत जो पानी था वह रोहतक भेज दिया गया और वहां पर लोगों को पानी नहीं मिला । इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे दो चार मिन्ट दिए जिनमें मैंने अपने इन टूटे फूटे ख्यालात का इज़हार किया है। बाकी बातें मैं किसी और वक्त कहूंगा जब कि मुझे मौका मिलेगा।

Mr. Chairman : Sardar Umrao Singh.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਦੋ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਇਕ ਬੁਲਾ ਲਉ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ । (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਪੱਟੀ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ । ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਕੇ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਢਹੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਛਪਰ ਲਥ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੁਕ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਾਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ,

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਜ਼ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਸ ਦਸ ਮੀਲ ਇਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੂਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਜਾਨ ਤਕ ਗਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ (ਵਿਘਨ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੂਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਸ਼ੈਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁਛੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਜਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਐਨੀਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਆਰਡਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੀਪ ਦੈਮ ਪੈਂਡਿਗ"। ਕੀ ਇਹੋ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? (ਵਿਘਨ) ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਥਾਰੀ-ਟੀਜ਼ ਪਾਸ ਪੁਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਉ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਉ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਢਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਈ— ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ— ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਹ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਵਿਘਨ) ਇਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ । ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਿਆ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਰੇਗਾ। ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ : ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਡੀ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਫੇਅਰ ਸੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਟਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੈਡ-ਵਿਨਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਮਰੇ । ਉਸ ਵਕਤ ਉਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 15, 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਵਰਸਲੇ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਟੀ, ਦੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਔਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਕੁਛੜ ਵਿਚ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਕ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਰਾਜ ਜੀ ਪਰਧਾਨ ਆਲ-ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਆਏ ਸਨ, ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾ ਨੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਥਾਰੇ-ਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿਉ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15, 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰੇਟੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15, 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਥਾਰੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਉਹ ਕਰਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਥਾਰੇਟੀਜ਼ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਿਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਨਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਕਹੇ ਉਸ ਗਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ । ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਅਫਸਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਸ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮਾਈਨਜ਼ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲਾਂ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਹਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੇਲ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ । ਉਥੇ ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕੀ ਇਥੇ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਾਈਨਾਂ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ।

Mr. Chairman: Please wind up now.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸ-ਟਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਡਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਗਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹੋ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1947 ਵਿਚ ਉਧਰੋਂ ਰਿਫੀਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ ।

Mr. Chairman: Sardar Lachhman Singh Gill.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ।

Mr. Chairman : The hon. Member should know that he was about to be called but he was not present in the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜ ਲਿਸਟ ਆਪ ਪਾਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ।

Mr. Chairman: The hon. Member must know that only one Member can speak at a time. I have already called upon the hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਥੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਸਮਝੋ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹਨ । ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਂਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਿਕਰੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੂਰਤੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਖੈਰ ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ । ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ 18 ਜਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਲੂ, ਸਪਿਤੀ, ਕਾਂਗੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਇਕਨੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਚੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬਲੈਕਮਾਰਕਿਟੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਮੁੰਡੂ ਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ

1.00 p.m.

ਇਹ ਹਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਧਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਲ ਹੈ ? ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਹਿਤੂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜੀ । ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਜਿਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਿਥੇ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਗਰ ਸਿਖ ਵਸੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਤੇ ਹਰੀਜਨ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਘਟ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਧਕਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ? ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੀ ਹਿਕ ਡਾਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਸਬਾਨਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣਗੇ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ-ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਥੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਸਟ੍ਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੇਰ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਗਲ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਥੇ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਫਸਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਅਗਰ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਥੇ ਅਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਭੁੰਜੇ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਲਗਵਾਉ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 16, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਲ ਵੀ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਗ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਵਾਜ਼ੇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਗਾਂ ਨਾ ਲਾਉ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਦ ਤਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਪੀਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਾ

ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਜ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਲਗਾਉ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੀਸ਼ ਗੰਜ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗੇ ਸੀਸ ਨਾ ਨਿਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸੀਸ਼ ਕਟਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ

ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗ ਤਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਜਾ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣੇ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਏਂ ਬਾਏਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਨਾਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਪਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ । ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਣਪੜ੍ਹ ਤਬਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੀ, ਸੱਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਪ ਉਠਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਬੂ ਆਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ । ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ ਬਾਵੇ ਕੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੋਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਮੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਟੇਟ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ । ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਛਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਖਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ । ਕੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ? ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਵਾਤੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਅਜ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗ ਜ਼ਰਾ ਮਧੱਮ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਅਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਮੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਚਲਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਆਣ ਦੇਣ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਸਿਸਟ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਫੋਰਸਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਗੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ

ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਫਤਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ ਇਹ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸ ਨੂੰ ਲੂਹ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਸਿਸਟ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਜਗਾਹ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਿਸਟ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਹਨ, ਰਾਈਟਿਸਟ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਅਗ ਲਗਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਸ ਵਿਚ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੈ 'ਮਿਲਾਪ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕਲ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

"ਇਸ ਲੀਏ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੋ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਤਾ
ਹੂੰ ਵਹਾਂ ਇਨਕਾ ਯਹ ਹੱਕ ਭੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ
ਕਿ ਵੋਹ ਅਪਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰਜ ਕਰੇਂ"

ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪਰਤਾਪ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

"ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ—
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ
ਫੌਜਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ।"

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਫਿਰ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :-

"ਏਕ ਵਕਤ ਵੋਹ ਭੀ ਆਇਆ ਜਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਵੋਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵਸੀਹ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਔਰ ਸੋਨੀਪਤ ਕਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਏਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋ ਕ਼ਾਟਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਤੀ। ਕੌਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਏਕ ਅਰਸਾ ਸੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉਸ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਬ ਤਕ ਜਹਾਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਕੀ ਸਾਲਾਮੀਅਤ ਕੀ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਪਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀ ਔਰ ਇਸ ਸੂਬਾ ਕੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰਖਾ ਵਹਾਂ 1964 ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਸੇ ਏਕ ਐਸੇ ਸਬਜ਼ ਕਦਮ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਜਿਨਹੋਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਦੀਏ। ਜਿਨ ਕੀ ਕੰਮ-ਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜੈਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਛਿਨ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਨਾ ਇਸ ਸੇ ਕਟ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਕੀ ਖਾਤਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਫਾਨੋਂ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜ਼ਦਨ ਮੇਂ ਮਿਟੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਕਰ ਰਖ ਦੀਆ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ।)

ਅਤੇ ਇਹ ਅਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1952 ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਨਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੀਨੀਐਨਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ? ਇਹ ਇਕ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ । They should learn to stand on their own legs. ਦਿਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਦੀ ਐਡ-ਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਕ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਰ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਇਕ ਐਟਰਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।

ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ! ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹਨ । ਇਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰਾਪ ਦਾ ! ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਬਣੀ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਪਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ-ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਰੂਰਲ ਸਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 63 % ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 32 % ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨੀਲੈਂਡਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੀਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਸਣ । ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਰਲੀ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਗਰੁਪ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Chaudhri Darshan Singh: On a point of order, Madam.

Deputy Speaker I do not allow your point of order.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਹਿਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। I am not afraid of any body. (The hon. Member will not be given time if he speaks by raising a point of order. I am not afraid of any body.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਆਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਐਂਟੀ-ਜਨਤਾ, ਐਂਟੀ-ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ । ਐਂਟੀ-ਪਬਲਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ । ਰੈਵੇਨੀਉ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ । ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਓ. ਰੀਟਰੈਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਚਲਿਆ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਨੂਮਨਥਈਆ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਿਲੀ-ਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ there is no food shortage in Punjab. ਫੂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ? 1964-65 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ– Profiteers and black-marketeers are the greatest enemies of the country. ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ । ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । 'ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਅਤੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ।

ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਟ ਰਹੇ ਨੇ । ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਦਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੀਵ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫੈਮਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ 2 ਤੇ ਕੁਲਹਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਡਿਆਂ 2 ਨੂੰ ਕਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਭਦਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਹੈ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾ-ਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ । ਜਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਡੇ 2 ਬੈਂਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਹੈ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਾਨੌਮੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਕਲਚਰਲ ਇਕਾਨੌਮੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਪੋਲਿਸਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ । ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਬੈਂਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ । ਸ਼ੈਡਲਊਡ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਕਿਊਬਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਖੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ । ਏਥੇ ਕਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ । ਗੰਨਾ ਆਮ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਗੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ, ਜਗਤਜੀਤ ਮਿਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਹੈ । ਗਰੋਅਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਸੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਰਹੁ ਘਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਉ 2 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ । ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਮਣ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੰਨਾ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਉਹ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਕਰਸ਼ਰ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਦੇ ਨੇ । ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਉਥੇ ਗੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ । (ਘੰਟੀ) ਚੌਧਰੀ ਹਰਦੁਆਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ । ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੀਮੂਰਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਹਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ । ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ

ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਲਖ ਜਾਂ 82 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ । ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ । ਸਾਡੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨੇ 'ਮਿਲਾਪ' ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਈ । ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ । ਉਹ ਮੁਤਮੱਈਅਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੇ-ਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਬਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । ਐਤੀਆਣੇ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੁਰਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਡਾ ਭਵਿਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ । (ਘੰਟੀ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਉ । ਅਜ ਇਹ ਜਨ ਸੰਘੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਉ । ਕਿਤਨੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹਥ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਹਨ ਮਗਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਖਰੀਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਰੀਬੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 90% ਹਿੰਦੂ ਅਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]
ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ । ਬਸ ਮੈਂ ਏਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कैसा इनसाफ करती हैं । उधर से आठ आदमी बोल चुके हैं मगर आप हमें टाईम नहीं दे रहीं ।

Deputy Speaker : Let me see the record please.

श्री चांदी राम वर्मा (अबोहर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार कपूर सिंह जी नें जो बजट पेंश किया है वह बहुत मेहनत करके और बहुत लम्बी स्पीच के ज़रिए हाउस के सामने पेश किया है । मेरे खयाल में इस से पहले इतनी लम्बी स्पीच का बजट कभी नहीं पेश हुआ । सरदार जी बड़े फिकर में थें कि कैसे बजट पेश किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने से सूबे के हालात बहुत खराब हो चुके थें । खैर, उन को सारे हालात का जायज़ा लेकर बजट पेंश करने का मौका मिला है । मैं समझता हूं कि सूबे के हालात के पेशेनज़र सरदार साहिब अगर टैक्स न लगा कर घाटे का बजट पेश कर देते तो वह ज्यादा बधाई के पात्र होते । लेकिन फिर भी बहुत सी उलझनों के बावजूद जो उन्हों ने बजट तैयार करने के लिए मेहनत की है उस की मैं दाद देता हूं । मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब के नोटिस में दो चार बातें लाना चाहता हूं, जो है तो बहुत मामूली लेकिन उन पर ध्यान कम दिया जाता है । दो चीज़े हमारे सामने बिल्कुल एसेन्शल सप्लाईज़ की हैं । एक कोयला और दूसरा तेल-डीज़ल, पैंटरोल वगैरा । यह एशिया इनसानी ज़रूरियात के लिए अज़हद ज़रूरी हैं । पंजाब भर में कोयले के डिपो और भट्ठे जो दिए जाते हैं वह गवर्नमैंट जिन को चाहे दे देती है लेकिन चण्डीगढ़ के लिए शुरू से ही कोयले के डिपो देनें का निराला तरीका है । कोयले के डिपू के लिए एक जगह मखसूस की जाती है और उस की नीलामी की जाती है । अभी अभी एक कनाल जगह का प्लाट कोयलें के डिपो के लिए एक लाख 6 हज़ार रुपए में नीलाम हुआ । इसी तरह 7/8 डिपो चन्ड़ीगढ़ के अन्दर चल रहे हैं । जिन की कीमत एक एक लाख के करीब है और आयंदा के लिए अगर कोई डिपो नीलाम हुआ तो उस की कीमत $1\frac{1}{2}$ लाख से कम नहीं होगी क्योंकि बोली में लोगों की आदत होती है कि वह बढ़ जाते हैं । मैं इस पर ऐंतराज़ न करता अगर कुछ तहफ्फज़ भी होता । चण्डीगढ़ में कोयले के डिपो के लिए $1\frac{1}{2}$ लाख तो प्लाट पर खर्च करना पड़ता है और फिर चार दीवारी पर खर्च करना है । दो लाख रुपया लगा कर "कोयले की दलाली और मुंह काला" दो लाख रुपए के तो सूद से ही आदमी आराम की रोटी खा सकता है । लेकिन इस बात का कोयले के डिपो वाले को तहफ्फज नहीं दिया गया । इन के सिवाए बाहिर से कोयला यहां पर आ कर नहीं बिक सकता हालांकि यह शर्त है कि बाहिर से यहां कोयला आ कर नहीं बिकेगा । मगर बावजूद इस के

जो आस पास की मनीमाजरे जैसी जगहें हैं जहां डिपो मुफत में मिल जाते हैं वहां अपना कोयला ले कर यहां पर बेच देते हैं हालांकि कोयला बेंचने के कार्ड भी बने हुए हैं। पता नहीं सिविल सपलाई के आफ़ीसर्ज ने मनीमाजरे के कोयले डिपो-होलडर पर कैसे मेहरबानी कर रखी है वह जितना कोयला चाहे इंजीनियरिंग कालेज में भेज सकता है । मैं मुख्य मंत्री साहिब के नोटिस में भी यह बात लाया हूं । मगर मिनिस्टर्ज को जितनी भी दरखास्तें की जाती हैं उन को लेने वाले पी० ऐज़० होते हैं इस लिए वह बात अंधेरे में ही चली जाती है । लोग कहते हैं कि कोयला बहुत खराब आता है । उस की बात यह है कि दो लाख की लागत लगाने के बाद चण्डीगढ़ में आदमी डिपो चलाता है लेकिन उसे कलकत्ता से सीधा कोयला मंगाने की इजाज़त नहीं है । उस की सप्लाई का इन्तज़ाम सिविल सप्लाईज डिपार्टमैंट वाले ही करते हैं । कलकत्ता से एक डिप्टी डायरैक्टर आए और उन्हों ने कहा कि डिपो होलडर्ज़ का चायस होना चाहिए कि जहां से चाहे मंगवा ले और अगर कोयला खराब हो तो वह कह सके कि हमें अच्छी क्वालिटी का कोयला भेजो । लेकिन उन को वही लेना पड़ता है जो सिविल सपलाईज़ वाले मंगवा कर देते हैं । चाहे उस में मिट्टी हो चाहे केरी हो । इस लिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस सारी चीज़ को एग्ज़ामिन करके सारी शिकायतों को दूर करने का यत्न करे ।

अब मैं दूसरी बात करता हूं । आज एमर्जेंसी के ज़माने के अंदर हमें यह कहा गया है कि इन्डस्ट्री के लिए फिरोज़पुर, गुरदासपुर और अमृतसर के रहने वालों को कर्जे दिए जाएंगे । कर्जे देने के लम्बे चौड़े चिट्ठे बनाए गए हैं लेकिन मंजूर होने के बाद भी लोगों को कर्ज़ा नहीं दिया गया । एक बात का आखिर में मैं खास तौर पर जिकर करना चाहता हूं । अभी एक दिन सरदार गुरचरन सिंह ने हमारे ज़िला के डी. सी. के सम्बन्ध में निहायत ही गलतब्यानी की । मैं उसका जवाब देना चाहता हूं क्यों कि अगर काम करने वाले अफसरों के बारे में इस तरह की गलतब्यानी की जाए तो यह शोभा नहीं देता । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पूना के मिलट्री हास्पिटल के कमांडिंग अफ़सर श्री ओ० सी सेनापती हैं । हमारे जिला के डी.सी. विर्क साहिब का लड़का वहां मिलट्री हास्पिटल में दाखिल था और वह वहां अपने लड़के को देखने गए......

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : *X X X
X X X X

(ਸ਼ੋਰ)

श्री चांदी राम वर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्हें लफज वापस लेने चाहिएं....(शोर)

*Note—Expunged as ordered by the Chair.

Deputy Speaker : Please withdraw these words.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : *X X X
X X X X

(ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker : Please withdraw these words.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ.......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ that will be expunged. (Whatever has been said by Babu Ajit Kumar will be expunged.)

श्री चांदी राम वर्मा : मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब विर्क साहिब पूना में अपने बीमार लड़के को मिलट्री हास्पिटिल में देखने गए तो वहां के उस कमांडिंग अफसर ने कहा कि यहां कुछ नौजवान टी. बी. के मरीज़ हैं अगर उनकी कुछ मदद कर सकते हो तो करो । उन्हों ने कहा कि अपने ज़िला के अगर मरीज हों तो उनकी मदद कर सकता हूं । खैर, हमारे वहाँ डिस्टिरिक्ट सिटीज़न कमेटी की मीटिंग ज़ेर सदारत मरहूम सरदार बसंत सिंह मोगा वाले हुई और वहां कुछ रकम पास करके बज़रिया चैक फिरोज़पुर ज़िला के वहां पड़े X X.... तीन चार टी.बी. के मरीज़ों को भेजी गई । उन में से एक आदमी अबोहर का था, एक मुक्तसर का और एक फाज़िलका का था । इस तरह के झूठे अलजाम हाउस में खड़े हो कर लगाना अच्छा नहीं लगता । वह अफसर जो अच्छे काम करे उसकी तो सराहना करनी चाहिए ।

अब मैं कहना चाहता हूं कि मुलाज़मीन की हालत अच्छी नहीं । उनकी मदद की जानी चाहिए । (घंटी) अच्छा जी, बैठ जाता हूं ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज जो पंजाब में हालात हो रहे हैं उनके लिए यह सरकार जिम्मेदार हैं । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंजाबी सूबा की मांग को तो पूरा कर दिया लेकिन हरियाणा प्रांत की मांग जो इस से भी पुरानी मांग चली आती थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा । हरियाणा प्रांत की मांग आज से नहीं, 1857 के वक्त से चली आती है । हरियाणा की 90 फी सदी आबादी गांव में रहती है और वह सारी की सारी

*Note—Expunged as ordered by the Chair.

हरियाणा प्रांत बनाए जाने के हक में हैं । यह जो चंद आदमी शहरों में हैं, जन संघ और आर. एस. एस. के वर्कर्ज़ हैं और डी.एज़. वी. कालिजों के प्रोफैसर्ज़ हैं, वही यह सारी आग भड़का रहे हैं । वरना कोई ऐजीटेशन इसके खिलाफ नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह गवर्नमैंट इस का इन्तज़ाम न कर सकी तो हम हरियाणा के लोग इन्तज़ाम करने के लिए तैयार हैं और वहां पत्ता तक नहीं हिलने देंगे । अब यह हाल है कि वहां जो वाकियात हुए हैं उनके लिए ज़िम्मेदार किसी जन संघी वर्कर को ग्रिफतार नहीं किया गया है । वहां के ऐस. डी. ऐम. और डी. सी. ने खुद यह सारी आग भड़काई है वरना वहां पूरा अमन चैन था । वहां के लोग जनसंघी नहीं क्योंकि पिछले चुनाव में जन संघी उमीदवारों की ज़मानतें ज़बत हो गई थीं । आप ने भी, डिप्टी सपीकर साहिबा, तकरीर करते हुए चेतावनी दी थी कि पंजाब कमजोर हाथों में न रहे । फिनांस मिनिस्टर साहिब बैठे हैं, मैं उन से कहता हूं कि जो वातावर्ण आप ने पैदा किया है उसे कंट्रोल करें वरना अगर यह आग गांव तक फैल गई तो पता नहीं पंजाब का क्या नकशा बनेगा । (शोर) डिप्टी सपीकर साहिबा, हमें मजबूर हो कर यह मांग करनी पड़ी । हरियाणा डिवैल्पमैंट कमेटी ने अपनी इन्टैरिम रिपोर्ट दी लेकिन फिनांस मिनिस्टर साहिब ने एक लफ्ज़ भी उसके बारे में नहीं कहा । यह ठीक है कि जिस परेशानी के हालात में उन्हों ने बजट पेश किया उसकी मैं उन्हें दाद देता हूं । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर सीगा में हरियाणा के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है । वहां बिजली नहीं और इरीगेशन की हालत बुरी है । टैकनीकल अदारे और इन्जीनियरंग कालिज वहां नहीं । हस्पतालों में न दवाई है और न डाक्टर । जो मरीज़ वहां दाखिल हो जाता है मरे बगैर नहीं निकलता । अब यह शोर इस लिए मच रहा है क्यों कि पंजाबी हिन्दू अब समझता है कि हरियाणा वाले अपना हक ले लेंगे और उनका डाउनफाल आ गया है । आप देख लें पटियाला का एक हिन्दू है राम प्रताप गर्ग जो वहां से आया है । बठिंडा का एक हिन्दु है हरबंस लाल जो सपीकर बना बैठा है और डी.डी. खन्ना चेयरमैनी संभाले बैठा है । इसी तरह बाकी जगह के चन्द पंजाबी हिन्दु सारा कुछ लिए बैठे हैं । अब अपना डाउन फाल आता देख कर पंजाब में आग लगा रहे हैं । अगर हमें प्यार से रखते और हमारे हकूक दबाए न बैठे रहते तो यह बात न होती जो हम कर रहे हैं । पंजाब में हरियाणा प्रांत को हर सीगा में नज़र अंदाज़ किया गया और इसी वजह से वहां की सारी आबादी एक ज़बान से हरियाणा प्रांत की मांग कर रही है । आप देखें सफीदों में इन्डस्टरियल इन्स्टीट्यूट खोलने का फैसला हुआ था लेकिन आज तक नहीं खोला गया । 1962 मे गवर्नर साहिब ने अपने एड्रैस में कहा था कि वहां मिल्क पलांट लगाएंगे और अब की दफा फिर वही वायदा किया गया है लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया ।

2.00 P.M.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा इलाके के अन्दर जितनी भी सड़कें बनाने की स्कीमें हैं, उन पर एक चौथाई भी खर्च नहीं किया

[चौधरी इन्द्र सिंह मलिक]

जा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे हलके के अन्दर 4 स्कीमें मंज़ूर हुई थीं। यह बिजली के बारे में हैं। यह आलाना से कालवा आंटा से रोढ़ आदि हैं। इन में से तीन तो मंज़ूर हो चुकी है लेकिन अभी तक उन स्कीमों पर अमल नहीं हो रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन स्कीमों को जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आंटा के निक्ट हज़ारों एकड़ ज़मीन सेम के नीचे आ रही है। वह ज़मीन काबले काश्त नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ज़मीन को रीक्लेम किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार किसानों को वक्त पर फसल के लिए पानी सप्लाई नहीं करती। लेकिन इस के इव्ज़ में किसानों से आबियाना पूरी शरह से ले लेती है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर पानी देने के लिए मीटर लगाए जाएं ताकि किसानों से पानी के हिसाब से आबियाना वसूल किया जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने लोगों को 50 प्रतिशत सबसिडी इन्जनों पर देने का एलान तो कर दिया है लेकिन यह सबसिडी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सरकार से कर्ज़ा ले कर पम्पिंग सैट्स लगाएंगे। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों को भी सबसिडी दे जो किसान खुद अपनी पूंजी से लगाएंगे। सरकार को हर तहसील में ट्रैक्टर के लिए सर्विस स्टेशन खोलना चाहिए। वहां पर ही लोगों को सस्ते भाव पर पुर्ज़े मिलने चाहिएं ताकि किसानों को खेती करने में सहायता मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने एक कमेटी प्रोडक्शन की असैस करने के लिए बिठाई थी। उस की रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह उस कमेटी की रिपोर्ट पर जल्दी अमल करे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ब्लाक डिपार्टमेंट से जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह डिपार्टमैंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिला दिया जाए ताकि उस द्वारा लोगों को कोई लाभ हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं वित्त मंत्री साहिब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब तक हरियाणा प्रान्त अलग नहीं हो जाता तब तक सरकार को वहां की हालत सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए ताकि लोग माननीय वित मंत्री को याद रख सकें।

Deputy Speaker : Sardar Gurbakhsh Singh.

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम । मैं ने अपने हलके की बात हाउस के अन्दर रखनी है । इस लिए मुझे टाइम दिया जाए ।

उपाध्यक्षा : आप के व्हिप (बाबू बचन सिंह) की तरफ से लिस्ट आई है, उस में आप का नाम नहीं है । (I have received from your whip, Baboo Bachan Singh, a list of the hon. Members and your name is not included in it.)

श्री जगन्नाथ : इस का मतलब यह नहीं कि जो कुछ बाबू बचन सिंह ने कहा है, वह ठीक है । मैं ने तो अपने हलके की बातें हाउस के अन्दर रखनी है। इस लिए मुझे टाइम दिया जाए।

Deputy Speaker : The Chair cannot be dictated by an hon. Member. Please take your seat.

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पाकर साहिबा, मैं ने अपने हलके की बातें हाउस के अन्दर बतानी है। अगर मुझे टाइम न दिया गया तो भी मैं ने 10 मिन्ट ऐसे ही वेस्ट कर देने हैं । इस लिए मुझे बोलने के लिए वक्त दिया जाए ।

Deputy Speaker : He must take his seat, otherwise I will have to name him.

Shri Jagan Nath : Sorry, madam.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ (ਧਾਰੀਵਾਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋਨੋ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਉਤੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸਦਾ ਹਥ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ]

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ 5, 6 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਛੁਟੀ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਡੋ ਅੱਡ ਮਿਲੇ, ਇਕ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਬਚੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ 1960 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਿਜ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲਿਜ ਤੋਂ ਕਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਮਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀ ਮਚਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁਪ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ

ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ । ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ । ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਹੈ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ । (The hon. Member Sardar Gurbakhsh Singh may please resume his seat now).

श्री जगन्नाथ (तोशाम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे हल्के भिवानी तहसील में कहत पड़ा हुआ है । वहां रेगिस्तान है । उस के मुताल्लिक गवर्नमेंट रोज़ एलान करती है लेकिन करती कुछ नहीं है । सड़कों का कुछ काम हो रहा था लेकिन चौधरी रणबीर सिंह ने आर्डर कर दिया कि जहां पहले अलाईनमेंट की हुई है 6 लाख रुपया खर्च हो चुका है, उस को बंद कर दो और दूसरी जगह पर काम शुरू करो । वहां पर कहत के हालात हैं , लोग तो वहां पर भूखे थे । कामरेड राम किशन ने, अमृतसर के जन संघियों ने [*× × × ×] मिल कर शरारत की और भिवानी के अंदर भूखे बच्चों पर गोली चलवा दी । चार बच्चे खत्म हो गए, कितने ज़ख्मी हुए और न जाने और भी कितने खत्म हो जाएंगे । उन की तो गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिये थी क्योंकि वे भूखे थ, उन को रोटी मिलनी चाहिये थी । आज सुबह सरदार दरबारा सिंह होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैंने कामरेड राम किशन से कहा है कि या तो ला एंड आर्डर को सम्भालो नहीं तो मैं संभालता हूं । वहां पर कामरेड राम किशन ने अपना अफसर एक. जनसंघी छोकरा एस० डी० ओ० लगा रखा है । उस को कुछ पता ही नहीं है कि ला एंड आर्डर क्या होता है । उसने बच्चों को कत्ल करवा दिया । हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं । कल कुछ आदमियों ने यूनीवर्सिटी में भी शरारत करने की कोशिश की । वहां से जलूस तैयार हो कर नौ बजे के करीब ला कालिज के सामने पहुंचा तो दूसरी *तरफ कुछ हरियाणा के और सिख लड़के भी थे । उन की हिम्मत नहीं शरारत करने की और फिर वह जलूस डी० ए० वी० कालिज में पहुंच गया । वहां पर भी हरयाणा के लड़के थे । उन्होंने कहा कि अगर कुछ करोगे तो खून खराबा हो जाएगा, इस लिये जलूस पांच सात मिन्ट रुका और आगे बढ़ गया स्टूडैंट्स में लाठियां बांटी जाती हैं । भला छोटे-छोटे बच्चों की यह शरारत हो सकती है ? यह तो कामरेड राम किशन की शरारत है [*× × × × ×] इन का रवैया ही यही है कि जहां पर जाते हैं [*× × × ×] करते हैं

*Note :—Expunged as ordered by the Chair.

[श्री जगन्नाथ (तोशाम)]

पिशावर जाएं तो [* × ×] करते हैं, लाहोर में रहें तो [* × × ×] करते हैं । और दिल्ली में जाएं तो भी [* × × ×] करते हैं ।

इन आदमियों और यहूदियों में कोई फर्क नहीं है । यह कहते हैं पंजाबी सूबे को भी रोकना है और हरियाणा को भी नहीं बनने देना । इन्होंने जीपें जला दी हैं, बसों को आग लगा दी और दूकानें जलवा दो । मैं कहता हूं कि अगर आग लगाने से ही सूबे बन सकते हैं, या बनने से रुक सकते हैं तो हरियाणा के लोग हज़ारों लाइनें उखड़वा सकते हैं, बसें जला सकते हैं और आगें लगावा सकते हैं । क्या हरियाणा वाले जंन संघियों से भी कमज़ोर हैं । जिन्होंने कभी ग्राउड् नहीं देखा, स्कूल की गेम्ज़ में कोई पार्ट पले नहीं किया, दही भल्ले खाने वाले जन संघी भला हरियाणा वालों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं । इसी चीफ मिनिस्टर ने ला एंड आर्डर के बारे में अढ़ाई साल पहले एक कमिश्न बैठाया था । उस कमिश्न पर अढ़ाई लाख रुपया खर्च आया लेकिन आज तक उस की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गिया । कमिश्न ने रीपोर्ट दी कि इन्वैस्टीगेशन अफ़सर अलग होना चाहिये और रीपोर्ट को दर्ज करने वाला अफ़सर अलग होना चाहिये । मैं अर्ज़ करूं कि पांच सात दिन हो गए हांसी में एक केस हुआ । पुलिस ने एक लड़के को खत्म कर दिया । आज तक उसकी लाश तक नहीं मिली । इस बेशर्म गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया (आवाजें: शेम शेम) क्या अर्ज़ करूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हज़ारों केस ऐसे होते हैं ।

सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त कहा करते थे कि एक आदमी के हाथ में ताकत है । यह माना कि एक आदमी के हाथ में ताकत थी लेकिन अब तो किसी के हाथ में भी ताकत नहीं है । सब पुलिस अफसर मन मानी कर रहे हैं । उन की अपनी मर्जी है कि किसी केस को रजिस्टर करें या न करें । जन संघियों ने टंडन के इशारे से, डाक्टर बलदेव प्रकाश के इशारे से कहो या [* × × × × ×] के इशारे से कहो....

उपाध्यक्षा: श्री जगन्नाथ जी नन्दा जी का नाम न लो । जहां जहां पर नन्दा का नाम आया है वह एकसपंज कर दिया जाए । (The Hon. Member Shri Jagan Nath should not please mention the name of Shri Nanda. Wherever the name of Shri Nanda has been mentioned it should be expunged.)

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा यही लोग शरारत कर रहे हैं उन को पता नहीं है कि जिस ढंग से यह लोग शरारत कर रहे हैं अगर हरिवाणा वाले भी करगे तो हालात कैसे हो जाएंगे ।

*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

इन का हाल भी वही होगा जो यहूदियों का हुआ था। जन संघी, कामरेड राम किशन [×   ×   ×   ×   ×] को पता लग जाएगा। ये लोग हमारे हरियाणा के अंदर शरारत करवा रहे हैं। हिसार के अंदर एक सिख भाई का होटल था। जन संघियों ने जलूस निकाला तो उस के बरतन उठा कर फैंक दिये। वहां पर तो एक सिख भाई के साथ ऐसा किया है। अगर फिरोजपुर में भी ऐसे हालात हो गए तो यह लोग कहां जाएंगे जन संघी इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना सिख भाई कर जाएंगे। इस लिये इन को या आप समझाएं या कोई और समझाए। ऐसी बातें कोई भी टालरेट नहीं करेगा। हरियाणा के लोग 1962 में चीन की लड़ाई में हज़ारों की तादाद में मर गए थे। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो भी हज़ारों की तादाद में मर गए और अपनी तरक्की के लिये भी हज़ारों की तादाद में ही मर सकते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करेंगे

(घंटी की आवाज़)

मैं इन शब्दों के साथ आप का धन्यवाद करता हूं।

वित्त मन्त्री (सरदार कपूर सिंह): **डिप्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मेम्बर्ज़ ने छः दिन से इस बजट पर बहस की है और कुछ नुक्ताचीनी भी की है। मैं मतवातर छः दिन से उन की नुकताचीनी और उन के ख्यालात को अच्छी तरह से नोट करता रहा हूं। (विघ्न) अब मुझे पंजाबी में तकरीर कर लेने दो।**

ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਸਬਮਾਮੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਲਿਊਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਸਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੌਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੈਸਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ,

*Note: Expunged as Order by the Chair.

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਉਤੇ, ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ—ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਜ ਕਰਕੇ ਛਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ—ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ—ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ....

(*Mr. Speaker in the Chair.*)

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਲ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਉ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਲੈਨ ਮਖਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪਲੈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਲੀ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ; ਇਹ ਦਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨੀਊ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਡਿਊਢਾ ਜਾਂ ਦੂਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।

ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵੇਹੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਡਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡੀਟਰਮਿੰਡ ਸੀ—ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਸੈਂਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਆਈ । ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲੈਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹ ਲਓ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਆਪ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ ਪਏ । ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ $5\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਤੁਸਾਂ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪਲੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਈਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2.2 ਕਰੋੜ ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਆਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗ ਭਗ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਬਸਾਂ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਯਾਨੀ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਰਿਟੇਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 8 ਆਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 8 ਆਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ 8 ਆਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 1961 ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਇਹ 76 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ । ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ । ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਹੈ । (ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨੀਉ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਵੀ ਖੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ 1961 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨੀਉ 4 ਕਰੋੜ 25 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਹ 1961-62 ਵਿਚ 3.98 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1962-63 ਵਿਚ ਇਹ 4.66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 3.13 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਨਤੀਜਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ 1961 ਵਿਚ 4.25 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਹ 3.13 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਟੈਕਸ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨੀਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਅਰਬਨ ਪਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 240 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਮੈਂਡਿਡ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । (ਵਿਘਨ) ਜੋ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨੀਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਦਾ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਫੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿ 13% ਤੋਂ 6% ਕੀਤਾ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ 11 ਲਖ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 68 ਲਖ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਇਨਕਮ ਵਧਕੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ 6 ਕਰੋੜ 81 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਘਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਕਮ ਵਧਾਈ । (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਭੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇੰਕਮ ਵਧਾਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੈ 'ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ' ਨਾਲ । ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ । ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਪਰਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । (ਵਿਘਨ) ਦੋ ਕਰੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਵਧੀ । ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਕਮ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 76 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਸੁਣੀ ਜਾਉ । ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ । ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ । ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਉ । ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਕਮ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕ ਪੈਸਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ । ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫ਼ਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਈਵੇਜ਼ਨ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ-ਵਲੋਰਮ, ਹੋਲ ਸੇਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਈਵੇਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਟੇਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟ ਲਗੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿਤਾ । ਬਾਕੀ ਜਿਥੇ ਈਵੇਜ਼ਨ ਸੀ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਫਿਰ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨਅਰੰਡ ਇੰਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਗਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਇਹ ਅਨਅਰੰਡ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਸੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨ ਦੀ ਲਾਂਗ ਰਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਇਕ ਡੀਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖਾਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਘਟ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵਾਲਵਡ ਨੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫ਼ਿਗਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ । 250 ਕਿਲੋ ਤੇ 5.65 ਹੈ; ਫਿਰ ਕਿਤੇ 11.10, 9.7 ਫਿਰ 10 ਕਿਤੇ 13 ; ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 9.38 ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਏਗੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ।

(*Interruption by Sardar Harchand Singh*)

Mr. Speaker : Sardar Harchand Singh, please do not obstruct the proceedings of the House.

(*Interruption*)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ । (The hon. Finance Minister has only five minutes more at his disposal.)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਇਮ ਘਟ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ।

(ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਠੀਕ ਲਗਾਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿਤੇ 24 ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਕਿਤੇ 36 ਪਰਸੈਂਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਥੇ 24 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸੂਦ ਤੇ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਵੀ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ। (ਹਾਸਾ) ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਅਜੇ ਕਲ੍ਹ ਹੀ 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਹੋਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਦੁਆਨੀ ਦੁਆਨੀ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੌਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੇ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ....(ਵਿਘਨ)।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ......(ਵਿਘਨ) ।

Mr. Speaker : No interruption please.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This is no point of order. Please take your seat.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ 46 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ that would come back to that very fund.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਲਈ ਟਾਇਮ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰੱਪਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । (Order please. The time for reply by the hon. Finance Minister is fixed. So he will not be able to reply to all the points if Points of Order and interruptions are going on like this.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਟਾਇਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਈਟਮ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (Since the time fixed for general discussion on the Budget is over so we take up the next item on the agenda.)

ADJOURNMENT OF THE HOUSE

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, may I suggest 10 minutes adjournment before we take up next item as we are sitting continuously since morning.

Mr. Speaker : I think this is quite all right. I adjourn the House for 15 minutes.

3.00 p.m.

(At this stage the House adjourned and reassembled at 3.15 p.m.)

DISCUSSION ON LAW AND ORDER SITUATION IN THE STATE

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਔਰ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਉਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਜ਼ ਕੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਸਾਦ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਦਫਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਮ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਰੀਵੋਕੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਜਨ ਸੰਘ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਏਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ । ਏਥੋਂ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੈਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰਕੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਕੌਣ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਾਰੇਟੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੀਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ; ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹੋ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਵਾਜਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਾਰੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਅਪਣੇ ਹਡ ਗੋਡੇ ਭਨਾਈ ਜਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਉ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ? ਬਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਜਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ । ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨਸ-ਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੇਫ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਲ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਘ]

ਨਹੀਂ । ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ । ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ । ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਭੇਜਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ । ਉਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ।

Sardar Lachhman Singh Gill : Arrest that Minister and put him behind the bars.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਥਰ ਬਰਸਾਏ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ—

> "The Sisganj Gurdwara became the focal point. Their ranks swollen by a sizeable number of urchins, the Sangh workers converged on the gurdwara from three sides throwing stones in the direction of the gurdwara. The congregation which had remained peaceful till then took up the challenge. After 11 A.M., there was a series of pitched battles and at one stage swords and spears were freely brandished.
>
> Around 2 P.M. the situation appeared to be deteriorating with the police officials and intervening only occasionally and only when the parties were in close combat."

ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ । ਓਥੇ 12 ਜੂਨ, 1960 ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਤ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਓਥੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਨ ਸੁਟੇ ਹਨ । ਪੀਸਫੁਲ ਕਾਂਗਰੇਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਟੀਆਂ ਜਾਣ । ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੁਟ ਲਵਾਂਗੇ । ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡੀਫੈਂਸ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਗੀ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਵੋਕ ਕਰੀਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੋਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ; ਮਗਰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ

ਪ੍ਰੈਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਕ ਹੈ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ-ਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਈਲੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮਿਟਾਏ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ । ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਜੀ ਹਨ । ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਯਗਯ ਦੱਤ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਓਥੇ ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਹੋਣ । ਓਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ । ਓਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਲੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ—ਪਰਦੀਪ, ਪਰਤਾਪ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਮਿਲਾਪ—ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ 60,000 ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ 'ਪਰਭਾਤ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਅਖਬਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚਲਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਗਯ ਦਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਿਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ । ਅਗਰ ਅਸੀ ਵਾਈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸੀ ਜਾਏ ? ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਈਲੈਂਸ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਵਾਈਲੈਂਸ ਦੇ ਬਣੇਗਾ । ਮੈਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਣ । ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ । ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

प्रिंसीपल रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय; कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से जो फैसला हुआ कि पंजाबी सूबा कायम करेगी, पंजाब की तकसीम की जाएगी

[प्रिंसीपल रला राम]

वह एक गलत फैसला था वह एक गलत, नुकसान देह और अफसोसनाक फैसला था। इस लिए कुदरती तौर पर उन लोगों के दिल में जो कि पंजाब के विभाजन, इसकी तकसीम नहीं चाहते थे एक बड़ा भारी रोष, एक बड़े भारी रोष का जज़बा पैदा हुआ। यह रोष किसी फिरके के विरुद्ध नहीं है बल्कि वह इस बात से पैदा होता है कि पंजाब की तकसीम न चाहने वाले लोग लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं। (विघ्न) (शोर) इस लिए यह जो जज़बा, यह जो रोष लोगों में प्रकट हुआ, ज़ाहिर हुआ इस के लिए बहुत हद तक वह प्रापेगंडा भी ज़िम्मेदार है जो मास्टर तारा सिंह जी और उनके अनुयाइयों की तरफ से पिछले छः सात महीनों से खास कर और पिछले कई सालों से आम तौर पर हम सुनते रहे हैं। अगर उस जज़बे का मुज़ाहरा जालंधर के जलूस में न होता और ऐसी किस्म के स्लौगन्ज़ जो बहुत ही इशत्याल देने वाले थे वह न लगाए जाते, जहां तक कि हमारे प्राईम मिनिस्टर की इज्जत पर भी हमला हुआ, अगर यह बात न होती तो मैं यह समझता हूं कि शायद यह गमो गुस्सा इस हद तक न पहुंचता। एक तो वह तकसीम करने का गलत फैसला है और दूसरे मास्टर तारा सिंह जी और उन का विचार रखने वाले जो भाई हैं उन के जो खयालात हैं उस के विरुद्ध यह एक कुदरती तौर पर मुज़ाहरा है। मैं समझता हूं कि इस तकसीम के खिलाफ आवाज़ उठाने का इस प्रजातंत्र लोकराज के अंदर हर एक को हक है। अगर कोई इस के खिलाफ कंस्टीट्यूशनल ढंग से, पुरअमन तरीके से अपने जज़बात का इज़हार करता है तो वह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यह जज़बा जो है वह हिंसा या तशद्दद का रूप धारण कर लेता है तो उस का समर्थन नहीं किया जा सकता और उस को कंडेम करना हरेक शहरी का फर्ज़ अवलीन है। इस लिए मैं यह समझता हूं यह जो पब्लिक प्रापर्टी को आगे लगा कर वायलेंस का तरीका अख्तियार किया गया है इस की जितनी मुज़म्मत की जाए थोड़ी है। इस सवाल के दो पहलू हैं कि यह जज़बा गुस्से का, रोस का क्यों पैदा हुआ। इस को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी के गलत फैसला से हुआ है। मगर जो कोई भी इस आन्दोलन में है उन सब का फर्ज़ था कि कंस्टीट्यूशनल ढंग से कार्यवाही करते। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वायलेंस इस डैमांस्ट्रेशन्ज़ के अन्दर से आई है मैं उस की न प्रशंसा करता हूं, न समर्थन करता हूं बल्कि उस को ज़ार से कंडेम करता हूं, वह कंडेम होनी चाहिए। लेकिन, स्पीकर साहिब, एक बात मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि जो भाई वह चाहते हैं और जिन का ख्याल है कि क्यों कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला हो गया है इस लिए पंजाबी सूबा बनेगा, उन भाइयों का फर्ज़ है कि अपनी तकरीरों के अंदर धमकी आमेज़ बातें कहनी बंद करें। आज लीडर आफ दी आपोज़ीशन ने अच्छे जज़बात का इज़हार किया मगर मुझे अफसोस है कि आखिर

में उन्हों ने फिर भी धमकी दी है। मैं उन की बहादरी समझूंगा और उन की प्रशंसा करूंगा अगर वह अपने आदमियों को उपदेश करें कि प्रोवोकेशन के बावजूद भी उन की तरफ से वायलेंस नहीं होगा। अगर वह ऐसा कहते तो मैं इस बात की तारीफ करता लेकिन हसब मामूल, हसब आदत इस दफा भी उन्हों ने धमकी दी है। मैं समझता हूं कि यह उन्हों ने अच्छा नहीं किया। मैं कहता हूं कि दूसरी तरफ के जो जज़बात हैं उन को समझने का यत्न करना चाहिए। मास्टर तारा सिंह और उन के विचार के जो लोग हैं उन्हों ने एक जज़बा पदा किया है। मैं पिछले शनिवार को अपने हलके में गया था, और मैं ने उस दिन एड्रैस किया कि आप की तरफ से कोई तशद्दद नहीं होना चाहिए तो उस समय एक भाई ने, जो डाक्टर है और मंडल कांग्रेस का सेक्रेटरी है, कहा कि जिस दिन ऐलान हुआ था उस के दूसरे दिन हमारी एक पड़ोसन हमारे घर आई और बड़े मासूम तरीके से उस ने कहा कि बहन जी आप ने तो यह मकान छोड़ कर अब चले जाना है, तो जब आप जाएंगे कृपा करके यह मकान हमें खुद ही दे कर जाना। यह उस का अपना ख्याल नहीं था, कुछ लोग इस किस्म के मौजूद हैं जिन्हें आप को समझाना होगा। मैं चाहता हूं कि अमन रखा जाए। उस के लिए आप सब भाइयों को गवर्नमैंट के साथ तुआवन देना चाहिए। कई भाई कहते हैं कि हमारे कुछ मिनिस्टरों ने कहा था कि हम पंजाबी सूबा नहीं बनने देंगे। तो अब जब बन गया है तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह अमन कायम रखेंगे। मैं उन को गोशगुज़ार करना चाहता हूं कि वह कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की बनावट को नहीं समझते। जिस वक्त रिजनल फारमूला आया था तो मुझे याद है कि कैरों साहिब उस के खिलाफ थे। जब सच्चर फारमूला आया तो उस वक्त भी कैरों साहिब उस के खिलाफ थे। लेकिन जब हाई कमांड ने पास कर दिया तो उन्हों ने बड़ी ईमानदारी के साथ उस को इंप्लीमेंट करने का यत्न किया। इस लिए यह शुभात करने कि यह गवर्नमैंट इमानदारी से ला एंड आर्डर कायम नहीं रखेगी यह गलत बात है। यह कांग्रेस के दयानतदार सच्चे सिपाही हैं। अगर हाई कमांड ऊपर से आज्ञा देगी तो यह नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर स्टेट के अन्दर ला एंड आर्डर को मेंनटेन करने की कोशिश न करें। इस लिए ऐसे शुभात रखने गलत हैं। लोगों के अंदर, स्पीकर साहिब, एक गुस्से का जज़बा है, उसे काबू करने के लिए आखिर वक्त लगेगा। ला एंड आर्डर को मेंनटेन करने के लिए हमारी गवर्नमैंट 100% कामयाब रहेगी। यह ख़याल करना कि यह लोग जिन्हों ने सारी उमर देश सेवा के लिए लगाई है यह ला एंड आर्डर मेंनटेन करते में कोताही करेंगे यह सख़्त गलती है। मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि जो भी आदमी फिरकाप्रस्ती के नाम पर लोगों को उत्तेजना या इशत्याल दिलाता है, या लूट मार करता है या मकानों वगैरा को आग लगाता है उस को फर्म हैंड से डील करना होगा, उस की रूरियात नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पिछले तीन चार दिन से गवर्नमैंट ने जिस मज़बूती के साथ सिचुएशन को

[प्रिंसीपल रला राम]

कंट्रोल करने का यतन किया है हमारी सरकार ला एंड आर्डर मेनटेन करने में हर तरह से कामयाब रही है और आयंदा रहेगी । आप भाइयों से मैं कहूंगा कि आप लोगों के अंदर एतमाद या विश्वास का जज़बा पैदा करो और इशत्याल अंग्रेज़ धमकियां देना बंद करो क्योंकि उस से वातावरण खराब होता है ।

आप का धन्यवाद ।।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਚਰਚਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਪੁਜੀਏ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੀ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਅਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਧਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ (Thumping) ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ—ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ., ਰਿਪਬਲਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਗਰਜ਼ੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ — — — —

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ; ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿਉ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਅਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਦਅਮਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ

ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਲੁਟ ਮਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮਿਟਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜੰਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ....(ਸ਼ੋਰ) ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰਖਣੀ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਗੇ, ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਖੜੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਨਸੰਘੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਪਰਦੀਪ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਅਪਨੇ ਵੋਟਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਗਦਾਰੀ ਹੈ" ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜੰਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੇਡੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੇਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੜ ਬੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੰਘ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੜ ਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਚਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਗੋਲੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. 1960 । ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜੰਨ ਸੰਘੀ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸ਼ੋਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਜ ਤਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀਉਲਜ਼ਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫੱਟੇ. ਵਗੈਰਾ ਲਾਹਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਈਏ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਨਾਂ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਮਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ... ——

Mr. Speaker : Please wind up now.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ......(Thumping)

Mr. Speaker : Please stop now.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜੇਕਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਹਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : स्पीकर साहिबा, मैं इस समय केवल पंजाब की ला एंड आर्डर की सिच्यूएशन तक ही सीमित रहूंगा । सब से पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहिब

की पिछली स्टेटमेंट जो ला एंड आर्डर के बारे में दी गई, उस का जिक्र करना चाहता हूं । आज से चन्द रोज पहले हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर साहिब लगातार कहते चले आए थे कि पंजाब की सरकार इस बात पर पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि पंजाब के अन्दर ला एंड आर्डर कायम रखा जाएगा । उन ब्यानों से साफ जाहिर होता था कि उन को पता था कि पंजाब के हालात किसी भी वक्त खराब हो सकते हैं और वह इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं । मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में क्या जवाब देगी कि इस वक्त पंजाब का ला एंड आर्डर उन के काबू में है या नहीं अथवा ला एंड आर्डर तसल्ली बख्श है या नहीं । जब सरकार इस बात का जवाब हाउस के अन्दर देगी तो पता लग सकेगा । मैं इस समय जालन्धर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहिब ने जो नोटिस वरनैकुलर अखबारात को दिया, वह हाउस के अन्दर पढ़ना मुनासिब समझता हूं। वह यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने वरनैकुलर अखबारों को आदेश दिया कि "पंजाब के हालात काबू से बाहिर हैं और पंजाबी सूबा के सम्बन्ध में कोई समाचार चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो, वह अखबारों में सैंसर किए बिना छापा नहीं जा सकता है ।" मैं नहीं जानता कि इस बारे में सरकार की क्या पोज़ीशन होगी लेकिन ज़िला जालन्धर के डिप्टी कमिश्नर साहिब ने जो सर्टिफिकेट दिया है, उस से पंजाब की ला एंड आर्डर की पोज़ीशन वाज़ेह हो गई है कि पंजाब के हालात काबू से बाहिर हैं इस लिए वहां पर अखबारों को सैंसर करना पड़ा है । पंजाब के अन्दर 4,5 दिन में जो कुछ हुआ, वह निहायत ही काबले अफसोस है । वह निहायत ही शर्मनाक है । आपने देखा होगा कि लोगों ने पब्लिक प्रापर्टी को और प्राइवेट प्रापर्टी को कितनी बेरहमी से जलाया है । पंजाब के अन्दर जितनी बेचैनी है वह भी माननीय सदस्यों को मालूम है । इस के अलावा इस तनाव में स्टूडैंट्स को गुमराह किया गया जिससे कई कीमती जानें चली गई हैं; वह भी बहुत अफसोसनाक बातें हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को ला एंड आर्डर मेनटेन करने के लिए अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए । सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा होना चाहिए और जनता को दोनों पर भरोसा होना चाहिए कि वह हालात को काबू में रखेंगे । आज हालात क्या हैं । आज से चन्द रोज़ पहले यूनियन होम मिनिस्टर ने पंजाब के हालात का जायज़ा लेने के लिए पंजाब के पोलीस आफीसर्ज़ और दीगर बड़े बड़े अफसर बुलाए । उन्होंने यह आफिसर्ज़ मिनिस्टरों के साथ बुलाए ताकि पंजाब के हालात का अनुमान ले सकें । शायद उन को हिदायत देने के लिए बुलाया गया हो । इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब की मिनिस्टरी के ऊपर केन्द्रीय सरकार का कितना भरोसा है । इस के बाद यूनियन होम मिनिस्टरी के स्टेट मिनिस्टर पंजाब का जायज़ा लेने के लिए आए अथवा आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा कि दिल्ली से एक सीनियर आफिसर भी पंजाब के हालात का जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं । मैं नहीं जानता कि इस के बीच में क्या बात है लेकिन एक बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार को अपने ऊपर विश्वास नहीं । दूसरी बात मैं यह कह सकता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट

[श्री मोहन लाल]

4.00 P.M. को पंजाब सरकार की कैपेसिटी पर भरोसा नहीं है कि वह पंजाब के अन्दर ला एंड आर्डर मेनटेन कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि जब हमारी सरकार कहती रही है कि वह पंजाब के अन्दर हर प्रकार की हलचल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो आज हालात काबू से बाहर क्यों हैं। आज पंजाब के अन्दर ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि कि अमृतसर से ले कर भिवानी तक आग सुलग चुकी है। शायद पंजाब के अन्दर कोई भी शहर नहीं जहां पर यह आग सुलगी न हो। पंजाब के अन्दर ला एंड आर्डर मेनटेन करना सरकार का काम है। मैं समझता हूं इस में सरकार स्वयं धोखे में रही है।

स्पीकर साहिब, मैं इसी सिलसिला में कहना चाहता हूं कि हमें हाउस के अन्दर और हाउस के बाहिर कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं जिस से फिरकाप्रस्ती को प्रोत्साहन मिले। मैं ने कल भी कहा था कि हमें पंजाब के अन्दर हिन्दु और सिखों को भाई भाई की तरह रहना होगा। इन्हें प्यार से रहना होगा। इस लिए हर एक का फर्ज़ है कि हाउस के अन्दर या बाहिर कोई भी नफरत पैदा करने वाली बातें न कही जाएं। इस में कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, किसी को भी ऐसी नफरत पैदा करने वाली बातें नहीं करनी चाहिएं जिस से कि पंजाब के हालात में और गड़बड़ी होने का अन्देशा हो। यहां पर मेरे से पहले कुछ दोस्तों ने बातें की, उन की बातों का ज्यादा डिटेलज़ में चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि वक्त कम है। मैं समझता हूं कि यहां पर कुछ बातें ओपनली करना भी मुनासिब नहीं है। कई जगह पोलीस के बारे में इल्ज़ामात लगाए गए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कई जगह पर पोलीस को कंट्रोल करने के लिए इतनी ताकत के प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं थी। इस सिलसिले में मुझे एक ज़िम्मेदार पब्लिक मैन की अमृतसर से चिठ्ठी मिली है जिस को हाउस के अन्दर पढ़ देना मुनासिब समझता हूं। वह यह है कि—

"Encouraged by the attitude of authorities, subordinate officials have not spared even known Congressmen from beating in the bazars before the public who include Sarvshri Avinash Chandra, Municipal Commissioner, Lala Yograj, Chacha Chuni as also myself. I particularly lodged a complaint against this with the both D.C. and the S. S. P. on the advice of Seth Radha Kishen which has remained quite un-heeded."

इस के आगे मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि —

"........the beating mercilessly of innocent by-passers will not bring peace to the life of the city. The District Congress is very clear and united on the point that police particularly has been responsible in creating the present situation."

यह एक ज़िम्मेदार आदमी की तरफ से चिठ्ठी आई है। मैं इस लिए कहता हूं कि सरकार ने जहां कि तशद्दद की ज़रूरत थी, वहां की नहीं और हालात के मुताबिक जहां ज्यादा तशद्दद की। ज़रूरत नहीं थी वहां की। सरकार को हालात का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह से डील करना चाहिए । ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिस से किसी सिटीज़न को और अमन पसंद लोगों को तथा जो लोग सिच्यूएशन को कंट्रोल करन में सरकार की मदद करें, उन को सरकार बुरी तरह से हरास करें । इस लिए सरकार को चाहिये कि अपने इख्तियारात को ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करे । (घंटी)

स्पीकर साहिब, आप का शुक्रिया।

चौधरी देवी लाल(फतेहआबाद): स्पीकर साहिब, आज से 4, 5 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस को अकाली पार्टी, प्रोग्रेसिव इंडीपैंडेंट पार्टी, और कम्यूनिस्ट पार्टी ने एक धमकी समझा था । स्पीकर साहिब, आप को याद होगा कि हाउस के अन्दर श्री बलरामजी दास टंडन ने लफ़ज़ कहे थे कि पंजाब के अन्दर ला एंड आर्डर मेन्टेन करना सरकार का फर्ज़ है । स्पीकर साहिब, वही लोग आज अंडर ग्राउंड हो कर पंजाब के ला एंड आर्डर को भंग करने के लिए सरकार के साथ मिले हुए हैं आज पंजाब के अंदर ला एँड आर्डर खराब हो रहा है। प्रिंसीपल रला राम, चेयरमैन पंजाबी रिजनल कमेटी ने कहा कि पंजाब की तकसीम के बारे में गलत फैसला हुआ है ।

श्री फतेह चंद विज : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । कल आप ने यहां हाउस में डी० सी०, अमृतसर का पैग़ाम पढ़ कर सुनाया था कि श्री बलराम जी दास टंडन अमृतसर जेल में हैं । लेकिन आज चौधरी देवी लाल कह रहे हैं कि वह अंडर ग्राउंड हो गए हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । (Please take your seat.)

चौधरी देवी लाल : पंजाब की तकसीम हुई है या रीआर्गेनाईज़ेशन हुई है, यह फैसला गलत है या ठीक है इस का सबूत इस बात से मिलता है कि इस हाउस के 91 एम० एल० एज़० ने लिख कर दिया है कि हरियाणा प्रान्त और पंजाबी सूबा बनाया जाए और कांगड़ा और लाहौल स्पीती को हिमाचल के साथ मिला दिया जाए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान पंडित भगवद् दयाल शर्मा उस वकत इन ख्यालात के नहीं थे लेकिन जिस वक्त हम ने मैमोरेंडम दिया उस वक्त तक उन का लैटर प्राईम मिनिस्टर के पास पहुंच चुका था । वे भी हम से इत्तफाक रखते हैं । उस समय 15 एम० एल० एज़० हाज़िर नहीं थे । इस का मतलब यह हुआ कि 152 में से 106 एम० एल० एज़ हरियाणा प्रान्त बनाए जाने के हक में हैं, पंजाबी सूबे के हक में हैं । यह बहुत पुरानी मांग थी । जिन

[चौधरी देवी लाल]

भाइयों ने पंजाब के हालात को बिगाड़ कर यह सिलसिला शुरू किया है मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि हम तो एंटी-नेशनलिस्ट थे, अकाली भी माना कि ऐंटी-नैशनलिस्ट थे लेकिन तुम तो नैशनलिस्ट थे तुम क्यों नेशन की प्रापर्टी खराब कर रहे हो ? (प्रशंसा) इस में शक नहीं है कि यह सारी बात सरकार के इशारे से हो रही है । मैं पंजाबी हिन्दु की ज़हनियत ब्यान कर रहा हूं । मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं उन से कहना चाहता हूं कि जो पंजाब में अपनी डामीनेशन कायम रखना चाहते हैं वे समझते हैं कि 21 आदमियों की जो कंसलटेटिव पालियामेंटरी कमेटी बनी हुई है वे युनानीमस है कि हिमाचल प्रदेश बनेगा, पंजाबी सूबा बनेगा तो उस के बाद उन की एक्सप्लाएटेशन खत्म हो जाएगी । इसी लिये वे लोग अपने प्रेशर टैकटिक्स दिखाना चाहते हैं । जैसे हमारे प्रिंसीपल साहिब ने कहा कि करोड़ों आदमी इस के खिलाफ हैं । मुझे समझ नहीं आता कि करोड़ों आदमी कौन से हैं । आखिर अपने हरियाणा प्रान्त के रीप्रीज़ेंटेटिव्ज़ तो हम ही हैं । हम इस बात की मांग करते हैं । 11 मेम्बर हिमाचल में मिलने की मांग करते हैं । हिन्दी रिजिन के जो हरिजन हैं वे इस बात की मांग करते हैं कि पंजाबी सूबा बनना चाहिये और हरियाणा प्रान्त बनना चाहिये । लेकिन जो वैल आर्गेनाईज्र्ड पार्टी है वह इस के खिलाफ काम कर रही है । भिवानी में आग लगा दी है, हिसार और पानीपत में दूकानें बंद कर के यह दिखाना चाहते हैं कि पापुलर मूवमेंट तो हमारी है, हरियाणा के लीडरों की नहीं है । जहां तक जन संघ का ताल्लुक है मैं कहना चाहता हूं कि इसी इलैक्शनों में जनसंघ वालों की ज़मानतें भी ज़ब्त हुई थीं । "Who's Who" एक किताब है उस में यह इत्तलाह दी हुई है । चौधरी रतन सिंह, अच्छी फैमीली के हैं, पहले डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, वे जन संघ की टिकट पर पालियामेंट के उम्मीदवार थे । उन की ज़मानत भी जब्त हो गई थी । ठाकुर चरणजीत सिंह का बच्चा मरवा दिया। पिछली अक्तूबर की 6 तारीख को उन्हों ने हरियाणा सम्मेलन की भिवानी में और दादरी में सदारत की थी । उन्हों ने हरियाणा प्रान्त की हिमायत की थी । उन का बच्चा कल गोली से मार दिया गया । इस का मतलब यह नहीं था कि हमारी आईडियालोजी एक थी । बात यह थी कि हमारा इलाका बैक्वर्ड था; हम जा कर अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे । हम जानते थे कि पंजाबी सूबा बनेगा, यह जायज़ मांग है । उस के साथ हरियाणा प्रान्त भी बनेगा । स्पीकर साहिब, हमारे इलाके में अखबार कौन कौन से जाते हैं ? प्रदीप, मिलाप, प्रताप अखबार इलाके में जाते हैं । हमें कहते हैं कि तुम को गद्दार कहेंगे, एंटी-नेशनल कहेंगे, हमें यह धमकियां देते हैं । चौधरी लहरी सिंह जो जन संघ के टिकट पर चुने गए थे उन्हों ने मीटिंग पर प्रीज़ाईड किया औरं कहा कि मैं ने तो

चमारों के वोट बांटने के लिए ऐसा किया था। आज उन्हों ने इस्तीफा दे दिया है। मैं अर्ज़ करता हूं कि जन संघ की हरियाणा में कोई ताकत नहीं है। भिवानी में इलैक्शन के वक्त, जब श्री सागर राम गुप्ता इलैकट हुए, कुल 44,486 वोट पोल हुए और जन संघ को 7,573 वोट मिले। इसी तरह हिसार में 51,150 वोट पोल हुए, जब 1962 में श्री हुन्ना मल जी कामयाब हुए, तो जन संघ को 2,212 वोट मिले थे। हांसी में कुल 60,149 वोट पोल हुए जिस में 7,372 वोट जन संघ को कास्ट किये गए। तोशाम की कांस्टीच्यूएंसी में कुल 37,805 वोट कास्ट हुए जिन में से 1,115 वोट जन संघ के लिये दिये गए। मैं यह बात इस लिये बता रहा हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि पंजाब के करोड़ों लोग इस मूवमेंट के खिलाफ हैं कि नए सिरे से हरियाणा की और पंजाबी सूबे की तशकील हो, वे लड़कों को गुमराह करते हैं। हमें खुद इस की बाबत पहले कनफ्यूज़न था। आज से सात आठ साल पहले हिन्दु धर्म के नाम पर हिन्दु और सिख का सवाल पैदा कर के हमारे लोगों को हिन्दी भाषा के नाम पर बहकाया गया। हिन्दू धर्म के नाम पर लोगों के जज़बात को भड़का कर हिन्दू और सिखों को लड़ाना चाहते थे। जब 9 आदमियों की वज़ारत बनी तो 17 पंजाबी रिजिन के हिन्दुओं में से एम० एल० एज़० म से तो चार मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर लेकिन हरियाणा के 65 एम० एल० एज़० के पीछे एक मिनिस्टर दिया गया। हमारे राईट्स तो यह लोग यूज़ करते रहे। हमारी अटेन्शन डाईवर्ट करने के लिये इन्हों ने हिन्दू और सिखों का सवाल पैदा किया और हिन्दी एजीटेशन चलाई। हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में गए लेकिन यह लोग, 'आग लगा के डब्बू कंध ते।" (हंसी) आज फिर वे लोग हरियाणा में पंजाबी लागू करवाना चाहते हैं। इस किस्म का प्रापेगंडा हो रहा है; पड़ोसन की मिसाल दी गई। में पूछता हूं कि कहीं सिखों ने ज्यादती की है ? कल इन्दिरा जी से हमारा डेलीगेशन मिला। हम ने प्राईमिनिस्टर से कहा कि बहन जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स यहां आए थे, औरतों के जत्थे बन कर आप के पास आते रहे कि हमारी इज्ज़त महफूज़ नहीं है, हम बच नहीं सकते आप ने पांच दिन की एजीटेशन में देखा कि एग्रेसिव पंजाबी हिन्दू हैं या सिख। सिख नहीं है। मैं आप के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करता हूं कि आप लोगों को संभालिये। होम मिनिस्टर साहिब से यह दरखास्त करता हूं कि पता नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन होम मिनिटर बनेगा निकालो इस ख्याल को दिमाग में से। सोचते सोचते ही पंजाब तबाह कर बैठोगे तो न कांग्रेस रहेगी, न होम मिनिस्टर रहेगा और न चीफ मिनिस्टर रहेगा। ला एंड आर्डर को काबू में कीजिये मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि ला एंड आर्डर को सख्ती से मेन्टेन कीजिये। यहां पर स्पीच दे कर धमकी तो दे गए थे लेकिन इन को अपने अख्तियार अपने ही

[चौधरी देवी लाल]

भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करनें पड़ रहे हैं । इन को डर है कि कल को वहां से रीटर्न हो कर नहीं आ सकेंगे । यश जी तो भाग रहे हैं कि हम तो कांग्रेस ही छोड़ते हैं ....

(घंटी की आवाज़)

यह बात कह कर मैं अपनी सीट लेता हूं ।

Mr. Speaker : Sardar Darbara Singh.

(At this stage Giani Kartar Singh also rose to speak.)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ । (ਵਿਘਨ)

ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਿਉ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਤਕ ਬਹਿਸ ਚਲਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ । (The hon. Member, Giani Kartar Singh, may please resume his seat. (Interruption) The hon. Member may please listen to me and let me regulate the proceedings. This is my function as to who is to be called to speak. Perhaps, no body will have such an objection at the close of the discussion. But I may be allowed to regulate the proceedings.)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਜਣਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ—ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਟੇਟ ਕਰਵ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹੈ । ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਨਜ਼,

ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ—ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਖਤਲਾਫ਼ ਰਾਏ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ਼ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪੋ ਵਿਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ—ਜੋ ਕੁਛ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ। (Thumping of tables) ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਥੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜੋ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। (Thumping of tables) ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ for argument sake ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਲਗਣ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵੱਸਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਇੱਟਾਂ ਖਾਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਿੰਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ— ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ; ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਅਤਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਿਦਾਇਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਗਈ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਓਵਰ-ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਰਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ—ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਅਜ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਰਦ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਜੋ ਮਾੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰੇ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ । ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ—ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਥੇ ਭਰਾ ਹਾਂ—ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ । ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਟੀ ਅਸਾਂ ਰਖਣੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਟੀ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਫ਼ਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਤਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼।

ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। (ਵਿਘਨ)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਰੀਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਆਬਸਟਰਕਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜ਼ਰਾ ਧੀਰਜ ਰਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ । (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕਲ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ । (ਵਿਘਨ) ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਸ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਐਫਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਲਗੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੱਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਉ ।

Mr. Speaker : Order please. No interruptions.

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ, ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਗਾੜਦਾ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ— ਉਸ ਉਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਊਣਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਟੇਗਾਰੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।

ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ । ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਟਰਨੈਸ ਵਧੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਆਣ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਐਮਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ । ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਔਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ— (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਇਕੋ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਮ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ-ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਚੂਡ ਐਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਆ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕਠ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਸ਼ਬ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਟ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫਸਾਦ ਮੁਕਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਦ ਕਰ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗੇ ਪਰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਨਾ ਪਰਾਂਤ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਲਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਕਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਈਯਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਮੇਈਯਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੱਗਦਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੈਨਸਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਟਰੀਬਿਊਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਮਿਲਾਪ', 'ਪਰਤਾਪ' ਔਰ 'ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ' ਜੋ ਜ਼ਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ 'ਮਿਲਾਪ' ਜਾਂ 'ਪਰਤਾਪ' ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ— ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ

[ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ]

ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਉ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਉ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਅਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਾਉ। (ਵਿਘਨ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਘੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਾਕੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗਰਾਂਟ ਤੁਹਾਥੋਂ ਲੈਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਥੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਬੇ ਉਸ ਇਕ ਬੰਬਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, जिस मसले पर आपने यहां पर डिसकशन करने का मौका दिया उस में आपने देखा होगा कि जितनी भी रीऐक्शनरी फोर्सिज़ थीं उन सब ने मिलकर एक पार्टी को आगे रख लिया और पानी पी २ कर उसे कोसना शुरू कर दिया।

(हंसी)

मैं अर्ज़ करता हूं कि इधर मेरे कुछ भाई बैठे हैं, उन की बात कुछ समझ आती है मगर कुछ भाई इधर मेरे बाएं तरफ बैठे हैं जो फरमाते हैं कि एक ही यह

पार्टी है, सौलेटरी पार्टी है जो इस की मुखालिफत करती है। मैं कहता हूं कि इन कि बात भी हमें समझ आती है। इन का तो शुरू से एक ही सिद्धांत रहा है और यह चीन और रूस की हिज़ मास्टर्ज़ वायस बैठे हुए हैं। (विघ्न) देखिये, हम ने आप की बात पूरे सबरो तहम्मल के साथ सुनी। मुझे ख्याल था कि जब हम बोलेंगे तो इन को बवासीर का दौरा होगा। (हंसी) अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुनने के लिये भी कान होने चाहिएं। हम ने बड़े आराम से आप की बात सुनी तो अब हमारी बात भी सुनिये। इन का सिद्धांत रहा है कि हिन्दोस्तान के अन्दर तोड़ फोड़ होती रहे और इश्तआल अंगेजी होती रहे। आपने सुना होगा कि अगर कोई औरत किसी की लड़की को जा कर कहे कि मुझे तो तुम से तेरी मां से भी ज्यादा प्यार है तो साफ बात है कि उस की नियत साफ नहीं है। तो मैं अपने अकाली भाइयों से कहना चाहता हूं कि इन की नियत साफ नहीं है, पता नहीं यह तुम को कहां ले जाएं (हंसी) फिर चौधरी देवी लाल जी की बात है। यह बहुत सीधे सादे जाट आदमी हैं। इन्होंने तो अपने मुंह से बताया है कि वह कहां से कहां जख्म खुरदा हुए हैं। अभी सरदार प्रताप सिंह कैरों के साथ मिल कर हकूमत चलाते रहे, कभी हिन्दी ऐजीटेशन वालों से मिल कर लाठियां खाते रहे और आज इतने तजरूबें के बाद डेनियल कम्ज टू जजमैंट। (हंसी) अब जा कर उन को होश और अकल आई है। मैं इन को बताना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल, पंजाबी सूबे का तो ऐलान हो गया मगर आप का हरियाणा कहां है, वह त्रिशंकू कि तरह बीच में ही लटक रहा है। (हंसी) यह कहां बनेगा? आप की बात ने पंजाबी सूबा तो बनवा दिया वह हमें दिखाई देता है, आप ने उन को तकवियत दी और उन का उल्लू सीधा करवा दिया। (विघ्न) मगर आप कहां लटक रहे हैं। (हंसी)

सरदार गुरनाम सिंह जी ने भी कुछ बातें कीं। मैं उन की बड़ी इज्ज़त करता हूं, वह हाईकोर्ट के जज रहे हैं। मगर उन की स्पीच सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन को तो कन्सट्रकटिव स्पीच करनी चाहिए थी जिस से पंजाब के अन्दर हालात ठीक होते। मगर उन के इस तरह से जन संघ को और इस की लीडरशिप को गालियां देने से तो हालात ठीक नहीं होते। अगर आप सही मायनों में देश के और सूबे के हालात सुधारना चाहते हैं तो बैठ कर, सब की कोआपरेशन के साथ ही ऐसा हो सकता है। लेकिन इन की बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह किस रूप में बात करते हैं। मगर जिस का जो असली रूप हो वह दिखाई दे ही जाता है। स्पीकर साहिब, आप देखिये किस ढंग से बात की जाती है। कहते हैं कि मास्टर तारा सिंह ने बड़ी बेहूदा मूव की थी, उन को पकड़ना ही

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

चाहिये था। स्पीकर साहिब, इन को मैं याद करा दूं कि लुध्याना में सरदार हरी सिंह नलवा के जनम दिन पर इन्होंने मास्टर तारा सिंह की सरकरदगी में एक कनवैन्शन की थी जिस में इन्होंने सल्फ डिटरमीनेशन का रैज़ोल्यूशन पास किया था (विघ्न) मगर यज्ञ दत्त की तरफ से इस मूव की सपोर्ट तो नहीं आई थी। (विघ्न) यह पंजाब में क्या हो रहा है यह सरदार गुरनाम सिंह ही जानें। मगर इस हालत का अगर हल होगा तो सब की कोआपरेशन से होगा। स्पीकर साहिब, जन संघ का ऐलान साफ था। वह अगर कुछ कहते हैं या लड़ते हैं तो प्रिंसीपल पर लड़ रहे हैं। उन्होंने स्टेटस कौ के हक में अपनी राए दी। जो उन का प्वायंट आफ वियू था उस से दे डिड नाट बज ऐन इंच आईदर वे। उन का यह सिद्धांत है, नैशनल प्वायंट आफ वियू है। नेशन को देखते हुए यह मांग रखी। मैं अर्ज़ करता हूं कि जिस ढंग से यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रैज़ोल्यूशन आया, अखबारात में शाया हुआ उस से आतिशफशां पहाड़ फट पड़ा, सूबे में आग लग गई, लोगों के जज़बात भड़क उठे। जनसंघ पार्टी के जैनरल सैक्रेटरी पूजनीय यज्ञ दत्त शर्मा जी की तरफ से ऐलान किया गया एक बड़े पीसफुल वे में कि ही विल फास्ट अन टू डैथ। (विघन) नहीं, यह कहना गल्त है कि यज्ञ दत्त अच्छा आदमी नहीं है मैं आप को बताता हूं। He is a very simple man, original and practical. He has no ill-will against any individual or party. उन्होंने किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, उन्होंने वायलैंस को कनडैम किया है। उन्होंने देश की यकजहती और एकता के लिये अपनी जान की बाजी लगा दी है, हिन्दोस्तान की खातिर वह अपनी ज़िन्दगी को कुछ नहीं समझते। (विघ्न) क्या बात करते हैं, किस ने वांयलैंस के अन्दर हिस्सा लिया है। ज्ञानी करतार सिंह जी ने कहा कि फलां ने झगड़ा किया (विघ्न) शुक्र करो कि तुम्हारा नाम नहीं लिया। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि मैंने एक चीज़ देखी कि जिस वक्त यह सिलसला चल रहा था तो उन्होंने कह दिया कि प्रापर्टी जलाई गई। फलां चीज़ जलाई गई। मैं अर्ज़ करता हूं कि पंजाब में फसादात करा के, इश्तिआल दिला कर बहुत बुरे हालात पैदा किये गए। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर हालात इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके पैदा किए गए हैं। किस तरह से इन्नोसैंट पर्सन्ज़ को हरास किया गया। टीनएजर्ज को और औरतों को पीटा गया और तरह तरह के मुजालिम पुलिस के द्वारा उन पर ढाए गए। मन्दिरों के अन्दर जा जा कर और घरों के अन्दर से निकाल कर उन्हें पीटा गया। हाउस टाप्स से लोगों को नीचे फैंका गया।

आवाज़ें : ग़ल्त, ग़ल्त ।

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक इस तरह के हरब, स्पीकर साहिब, इस्तेमाल किए गए और मुज़ालिम किए गए ।

स्पीकर साहिब, पंजाबी सूबे के खिलाफ हम तीन रोज़ तक सैंटर की लीडरशिप को मिलते रहे और वहां पर जा कर पता चला कि कांग्रेस हाई कमान किस तरह से लोगों को धोका देती रही और साफ बात कभी न की। मैं अपने आप को एक छोटा सा वर्कर समझता हूं और अपनी नाकस राए समय समय पर दिल्ली में पहुंचाता रहा हूं लेकिन मुझे पता लगा कि पंजाबी सूबा की मांग तो सैंटर की तरफ से उस वक्त ही कन्सीड हो चुकी थी जब कि संत फतह सिंह जी ने अपना फास्ट छोड़ा था, व्रत को ब्रेक किया था । वह बड़े आदमी हैं । (विघ्न) (घंटी)

स्पीकर साहिब, मुझे तो इन सब से चार गुना टाइम मिलना चाहिए ताकि इन की सारी बातों का जवाब दे सकूं ।

Mr. Speaker : Please wind up.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : दिल्ली में जब हम गए तो पता चला कि जिस वक्त संत फतह सिंह ने फास्ट ब्रेक किया तो सूबे की मांग को सैंटर की लीडरशिप ने मान लिया था ।

The demand had been conceded at that time by the Congress High Command.

वह लोगों को धोखा देते रहे । कभी किसी डैपूटेशन को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया । मेरे साथ डा० बलदेव प्रकाश थे तो मैंने उन को कहा कि आप किन से बातें कर रहे हो, यहां तो इन्होंने पंजाब का भट्ठा बिठा दिया है और इस को यह लीडरशिप मिटा चुकी है पहले से ही। (घंटी) स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो यह डिसियन हुआ और जिस किस्म की बातें हुई मैं यह बताना चाहता हूं कि क्यों हुई । यहां पर सामने यह पार्टी बैठी है, मैं औरों का नाम तो नहीं लेना चाहता

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

कि जिन को बातें सुन कर ही ब्लड प्रेशर हो जाए। मैं सिफ चीफ मिनिस्टर को ही लेता हूं कि इस चीफ मिनिस्टर की कमजोरी की वजह से यह सारी चीज़ हुई। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब निहायत शरीफ आदमी हैं, क्या करें! लेकिन यह सारी इन की कमज़ोरी की वजह से हुआ। हमें कांग्रेस हाई कमांड का चपड़ासी इस सूबे में चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए था। पंजाब को जरूरत थी एक बहुत मज़बूत चीफ मिनिस्टर की। स्पीकर साहिब, अगर हाई कमांड और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने हमारा चीफ मिनिस्टर मज़बूत स्टैप लेता कि पंजाब के अन्दर लोगों की राए इस के खिलाफ है, पंजाब की कांग्रेस पार्टी का यह रज़ोल्यूशन पंजाबी सूबा बनाने के खिलाफ है और कैबिनिट का फैसला भी इस तरह का है तो किसी की हिम्मत न हो सकती थी कि इस तरह का फैसला करते कि पंजाबी सूबा बना दो। सरदार प्रताप सिंह कैरों को हम पानी पी पी कर आज कोस्ते हैं लेकिन उस के बदले में यह आए जो निहायत कमज़ोर साबित हुए। (विघ्न)

Mr. Speaker: please wind up. You have already taken enough time.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक: इस चीफ मिनिस्टर ने हमारा भट्ठा ही बिठा दिया। इस कमज़ोर चीफ मिनिस्टर ने पंजाब की लुटिया डिबो दी। जब कि कांग्रेस पार्टी का पंजाब में यह रैज़ोल्यूशन यूनानीमस्ली पास किया गया था कि पंजाबी सूबा नहीं बनना चाहिए और पंजाब में स्टेटस को रखा जाना चाहिए इस के बावजूद यह चीफ मिनिस्टर वहां पर गया और सैंटर की लीडरशिप के आगे अपना सर झुका दिया।

He became stooge of the Congress High Command.

Mr. Speaker: You have taken 14 minutes. Please stop now

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक: मैं स्पीकर साहिब, अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब के हिस्से में इस किस्म की बातें आई जो कांग्रेस पार्टी के अपने सिद्धांत के उल्ट हैं। एक तरफ तो कांग्रेस लैजिसलेचर पार्टी और प्रोविन्शल कांग्रेस कमेटी यह रैज़ोल्यूशन पास करें कि जो मैमोरेंडम अकालियों की तरफ से दिया गया है उस को अपोज़ किया जाए और फिर कैबिनिट पास करे और इस बात पर यूनानीमस हो कि इस को अपोज करना है तो फिर ऊपर से हमारी खोपड़ी पर

इस तरह का एटम बंब फैंक दिया जाए। यह बातें इस लिए हुई कि हमारा चीफ मिनिस्टर कमज़ोर था और शरीफ था। (घंटी) मैं सिरफ एक बात कह कर खत्म करता हूं। मैं गाड़ी में आ रहा था तो दो दोस्तों में आपस में इस बात पर झगड़ा हो गया कि..

(विघ्न)

Mr. Speaker : Please finish now.

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : I am finishing it.

Mr. Speaker : You are making stories.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : वह आपस में इस लिए लड़ रहे थे कि एक कहता था कि शेरनी बच्चे देती है और दूसरा कहता था कि शेरनी अण्डे देती है। मैं पास बैठा था तो मुझे कहने लगे कि तुम बताओ और इस बात का फैसला करो। मैंने कहा कि शेरनी एक बड़ा जानवर है, कभी यह बच्चे दे देती है और कभी यह अण्डे दे देती है। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है, कभी सरदार प्रताप सिंह जैसे मजबूत चीफ मिनिस्टर दे देती और कभी इस तरह के कमजोर श्री राम किशन जैसे चीफ मिनिस्टर। बड़ी पार्टी है इस की बड़ी बातें हैं। (विघ्न) (शोर)

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मुझे बोलने के लिए टाईम दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप को समय नहीं मिल सकता, प्लीज़ टेक योअर सीट। (The hon. Member cannot get time. He may please take his seat.)

चौधरी नेत राम : मुझे समय ज़रूर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। चौधरी नेत राम जी, आप बैठ जाइए। (Order Please. The hon. Member Chaudhri Net Ram may please resume his seat.)

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI YASH PAUL

श्री यश पाल : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

श्री अध्यक्ष : आप कल कर लेना। (The hon. Member may give his personal explanation to-morrow.)

श्री यश पाल : कल तो मैं यहां नहीं हूंगा। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा।

Mr. Speaker : Yes please.

श्री यश पाल : स्पीकर साहिब, मेरे बारे में दो बातें कही गई हैं । एक तो यह की मैं किसी एकशन कमेटी का मैम्बर हूं । इस के बारे में जहां तक मुझे पता है मैं किसी एकशन कमेटी का मैम्बर नहीं हूं ।

एक आवाज़ : एकशन कमेटी नहीं, एकता कमेटी ।

Mr. Speaker : Order please. No interruption.

श्री यश पाल : दूसरी बात यह कही गई ज्ञानी करतार सिंह की तरफ से कि मैंने यह बात कही कि कांग्रेस से अस्तीफा दे दिया क्योंकि हम यूनाईटिड पंजाब का समर्थन करते थे और इसी पर इलेक्शन जीत कर आए थे, अगर यह बात होती तो जिस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र का सूबा बना तो क्यों अस्तीफा न दिया ? मैं ज्ञानी जी को क्या कहूं कि जिन का कोई असूल नहीं, कोई पार्टी नहीं, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी असूल पर चलने लगे । और हर वक्त पैंतरा बदल सकते हैं । (विघ्न)

Sardar Gurnam Singh : This is no personal explanation.

PERSONAL EXPLANATION BY GIANI KARTAR SINGH

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

(ਸ੍ਰੀ ਭਗੀਰਥ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please.

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON LAW AND ORDER SITUATION IN THE STATE

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : इस बार्डर और स्ट्रैटेजिक सटेट में हर कीमत पर अमन अमान रखना जरूरी है । पंजाब तारीख के एक निहायत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है । इस धरती के लोग भी काफी गंभीर हैं, इस मौके पर

एक दूसरे की निंदा करने से, एक दूसरे को लान तान करने से, शोला अंगेज तकरीरें करने से पंजाब का सवाल हल नहीं होगा । इस वक्त अगर ज़रूरत है तो वह है कार्डियल ऐटमासफियर पैदा करने की । एक दूसरे के लिए सद्भावना पैदा करने की और ऐसा वातावरण पैदा करने की जिस से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया है, जैसे जैसे भी गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया इसकी डिटेल्ज़ वर्क आउट करेगी, इस के मुताल्लिक फैसला करके एक अच्छे वातावरण के अंदर इसको अमली जामा दिया जायेगा । हमारा पंजाबी करैक्टर जो है, यह एक ज़बरदस्त हीरोज का करैकटर है । आज ज़रूरत इस बात की है कि जगह जगह जा कर प्यार और मुहब्बत से एकता, अमन और शान्ति का संदेश इन लोगों को दिया जाये । इस हाउस के अंदर भी मैं कहूंगा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी तकरीर या कोई ऐसा लफ्ज़ न कहा जाए जिस से दूसरों के दिलों को दुख हो । आज यहां पर शोला अंगेज़ तकरीरों की ज़रूरत नहीं है । और न ही तीखी कलम की नोक से लिखने की ज़रूरत है, और न ही तेसे की सी तेज़ ज़बान रखने की ज़रूरत है । पंजाब के अंदर जिन हालात का हमें सामना करना पड़ा है खास तौर पर पिछले छ: दिन के अंदर यह निहायत ही अफसोसनाक है । जो वाक्यात इन दिनों तशद्दद और वायलेंस के हुए हैं, स्पीकर साहिब, इस हाउस का कोई भी मैंबर, खाह वह किसी भी विचार धारा का है वह इन्हें पसंद नहीं करेगा । आज पंजाब के अंदर कोई भी भाई वायलेंस नहीं चाहता । हमें पीसफुल ऐटमासफियर की ज़रूरत है । आज वकत की डिमांड है कि हम सब भाई चाहे कैसे भी विचार रखते हों आपस में बैठ कर अपनी गिला गुज़ारियों को दूर करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें । नये पंजाब की हम जो रूप रेखा बनायें, पंजाब की जो नई स्टेट बनायें वह निहायत ही मज़बूत हो, जिसमें सारे पंजाबी पूरी तरह से तरक्की कर सकें । स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत इस हाउस से कहना चाहता हूं कि जो भी वाक्यात हुए हैं वह निहायत ही काबले मुज़म्मत हैं । यहां पर सरदार गुरनाम सिंह जी ने ज़िक्र किया कि सीस गंज पर बदले की भावना से पत्थर बरसाये गये । अगर इस तरह की पवित्र जगह पर भी किसी तरह से पत्थर बरसाये जा सकते हैं, जोकि हमारे लिए माथा टेकने की जगह है, एक पाक स्थान है, मैं समझता हूं यह हमारे लिये एक शर्म की बात है, जिस ने कि ऐसी कमीनी और बेहूदा हरकत की है । यह एक काबले मुज़म्मत वाक्या है । इसे किसी

5.00 P.M.

तरह से भी पसन्द नहीं किया जा सकता । मैं आपके ज़रिए इस हाउस से कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर ला एंड आर्डर को हर कीमत पर रखा जायेगा । यहां पर इसी हाउस में लीडर आफ दी आपोज़ीशन और दूसरे साथियों ने यह बात बार बार कही है कि पंजाब के अंदर रूल आफ ला की ज़रूरत है, अगर किसी एजीटेशन को, किसी ला को हाथ में लेने की ज़रूरत पड़े तो सरकार को मिनीमम फोरस इस्तेमाल करनी चाहिये । पंजाब पुलिस ने इस बात को मद्देनज़र रख कर काम किया है, मुझे इस बात की खुशी है । मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाब पुलिस किसी तरह की भी प्रोवोकेशन के अंदर

[मुख्य मन्त्री]

नहीं आई । ठीक है कि ईटें पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं और उन्हों ने इस चीज़ को बरदाश्त किया है । बुनयादी चीज़ जो इस सिलसले के अंदर थी वह यही थी कि पंजाब के अंदर गोली न चलाई जाये, अगर ऐसा हुआ तो सारा पंजाब इस भड़कती हुई आग में खाक हो जायेगा । इस के बचाने के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े वह हम करने को तैयार हैं । मगर सूबे में कमयुनल हारमनी हर कीमत पर रहनी चाहिये । हिंदू और सिख के इस सूबे में बुन्यादी तौर पर जितने भी रसमो रिवाज़ हैं वह एक हैं । दोनों एक दूसरे के धार्मिक और पवित्र ग्रन्थों की पूरी तरह से पूजा करते हैं । गुरुओं की बाणी हमारी अपनी बाणी है । आज ज़रूरत ऐसे विचार देने की है जिन से एक दूसरे के मुंह से मीठी बाणी निकले। मैं, स्पीकर साहिब, आपके ज़रिये मैंबरान से यह अपील करूंगा कि आज के पंजाब के हालात के मुताबिक हमें आपस में मिलकर और एक होकर अमन कायम करना चाहिये । हमें ऐसा ऐटमासफियर कायम करना चाहिये जिस की वजह से किसी और को वाक्यात के दोहराने की ज़रूरत न पड़े । यह सारी चीज़ देख कर दुख होता है कि हम एक होकर रहने वाले कैसी कैसी हरकतें करते हैं । जहां तक पंजाब राज्य में ला-एंड-आर्डर का सवाल है मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि हर कीमत पर ला-एंड-आर्डर कायम रखा जायेगा । जो भाई अमन को भंग करने की कोशिश करता है, अमन के अंदर किसी तरह का खलल डालता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का है उसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा । सरकार का यह फर्ज़ है कि अमन हर कीमत पर बहाल किया जाये । ला-एंड-आर्डर को बहाल रखा जाये और इसके मुताबिक जो भी हम सटैप्स उठा सकते थे वह उठाये हैं और अमन को बहाल करने के लिये जो भी और सटैप्स हम उठा सकते हैं उठायेंगे । पंजाब के अंदर एक दो शहरों को छोड़ कर सभी जगह अमन है । (विघन)

आवाज़ें : लाला जगत नारायण के बारे कहें ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।

मुख्य मंत्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि ला-एंड-आर्डर हर कीमत पर बहाल रखा जायेगा और इससे जितनें भी बुरे ऐलीमैंटस हैं उन को खत्म किया जायेगा । (विघ्न) इन सारी चीज़ों पर पंजाब सरकार सख्ती से अमल करेगी।

स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत हाउस से यह भी कहना चाहता हूं कि इस सारे सिलसिले में पीस एँड ट्रैंक्विलिटी कायम करने में उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि बनी है, जब बात सर से गुजर जाती है तब तशद्दद की तरफ यह सारी चीज़ें आती हैं कोई भी गवर्नमेंट उसको बरदाश्त नहीं कर सकती । (प्रशंसा) उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं । मैं यह कहना

चाहता हूं कि यहां कुछ तकरीरें हुई । जहां तक डिस्ट्रिक्ट्स अथारिटीज़ का ताल्लुक है गवर्नमेंट की लैवल पर इस बात की हिदायात की गई हैं कि जहां जहाँ लूट और आर्सन की बातें होती हैं, तशद्दुद की बातें होती हैं वह प्रोवोकेशन में न आएं । इस के लिए उनको पूरी तरह से सख्ती से जिस तरह से कुचल सकते हैं इन चीज़ों का सख्ती से मुकाबला करना चाहिए । मैं आपकी मार्फत अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ने इस बात की भी हिदायत जारी की हैं कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ और क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक इस चीज़ को रिगोरसली इन्फोर्स किया जाए । यह हैं वे प्रोवियन्ज़—

"1. Offences concerning assault on Police Officials, intimidation etc., can be proceeded against under Rule 35/41 of the Defence of India Rules, which provides heavy penalty of rigorous imprisonment extending to five years or with fine, or with both. The offences are both cognizable and non-bailable.

2. Similarly cases of arson, or, attempted arson are also punishable under rule 36 of the Defence of India Rules, which prescribes heavy penalty of rigorous imprisonment of seven years or with fine or with both.

3. Other offences to be committed in such agitations are activities like 'Siapa', picketing, compelling others to close their shops or abstain from their work etc., with intent to prevent persons from performing their lawful duties. These can be dealt with under section 7 of the Punjab Criminal Law Amendment Act, 1932. The offence is both cognizable and non-bailable........"

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ । ਬੰਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੜਨੇ ਨੇ । (The reply to the point of order raised by the hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill is clear that the persons are to be arrested but they are to be arrested under the law.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇਣਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜ ਆਰਸਨ ਅਤੇ ਲੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਉਂ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ. ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । (*Interruptions and noise*)

Mr. Speaker: Order, order, please.

Chief Minister: I was stating—

"The offence is both cognizable and non-bailable, and is punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 500/-, or, with both......"

स्पीकर साहिब, यह प्रोवियन्ज़ हैं जिन को हम ने कहा है कि स्ट्रिक्टली एन्फोर्स किया जाए। मैं एक एक चीज़ को नहीं पढ़ रहा। मैं यह हाउस की टेबल पर रखता हूं। (इस समय* कागज़ हाउस की टेबल पर रखा गया।)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਰਬੋਧ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੋ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾ ਸਮਝ ਗਏ। (ਹਾਸਾ) (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ) (Addressing Sardar Gurnam Singh) (Today Sardar Tara Singh has understood law in English.) (Laughter) (Noise) (Interruptions)

मुख्य मन्त्री: स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जो इस वक्त स्टेट की हालत है उसके मुताबिक मैं आप के ज़रिए तमाम पुलीटीकल पार्टीज़, उनके लीडर्ज़ और पंजाब की अवाम से यह अपील करना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जल्दी से जल्दी अमन और शाँति कायम करने के लिए तुआवन दें। यह जो मुख्तलिफ जाइदादों को, चाहे गवर्नमेंट की प्रापर्टी है या दूसरे बेगुनाहों की हैं, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को इंटिमिडेट किया जा रहा है इन चीज़ों से उनको बाज़ रहना चाहिए।

विरोधी पक्ष की ओर से आवाज़ें : कौन जलाता है?

मुख्य मन्त्री : यह नैशनल प्रापर्टी है अपनी ही प्रापर्टी का नुक्सान किया जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ का ताल्लुक है वह पूरी तरह से पंजाब के अंदर ला-एंड-आर्डर को कायम करने में अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। पुलिस ने काफी रिस्ट्रेंट किया है। पंजाब में 164 के करीब आफीसर्ज पुलिस वाले और दूसरे जख्मी हुए हैं। उन में एक हमारे एडीशनल डिप्टी कमीश्नर, 2 मैजिस्ट्रेट एक डी. एस. पी, बाकी हमारे इंस्पैक्टर्ज़, पुलिस कंस्टेबल्ज़ और दूसरे आफीसर्ज़ हैं। उनके साथ मैं समझता हूं कि सारे हाउस को सहानुभूति होगी। मुसीबत में उन्हों ने सारी चीज़ें बरदाश्त की हैं। उनकी हम दाद देते हैं। उनको पूरी तरह से यकीन दिलाया है कि सरकार पूरी तरह उनके पीछे है। उन के परिवारों की और दूसरों की हम पूरी तरह से मदद करेंगे। जहाँ तक इस एजीटेशन का ताल्लुक है, स्पीकर साहिब, आपको मालूम है कि पंजाब में यह एजीटेशन भारतीय जन संघ ने चलाई है। इस के अंदर जो

*Placed in the Library.

अनरूली एलीमेंट है उस में कहीं तशद्दुद वाला एलीमेंट आ गया है। मेरे दोस्त कम्यूनिस्ट कह रहे थे। जहां तक भिवानी का ताल्लुक है मुझे दुख है कि भिवानी के जो इंसीडेंट हुए हैं उन में कुछ कम्यूनिस्ट भाईयों का भी हाथ है। इस में किसी ढंग से जन संघ की तरफ से और कम्यूनिस्टों की तरफ से हाथ है। वह सब का सब काबले मुज़म्मत है। मैं आशा रखता हूं कि आप तमाम भाई और तमाम पार्टीज़ इसमें हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे, पूरी तरह से सहयोग देंगे। पंजाब राज्य की तरफ से इस ला-एंड-आर्डर को कायम करने के लिए कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं किया जाएगा। यह हमारा पवित्र फर्ज़ है।

EXTENSION OF THE SITTING

Mr. Speaker : Time is over now. Does the honourable Chief Minister want more time ?

Chief Minister : Only five minutes or so.

Mr. Speaker : If the House agree, time of the sitting may be extended by five minutes.

Voices : Yes, yes, please.

Mr. **Speaker** : Time is extended by five minutes.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON LAW AND ORDER SITUATION IN THE STATE

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਏਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। (ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (Comrade Shamsher Singh Josh has given a long speech while raising a point of order. He should not misuse the right of point of order.)

मुख्य मन्त्री : इस वक्त तक 466 पब्लिक के आदमी जख्मी हुए हैं। जिन्हों ने मेडीकल एग्ज़ामीनेशन करवाया उन की गिनती 132 के करीब हैं। इसी तरह 164 आफीसर्ज़ जख्मी हुए हैं। इस के अलावा जो पंजाब की पब्लिक प्रापर्टी

[मुख्य मंत्री]

डैमेज की गई या जलाई गई है उस की तफसील इस तरह से है ।

Government Jeeps burnt	..	2
Punjab Roadways Buses damaged	..	25
Punjab Roadways Buses burnt	..	4
Telephone Exchange damaged	..	1
Telegraph office damaged	..	1
Telephone boxes damaged	..	2
Post Offices damaged/looted	..	13
Other Government buildings, a police post, S. D. M.'s Court (Bhiwani), Electric Power House (Tunda Talab Amritsar), Schools and libraries burnt/damaged.	..	8
Railway level crossing Gates damaged	..	4
Railway outer signals damaged	..	5
Railway Cabins burnt/damaged	..	6
Railway Booking agency record burnt	..	1
Public relations office burnt	..	1

इन सारे हालात के होते हुए भी जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है और हमारे आफिसर्ज़ का ताल्लुक है वह प्रोवोकेशन में नहीं आए मगर मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि पंजाब में हर कीमत पर अमन-अमान कायम रखा जाएगा, कम्युनल हारमनी हर कीमत पर रखी जाएगी, किसी मुहल्ले में कम्युनल डिस्टर्बेंसिज़ किसी शक्ल में भी नहीं होने दी जाएगी । में आशा रखता हूं कि इस काम में सारे पंजाब के लोग राज्य सरकार की मदद करेंगे, प्रैस से भी मैं आशा रखता हूं वि वह रेसट्रेंट से काम लेगा और सब भाई ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिस से अच्छा वायुमण्डल पैदा हो सके । मुझे इस बात का दुख है कि श्री यज्ञ दत जी ने आज भूख हड़ताल की हुई है । उन की विचारधारा से किसी को भी इखतलाफ हो सकता है लेकिन जहाँ तक उन के जज़बे का सम्बंध है उस के लिए हमारा सब का फर्ज़ है कि हम इस बात की कोशिश करें कि वह भूख हड़ताल छोड़ दें । हम ने आपस में बैठ कर एक नए पंजाब की तस्वीर बनानी है, उस के लिए वातावरण पैदा करना है । मैं लीडर आफ दी आपोज़ीशन से खास करके अर्ज़ करूंगा कि वे इस तरह का वातावरण पैदा करें। जहां तक पंजाब सरकार का ताल्लुक है हम पूरी तरह से ला एंड आर्डर रखेंगें। मुझे आशा है कि सरकार को सब पार्टियां तुआवन देंगी ।

5.20 p. m.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 A. M. tomorrow the 16 March, 1966.

(The House then adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday the 16th March, 1966.)

1637—15-6-66—386 copies—C., P. & S., Pb., Patiala.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

16th March, 1966

Vol. I, No. 20



CONTENTS

Wednesday, the 16th March, 1966

Punjab Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh

Price 6.95

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 20, dated the 16th March, 1966.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Motions	M tions	Title	21
[Irrig tion and Power Minister]	(2 [Irrigation and Power Minister]	(20)30	1
Chaudhri Rizaq Ram	Chaudhari Rizaq Ram	(20)44 (20)49	19 5
Shri Rup Singh Phul	Shri Rup Singh Paul	(20)50	15 from below
House	Hou e	(20)60	10
ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪਰ	(20)73	27
ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ	ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿਘ ਸੰਧੂ	(20)86 (20)88	1, 8 4 from below
members	m mbers	(20)87	7
ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ	ਸੀ ਸਪੀਕਰ	(20)88	1
शिक्षा मन्त्री	शिशा मन्त्री	(20)89	3
themselves	themsel es	(20)91	Last but one
compelled	compell d	(20)93	22-23
जाऊंगा	जाउ'गा	(20)95	4
चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक	चौधरो मुख्तियार सिंह मालिक	(20)102	10
में	मैं	(20)107	11

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, rhe 16th March, 1966

The Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan Sector 1, Chandigarh, at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

KUMRA GARDEN AND ZAKHIRA GARDEN AT KAPURTHALA

*9006. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the area of the Kumra Garden, and the Zakhira Garden, respectively at Kapurthala;

(b) the amounts for which the aforesaid lands/gardens were leased out during the years 1962-63, 1963-64, 1964-65 and 1965-66 (to date);

(c) if the land/gardens referred to in part (a) above were not leased out, the use to which they were put and the expenditure incurred on their up-keep during the period mentioned in part (d) above?

Sardar Darbara Singh : (a) Kumra Garden .. 37 acres.

Zakhira Garden .. 37 acres.

(b)

Year		*Kumra Garden*	*Zakhira Garden*
		Rs	Rs
1962-63	..	438.50	1,100
1963-64	..	694.00	825
1964-65	..	1,184.00	825
1965-66	..	Not yet available	1,450

(c) Does not arise.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : कुमरा गारडन्ज़ की 37 एकड़ जमीन है लेकिन 1962-63 में कुल आमदनी 438 रुपए 50 पैसे हुई है जो कि फी एकड़ 12 रूपए बनती है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी कम आमदनी क्यों हुई है।

मंत्री : जमीन बहुत सारी लैंड स्केपिंग के लिए है और वह दूसरी इन्स्टीच्यूश्न्ज़ को भी दी जाती है।

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਮੈਂ 'ਸੀ' ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਖਰਚ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

		Rs.
1962-63	..	5,970
1963-64	..	4,810
1964-65	..	6,890
1965-66	..	figure not available yet.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਖਰਚ ਵਧ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

कामरेड राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट ने पालिसी के तौर पर कोई ऐसी एजैंसी कायम की हुई है जो गवर्नमैंट प्रापर्टी की इन्वैस्टमैंट और मेनटेनैंस को देखते हुए अंदाज़ा लगाए कि उस से कितनी आमदनी हो सकती है। अगर नहीं तो क्या उसका हल सोचा जाएगा ?

मंत्री : यह ठीक है कि खर्च के मुताबक वहां आमदनी हो लेकिन कई चीज़ें सिर्फ आमदनी के लिए ही नहीं होतीं। लैंड स्केपिंग के लिए जगह थी। इसकी देख भाल के बाद अगर उसे किसी इन्स्टीच्यूशन के सुपुर्द करना पड़े तो उस पर विचार किया जा सकता है।

कामरेड राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि यह आमदनी के लिए नहीं किसी और मकसद के लिए है। जब यह प्रोपोज़ल बनी थी तो क्या यह बात सामने रखी गई थी कि इस मकसद को हल करने के बाद जो आमदनी होगी वह मेनटेनैंस को जस्टीफाई कर देगी ?

मंत्री : कुछ ज़मीन जो है वह महकमा ज़रायत के अलावा सैनिक स्कूल, माडल स्कूल वगैरा को इस्तेमाल के लिए दी जाती है।

श्री **ओम प्रकाश अग्निहोत्री** : 1962-63 में जखीरा गारडन्ज़ की आमदनी 1,100 रुपए थी लेकिन अब जब चीजों के भाव बढ़ गए हैं ज़मीन की कीमत भी बढ़ी है तो 1963-64 में यह आमदनी 300 रुपए कम हो गई और 1964-65 में भी कम हो गई इस का क्या कारण है ?

मंत्री : यह मारशी और लो लाइंग एरिया है, कल्टीवेशन होती नहीं, खर्च ही होता है और मेनटेनैंस ही की जाती है। ज्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे फिर बिकेंगे तो आमदनी होगी। फिलहाल यही पुज़ीशन है।

COMPLAINT AGAINST THE B. D. O. MOGA-I

***9487. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal** ; Will the Minister for Home and Development be pleased to State—

(a) whether it is a fact that a representation from a Harijan member of Block Samiti, Moga-I was received by the S.D.M., Moga or the Deputy Commissioner, Ferozepore, during the month of August/September, 1965, complaining therein that the B.D.O. Moga-I had insulted him;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, a copy of the said representation alongwith the details of action taken thereon be laid on the Table of the House ;

(c) whether any enquiry into the representation referred to in part (a) above was conducted; if so, when;

(d) whether the result of the enquiry referred to in part (c) above has been conveyed to the complainant; if not, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) A copy of the representation is laid on the Table of the House. The matter was dropped after enquiry.

(c) Yes. The enquiry was started on 23rd August, 1965.

(d) Yes, the complainant was personally informed by the Sub-Divisional Officer (C), Moga.

COPY

To

THE S. D. O., MOGA

Subject :—Insult and abuse by the B. D. & P. O. Moga-I.

I visited the office of the B.D.O., Moga-I today. I am member Block Samiti, Moga-I. The B.D.O. insulted me and abused me. There were present at that time Shri Dalip Singh, Member Zila Parishad, Shri Kartar Singh, Member, Panchayat, Takhanwadh, Shri Major Singh son of Budh Singh of village Bughipura, tehsil Moga and Ujagar Singh and Shri Daman Singh, Member Panchayat Samiti, Moga-I.

An enquiry may kindly be held and an action taken against him. The whole facts will be treated to you at the time of enquiry.

Yours faithfully,

(Sd.)

Rakha Singh Member Block Samiti,
Moga-I, Village Nahal Khote tehsil Moga.

Dated 21-8-65

Copy to The Deputy Commissioner, Ferozepore, for information and necessary action please.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਰੀਜਨ

ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ., ਵਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੁਛ ਗਿਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जैसा कि शिकायत करने वाले ने लिखा है कि जब उस की बेइज्ज़ती की गई तो ज़िला परिषद के मैम्बर और दूसरे लोग भी हाज़र थे तो क्या इन्कवायरी अफसर ने उन सब से पूछा और उन्हें सबूत देने का मौका दिया ?

मंत्री : पूरी डिटेल्ज़ तो, जैसा मैं ने अर्ज़ किया, मेरे पास नहीं लेकिन कोई इन्कवायरी मुकम्मल नहीं होती जब तक मुतालिका लोगों से पूछा न जाए ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗੇ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਿਵਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जैसा कि उन्होंने कहा कि मैटर ड्राप कर दिया गया है मैं पूछना चाहता हूं कि जब इन्कवायरी अफसर ने लिखा कि ऐलीगेशन्ज ठीक नहीं और गलत शिकायत की गई है तो क्या शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया, अगर नहीं तो क्यों ?

मंत्री : यह वही बात है जैसा कि मैं ने अर्ज़ किया कि अगर शिकायत करने वाले और दूसरों को साथ लेकर इन्कवायरी नहीं हुई और जैसा कि उन्होंने कहा कि सबूत देने के लिए वह तैयार हैं तो न सिर्फ नए सिरे से इन्कवायरी होगी बल्कि गलत इन्कवायरी करने वाले की पूछ ताछ भी होगी ।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN KANGRA DISTRICT

***9501. Bakshi Partap Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of villages in district Kangra, tehsil-wise, which were electrified during the year 1964-65 ;

(b) whether villages Bhalana and Sansai in Palampur Tehsil were included in any of the electrification schemes ;

(c) if the reply to (b) above be in the affirmative, whether it is a fact that the material required for the electrification of the said villages was first carried to these villages and then removed; if so, the reasons therefor ;

(d) the steps, if any, being taken to electrify the above mentioned two villages ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a)

Tehsil Dehragopipur	*Tehsil Palampur*	*Tehsil Kangra*
(i) Tirpal	(i) Molag	(i) Balher
(ii) Nangal Chowk	(ii) Chaluhi	(ii) Ujjan
(iii) Dhahiara	(iii) Naun	(iii) Anwari
	(iv) Rampur	
	(v) Nanwar	

(b) Yes.

(c) No.

(d) The work of electrification of these villages is in hand and will be completed when requisite material is available.

बख्शी प्रताप सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर बिजली लगाने का मैटीरियल कब तक सपलाई किया जाएगा ?

मंत्री : वैसे वहां पर काम चालू हो चुका है। डैफिनिटली कहा नहीं जा सकता कि कब तक मैटीरियल सप्लाई किया जाएगा लेकिन कोशिश की जा रही है कि वहां पर जल्दी ही मैटीरियल पहुंचाया जाए ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੋਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : कोई ऐसी बात नहीं है । वहां पर पहले काम चालू था लेकिन बीच में काम रुक गया था ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Honourable Irrigation and Power Minister to let us know whether electrification of villages in Punjab will be taken up at all during the coming year ?

मंत्री : वैसे तो ट्यूबवैल्ज को बिजली के कुनैक्शन देने की बात है, लेकिन अगर बीच में कोई गांव आ जाएं तो वह गांव इलैक्ट्रीफाई कर दिए जाते हैं ।

पंडित मोहन लाल दत : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि रूरल एरिया के अन्दर जहां पर बिजली लगाने के प्राजैक्ट मंज़ूर हो चुके हैं और उन में से कुछ गांव इलैक्ट्रीफाइड किए जा चुके हैं क्या सरकार उन प्रौजैक्टस को चालू करने के लिए तैयार है ?

मंत्री : इस के लिए सैपरेट नोटिस दिया जाए । वैसे होशियारपुर जिला के बारे में बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर के साथ कल मीटिंग हो रही है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह कल चीफ इंजीनियर के साथ सारा केस डिसकस कर लें ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के लिए स्कीमें सैंकशन्ड हो चुकी है और वहां पर ट्यूबवैल्ज़ के लिए डिमांड भी नहीं है तो इन हालात में सरकार उन स्कीमों को इम्पलीमेंट करने के लिए तेयार है या नहीं ?

मंत्री : प्रयार्टी तो ट्यूबवैल्ज़ को कुनैकशन देनें की होगी । जहां तक कोई पहले प्राजैक्ट मंज़ूर हुए हैं, इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शन के लिए कितनी दरखास्तें आएं तब वहां बिजली पहुंचाने की प्रायर्टी दी जाती है ।

मंत्री : ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल्ज़ के कुनैकशन के लिए दरखास्तें आएं ताकि जस्टीफाइड लोड बन सके ।

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हाउस के अन्दर जो एलान किया था कि 11 के. वी. लाइन के आधा मील के फासले पर जो गांव होंगें उन को बिजली दी जाएगी, क्या सरकार ने उस एलान को कैंसल कर दिया है ?

मंत्री : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले साल ट्यूबवैल्ज़ के कुनैक्शन के लिए 13 हज़ार के करीब दरखास्तें पैंडिंग पड़ी थीं । उन को कुनैक्शन देने का प्रबन्ध सरकार ने किया ताकि किसान खेती की उपज बढ़ाने की कोशिश कर सकें । इसलिए मील की जो शर्त थी, उस को सामने नहीं रखा गया है बल्कि ट्यूबवैल्ज़ को कुनैक्शन देने की प्रायर्टी दी जा रही है ।

चौधरी रण सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर नहरों के द्वारा ग्राबपाशी के साधन नहीं हैं, अगर वहां पर लोग ट्यूबवैल्ज़ के कुनैक्शन मांगे तो क्या सरकार वहां पर बिजली पहुंचाने की कोशिश करेगी ?

मंत्री: इस के लिए छपे हुए फार्म्ज़ हैं। लोग उन फार्मों को पुर कर के कन्सर्ंड डिपार्टमैंट को दें । वहां पर आफिसर सारे पहलुओं को एग्ज़ामिन करते हैं । जहां पर ट्यूबवैल्ज़ कामयाब हो सकते हैं, वहां पर बिजली के कुनैक्शन देने की कोशिश की जाती है । वह बाकायदा सिक्योरिटी भी जमा कराएं । लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवैल्ज़ के कुनैक्शन के लिए दरखास्तें दें ताकि वहां पर लोड जस्टीफाइड हो सके ।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : पहले ट्यूबवैल्ज़ के लिए जो हुकम जारी किया था वह विदड्रा कर लिया गया है ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगें कि जहां पर ट्यूबवैल्ज़ लगे हुए हैं लेकिन वहां पर बिजली की लाइन नहीं जा रही है, क्या सरकार वहां पर बिजली पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि ट्यूबवैल्ज़ को कुनैक्शन मिल सकें ?

मंत्री : अगर वहां पर जस्टीफाइड लोड बन सकता है तो ठीक है, अगर जस्टीफाइड लोड नहीं बनता तो इस हालत में अनजस्टीफाइड पोर्शन की पेमेंट के लिए व्यक्ति तैयार हो तो देखा जाएगा । जहां तक ट्यूबवैल्ज़ को कुनैकशन के लिए दरखास्तें आएं तो उस के हर पहलू को एग्ज़ामिन किया जाता है । उस के लिए ऐस्टीमेट्स तैयार किए जाते हैं । वहां पर जल्दी से जल्दी बिजली देने की कोशिश की जाती है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ?

मंत्री: वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल्ज़ के कुनैकशन के लिए दरखास्तें दें ताकि उस के बारे में गौर किया जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੀ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਕਿਊਰਿਟੀਆਂ ਭੀ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

मंत्री : पिछले साल 13 हज़ार के करीब ट्यूबवैल्ज़ की दरखास्तें आई । उस में से 7 हज़ार के करीब कुनैक्शन दिए जा चुके हैं । इस साल हज़ार के करीब दरखास्तों पर गौर किया जा रहा है । ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की अर्जियां पैंडिंग होंगी । अगर नई जगहों पर भी लोगों ने टैस्ट रिपोर्टस पुर कर के दी होंगी, वहां पर भी बिजली के कुनैक्शन देने की कोशिश की जा रही है । यह आगे के लिए कन्टीन्युअस प्रासैस है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਸ ਵਿਚ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਥੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ?

मंत्री : अगर बाकायदा दरखास्तें आएंगी तो जरूर देंगे ।

श्री फतेह चंद विज : पिछले साल सरकार ने एक तारीख मुकर्रर की थी, शायद वह 30 अक्तूबर थी, कि इस से पहले पहले जिस की टैस्ट रिपोर्ट आ जाएगी और सिक्योरिटी दाखिल हो जाएगी, उन को कुनैकशन द दिया जाएगा । मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सब दरखास्तें खत्म हो गई हैं या कुछ बाकी हैं ?

मंत्री : वह तारीख 30 नवम्बर मुकर्रर की थी । पिछले साल में कोई दरखास्त बाकी नहीं रहती । दे वर डिस्पोज्ड आफ लास्ट ईअर । उस के बाद और दरखास्तें आई और 10-11 हज़ार इस साल भी डिस्पोज आफ की हैं ।

FREE BORING SERVICE TO THE AGRICULTURISTS FOR INSTALLATION OF TUBE-WELLS

*9895. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Government is considering any proposal to provide facilities for free boring service to those Agriculturists in the State who plan installing tubewells or wells for increasing agricultural production, if so, the time by which a final decision in the matter is likely to be taken ?

Sardar Darbara Singh : No, further question does not arise.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕੰਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਮਤਨ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਰਿਗਜ਼ ਐਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਜ਼ ਭੇਜੋ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਹੈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈਏ । ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਿਗਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀ-ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਨ, ਬੋਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਟੀਊਬਵੈਲਜ਼ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਏਰੀਆ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬ-ਮਾਊਂਟੈਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫ੍ਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਊਰੀਟੀ ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੀਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਸਕਣ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ।

ਡਾਕਟਰ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ : ਕੀ ਹੋਮ ਅਤੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਗਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੈਫ੍ਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰਿਗਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਕਾਂ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

FAZALPUR-ALLAWALPUR ROAD

***9762. Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the road from Fazalpur to Allawalpur in Palwal Tehsil has not yet been constructed by the Zila Parishad;

(b) whether Government has sanctioned some amount for the construction of a portion of the above-mentioned road, if not, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) No amount has been sanctioned by the Government exclusively for the construction of any portion of Fazalpur-Allawalpur Road. The construction of this Road could not be taken up by the Zila Parishad as the Panchayat Samiti, Palwal, failed to contribute its share on account of paucity of funds.

श्री रूप लाल महता : पिछले साल मन्त्री महोदय ने बताया था कि फजलपुर से अलावलपुर तक सड़क की सैंकशन हुई है । बाद में एक काल-अटेनशन मोशन दी गई थी कि वह सड़क बनी है या नहीं बनी तो उन्होंने जवाब दिया कि बन गई है । अब कहते हैं कि वह सड़क नहीं बन सकी । तो क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि किस जवाब को सही माना जाए ?

मंत्री : पंचायत समिति को बीस हज़ार रुपया देने के लिये कहा था, उन्होंने नहीं दिया इस लिये सड़क नहीं बन पाई ।

श्री रूप लाल महता : क्या मन्त्री महोदय का मतलब यह है कि जिला परिषद पलवल को पांच हज़ार रुपया देने के लिये कहा गया और दस हजार रुपया डी०सी० को अपने फंडज में से देने के लिये कहा गया तो उन्हों ने रुपया नहीं दिया ? अगर दिया है तो सड़क क्यों नहीं बनाई गई ? वह बड़ी इम्पार्टैंट रोड़ है ।

मंत्री : इस बात को कंसिडर किया जा सकता है । लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है कि बीस हज़ार रुपया उन्हों ने दे दिया हो ।

REPRESENTATION FROM GENERAL SECRETARY, KHETIHAR MAZDOOR-WA-KISAN SANGH, BHIWANI, FOR REDUCTION IN WATER RATES

*9590. **Shri Sagar Ram Gupta** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Chief Minister received a representation dated 22nd April, 1965, from the General Secretary, Khetihar Mazdoor-Wa-Kisan Sangh, Bhawani, for a reduction in the water rates for the water supplied through lift channals as was done by the Government in the case of the tube-well irrigation; if so, the details thereof and the action taken thereon;

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to bring down the water rates for water supplied through lift channels, if so, from what date and to what extent ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) No.

श्री सागर राम गुप्ता : क्या मनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि लिफट चैनल के वाटर रेट्स को बढ़ाने और घटाने के बारे में क्या पालेसी है ?

मन्त्री : अभी लिफट चैनल के वाटर रेट्स में तरमीम करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री सागर राम गुप्ता : क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि जिन इलाकों में लिफ्ट चैनल्ज़ काम करते हैं, वे बैक्वर्ड इलाकाजात हैं और उन इलाकों की बैक्वर्डनैस को ध्यान में रखते हुए वहां पर वाटर रेट्स को कम कर दिया जाए ?

मन्त्री : अभी तक कोई विचार नहीं है । पहले पानी तो ले लो, फिर सोच लेंगे ।

———

VACANT POSTS IN PUNJAB POLICE CLERICAL CADRE

*9899. **Principal Rala Ram** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of permanent and temporary posts in the Punjab Police Clerical Cadre in each rank ;

(b) the total number of posts referred to in part (a) above lying vacant and the date since when they have been lying vacant;

(c) the number of officials with more than 5 years and 10 years service, separately, working against the said permanent posts who are still temporary ;

[Principal Rala Ram]

(d) whether any instructions have been issued or rules framed by the Government for making the temporary employees permanent; if so, the action, if any, taken to make the employees mentioned above permanent accordingly ;

(e) the total number of police officials (clerical) who applied for their transfer to other departments for betterment of their career during the last five years (1st January, 1960 to 31st December, 1965);

(f) the total number of the officials (clerical) referred to in part (e) above who were actually relieved to join other department;

(g) the total number of cases in which the applications of the officials mentioned in part (e) above were rejected with the reasons therefor in each case ;

(h) the details of the instructions issued or rules framed by the Government in regared to relieving officials to join other departmentt.?

Sardar Darbara Singh ;

(a)
(b)
(c)
(d) The information asked for is contained in the statement placed on the Table of the House.
(e)
(f)
(g)
(h)

STATEMENT

(1) Rank		Total	Permanent	Temporary
Deputy Superintendent	..	13	10	3
Assistant	..	80	60	20
Senior-Scale Steno	..	5	4	1
Auditor	..	7	5	2
Head Clerk (Ranges & G.R.P.)	..	5	5	—
Head Clerk (P.A.P. & C.I.D.)	..	34	14	20
Junior-Scale Steno	...	18	14	4
Steno-typist	..	70	35	35
Clerk	..	437	300	137
Restorer	..	16	9	7

(b) Rank	Number of posts lying vacant	Date from which lying vacant
Auditor (PAP)	2	.. 2 with effect from 1-4-65
Head Clerk (PAP)	3	1 ,, 23-9-65
		1 ,, 23-2-66
		1 ,, 5-3-66
Steno-typist	8	.. 2 ,, 10-5-65
		1 ,, 31-8-65
		4 ,, 23-9-65
		1 ,, 21-2-66
Clerk	93	.. 1 ,, 21-6-64
		1 ,, 17-9-64
		1 ,, 24-9-64
		1 ,, 27-11-64
		1 ,, 4-1-65
		1 ,, 21-1-65
		1 ,, 13-1-65
		1 ,, 9-4-65
		1 ,, 12-5-65
		5 ,, 18-5-65
		1 ,, 23-5-65
		7 ,, June, 1965
		1 ,, 1-7-65
		1 ,, 5-7-65
		2 ,, 11-7-65
		1 ,, 12-7-65
		1 ,, 14-7-65
		3 ,, 20-7-65
		4 ,, July, 1965
		1 ,, 10-8-65
		1 ,, 27-8-65
		1 ,, 30-8-65
		6 ,, 31-8-65
		3 ,, August, 1965
		1 ,, 1-9-65
		12 ,, 23-9-65
		1 ,, 11-10-65
		1 ,, 18-10-65
		2 ,, 22-10-65
		1 ,, 1-11-65
		1 ,, 7-11-65
		1 ,, 8-11-65
		1 ,, 19-11-65
		1 ,, 22-11-65
		3 ,, 30-11-65
		1 ,, 6-12-65
		1 ,, 9-12-65

[Home and Development Minister]

(b) Rank	Number of posts lying vacant	Date from which lying vacant	
Clerk—*concld*	1	„	13-12-65
	1	„	December, 65
	1	„	1-1-66
	3	„	4-1-66
	1	„	5-1-66
	1	„	6-1-66
	1	„	18-1-66
	1	„	20-1-66
	1	„	24-1-66
	1	„	26-1-66
	1	„	27-1-66
	1	„	31-1-66
	1	„	1-2-66
	1	„	9-2-66
	3	„	February, 66

(c) *Number of officials with more than 5 years service*	*Number of officials with more than 10 years service*
116	5

(d) Yes. The State Government have recently placed an embargo on the confirmation of Assistants till the issue of general instructions, which are being awaited to decide the cases of eligible officials.

(e) 116

(f) Only 31 officials were selected for jobs outside the Police Department and all of them were relieved.

(g) 113. For Administrative reasons.

(h) Government instructions imply that if the interests of public service permit and the officials concerned who apply for service in other Government Departments to better their prospects can be spared without detriment to work and if suitable substitutes are available they may be relieved to join other departments. These instructions were kept in view while deciding such cases.

प्रिंसिपल रला राम : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एम्बार्गो कन्फर्मेशन पर लगा हुआ है, वह कब तक रहेगा और जेनरल इन्स्ट्रक्शन्ज़ केबिनिट की तरफ से जारी होंगी या पुलिस डीपार्टमैंट की तरफ से जारी होंगी ?

मन्त्री : अभी तक रुकी हुई है। हिदायात पुलिस की तरफ से जारी होंगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Home and Development Minister if it is a fact that persons with M. A., LL. B. as qualifications are rotting as Head Constables and they are not being given promotions? What measures will the Government adopt to give encouragement to such persons?

ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਏਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫ਼ੀ ਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਪੇਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

10.00 a. m.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਮਪਰੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਐਸ. ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਫ਼ਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

SUPPLY OF ELECTRICITY AT CONCESSIONAL RATES IN BACKWARD HILLY AREAS IN THE STATE

*9555. **Shri Surinder Nath Gautam** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the tariff of electricity charges in the State for different categories of consumers;

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to supply electricity at concessional rates in the backward hilly areas of the State?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No.

STATEMENT

Punjab State Electricity Board

EXISTING TARIFF FOR SUPPLY OF ENERGY

1. "SCH. D. S".	DOMESTIC SUPPLY		
	1st 15 Units/month	..	31.25 Paise per unit
	Next 25 ,, ,,	..	12.50 ,, ,,
	Above 40 ,, ,,	..	6.25 ,, ,,
2. "SCH. C. S".	COMMERCIAL SUPPLY		
	1st 30 Units/month	..	31.25 Paise per unit
	Next 50 ,, ,,	..	12.50 ,, ,,
	Above 80 ,, ,,	..	9.28 ,, ,,

[Irrigation and Power Minister]

3. "SCH. S. P". SMALL POWER (FOR LOADS UP TO 20 KW.)

1st 500 Units/month	..	10.94 Paise per unit
Next 1,000 ,, ,,	..	9.38 ,, ,,
Above 1,500 ,, ,,	..	7.81 ,, ,,

4. "SCH. M. S". MEDIUM SUPPLY (FOR LOADS FROM 21 TO 100 kW.)

Demand charges Rs 6.00 per kW./month.

Plus

Energy charges

1st 5,000 Units/month	..	5.31 Paise per unit
Next 10,000 ,, ,,	..	4.69 ,, ,,
Above 15,000 ,, ,,	..	4.38 ,, ,,

Subject to a maximum overall rate of 9.38 Paise per unit.

5. "SCH. L. S". LARGE SUPPLY (FOR LOADS ABOVE 100 kW.)

Demand Charge Rs 5.00 per kVA per month

Plus

Energy charges.

1st 100,000 Units/month	..	4.06 Paise per unit.
Next 200,000 ,, ,,	..	3.75 ,, ,,
Above 300,000 ,, ,,	..	3.44 ,, ,,

Subject to (i) a rebate of 0.94 P/Un for all units in excess of 36 units for kVA/month

(ii) A maximum overall rate of 5.63 P/unit.

6. "SCH. S. L." STREET LIGHTING SUPPLY

Energy Charges	..	14.06 Paise per unit

Note.—A rebate of 25 per cent for street lighting in village Panchayats is allowed.

7. "SCH. A. P." AGRICULTURAL SUPPLY UP TO 20 kW/RURAL COTTAGE INDUSTRIAL SUPPLY (UP TO 10 BHP).

1st 1,500 units/month	..	9.38 Paise per unit
Above 1,500 ,, ,,	..	7.81 ,, ,,

8. "SCH. G. S." GRID SUPPLY TO LICENSEE

Demand Charges Rs. 5.50 P. kVA/month

Plus

Energy Charges

1st 10,000 units/month	..	4.38 Paise/month
Next 20,000 ,, ,,	..	4.00 ,, ,,
Above 30,000 ,, ,,	..	3.75 ,, ,,

Subject to overall maximum rate of 7.31 Paise per unit.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि हिल एरियाज़ ऐडवाइजरी कमेटी की इन्डस्ट्रीज़ सब-कमेटी ने गवर्नमैंट को कोई इस किस्म की रिकमैन्डेशन भेजी है कि जिन बैक्वर्ड्ज हिली एरियाज के देहातों को कमरशल बेसिज़ पर इलैक्ट्रिसिटी नहीं दी जा सकती उन को नान-कमरशल बेसिज़ पर ट्रीट किया जाए और उन देहातों को नान-कमरशल बेसिज़ पर बिजली दी जाए ?

मन्त्री : ऐडवाइजरी कमेटी ने तो कोई इस तरह की स्पैसिफिक रिकमैन्डेशन नहीं की है । लेकिन ऐसी कोई प्रोपोज़ल नहीं है कि टैरिफ को रिवाईज़ किया जाए । हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए टैरिफ है वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में पहले ही बहुत कम है ।

COMPLAINT AGAINST S.D.O., PEWAH SUB-DIVISION AND A CANAL PATWARI OF PEWAH CIRCLE

*9370. **Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether he received on the 28th January, 1966 any written complaint from an M.L.A. of Karnal, against the S.D.O., Pewah Sub-Division and the Canal Patwari of Pewah Circle; if so, the action, if any, taken thereon?

Chaudhri Rizaq Ram : No.

BUNDS ON BOHA RAJBAHA OF GHAGGAR BRANCH

*9978. **Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Chief Engineer (South) raided bunds which were alleged to be unauthorised on the Boha Rajbaha of the Ghaggar Branch on 12th November, 1965;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the said Chief Engineer found any unauthorised bunds ;

(c) whether any officer was suspended as a result of the said raid; if so, on what charges and the details of action so far taken against him ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes, for negligence of duty and mismanagement. Report of enquiry officer is awaited.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Minister : Two Sectional Officers were suspended and the Sub-Divisional Officer and the Executive Engineer were transferred.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मन्त्री : हां, यह बात ठीक है । उस ऐक्स. ई. ऐन ने रिप्रिज़ैंटेशन की थी कि जिस ऐस. ई. को एनक्वायरी के लिए लगाया गया था उस की उस के साथ कोई प्रसनल इलविल्ल थी और उसके खिलाफ कम्पलेंट आई हुई थी यह एनक्वायरी एनट्रस्ट होने से पहले । इस लिए कि इस में कोई बायस न हो, ऐसा किया गया ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਾਈਂਡਿੰਗਜ਼ ਕਦ ਤਕ ਮਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

मन्त्री : यह मैं नहीं कह सकता । कुछ टाईम तो लगेगा ही । It will take some time.

SUPPLY OF ELECTRICITY IN DISTRICT MAHENDRAGARH

***9692. Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of the schemes formulated for supplying electricity to district Mahendragarh together with the details thereof ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Names of villages covered in the scheme	Names of villages electrified
1.	2	3	4	5
		Rs		
1.	S. P. E. of Dadri	1,26,504.00	Dadri	Dadri
2.	S. P. E. of Mohindergarh	1,45,410.00	Mohindergarh	Mohindergarh
3.	S. P. E. of Narnaul, Ateli	5,48,940.00	Narnaul Ateli	(1) Narnaul
				(2) Ateli
4.	S. P. E. of Jhoju Kalan and Kaliana and S. R. A.	9,81,018.00	(1) Jhoju Kalan	(1) Jhoju Kalan
			(2) Kaliana	(2) Aswari
			(3) Aswari	(3) Towala
			(4) Tiwala	(4) Patal
			(5) Badal	(5) Atela Khurd
			(6) Atela Kalan	(6) Atela Kalan
			(7) Atela Khurd	(7) Jhoju Khurd
			(8) Jhoju Khurd	(8) Pachopa Kalan
			(9) Godana	(9) Todi
			(10) Pachopa Kalan	(10) Pachopa Khurd
			(11) Todi	(11) Bindra
			(12) Pachopa Khurd	(12) Kaliana
			(13) Bindra Ban	(13) Gudana
			(14) Mandi Harya	(14) Mandi Pran
			(15) Mandi Parana	(15) Mandi Harya
			(16) Berla	(16) Atela Kalan (New)
			(17) Atela Kalan (New)	

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Names of villages covered in the scheme	Names of villages electrified
1	2	3	4	5
		Rs		
5.	Electrification of 9 Nos. villages towards North of Dadri	7,92,430.00	(1) Rawaldhi	(1) Rawaldhi
			(2) Kamodha	(2) Kamodha
			(3) Misri	(3) Misri
			(4) Jhinjar	(4) Jhinjar
			(5) Achina	(5) Achina
			(6) Sanwar	(6) Sanwar
			(7) Sanjarwar	(7) Sanjarwar
			(8) Rohila	(8) Rohila
			(9) Bond Kalan	(9) Bond Kalan
6.	Electrification of villages Kaniana Khas and S. R. A.	5,80,358.00	(1) Sagra	(1) Kaninana Khas
			(2) Bhojawas	(2) Gada
			(3) Jhagrauli	(3) Chalawas
			(4) Goda	(4) Bhojawas
			(5) Ghalowas	(5) Jhagrauli
			(6) Dhananda	(6) Dhanauda
			(7) Kaniana Khas	(7) Segra
			(8) Othani	(8) Othani
7.	Electrification of villages Imlota and S. R. A.	14,30,135.00	(1) Brishamashpur	(1) Bhagwi
			(2) Bhagwi	(2) Sarupgarh

			(3) Sarupgarh	(3) Dhani
			(4) Imlota	(4) Shamaspur
			(5) Dhani	(5) Khatiawas
			(6) Patuwas	(6) Loharwala
			(7) Shamaspur	(7) Santor
			(8) Khatiawas	(8) Kanethi
			(9) Loharwala	(9) Morwala
			(10) Nimli	
			(11) Santor	
			(12) Kanethi	
			(13) Morwala	
			(14) Kidara	
			(15) Bagoa	
8.	Electrification of Kheri Sanwal Khanpur Kalan and S. R. A.	5,90,753.00	(1) Kapuri	(1)
			(2) Mori	(2) Mori
			(3) Kheri Sanwal	(3) Gothara
			(4) Mehranana	
			(5) Tikan Kalan	
			(6) Santokh Pura	
			(7) Gothara	
			(8) Makrani	
9.	Electrification of villages Rambas, Gokal, Kadma and S. R. A,	14,10,032.00	(1) Ramalwas	Ramalwas
			(2) Gokal	
			(3) Rambas	
			(4) Dugroli	
			(5) Kanhera	
			(6) Nimar	
			(7) Chandwas	
			(8) Hansawas Khurd	

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Names of villages covered in the scheme	Names of villages electrified
1	2	3	4	5
		Rs		
			(9) Jeoli	
			(10) Kashkaudh	
			(11) Hansawas Kalan	
			(12) Dhansari	
			(13) Kadma	
			(14) Badrai	
			(15) Chandani	
			(16) Main Khurd	
			(17) Main Kalan	
			(18) Nauran Gabad	
			(19) Rudrol	
			(20) Bijna	
			(21) Jawa	
			(22) Badhwana	
			(23) Palri	
10.	Electrification of villages Khatodra, Balana, Madho-Garh, Satnali and S. R. A.	14,24,802·00	(1) Khatodra	
			(2) Balana	
			(3) Madhogarh	
			(4) Gadarwas	
			(5) Dalanwas	

			(6) Sureti Jakhir	
			(7) Sureti Hariana	
			(8) Sureti Mawniana	
			(9) Dhana	
			(10) Bas	
			(11) Pathrwa	
			(12) Jarwa	
			(13) Shampur	
			(14) Bassi	
			(15) Sohri	
			(16) Satnali	
			(17) Barra	
11.	Electrification of villages Dolana, Bawania, Partal and S. R. A.	14,96,504·00	(1) Chandhera	(1) Dolana
			(2) Bhandor	(2) Bawania
			(3) Nichi Beri	(3) Khera
			(4) Dolana	
			(5) Meghanwas	
			(6) Bacholi	
			(7) Chitlan	
			(8) Deowas	
			(9) Bhandar Unchi	
			(10) Jasawas	
			(11) Khera	
			(12) Bawania	
			(13) Akbarpur Nangal	
			(14) Koka	
			(15) Sunder Pura	
			(16) Jagoan	
			(17) Modian	
			(18) Bechini	

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Names of villages covered in the scheme	Names of villages electrified
1	2	3	4	5
		Rs		
			(19) Biyol	
			(20) Kharana	
			(21) Mondia Khera	
			(22) Partal	
			(23) Rambas	
			(24) Kakrala	
			(25) Bhojwas	
			(26) Gomla	
			(27) Mohamad Pur	
			(28) Nangal	
			(29) Dongrajat	
12.	Electrification of Jatwas, Jonawas, Serohi and S.R.A.	13,08,858.00	(1) Khaira	Khaira
			(2) Jatwas	Jatwas
			(3) Jandriawas	
			(4) Jonawas	
			(5) Budin	
			(6) Balicha	
			(7) Nebheri	
			(8) Dadhor	
			(9) Sohia	

			(10) Nimbi	
			(11) Chhajawas	
			(12) Karoli	
			(13) Dolot	
			(14) Serohi Nangal	
			(15) Nehlawas	
			(16) Kuksi	
			(17) Barawas	
			(18) Gadhiya	
			(19) Pal	
			(20) Kherki	
			(21) Galaula	
13.	Electrification of villages Khas Pur, Nawar Nangar and S. R.A.	25,55,980.00	(1) Luni	
			(2) Shaikhpur	
			(3) Nasib Pur	Nil
			(4) Nangtheri	
			(5) Bargaon	
			(6) Barkoda	
			(7) Kutbapur	
			(8) Luni Kalan	
			(9) Shawan Pur	
			(10) Saloni	
			(11) Lehroda	
			(12) Feizabas	
			(13) Hodiana	
			(14) Rampura	
			(15) Mai	
			(16) Akbar Pur Ramun	
			(17) Mitar Pura	
			(18) Khas Pur	

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Name of villages covered in the scheme	Name of villages electrified
1	2	3	4	5
		Rs		
			(19) Kham Pura	
			(20) Sima	
			(21) Umara Bad	
			(22) Sakar Pur Mehta	
			(23) Manolana	
			(24) Nawaz Nagar	
			(25) Azim Nagar	
			(26) Hazi Pur	
			(27) Bas Husain Khan	
			(28) Abdulan Nagar	
			(29) Mahram Pur	
			(30) Dharson	
			(31) Gohli	
			(32) Khantoli Sultanpur	
			(33) Jakhani	
			(34) Khorma	
			(35) Baproli	
			(36) Jadon Pur	
			(37) Chanalia	
			(38) Mohamad Pur	
			(39) Dohar Kalan	

			(40) Dohar Khurd	
			(41) Godh	
			(42) Bawah Kalan	
			(43) Bawah Khurd	
			(44) Bado Pur	
			(45) Raghunath Pura	
			(46) Makhsus Pur	
			(47) Hamir Pur	
			(48) Bhankari Khurd	
			(49) Bhankari Kalan	
			(50) Khatoli Khurd	
			(51) Dochana	
14.	Electrification of villages Durga-Ka-Nangal, Karauli and S.R.A.	20,34,160.00	(1) Amarpur Jurasi	
			(2) Tahla	
			(3) Mukand Pur Gujran	Nil
			(4) Rerondla	
			(5) Dholera	
			(6) Begopur	
			(7) Meghot Binja	
			(8) Meghot Nala	
			(9) Durga-Ka-Nangal	
			(10) Gangotana	
			(11) Gohand	
			(12) Balki Dhani	
			(13) Musnota	
			(14) Dhankora	
			(15) Saidali Pur	
			(16) Bodhanti	
			(17) Dosat Pur	
			(18) Shahabazpur	

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Name of villages covered in the scheme	Name of villages electrified
1	2	3	4	5
		Rs	(19) Sirin	Nil
			(20) Lujat Pur (Lojata)	
			(21) Islam Pur	
			(22) Naizali Pur	
			(23) Gaonri	
			(24) Basirpur	
			(25) Karauli	
			(26) Malauli	
			(27) Chiraru	
			(28) Ghatasher	
			(29) Napla	
			(30) Nizampur	
			(31) Khawari Was	
			(32) Kultaz Pur	
			(33) Thana	
			(34) Hassan Pur	
			(35) Panch Nota	
15.	Electrification of villages Sekha, Kale-ka- Nangal and S.R.A.	29,59,364.00	(1) Kadanya	Nil
			(2) Sekha	
			(3) Fazli Pur	
			(4) Mandhana Kalan	
			(5) Mandhana Khurd	

(6) Bhushan Kalan	Nil
(7) Bhushan Khurd	
(8) Sobha Pur	
(9) Tazi Pur	
(10) Shah Pur	
(11) Dhani Bathiatha	
(12) Khan Pur	
(13) Khanwi	
(14) Murari Pur	
(15) Karota	
(16) Daongli	
(17) Khatoli Jat	
(18) Khatoli Ahir	
(19) Tota Heri	
(20) Salar Pur	
(21) Bhojawas	
(22) Shimli	
(23) Akbar Pur Sirohi	
(24) Bhamarkha	
(25) Malodi	
(26) Nangli	
(27) Gadwa	
(28) Kamania	
(29) Pipa-Ka-Nangal	
(30) Chhapra Bibi Pur	
(31) Antri	
(32) Behari Pur	
(33) Kalia-Ka-Nangal	
(34) Serohi Bahali	
(35) Mohan Pur	

(2[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the scheme	Estimated Cost	Name of villages covered in the scheme	Name of villages elelctrified
1	2	3	4	5
		Rs	(36) Zain Pur	Nil
			(37) Nangal Chowdhri	
			(38) Kalba	
			(39) Dhantal	
			(40) Lohia-Ka-Nangal	
			(41) Binhari	
			(42) Thanwas	
			(43) Amarpura	
			(44) Sodha-Ka-Nangal	
			(45) Dhan	
			(46) Bhudwal	
			(47) Asrawas	
			(48) Morand	
			(49) Nemat Pur	
			(50) Premki-Dhani	
			(51) Gotri	
			(52) Nain	
			(53) Akoli	
16.	S. P. E. for the electrification of villages Jharli, Nahar and villages enroute.	7,92,430.00	(1) Ghasola	Ghasola
			(2) Balkara	Balkara
			(3) Makrana	Makrana

The other villages included under this scheme full in district Rohtak.

श्री बनवारी लाल : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्राजैक्ट्स की लिस्ट मुझे दी गई है, उन में से कौन कौन से प्राजैक्ट्स इलैक्ट्रिफाई हो चुके हैं ?

मन्त्री : यह बात तो मेन सवाल में आप ने पूछी नहीं थी । इस में तो आप ने यही पूछा था कि कौन कौन से प्राजैक्ट्स सैंक्शन हुए हैं । वह सारी डिटेल्ज़ मैंने आप को दे दी है । यह सवाल इस से पैदा नहीं होता ।

Mr. Speaker: Proper reply is there.

DISPUTE BETWEEN THE COOPERATIVE SUGAR MILLS AT BHOGPUR AND AT MORINDA AND THE SUGAR-CANE GROWERS

*9813. **Comrade Gurbakhsh Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government has appointed some Committee to find out a solution of the dispute regarding recovery of two annas per 40 kilograms of sugar-cane existing between the managements of the Cooperative Sugar Mills at Bhogpur and at Morinda and the sugar-cane growers of the areas;

(b) whether the said Committee has submitted its reports, if so, the details of the recommendations made by it;

(c) whether the said recommendations have been implemented, if not, the reasons therefor?

Ch. Rizaq Ram (a) Yes.

(b) Yes. The details are placed at the table of the House.

(c) The recommendations with regard to stoppage of two annas deduction have been accepted and implemented in both the mills Bhogpur and Morinda.

Information asked for in item (b) of starred question No. 9813—tabled by Comrade Gurbakhsh Singh M. L. A.

Recommendations of the Sub-Committee appointed for Sugar Mills, Bhogpur.

"The sub-committee went through the memorandum prepared by the Member Secretary and examined the estimated financial forecast for the seasons 1965-66. After examining the figures, the sub-committee was unanimously of the view that the Janta Co-operative Sugar Mills Ltd. Bhogpur is in a position to pay the last instalment of Rs. 5,56,391/- payable to the Industrial Finance Corporation of India in May, 1966, without applying the cut of 13 paise per maund from the price of sugar-cane for the current season. The sub-committee, therefore recommended to Government that the cut should be stopped with immediate effect.

[Minister for Irrigation and Power]

Recommendations of the Sub-Committee appointed for Sugar Mills, Morinda.

(1) Every bondee for the season 1965-66 who is not a share-holder of the society, be called upon to purchase at least one full share of Rs. 100/- immediately. The sub-committee was of the view that normally in a surplus year like the present, the cane of the shareholders only should have been accepted by the society. If it extended the facility to a non-shareholder, he may be brought at par with the shareholder, by subscribing to at least one full share.

(2) The amount of second call money due from the bondees for the season 1965-66 should be recovered either in lump sum or by applying a deduction to the cane price supplied by him during the season.

(3) No deduction from the cane price should be made in respect of the share holders during 1965-66 season.

(4) The society shall announce immediately that next year it shall enter into bond for the supply of sugar-cane with the share holders within 15 miles radius of the Sugar Mill only. This will enable the society to increase its membership and so also the share-capital.

(5) Till Government takes a final decision in the matter, deduction from the cane price of share-holders only should be suspended forth-with.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਕਮੈਨਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मन्त्री : उन पर गौर किया जा रहा है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब यह बताएंगे कि जो शेअर होल्डर्ज़ नहीं हैं उन से अब भी दो आने के हिसाब से डीडक्शन की जा रही है जब कि उन को शेअर होल्डर्ज़ के तौर पर केन सप्लाई करने की फैसिलीटीज़ नहीं है ?

मन्त्री : ऐसी कोई बात नहीं है । अगर हो तो आप नोटिस में लाएं उसको देखा जा सकता है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ—ਦੋ ਆਨੇ ਕਟੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 20% ਕੱਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਬੜੇ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਖੁਦ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ—, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਮਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ?

मन्त्री : जो कमेटी की रिकमैंडेशंज़ है, उन में कुछ वेगनैस थी। रजिस्ट्रार को बुलाया गया और डिस्कशन कर रहे हैं। उस में कुछ ऐसी रिकमैंडेशन थी दो आने के हिसाब से जो कट लगाया उस में से आधा रुपया शेयर से कुलैक्ट किया हुआ था और बाकी का हिस्सा पूरा कर लेने की बाबत रिकमैंडेशन थी। इस सम्बन्ध में डिस्कशन करके इस मैंटर को फाइनेलाइज़ किया जा रहा है। वैसे The Registrar has been asked to comply with the directions fully.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि भोगपुर और मोरिंडा शूगर मिल्ज़ की बाबत तो हिदायात जारी की है कि दो आने का कट नहीं होना चाहिए, क्या दूसरी कोआपरेटिव मिल्ज़ बटाला, पानीपत और रोहतक के बारे में भी यह हिदायात जारी की गई हैं ?

मन्त्री : ऐसी कोई बात नहीं है। जहां जहां पर कोई इन्डीविजुअल केस एराइज़ हुआ लोगों की रिप्रिज़ैंटेशंज़ आई और वहां वहां केस को ऐग्ज़ामिन कराया है। वैसे यह चीज़ यूनीवर्सली नहीं की है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब जब यह पालेसी मैटर है कि जो शेयर होल्डर न हों और वह मिल को अपना गन्ना दें तो उन से यह दो आने फी मन के हिसाब से ऐज़ शेयर मनी न काटी जाए तो यह चीज़ पंजाब में जितनी भी शूगर मिल्ज़ हैं उन पर क्यों लागू नहीं की जा रही। जब पालेसी मैटर है तो......

मन्त्री : यह पालेसी मैटर नहीं है वैसे जहां जहां इस बारे में पब्लिक की तरफ से ऐसी रिप्रीज़ैंटेशन्ज़ आई है वहां के लिए यह हुकम जारी कर दिया गया है और जहां से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई वहां नहीं किया गया। अगर आनरेबल मैम्बर के नोटिस में ऐसी चीज़ कहीं होती है तो वह हमारे नोटिस में लाएं तो मुनासिब कार्यवाही की जाएगी।

NUH CO-OPERATIVE MARKETING-CUM-PROCESSING SOCIETY, LTD. NUH, DISTRICT GURGAON.

***9997 Chaudhri Khurshid Ahmed** (Put by Babu Ajit Kumar): Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Nuh Co-operative Marketing-cum-processing Society (Oil Mills) Ltd., Nuh, district Gurgaon was closed down for some time in the year 1964-65 without proper

[Babu Ajit Kumar For Chaudhri Khurshed Ahmed]

authorisation from the Board of Directors, if so, the name/ names of persons with their designation who were responsible for this unauthorised closure of the said society;

(b) whether any enquiry in this connection was instituted by the Assistant Registrar, Cooperative Socities, Palwal, if so, a copy of the report, if any submitted by him be laid on the table of the House;

(c) whether any amount was proposed by the office mentioned in part (b) above as surcharge to be realised from the defaulting person or persons, if so, the extent of the amount so proposed and the name or names of persons from whom it was to be realised;

(d) whether the said amount has since been realised, if not, the detailed reasons therefor?

Chaudhri Rizaq Ram:

The resquisite information is laid on the table of the House.

(a)	Part I.	Yes from 12-6-64 to 29-6-64.
	Part II.	Shri Tayab Hussian Khan President of the society. This point was however, brought on the Board meeting on 23-6-64 and it was resolved that the Mill is closed with the verbal order of the President. Now it should be started.
(b)	Part I.	Yes
	Part II.	A copy of the requisite enquiry report is attached herewith.
(c)	Part I.	Yes.
	Part II.	Rs. 1,145.49.
	Part III.	Sh. Tayab Hussain Khan, President of the Society.

(d) No. The matter is pending decision with the Deputy Registrar.

ANNEXURE

Enquiry Report of the Nuh Co-operative Marketing Cum Processing Society, Ltd. (Oil Mills), District Gurgaon.

The Nuh Co-operative Marketing-cum-Processing Society was registered on 11th August, 1956. It was organised with the object of processing of oil seeds. For this purpose the society installed forty bengal type kohloos and two expellers. Total expenditure on building and machinery was incurred to the tune of Rs. 245879·43 (building Rs. 1,22,784 and machinery Rs. 1,23,094·76). The Mill was commissioned into action on 13th April, 1964 with 23 persons on roll.Forty Kohloos were operating in one shift only. In the beginning purchases and sales were made by the Manager. Later on for the sale of oil and oil cakes, Shri Tara Chand and Hakim Ajmal Khan were appointed by the Committee vide its resolution No. 9 dated 23rd June, 1964. Again Shri Shamshudin member of the society was appointed to purchase oil seeds and sell oil cakes vide resolution No. 6 dated 5th June, 1964. In the same resolution Sarvshri Tara Chand and Mohd. Yasin Khan were authorised to sell oil.

2. On 23rd June, 1964 Shri Tara Chand was authorised to purchase oil seeds. For the sale of oil and oil cakes, Shri Tara Chand and Hakim Ajmal Khan were authorised vide resolution No. 9 dated 23rd June, 1964.

3. The Mill had worked from 13th April, 1964 to 11th June, 1964. The President, as reported by the then Manager to the Assistant Registrar gave him verbal order to close the Mill forthwith. So from 12th June, 1964 the Mill was closed by the Manager which remained closed upto 29th June, 1964 for 18 days. The Board of Directors met on 23rd June, 1964 and resolved that Mills which was closed under the orders of the President, Sh. Tayab Hussain Khan should be restarted. So it was switched on to action on 30th June, 1964 again. At the time of the closure of the Mills 15 persons were working in the Mills. As a result of the closure, the society had to bear the expenses of the staff given below—

S. No.	Name and designation	Pay P.M.	No. of days for which paid	Amount
		Rs		
1.	Sh. S. L. Gupta, Manager	500	18	300·00
2.	Sh. Radhe Shyam, Typist	100	18	80·00
3.	Sh. Chameler Khan, oil clerk	80	18	48·00
4.	Sh. Ayub Khan, Chaukidar	50	18	30·00
5.	Sh. Shabadin	45	15	22·50
6.	Sh. Prabhati	50	3	5·00
7.	Sh. Gajraj, Mistri	175	18	105·00
8.	Sh. Ajmar Singh, Lineman	85	18	51·00
9.	Sh. Dal Chand, Lineman	85	18	51·00
10.	Sh. Chet Ram	150	18	90·00
11.	Sh. Kacheroo, Fitter	75	18	45·00
12.	Sh. Majid Khan, Kohloo Cutter	125	4	16·66
13.	Sh. Roshan Lal, Fitterman	110	18	66·00
14.	Sh. Hazari Lal, Munim	100	18	60·00
15.	Sh. Ranbir, Kohloo colly	50	14	23.33
	TOTAL			973.49

4. The above action of Shri Tayyab Hussain Khan was absolutely wrong and without jurisdiction. Bylaws of the society or Co-operative Act and Rules do not vest any authority on the President to stop the Mills from working. Further no reason for taking such a drastic action was advanced. If there was any thing wrong, the President should have called special meeting of the Board and should have taken the desired decision.

6. During the month of June, 1964, the society worked for ten days. The average processing oil seeds comes to 2592 kilos per day. In 18 days the following business would have been done.

Working days	15
Sundays	3

[Minister for Irriggtion and Power]

	Rs
Estimated cost of oil seeds @ Rs. 120/- per quintal	46,626.00
Arhat	583.00
Purchase tax	932.00
Establishment	973.00
Cartage and labme	91.00
Electricity	396.00
Intt. on loan	152.00
Total	49753.00
Sale oil 129.60 quintals @ Rs. 300 per quintal	38,880.00
Oil cakes 259.20 quintals @ Rs. 42.50 per quintal	11,015.00
Total	49,895.00
Profit	142.00

Thus the society would have earned a net profit of Rs.142. if it had worked in those days. It may be added that the profit might have been much higher as prices of oil were rising rapidly in those days.

In addition to it, due to closure of Mills reputation of the society received a great set back in the market and in the area.

From the above, it is evident that the society has suffered following loss for which, Sh. Tayab Hussain Khan, President is responsible, because of issuing wrong orders.

	Rs
1. Cost of establishment	973.49
2. Estimated profit	142.00
Total	1,145.49

Notwithstanding above facts, it is worth while mentioning here that there is no record in black and white to show that the President gave such orders. The Manager has stated that the President gave verbal orders. He brought it to the notice of the Assistant Registrar, Cooperative Societies, Palwal. There is nothing on the record that the Assistant Registrar Palwal wrote any letter to Shri Tayab Hussain Khan asking for clarification for the closure of the Mills. Further the the committee meeting held on 23rd June, 1964 which resolved to restart the Mill was not attended by the president. The committee, too, did not seek any explanation from the President for his arbitrary action for closing the mill.

Under the circumstances, Shri Tayab Hussain Khan President may be asked to clear his position for this commission.

Sd/ Om Parkash Sudal
Assistant Registrar,
Co-operative Societies, Palwal
25-1-1966.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ 26-1-1966 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਅਦ 1,145 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੀਏਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'the matter is pending decision of the Deputy Registrar.' ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ?

मन्त्री : डिप्टी रजिस्ट्रार के पास इनक्वायरी भेजी है और वही उस पर ऐक्शन एक्सपेडाईट करेगा।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਸੀਅਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

मन्त्री : जो प्रेज़ीडेंट है या जो मेम्बर कनसर्नड है, उन से पूछना है। उस के बाद ही ऐक्शन लिया जाएगा।

GRANT OF LOANS TO THE MEMBERS OF SCHEDULED CASTES FOR PURCHASE OF BANJAR EVACUEE LAND

*9896. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Government have issued instructions to the Deputy Commissioners and Sub-Divisional Officers (Civil) in the State to stop the grant of loans to members of the Scheduled Castes for the purchase of Banjar evacuee land, if so, the manner in which the Harijan Welfare Fund is proposed to be spent ;

(b) whether it is a fact that all the departments have been directed to spend 30 per cent of their funds on the Welfare of the Harijans ?

Chaudhri Chand Ram : (a) Yes. The schemes to be financed out of Harijan Kalyan Fund are being worked out.

(b) It has not been possible to set apart any percentage of the budget allocations under the General Sector Schemes. However, departments have been advised that other things being equal, preference should definitely be given to Scheduled Castes & Backward Classes.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਗੀ ?

मन्त्री : शायद आनरेबल मेम्बर को इस बात का इल्म नहीं है कि जो इवैक्वी लैंड है वह रैस्ट्रिक्टिड आकशन में हरिजनों को देनी है और वह उस के लिए उन्हें सिर्फ बिड मनी का 5 फी सदी उस वक्त देना पड़ेगा और बाकी की रकम 20 किश्तों में उन्हों ने देनी होती है जो कि उन्हों ने दस सालों में देनी होती है और पहली किश्त एक साल के बाद देनी होती है ... ...

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪਹਿਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ?

मन्त्री : पैसे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता पहले जब उन ज़मीनों की नीलामी हुई थी तो सरकार 5 हज़ार रुपए for full payment दे देती थी लेकिन यह चार्ज होने के बाद देती थी। अब गवर्नमेंट ने यह पालेसी चेंज कर दी है। अब रैस्ट्रिक्टिड आकशन हरिजनों के लिए होती है और पहले उन्हें बिड मनी का 5 फी सदी देना पड़ता है और बाकी रकम 10 सालों में 20 किशतों में देनी पड़ती है। इस लिए अब लोन बन्द कर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या यह सही नहीं है कि यह ज़मीन हरिजनों को नहीं मिल रही ? ज़मींदार जो हैं वह हरिजनों से बोली करवा कर खुद पैसे देक ज़मीन उन के नाम बोली में करवा देते हैं और बाद में उन से खुद ले लेते हैं।

मन्त्री : यही बात हमारे नोटिस में आई थी इस लिये हम ने उन पर यह पाबन्दी लगा दी है कि वह ज़मीन 10 साल तक किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकेगा ।

चौधरी रण सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या आज कल इवैक्वी लैंड की आकशन बन्द है ?

मन्त्री : नहीं, आकशन जारी है। अगर किसी जगह पर बन्द की गई है और आनरेबल मेम्बर के नोटिस मे यह हो तो वह हमारे नोटिस में लाएं ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ?

मन्त्री : यह तो अबवीयस बात है कि जब वह लोन रियेलाईज किया जाएगा तो यह उसी फंड में जाएगा ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਜਦ ਕਿ ਅਜ 16 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

मन्त्री : इस में कुछ ए० जी० की तरफ से अड़चन डाली गई थी इस करके देर हो गई है। यह रकम जरूर दी जाएगी और मैं हाउस को एश्योर कराता हूं कि इन स्कीमों का एक पैसा भी लैप्स नहीं होने दिया जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

मन्त्री : ऐसा कोई आर्डर नहीं किया गया। हम ने तो बल्कि यह आर्डर किए हुए हैं कि जहां जहां जमीन बेची जाए उस के कब्जे जल्दी दिलाए जाए।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ . ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ?

मन्त्री : स्पीकर साहब, इस का इस सवाल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर यह सेपरेट नोटिस इस के लिए दे दें तो जवाब दिया जाएगा।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मिनिस्टर साहब की नालेज में यह चीज़ है कि हरिजनों को जो लोन दिए जाते हैं उन में से उन्हें लोन दिलाने वाले सौ-सौ या दो दो सौ रुपए की गोली खुद बना लेते हैं, अगर है तो गवर्नमेंट इस को रोकने के लिए क्या एक्शन ले रही है ?

मन्त्री : यह काम तो एड हॉक कमेटियां करती हैं। अगर आनरेबल मेम्बर के नोटिस में कोई ऐसे केस हैं तो वह बताएं। हम एकशन लेने के लिए तैयार हैं।

REHABILITATION OF OUSTEES FROM PONG DAM AREA

*8914. **Shri Rup Singh Phul** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total number of persons likely to be ousted due to the construction of the Pong Dam ;

(b) the area and location of the land provided or proposed to be provided for the rehabilitation of the oustees referred to in (a) above ;

(c) the maximum and minimum area of land proposed to be allotted for the rehabilitation of each oustees' family falling in the category of landowners, tenants and landlords, separately ;

(d) the time by which the process of ousting the persons referred to in part (a) above is expected to commence ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The total number of persons likely to be affected due to the construction of Pong Dam is roughly estimated at 72,000.

(b) 3.25 lacs acres of land is proposed to be allocated by Rajasthan Government in Bikaner Division in the zone commanded by the Rajasthan Canal for rehabilitation/allotment to the oustees of Punjab and Himachal Pradesh.

[Minister for Irrigation and Power]

(c) No final decision has so far been taken in this regard.

(d) According to present planning, the process of displacement of oustees of Beas Dam Project up to the elevation level of 1,290 feet is expected to commence from June, 1967.

श्री रूप सिंह फूल : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि जब पहला निकासी जत्था यहां से राजस्थान जाएगा जहां पर उन को आबाद करना है क्या उन के वहां जाने तक उन के लिये ज़रूरी सहूलियात जैसे मकान वगैरा बहम पहुंचा दी जाएंगी या नहीं ?

मंत्री : यह सवाल इस सवाल से ऐराइज़ तो नहीं होता मगर इतना अर्ज़ करता हूं कि इन लोगों को भी मकान, ट्रांस्पोर्ट, स्कूल और दूसरी सारी सहूलियात जो भाखड़ा आउस्टीज़ को दी गईं इन को भी दी जाएंगी।

श्री रूप सिंह फूल : क्या यह मकान और ट्रांस्पोर्ट की सहूलियात उन को काफी अरसा पहले दी जाएंगी ताकि वह आराम से अपने साज़ोसामान के साथ वहां पर पहुंच सकें ?

मंत्री : जिन की ज़मीन ऐक्वायर कर रहे हैं उन को मुआवज़ा साथ साथ दे रहे हैं, लैंड ऐक्वीज़ीशन अफसर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल : इन्होंने कहा है कि लैंड-ओनरज़ को ज़मीन दी जायगी। मगर जो लैंडलैस हरिजन हैं क्या सरकार ने उन के कारोबार के बारे में भी कुछ सोचा है ?

मन्त्री : लैंडलैस लेबरर्ज़ को आबाद करने के लिये उन के ऐवोकेशन्ज़ का भी इतज़ाम करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਲੱਧੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਐਕਾਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

मन्त्री : उन्होंने ज़मीन जो ऐलोकेट की है वह बताई है। अब उसे हमारे अफसर देख रहे हैं कि वह कैसी है, अच्छी है या बुरी है। लोगों को अभी अलाटमैंट नहीं हुई।

श्रीमती सरला देवी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों को मैक्सीमम और मिनीमम कितनी ज़मीन दी जाएगी ताकि वह अपना गुज़ारा अच्छी तरह से चला सकें ?

मन्त्री : इस का जवाब 'सी' में आ गया है कि अभी इस का फैसला नहीं हुआ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन आउस्टीज़ को राजस्थान में बसाया जायगा क्या सरकार उन के लिये कोई हाउसिंग कालोनी बनाने के लिये तैयार है ?

मन्त्री : ज़मीन उन को देंगे, सहूलियात देंगे। कालोनी तो कोई नहीं होगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ?

मन्त्री : ऐसी कोई बात नहीं है ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ?

मन्त्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि अभी तो उन्होंने ज़मीन दी है अभी किसी को नहीं दी गई । कुछ 50 हज़ार ऐकड़ के करीब उन्होंने बताई है । उस एरिया को अफसर देख रहे हैं, अथारिटीज़ के रैप्रेज़ैंटेटिव्ज़ देखेंगे, उस के बाद पोज़ैशन ले लेंगे । ज़मीन पर कोई झगड़ा नहीं है, ज़मीन खाली पड़ी है । उन्होंने विलिंगनैस दी है कि वह तैयार हैं ।

पंडित सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के मकानात और ज़मीन ऐक्वायर हो चुके हैं उन को मुआवज़ा मिल चुका है ? क्या ऐसे भी लोग हैं जिन की ज़मीन और मकान तो इस में आ चुके हैं मगर उन को न तो मकान का मुआवज़ा दिया गया है और न ही मलबा उठाने के लिये मुआवज़ा दिया गया है ?

मन्त्री : इस के मुताल्लिक सेपरेट नोटिस दें वैसे मलबे के बारे में रैप्रेज़ैंटेशन्ज़ तो आए थे जो कि अथारिटीज़ को भेज दिये गए थे कि इस के बारे में फैसला करें । यह इस के मुताल्लिक फ्रैश नोटिस दें ।

APPLICATIONS FOR ELECTRIC CONNECTIONS FOR PUMPING-SETS IN TEHSIL UNA, DISTRICT HOSHIARPUR

*9848. **Shri Surinder Nath Gautam** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State —

(a) the total number of applications received for electric connections for pumping sets in tehsil Una, district Hoshiarpur, block-wise during the years 1964-65 and 1965-66, together with the names of the applicants and the villages concerned ;

(b) the total number of connections given so far with the total number of applications pending, stating the names in each case and reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram :

	Name of Block	Year	Number of applications	Remarks
(a)	1. Una	1964-65 1965-66	9 13	For rest of the information see Annexure 'A'
	2. Other Blocks	Nil	Nil	
(b)	1. Una	1964-65 1965-66	8 5	Ditto
	2. Other Blocks	Nil	Nil	

[Minister for Irrigation and Power]

Statement showing the particulars of applications for tube-well connections received in tehsil Una, district Hoshiarpur—Blockwise during the year *(1964-65 and 1965-66) with the names of applicants and villages

Serial No.	Name of the applicant	Name of village	Year	Connection given or not	The present position of the case	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Kamal Krishanan ..	Mallati	1964-65	Given	—	
2.	Shri Banta Singh ...	Charatgarh	1964-65	Do	—	
3.	Shri Shiv Paul Singh ...	Jalgran	1964-65	Do	—	
4.	Shri Sham Singh ..	Nagra	1964-65	Do	—	
5.	Shri Nand Singh ..	Do	1964-65	Do	—	
6.	Shri S. S. Soni ...	Hazipur	1964-65	Do	—	
7.	Shri Inder Singh ..	Do	1964-65	Do	—	
8.	M/s Miya Singyoga Singh ..	Do	1964-65	Do	—	
9.	Shri Ram Asra ..	Takka	1964-65	Not given	Demand notice to the applicant is being issued now. The delay is due to the fact that the estimate was found unjustified in the first instance.	
10.	Shri Ved Parkash ...	Baanoh	1965-66	Given	—	
11.	Shri Ram Rakha ..	Ransari	1965-66	Do	—	
12.	Shri Surinder Nath Gautam, M.L.A. ..	Santokhgarh	1965-66	Do	—	
13.	Shri Nasib Chand ..	Do	1965-66	Do	—	
14.	Sarpanch ...	Surewal	1965-66	Do	—	

15.	Shri Ishwar Dass	Chatara	1965-66	Not Given	Estimates have been got sanctioned. Demand Notices will be issued in turn.
16.	Shri Vishwa Nath	Santokhgarh	1965-66	Ditto	
17.	Shri Chet Ram	Ajola	1965-66	Ditto	
18.	Sarvshri Karam Singh-Surat Singh	Sanohli	1965-66	Ditto	
19.	Shri Kehr Singh	Hazipur	1965-66	Ditto	
20.	Shri Bhagwan Singh	Do	1965-66	Ditto	
21.	Shri Dhana Singh	Sajjowal	1965-66	Ditto	—
22.	Shri Ram Lal	Ajoli	1965-66	Ditto	Estimate is under preparation and demand notice will be issued in turn if the estimate is found justified.

Others Blocks.

No application from any other block of Una Tehsil has been received.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने सिक्योरिटी जमा करा दी है, जिन के ऐस्टीमेट सैंकशन हो चुके हैं उन को कुनैक्शन देने में क्या रूकावट है ?

मन्त्री : इस में कुछ टाइम तो लगता ही है । डिमांड नोटिस दिया जाता है, टैस्ट रिपोर्ट होती है, मैटीरियल का सवाल है। बाकी अगर किसी स्पैसिफिक केस के बारे में पूछना चाहते हों तो नोटिस दें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन के ट्यूब-वैल्ज़ भाखड़ा के नज़दीक हैं, जहां से कि बिजली पैदा होती है, उन की दरखास्तों पर अभी तक गौर न करने के क्या कारण हैं ?

मन्त्री : जहां जहां पर जस्टीफायेबल केसिज़ हैं, कुनैक्शन दे रहे हैं, नज़दीक या दूर का सवाल नहीं है । हुशियारपुर ज़िला और ऊना तहसील अनड्रीगेटिड ऐरिया है, इस लिये उन को प्रायर्टी बेसिज़ पे दे रहे हैं। कल सारे लैजिस्लेटर्ज़ वगैरह की मीटिंग बुलाई है, उस में डिसकस करेंगे ।

CANALS TAKEN OUT FROM THE MARKANDA RIVER

*9397. **Sardar Piara Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of canals taken out from the Markanda River for additional reclamation together with the names of such canals which have been completed so far ?

Chaudhari Rizaq Ram : Seven channels have been taken out from Markanda River for reclamation. Their names are :—

1. Main Gulha Reclamation Channel.
2. Pehowa Minor.
3. Bhunna Sub-Minor.
4. Pharpur Minor.
5. Bakhli Minor.
6. Papsar Sub-Minor.
7. Urnala Minor.

Works on all the channels have been taken up but these are yet to be completed in respect of earthwork in reaches where masonry works and other crossings are to be constructed, and also the masonry work and crossings.

कंवर राम पाल सिंह : मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है "येट टू बी कम्पलीटिड" तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चैनल बनाने में और कितना टाइम लगेगा ?

मन्त्री : इस में फन्ड्ज़ की बात है । पुल और क्रासिंग्ज़ बनाने हैं अगर पैसा मिल जाए तो बना देंगे ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस चैनल के कम्पलीट होने पर इस में पानी की सप्लाई के लिये मारकन्डा रिवर का पानी काफी होगा और वह कितने एरिया को सैराब करेगा ?

मन्त्री : इस में 6 डिफरैंट चैनल्ज़ हैं, कोई इक हज़ार क्यूसिक की और कोई कुछ । इस से काफी एकड़ रकबा रिक्लेम होगा, सैराब होगा ।

चौधरी नेत राम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो घघर रिक्लेमेशन स्कीम एक साल से बन्द पड़ी है उस को आप चालू करेंगे ?

मन्त्री : घघर का सवाल तो इस में से एराइज़ नहीं होता । मगर घघर के मुताल्लिक कई स्कीम्ज़ टेक अप कर रखी हैं । कुछ और रुपया मांगा है जैसे रंगाई कनाल के लिये, वग़ैरा वग़ैरा ।

कामरेड राम प्यारा : यह बहुत सारे सवालों के जवाब में कहते हैं कि इट डिपैंड्ज़ अपौन दी अवेलेबिलिटी आफ फंड्ज़ । तो क्या मिनिस्टर साहिब या गवर्नमैंट इस बात को वाज़य कर सकती है कि यह जो फंड्ज़ है यह दो साल में अवेलेबल होंगे या तीन साल में होंगे या इसी तरह से हाउस और पब्लिक को ससपैंस में रखा जायगा ?

मन्त्री : आनरेबल मेम्बर इस बात को ऐप्रीशियेट करेंगे कि इन्डो-पाकिस्तान जंग की वजह से महकमे के फंड्ज़ में काफी कटौती हुई और ड्रेनेज वग़ैरह के काम के लिये हमें रुपया न मिल सका, बहुत कम मिला । इस लिये ससपैंस तो है। डैफीनिटली नहीं कहा जा सकता कि कब रुपया मिल जाएगा।

कंवर राम पाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय ऐसा नहीं कर सकते कि तमाम चैनल्ज़ पर काम कन्टीन्यू करने की बजाए उन में से कुछ को, जो ज्यादा इम्पार्टेंट हों, पहले कम्पलीट कर लिया जाए । क्या ऐसा करने के लिये सरकार तैयार है ?

मन्त्री : देख लेंगे आनरेबल मेम्बर की इस सजैशन को ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45.

KACHA MOGA OF FATEHGARH DISTRIBUTARY AT BURJI NO. 21,000 OF UPPER BARI DOAB CANAL IN GURDASPUR DISTRICT.

*9983. **Comrade Jangir Singh Joga** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is a Kacha Moga of the Fatehgarh Distributary at Burji No. 2,1000 of the Uppar Bari Doab Canal (Amritsar Division) in Gurdaspur District ;

(b) whether he is aware of the fact that the amount to get this moga made pacca was deposited by the peasants concerned on the 31st May, 1961 ;

(c) whether he is further aware of the fact that the said Moga has not been made pacca and that neither Chak-Bandi nor Wara-Bandi has taken place so far ;

(d) if the reply to parts (a) to (c) above be in the affirmative, the reasons for the delay and the time by which the said Moga will be turned into a pacca one ?

Chaudhri Rizaq Ram :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) The areas on this outlet are not yet finalised. As a result of revised Chakbandi, numerous applications have been given by the shareholders, action on which is being taken. As soon as the areas are finalised the outlet will be installed on permanent basis. It is expected to be made pacca before Rabi 1966.

MISAPPROPRIATION OF OCTROI DUTY IN TARN TARAN MUNICIPAL COMMITTEE, DISTRICT AMRITSAR.

*9314. **Comrade Gurbakhsh Singh** : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Executive Officer of the Municipal Committee, Tarn Taran, district Amritsar has detected misappropriation/embezzlement of octroi duty on a large scale ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the date when it was detected with the details of the Mis-appropriation/embezzlement and the period since when it has been going on ;

(c) the approximate amount involved in the alleged misappropriation/embezzlement and the action, if any, taken so far against the persons involved therein ?

Sardar Ajmer Singh : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT RELATING TO ASSEMBLY QUESTION NO. *9814 ASKED BY COMRADE GURBAKHSH SINGH, M. L. A. REGARDING MIS-APPROPRIATION OF OCTROI DUTY IN TARN TARAN MUNICIPAL COMMITTEE, DISTRICT AMRITSAR

(a) Yes.

(b) (i) The first case was detected on 7th January, 1966.

(ii) A statement showing details of the cases of alleged mis-appropriation/embezzlement of octroi based on the information received from the Municipal Committee is added as Annexure 'A' to this statement.

(iii) The alleged misappropriation/embezzlement is reported to have been going on since April, 1965.

(c) (i) The approximate amount so far detected is Rs 1074.57.

(ii) The Municipal Committee has placed the following employees under suspension, pending enquiry :—

(i) Shri Ramdas Singh, Head Clerk.

(ii) Shri Ram Hari Narain Singh, Moharrir.

(iii) Shri Gurnam Singh, Moharrir.

(iv) Shri Ajit Singh Arora, Moharrir.

Shri Dip Kumar, Octroi Superintendent, has been transferred from Octroi Section.

ANNEXURE A

DETAILS OF THE CASES OF ALLEGED MISAPPROPRIATION/ EMBEZZLEMENT OF OCTROI DETECTED BY THE EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COMMITTEE TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR.

Serial No.	Name of the octroi post	Receipt No. and Book No. and date	Amount alleged to have been misappropriated/ embezzled
1.	Jandiala Road	128/228, 4-4-65	24.00
2.	ditto	1/293, 27-4-65	27.28
3.	ditto	100/191, 11-7-65	27.72
4.	ditto	58/29, 22-8-65	28.00
5.	ditto	125/85, 5-10-65	27.00
6.	ditto	43/105, 8-10-65	32.00
7.	ditto	1/97, 12-10-65	21.28

[Minister for Planning and Local Government]

Serial No.	Name of the octroi post	Receipt No. and Book No. and date	Amount alleged to have been misappropriated/ embezzled
8.	Jandiala Road	12/116, 15-10-65	25.00
9.	ditto	58/137, 22-10-65	11.00
10.	ditto	179/156, 7-11-65	24.00
11.	ditto	90/37, 24-11-65	25.75
12.	ditto	139/306, 22-12-65	5.00
13.	ditto	29/97, 10-10-65	27.72
14.	ditto	96/116, 21-10-65	26.00
15.	ditto	130/105, 11-10-65	27.38
16.	ditto	187/151, 1-11-65	26.00
17.	ditto	121/137, 26-10-65	10.00
18.	Amritsar Road	82/328, 22-12-65	40.00
19.	Jandiala Road	123/137, 26-10-65	57.12
20.	ditto	36/284, 23-4-65	103.42
21.	ditto	37/284, 23-4-65	103.46
22.	ditto	38/284, 23-4-65	104.44
23.	ditto	171/105, 12-10-65	112.00
24.	ditto	172/105, 12-10-65	105.00
25.	ditto	119 to 177/199	22.0
26.		125/326	2.00
27.		115/221	30.00
		Total	1074.57

NUH CO-OPERATIVE MARKETING-CUM-PROCESSING SOCIETY LTD., NUH, DISTRICT GURGAON.

***9998. Chaudhri Khurshed Ahmed** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether any member or the President of the Board of Directors of the Nuh Co-operative Marketing-cum-Processing Society (Oil Mills) Ltd., Nuh, District Gurgaon is/are the member/members of the Nuh Mewat Co-operative Transport Society Ltd., Nuh or any other society which is in the process of being wound up, if so, the name or the names of such Director or Directors ;

(b) whether the Government has received any communication from any Legislator of Gurgaon District in connection with Part (a) above, if so, the action taken thereon, if no action was taken, the reasons therefor ?

Chaudhari Rizaq Ram :

(a) Part I. Yes.

Part II. Shri Tayab Hussain Khan.

Shri Kole Khan.

(b) Yes. The matter is being looked into.

MUNICIPAL COMMITTEES WORKING IN THEIR RESPECTIVE REGIONAL LANGUAGES.

*9897. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state —

(a) whether any instructions have been issued by the Government to the Municipal Committees in the Hindi and the Punjabi regions directing them to do their work in their respective regional languages ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the number of Municipal Committees in these Regions which are doing their work in their respective regional languages and also the names of those which are not acting upon the above instructions ;

(c) the details of the further steps proposed to be taken to ensure full compliance of the above instructions by all the Municipal Committees ?

Sardar Ajmer Singh :

(a) Yes.

(b) & (c). A statement is laid on the table of the House.

Statement furnishing the answer to *Question No. 9897.

(b) All the Municipal Committees in the Hindi and the Punjabi regions are doing their work in their respective regional

[Minister for Planning and Local Government]

languages excepting the Municipal Committees noted below :—

1.	Phillaur	In Jullundur District.
2.	Nurmahal	
3.	Amritsar	In Amritsar District.
4.	Malout	In Ferozepur District.
5.	Pathankot	In Gurdaspur District.
6.	Narot Jaimal Singh	
7.	Sujanpur	
8.	Batala	
9.	Dina Nagar	
10.	Dalhousie	
11.	Gurdaspur	
12.	Qadian	
13.	Rupar	In Ambala District.
14.	Morinda	
15.	Mukerian	In Hoshiarpur District.
16.	N. A. C. Nangal Township	
17.	All the Municipal Committees (In Simla District).	

(c) The Deputy Commissioners concerned have been asked from time to time to ensure that the defaulting Municipal Committees start doing their work in their respective regional languages immediately.

PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD.

*8915. **Shri Rup Singh Paul** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps that the Government have so far taken or propose to take to improve the working of the Punjab State Electricity Board ?

Chaudhri Rizak Ram : The Punjab State Electricity Board is a Body Corporate constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948. Various matters pertaining to the functioning of the Board are considered by the Government from time to time and appropriate action taken, whereon called for.

COMPLAINT AGAINST THE EMPLOYEES OF THE FOREST DEPARTMENT.

*9398. **Sardar Piara Singh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state whether Government received any complaint against the employees of the Forest Department from any resident of Karnal on the 18th November, 1965 or thereafter, if so, the action, if any, taken thereon so far ?

Shri Chand Ram :

Part I. Yes, complaint dated the 18th November, 1965 was received.

Part II. The complaint was pseudonymous. However, the allegations are being looked into.

PROMOTIONS IN THE POLICE DEPARTMENT.

*9702. **Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any persons were promoted as Head Constables, A. S. Is., S. Is. and Inspectors in the Police Department in the State during the years 1964-65 and 1965-66, respectively.

(b) whether any persons, out of those mentioned in part (a) above, belonged to the scheduled castes and backward classes;

(c) whether the Government instructions regarding 10 per cent reservation in promotions for the scheduled castes and Backward classes were kept in view ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

NON-PRODUCTION OF THE PROCEEDINGS OF THE PANCHAYAT SAMITI, LEHRA GAGA.

*9815. **Comrade Gurbakhsh Singh**
Comrade Babu Singh Master
Comrade Bhan Singh Bhaura } Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the B. D. and P. O. Lehra Gaga district Sangrur refused to produce the Proceedings Book in the meeting of the Panchayat Samiti held on 15th September' 1965 ;

(b) whether it is also a fact that the said B. D. and P. O. did not note the proceedings of the meeting of the Lehra Gaga Block Samiti held on 30th October, 1965 ;

(c) whether it is further fact that both the said incidents were duly brought to the notice of the higher authorities, if so, the action, if any taken against the said B. D. and P. O., if no action has been taken, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh :

(a) No.

(b) No.

(c) No. Question does not arise.

NUH CO-OPERATIVE MARKETING-CUM-PROCESSING SOCIETY LTD. NUH DISTRICT GURGAON.

***9999. Chaudhri Khurshed Ahmed** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the number of days for which the Nuh Co-operative Marketing-cum-Processing Society (oil mills) Ltd. Nuh, district Gurgaon did the processing work during each of the years 1963, 1964, 1965 and 1966 ;

(b) the profit earned or loss incurred by the said society during each of the said years and a copy of the balance sheet, year-wise be laid on the Table of the House ;

(c) the amount of loans, if any advanced to the said society during the said period, and the names of the agencies which advanced them ;

(d) whether the said Society has recently asked the Gurgaon Central Co-operative Bank Ltd., Gurgaon to advance any loan, if so, the amount of the loan asked for and the security offered, if any ;

(e) whether there is any share money due to the Punjab Government from the said Society, if so, since when and the reasons for its not returning the same to the Government ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) to (c) : Requisite information is laid on the table of the House as per Annexure.

ANNEXURE

(a) The number of days for which the Nuh Co-operative Marketing-cum-Processing Society Ltd., (Oil Mills), Nuh, processed seeds during each year is given below :—

Co-operative year (1st July to 30th June)	No. of working days of the Mills during the Co-operative year
1962—63	Nil
1963—64	49
1964—65	78
1965—66	50 (upto 28-2-66)

(b) (i) The profit earned or loss incurred during each of the year in question is as follows :—

Co-operative year (1st July to 30th June)	Profit	Loss
1962—63	—	26,369
1963—64	3,124	—
1964—65	—	7,860
1965—66	5,945	—

(ii) Copies of the Balance Sheet for each of the year are attached.

(c) The amount of loan advanced during each of the Co-operative years 1962-63 to 1965-66 (upto 16-3-1966) by the Various agencies is as follows :—

Co-operative year	Loans advanced	during year
	Central Co-operative Bank, Gurgaon	State Bank of India
1962—63	43,691	—
1963—64	52,764	—
1964—65	11,57,034	23,800
1965—66 (16-3-66)	5,86,702	1,63,437

(d) Yes. The Society has applied to the Central Co-operative Bank, Gurgaon, for sanctioning cash/credit limit to the extent of Rs. 10 lacs vide its resolution dated 2nd February, 1966 against the security of stocks of oil, oil seeds, etc.

(e) Yes. A sum of Rs. 4,999 is due to the State Government from the Society on account of share money since 13th September, 1965. Paucity of funds is the reason for Society's failure to repay the amount.

BALANCE SHEET OF THE NUH CO-OPERATIVE MARKETING-CUM-PROCESSING SOCIETY (OIL MILLS) LTD. NUH, DISTRICT GURGAON AS ON 30TH JUNE, 1963.

Shares	Rs.		
(i) Individuals	68,950.00	Saving Bank Account	13,424.59
(ii) Societies	43,400.00		
(iii) Government	1,19,999.99	Shares of institutions	1,850.00
C. B. Clean loan	30,034.52	Security	22.00
C. B. Cash Credit	13,691.03	Land and Building	1,15,539.03

[Minister for Irrigation and Power]

	Rs P.		Rs. P.
Deposit	12.46	Machinery	81,063.66
Deposit of Non-members	74.46	Electric fitting	12,184.09
Deposit of Societies	7,430.95	Stocks	28,688.43
Fert. sales	759.72	Furniture	2,249.40
D. W. S. Gurgaon	1,439.44	Advances	4,940.13
Securities	2,800.00	Losses	28,652.17
Sale Tax	29.40	Cash in hand	8.47
Total	2,88,621.97		2,88,621.97

Losses incurred during the year according to profit and loss account Rs 25,369.17.

BALANCE SHEET OF THE NUH CO-OPERATIVE MARKETING CUM-PROCESSING (OIL MILLS) SOCIETY, LTD., AS ON 30TH JUNE, 1964.

Shares			
Individuals	71,100.00	Cash in hand	4,261.76
Societies	63,450.00	Saving Bank Account	2,364.15
Government	1,19,999.99	Shares of Co-operative Institutions	9,800.00
C. B. pledge loan	71,007.43	Security	22.00
C. B. Medium loan	20,000.00	Land and Building	1,16,600.48
C. B. Cash credit	12,511.98	Machinery	1,07,219.76
Sundry creditors	35,051.51	Electric fitting stock	12,184.09
		Stock	1,25.385.46
Securities			
Sugar	12,800.00	Stock furniture	4,489.15
Fertilizer	1,800.00	Transport charges recoverable	2,304.00
Bill payable	212.05	Losses	25,527.77
Sale tax payable	1,599.60		—
Intt. payable	626.06		
Total	4,10,158.62		4,10,158.62

Profit earned during the year according to profit and loss account is Rs 3,124.40. It is all due to sugar business only, otherwise. in processing work the society is in loss.

BALANCE SHEET OF THE NUH CO-OPERATIVE MARKETING CUM-PROCESSING SOCIETY (OIL MILLS) LTD., NUH AS ON 30TH JUNE, 1965.

	Rs. P.		
Shares			
Government	1,20,000.00	In hand	5,400.00
Societies	64,100.00	With Bank	211.00
Member	71,225.00	Shares of Co-operative institutions	10,450.00
C. B. Loan	59,034.00	Stocks	1,52,551.00
Short term loan	13,000.00	Sundry debtors	18,159.00
Medium term loan	74,435.00	Fertilizer transport	1,632.00
S. B. I. loan	23,800.00		
Depreciation fund	22,145.00	Charges recoverable godown	1,19,346.00
Reserve fund	95.00	Plant and Machinery	1,27,894.00
Fertilizer cash	1,116.00	Lands	6,370.00
Securities	25,600.00	Furniture	5,525.00
Bills payable	4,446.00	Security	22.00
		Previous year losses	23,576.00
		Losses of the year	7,860.00
Total	4,78,996.00		4,78,996.00

BALANCE SHEET OF THE NUH CO-OPERATIVE MARKETING-CUM-PROCESSING SOCIETY (OIL MILLS) LTD. NUH, DISTRICT GURGAON AS ON 15TH JANUARY, 1966.

	Rs. P.		
Shares			
Individuals	71,250.00	Machinery	1,30,167.12
Societies	64,100.00	Land and Building	1,25,900.60
Government	1,05,000.00	Shares C. B. Gurgaon	8,250.00
C. B. clean loan	20,000.00	Shares C. W. H.	1,700.00
C. B. pledge loan	27,445.00	Shares Marketing Federation	500.00
C. B. Medium term loan	13,000.00	Stocks	1,59,578.06
Cash credit loan	73 030.40	N. D. Certificates	500.00
S. B. I. Loan	15,563.33	Saving bank account	4,431.67

[Minister for Irrigation and Power]

Security Sugar depots	17,000.00	Sundries	14,011.53
Security Fert. depots	8,600.00	Security in M. C.	22.00
Bills payable	303.25	Furniture and Fixture	6,720.34
Reserve fund	100.00	Security of Electricity	20.00
Depreciation fund	10,344.60		
Cash sale of fert.	19,364.78	Security with D. F. S. O.	1,500.00
Intt. payble	1,912.26	Intt. recoverable	0.85
Others payable insurance bills	1,939.00	Commission recoverable	3,565.63
Commission	2,005.24	Transport charges	811.10
Electricity	626.20	Cash in hand	531.71
Rent	180.00		
S. B. I. Intt.	500.00		
Profits	5,945.59		
Total	4,58,210.61		4,58,210.61

WRITTEN ANSWERES TO POSTPONED STARRED QUESTIONS DEEMED TO HAVE BEEN ANSWERED UNDER RULE 45.

ELECTION OF MALOUT CO-OPERATIVE MARKETING SOCIETY, IN DISTRICT FEROZEPORE.

*9749. **Sardar Kulbir Singh** / **Chaudhri Satya Dev**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the date on which the election of Malout Co-operative Marketing Society in district Ferozepore took place ;

(b) the reasons for not holding the annual elections of the said Society ;

(c) the details of audit Reports of the said Society for years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 ;

(d) the number of cases filed against the Manager of the said Society in 1962-63 and 1963-64 and the result thereof ;

(e) the date of filing of appeal or appeals by the said Manager for his reinstatement alongwith the decision, if any, taken thereon ; if no decision has been taken, the reasons therefor;

(f) the amount of loan, if any, taken by the President of the said Society and the Rules, if any, under which the loan was granted to him alongwith the conditions imposed thereon ;

(g) the authority who sanctioned or granted the said loan and the action, if any, taken against those who sanctioned the loan to the President against the rules ?

Chaudhri Rizak Ram : The statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) 10th July, 1963.

(b) Annual election could not be held due to the negligence of the Managing Committee of the Society. According to the bye-laws, it is the duty of the Managing Committee of a Society to call its general meeting for the purpose of holding election of its Managing Committee However, suitable instructions in this behalf have been issued to the Assistant Registrar concerned to ensure early election of the Managing Committee.

(c) Audit of the Society, for the period ended with co-operative years 30th June, 1964 and 30th June, 1965, has not so far been completed. As regards audit report for the year 1962-63 it is very lengthy and the time and labour involved in the preparation of copies thereof will not be commensurate with any possible benefits to be obtained.

(d) Three cases involving a sum of Rs. 27 967 have been registered with the Police against the Ex-Manager, Shri Gurpal Singh. However one more case of embezzlement of Rs. 1,240 is yet under consideration with the Assistant Registrar.

(e) Shri Gurpal Singh filed his appeal to the Assistant Registrar, Ferozepore, on 22nd January, 1964. No decision of this appeal has so far been taken because Shri Gurpal Singh has not so far supplied a copy of the order against which he had preferred the appeal. The appeal could only be entertained and considered if the appellant had submitted the order appealed against alongwith his appeal petition.

(f) It is alleged that a sum of Rs. 5,000 is outstanding against the President as advance whereas the contention of the President is that he has not obtained any advance or loan from the society. This is a disputed matter and has been referred for arbitration under Section 55 of the Punjab Co-operative Societies Act. Definite information in this behalf will be available only after the dispute in question is adjudicated.

(g) The question does not arise in view of reply to (f) above.

ELECTRIFICATION OF CERTAIN ROADS IN DISTRICT SANGRUR.

***10000. Shri Fakiria** : Will the Minister for Irrigation and Power, be pleased to state the time by which Narwana to Kalayat, Uklana Tohana and Khanauri roads in district Sangrur, are likely to be electrified ?

Chaudhri Rizaq Ram : The Punjab State Electricity Board has no proposals to electrify roads.

ADJOURNMENT MOTION

कामरेड राम चन्द्र : स्पीकर साहिब, सूबे में ला ऐंड आर्डर की हालत बहुत खराब है । पानीपत में तीन आदमियों को ज़िन्दा जला दिया गया है । मैं एडजर्नमैंट मोशन पेश करना चाहता हूं .. (विघ्न) .. (शोर)

(एक दम बहुत से सदस्य खड़े हो कर बोलने लगे)

Shri Mohan Lal : Mr. Speaker, Sir, before you give your ruling, I would request that the hon. Members may be heard. The technicality of rules should not be allowed to stand in the way because it is a very serious matter. *(Noise and interruptions)*

Mr. Speaker : Order, please.

(शोर)

(इस समय बहुत से मेम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए ।)

(विघ्न, शोर)

Mr Speaker : Order please.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਅਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ । (ਸ਼ੋਰ)

पंडित भगीरथ लाल : ऐसे आदमियों को फौरन गिरफतार करना चाहिए । आप कृपा करके हमें सुन तो लें .. (विघ्न)

(इस समय खान अब्दुल ग़फ़ार खां, सरदार प्यारा सिंह, श्री राम प्यारा और अन्य सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए ।)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ । देखिए, आखिरकार कोई चीज़ हो वह ज़ाबता से ही चल सकती है । यह एडजर्नमैंट मोशन 10 बज कर 15 मिनट पर आई जब कि सैशन 9 बज कर 30 मिनट पर शुरू हुआ था । रूल्ज़ के मुताबिक एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस मीटिंग शुरू होने से कम अज़ कम डेढ़ घंटा पहले आना चाहिए था । (Order please. After all the business has to be transacted in accordance with the Rules of Procedure. The notice of this adjournment motion was received at 10.15 a. m. when the sitting had commenced at 9.30 a. m. Acording to Rules this notice should have been received at least 1½ hours before the commencement of the sitting.) (विघ्न, शोर)

(इस समय फिर आनरेबल मेंम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए) (शोर)

श्री राम प्यारा : हालात बहुत बुरे हैं, स्पीकर साहिब, आप पहले हमें सुन तो लें ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਸ਼ੋਰ)

श्री देव राज आनन्द : आप हाउस की सेंस तो ले लें, यह बहुत सीरियस बात है । (शोर, विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ । ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਉ (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ).।

Mr. Speaker : Order Please.

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ।)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਬੈਠੋਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਬੈਠ ਜਾਈਏ । (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

(Will you please resume your seat ? Please take your seats.) (*Interruptions noise*)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਉ । (Order please. All of you please resume your seats.)

चौधरी मनफूल सिंह : पंजाब के लोगों के सैंटीमैंटस से खेला जा रहा है। इस बात पर विचार होनी चाहिए । (शोर)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਉ । (ਵਿਘਨ ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਆਪ ਸਭ ਬੈਠੋਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ । (Order please. Will you resume your seats or not ?) (ਸ਼ੋਰ, ਵਿਘਨ)

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ।)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ (Order please) ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (Since many hon. Members are obstructing the proceedings, the House is adjourned for half an hour.)

10.35 a.m.

(The Sabha than adjourned for half an hour.)

(The House re-assembled at 11.05 a. m.)

ADJOURNMENT MOTION (RESUMPTION)

कामरेड राम चन्द्र : मैं हकूमत के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस दिन से पंजाबी सूबे का सवाल हमारे सामने आया है . . . . (विघ्न)

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहिब, मैं यह बात दरियाफत करना चाहता हूं कि आप ने कामरेड जी को बोलने की जो इजाजत दी है, क्या मैं यह समझ लूं कि आप ने एडजर्नमैंट मोशन को एडमिट कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह मोशन मैं ने एडमिट नहीं की है । हाउस की चूंकि काफी फीलिंगज़ हैं, ग्रुप लीडर्ज से आपस में बात चीत करने के बाद हम ने यह फैसला किया है कि हर ग्रुप से एक दो मैम्बर्ज़ बोल कर अपने फीलिंगज ऐक्सप्रैस कर लें उस के बाद इस एडजर्नमैंट मोशन की एडमिसीबिलिटी की बाबत अपनी रूलिंग दूंगा । (I have not admitted this adjournment motion. Since the House appears quite concerned with this matter it has been decided in consultation with the group leaders in the House that one or two Members belonging to each group may express their feelings before I give my ruling on the admissibility of this adjournment motion.)

श्री मोहन लाल : मुझे यह नहीं पता कि कोई ऐसी अंडर स्टैंडिंग भी हुई है और हमारे ऊपर किसी ऐसी अंडर स्टैंडिंग की कोई बाईंडिंग नहीं है । हम यह चाहते हैं कि अगर कोई डिसकशन हो तो पहले यह एडजर्नमैंट मोशन एडमिट कर ली जाये फिर इस पर आप कोई डिसकशन एलाऊ करें, वरना ऐसे ही डिसकशन का हम कोई फायदा नहीं समझते और इस में हम कोई पार्टी बनने को तैयार नहीं हैं ।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, जहां तक एक प्रोसीजर एडाप्ट करने का सवाल है, उस से तो यही नज़र आता है कि मैम्बरज़ को सैंटीमैंटस ऐक्सप्रैस करने की इजाज़त है। मगर जैसे पंडित मोहन लाल जी ने कहा है, हमें इस तरह से बगैर एडजर्नमैंट मोशन के एडमिट किये, पब्लिक सैंटीमैंटस को एक्सप्लायट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिये। इस तरह पहले इधर से बोलेंगे फिर टरेज़री बैंचिज़ वालों की तरफ से जवाब दिया जायेगा। इस लिये मैं पुलिटीकल ऐक्स-प्लायटेशन करने के हक में नहीं हूं। ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने पहले कहा है मैं ने इस एडजरनमैंट मोशन को एडमिट नहीं किया। अगर कोई मैंबर इस बात पर बोलना चाहे कि क्यों ऐडमिट नहीं किया वह बोल सकते हैं। और पुलीटीकली ऐक्स्पलायट करने की इस में कोई बात नहीं है। (As I have already said, I have not admitted this adjournment motion. In case any hon. Member wants to express himself on this aspect, he can do so. There is no question of political exploitation in it.)

कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, जिस दिन से पंजाबी सूबे का सवाल हमारे सामने आया है, लोगों के जज़बात भड़के हुए दिखाई देते हैं और जन संघ ने खास तौर पर लोगों को निहायत ही गुमराहकुन रास्ता में डाल दिया है। मगर जब सरकारी मशीनरी को हालात पर काबू पाने के लिये कहा जाता है तो यह कहते हैं कि हालात हमारे काबू में हैं, कण्ट्रोल में है। इधर लगातार लोगों की दुकानें जलायी जा रही हैं, जायदादें जलाई जा रही हैं। जिस वक्त इस हाउस में इस मौज़ू पर कल चीफ मिनिस्टर साहिब अपना स्टेटमैंट दे रहे थे उस वक्त पानीपत में एक हंगामा हुआ। वहां पर तीन आदमियों को एक दुकान में बंद करके ज़िन्दा जला दिया गया। (शेम, शेम की आवाज़ें।)

(*Interruptions by different Members*)

इस की ज़िम्मेदारी और किसी पर नहीं है इस के लिये महज़ एक जन संघ पार्टी ही है जो इन सानिहों की ज़िम्मेदार है। एक जन संघ पार्टी ही है जो लोगों को गुमराह कर रही है। इन लोगों ने तीन आदमियों को दुकान में बंद होने के लिये पहले मजबूर किया, जब यह ना माने तो इन तीनों को एक दुकान में बंद करके पैट्रोल डाल कर फूंक दिया और ज़िंदा जला दिया। (शेम, शेम)

इनमें से एक का नाम है क्रान्ति कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी का एक भारी वरकर था, दूसरे का नाम है दीवान चंद ककर, तीसरा है श्री संत राम। यह वाका ग्रेड ट्रंक रोड का है। यह वाका करने के बाद भी वह लोग 4–5 घंटे तक शहर में फिरते रहे और गुंडा गरदी की। मैं पूछता हूँ कि क्या इस की ज़िम्मेदारी हकूमत पर नहीं है ? क्या गवर्नमैंट ला एंड आर्डर बरकरार रखने की ज़िम्मेदार नहीं है ? क्या यह दरुस्त नहीं है कि अफसरान ने अपना फर्ज़ अदा नहीं किया ?

[कामरेड राम चन्द्र]

मैं पूछता हूं कि गवर्नमैंट को कल इस वाके की पूरी इतलाह कब मिली ? मैं कहूंगा कि अगर हकूमत की तरफ से इस तरह की ढील रही तो याद रखो सारा पंजाब जल उठेगा । इस सूबे के हालात बहुत ही सीरियस किस्म के हैं, बड़े अफसोसनाक हैं इस के बावजूद भी यह बात मेरे देखने में आती है कि हम बाकायदा पार्टियां अटैंड करते हैं और दूसरी शुगल की चीजें भी करते हैं । मेरी यह अपील है कि हम इन सारी चीजों को भुला कर जो सूबे में आग भड़क उठी है किसी तरह से उस आग को बुझायें । जो इकदामात सरकार की तरफ से इस वक्त तक उठाये गये हैं मैं समझता हूं उन से कोई तसल्ली बख्श तबदीली सूबे के सूरते हालात में नहीं हुई । मैंने यह कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि अब ज़रुरत इस बात की है कि ला ऐंड आर्डर को मज़बूती से कायम रखा जाये । जो लोग इस तरह के शर्मनाक जुर्म करते हैं, उन के खिलाफ सख्ती से कारवाई की जाये । मुझे खुशी हुई थी जब चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ख्वाह कोई भी आदमी क्यों ना हो, मैं हरगिज़ किसी का लिहाज़ ना करुंगा चाहे वह कितना ही इमपार्टेंट आदमी क्यों न हो । मैंने आज अखबार में उचटती नज़र से यह सुरखी पढ़ी कि लुधियाना में फौज बुला ली गई है । यह कोई अच्छी बात नहीं है कि पुलिस ला ऐंड आर्डर कायम रखने के काबल न रहे और हमें फौज बुलानी पड़े । मगर ला तो आखिर मेनटेन होना ही है । अगर पुलिस हालात को संभाल नहीं सकती तो फौज बुलानी पड़ती है । ज़रुरत इस बात की है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाये जिस से बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया न जायें । पब्लिक प्रापर्टी के साथ जनता की जायदाद का नुकसान भी किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं वह इन्तहा दर्जे के मुजरिम हैं । उन के खिलाफ सख्ती से कारवाई करनी चाहिये । मैं यह चीज़ आप के नोटिस में लाना चाहता था कि अब तक जो भी इंतज़ामात सरकार की तरफ से किये गये हैं वह ना-तसल्ली बख्श हैं । कण्ट्रोल स्पीचिज़ से नहीं होगा यह तो अमल से ही होगा । अगर पुलिस इस काबल नहीं है कि वह कंट्रोल कर सके तो बेशक फौज आये । मगर मैं यह भी तम्बीह करना चाहता हूं कि कई दफा बेगुनाह मारे जाते हैं और मुजरिम बच निकलते हैं । भिवानी में जो लड़का रनबीर सिंह मारा गया है वह कालिज के अहाते के अंदर था जहां उसे गोली लगी । इस तरह के जो वाक्यात हैं यह निहायत ही संगीन हैं । गवर्नमैंट को इस तरफ फौरन तवज्जो देनी चाहिये ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ । ਏਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੂਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨੇਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੂਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ (ਸ਼ੇਮ-ਸ਼ੇਮ-ਸ਼ੇਮ) ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਏਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ । A sizeable section of the administration alongwith those Ministers who opposed the reorganisation of the State on linguistic basis are conspiring with Jan Sangh and other forces to set fire to the peace and property of the State. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ । ਹੋਮ ਸਕਟਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯਗਯਾਦੱਤ ਨੂੰ ਬਰਤ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਕਲ ਏਥੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਉਂ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਇਨ-ਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉ । ਐਸ. ਪੀ. ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਭਿਵਾਨੀ.ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ । ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼, ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਛਡ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਅਜ 3 ਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੈਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਦੀਆਂ ਛਡ ਦੇਣ । ਜੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛਡਣ । ਮਨਿਸਟਰੀ ਰੀਆਰਗੈਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ । ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ? ਯਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਰੀਆਰਗੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਉ । ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਉ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਟਿੱਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਕੀ ਬਹਿਸ 'ਇਨ ਕੈਮਰਾ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ।

श्री देव राज आनन्द (अम्बाला छावनी) : मुहतिरम स्पीकर साहिब, आज पंजाब में यह हालात हैं कि तमाम पंजाब जल रहा है । आज से चंद दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस हाऊस में यह बात कही कि ला एंड आर्डर की तमाम सिचुएशन हमारे हाथ में है, अगर कोई शख्स सर उठाएगा तो हम अच्छी तरह से उस की सरकोबी करने के लिए तैयार हैं । हमारे देखने में यह आया कि तमाम एशोरैंसिज़ हाउस में दी हुई गलत साबत हो रही हैं । यहां तक हुआ कि पानीपत में जी. टी. रोड पर सरदार भगत सिंह के साथी, श्री दीवान चंद व दीगर आदमी को जन संघ के जलूस ने आग लगा कर ज़िंदा जला दिए । उन को दुकान बंद करने के लिए कहा गया । उन्होंने इन्कार कर दिया तो दुकान को जला दिया । इस से साफ ज़ाहिर है कि हम और आप भी कभी इस आग की लपेट में आ जाएंगे (प्रशंसा) । हम इस गवर्नमैंट से पूछते हैं कि क्या यह आर्सन बंद नहीं कर सकती ? एक गवर्नमैंट इनएफीशैंट हो जाती है । उसे यह सोच लेना चाहिए कि हम हालात पर काबू नहीं पा सकते । मैं पुरज़ोर अलफाज़ में कहता हूं कि यह काबू नहीं पा सके । यह पुराने कांग्रेसियों को इस तरह जलाने पर तुले हुए हैं । जन संघ को बिलकुल बैन कर दो ताकि वह एक कदम न उठा सकें । जब तक जन संघ की जमात बैन नहीं की जाती सूबे में यह आग लगाते रहेंगे । सूबे में यह आग जन संघ वालों ने लगाई है । यह गवर्नमैंट को अच्छी तरह से मालूम है । मगर वह बिल्कुल खामोश बैठी है और हाथ पर हाथ धर कर बैठी है । यह हमारे लिए बहुत ही मायूसी की बात है कि हम हालात पर काबू नहीं पा सके । मैं गवर्नमैंट से अपील करता हूं कि प्रबंध होना चाहिए, बराए मेहर बानी ऐसे कदम उठाएं ताकि दूसरे आदमियों को इबरत हासल हो कि इस के बाद कोई ऐसा कदम न उठा सकें ताकि न ही कोई सरकारी इमारत जलाई जाए न ही कोई बस जलाई जाए, न ही कोई आदमी जले, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि जब यह चीफ मिनिस्टर तमाम आदमियों को जला डालेगा ।

चौधरी खुरशीद अहमद (नूह) : जनाब स्पीकर साहिब, जैसा कि आप के सामने आ चुका है, आज इस हाऊस की यह ओपिनियन हो चुका है कि पंजाब सरकार सिर्फ एक छोटी सी मिकदार के एजीटेटर्ज़ को काबू नहीं कर सकी, नहीं तो

अगर मास एजीटेशन होती तो पता नहीं कि सरकार का क्या बनता। आज यह समझती है कि कोई 10 फी सदी के करीब आदमी एग्रीव्ड हैं, उन्होंने पंजाब में यह हालात लाए हैं। ज़िंदा इन्सानों को दुकान में बैठे हुए दिन दिहाड़े फूंका जाता है। यह पंजाब के नीरो असैंबली में बैठे बंसुरी बजाते हैं। आज पंजाब के यह हालात हो गए हैं। यह मिनिस्टरी लोगों को झांसा दे रही है कि हम ने हालात पर काबू पा लिया है। यह कल का मिनिस्टरी का ब्यान है कि हम पंजाब के हालात को खराब नहीं होने देंगे। हालात यह हैं कि सरकार की जायदाद को जलाया जा रहा है, लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है। आज दो आदमी एजीटेशन करते हैं तो पुलिस रोक नहीं सकती। यह क्या राज़ है ? इस राज़ को फाश किया जाए। अगर न किया गया तो यह कारवाई इस तरह नहीं चलने दी जाएगी। इस मिनिस्टरी को कोई हक नहीं कि इन कुर्सियों पर बिराजमान रहे और स्टेट जलती रहे। मेरा पुरज़ोर मुतालबा है अपनी पार्टी वालों से और हाउस से कि गवर्नमैंट अपना कंट्रोल छोड़ दे। जिन्हें हकूमत करनी नहीं आती, वह छोड़ दें। हकूमत की कुर्सी बड़े-बड़े आदमियों का काम है, छोटे आदमी का काम नहीं है। मैं कहता हूं अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, पंजाब के नीरो को कि वह बंसुरी बंद करे, लोगों को निजात दिलाएं और लोगों को रहने की इजाजत दें।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : स्पीकर साहिब, पंजाब के सामने इस वक्त एक बड़ा मसला है। पंजाब में एक ज्वालामुखी भड़क उठा है। अब आप के सामने सिर्फ इतना मसला है कि आया इस एडजर्नमैंट मोशन को एडमिट किया जाए या न। इस बारे में मैं दो-चार मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। स्पीकर साहिब, 10 या 12 साल पहले जब कि श्री भीम सैन सच्चर पंजाब के मुख्य मंत्री थे मेरे रोहतक के ज़िला में बड़ी गड़बड़ थी। ज़िंदा आदमियों को कत्ल कर दिया जाता था और किसी की ज़िंदगी सेफ नहीं थी। उस वक्त श्री भीम सैन सच्चर रोहतक तशरीफ ले गए। उस वक्त चौधरी लहरी सिंह मिनिस्टर थे। सरदार गुरचरन सिंह एस. पी. को कहा गया

"If you cannot control the situation I can transfer you"

इस पर एस. पी. ने विद कान्फीडैंस यह लफ्ज कहे थे :

"Well Sir, I can liquidate them all within a week provided I am given powers to do so."

स्पीकर साहिब, आप यकीन करेंगे कि न सिर्फ रोहतक ज़िला में बल्कि देहात में भी जितना गुंडा एलीमैंट था सरदार गुरचरन सिंह एस. पी. ने एक हफ्ते में लिक्वीडैट कर दिया। उस वक्त के मुख्य मन्त्री ने उसे कहा था :

"I give you unfettered powers."

मुझे 12 साल के बाद उस वक्त के राज की बात याद आती है। आज यह अमर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रैज़ोल्यूशन पास कर दिया है। उसको अमली जामा पहनाने का फर्ज और ज़िमेंदारी सरकार की है। लेकिन अभी उसकी सियाही

[पंडित चिरंजी लाल]

खुश्क नहीं होने पाई थी कि पंजाब में एक आग लगी और यह अमर खास तौर पर काबले जिक्र है कि यहां कोई कम्यूनल क्वैस्चन नहीं, यहां हिन्दू और सिख की प्राबलम नहीं । कुछ समझ में नहीं आता कि पंजाब में एक ऐसा एलीमैंट है जिस ने कारखाने जला दिए, दुकानें और बसें जला दीं और अब भिवानी और पानीपत में जो आग लगी है उसमें अपने ही भाई दूसरे आदमी को जलाते हैं । वह खदर पहनता था । वह एक पुलीटीकल आर्गेनाईज़ेशन से ताल्लुक रखता था । उसको ज़िंदा जला दिया । और यह हकूमत खामोशी धारण करके बैठी है । मैं समझता हूं कि इस हकूमत को इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं । शान तो उस में थी कि यह अलहदा हो जाते । यह हकूमत के मंत्री साहिब बलंद आवाज़ में कहते थे कि पंजाब की तकसीम नहीं की जाएगी पंजाब एक रहेगा । अगर इनकी आवाज़ वहां नहीं थी, सैंटर इनके साथ नहीं था, तो इनकी इज्ज़त इसी बात में थी कि यह कहते कि हम इस्तीफा देते हैं । यह कहते कि आप दूसरी मिनिस्टरी लाएं । अपनी जमीर के खिलाफ हकूमत का ठौंसना ठीक नहीं । इस मिनिस्टरी को लात मारो वरना उन्हों ने यह जिस तरह से कहा है और तै किया है कि इसे बनाया जाए वह किया जाए । इन को इस झील में डूब कर मर जाना चाहिए । वक्त का तकाजा है अगर हालात को यह नहीं कण्ट्रोल कर सकते तो जवाब दे दें । इस पंजाब के अंदर ऐसे आदमी हैं जो कन्ट्रोल कर सकते हैं, यहां पर पीस और ला एंड आर्डर रेस्टोर कर सकते हैं । आप को याद होगा कि पैप्सू के अंदर एक ही आदमी ने ला एंड आर्डर कायम कर दिया था, यह तो बहुत से आदमी बैठे हुए हैं लेकिन मुश्किल यह है कि इन का आपस में ट्रस्ट नहीं है, यह एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं । यहां पालेटिक्स की आग लगी हुई है (हंसी) यह हंसी की बात नहीं है, मजाक का मौज़ू नहीं है । पंजाब की जनता आज रो रही है, पंजाब में आग लग रही है, गवर्नमैंट कतई फेल हो चुकी है । उन की अपनी पार्टी गवर्नमैंट के खिलाफ नारे लगा लगा कर बगावत बुलँद कर रही है । इस लिए अगर आप ऐसे हालात में एडजर्नमैंट मोशन एडमिट करके उस पर डिसकशन की इज़ाजत देंगे तो मुनासिब होगा ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : स्पीकर साहिब, हम जानते हैं कि आप के रास्ते में रूलज़ की रूकावट है इस एडजर्नमट मोशन को एडमिट करने में लेकिन ऐसे क्यों हुआ वह सरकमस्टांसिज़ आप के सामने रखने जरूरी हैं । आप जानते हैं कि आज पंजाब में सैंसरशिप है, कोई खबर अखबारों के ज़रिए पहुंचती नहीं, कई स्थानों पर टैलीफोन बंद हैं, तारें टूटी हुई हैं, इस लिए इस हाउस के किसी मेम्बर को सही वाक्यात का उस वक्त तक इलम नहीं था जब तक कि हम विधान सभा में नहीं आए थे । इस के मुताल्लिक ऐसी खबर निकाली गई कि तीन आदमियों को जला दिया गया और वह भी सिर्फ ट्रिब्यून में क्योंकि और सब अखबार बंद हैं, पंजाब में सैंसरशिप हैं । खबर आई जैसे कोई मामूली वाका हुआ है । इस बात का किसी को

इलम नहीं था कि वह कौन तीन आदमी थे, उन को कैसे जलाया गया और वाक्या क्या हुआ । मगर यहां आने के बाद पता लगा कि वह कौन थे जो जलाए गए । एक थे मशहूर क्रान्तिकारी श्री क्रान्ति कुमार जो सरदार भगत सिंह और सरदार गुलाब सिंह के साथी रह चुके थे, जिन को आप जानते हैं आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, जो बहुत लम्बी कैद काट कर आए थे देश के लिए, जो आज गरीबी की ज़िन्दगी बसर कर रहे थे, जिन्हों ने अपनी कुरबानी का कोई सिला नहीं मांगा था, उन को जी. टी. रोड पर रोज़ेरौशन दोपहर के वक्त पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों के सामने अगर जलाया जा सकता है तो इन के बलंद बांग दावे जो कल किए गए, पहले भी जो एश्योरेंस दी गई कि हम हरेक बात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ला एंड आर्डर को मेनटेन करने के लिए, इन की वह एश्योरेंसिन्ज़ कहाँ गईं । आप के रास्ते में, स्पीकर साहिब, जो रूल्ज़ की रूकावट है, वह इस लिए दूर की जाए क्योंकि मुर्दा ज़मीरों को आज झंझोड़ने की ज़रूरत है । अगर ज़मीर होती मुख्य मंत्री साहिब की तो जिस वक्त इन्होंने सुना था कि श्री क्रान्ति कुमार और दीवान चन्द ठाकुर को दिन दिहाड़े जला दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के देखते हुए तो यह उसी वक्त अपने कर्तव्य को पूरा करते और रीज़ाइन कर देते लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कुर्सी के लालच की वजह से इन की ज़मीर मुर्दा हो चुकी है । मैं समझता हूं कि इन सब बातों को सामने रखते हुए आप हकबजानब हैं, दरियाफत करने के लिए कि जो रूल्ज़ की रूकावट है उस को किस तरह दूर किया जा सकता है । मैंने वाक्यात बताए हैं कि आप को क्यों एडजर्नमेंट मोशन वक्त पर नहीं दिया जा सका । आज के हालात के मुताबिक सैंसरशिप की वजह से मैंबर साहिबान के सामने सही हालात नहीं थे । मैं अर्ज़ करूंगा कि आप ने हाउस की सैंस को देख लिया है । इस लिए आप डिसकशन एलाउ करने के लिए हाउस की सैंस को सामने रखें । कल पार्टी मीटिंग हुई थी जो शाम के सात बजे तक चलती रही । उस वक्त तक हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने नहीं बताया कि श्री क्रान्ति कुमार और उन के साथियों को रोज़े रोशनी जला दिया गया है और आज भी क्या इन का कर्त्तव्य नहीं था कि यह पब्लिक को कानफीडैंस में लेते । लेकिन इन्होंने तो समझा कि कोई भेड़ बकरी थी जो जला दी गई । पानीपत में कल भी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी और आज फिर कहते हैं कि शान्ति है, हालात काबू में हैं । क्या इन को शर्म नहीं आती जब यह ऐसे एलान करते हैं । रेडियो में एनाऊंसमैंट होती है कि हालात काबू में हैं, पार्लियामेंट में बताया जाता है कि हालात अन्डर कन्ट्रोल हैं । मगर जैसे हालात इन के काबू में हैं उस का नमूना हमारे सामने है । मैं पूछता हूं कि क्या इन्हों ने पार्लियामेंट को अपनी पार्टी को और पब्लिक को अंधेरे में रखने के लिए बहुत नाजायज़ कोशिश नहीं की । मैं, स्पीकर साहिब, आप से अपील करूंगा कि इस मोशन को आप इस लिए एडमिट करें क्योंकि यह इतना इम्पाटेंट मामला है कि आज तक इस पंजाब की हिस्ट्री में इस से ज़्यादा इम्पार्टेंट मैटर कभी नहीं देखने में आया ।

[श्री मोहन लाल]

मैं ने आपसे अर्ज़ किया है कि वाक्यात क्या हैं। इस लिए अगर रूल्ज़ की बिना पर इस मोशन को एडमिट नहीं किया जा सकता तो इस हालात की बिना पर मैं चाहूंगा, स्पीकर साहिब, कि आप रूल्ज़ को छोड़ कर यह बात हाउस के वोट पर छोड़ दें। आखिर यह रूल्ज़ भी तो हाउस ने ही बनाए हैं। मैं समझता हूं कि आज कोई भी और चर्चा इस मोशन के मुकाबले में हेच है। हमारे लिए यह शर्म की बात होगी अगर हम इस बात को छोड़ कर और किसी बहस में पड़े। इस लिए आज का सारा दिन आप इसी बात पर चलने दें और इसी पर डिबेट रखें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हम पंजाब के साथ, इस हाउस और पंजाब की जनता के साथ इनसाफ नहीं करते। इस लिए आप कृपा करके रूल्ज़ से ऊपर उठ कर हाउस का वोट लेकर इस माशेन को एडमिट करें।

कामरेड राम प्यारा (करनाल): : स्पीकर साहिब, कल जो पानीपत में वाक्या हुआ है उस पर मुझे सख्त अफसोस भी है और मैं उसकी पुरज़ोर मुज़म्मत भी करता हूं। मुझे दुख है कि उस में मेरे तीन साथी बलिदान हुए। उस वाक्या से यह बात तो कन्फर्म होती है कि पंजाब में फिरकाप्रस्ती नहीं है क्योंकि वह तीनों ही हिन्दु कांग्रेसी थे। पंजाब की जनता मुबारिकबाद की मुस्तहिक है कि उसने फिरकाप्रस्ती की बात नहीं उठाई। यह जो हालात बिगड़े हैं इन्हें हमें सबको मिल कर सम्भालना चाहिए। जहां तक पंजाब में अमन का ताल्लुक है, मैं अर्ज़ करता हूं कि कल जिस वक्त यहां कामरेड राम किशन और सरदार दरबारा सिंह अमन अमान की दुहाई देते हुए इस हाउस में नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे थे, तो उस वक्त पानीपत जल रहा था। जो यह बात पंडित मोहन लाल ने कही कि चीफ-मिनिस्टर साहिब को हालात का पता था। लेकिन कल उन्हों ने बयान नहीं दिया पार्टी में, उस में वज़न नहीं क्यों कि मेरी इत्तलाह के मुताबक अगर वह ठीक है कि रात के 9 वजे तक जब यह तीनों साथी आपने घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश जारी हुई।

पहले खयाल था कि घर चले गए और घर वालों को ख्याल था दुकान पर हैं लेकिन 9 बजे जब घर नहीं पहुंचे तो चर्चा शुरू हुआ। 9 बजे के बाद जब श्री दीवान चन्द की जली हुई दुकान को खोला तो उस में से जली हुई लाशें मिली (शोर) मेरी इत्तलाह के मुताबिक अगर वह सही है तो उस दुकान में बहुत सारा इनफलेमेबल सामान था। जब मलबा उठाया गया तो तीनों लाशें मिलीं। मैं जनता को इतना अलज़ाम नहीं देता जितना अफसरों को देता हूं। (शोर) मुझे एक मिन्ट सुन तो लो ... शोर ... मुझे पता है कौन बोल रहा है दरबारा सिंह बीच में बोल रहा है। (शोर)

जिस वक्त उस बच्चे को गोली लगी थी तो जब उसका हस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा था तो उस वक्त पुलिस ने कोई ध्यान इस बात की तरफ नहीं दिया कि शहर में इस हादसा के खिलाफ जज़बात उभर सकता है । और कुछ हो सकत है उस वक्त अफसरों की चाहे वह एस० डी०ओ० है या पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी थी । कि वह शहर में जा कर हालात को देखते लेकिन वह हस्पताल में बैठे रहे । इस में एक और बात पता करने वाली है और मैं चाहता हूं गवर्नमैंट उसका पता करे कि आया जिस वक्त जलूस या माब गुज़र रहा था तो उसके शुरू में गोली चली या जलूस का कुछ हिस्सा गुज़र जाने के बाद गोली चली । अगर जलूस गुज़रने के बाद गोली चली तो मैं समझता हूं जान बूझ कर अमन खराब करने की कोशिश की गई.. (शोर) जहां तक यह आवाज़ आई है कि राम किशन बोल रहा है, मैं समझता हूं कि जहाँ गवर्नमैंट की बददयानती हो वहां उसके लिए राम किशन भी उतना ज़िम्मेदार है और दरबारा सिंह भी उतना ज़िम्मेदार है। I have no special preference either for Comrade Ram Kishan or Sardar Darbara Singh । स्पीकर साहिब, मिनिस्ट्री किसी की आए किसी की जाए हम यह चाहते हैं कि गवर्नमैंट में इमानदारी होनी चाहिए और अमन डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए । मिनिस्ट्री चाहे दरबारा सिंह की हो, मोहन लाल की हो या राम किशन की हमें इस से ताल्लुक नहीं । पंजाब की जनता की मांग है कि अमन कायम हो ।

जहां तक यह बात है कि वह रिज़ाइन करें मैं उन लोगों के साथ हूं जो कहते हैं रिज़ाइन न करो बल्कि इस की जुडीशल इन्क्वायरी कराओ और जो ज़िम्मेदार है उसे प्रासीक्यूट किया जाए । वह कौन से हालात हैं जिन की वजह से मैं आपसे कहूं कि यह मोशन एडमिट हो ? वह यह हैं कि आज पंजाब में आग लगी हुई है और इस पर कल दो घंटा बहस भी हुई । पंजाब में पिछले पांच-सात दिनों में कई नौजवान इस आग की आहुति में आ गए और बहुत सारे शहरों में अमन को खतरा हो गया है ।

मेरी खुशकिसमती है और करनाल वाले मुबारिकबाद के मुस्तहिक हैं कि जलूस के बावजूद वहां पर कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे शहरों में गड़बड़ हो रही है । इन हालात में आप रूल्ज़ को न देखें । रूल्ज़ बहुत छोटी चीज़ हैं

(घंटी)

आप रूल्ज़ से ऊपर उठें । आप जब चाहें अपना डिसक्रीशन य्यूज़ कर सकते हैं । आप इस मोशन को ऐडमिट करें ।

जो बात पंडित मोहन लाल ने वोटिंग वाली कही मैं ताकत दिखाने वाली स्पिरिट में नहीं जाता हूं बल्कि इस स्पिरिट में जाता हूं कि यह हाउस की, जनता की मांग है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अमन को बिगाड़ने में दरबारा सिंह और राम किशन किस तरह ज़िम्मेदार हैं । (शोर)

[कामरेड राम प्यारा]

एक मिनिस्टर ग्रार्डर देता है कि फलां फलां पुलिस अफसर बदमाश है, कुरप्ट है उसे बदलो लेकिन दूसरा मिनिस्टर उस ग्रार्डर को रोक देता है । राम किशन ग्रार्डर देता है, दरबारा सिंह रोक देता है और दरबारा सिंह ग्रार्डर देता है तो राम किशन रोक देता है ।

(शोर)

ग्राज गवर्नमैंट कानून की पैरवी नहीं कर रही बल्कि ज़ाती हुकमों की पैरवी कर रही है ।

(घंटी)

ग्राखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि 7/8 फरवरी को एडीशनल ग्राई० जी० करनाल गए थे । उन्हें एक ग्रादमी ने एक ऐफीडेवट दिया... ..

(शोर)

Mr. Speaker : This has nothing to do with this motion.

कामरेड राम प्यारा : मैं उसी बात पर ग्रा रहा हूं कि उन्हें एक ग्रादमी ने एफीडेवट दिया कि इस थानेदार ने मेरे सामने मेरी बीवी के साथ रेप किया....

(शोर)

इस थानेदार का काम ग्रौरतें स्पलाई करना है..........यह ग्रौरतें स्पलाई करता है इस वजह से उनके खिलाफ कोई ऐकशन नहीं लिया जा रहा---

(शोर)

मरा यह ग्रलज़ाम उन ग्रादमियों के खिलाफ है जो ग्रफसरों से ऐसे काम कराते हैं ग्रौर उनके खिलाफ कोई ऐकशन नहीं लेते......

(शोर)

Mr. Speaker : Order, order. Please take your seat now.

श्री रूप लाल महता (पलवल) : स्पीकर साहिब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के बाद पंजाब में जो ग्राग भड़की है ग्रौर स्टेट में फसादात कराने की कोशिश की जा रही है, उसकी सख्त मुज़म्मत करनी चाहिए । मैं समझता हूं कि यह तबके, जो यह ग्राग भड़का रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ग्रगले चुनाव में चोट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

स्पीकर साहिब, इस में कोई शक नहीं है कि जन संघ पार्टी ने ग्रौर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि पंजाब की ग्रौर तक्सीम न की जाए । पंजाब के दोनों रिजन इसी पंजाब के ग्रन्दर 'स्टेटस को' रहें ग्रौर दोनों रिजन फूलें फूलें ।

इस के बारे में इख्तिलाफ हो सकते हैं लेकिन जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस के बारे में फैसला दे दिया तो कांग्रेसियों ने, जो कि ग्रपनी पार्टी के वफादार सिपाही हैं, उन्हों ने ग्रपनी पार्टी के वरडिक्ट को मान लिया । ग्राज से तीन चार दिन पहले पंजाब के ग्रन्दर जो कुछ हुग्रा ग्रौर हो रहा है, वह काबले मज़म्मत है । उस के लिए जितना भी कोसा जाए उतना थोड़ा है ।

इस के अलावा सरकार का फर्ज है कि वह पंजाब के अन्दर ला एंड आर्डर मेनटेन करे और जो एडमिनिस्ट्रेशन में ढील है, उस को त्यागा जाए। पंजाब के अन्दर जो गुंडागर्दी का ऐलीमेंट है, उस को सखती से क्रश किया जाए ताकि पंजाब के अन्दर अमन कायम हो सके।

इस से पहले पंजाबी भाषा को मान्यता देने के लिए और हिन्दी भाषा को मान्यता देने के लिए बड़े बड़े आन्दोलन पंजाब के अन्दर चले। उस समय भी हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी विचारों को प्रदर्शित करने के लिए मुज़ाहरे किए लेकिन आज कल जैसे हालात पहले कभी नहीं हुए। आज पंजाब के हालात बहुत ही नाखुशगवार हो चुके हैं। आज आवाम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्रांतिकारी कान्ति कुमार मेरा जेल का साथी था। उस ने देश की हमेशा सेवा की। वह फिरकाप्रस्ती वालों के हाथों से अग्नि में भेंट हुए। पंजाब के हुल्लड़ मचाने वालों ने उसको और उसके दो साथियों को मार दिया। वह देश-भक्त थे और देश को ही वह सर्वोपरि समझते थे। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से या ला एंड आर्डर के मिनिस्टर इन्चार्ज से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपने फर्ज़ को अच्छी तरह से निभाएं और जो इस मामले में गुनाहगार हैं, उन पर सख्त कार्यवाही की जाए।

मैं समझता हूं कि यहाँ पर गर्म तकरीरें करने से पंजाब में अच्छा वातावरण पैदा नहीं हो सकता है। यह झगड़ा तो सखत कदमों के द्वारा ही खत्म हो सकता है। इस की मुज़म्मत ट्रेज़री बैंचों और अपोज़ीशन के बैंचों की तरफ से होनी चाहिए क्योंकि यह बातें काबले मुज़म्मत है। जनता ने हमें अपने नुमायंदे चुन कर यहाँ पर भेजा है। इस लिए हमारा फर्ज़ बन जाता है कि हम पंजाब के अन्दर ला एंड आर्डर को कायम रखें ताकि शान्ति चाहने वाली जनता अपने आप को सुरक्षित समझ सके।

मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि श्री कान्ति कुमार ने देश की बहुत सेवा की है। वह जेल के अन्दर मेरे साथ रहे। मैं उन की बहुत कदर करता था। वह पानीपत के अन्दर अपना कारोबार करते थे। वह फिरकाप्रस्त बातों को अच्छा नहीं समझते थे। कल कुछ हुल्लड़बाजों ने उसे ज़िन्दा ही जला दिया। मैं वजीर साहिबान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह उन के घर पर जा कर शोक प्रकट करें और जो कुछ उस की हानि हुई, उस को असैस किया जाए और उस का मुआवज़ा उस के परिवार को दिया जाए।

(घंटी)

स्पीकर साहिब, जालन्धर अमृतसर और भिवानी के अन्दर जो कुछ हुआ, वह काबले मुज़म्मत बात है। यह चीजें जन संघ पार्टी ने अपने मुफाद के लिए कीं। इन्हों ने अपने मुफाद के लिए पंजाब के अन्दर गड़बड़ी फैलाई। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसी कारवाई करने वालों को जो कोई भी हो उस को

[श्री रूप लाल महता]

गैर कानूनी करार कर दिया जाए। चाहे जनसंघ हो या कोई और हो। अमन कायम रखना इस हाऊस का काम है। यह हाऊस अमन का ज़ामन है। ऐसी पार्टी को गैर कानूनी करार दिया जाए ताकि यहाँ अमन कायम हो सके। पंजाब की तकसीम के बारे में सैंटर सरकार ने फैसला करना है। लेकिन इस तरह के हालात पैदा करने की इजाज़त हमारी सरकार को नहीं देनी चाहिए।

(घंटी)

स्पीकर साहिब, मैं सरकार को प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन लोगों का 4,5 दिनों के अन्दर जो नुक्सान हुआ है, उस का सरकार जायज़ा ले और लोगों को सरकार की तरफ से मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।

Chaudhri Hardwari Lal (Bahadurgarh) : Mr. Speaker, the situation, which is sought to be discussed through this Adjournment Motion, has two aspects—the first that the Police and the Government forces should quell disturbances wherever they occur; and secondly that the Police should not murder innocent people on the excuse that they are enforcing Law and Order. A great deal has been said on the first issue, but practically nothing about the second one. The town of Bhiwani has been mentioned by a few friends in a wrong way and in the wrong context. I have got an authentic story from the Principal of the Vaish College, Bhiwani. He says :—

"At about 10.30 a.m., a peaceful procession was coming from the T.I.T. Mill side shouting slogans : "Hindu Sikh Unity—Amar Rahe", "Hindu Sikh—Bhai Bhai", "Punjab Ekta—Zindabad", "Punjabi Suba—Murdabad", and when it reached near the college gate a reckless lathi-charge was made.

As a result of lathi-charge, the situation became tense and explosive. The unruly element in the procession began brick-batting the Police. The Police got flared up and resorted to indiscriminate firing in all directions including towards the college without any provocation from the college premises which resulted in injuries to several persons.

According to my instructions to the college students they were dispersing in batches in two's and three's at about 12.30 p.m. while the students were about to leave the College gate, the Police party along with the S.D.M., were seen coming on their way back from the Railway Station side. As they came in front of the college building, the Police again resorted to indiscriminate firing aiming towards the college premises, without any provocation whatsoever. The firing was inhuman, barbarous and callous. One of the bullets hit Mr. Ranbir Singh who was in the college premises. He collapsed on the spot. Some others were injured. He was the only son of Shri Matu Ram of the village Rudral, P. O. Chandani, district Mohindergarh. Several rounds were fired.

Immediately, after this serious incident, I, along with a few members of the staff went to S.D.M.'s Court to protest against this inhuman and unjustified firing.

After that, the Deputy Commissioner, the S. P., had reached Bhiwani from the Head quarters. I, accompanied by a few members of the staff brought them to the college and narrated to them the whole story and showed them the pools of blood in the college premises and a few bullet marks which were photographed. They assured me and the members of the staff that an enquiry would be instituted and the guilty would not be shielded at all."

Mr. Speaker, there has been a demand from various quarters of the House, including (from) the Congress Benches, for the Government to resign. I shall respectfully suggest, Sir, that for once, for a change, if not for anything else, the Government should listen to the House, and to its own supporters. There are only two alternatives before it. Either it should rise to the occasion immediately and maintain peace in the State, or, alternatively like self-respecting people, the Government should quietly resign and make room either for those who can maintain peace, or for the promulgation of the Governor's Rule.

Voices : No, not Governor's Rule.

Chaudhri Hardwari Lal : These are the only two alternatives, Sir. If the Government cannot rise to the occasion, it should resign and law and order should be restored. I would, therefore, request you to admit the Adjournment Motion, so that a fuller discussion on the whole situation is made.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ । ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ । ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੱਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫ਼ਰਰਜ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਖਿਆਲ ਸਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਡਿਸਓਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨ-ਲਾ ਫੁਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰ–ਮਿਲਾ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਪਿਛੇ

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ—ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.... (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿਉ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰਅਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ Law-abiding citizen ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜਸਟੀ-ਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ spare ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ spare ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ

12.00 noon

ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਐਰੌਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਵਾਜਿਬ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਥੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਲਿਸਟਾਂ ਚੁਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿਓ । ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਉ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਉ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਤਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖ ਲੈਣਾ । ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ।

श्रीमती शन्नो देवी (उपाध्यक्षा) : स्पीकर साहिब, आज पंजाब के लिये एक काला दिन है। जिन लोगों ने फांसी के तख्ते को चूमा था, जो लोग काल कोठड़ियों में रहे मुझे अफसोस है कि आज की हकूमत या पहली हकूमत उनको किसी दर्जे पर न पहुंचा सकी। जब कौंसिलों में भेजने का वक्त आया, जब राज्य सभा में भेजने का वक्त आया तो राज द्वारों में से रानियों और महारानियों को निकाला गया। (आवाजें: शेम, शेम)

बड़े घरों में रहने वाले लोगों को निकाला गया। जब हकूमत बनाने की ज़रूरत हुई तो न सोचा कि जिन लोगों ने यह पौधा लगाया था, जिन लोगों को इस पौधे के उखड़ने से तकलीफ होगी, उन को पास न फटकने दिया। आज के दिन क्रान्ति कुमार का इस तरह से दिन दिहाड़े जलाया जाना हमारी डैमोक्रेटिक इन्स्टीच्यूशन और कांग्रेस की शानदार इन्स्टीच्यूशन के लिये एक बदनुमा धब्बा है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज पंजाब में ला एंड आर्डर की हालत यह है कि (इस समय जब श्री प्रबोध चन्द्र शिक्षा मन्त्री बाहर जाने लगे तो हाउस में बहुत शोर शराबा हुआ।)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (Order, order)

श्री मती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब, मैं बड़े अदब से आप की मार्फत इस हाउस के मेम्बरों से दरखास्त करना चाहती हूं कि मुझे दो मिन्ट के लिए बोल लेने दो इस के बाद मालूम नहीं कि किस को जलना है और किस को मरना है।

मैं कह रही थी कि ला एंड आर्डर की हालत इस सूबे में यह हो कि चंद लोग उठ कर जिस को चाहें जला दें। कल शाम को जब मैं पार्टी मीटिंग में जा रही थी तो मैंने कामरेड राम किशन से पूछा कि सुना है कि लुधियाना को मिल्टरी के सुपुर्द कर दिया है। अच्छा किया, उन्होंने मुझे बताया नहीं। गवर्नमैंट के अपने राज़ होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझ सकी कि कल तीन चार-बजे क्रान्तिकारी क्रान्ति कुमार, दीवान चन्द और लांबा को जला दिया गया और हमें पता तक न लगे कि जा कर अपने हाथ से लकड़ी तो डाल दी होती। स्पीकर साहिब, क्रान्ति कुमार ने आज़ादी के बाद निहायत गुरबत और तंगदस्ती में जिस तरह से अपने दिन गुज़ारे हैं मुझे मालूम है। उस के बाल बच्चों के पास खाने को भी नहीं था। वह आप भी मज़दूरी करते थे। वह तो सवर्ग में जाएंगे ही क्योंकि उन्होंने सारी जिन्दगी इस कौम को बनाने में लगादी। आज जिस तरह से उन की हत्या हुई है, हमें सोचने का इमकान है कि हम किधर जा रहे हैं किधर से चले थे और किधर पहुंच गए हैं। मैं निहायत अदब से कामरेड राम किशन से कहना चाहती हूं कि अगर नहीं सम्भाल सकते तो अलग हो जाओ, छोड़ दो, किसी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दो जो इस सूबा को संभाल सके आप को अब दस्त बरदार हो जाना चाहिए—

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : आदरणीय स्पीकर साहिब, आप के सामने एक एडजर्नमैंट मोशन आई, आपने हाउस की राए जाननी चाही कि वह किस तरह से मानी जा सकती है। इस के लिये मैं अर्ज़ करूं कि कायदा कानून हमेशा अमन कायम रखने के लिये, भले काम करने के लिये और मज़लूमों की सहायता करने के लिये होते हैं। और उसके लिए कुछ कायदे कानून का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर साहिब, मैं आप से अर्ज़ करूं कि आज पंजाब की जो हालत है, मैं नहीं समझ पाया कि यह सरकार किस तरह से इस के लिए दोषी नहीं है जब कि इस मन्त्री मंडल के मन्त्रियों ने बार बार यह ऐलान किए स्टेजों से अखबारों से, रेडियो से कि पंजाब का विभाजन हमारी लाशों पर होगा। उस वक्त उन्होंने पंजाब की जनता के सैंटीमैंट्स को उभारा लोगों के जज़बात को भड़काया। उस वक्त उन्होंने इस बात को बिल्कुल नज़र अन्दाज़ कर दिया कि वे हिन्दुस्तान की एक बड़ी तन्ज़ीम शुदा पार्टी के मैम्बर हैं। उन्होंने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि उपर जो हाई कमांड है, जो संस्था के लीडर हैं वह जो आदेश देंगे वह इन को मानने पड़ेंगे। आज इस के मुताबिक दूसरी तरह की बातें करते हैं जब की पहले इन्होंने ही पंजाब के अन्दर लोगों के जज़बात को उभारा। स्पीकर साहिब, यहां पर रोम और नीरों का जिक्र किया गया, डायर का ज़िक्र किया गया कि वह अमृतसर में गोलियां चलाता रहा। स्पीकर साहिब, नीरों मस्त था और उस वक्त रोम चल रहा था...... (विघन)

Mr. Speaker : Order, please.

चौधरी नेत राम : लेकिन यह नपुंसक वजीर यहां पर बैठे हुए हैं यह बार बार अपनी जबान को बदल रहे हैं। बार बार अपनी जबान को तब्दील कर के पंजाब को फूंक रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई, आज तक सुनने में नहीं आई कि सरकार ने खुद ही देश में बदअमनी फैलाई हो जैसा कि आज यहां पर हो रहा है। यह बात आज तक सुनने में नहीं आई कि सरकार की पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की गोलियों की मौजूदगी में फिरकाप्रस्त हजूम पंजाबी सूबा मुर्दाबाद, हरयाणा प्रान्त मुर्दाबाद के नारे लगाए, भड़काऊ कार्यवाही करें, लूटमार करें और आग लगाए लेकिन फिर भी पुलिस चुपचाप खड़ी रहे और कोई एक्शन न ले। ऐसी हालत में जब कि मुजाहिरा करने वालों की राए के मुताबिक कोई पंजाबी सूबा मुर्दाबाद नहीं कहता, हरयाणा प्रान्त मुर्दाबाद नहीं कहता, हड़ताल में शामिल नहीं होता तो उस को मारा जाए, पीटा जाए और इस तरह से सारी विनाशकारी कार्यवाहियां होती हों और पुलिस कोई ऐक्शन ले। यह कैसी शर्मनाक बात है ?

स्पीकर साहिब, मैं पिछले शनीवार को यहां से हिसार गया तो जनसंघियों ने मेरी बाबत यह कहा कि यह हरयाणा प्रान्त का हामी है। मैं हैरान था कि पुलिस वाले खड़े हैं, उन के पास राइफलें और रिवाल्वर मौजूद हैं, पी. सी. ऐस. अफसर वहां पर मौजूद हैं.... (विघ्न)

उन सभी की हाज़री में उन सब के रूबरू उन लोगों की इस कदर हिम्मत हो गई, उन की इस कदर जुर्रत बढ़ गई कि वह ऊंगली उठा कर यह कहे यह हरयाणा प्रान्त का हामी आ गया है ।

(विघ्न)

Mr. Speaker : Order, please.

चौधरी नेत राम : मैं हैरान था कि पुलिस की मौजूदगी में भी फिरकाप्रस्त अनासर इस तरह से शरारत करवा सकता है । मैं हरान था कि पुलिस की तरफ से उस वक्त वहां पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ और इस किसम की बातें मेरे खिलाफ हुईं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए । (He should resume his seat now.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, एक ही मिसाल देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं । मैं आप की सेवा में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप उस फौजी की तरह से इस बात का निर्णय न दीजिएगा जो कि छुट्टी पर घर आया हुआ था । कहानी इस तरह से है कि एक फौजी छुट्टी पर घर आया हुआ था । वह रात को सोया हुआ था उस के सोते सोते एक चोर घर में चोरी करने आ गया । उस ने देखा को चोर चोरी कर रहा है । लेकिन वह सोया रहा और उसने कुछ न किया । सुबह हुई तो घर वालों ने कहा कि चोरी हो गई है कौन चोरी करने आया था, कब चोरी हुई तो इस पर उस फौजी ने कहा कि मैंने रात को चोर को देखा था लेकिन क्योंकि मैं छुट्टी पर था ड्यूटी पर नहीं था इस लिए चोर के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई । इस लिए आप से भी यही प्रार्थना है कि आप इस एडजर्नमैंट मोशन को रूलज़ का सहारा लेकर डिस्एलाऊ न कीजिए । आप यह न कहिए कि कानून इस को इजाज़त नहीं देता । फौजी की तरह से काम न लीजिए, अपनी अकलमन्दी से काम लीजिए और जलते हुए पंजाब को बचाइए नहीं तो इस खुसरा नपुंसक कांग्रेस गवर्नमैंट की धज्जियां उड़ाने के लिए यह अपोज़ीशन त्यार है । (शोर)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ (ਫਰੀਦਕੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਤੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਉਤੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ (*Thumping from the Opposition Benches*) ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ । (*Thumping from the Opposition and some Congress Benches*) ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ point of view ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ—ਅਸੀਂ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋ' ਰਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ । ਕਲ ਇਥੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ—ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ.......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਵੋ (The hon. Member may express himself on this Motion also).

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਹਮਣੇ ਜ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਐਜ਼ੀਟੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ । ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ; ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10% ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ (ਵਿਦ ਆਨਰ) ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ । (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਥੰਪਿੰਗ) ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ

ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸਿਵਾਏ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਲੂਸ ਕਢਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ—ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ—ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਹਨ; ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਖੁਦ ਐਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸਨ ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਤਸ਼ਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਉ। ਜੇਕਰ ਇਤਨੀ ਜੁਰੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰਖੇ ਵਰਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । स्पीकर साहिब, ग्राज एक बड़ी एहम एडजर्नमेंट मोशन मनजूरी के लिए हाउस के सामने पेश है लेकिन जो कनसर्नड मिनिस्टर हैं वह यहां पर मौजूद नहीं हैं । क्या ऐसा हो सकता है ?

Mr. Speaker : The Chief Minister is here,

चौधरी देवी लाल : पर यह शिकायत तो एजुकेशन मनिस्टर के खिलाफ है ।

एक ग्रावाज : वह भी पीछे बैठे हुए हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Mr. Speaker : Order please. • Sardar Gurnam Singh.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦਿਉ.......

Mr. Speaker : I have already called Sardar Gurnam Singh.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਅਜ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਕਿਆਤ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਨੈਲਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਔਰ ਹਰੀਆਨੇ ਪਰਾਂਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਉਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੂਲ ਨ: 66 ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ—

RULE 66

"Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker".

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰੂਲ 67 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਾਏ ਤਾਕ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਏ ਤਾਕ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨੈਲੇਸਿਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਉਲੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਕ ਮਿਨਟ ਲਈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਇਉਲੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹਟਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

"He said that the Government's attitude towards those who were against the Punjabi Suba was lenient during the past five days so that they could express their feelings peacefully."

ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੀਬੀਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਐਜੀਟੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਐਜੀਟੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਐਕਸਪਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਓਨ

ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇੰਟ ਰੈਸਪਾਨਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੁਐਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੁਐਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਕਰਫੀਉ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਫੀਉ ਦਾ ਵਕਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨੋਂ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਫੀਉ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਓ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਫੀਉ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਚਾਰ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਟ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟਰੱਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਓ। 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੀਉਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਔਰ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗਏ ਔਰ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਸਾਈਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਈਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

> "It is to draw the general attention of the authorities to the following speech, made by Shri Prabodh Chandra, Education Minister, Punjab, on March 11, 1966 at 12.30 p. m. He was presiding over the annual Prize Distribution Function of the State Sports College for Women, Kurukshetra...."

ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਸੇਫ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਫਜ਼ ਇਹ ਸੀ—'ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਹੈ'। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੁਐਲ ਕਰਨ ਚਲੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 65 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਾਲਜਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ)

ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗਵਾਈ ਹੈ । ਅਜ ਹੀ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਸ ਡੈਮਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ । (ਸ਼ੇਮ, ਸ਼ੇਮ) ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਸਪਾਨਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ. . . .ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਗਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਪੀਲ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ । ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਚੌਧਰੀ ਹਰਦਵਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਸੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਤਾ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿਤੇ । ਐਸਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ-ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੁੰਡੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ । ਜਦ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਿਮਾਲਾਇਨ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ । ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਮਿਊਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਗਦੱਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਤ ਛਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ।

ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਹਥ ਦੇ ਦਿਉ । ਆਪ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ-ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੋਟ ਲਿਆਉ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੇਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿਚ ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੈਸਟਸ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ.... (ਵਿਘਨ) ਯਸ਼ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਿੰਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫ ਰੈਫ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ ਤੋਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 'ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਉ' ਹੀ ਕਨਵਿਨਸਿੰਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ! ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜ ਸਿਖ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਗ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕਰਾ ਦਿਉ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ।

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, मुझे दो मिनट दें । (विघन) कांग्रेस पार्टी के 10 आदमी बोल चुके हैं......

Mr. Speaker : No please. (*interruption*)

शिक्षा मंत्री : स्पीकर साहिब, मुझे दो मिनट दें कुछ एक्सपलेन करने के लिये........

श्री अध्यक्ष : हां, आप परसनल ऐक्सपलेनेशन दे लें । (Yes, he may give his personal explanation.

(*Babu Ajit Kumar and Chaudhri Net Ram stood up and started shouting to get time.*

Mr. Speaker : Order please. Please take your seat (*interruption*)

देखिये मुझे प्रोसीडिंग्ज़ रैगूलेट करनी हैं। 20, 25 मैम्बरान और बोलना चाहते हैं। अगर हर एक ने बोलना है तो काम नहीं चल सकता। (विघन) डेढ़ घंटे तक हाउस ने अपने विउज़ इस बारे में दिए हैं इस से ज्यादा टाईम नहीं दे सकता..[Order please. Please take your seat--(Interruptions), well, I have to regulate the proceedings of the House. Twenty or twenty five members are still anxious to participate in this. It is not possible to carry on in case all were to speak (Interruption) the House has expressed views on this subject for one and a half hour. No more time can be given])

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, इससे अहम मामला और क्या हो सकता है? । (विघन) चाहे इस पर 5 दिन लग जाएं, इस पर बोलने की इजाज़त देनी चाहिए ।

Mr. Speaker : I am sorry, अब नहीं । (I am sorry. Not now)

शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : जनाबाली, सरदार गुरनाम सिंह ने मेरे बारे में काफी सख्त इल्जाम लगाया है । (विघन) दो-तीन बातें मेरे बारे में इन्हों ने कही है (विघन सरदार लछमण सिंह गिल की तरफ से)

श्री अध्यक्ष : आखिर कोई तो कोड आफ कन्डक्ट होनी चाहिए । (After all there should be some code of conduct)

शिक्षा मंत्री : इन के लिए कोई कोड आफ कन्डक्ट नहीं है । स्पीकर साहिब, इनसान गलतियां तो करता है और सिआसी जिंदगी में भी गलतियाँ होती हैं । मगर मैं कभी इस गुनाह का मुरतकिब नहीं हुआ कि फिरकादाराना फसादों में हिस्सा लिया जाए । नौ मार्च से पहले चाहे मेरी कोई भी राय थी मगर जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया मैं ने उसी दिन कहा कि हमें इस फैसले को ग्रेसफुली और इमानदारी से ऐक्सैप्ट करना चाहिए । (विघन) यह नहीं कि जो फैसला हमारी मरज़ी के मुताबिक हो उसे तो हम ठीक समझें और कबूल कर लें और जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो उस में कहें कि हम इस में हिस्सेदार नहीं हैं । मैं समझता हूं कि इस बड़ी गदारी अपनी पार्टी के साथ नहीं हो सकती । जो फैसला हुआ वह बसरोचश्म कबूल करना चाहिए ।

फिर, स्पीकर साहिब, यहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ । मेरे मुताल्लिक जो इन्हों ने कहा है यह बिल्कुल गलत है । इन्हों ने कहा कि हिन्दू और सिख लड़कों ने साईन करके इन को खत भेजा है । इस के मुताल्लिक मैं यह कहूंगा कि इस की जो नकल मुझे अगर हाउस में दी गई है उस पर सिर्फ तीन सिख लड़कों के सिगनेचरज हैं । (विघन)

Mr. Speaker : Order, please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕੇਇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਖ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ (Order, please)

एक आवाज : इस पर तो चार हिन्दू और तीन सिक्ख लड़कों के दस्तखत हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । Order please.

शिक्षा मंत्री : जनाबे आली मैं तो इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि जो जस्टिस गुरनाम सिह ने मेरे बारे में कहा है । उन्हों ने कहा है कि इन्हें हिन्दू और सिक्ख लड़कों ने कहा है । मेरा ख्याल है कि यह जो कागज इनके पास हैं, जिस में यह कहते हैं कि लड़कों के दस्तखत हैं, इस की ही एक नकल मुझे आज अपर हाउस में दी गई है । मैं ने जो लफ़ज़ वहां पर कहे थे मैं आज उन्हें फिर यहां पर दोहराना चाहता हूं । मुझे जब इस के बारे में पूछा गया कि क्या फिर से सन 1947 के वाक्यात रूनुमा होंगे तो मैं ने कहा कि अगर कोई भाई यह चाहते हैं कि सिक्ख स्टेट इंडिया से अलहदा हो जाए तो वह आदमी हकीकत की दुनियां में नहीं रहता बेवकूफों की दुनियां में रहता है । (विघन शोर) वह बेवकूफों की दुनिया में रह कर ही इस तरह सोच सकता है कि पंजाबी ज़बान के आधार पर अलहदा मुल्क बना दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप ने प्रबोध चन्दर जी पंजाबी भाषा का नाम ले दिया । (The hon Minister Shri Prabodh Chandra has referred to the Panjabi language) (विघन, शोर)

शिक्षा मन्त्री: मैं, स्पीकर साहिब, जो बात वहां पर कही थी उस पर पाबन्ध हूं कि अगर कोई आदमी ऐसी चीज़ करेगा कि मजहब की बिना पर अलहदा हकूमत बन सकती है या अलहदा मुल्क बन सकता है तो वह हकीकत की दुनिया में नहीं रहता (शोर, विघन)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज़ । (Order please)

सरदार अजायब सिह संधु आन ए प्वायट आफ आर्डर सर. . . (विघन, शेर)

सरदार तारा सिह लायलपुरी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर. . . . (विघन, शोर)

श्री सुरेन्द नाथ गोतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर. . . . (शोर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ (Order, please)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪਵਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ? ਕੀ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ 1947 ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਅਗ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਨ....(ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ, ਪਲੀਜ਼ (Order, please)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਲੁਧਿਆਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : This is no point of order

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ, ਨੋ ਇਨਟਰਪਸ਼ਨਜ (Order please, no interruptions)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ (x x) ਮਚਵਾਈ ਹੈ। (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

Education Minister : You should talk sense.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : You are not the only sensible person to talk sense.

Education Minister : I know whether you are sensible or I am sensible.

(शोर, विघन)

Mr. Speaker : Order, please.

शिक्षा मंत्री : अगर आप यह समझते है कि इस तरह से शोर मचा कर आप मुझे दबा सकते हैं तो मैं इस तरह दबने वाला नहीं हूं। जनाबे आली, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कहते रहे हम सब ने सुना अब इन्हें जरा ठंडे दिल से सारी बात को सुन लेना चाहिए। बात सुनने की जुर्त होनी चाहिए। इस तरह शोर मचाने से मैं दब नहीं सकता।

(विघन, शोर)

Note.—Expunged as ordered by the chair.

सरदार लछमन सिंह गिल : कोई आदमी हो तो बात सुने । (विघन)

सरदार अजायब सिंह सन्धु : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं, सरदार गुरनाम सिंह जी, आप से कहना चाहता हूं कि आप की पार्टी में दो मेम्बर सरदार लछमन सिंह गिल और सरदार अजायब सिंह सन्धु यह समझते हैं कि जो वह कहते हैं वही ठीक है और चाहे कुछ भी हो । (Order please, I would like to point out to Sardar Gurnam Singh that two members of his party viz, Sarvshri Lachhman Singh Gill and Ajaib Singh Sandhu appear to feel that whatever they say is correct although others may not subscribe to them (विघन, शोर)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰੱਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ मिनिस्टर साहिब कहना चाहें उनकी बात को पूरी करने देना चाहिए, चाहे आप के ख्याल उस के बारे में कुछ ही क्यों न हो लेकिम यह बात नहीं होनी चाहिए कि उन की बात को सुना ही न जाए । (Order please, I would, therefore, request you to let the Minister have his say irrespective of your individual opinion in relation to him But he should not go unheard I would request you to persuade them not to interrupt)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : First of all persuade your members not to interrupt.

शिक्षा मंत्री : मैं फिर यह अर्ज़ करता हूं कि जो लीडर इस तरह की मांग करता है कि हमें अलहदा मुल्क दिया जाए वह हकीकत की दुनिया में नहीं रहता (विघन, शोर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ (Order please)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ .... ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ । ਕੀ ਜਦ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲੇਜ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਨਸੈਸਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ।

ਸੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ (Order please)

शिक्षा मंत्री : अगर उन्हों ने मेरी सारी तकरीर सुनी होती तो इस तरह का सवाल न करते । मैं ने पहले ही ज़िक्र किया था कि वहां के रेस्ट हाउस में मुझे कुछ दोस्त मिले ..... (विघ्न)

सरदार लछमन सिंह गिल : नेम दैम । कौन थे वह ।

शिक्षा मंत्री : उन दोस्तों ने खदशात जाहिर किए । उन के खदशात का जवाब देते हुए मैं ने कहा था कि सन 1947 के वाक्यात अंग्रेज की एक तहशुदा पालेसी के मुताबिक हुए । लेकिन आज एक आज़ाद मुल्क में इस तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही कोई किसी मज़हब की बिना पर अलहदा मुल्क बनने वाला है । (विघ्न, शोर)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤੁਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । (ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

Sardar Ajaib Singh Sandhu: Name those friends.

Mr. Speaker: Order please.

शिक्षा मन्त्री : जनाबे आली, मैं तो यह कहूंगा कि मेरी तरफ से पंजाब के एजूकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर को 10 तारीख को हिदायत गई है और वह आज तयार नहीं की गई। गवर्नमेन्ट के रिकार्ड में उस तारीख की फ़ाइल में मौजूद है कि तमाम सी० औज़० इ० और डी० इ० औज़० की तरफ से तमाम डिनामीनेंश्नल कालेजों और स्कूलों में हिदायत कर दी जाए कि उन की मैनेजिंग कमेटियां इस बात का ख्याल रखें कि अगर वह इस तरह के झगड़े में किसी तरह से भी कनाइत करेंगे तो उन की ग्रांटस को बंद कर दिया जाएगा । और यह हिदायतें तमाम जगहों पर पहुंच गई हैं । (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ?

शिक्षा मन्त्री : अब यह कहा गया कि मैं यश जी को मिला हूं और वह मेरे साथ थे लेकिन मैं ने आज उनको कई दिनों के बाद तो यहां पर इस हाउस में देखा है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ?

शिक्षा मन्त्री: मैं ने सरकट हाउस में मीटिंग बुलाई थी। वहां पर डी.सी. एस.पी. थे, अकाली भाई थे और दूसरी पार्टियों के आदमी भी मौजूद थे। और मैं ने उन्हें ऐडरैस किया। इसी तरह जालंधर अमृतसर में और लुधियाना में भी मीटिंग को ऐंडरैस किया। मेरे साथ वीरेन्द्र जी भी थे और लाला जगत नारायण जी भी थे। मैं उन को इन से ज्यादा ज़िमेवार समझता हूं। (विघन, शोर) और मैं उन की इन से कहीं ज्यादा इज्जत करता हूँ। वह आप से हज़ार दर्जा बेहतर इन्सान हैं।

Sardar Ajaib Singh Sandhu: The cat has come out of the bag now, Mr. Speaker.

(*Interruption, noise*)

Mr. Speaker : Order, please. No interruptions.

Giani Kartar Singh : On a point of order Sir.

Mr. Speaker : Order, please, I am standing

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪਵਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ।

मैं फिर मेम्बर साहिबान से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह से इन्ट्रप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से हाउस की प्रोसीडिंगज नहीं चल सकतीं। आप का रिएकशन कुछ भी हो सकता है और जो आप ने स्पीचें की हैं उन के बारे में भी कोई और रिएक्शन हो सकता है। इस लिए इस तरह की इन्ट्रप्शन्ज नहीं होनी चाहिए (विघन) आर्डर प्लीज। (I am on my legs. The hon. Member Giani Ji may please resume his seat. I would again request the hon. members not to resort to such interruptions because the proceedings of the House cannot be conducted smoothly in this manner. You may have a different reaction and the speeches which you have made might have also found reaction in a different way. Therefore, such interruptions should not be repeated (Interruptions) Order please.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਜ ਸਤ-ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ......... (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ? (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ, ਪਲੀਜ਼ (Order please.)

शिक्षा मन्त्री : जनाबे ग्राली, मैं बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि यह चीज बिल्कुल बेबुन्याद ग्रौर गलत है। मेरी तरफ से किसी को बरगलाया नहीं गया । सर्वश्री वीरेंद्र ग्रौर यश जिन के मुताल्लिक इन लोगों को शिकवा है, मैं उन की इन लोगों की निसबत हजार दरजे ज्यादा इज्जत करता हूं । इस लिये कि इन लोगों ने इस सूबे की शान को ऊंचा किया है। मैं ग्रगर उन से मिला हूँ तो मैं ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया । लुध्याना में जब मैं इन से मिला तो ग्रौर बीसियों ग्रकाली भी वहां माजूद थे । वहां पर सरदार हरनाम सिह लुध्याना वाले थे । इसके ग्रलावा प्रैजीडैंट कलगीधर गुरदवारा ग्रौर इन की मैनेजिग कमेटी के जरनल सैक्रेटरी भी थे । मैं कहता हूं मैंने इस सारी चीज को बहुत ही बुरी तरह कंडैम किया है । ग्रगर एक ग्रादमी भी, जो कि वहां था, यह कह दे कि मैं ने कंडैम नहीं किया तो जो मरजी सज़ा दें । ग्रमृतसर में कोई चार बजे पहुंचा हूँ दो बजे तक मैं जालन्धर में ही था । वहां पर लोगों ने मुझे इँसिस्ट किया कि शहर की हालत खराब नहीं है करफ्यू हटाग्रो, यह मांग उन लोगों ने मेरे सामने की । मैं ने उन को यह कहा कि करफ्यू लगाना या करफ्यू हटाना यह लोकल ग्रथारिटीज़ का काम है । ग्राप ग्रपने ऐमाल से ग्रगर साबत कर देंगे कि ग्रमन है तो करफ्यू हट सकता है। ग्राप मेरे ग्रल्फाज की तसल्ली किसी से भी जो वहां था, पूछ कर कह सकते हैं । एक तरफ तो ग्राप कहते हैं कि मैं फिरकादार हूं दूसरी तरफ ग्राप कहते हैं मैं लोगों को बरगलाता हूं ग्रगर मैं ग्रमन कायम करने के लिये दौड़ धूप करता हूं । मैं जब श्री यज्ञ दत्त जी से रिक्वेस्ट करने गया हूं. मैं ही जानता हूं कि किस बुरी तरह से वहां की सिचूएशन को हैंडल किया गया। वहां मेरे ऊपर पत्थर पड़े, मेरी कार के शीशे तोड़ दिये । स्पीकर साहिब, मैं ग्राप से रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राप इस तरह से किसी खास ग्रादमी के बारे में किसी तरह का प्रापेगंडा करने की इन को इजाजत न देंगे । सरदार ग्रजायब सिंह की बात भी मैं समझता हूं कि मैंने उन के एक काम में जवाब दिया है । मगर ग्रगर यह समझते हैं कि इस तरह के इलज़ाम लगा कर या किसी तरह का दबाव डालकर यह ग्रपना काम करवाना चाहते हैं तो मैं हरगिज हरगिज इनकी बातों में ग्राने वाला नहीं हूं । इस तरह की इनकी bullying में मैं हरगिज़ नहीं ग्राऊंगा ।

(*Interruptions*)

चौधरी देवी लाल : On a point of order, Sir, आनरेबल मैंबर के खिलाफ एक आनरेबल मिनिस्टर ने यह इलजाम लगाया है कि यह मेरे डिपार्टमेंट में काम कराने की गरज़ से आये। मैं कहता हूं कि हर लैजिसलेटर का यह हक है कि वह अपने इलाके की तकालीफ दूर कराने के लिये मुताल्लिका आफीसर या वज़ीर से मिलें। मगर क्या कोई वज़ीर लैजिसलेटर को इस तरह से बदनाम कर सकता है (No reply from the chair)

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR AJAIB SINGH SANDHU

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੁਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਪਲਾਨੇਸ਼ਨ । ਏਥੇ ਹੁਣੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਮਿਲਿਆਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਂਹੀਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਹਾਸ਼ਾ ਯਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਕਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । (I would like to remind the hon. Member that such things are not covered by Personal Explanation. He has started making a speech.

ADJOURNMENT MOTIONS (RESUMPTION).

S. Gurcharn Singh : On a point of order, Sir.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (I would like to point out that keeping in view the feeling of the House I have allowed opportunity to a maximum possible number of hon. Members to express themselves on this issue).

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣੇ ਹਨ ਜੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । (Sardar Tara Singh Ji, I do not like such interruptions when I am speaking. It is a separate matter if the House want to conduct the proceedings of their own accord, otherwise I feel that maximum number of hon. Members have been allowed to express their views on the subject. No more hon. Member can now be permitted to speak. Now only the Chief Minister will take the floor. In case any hon. Member insisted to obstruct the proceedings I would adjourn the House.)

(ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਠੇ ।)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ । (A lot of time has already been taken, Please resume your seat now.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਵਿਘਨ) ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਵਿਘਨ) ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ । (ਵਿਘਨ) ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, (Please resume your seat,)

NAMING OF A MEMBER

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਉ (Babu Ajit Kumar should please resume his seat,)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਬੈਠ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member Babu Ajit Kumar can not be permitted to speak again. He should resume his seat and not interrupt the proceedings.)

(ਬਾਰ ਬਾਰ 'ਬੈਠ ਜਾਓ' ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ?

Mr. Speaker : It is for me to regulate the proceedings.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ; ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ । (Despite my repeated requests Babu Ajit Kumar is interrupting the proceedings of the House, therefore order him to withdraw from the House.)

(ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ)

Mr. Speeker. Please withdraw from the House (interruption).

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ [Please withdraw from the House (Interruption). (Since he is not withdrawing from the House I am compelled to direct the Serjeant at Arms to enforce my orders) (ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹਥ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ)

(ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਏਂ । ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵਿਦਡਰਾ ਫਰਾਮ ਦੀ ਹਾਊਸ । (Chaudhri Net Ram should resume his seat and Babu Ajit Kumar should withdraw from the House).

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ........ (ਵਿਘਨ-ਸ਼ੋਰ)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ।

Mr. Speaker: I am sorry that can never be allowed. (interruption)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.... .....(ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker: Please withdraw from the House.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker: Please withdraw from the House.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ।)

PERSONAL EXPLANATIONS

श्री यश पाल (जालंधर-दक्षिण पश्छिम) : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्स-पलेनेशन, सर। स्पीकर साहिब, मैं गुजारिश करुंगा कि कल से बार बार मेरा जिक्र हो रहा है, अगर मैं अपना प्रसनल एक्सप्लेनेशन देता हुआ कुछ ज्यादा वक्त ले लूं तो आप इजाज़त दे देंगे, मेरे मुतालिक इतना जिक्र आया है ।

श्री अध्यक्ष : जो आप के खिलाफ एलीगेशन हैं उनका जवाब दें । मेहरबानी करके स्पीच ना करें । (He should reply only to the allegations made against him. He should not make a speech.)

श्री यश पाल : बार बार अकाली मैम्बरों और कम्यूनिस्ट मैम्बरों की तरफ से कहा गया कि यश को गरिफ्तार क्यों नहीं करते ।

ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

श्री यश पाल : जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से कहा है मैं उन्हें कांग्रेसी नहीं समझता, वह तो अकाली हैं ।

ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਯੂ ਆਰ ਏ ਜਨ ਸੰਘੀ ।

श्री यश पाल : अगर मेरे गिरफतार होने से अमन हो सकता है तो मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूं । इससे जो मुज़ाहरे मेरे खिलाफ हो रहे हैं वे नहीं होंगे । अब तो कांग्रेसियों को जलाया जा रहा है, कम अज़ कम जलने से तो बच जाउंगा । जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने कहा है, कि यश ने कांग्रेस के डिसिप्लन को डिफाई किया है । मैं कांग्रेस के असूलों का पाबंद हूं, मैंने 7 बरस जेल में गुज़ारे । मेरे लिए कांग्रेस से डिफाई करने का सवाल पैदा नहीं होता । मैंनें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेज़ोल्यूशन से इतफाक नहीं किया कुछ लोग ऐसे होतें हैं कि अपनी आत्मा को, ज़मीर को कुचल देते हैं । मेरी तबीयत इस से कुछ मुख्तलिफ हैं । अजीब बात है कि कल तक पंजाबी सूबे की डिमांड को कम्युनल कहा जाता था, और आज इसे फिरकाप्रस्ती की बजाए ज़बान के आधार पर कहा जा रहा है । आज हम इसकी मुखालफित करते हैं तो इस पर हमें फिरकाप्रस्त कहा जा रहा है । लोगों का अपना नज़रिया है । न ही अभी मेरे अस्तीफा देने का सवाल पैदा होता है । जिस दिन पंजाब को डिसइन्टैग्रेट किया जायगा उस दिन मैं कांग्रेस असैंबली पार्टी और असैंबली से अस्तीफा दे दूंगा । 18 बरस तक जिसकी मैं मुखालिफत करता रहा हूं अब मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकता । इस बारे मे मैंने अपनें वोटरों को एशोरेंसिज़ दी हैं, वह मेरी अपनी नहीं है, वह पंडित जवाहर लाल जी नेहरु का वादा है । उस के मुताबिक मैंने लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई को जारी रखूंगा ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ . ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ

1.00 p.m.

ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ।

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । श्री अजीत कुमार खड़े हुए वह बार 2 खड़े हुए। यह रिपब्लीकन पार्टी का व्यू रखना चाहते थे । उन्हें इजाज़त नहीं दी गई । श्री बनवारी लाल जी खड़े हुए तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई । जब हरिजन मैंबर खड़े होते हैं तो ऐसे ही होता है । जब यश जी खड़े होतें हैं तो इन्हें 15, 15 मिनट दे देते हैं । आपका यह रवैया ठीक नहीं । जो पंजाब का हिन्दू होता है उसे इजाज़त दे देते हैं । (विघ्न) जब हरिजन मैम्बर खड़ा होता है तो इजाज़त नहीं देते आप हरेक से ऐसा करते है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ, बैठिए । देखिए, आपने चेयर पर कुछ रिफलेक्शेज़ की हैं । अपने लफ़ज वापिस लें। (Sh. Jagan Nath to please resume his seat. He has made somerefelctions on the Chair. He should withdraw his words.)

श्री जगन्नाथ : मैंनें ठीक कहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप वह लफज वापस लीजिए । (Please withdraw those words.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है मगर वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आप को फिर मौका देता हूं । आप ने अपने लफजों पर दोबारा इंसिस्ट किया है अनकंडीशनली विदड्रा करें । (I give you another chance. He has insisted again on his words. Please withdraw these words unconditionally.)

श्री जगन्नाथ : आप ने जितने वर्डज़ पर एतराज किया है वह वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप ने कुछ लफज़ कहे हैं वह विदड्रा करें । (You have uttered some words which should be withdrawn.)

श्री जगन्नाथ : मैंने जो बात कही थी, बिदड्रा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, आपका प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । (Please resume your seat. This is no point of order.)

श्री यश पाल : एक यहां पर यह कहा गया कि प्रबोध जी ने मुझे मिल कर बात की है । मेरे प्रबोध जी के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं । मुद्दत से हम बात नहीं करते । पंजाबी सूबे के बारे में, पंजाबी सूबे के खिलाफ एजीटेशन के बारे में, अंदोलन के सिलसिले में आज तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई । अफसोस इस बात से होता है कि इतने जिम्मेदार आदमी इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कहते हैं । अगर यह पंजाब गवर्नमैंट मुझे गिरफतार नहीं कर सकती तो कम अज कम किसी जेलखाने में एक कमरा अलाट कर दें, मैं आराम से वहां बैठूगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ । (Sardar Lachhman Singh should please resume his seat).

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ।

(*Interuptians*)

Mr. Speaker : Order, please. (*Noise*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਔਗਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਲ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕੇਸ਼ਬ ਚੰਦਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮਧੋਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ । ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ । ਉਥੇ ਯਸ਼, ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨ-ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker: Order please. This is no point of order. (*noise*)

(*At this stage Giani Kartar Singh rose on a point of personal explanation*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। (Giani ji, I have heard the proceedings. Nobody has said anything against you.)

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਅਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ । ਬਸ ਮੈਂ ਏਨੀ ਗਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ।

ADJOURNMENT MOTIONS (*Resumption*)—(conld.)

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, पानीपत में जो कल वाका हुआ है उस पर मैम्बर साहिबान ने जो रोष का इजहार किया है वह बजा है क्योंकि इस से बढ़ कर heinous, gruesome, कमीना और ज़लील खेल और कोई नहीं हो सकता । यह आग लगाने की बात ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि यह एक इतना नंगा मर्डर किया गया है जिस की कोई भी इनसान निन्दा किए बगैर नहीं रह सकता । ऐसा वाका राज में हो और उस की हम मजम्मत न करें । तो हमारी जमीर जागती नहीं बल्कि सोई हुई रहती है जहां तक एडजर्नमैंट मौशन्ज़ का ताल्लुक है उस पर तो मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज करनी चाहता हूं । रूल्ज़ आफ बिज़नेस के सैकशन 67 में लिखा है ।

(मुख्य मंत्री)

(1) "Notice of an adjournment motion shall be given in writing not less than one and a half hours before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following :—

(i) Speaker.

(ii) Minister concerned or Chief Parliamentary Secretary.

(iii) Secretary.

(2) Notice of an adjournment motion shall be accompanied by a brief explanatory memorandum explaining the motion. Such memorandum shall not be part of the motion."

लेकिन, स्पीकर साहिब, आप ने इस मुताबिक इस पर डिसकशन की अजाजत दी है ताकि मैम्बर साहिबान अपने खयालात का इज़हार करें। चुनाचे तमाम मैम्बरान ने अपने खयालात का इज़हार करके उन वाक्यात की पूरे ज़ोरों से मुज़म्मत की है। ठीक है, करनी चाहिए थी स्पीकर साहिब, सवाल इस से कुछ और भी उठते हैं। जहां तक पानीपत के वाके का ताल्लुक है कल शाम के छः बजे हमारे पास इतलाह आई कि पानीपत में एक वायलेंट माब वायलेंट प्रोसेशन की शकल में निकला है। रास्ते में पुलिस को एक जगह उस पर गोली चलानी पड़ी जिस से एक स्टूडट ज़ख्मी हो कर चन्द मिन्ट बाद मर गया और उस का पोस्ट मार्टम हो रहा है। जिस वक्त यह इतलाह आई उस वक्त हमारी पार्टी मीटिंग हो रही थी। और डिटेल्ज़ नहीं पहुची थी जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने उस वक्त डी. सी., एस. पी. और डी. आई. जी. को कांटैक्ट किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैं हस्पताल से बोल रहा हूं, यहां लड़के का पोस्ट मार्टम हो रहा है। मैं पूरी डिटेल भेज रहा हूं कि और कौन कौन जख्मी हुआ है उसके आध घंटा बाद वहां के आर्य कालज के प्रिंसीपल का टैलीफून आया और उन्होंने कहा कि एक स्टूडैंट की डैथ हो गई है आप उसकी इन्क्वायरी करवाएं। मैंने उन को कहा कि मेरे पास कोई डिटेल नहीं, डिटेलज़ आने के बाद देखेंगे कि सारे वाक्यात क्या हैं। उस के बाद स्पीकर साहिब रात के पौने गयारा बजे के करीब मुझे पानीपत से डिप्टी कमिशनर की तरफ से फोन आया। इस के आधा घंटा बाद खादी आश्रम पानीपत से फोन आया। फिर एक बजे एक कांग्रेस वरकर मलिक अमृत लाल बतरा का टैलीफून आया। मैंने उसी बक्त डी. आई. जी. सी. आई. डी. को डी. सी., एस. पी. और ऐस. डी. एम. को कोंटेक्ट करने की कोशिश की तांकि इस की डिटेलज़ ली जाए और यह पता चले कि जो ज़लील फेल हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहां के एस. पी. जो थे वहां एग्जामीनेशन बोर्ड के सिलसले में फिलौर गए हुए थे। मैंने हिदायत की कि वह फौरन करनाल पहुंच जाएं और डी. आई. जी. को कहा कि अम्बाला डिवीजन की पुलिस फोर्स ले कर वहां पहुंचे। सुबह फिर मैंने डी. सी., एस. पी. और एस. डी. एम. से बात की है और उन को कहा है कि आज दोपहर से पहले जिन लोगों ने यह फेल किया हैं उनको जरूर arrest किया जाना चाहिए चाहे जो भी स्टैपस़ लेने पड़े क्यों कि यह गवर्नमैंट पर इस से बढ़ कर बदनुमा धब्बा और कोई नहीं हो सकता हम ने यहां से अपने इडीशनल आई. जी. पी. को भी फौरन वहां पर भेजा

है और अम्बाला डिवीजन के कमिशनर को इनक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया है और कहा है कि 24 घन्टों के अन्दर अन्दर सारी रिपोर्ट आनी चाहिए । उन को यह भी कहा है कि इस बात की भी तहकीकात करनी है कि वहां के अफसर ने तो किसी किस्म की ड्यूटी देने में कोताही तो नहीं की, जब आग लग रही थी तो उन्हों ने क्या पार्ट पले किया । उन से कहा है कि पूरी छान-बीन करके हमें रिपोर्ट आनी चाहिए । मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह गवर्नमैंट अवाम के जज़बात की कद्र करने वाली है, उन के जज़बात से खेलने वाली नहीं है । मैं यह भी यकीन दिलाना चाहाता हूं कि कल रिपोर्ट पहुंचने पर अगर यह मालूम हुआ कि किसी अफसर ने कोई नैगलीजेंस आफ ड्यूटी की है तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता होगा वह लिया जाएगा । जहां तक कातलों का ताल्लुक है उनके मुताल्लिक जो इतलाह आई है वह यह है कि इस में 9 अशखास शामिल थे जिन में से चार आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और डी. सी. साहिब ने बताया है कि इस काम के लिए सारी फोर्स लगाई हुई है और वह हमें आफटर नून को खबर बताएंगे । हम आशा रखते हैं कि उन तमाम आदमियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे । स्पीकर साहिब, यह एक ऐसा फेल है जिसकी जितनी भी निन्दा की जाए उतनी कम है । यह तीनों, श्री कान्ति कुमार, श्री दीवान चन्द ठक्कर और श्री सन्त राम लाम्बा मेरे नज़दीकी साथी थे । जहां तक श्री कान्ति कुमार का संबंध है, उनके और हमारे पारिवारिक संबंध हैं । हम लाहौर में एक ही गली में रहते थे और जेल में भी हम एक दूसरे के साथ रहे । मुझे तो ज़ाती तौर पर भी भारी चोट लगी है । हम ऐसी चीजें कभी बरदाश्त नहीं कर सकते । इस बारे में मैं हाउस को पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं । पंजाब में रहने वाला एक एक इनसान एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है । हमारे लिए खाह हमारे मुखालिफ हों या साथी हों एक एक इनसान की जान हमारे लिए कीमती है और उसकी पूरे ज़ोर के साथ हिफातज़ की जाएगी । श्री कान्ति कुमार ने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुरबानियां की हैं और अब उन्होंने देश के लिए ही बलिदान दे दिया है । यह हम बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । इस बारे महता रूप लाल जी ने एक सुझाव दिया है । मैं जानता हूं कि यह तीनों परिवार कसमपुरसी की हालत में हो गए हैं उन की कीमत कौन दे सकता है ? लेकिन फिर भी गवर्नमैंट ने उसी वक्त पांच पांच हज़ार रुपए इन तीनों परिवारों के लिए सैंक्शन किए हैं (Cheers) ताकि उन के परिवारों की कुछ न कुछ देखभाल हो सके । यह कोई कीमत नहीं है । हमारा यह इनसानी फर्ज़ है कि हम उनके परिवारों की देख भाल करें । सोमवार को फिर जब पुलिस और ऐडमिनिस्ट्रेशन की मांगों पर बहस हो रही है उस वक्त यह सारी बातें आएंगी और जो वाकयात उस वक्त तक हमारे पास आएंगे वह, स्पीकर साहिब, आपकी मारफत हाउस में पेश करूंगा । चौधरी हरद्वारी लाल जी और कामरेड शमशेर सिंह जोश ने भिवानी के बारे में ज़िक्र किया था । भिवानी के वाक्यात का

[मुख्य मंत्री]

जहां तक सम्बन्ध है वहां जैसा कि सरदार गुरनाम सिंह जी ने कहा वहां एक वायोलैंट माब आया जिसने रैस्ट हाउस, एस. डी. एम. की कोर्ट, रेजीडैंस और सरकारी इमारतों को जलाया। उस वायोलैंट माब को डिसपर्स करने की कोशिश की गई और उन में एक डी. एस. पी. और दूसरे पुलिस कर्मचारी ज़ख्मी हुए कल मैंने उस वायोलैंट माब में कम्युनिस्टों के शामिल होने का ज़िक्र किया था इस बारे में मुझे जोश साहिब और दूसरे कम्युनिस्ट भाई मिले और कहा कि आपने हमारी पार्टी का नाम साथ लगा कर ठीक बात नहीं कही। मैं मानता हूं कि जहां तक बाकी जगहों का सम्बन्ध है वहां अमन शान्ति रखने के लिए कम्युनिस्ट साथियों ने पूरा तुआवन दिया है लेकिन भिवानी के बारे में जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उस में यही है कि कम्युनिस्ट उसमें शामिल हुए हैं। मैंने उन से कहा था कि आप चैक कर लें और मेरे नोटिस में लाएं। डी. आई. जी., डी सी और दूसरे अफसरों की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक तो जो मैंने कहा ठीक है। माब के पास कैरोसीन आयल और पट्रौल के टीन थे। चौधरी हरद्वारी लाल ने एक लैटर को पढ़ा। मैंने कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो इन-वेस्टीगेशन कर लेंगे जो बात आप करते हैं। जो वाक्यात आए हैं वे यह हैं कि माब ने वायोलैंस किया। तहसील जलाने की, टैलीफून ऐक्सचेंज' जलाने की कोशिश की। एक्सचेंज कट आफ रहा। रेलवे स्टेशन भिवानी से टैलीफोन आया तब सारा पता लगा। बहरहाल जहां तक उन्होंने कालिज की बात कही है उसकी इन्वेस्टीगेशन कर लेंगे। हमें हर बेगुनाह के साथ हमदर्दी है लेकिन रायटर के साथ नहीं हो सकती।

ला ऐंड आर्डर के बारे में यहां काफी कुछ कहा गया है। मैं मानता हूं। इस ऐजीटेशन में पांच सात दिन से सिचुएशन ऐसी हुई है जिसे सीरियस कहा जा सकता है लेकिन अब हालात अमृतसर में नारमल हो रहे हैं। सुबह की इतलाह के मुताबिक जालंधर में मंडी फैंटन गंज, सबजी मंडी बगैरा के बाजार खुल गए हैं और नार-मैलसी आ रही है। लुधियाना में कुछ जगह दुकानें नहीं खुली हैं बाकी जगह खुल रही हैं। यह ठीक है कि पिछले पांच सात दिन में ऐसे वाक्यात हुए हैं जिन में वायोलैंस हुआ है, प्रापरटी फूंकी गई है। यह चीज़ काबिले मुजम्मत है। गवर्नमैंट जो स्टैप्स ले सकती थी हालात के मुताबिक लिए हैं हम ने डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रकशनज दी हैं कि अमन कायम रखने के लिए आपको खुली छुट्टी है और अपने अपने इलाकों में अमन कायम रखने के लिए और दंगा फसाद करने वालों से डील करने के लिए आन दी स्पाट जो मुनासिब समझें कार्यवाही करें जो कि हालात के मुताबिक करनी जरूरी हो उन से कहा गया है कि पंजाब में हर हालत में अमन कायम रखना है। जालंधर में ठीक है कुछ बहुत अफसोसनाक वाक्यात हुए हैं और उन्हें देख कर मेरा सिर शर्म से झुकता है। जिस जालंधर से मैं रिटर्न हो कर आता हूं वहां अगर ऐसे वाक्यात हों तो मेरे लिए इस से बढ़ कर और अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है आई. जी. साहिब को भेजा है कि वह लुधियाना, जालंधर, अमृतसर जाकर हालात को देखें और जिला अफसरों से

मिल कर तमाम वाक्यात की ग्रान दी स्पाट स्टडी करें ग्रौर जरूरी कदम उठाएं ताकि ग्रायंदा ऐसे वाक्यात न होने पाएं गुंडा ग्रनसर जो फसादात करना चाहता है उसे दबाएं ग्रौर उन ऐलीमैंट्स को जो दो कम्युनिटीज में फर्क पैदा करना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी से खेलना चाहते है, उनको कर्ब करने के लिए जो कदम उठाए जाने जरूरी हैं उठाएं। श्री डी. एस. ग्रेवाल को जालंधर शहर के लिए मुकर्रर किया है ताकि वह इन सारी चीजों को देखें, उसको काबू करें। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ला ऐंड ग्रार्डर कायम रखने के लिए जो भी तदबीर की जानी जरूरी हैं करेंगे। इस में किसी तरह की ढील, कमजोरी, नहीं ग्राएगी।

जहां तक चीफ मिनिस्टरशिप का सम्बन्ध है यह तो ग्राने जाने वाली चीज है। हमारे साबिक होम मिनिस्टर साहिब पंडित मोहन लाल जी ने मुझे याद दिलाया है कि मेरी जमीर सो गई है ग्रौर उसे उन्होंने जगाया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी ग्रपनी जमीर उस दिन कहां सोई पड़ी थी जिस दिन मोहनगढ़ में घंटा डेढ़ घंटा में 18 मुजारे, ग्रौरतें बच्चे गोली से उड़ा दिए गए थे। उस वक्त उनकी जमीर, पंजाब गवर्नमैंट की जमीर क्यों नही जागी थी ? यह शायद उनकी होम मिनिस्टरशिप के वक्त हुग्रा ग्रौर उन दिनों ऐसे वाक्यात भी नहीं थे जो ग्राज हैं उस वक्त उन्हों ने उसकी तहकीकात कराना भी मंजूर नहीं किया था। ग्राखिर वह भी इनसान थे। इन्होंने उनके परिवारों की तड़प को नहीं देखा ग्रौर उनकी तड़प से इनकी जमीर नहीं जागी। इनकी जमीर उस वक्त भी नहीं जागी जब फिरोजपुर जेल ग्रौर बाहूग्रकबरपुर में निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज हुग्रा ग्रौर गोलियां चली थीं। उस वक्त इनकी जमीर कहां थी जो ग्राज मेरी जमीर की बातें करते हैं ? मैंने भी कांग्रेस पार्टी के मैम्बर के तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो पालीसी थी उसके साथ स्टैंड किया था। मैं इस पार्टी की, जिसका मैं एक सिपाही हूं पालसी के साथ उस वक्त भी स्टैंड करता था, ग्रब भी करता हूँ ग्रौर ग्रागे को भी करुंगा। (Cheers) मैंने कांग्रेस के वफादार सिपाही होने के नाते जिन्दगी कुरबान की है ग्रौर कुछ न कुछ हिस्सा डाला है। मैं पूछता हूं उस वक्त उनकी जमीर कहां गई थी जब दास कमीशन ने उनके खिलाफ फतवा दिया था ग्रौर उन्होंने होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया था। (Cheers)

स्पीकर साहिब, जिस वक्त इन के डिसमिसल के ग्रार्डर जारी नहीं हुए, उस वक्त तक इनकी जमीर का क्या हाल था ? मेरी जमीर ग्रभी भी कायम है, मेरी जमीर ग्रभी तक क्लीयर है। मैं तो पंजाब के ग्रन्दर हिन्दू, सिख ग्रौर मुस्लिम की एकता के लिए तथा नई स्टेट को ग्रच्छा बनाने के लिए ग्रपनी जिन्दगी को कुरबान कर दूंगा (तालियां)। हम नें कांग्रेस के सिद्धांत को माना है। मैंने महात्मा गांधी के ग्रादर्श को ग्रपनाया है। हमारे सामने जो सैकूलरिज्म ग्रौर डेमोक्रेसी का ग्रसूल ग्राया है, मैं उस विधान की एक एक धारा पर पूरी तरह से पाबन्द हूं। हम पंजाब के ग्रन्दर सब मिल कर नया राज्य कायम करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि वह कम्युनल स्टेट नहीं होगी। सरकार ने यह सूबा भाषा के ग्राधार पर बनाने का फैसला किया है। (शोर) (विघ्न)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । स्पीकर साहिब ग्राप ने एडजर्नमैंट मोशन को एडमिट करने के बारे में सारी पार्टियों के मेम्बरों के विचार जानने की कोशिश की । उन्होंने पंजाब के लालैसनैस के बारे में सरकार के नोटिस में बातें लाईं । चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी इस बारे में बताने की कोशिश की । मैं ग्राप के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि इन की पार्टी की तरफ से नो कांफीडैंस के बराबर की मोशन ग्राई है, क्या वह इस बिना पर इस्तीफा देने के लिए तैयार है ? (शोर) (विघ्न)

Mr. Speaker : Please sit down. This is an absolutely gross misuse of Point of Order.

चौधरी मुख्तियार सिंह मालिक : मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं ? क्या ग्रपनी ज़मीर को मार कर गद्दियों पर चिमटे रहना चाहते हैं ? मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि इन की ग्रपनी पार्टी में काफी फूट है जो कि हाउस के ग्रन्दर ही नज़र ग्रा रही है । लेकिन इस की लपेट के ग्रन्दर जन संघ पार्टी को कोस रहे हैं । (घंटी) स्पीकर साहिब, ग्राप तो ग्रौर मेम्बरों को बोलने की इजाज़त देते हैं, लेकिन हमें ग्रपने विचार रखने को इजाज़त नहीं देते क्योंकि हम शरीफ हैं ।

Mr. Speaker : You should resume your seat. You are obstructing the proceedings of the House.

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि पंजाबी सूबे के बारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया । ग्रभी तक गवर्नमेंट ने फैसला करना है । गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने इस सूबे की डिमार्केशन की डिटेल्ज़ तय करनी है । ग्रभी तक इस के बारे में डिटेल्ज़ बननी हैं । वह डिटेल्ज़ लोगों के सामने ग्राएंगी । विधान के मुताबिक माइनारिटीज़ को जो ग्रधिकार है, जैसा कि भारत की ग्रन्य स्टेट्स के ग्रन्दर ग्रधिकार है, वही ग्रधिकार पंजाबी सूबे में माइनारिटी कम्युनिटीज़ को मिलेंगे । मुझे निश्चय है कि जो नया राज कायम होगा, वह कम्यूनल बेस पर नहीं बनेगा । वहां पर विधान के ग्रनुसार मुख्तिलफ पार्टियां चुनाव लड़ेंगी । उस में जो पार्टी बरसरे इक्तदार ग्राएगी वह यहां पर ग्रपनी वज़ारत कायम करेगी ग्रौर वह स्टेट को सैक्यूलरिज्म के ग्रसूलों से चलाएगी । इस से सैक्यूलरिज्म मज़बूत होगा । यहां पर हिन्दु सिख भाई भाई की तरह रहेंगे । उन में ग्रापस में प्यार होगा । मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस के बारे में किसी प्रकार का खदशा है या गलतफहमी है, वह गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया के ग्रधिकारियों से मिलें ताकि उन के खदशात दूर हो सकें । मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि यह राज्य भी उसी ग्राधार पर बनाया जा रहा है जिस तरह से देश के ग्रन्दर दूसरे राज्य हैं । विधान के ग्रन्दर 14 ज़बानें निश्चित की गई हैं । उन में पंजाबी भाषा भी एक भाषा निश्चित है । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसी ग्रसूल को सामने रख कर पंजाबी सूबा बनाने का फैसला किया है । मैं समझता हूं कि इस चीज़ का तशद्दद के तरीके से हल नहीं होगा ।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ क्लैरीफिकेशन, सर । चीफ मिनिस्टर साहिब ने डैमोक्रेसी तथा विधान का हवाला दिया है कि पंजाबी भाषा 14 ज़बानों में से एक है, जो विधान में मानी गई है । मैं पूछना चाहता हूं कि इन की बात मान ली गई है, बाकी जो रह गये हैं, उस का क्या बनाया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं यही बात मज़ाक के तौर पर कह रहा हूं। माननीय सदस्य इस बात को सीरियसली न लें । मैं ने ब्रिटिश की हिस्टरी पढ़ी, मैं ने इस के बारे में पुराने रिकार्डज़ पढ़े हैं, मैं ने भाषा के बारे में डाक्टर ग्रियर्सन की रिपोर्ट पढ़ी है, उन से पता चलता है कि घग्गर के एक तरफ का एरिया और तहसील सिरसा का इलाका पंजाबी भाषी है । वहां पर पंजाबी भाषा बोली जाती है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ क्लैरीफिकेशन, सर । मैं ने तो कामरेड राम किशन से जवाब नहीं मांगा था बल्कि चीफ मिनिस्टर साहिब से अपने प्वायंट की क्लैरीफ़िकेशन सीरिसयली मांगी है । जहां पर जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं, उन की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना जिक्र करना चाहता हूं कि चौटाला या सिरसा तहसील पंजाबी सूबा में जाए या न जाए, सवाल तो यह है कि मुझे पहले भी चौधरी लहरी सिंह, एम.पी. कहा करते रहे हैं कि आप अलीगढ़ के मुस्लिम लीगी हो । मैं हरियाणा प्रान्त के लिए मुस्लिम लीगी होने के लिए तैयार हूं लेकिन वहां पर हरियाणा प्रान्त बनाया जाए । मैं तो चीफ़ मिनिस्टर साहिब से सीरिसयली पूछ रहा था लेकिन उन्हों ने इस बात को मज़ाक में उड़ा दिया । क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब इतनी गम्भीर बात को मज़ाक के तौर पर कह सकते हैं ?

मुख्य मंत्री : इस के बारे में केन्द्रीय सरकार ने फैसला करना है । उन्होंने यह सूबा भाषा के असूल पर माना है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें पंजाब के अन्दर ऐसा वायु मंडल बनाना है जिस से पंजाबी सूबा के फैसले को खुशअसलूबी से अमली जामा पहना सकें ।.... (विघ्न)

[मुख्य मंत्री]

उस के मुताबिक अब हिन्दोस्तान की तकरीबन तमाम पार्टीज़ ने एक आध को छोड़ कर, जो वाक्यात हो रहे हैं इन की मज़म्मत की है। जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, इस के मेम्बरान ने हाउस के अंदर भी और बाहर भी इन वाक्यात की मज़म्मत की है। लेकिन मज़म्मत करने ही की बात नहीं है, अब वक्त आ गया है कि एजीटेशन्ज़ को बंद किया जाए और इनसानी जिंदगियों से ना खेला जाए। आखिर कार हम लड़ किस से रहे हैं? आप एक एक परिवार के अंदर देखें हिन्दू भी है और सिख भी हैं। हमारे धार्मिक स्थान एक ही हैं। आप के ज़रिये मेरी उन दोस्तों से दरखास्त है, जिन को कोई खदशात हों कि वह उन खदशात को दूर करें। पंजाब की तमाम पुलीटीकल पार्टीज़ से, पुलीटीकल लीडर्ज़ से, जितने सन्त हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं गुरद्वारों के ग्रन्थी हैं, मन्दिरों के पुजारी हैं और कुछ ऐसे हैं जिन की किसी जगह पर भी मानता होती है, इज्जत होती है, एहतराम है और जितनी प्रेस है मैं ने उन से यही कहना है कि पंजाब में अमन कायम रखने के लिये, ला एंड आर्डर रेस्टोर करने के लिये, रूल आफ ला कायम करने के लिये और अमनो अमान को मज़बूत करने के लिये वे हमारा ताव्वुन दें। अकेली गवर्नमेंट पर ही यह काम ना छोड़ दें। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां पर भी स्ट्रिजेंट मैयर्ज़ लेने की जरूरत होगी, वहां पर लेंगे। जब माब वायलेंट होता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, और यह हुआ है, इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। उन को सप्रैस करने के लिये पुलिस को कहीं कहीं मुश्किलात पेश आई जहां पर माब छोटी छोटी गलियों में घुस जाता रहा।

स्पीकर साहिब, यहां पर श्री प्रबोध चन्द्र जी की स्टेटमेंट का ज़िक्र किया गया। मैं ख्याल करता हूं कि उस का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। गवर्नमेंट का उस के मुताबिक फैसला है। हमारी हिदायात डिस्ट्रिकट अथारिटीज़ को हैं कि किसी तरह से भी प्रोवोकेशन में नहीं आना। जहां पर माब वायलेंट होता है तो वायलेंट माब को दबाना है। इस में कोशिश यह करो कि मिनीमम फोर्स इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर किसी जगह पर इनसानी जिंदगी को खतरा पड़ता है और कम्यूनल टेंडेंसी पैदा होती है उस को दबाने के लिये डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ को हिदायात हैं कि "you are the Masters on the spot" जो भी ऐक्शन आप लेना चाहें लें। मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ ने स्टेट में अपनी जानों की परवाह ना करते हुए भी अमन कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। कई अनरूली माब आए हैं कि जिन को जिस तरह से दबाना चाहिये था नहीं दबा सके, मसलन ब्रिक बैटिंग और कैरोसीन आयल के वाक्यात, लेकिन उन्हों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन की हिम्मत काबले दाद है। हम इस बात पर डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ को मुबारिकबाद देते हैं। स्पीकर साहिब, यहाँ पर होम सेक्रेटरी का भी ज़िक्र किया गया। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें बिलकुल शक और शुबाह की गुंजाइश नहीं है, तमाम अफसरान

जो स्टेट के हैं पूरी तरह से गवर्नमेंट के लायल हैं। पंजाब के लोगों के भले के लिये, फायदे के लिये, बहबूदी और वैलफेयर के लिये लायलटी से काम कर रहे हैं। किसी के खिलाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई चीज़ नहीं आई। वे तमाम लोग आर्डर्ज़ और इन्स्ट्रकशंज़ फेथफुल्ली कैरी कर रहे हैं और सिचुएशन को अच्छी तरह से काबू करेंगे। अगर कुछ मजीद स्टेप उठाने की आवश्यकता होगी तो वह भी उठाएंगे। किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पंजाब का ला एंड आर्डर कायम रखने के लिये, पंजाब में अमन कायम रखने के लिये हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हर कीमत पर यहां अमन कायम रखा जाएगा और लोगों की जानों को खतरे से बचाया जाएगा।

अभी अभी पानीपत से इत्तलाह आई है कि 9 आदमियों में से 6 इस वक्त ग्रिफतार किये जा चुके हैं। पुलिस प्रोसेशन को रोकने में लगी हुई थी। इस वक्त सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। डैड बाडीज़ को क्रीमेट कर दिया गया है। एस० डी० ओ० और पुलिस प्रोसेशन को रोकने में लगी हुई थी। कोई प्रोसेशन नहीं निकाला गया। मैं आशा रखता हूं कि बाकी के आदमियों को भी पुलिस ग्रिफतार कर लेगी और मज़ीद कार्यवाही उस के मुताबिक की जाएगी। स्पीकर साहिब, मैं एक बार फिर तमाम मेम्बरान से, आपोज़ीशन के लीडर, आपोज़ीशन के मुख्तलिफ ग्रुप्स के लीडर्ज़ से आशा रखता हूं कि इस बात में हमें उन सब का ताव्वुन हासिल होगा, कोआप्रेशन हासिल होगी ताकि हम पंजाब को खुशहाल बना सकें और पंजाबियों का जो कैरेक्टर है, टालरेंस और लव फार ह्यूमैनिटी है उस माटो को सामने रखते हुए पंजाब को आगे ले जा सकें। तीन चार दिन के लिये यह हाउस एडजर्न हो रहा है। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसी जाएंगे तो ज्यादा ध्यान इस बात की तरफ देंगे कि दूसरे लोगों की सहायता से भी वायलेंट एलीमेंट को डिसकरेज किया जाए। आप ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट की प्रापर्टी को नुकसान न हो और कम्यूनल हारमनी कायम रहे। जब सोमवार को हम इकट्ठें हों तो बतौर अमन पसंद पंजाबी के इकट्ठे हों, उस वक्त पंजाब में आग न हो और ऐसा पंजाब हमारे सामने आए जो कि 9 मार्च से पहले था ताकि हम सब फैसलों को खुशअस्लूबी के साथ लागू कर सकें। स्पीकर साहिब, अब डिस्कशन हो चुकी है। आप से दरखास्त है कि आप एड्जर्नमेंट मोशन अलाउ न करें। जिन जज़बात का मैं ने इज़हार किया है मैं आशा रखता हूं कि उन जज़बात के पीछे तमाम लोगों की कोआप्रेशन होगी ताकि हम पंजाब को शक्तिशाली और खुशहाल बना सकें।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, जो आदमी ग्रिफतार किये गए हैं उन के नाम बताएं तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आर्डर, आर्डर। (Please resume you seat. Order please).

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, यहां पर चंडीगढ़ का जिक्र किया गया था मुझे जो इनफार्मेशन मिली है ....

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : सरदार लछमन सिंह जी, आप कोई कार्यवाई नहीं होने देते । (Sardar Lachhhman Singh is obstructing the proceedings.)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आप का काम है यह कहना ।

Mr. Speaker : Please withdraw you words.

सरदार लच्छमन सिंह गिल : मैं विदडरा करता हूं । हर रोज आप यह कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बार बार इन्ट्रप्ट करते हैं । मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा । Will you please withdraw these words ? (You interrupt time and again. I will not permit it. Will you please withdraw these words?)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : मैं ने विदड्रा कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष : आप बार बार इन्ट्रप्ट करते हैं I will not allow you to interrupt the proceedings. (You interrupt again and again. I will not allow you to interrupt the proceedings.)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आप हर बार यही कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप इन्ट्रप्ट करेंगे तो मैं रोकूंगा । (In case you interrupt, I will check you.)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आप नाजायज़ करेंगे तो मैं भी रोकूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आप स्पीकर को चैलेंज नहीं कर सकते । मैं ने आप को बहुत कंसैशन दिये हैं । आप बहुत इन्ट्रप्ट करते हैं । (Order. You cannot challenge the Speaker. I have given you a number of concessions. You make repeated interruptions.)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : मुझे आप के कंसैशन की ज़रूरत नहीं है ।

(Chief Minister was about to resume his Speech when Comrade Babu Singh Master rose on a point of order.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗੀ ਹਈ ਹੈ ਪਰ ਮੌਬ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਦਫਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ? ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਸਣ ਕਿ ਦਫਾ 144 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, दफा 144 के अधीन उसकी खिलाफ वर्ज़ी में जहां जहां भी कोई कार्यवाई पुलिस ने और अथारिटीज़ ने करनी है वह उस के मुताबिक की जा रही है। इस को किसी तरह से भी नजर अन्दाज नहीं किया जा रहा।

चंडीगढ़ की बाबत अर्ज़ करना चाहता हूं। आज यहां पर स्टुडैंट्स का जलूस निकला। वह तीन चार सैक्टर्ज़ के अन्दर गया है। कुछ जगह उन्होंने बसिज़ को डैमेज किया है, तीन चार जगहों पर कारों को भी डैमेज किया है, नीलम सिनेमा के डोर्ज़ और विन्डोज़ के शीशों को डैमेज किया है और इस के साथ ही उन्होंने फायरब्रिगेड स्टेशन पर भी पत्थर वगैरा फैंके हैं। वहां पर भी कुछ डैमेज किया है। इस वक्त उन डिमांस्ट्रेटरज़ का जलूस शायद सैक्टर 22 के नजदीक है। जो पुलिस ने इस सिलसिले में कार्यवाही करनी है वह करेगी।

(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। (Order please.)

(इस समय कई तरफ से प्वायंट आफ आर्डर की आवाजें आई।)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ, ਇਕ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਅਨੰਦ, ਔਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ਼ ਵਿਊ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਰੂਲ 67 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਾਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ subject to the consent of the Speaker. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਲ 68 ਦਾ ਸਬ-ਰੂਲ 8 ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ within reasonable time ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੰਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ out of order declare ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (There are two adjournment motions before the House—one was given notice of by Sarvshri Ram Chander, Dev Raj Anand and Khurshed Ahmad and the other one was tabled during the Course of this discussion by Shri Mohan Lal and many other hon. Members in connection with the Panipat incident. The position is that by now all points of view have been placed before the House.

[Mr. Speaker]

According to Rule 67 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, the notice of such a motion should be given at least one and a half hour before the Commencement of the sitting and it can be accommodated subject to the consent of the Speaker. Besides, Sub Rule VIII of Rule 68 envisages that such a Motion can be ruled out in case the matter in question is anticipated to be brought under discusion in the House within a reasonable time. The demands relating to General Administration and Police are going to be discussed today and on Monday next. The action of police in relation to this incident can be brought under discussion on that occasion. This matter can be discussed in details on both these occasions. Moreover there will be voting on these demands. I, therefore, declare both these motions out of order.)

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in their Second Report in regard to the Demands for Grants.

The Committee, after some discussion, recommended that—

(i) on Thursday, the 17th March and Friday, the 18th March, 1966, there shall be no sittings of the Sabha ;

(ii) the House shall also meet on Saturday, the 26th March, 1966 ; and

(iii) that the Voting of Demands for Grants shall take place in the following order—

Sl. No.	Demand No.	Particulars of Demands	Date of discussion
1.	9	19—General Administration	16th March 1966 &
	12	23—Police	21st March 1966
2.	19	31—Agriculture	
	44	95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.	
	26	42—Multipurpose River Schemes	
	27	43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).	
		44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).	
	28	Charges on Irrigation Establishment	22-3-66
	29	47—Capital Outlay on Multipurpose River Scheme.	& 23-3-66
	46	98—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.	
	47	99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).	

3.	16	28—Education.	24-3-66
4.	22	35—Industries.	25-3-66 & 26-3-66
	45	96—Capital Outlay on Industrial Development.	
	24	38—Labour and Employment (Labour only)	

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion mas carried.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Accounts of the Pepsu Road Transport Corporation for the year 1963-64, together with the Financial Review and the Audit Report thereon, as required under Section 33 (4) of the Road Transport Corporations Act, 1950.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ।(The hon. Member may say it during the course of discussion on the Demand of General Administration.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਥੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ । ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜੂਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । (ਵਿਘਨ) ਇੱਟਾਂ ਵਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਿਰ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order Please.

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ; ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲੂਸ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੁਜ ਜਾਏਗਾ ?

(Interruptions.)

Mr. Speaker : Order please.

STATEMENT LAID ON THE TABLE BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to lay a statement in reply to Call Attention Notice No. 38 by Pandit Mohan Lal Datta on the Table of the House.

STATEMENT

The relations between a landowner and a tenant are governed in this State by the following Acts—

(1) Punjab Tenancy Act, 1887 (ACT NO. XVI of 1887).

(2) The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953. (PUNJAB ACT X of 1953).

(3) The Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955. (Act No. 13 of 1955).

After the attainment of Independence, the Planning Commission laid down the following objectives for land reforms:—

(1) Abolition of intermediaries.

(2) Security of tenure to the tenants.

(3) Improvement of the conditions of agricultural workers.

(4) Provision of fair rent.

(5) Fixation of ceiling on land holdings and distribution of surplus land.

(6) A right of purchase to the tenant.

3. Abolition of Intermediaries

In order to remove the intermediaries, the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act of 1952 and the Pepsu Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act of 1953 were passed in the two States before merger. As a result, about 6,47,740 occupancy tenants have acquired proprietary rights over an area measuring 18,50,489 acres. The landowners have been duly compensated according to the principles laid down for determining the compensation under the two Acts. Inferior landowners have been given full ownership rights under the Punjab Abolition of Ala Malkiyat and Talukdari Rights Act of 1953 and the Pepsu Abolition of Ala Malkiyat Act of 1953. The superior owners have been duly compensated under these Acts. 22,630 Adna Maliks have acquired full ownership rights over an area measuring 13,13,228 acres. With the occupancy tenants and inferior Maliks acquiring ownership rights, intermediary rent receiving tenures have all been abolished. The only tenants left now are tenants-at-will.

4. Security of Tenure to Tenants

Security of tenure to tenants has been provided under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, and the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955. A tenant cannot now be ejected so long as he continues to pay rent regularly and cultivates the land properly. Of course, a big landowner, from his permissible area, and small landowner can seek ejectment of a tenant but a tenant has to be accommodated on a surplus area before he is actually dispossessed. Already 73,763 ejected tenants have been allotted surplus area measuring 1,41,117 standard acres. A tenant who fails to pay rent regularly is ejected summarily and is not considered for allotment of alternative land.

5. Improvement of condition of Agricultural Workers.

Siris or agricultural labourers are not equated with tenants as they do not hold land under a landowner. They get wages for the odd jobs they are put to by a landowner. Their wages have been fixed by the Labour Department in their notification No. 563-3 Lab—II—60/2746, dated 1st February, 1960. Under the Minimum Wages Act of 1948, any landowner paying less wages is liable to punishment under the Act.

6. Provision of Fair Rent.

Under both the Punjab Security of Land Tenures Act and the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, maximum rent payable by a tenant has been fixed at one-third of the produce. Any landowner who fails to give a receipt is punishable with fine up to Rs. 100 under the Punjab Act. Under the Pepsu Act, a penalty not exceeding three times the amount of land revenue can be levied, if a landowner does not give a receipt for recovery of rent. Under the Punjab Act, if a landlord refuses to accept rent from his tenant or demands rent in excess of what he is entitled to, the tenant can report to the Assistant Collector, 2nd Grade, and the Assistant Collector then requires the landowner to accept the rent and to give a receipt. It will thus be seen that adequate provision exists under the two Acts for payment of fair rent. Any attempt by a landowner to charge rent in excess of the prescribed rate of rent is liable to be visited with penalties provided under the two Acts.

7. Ceiling on Land Holdings

Broadly, a ceiling of 30 standard acres for locals has been fixed under both the Punjab and Pepsu Acts. For displaced persons under the Punjab Act, a ceiling of 50 standard acres and under the Pepsu Act of 40 standard acres has been fixed. Under both the Acts, permissible area of a tenant is 30 standard acres. The area within the ceiling of the landowners is treated as permissible area meant for their self-cultivation. The area in excess of the permissible area of the landowners and of the tenants is declared as surplus and is utilised for resettlement of ejected and ejectable tenants. Under the Pepsu Act, the surplus area vests in the State. Under the Punjab Act, the ownership of the surplus area remains with the original landowner. Area measuring 3,68,474 standard acres has so for been declared as surplus. The work of assessment of surplus area has almost been completed.

Both the Punjab and Pepsu Acts and Rules have provided certain exemptions, which are listed below—

Under Punjab Act ond Rules.

(a) Cooperative Garden Colonies which were registered before the coming in to force of the Act.

(b) Area under orchards at the commencement of the Act.

(c) Lands granted to the members of the Armed Forces for gallantry.

(d) Tea Estates and well-run farms.

(e) Land held by Government or Local Bodies.

Under executive instructions lands under orchards planted up to 30th July, 1958 have been exempted from utilisation for resettlement of ejected tenants.

Under Pepsu Act and Rules—

(a) Orchards, specialised farms engaged in cattle breeding, dairying or wool raising.

(b) Sugarcane farms operated by sugar factories.

(c) Efficiently managed farms.

(d) Lands belonging to registered Co-operative Societies, as on 30th October, 1956.

(e) A landowner planting an orchard in an area not exceeding 10 standard acres within two years of the commencement of the Act.

(f) Lands owned or vested in State Government.

(g) Lands belonging to religious or charitable institutions.

(h) Gallantry Grants.

(i) Lands belonging to Panchayats or Local Bodies.

(j) Nazool lands transferred to Co-operative Societies formed by members of the Scheduled Castes.

(k) Lands to which the Pepsu Bhoodan Yagna Act applies.

[Chief Parliamentary Secretary]

Area measuring 90,323 standard acres has been exempted under the various heads given above.

8. Right of Purchase to Tenants

Under the Punjab Act—

(1) The right of purchase is available to a tenant who has been in continuous occupation of the land for six years or more provided that—

(a) the tenancy is not part of the reserved area of the landowner ;

(b) the tenancy is not part of the holding of a small landowner and

(c) a tenant has not sublet the land.

(*See* Section 18 of the Act).

Under the Pepsu Act—

Uuder section 22 read with sections 7-A and 20 of the Act, the right of purchase is given to tenants—

(i) who are not liable to be ejected under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 7-A, and

(ii) under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 7-A.

No tenant, however, can by such purchase acquire more land than his permissible area.

Under both Acts, the landowner is entitled to compensation.

As regards surplus area, under the Punjab Act a tenant settled on surplus area can acquire proprietary rights after six years of continuous occupation. Under the Pepsu Act, a tenant settled on surplus area acquires full proprietary rights as soon as all payments due for such land have been made and in the intervening period, the tenant is required to pay only land revenue and the instalments of the purchase price.

So far 20,516 tenants in the areas of erstwhile Punjab and Pepsu have acquired proprietary rights in 1,37,259 acres of land.

9. What Land Reforms have so far achieved

The following benefits have accrued to the tenant class as a result of the various Land Reforms Acts passed since independence:—

(1) 6,47,740 occupancy tenants have become full proprietors.

(2) 22,630 Adna Maliks have become full owners.

(3) 20,516 tenants have acquired proprietary rights in 1,37,259 acres under the Punjab and Pepsu Acts.

(4) 46,238 tenants have actually been settled on surplus area.

(5) 27,525 tenants have been allotted surplus area but possession has not been delivered for the following reasons:—

(a) Stay orders from the appellate authorities ;

(b) the reluctance of tenants to pay compensation for standing crops;

(c) inferior quality of the land allotted ;

(d) reluctance of tenants to accept allotment made in another village ;

(e) in certain districts, the number of tenants to be legally ejected is far in excess of surplus area available in the district and such tenants are unwilling to be settled on surplus areas available in other districts, where surplus area in excess of what is required for the resettlement of tenants of that district is available ; and

(f) the efforts of influential landlords to prevent the utilisation of their surplus areas.

6. As a result of the security given to tenants under the Acts, the ejectment of thousands of tenants has been stopped. Only tenants who default in the payment of rent or who do not pay rent regularly or who are tenants of small landowners have been ejected. So far as tenants of small landowners and the tenants of permissible areas of big landowners are concerned, they cannot be ejected from the prescribed area until they are settled on surplus area. There are in all 28,71,402 tenants-at-will as against 45,31,380 landowners. The average size of a holding in Punjab is 4.4 acres. The bulk of the holdings in the State, as the figures below show, are below 20 acres:—

Sl. No.	Size of holding		Percentage of total number of holdings in the State
1.	Below 10 acres	..	83.9%
2.	Between 10 and 20 acres	..	9.5%
3.	Between 20 and 30 acres	..	3.2%
4.	Between 30 and 40 acres	...	1.4%
5.	Between 40 and 60 acres	...	1.1%
6.	Between 60 and 100 acres	..	0.6%
7.	Above 100 acres	..	0.3%

The position in Punjab is peculiar because of the mass displacement of peasant proprietors from West Punjab and the allotment to them of lands which were not always free of tenants. Had there been no partition, the tenant problem would have been much simpler. Unfortunately in this State, there is a clash of interests between small peasant proprietors, who have been allotted lands on a part of which or on the whole of which old tenants are sitting, and such tenants. It is not so much a case of absentee landowners wanting to eject old tenants, but it is a case of small peasant proprietors wanting full possession of land for personal cultivation. The process of Land Reforms must, in such circumstances, be evolutionary and must take into account the interests of both landowners and tenants. The ejectment of a certain number of tenants is inevitable unless the small self-cultivating proprietor is to be denied his land. As the figures given above show, nearly 84% of the holdings in Punjab are less than 10 acres, while the number of holdings between 10 and 30 acres constitute nearly 13% and holdings above 30 acres amount to not more than 4% of the total number of holdings in the State. Land Reforms should not result in the displacement of small peasant proprietors so that sitting tenants can become proprietors in their place.

10. Schemes for the Benefit of Tenants.

(1) *Legal Aid Scheme.*—Under the Legal Aid to Tenants Rules, 1961, a tenant whose average monthly income does not exceed Rs. 200 is eligible for legal aid, by providing an Advocate and cash for defraying court fee expenses etc. not exceeding Rs. 50. Legal Aid is available for filing appeals, reviews and revisions as well. Very little use, however, is made of this legal aid by tenants in prosecuting or defending cases instituted by or against them.

(2) *Financial assistance to tenants settled on surplus area.*—Under a Plan scheme, tenants who are settled outside their village are eligible for a sum of Rs. 562·50 as subsidy and Rs 187·50 as loan (Total Rs. 750) for the purpose of construction of their houses and reclamation of land allotted to them. So far, Rs 6,35,500 have been advanced under this scheme. About 1,000 tenants have availed of this financial aid.

11. Difficulties experienced in the administration of Land Reforms Laws.

(1) There is need to have a single Act for the State. The integration of the Pepsu and Punjab Acts is being undertaken.

(2) Some of the provisions have resulted in conflicting interpretations. It is, therefore, necessary to remove all ambiguities and simplify the law to the maximum extent so as to eliminate, as far as possible, conflicting interpretations.

[Chief Parliamentary Secretary]

(3) Tenants, either through ignorance or defective legal assistance, do not take advantage of the many provisions in both Acts to ensure security of tenure, to prevent high handed action by landowners, to restore tenants unlawfully ejected etc.

(4) The difficulty created by tenants themselves in not paying rent properly, in not paying compensation to landowners for the conversion of occupancy rights into proprietary rights or for the purchase of tenancy lands.

(5) The available surplus area is not enough for the resettlement of all tenants liable to be lawfully ejected either from the holdings of small landowners or the reserved area of big landowners.

12. The impact of Land Reforms on food production

While the process of Land reforms must necessarily create some uneasiness in the minds of both landowners and tenants, the factors on which food production depends are—

(1) Increase in irrigation.

(2) A sound irrigation policy which should ensure against waterlogging.

(3) Effective tackling of floods and waterlogging problem.

(4) Good credit facilities for the farmer.

(5) Adequate and regular supplies of fertilizers, improved seeds, pesticides and improved implements.

(6) The elimination of middle men in the marketing of agricultural produce.

(7) Good marketing arrangements and good prices for agricultural produce.

It would, therefore, be wrong to overemphasise the impact of Land Reforms on agricultural production. As shown earlier, the number of holdings in excess of 30 acres is insignificant compared with total number of small holdings in the State and such uncertainty as may exist in the minds of so-called big landowners about their future is not likely to have an adverse effect on agricultural production. The factors enumerated above are of greater importance to small peasant proprietors and tenants in the State than radical land reforms.

The integration of the Punjab and Pepsu Acts is in hand. As soon as the draft of the Bill is ready, a Committee reflecting the various shades of Public opinion will be constituted to go into the draft Bill.

DEMANDS FOR GRANTS

(1) 19—GENERAL ADMINSTRATION

(2) 23—POLICE.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Demands for Grants.

Chief Minister (Shri Ram Kishan): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 4,93,17,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1966-67 in respect of charges under head 19— General Administration.

I also beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 13,83,25,890 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1966-67 in respect of charges under head 23—Police.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a sum not exceeding Rs. 4,93,17,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1966-67 in respect of charges under head 19—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 13,83,25, 890 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1966-67 in respect of charges under head 23—Police.

Both these demands shall be discussed together.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਐਡ-ਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਕਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 40/50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ । ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਸੀ । ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਖਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਠ ਨੌ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਟਿਆਨਾ ਨੂਰੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਫਾ 144 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਪਦਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵਗਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(Shri Ram Saran Chand Mital, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.)

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਪਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਆਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬੰਬਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1958 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਮੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤੋਂ ਦੇ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖੁਦ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਕਈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਪਖੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਈਨਾਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਫਸਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਝਗੜੇ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਵਾਇਅਲੈਂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਿੰਗੁਇਸਟਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ

ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਫਾਸਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਵਡੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਤਨਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਫਾਸਿਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਚ 3 ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੈਜਾਰਟੀ ਉਤੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਦਾਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ .. ..

2 P. M.

Mr Chairman (Shri Ram Saran Chand Mital) : The time is up. The House is adjourned to meet again on Monday, the 21st March, 1966 at 2.00 P. M.

(The House then adjourned till 2.00 p. m. on Monday, the 21st March, 1966)

1654 PVS—386—18-8-66—C., P., & S., Pb., Patiala.

Date Due

32474 PVS—15,000—Govt. Press, U. T., Chd.

32474 PVS—15,000—Govt. Press,

PUNJAB VIDHAN SABHA

Library, Chandigarh

Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrower. In case of set of volumes, price for the whole set will be realised.

Help us to keep the books fresh and clean.